

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj )**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER S No	DUE DTATE	SIGNATURE

# मुद्रा, विनिमय तथा अधिकोषण

Money, Exchange & Banking

( चतुर्थ संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण १९६० )

लेखक

एस. आर. रत्न बी० बी० (घातमं) परमिषम)  
भूतपूर्व उपाचार्य, विजयमजोत सिंह संगानन घमं बानज, बानपुर

एवं

ताम्रिक सलाहकार, यू० पी० चैम्बर ऑफ कामर्स

तथा

पी. एल. गोलवलकर, एम० ए०, बी० बी०  
प्रमुख वाणिज्य विभाग, महाराजा कॉलेज, छत्रपुर (मध्य प्रदेश)



रामप्रसाद एण्ड संस : आगरा

ਮੂਲ੍ਯ ਆਠ ਰੁਪਯੇ ਪਿਚਹੁੱਤਰ ਨਐ ਪੈਸੇ

ਦੁਰਗਾ ਟ੍ਰਿਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ - ਆਗਰਾ

## प्रस्तुत संस्करण के लिए

अनेक विश्वविद्यालयों के विद्वान प्राध्यापकों एवं विद्यार्थियों ने जिस सहृदयता से इन पुस्तक को अपनाया है उसने लिए मैं उन सबका आभारी हूँ। पुस्तक को अनेक विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में स्थान मिलना ही पुस्तक की उपयोगिता का परिचायक है। इसी लोकप्रियता के कारण यह नवीन आवृत्ति पुनः प्रस्तुत हो रही है।

प्रस्तुत संस्करण का पूर्णतः मशोधित किया गया है तथा यथामुम्भव नवीन आवश्यक आंकड़ों का समावेश भी किया गया है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्णरूपेण ध्यान रखते हुए विवेचन अति सरल भाषा में किया गया है जिससे पुस्तक की लोकप्रियता में वृद्धि होगी ऐसा विश्वास है।

विश्वास है कि पिछले संस्करणों की भाँति ही प्रस्तुत संस्करण अपनी लोकप्रियता का परिचय देन में सफल होगा। पुस्तक के मुद्रण के लिए जो भी मुन्नाव आर्थिक, उनका सघन्यवाद स्वागत होगा।

—पी एल गोलवलकर

## द्वितीय आवृत्ति के लिए प्रस्तावना

इस पुस्तक की द्वितीय आवृत्ति आज निकल रही है यह वास्तव में हमारे लिए हर्ष की बात है क्योंकि नवीन पुस्तक हान के नाम इसकी इतनी शीघ्र द्वितीयावृत्ति निकलगी इसी आशा नहीं थी। अल्पावकाश में ही इसकी द्वितीयावृत्ति निकल रही है इससे यह स्पष्ट है कि पुस्तक का स्वागत विद्यार्थियों एवं अध्यापकों ने खुले दिल से किया है जिससे लेखकों को प्रोत्साहन मिला है।

विद्यार्थियों की ओर से हमारे पास कुछ पत्र आये, कुछ अध्यापकों ने भी हम से प्रत्यक्ष कहा कि 'भाषा जरा कठिन है इसको सरल बनाया जाय'। इस बात के लिए हम उन सबके आभारी हैं कि उन्होंने हम व्यावहारिक सुझाव दिया। उन मुन्नाव के अनुसार हमन पुस्तक की भाषा को यथासम्भव सरल बनाने एवं व्यावहारिक हिन्दी शब्दों का समावेश करने का प्रयत्न किया है।

हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए हमको शुद्धतम हिन्दी लिखनी चाहिए और इस कार्य में अध्यापक ही प्रत्यक्ष कार्य कर सकते हैं, जिन्हें देश के भावी लेखकों का, नेताओं का और विद्वानों का निर्माण करना है। शुरु में कठिनाइयाँ तो हर काम में आती ही हैं, उनको दूर कर यदि हम आगे बढ़ते हैं तभी तो हम सफलता मिल सकती है। अत आरम्भ में यह कठिनाई हिन्दी के विषय में भी रहेगी ही, क्योंकि पारिभाषिक शब्दों का अभाव है जो आज नये मालूम होते हैं। परन्तु धीरे-धीरे उनका प्रयोग हम उसी प्रकार करेंगे जैसे कि आज अंग्रेजी का करते हैं।

इस पुस्तक को अद्यावत बनाने के लिए आज तक जितनी भी नवीन घटनाएँ हुई हैं तथा चलन एवं अधिकोपण परिस्थिति में जो भी परिवर्तन हुए हैं उनका समावेश किया गया है जिससे विद्यार्थियों को किसी विषय विशेष का अभाव प्रतीत न हो। इसमें रुपये का अवमूल्यन एवं पुनर्मूल्यन, अधिकोप दर में रिजर्व बैंक द्वारा परिवर्तन एवं उसका प्रभाव, देश की मन्दी आदि नवीन समस्याओं का विवेचन किया गया है।

इस सम्बन्ध में हम अपने मित्र प्रो० चादुरकर, कॉमर्स कालेज, वर्धा के अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने हम व्यावहारिक सूचनाएँ दी एवं पत्र-द्वारा सहायता दी। पुस्तक के संपादन के लिए एवं इसको अद्यावत बनाने के लिए सम्पूर्ण टिप्पणियाँ बनाने का काम सौ० आशा गोलवलकर ने ही किया है, जो एक महत्वपूर्ण कार्य था। अत हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट किये बिना नहीं रह सकते।

अन्त में श्री० हनुहरनाथ जी अग्रवाल ने जिस सहृदयता एवं रुचि से द्वितीय आवृत्ति के प्रकाशन में कार्य दिया है उसके लिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

हमें पूर्ण विश्वास है कि वी० कॉम०, वी० ए० तथा इन्टरमीडिएट विद्यार्थियों की ओर से इस पुस्तक का स्वागत अच्छा ही होगा, जो लेखकों के लिए एक हर्ष की बात होगी।

मकरमकर,  
१४ जनवरी, १९५३

एस० प्रार० रत्न  
पी० एल० गोलवलकर

## दो शब्द

भारतीय स्वातन्त्र्योदय के साथ इस बात का महत्व प्रस्थापित होने लगा है कि विश्वविद्यालयीन शिक्षा अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी अथवा प्रान्तीय भाषाओं के माध्यम से दी जानी चाहिए। क्योंकि शनैः-शनैः यह अनुभव होने लगा था कि यदि शिक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा प्रान्तीय भाषाएँ रहें तो विद्यार्थिगण विषय का भलीभाँति समझ सकते हैं तथा उनकी ग्रहण-शक्ति भी बढ़ती है। यहाँ लार्ड विनियम बंटेक के सुधारों का उल्लेख करना अनिवार्य है क्योंकि उसने अपने सुधारों द्वारा प्रान्तीय भाषाओं को वाय्यानीय भाषा (official language) का रूप दिया। उस समय शिक्षा का माध्यम प्रान्तीय भाषाओं को बनाना सम्भव था परन्तु भारतीय वैधानिकों एवं शिक्षाविदों ने इस विषय में कोई विचार ही नहीं किया। माध्यमिक विद्यालयों में भी उस समय अंग्रेजी ही शिक्षा का माध्यम थी। प्रान्तीय भाषा को माध्यम बनाने का श्रेय डेक्कन ऐज्युकेशनल सोसाइटी को है, जिन्होंने १९०२-०४ में अपने मतारों तथा पूना के विद्यालयों में कुछ विषयों की शिक्षा मराठी में देना प्रारम्भ किया। इसी प्रकार विश्वविद्यालयीन शिक्षा में हिन्दी तथा मराठी को माध्यम बनाने का श्रेय गोविन्दराम मेक्मरिया वाणिज्य महाविद्यालय, वर्धा को प्राप्त है।

नागपुर तथा बनारस के विश्वविद्यालयों ने सर्वप्रथम हिन्दी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य रूप में घोषित किया। उनका अनुकरण कुछ अंशों में अन्य विश्वविद्यालयों में भी हो रहा है। आगरा विश्वविद्यालय, अजमेर बोर्ड तथा यू० पी० बोर्ड ने भी विद्यार्थियों के लिए हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर लिखना ऐच्छिक बना दिया है। किन्तु शिक्षा का माध्यम हिन्दी होने पर हम पाठ्य-पुस्तकों का अभाव प्रतीत होने लगता है जिसकी पूर्ति के लिए हिन्दी में विभिन्न विषयों पर ग्रन्थ निर्माण होन की अतीव व शीघ्र आवश्यकता है। इस दिशा में नागपुर, पटना तथा बनारस के विश्वविद्यालय प्रयत्न कर रहे हैं।

हिन्दी में इस विषय पर पुस्तक लिखकर इसके अभाव की पूर्ति करने का विचार बहुत दिनों से था और सरस्वती देवी की कृपा से यह कार्य आज पूर्ण हो रहा है।

यह पुस्तक विशेषतः इण्टरमीडिएट के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर लिखी गई है तथा बी० ए० व बी० कॉम० के पाठ्यक्रम का भी समावेश इसमें किया गया है। आशा है उन्हें भी यह पुस्तक उपयोगी सिद्ध होगी तथा विद्यार्थी समुदाय इसका सहृदयता से स्वागत करेगा।

पुस्तक की भाषा को, जहाँ तक सम्भव हो सका, सरल एवं सुदीर्घ बनाने का प्रयत्न किया गया है। यथासम्भव पारिभाषिक शब्द डॉ० रघुवीर के शब्द कोशों (प्रकाशक—गोविंदराम सेक्सरिया अर्थ-साहित्य प्रकाशन, वर्धा) से लिये गये हैं तथा सुगमता लाने के लिए उनके अंग्रेजी प्रतिशब्द साथ ही साथ कोष्ठकों में दे दिये हैं।

इस विषय के अध्ययन एवं अध्यापन कार्य में जो कठिनाइयाँ अनुभव होती हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयत्न किया गया है, किन्तु इसमें हमें वहाँ तक सफलता मिली है, यह तो पाठक, अध्यापक एवं विद्यार्थीगण ही बता सकेंगे।

इस पुस्तक को लिखन समय हमें इस विषय की अनेक अंग्रेजी पुस्तकों की सहायता लेनी पड़ी है जिनका यथास्थान नाम-निर्देश किया गया है। उन सब पुस्तकों के लेखकों एवं प्रकाशकों के हम ऋणी हैं और आभारी भी।

जिन महानुभावों ने हमें इस कार्य में समय-समय पर सहायता प्रदान की है तथा प्रोत्साहित किया है उनके हम विशेष रूप से ऋणी हैं। इनमें विक्टोरिया कॉलेज, ग्वालियर के वाणिज्य विभाग के प्रमुख श्री सी० एम० पालविया तथा प्रोफेसर वाघ के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इनके अनिरिक्त सी० आशा गोलवलकर ने भी हमें इस कार्य को पूरा करने में जो सहायता दी है उसके लिए हम उनके ऋणी हैं। पुस्तक के प्रकाशन कार्य में जिम तत्परता से, प्रेमपूर्ण भावना एवं आत्मीयता से सर्वश्री रामप्रसाद एण्ड सन्स ई० संचालक श्री हरिहरनाथ अग्रवाल ने कार्य किया है उसका लिए वे भी धन्यवाद के पात्र हैं।

इस पुस्तक की रचना-पद्धति, पारिभाषिक शब्द आदि में सशोधन एवं सुधार के विषय में जो भी सुझाव दिये जायेंगे उनका हम सधन्यवाद स्वागत करेंगे।

६ दिसम्बर, १९५०

एस० आर० रत्न  
पी० एल० गोलवलकर

# विषयानुक्रम

## भाग १

- अध्याय १ : विषय प्रवेश १-५  
विनिमय की आवश्यकता, विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय क्या है, वस्तु विनिमय कब सम्भव होता है, वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ, साराश ।
- अध्याय २ : मुद्रा का उद्गम तथा कार्य ६-१४  
मुद्रा का उद्गम, मुद्रा की परिभाषा, मुद्रा के कार्य, मुद्रा का स्वरूप, मुद्रा का महत्व, मुद्रा के दोष, साराश ।
- अध्याय ३ : मुद्रा वस्तु के गुण-धर्म अथवा विशेषताएँ १५-१७  
मुद्रा धातु की विशेषताएँ, साराश ।
- अध्याय ४ : मुद्रा का वर्गीकरण एवं तत्सम्बन्धी शब्द प्रयोग १८-२४  
मुद्रा का वर्गीकरण, प्रधान मुद्रा, गौण मुद्रा, क्या भारतीय मुद्रा प्रधान सिक्का है, मुद्रा की उत्पत्ति, मुद्रा-टंकण सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द, मुद्रा टंकण का हेतु, साराश ।
- अध्याय ५ : पत्र-मुद्रा २५-४३  
पत्र-मुद्रा क्या है, पत्र-मुद्रा का उद्गम, पत्र-मुद्रा के प्रकार, पत्र-मुद्रा से लाभ, पत्र-मुद्रा के दोष, अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा के चलनाधिक्य के लक्षण, पत्र-मुद्रा संचालन कौन करे, पत्र-मुद्रा चयन के सिद्धान्त, पत्र-मुद्रा नियमन की पद्धति, पत्र-मुद्रा चलन की विभिन्न विधियाँ, साराश ।
- अध्याय ६ : मुद्रा का मूल्य तथा मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त ४४-६१  
मुद्रा का मूल्य, मुद्रा की माँग तथा पूर्ति, मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त, मुद्रा-मूल्य की विशेषता, मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के साध्य, सिद्धान्त की आलोचना, कैम्ब्रिज का मुद्रा परिमाण समीकरण, कैम्ब्रिज समीकरण के आधारभूत सिद्धान्त, समीकरण का व्यावहारिक रूप, वीन्स का मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त, साराश ।

## अध्याय ७ : मूल्य-निर्देशांक

६२-७८

मूल्य-निर्देशांक क्या हैं, मूल्य-निर्देशांक बनाने की विधियाँ, नामान्य निर्देशांक, भारतीय निर्देशांक, निर्देशांक बनाने समय ध्यान में रखने योग्य सूचनाएँ, निर्देशांक बनाने से लाभ, विद्वन्मनीय निर्देशांक स्रोत, सारांश ।

## अध्याय ८ : मुद्रास्फीति तथा मुद्रा-संकोच

७३-८०

मुद्रास्फीति अथवा मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रा-संकोच अथवा मुद्रा का अवमूल्यन, मुद्रास्फीति के कारण, मुद्रा-संकोच के कारण, मुद्रास्फीति एवं संकोच का प्रभाव, मूल्य स्तर नियमन, सारांश ।

## अध्याय ९ : मुद्रा-मान पद्धतियाँ

८१-१०४

अच्छी मान पद्धति के लक्षण, एक धातुमान पद्धति, स्वर्णमान पद्धति, स्वर्ण मुद्रामान, स्वर्ण धातुमान, स्वर्ण विनिमय मान, द्वि-धातुमान, द्वि-धातुमान पद्धति का इतिहास, प्रेशम का मुद्रा-चलन सिद्धान्त, नियम लागू होने की परिस्थितियाँ, सिद्धान्त की भर्पादाएँ, द्वि-धातुमान के लाभ, हानियाँ, अन्तरराष्ट्रीय द्वि-धातुमान, अगुद्ध द्वि-धातुमान, समानान्तर द्वि-धातुमान, निर्देशांक मान, द्वि-धातु मिश्रित मान, विनिमय मान पद्धति, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा मान, भारतीय मौद्रिक मान, सारांश ।

## अध्याय १० : स्वर्णमान पद्धति का इतिहास एवं भविष्य

१०५-११६

स्वर्णमान ही क्यों ? १९१४ तक स्वर्ण विनिमय मान की कार्य-पद्धति, १९१४ से १९१६ तक, १९१६ के बाद-स्वर्णमान का पुनः स्थापन, युद्ध-पूर्व एवं युद्धोपरान्त स्वर्णमान, स्वर्णमान का परित्याग, स्वर्णमान का भविष्य, सारांश ।

## अध्याय ११ : विदेशी विनिमय

१२०-१५६

विदेशी विनिमय क्या है ? विदेशी विलों की कार्य-प्रणाली, विदेशी विनिमय की माँग एवं पूर्ति, विनिमय की दर, विनिमय की समता, स्वर्ण विन्दु, क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त, क्रय-शक्ति समता सिद्धान्त की आलोचना, विनिमय दर को प्रभावित करने वाले घटक, विदेशी विनिमय सम्बन्धी शब्द प्रयोग, विनिमय दरों का वर्गीकरण, अग्र विनिमय, विनिमय दर का

संगोघन, विनिमय-नियन्त्रण, विनिमय-स्थिरता तथा अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा-बोप, सारास ।

अध्याय १२ : भारतीय चलन का इतिहास (१९१४ तक) १५७-१७३

रुपये का स्वर्ण मूल्य गिरने के कारण, ह्यूगेल समिति, फाउलर समिति, स्वर्ण विनिमय मान की कार्य-प्रणाली, स्वर्ण विनिमय मान की आलोचना, १९१३ के बाद, चेम्बरलेन समिति, सारास ।

अध्याय १३ : भारतीय चलन का इतिहास (१९१४-१९३६) १७४-२०१

युद्धकालीन, स्वर्ण विनिमय मान का अन्त, युद्धकालीन सरकारी प्रयत्न, युद्धोपरान्त—वेविग्टन स्मिथ समिति, सरकारी नीति की आलोचना, हिल्टन यंग कमीशन—चलन पद्धति के दोष, डिफरिन्स, विनिमय दर सम्बन्धी विवाद, १९२७ से १९३६, १९३१ का चलन मरकट तथा रुपये के स्टैलिग से सम्बन्ध, रुपया-स्टैलिग गठबन्धन क्यों ? भारत ने स्वर्ण-निर्यात, रिजर्व बैंक की स्थापना, सारास ।

अध्याय १४ . भारतीय चलन पद्धति (१९३६-१९४५) २०२-२१७

युद्ध के तत्कालीन परिणाम, व्यापारिक स्थिति, विनिमय नियन्त्रण, कर-वृद्धि, युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति, सारास ।

अध्याय १५ भारतीय चलन पद्धति (१९४६-१९६०) २१८-२३०

युद्धोपरान्त मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति का प्रभाव, मुद्रास्फीति को रोकने के लिए प्रयत्न, मन्दी की लहर, पंचवर्षीय योजना-काल, हमारे चलन की वर्तमान स्थिति, सारास ।

अध्याय १६ भारतीय पत्र चलन का इतिहास २३१-२४५

१८६१ में, १८६३ में, चेम्बरलेन समिति, प्रथम विश्व युद्ध-काल, वेविग्टन स्मिथ कमेटी, हिल्टन यंग कमीशन, द्वितीय विश्व युद्ध-काल, युद्ध के बाद, पत्र-चलन पद्धति के दोष, वर्तमान पत्र-चलन व्यवस्था, सारास ।

अध्याय १७ हमारे पौंड पावने २४६-२५२

पौंड पावना का भुगतान, पौंड पावनी का महत्व, पौंड पावनी सम्बन्धी भारत और ब्रिटेन के भ्रमस्रोत, सारास ।

**अध्याय १८ : अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सस्थाएँ**

२५३-२७१

अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष—कोष की सदस्यता एवं पूंजी, सदस्य देशों पर प्रतिबन्ध, कोष का प्रबन्ध कोष का मौद्रिक क्षेत्र में महत्व, कोष की स्वर्ण नीति, भारत और मुद्रा कोष ।

अन्तरराष्ट्रीय बैंक—उद्देश्य, पूंजी एवं सदस्यता, प्रबन्ध, ऋणनीति, क्रियाएँ, अन्तरराष्ट्रीय बैंक और भारत, बैंक का महत्व ।

परिशिष्ट—अन्तरराष्ट्रीय बैंक एवं कोष (नवीन विकास), सारांश ।

**अध्याय १९ : रुपये का अवमूल्यन एवं पुनर्मूल्यन**

२७२-२९१

पृष्ठभूमि, रुपये का अवमूल्यन, अवमूल्यन क्यों ? अवमूल्यन के बाद, पाकिस्तानी-चाल, अवमूल्यन के परिणाम, पुनर्मूल्यन की समस्या, पुनर्मूल्यन के पक्ष में, पुनर्मूल्यन के विरोध में, पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन, सारांश ।

**अध्याय २० : भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली**

२९२-२९७

पूर्व-इतिहास, दाशमिक सिक्के क्यों ? भारतीय टकन अधिनियम १९५५, दाशमिक मुद्रा-प्रणाली का परिचय, परिवर्तन-तालिका, दाशमिक मुद्रा-प्रणाली के लाभ, कठिनाइयाँ, सारांश ।

**द्वितीय भाग****(मुद्रा विनिमय एवं अधिकोषण)****अध्याय १ : बैंक-विकास, परिभाषा एवं कार्य**

३०१-३१३

बैंको का विकास, भारतीय बैंकिंग का विवास, बैंक की परिभाषा, बैंको का वर्गीकरण, बैंको के कार्य एवं सेवाएँ, सारांश ।

**अध्याय २ : बैंकिंग का स्वरूप**

३१५-३२०

बैंकिंग का स्वरूप, एकक बैंकिंग तथा शाख बैंकिंग, शाख बैंकिंग के पक्ष में, एकक बैंकिंग के पक्ष में, मिश्रित बैंकिंग, भारत में शाख बैंकिंग, मुसंचालित बैंकिंग की आवश्यकताएँ, सारांश ।

## अध्याय ३ : बैंक स्थिति विवरण

३२२-३३६

स्थिति विवरण के दो विभाग—देय भाग पूंजी, मचित निधि, निक्षेप, सग्रहण के लिए आये हुए विल, स्वीकृत बिलों पर देय, लाभ हानि लेखा, सम्पत्ति भाग हस्तम्य तथा बैंकों में रोकड़-याचित एवं अल्पकालीन सूचना वाले ऋण, शीत एवं कटौती किये हुए विल, विनियोग, अग्रिम तथा ऋण, प्राप्त विल, ग्राहकों का स्वीकृत पर दायित्व भूगृहादि, निष्कर्ष, स्थिति विवरण से लाभ, बैंकिंग अनुपात, सारांश ।

## अध्याय ४ : बैंकों की विनियोग नीति

३३७-३५०

विनियोग नीति का आधार, विनियोग की पद्धति, रोकड़ निधि, रोकड़ निधि का आधार, लाभ कर उपयोग याचिन एवं अल्पकालीन ऋण, बिलों का न्य एवं कटौती विनियोग पत्र, विनियोग पत्रों में लाभ विनियोग पत्रों का आधार प्रतिभूतिया का वर्गीकरण, ऋण एवं अग्रिम, ऋण के प्रकार एवं स्वरूप, सारांश ।

## अध्याय ५ : जमानत अनुबंध एवं सहायक प्रतिभूतियाँ

३५१-३६७

व्यक्तिगत जमानत जमानती अनुभूति जमानत लेते समय सावधानी, बैंकर की जिम्मेदारी, जमानतदार के अधिकार, महाभन प्रतिभूतियाँ—गहायक प्रतिभूतिया का स्वरूप—ग्रहणाधिकार, रहन, यपन, उपप्राधीयन सहायक प्रतिभूतियाँ लेते समय सावधानी, प्रतिभूतिया के प्रकार—स्वयं विनिमय प्रतिभूतियाँ, वस्तु अथवा वस्तु अधिकार प्रलेख, वस्तु अधिकार प्रलेखों के प्रकार, जीवन बीमा पालिमी, भवन आदि, सारांश ।

## अध्याय ६ : बैंक और ग्राहक

३६८—३७३ ✓

बैंकर और ग्राहक का सम्बन्ध—ऋणी एवं ऋणदाता, बैंक ग्राहक का प्रत्यासी, प्रधान एवं अभिकर्ता, सारांश ।

## अध्याय ७ : साख और साख-निर्माण

३७४—३८६

परिभाषा, साख के तत्व, साख के प्रकार, साख में लाभ, साख से हानि, बैंक द्वारा साख निर्माण, निक्षेपों के दो प्रकार, साख निक्षेपों का निर्माण, साख निर्माण की सीमा, साख ही

पूँजी है ? साख और मूल्य, साख को प्रभावित करने वाली बातें, सारांश ।

अध्याय ५ : साख-पत्र

४८७—४२८

बेचानसाध्य साखपत्र, धारी, यथाविधि धारी, चैंक की परिभाषा, चैंक के पक्ष, महत्वपूर्ण परिवर्तन, चैंको का वर्गीकरण, रेखांकन, रेखांकन कौन कर सकता है ? चैंक खोना, चिह्नित चैंक, यथाविधि उपस्थिति, विकृत-चैंक, जाली चैंक, बेचान—परिभाषा, बेचान कौन कर सकता है ? बेचान के प्रकार, चैंको से लाभ, विनिमय-बिल—परिभाषा, बिलों के प्रकार, बिलों की स्वीकृति, बिलों से लाभ, बिलों का बेचान, उपस्थिति, अनादरण, हुण्डियाँ—हुण्डी में सम्बन्धित शब्द-प्रयोग, प्रतिज्ञापत्र—परिभाषा, प्रतिज्ञापत्र के तीन प्रकार, अन्य साख-पत्र, सारांश ।

अध्याय ६ : बैंक-लेखों के प्रकार

४२६—४३६

✓ चल-निक्षेप चल-लेखा खोलने की विधि, निक्षेप पर्वी पुस्तिका, द्राहक-पुस्तिका, चैंक पुस्तिका, बचत-लेखा, स्थायी निक्षेप लेखा, शकधर सचय निक्षेप लेखा, सारांश ।

अध्याय १० : भुगतानकर्ता एवं सप्राहक बैंक

४४०—४४७

भुगतानकर्ता बैंक, यथाविधि भुगतान बैंक की जिम्मेवारी, बैंक सप्राहक के चैंको का भुगतान कब रोक सकता है ? सप्राहक बैंक, बिलों का संग्रहण, सारांश ।

अध्याय ११ : केन्द्रीय बैंक

४४८—४६१

सरकार और केन्द्रीय बैंक, केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता, केन्द्रीय बैंक के कार्य, केन्द्रीय बैंक द्वारा माख-नियन्त्रण, माख-नियन्त्रण के साधन, बैंक दर का महत्व, सारांश ।

अध्याय १२ : समाशोधन गृह

४६२—४७०

समाशोधन गृहों का विकास, कार्यप्रणाली, समाशोधन गृह से लाभ, भारतीय समाशोधन गृह, समाशोधन गृहों की सदस्यता, व्यवस्था, भारतीय समाशोधन गृह के दोष, सारांश ।

अध्याय १३ : भारतीय बैंकिंग का विकास

४७०—४८०

प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग, बैंकिंग संकट (१९१३-

१७), बैंक विनीयन के कारण, बैंकिंग सक्ट के परिणाम, बैंकों का जव्यवस्थित विकास, दूसरे युद्ध का बैंकिंग पर परिणाम, युद्धकालीन बैंकिंग विकास के दोष, भारत-विभाजन का बैंकिंग पर प्रभाव, भारत में बैंकों का एकीकरण, भारतीय बैंकिंग का भविष्य, सारांश ।

#### अध्याय १४ : भारतीय मुद्रा मण्डी

४६१—५००

भारतीय मुद्रा-मण्डी दोषपूर्ण होने के कारण, भारतीय मुद्रा-मण्डी के भाग, भारतीय मुद्रा-मण्डी के दोष, विनों की कमी के कारण, रिजर्व बैंक द्वारा बिल बाजार का निर्माण, सारांश ।

#### अध्याय १५ : स्वदेशीय बैंकर

५०१—५१४

परिभाषा, सामान्य नृणक्षता एवं स्वदेशी बैंकर में भेद, स्वदेशी बैंकरो की कार्यप्रणाली, इनका वर्तमान महत्व, वर्तमान अग्रगति के कारण, स्वदेशी बैंकर एवं व्यापारिक बैंकों का सम्बन्ध, स्वदेशी बैंकरो के दोष, सुधार के लिए सुझाव, स्वदेशी बैंकर तथा रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक में सम्बन्धित होने के लाभ, सारांश ।

#### अध्याय १६ : व्यापारिक बैंक

५१५—५२६

व्यापारिक बैंकों का वर्गीकरण, कार्यप्रणाली, व्यापारिक बैंकों की विदेशी शाखाएँ, कार्यप्रणाली की त्रुटियाँ, बाहरी कठिनाइयाँ, व्यापारिक बैंकों की उन्नति के सुझाव, सारांश ।

#### अध्याय १७ : विनिमय बैंक

५२७—५४६

विकास, विदेशी विनिमय बैंकों का वर्गीकरण, भारतीय बैंकों ने विदेशी-व्यापार क्यों नहीं अपनाया, भारतीय बैंकों की विदेशी-विनिमय विद्याएँ, विनिमय बैंकों के कार्य, इनकी कार्य-पद्धति, कार्य-पद्धति की त्रुटियाँ, विदेशी विनिमय बैंकों की भारत को देन, विदेशी विनिमय बैंकों का नियन्त्रण, भारतीय विनिमय बैंक, सारांश ।

#### अध्याय १८ : रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

५४७—५६०

रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों ? अद्यपारियों का बैंक अथवा सरकारी बैंक ? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण

बन्धों ? रिजर्व बैंक का विधान—पूँजी, प्रबन्ध, अन्तरिक संगठन एवं व्यवस्था, रिजर्व बैंक के कार्य, रिजर्व बैंक द्वारा साख्त-नियन्त्रण, रिजर्व बैंक का कृषि साख्त विभाग, रिजर्व बैंक का अमूचीवद्ध बैंको से सम्बन्ध, रिजर्व बैंक का भारतीय मुद्रा-मण्डो पर प्रभाव, रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय नियन्त्रण, रिजर्व बैंक का साप्ताहिक विवरण, रिजर्व बैंक से आशाएँ, राष्ट्रीयकरण के बाद, सारास ।

#### अध्याय १९ : स्टेट बैंक और इम्पीरियल बैंक

५९१—६१५

इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया, स्थापना के उद्देश्य, संगठन, इम्पीरियल बैंक के कार्य, रिजर्व बैंक एवं इम्पीरियल बैंक, इम्पीरियल बैंक की क्रियाएँ, इम्पीरियल बैंक के विरुद्ध आक्षेप, इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण । स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया—संगठन, प्रबन्ध, स्टेट बैंक के कार्य, स्टेट बैंक की निषिद्ध क्रियाएँ, बैंक के कोष, स्टेट बैंक एक्ट में संशोधन, स्टेट बैंक की क्रियाएँ, स्टेट बैंक की आलोचना, सारास ।

#### अध्याय २० : औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन

६१६—६२२

औद्योगिक बैंको की आवश्यकता, औद्योगिक बैंक, प्रारम्भिक स्थिति—प्रबन्ध अभिकर्ता, स्वदेशी बैंकर, जनता के निक्षेप, अक्ष एवं ऋणपत्र, व्यापारिक बैंक, केवल दो मार्ग—व्यापारिक बैंको की पद्धति में परिवर्तन, औद्योगिक बैंको की स्थापना, सारास ।

#### अध्याय २१ : औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन—विशेष सत्थाएँ

६२३—६५३

भारतीय औद्योगिक अर्थ-प्रमडल—उद्देश्य, पूँजी, प्रबन्ध, प्रमडल के कार्य, ऋण देने की शक्ती, प्रमडल की क्रियाएँ, आर्थिक परिणाम, अर्थ-प्रमडल की आलोचना, अर्थ-प्रमडल की कठिनाइयाँ, राज्य औद्योगिक अर्थ-प्रमडल—पूँजी, प्रबन्ध, कार्य, निषिद्ध कार्य, बम्बई राज्य द्वारा नया कदम । राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम—पूँजी, उद्देश्य, प्रबन्ध, क्रियाएँ, औद्योगिक साख्त एवं विनियोग निगम—पूँजी एवं आर्थिक साधन, उद्देश्य, प्रबन्ध, अधिकार एवं दायित्व, क्रियाएँ, पुनर्वित्त निगम—विचारधारा, संगठन, प्रबन्ध, उद्देश्य.

व्याज आदि, अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-प्रमदत—पूँजी, उद्देश्य, विनियोग प्रस्तावों की योग्यता एवं स्वरूप, राष्ट्रीय-तन्त्र-उद्योग निगम—पूँजी, कार्य, नियाएँ, सारांश ।

अध्याय २२ : सहकारी बैंक

६५४—६८१

उगम, प्रमुख लाभ, सहकारी तथा व्यापारिक बैंक की तुलना, प्राथमिक सहकारी साख समितियाँ, ग्रामीण सहकारी साख समितियाँ—मगठन, पूँजी, ऋण नीति एवं कार्य, प्रबन्ध, नगर सहकारी बैंक—मगठन, पूँजी, लाभ वितरण एवं प्रबन्ध, ऋणनीति, प्राथमिक सहकारी बैंकों की प्रगति, केन्द्रीय सहकारी बैंक—कार्य, पूँजी, लाभ नियोजन, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी आन्दोलन एवं समितियों की तिफारिश—ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति, ग्रामीण साख सर्वे समिति, द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में, रिजर्व बैंक और सहकारी आन्दोलन, सहकारी आन्दोलन की चुटियाँ, सर माल्कम डालिंग के विचार, डालिंग के सुझाव, भूमिबधक बैंक—परिभाषा, प्रकार, उगम तथा विकास, कार्यशील तथा अन्य पूँजी, कार्य, साभास, विकास-क्षेत्र, भविष्य, सहकारी आन्दोलन एवं सरकार, सारांश ।

अध्याय २३ भारतीय बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम

६८२—६९७

अधिनियम के लाभ, परिभाषा, प्रबन्ध, न्यूनतम निधि एवं चुकता पूँजी, चुकता, प्राप्त, अधिकृत पूँजी एवं मनदान, रोकड-निधि, लाइसेंस, शाखाएँ, वैधानिक कोष, बैंकिंग कम्पनियों की सम्पत्ति, बैंकिंग कम्पनियों पर अन्य प्रतिबन्ध, रिजर्व बैंक के अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार, अन्य अधिकार, बैंकिंग कम्पनीज सशोधन अधिनियम—१९५१, १९५३, १९५६, १९५८, समालोचनात्मक अध्ययन, सारांश ।

परिशिष्ट १ : रिजर्व बैंक एक्ट में सशोधन, स्टेट बैंक एक्ट में सशोधन ६९८

परिशिष्ट २ : विदेशी विनिमय बैंक—भारतीय बैंकों के विदेशी कार्यालय

६९९

परिशिष्ट ३ : विदेशी विनिमय बैंक—भारतीय सूचीबद्ध बैंकों के विदेशी कार्यालयों की सम्पत्ति एवं देनदारी

७००

हिन्दी-ग्रंथों की प्रतिशब्दों की आवश्यक सूची

७०१—७०४

## अध्याय १

# विषय प्रवेश

### विनिमय की आवश्यकता (Necessity of Exchange)

आधुनिक विश्व में प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का निमाण नहीं कर सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति विनिमय (exchange) द्वारा ही करनी पड़ती है। अतः आज हम यह देखते हैं कि वस्तुओं उत्पादन में उद्भोक्ता तथा पहुँचने के लिए कई कड़ियाँ होती हैं जिनका एक मूल में जाने के लिए विनिमय ही एकमात्र माध्यम होता है। कारण एक मनुष्य अपनी वस्तु किसी भी दूसरे व्यक्ति को बिना किसी प्रतिफल (consideration) के अथवा बदले में कुछ लिये बिना नहीं देता। इसी कारण आजकल किसी भी समाज में विनिमय की अत्यन्त आवश्यकता होती है। इतना ही नहीं अपितु विनिमय के अभाव में तो उत्पादन इतना मुगम हो सकता है और न प्रत्येक व्यक्ति इतनी मुगमता से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति ही कर सकता है। विनिमय के अस्तित्व के कारण ही धर्म विभाजन एवं बड़े परिमाण में उत्पादन सम्भव हो सका है। अतः आधुनिक अर्थ व्यवस्था में विनिमय का प्रमुख स्थान है। यह विनिमय वर्तमान समय में मुद्रा के माध्यम के द्वारा होता है।

विनिमय क्या है ?

विनिमय वस्तु अथवा सम्पत्ति की बदला-बदली की उस क्रिया को कहते हैं जिसमें स्वेच्छा में सम्पत्ति का हस्तान्तरण अथवा लेन देन एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य के हाथ होता है। अर्थात् एक मनुष्य जब अपनी इच्छा में एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरी वस्तु—स्पष्टा पैसा अथवा अन्य कोई सम्पत्ति—लेता है तब उसे हम विनिमय कहते हैं।

यह विनिमय दो प्रकार से होता है —

१ वस्तु-विनिमय (Barter System) इसमें एक मनुष्य अपने पास की अतिरिक्त वस्तु के साथ दूसरे व्यक्ति से अपनी आवश्यक वस्तु बदलता है।

इसकी व्याख्या है . "तुलनात्मक अतिरिक्त वस्तु के साथ तुलनात्मक आवश्यक वस्तु का आदान-प्रदान ।" उदाहरणार्थ, अपने पास का अतिरिक्त कपडा देकर अपने लिए आवश्यक गेहूँ लेना ।

२. अप्रत्यक्ष विनिमय अथवा मुद्रा माध्य विनिमय (Indirect Exchange) विनिमय की अथवा बदला बदली की इस पद्धति को क्रय-विक्रय विनिमय (exchange through sale and purchase) भी कहते हैं । इस प्रकार के विनिमय में वस्तुओं के बदले में वस्तुओं की बदला बदली प्रत्यक्ष न होते हुए मुद्रा के माध्यम से होती है । इसलिए इस पद्धति को मुद्रा माध्य अथवा अप्रत्यक्ष विनिमय भी कहते हैं । इसमें मुद्रा के माध्यम से पहले अपनी अतिरिक्त वस्तुएँ अथवा सेवाएँ बेचकर उनके बदले में मुद्रा ली जाती है और फिर उसी मुद्रा से अपने लिए आवश्यक वस्तु खरीदी जा सकती है । चूँकि इसमें एक वस्तु दूसरी वस्तु के साथ बिना किसी माध्यम के नहीं बदली जा सकती, इसे अप्रत्यक्ष विनिमय कहते हैं । जिस वस्तु के माध्यम से हम अपनी अतिरिक्त वस्तुओं का विक्रय एवं आवश्यक वस्तुओं का क्रय करते हैं उसे विनिमय-माध्यम अथवा मुद्रा कहते हैं ।

वस्तु-विनिमय अथवा प्रत्यक्ष विनिमय (Barter) क्या है ?

समाज की प्रारम्भिक अर्ध-व्यवस्था में मनुष्य की आवश्यकताएँ कम थीं एवं श्रम-विभाजन भी नहीं था । प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का निर्माण स्वयं करता था । उस समय विनिमय की आवश्यकता नहीं हुई । किन्तु क्रमशः समाज की आर्थिक उन्नति के साथ अल्प परिमाण में श्रम-विभाजन का प्रारम्भ हुआ । उस समय विनिमय की आवश्यकता हुई । वस्तु-विनिमय से उनका कार्य सुगमता से हो सकता था ।

वस्तु-विनिमय कब सम्भव हो सकता है ?

वस्तु-विनिमय सम्भव होने के लिए आवश्यकताओं का दोहरा सगम होना आवश्यक है । अर्थात् दो ऐसे व्यक्ति हों जिनके पास ऐसी वस्तुएँ हों जो कि एक-दूसरे को देना चाहते हैं तथा वे एक-दूसरे की वस्तुओं को लेना चाहते हैं । अर्थात् दोनों व्यक्तियों के पास अपनी वस्तुओं की अधिकता है तथा एक को दूसरे की वस्तु की आवश्यकता भी है । जब तक ऐसे दो व्यक्ति नहीं मिले तब तक विनिमय की कोई सम्भावना नहीं हो सकती ।

दूसरे, वस्तु-विनिमय समाज की पिछड़ी हुई अवस्था में ही सम्भव है क्योंकि समाज की पिछड़ी हुई अवस्था में मानवी आवश्यकताएँ कम होती हैं ।

इसलिए, समाज की पिछड़ी हुई आर्थिक अवस्था वस्तु विनिमय की दूसरी शर्त है।

तीसरे, वस्तु विनिमय की सम्पन्नता के लिए बाजारों का क्षेत्र सीमित होना चाहिए जहाँ आवश्यकता की वस्तुएँ मिलती हों। यदि बाजारों का क्षेत्र बड़ा होगा तो मनुष्य को यह सम्भव नहीं होगा कि वह अपनी आवश्यकता की वस्तु लेने के लिए काफी दूर-दूर तक अपनी गतिरिक्त वस्तु न जा सके।

अतः वस्तु विनिमय केवल तीन ही परिस्थितियों में सम्पन्नता एवं अच्छी तरह से कार्य कर सकता है १ आवश्यकताओं का दुहरा भगम, २ समाज की पिछड़ी हुई आर्थिक अवस्था एवं मानवी आवश्यकताओं की कमी तथा ३ बाजारों का सीमित क्षेत्र।

जैसे जैसे इन परिस्थितियों में विशेषतः दूसरी एवं तीसरी में, उन्नति होती गई वैसे-वैसे वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ होने लगीं। फिर भी प्रारम्भिक व्यवस्था में वस्तु विनिमय ही में आवश्यकताओं की पूर्ति होती रही। किन्तु क्रमशः सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ी, धर्म विभाजन में परिवर्तन हुआ एवं उत्पादन की वृद्धि हुई, जिसके कारण आदान-प्रदान के लिए वस्तुओं की मर्यादा में वृद्धि हुई और बाजारों का विकास हुआ। इनसे वस्तु विनिमय में अनेक कठिनाइयाँ प्रतीत होने लगीं और विनिमय के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता प्रतीत हुई।

**वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ**

१ आवश्यकताओं के दोहरे भगम का अभाव (Lack of Double Coincidence of Wants) यह हम ऊपर बता चुके हैं कि वस्तु विनिमय सम्भव होने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं वस्तुओं की अधिकता का दोहरा भगम होना चाहिए अन्यथा वस्तु विनिमय नहीं हो सकता। परन्तु कोई भी दो व्यक्ति अथवा कोई भी दो वस्तुओं के होने से काम नहीं चलेगा। ये दोनों व्यक्ति तथा दोनों वस्तुएँ ऐसी होनी चाहिए कि जो वस्तु एक व्यक्ति के पास अधिक है उसे दूसरा व्यक्ति लेना चाहता है। पहले व्यक्ति के पास जो वस्तु अधिक है वह दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता है एवं दूसरे व्यक्ति की अधिक वस्तु पहले व्यक्ति की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति को आवश्यकताओं का दोहरा भगम कहते हैं। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति के पास कपड़ा अधिकता में है तथा वह गेहूँ चाहता है, अतः उसे ऐसे व्यक्ति को खोज करनी पड़ेगी जो कपड़ा चाहता है तथा जिसके पास गेहूँ है और उसके बदले में कपड़ा

लेने को तैयार है। ऐसा दूसरा व्यक्ति मिलन पर ही वस्तु-विनिमय होगा। अतः ऐसे दो व्यक्ति, जिनकी आवश्यकताएँ एवं अधिकताएँ परस्पर पूरक हैं, एक समय एवं एक ही जगह मिलना चाहिए, जो बहुधा कठिन है। यह पहली बाधा वस्तु-विनिमय में उपस्थित होती है।

२. सर्वमान्य परस्पर मूल्यमापक का अभाव (Lack of a Common Measure of Value) यदि ऐसे दो व्यक्ति मिल गए जो एक-दूसरे से अपनी वस्तुएँ बदलना चाहते हैं, फिर भी उन दोनों को उनकी वस्तुओं का परस्पर मूल्य निश्चित हाकर वह मूल्य एक-दूसरे को मान्य होना चाहिए। जब तक यह नहीं होता तब तक उन दोनों में अदला-बदली नहीं हो सकती। जैसे एक गज कपड़े के बदले में एक सेर गेहूँ एक व्यक्ति लेना चाहता है परन्तु दूसरा व्यक्ति एक गज कपड़े के बदले केवल आधा सेर गेहूँ देना चाहता है, तो फिर उनमें वस्तुओं की अदला-बदली नहीं हो सकती, क्योंकि वस्तु-विनिमय में भिन्न-भिन्न वस्तुओं का सर्वमान्य परस्पर मूल्य निश्चित करने का कोई भी साधन नहीं होता, अपितु, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार अपनी-अपनी वस्तुओं का मूल्य आकता है। अतः भिन्न-भिन्न वस्तुओं के सर्वमान्य परस्पर मूल्यमापक का अभाव, व्यक्ति के पास एक दूसरी अडचन के रूप में वस्तु-विनिमय में उपस्थित होता है।

३. विभाजन की कठिनाई (Lack of Divisibility) यदि एक व्यक्ति के पास एक गाय या घोड़ा है और वह इसके बदले में गेहूँ, कपड़ा तथा दूध लेना चाहता है, तो ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है जिसके पास ये तीनों वस्तुएँ हो और एक वस्तु के बदले में गाय या घोड़ा भी नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए कि गेहूँ वाला, कपड़े वाला तथा दूध वाला, गाय या घोड़े के बदले में अपनी वस्तु देने के लिए तैयार है और इनका मूल्य भी निश्चित हो गया है। फिर भी गाय या घोड़े को तीन टुकड़ों में नहीं बाँटा जा सकता क्योंकि ऐसा करने से गाय या घोड़े की उपयोगिता तथा मूल्य में कमी आ जाएगी। अतः ऐसी दशा में वस्तु-विनिमय नहीं हो सकता। इस प्रकार वस्तु के मूल्य अथवा उपयोगिता में कमी आए बिना विभाजन की कठिनाई वस्तु-विनिमय की तीसरी बाधा है।

इन तीन कठिनाइयों के कारण ही विनिमय क्षेत्र सकुचित रहता है तथा आर्थिक उत्पत्ति में बाधा आती है। इसको दूर करने के लिए मनुष्य को किसी न किसी सर्वमान्य माध्यम को, जिसे हम मुद्रा कहते हैं, स्वीकार करना पड़ा जिससे ये कठिनाइयाँ दूर होकर वर्तमान आर्थिक विकास सम्भव हो सका है।

इस सम्बन्ध में एक आशय यह किया जा सकता है कि आज भी विभिन्न देशों के बीच वस्तु विनिमय होता है जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मटन लकड़ें हम कोयला देते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि इन दोनों ही वस्तुओं की कीमतें पाकिस्तानी एवं भारतीय रुपया में निश्चित करली जाती हैं जिसके आधार पर ही यह विनिमय होता है। आरम्भिक वस्तु विनिमय की भाँति नहीं। अतः वर्तमान वस्तु विनिमय का आधार मुद्रा है, जिससे वास्तव में वह मुद्रासाध्य विनिमय हो जाता है। इस माध्यम में पहले तो व्यक्ति अपनी अधिक वस्तुओं का बचकर-मुद्रा ले सता है और फिर उसके बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुओं की खरीद कर उनकी पूर्ति करता है। इसमें विनिमय में भी सुगमता होती है।

मुद्रा के आविष्कार से हमको पहिले किसी चीज का बचकर बाद में अपनी आवश्यक वस्तु खरीदनी पड़ती है यह बात निर्विवाद है। मुद्रा से विनिमय जितना सुविधाजनक हो गया है उतना पहिले कभी न था। इतना ही नहीं अपितु मुद्रा के कारण ही आज उत्पादक से उपभोक्ता तक मान्य सुगमता से पहुँच सकता है। मुद्रा से हम किसी भी व्यक्ति को छोटी मात्रा में भुगतान कर सकते हैं क्योंकि मुद्रा का विभाजन छान से छोटे भाग में भी हो सकता है जैसे रुपये का विभाजन १०० नये पैसा में। इसी में उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच अनेक कड़ियाँ हों हुए भी क्रय विक्रय मरन हो गया है। इस प्रकार पहिले की अपेक्षा विनिमय की क्रिया आज अधिक सुगम एवं सुविधाजनक हो गई है।

### सारांश

विनिमय के दो प्रकार वस्तु विनिमय एवं मुद्रासाध्य विनिमय (क्रय-विक्रय से)।

वस्तु विनिमय अतिरिक्त वस्तु का आवश्यक वस्तु से लेन-देन।

वस्तु विनिमय की परिस्थिति १ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, २ सीमित बाजार क्षेत्र, ३ समाज की पिछड़ी अवस्था।

वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ १ आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, २ मूल्यमापक का अभाव, ३ विभाजन की कठिनाई।

इसलिए मुद्रा का आविष्कार।

## अध्याय २

# मुद्रा का उद्गम तथा कार्य

### मुद्रा का उद्गम तथा इतिहास

मुद्रा माध्यम के रूप में कब से प्रयोग में आई, यह बताना तो असम्भव है, किन्तु यह निश्चित है कि हजारों वर्ष पूर्व मुद्रा का चलन था जो वैदिक कालीन 'निष्क', शतमान, 'सुवर्ण', 'पाद' आदि मुद्रा के नामों से स्पष्ट है। प्राचीन काल में प्रारम्भ में किसी प्रकार का धनाज, पशु, चमड़ा, कौड़ियाँ आदि वस्तुएँ भी मुद्रा के रूप में उपयोग में आती थी इसकी साक्षी इतिहास देता है, क्योंकि भारतीय इतिहास में 'पशुधन' का बार-बार उल्लेख आता है। ग्रीक इतिहास में भी 'पशु' का मुद्रा के रूप में उपयोग होता था। यह 'Pecunia' (धन) शब्द से स्पष्ट है क्योंकि इस शब्द की उत्पत्ति 'Pecus' शब्द से हुई जिसका अर्थ है 'पशु'। इससे यह स्पष्ट है कि पशु आदि ही प्राचीन काल में विनिमय-माध्यम थे किन्तु इन सब प्रकार के माध्यमों में समाज की आर्थिक उन्नति के साथ-साथ कुछ ऐसी कठिनाइयाँ सामने आईं जिनके कारण ही आज माध्यम के रूप में धातु या भूतल्यमापक के रूप में सोना या चांदी का उपयोग होना प्रारम्भ हुआ। यह क्यों हुआ, इसका उल्लेख हम आगे करेंगे।

### मुद्रा की परिभाषा

मुद्रा का अर्थ है 'चिह्न', अर्थात् किसी भी वस्तु पर यदि कोई ऐसा चिह्न बना दिया जाय जो सर्वमान्य हो, तो हम उसे 'मुद्रा' कहेंगे। ऐसी मुद्रा को प्रत्येक व्यक्ति विनिमय के लेन-देन में स्वीकार करेगा, चाहे वह मुद्रा किसी भी वस्तु पर क्यों न हो। भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसकी परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार से की है। जब कभी एक से अधिक अर्थशास्त्री एकजुट होते हैं तो उनका एकमत होना प्रायः असम्भव होता है और हर एक अपना दृष्टिकोण सामने रखता है। किन्तु हम यह प्रत्यक्ष अनुभव से कह सकते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है "जो बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के सवग्राह्य हो, विनिमय माध्यम का काम करती हो तथा जिसको देने से हम पूर्णतया ऋणमुक्त हो सकते हो,"

चाहे ऐसी वस्तु कोई भी क्यों न हो। प्रो० एली का कथन है कि "मुद्रा शब्द का प्रयोग वही तक सीमित है जहाँ तक उसका हस्तान्तरण बिना किसी एकावट के विनिमय माध्यम के रूप में तथा अग्निम ऋणशोधन के रूप में सर्वग्राह्य हो।"<sup>1</sup> राबर्टसन के अनुसार "कोई भी वस्तु जो माल के भुगतान में अथवा अन्य प्रकार के व्यापारिक ऋणशोधन में सर्वत्र स्वीकृत हो, वही मुद्रा है।"<sup>2</sup> प्रो० सेलिंगमैन के शब्दों में "मुद्रा वह वस्तु है जिसमें सर्वग्राह्यता है।"<sup>3</sup> प्रो० ब्रातफोर्ड मार्शल के अनुसार "ऐसी सब वस्तुएँ जो बिना किसी गन्देह अथवा विशेष जाँच के सेवाप्रो, वस्तुप्रो के क्रय एवं खर्चों के भुगाना में माध्यम की तरह चलन में हो, वही मुद्रा हैं।"<sup>4</sup> श्री क्राउयर के शब्दों में "कोई वस्तु जो विनिमय के साधन के रूप में सामान्यतः सर्वग्राह्य हो तथा उसी समय मूल्यमापन एवं मूल्य-मचय का कार्य करती हो, मुद्रा है।"<sup>5</sup>

इन सब परिभाषाओं को देखने में यह स्पष्ट होता है कि मुद्रा विनिमय के माध्यम, मूल्यमापन तथा मूल्य-मचय का कार्य करने वाली सर्वग्राह्य वस्तु होनी चाहिए, और सर्वग्राह्य वस्तु वही हो सकती है जिसका मूल्य एवं प्रचार सब देशों में हो। अतः ऐसी मुद्रा केवल मूल्यवान् धातु पर्यात् सोन व चाँदी की ही हो सकती है। किन्तु आधुनिक धर्म व्यवस्था में पत्र मुद्रा या कागज के नोट भी चलन में रहते हैं और किसी देश की पत्र मुद्रा उस देश में ही सर्वग्राह्य होती है। अतः इन सब परिभाषाओं में अधिक उपयुक्त बात ही परिभाषा है। उनके शब्दों में "मुद्रा ऋण शक्ति है—कोई भी वस्तु जिसमें अथ वस्तुएँ खरीदी जा सक।"<sup>6</sup> इसके अन्तर्गत एस सब साधन आ जाते हैं जो विनिमय का कार्य

<sup>1</sup> The use of the term money is restricted to those instruments of general acceptability, which pass freely from hand to hand as a medium of exchange and are generally received in discharge of final debts as money

<sup>2</sup> Anything which is widely accepted in payment for goods or in discharge of other kinds of business obligations

<sup>3</sup> Money is one thing that possesses general acceptability

<sup>4</sup> All those things which are generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities and services and of defraying expenses

<sup>5</sup> Anything that is generally acceptable as a means of exchange and at the same time acts as a measure and as a store of value

<sup>6</sup> Money is Purchasing Power—something which buys things

करते हैं, उदाहरणार्थ धातु-मुद्रा, पत्र-मुद्रा, चैक, हुण्डी आदि। किन्तु “हमारी मुद्रा की विचारधारा में से चैक तथा हुण्डियों को हमें बहिष्कृत करना पड़ेगा”<sup>१</sup>, ऐसा भी उन्होंने कहा है। हार्टले विद्वान् के शब्दों में “मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है”<sup>२</sup> अर्थात् मुद्रा के कार्य करने वाली जितनी भी वस्तुएँ हैं वे मुद्रा हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं के होते हुए भी ऐसी एक भी सरल परिभाषा नहीं है जिससे मुद्रा का सम्पूर्ण रूप प्रकट हो सके। अतः हमारी दृष्टि से मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्यमापन तथा मूल्य संचय का कार्य करते हुए सबसे आवश्यक कार्य विनिमय-माध्यम का करे। इसी प्रकार की परिभाषा बॉकर ने भी की है—“जो वस्तु सम्पूर्ण ऋणशोधन के लिए एक दूसरे के प्रति बिना किसी मन्देह के अनिवर्ण्य रीति से हस्तान्तरित होती है तथा जो देने वाले व्यक्ति की साख के सोच विचार के बिना निस्सन्देह स्वीकृत होती है, ऐसी किसी भी वस्तु को हम मुद्रा कह सकते हैं।” इस परिभाषा के अन्तर्गत चैक, हुण्डियाँ आदि नहीं आते क्योंकि उनको बिना साख की जाँच किए अथवा बिना उस व्यक्ति की जानकारी के कोई भी व्यक्ति सम्पूर्ण ऋणशोधन में अथवा माल के भुगतान में स्वीकृत नहीं करता। अतः प्रतिनिधिक चलन, जैसे चैक आदि में अनिवर्ण्य सर्वग्राह्यता नहीं होती, किन्तु विनिमय के सब प्रकार के लेन देन में अथवा भुगतान में अनिवर्ण्य सर्वग्राह्यता, मुद्रा का विशेष लक्षण है। आजकल यह सर्वग्राह्यता कानून द्वारा घोषित की जाती है इसलिए हम उसे विधिग्राह्य (legal tender) कहते हैं, और जो मुद्रा किसी राष्ट्र विशेष में विधिग्राह्य होती है वही उस देश का चलन होता है।

### मुद्रा के कार्य (Functions of Money)

उपरोक्त परिभाषाओं को देखने से यह मालूम होता है कि मुद्रा का कार्य केवल विनिमय-माध्यम है क्योंकि इन सभी परिभाषाओं में विशेषतः मुद्रा के विनिमय माध्यम एवं सर्वग्राह्यता पर ही जोर दिया गया है। परन्तु मुद्रा केवल विनिमय माध्यम का कार्य ही न करते हुए और भी अनेक कार्य करती है जिनको समझे बिना हमें मुद्रा के स्वरूप की पूर्ण कल्पना नहीं हो सकती। मुद्रा के सम्पूर्ण कार्यों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं —

#### (क) प्राथमिक कार्य (Primary Functions)

<sup>1</sup> It is most expedient to exclude Bills of Exchange as well as Cheques from our conception of money

<sup>2</sup> Money is what money does

(ख) गौण कार्य (Secondary Functions)

(ग) आकस्मिक कार्य (Contingent Functions)

(अ) प्राथमिक कार्य—मुद्रा के प्राथमिक कार्य वे हैं जो मुद्रा द्वारा मर्दव तथा किसी भी समाज में अवाधित रूप से किए जाते हैं। ये कार्य दो हैं —

१ विनिमय-माध्यम—मुद्रा में सबग्राह्यता होने के कारण वह विनिमय में सुगमता लाती है। सब प्रकार की वस्तुओं के मूल्य मुद्रा-माध्यम में प्रकट होने के कारण वस्तु विनिमय की कठिनाइयों को भी वह दूर करती है। मुद्रा के द्वारा पहले हम अपनी सेवाओं अथवा अनिश्चित उत्पादन को बेचकर मुद्रा पर अधिकार प्राप्त करने हैं। फिर उसी मुद्रा में हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य वस्तुओं अथवा सेवाओं को खरीदते हैं। अतः वही मुद्रा सर्व-ग्राह्य हो सकती है एवं सर्वमान्य रूप से चलन में आ सकती है या हम प्राथमिक तथा अत्यावश्यक कार्य को कर। मुद्रा की हम इसलिए आवश्यकता है कि वह हमें दूसरी वस्तुओं पर अधिकार दिलाती है—वह हमारी क्रयशक्ति है।

२ मूल्यमान या मूल्यमापन का साधन—प्रत्येक वस्तु के नापने के लिए हम किसी न किसी मापक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार दूरी नापने के लिए गज, बज्र नापने के लिए पौण्ड, मन, मेर छतक आदि हैं, उसी प्रकार मुद्रा मूल्यमापन का कार्य करती है। इसी कारण सब वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में ही प्रकट किया जाता है। मुद्रा के इस कार्य द्वारा वस्तुओं के परस्पर मूल्यों की तुलना करन तथा उनके मूल्य निर्दिष्ट करन में सुगमता होती है। इस प्रकार वस्तु विनिमय में मूल्यमापन के अभाव की जो कठिनाई थी वह भी दूर हो जाती है तथा विनिमय का कार्य अधिक सुगम हो जाता है। यह मुद्रा का प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण कार्य है जो वह समाज की किसी भी आर्थिक अवस्था में करती है।

(ख) गौण कार्य—प्राथमिक कार्य समाज की आवश्यक आर्थिक अवस्था में मुद्रा द्वारा पूर्ण किए जाते हैं परन्तु समाज की आर्थिक उत्पत्ति के साथ ही मुद्रा के गौण कार्य दिखाई देते हैं। इन कार्यों की उत्पत्ति भी मुद्रा के प्राथमिक कार्यों से ही होती है अतः इनका गौण कार्य कहा जाता है। ये कार्य हैं —

१ मूल्य-संचय (Store of Value)—मुद्रा मूल्यों को संचय करन में सहायक होती है। मुद्रा के मूल्य का अर्थ है मुद्रा की क्रय शक्ति। इसलिए बेंथम (Bentham) ने मुद्रा को तरल सम्पत्ति कहा है।

प्रत्येक व्यक्ति जितने रुपये मासिक कमाता है उन्हे वह उसी महीने में खर्च नहीं करना चाहता, बल्कि कुछ रुपये वह बचाता है जिससे समय पर उनका उपयोग हो सके। जो वह उसी मास में खर्च करता है वह उसका 'वर्तमान-कालीन उपभोग' है और जो वह बचाता है वह भविष्य के उपयोग के लिए होने के कारण उसे 'भविष्यकालीन उपभोग' कहेंगे। यह प्रवृत्ति प्रत्येक मनुष्य की होती है कि वह कुछ सफट के लिए बचाए अर्थात् मूल्य का सग्रह करे। वस्तुओं का सग्रह सम्भव नहीं होता क्योंकि वे शीघ्र-नाशवाग् होती हैं अतः भविष्य की उपभोग्य वस्तुओं का सग्रह करने का साधन प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और मुद्रा के मूल्य में स्थिरता एवं मुद्रा क्रय-शक्ति होने से हम मुद्रा के रूप में सग्रह कर सकते हैं। इसके प्रतिरिक्त, मुद्रा का सग्रह अपने पास न करते हुए यदि हम बैंक में उसे जमा रखें तो उसी रकम से उत्पादन में भी वृद्धि हो सकती है।

२. स्थगित देयमान (Standard for Deferred Payments) — भविष्य-कालीन लेन-देनो के भुगतान का कार्य भी मुद्रा ही करती है। आधुनिक व्यापारिक लेन-देन में साख का बहुत महत्व है। हम प्रत्येक वस्तु के बदले में उसी समय भुगतान नहीं करते, अपितु भविष्य में भुगतान करते हैं इसीलिए ऐसे देय को स्थगित देय कहा जाता है। ऐसे स्थगित देय के व्यवहार आजकल बहुत अधिक परिमाण में होते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि मुद्रा के मूल्य में स्थिरता रहती है तथा वस्तुओं के मूल्य भी मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। इस कारण आज १०० रुपये में खरीद हुए माल का भुगतान हम एक वर्ष बाद १०० रुपये देकर ही कर सकते हैं। यह मुद्रा का चौथा कार्य है। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता होने के कारण मुद्रा यह कार्य जितनी सुगमता से कर सकती है उतनी सुगमता से यह कार्य अन्य वस्तुओं द्वारा नहीं किया जा सकता है।

३. मूल्य हस्तान्तरण — मुद्रा तरल संपत्ति होने के कारण आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान को किसी भी समय भेजी जा सकती है। इसी वजह से आजकल साधारणतः अधिकतर काम उधार ही से चला जाता है। इस प्रकार मुद्रा मूल्य हस्तान्तरण का कार्य भी करती है।

(ग) आकस्मिक कार्य — प्रो० विन्ने के अनुसार मुद्रा चार आकस्मिक कार्य और करती है जो केवल आज की गर्य-व्यवस्था में होने हैं, प्राथमिक अवस्था में नहीं होने थे और न यही कहा जा सकता है कि आगामी अर्थ-व्यवस्था में वे कार्य होवे ही। ये कार्य निम्न हैं —

१. मुद्रा साख के आधार का कार्य करती है<sup>१</sup>—राज के समाज में प्रतीक-पत्रों अथवा साख-पत्रों (जैसे चैक, हुण्डी आदि) का उपयोग मुद्रा की तरह ही होता है क्योंकि प्रतीक-पत्रों का अधिकार हमको उनके निर्देशित मूल्य की मुद्राओं पर अधिकार देता है। चैक जो पक्का-मुद्रा चयन में लाते हैं उनकी साख रखने के लिए अपने कोष (reserve) में कुछ न कुछ मुद्रा अवश्य रखते हैं जिससे ऐसे प्रतीक-पत्रों के बदले में वह मुद्रा दे सकें। हममें यह स्पष्ट है कि मुद्रा के अभाव में प्रतीक-पत्रों का चयन नहीं हो सकता था और न मास की ही इतनी वृद्धि हो सकती थी जितनी आज हम देखते हैं। इस प्रकार मुद्रा साख के आधार का कार्य करती है। मास के विकास एवं उपयोग के कारण पूँजी की गति (mobility) भी गिननी है अर्थात् पूँजी एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार भेजी जा सकती है। पूँजी की इस गतिशीलता के कारण देश का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास होने में सहायता मिलती है। इतना ही नहीं अपितु मुद्रा के कारण पूँजी की गतिशीलता केवल देश के भीतर ही सीमित न रहते हुए वह देश के बाहर भी भेजी जा सकती है अथवा विदेशों में भेगाई जा सकती है।

२. मुद्रा उद्योगों की सघुक्त श्रम के वितरण का कार्य करती है<sup>२</sup>—मुद्रा मूल्यमापक होने के कारण प्रत्येक वस्तु का मूल्य मुद्रा में निश्चित किया जाता है एवं उसे मुद्रा में ही व्यक्त करते हैं। उद्योगों में अनेक व्यक्ति मिलकर कुछ उत्पादन करते हैं तथा इस उत्पादन में भूमि, पूँजी एवं मजदूर का भी कुछ हिस्सा होता है। मुद्रा के अभाव में इन इकाइयों को उनकी सेवाओं का मूल्य देना इतना मुश्किल नहीं था जितना कि आज है और न पहले इनके बड़े पैमाने पर उत्पादन करना बाले कारखाने ही थे। किन्तु आज उत्पादन का मूल्य मुद्रा में निश्चित होने के कारण मुद्रा में ही श्रमिकों की तथा पूँजी आदि की सेवाओं का मूल्य उन्हीं दिया जा सकता है।

३. उपभोक्ता को समीचीन उपयोगिता प्राप्त कराने में मुद्रा सहायक होती है<sup>३</sup>—प्रत्येक वस्तु में मिलने वाली उपयोगिता की तुलना हम उस पर खर्च होने वाली मुद्रा में कर सकते हैं इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपना खर्च इस प्रकार में करता है जिससे उसको कम व्यय में अधिकतम उपयोगिता मिले।

१ Money forms a basis of credit.

२ It functions as distributor of joint products

३ It helps to attain equal marginal utility to the consumers.

४. मुद्रा सब प्रकार की सम्पत्ति तथा पूँजी को एक सामान्य मूल्य देता है<sup>१</sup>—पूँजी अथवा सम्पत्ति को एक सरल रूप में—मुद्रा के रूप में—रख सकते हैं जिसके द्वारा हम अपनी आवश्यक वस्तुओं को किसी भी समय खरीद सकते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा सब प्रकार की पूँजी को तरल (liquid) रूप देती है। प्रत्येक समय में कुछ न कुछ ऐसी पूँजी अवश्य होती है जिसे हम कहीं न कहीं लगाना चाहते हैं। यह पूँजी का विनियोग इसीलिए जल्दी एवं सुगमता से होता है क्योंकि वह मुद्रा में रखी जा सकती है, जो गतिशील है। दूसरे, मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो सर्वमान्य है, जिसे लेने में कोई भी मना नहीं करता। मुद्रा की इसी विशेषता को प्रो० कीन्स ने तरलता-अधिमान (liquidity preference) कहा है जो आजकल मुद्रा का एक आवश्यक गुण माना गया है।

किन्तु उपर्युक्त बातों को करने के लिए यह आवश्यक है कि मुद्रा के मूल्य में स्थिरता हो तथा उसमें जनता का विश्वास रहे तथा लेन-देन में भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट न हो।

### मुद्रा का स्वरूप (Nature of Money)

विनिमय एवं मुद्रा के उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि हम अपनी सेवाएँ तथा वस्तुएँ दूसरे व्यक्तियों की सेवाओं तथा वस्तुओं के साथ बदलते हैं किन्तु यह हमारा साध्य नहीं है। क्योंकि ये सेवाएँ अथवा वस्तुएँ हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए—उपभोग के लिए—चाहते हैं, अतः ये हमारे साधन हैं। अब वही वस्तुएँ अथवा सेवाएँ हम मुद्रा के माध्यम से खरीद अथवा बेच सकते हैं, फिर भी मुद्रा हम अपने पास रखने के लिए नहीं चाहते बल्कि इसलिए चाहते हैं कि उनमें क्रय-शक्ति है—उसको देने में हम आवश्यक वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त करते हैं। मुद्रा साधन रूप है और वस्तुओं का क्रय एवं उनका उपभोग साध्य है। हमारे पास यदि मुद्रा—क्रय-शक्ति—है तो हम किसी भी समय किसी भी वस्तु पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु के शब्दों में 'मुद्रा वस्तु-संग्रह के अधिकार का प्रमाण-पत्र है जो समाज के द्वारा मान्य किया जाएगा।'<sup>२</sup> क्रय शक्ति का मुद्रा में होना अथवा मुद्रा के अस्तित्व से किसी भी वस्तु पर अधिकार मिलना मुद्रा का वास्तविक स्वरूप है।

<sup>१</sup> It gives a generic value to capital (*Money* by Kinlay, p. 65)

<sup>२</sup> It is a certificate that the claims a man has upon the stock of goods will be honoured

इसलिए मनुष्य मुद्रा-प्राप्ति के लिए अविरत प्रयत्नशील है। साथ ही मुद्रा मूल्यमान का कार्य करती है, इसलिए मुद्रा के द्वारा हम अन्य वस्तुओं के मूल्यों की तुलना करते हैं। इस कारण भी प्रत्येक व्यक्ति ऐसी मूल्यमापक वस्तु सदैव अपने पास रखना चाहता है, अर्थात् मूल्यमापकता तथा क्रयशक्ति, यह मुद्रा का मूल्य एवं वास्तविक स्वरूप है।

### मुद्रा का महत्त्व

आज के आर्थिक समाज में मुद्रा का महत्त्व बहुत अधिक है क्योंकि उससे होने वाले लाभ भी बहुत हैं। मुद्रा के अस्तित्व के कारण ही वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ दूर हुईं तथा वर्तमान आर्थिक मङ्गल में सम्भव हुआ क्योंकि आजकल बाजारों में मान निकेला, इस सम्भावना से ही उत्पादन किया जाता है, उसी प्रकार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी पहन की तरह प्रत्यक्ष विनिमय से न होकर हुए कई स्तरों के बाद होती है। मुद्रा के कारण तथा विनिमय पद्धति में सुधार होने में ही बड़े-बड़े कारखाने तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्भव हो सका है तथा उद्योगों में श्रम विभाजन के तत्त्व का भी प्रवर्धन हो सका है। आजकल के कारखानों के लिए आवश्यक भिन्न-भिन्न घटकों (factors of production) का एकीकरण मुद्रा से ही सम्भव हुआ है। वर्तमान समय में बैंक, बीमा आदि बड़ी-बड़ी व्यापारिक मस्याओं की बाढ़ का एकमात्र कारण मुद्रा ही है। इसके अनिरिक्त बड़े-बड़े कारखानों के लिए जो बड़ी मात्रा में पूँजी लगी है उसमें भी मुद्रा के अस्तित्व से ही गति-सामर्थ्य आया क्योंकि बैंक मुद्रा को—पूँजी को—दूसरी जगह जहाँ पर वह अच्छी तरह से उपयोग में आ सके, विनियोग करते हैं। आज जो बाजारों का इतना विस्तार हुआ है एवं अन्तरराष्ट्रीय बाजारों की उन्नति हुई है वह केवल मुद्रा के अस्तित्व के कारण ही सम्भव हो सकी है। इतना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य, समाज एवं देश की अन्य व्यक्तियों, समाजों एवं देशों पर अपनी आवश्यकताओं के लिए निर्भर रहना पड़ता है, इस कारण राष्ट्रीय एकीकरण तथा अन्तरराष्ट्रीय मेल-जोल बढ़ा। मुद्रा के अस्तित्व से स्पर्धा तथा अनुबंध (contract) ने रुढ़ियों को हटाने दिया और मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से स्वतन्त्र बनाया। अर्थात्, मार्शल के शब्दों में, "मुद्रा अर्थ-शास्त्र की गति का केन्द्र है।"<sup>१</sup>

<sup>१</sup> Money is the pivot around which economic science clusters

## मुद्रा के दोष

इतना सब लाभ होते हुए भी मुद्रा में कुछ दोष अवश्य हैं। अखिल विश्व आर्थिक कार्यों के लिए मुद्रा पर निर्भर हान से उसके मूल्य के थाड़े-से भी उतार चढ़ाव से समाज पर भयंकर परिणाम होता है। मुद्रा का मूल्य पूर्णतः स्थायी नहीं है, उसमें थोड़ा-बहुत परिवर्तन होता रहता है। आज की दोषपूर्ण वितरण पद्धति, बाजारों की तेजी व मंदी, तथा व्यापारिक अनैतिकता, ये सब मुद्रा के ही दोष हैं। किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता कि मुद्रा एक बुरी वस्तु है। जहाँ इससे इतने लाभ हैं वहाँ इसमें कतिपय दोष भी हैं जो अन्तरराष्ट्रीय ढंग पर सुसंचालित मुद्रा मान पद्धति के अवनम्य से दूर किये जा सकते हैं।

## सारांश

परिभाषा भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी गई हैं अतः एक निश्चित परिभाषा दे सकना अत्यन्त कठिन है। मुद्रा 'चिह्न' को कहते हैं, चिह्न किसी भी वस्तु पर लगाकर उसे सर्वमान्य बनाया जा सकता है। "मुद्रा वह वस्तु है जो मूल्य संचय का कार्य करते हुए सबसे आवश्यक कार्य विनिमय के माध्यम का करे।"

कार्य मुद्रा के कार्य तीन भागों में विभाजित हैं—१ प्राथमिक कार्य—(क) विनिमय का माध्यम, (ख) मूल्य-मापन। २ गौण कार्य—(क) मूल्य-संचय, (ख) स्थगित देयमान, (ग) मूल्य हस्तान्तरण। ३ अहस्तिक कार्य—ये कार्य केवल आज की अर्थ-व्यवस्था में सम्पन्न होते हैं—(क) साज का आधार, (ख) समुक्त धन का वितरण, (ग) उपभोक्ता को समसीमान्त उपयोगिता प्राप्त कराने में सहायक, (घ) सब प्रकार की सम्पत्ति तथा पूँजी को सामान्य मूल्य प्रदान करना।

मुद्रा का स्वरूप मुद्रा साध्य नहीं साधन मात्र है। क्रय-शक्ति अर्थात् मुद्रा के अस्तित्व से किसी भी वस्तु पर अधिकार प्राप्त होता है।

मुद्रा का महत्त्व आर्थिक विकास, बड़ी मात्रा में उत्पादन, अन्तरराष्ट्रीय बाजार मुद्रा के अस्तित्व के कारण ही सम्भव हो सका।

मुद्रा के दोष सदोष वितरण पद्धति, व्यापारिक तेजी-मंदी, व्यापारिक अनैतिकता।

## मुद्रा-वस्तु के गुण-धर्म अथवा विशेषताएँ

हमने पहले अध्याय में देखा कि प्रायमित्र अवस्था में अभी तक अनेक वस्तुएँ मुद्रा के रूप में आईं, लेकिन सभी सब वस्तुएँ मुद्रा के प्रायमित्र कार्य ही करने में समर्थ थीं। अन्त में हमारे सामने सर्वमान्य मुद्रा-वस्तु के रूप में सोना तथा चाँदी का उपयोग होने लगा तथा आज भी होता है। अतः यह जानना आवश्यक है कि मुद्रा-वस्तु में कौन-कौन गुण धर्म होना आवश्यक है जिसमें कि वह सर्वमान्य हो तथा मुद्रा के कार्यों को भली-भाँति पूर्ण कर सके। यदि हम मुद्रा के कार्यों का विचार करें तो कौन-कौन गुण-धर्म मुद्रा-वस्तु में होना आवश्यक है, यह हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसका विवरण नीचे दिया है —

- १ विनिमय माध्यम सर्वमान्यता, वहनीयता, विभाज्यता तथा एकरूपता।
- २ मूल्यमान मूल्य, विभाज्यता, एकरूपता तथा सुपरिचयता।
- ३ मूल्य-सचय मूल्य स्थिरता (stability in value), अविनाशता (durability)।
- ४ स्थगित देयमान मूल्य स्थिरता।

उपर्युक्त विद्वेषण से यह स्पष्ट है कि मुद्रा-वस्तु में १ सर्वमान्यता (general acceptability), २ मूल्य (value), ३ वहनीयता (portability), ४ एकरूपता (homogeneity), ५ सुपरिचयता (cognisability), ६ मूल्य स्थिरता (stability in value), ७ विभाज्यता (divisibility) तथा ८ अविनाशिता (durability) ये आठ विशेषताएँ होनी चाहिएँ।

प्राचीन काल में जिन वस्तुओं ने विनिमय-माध्यम का कार्य किया उनमें उपर्युक्त विद्वेषताओं में से किसी न किसी का अभाव होने के कारण ही उनके बदले सोना और चाँदी मुद्रा-वस्तु के रूप में विराजमान हुए।

१. सर्वमान्यता कोई भी वस्तु लेन-देन में बिना किसी शर्त के स्वीकृत हो इसके लिए यह आवश्यक है कि उस वस्तु में मूल्य हो। सोना और चाँदी में

उनकी कमी होने के कारण तथा उनकी दुर्लभता के कारण मूल्य है। गहने तथा कला के काम में भी ये धातुएँ उपयोग में आती हैं इसीलिए इनमें सर्वमान्यता है तथा आन्तरिक मूल्य भी है। उपयोगिता का गुण भी मुद्रा-वस्तु में होना चाहिए। वैसे तो मुद्रा विधिग्राह्य कर देने में उसमें सर्वमान्यता की विशेषता आ जाती है, किन्तु केवल उभी देश में जहाँ पर कि वह प्रचलित है। परन्तु किसी भी वस्तु की सभी देशों में अनिवार्य ग्राह्यता तभी होगी जब उसमें उपयोगिता एवं आन्तरिक मूल्य होगा।

२. मूल्य मुद्रा-वस्तु में बाहरी मूल्य के साथ साथ आन्तरिक मूल्य भी होना चाहिए तभी ऐसी मुद्रा बिना किसी जाँच या सन्देह के सर्वमान्य एवं सर्वग्राह्य होती है।

३. बहनीयता अर्थात् एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुगमता मुद्रा को एक जगह से दूसरी जगह हमको भेजना पड़ता है तथा मूल्य का हस्तान्तरण करना पड़ता है। ऐसे समय वह मुद्रा-वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसमें कम आकार में तथा कम वजन में अधिक मूल्य मिले। उदाहरणार्थ, गेहूँ अथवा पशु का जब मुद्रा के रूप में उपयोग होता था तब उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कठिनाई पड़ती थी किन्तु अब सीना एवं ऐसी वस्तु है जिसके छोटे-से टुकड़े में ही अधिक मूल्य रहता है। यह विशेषता सबसे अधिक पत्र-मुद्रा में है, परन्तु उसमें आन्तरिक मूल्य एवं उपयोगिता न होने के कारण वह बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के स्वीकार नहीं होगी।

४. एकरूपता अथवा समरूपता मुद्रा-वस्तु में समरूपता होनी चाहिए अर्थात् वह वस्तु ऐसी हो जिसके समान वजन अथवा समान आकार के यदि अनेक टुकड़े कर दिये जाएँ तो उनका मूल्य एक ही हो। इसी प्रकार ऐसे टुकड़ों को एक ठोस टुकड़े में परिवर्तित करने से वस्तु में एकरूपता रहे एवं मूल्य में भी कमी न आए।

५. सुपरिच्यता अर्थात् वह वस्तु बिना किसी कठिनाई के पहिचानी जा सके तथा उसमें धोखे की सम्भावना कम हो।

६. मूल्य स्थिरता मुद्रा-वस्तु में मूल्य-स्थायित्व होना आवश्यक है जिससे वह मुद्रा के मूल्य सचय तथा स्थगित देयमान आदि कार्यों को कर सके, क्योंकि अगर मूल्यों में मँदव उतार चढ़ाव रहेगा तो ऐसी वस्तु का कोई भी व्यक्ति सग्रह नहीं करेगा क्योंकि उसमें हानि की सम्भावना रहती है। इसी प्रकार स्थगित देयमान का कार्य भी वह मुद्रा-वस्तु नहीं कर सकेगी क्योंकि मूल्यों के

उत्तर-चढ़ाव के कारण देनदार अथवा लेनदार किसी न किसी को हानि होती ही है। अतः मुद्रा-वस्तु में मूल्य-स्थायित्व होना चाहिए।

७ विभाज्यता अर्थात् मूल्य अथवा उपयोगिता में किसी प्रकार की हानि न होते हुए उस वस्तु का विभाजन सम्भव होना चाहिए जिससे कि थोड़ी रकम के लेन-देन के उपयोग में भी वह वस्तु आ सके।

८. अविनाशिता मुद्रा-वस्तु में अविनाशिता होना इसलिए आवश्यक है कि उसमें अधिक समय तक चलन में रहने में घिसावट (wear and tear) अधिक न हो। उसी प्रकार यदि उसका एक स्थान पर कई वर्षों तक रख भी दिया जाए तो भी उसके मूल्य में हानि न हो। इसी गुण से उस वस्तु में मूल्य-स्थायित्व भी रहता है तथा वह मूल्य सचय एवं स्थगित देयमान का कार्य भी कर सकती है।

इन विशेषताओं के अतिरिक्त मुद्रा-वस्तु में शीघ्र-द्रव्यता एवं शीघ्र-घनता के गुण भी होने चाहिए जिससे सिक्के बनाने में सुगमता हो तथा द्रवीकरण (गलने) अथवा घनीकरण (ठोस होने) में उसके मूल्य एवं उपयोगिता में किसी प्रकार की कमी न हो क्योंकि सिक्के ढालने के लिए यह आवश्यक होता है कि जिस धातु के सिक्के बनाए जाएँ वह धातु आसानी से गलाई जा सके तथा ठोस भी शीघ्र हो।

उपर्युक्त गुणों का एक साथ अस्तित्व हम केवल सोना एवं चाँदी में ही पाते हैं इसीलिए सभी देशों में मुद्रा-वस्तु के रूप में इनका प्रचार एवं उपयोग हुआ।

### सारांश

मुद्रा के कार्यों के अनुसार मुद्रा-वस्तु में निम्न गुण होने चाहिए —

- १ विनिमय माध्यम सर्वमान्यता, वहनीयता, विभाज्यता तथा एकरूपता।
- २ मूल्य मान मूल्य, विभाज्यता, एकरूपता तथा सुपरिचयता।
- ३ मूल्य सचय मूल्य स्थिरता तथा अविनाशिता।
- ४ स्थगित देयमान मूल्य स्थिरता।

अतः जिस पदार्थ की मुद्रा बनाई जाए उसमें निम्न गुण होने चाहिए —

- १ सर्वमान्यता, २ मूल्य, ३ वहनीयता, ४ एकरूपता, ५ सुपरिचयता, ६ मूल्य स्थिरता, ७ विभाज्यता, ८ अविनाशिता।

## अध्याय ४

# मुद्रा का वर्गीकरण एवं तत्सम्बन्धी शब्द-प्रयोग

मुद्रा का वर्गीकरण अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है, परन्तु हमको व्यावहारिक जगत् में विशेषतः दो प्रकार की मुद्राएँ मिलती हैं —

१ धातु-मुद्रा (metallic money) तथा

२ पत्र मुद्रा (paper money)

धातु मुद्रा वह है जिसमें किसी न किसी धातु के सिक्के चलन में रहते हैं तथा बैंक-पत्र-मुद्रा वह है जो किसी विशेष अधिकृत व्यक्ति अथवा सरकार द्वारा कागज पर अपने विशेष चिह्न लगाकर व्यवहार में लाई जाती है।

धातु-मुद्रा भी दो प्रकार की होती है — प्रधान, प्रमाणित अथवा सर्वांग-मुद्रा (standard money) तथा गौण, साकेतिक अथवा प्रतीक-मुद्रा (token money)।

## प्रधान मुद्रा

प्रधान मुद्रा उस धातु की बनाई जाती है जो किसी भी देश में कायदे में विनिमय-माध्यम तथा मूल्यमान के लिए निश्चित की जाती है। ऐसी मुद्रा सोने या चाँदी की होती है। इस मुद्रा के सिक्के किसी विशिष्ट एवं निश्चित वजन के, निश्चित मूल्यमापक तथा निश्चित शुद्धता वाले बनाए जाते हैं जो देश के टंकण विधान (Coinage Act) के द्वारा निश्चित किया जाता है। इस मुद्रा के प्रधान लक्षण निम्नलिखित हैं —

१ मूल्यमापक एवं विनिमय माध्यम—ये सिक्के देश के प्रधान सिक्को के रूप में चलने रहते हैं तथा इन्हीं सिक्को में किसी भी वस्तु का अथवा अन्य सिक्को का मूल्य आँका जाता है। अतः प्रधान सिक्के देश में मूल्यमापन एवं विनिमय माध्यम का कार्य करते हैं।

२ टंकण स्वातन्त्र्य (Free Coinage)—इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपना आवश्यकतानुसार, उसके बदले उतने ही वजन एवं मूल्य की धातु देकर, सिक्को का टंकणन से टंकण करा सकता है। इसमें सरकार की ओर से किसी भी

प्रकार का प्रतिवन्ध अथवा रकावट नहीं होनी। ऐसे टक्का के लिए सरकार उस व्यक्ति से टक्का शुल्क (charge for coinage) लेती है अथवा नहीं भी लेती। इस अवस्था में सिक्को की कमी नहीं आनी क्योंकि यदि सिक्को की कमी हो तो जनता अपने स्वर्ण को टक्कात से सिक्को में बदल लेती है।

३. आन्तरिक एवं बाहरी मूल्य में समानता (Equality in the Face Value and Intrinsic Value)—टक्का प्रिचन के अनुसार सिक्के का बाहरी मूल्य तथा उसमें होने वाली मुद्रा धातु की मात्रा की निश्चित किया जाता है। प्रधान सिक्के के आन्तरिक मूल्य तथा बाहरी मूल्य में समानता होनी चाहिए—जैसे, भारतीय रुपये का बाहरी मूल्य १०० नये पैसे है तो उसमें १०० नये पैसे मूल्य की ही चाँदी होनी चाहिए प्रथम आन्तरिक मूल्य १०० नये पैसे ही होना चाहिए।

४. असीमित विधिप्राप्तता (Unlimited Legal Tender)—उपर्युक्त दो विशेषताओं के कारण तथा यह मुद्रा देश की प्रधान मुद्रा होने के कारण किसी भी व्यक्ति को यह असीमित मात्रा में वास्तुनत स्वीकार करनी पड़ती है। इसे असीमित विधिप्राप्तता कहते हैं। बड़े-बड़े लेन-देन के व्यवहार प्रधान मुद्रा में ही होते हैं।

### गौण मुद्रा

प्रधान मुद्रा के विपरीत नक्षण प्रतीक अथवा गौण मुद्रा में पाए जाते हैं। गौण मुद्रा केवल मरुप परिमाण के व्यवहारों के भुगतान के लिए बनाई जाती है जिसमें कि वह प्रधान मुद्रा के लिए महामय रह। यह सिक्का प्रायः हल्की अथवा गौण धातु का बनाया जाता है, जैसे, ताँबा, निक्केल आदि। दूसरे, कोई भी व्यक्ति इसका टक्का नहीं कर सकता अर्थात् यह केवल देश की सरकार द्वारा ही डलयाया जाता है। तीसरा, इसका बाहरी मूल्य इसके आन्तरिक अथवा धातु मूल्य से अधिक होता है। चार्जे, एमे सिक्को को लेन देन में सीमित मात्रा में ही दिया जाता है, जैसे, इंग्लैण्ड में निनिग ४० की मरुधा तब विधिप्राप्त है तथा भारत में नये पैसे केवल १० रुपये तक विधिप्राप्त हैं। इस प्रकार गौण, प्रतीक अथवा मार्केटिक मुद्रा के निम्न चार लक्षण हैं —

१. प्रतिबन्धित टक्का (restricted coinage)
२. आन्तरिक मूल्य में बाहरी मूल्य में अधिकता (more face value than intrinsic value)

३. सीमित विधिग्राह्यता (limited legal tender)

४. हल्की अथवा कम मूल्य की धातु का उपयोग ।

क्या भारतीय रुपया प्रधान सिक्का है ?

भारतीय सिक्का रुपया शुरू से आज तक प्रधान सिक्का माना जाता है किन्तु प्रधान सिक्के की सब विशेषताएँ इसमें नहीं हैं अर्थात् न आन्तरिक एवं बाहरी मूल्य में समानता है और न टक्कण-स्वातन्त्र्य ही है । यह टक्कण-स्वातन्त्र्य सन् १८६३ तक भारतीय रुपये में था किन्तु १८६३ से वह छीन लिया गया । यह असीमित विधिग्राह्य अवश्य है । सारांश, इसमें केवल असीमित विधिग्राह्यता ही प्रधान सिक्के का लक्षण है, अन्य दो लक्षण—प्रतिबन्धित टक्कण तथा बाहरी मूल्य की धातु मूल्य से अधिपता—प्रतीक अथवा गौण मुद्रा के हैं अतः यह भारत की वास्तविक प्रधान मुद्रा होते हुए भी सर्वांग पूर्ण प्रधान मुद्रा नहीं कही जा सकती ।

मुद्रा की उत्क्रान्ति

सोने व चाँदी का मुद्रा-वस्तु के रूप में जब सर्वप्रथम उपयोग प्रारम्भ हुआ उस समय ये टुकड़ों में ही प्रयोग में आते थे और लेने वालों को इनकी शुद्धता तथा वजन की तौल एवं जाँच करनी पड़ती थी । अतः बाजार में व्यापारियों को सोने चाँदी की जाँच तथा वजन करने के लिए आवश्यक वस्तुएँ साथ रखनी पड़ती थी । इस कठिनाई को हटाने के लिए जगत् में सेठ जैसे कुछ प्रतिष्ठित सर्राफों एवं साहूकारों ने, जिनकी साख का जनता को विश्वास था, सोने-चाँदी पर अपनी मुद्रा अथवा विशेष चिह्न लगाना प्रारम्भ किया जिससे उनकी शुद्धता में मिलावट न की जा सके । फिर भी वजन तो करना ही पड़ता था । इस प्रकार के चलन को “भारत-चलन” (currency by weight) कहते हैं । इस वजन करने की कठिनाई को दूर करने की दृष्टि से धातु के एक निश्चित वजन के टुकड़े लेकर उन पर मुद्रा अंकित की जाने लगी जिससे न उनकी तौल की और न जाँच की आवश्यकता रहे । फिर भी, इनमें से किनारे काटकर वजन की कमी कर ली जाती थी, अतः तौलने की आवश्यकता कभी कभी प्रतीत होती थी । इसके बाद क्रमशः सिक्के बनने लगे जिनमें धोबे व जालसाजी की सम्भावना कम थी । तभी से गिने जाने वाली मुद्रा का प्रादुर्भाव हुआ । आज का सिक्का गोल, समान वजन का, निश्चित धातु-मान का एवं कटकिटीदार किनारे का है जिससे उसमें धोबे या जालसाजी की बहुत कम सम्भावना है । फिर भी जानी सिक्के आज भी बनते ही हैं । परन्तु वे आसानी से पहचाने जा सकते हैं ।

## मुद्रा-टक्कण सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द

मिक्का बनाने का कार्य सरकार अथवा सरकार द्वारा नियुक्त किसी मन्थ्या का होता है। मिक्का अथवा मुद्रा धातु के उम टुकड़े को कहते हैं जिसका वजन एवं शुद्धता उम पर लगी हुई मुद्रा अथवा मुहर द्वारा प्रमाणित की जाती है।<sup>1</sup> जहाँ ये सिक्के बनते हैं उसे टङ्कशाला या टक्काल (mint) तथा सिक्का बनाने की क्रिया को टक्कण (coinage) कहते हैं। यह टक्कण तीन प्रकार का होता है —

**टङ्कण स्वातन्त्र्य (Free Coinage)** —जिनमें कोई भी व्यक्ति टङ्कशाला में धातु ले जाकर सिक्के में परिवर्तित करा सकता है। यह टङ्कण नि शुल्क अथवा मजुल्क होता है। जब टङ्कण के लिए जनता में किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता तब हम उसे नि शुल्क टङ्कण कहते हैं। जब यह शुल्क मिक्का बनाने में जो लगे होता है उसी के बराबर लिया जाता है, तो उसे टङ्कण शुल्क (brassage) कहते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार कभी-कभी मुद्रा-टङ्कण से लाभ उठाना चाहती है। उस समय वह शुल्क रुप में वास्तविक रुप में अधिक रकम वसूल करती है, जिसे मुद्रा-टङ्कण लाभ (seigniorage) कहते हैं। मुद्रा टङ्कण लाभ दो प्रकार से लिया जाता है—एक तो उतनी कीमत की धातु सिक्के में निकाल कर अन्य धातु की मिलावट करके, तथा सिक्का बनाने समय ही यह लाभ वसूल करके। इस प्रकार का टङ्कण लाभ सांकेतिक अथवा प्रतीक मुद्रा में सबसे अधिक होता है। उदाहरणार्थ, १९४३ के पूर्व रुपये में १६५ ग्रेन चांदी तथा १५ ग्रेन अन्य धातु थी, उसमें चांदी का मूल्य केवल ६ आने २½ पाई था किन्तु रुपये का बाहरी मूल्य १६ आने होने से उस पर सरकार ६ आने ६½ पाई प्रति रुपया टङ्कण लाभ लेती थी।

**प्रतिबन्धित टङ्कण (Restricted Coinage)** में सिक्के ढालने का एकाधिकार केवल सरकार तक ही सीमित रहता है, अन्य कोई व्यक्ति टङ्कशाला में धातु लेकर मिक्का में परिवर्तित नहीं करा सकता, अर्थात् जनता के लिए टङ्कशाला खुली नहीं रहती।

**विधिप्राप्तता**—जिन सिक्कों को कानून के द्वारा स्वीकार करने के लिए सरकार बाध्य करती है उन्हें विधिप्राप्त कहते हैं। यह विधिप्राप्तता यदि असीमित मात्रा में हो तो उसे असीमित विधिप्राप्त तथा सीमित मात्रा में हो

<sup>1</sup> Jevons

तो उसे सीमित विधिग्राह्य कहते हैं। ऐसे सिक्को को जनता चाहे या न चाहे उसे उन्हे स्वीकार करना ही पड़ेगा।

**अवक्षयण (Debasement)**—जब कानून में हेर-फेर किए बिना किसी भी सिक्के की प्रमाणित धातु को अधिकृत रूप से कम किया जाता है तब उसे अवक्षयण कहते हैं। उदाहरणार्थ, कानून के अनुसार रुपये में १६५ ग्रेन चांदी तथा १५ ग्रेन अन्य धातु होनी चाहिए, परन्तु जब विधान में बिना किसी परिवर्तन के चांदी का अंश १६५ ग्रेन से १५५ ग्रेन तथा अन्य धातु का अंश १५ ग्रेन से २५ ग्रेन कर दिया जाता है तब उसे हम अवक्षयण कहेंगे।

इसी प्रकार यदि कानून द्वारा निश्चित धातु का सिक्का चलन में हो और उसके बाहरी मूल्य को पहले की अपेक्षा बढ़ा दिया जाए तो भी उसे अवक्षयण कहते हैं। उदाहरणार्थ, रुपये के चांदी के भाग में किसी प्रकार की कमी न करते हुए यदि उसका मूल्य १०० नये पैसे में १२० नये पैसे घोषित किया जाए तो वह भी अवक्षयण होगा।

**अवमूल्यन (Devaluation)**—अवमूल्यन किसी भी समय मुद्रा के विदेशी विनिमय मूल्य में कमी करने की क्रिया को कहते हैं। उदाहरणार्थ, रुपये की क्रयशक्ति का अर्थ हम दो प्रकार से लेते हैं—एक तो वह देश में कितनी वस्तुएँ अथवा सेवाएँ खरीदता है तथा दूसरे वह देश के बाहर कितनी वस्तुएँ अथवा सेवाएँ खरीदता है। देश के बाहर अथवा विदेशों में रुपया सर्वथा न होने से हम रुपये से पहले विदेशी मुद्राएँ खरीदेंगे और फिर उन विदेशी मुद्राओं से हम उस देश की वस्तुएँ खरीद सकेंगे, अर्थात् रुपये की देश के भीतर जो क्रयशक्ति है उस क्रयशक्ति में किसी प्रकार की कमी न करते हुए जब उसका विदेशी विनिमय मूल्य कम किया जाए तब हम उसे रुपये का अवमूल्यन कहते हैं। जैसे भारतीय रुपया १८ सितम्बर १९४६ के पहिले ३०.५ सेण्ट (अमरीकी मुद्रा) अथवा ०.२६८६०१ ग्राम सोना खरीदता था उसके बदले में १८ सितम्बर से उसका मूल्य २१ सेण्ट अथवा ०.१८६६२१ ग्राम सोना कर दिया गया। रुपये की इस विदेशी क्रयशक्ति की कमी को हम अवमूल्यन कहते हैं।

### मुद्रा-टङ्कण का हेतु

अभी हमने मुद्रा-टङ्कण सम्बन्धी पारिभाषिक शब्द देखे, किन्तु मुद्रा-टङ्कण का असली कारण क्या है यह भी हमको समझ लेना चाहिए। मुद्रा-टङ्कण का अधिकार एक अधिकृत संस्था अथवा सरकार के हाथों में होने से सिक्को में एकरूपता रहती है। और ये सब सिक्के किसी एक विशिष्ट धातु, वजन

तथा चिह्नो के होने के कारण उनमें सुपरिचयता होती है। साथ ही ऐसे मिक्चो में धोमे अथवा जानगाजी की सम्भावना भी कम होती है। अतः मिक्चो में एकरूपता व सुपरिचयता लाना तथा धोमे की सम्भावना दूर करना, यही मुद्रा-टङ्कण के मूल हेतु हैं।

### सारांश

मुद्रा के दो प्रकार होते हैं—१. धातु मुद्रा, २. पत्र मुद्रा। किसी धातु की बनी मुद्रा धातु मुद्रा और किसी अधिकृत व्यक्ति अथवा सरकार द्वारा कागज पर चिह्न लगाकर व्यवहार में लाई गई मुद्रा पत्र मुद्रा होती है। धातु मुद्रा दो प्रकार की होती है—१. प्रमाणित अथवा प्रधान, २. प्रतीक अथवा गौण।

प्रमाणित मुद्रा के ४ लक्षण होते हैं—

१. आन्तरिक एवं बाहरी मूल्य में समानता; २. टंकण स्वातन्त्र्य; ३. असीमित विधिग्राह्यता; ४. मूल्यमापक एवं विनिमय माध्यम दोनों कार्य करना अर्थात् देश की प्रधान मुद्रा।

प्रतीक मुद्रा के ४ लक्षण —

१. आन्तरिक मूल्य से बाहरी मूल्य की अधिकता; २. प्रतिबधित टंकण; ३. सीमित विधिग्राह्यता, ४. हल्की अथवा कम मूल्य की धातु।

भारतीय रुपये में केवल असीमित विधिग्राह्यता होने के कारण वह कानूनन प्रधान मुद्रा होते हुए भी सर्वांग पूर्ण प्रधान मुद्रा नहीं कही जा सकती।

मुद्रा की उत्पत्ति पहले मुद्रा का सोने और चांदी के टुकड़ों के रूप में प्रयोग। अतः उन्हें तौलने और शुद्धता की जाँच करने की आवश्यकता। इस काम को दूर करने के लिए प्रतिष्ठित सर्राफों ने चिह्न अंकित करना प्रारम्भ किया। फिर भी वजन करने की आवश्यकता। अतः निश्चित वजन के टुकड़ों पर चिह्न अंकित किया जाने लगा। अब किनारे काटकर वजन कम किया जाने लगा। अतः वजन करने की आवश्यकता दूर न हुई इसलिए किनारे कटिकटीदार बनाया जाने लगा। इस प्रकार धीरे-धीरे गोल, समान वजन, निश्चित धातु मात्रा और कटिकटीदार किनारे की मुद्रा का चलन हुआ।

टंकण धातु से मुद्रा बनाने की विधि को कहते हैं। दो प्रकार का होता है—१. स्वतन्त्र; २. प्रतिबन्धित।

स्वतन्त्र जनता को अपनी धातु मुद्रा में परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता। यह भी दो प्रकार का होता है—निःशुल्क और सशुल्क।

जब मुद्रण कार्य के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता तब मुद्रण नि शुल्क होता है और शुल्क लिए जाने पर संशुल्क होता है ।

शुल्क भी दो प्रकार का होता है—१ टकरण शुल्क, २ मुद्रा-टकरण लाभ ।

प्रतिबन्धित जनता को अपनी धातु मुद्रा में परिवर्तित कराने की स्वतन्त्रता नहीं होती । मुद्रण का कार्य सरकार अपने हाथ में रखती है ।

विधिग्राह्यता जिस मुद्रा को स्वीकार करने के लिए बंधानिक बाध्यता होती है उसे विधिग्राह्य कहते हैं । जब विधिग्राह्यता एक निश्चित सीमा तक रखी जाती है उसे सीमित विधिग्राह्य कहते हैं और कोई सीमा न होने पर असीमित विधिग्राह्य कहते हैं ।

मुद्रा-टकरण का हेतु मुद्रा में सुपरिचयता लाना तथा उसे जालसाजी से दूर रखने का प्रयत्न करना ।

## अध्याय ५

### पत्र-मुद्रा

पत्र-मुद्रा क्या है ?

पत्र-मुद्रा बागज पर निम्नी सरकार अथवा अधिकृत मर्या (जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया) के विशेष चिह्नों द्वारा, माँगने पर निश्चित मर्या में प्रधान मुद्रा देने का लिखित वायदा है, जैसे १० रुपये का नोट—इसमें रिजर्व बैंक यह वायदा करती है कि उसे भुनाने पर यहाँ के १० प्रधान मित्रके अर्थात् रुपये, वह देगी। पत्र-मुद्रा का चलन मूल्यवान धातुओं की घिसावट से होने वाली हानि को बचाने के लिए तथा पत्र-मुद्रा की सुरक्षितता, सुवाह्यता आदि लाभों के कारण हुआ। इस प्रकार बचाया हुआ सोना-चाँदी अन्य देशों में वित्तियोग के काम में तथा कला-कौशल के कामों में लाया जाता है। इसके अतिरिक्त पत्र-मुद्रा सरकार को सबसे अधिक लाभप्रद है क्योंकि जब उसकी माँग में जनता का विश्वास उठ जाता है तथा ऋणपत्र नहीं खरीदे जाते उस समय पत्र-मुद्रा के प्रसार के द्वारा वह अपने खर्चें पूरे कर सकती है। वास्तव में पत्र-मुद्रा प्रतीक मुद्रा है।

पत्र-मुद्रा का उगम

पत्र-मुद्रा की कल्पना, हम जैसा सामान्यतः सोचते हैं, नई न होते हुए पुरानी ही है। प्राचीन काल में कागज का शोध न होने के कारण चमड़ा, पेड़ की छाल अथवा भोजपत्र का प्रयोग मुद्रा के रूप में इसी हेतु किया जाता था कि बहुमूल्य धातुओं की घिसावट से होने वाली हानि में बचत हो। पत्र-मुद्रा का उपयोग सर्वप्रथम चीन में ६वीं शताब्दी के लगभग होने लगा और फिर वहाँ से उनका प्रसार अन्य देशों में हुआ।<sup>१</sup> आधुनिक विश्व में पत्र-मुद्रा का उपयोग विशेष रूप से १७वीं शताब्दी में होने लगा और १८वीं शताब्दी में उसका प्रसार लगभग सभी देशों में हो गया। इसी शताब्दी में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का उपयोग भी उन देशों में होने लगा जिन देशों में परिवर्तनीय पत्र-

<sup>१</sup> Money by Kinlay, p. 329

मुद्रा का चलन था ।<sup>१</sup> भारत में पत्र मुद्रा का उपयोग सर्वप्रथम १९वीं शताब्दी में आरम्भ हुआ जबकि बैंक ऑफ बंगाल को १८०६ में पत्र मुद्रा चलाने का अधिकार मिला ।

पत्र-मुद्रा के प्रकार

### पत्र-मुद्रा सम्बन्धी तालिका

#### पत्र-मुद्रा-चलन

प्रकार	१ प्रतिनिधि	२ परिवर्तनीय	३ अपरिवर्तनीय
निधि	सम्पूर्ण धातु निधि	धातु निधि तथा प्रतीक निधि	किसी भी प्रकार का निधि नहीं
गुण दोष	१ धातु की बचत नहीं होती, अतः मितव्ययता की कमी	१ प्रतीक निधि के बराबर धातु की बचत अतः मितव्ययता	१ धातु की बचत
	२ लोच की कमी	२ लोच	२ मितव्ययता
	३ सुरक्षा एवं परिवर्तनशीलता	३ सुरक्षा एवं परिवर्तनशीलता	३ लोच
			४ चलन में अधिक होने की सम्भावना
			५ सुरक्षा एवं परिवर्तनशीलता की कमी

पत्र-मुद्रा तीन प्रकार की होती है —प्रतिनिधि, परिवर्तनीय तथा अपरिवर्तनीय ।

प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा—जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस प्रकार की पत्र-मुद्रा, कितने मूल्य का सोना चाँदी बैंक के निधि में एकत्रित है अथवा उस देश के खजाने में है, यह बताती है तथा उसका प्रतिनिधित्व करती है । उदाहरणार्थ,

१,००,००० रुपये की प्रतिनिधि मुद्रा का चलन यह बताएगा कि हमारे बैंक में, जिनमें पत्र मुद्रा को प्रसारित किया, अथवा राष्ट्रीय खजाने में १,००,००० रुपये का सोना या चांदी है। इस प्रकार की प्रतिनिधि मुद्रा के अच्छे उदाहरण हैं—अमरीकी स्वर्ण तथा रजत प्रमाणपत्र (American gold and silver certificates) जिनके बदले में उतनी ही रकम का सोना या चांदी अमरीकी खजाने में रखा जाता था। धातु मुद्रा से इनके उपयोग में भुविधा रहती है। प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा सरकार अथवा बैंक द्वारा चलाई जा सकती है।

**परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा**—यह वह मुद्रा है जिसको हम किसी भी समय प्रधान सिक्के में बदल सकते हैं अर्थात् इस प्रकार की मुद्रा में इसको चलाने वाली मस्था यह आश्वासन देती है कि उस कागजी मुद्रा के बदले में, किसी भी समय माँग पर प्रधान मुद्रा दे दी जाएगी। इस आश्वासन के कारण ही ऐसी मुद्रा में जनता का विश्वास होता है तथा वह उस देश में सर्वप्राप्य होती है।

उदाहरणार्थ भारत में ५), १०) एवं १००) का नोट, जिस पर विधि-प्राप्त प्रमाणित मुद्रा देने का आश्वासन I promise to pay the bearer on demand a sum of Rupees इन शब्दों में रिजर्व बैंक द्वारा दिया जाता है। यदि देश की पत्र-मुद्रा विधिप्राप्त मुद्रा में परिवर्तनशील न होते हुए अन्य किसी चीज में, जैसे गेहूँ, चावल, जमीन आदि में परिवर्तनशील है तो उस पत्र-मुद्रा को परिवर्तनीय पत्र मुद्रा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि मुद्रा शास्त्र में 'परिवर्तनीय' शब्द का अर्थ केवल विधिप्राप्त प्रधान मुद्रा की परिवर्तनशीलता तक ही सीमित है।<sup>१</sup> इस प्रकार की पत्र-मुद्रा बैंक अथवा सरकार द्वारा चलाई जाती है।

ऐसी पत्र मुद्रा चलन के परिवर्तन के लिए उसके वास्तविक मूल्य के बराबर धातु नहीं रखी जाती बल्कि वह कम होती है। वास्तव में इस प्रकार की पत्र मुद्रा में निधि (reserve) तो उसके बाहरी मूल्य के बराबर ही रखा जाता है, किन्तु कुछ धातु में रखा जाता है तथा शेष किसी प्रकार के विनियोगों (securities) में। जो निधि धातु में रखी जाती है उसे धातु-निधि (metallic reserve) अथवा रक्षित भाग तथा जो विनियोगों में रखी जाती है उसे प्रतीक

<sup>1</sup> The word 'Convertible' is restricted in Monetary Science to redeemability in legal tender standard money, and in that alone.—*Money* by Kunlay, p 331

निधि अथवा अरक्षित भाग (uncovered portion or fiduciary portion) कहते हैं। उदाहरणार्थ, किसी देश में १०० रुपये मूल्य की पत्र मुद्रा चलन में है। उसके लिए बैंक ने ३० रुपये का सोना निधि में रखा है तथा ७० रुपये के विनियोग-पत्र (securities) हैं, तो ३० रुपये वाले भाग को धातु निधि तथा ७० रुपये वाले भाग को प्रतीक निधि कहेंगे। धातु निधि की मात्रा प्रत्येक देश की जनता की आदत पर निर्भर रहती है। यदि पत्र-मुद्रा का परिवर्तन अधिक माना में किया जाता है तब धातु निधि अधिक अनुपात में रखना पड़ेगा।

अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा—इस प्रकार की पत्र-मुद्रा के बदले में किसी प्रकार के सिक्के अथवा धातु देने के लिए सरकार कानूनन बाध्य नहीं होती। इसका चलन केवल सरकार की भाख में जनता का विश्वास होने के कारण अथवा सरकारी फर्मान के द्वारा होता है। इस प्रकार का चलन तभी होता है जब सरकार को पत्र मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है, जैसे युद्धकाल में। इस प्रकार की पत्र-मुद्रा का उदाहरण भारतीय १ रु० की पत्र मुद्रा है। जनता का विश्वास कायम रखने के लिए यह आवश्यक है कि चलन इस प्रकार नियन्त्रित हो जिसमें माँग में अधिक उसका चलन न हो अन्यथा उससे भयकर परिणाम होते हैं। इसका विवेचन हम आगे करेंगे। इसीलिए गाइड ने कहा है कि “यह (अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा) न तो किसी का प्रतिनिधित्व करती है, न किसी (वस्तु) पर अधिकार ही देती है।”<sup>१</sup> इस प्रकार की मुद्रा जनता की सम्मति के बिना लगाए हुए कर के रूप में अथवा जबरदस्ती लिए हुए ऋण के रूप में होने से सामान्यतः अविश्वसनीय होती है। फिर भी जनता को मुद्रा के रूप में अथवा विनिमय माध्यम के लिए दूसरी वस्तु न होने के कारण अथवा सरकारी आदेश के कारण उसको ग्रहण करना ही पड़ता है। अथवा जिस काम के लिए उन्हें मुद्रा चाहिए वह काम अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा से पूर्ण होने के कारण उन्हें भी इसके विरुद्ध किसी प्रकार का आक्षेप नहीं रहता।

### पत्र-मुद्रा से लाभ

आजकल सामान्यतः सब देशों में परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा चलन में है क्योंकि इस दृष्टि में छोटे-छोटी की वृद्ध तथा मुद्रा की पूर्ति में लोच रहती है। इसी प्रकार धातु-मुद्रा में परिवर्तन का आश्वासन होने से सुरक्षितता तथा इसके मूल्य में स्थायित्व भी रखा जा सकता है, अतः प्रतिनिधि तथा अपरिवर्तनीय पत्र-

<sup>1</sup> Conventional Paper Money represents nothing and confers a claim to nothing.

मुद्रा से परिवर्तनीय पत्र-मुद्रा श्रेष्ठतर है। पत्र-मुद्रा से होने वाले लाभ नीचे दिए हैं :—

१. बहुमूल्य धातुओं की बचत—इसमें बहुमूल्य धातुओं—सोना-चांदी की बचत होती है क्योंकि धातु-मुद्रा के स्थान पर पा मुद्रा चलन में होने से पितावट से होने वाली हानि नहीं होती। इतना ही नहीं बल्कि इस तरह से चलन से बचाई गई धातु अन्य बनाव-कौशल के कामों में अथवा औद्योगिक विकास के कामों में लगाई जा सकती है। इसीलिए एडम स्मिथ ने पत्र-मुद्रा की तुलना हवा में उड़ने वाले रेल के डिब्बे में की है, जिसमें सामान ले जाने का काम तो होता ही है और साथ में नीचे की जमीन में सेनी भी की जा सकती है।

२. मितव्ययता—धातु-मुद्रा ढालने के लिए जो आवश्यक धन, पूंजी आदि लगते हैं उनका किसी दूसरे जन-उपयोगी उद्योगों में लगाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है तथा चलन में बचाई गई मूल्यवान् धातुओं को देश में उद्योगों की वृद्धि के लिए तथा विदेशों में आवश्यक वस्तुओं खरीदने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है अथवा उनका विदेशों में विनिर्माण कर अधिक आय कमाई जा सकती है।

३. सहनीयता—पत्र-मुद्रा वजन में हल्की होने के कारण उसका उपयोग करने में अधिक सुविधा होती है। उसी प्रकार बड़ी-बड़ी रकमों का भुगतान करने में भी अधिक सुविधा रहती है। उदाहरणार्थ, १०० रु० का नोट और १ रु० का नोट। इन दोनों के वजन में कोई अन्तर नहीं होना और इनको साथ में ले जाना भी सुगम होना है परन्तु वही १०० रु० की धातु-मुद्रा भारी होती है। दूसरे इस प्रकार की मुद्रा स्थानान्तरण के लिए सस्ती भी होती है क्योंकि डाकघरों से बीम द्वारा कम कीमत में भेजी जा सकती है जो कि निष्का में सम्भव नहीं होता। उसी प्रकार गिनती करने में भी सुगमता हानी है।

४. लेन-देन में सुगमता—यदि आगक पाग हजार रुपये के नोट हैं तो किसी को इगका जान भी नहीं हो सकता किन्तु गिरा में अथवा धातु-मुद्रा में ऐसा नहीं रहता जिससे दूसरे लोगों को ईर्ष्या होती है तथा जीवन का भी सकट रहता है।

५. निर्माण करने में कम व्यय—इसके बनाने के लिए धातु से व्यक्ति तथा एक मुद्रण-मशीन की तथा कामज की आवश्यकता होती है। अब धातु-मुद्रा की अपेक्षा इस प्रकार की मुद्रा बनाने में सुगमता एवं मितव्ययता है। इस प्रकार धन एवं पूंजी जो निष्का डलाई में लगती है उसमें बचत होकर इसका निर्माण-व्यय कम होता है।

६. लोच—इसका चलन माँग के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है जो धातु-मुद्रा चलन में सम्भव नहीं होता। कारण यह है कि मुद्रा-धातु—सोना, चाँदी—का उत्पादन सीमित होना है परन्तु इसमें ऐसा नहीं है। पत्र-मुद्रा के संकुचन तथा प्रसार की यह क्रिया शीघ्र गति से होती है क्योंकि इसको बनाने में केवल कागज की आवश्यकता होती है।

७. सरकार की लाभ—सरकार को आवश्यकता के समय कुछ निश्चित व्याज पर ऋण लेना पड़ता है परन्तु जब सरकार की माँग गिर जाती है अथवा जनता का विश्वास सरकार में उठ जाता है तब उसे जनता से रुपया उधार लेना सम्भव नहीं होता, अथवा सरकार को रुपया उधार लेने के लिए अधिक व्याज का प्रलोभन देना पड़ता है। ऐसे समय में सरकार पत्र-मुद्रा का चलन बढ़ाकर अपनी इस आवश्यकता को पूर्ति कर सकती है। अधिक व्याज की दर पर यदि सरकार ऋण लेती है तो व्याज का सन्तुलन नहीं रहता जिसके लिए सरकार को अधिक कर लगाने की आवश्यकता होती है। परन्तु ऐसे समय में सरकार अधिक कर लगाकर जनता का रोप अपने ऊपर लेने की अपेक्षा पत्र-मुद्रा चलन बढ़ाकर आय व्यय बजट का सन्तुलन कर सकती है। इस प्रकार पत्र-मुद्रा चलन से सरकार को भी लाभ होते हैं, किन्तु देश एवं जनहित की दृष्टि से सरकार को पत्र-मुद्रा पर नियन्त्रण रखना आवश्यक है जिससे उसके चलनाधिक्य से होने वाली हानि न हो।

### पत्र-मुद्रा के दोष

प्रत्येक वस्तु में यदि गुण है तो दोष भी है। यह तो हम बता चुके हैं कि इसका मूल्य सरकार की अथवा जो अधिकोप इससे चलाता है उसकी साख पर निर्भर रहता है। इसका मूल्य कानून से निश्चित किया जाता है एवं सर्वमान्य होता है। अतः राष्ट्रीय संकट काल में इसमें जनता का अविश्वास हो जाता है तथा कीमतें भी बढ़ने लगती हैं। सरकार भी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए माँग की चिन्ता न करते हुए नोटों का चलन बढ़ाती जाती है जिसमें मुनाफाखोरी की बगल पड़ती है तथा व्यापारीवर्ग में अनैतिकता का बोलबाला होता है। इसके मुख्य दोष निम्नलिखित हैं —

१. पत्र-मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा है—जिस देश की सरकार इसको प्रचलित करती है उसी देश की सीमा में इसका चलन होता है। विदेशी इसको भुगतान में स्वीकार नहीं करते, वे केवल मूल्यवान् धातु-मुद्रा ही स्वीकार करते हैं। अतः यह अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा न है और न हो ही सकती है।

२ धातु-मुद्रा की अपेक्षा पत्र-मुद्रा में मूल्य स्थिरता की कमी है—पत्र-मुद्रा का चलन सरकारी नीति पर निर्भर होता है तथा अधिक प्रसार होने से इसके मूल्य कम होत हैं एवं वस्तुएँ महँगी होती हैं, जिससे सामाजिक तथा आर्थिक हानि होती है। इस प्रकार की सम्भावना धातु मुद्रा में नहीं होती क्योंकि मुद्रा धातुओं का उत्पादन सीमित है। अतः मुद्रा प्रसार की सम्भावना के कारण इसके मूल्य स्थाई नहीं रहते अपितु बदलत रहने हैं।

३ पत्र-मुद्रा शीघ्र नष्टवान हैं—तेज या पानी से भीग जाने पर नोट पुरान हो जात हैं, उनके ऊपर का धङ्क (note number) मिट जाता है जिससे उनका मूल्य कागज के टुकड़े से अधिक नहीं रहता अर्थात् नष्ट के बराबर हो जाता है।

४ चलनाधिक्य का भय—पत्र मुद्रा में चलनाधिक्य का भय सदैव बना रहता है। पत्र मुद्रा के चलन में यह आवश्यक नहीं होता कि पूरा चलन के बराबर धातु कोष में रखा जाए। इसलिए सरकार अथवा नोट चलाने वाली संस्था कठिनाई के समय पत्र मुद्रा का चलन बढ़ा सकती है जिसमें कीमतें बढ़ जाती हैं और देश की जनता को हानि उठानी पड़ती है और कभी-कभी तो यह चलन इतना अधिक हो जाता है कि उसका मूल्य नहीं के बराबर हो जाता है और जनता उसे लेने से इनकार कर देती है।

५ पत्र मुद्रा—वास्तविक मुद्रा न होते हुए इसका मूल्य केवल सरकार की अथवा पत्र मुद्रा चलाने वाली संस्था की शक्ति के ऊपर निर्भर रहता है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा चलन से होने वाली हानियाँ

अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा चलन में सदैव आवश्यकता से अधिक प्रसार होने की सम्भावना रहती है विशेषतः संकट-काल तथा युद्ध-काल में। अधिक प्रसार के कारण पत्र मुद्रा का मूल्य वस्तुओं के रूप में गिर जाता है अर्थात् उसी रकम से कम वस्तुएँ खरीदी जाती हैं तथा मुद्रा स्थिति (inflation) के लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं जिस में धातु मुद्रा का—और पत्र मुद्रा से स्थिति में अच्छी होती है—मंचय करने का प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करता है। इस प्रकार मंचित की हुई धातु मुद्रा या तो भूमिगत होती है या गन्वाई जाती है या विदेशी सनदारों के भुगतान के लिए उपयोग में नई जाती है। वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाने में रपायी आय वाले लोगों को सनदारों को तथा उपभोक्ताओं का हानि होती है। इसी प्रकार विदेशी व्यापार में भी बाधा आती है। वस्तुओं की कीमतें बढ़ने में आयात अधिक हाता है और निर्यात कम होता है। किन्तु यह

तभी होता है जब ऐसी अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा उससे विचलित हुई धातु-मुद्रा से अधिक परिमाण में चलन में आती है।

अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा के चलनाधिक्य के लक्षण

१ धातु-मुद्रा का विचलन (Displacement or Disappearance of Standard Metallic Money)—इस मुद्रा का माँग से अधिक प्रसार होते ही वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं। अर्थात् पत्र मुद्रा का मूल्य धातु मुद्रा के मूल्य से कम हो जाता है। कारण यह है कि जनता का विश्वास पत्र मुद्रा से उठ जाता है। इसलिए, जैसा कि ऊपर बताया गया है, धातु-मुद्रा का संचय होने लगता है और धातु मुद्रा का विचलन होकर केवल पत्र मुद्रा ही चलन में रहती है।

२ स्वर्ण पर प्रव्याजि (Premium on Gold)—धातु-मुद्रा और पत्र-मुद्रा के मूल्यों में अन्तर पड़ते ही समाज पत्र-मुद्रा के बदले में धातु मुद्रा लेना चाहता है, इस कारण तुलनात्मक दृष्टि से धातु मुद्रा का मूल्य पत्र मुद्रा से बढ़ जाता है। उदाहरणार्थ, १०० रु० के नोट के बदले में केवल ९० चाँदी के रुपये दिए जाना (इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे देश में द्वितीय महायुद्ध का है)। इसका अर्थ यह है कि धातु मुद्रा अर्थात् स्वर्ण पर प्रव्याजि देनी पड़ती है, और जो लोग विदेशों में भेजने के लिए सोना चाहते हैं उनको १०० रु० के सोने के बदले में १०० रु० से कुछ अधिक रुपये के नोट देने पड़ते हैं, क्योंकि विदेशियों का भुगतान स्वर्ण में ही करना पड़ता है।

३ विनिमय-दर में वृद्धि (Rise in the Rate of Foreign Exchange)—जब स्वर्ण पर प्रव्याजि लगने लगती है तब विदेशी विनिमय की दर में भी वृद्धि होती है। जिस दर पर विदेशी वृण्डियाँ विकती हैं, उसे विनिमय की दर कहते हैं। इन वृण्डियों का भुगतान धातु मुद्रा में करना पड़ता है—अर्थात् आम तौर से सोने में। इसका स्पष्ट अर्थ है कि स्वर्ण पर प्रव्याजि लगते ही विदेशी विनिमय दर में वृद्धि होती है, जिससे आयात करने वाले व्यापारी को कम लाभ होता है और निर्यात में जाने वाला लाभ कम हो जाता है। परिणामस्वरूप विदेशी व्यापार विस्थापित हो जाता है और आयात की हुई वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है।

४ कीमतों में वृद्धि (Rise in Prices)—विनिमय दर में वृद्धि होने से आयात वस्तुओं के मूल्य में तो वृद्धि होती ही है किन्तु अन्य वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि होती है जैसा कि हम ऊपर (१) में स्पष्ट कर चुके हैं।

किन्तु यह तभी होता है जब मुद्रा-प्रकार विस्थापित धातु-मुद्रा के परिमाण से अधिक परिमाण में हो।

५. पत्र-मुद्रा के मूल्य में कमी (Depreciation of Paper Money)—धातु-मुद्रा के विचलन के साथ ही पत्र-मुद्रा के मूल्य में कमी आती है। जैसे-जैसे अधिक-अधिक माना में धातु मुद्राओं का विचलन होता है, पत्र-मुद्रा का मूल्य गिरता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब जनता अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा को लेने में इनकार कर देती है। इस प्रकार देश में पत्र-मुद्रा के मूल्य की गिरावट-में समाज उसे लेने में भी इनकार कर देता है।

पत्र-मुद्रा कोन संचालित करे ?

पत्र-मुद्रा का संचालन बैंक के द्वारा किया जाय या सरकार के द्वारा ? यह प्रश्न प्रारम्भ में ही विवादग्रस्त रहा है, तथा इसका संचालन देश में केवल एक ही बैंक करे अथवा अनेक बैंक करें, यह भी एक समस्या है। यहाँ पर हम पत्र-मुद्रा-संचालन सरकार के अधिकार में हो अथवा बैंकों के, इसका विवेचन करेंगे। इन दोनों पक्षों में बड़ा वाद-विवाद होता रहा है। एक वर्ग सरकार की ओर से पत्र-मुद्रा के संचालन का समर्थन है तथा दूसरा वर्ग बैंकों के द्वारा संचालन हो, इस मत का समर्थन है।

सरकारी संचालन के पक्ष में तर्क

जो वर्ग सरकारी नोट के संचालन का समर्थन करता है उसका कहना है कि—

(१) सरकारी पत्र-मुद्रा के चलन में अधिक सुरक्षितता होती है, क्योंकि उनकी परिवर्तनशीलता तथा जनता का विश्वास कायम रखने के लिए देश की सब सम्पत्ति निधि के रूप में रहती है।

(२) सरकार पत्र-मुद्रा का चलन अधिक परिमाण में नहीं करेगी क्योंकि परिवर्तनशीलता रखने के लिए उसका प्रत्येक कार्य बहुत सोच विचार के बाद ही किया जाएगा।

(३) पत्र-मुद्रा चलन से होने वाला लाभ सरकारी खजाने में रहेगा जिसका उपयोग सामाजिक हितों में ही होगा, जो हिस्सेदारों के बैंक से सम्भव नहीं है।

(४) चूंकि देश के लेन-देन एवं मुद्रा की व्यवस्था प्राचीन काल से ही सरकार करती आई है इसलिए पत्र-मुद्रा-संचालन का अधिकार भी उसी को होना चाहिए।

सरकारी सञ्चालन के विपक्ष में तर्क

(१) इसके विपरीत दूसरे वर्ग का कथन है कि पत्र मुद्रा-संचालन यदि सरकार के हाथ में रहे तो उमम लाभ नहीं रहेगा क्योंकि सरकारी कार्य ढिलाई से और बहुत सोच विचार के उपरान्त किया जाता है। अतः मुद्रा की आर्थिक आवश्यकता होने ही उसकी पूर्ति नहीं हो सकती।

(२) सरकार की भी अपनी आर्थिक आवश्यकताएँ होती हैं, अतः ऐसे समय में सरकार जनहित का ध्यान न रखते हुए एक अधिक मुद्रा की माँग न होती हुए भी, पत्र-मुद्रा प्रसार कर दगी जिससे व्यापारी वर्ग एवं देश के हितों को हानि पहुँचेगी।

(३) सरकार का देश के व्यापारी वर्ग से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं रहता। अतः किसी समय मुद्रा की कितनी आवश्यकता है यह वह ठीक प्रकार से नहीं जान सकती। इसका समुचित ज्ञान तो केवल बैंकों को ही होता है। अब रहा केवल पत्र मुद्रा चलन में होने वाले लाभ का प्रश्न, तो इसके लिए यह उपाय है कि कुछ निश्चित मात्रा में लाभार्थ वितरण के बाद जो लाभ शेष रहे वह सरकारी खजाने में जाना चाहिए।

अतः इन दोषों को देखते हुए पत्र मुद्रा-संचालन का काम बैंकों द्वारा ही होना चाहिए जिसमें पत्र मुद्रा में लोच रहे। अर्थात् उसका प्रसार एवं संचालन माँग के अनुसार रहे जो केवल बैंक ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त बैंकों का साख मुद्रा के ऊपर नियन्त्रण होने से वे पत्र मुद्रा का प्रसार एवं सकोच आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं, जो सरकार के लिए सम्भव नहीं होता। बैंक का व्यापारी वर्ग से दैनिक सम्बन्ध रहता है तथा नकद रकम के लेन-देन से वह मुद्रा की आवश्यकता का ठीक अन्दाज लगा सकता है। जहाँ तक सुरक्षा एवं परिवर्तनशीलता का प्रश्न है, इसके लिए सरकार बैंक को पत्र-मुद्रा-चलन का कुछ भाग सोना या चाँदी में रखने को कानून द्वारा बाध्य करे। इस प्रकार यदि पत्र मुद्रा का संचालन बैंक द्वारा होगा तो उमम सुरक्षा, परिवर्तनशीलता, लोच तथा एकरूपता रहेगी। इसके अतिरिक्त बैंक की सरकार की तरह निजी आर्थिक आवश्यकताएँ न होने में पत्र मुद्रा प्रसार की सम्भावना भी न रहेगी।

एक अथवा अनेक बैंकों द्वारा पत्र-मुद्रा-संचालन—अब यह प्रश्न उठता है कि पत्र मुद्रा का प्रसार एवं संचालन एक बैंक द्वारा हो अथवा अनेक बैंकों द्वारा। ब्रिटन के इतिहास में अथवा भारत के इतिहास में (जब प्रेसीडेन्सी

बैंको द्वारा पत्र-मुद्रा-संचालन होना था) स्पष्ट है कि उसमें अनेक दोष थे। पहिले तो भिन्न भिन्न बैंको द्वारा संचालित मुद्राएँ भिन्न-भिन्न प्रकार की थी जिनमें समानता न होने से गरी या खोटी मुद्रा पहिचानी जा सकती थी। दूसरे, जिस बैंक की मुद्रा ज्यादा माँगी जाती है उस सम्बन्ध में बैंक में प्रतिस्पर्धा होती है जो जनहित की दृष्टि में हानिकारक है। तीसरे, पत्र-चलन निधि प्रत्येक बैंक को अपने पास रखनी पड़ती है जिनमें निधि के लिए अधिक मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है अर्थात् इसमें मितव्ययता नहीं होती और न इसका राष्ट्रीय मकद बाल में सीधे एकत्रीकरण हो सकना है। चौथे, भिन्न-भिन्न बैंको द्वारा मुद्रा संचालन के नियन्त्रण एवं निरीक्षण में भी सुगमता नहीं आती क्योंकि भिन्न भिन्न बैंको की भिन्न-भिन्न संचालन नीति होती है।

अतः इन सब त्रुटियाँ को दूर करने की दृष्टि से पत्र-मुद्रा-संचालन का अधिकार देन के केन्द्रीय बैंक को होना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित लाभ होते हैं—(१) पत्र-मुद्रा-संचालन में सुगमता, (२) पत्र-मुद्रा में एकदृष्टता रहती है जिसमें जालसाजी का भय न रहने हुए गरी या खोटी मुद्रा पहिचानी जा सकती है, (३) पत्र-मुद्रा-चलन का एकाधिकार केन्द्रीय बैंक को प्राप्त होने के कारण वह लाभ प्रेरित नहीं होती, (४) पत्र-चलन निधि एक ही स्थान पर रहने के कारण उसमें मितव्ययता रहती है तथा यह मकद बाल में उपयोगी हो सकती है, (५) पत्र-चलन की नीति एक ही बैंक के अधिकार में होने के कारण उसका नियन्त्रण एवं परीक्षण भी सुगम होता है। ऐसे पत्र-मुद्रा-चलन को सरकार की मान्यता भी प्राप्त होती है जिनमें जनता का विश्वास प्रदिग्ग रहता है। इन सब बातों को दखते हुए केन्द्रीय बैंक को ही पत्र-मुद्रा-संचालन का एकाधिकार मिलना चाहिए।

### पत्र-मुद्रा-चलन के सिद्धान्त

पत्र-मुद्रा-चलन की दो प्रणालियाँ दो सिद्धान्तों के अनुसार हैं। ये सिद्धान्त विभिन्न देशों द्वारा प्रकट किए गए हैं—पहिला चलित-मुद्रा सिद्धान्त (currency principle) तथा दूसरा बैंकिंग सिद्धान्त (banking principle)।

चलित-मुद्रा सिद्धान्त के समर्थक का कथन है कि पत्र-मुद्रा-चलन को पूर्णतः सुरक्षित करने के लिए पत्र-मुद्रा-चलन के मूल्य के बराबर ही धातु निधि रखी जानी चाहिए। इस प्रकार पत्र-मुद्रा-चलन का प्रसार एवं मकोच धातु निधि की कमी अथवा अधिकता पर निर्भर रहना चाहिए क्योंकि पत्र-मुद्रा-चलन का मूल हेतु धातु-मुद्रा को विचलित करके मूल्यवान् धातुओं की

घिसावट की वृत्त करने का है। इस तत्व के अनुसार मुद्रा-चलन में लोच नहीं रहती अर्थात् पत्र-मुद्रा चलन व्यापारिक आवश्यकतानुसार घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता बल्कि उसका प्रसार या संकोच धातु निधि की कमी या अधिकता पर निर्भर रहेगा। दूसरे, इस पद्धति में सोने या चाँदी की वृत्त नहीं हो सकती है, किन्तु चलनाधिक्य से सुरक्षा तथा परिवर्तनशीलता रहती है। सारांश, इसमें मितव्ययिता तथा लोच का अभाव, ये दोष एवं चलनाधिक्य से सुरक्षा तथा परिवर्तनशीलता, ये गुण हैं।

बैंकिंग सिद्धान्त के समर्थकों का कथन है कि विनिमय-माध्यम का कार्य अच्छे प्रकार में होने के लिए मुद्रा का आवश्यकतानुसार प्रसार तथा संकोच होना आवश्यक है, अर्थात् चलन में लोच होना चाहिए। अतः इस लोच के लिए आवश्यक है कि बैंक, मुद्रा का कितना चलन रहे इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र हो। किन्तु ऐसी परिस्थिति में पत्र-मुद्रा में परिवर्तनशीलता तथा सुव्यवस्थितता एवं सुरक्षा के हेतु बैंकिंग पद्धति का अवलम्बन भी होना आवश्यक है क्योंकि लोच रखने का कार्य जनता तथा व्यापारी वर्ग के सम्पर्क में रहने के कारण बैंक ही अच्छी तरह कर सकता है। इस प्रणाली में चलनाधिक्य का भय नहीं रहता तथा धातु मुद्रा के सब गुण इसमें रहते हैं एवं इसके उपयोग में वहीनियता, सुगमता और बनाने में सस्तापन रहता है।

इन दोनों प्रणालियों में गुण दोष तो हैं ही क्योंकि चक्षित-मुद्रा-तत्व प्रणाली में लोच का अभाव रहता है तो दूसरी प्रणाली में सुरक्षा कम होती है एवं चलनाधिक्य का भय रहता है। अतः पत्र-मुद्रा-चलन की अच्छी पद्धति वही है जिसमें इन दोनों का संगम हो, जिसमें सुरक्षा तथा परिवर्तनशीलता के साथ पत्र-चलन में लोच हो। अतः बैंकिंग तत्व प्रणाली में धातु निधि अथवा अन्य साधनों का नियोजन करके सुरक्षा का गुण लाया जा सकता है।

अब हम पत्र-मुद्रा-चलन की विभिन्न पद्धतियाँ कौन-कौनसी हैं तथा उनके सुव्यवस्था कैसे लाई जाती है, यह देखेंगे।

**पत्र-मुद्रा नियमन (Regulation) की पद्धति**

पत्र-मुद्रा-चलन की विधियों का अध्ययन करने के पूर्व पत्र-मुद्रा-चलन में कौनसी विशेषताएँ अथवा कौनसे तत्व होने चाहिए यह हम देखेंगे। पत्र-मुद्रा-चलन प्रणाली वही अच्छी समझी जाती है जिसमें नीचे दिये हुए गुण होते हैं —

१. लोच (elasticity), २. मितव्ययता (economy), ३. परिवर्तन-

शीलता (convertability), तथा ३ अधिक चलनाधिक्य से बचाव अथवा सुरक्षा (security against over-issue) ।

किसी भी देश की मुद्रा में लोच होना आवश्यक है जिससे वह माँग के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सके। पत्र-मुद्रा का मुख्य हेतु मूल्यवान् मुद्रा-धातु सोना चाँदी की वचत करके उसे अन्य उपयोग में लाना है। इसलिए पत्र-मुद्रा-चलन वही प्रवृत्ति है जिसमें कम से कम माना में सोने या चाँदी की आवश्यकता पड़े। अतः उसमें मितव्ययिता (economy) का गुण होना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि पत्र-मुद्रा परिवर्तनीय न हो क्योंकि यदि माँग पर उसके बढ़ने में धातु-मुद्रा या सोना चाँदी नहीं दिया जाता तो उसमें जनता विश्वास खो बैठती है, इसलिए पत्र-मुद्रा-चलन में परिवर्तनीयता भी होनी चाहिए। अतः इस परिवर्तनीयता को रखने के लिए पत्र-मुद्रा मन्त्रालय को कुछ न कुछ सोना या चाँदी अपने निधि में रखना पड़ना है जिस पर सरकारी नियन्त्रण एवं निरीक्षण रहता है। पत्र-मुद्रा-चलन का दाप उसके चलनाधिक्य में है, यह हम ऊपर बता चुके हैं। इस चलनाधिक्य में समाज की तथा व्यापारी वर्ग की अनेक हानियाँ होती हैं अतः समता की दृष्टि से इसमें बचन के उपाय भी होने चाहिए।

इस चलनाधिक्य से बचने के लिए तथा पत्र-मुद्रा की परिवर्तनीयता कायम रखने के लिए सरकार धातु निधि को कानून द्वारा नियन्त्रित करती है अथवा पत्र-मुद्रा-चलन का अधिकतम आँकड़ा निश्चित कर देती है, जिससे अधिक पत्र-मुद्रा का चलन नहीं बढ़ाया जा सकता। परन्तु ऐसी दशा में सरकार बैंक को सफ्टकाल में अनिश्चित पत्र-मुद्रा चलाने का अधिकार दे देती है। ऐसी मकटकालीन पत्र-मुद्रा (emergency currency) केवल व्यापारिक विपत्तियों के आधार पर चलाई जानी है। इस प्रकार का अधिकार भारत में इम्पीरियल बैंक को था जब वह अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए १२ करोड़ रुपये का पत्र-चलन कर सकता था। ये आँकड़े कानूनी तथा परिस्थिति के अनुसार बढ़ने जाते हैं। पत्र-मुद्रा चलन निधि रखने की भी विभिन्न पद्धतियाँ हैं।

**पत्र-चलन की विभिन्न विधियाँ**

१. निश्चित अधिकतम पत्र-चलन पद्धति (Fixed Maximum Note Issue) — इस पद्धति में कानून से पत्र-मुद्रा की अधिकतम मात्रा निश्चित कर दी जाती है जिसमें अधिक पत्र-मुद्रा का चलन नहीं हो सकता। इसमें धातु निधि

(metallic reserve) का पत्र-मुद्रा-चलन से कोई सम्बन्ध नहीं होता। धातु निधि को बढ़ा भी दिया जाए फिर भी निश्चित मात्रा से अधिक पत्र-मुद्रा का चलन वानून से नहीं किया जा सकता, जब तक परिवर्तन न हो। सामान्यतः यह पत्र-चलन की अधिकतम समस्या का आँकड़ा अवश्य पत्र-मुद्रा की सख्या से अधिक ही निश्चित किया जाता है। यह अधिकतम आँकड़ा समय-समय पर देश की व्यापारिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार बदला जाता है। इस प्रकार पत्र-मुद्रा-चलन पद्धति इङ्ग्लैण्ड में १९३६ में थी। इस पद्धति में पत्र-मुद्रा-चलन में लोच नहीं रहती क्योंकि अधिकतम मात्रा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल नहीं बढ़ाई जा सकती। दूसरे, यह अधिकतम मात्रा किसी भी समय विधान परिषद् द्वारा बढ़ाई जा सकने के कारण मुद्रा-प्रसार की अधिकता की सम्भावना घनी रहती है, जिससे मुद्रा-स्फीति का भय बना रहता है। इसमें एक लाभ यह अवश्य है कि अधिकोप अथवा मचावक आवश्यकता के समय पत्र-मुद्रा निधि का उपयोग करने में स्वतन्त्र रहता है, जिससे किसी भी समय मुद्रा-स्फीति को रोकने के लिए इस निधि का उपयोग किया जा सकता है। पत्र-मुद्रा के वानूनी नियन्त्रण के लिए यह पद्धति सबसे अच्छी मानी गई है।<sup>१</sup>

## २. साधारण निधि पद्धति (Simple Deposit Method)—

इसमें पत्र-मुद्रा-चलन के मुख्य के बराबर सोने या चाँदी से धातु निधि रखना आवश्यक है अर्थात् इस प्रकार की पत्र-मुद्रा प्रतिनिधि होती है। इस पद्धति में लोच तथा मितव्ययता का अभाव रहता है। इसमें सुरक्षा तथा परिवर्तन-शीलता, ये लाभ भी हैं, किन्तु यह पद्धति कहीं भी उपयोग में नहीं है।

## ३. न्यूनतम निधि पद्धति (Minimum Reserve Method)—

इस पद्धति में निधि में कितना सोना या चाँदी कम से कम होना चाहिए यह विधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। इससे कम निधि नहीं हो सकती, चाहे पत्र-मुद्रा कितनी ही मात्रा में चलन में क्यों न रहे। इस पद्धति में लोच, मितव्ययता तथा परिवर्तनशीलता, ये गुण हैं। इस पद्धति में सबसे बड़ा खतरा यह है कि यदि जनता को जरा भी सन्देह हो जाए कि अब पत्र-मुद्रा का परिवर्तन नहीं हो सकता तो पत्र-मुद्रा के परिवर्तन की माँग बढ़ जाएगी जिसे वेन पूर्ण न कर सकेगा। फलतः निधि रखने का जो हेतु है वह हेतु सफल नहीं होगा।

अतः व्यावहारिक दृष्टि से यह पद्धति उपयोगी नहीं है।<sup>१</sup> भारत में १९५८ से यह पद्धति चालू की गई है।

४. निश्चित प्रतीक पत्र-मुद्रा-चलन पद्धति (Fixed Fiduciary Note-issue)—इस पद्धति के अनुसार धातु निधि न रखते हुए एक निश्चित मात्रा में पत्र-मुद्रा का चलन हो सकता है परन्तु उसमें अग्रिम चलन होने पर धराचरो में मोना या चाँदी धातु निधि में रखना अनिवार्य है। इसका अद्यतन इङ्ग्लैण्ड में बैंक चार्टर एक्ट १८८४ के अनुसार हुआ था। उस समय प्रतीक पत्र-मुद्रा की अधिकतम मर्यादा १८ मिलियन पाउंड थी। १९३६ के पहिले यह अधिकतम मर्यादा २७५ मिलियन पाउंड थी जो १९३६ के फरेसी एवं बैंक नोट एक्ट द्वारा ६३० मिलियन पाउंड कर दी गई तथा क्रमशः बढ़ते-बढ़ते यह आँकड़ा २३ अगस्त १९४४ में १२०० मिलियन पाउंड हो गया था। इङ्ग्लैण्ड में यह आँकड़ा सन् १९२८ में २६० मिलियन पाउंड था। इसका मतलब यह नहीं कि धातु निधि इस पद्धति में नहीं रखी जानी किन्तु धातु निधि जितने मूल्य की होनी है उतना पत्र-मुद्रा-प्रसार तो बँक कर ही सकता है। मर्यादा केवल उस पत्र-मुद्रा-चलन के लिए है जो धरक्षित है अर्थात् जिसके लिए धातु निधि नहीं है। प्रतीक पत्र-मुद्रा के बदले में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड को प्रतिभूतिपत्र, विलियोग पत्र आदि निधि में रखने पड़ते हैं। इसी पत्र-मुद्रा का चलन निश्चित मर्यादा से बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि जितना मूल्य की पत्र-मुद्रा की वृद्धि चलन में हो उतना ही मूल्य में धातु निधि में वृद्धि की जानी चाहिए। इसलिए इस पद्धति में न तो मितव्ययिता हाती है और न माँच रहती है। दूसरे, सोना-चाँदी निधि में कम हा जान पर उतना मूल्य की पत्र-मुद्रा का सञ्चालन करना आवश्यक हो जाता है चाहे माँग अधिक चलन के लिए क्यों न हो। अतः इस पद्धति की कार्यप्रणाली में सुगमता का भी अभाव है। इन दोषों का निवारण तभी हो सकता है जब निधिविहीन परवा धरक्षित पत्र-मुद्रा-चलन की मर्यादा का आकड़ा बहुत अधिक हो। इस पद्धति में यह लाभ अवश्य है कि पत्र-चलन में सुरक्षितता रहती है और चलनाधिक्य का भय नहीं रहता। यह पद्धति तीसरी पद्धति से अग्रिम अच्छी लगती है क्योंकि इसमें कुछ पत्र-चलन का अग्र स्वरूप में निधि के रूप में रखना पड़ता है। इसीलिए इस पद्धति को आंशिक निधि पद्धति (partial deposit method) कहते हैं।

५. आनुपातिक निधि पद्धति (Proportional Reserve

<sup>१</sup> Money by Kinlay, p 3762.

**Method)**—इस पद्धति के अनुसार पत्र-मुद्रा-चलन तथा धातु निधि का अनुपात निश्चित कर दिया जाता है, अर्थात् पत्र-चलन का कितना प्रतिशत धातु निधि वेच म होंगी चाहिए। यह निधि सरकार की अनुमति से कम या अधिक की जा सकती है। इसको अमेरिका, इङ्गलैण्ड, भारत आदि देशों में अपनाया गया है। रोप पत्र-मुद्रा-चलन का भाग उतने ही मूल्यों के विनिमोणो (gold-edged securities or investments) द्वारा सुरक्षित किया जाता है जिसको प्रतीक अथवा अरक्षित भाग कहते हैं। इस पद्धति में लोच, मितव्ययिता तथा चलनाधिक्य से सुरक्षा एवं परिवर्तनशीलता भी रहती है। इसीलिए इस पद्धति का अवलम्बन सब देशों में है। प्रो० वीन्स के मतानुसार इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें निश्चित मूल्य का मोना-चाँदी व्यर्थ ही निधि में रखा जाता है जो पत्र-मुद्रा परिवर्तन के लिए भी विशेष आवश्यक नहीं होता।

६ **आनुपातिक न्यूनतम स्वर्ण-निधि पद्धति (Percentage Method with Minimum Gold Reserve)**—यह पद्धति उपरोक्त पाँचवी पद्धति का संशोधित रूप है जो आजकल अनेक देशों में उपयोग में है। इन पद्धति के अनुसार आनुपातिक निधि का कुछ अंश स्वर्ण तथा चाँदी में देश के भीतर रखा जाता है तथा शेष भाग दूसरे देश के साथ पत्रों में अथवा विदेशी बैंकों की दृष्टियों में रखा जाता है। स्वर्ण एवं चाँदी का जो भाग देश में रखा जाता है उसकी राशि निश्चित होती है जिसमें किसी भी समय कमी नहीं आनी चाहिए। इस पद्धति में सोने या चाँदी में बचत होती है एवं पाँचवी पद्धति के भी लाभ प्राप्त होते हैं। भारत में १९५८ तक यही पद्धति थी।

मुद्रा-बाजार पद्धति वही अच्छी होती है जिसमें लोच, मितव्ययिता, परिवर्तनशीलता तथा चलनाधिक्य से सुरक्षा हो। सबसे अच्छी पद्धति तो यह है कि देश के केन्द्रीय बैंक के हाथ में इसका चलन सौंप दिया जाए तथा चलन की कमी या अधिकता तथा धातु निधि का नियोजन वह अपनी इच्छानुसार करे। हाँ, जनता की सुरक्षा तथा परिवर्तनशीलता की दृष्टि से सरकार उस बैंक पर दो मर्यादाएँ लगादे—एक तो न्यूनतम धातु निधि कितनी रखी जाए, तथा दूसरे, अधिक से अधिक कितने मूल्य की पत्र-मुद्रा का चलन हो। इन दोनों मर्यादाओं में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किये जाएँ क्योंकि किसी भी पद्धति का अवलम्बन उस देश की जनता की प्रकृति, मोना या चाँदी की उपलब्धता तथा मुद्रा बाजार (money market) की परिस्थिति पर निर्भर रहता है।

उपर्युक्त पद्धतियों को देखने में यह स्पष्ट होता है कि पहली, दूसरी तथा

चौथी पद्धति चलित-मुद्रा तत्व पर आधारित है तथा तीसरी, पाँचवीं एवं छठी पद्धति बैकिंग तत्व पर आधारित है।

## मुद्रा का विकास

इस अध्याय में तथा पिछले अध्यायों में हमने मुद्रा का किस प्रकार विकास हुआ इसका सूक्ष्म अध्ययन किया, जिसका मारादा नीचे दिया जाता है —

१ प्रारम्भिक अवस्था में विनिमय की आवश्यकता नहीं थी, किन्तु जब आवश्यकता प्रतीत होने लगी उस समय वस्तु विनिमय से काम होने लगा।

२ तस्तु-विनिमय की कठिनाइयाँ दूर करने के लिए माध्यम का उपयोग होने लगा जिसे हम मुद्रा कह सकते हैं। अमरा निभिन्न वस्तुएँ मुद्रा के रूप में उपयोग में आईं और कुछ न कुछ कठिनाई के कारण उनका स्थान धातु अर्थात् सोने एवं चाँदी की मुद्रा ने ग्रहण किया।

३ धातु-मुद्रा-संचालन कार्य में सुरक्षितता लाने के लिए सरकार का प्रवेश हुआ तथा आगे चलकर पत्र-मुद्रा तथा बैंक-मुद्रा का आवश्यकतानुसार निर्माण एवं विकास हुआ जिससे मुद्रा में सोच आई।

४ सरकार के हस्तक्षेप के उपरान्त क्रमशः अधिकाधिक सुरक्षा लाने की दृष्टि से मुद्रा-संचालन का कार्य पूर्ण निरीक्षण एवं नियन्त्रण में होने लगा।

मुद्रा-विकास की ये चार सीढ़ियाँ (stages) हैं।

## सारांश

पत्र-मुद्रा—कागज पर किसी सरकार अथवा अधिकृत संस्था के विशेष चिह्नों द्वारा माँग पर निश्चित सत्या में प्रधान मुद्रा देने का वायदा है।

पत्र-मुद्रा का उद्गम—कागज का संशोधन होने के पहले बहुमूल्य धातु की बचत करने के हेतु पेट की छाल, चमड़े इत्यादि का मुद्रा के लिए उपयोग। सर्वप्रथम ६वीं शताब्दी के लगभग चीन में पत्र-मुद्रा का उपयोग विशेष रूप से १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में विश्व में पत्र-मुद्रा का उपयोग होने लगा। १८वीं शताब्दी में लगभग सभी देशों में प्रसार। भारत में सर्वप्रथम सन् १८०६ में पत्र-मुद्रा का उपयोग।

पत्र-मुद्रा के प्रकार—१ प्रतिनिधि; २ परिवर्तनीय; ३. अपरिवर्तनीय।

प्रतिनिधि—जो धातु-मुद्रा का प्रतिनिधित्व करे अर्थात् जितने मूल्य की पत्र-मुद्रा-चलन में हो उसके पूर्ण मूल्य के बराबर धातु निधि में रखी जाए।

परिवर्तनीय—सम्पूर्ण मूल्य के बराबर धातु निधि न रखकर कुछ मूल्य के

बराबर प्रतीक निधि रखी जाए। मांग करने पर धातु-मुद्रा में परिवर्तन किया जाता है। किन्तु परिवर्तन की मांग एक साथ न होने के कारण पूर्ण मूल्य के बराबर धातु निधि न रखने पर भी परिवर्तन सम्भव।

अपरिवर्तनीय—इस पत्र-मुद्रा के बदले प्रधान मुद्रा देने का वापदा नहीं होता। किसी प्रकार की निधि भी नहीं रखी जाती।

पत्र मुद्रा में साम—१ बहुमूल्य धातुओं की वृद्धि, २ मितव्ययिता, ३ वहनीयता, ४ लेन-देन की सुगमता, ५ निर्माण करने में कम व्यय, ६ लोच, ७ सरकार की साम।

दाय—१ राष्ट्रीय मुद्रा अतः विदेशी मुगलान में अस्वीकार्य, २ मूल्य स्थिरता का अभाव, ३ पत्र-मुद्रा के गलने, फटने, लेन में गिरने से मूल्य नाश होता है, ४ चलनाधिक्य का भय, ५ मूल्य सरकार अथवा चलनाधिकारी की साम पर निर्भर।

अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा के चलनाधिक्य के लक्षण—१ धातु-मुद्रा का विचलन, २ स्वर्ण पर प्रव्याजि, ३ विनिमय दर में वृद्धि, ४ कीमतों में वृद्धि, ५ पत्र-मुद्रा का अपमूल्यन।

पत्र-मुद्रा-मचानन कौन करे—यह प्रश्न विवादप्रस्त है। संचालक दो हो सकते हैं—१ सरकार, २ बैंक।

सरकार द्वारा मचानन के पक्ष में तर्क—१. अधिक सुरक्षितता, २. चलन उचित प्रमाण में होगा, ३ पत्र चलन से होने वाला साम सरकारी खजाने में जमा होगा जिसका उपयोग जनहित में हो सकेगा, ४ पुरातन काल से सरकार ही मुद्रा चलन करती आई है।

सरकार के विपक्ष में तर्क—१ डिलाई, २ अपनी आर्थिक आवश्यकता-नुसार मुद्रा निर्गमन, ३ सरकार का देश के व्यापारी वर्ग से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं।

चलन के सिद्धान्त—सिद्धान्त दो हैं—१ बैंकिंग सिद्धान्त, २ चलित मुद्रा सिद्धान्त।

बैंकिंग के पहिले सिद्धान्त के अनुसार धातु निधि रखने में बैंक स्वतंत्र होती हैं। दूसरे के अनुसार पत्र चलन केवल उतने ही मूल्य का हो सकता है जितनी धातु कोष में रखी जाए। इन दोनों पद्धतियों का समीप ही अच्छी पत्र चलन पद्धति के लिए आवश्यक है जिसमें उसमें परिवर्तनशीलता, सुरक्षा, मितव्ययता तथा लोच रहे।

पत्र-मुद्रा नियमन की पद्धतियाँ—ये निम्न हैं :—

१. निश्चित अधिकतम पत्र-चलन पद्धति
२. साधारण निधि पद्धति
३. न्यूनतम निधि पद्धति
४. निश्चित प्रतीक पत्र-चलन पद्धति
५. आनुपातिक निधि पद्धति
६. आनुपातिक न्यूनतम स्वरूप निधि पद्धति ।

## मुद्रा का मूल्य तथा मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त

### मुद्रा का मूल्य (Value of Money)

जिस प्रकार गेहूँ के मूल्य में हम यह समझते हैं कि गेहूँ के बदले में दूसरी वस्तु कितनी मिल सकती है, उसी प्रकार मुद्रा के मूल्य से यही तात्पर्य है कि विनिमय में हम एक मुद्रा देकर कितनी वस्तुओं पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात् मुद्रा का मूल्य उसकी क्रयशक्ति है, जो हमेशा स्थिर नहीं रहती, अपितु बदलती रहती है। उदाहरणार्थ, कभी हम १ रुपये के ४ सेर गेहूँ लेते थे किन्तु आज हम दो सेर लेते हैं अर्थात् मुद्रा की क्रयशक्ति घट गई है या मुद्रा का मूल्य कम हो गया है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जब मुद्रा का मूल्य गिरता है उस समय वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और जब मुद्रा का मूल्य बढ़ता है उस समय वस्तुओं की कीमत घटती है। मुद्रा के मूल्य की कमी अथवा बढ़ती का माप वस्तुओं की कीमतों के उतार चढ़ाव से किया जाता है और यह इसीलिए सम्भव है कि मुद्रा विनिमय माध्यम का काम करती है तथा वस्तुओं की कीमत मुद्रा में प्रवृत्त की जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मुद्रा के मूल्य तथा वस्तुओं की कीमतों का परस्पर विरोधी सम्बन्ध है।

मुद्रा के मूल्य में घट बढ़ होने का कारण क्या है, तथा किन बातों पर मुद्रा का मूल्य निर्भर रहता है, यह प्रश्न हमारे सामने आता है। मुद्रा के मूल्य में कमी अथवा बढ़ती का कारण मुद्रा की माँग तथा उसकी पूर्ति है। मुद्रा का मूल्य भी अन्य वस्तुओं की तरह उसकी माँग तथा नियम पर निर्भर रहता है। उदाहरणार्थ किसी देश में उत्पादन स्थिर रहे तथा मुद्रा का परिमाण (quantity) अधिक है तो इससे यह स्पष्ट है कि जनता के पास क्रयशक्ति अधिक है और वस्तुएँ कम जिसका परिणाम यह होगा कि उसी वस्तु का खरीदने के लिए लोग अधिक कीमत देने लगेंगे। इस दशा में मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा या वस्तुओं की कीमत चढ़ जाएंगी। ठीक इसी प्रकार यदि उत्पादन स्थिर है और मुद्रा का परिमाण घटा दिया जाता है तो मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा तथा

वस्तुओं की कीमतें घट जाएंगी। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य मुद्रा के परिमाण तथा माँग पर निर्भर रहता है। यह मुद्रा का मूल्य ठीक उम्मी अनुपात में कम या अधिक होता है जिस मात्रा में मुद्रा में वृद्धि अथवा कमी की जाए। उदाहरणार्थ, मुद्रा की संख्या एक समय १०० रुपये है तथा उस मुद्रा के द्वारा विनिमय होने वाली वस्तुओं की संख्या ५० है तो उपर्युक्त सिद्धान्त के अनुसार एक वस्तु की कीमत २ रुपये होगी। किन्तु यदि वस्तुओं का परिमाण अथवा उत्पादन स्थिर रहता है और मुद्रा का परिमाण १०० रुपये में ३०० रुपये कर दिया जाता है तो प्रत्येक वस्तु की कीमत २०० २०—५०=४ ६० होगी अर्थात् मुद्रा का मूल्य कम होगा और वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसके विपरीत यदि मुद्रा का परिमाण १०० रुपये में घटकर ५० रुपये हो जाता है तो प्रत्येक वस्तु की कीमत ५० ६०—५०=१ २० हो जाएगी अर्थात् वस्तुओं की कीमतें कम होंगी और मुद्रा का मूल्य अथवा मुद्रा की क्रयशक्ति बढ़ जाएगी। अतः यह स्पष्ट है कि मुद्रा के परिमाण में जिस अनुपात में कमी या वृद्धि की जाएगी, उसी अनुपात में मुद्रा का मूल्य अधिका अथवा कम होगा तथा वस्तुओं की कीमतें कम या अधिक होंगी। मुद्रा परिमाण का उसके मूल्य अथवा क्रयशक्ति से विरोधी सम्बन्ध है तथा वस्तुओं की कीमतों से सीधा अथवा प्रत्यक्ष सम्बन्ध है। किन्तु यह तभी होगा जब कि उत्पादन में अथवा विनिमय की वस्तुओं में किसी प्रकार की कमी या अधिकता न हो। इसी को मुद्रा परिमाण सिद्धान्त (quantity theory of money) कहते हैं।

### मुद्रा की माँग तथा पूर्ति

हमने ऊपर बताया कि मुद्रा की क्रयशक्ति भी उसकी माँग तथा पूर्ति पर निर्भर है। किन्तु यह माँग कैसी होती है तथा उसकी पूर्ति कौन एवं कैसे करता है, अब हम यह देखेंगे।

**मुद्रा की माँग**—प्रत्येक व्यक्ति का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्रयशक्ति अथवा मुद्रा की आवश्यकता होती है और किसी समाज अथवा देश में किसी एक समय में विनिमय की निश्चित मात्रा में वस्तुएँ होती हैं। अतः इन वस्तुओं के विनिमय के लिए कितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी, इस पर मुद्रा की माँग निर्भर है। अर्थात् किसी निश्चित अवधि में कितनी वस्तुएँ अथवा सेवाएँ विनिमय के लिए बाजार में उपलब्ध हैं, इस पर मुद्रा की माँग निर्भर रहेगी।

**मुद्रा की पूर्ति**—मुद्रा की पूर्ति, जो मुद्रा चलन में है उससे प्रकट होती है।

और चूँकि मुद्रा एक दिन म कई बार विनिमय में हस्तान्तरित होती है अतः मुद्रा की पूर्ति किसी समय में मुद्रा परिमाण-गति अथवा भ्रमण-गति में हम जान सकते हैं। उदाहरणार्थ, किसी समय चलन में १०० रुपये हैं तो मुद्रा-चलन १०० है। अब मान लीजिए ये रुपये प्रतिदिन १० बार हस्तान्तरित होते हैं तो १०० रुपया में प्रत्येक रुपया १० रुपये का काम करता है। (इस हस्तान्तरण की क्रिया को मुद्रा की गति अथवा भ्रमण-गति कहते हैं।) अतः १०० रुपये के द्वारा  $100 \times 10 = 1000$  रुपये के विनिमय का कार्य होता है अतः उस समय मुद्रा का कुल परिमाण १००० रुपये है अथवा मुद्रा की पूर्ति १००० है। मुद्रा की पूर्ति देश में सरकार द्वारा की जाती है तथा उसकी भ्रमण-गति पर निर्भर रहती है।

### मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त

मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त के अनुसार, स्थिर दना में अथवा अन्य बातें समान रहते हुए, मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होने से उसी अनुपात में मुद्रा के मूल्य में विरोधी तथा वस्तुओं की कीमतों में उसी अनुपात में प्रत्यक्ष अथवा सीधा परिवर्तन होता है।<sup>१</sup> इसका तात्पर्य यह है कि मुद्रा-परिमाण को यदि दुगुना कर दिया जाए तो मुद्रा की क्रयशक्ति आधी हो जाएगी तथा वस्तुओं की कीमतें दुगुनी हो जाएँगी। उसी प्रकार मुद्रा का परिमाण आधा कर दिया जाए तो मुद्रा की क्रयशक्ति दुगुनी हो जाएगी तथा वस्तुओं की कीमतें आधी हो जाएँगी। किन्तु यह तभी सम्भव है जब अन्य परिस्थिति स्थिर रहे और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो। परन्तु यह आज के परिवर्तनशील समाज में सम्भव नहीं है, अतः इस सिद्धान्त को पूर्णतः लागू करने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। इस सिद्धान्त के सरल रूप का समीकरण नीचे दिया है—

$$\text{कीमत} = \frac{\text{मुद्रा-परिमाण}}{\text{व्यापार अथवा उत्पादन}} \quad [ P = \frac{M}{T} \text{ or } PT = M ]$$

अथवा वस्तुओं की कीमते  $\times$  उत्पादन = मुद्रा-परिमाण ।

हमने ऊपर बताया है कि परिस्थिति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अतः वह कौनसी परिस्थिति है अथवा किस अवस्था में यह सिद्धान्त सत्य होगा? वह परिस्थिति निम्नलिखित है—

1 Other things being equal, with every change in the supply of money, value of money varies inversely proportionately and the price-level varies directly proportionately

१. उपयोग में केवल धातु-मुद्रा ही है, साख का उपयोग नहीं होता तथा प्रत्येक मुद्रा विनिमय के अतिरिक्त अन्य किसी काम में नहीं चाई जाती ।

२. मुद्रा केवल विनिमय के कार्य में ही उपयोग में आती है तथा उसका संचय आदि नहीं होता ।

३. मुद्रा की गति अथवा भ्रमण-गति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता ।

४. वस्तु-विनिमय प्रचार में नहीं है अथवा प्रत्यक्ष विनिमय द्वारा वस्तुएँ न खरीदी जाती हैं और न बची जाती हैं ।

५. उत्पादन-परिमाण में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता ।

६. जनता का उपयोग, जनसंख्या का परिमाण आदि जिनमें व्यापार प्रभावित होता है, इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता ।

किन्तु उपर्युक्त बात, जिन्हें हम स्थिर मानते हैं, परिवर्तनीय है तथा वास्तव में विनिमय के लिए केवल धातु-मुद्रा का ही उपयोग न होते हुए केवल द्वारा चलाई हुई पत्र मुद्रा तथा साख का भी उपयोग होता है । उसी प्रकार एक मुद्रा में एक ही विनिमय कार्य न होते हुए अनेक विनिमय कार्य होने हैं । इस अनेक विनिमय कार्य होने को हम मुद्रा की गति (*velocity of money*) अथवा मुद्रा की भ्रमण-गति कहेंगे । इस गति में भी परिवर्तन होता रहता है तथा उसी प्रकार उत्पादन भी स्थिर नहीं रहता और वस्तु-विनिमय के द्वारा विनिमय का हमेशा थोड़ा-बहुत अय-विक्रय होता है । अतः इन सब चीजों के लिए छूट देना आवश्यक है जिसमें कि हम सिद्धान्त की सत्यता आज की परिस्थिति में भी प्रमाणित हो सके । इसलिए हमको वस्तुओं के विनिमय का वेग, धातु-मुद्रा की भ्रमण-गति, साख-पत्रों का उपयोग एवम् भ्रमण-गति तथा वस्तु-विनिमय, इनके लिए छूट देनी पड़ेगी । अतः इस अवस्था में हम सिद्धान्त को हम निम्नलिखित परिभाषा में व्यक्त करेंगे — वस्तुओं की कीमतों का स्तर मुद्रा परिमाण एवम् गति के समान अनुपात में तथा विनिमय-माध्य वस्तुओं के विरुद्ध अनुपात में बदलता है, अथवा मुद्रा के परिमाण एवम् भ्रमण-गति के साथ कीमतों का सीधा सम्बन्ध होता है तथा मुद्रा के मूल्य के साथ विरोधी सम्बन्ध होता है । अर्थात् मुद्रा-परिमाण में अथवा उसकी भ्रमण-गति में वृद्धि होने से वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाएँगी तथा मुद्रा का मूल्य अथवा क्रय-शक्ति घट जाएगी । उसी प्रकार मुद्रा-परिमाण अथवा उसकी भ्रमण-गति में कमी आने से उसी अनुपात में वस्तुओं की कीमतें गिर जाएँगी तथा मुद्रा की

क्रयशक्ति बढ़ जाएगी। इस सशोधित सिद्धान्त का समीकरण इस प्रकार होगा -

$$M V + M' V' = P T$$

अथवा

$$\text{कीमत} = \frac{\text{मुद्रा} \times \text{गति सामर्थ्य} + \text{साक्ष मुद्रा} \times \text{गति सामर्थ्य}}{\text{व्यापार (उत्पादन)}}$$

$$\text{or } P = \frac{M V + M' V'}{T}$$

### मुद्रा मूल्य की विशेषता

इस प्रकार मुद्रा के परिमाण के परिवर्तन के साथ उम्मी अनुपात में कीमतों के स्तरों में परिवर्तन होने का मुख्य कारण यह है कि अन्य वस्तुओं की अपेक्षा मुद्रा में यह विशेषता है कि अन्य वस्तुओं की कीमतें उसकी पूर्ति के परिमाण के अनुपात में नहीं बदलती क्योंकि अन्य वस्तुएँ उपभोग के लिए होती हैं तथा उनकी माँग में लोच होती है। किन्तु मुद्रा की माँग विनिमय कार्य पर निर्भर है, जो उत्पादन में परिवर्तन हुए बिना नहीं बदलती अतः किसी विशिष्ट परिस्थिति में मुद्रा की माँग की लोच समानुपात होती है।

दूसरे, मुद्रा की एक और विशेषता है जो अन्य वस्तुओं में नहीं होती। वह यह कि अन्य वस्तुओं की उपयोगिता उनकी उपलब्ध मात्रा पर निर्भर होती है। परन्तु मुद्रा की उपयोगिता उसकी राशि पर निर्भर नहीं रहती क्योंकि मुद्रा में यदि क्रयशक्ति न हो तो वह हमारे लिए किसी काम की नहीं। इसलिए मुद्रा की उपयोगिता उसकी क्रयशक्ति पर निर्भर रहती है न कि उसके परिमाण पर। उदाहरणार्थ यदि देश के कुल गेहूँ का आधा गेहूँ खराब हो जाए अथवा जला दिया जाए तो देश की सम्पूर्ण उपयोगिता में हानि होगी क्योंकि गेहूँ की उपलब्ध मात्रा घट जाएगी। इसके विपरीत यदि आधी पत्रमुद्रा जला दी जाए तो हमारे उपभोग के साधन उतने ही रहते हैं जिससे हमारी उपयोगिता का किसी प्रकार से नाश नहीं होता। उदाहरणार्थ यदि मेरे पास सिनेमा का टिकट है और वह जल जाता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि मैं अब सिनेमा नहीं देख सकूँगा क्योंकि सिनेमा घर तो है ही। केवल मुझे दूसरा टिकट लेना पड़ेगा। परन्तु यदि सिनेमा घर ही जल जाए तो मेरे पास टिकट होते हुए भी वह बेकार हो जाता है। इसी प्रकार मुद्रा की उपयोगिता मुद्रा में न होते हुए उसकी क्रयशक्ति में होती है। कुछ मुद्रा जल जाने से समाज की किसी प्रकार

में हानि नहीं होती। हाँ केवल मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी जिसमें वस्तुओं की कीमते गिर जाएँगी।

### मुद्रा परिमाण मिद्धान्त के साध्य (Propositions)

मुद्रा की उपरोक्त विशेषताओं के कारण ही मुद्रा की पूर्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने में वस्तुओं की कीमतों में उसी दिशा में आनुपातिक परिवर्तन होता है तथा मुद्रा के मूल्य में विपरीत दिशा में आनुपातिक परिवर्तन होता है। अर्थात् वस्तुओं का मूल्यस्तर (P) इस मिद्धान्त के समीकरण के अन्य घटकों का कार्य अथवा परिणाम है, कारण नहीं।<sup>१</sup> इस मूल्यस्तर में परिवर्तन लाने वाले कारण निम्नलिखित हैं —

- (१) चलन में होने वाली धातु-मुद्रा (M)
- (२) चलन में होने वाली साख-मुद्रा एवं पत्र-मुद्रा (M')
- (३) धातु-मुद्रा की गति (V)
- (४) पत्र एवं साख-मुद्रा की गति (V')
- (५) व्यापार (T)

प्रो० फिशर के अनुसार मक्रमण कात्र के अनिश्चित सामान्यत मूल्यस्तर, समीकरण के अन्य घटकों (factors) के साथ बदलना चाहिए। इसलिए प्रो० फिशर ने निम्नलिखित साध्यों को आधार माना है —

( 1 ) किसी भी समय यदि मुद्रा ( M ) का परिमाण बढ़ा दिया जाए तो उसी अनुपात में साख-मुद्रा ( M' ) जो कि अधिकोपों द्वारा निर्माण की जाती है वह भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अधिकोपों द्वारा साखनिर्माण उनके पास जो जनता की जमा राशि होती है उस पर निर्भर रहेंगे। जमा राशि और साख का कुछ न कुछ अनुपात निश्चित रहता है। इसलिए यदि मुद्रा की राशि बढ़ा दी जाती है तो उसी अनुपात में साख-मुद्रा ( M' ) में भी वृद्धि होगी। इन दोनों के बढ़ने में मूल्यस्तर में भी उसी अनुपात में वृद्धि हो जाएगी तथा उसके विपरीत अनुपात में मुद्रा के मूल्य कम होंगे।

( 11 ) किसी भी देश में मुद्रा के परिमाण में यदि वृद्धि होती है तो उसका प्रभाव उसी धातु-मान पर आधारित अन्य देशों पर भी होता है, क्योंकि जैसे ही मूल्यस्तर अथवा मुद्रा के मूल्य एवं धातु मूल्य में अन्तर निर्माण होगा वैसे ही धातु-मुद्रा या तो गन्नाई जाएगी या विदेशों में भेजी जाएगी।

<sup>1</sup> *Purchasing Power of Money*—Fisher, pp. 181-182

इसके फलस्वरूप जागतिक मूल्यस्तर में वृद्धि होगी अर्थात् एक देश के मुद्रा-परिमाण में वृद्धि होने से अन्य देशों के मूल्यस्तर भी बढ़ेंगे—यदि ऐसे देश अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में हैं।

( iii ) इसी प्रकार धातुमुद्रा (  $M$  ) की अपेक्षा यदि साखमुद्रा (  $M'$  ) के अनुपात में वृद्धि होती है तो उससे भी धातुमुद्रा का विचलन होकर जागतिक मूल्यस्तर बढ़ेंगे।

( iv ) धातुमुद्रा (  $M$  ) में अथवा साखमुद्रा (  $M'$  ) के परिमाण में वृद्धि होने से उनकी गति बढ़ेगी ही ऐसा आवश्यक नहीं है, क्योंकि मुद्रा की एवं साखमुद्रा की गतिशीलता (  $V + V'$  ) मुद्रा की श्रुति पर निर्भर न रहते हुए स्वतन्त्र है एवं अन्य कारणों पर निर्भर है। ये अन्य कारण जिनसे मुद्रा तथा साखमुद्रा की गतिशीलता बढ़ती है बाहरी कारण हैं। जैसे —

( १ ) समाज के व्यक्तियों की आदतें :—

- ( क ) दत्त अथवा भूमिगत धन रखने के विषय में
- ( ख ) साख-व्यवहारों (book-credit) के विषय में तथा
- ( ग ) बैंकों के उपयोग के विषय में

( २ ) समाज में भुगतान करने की पद्धतियाँ :—

- ( क ) राशि के लेन-देन की तीव्रता (frequency)
- ( ख ) राशि के लेन-देन की नियमितता (regularity)
- ( ग ) लेन-देन की राशि एवं समय का सम्बन्ध

( ३ ) सामाज्य कारण :—

- ( क ) जनसंख्या का घनत्व
- ( ख ) यातायात साधनों की दीर्घवाहकता

फिर भी यदि मुद्रा एवं साखमुद्रा की गति (  $V \times V'$  ) में वृद्धि होती है तो मूल्यस्तर भी बढ़ेंगे।

( v ) व्यापार (  $T$  ) की कमी अथवा अधिकता भी मुद्रा के परिमाण पर निर्भर न रहते हुए अन्य बाहरी कारणों पर निर्भर रहती है। जिन कारणों पर व्यापार (  $T$  ) का विस्तार अथवा कमी निर्भर रहती है, उन कारणों का समावेश हमारे सिद्धान्त के समीकरण में नहीं आता। ये कारण अनेक हैं एवं तांत्रिक हैं।<sup>१</sup>

<sup>१</sup> *Purchasing Power of Money*—Fisher, pp 74-75, 181-182

(१) उत्पादकों को प्रभावित करने वाली परिस्थिति :—

- (क) नैसर्गिक साधनों के सम्बन्ध में भौगोलिक अन्तर ।
- (ख) उत्पादन-रत्ना का ज्ञान ।
- (ग) श्रम-विभाजन ।
- (घ) पूँजी का मूल्य ।

(२) उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाली परिस्थिति :—

मांगी इच्छाओं का विकास एवं भिन्नता ।

(३) उत्पादक एवं उपभोक्ताओं से सम्बन्ध : —

- (क) यातायात की सुविधाएँ ।
- (ख) व्यापार की पारम्परिक स्वतन्त्रता ।
- (ग) मौद्रिक एवं वित्तीय पद्धति की विरोधताएँ ।
- (घ) व्यापारिक विश्वास (confidence) ।

इन कारणों के प्रभाव से व्यापार का विकास होता है । यदि मुद्रा की पूर्ति ( $M, M'$ ) एवं मुद्रा की गति ( $V, V'$ ) में भी उमी अनुपात से वृद्धि नहीं होती तो व्यापारिक विकास के अनुपात में मूल्यस्तर गिरेंगे । परन्तु व्यापारिक विकास के साथ मुद्रा की गतिशीलता तथा मुद्रा के साथ रहने वाला साखमुद्रा का अनुपात भी बढ़ता है जिससे व्यापारिक विकास से मूल्यस्तर में होने वाली कमी नहीं आने पाती अथवा उनमें गिरावट कम आती है ।<sup>१</sup>

(v1) उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त अन्य अनेक ऐसे स्वतन्त्र कारण होते हैं जिनसे मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के समीकरण के पाँचो घटक ( $M, M', V, V', T$ ) प्रभावित होकर उनसे मूल्यस्तर भी प्रभावित होते हैं । ऐसे बाहरी कारणों में दूसरे देशों के मूल्यस्तर का उसी प्रकार, अन्य देशों के युद्ध का प्रभाव महत्वपूर्ण है जिससे किसी भी देश के मूल्यस्तर में परिवर्तन होते हैं ।

सक्रमण काल में यह सिद्धान्त लागू नहीं होगा यह सम्भव है क्योंकि उस समय मुद्रा से साखमुद्रा का अनुपात बहुत अधिक हो जाता है जो सामान्यतः दीर्घकालीन अवधि में एवं साधारण परिस्थिति में नहीं होता । सक्रमण काल में विरोधत मूल्यस्तर में पहिले वृद्धि होती है क्योंकि जनता की ओर से वस्तुओं की माँग बढ़ जाती है और व्यापारी अधिक लाभ कमाने की दृष्टि से

<sup>१</sup> *Purchasing Power of Money*—Fisher, p. 182

वस्तुओं की कीमतें बढ़ा देते हैं। बढ़ता हुआ लाभ देखकर उद्योगपति अपने-अपने उद्योगों का विकास करते हैं जिसके लिए उनकी अधिव पूँजी की आवश्यकता होती है। इस पूँजी को वे अधिवोधों से लेते हैं। मूल्य-स्तर जिस अनुपात में बढ़ता है उस अनुपात में व्याज दरों का समायोजन (adjustment) नहीं होने पाना। यह क्रिया अब लागू हो जाती है तब मूल्य बढ़ते जाते हैं और मुद्रा के परिमाण में साख-मुद्रा का साधारण अनुपात बढ़ता जाता है, जिससे मुद्रा की गति भी बढ़ जाती है और व्यापारिक क्षेत्र भी। इस प्रकार यह व्यापार-चक्र (trade cycle) आरम्भ हो जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक कि व्याज दरों का समायोजन मूल्य-स्तर से नहीं होता। जैसे ही यह समायोजन हो जाता है व्यापार-चक्र पूर्ण होकर साधारण काल आ जाता है। केवल ऐसे समय में ही मुद्रा के परिवर्तन के माध्यम मूल्य-स्तर में अनुपातिक परिवर्तन नहीं होते। परन्तु इसके बाद मुद्रा के परिमाण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन मूल्य-स्तर को उसी दिशा एवं अनुपात में परिवर्तित करेगा। मारास में अन्य बातें समान रहते हुए मुद्रा के परिमाण में किसी भी प्रकार के परिवर्तन से मूल्य-स्तर उसी दिशा में एवं उसी अनुपात में बदलेंगे तथा मुद्रा का मूल्य विपरीत दिशा में एवं उसी अनुपात में बदलेगा।

### सिद्धान्त की आलोचना

(१) इस सिद्धान्त के विरुद्ध अर्थशास्त्रियों ने अनेक आक्षेप किये हैं। सबसे पहला आक्षेप यह है कि इस सिद्धान्त में कोई विशेषता नहीं है बल्कि यह भाँग एवं पूर्ति नियम के विवेचन का सरल ढंग है। किन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें मुद्रा के परिमाण में कमी या अधिकता होने से क्या परिणाम होते हैं, इसका विवेचन है जिससे हम कीमतों पर, मुद्रा-परिमाण में परिवर्तन करके, नियन्त्रण कर सकते हैं।

(२) यह सिद्धान्त भाँग एवं पूर्ति नियम पर आधारित स्वयमिच्छा सत्य है जिसको बहुत महत्व दिया गया है। किन्तु स्वयमिच्छा सत्य होने के प्रतिरिक्त इस सिद्धान्त के द्वारा कीमतों का समायोजन करने में इसमें प्रत्यक्ष सहायता मिलती है अतः यह सिद्धान्त उपयोगी है, जिसका अध्ययन मुद्रा एवं बैंक के ठीक अध्ययन के लिए आवश्यक है।

(३) यह सिद्धान्त काल्पनिक एवम् अपूर्ण है क्योंकि इसमें हम किसी भी समय मुद्रा-चलन के परिमाण का ठीक-ठीक आँकड़ा नहीं मालूम कर सकते जो केवल अनुमान पर निर्भर है। इतना ही नहीं, अगिनु जिन बातों को हम

स्थिर मानते हैं वे वास्तविक सृष्टि में कभी स्थिर नहीं रहती अतः उनका ठीक नाप नहीं किया जा सकता। अर्थात् यह सिद्धान्त केवल स्थिर समाज में ही लागू हो सकता है, परिवर्तनशील समाज में नहीं।

(४) यह आक्षेप प्रो० वीन्स का है। उनका कथन है कि आजकल विनिमय के व्यवहार अधिकतर साख-पत्रों द्वारा होते हैं जिसका धानुनिधि से बहुत कम सम्बन्ध रहता है और मुद्रा द्वारा होने वाले अधिकांश व्यवहार औद्योगिक, व्यापारिक अथवा आर्थिक (financial) होते हैं तथा बहुत कम विनिमय इस प्रकार का होता है जिसे हम 'व्यापार' (T) शब्द प्रयोग के द्वारा समीकरण में दिखाते हैं। अतः मुद्रा-परिमाण-समीकरण द्वारा मुद्रा की क्षमता का माप न होने हुए एक व्यवहार का मान (cash transaction standard) होता है।

(५) मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त, कीमता के स्तर में किम प्रकार परिवर्तन होता है यह नहीं बताता और न इसी का स्पष्टीकरण करता है कि व्यापार-चक्र (trade cycles) में मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन न होते हुए भी कीमतें क्यों गिरती हैं अथवा क्यों चढ़ती हैं।

(६) इस सिद्धान्त में मुद्रा की माँग की अपेक्षा पूर्ति पर ही अधिक जोर दिया गया है जिसका प्रभाव कीमतों अथवा क्षमता पर होता ही है। किन्तु हम देख चुके हैं कि किसी विशिष्ट परिस्थिति में मुद्रा की माँग की लोच समानुपात होती है—अर्थात् मुद्रा की माँग न घटती है न बढ़ती है। किन्तु मुद्रा की पूर्ति केवल सरकारी चलन पर निर्भर न रहने हुए उस पर सोन या चाँदी के अधिक उत्पादन का अथवा नई खाना की खोज (discovery) का प्रभाव पड़ता है इसलिए पूर्ति पर ही अधिक जोर दिया गया है।

(७) किसी विशिष्ट देश की कीमता की तेजी अथवा मन्दी के कारणों का विवेचन इस सिद्धान्त द्वारा नहीं हो सकता तथा उसके लिए अन्य देशों की कीमता का सम्बन्ध लेना आवश्यक है।

किन्तु इन सब आक्षेपों के हात हुए भी माद्रिक जगत में इस सिद्धान्त की मान्यता स्वीकृत की गई है। प्रो० फिशर ने अपनी डॉलर स्थायित्व-मान-योजना (compensated dollar scheme) में इस सिद्धान्त की कितनी महत्त्वता हुई यह सिद्ध किया है। प्रो० वीन्स भी यह मानते हैं कि सत्स्था-त्मक जाच के लिए मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के समीकरण की सहायता से अधिक उन्नति की जा सकती है क्योंकि समीकरण में दिया हुआ  $MV$  (मुद्रा  $\times$  भ्रमण-गति) अधिकोपा की गुणनान से साम्य रखता है, तथा  $M$  (मुद्रा)

अधिकोषों में जो स्वयं जमा की जाती है, उससे ममता रखती है। इन दोनों के आँखों में आजकल उपलब्ध है तथा मुद्रा के आँखों से उसकी भ्रमण-मति V भी निकाली जा सकती है। अतः मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त में कुछ सत्य का अंश होने से यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिद्धान्त भी अर्थशास्त्र के अन्य नियमों की भाँति ही, किसी विशिष्ट परिस्थिति में कौनसी प्रवृत्ति कार्य करेगी, यह स्पष्ट करता है।

### केम्ब्रिज का मुद्रा परिमाण समीकरण

केम्ब्रिज समीकरण मुद्रा परिमाण सिद्धान्त का नवीन रूप है जिसे मार्शल, पीगू, वेंन, रॉबर्टसन आदि अर्थशास्त्रियों ने प्रतिपादित किया। यह समीकरण निम्न है —

$$P = \frac{M}{KR}$$

जिसमें  $P$  = सामान्य मूल्यस्तर,

$M$  = मुद्रा की इकाइयों की संख्या,

$R$  = समाज की आय,

$K$  = समाज की कुल आय का वह अनुपात जिसे मुद्रा के रूप में जनता रखती है।

फिदर के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त के समीकरण तथा केम्ब्रिज समीकरण में महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि फिदर के समीकरण में मुद्रा की माँग से तात्पर्य समस्त विनिमय व्यवहारों के लिए आवश्यक मुद्रा के परिमाण से है जबकि केम्ब्रिज समीकरण के अनुसार मुद्रा की माँग में केवल वह मुद्रा का परिमाण है जो जनता अपने पास नकद-रूप में भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संग्रह करती है।

केम्ब्रिज समीकरण में  $K$  का स्थान महत्वपूर्ण है जो वास्तविक आय का वह अनुपात है जिसे मुद्रा के रूप में व्यक्ति, समाज अथवा संस्था अपने पास रखती है। उदाहरणार्थ एक श्रमिक जो २ रु० दैनिक पाता है वह, मान लीजिए कि, सप्ताह के अन्त में अपने पास २ रु० रखना चाहता है। इस उदाहरण में  $K$  मालूम करने के लिए सबसे पहले यह मालूम करना होगा कि वह प्रतिदिन औसत कितना खर्च अपने पास रखता है। यह निम्न रीति से मालूम होगा —

$$\frac{(12) + (10) + (8) + (6) + (4) + (2) \text{ रु०}}{6 \text{ दिन}} = \frac{42 \text{ रु०}}{6 \text{ दिन}} = 7 \text{ रुपये औसत दैनिक}$$

इससे यह स्पष्ट है होता है कि वह औसत रूप से दैनिक ७ रुपये पाम रसेगा। उसको सप्ताह की आय १४ रु० है (७ दिन  $\times$  २ रु०)। अतः  $K = \frac{७}{१४}$  या  $\frac{१}{२}$ । यह K सदैव समान नहीं रहेगा अपितु कम अधिक होता रहेगा।

केम्ब्रिज समीकरण के आधारभूत सिद्धान्त—इस सिद्धान्त का व्यवहारिक पक्ष जानने के पूर्व इसके आधारभूत सिद्धान्तों को देखना आवश्यक है जो निम्न हैं —

(१) मुद्रा की माँग—मनुष्यम इस सिद्धान्त में मुद्रा की माँग का जानना आवश्यक है। फिशर के मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त में मुद्रा की माँग से तात्पर्य कुछ विनिमय व्यवहारों के मौद्रिक मूल्य में है। किन्तु केम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की माँग में तात्पर्य मुद्रा के उन भाग में है जो कोई व्यक्ति, संस्था या समाज अपने पास भविष्यकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाकर रखता है। साधारणतः यह देखा जाता है कि मनुष्य की आय सीमित होती है किन्तु व्यय असीमित होते हैं। उसे निश्चित आय से मिश्र-मिश्र व्यय करने पड़ते हैं। सम्भव है कि एक मनुष्य की आय १०० रु० हो फिर भी वह अपने पास कुछ राशि भविष्यकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचाकर रखना चाहता है। मान लीजिए इस हेतु वह २० रु० बचाना है तो भविष्यकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उरबा नगद बाँग २० रुपये होगा। ठीक इसी प्रकार उत्पादक भी कच्चा मान खरीदने, मजदूरी का भुगतान करने तथा अन्य दैनिक व्ययों के लिए अपने पास नगद कोष रखा।

प्रोफेसर कॅनन के अनुसार “जिस प्रकार मकान की वास्तविक माँग मकान में रहने वालों से होती है न कि मकान के क़ता और विक़ताओं से, ठीक उसी प्रकार मुद्रा की वास्तविक माँग वह भाग है जो व्यक्ति, समाज एवं संस्था अपना व्यय चलाने के लिए अपने पास नगद कोष में रखते हैं।

(२) तरलता पूर्वाधिकार (Liquidity Preference)—प्रत्येक व्यक्ति स्वभावतः तरलता पसन्द करता है। इसलिए वह अपने पास मुद्रा अथवा ऐसी अन्य वस्तुएँ रखता है जिनमें तरलता हो अर्थात् जो तरलता में रोकड़ में बदली जा सकें। जैसे एक व्यक्ति मकान खरीदता है, दूसरा अना, प्रतिभूतियाँ आदि तथा तीसरा बैंक में धन्य जमा करता है। इन तीनों व्यक्तियों का हेतु एक ही है कि आवश्यकता के समय उनसे उनकी पूर्ति ली जा सके। केम्ब्रिज

समीकरण में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, मर्यादा या समाज नगद कोष रखता है। अतः तरलता पूर्वाधिकार से मुद्रा की माँग प्रभावित होती है।

(३) मुद्रा की चलनगति का माँग पर प्रभाव—मुद्रा की चलनगति का प्रभाव भी मुद्रा की माँग पर होता है। यदि देशवासियों में तरलता पूर्वाधिकार की प्रवृत्ति हावी तो रुपये की चलनगति कम होगी क्योंकि वे उसे अपने पास सदैव नगद कोष के रूप में रखेंगे। इसके विपरीत यदि देशवासियों में तरलता पूर्वाधिकार की प्रवृत्ति कम होगी तो मुद्रा की चलनगति अधिक होगी।

(४) नगद कोष को प्रभावित करने वाली बातें—एक व्यक्ति, मर्यादा या समाज की जितना नगद कोष रखना चाहिए यह तरलता पूर्वाधिकार से ज्ञात नहीं हो सकता क्योंकि इस कोष को प्रभावित करने वाले निम्न घटक होते हैं—

(अ) देश की जनसंख्या—यदि देश की जनसंख्या अधिक होगी तो नगद कोष की राशि भी अधिक होगी क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने पास कुछ न कुछ नगद कोष रखना चाहेगा।

(आ) धन का वितरण—देश में यदि धन का वितरण समानता से हो रहा है तो प्रत्येक व्यक्ति समानता से नगद कोष रखेगा। अन्यथा नगद कोष की राशि में भी असमानता रहेगी।

(इ) आय प्राप्त होने का समय—आय प्राप्त होने का समय जितना कम होगा उतनी ही नगद कोष की राशि कम होगी और जितना अधिक समय लगेगा उतनी ही नगद कोष की राशि अधिक होगी। उदाहरणार्थ यदि साप्ताहिक अवधि में आय मिलती है तो नगद कोष की राशि कम होगी, मासिक अवधि में अधिक और वार्षिक अवधि में अत्यधिक नगद कोष रखना होगा।

(ई) साख पत्रों का उपयोग—जिम समाज अथवा देश में साख पत्रों का उपयोग होता है वहाँ नगद कोष की कम आवश्यकता होती है, अन्यथा अधिक नगद कोष रखने की आवश्यकता होती है।

(उ) समाज की आर्थिक अवस्था—समाज की आर्थिक अवस्था अथवा उन्नति से भी नगद कोष की राशि प्रभावित होती है। जैसे भारतीय समाज की तुलना में आर्थिक दृष्टि में अमरीकी समाज अधिक उन्नत होने से अमरीकी व्यक्ति को भारतीय व्यक्ति की अपेक्षा अधिक नगद कोष रखना होगा, क्योंकि

वहाँ की सामाजिक एवं अन्य आवश्यकताएँ भारतीय व्यक्ति की अपेक्षा अधिक होगी।

(ऊ) वस्तुओं की कीमतें—वस्तुओं की कीमतों का भी नगद कोष पर प्रभाव होता है। यदि कीमतें अधिक होगी तो अधिक नगद कोष रखना होगा क्योंकि उतनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक धन की आवश्यकता होगी। इसके विपरीत अवस्था में कम नगद कोष रखना होगा।

समीकरण का व्यवहारिक रूप

$$P = \frac{M}{KR}$$

इस समीकरण के अनुसार  $M = KR$  और प्रति इकाई मुद्रा का मूल्य  $\frac{KR}{M}$  होगा क्योंकि मुद्रा के मूल्य तथा वस्तु के मूल्य में विपरीत अनुपात में परिवर्तन होता है जैसा कि पिछर के समीकरण से स्पष्ट है। अतः  $P$  (सामान्य मूल्य-स्तर) बराबर होगा  $\frac{M}{KR}$  के। उदाहरणार्थ, श्रीमिष के उदाहरण में हमने देखा कि  $K$  बराबर  $\frac{2}{3}$  के है,  $R$  बराबर १००० मन गहुँ और  $M$  बराबर ५००० रुपये के है। इस स्थिति में

$$\text{सामान्य मूल्य-स्तर अथवा } P = \frac{५००० (M)}{(R) १००० \times (K) \frac{2}{3}}$$

$$\text{अथवा } P = \frac{५०००}{५००} = १० \text{ रु० प्रति मन}$$

इस समीकरण से यह स्पष्ट होता है कि मुद्रा का उपयोग वस्तुओं को तत्काल खरीदने के लिए ही नहीं अपितु नगद कोष के रूप में भविष्यकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है क्योंकि देशवासी भविष्य-कालीन आवश्यकताओं की मनुष्य के लिए नगद काय रखते हैं।

पिछर के मुद्रा परिमाण सिद्धान्त समीकरण तथा कैम्ब्रिज समीकरण में थोड़ा सा अन्तर है। पिछर ने मुद्रा की भाग से तात्पर्य कुल विनिमय-व्यवहारों के मूल्य से लिया है तो कैम्ब्रिज समीकरण में नगद कोष से लिया है। दूसरे, पिछर के समीकरण में दीर्घकालीन अवधि की आरम्भ है तो कैम्ब्रिज समीकरण में अल्पकालीन अवधि अथवा क्षण विशेष की आरम्भ है। इन अन्तरों के होने हुए भी दोनों समीकरणों में बहुतसा समानता है। जहाँ तक दोनों समीकरणों के लक्ष्यों का सम्बन्ध है वे समान हैं किन्तु उनकी पूर्ति की विधि में किंचित् अन्तर है।

## कीन्स का मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त

प्रो० कीन्स ने केम्ब्रिज समीकरण में थोड़ा सा संशोधन कर उसे नए रूप में प्रस्तुत किया है अतः इसे मुद्रा-परिमाण का कीनीसन सिद्धान्त भी कहते हैं। कीन्स का निम्न समीकरण है —

$$n = p(k + rk')$$

जिसमें  $n$  = चलन की माथा,

$p$  = उपभोग की एक इकाई का मूल्य,

$k$  = उपभोग की इकाइयाँ जिनके लिए जनता क्रयशक्ति संचित कर अपने पास रखती है,

$r$  = बैंक में जनता के जो निक्षेप होते हैं उनके भुगतान के लिए बैंक जो नगद कोष अपने पास रखते हैं उसका कुल निक्षेपों से अनुपात,

$k'$  = उपभोग की इकाइयाँ जिनके लिए साख-मुद्रा में संचय किया जाता है।

कीन्स के समीकरण में यह बताया गया है कि जनता भविष्यकालीन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि के लिए अपने पास नगद कोष जमा करती है। इसको कीन्स ने  $k$  की सजा दी है। इसी प्रकार उपभोग की वस्तुओं को कीन्स ने उपभोग की इकाइयाँ (consumption units) कहा है। उक्त नगद कोष के सिवा जनता बैंक में भी कुछ मुद्रा इसी उद्देश्य से जमा करती है जिसे कीन्स ने  $k'$  कहा है। इसका तात्पर्य है कि जनता अपने पास तथा बैंक में कुछ कोष जमा करती है जिसमें वह अपनी भविष्यकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। बैंक में जनता जो रुपया जमा करती है उसे बैंक अपने पास न रखते हुए विनियोजित करते हैं। किन्तु निक्षेपकर्ताओं की मांग का भुगतान करने के लिए बैंक अपने पास नगद कोष (रोकड़ निधि) रखते हैं और जिस अनुपात में बैंक यह नगद कोष रखता है वह समीकरण में  $r$  है।

अतः कीन्स के अनुसार  $n$  में परिवर्तन होने से  $k$ ,  $k'$  तथा  $r$  प्रभावित होते हैं। किन्तु साधारण परिस्थितियों में  $k$ ,  $k'$  तथा  $r$  में परिवर्तन नहीं होते। अर्थात्  $n$  या मुद्रा में वृद्धि या कमी होने से  $k$ ,  $k'$  तथा  $r$  में परिवर्तन होंगे।

कीन्स ने अपने समीकरण में साख-मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार जनता बैंक में रुपया जमा करती है और आवश्यकता के समय उसे बैंक या अन्य साख पत्रों से निकालती है। इसलिए साख-मुद्रा को मुद्रा-

परिमाण सिद्धान्त में उचित स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि कीन्स के अनुसार वर्तमान आर्थिक विश्व के अधिकांश व्यवहार साम्र-मुद्रा से किए जाते हैं न कि वास्तविक मुद्रा से।

इस समीकरण का प्रमुख दोष यह है कि  $L$  तथा  $L'$  को निश्चित रूप से मानूम नहीं किया जा सकता। फिर व कीन्स के समीकरणों में भी थोड़ा सा ही अन्तर है। फिर न मुद्रा की माँग में सभी विनिमय व्यवहारों की मौद्रिक राशि का समावेश किया है जबकि कीन्स समीकरण में केवल उनी धनराशि का समावेश है जो जनता भविष्यवाणीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपना पास या बैंक में जमा करती है। दूसरे, फिर व के समीकरण में दीघकालीन अवधि पर अधिक बल दिया गया है तो कीन्स के समीकरण में अल्पकालीन अवधि पर।

### सारांश

मुद्रा का मूल्य उसकी प्रयत्नशक्ति है। यदि कीमतें बढ़ती हैं तो मुद्रा का मूल्य कम होता है और कीमतें गिरती हैं तो मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। मुद्रा का मूल्य अन्य वस्तुओं की भाँति उसकी माँग एवं पूर्ति पर निर्भर रहता है।

मुद्रा की माँग किसी समाज में वस्तुओं के विनिमय के लिए जितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी उतनी मुद्रा की माँग रहेगी।

मुद्रा की पूर्ति जो मुद्रा (पत्र मुद्रा एवं धातु मुद्रा) चलन में होती है उसे मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। परन्तु एक मुद्रा यदि १० बार लेन-देन में आती है तो वह १० मुद्रा का कार्य करती है। अर्थात् मुद्रा की पूर्ति वास्तविक मुद्रा को उसकी चलनगति से गुणा करके मानूम होनी है।

मुद्रा-परिमाण सिद्धान्त के अनुसार अन्य बातें समान रहते हुए मुद्रा के परिमाण में परिवर्तन होते ही मुद्रा के मूल्य में विरोधी दिशा में तथा वस्तुओं की कीमतों में उसी दिशा में अनुपातिक परिवर्तन होगा।

अन्य बातें जो समान रहनी चाहिए —

- १ उपयोग में केवल धातु-मुद्रा हो।
- २ मुद्रा केवल विनिमय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती हो।
- ३ मुद्रा की गति में परिवर्तन न हो।
- ४ वस्तु विनिमय न होता हो।
- ५ उत्पादन स्थिर रहे।

६. जनता की संख्या, उपभोग की आदतें आदि स्थिर रहे ।

७. साल का उपयोग न होता हो ।

परन्तु आज के परिवर्तनशील समाज में न तो यह सम्भव है और साथ ही बैंक निर्मित साल का उपयोग भी होता है अतः मुद्रा परिमाण सिद्धान्त में हमको साल एवं साल की गति का समावेश भी करना होगा ।

समीकरण : प्रारम्भिक दशा में सिद्धान्त का समीकरण होगा ।

$$PT = MV \text{ अथवा } P = \frac{MV}{T}$$

साल का समावेश करने के बाद

$$PT = MV + M'V' \text{ अथवा } P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

मुद्रा के लिए अलग से सिद्धान्त होने का प्रमुख कारण मुद्रा की विशेषता है । अन्य वस्तुओं की उपयोगिता उनकी कितनी मात्रा उपलब्ध है इस बात पर निर्भर होती है पर मुद्रा की उपयोगिता मुद्रा में न रहते हुए उसकी क्रय-शक्ति पर निर्भर रहती है । दूसरे, मुद्रा की माँग विनिमय कार्य पर निर्भर है जो उत्पादन आदि में परिवर्तन हुए बिना नहीं बदलती । अर्थात् मुद्रा की माँग की लोच समानुपात (unity) रहती है ।

सिद्धान्त की मान्यताएँ

कीमतेँ समीकरण की अन्य बातों के परिणाम हैं, कारण नहीं । अर्थात् इनमें चलन में रहने वाली धातु-मुद्रा एवं साल-मुद्रा, इनकी गति तथा व्यापार के परिवर्तन के कारण हेरफेर होता है । इसलिए सिद्धान्त की निम्न मान्यताएँ हैं :—

(१) धातु-मुद्रा में परिवर्तन के साथ साल मुद्रा में भी निश्चित अनुपात में परिवर्तन होगा ।

(२) एक देश की धातु मुद्रा की वृद्धि का परिणाम समान प्रमाण वाले अन्य देशों पर भी होता है ।

(३) धातु-मुद्रा की अपेक्षा साल-मुद्रा अधिक अनुपात में बढ़ने पर धातु मुद्रा का विस्थापन होगा और विश्व के मूल्यस्तर बढ़ेंगे ।

(४) धातु-मुद्रा या साल मुद्रा की वृद्धि से उनकी गति में वृद्धि होगी, यह आवश्यक नहीं है । गति में वृद्धि लाने वाले अन्य कारण हैं ।

(५) व्यापार में परिवर्तन मुद्रा परिमाण पर निर्भर न रहते हुए अन्य बाहरी कारणों पर निर्भर रहते हैं ।

### आलोचना

१ मांग एवं पूर्ति के नियम का सरल विवेचन है ।

२ मांग एवं पूर्ति के नियम पर आधारित स्वयंसिद्ध सत्य है ।

३ यह काल्पनिक एवं अपूर्ण है क्योंकि मुद्रा एवं साग के सही-सही आँकड़े नहीं मासूम हो सकते ।

४ कीन्स के अनुसार आजकल अधिकांश विनिमय-व्यवहार माणपत्रों द्वारा होते हैं जिनका घातु निधि से बहुत कम सम्बन्ध है । अतः यह सिद्धान्त मुद्रा की क्रयशक्ति का नाप होते हुए रोकड़-व्यवहार का प्रमाण बताता है ।

५ सिद्धान्त में मुद्रा की मांग की अपेक्षा पूर्ति पक्ष पर ही अधिक जोर दिया गया है ।

६ तैजी-मदी के समय कीमती के उतार चढ़ाव के कारणों को बताने में यह सिद्धान्त बेकार है ।

इन आलोचनाओं के होते हुए भी मूल्यस्तर को ठीक करने के लिए यह सिद्धान्त वास्तविक व्यवहार में अधिक उपयोगी है ।

## मूल्य निर्देशांक

मुद्रा का मूल्य उसकी क्रयशक्ति है, यह हम अभी देख चुके हैं। जहाँ तक मुद्रा से हम वस्तुएँ खरीदते एवं बेचते हैं वहाँ तक मुद्रा का मूल्य एवं वस्तुओं की कीमतों के साथ सम्बन्ध होता है, यह सम्बन्ध हमने पिछले अध्याय में देखा। सारांश में उसी मुद्रा में यदि पहिले की अपेक्षा कम वस्तुएँ खरीदी जाती है तो हम यह कहेंगे कि मुद्रा की क्रयशक्ति कम हो गई है। इसके विपरीत यदि उसी मुद्रा से हम पहिले की अपेक्षा अधिक वस्तुएँ खरीद सकते हैं तो हम यह कहेंगे कि मुद्रा की क्रयशक्ति बढ़ गई है। साधारण बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं या घट गई हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि “कीमतें मुद्रा का मूल्य तथा अन्य वस्तुओं के बीच का अनुपात है जिसे किसी भी एक पक्ष में परिवर्तन करने से—मुद्रा के पक्ष में अथवा वस्तुओं के पक्ष में—बदला जा सकता है।” अर्थात् मुद्रा का मूल्य एवं वस्तुओं की कीमतों का विरोधी सम्बन्ध होता है। जब मुद्रा-मूल्य घटता है तो कीमतें बढ़ती हैं और जब मुद्रा-मूल्य बढ़ता है तो कीमतें घटती हैं।

**मूल्य निर्देशांक (Index Numbers) क्या है ?**

हम यह तो देखते ही हैं कि किसी भी समय वस्तुओं के मूल्य न तो एक साथ बढ़ते हैं और न एक साथ घटते ही हैं। कुछ वस्तुओं की कीमतें घटती हैं और कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं, परन्तु यदि कीमतों का औसत निकाला जाए तो उसमें या तो गिरती हुई प्रवृत्ति या बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देगी। इस औसत के उतार-चढ़ाव से ही हम मुद्रा के मूल्य के परिवर्तनों का अनुमान लगा सकते हैं। मुद्रा के मूल्य-परिवर्तनों को नापने की कोई भी ठीक-ठीक एवं निश्चित विधि नहीं है, परन्तु हम कीमतों के उतार-चढ़ाव से ही मुद्रा के मूल्य-परिवर्तनों को आँक सकते हैं। मूल्य-स्तर में किस परिमाण में परिवर्तन हो रहा है इसका साधारण अनुमान एक पद्धति द्वारा लगाया जाता है जिसे सांकेतिक संख्याएँ अथवा निर्देशांक कहते हैं।

निर्देशांक निबानने की पद्धति के अनुसार हम किसी पूर्वकाल के मूल्य-स्तरों की तुलना उत्तरकाल के मूल्य-स्तरों से करते हैं, जिसमें भिन्न-भिन्न वस्तुओं के समूह बनाकर उनके विभिन्न काग के मूल्यों की तुलना की जाती है। अतः यदि हम एक समय के मूल्यों की तुलना दूसरे किसी समय के मूल्यों के साथ करें तो हमको यह दिखाई देगा कि एसी अवस्था में भी मूल्यों का सामान्य स्तर एक ही दिशा में होगा, अर्थात् कीमतों के सामान्य स्तर में या तो चढ़ाव होगा या उतार। इस मूल्य-स्तर के चढ़ाव-उतार को नापने की क्रिया को ही हम मूल्य निर्देशांक कहते हैं। यह केवल कीमतों का औसत रख जिस दिशा में है यह नकेत करता है अथवा केवल उनकी प्रवृत्ति बनाता है न कि विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में होने वाले पृथक् परिवर्तन। इसलिए यह मूल्य-स्तर का केवल सांकेतिक उत्तर है, सही उत्तर अथवा वास्तविक उत्तर नहीं। इसी कारण निर्देशांक को सांकेतिक संख्याएँ भी कहा जाता है।

### मूल्य निर्देशांक बनाने की विधियाँ

मूल्य निर्देशांक बनाने की दो प्रमुख विधियाँ हैं —

- (क) सामान्य निर्देशांक (general index numbers)
- (ख) भारतील निर्देशांक (weighted index numbers)

**सामान्य निर्देशांक**—सामान्य निर्देशांक बनाने के लिए हमें किस वर्ष की कीमतों की तुलना करना है, यह निश्चय करना होगा। यह वर्ष, जिसको आधार वर्ष (base year) कहते हैं, ऐसा हो जिसमें वस्तु-मूल्यों में अधिक चढ़ाव-उतार न हुए हो, न कोई ऐसी घटनाएँ घटी हो जिससे कि आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा हो। इस वर्ष को निश्चित करने के उपरान्त निर्देशांक में किन किन वस्तुओं के मूल्यों का समावेश हो यह निश्चित करना होगा। अगर हम जीवन-स्तर-मान निर्देशांक (cost of living index) बना रहे हैं तो उमम ऐसी ही वस्तुओं का समावेश करना होगा जो हमारे जीवन से सम्बन्धित हों—अर्थात् ये वस्तुएँ निर्देशांक के उद्देश्य पर निर्भर रहेगी। उस प्रकार मूल्य चोक हा अथवा फुटकर यह भी निर्देशांक के हेतु पर निर्भर रहेगा। यह सब निश्चय कर लेन के बाद हम आधार-वर्ष की विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों को १०० में परिणित करेंगे और इस प्रकार की परिणिति के उपरान्त उनके योग को वस्तुओं की संख्या से भाग देंगे। जो भागफल आएगा वह आधार वर्ष का निर्देशांक होगा। इसी प्रकार जिस वर्ष के मूल्यों की तुलना कर रहे हैं उसको भी आधार वर्ष के मूल्यों की तुलना में १०० में परिणित करके उनके

योग को वस्तुओं की मूल्या में भाग देगे। इससे जो भागफल आएगा वह उस वर्ष का निर्देशांक होगा। अब दोनों निर्देशांकों की तुलना में हम यह समझ जाएंगे कि मूल्यों के सामान्य स्तर में किस प्रतिशत में चढ़ाव या उतार हुआ है। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि १९३६ तथा १९४८ के मूल्य स्तरों की तुलना करनी है और १९३६ में दूध, शकर, चाय तथा कोयले की कीमत क्रमशः ४ आने सेर, ३ आने सेर, १ रु० पौड तथा १ आने सेर है और १९४८ में इन्हीं वस्तुओं के मूल्य क्रमशः १ रु० सेर, ७½ आने सेर, २ रु० पौड तथा ३ आने सेर हैं तो इनके निर्देशांक निम्न प्रकार होंगे —

वस्तुएं*	मूल्य-स्तर १९३६		मूल्य-स्तर १९४८	
	वास्तविक मूल्य	निर्देशांक	वास्तविक मूल्य	निर्देशांक
१ दूध	४ आने सेर	१००	१ रु० सेर	४००
२ शकर	३ आने सेर	१००	७½ आने सेर	२५०
३ चाय	१ रु० पौड	१००	२ रु० पौड	२००
४ कोयला	१ आने सेर	१००	३ आने सेर	३००
योग		४००		११५०
		—४		—४
मूल्य-स्तर निर्देशांक		१००		२८७½

यदि दोनों वर्षों की प्रत्येक वस्तु के मूल्य की हम तुलना करें तो दूध की कीमत ४ गुनी, शकर की २½ गुनी, चाय की दुगुनी तथा कोयले की तिगुनी हो गई है, यह स्पष्ट हो जाता है। अतः १९३६ के १०० की तुलना में इनके निर्देशांक क्रमशः  $100 \times 4$ ,  $100 \times 2\frac{1}{2}$ ,  $100 \times 2$  तथा  $100 \times 3$  अथवा ४००, २५०, २०० तथा ३०० होंगे और योग ११५० होगा। १९३६ में कुल योग ४०० था तो १९४८ में ११५० है। इनको ४ से विभाजित करने के बाद

\* वस्तुएं तथा उनके मूल्य कात्पनिक हैं।

मूल्य-स्तर निर्देशाव क्रमशः १०० और २८७ $\frac{1}{2}$  आते हैं। अर्थात् १९३६ की अपेक्षा मूल्य-स्तर बढ़ गया है तथा यह वृद्धि १८७ $\frac{1}{2}$  प्रतिशत है। दूसरे घब्दों में मुद्रा का मूल्य १८७ $\frac{1}{2}$ % कम हो गया है।

**भारतीय निर्देशाव**—यह निर्देशाव बनाने की दूसरी पद्धति है जिसके अनुसार वस्तुओं के महत्त्व के अनुसार उनको कुछ भार दिया जाता है। जिन वस्तुओं के लिए निर्देशाव तैयार किये जाते हैं उनमें सब वस्तुओं का महत्त्व एकसा न होते हुए, कुछ वस्तुओं का महत्त्व अधिक एवम् कुछ का कम होता है। इसलिए प्रत्यक्ष उपयोग के लिए भारतीय निर्देशाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं विश्वस्तनीय माने जाते हैं। जिन वस्तुओं को अधिक महत्त्व दिया जाता है उनकी कीमतों में परिवर्तन होने से जीवनमान में भी परिवर्तन होने की सम्भावना रहती है क्योंकि आय का अधिक भाग उन पर खर्च होता है। किन्तु जो वस्तुएँ कम महत्त्वपूर्ण होती हैं उन पर कम खर्च होता है तथा उनकी कीमतों में परिवर्तन होने से जीवनमान में परिवर्तन होने की सम्भावना कम होती है। प्रत्यक्ष वस्तु को यह भार उसी परिमाण में दिया जाना चाहिए जितना उपभोग में उसका वास्तव में महत्त्व है। अब हम पहले उदाहरण को ही भारतीय निर्देशाव में परिवर्तन करेंगे।

मान लीजिए<sup>१</sup> कि दूध, शक्कर, चाय तथा कोयले का क्रमशः ४, १, २ और १ महत्त्व की दृष्टि से भार है। १९३६ की कीमतों को हम पूर्ववत् १०० में परिणित करके, उनको उनके भार से गुणा करेंगे। फिर जो योग आया उसका औसत वस्तुओं के कुल भार से विभाजित करके निकालेंगे। यही औसत १९३६ का भारतीय निर्देशाव होगा। इसी प्रकार १९४८ के मूल्यों को भी हम १९३६ के मूल्यों की तुलना करते हुए १०० में परिणित करेंगे तथा उन कीमतों को उनके भार से गुणा करके वस्तुओं के कुल भार से विभाजित करेंगे। भागफल हमारा औसत होगा जो १९४८ के मूल्यों का भारतीय निर्देशाव होगा।

अब दोनों निर्देशावों की तुलना में हमको यह आश्चर्य हो जायगा कि कितने प्रतिशत मूल्य-स्तर में वृद्धि या कमी हुई है। उदाहरणार्थ, पहले उदाहरण को ही हम भारतीय निर्देशाव में परिणित करेंगे जिससे दोनों पद्धतियों का भेद स्पष्ट हो जायगा।

<sup>१</sup> यह उदाहरण काल्पनिक है।

वस्तुएँ	१९३६ का मूल्य स्तर			१९४८ का मूल्य-स्तर		
	वास्तविक मूल्य	भार	हिटलर	वास्तविक मूल्य	आधार वर्ष में तुलनात्मक मूल्य	भारतीय परिवर्तित मूल्य
दूध	४ आने सेर	४	४००	१ ६० सेर	४००	$\times 4$ = १६००
शक्कर	३ आने सेर	३	३००	७३ आ० सेर	२५०	$\times 3 = ७५०$
चाय	१ ६० पाउंड	२	२००	२ १० पाउंड	२००	$\sqrt{2} = ४००$
कोयला	१ आने सेर	१	१००	३ आने सेर	३००	$\times 1 = ३००$
याग		१०	१०००			३०५० — १०
निर्देशांक	( औसत )		१००			३०५

उपर्युक्त भारतीय निर्देशांक में यह स्पष्ट होता है कि १९३६ तथा १९४८ के निर्देशांक १०० तथा ३०५ है। अतः तुलनात्मक दृष्टि से १९४८ के मूल्य स्तर में २०५ प्रतिशत वृद्धि हुई है। हमारे शब्दों में मुद्रा का मूल्य २०५ प्रतिशत कम हो गया है।

यदि हम दोनों पद्धतियों के निर्देशानुसार की तुलना करें तो सामान्य निर्देशांक और भारतीय निर्देशांक से प्रदर्शित मूल्य-वृद्धि में बहुत अधिक अन्तर है जिसकी सम्भावना का कारण यह हो सकता है कि हमने वस्तुओं को जो भार दिया है वह उनके वास्तविक उपभोग के महत्त्व में अधिक हो। अतः भारतीय निर्देशांक कम विश्वसनीय होने है, किन्तु सामान्य निर्देशांक से हम वस्तु स्थिति का ठीक अनुमान लगा सकते हैं। परन्तु इनको तैयार करने में वस्तुओं का चुनाव ठीक होना तथा उनकी कीमत ठीक प्रकार ली जाना आवश्यक है। सामान्य निर्देशांक बनाते समय यदि अधिक सख्या में वस्तुओं का समावेश किया जाय तो सामान्य निर्देशांक अधिक विश्वसनीय हो सकते हैं।

**निर्देशांक बनाते समय ध्यान में रखने योग्य सूचनाएँ**

१. आधार-वर्ष का चुनाव—सबसे पहिले आधार वर्ष का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए। यह वर्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें ऐसी कोई भी

घटना न घटी हो जिसके कारण वस्तु-मूल्यो में अधिक अन्तर पड़े क्योंकि उस अवस्था में निर्देशान तैयार करने का मूल हेतु—अर्थान् मुद्रा की क्रयशक्ति पर क्या प्रभाव हुआ, यह जानना—सफ़्त नहीं हो सकता। दूसरे, ऐसे वर्ष के मूल्य-स्तर उस आन्तरिक घटना में प्रभावित हान व कारण मूल्य-स्तर का भी ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। फिर भी आधार-वर्ष कोनसा लिया जाय यह निर्देशान बनाने के उद्देश्य पर निर्भर है। उदाहरणार्थ, युद्ध के पहिले तथा युद्ध के बाद के मूल्य स्तर की तुलना करने के लिए युद्ध-पूर्व वर्ष १९३६ लेना ही लाभकर होगा।

२. वस्तुओं का चुनाव—निर्देशान में तब वस्तुओं का समावेश किया जाय, इसमें भी सावधानी की आवश्यकता है। यह वस्तुएँ ऐसी हानी चाहिए जिनमें निर्देशान बनाने का हमारा उद्देश्य सफल हो सके। उदाहरणार्थ, यदि श्रमिकों के जीवन स्तर के अन्तर को हम जानना चाहते हैं तो वस्तुएँ ऐसी हो जो अधिकतर श्रमिकों के उपभोग में आती हों और सामान्य जनता का जीवन-स्तर जानना हो तो सर्व-साधारण के उपभोग की वस्तुओं को ही निर्देशान बनाने के लिए लेना होगा। ये वस्तुएँ देश, काल एवं परिस्थिति के अनुसार भिन्न होंगी। अधिक से अधिक वस्तुओं का समावेश निर्देशान बनाने समय करना चाहिए जिनमें विवक्षणीय परिणाम पर पहुँच सकें। इस कार्य में विभिन्न वस्तुओं के सामाजिक एवं आर्थिक महत्त्व का भी ध्यान में रखना होगा क्योंकि सभी वस्तुओं का महत्त्व समान नहीं होता।

३. वस्तुओं की कीमतें—वस्तुओं की कीमतों का समावेश करते समय भी सावधानी रखनी चाहिए। वस्तुओं की कीमतें बिक हो अथवा फुटकर यह बात निर्देशान बनाने के उद्देश्य पर निर्भर रहेगी। यदि जीवन-स्तर मासूम करना है तो फुटकर मूल्य लेना होगा। इसके विपरीत, यदि निर्देशान अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की जानकारी के लिए हो तो अन्तरराष्ट्रीय मूल्य तथा विदेशी व्यापार में आनेवाली वस्तुओं को ही लेना पड़ेगा। इसके साथ ही, वस्तुओं के मूल्य सही हैं, यह देखना भी आवश्यक है।

४. वस्तुओं की संख्या—निर्देशान विश्वसनीय होने के लिए यह भी आवश्यक है कि वस्तुओं की संख्या अधिक हो। जितनी ही वस्तुओं की संख्या अधिक होगी उतनी प्रामाणिकता निर्देशानों की बढ़ेगी। वस्तुओं की संख्या जितनी हो इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता अपितु वस्तुओं की संख्या साधारणतः निर्देशान के हेतु पर निर्भर रहेगी। भारत-सरकार के आर्थिक मन्त्रालय के मत से २२ संख्या पर्याप्त है।

५. मूल्य के अनुपातो का औसत—मूल्य के अनुपातो का औसत भी बहुत ही सावधानी से निकालना, चाहिए, जिसमें उसमें किसी प्रकार की भूल न हो जाय। औसत निकालने की भिन्न-भिन्न विधियाँ हैं जिस सम्बन्ध में अभी तक एक मत नहीं हुआ है। परन्तु सामान्यतः अद्भुतगणित औसत से ही काम लिया जाता है और यह पद्धति भरन भी है।

निर्देशांक बनाने की कठिनाइयाँ

इतनी सब सावधानी रखते हुए भी निर्देशांक मुद्रा के मूल्य-परिवर्तन को अथवा वस्तुओं के मूल्य-स्तर को नहीं-सही दिग्दर्शित नहीं करते क्योंकि वे केवल मूल्य-स्तर का मध्यम मान (average mean) बताते हैं तथा मुद्रा के प्रसार अथवा सिकोच में होने वाले परिणामों को नहीं बता सकते। किन्तु मुद्रा के मूल्य-परिवर्तन का हम अनुमान लगा सकते हैं। अतः रॉबर्टसन के शब्दों में “तात्पर्य यह कि मुद्रा के मूल्य-परिवर्तनों का ठीक से माप लेना न सैद्धान्तिक दृष्टि से और न प्रत्यक्ष व्यवहार में ही सम्भव है। हाँ, मुद्रा-मूल्य में परिवर्तन होता है और यदि पर्याप्त सावधानी रखी गई तो प्रत्यक्ष उपयोग के लिए उसका माप ठीक रीति से लिया जा सकता है।”<sup>१</sup>

निर्देशांकों के बनाने में वास्तव में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं जिनकी वजह से हमारा निर्देशांक की सहायता से निकाला हुआ परिणाम गलत हो सकता है। इसलिये मार्शल ने कहा है कि “क्रयशक्ति का पूर्णतः नहीं माप लेना असम्भव ही नहीं किन्तु विचारणीय भी नहीं है।”<sup>२</sup> ये कठिनाइयाँ निम्नलिखित हैं—

१. आधार-वर्ष का चुनाव अत्यन्त कठिन होता है—आधार-वर्ष का चुनाव ही निर्देशांक में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है क्योंकि यदि गलती से भी कोई ऐसा वर्ष चुन लिया जाय जिसमें कोई विशेष घटनाएँ न हों तो उससे हमारा निकाला हुआ निर्देशांक कभी भी नहीं नहीं होगा। इस कठिनाई को दूर करने के लिए विदेशों में सामान्यतः ५ वर्षों के मूल्य-स्तर का औसत लेकर उसे आधार वर्ष मानते हैं—उदाहरणार्थ, इकॉनॉमिस्ट के निर्देशांक जो १९४५-१९५० की औसत कीमतों को आधार मानते हैं।

२. वस्तुओं के चुनाव में कठिनाई—वस्तुएँ चुनने में कठिनाई इसलिए

<sup>१</sup> *Money by Robertson*, p 27

<sup>२</sup> “A perfectly exact measure of purchasing power is not only unattainable but even unthinkable.”—*Marshall*.

प्रतीत होती है क्योंकि मांगवी आवश्यकताएँ स्थिर अथवा एकत्री न रहते हुए उनमें समयानुसार परिवर्तन होता रहता है अथवा अनेक चीजों के लिए माँग भी नहीं रहती। उदाहरणार्थ, आजरल नेकटाई की माँग पहिल की तुलना में कम हो गई है, इसके विपरीत खद्दर के कपड़े की माँग बढ़ गई है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खद्दर पहिन कर नेता बनने अथवा कहलाने का इच्छुक है।

३ कीमतों सम्बन्धी कठिनाई—प्रत्येक वस्तु की कीमत प्राप्त करना भी इतना सुलभ नहीं होता। दूसरे, निर्देशांक बनाते समय उनकी थोड़ी कीमतें ली जायँ अथवा फुटकर। इसके साथ ही फुटकर कीमतों एवं थोक कीमतों में परिवर्तन भी कभी एक साथ नहीं होना। थोक कीमतें कम हो सकती हैं परन्तु फुटकर कीमतें वही रह सकती हैं। इससे यथाया कुद्द व्यापार वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं के थोक भाव भी विवक्षनीय रूप से नहीं जाने जा सकते क्योंकि सभी वस्तुओं के थोक भाव प्रसारित नहीं होते हैं। फिर जिस वस्तु के थोक भाव मालूम भी हों वह किस प्रकार की है इसके विषय में हमको कुछ भी नहीं मालूम होता।

४ व्यवहारिक कठिनाई—उपर्युक्त कठिनाइयों के अतिरिक्त औसत निकालने की कठिनाई रहती ही है कि कौनसी पद्धति का उपयोग किया जाय। मान लीजिए कि औसत निकाल भी लिया जाय, तब भी हम निर्देशांक का विभिन्न देशों की मुद्रा का मूल्य जानने के लिए उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि विभिन्न देशों की सभ्यता, संस्कृति एवं आर्थिक स्तर में भिन्नता होती है। हाँ, हम औसत अनुमान लगा सकते हैं कि मुद्रा-मूल्य गिर रहा है अथवा नहीं। इसीलिए निर्देशांक का मूल्य नापने का एक औसत साधन माना जाता है परन्तु सही साधन नहीं।

निर्देशांक बनाने से लाभ

निर्देशांक वस्तुओं की कीमतों का अथवा मुद्रा के मूल्य का औसत स्तर किस ओर जा रहा यह बताने हुए भी अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों एवं शासन के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं। निर्देशांक से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं—

१ निर्देशांक के द्वारा हम क्रयशक्ति के परिवर्तन को जान सकते हैं। ये परिवर्तन अर्थशास्त्र के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं क्योंकि इनसे किसी भी देश के जीवन-स्तर के परिवर्तनों को जाना जा सकता है।

२ क्रयशक्ति परिवर्तन से मिला मिला समय में तथा भिन्न भिन्न देशों में जनता की आय तथा श्रमिकों के वेतन में क्या अन्तर पड़ता है, इसकी जानकारी

प्राप्त होती है तथा निर्देशावली के द्वारा वेतन-स्तर में समायोजन (adjustment) करना सम्भव होता है।

३ मुद्रा-संकोच अथवा मुद्रा-प्रसार के कारण क्रयशक्ति पर क्या एवं कितना प्रभाव पड़ता है, इसको ध्यान दिया जाता है।

४ दीर्घकालीन ऋणों के भुगतान में समता लाने के लिए निर्देशावली अधिक उपयोगी हैं क्योंकि इनके द्वारा क्रयशक्ति की कमी या बढ़ती का माप मिलता है।

५ फिस्कर, वीन्स आदि अर्थशास्त्रियों के मतानुसार वस्तुओं का मूल्य-स्तर स्थिर रखने के लिए तथा व्यापार में स्थायित्व लाने के लिए ये बहुत उपयोगी हैं क्योंकि कीमतों के परिवर्तन के कारण व्यापार एवं उद्योगों पर क्या प्रभाव हुआ यह निर्देशावली की सहायता से जाना जा सकता है।

६ सरकार के लिए तथा वैयक्तिक दृष्टि से भी विभिन्न देशों की मौद्रिक धातु के मूल्य की तुलना करने में निर्देशावली सहायक होते हैं जिससे मौद्रिक धातु के मूल्य की अधिकता के अनुसार अपने खर्चों का अथवा विनियोगों का समायोजन सम्भव हो सके।

इस प्रकार निर्देशावली की सहायता में मूल्य-स्तर में होने वाले परिवर्तन जाने जा सकते हैं तथा उनसे समाज के विभिन्न वर्गों पर होने वाले परिणाम जाने सकते हैं, जिससे मुद्रा मूल्य में स्थिरता लाने के प्रयत्न इनकी सहायता में किये जा सकते हैं। उसी प्रकार मजदूरी एवं धातु का समायोजन करने के लिए भी ये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। उदाहरणार्थ भारत में मंहगाई भत्ते में परिवर्तन इन्हीं निर्देशावली की सहायता में किया जाता है।

हमके विवाय अर्थशास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी को देश के आर्थिक जीवन में होने वाली उधम-गुथम का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करने के लिए तथा किसी विशेष निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए निर्देशावली अत्यन्त सहायक प्रमाणित हुए हैं।

इसी प्रकार व्यापारियों की दृष्टि से भी निर्देशावली अत्यन्त उपयोगी है क्योंकि निर्देशावली की सहायता में पूँजी व्यापार में होने वाले उत्तर-व्यत्यय तथा धातु के परिवर्तनों को जान सकते हैं जिससे वे अपनी विनियाम-क्रियाओं का नियन्त्रण सफलता से कर सकते हैं। इसी प्रकार व्याज-दर, मजदूरी आदि का मूल्य स्तर के साथ समायोजन करने के लिए भी निर्देशावली अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुए हैं। इस प्रकार निर्देशावली अर्थशास्त्र, व्यापारी एवं इतिहास के

विद्यार्थी के लिए तुलनात्मक अध्ययन का एक उपयोगी साधन है जिसके व्यावहारिक महत्त्व की किसी भी तरह कम नहीं आवा जा सकता ।

### विश्वसनीय निर्देशाव-स्रोत

विभिन्न देशों में विश्वसनीय निर्देशाव प्राप्त करने के स्रोत निम्नलिखित हैं

इङ्गलैण्ड में 'सॉर्रेव' तथा 'इक्वॉलिमिस्ट' ये दोनों संस्थाएँ अपने निर्देशाव बनाने के लिए क्रमशः ६५ और २२ वस्तुओं का समावेश करती हैं । भारत में श्रीमती के जीवन-स्तर सम्बन्धी बम्बई श्रम-मन्त्रालय के निर्देशाव तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के निर्देशाव विश्वसनीय स्रोत हैं । संयुक्त राज्य अमेरिका में 'व्यूरो ऑफ लबर स्टैटिस्टिक्स' व तथा संयुक्त राज्य में श्रम मन्त्रालय तथा 'बोर्ड ऑफ ट्रेड' के निर्देशाव विश्वसनीय हैं ।

### सारांश

निर्देशाव क्या है—मूल्य स्तर के चढ़ाव-उतार की नापने की क्रिया को ही मूल्य निर्देशाव कहते हैं ।

बनाने की विधियाँ (१) सामान्य निर्देशाव—जिस वर्ष के मूल्यों की तुलना करनी हो उसे आधार वर्ष मानकर उसके मूल्यों को १०० में परिणित किया जाता है । उद्देश्य के अनुसार वस्तुओं की संख्या तथा गुण एवं उनका मूल्य लेना चाहिए । परिणित मूल्यों का योग करके उसमें वस्तुओं की संख्या से भाग देंगे । इसी प्रकार जिस वर्ष के मूल्यों की तुलना करनी है उसके मूल्यों को भी आधार वर्ष के मूल्यों की तुलना में १०० में परिणित करके इनके योग को वस्तुओं की संख्या में भाग देंगे । भागफल निर्देशाव होगा । दोनों वर्षों के निर्देशावों की तुलना करके मूल्य के उतार चढ़ाव की नाप की जा सकती है ।

(२) भारतीय निर्देशाव—वस्तु के उपभोग के महत्त्व के अनुसार उसे एक भार दिया जाता है । आधार वर्ष के मूल्यों को १०० में परिणित करके भार से गुणा किया जाता है । भारतीय मूल्यों के योग को भार के योग से भाग देने पर आधार वर्ष का निर्देशाव प्राप्त होगा । इसी प्रकार तुलना किये जाने वाले वर्ष के मूल्यों को आधार वर्ष के मूल्यों की तुलना करते हुए १०० में परिणित करेंगे तथा भारतीय मूल्यों के योग को भार के योग से भाग देंगे । भागफल भारतीय निर्देशाव होगा ।

निर्देशांक बनाते समय ध्यान में रखने योग्य बातें—

१. आषाढ वर्ष का चुनाव,
२. वस्तुओं का चुनाव,
३. वस्तुओं की कीमतें,
- ४ वस्तुओं की संख्या,
- ५ मूल्य के अनुपातों का औसत ।

साम १ क्रयशक्ति के परिवर्तन का ज्ञान; २. चैतन-स्तर में समायोजन करना सम्भव; ३ मुद्रा प्रसार एवं संकोच का क्रयशक्ति पर प्रभाव; ४ दीर्घ-कालीन ऋण-शोधन में समता लाना; ५ वस्तुओं का मूल्य-स्तर स्थिर रखना तथा व्यापार में स्थायित्व; ६ सरकार को विभिन्न देशों की मौद्रिक आय के मूल्यों की तुलना करने में सहायक ।

## मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संकोच

मुद्रा-परिमाण में वृद्धि या कमी होना में वस्तुओं की कीमतें सामान्यतः प्रभावित होती हैं, यह हमने पिछले अध्याय में देखा। मुद्रा परिमाण में यदि माँग से अधिक वृद्धि होती है तो उस समय वस्तुओं का मूल्य-स्तर बढ़ने लगता है अथवा मुद्रा का अवमूल्यन (depreciation of money) होने लगता है अर्थात् वही मुद्रा पहले की अपेक्षा कम वस्तुएँ खरीद सकती है। इसके विपरीत जब किसी कारणों से माँग की अपेक्षा मुद्रा-परिमाण में कमी की जाती है तो वस्तुओं का मूल्य-स्तर घटने लगता है या कीमतें गिर जाती हैं अथवा वही मुद्रा अब पहले की अपेक्षा अधिक चीजें खरीद सकती है। ऐसी अवस्था में मुद्रा का अधिमूल्यन (appreciation of money) होता है। मुद्रा की माँग की अपेक्षा अधिक वृद्धि करने की क्रिया को हम मुद्रा-स्फीति (inflation) तथा कम करने की क्रिया को मुद्रा-संकोच (deflation) कहते हैं।

मुद्रा-स्फीति अथवा मुद्रा का अवमूल्यन—जब माँग की अपेक्षा मुद्रा की पूर्ति अधिक होने के कारण वस्तुओं का मूल्य-स्तर अधिक बढ़ने लगता है तब उसे मुद्रा स्फीति कहते हैं। यह मुद्रा-स्फीति अथवा वस्तुओं के मूल्य-स्तरों में वृद्धि तीन कारणों से होती है :<sup>1</sup>

( १ ) साधारण परिस्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन हुए बिना यदि देश का उत्पादन घट जाता है तथा मुद्रा की मात्रा वही रहती है।

( २ ) यदि उत्पादन एवं बिक्री के लिए वस्तुओं में किसी प्रकार की कमी अथवा अधिकता न होते हुए मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाती है।

( ३ ) उत्पादन एवं बिक्री के लिए वस्तुएँ तथा मुद्रा की पूर्ति उन्नी प्रकार रहते हुए यदि साम्र की मात्रा अधिक हो जाती है।

मुद्रा-संकोच अथवा मुद्रा का अधिमूल्यन—मुद्रा-स्फीति के विपरीत यदि मुद्रा की पूर्ति उसकी माँग की अपेक्षा कम होने से वस्तुओं के मूल्य-स्तर में गिरावट

<sup>1</sup> *Money by Kinley, pp 179-181*

आती है तब उसे मुद्रा सकोच कहते हैं। मुद्रा सकोच के कारण मुद्रा स्फीति के विपरीत हैं।

मुद्रा सकोच अथवा मुद्रा का अधिमूल्यन उम क्रिया को कहते हैं जिससे मुद्रा का चलन माग की अपेक्षा बहुत कम हो जाता है।

### मुद्रा-स्फीति के कारण

मुद्रा स्फीति अनेक कारणों से हाता है। कुछ प्राकृतिक तो कुछ बनावटी कारण भी होन हैं।

प्राकृतिक कारणों में हम एस कारणों का समावेश करेंगे जो सरकार के नियन्त्रण में नहीं होत जैसे सोने या चांदी का खानों से अधिक उत्पादन होना नई खानों की खोज तथा सोना चांदी का अधिक मात्रा में आयात होने लगना। यदि स्वर्ण के अधिक आयात के कारण अथवा स्वर्ण की पूर्ति बढ़ने के कारण मूल्य-स्तर बढ़ते हैं तो उसे स्वर्ण मुद्रा-स्फीति (gold inflation) कहते हैं।

बनावटी कारणों में वे कारण होते हैं जिन्हें सरकार राष्ट्रीय वज्रट को सन्तुलित करने के लिए कार्य में लाती है। जैसे किता सकट काल में अथवा युद्धकाल परिस्थिति में सरकार को जब अधिक व्यय करना पड़ता है उस समय या तो ऋण लेकर काम हो सकता है या फिर पत्र मुद्रा का चलन बढ़ाकर। ऐसी अवस्था में आवश्यकता से अधिक पत्र मुद्रा चलन में लाई जाती है। इस अवस्था में उसे चमाथ मुद्रा स्फीति (currency inflation) कहते हैं। दूसरे मुद्रा के चलन में कमी न होने हुए जब उत्पादन घटने लगता है उस अवस्था में विनिमय के लिए वस्तुओं की कमी के कारण कीमत बढ़ने लगती हैं। इस अवस्था में उसे उत्पादन स्फीति (production inflation) कहते हैं। इसी प्रकार जब धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा का परिमाण घट्टी रहने हुए सोने मुद्रा की पूर्ति माग की अपेक्षा अधिक हो जाती है और वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है तब उसे साख स्फीति (credit inflation) कहत हैं। जिस समय किसी भी देश में पत्र मुद्रा का चलन माग से इतना अधिक हो जाना है कि जनता का विश्वास उस मुद्रा में उठ जाय तब ऐसी अवस्था में उस मुद्रा का मूल्य जिसकी वह बनाई जाती है उससे भी कम हो जाता है। इसका उदाहरण हमारा चीन के अथवा जपान के इतिहास से मिलता है। इस प्रकार की स्फीति को अति स्फीति (hyper inflation) कहते हैं। इसी प्रकार उत्पादन क्षमता में कमी कभी ऐसा होना है कि उत्पादन के साधनों

का मूल्य वही रहता है परन्तु प्रत्येक साधन की उत्पादन क्षमता बढ़ने से उत्पादन का परिमाण बढ़ जाता है जिससे उत्पादन का लाभ भी बढ़ जाता है। परन्तु इस लाभ का वितरण उत्पादन के अन्य माधना का न करत हुए उत्पादक स्वयं ही हृष्य जाता है तब उस लाभ-स्फीति (profit inflation) कहते हैं।

दूसरे जब देश के उद्योग घटा का प्रिनाम करने के लिए दस की सरकार तसार के मूल्य स्तर की अपेक्षा दस का आन्तरिक मूल्य-स्तर ऊँचा करना चाहती है तब वह माँग की अपेक्षा मुद्रा का पुनि घटा देता है।

### मुद्रा-संकोच के कारण

( १ ) पहिला कारण यह है कि जब उत्पादन की मात्रा घटती है तथा मुद्रा परिमाण पूर्ववत् रहता है उस अवस्था में मुद्रा विनिमय के लिए वस्तुएँ अधिक हो जाने से मुद्रा की क्रयशक्ति बढ़ जाता है तथा कीमत गिरने लगती है।

( २ ) जिस समय किसी कारण से सरकार दस का मुद्रा का परिमाण कम कर देती है और उत्पादन अथवा विनिमय के लिए प्राप्त वस्तुओं की संख्या में कमी नहीं आती उस समय भी मुद्रा की क्रयशक्ति बढ़ने लगती है अथवा कीमत गिरने लगती है।

( ३ ) उत्पादन एवं विन्याय वस्तुओं में तथा पनमुद्रा एवं धातुमुद्रा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन न होने हुए भी यदि रिमा कारण से साल का उपयोग कम हो जाता है तो ऐसा देश में माँग का कम हो कारण उपद्रव मुद्रा एवं माँग माधना में हो विनिमय हो सकता है। परिणामस्वरूप वस्तुओं की कीमत गिरने लगती अथवा मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा।

### मुद्रा स्फीति एवं संकोच का प्रभाव

मुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा संकोच जिस समय किसी देश में होता है उस समय प्रत्येक वस्तु की कीमत न तो एकसी रहती है और न प्रत्येक वस्तु की कीमत गिरती है। बल्कि कुछ वस्तुओं की कीमत गिरती है तथा कुछ वस्तुओं का कीमत बढ़ता है और मूल्य स्तर में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है। अर्थात् मुद्रा-स्फाति की अवस्था में मूल्य स्तर बढ़ने लगता है और मुद्रा-संकोच की अवस्था में मूल्य-स्तर घटने लगता है जिसका अनुमान निर्देशाङ्क से लगाया जा सकता है। कामत जिस समय बढ़ता या घटता है उस समय समाज के विभिन्न वर्गों पर विभिन्न परिणाम होते हैं क्योंकि किसान भी

समाज में कुछ देनदार होते हैं तथा कुछ लेनदार, कुछ उत्पादक (producers) या व्यापारी होते हैं, कुछ लोग श्रमिक या निश्चित वेतन पाने वाले कर्मचारी होते हैं तथा सभी लोग उपभोक्ता होने हैं। इनमें से प्रत्येक वर्ग की आर्थिक शक्ति भी भिन्न होती है। इस विभिन्नता की दृष्टि से प्रो० कीन्स ने समाज का वर्गीकरण इस प्रकार किया है —

- १ विनियोगकर्ता (investing class) ( विनियोक्ता )
- २ व्यापारी अथवा उत्पादक वर्ग , तथा
- ३ श्रमिक एवं कर्मचारी वर्ग ।

**मुद्रा-स्फीति ( अथवा मुद्रा के अवमूल्यन ) के परिणाम**

१ बढ़ती हुई कीमतों से व्यापारियों तथा उत्पादकों का लाभ बढ़ता है जिससे उत्पादन एवं व्यापार कार्य में वृद्धि होती है क्योंकि उत्पादन मूल्य जिस परिमाण में कीमतें बढ़ती हैं उसी परिमाण में नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से लाभ बढ़ता है तथा व्यापार एवं उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। यदि कीमतें क्रमशः बढ़ती रही तो उत्पादन एवं व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। इसके विपरीत यदि तीव्र गति से कीमतें बढ़ती हैं तो व्यापार में अनिश्चितता आ जाती है और मट्टेबाजी शुरू होकर अनंतिकता फैलती है जिसका व्यापार तथा देश पर बुरा परिणाम होता है। उत्पादक के नाते किसानों पर भी यही परिणाम होते हैं।

२ बढ़ती हुई कीमतों के समय लेनदारों को लाभ होता है क्योंकि मुद्रा की क्रयशक्ति कम होने से वे वस्तुओं में कम भुगतान करते हैं। इस समय लेनदारों को हानि होती है क्योंकि वे उनकी ही मुद्रा से अब पहिले की अपेक्षा — मुद्रा की क्रयशक्ति कम होने से — कम वस्तुएँ ले सकते हैं। हम यह जानते हैं कि व्यापारियों का कार्य भी लेन देन से ही चलता है और जहाँ तक लेन-देन का सम्बन्ध है, वे भी लेनदार तथा देनदार होते हैं। अतः देनदार व्यापारी की दृष्टि से उसे लाभ होता है एवं लेनदार व्यापारी को हानि होती है।

३ श्रमिक तथा कर्मचारी वर्ग को मुद्रा स्फीति अथवा मुद्रा के अवमूल्यन के समय हानि ही होती है क्योंकि मुद्रा की क्रयशक्ति कम हो जाने से वे अपनी निश्चित आय में कम वस्तुएँ खरीद सकते हैं तथा उनकी वास्तविक आय कम हो जाती है। जहाँ तक उत्पादन कार्य में वृद्धि होती है वहाँ तक उनको लाभ होता है क्योंकि रोजगार बढ़ जाता है और अधिक आयों को काम मिलता है। फिर भी तीव्र गति से जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ने लगती

है तब उनकी हानि ही होती है। यह बतल जा सकता है कि उनकी महंगाई-भत्ता आदि भी दिया जाता है किन्तु यह तत्त्वान नहीं दिया जाता और न मूल्य-स्तर निर्देशक के अनुसार उमम वृद्धि ही होती है। इसके अतिरिक्त यह भत्ता या लाभ भी उन्हीं दशा में जन्दी मिलता है जहाँ पर धन-संगठन अच्छी प्रकार से है किन्तु पिछड़े हुए दशा में धर्मिका को बुरी तरह हानि होती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण भारत में देखने को मिलता है।

४ कीमत बढ़ने समय सरकार को लाभ होता है क्योंकि इन समय में सरकार का ऋण भाग कम हो जाता है अथवा पुनः ऋण पत्रों का कम व्याज के नये ऋण-पत्रों में बदल दिया जाता है। व्यापारिक एवं औद्योगिक विकासा में वृद्धि होने के कारण सरकार का आय और अथवा व्यय कम रूप में अधिक आय होती है। इस अवस्था में सरकार नये-नवीन विधान योजनाएँ बनाकर राष्ट्रीय आय की वृद्धि करती है। परन्तु इसके विपरीत सामाजिक उन्नति-मुयन के कारण सरकारी व्यय भी बढ़ जाने से जिनमें बचत में घटा होने लगता है और आय-व्यय का सम्बलन जगड़ जाता है।

५ व्यापार में वृद्धि होने के कारण विनियोगकर्ताओं को मुद्रा लाभ होता है क्योंकि उनके विनियोग-पत्रों के मूल्य बढ़ जाते हैं। परन्तु जहाँ तक लाभान्वित एवम् व्याज का सम्बन्ध है, वह निश्चित मात्रा में ही मिलता है, प्रत्यक्ति कम होने से उनकी हानि ही होती है क्योंकि एक ओर तो विनियोग-पत्रों का मूल्य बढ़ता है और दूसरी ओर वस्तुओं की कीमतें। अतः उनकी वास्तविक आय घटती है। परन्तु औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिलने के कारण पूँजी की माँग बढ़ती है जिससे विनियोग-बाजार तथा पूँजी-बाजार में गर्माहट होती है और अधिक व्याज मिलने की सम्भावना से नये-नये उद्योगों का विकास होता है।

६ मुद्रा-स्फीति का विदेशी व्यापार पर भी बुरा असर पड़ता है क्योंकि ससार के मूल्य-स्तर से आन्तरिक मूल्य-स्तर ऊँचा होने से मुद्रा-स्फीति वाले देश में बाल महंगा हो जाता है। फलस्वरूप विदेशी बाल बाल कम खरीदते हैं अतः निर्यात कम होते हैं। इसके विपरीत विदेशी वस्तुएँ सस्ती होने से उनका आयात बढ़ जाता है। घटते हुए निर्यात एवं बढ़ते हुए आयात के कारण व्यापारिक लेख (trade balance) मुद्रा-स्फीति वाले देश के विपक्ष में हो जाता है।

७ सर्व-सामान्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने से देश के उपभोक्ताओं को

हानि होती है क्योंकि पूर्ववत् जीवन स्तर रखने के लिए उनको अधिक व्यय करना पड़ता है ।

इस प्रकार से मुद्रा स्फीति से कुछ मर्यादा तक तो लाभ होता है किन्तु यदि यह तीव्र गति से बढ़ता ही गया तो व्यापार एवं उत्पादन में अस्थिरता आ जाती है सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाता है तथा अन्त में भयंकर राष्ट्रीय हानि होती है ।

**मुद्रा सकोच (अथवा मुद्रा के अधिमूल्यन) के परिणाम**

मुद्रा-सकोच के समय विभिन्न वर्गों पर मुद्रास्फीति के विपरीत परिणाम होते हैं ।

१ इसमें वस्तुआँगा उत्पादन घट जाना से उत्पादक वर्ग को तथा किसानों को हानि होती है जबकि उत्पादन शक्ति में निश्चिन्ता आ जाती है । असम्भाव्य हानि के कारण अनेक उद्योग नष्ट हो जाते हैं जिससे देश में आर्थिक अस्थिरता और बेकारी फैल जाती है जिसको दूर करने के लिए सरकार को बहुत खर्च करना पड़ता है और सरकारी बजट असन्तुलित हो जाता है ।

२ घटती हुई कीमतों के कारण देनदारों को हानि तथा लेनदारों को लाभ होता है क्योंकि उसी मुद्रा से लेनदार अधिक वस्तुएँ खरीद सकते हैं तथा उसी मुद्रा को लौटाने में देनदार अधिक क्रयशक्ति देते हैं जिससे उन्हें हानि होती है ।

३ थमिक अथवा कर्मचारी वर्ग को कीमतों के घटने से लाभ होता है क्योंकि ये अब निश्चित आय में अधिक वस्तुएँ खरीद सकते हैं । परन्तु यदि तीव्र गति से कीमत घटती गई तो उद्योग बंद हो जाते हैं तथा बेकारी फैलती है । अतः क्रमशः होने वाले अधिमूल्यन अथवा सकोच के समय इस वर्ग को लाभ होता है तथा तीव्र गति से होने वाले सकोच में हानि होती है क्योंकि उन्हें बेकारी का सामना करना पड़ता है ।

४ कीमत घटने से मुद्रा की क्रयशक्ति बढ़ जाती है, जिससे सरकार पर ऋण भार बढ़ जाता है । बेकारी आदि की नई समस्याएँ उपस्थित होती हैं जिनके ऊपर सरकारी व्यय बढ़ता है तथा बजट में असन्तुलन होता है । इसी प्रकार औद्योगिक निश्चिन्ता के कारण सरकारी आय भी घट जाती है ।

५ विनिमयकर्ताओं को जहाँ तक लाभार्थ एवं व्याज का सम्बन्ध है, उसी मात्रा में मिलता है तथा कीमत घटने से उसी मुद्रा से वे ज्यादा वस्तुएँ खरीद सकते हैं अर्थात् उनको लाभ होता है ।

६ विदेशी व्यापार पर मुद्रा-संकोच का परिणाम अच्छा होता है क्योंकि इस देश की कीमते गिर जाने से विदेशी यहाँ में अधिक मात्र खरीदने हैं जिनमें निर्यात में वृद्धि होती है। तुलनात्मक दृष्टि में विदेशों में वस्तुएँ महंगी होने में आयात कम होता है। परिणाम स्वरूप व्यापारिक मन्तुवन इस देश के पक्ष में होता है।

७ उपभोक्ताओं को वस्तुओं की कीमते गिर जाने में लाभ होता है क्योंकि उनका जीवन-स्तर पर हानि वाला भत्ता कम होता है।

उपसुंक्ष्ण विभिन्न लाभ-हानियों में यह स्पष्ट होता है कि तीव्र गति में होने वाला मुद्रा-संकोच के समय देश को हानि ज्यादा उठानी पड़ती है। इसलिए अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मुद्रा-स्फीति तथा मुद्रा-संकोच में मुद्रा का संकोच सबसे हानिकारक है। वैसे तो दाना में हों सम्पत्ति वितरण में समता नहीं रहती इसलिए मूल्य-स्तर में स्थायित्व होना ही देश एवं समाज की दृष्टि में लाभदायक है क्योंकि इसमें देश के ग्राहक टाँचे में संतुलन रहता है तथा व्यापार, उत्पादन आदि को प्रोत्साहन मिलता है।

### मूल्य-स्तर-नियमन (Reflation)

बढ़ती हुई कीमतों को अथवा गिरती हुई कीमतों को पहले के स्तर पर लाने के लिए अथवा मूल्य-स्तर में स्थिरता लाने के लिए जब आवश्यक हो मुद्रा-स्फीति या मुद्रा-संकोच किया जाता है उस स्थिति में ऐसी मुद्रा-स्फीति या मुद्रा-संकोच को मूल्य-स्तर-नियमन कहते हैं। मूल्य-स्तर के लिए जब सरकार इस प्रकार से मुद्रा-परिमाण का नियन्त्रण करती है सभी मूल्यों में स्थिरता रखी जा सकती है, यह तथ्य आजकल सर्वमान्य है।

### सारांश

#### मुद्रा-स्फीति

अर्थ—माँग की अपेक्षा मुद्रा का चलन अधिक होने से मूल्य-स्तर अधिक बढ़ने लगता है तब उसे मुद्रा-स्फीति कहते हैं।

#### मुद्रा-स्फीति की तीन परिस्थितियाँ

१ बिना किसी विशेष परिवर्तन के उत्पादन का घटना और मुद्रा की मात्रा स्थिर रहना।

२. उत्पादन एवं विक्रयार्थ वस्तुओं में घट-बढ़ न होकर मुद्रा की मात्रा बढ़ जाना।

३ उत्पादन एवं विक्रयार्थ वस्तुओं तथा मुद्रा की मात्रा का स्थिर रहना परन्तु साल की मात्रा बढ़ना ।

उपरोक्त परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर मुद्रा सकोच हो जाता है ।

मुद्रा-स्फीति के कारण—१ प्राकृतिक २ कृत्रिम

१ प्राकृतिक—जिन पर सरकार का कोई नियन्त्रण न हो—सोना या चाँदी की खानों से अधिक उत्पादन, नई खानों की खोज, अधिक मात्रा में आयात ।

२ कृत्रिम—सरकार द्वारा राष्ट्रीय बजट को संतुलित करने के लिए किया जाना ।

मुद्रा-स्फीति का प्रभाव—समाज का निम्नवर्गों में वर्गीकरण : १. विनियोगकर्ता, २ व्यापारी अथवा उत्पादक, ३ कर्मचारी वर्ग ।

मुद्रा-स्फीति का परिणाम—१ व्यापारियों तथा उत्पादकों को मूल्य बढ़ने से लाभ । किन्तु तीव्र गति से मूल्य वृद्धि के कारण सट्टेबाजी तथा अनैतिकता का फैलाव ।

२ देनदारों को लाभ, लेनदारों को हानि ।

३ श्रमिक तथा कर्मचारी वर्ग को हानि क्योंकि उनकी आय निश्चित होती है तथा मूल्य स्तर बढ़ जाता है ।

४ सरकार को लाभ ।

५ विनियोगकर्ताओं को लाभ क्योंकि लाभांश तथा व्याज की दर में वृद्धि ।

६ विदेशी व्यापार में हानि क्योंकि निर्यात कम, आयात अधिक होते हैं ।

७ उपभोक्ताओं की हानि ।

मुद्रा सकोच का परिणाम—मूल्य घट जाने के कारण —

१ देनदारों की हानि, लेनदारों को लाभ ।

२ कर्मचारी वर्ग को लाभ ।

३ सरकार को हानि—ऋण भार का बढ़ना ।

४ उत्पादक वर्ग की हानि ।

५ विनियोगकर्ताओं को लाभ—लाभांश तथा व्याज पूर्व दर पर मिलने से उसी मुद्रा से अब ज्यादा वस्तुएँ खरीद सकते हैं ।

६ विदेशी व्यापार में लाभ ।

७ उपभोक्ताओं को लाभ ।

## मुद्रा-मान पद्धतियाँ

विनिमय की आवश्यकता तथा मुद्रा का विकास आर्थिक प्रगति के अनुसार किस प्रकार हुआ एवम् मुद्रा के लिए भिन्न भिन्न वस्तुओं का प्रयोग कैसे किया गया, यह हमें पढ़ने और समझने में देखा। क्रमशः आर्थिक विकास, अधिक परिमाण के उत्पादन एवम् धर्म विभाजन तथा अन्तर्देशीय व्यापार की वृद्धि एवं विकास के साथ यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि मुद्रा-वस्तु में मूल्य की स्थिरता रहे, जिसमें मुद्रा-स्फीति एवं मुद्रा-संकोच में होने वाली हानियाँ न हों तथा व्यापार का भली भाँति संचालन हो सके, मुद्रा-मान (monetary standard) अथवा मुद्रा-पद्धति ऐसी हो जो मजबूत हो एवम् जिससे अन्तर्देशीय व देशीय व्यापार में सुगमता हो इसके साथ ही वह मुद्रा के काय करने में भी सफल हो। मुद्रा मान देश की उस मुद्रा को कहते हैं जिसके साथ सब वस्तुओं का मूल्यमापन किया जाय तथा जिससे उस देश के अन्य सांकेतिक या प्रतीक सिक्के सम्बन्धित हों। ये मुद्रा मान भिन्न भिन्न देशों में उनकी आवश्यकतानुसार एवं आर्थिक प्रगति के अनुसार भिन्न भिन्न रहते हैं। ये मुद्रा मान या तो किसी ऐसी वस्तु से सम्बन्ध रखते हैं जिसमें बाह्य मूल्य अथवा वस्तु-मूल्य रहता है अथवा किसी ऐसी वस्तु से सम्बन्ध रखते हैं जिसमें बाह्य मूल्य नहीं होता। उनकी तात्पर्यता बड़े पैरपट्ट पर दी है।

### अच्छी मान पद्धति के लक्षण

यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि अच्छी मुद्रा मान पद्धति में क्या-क्या गुण होने चाहिए। किन्हीं भी अच्छी मुद्रा मान पद्धति में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है — मूल्य स्थिरता (stability in value), सरलता (simplicity), लोच (elasticity), स्वयंपूर्ण कार्यशीलता (automatic in its operation) तथा मितव्ययिता (economy)।

मूल्य में स्थिरता मुद्रा-मान पद्धति ऐसी होनी चाहिए जिससे देश के मूल्य-स्तर तथा विदेशी विनिमय की दर में स्थिरता रखी जा सके। इस प्रकार

कीमतों के उतार-चढ़ाव के कारण होने वाली हानियां से बचाव रहे। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत तो यह है कि विदेशी विनिमय दर की स्थिरता की अपेक्षा देश का मूल्य-स्तर स्थिर रहना अधिक आवश्यक है जिससे व्यापार एवं उद्योगों का विकास अच्छी प्रकार हो।

**सरलता**—मुद्रा मान पद्धति सरल होनी चाहिए जिससे कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। ऐसी पद्धति में जनता को शीघ्र ही विश्वास हो जाता है।

**लोच**—मुद्रा मान पद्धति में लोच का होना भी आवश्यक है जिससे उस देश की व्यापारिक आवश्यकता के अनुसार मुद्रा का परिमाण घटाया या बढ़ाया जा सके। मुद्रा के मूल्य में स्थिरता नाने के लिए मुद्रा मान में लोच होना आवश्यक है। यदि मुद्रा मान पद्धति में लोच का अभाव होमा तो व्यापारिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की पूर्ति न तो बढ़ाई जा सकती है और न घटाई जा सकती है। परिणाम स्वरूप व्यापारिक एवं औद्योगिक परिस्थिति पर इन दोनों ही स्थितियों में बुरे परिणाम हुए बिना नहीं रहते एवं उनको घबरा पहुँचता ही है।

**स्वयंपूर्ण कार्यशीलता**—मुद्रा-मान पद्धति में सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तथा वह स्वयम् ही कार्यशील होनी चाहिए क्योंकि यदि सरकार द्वारा हस्तक्षेप अधिक होता है तो उस पद्धति में जनता का विश्वास कम हो जाता है। मत मुद्रा मान पद्धति स्वयंपूर्ण कार्यशील होनी चाहिए जिससे उसमें निश्चितता रहे। उदाहरणार्थ स्वर्ण चलन मान प्रणाली में जिसमें स्वर्ण के मापात एवं निर्यात से अपने आप ही मुद्रा का चलन कम-अधिक हो जाता था, जिससे आंतरिक मूल्यों में उतार-चढ़ाव होकर विश्व के मूल्य-स्तर में समानता रहती थी।

**निश्चितता**—मुद्रा-मान पद्धति में खर्च की कमी होनी चाहिए जिससे उसके संचालन में अधिक व्यय न हो तथा सोना चाँदी की घिसावट भी न हो। और इसके साथ ही निधि में भी स्वर्ण एवं चाँदी अधिक रखने की आवश्यकता न रहे।

**अनिश्चितता से मुक्ति**—अच्छी मुद्रा-मान पद्धति में किसी भी प्रकार की ऐसी उलझनें न होंनी चाहिए जिन्हें जन साधारण न समझ सके क्योंकि यदि उसमें प्रत्येक बात विधान न स्पष्ट रूप में नहीं दी जाती तो जनता उस मान पद्धति के विषय में संशय हो जाती है। इस प्रकार यदि सब बात साफ-साफ हो तो

ऐसी मान पद्धति में जनता का विश्वास जल्दी जम जाता है। अतः उपर्युक्त गुणों को ध्यान में रखकर प्रत्येक देश में उस देश की आवश्यकतानुसार एक आर्थिक परिस्थिति के अनुसार कौनसा मुद्रा मान ठीक होगा यह निर्दिष्ट करना चाहिए। इसके साथ ही यदि किसी भी देश में एक-मुद्रा-मान अपनाया जाता है अथवा साकेतिक अथवा प्रतीक मुद्राओं का चलन होता है तो उसमें परिवर्तनशीलता तथा अत्यधिक मुद्रा प्रसार के विरुद्ध सुरक्षा भी रहनी चाहिए, जिसमें जनता का विश्वास उस प्रणाली में जम सके, क्योंकि मुद्रा मान का उपयोग जनता की आदतों पर ही निर्भर है। विभिन्न देशों में जिन मुद्रा-मान पद्धतियों का उपयोग हुआ वे विशेषतः निम्नलिखित प्रकार की हैं —

१ एक-धातुमान पद्धति (mono-metallic standard)

२ द्विधातुमान पद्धति (bi-metallic standard)

### एक-धातुमान पद्धति (Mono-metallic Standard)

एक-धातुमान पद्धति में किसी एक ही धातु के—सोने या चांदी के—सिक्के प्रधान मुद्रा के रूप में चलन में होते हैं। इन सिक्कों के साथ साकेतिक मुद्रा का मूल्य सम्बन्धित होता है तथा यही मूल्यमापन का काम करते हैं। इस धातु की मुद्रा असंमित विधिग्राह्य होती है, टक्का स्वातन्त्र्य होता है अथवा कोई भी व्यक्ति वह धातु ले जाकर सिक्के ढलवा सकता है, तथा इनके आन्तरिक मूल्य एक बाह्य मूल्य में समानता रहती है। इसके अनिरीकृत दैनिक उपयोग के लिए प्रतीक अथवा गौण मुद्रा का चलन होता है जो किसी गौण धातु की अथवा कागज की बनाई जाती है एवं सीमित विधिग्राह्य होती है। इस गौण मुद्रा के बदले में किसी भी समय प्रधान मुद्रा या सोना या चांदी मिल सकती है। यदि इस पद्धति में प्रधान मुद्रा सोने की हो तो उसे स्वर्णमान पद्धति (gold standard) और अगर चांदी की प्रधान मुद्रा हो तो उसे रजतमान पद्धति (silver standard) कहते हैं।

### स्वर्णमान पद्धति

स्वर्णमान पद्धति में स्वर्ण वस्तुओं के मूल्यमापन का कार्य करता है। इसमें यह आवश्यक नहीं है कि सोने के सिक्के चलन में हों, किन्तु जो सिक्का चलन में हो अथवा प्रतीक मुद्रा के रूप में हो उसका परिवर्तन स्वर्ण में होना आवश्यक है। केमरर के शब्दों में “यह वह मान पद्धति है जिसमें कीमती, ऋण तथा मजदूरी उस मुद्रा में व्यक्त की जाती हैं, तथा उसी मुद्रा में उनको चुकाया

जाता है, जिसका मूल्य स्वतन्त्र स्वर्ण-बाजार में निश्चित होने की मात्रा में होता है।<sup>१</sup> इस व्याख्या के अनुसार न तो स्वर्ण-मुद्रा का चलन ही आवश्यक है और न उसकी विधिग्राह्यता ही। उसी प्रकार शानेनिय मुद्रा अथवा पत्र मुद्रा का स्वर्ण में परिवर्तन होना भी आवश्यक नहीं है किन्तु इच्छित है। यह पद्धति विभिन्न देशों में तीन रूपों में उपयोग में रही।—

- १ स्वर्ण-मुद्रा-मान (gold currency standard)
- २ स्वर्ण-धातु-मान (gold bullion standard), तथा
- ३ स्वर्ण-विनिमय-मान (gold exchange standard)

### १ स्वर्ण-मुद्रा मान

स्वर्ण-मुद्रा-मान पद्धति का प्रारम्भ शुरू-शुरू में इस प्रकार हुआ। इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं —

१ स्वर्ण मूल्यमापक होता है अतएव अन्य वस्तुओं की कीमतें एवं उसी प्रकार गौण सिक्कों का मूल्यांकन स्वर्ण के साथ किया जाता है।

२ साथ ही साथ, स्वर्ण विनिमय-माध्यम का कार्य भी करता है अर्थात् स्वर्ण के प्रमाणित सिक्के चलन में रहते हैं, जिनका मुक्त टक्का होता है, जो असीमित विधिग्राह्य होने हैं और जिनका वाह्य मूल्य तथा आन्तरिक मूल्य बराबर होता है।

३ स्वर्ण की वचन करने के लिए पत्र-मुद्रा अथवा अन्य गौण मुद्राओं का यदि चलन होता है तो ऐसी सभी मार्केटिक मुद्राएँ स्वर्ण में किसी भी समय माँग पर बदली जा सकती हैं।

४ सोने के आयात एवं निर्यात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता। १९१४ के पूर्व यह पद्धति इंग्लैंड, समुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी आदि देशों में प्रचलित थी।

यदि स्वर्ण की जगह चाँदी का उपयोग इसी प्रकार से होता हो तो उसे रजत-मुद्रा-मान (silver currency standard) कहेंगे। इस प्रकार की पद्धति कहीं भी प्रचलित नहीं है।

१ 'Is a money-system where the unit of value, in which prices and wages and debts are customarily expressed and paid, consists of the value of a fixed quantity of gold in a Free Gold Market'

**स्वर्ण-मुद्रा-मान के लाभ—१** स्वर्ण में जनता का विश्वास होने के कारण इस पद्धति में जनता का विश्वास शीघ्र ही स्थापित होता है।

२. इसकी कार्य-पद्धति सरल होने के कारण यह प्रत्येक व्यक्ति की समझ में शीघ्र आ जाती है।

३. स्वर्ण के आयात-निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न होने से राज्य की ओर से इसकी कार्य-पद्धति में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता जिससे स्वयंपूर्ण कार्यशीलता रहती है तथा कीमतों का स्तर अपने आप विश्व-परिस्थिति से ठीक हो जाता है। उदाहरणार्थ, यदि एक देश से दूसरे देश में निर्यात में अधिक आयात होता है तो उग देश में पहिला देश दूसरे देश का ऋणी रहेगा और उसे भुगतान के लिए गाना भेजना पड़ेगा। परिणामस्वरूप पहिले देश में मुद्रा का संकोच होकर कीमतें गिर जायेंगी और अन्य देशों की आपेक्षा यहाँ की कीमतें कम होने से इस देश का निर्यात-व्यापार बढ़ेगा जिससे यहाँ पर सोने का आयात होगा। सोने का आयात होते ही मुद्रा-प्रसार होगा तथा कीमतें चढ़ जायेंगी। इस क्रिया के कारण विश्व-भूतलों में स्थिरता रहेगी तथा यह आयात-निर्यात के कारण किसी के हस्तक्षेप के बिना होता रहेगा। फलस्वरूप इस मान में स्वयंपूर्ण कार्यशीलता रहेगी। इसके साथ ही इस पद्धति में विदेशी विनिमय दर में स्थिरता रहती थी।

४. स्वर्ण सर्वप्राप्त होने के कारण स्वर्ण की प्रधान मुद्रा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा होती है जिससे स्वर्ण पर आधारित राष्ट्रों के साथ व्यापार सुगम होता है।

५. वस्तुओं की कीमतों का समायोजन सोने के आयात-निर्यात से स्वयमेव होता था, इस कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव अधिक न हान हुए मूल्यों में स्थिरता रहती थी।

६. स्वर्ण का आयात निर्यात स्वतन्त्रता के साथ होने के कारण एक देश के मूल्यस्तर का प्रभाव अन्य देशों के मूल्यों पर पड़ता था जिससे अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों का समायोजन हो जाता था।

**दोष—**इस पद्धति में सबसे बड़ा दोष यह है कि स्वर्ण मुद्राएँ चलन में होने के कारण इसमें सोना अधिक लगता है एवं स्वर्ण मुद्राएँ चलन में होने के कारण धिमावृत्ति से होने वाली हानि की वृत्ति नहीं होती। दूसरे, जिन देशों में स्वर्ण की कमी रहती है वे इस पद्धति को नहीं अपना सकते जिससे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। तीसरे, सोने का उपयोग चलन के

अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं किया जा सकता है। अतः यह पद्धति अधिक खर्चीली है क्योंकि इसमें मितव्ययिता का अभाव है।

## २ स्वर्ण-धातुमान

पहिले महायुद्ध में स्वर्ण-मुद्रा-मान पद्धति में अनेक कठिनाइयाँ आईं क्योंकि युद्ध के कारण सोने का मुक्त बाजार, एवं आयात-निर्यात अनेक देशों की सरकारों द्वारा बन्द किया गया। इस तथा अनेक अन्य कठिनाइयों के कारण स्वर्ण-मुद्रामान पद्धति का तोप हुआ और स्वर्ण-धातुमान पद्धति का अवलम्बन हुआ। इसको १९२५ में इंग्लैंड ने अपनाया। इस पद्धति के मुख्य लक्षण निम्न-लिखित हैं —

१ इस पद्धति में भी स्वर्ण-मुद्रामान पद्धति की तरह स्वर्ण मूल्यमापक होता है लेकिन स्वर्ण के सिक्के न तो ढाले ही जाते हैं और न चसन में ही होते हैं अर्थात् स्वर्ण विनिमय-माध्यम का कार्य नहीं करता।

२. देश की विधिग्राह्य मुद्रा किसी गौण धातु की बनाई जाती है अथवा पत्र-मुद्रा चलन में होती है जिसके द्वारा विनिमय-माध्यम का कार्य होता है। ये साकेतिक मुद्राएँ एक निश्चित दर पर सोने में परिवर्तित की जाती हैं किन्तु सोने में साकेतिक मुद्रा का परिवर्तन एक निश्चित वजन से कम में नहीं किया जाता—चाहे स्वर्ण किसी भी काम के लिए क्यों न लिया जाय।

३ सोने के बेचने में सुविधा हो इसलिए मुद्रा संचालक को कुछ स्वर्ण-निधि देश में रखनी पड़ती है। इस प्रकार की पद्धति का अवलम्बन १९२५ में इंग्लैंड तथा अन्य देशों में शुरू हुआ। यह पद्धति १९२७ में भारत के लिए भी हिन्दन यंग कमिशन द्वारा अपनाने के लिए प्रस्तुत की गई थी तथा अपनाई गई थी, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति कम से कम ४०० ग्राम (१०६५ तोले) मोना २१ रु० ३ आ० १० पाई प्रति तोले की दर में प्रतीक मुद्रा के बदले में खरीद सकता था। यह पद्धति १९३१ तक चालू रही जिसके बाद अनेक कठिनाइयों के कारण इसका भी परित्याग हमेशा के लिए कर दिया गया। स्वर्ण के स्थान पर चाँदी का यदि इसी प्रकार उपयोग हो तो रजत-धातुमान पद्धति कहेंगे।

स्वर्ण-धातुमान पद्धति के लाभ—१ इस पद्धति में सोने का चलन न होने के कारण घिसावट से होने वाली हानि नहीं होती और सिक्कों के ढालने में जो खर्च होता है उसकी भी बचत होती है। अतः पहिली पद्धति की अपेक्षा इस पद्धति में मितव्ययिता होती है।

२. विनिमय-दर की स्थिरता के लिए सोना चलन में रहने की अपेक्षा मुद्रा-संचालक के निधि में होता अधिक उपयोगी है। इसके अतिरिक्त सोने की मात्रा चलन की अपेक्षा निधि में कम रहनी पड़ती है, अतः सोने की वचत भी होती है जिससे देश भी इस पद्धति को अपना सकते हैं। परन्तु स्वर्ण-मुद्रामान पद्धति में यह सम्भव नहीं होता।

३. देश की साख भी बनी रहती है क्योंकि किसी भी काम के लिए साकेतिक मुद्रा का परिवर्तन सोने में किया जा सकता है, जिसके लिए सरकार का नूनन बाध्य होता है। इससे इस पद्धति में जनता का विश्वास भी स्थापित हो जाता है।

४. इस पद्धति में निश्चित मात्रा में कम सोना नहीं खरीदा जा सकता और निश्चित मात्रा में प्रत्येक व्यक्ति न खरीद सकने का कारण, निधि में कम सोने की आवश्यकता होती है जिससे अतिरिक्त सोने को विनिमय-पत्रों में अथवा अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया जा सकता है अथवा विदेशी अधिग्रहणों में रखा जा सकता है जिससे आय हो।

५. ऐसा भी कहा जाता है कि इस पद्धति में भी स्वयंपूर्ण कार्यशीलता रहती है जिसमें मुद्रा का सकोच अथवा प्रसार सोने के क्रय-विक्रय के अनुसार अपने आप होता है। उदाहरणार्थ, जिस समय मुद्रा की माँग कम रहती है उस समय लोग सोना खरीदते हैं और बदले में पत्र-मुद्रा अथवा साकेतिक मुद्रा देते हैं जिससे मुद्रा का स्वयं सकोच होता है। उसी प्रकार जब मुद्रा की माँग अधिक होती है उस समय लोग सोना बेचते हैं और साकेतिक मुद्रा प्राप्त करते हैं जिससे मुद्रा-चलन बढ़ता है। इस प्रकार इसमें अपने आप लोच-रपन की क्षमता होती है जिससे मूल्य-स्तर में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं हाते तथा कीमतों का समायोजन अपने आप हो जाता है।

६. स्वयंपूर्ण कार्यशीलता होने के कारण इस पद्धति में लोच भी रहती है अर्थात् मुद्रा की पूर्ति व्यापारिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार कम-अधिक की जा सकती है।

टिप्पणी—किन्तु इसमें सत्यास बहुत कम है जैसा कि बेयरर ने लिखा है कि “करीब-करीब सब देशों में इसकी स्वयंपूर्ण कार्यशीलता युद्धपूर्व स्वर्ण-मुद्रामान से कम थी क्योंकि स्वर्ण-धातुमान तथा स्वर्ण विनिमय-मान में केन्द्रीय बैंकों को तथा सरकारों को चलन की पूर्ति में हस्तक्षेप करने एवं स्वर्ण-चिन्तु से च्युत होने में स्वर्ण-चलन-मान की अपेक्षा—जिसमें स्वर्ण-मुद्रा-चलन एवं स्वर्ण-मुद्रा-

परिवर्तन था—अधिक आसानी थी।<sup>१</sup> यही इस पद्धति का सबसे बड़ा दोष है। सारांश में, इस पद्धति का सबसे पहला दोष यह है कि इसमें स्वर्ण का निधि एवं सांकेतिक मुद्रा का संचालन सरकार अथवा केन्द्रीय बैंक के पास होने के कारण यह पद्धति नियन्त्रित पद्धति है जिससे इसमें स्वयंपूर्ण कार्यशीलता का अभाव रहता है।

### ३. स्वर्ण-विनिमय-मान

इस प्रकार के स्वर्णमान में निम्नलिखित लक्षण होना आवश्यक है —

१ स्वर्ण मूल्यमापन का कार्य करता है किन्तु विनिमय माध्यम का कार्य नहीं करता अर्थात् सोने के सिक्कों का न तो चलन होता है और न वे ढाले ही जाते हैं।

२ देश में पत्र-मुद्रा अथवा किसी अन्य धातु की गोण मुद्रा का चलन होता है जिसका सम्बन्ध स्वर्ण की निश्चित माना एवं शुद्धता में निश्चित किया जाता है। यदि कोई देश स्वर्णमान पद्धति पर नहीं है तो उस देश के सिक्के का मूल्य किसी दूसरे देश के सिक्के से परिवर्तित किया जाता है जो स्वर्णमान पर आधारित है और उस देश के चलन के साथ देशी सिक्के का परिवर्तन वैधानिक दर पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, भारत में जब यह पद्धति थी उस समय भारत के रुपये की दर १ शि० ६ पेंस इंग्लैण्ड के सिक्के में निश्चित की गई थी और विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए इस दर पर सरकार अथवा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया रुपयों के बदले में केवल विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण अथवा स्टैलिंग देने को बाध्य थी, परन्तु वास्तव में स्टैलिंग ही दिया जाता था।

३ विदेशी भुगतान के लिए सरकार एक निश्चित दर पर सोना अथवा विदेशी सिक्का देने के लिए बान्धन बाध्य होती है।

४ अतः देश का केन्द्रीय बैंक अथवा सरकार विदेशी बैंकों से स्वर्ण-निधि रखती है अथवा अपने देश में विदेशी विनिमय अथवा विदेशी सिक्के रखाती है।

५ स्वर्ण-बाजार मुक्त न होते हुए सरकार द्वारा नियन्त्रित एवं नियमित होता है, जिससे कोई भी व्यक्ति न तो सोने का आयात कर सकता है और न निर्यात ही। अतः इस पद्धति में सोना अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा का कार्य करता है तथा देश के भीतर पत्र-मुद्रा अथवा अन्य गोण मुद्रा विनिमय

<sup>१</sup> *Gold and the Gold Standard* by Kemerrer, pp. 818-19

का कार्य करती है। इस पद्धति का प्रचलन सर्वप्रथम जावा में हुआ तथा बाद में भारत, फिलिपाइन्स, मेक्सिको, पनामा आदि देशों में हुआ। सोने के बदले यदि चांदी का उपयोग किया जाय तो उसे रजत-त्रिनिमय-मान कहेंगे।

स्वर्ण-दिनिमय-मान के लाभ—१ यह स्वर्ण-मान की सबसे कम खर्चीली पद्धति है, क्योंकि देश में न तो सोने के सिक्कों का चलन ही होता है और न देश के अन्तर्गत कार्यों को सोना देने को ही सरकार बाध्य होती है। इसमें केवल विदेशी भुगतान के लिए विदेशी बैंक में मान की निधि रखनी पड़ती है जिसके लिए सोने की बहुत कम मात्रा आवश्यक होती है।

२ यह पद्धति अधिक लोपदार होती है अर्थात् आवश्यकतानुसार मुद्रा-प्रसार तथा मुद्रा-संकोच किया जा सकता है क्योंकि अन्य स्वर्णमानों में सोने की उपलब्धता पर मुद्रा प्रसार किया जा सकता था, परन्तु इसमें स्वर्ण-चलन अथवा देश की मुद्रा का परिवर्तन सोने में, विदेशी दिनिमय के अतिरिक्त, न होने से किसी मात्रा में आवश्यकतानुसार मुद्रा का चलन बढ़ाया जा सकता है।

३ इस पद्धति को अपनाते में स्वर्णमान के सब लाभ प्राप्त होत हैं। इसी के साथ देश की मुद्रा किसी भी अन्य धातु की हो सकती है जैसा कि रॉबर्टसन ने इस पद्धति के विषय में कहा है —“इन देशों में सांकेतिक मुद्रा ही प्रमाणित मुद्रा होती है परन्तु उसका नियमन सरकार इस प्रकार से करती है कि वह निराधार नहीं होती किन्तु इस प्रकार से बनाई जाती है जिसमें प्रमाणित मुद्रा के मूल्य में किसी अन्य देश की मुद्रा के अथवा सोने के मूल्य के साथ स्थिरता रहे।”

४ यह पद्धति निर्धन एवं अविश्वसित देशों के उपयोग के लिए सबसे अच्छी है तथा अधिकांश देशों में स्वर्णमान पद्धति का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसका अपनाने के लिए स्वर्ण बहुत कम लगता है।

दोष—१ इस पद्धति में केवल विदेशी भुगतान के लिए ही स्वर्ण देने को सरकार बाध्य होती है इसलिए इस पद्धति में जनता का विश्वास कम होता है।

२ विदेशी मुद्रा के लिए विदेशी बैंकों में स्वर्ण निधि रखा जाता है जो खतरनाक है क्योंकि विदेशी बैंकों के दूट जान में देश की निधि की हानि होती है।

३ इस पद्धति में लोच की कार्यशीलता स्वयं-निभर नहीं होती, जैसी कि पहली दो पद्धतियों में होती है। इस पद्धति में मुद्रा का प्रसार एवं संकोच

सरकार के ही हाथ में रहता है क्योंकि उसी के हाथों में विदेशी विनिमय का नियन्त्रण रहता है ।

### द्विधातुमान पद्धति

द्विधातुमान पद्धति में स्वर्ण तथा चाँदी दोनों धातुओं के प्रमाणित सिक्के चलन में रहते हैं जिनमें एक-दूसरे का वैधानिक अनुपात में सम्बन्ध रहता है तथा दोनों ही धातुओं के सिक्के विनिमय माध्यम एवं मूल्यमापन का वाय करते हैं । इसके मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं —

- १ स्वर्ण तथा चाँदी दोनों ही विनिमय माध्यम तथा मूल्यमापन का वाय करते हैं ।
- २ दोनों धातुओं की मुद्राएँ प्रमाणित मुद्राएँ होती हैं एवं उनमें परस्पर निश्चित वैधानिक सम्बन्ध रहता है जिससे वे एक-दूसरे के साथ बदल जा सकें ।
- ३ दोनों धातुओं का टक्कण स्वातन्त्र्य जनता को प्राप्त होता है अर्थात् कोई भी व्यक्ति सोना या चाँदी टक्काल में ल जाकर उसको प्रमाणित मुद्रा में परिवर्तित करा सकता है ।
- ४ दोनों धातुओं की मुद्राएँ असीमित विधिप्राप्त होती हैं ।
- ५ दोनों धातुओं की मुद्रा के बाह्य मूल्य एवं आन्तरिक मूल्य में समानता होती है ।

उपर्युक्त सब लक्षण जिस मान पद्धति में उपलब्ध हों उसी को पूर्ण द्विधातु मान पद्धति कहते हैं ।

### द्विधातुमान पद्धति का संक्षिप्त इतिहास

संयुक्त राज्य अमेरिका ने सर्वप्रथम सन् १७६२ के मिण्ट एक्ट के अनुसार द्विधातुमान पद्धति का अवलम्बन किया जिसके अनुसार प्रधान मुद्रा दोनों धातुओं—स्वर्ण तथा चाँदी—की बनाई गई जो असीमित विधिप्राप्त थी तथा उन्हें सरकार भी असीमित मात्रा में लेने को बाध्य थी । उनको सिक्को में ढालने का स्वातन्त्र्य जनता को था तथा उन दोनों धातुओं का अनुपात १५ : १ निश्चित किया गया अर्थात् १५ चाँदी के सिक्कों के बदले में १ सोने का सिक्का मिल सकता था अथवा १ औंस सोने की वीमत १५ औंस चाँदी के बराबर थी । १७६२ में बाजार में भी सोने चाँदी का यही अनुपात था । जब तक बाजार अनुपात तथा टक्क अनुपात में समानता थी तब तक किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई । किन्तु १७६५ से १८३३ तक बाजार अनुपात

१५६ : १ या जिसके अनुसार बाजार में १ औंस सोना खरीदने के लिए जहाँ १५६ औंस चाँदी देनी पड़ती थी, वहाँ टक्काला से केवल १५ औंस चाँदी के बदले १ औंस सोना मिल सकता था अर्थात् टक्काला में चाँदी का अधिमूल्यन तथा सोने का अवमूल्यन था। परिणामस्वरूप सोना बाजार में टक्काला की अपेक्षा अधिक कीमती हो गया जिससे स्वर्ण के मिकके लोगो ने इकट्ठे करके या तो उनको गनाना शुरू किया, या बाजार में बचने लगे या विदेशी भुगतान में उपयोग में लाने लगे। इसी समय फ्रांस में, जहाँ द्विधातुमान पद्धति थी, १८०३ में १८३३ तक टक-अनुपात १५ $\frac{1}{2}$  : १ था। अतः अमेरिका से फ्रांस को सोने का निर्यात होना भी लाभदायक ही था। इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति के कारण २८ जून १८३४ को टक-अनुपात १५ : १ के बदले १६००२ : १ कर दिया गया। चूँकि यह अनुपात बाजार-अनुपात से भिन्न था जो सब भी १५६ : १ था इसलिए अब टक्काला पर सोने का अधिमूल्यन हुआ तथा चाँदी का अवमूल्यन, अथवा जहाँ बाजार में १ औंस सोने के बदले १५६ औंस चाँदी मिलती थी वहाँ टक्काला पर १ औंस सोने के बदले १६००२ औंस चाँदी मिलती थी अतः बाजार में चाँदी कीमती होने के कारण चलन में चाँदी के मिकके हटाय जाय लगे और उनका गलाकर बेचा जाने लगा। १८५० में सोने की अधिक खानों की खोज हो जाने से स्वर्ण का उत्पादन बढ़ गया और बाजार में सोने की कीमत और भी गिर गई। इसका भी यही परिणाम हुआ कि विनिमय के लिए जनता सोने का उपयोग करने लगी तथा चाँदी को अन्य कामों में लाने लगी क्योंकि मिकके के रूप में सोना अधिमूल्यन तथा चाँदी अवमूल्यन थी। इस क्रिया के निरन्तर चालू रहने के कारण—जिसे प्रथम का चलित मुद्रा सिद्धान्त कहते हैं—अमेरिका में मन् १८७३ में चाँदी का टकण स्वातन्त्र्य छीन लिया। इसी समय यूरोपीय राष्ट्रों में स्वर्णमान पद्धति का अवलम्बन हो रहा था इसलिए आगे चलकर १ जनवरी १८७६ में अमेरिका में विमुद्रा स्वर्णमान पद्धति को अपनाया गया जिसमें स्वर्ण टकण का स्वातन्त्र्य जनता को था।<sup>१</sup> इस प्रकार अमेरिका में इस पद्धति का परित्याग कुछ अंश में १८७३ में तथा पूर्णतः १८७६ में किया गया।

फ्रेंच तथा लैटिन मॉड्रिफ सघ के देश में भी इस मान का उपयोग मन् १८०३ से १८७३ तक था। वहाँ का द्विधातुमान का इतिहास बहुत मनोरंजक

<sup>१</sup> *Gold and the Gold Standard by Kemerrer,*

है। १८०३ में फ्रांस ने जब अपनी चलन-पद्धति को सङ्गठित किया उस समय वहाँ १५ १ के अनुपात में द्विधातुमान पद्धति का अवलम्बन हुआ। किन्तु वहाँ भी बाजार-अनुपात तथा टक-अनुपात की समानता में कभी सोना अवमूल्यित होता था और कभी चाँदी। ऐसी अवस्था में मँहगी धातु जनता द्वारा गलाकर अन्य उपयोगों में लाई जाती थी। इस प्रकार ग्रेशम के सिद्धान्त के अनुसार वहाँ पर सदैव एक ही धातु की मुद्रा—खराब मुद्रा—चलन में रहती थी। इस प्रकार द्विधातुमान पद्धति कार्यान्वित रही किन्तु १८४८ से १८५६ के बीच आस्ट्रेनिया तथा केलिफोर्निया में नई सोने की खानों की खोज हुई। परिणामस्वरूप चाँदी की कीमतें बाजार में घट गईं और टकमाल पर उसका अधिमूल्यन हुआ, धन चाँदी की मुद्रा ही चलन में रहने लगी तथा स्वर्ण-मुद्रा का लोप होने लगा। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए फ्रान्स ने इटली, बेल्जियम और स्विटजरलैंड के सहयोग से एक लैटिन मौद्रिक संध बनाया, जहाँ द्विधातुमान पद्धति का अवलम्बन था। सन् १८६८ में ग्रीस ने भी इसी संध की सदस्यता स्वीकार की। परन्तु फिर भी मासार्क कारणों से इस संध के देशों से स्वर्ण-मुद्रा का लोप होने लगा और धातु की अपेक्षा सिक्के में कीमती धातु—चाँदी—का ही चलन रहा। इसके लिए दो कारण प्रमुख थे—एक तो दुनिया के प्रमुख राष्ट्र चाँदी का परित्याग करके स्वर्णमान को अपना रहे थे। दूसरे, चाँदी की नई खानों के खोज के कारण १८७३ के लगभग चाँदी का उत्पादन बढ़ रहा था। अतः बाजार में सोने की तुलना में चाँदी की कीमतें बुरी तरह गिर रही थी। इसलिए १८७४ में लैटिन मौद्रिक संध ने भी चाँदी का टकण स्वातन्त्र्य छीन लिया जिससे विद्युत् एक पूर्ण द्विधातुमान पद्धति का अस्तित्व वहाँ भी न रहा।

इसी समय सन् १८७३ में विद्वत् में मन्दी आई जिससे वस्तुओं की कीमत घडाघडा गिरने लगी और द्विधातुमान के समर्थकों ने अन्तरराष्ट्रीय ढंग पर द्विधातुमान अपनाने का प्रचार शुरू किया। उनका कहना था कि उस समय विनिमय कार्यों के लिए मुद्रा कम होने से कीमतें गिर रही हैं। यदि अन्तरराष्ट्रीय द्विधातुमान का अवलम्बन किया जाय तो चाँदी की मुद्रा भी विनिमय-माध्यम का कार्य करेगी जिससे विनिमय कार्यों के लिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ जायगी एवं क्रमशः कीमतें बढ़ने लगेंगी। किन्तु एकमान अथवा स्वर्णमान के समर्थक इससे सहमत नहीं थे। अतः द्विधातुमान का अवलम्बन करने के हेतु दो अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सभाएँ (conferences) क्रमशः १८७८

और १८६२ में हुई, परन्तु डब्लू.के. वट्टर विरोध के कारण द्विधातुमान को अन्तरराष्ट्रीय हथ पर नहीं अपनाया गया अपितु इसका उगवे वाद सदैव के लिए परित्याग कर दिया गया। १८६३ में भारत ने चाँदी का टक्का-स्वातन्त्र्य छोड़ लिया तथा क्रमशः १८६७ और १८६३ में आस्ट्रिया, जापान और रूस ने भी स्वर्णमान का अवलम्बन किया। इस प्रकार १९वीं शताब्दी के अन्त में द्विधातुमान का परित्याग सदैव के लिए कर दिया गया क्योंकि देश में केवल खराब मुद्रा का ही चलन रहता है। इस प्रवृत्ति को ग्रेशम का सिद्धान्त कहते हैं।

### ग्रेशम का मुद्रा-चलन सिद्धान्त

(Gresham's Law of Circulation of Money)

पिछले अध्यायो के विवेचन में अब यह स्पष्ट हो चुका है कि कोई भी वस्तु जो सर्वमान्य अथवा सर्वग्राह्य होती है वह मुद्रा के रूप में कार्य कर सकती है। अथवा ऐसी वस्तु जिसमें जनता का विश्वास हो एवं जो सर्वग्राह्य हो अथवा जो किसी सरकार द्वारा मुद्रा के रूप में चलाई जाय एवं सरकार की माल में यदि जनता का विश्वास हो तो वह मुद्रा के रूप में चलन में रहती है। इस प्रकार एक ही समय में सरकार द्वारा चलाई हुई मुद्राएँ कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे द्विधातुमान पद्धति में स्वर्ण तथा चाँदी की मुद्राएँ एक साथ चलन में होती हैं अथवा एक धातुमान में एक ही धातु के नये एवं पुराने सिक्के एक ही साथ चलन में रहते हैं, अथवा धातु मुद्रा एवं पत्र-मुद्रा एक ही समय प्रधान मुद्रा की तरह चलन में रहती हैं। ऐसे समय भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राओं की ग्राह्यता में भी भिन्नता होती है क्योंकि यह मानव प्रवृत्ति है कि जहाँ तक किसी वस्तु के लेने का सम्बन्ध है, हम हमेशा अच्छी वस्तु ही लेंगे। यह प्रवृत्ति मुद्रा के बारे में भी लागू होती है। जहाँ तक पत्र-मुद्रा एवं धातु-मुद्रा उसे अर्थशक्ति के लिए अथवा विनिमय-माध्यम के लिए चाहिए, वह कोई भी मुद्रा ले लेगा। परन्तु जब वह मुद्राओं को बिन्ही अन्य कारणों के वशीभूत होकर संग्रह करेगा उस समय वह अच्छी मुद्रा ही लेगा अर्थात् ऐसी मुद्रा लेगा जो मुद्रा के अतिरिक्त भी धातु मूल्य रखती हो अथवा जो विनिमय कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए उपयोग में आ सके। जहाँ मुद्राएँ किसी धातु की हैं, वहाँ पर जिस सिक्के का धातु-मूल्य मुद्रा-मूल्य से अधिक है, वही मुद्रा संग्रह में रखने का प्रत्येक व्यक्ति प्रयत्न करेगा अर्थात् किसी भी समय सिक्के के रूप में खराब मुद्रा चलन में रहेगी

और अच्छी मुद्रा चलन में निवान ली जायगी। इसी प्रवृत्ति को प्रेशम का मुद्रा-चलन सिद्धान्त कहते हैं क्योंकि इस मानमित्र प्रवृत्ति को सर टॉमस प्रेशम नामक व्यक्ति ने, जो एनिजाउथ का आर्थिक मलाहकार था, अधिक स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया था।

सर टॉमस प्रेशम नन्दन का एक प्रसिद्ध व्यापारी था। रॉयल एक्मचेंज की नींव भी इसी में डानी थी। मन्त्राजी एनिजाउथ के राज्यकाल में अधिकतर ऐसी ही मुद्राएँ चलन में थी जो या तो काटी हुई थी या घिसी हुई थी अथवा वजन में कम थी। इस स्थिति को सुधारने के लिए नये सिक्के भी बनाये गये किन्तु फिर भी पुराने एवं घिसे हुए सिक्के चलन में रहे तथा नये सिक्के चलन से निकल गये। इसी प्रवृत्ति को प्रेशम ने “खराब सिक्कों में अच्छे सिक्कों को चलन से निवान देने की प्रवृत्ति होती है”<sup>१</sup> इन शब्दों में व्यक्त किया। उसने यह स्पष्ट किया कि जब चलन में अच्छे तथा पूर्ण वजन के सिक्के और पुराने तथा घिसे हुए सिक्के होते हैं उस समय देश में भुगतान के लिए दोनों एक ही मूल्य के एवं विधिग्राह्य भी होने हैं। इसलिए खराब सिक्के देश के भुगतान के लिए चलन में रह जाते हैं तथा अच्छे सिक्कों का जनता या तो संग्रह करती है, या गलाकर उनको धातुरूप में बचती है अथवा विदेशी भुगतान के लिए निर्यात करती है। चूंकि इस काम के लिए कम वजन के एवं खराब सिक्कों की अपेक्षा भारी एवं विधुद्ध सिक्के ही अधिक लाभदायक होते हैं इसलिए यह नियम पूर्णरूप से किसी भी समय लागू होता है। इसी नियम को मार्शल ने “खराब मुद्राएँ यदि परिमाण में सीमित नहीं हैं, तो अच्छी मुद्राओं को चलन से बाहर निवान देती हैं”<sup>२</sup> इन शब्दों में व्यक्त किया है। इसी को हम यों भी कह सकते हैं कि जब किसी देश में दो प्रकार की विधिग्राह्य मुद्राएँ होती हैं तो खराब मुद्राएँ अच्छी मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं, यदि मुद्राओं का परिमाण सीमित नहीं है।

अच्छी मुद्राएँ तीन प्रकार से चलन से बाहर निकलती हैं —

- १ संग्रह करने से,
- २ गलाकर धातुरूप में बेचने से, तथा
- ३ विदेशी भुगतानों के लिए निर्यात करने से।

1 Bad money tends to drive good money out of circulation

2 An inferior currency, if not limited in quantity, will drive out the superior currency

## नियम तालू होने की परिस्थितियाँ

यह नियम तीन परिस्थितियों में किसी देश में लागू होता है —

१. एक-धातुमान पद्धति में—जब एक ही धातु की मुद्राएँ—जो वजन में अथवा विमुद्धता में भिन्न-भिन्न हैं किन्तु एक ही मूल्य रखती हैं—चलन में होती हैं उस समय कम वजन एवं कम विमुद्धता वाली धातु-मुद्राएँ ( खराब मुद्राएँ ) भारी एवं विमुद्ध मुद्राओं की चलन में बाहर कर देती हैं। उदाहरणार्थ, भारत में बिक्टोरिया के एक जार्ज पट्टम् के रुपये जब चलन में थे तब बिक्टोरिया के रुपये में चाँदी का भाग जार्ज पट्टम् वाले रुपयों में अधिक होने के कारण लोगों ने बिक्टोरिया के रुपयों को संग्रह करना शुरू किया अर्थात् वे चलन से बाहर निकाल दिये गये। दूसरा उदाहरण एलिजाबेथ के राज्यकाल में मिलता है जिसमें ग्राम ने हम नियम को स्पष्ट रूप से दिया।

२. द्विधातुमान पद्धति में—जब दो धातुओं की—चाँदी तथा सोने की—प्रमाणित मुद्राएँ निश्चित टक्-अनुपात से चलन में होती हैं, उस समय यदि बाजार-अनुपात में और टक्-अनुपात में अन्तर होता है तो टक् अनुपात से अधमूल्यित होने वाली मुद्राएँ चलन से बाहर निकल जाती हैं तथा टक्-अनुपात में अधिमूल्यित मुद्राएँ ( खराब मुद्राएँ ) चलन में रहती हैं। इसका कारण यह है कि टक्-अनुपात पर अधमूल्यित मुद्रा का धातु-मूल्य उसके बाह्य मूल्य से अधिक होता है। इसलिए धातु के रूप में उनका संग्रह करना, गलाना अथवा निर्यात करना लाभदायक होता है। इसको हम यों भी कह सकते हैं कि एक विशेष अनुपात में जब चाँदी तथा सोने की प्रमाणित मुद्राएँ चलन में होती हैं तब जिस मुद्रा का धातु-मूल्य उसके बाह्य मूल्य में अधिक होता है, अर्थात् जो अच्छी मुद्रा होती है वह उस मुद्रा द्वारा, जिसका धातु-मूल्य बाह्य मूल्य से कम होता है, अर्थात् खराब मुद्रा द्वारा, बाहर निकाल दी जाती है। उदाहरणार्थ, जैसा कि द्विधातुमान पद्धति में फ्रान्स, अमेरिका आदि राष्ट्रों में हुआ।

३. जब किसी देश में पत्र-मुद्रा एवं धातु-मुद्रा प्रमाणित सिक्कों के रूप में चलन में होती हैं, उस समय पत्र-मुद्रा खराब मुद्रा होने के कारण धातु-मुद्रा ( अच्छी मुद्रा ) को चलन से बाहर कर देती है। उदाहरणार्थ, १९१४-१८ में इङ्ग्लैण्ड में चलन में केवल पत्र-मुद्राएँ रह गईं और स्वर्ण-मुद्राएँ चलन से निकाल दी गई थी। यदि पत्र-मुद्रा का अधमूल्यन हो तो यह प्रवृत्ति अधिक तीव्रतर होती है। उदाहरणार्थ, १९३१ में इङ्ग्लैण्ड में जब सोने की कीमतें बढ़ रही थी उस समय सावरिनो की धातु के रूप में घडाके से विक्री हुई थी।

आधुनिक समय में ग्रेशम के सिद्धान्त की प्रतिक्रिया को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलित मुद्रा का नियंत्रण होना है तथा खराब मुद्रा को ढालकर फिर से नई मुद्राओं में परिवर्तित किया जाता है। अतः कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार आधुनिक काल में यह सिद्धान्त बिल्कुल लागू नहीं हो सकता। उनका कहना है कि मध्य युग तथा ग्रेशम के समय में अवैज्ञानिक भौतिक पद्धति होने के कारण ही यह लागू होता था। परन्तु यह सिद्धान्त उपर्युक्त परिस्थितियों में किसी भी समय लागू हो सकता है जैसा द्विधातुमान पद्धति के १९वीं शताब्दी के इतिहास से, १६३१ के इङ्गलैण्ड के उदाहरण में स्पष्ट है। इसी प्रकार प्रथम महायुद्ध के समय भी पत्र-मुद्राओं का अवमूल्यन होने के कारण धातु मुद्राएँ चलन से निवाल दी गई थी।

**सिद्धान्त की भर्थादा**—ग्रेशम का सिद्धान्त उपर्युक्त तीन परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए निम्नलिखित भर्थादाएँ हैं —

१ दोनों प्रकार की मुद्राओं का चलन मुद्रा की माँग से अधिक नहीं है। अर्थात् यदि किसी भी समय विनिमय कार्य के लिए १०० मुद्राएँ आवश्यक हैं और चलन में भी अच्छी एवं खराब मिलाकर १०० मुद्राओं का ही चलन है तो यह सिद्धान्त लागू नहीं होगा।

२ यदि खराब मुद्राओं के चलन का जनता विरोध करती है तथा उसको वस्तुओं और नष्टों आदि के भुगतान में लेने से इनकार करती है तो यह सिद्धान्त लागू नहीं होगा, जैसा कि कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य की जनता ने अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा (ग्रीन बैक्स) को लेने से १८६१-६५ में अस्वीकार कर दिया था।

३ टॉमस<sup>१</sup> के अनुसार खराब मुद्रा का यदि इस प्रकार क्रमशः अवमूल्यन किया जाय कि जनता उसे समझ न पाये, तो इस स्थिति में यह नियम उस समय तक लागू नहीं होगा जब तक अवमूल्यन जनता की समझ में नहीं आता।

४ कुछ अर्थशास्त्रियों के मत से यदि अन्तरराष्ट्रीय ढंग पर द्विधातुमान अपना लिया जाय तो यह सिद्धान्त लागू नहीं होगा क्योंकि एक मुद्रा के अभाव की पूर्ति दूसरी मुद्रा की अधिकता से हो जायगी।

**द्विधातुमान पद्धति से साध—**द्विधातुमान पद्धति के इतिहास से यह स्पष्ट है कि अब इस प्रकार का मान केवल एक ऐतिहासिक अवशेष के रूप में है

किन्तु १६वीं शताब्दी में यह बहुत महत्वपूर्ण था तथा इसका अवलम्बन करने का प्रचार इनके गगर्थको ने बहुत किया। इनके गगर्थको के अनुसार इस मान से नीचे दिये हुए लाभ होने हैं —

१ क्रयशक्ति की स्थिरता अथवा मुद्रा के मूल्य में स्थिरता रहना, यह अच्छी मान-पद्धति का मुख्य गुण है। द्विधातुमान पद्धति में अन्तरराष्ट्रीय प्रयोग से सोने तथा चाँदी की मुद्राएँ चलन में रहेंगी, तब किसी भी एक धातु का अभाव दूसरी धातु के अधिक उत्पादन में पूरा हो सकेगा। परिणामस्वरूप दोनों धातुओं की मुद्राओं की क्रयशक्ति में स्थिरता रहेगी। उदाहरणार्थ, दो पियक्वड आदमी जब एक-दूसरे के सत्रारे चलते हैं तो वे एक-दूसरे को गिरने से बचाते हैं, इसी प्रकार सोने का अभाव चाँदी के अधिक उत्पादन में अथवा चाँदी का अभाव सोने के अधिक उत्पादन से दूर होकर मूल्यों में स्थिरता बना रहता है। दूसरे, दोनों धातुओं की मुद्राएँ प्रमाणित मुद्राओं के रूप में चलन में होने से मुद्रा का परिमाण अधिक रहता है और इसमें यदि कुछ मुद्राएँ चलन में अधिक भी हो जाएँ तो उसका मूल्यों पर बहुत कम मात्रा में प्रभाव होना है।

यह बात एक-धातुमान वाले देश में सम्भव नहीं होगी क्योंकि जिस धातु का उत्पादन कम हो जाता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। चूँकि वस्तुओं की कीमतों का मूल्य इसी धातु में आँका जाता है इसलिए वस्तुओं की कीमतें घट जाएँगी।

२ इस पद्धति में मुद्राओं का परिमाण अधिक होने से कीमतें ऊँची रहती हैं जिससे उत्पादकों को लाभ होकर उत्पादन कार्य को प्रोत्साहन मिलता है। जब १८७३ में बाजारों में मन्दी आई तब वस्तुओं की कीमतें गिरने लगीं क्योंकि सोने की पूर्ति आवश्यकतानुसार नहीं थी। इसलिए इस पद्धति के समर्थकों के अनुसार यदि अन्तरराष्ट्रीय ढंग पर इस पद्धति का अवलम्बन किया जाता तो दोनों धातुओं की मुद्राएँ चलन में होने से मुद्रा-परिमाण अधिक होता और कीमतें बढ़ जातीं जिससे उत्पादन कार्य को प्रोत्साहन मिलता तथा मन्दी का निवारण होता। दूसरे, कीमतों के बढ़ने से देनदारों को भी लाभ होता है।

३ इस पद्धति में स्वर्ण तथा चाँदी की प्रमाणित मुद्राएँ होने के कारण विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है क्योंकि दोनों ही मुद्राएँ प्रमाणित होने के कारण स्वर्णमान रखने वाले राष्ट्रों तथा रजतमान रखने वाले राष्ट्रों में व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो सकते हैं। इसी के साथ ऐसे देशों की विनिमय-दर में भी स्थिरता रखी जा सकती है।

४ इस पद्धति में दोनों धातुओं की मुद्राएँ प्रमाणित होने के कारण अधिकोपों को अपने निधि की व्यवस्था एवं संचालन करने में मितव्ययिता होती है तथा मुद्रा का चलन अधिक होने के कारण बैंकों के व्याज की दर भी कम होती है।

५ द्विधातुमान प्रणाली अत्यन्त सरल प्रणाली है जिसे समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसलिए यह जनता का विश्वास भी शीघ्रता से प्राप्त कर सकती है।

द्विधातुमान पद्धति से हानियाँ—१ प्रेशम का चयन मुद्रा सिद्धान्त लागू होने में द्विधातुमान वाले राष्ट्रों में केवल एक ही मुद्रा—वह भी खराब मुद्रा—चलन में रहनी है क्योंकि दोनों धातुओं के एक अनुपात तथा बाजार अनुपात में समानता नहीं रहती। इसलिए यह अन्तरराष्ट्रीय ढंग पर अपनाने से ही मफल हो सकती है।

२ जब बाजार अनुपात एवं एक अनुपात में अन्तर होता है उस समय लेनदार अपने ऋणों का भुगतान अच्छी मुद्रा में अथवा महँगी धातु में लेना पसन्द करते हैं और दूसरी ओर देनदार खराब मुद्रा में अथवा सस्ती धातु में भुगतान करना चाहते हैं जिससे लेन-देन में कठिनाइयाँ होती हैं।

३ बाजार अनुपात एवं एक अनुपात में समानता कायम रखना, यह ठेकी खीर है जो व्यवहार में कभी भी सफलता में नहीं किया जा सकता।

अन्तरराष्ट्रीय द्विधातुमान—उपर्युक्त लाभ-दोषों के प्रतिरिक्त यदि अन्तर-राष्ट्रीय ढंग पर और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग से द्विधातुमान पद्धति का अवलम्बन किया जाय तो प्रेशम का सिद्धान्त लागू नहीं होगा क्योंकि उस दशा में अन्तर-राष्ट्रीय सहयोग से दोनों धातुओं के बाजार एवं एक अनुपात में समानता रखी जा सकती है। उसी प्रकार अन्तरराष्ट्रीय द्विधातुमान में किसी एक धातु की मुद्राओं की न्यूनता का समायोजन दूसरी धातुओं की मुद्राओं की अधिकता से हो जाता है, इसी की द्विधातुमान का क्षतिपूरक कार्य कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि चाँदी की कीमत बाजार में अधिक होनी है और टक्काल पर कम, तो ऐसी दशा में चाँदी के सिक्के गनाए जाएँगे और सोने के सिक्कों की अधिकता होगी। परिणामस्वरूप बाजार में सोने की कमी और चाँदी की अधिकता होगी जिससे चाँदी का मूल्य बाजार में कम हो जाएगा और सोने का अधिक। परिणामस्वरूप एक अनुपात एवं बाजार अनुपात में समानता आ जाएगी। यही बात स्वर्ण के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। इस क्षतिपूरक क्रिया के

कारण ही द्विधानुमान में मूल्यस्थैर्य रहता है। अतः अन्तरराष्ट्रीय समझौते पर इस मान पद्धति का खवलम्बन किया जा सकता है। इस मान का अन्तरराष्ट्रीय खवलम्बन करने के लिए दो मौद्रिक परिपदे भी बुलाई गई थी (१८७८ और १८६२ में) जिनमें इंग्लैण्ड के विरोध में तथा अन्य व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण इसका खवलम्बन नहीं हुआ।

### अन्य मौद्रिक मान

उपर्युक्त मान पद्धतियों के अनिश्चित समानान्तर अथवा समानुपात मान पद्धति, निर्देशाङ्क मान पद्धति, विनिमय मान तथा अशुद्ध द्विधानुमान पद्धति आदि अन्य मौद्रिक मान हैं जिनका अब हम विवेचन करेंगे।

१ अशुद्ध द्विधानुमान पद्धति (Limping Standard)—इस पद्धति में द्विधानुमान पद्धति की तरह सोना तथा चाँदी दोनों की मुद्राएँ मूल्य-मापक तथा विनिमय माध्यम होती हैं और दोनों मुद्राएँ प्रमाणित होनी हैं। किन्तु एक धातु की मुद्राओं का टक्कण-स्वातन्त्र्य जनता को न होते हुए सरकार के एकाधिकार में होता है। बहुधा सोने की मुद्राओं का टक्कण-स्वातन्त्र्य होता है तथा चाँदी की मुद्राओं का टक्कण केवल सरकार द्वारा ही होता है अर्थात् चाँदी की मुद्राएँ प्रमाणित होने हुए भी जनता उनका टक्कण कराने के लिए स्वतन्त्र नहीं होती। १८०३ में फ्रान्स में जब चाँदी की मुद्राओं का मुक्त टक्कण-स्वातन्त्र्य छीन लिया गया था परन्तु सोने के टक्कण के लिए जनता स्वतन्त्र थी, उस समय वहाँ यही पद्धति थी।

२ समानान्तर अथवा समानुपात-मान पद्धति (Parallel Standard)—इस पद्धति में स्वर्ण एवं चाँदी की मुद्राओं का मुक्त टक्कण होता है एवं दोनों धातुओं की प्रमाणिक मुद्राएँ होती हैं। किन्तु द्विधानुमान की तरह इनमें निश्चित टक्कण-अनुपात नहीं होता बल्कि वह टक्कण-अधिकारियों द्वारा समय-समय पर बाजार अनुपात की बराबरी में साया जाता है। इस पद्धति में चाँदी के बढ़ने सोने की मुद्राएँ बाजार भाव पर ही बढ़ती जाती हैं, इससे प्रेषण का भिद्वान्त लागू नहीं हो सकता।

इस पद्धति को कुछ अर्थशास्त्रियों ने नव द्विधानुमान (neo-metallism) भी कहा है।

३ निर्देशांक-मान पद्धति (Tabular or Index Number Standard)—इस पद्धति में उस देश की चलित-मुद्रा का मूल्य स्थिर रखने के हेतु निर्देशांक बनाए जाते हैं जिनके द्वारा आधार वर्ष की कीमतों की तुलना

कर मुद्रा का मूल्य निश्चित किया जाता है। इसका कारण यह है कि इस प्रकार कीमतों के अनुसार मुद्रा का मूल्य मदैव एकसा ही बना रहेगा, जिससे देनदारों-लेनदारों के लेन देन में समता रहेगी और किसी की हानि नहीं होगी। किन्तु इसमें अनेक अडचने आती हैं जिसमें इसका महत्व केवल सैद्धान्तिक ही है, व्यावहारिक नहीं। निर्देशांक मूल्य-स्तर का माध्यम बताते हैं किन्तु वे पूर्णतः ठीक नहीं होते, अतः वास्तविक स्थिति को दिग्दर्शित करने में असमर्थ होते हैं। आधार वर्ष के मूल्य-स्तर पर निर्भर होने के कारण आधुनिक कारणों का, जिससे कीमतों में उतार-चढ़ाव हुआ, विश्लेषण करने में असमर्थ होने से आधुनिक समय में उनका उपयोग समता नहीं ला सकता। तीसरे, देश की सरकार को निर्देशांक मूल्याएँ पुनः पुनः बनानी पड़ेंगी तथा इनको अद्यावत् करना पड़ेगा जो असम्भव-सा प्रतीत होता है। इन कठिनाइयों के कारण ही इसका कभी भी प्रयोग न हो सका।

४. द्विधातु-मिश्रित-मान पद्धति (Symetallism)—इसका प्रचार सन् १८८६ में प्रो० मार्शल ने किया था। इस पद्धति के अनुसार सोने तथा चाँदी को निश्चित परिमाण में मिलाकर इस मिश्रित धातु की मुद्रा का चलन हो तथा इस मुद्रा के बदले में सरकार एक निश्चित दर पर पत्र मुद्राएँ दे अथवा ले। इस पद्धति के अनुसार एक पत्र-मुद्रा के बदले किसी भी व्यक्ति को दोनों ही धातुएँ लेनी पड़ेंगी जिससे ग्रेडम का मिद्धान्त लागू नहीं हो सकेगा। यह पद्धति भी सैद्धान्तिक ही है, व्यवहारिक नहीं।

५. विनिमय-मान पद्धति (Exchange Standard)—इस पद्धति में देश के अन्तर्गत व्यवहारों में चाँदी अथवा कागज की गौण मुद्रा उपयोग में होती है तथा विदेशी विनिमय के लिए उसका सम्बन्ध किसी दूसरे देश के निफे के निश्चित दर पर जोड़ दिया जाता है, जिसे सरकार हमेशा समानता पर रखने का प्रयत्न करती है। यह आवश्यक नहीं कि दूसरे देश की मुद्रा स्वर्णमान पर ही हो। इस प्रकार के दो देशों के सिक्कों के गठबन्धन को विनिमय-मान पद्धति कहते हैं तथा जिस सिक्के से यह गठबन्धन होता है उस सिक्के का नाम पहिले जोड़ दिया जाता है, उदाहरणार्थ, स्टर्लिंग-विनिमय पद्धति, जिससे भारतीय साकेतिक मुद्रा (रुपया) का गठबन्धन स्टर्लिंग से १ शि० ६ पैं० की दर से हुआ था। परन्तु अब भारत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य होने से अब भारतीय सिक्के का मूल्य स्वर्ण में निश्चित होने से रुपया अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतन्त्र है। अब रुपया-स्टर्लिंग का सम्बन्ध विच्छेद हो गया है।

इसमें सबसे बड़ी हानि यह है कि जिस देश की मुद्रा में ऐसा विनिमय सम्बन्ध स्थापित किया जाता है उस देश की आर्थिक परिस्थिति का प्रभाव अपने देश की स्थिति पर भी पड़ता है। दूसरे, विदेशी विनिमय के लिए दोनों देशों को एक-दूसरे की मुद्राएँ अपने-अपने निधि में रखनी पड़ती है।

१. अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा-मान पद्धति (Paper Currency Standard or Managed Currency Standard)—इस पद्धति में देश में मूल्यमापक तथा विनिमय-माध्यम का कार्य पत्र-मुद्रा ही करती है जिसका मूल्य किसी भी धातु में निश्चित नहीं किया जाता। इस प्रकार की पत्र-मुद्रा युद्ध-काल में अथवा सकटमय स्थिति में चलन में आती है। इस पद्धति के मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं —

१ पत्र मुद्रा ही प्रमाणित मुद्रा होती है एवम् अर्थापित विधिग्राह्य होती है।

२ पत्र-मुद्रा का मूल्य स्वर्ण अथवा अन्य किसी धातु से निश्चित नहीं किया जाता और न इसका स्वर्ण में किसी भी कार्य के लिए परिवर्तन हो हो सकता है।

३ पत्र-मुद्रा चलाने वाला बैंक अथवा सरकार चलन को इस प्रकार कम या अधिक करती है जिससे मूल्य-स्तर में समानता रहे। अर्थात् मूल्य-स्तर में समानता रखने के लिए सरकार द्वारा अथवा मुद्रा-संचालक बैंक द्वारा चलन का नियन्त्रण (management) किया जाता है।

४ विदेशी ऋणों के भुगतान के लिए देश में स्वर्ण-निधि की आवश्यकता होती है किन्तु आजकल अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋणों से भुगतान होने के कारण ऐसी किसी भी निधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। (इस प्रकार अन्तर-राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मार्फत ऋणों का भुगतान करने की व्यवस्था द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त १९४७ में की गई है।)

इस पद्धति के अनेक दोष हैं—१ पत्र-मुद्रा किसी धातु विरोध से सम्बन्धित न होने के कारण चलनाधिक्य होने की सम्भावना रहती है।

२ इसमें किसी भी हद तक मूल्य-स्तर में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि मुद्रा का विनिमय धातु-निधि पर निर्भर नहीं रहता एवं उसको चलाने वाली संस्था के ऊपर निर्भर रहता है।

३ पत्र-मुद्रा राष्ट्रीय मुद्रा होने के नाते अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में अनेक अड़चने उपस्थित होती हैं क्योंकि देश के मूल्य-स्तर में मदैव उत्तार-चढ़ाव होता रहता है जिसे विनिमय-दर में स्थिरता नहीं रहती।

४ जब सभी देशों में पत्र-मुद्रा-मान होता है उस समय किसी भी देश की आर्थिक परिस्थिति का परिणाम अन्य देशों की आर्थिक स्थिति पर होता है।

पत्र मुद्रा मान पद्धति की ये कठिनाइयाँ अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप तथा अन्तर-राष्ट्रीय बैंक की स्थापना होने से दूर हो गई हैं क्योंकि अन्तरराष्ट्रीय भुगतान अब इन्हीं सस्थाओं द्वारा होता है तथा प्रत्येक देश की मुद्रा का निश्चित स्वर्ण-मूल्य भी अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप द्वारा निश्चित कर दिया गया है। इन कारणों से पत्र-मुद्रा मान पद्धति होते हुए भी स्वर्णमान के सब लाभ अब प्राप्त हो सकते हैं।

**भारतीय मौद्रिक मान—**भारत में १९४६ तक स्टर्लिङ्ग विनिमय मान पद्धति थी जिसका सम्पूर्ण विवेचन “भारतीय चलन का इतिहास” नामक अध्याय में हम आगे करेंगे। वर्तमान पद्धति में भारत में पत्र मुद्रा तथा निश्चित के रुपये—जिनके सब लक्षण गौण मुद्रा के हैं—प्रमाणित मुद्रा की तरह चलन में हैं, जो असीमित विधिग्राह्य हैं। १९४६ तक रुपये का गठबन्धन विदेशी विनिमय की सुविधा के लिए स्टर्लिङ्ग से १८ पैसे प्रति रुपये की दर से किया गया था तथा इस दर को स्थिर रखने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की थी। रुपया ही हमारे यहाँ मूल्यमापक तथा विनिमय-माध्यम है जिसके बदले में किसी भी समय पत्र-मुद्राएँ तथा अन्य गौण मुद्राएँ ली जा सकती हैं तथा विदेशी विनिमय के लिए उन्हीं स्टर्लिङ्ग में बदला जा सकता है जो कायदे में इङ्गलैंड की अपरिपक्व पत्र-मुद्रा है एवं जिसका १९४७ तक स्वर्ण से कोई सम्बन्ध नहीं था। परन्तु अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप के द्वारा अब प्रत्येक देश के चलन को स्वर्ण में निश्चित मूल्य दिया गया है जिसके अनुसार रुपये का स्वर्ण मूल्य ३३ २२½ निश्चित किया गया था जो अबमूल्यन के पश्चात् २१ सट रह गया। इस प्रकार अब भारतीय रुपया अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में स्वतन्त्र मुद्रा हो गया है जिसको हम किसी भी देश की मुद्राओं में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप द्वारा निर्धारित स्वर्ण मूल्य के अनुसार बदल सकते हैं। अब रुपया एवं स्टर्लिङ्ग का सम्बन्ध विच्छेद हो गया है जिसमें रिजर्व बैंक की, रुपये का स्टर्लिङ्ग मूल्य १ शि० ६ पैसे बनाए रखने की, जिम्मेदारी भी समाप्त हो गई है। इसलिए वर्तमान समय में भारत में अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान है।

### सारांश

मुद्रामान उस पद्धति को कहते हैं जो सर्वग्राह्य हो एवं जिससे देशी एवं विदेशी व्यापार में सुगमता हो। मुद्रामान किसी ऐसी वस्तु से सम्बन्धित होते

हैं जिनमें बाहरी मूल्य होता है अथवा किसी ऐसी वस्तु से जिसका बाहरी मूल्य कुछ नहीं होता ।

एक अच्छी मुद्रामान प्रणाली में मूल्य-स्थिरता, सरलता, लोच, स्वयंपूर्ण कार्यशीलता तथा मितव्ययिता ये गुण होने चाहिए ।

मुद्रामान पद्धति देश की आर्थिक अवस्था के अनुसार अपनाई जा सकती है ।

एक धातुमान के अन्तर्गत स्वर्ण या चाँदी की प्रमाणित मुद्राएँ होती हैं जो मूल्यमापन एवं विनिमय माध्यम का कार्य करती हैं । जब ऐसी प्रणाली स्वर्ण की होती है तब उसे स्वर्णमान तथा जब चाँदी की होती है तब उसे रजतमान कहते हैं । स्वर्णमान के मुख्य तीन रूप होते हैं—स्वर्ण मुद्रामान, स्वर्ण विनिमय-मान तथा स्वर्ण धातुमान ।

द्विधातुमान में स्वर्ण एवं चाँदी के सिक्के प्रमाणित होते हैं जो निश्चित वैधानिक अनुपात में चलन में रहते हैं । यह पद्धति १७६२ में संयुक्त राज्य अमरीका में अपनाई गई परन्तु वैधानिक एवं बाजार अनुपात में भिन्नता होने से एक ही मुद्रा चलन में रहने लगी । अन्त में १८७३ में चाँदी की स्वतन्त्र डलाई न रही और १८७६ में अमरीका ने स्वर्णमान ही अपना लिया ।

इसी प्रकार फ्रेंच तथा लेटिन मौद्रिक सघ में यह मान १८०३ से १८७३ तक चलन में रहा । परन्तु ब्रूँकि बाजार एवं टकसाली अनुपात में भिन्नता रहती थी इसलिए १८७४ में इस सघ में भी चाँदी की स्वतन्त्र डलाई समाप्त कर दी गई । द्विधातुमान अपनाने के लिए १८७८ और १८६२ में दो अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन भी हुए परन्तु इङ्गलैण्ड के तीव्र विरोध के कारण इसे अन्तरराष्ट्रीय ढंग पर न अपनाया जा सका ।

द्विधातुमान के लाभ अथशक्ति की स्थिरता, कीमतें ऊँची रहने से उत्पादकों की लाभ विदेशी व्यापार में वृद्धि बैंकों को निधि रखने में मित-व्ययिता एवं सरलता ।

घोशम का नियम लागू होने से केवल एक ही धातु की मुद्रा चलन में होती है, लेन देन में कठिनाइयाँ, बाजार एवं टकसाली अनुपात में असमानता ये दोष हैं ।

घोशम का नियम घोशम ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया कि जहाँ किसी देश में दो प्रकार के प्रमाणित सिक्के साथ ही साथ चलन में रहते हैं तो सराव मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है । अच्छी मुद्राएँ या तो

जनता संग्रह करती है या गलाती है या विदेशी भुगतान में देती है। तीन स्थितियों में यह नियम लागू होता है—

(१) एकधातुमान में जब नये एवं पूर्ण वजनी सिक्कों के साथ पुराने एवं घिसे हुए सिक्के समान मूल्य पर चलते हैं तब नये सिक्के चलन से बाहर हो जाएंगे।

(२) द्विधातुमान में जब चांदी एवं सोने के सिक्के एक निश्चित अनुपात में चलन में होते हैं तब यदि बाजार अनुपात में भिन्नता धावे तो टकसाल पर मही मुद्राएँ (खराब मुद्राएँ) टकसाल पर जो मुद्राएँ सस्ती होंगी (अच्छी मुद्रा) उन्हें चलन से बाहर कर देंगी।

(३) जब धातुमुद्रा एवं कागजी मुद्रा दोनों ही प्रमाणित मुद्राओं के रूप में समान मूल्य पर चलन में हो तो कागजी मुद्राएँ धातुमुद्रा को चलन से बाहर कर देंगी।

नियम की सीमाएँ जब खराब एवं अच्छी मुद्राएँ देश की आवश्यकता से कम हों, खराब मुद्राओं का जनता विरोध करे, बुरी मुद्रा का अवमूल्यन धीरे-धीरे किया जाय कि जनता समझ न सके, अन्तरराष्ट्रीय द्विधातुमान हो।

अन्य मुद्रामान अशुद्ध द्विधातुमान पद्धति में दो धातुओं के सिक्के प्रमाणित मुद्रा के रूप में निश्चित अनुपात में चलते हैं परन्तु एक धातु के सिक्के की स्वतन्त्र दलाई नहीं होगी। समानांतर-मान में स्वर्ण एवं चांदी दोनों ही प्रमाणित मुद्राएँ होती हैं और उनकी स्वतन्त्र दलाई होती है किन्तु इनका आपसी अनुपात बाजार के अनुपात के साथ होता है। मिश्रित द्विधातुमान में स्वर्ण एवं चांदी को निश्चित अनुपात में मिलाकर सिक्के बनाये जाते हैं।

विनिमय प्रमाण पद्धति में देश की आन्तरिक मुद्रा कागज या अन्य गौण धातु की होती है तथा विदेशी विनिमय के लिए उसे किसी दूसरे देश के सिक्के से निश्चित दर पर सम्बन्धित किया जाता है। निर्देशांक मान में देश की मुद्रा का मूल्य निर्देशांक के अनुसार बदलता रहता है। यह पद्धति व्यवहारिक नहीं है क्योंकि निर्देशांक के अनुसार मूल्य निश्चित करने में कठिनाई होती है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रामान में नोट विनिमय माध्यम होते हैं जिनका मूल्य किसी अन्य धातु से निश्चित नहीं होता। इसमें चलनाधिक्य का भय बना रहता है।

भारत इन समय अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान पर है।

## स्वर्णमान पद्धति का इतिहास एवं भविष्य

स्वर्णमान ही क्यों ?

पिछले अध्याय में हमने देखा कि द्विधातुमान की अनेक कठिनाइयों के कारण तथा चाँदी की कीमतों में अधिक अन्तर होने रहने के कारण उस पद्धति का परित्याग कर दिया गया, जिसके बाद विद्वत् के सभी प्रमुख देशों में स्वर्णमान को किसी न किसी रूप में अपनाया गया। इतना ही नहीं अपितु आज भी अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अन्तरराष्ट्रीय ढंग पर स्वर्णमान का अवलम्बन कर स्वर्ण को मौद्रिक सिंहासन पर बिठाकर उसको मौद्रिक क्षेत्र में प्राचीन महत्त्व देता है। स्वर्ण की विजय के चार प्रमुख कारण हैं —

१ चाँदी की अपेक्षा सोने में छोड़े ही आकार में अधिक मूल्य रहता है, इससे उसमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में खर्च की कमी तथा सरलता होती है। अतः सबसे अधिक बहुनीयता स्वर्ण में होती है।

२ १९वीं शताब्दी में चाँदी के मूल्य में सोने के मूल्य की अपेक्षा द्रुत-गति से परिवर्तन हुए परन्तु सोने के मूल्य में स्थिरता बनी रही अर्थात् १८१९ से, जब इंग्लैंड में इस मान का अवलम्बन किया गया, १९१४ तक मूल्य-स्तर में समानता रही।

३ अन्य वस्तुओं की तरह सोने की कीमतों पर उसके उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अर्थात् सोने का उत्पादन बढ़ने में न तो सोने की कीमत घटती है और न उत्पादन कम होने में कीमत बढ़ती ही है, क्योंकि टंकमाल से उसके रूप-विकृत कर अन्य निश्चित ही रहता है। हाँ, उसके उत्पादन का प्रभाव योजना-वास्तुओं के मूल्य-स्तर पर अवश्य होता है क्योंकि स्वर्णमान में सोने की कीमत निश्चित की जाती थी किन्तु उसका मूल्य निश्चित नहीं किया जाता था।

४ स्वर्ण का बाजार असीमित था अर्थात् सोने की निश्चित कीमतों पर

सोना वही से भी खरीदा जाता था तथा बेचा भी जाता था। इन कारणों से ही स्वर्णमान का उपयोग विशेष रूप से सफल हुआ।<sup>१</sup>

१९१४ तक

उपर्युक्त कारणों में स्वर्णमान की १९वीं शताब्दी में विजय हुई और विश्व के प्रमुख राष्ट्रों में इसे अपनाया गया। फिर १८६२ तक द्विधातुमान पद्धति के अपनाने के लिए चर्चाएँ तथा परिपदे होती रही जिसका अन्त इसी काल में हुआ। १९१४-१६ की मजदूरी के प्रारम्भ तक इंग्लैंड, अमेरिका आदि प्रमुख राष्ट्रों में स्वर्ण चलन पद्धति का ही अवलम्बन था जिसमें स्वर्ण मूल्यमापक था तथा उसकी मुद्राएँ चलन में थी जो असीमित विधिप्राप्त थी एवं उनका टक्का-स्वातन्त्र्य मुक्त था अर्थात् कोई भी व्यक्ति स्वर्ण ले जाकर उसकी टक्काल से सिक्कों में डलवा सकता था। इस प्रकार सोने के सिक्के पूर्णतः प्रमाणित सिक्के थे। इन्हीं से देश की अन्य गौण मुद्राओं का मूल्य-सम्बन्ध था। विदेशी विनिमय का आधार भी स्वर्ण ही था अर्थात् स्वर्ण की ममता पर देश-विदेशों में ऋणों का भुगतान होता था और इनकी विनिमय-दर स्वर्ण-निर्यात बिन्दु तथा स्वर्ण-आयात बिन्दु के बीच बदलती रहती थी। स्वर्ण की घिसावट से होने वाली हानि बचाने के लिए सब देशों में स्वर्ण-चलन के बदले पत्र-चलन था जो किसी भी समय स्वर्ण से परिवर्तित किया जा सकता था, जिनके लिए पत्र-संचालक बैंक अपने पास स्वर्ण निधि रखते थे। किन्तु प्रत्येक बैंक जो साखमुद्रा का प्रसार करता था, उसे स्वर्ण निधि रखना पड़ता था जिससे देश का मोटा अधिक मात्रा में निधि में ही रहता था। इसलिए इसमें मितव्ययिता करने के उद्देश्य से निधि का केन्द्रीयकरण करना (centralisation of reserve) उचित समझा गया जिसके लिए प्रत्येक देश में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना की गई जो साख-मुद्रा तथा पत्र मुद्रा का नियमन एवं नियंत्रण करते थे और साथ ही स्वर्ण निधि का भी। इन्हीं के हाथों सोने का क्रय विक्रय एक निश्चित दर से किया जाता था। इसी के साथ स्वर्ण बाजार खुला होने के कारण अथवा अन्तरराष्ट्रीय बाजार में सोने की खरीद अथवा विक्री पर किसी भी प्रकार की रोक न होने के कारण डम बान में स्वयंपूर्ण कार्यशीलता थी। फलस्वरूप अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में अपने आप वस्तुओं के मूल्यस्तरों में समानता रखी जाती थी। उदाहरणार्थ, यदि किसी भी

<sup>१</sup> For detailed reference see *Gold and the Gold Standard* by E. W. Kemmerer.

देश की मुद्रा की विनिमय-दर में वृद्धि होती थी तो उस देश की कीमते अन्य देशों की अपेक्षा महँगी होने के कारण वहाँ निर्यात अधिक हो जाता था। उसी प्रकार दूसरे देशों की कीमते उस देश की अपेक्षा कम होने से विदेशों से माल यहाँ अधिक आता था। परिणामस्वरूप वह देश ऋणी हो जाता था तथा उसे विदेशों में भुगतान के लिए सोना देना पड़ता था अथवा विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती थी जिसके कारण विदेशी मुद्रा की कीमते भी बढ़ती थी और इस प्रकार मूल्य-स्तर में समानता आ जाती थी तथा विनिमय-दर में भी समानता रखी जाती थी। इस प्रकार इस पद्धति में स्वयंपूर्ण कार्यशीलता थी।

प्रथम महायुद्ध के पूर्व एक दूसरे रूप में भी स्वर्णमान का उपयोग होता था। इस मान का मूल हेतु स्वर्ण के उपयोग में मितव्ययिता लाना तथा स्वर्ण-मान वाले व रजतमान वाले राष्ट्रों की विनिमय-दर में स्थिरता रखना था, जिससे रजतमान वाले राष्ट्रों में भी विदेशी व्यापार बढ़ाया जा सके। इस पद्धति में सोने के सिक्के चलन में नहीं रहते बल्कि देशी व्यापारिक व्यवहारों में चाँदी के सिक्के तथा पत्र-मुद्रा का उपयोग होता है जो असीमित विधिप्राप्त होती है। इन मुद्राओं को किसी ऐसे देश की मुद्रा में सम्बन्धित किया जाता है जो स्वर्णमान पर हो। देशी कामों के लिए ये मुद्राएँ मोने में परिवर्तित नहीं होती किन्तु विदेशी भुगतान के लिए सरकार सोना अथवा विदेशी मुद्राएँ देने के लिए बाध्य होती है। इस पद्धति को स्वर्ण-विनिमय पद्धति कहते हैं। यह भारत में १८६८ से १९१८ तक प्रयोग में थी। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में भी सोना विनिमय माध्यम के रूप में काम आता है किन्तु वस्तुओं की खरीद बिक्री के लिए नहीं, बल्कि विदेशी चलन की खरीद बिक्री के लिए। अतः इसमें केन्द्रीय बैंकों को विदेशी विनिमय में निधि रखना पड़ना है जिसमें वे विदेशी भुगतान के लिए देशी मुद्रा के बदले विदेशी विनिमय दे सकें। उसी प्रकार विदेशी बैंकों में स्वर्ण निधि रखना पड़ना है जिसमें वे विदेशी दलदलारों का आवश्यकता के समय भुगतान किया जाय।

इस पद्धति का अवनमन जावा, भारत, आस्ट्रिया और हंगरी में १९वीं शताब्दी के अन्त में था तथा १९०० से १९३० तक के काल में अफ्रीका देशों में था। इसकी कार्य-पद्धति दो प्रकार की है—एक तो उन देशों में विनिमय-दर स्थापित करना जो स्वर्णमान पर हैं अथवा जिनका चलन स्वर्ण से सम्बन्धित है। दूसरे, ऐसे देशों में विनिमय दर स्थापित करना जिनमें एक देश स्वर्ण पर तथा दूसरा दल चाँदी पर आधारित है जैसे भारत तथा ब्रिटेन। भारत की

स्वर्ण-विनिमय पद्धति दूसरे प्रकार की थी जिसे मुद्रा रूप में स्वर्ण विनिमय-मान नहीं कहा जा सकता किन्तु विनिमय-मान कहा जा सकता था क्योंकि भारतीय रुपये का गठबन्धन एक निश्चित दर पर ( १८ पैसे प्रति रुपया ) किया गया था और स्टालिग स्वर्ण पर आधारित होने के कारण ही हमारी पद्धति को स्वर्ण-विनिमय-मान कहा जाता था । इसमें विनिमय-दर की स्थिरता के लिए केन्द्रीय बैंक अथवा सरकार द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता रहती है इसलिए यह पूर्ण-रूप से स्वयंपूर्ण बायेंशीज नहीं है अपितु नियन्त्रित चलन पद्धति (managed currency standard) है ।

### स्वर्ण-विनिमय-मान की कार्य-पद्धति

इस पद्धति में विनिमय मान वाले देश या केन्द्रीय बैंक स्वर्णमान वाले देश के केन्द्रीय बैंक के सहयोग से इस पद्धति का नियन्त्रण करता है । विनिमय-मान वाले देश का केन्द्रीय बैंक स्वर्णमान वाले देश के केन्द्रीय बैंक से स्वर्ण-निधि रखता है जिसमें से वह उस देश का विदेशी विनिमय निश्चित दर पर खरीदता है तथा बेचता है और उसका ध्येय यही रहता है कि विनिमय-दर में सदैव स्थिरता बनी रहे । इसी प्रकार का निधि "पत्र चलन निधि" वाले देश का केन्द्रीय बैंक अपने पास रखता है जिसमें से विदेशियों की माँग की पूर्ति उस देश के देनदारों के भुगतान के लिए की जाती है । इस पद्धति में केन्द्रीय बैंक चलन के प्रसार एवं सफाई द्वारा विदेशी विनिमय की दर का नियमन करता है । भारतीय स्वर्ण विनिमय मान की कार्य-पद्धति से इसका रूप हम पूर्णतः समझ सकते हैं ।

जब भारत में स्वर्ण विनिमय मान था उस समय भारतीय सरकार पर विदेशी ऋणों का भुगतान स्वर्ण में करने की वैधानिक जिम्मेदारी थी । उसी प्रकार इङ्ग्लैंड के आयात व्यापारियों को उनके भारतीय देनदारों को रुपये चुकाने की जिम्मेदारी इङ्ग्लैंड में भारत सचिव ( सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ) पर थी । इस प्रकार यह चलन पद्धति सदा सरकार की व्यवस्था एवं देख रेख में थी जिनमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा भारतीय सरकार दो बैंकों की भाँति कार्य करते थे । आन्तरिक व्यापारों तथा विनिमय के लिए रुपया ही प्रमाणित एवं असीमित ग्राह्य मुद्रा थी तथा बाह्य विनिमय ( external exchanges ) के लिए रुपया स्वर्ण मुद्रा के रूप में था जिसका मूल्य १ सि० ४ पैसे निश्चित किया गया था ।

भारत के विदेशी व्यापार का शेष सदा हमारे पक्ष में ही रहता था किन्तु

हमें प्रतिवर्ष व्याज तथा अन्य खर्चों के लिए इङ्ग्लैण्ड को कुछ वार्षिक रकम देनी पड़ती थी जिसे घर खर्च (home charges) कहते हैं। इस राशि का भुगतान या तो दानो देशों से एक्-दूमरे को माना भेजकर हो सकता था, जो खर्चीला तथा अमुविधाजनक तरीका था। दूसरा तरीका यह था कि भारत-सचिव भारत की ओर से इङ्ग्लैण्ड के देनदारों से माना लेकर बदल में उन्हें रुपया-बिपत्र (rupee bills or council bills) दे जिनका भुगतान भारत सरकार करे। इस प्रकार जो रकम भारत-सचिव के पान प्राप्ती थी उनमें से घर-खर्च निकाल कर बाकी रकम भारत सरकार के नाम जमा कर दी जाती थी। अंग्रेज देनदार भारतीय लेनदारों को ये रुपया-बिपत्र भेज देते थे जिनका भुगतान सरकारी खजाना में उनके बैंक के मार्फत उनसे भारतीय मुद्राओं में किया जाता था। इस प्रकार भारतीय लेनदारों का तथा अंग्रेजी सरकार के घर-खर्च का भुगतान परस्पर हो जाता था। जो शेष रकम भारत-सरकार के नाम इङ्ग्लैण्ड में रहती थी उसका उपयोग भारत सरकार अपने अन्य खर्चों के लिए करती थी। इसी प्रकार जब अंग्रेज लेनदारों को भुगतान करने की आवश्यकता पड़ती थी उस समय भारत सरकार रुपये के बदले में १६ पेंस की दर से भारतीय लेनदारों को स्टर्लिंग-बिपत्र (sterling bills or reverse council bills) देवती थी, जो भारतीय देनदार अपने लेनदारों को इङ्ग्लैण्ड में भेज देते थे। इनका भुगतान भारत-सचिव द्वारा अंग्रेज लेनदारों की हुण्डी के बदले स्टर्लिंग देकर किया जाता था। यह पद्धति हमारे यहाँ १९१४ तक इसी प्रकार कार्य करती थी।

यह पद्धति तभी तक अच्छे ढंग पर कार्य कर सकती है जब तक उस देश की परिस्थिति अच्छी है जिसमें स्वर्ण-निधि रखा गया है। परन्तु वहाँ की आर्थिक परिस्थिति खराब होते ही उन घटनाओं का प्रभाव दूसरे देशों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है जिसमें विनिमय दर में स्थिरता नहीं रहती और न विदेशी विनिमय-दर का नियमन ही ठीक प्रकार से होना है और यही आगे चलकर हुआ भी।

१९१४ से १९१६ तक

१९१४ में जब महायुद्ध प्रारम्भ हुआ उस समय कुल ५६ देश (स्वर्ण-विनिमय वाले देशों को मिलाकर) स्वर्णमान पद्धति पर थे। युद्धकाल के प्रारम्भ के दो-तीन वर्षों में ही स्वर्णमान परित्याग कर दिया गया और लगभग सभी देशों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का चलन हो गया क्योंकि युद्धजन्य परिस्थितियों के

कारण मुद्रा की आवश्यकता बढ़ गई थी जिसे पूरा करने का यही एकमात्र उपाय उपलब्ध था। मन्चे पहिले १९१७ में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वर्ण-निर्यात पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं बल्कि युद्धग्रस्त देशों के पुनः स्थापन में अधिक व्यय हुआ जिसके फलस्वरूप पत्र-मुद्रा वाले देशों को बहुत हानि हुई। कुछ देशों में तो वस्तुओं का मूल्य-स्तर बहुत ही बढ़ गया, विशेषतः जर्मनी, रूस और पोलैण्ड में। फ्रांस, बेल्जियम आदि देशों में मुद्रा-स्फीति से भयंकर दुष्परिणाम हुए किन्तु वहाँ की कीमतों का स्तर ३०० से ६०० प्रतिशत से अधिक ऊँचा नहीं गया। इन कारण पत्र-मुद्रा से जनता का विश्वास उठ गया था। लोग कोई ऐसी ठोस मुद्रा चाहते थे जिसमें जनता का विश्वास हो अथवा जो ऐसा विश्वास शीघ्र ही प्राप्त कर सके। ऐसी वस्तु स्वर्ण के अतिरिक्त दूसरी न थी।

इस उद्देश्य से विश्व के विभिन्न भागों में अनेक योजनाएँ बनाई गईं जिसमें अन्तरराष्ट्रीय ढंग पर स्वर्णमान का पुनः स्थापन हो सके। इस उद्देश्य से ब्रुसेल्स में १९२० में एक अन्तरराष्ट्रीय राजस्व-परिषद् (International Financial Conference) बुलाई गई जिसमें ३६ राष्ट्रों ने प्रतिनिधित्व किया। इस परिषद् ने यह स्वीकृत किया कि जिन राष्ट्रों ने स्वर्णमान का परित्याग किया वे पुनः स्वर्णमान का अवलम्बन करें। इसके दो वर्ष बाद ही जिनेवा में एक अन्तरराष्ट्रीय अर्थ-परिषद् (International Economic Conference) बुलाई गई थी। उसने घोषणा की कि “प्रत्येक देश के चलन में मूल्य-स्थिर्य होना आवश्यक है जिससे वहाँ का आर्थिक पुनर्संज्ञा हो सके और यूरोपीय चलन किसी सर्वसम्मति वस्तु पर—जो स्वर्ण है—आधारित किया जाय जिससे शीघ्र ही स्वर्णमान का अवलम्बन किया जा सके।”

### १९१६ के बाद

**स्वर्णमान का पुनः स्थापन**—ऊपर हमने यह बताया कि स्वर्ण के पुनः स्थापन के लिए अन्तरराष्ट्रीय देशों ने एक मत से अपनी सम्मति दी परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में दो विचारधाराएँ उस समय प्रचलित थीं। पहिली विचारधारा के अनुसार स्वर्णमान का पुनः स्थापन होना था, जिसके समर्थक प्रो० गुस्टाव कैंमेल एवं उनके अन्य साथी थे। दूसरी विचारधारा के समर्थकों का, जिसमें कीन्स तथा उनके अन्य साथी थे, कहना था कि स्वर्णमान का परित्याग कर सुसंचालित पत्र-मुद्रा-मान का वैज्ञानिक ढंग पर अवलम्बन किया जाय क्योंकि कीन्स के मतानुसार स्वर्ण भूतकालीन पिछड़ी अवस्था की स्मृति था।

इन दोनों विचारधाराओं के होते हुए भी जनता का विश्वास आकर्षित करने के लिए स्वर्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई भी दूसरी वस्तु नहीं थी जिसका अवलम्बन उस परिस्थिति में होगा सम्भव हो सके स्वीकारिए स्वर्णमान का पुनः संस्थापन हुआ ।

युद्ध के बाद सबसे पहिला देश जहाँ स्वर्णमान का पुनः संस्थापन हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका था । इस देश में जून १९१६ में ही स्वर्ण के निर्यात सम्बन्धी सब प्रतिबन्ध हटा दिये गये । इसके बाद धीरे-धीरे अन्य देशों में भी स्वर्णमान का फिर से अवलम्बन किया गया । इस प्रकार १९२७ में स्वर्णमान पर आधारित राष्ट्रों की समस्या युद्धपूर्व समस्या में भी अधिक हो गई थी । इंग्लैण्ड में स्वर्णमान का पुनः संस्थापन १९२४ में तथा भारत में १९२७ में किया गया ।

**मूल्य-स्पर्ध की दूर—**अब इस समय में जिस दर पर पत्र-मुद्रा का स्वर्ण में परिवर्तन किया जाय तथा इस नई स्वर्ण-मुद्रा में स्वर्ण की मात्रा कितनी हो, यह विवादग्रस्त था । जिन देशों में युद्धजन्य परिस्थिति के कारण अवमूल्यन अधिक मात्रा में हुआ था उनके लिए युद्धपूर्व स्वर्ण-समता पर आना कठिन था क्योंकि इन देशों को मुद्रा का अधिक मात्रा में संकोच करना पड़ता । इसलिए ऐसे देशों के लिए एकमात्र उपाय यही था कि वे स्वर्ण-मुद्रा का मूल्य उसी जगह स्थिर करें जहाँ पर कि वह पत्र-मुद्रा के वर्तमान मूल्य का ठीक-ठीक प्रतिनिधित्व करे । अर्थात् पत्र-मुद्रा का स्वर्ण-मूल्य पहिले की अपेक्षा बानूनन कम किया जाय—जिसे हम वैधानिक अवमूल्यन कहते हैं—जिससे मुद्रा-संकोच में होने वाली हानियों से देश बच सकता है । स्वर्णमान के पुनः संस्थापन के बाद अवमूल्यन द्वारा चलन में मूल्य-स्पर्ध लाने वाले देश फ्रान्स, बेलजियम, इटली, चीन आदि थे ।

कुछ देन ऐसे भी थे जहाँ पत्र-मुद्रा का सोने के सम्बन्ध में क्रयशक्ति पर बहुत कम प्रभाव पड़ा था जैसे अमेरिका, कनाडा, स्विटजरलैंड, अर्जेंटीना आदि । इन देशों में स्वर्णमान का पुनः संस्थापन युद्धपूर्व दर पर ही किया गया ।

इस प्रकार पत्रमुद्रा का दर स्वर्णमान के संस्थापन के बाद युद्धपूर्व स्वर्ण-समता पर मुद्रा-संकोच द्वारा स्थिर किया जाय अथवा स्वर्ण-समता की दर में कमी करके अथवा अवमूल्यन में स्थिर किया जाय, यह विवादग्रस्त समस्या थी, जिसका हल किस प्रकार किया गया वह ऊपर बताया गया है ।

इस प्रकार दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया, नार्वे, इंग्लैंड आदि देशों में—जिनमें इंग्लैंड प्रमुख था—स्वर्णमान वा पुनः संस्थापन मुद्रा-संकोच द्वारा किया गया तथा वहाँ की प्रत्येक मुद्रा का स्वर्ण-मूल्य युद्धपूर्व स्वर्ण-समता पर स्थिर किया गया। किन्तु इस स्वर्णमान पद्धति के लक्षण युद्ध पूर्व स्वर्णमान से बिल्कुल भिन्न थे। स्वर्ण-मुद्रा-मान तथा स्वर्ण-विनिमय-मान के दोषों का निवारण करने एवं स्वर्ण की मितव्ययिता करने का इस पद्धति में प्रयत्न किया गया था—जिसे स्वर्ण-धातु-मान कहते हैं।

इंग्लैंड में १९२५ में स्वर्णमान के पुनः संस्थापन के लिए “गोल्ड स्टेण्डर्ड ऐक्ट” स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार स्वर्ण का टक्का-स्वातन्त्र्य एवं चलन का स्वर्ण मुद्राओं में परिवर्तन वन्द किया गया। इस ऐक्ट द्वारा बैंक ऑफ इंग्लैंड को यह अधिकार दिया गया कि वह ३ पौंड १७ शिलिंग १० ३/४ पैसे प्रति औंस की दर से ४०० औंस वजन के छड़—जिनमें ३/४ भाग विशुद्ध सोना होता था—बेचे। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति चलन का ४०० औंस से कम सोने में परिवर्तन नहीं कर सकता था जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड के निधि का सोना जनता के पास जाने से बच गया।

इस पद्धति में स्वर्ण का निश्चित मूल्य पर एवं निश्चित वजन में क्रय-विक्रय करने के लिए केन्द्रीय बैंकों की स्थापना अनिवार्य समझी गई थी। इसी हेतु भारत में भी १९३५ में हिल्टन यंग समिति (१९२७) की सिफारिशों के अनुसार “रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया” स्थापित किया गया।

इस पद्धति में स्वर्ण-चलन न होने से स्वर्ण में मितव्ययिता होती है। देश में पत्र-मुद्रा तथा प्रतीक मुद्रा का चलन होता है जिसकी परिवर्तनशीलता के लिए केन्द्रीय बैंक में स्वर्ण निधि रखा जाता है जो अन्तरराष्ट्रीय भुगतान के लिए उपयोगी होता है। देश के स्वर्ण निधि का केन्द्रीकरण करने के लिए तथा स्वर्ण-धातुमान प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए १९२० से १९२७ के बीच में लगभग सभी प्रगतिशील देशों में केन्द्रीय बैंकों की स्थापना की गई। इस प्रकार यदि सब देशों के केन्द्रीय बैंक सहयोग से कार्य करें तो स्वर्ण के मूल्य में भी स्थिरता रखी जा सकती है। इन गुणों के कारण ही युद्धोपरान्त स्वर्ण मान का अवलम्बन हुआ।

**युद्धपूर्व एवं युद्धोपरान्त स्वर्णमान के लक्षण—साम्य-भेद**

उपर्युक्त इतिहास के अनुसार युद्ध के पहिले तथा बाद में जो स्वर्णमान

पद्धति विश्व में प्रचलित थी उसमें क्या लक्षण थे, यह अब हम तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं। युद्धोपरान्त स्वर्णमान से निम्नलिखित लाभ थे —

युद्धपूर्व स्वर्णमान	युद्धोपरान्त स्वर्णमान
१. स्वर्ण विनिमय माध्यम तथा मूल्य-मापन का कार्य करता है।	१. स्वर्ण केवल मूल्यमापक है, विनिमय माध्यम नहीं।
२. स्वर्ण का टक्का-स्वानन्द्य जनता को होता है तथा स्वर्ण की मुद्राएँ चलन में होती हैं।	२. स्वर्ण मुद्राएँ न तो चलन में होती हैं और न उनका टक्का ही होता है।
३. देश में पन मुद्रा अथवा प्रतीक मुद्रा का चलन होता है जो स्वर्ण मुद्राओं में किसी भी समय माँग पर बदली जा सकती है।	३. पन-मुद्रा एवं प्रतीक मुद्राओं का चलन होता है किन्तु इनका परिवर्तन केवल ४०० ग्रीस बजन की छड़ों में ही हो सकता है।
४. स्वर्ण उपयुक्त ढंग पर अन्तर्बाह्य कार्यों के लिए मिलता है।	४. स्वर्ण उपयुक्त ढंग पर अन्तर्बाह्य कार्यों के लिए मिलता है।
५. इसकी कार्य पद्धति स्वयं निर्भर (automatic) है।	५. इसकी चलन पद्धति सुमचालित (managed system) है जिसका नियन्त्रण केन्द्रीय बैंक द्वारा होता है।
६. इस पद्धति में विदेशी विनिमय दर की स्थिरता की अपेक्षा देश की आंतरिक कीमतों की स्थिरता पर अधिक जोर दिया जाता है।	६. इस पद्धति में आन्तरिक कीमतों के स्वरूप की अपेक्षा विदेशी विनिमय दर की स्थिरता पर अधिक जोर दिया जाता है।

१. इस पद्धति में स्वर्ण-चलन मान से होने वाला सब लाभ तो होते ही हैं, इसके अतिरिक्त स्वर्ण-मुद्रा चलन के लिए जो टक्का-व्यय होता था उसमें बचत होती है क्योंकि स्वर्ण मुद्रा का चलन नहीं होता।

२. निधि में स्वर्ण होने से विदेशी विनिमय को प्रभावशाली एवं स्थिर बनाता है तथा इस निधि के लिए स्वर्ण-मान-मुद्रा-चलन में जो स्वर्ण की माँग लगती है उससे कम मात्रा आवश्यक होने से स्वर्ण में मितव्ययिता होती है।

३ अतिरिक्त मात्रा में जो स्वर्ण किसी देश में होता है उस स्वर्ण की सहायता से अन्य देशों में भी स्वर्णमान अपनाया जा सकता है।

### स्वर्णमान का परित्याग

स्वर्णमान के पुनः स्थापन के बाद जिन देशों के चलन में मूल्य-स्थैर्य नहीं था उनमें मूल्य-स्थैर्य आगया था और व्यापार, विदेशी विनिमय, उत्पादन आदि में १९२५ में १९२८ के बीच काफी स्थिरता आई थी। परन्तु यह स्थिरता अल्पकालीन ही भावित हुई क्योंकि इङ्ग्लैण्ड में केवल ६ वर्ष बाद ही सितम्बर १९३१ में स्टर्लिंग की स्वर्ण-परिवर्तनीयता को स्थगित कर दिया गया। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि इङ्ग्लैण्ड ने स्वर्णमान का परित्याग किया। इसी प्रकार १९३३ में अमरीकी डॉलर की—जिसे आज भी ठोस एवं दुर्लभ मुद्रा माना जाता है—स्वर्ण-परिवर्तनीयता बन्द कर दी गई। सारांश में, सभी देशों से स्वर्णमान मौद्रिक सिंहासन से अलग कर दिया गया। स्वर्णमान के परित्याग के लिए निम्नलिखित कारणों का विशेषता से उल्लेख किया जा सकता है —

१ युद्धकाल में अमेरिका ने जो ऋण युद्धग्रस्त राष्ट्रों को दिये तथा युद्ध-जन्य हानिपूर्ति के लिए जर्मनी तथा अन्य मित्र राष्ट्रों में जो सन्धिर्मां हुई उनके फलस्वरूप अन्तरराष्ट्रीय ऋण सम्बन्धी क्षेत्रों में विशेष परिवर्तन हुआ तथा जो देश धनी थे वे ऋणी बन गये। इस वजह से विजयी राष्ट्रों के पास स्वर्ण की कमी हो गई तथा स्वर्ण की कीमतों में अधिक उतार-चढ़ाव होने लगे। दूसरे, स्वर्ण की कमी के कारण वहाँ पर मुद्रा की पूर्ति माँग की अपेक्षा घटती गई जिससे कीमतें भी गिरने लगी तथा मदी के लक्षण दिखाई देने लगे।

२ युद्ध के पूर्व इङ्ग्लैण्ड विद्वत् में सबसे बड़ा साहूकार देश था जिसकी प्राधिक परिस्थिति युद्ध ने बदल दी तथा अमेरिका और फ्रान्स अब साहूकार बन गये जिनका ऋणी इङ्ग्लैंड हो गया। क्योंकि युद्ध के लिए अपरिमित मात्रा में इङ्ग्लैंड ने ऋण लिया तथा उसी में से अन्य मित्र-राष्ट्रों को युद्ध-संचालन के लिए ऋण दिया, जिसका भुगतान फ्रान्स, इङ्ग्लैंड तथा मित्र राष्ट्रों को शत्रु राष्ट्रों द्वारा हानिपूर्ति के रूप में होना था। किन्तु साहूकार राष्ट्रों ने अपने ऋण का भुगतान वस्तुओं में लेना स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन्होंने ऊँची दरों पर आयात-कर द्वारा अपने बाजारों में विदेशी माल पर प्रतिबन्ध लगा दिये और वे स्वर्ण की माँग करने लगे।

३. इङ्ग्लैण्ड ने युद्धपूर्व अपने यहाँ की बहुत सी पूंजी लम्बी अवधि के

लिए अन्य देशों को उनके विकास के लिए ऋण पर दे दी थी। दूसरी ओर ऋणी राष्ट्रों ने अब (युद्ध के बाद) ऋण देने में अपना हाथ समेट लिया तथा जो ऋण दिये भी थे उनका उपयोग आर्थिक विकास की अपेक्षा ऋणों के भुगतान के लिए अथवा हानिपूर्ति के लिए ही होने लगा।

४ संयुक्त राज्य तथा फ्रान्स, जो साहूकार राष्ट्र थे, उन्होंने ऊँचे सरक्षक करों द्वारा आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया जिससे उनके ऋणों का भुगतान स्वर्ण में करना ही ऋणी राष्ट्रों के लिए अनिवार्य हो गया, फलस्वरूप बहुत बड़ी मात्रा में गोला अमेरिका तथा फ्रान्स में गया जिससे उन्होंने निष्क्रिय कर दिया अथवा जिसका प्रभाव आन्तरिक कीमती पर नहीं होने दिया। इस तरह इन देशों ने स्वर्णमान का जो आवश्यक नक्षण स्वयं निर्भरता है उसको कार्यान्वित नहीं होने दिया। उधर अन्य राष्ट्रों में स्वर्ण की कमी में मूल्य-स्तर गिरने लगे। परिणामस्वरूप ऋणी राष्ट्रों के ऋण का भार अधिकाधिक होता गया। इस प्रकार साहूकार राष्ट्रों द्वारा स्वर्णमान के नियमों का पालन नहीं किया गया जिससे विश्व के अन्य राष्ट्रों में स्वर्ण की कमी हो गई तथा उन्हें अपने मिक्को की स्वर्ण-परिवर्तनीयता बन्द करनी पड़ी।

५ इसके अनिश्चित कुछ समय के लिए ऋणप्रस्त राष्ट्रों में व्यापार एवं उत्पादन कार्य में उन्नति दिखाई दी जिसमें भविष्य की आशाओं पर अधिकाधिक सट्टेबाजी बटती गई। परिणाम यह हुआ कि उपभोग की अपेक्षा उत्पादन बढ़ता गया तथा माँगपूर्ति के नियम का उल्लंघन होने से उत्पादन एवं उपभोग का सन्तुलन बिगड़ गया जिसमें कीमतें घडाघड गिरने लगी।

६ मित्र राष्ट्रों के परस्पर दिये हुए ऋणों के कारण तथा इन ऋणों की भुगतान सम्बन्धी चर्चाओं के कारण सब देशों में अधिक अनिश्चितता, भय एवं अविश्वास पैदा हो गया।

७ जनता का विश्वास उठना—इन उपरोक्त कारणों की वजह से एक ओर तो विश्व के सभी देशों में भ्रष्टा की कमी होने से मूल्य-स्तर गिरने लगे। दूसरी ओर माँग एवं उत्पादन का सन्तुलन नष्ट हो गया क्योंकि व्यापार एवं उद्योग उत्पादन कार्य में उन्नति कर रहे थे। इस उज्ज्वल में विश्व में भयंकर आर्थिक मंदी आई। इसी मंदी में अमेरिकी स्वर्ण के सट्टे बाजार में मटोरियों की अधिक हानि हुई जिससे वे स्वर्ण के सट्टे पर रोक लगाने के लिए माँग करने लगे। इसी को वाल स्ट्रीट सैक्रेट (Wall Street Crash) १९२९ कहा जाता है। ऐसी परिस्थिति के कारण आस्ट्रिया का केन्द्रीय बैंक भी फेल हो

गया क्योंकि उसने अपने निधि का बहुत बड़ा भाग उद्योग-धन्धों में विनियोग किया था और उद्योग-धन्धों का ढाँचा मंदी से अस्त-व्यस्त हो रहा था। इस कारण वह जनता से आने वाली स्वर्ण परिवर्तन की माँग को पूरी न कर सका और उसे अपना दरवाजा बन्द करना पड़ा।

इस बैंक के फेल होते ही अन्य सभी देशों में स्वर्ण की माँग होने लगी जिसे पूरी करने में वहाँ के केन्द्रीय बैंक असमर्थ थे। इस वजह से सभी प्रमुख राष्ट्रों में स्वर्ण की परिवर्तनशीलता का अन्त हो गया।

तीसरे, इसी समय इङ्ग्लैण्ड में नाविक विद्रोह भी हो गया क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी जिससे जनता का विश्वास सरकार से उठ रहा था।

ऐसी विपरीत एवं विरोधी परिस्थिति में विश्व के स्वर्ण-संचय का लगभग ६० प्रतिशत भाग केवल फ्रान्स और अमेरिका में था तथा अन्य देशों में केवल ४० प्रतिशत ही था। अतः स्वर्णमान को वार्यान्वित करना तथा मूल्यों में स्थिरता रखना असम्भव हो गया। भय एवं चलन में अविश्वास होने के कारण १९२९-३१ के बीच विश्व मन्दी आ गई तथा जर्मनी, आस्ट्रिया आदि देशों ने स्वर्ण की सभी के कारण स्वर्ण देना बन्द कर दिया तथा यही परिस्थिति इङ्ग्लैण्ड की भी हो गई जिसने २० सितम्बर १९३१ को स्वर्ण देना बन्द किया। इस प्रकार १९३१ में विश्व के सभी राष्ट्रों ने अपने चलन का स्वर्ण से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया एवं स्वर्णमान का परित्याग हो गया।

सारांश में, स्वर्णमान परित्याग के कारण हैं —

१. हारे हुए राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली हानिपूर्ति की बड़ी राशि।
२. स्वर्ण का असमान वितरण।
३. फ्रान्स तथा अमेरिका—जिनके पास विश्व का ६०% स्वर्ण था—द्वारा स्वर्ण को निष्क्रिय बना देना। अर्थात् स्वर्णमान के नियमों का उल्लंघन।
४. आस्ट्रिया की केन्द्रीय बैंक का फेल होना।
५. आर्थिक मन्दी।
६. अमेरिका का वाल स्ट्रीट सकट।
७. इङ्ग्लैण्ड का नाविक विद्रोह।
८. राष्ट्रीय भावना के बशीभूत होकर प्रत्येक देश के द्वारा आयात पर रोक लगाना तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना।
९. स्वर्ण का अभाव।

## स्वर्णमान का भविष्य

१९३१ में स्वर्णमान का परित्याग होने के कुछ वर्षों बाद ही द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और विश्व के प्रमुख देशों में फिर से अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा की बहुलता हो गई। इससे होने वाले मूल्य-अस्थिरता के कारण विभिन्न देशों में भविष्य के चलन सम्बन्धी अनेक योजनाएँ बनाई गईं जिनको कार्यान्वित करके युद्ध के बाद अन्तरराष्ट्रीय भुगतान कम नई योजना के अनुसार हो सके। वीन्स, गुस्ताव कैसल आदि अर्थ-शास्त्रियों का मत था कि स्वर्ण के मूल्य में स्थिरता न रहने से उसने मौद्रिक क्षेत्र में अपना महत्त्व खो दिया है अतः आगे के लिए सुसंचालित पत्र-मुद्रा-चलन-मान ही सम्भव है जो इंग्लैंड आदि अनेक राष्ट्रों में यशस्वी रीति में कार्यान्वित है। किन्तु इस पद्धति का महान् दोष चलनाधिक्य की सम्भावना है जिससे अनेक हानियाँ होती हैं तथा इसमें जनता का विश्वास भी कायम नहीं हो सकता। अन्तरराष्ट्रीय भुगतान के लिए मुद्रा की अन्तरराष्ट्रीयता भी आवश्यक है। इसके विपरीत स्वर्णमान के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है जिसके न होने से ही स्वर्णमान का परित्याग किया गया। अतः जब तक अन्तरराष्ट्रीय सहयोग नहीं होता तब तक स्वर्णमान का कार्यान्वित होना असम्भव है क्योंकि इसके लिए स्वर्ण का, जिसका ८० प्रतिशत अमेरिका के पास है, पुनर्वितरण होना भी जरूरी है। यह तभी हो सकता है जब अनिवार्य अन्तरराष्ट्रीय व्यापार हो, आयात-निर्यात में रोक न हो तथा मुद्रा-स्फीति की नीति का त्याग किया जाय। तीगरे, जा वेश स्वर्ण के उत्पादन हैं वे देश ऐसे किसी भी मौद्रिक मान का समर्थन नहीं कर सकते जिसमें स्वर्ण को प्रमुख स्थान न दिया जाय, तथा चौथे, लम्बी अवधि की ऐसी कोई भी मान-पद्धति, जो स्वर्ण पर आधारित नहीं है, जनता की विश्वास प्राप्त नहीं हो सकती।

उपरोक्त कारणों से ही ब्रेटनवुड परिपद ( १९४४ ) में सब प्रमुख देशों की सम्मति से ब्रेटनवुड योजना की स्वीकृति हुई तथा अन्तरराष्ट्रीय बैंक एवं अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-निधि (International Monetary Fund) की स्थापना की गई। इस योजना का मूल उद्देश्य विश्व के राष्ट्रा की आर्थिक उन्नति करना तथा विदेशी विनिमय की दर में एवं अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों में स्थिरता रखना है। इस योजना के अन्तर्गत स्वर्णमान के सब लाभ तो प्राप्त होने ही हैं, उनमें जो अवगुण थे उनका निवारण भी अन्तरराष्ट्रीय सहयोग होने से हो सकता है। स्वर्ण की भी अधिक आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि देशों का आन्त-

रिक चलन प्रतीक मुद्रा का रहेगा और अन्तरराष्ट्रीय भुगतान अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-निधि ( I M. F. ) द्वारा होगा । इस प्रकार आज भी स्वर्ण ही मौद्रिक जगत में प्रमुख कार्य कर रहा है एवं वरेगा जैसा कि स्वर्णमान में होता रहा है । अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा स्वर्ण का मूल्य ३५ डॉलर प्रति विमुद्रा ग्राम निश्चित किया गया है । फलतः विश्व के मौद्रिक इतिहास में स्वर्ण का विशेष स्थान आज भी बना हुआ है ।

### सारांश

स्वर्णमान अपनाने के चार प्रमुख कारण हैं : कम आकार में अधिक मूल्य एवं वहनीयता, मूल्य स्थिरता, स्वर्ण की कीमतों पर उत्पादन का कोई प्रभाव न होना तथा स्वर्ण का अससीमित बाजार होना ।

१९१४ तक विश्व के विभिन्न देशों में स्वर्णमान ही था जिसमें स्वर्ण के सिक्के चलन में होते थे तथा विनिमय माध्यम एवं मूल्यमापन का कार्य करते थे । विनिमय दर में उतार-चढ़ाव स्वर्ण बिन्दुओं से सीमित थे । स्वर्ण का स्वतन्त्र बाजार था तथा मितव्ययिता के हेतु नोट चलाये जाते थे जो स्वर्ण में परिवर्तनशील थे । फलस्वरूप इसमें स्वयं कार्यशीलता, मूल्यस्थिरता एवं सरलता थी । लोच का अभाव था । स्वर्ण की कमी वाले देशों में स्वर्ण विनिमय प्रमाण का उपयोग होता था जिसमें देश की आंतरिक प्रमाणित मुद्रा चाँदी या अन्य होती थी । परन्तु उसको किसी अन्य देश की मुद्रा से सम्बन्धित किया जाता था जो स्वर्ण से सम्बन्धित हो ।

प्रथम युद्ध के आरम्भ में ५६ देश स्वर्णमान पर थे । युद्ध आरम्भ होते ही सभी देश स्वर्ण को मुद्रा रूप में खताने की जगह उसे एकत्र करने लगे और नोटों का चलन बढ़ने लगा । इसके साथ ही स्वर्ण के निर्यात पर रोक लगा दी गयी जिससे स्वर्णमान का अन्त हो गया । युद्धोत्तरकाल में स्वर्णमान की स्थापना के प्रयत्न होने लगे । फलतः जेनेवा के अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन (१९२२) में निश्चित हुआ कि “प्रत्येक देश के चलन में मूल्य-स्थिरता होना आवश्यक है । अतः शीघ्र ही स्वर्णमान का अवलम्बन किया जाय जिससे आर्थिक पुनर्गठन हो सके ।” युद्धोत्तर काल में सर्व प्रथम १९१६ में अमेरिका ने १९२५ में इंग्लैण्ड ने, १९२७ में भारत एवं अन्य देशों ने स्वर्णमान अपनाया । फलतः स्वर्णमान वाले देशों की संख्या युद्धपूर्व काल से भी बढ़ गई ।

युद्धोत्तर स्वर्णमान युद्धपूर्व स्वर्णमान से भिन्न था । इसमें स्वर्ण मूल्यमापक था किन्तु विनिमय माध्यम नहीं । सरकार या केन्द्रीय बैंक निश्चित दरों पर

४०० औंस से अधिक मात्रा में स्वर्ण का क्रय-विक्रय करती थी। स्वर्ण देशों एवं विदेशी कार्यों के लिए मिल सकता था।

परन्तु यह स्वर्णमान अल्पकालीन ही रहा क्योंकि १९३१ में इङ्ग्लैण्ड ने, १९३३ में अमेरिका ने तथा बाद में अन्य देशों ने अपनी मुद्रा को स्वर्ण में बदलना बन्द किया अर्थात् स्वर्णमान का त्याग किया। इसके लिए निम्न कारण थे : पराजित राष्ट्रों द्वारा दी जाने वाली हानिपूर्ति की बड़ी राशि, स्वर्ण का असमान वितरण, फ्रांस तथा अमेरिका द्वारा स्वर्णमान के नियमों की उपेक्षा, आस्ट्रिया की केन्द्रीय बैंक का फेल होना, अमेरिका का घाल स्ट्रीट सफ्ट, इङ्ग्लैण्ड का नाविक विद्रोह, स्वर्ण की कमी, आर्थिक मंदी, राष्ट्रीयता के अन्तर्गत आयात पर रोक एवं निर्यात की प्रोत्साहन।

इन कारणों से स्वर्णमान का जो त्याग हुआ वह १९२५ तक पुनः न अपनाया जा सका। १९४५ में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से अब स्वर्ण पुनः मौद्रिक सिंहासन पर बैठ गया है।

## विदेशी विनिमय

विदेशी विनिमय क्या है ?

‘विदेशी विनिमय’ के भिन्न-भिन्न अर्थ किये जाते हैं। जिस समय हम यह कहते हैं कि विनिमय बैंक ‘विदेशी विनिमय’ का क्रय विक्रय करते हैं उस समय विदेशी विनिमय से तात्पर्य होता है ‘विदेशी विनिमय बिल’ (foreign bills of exchange) से। इसी प्रकार जब हम यह कहते हैं कि “विदेशी विनिमय हमारे पक्ष में नहीं है” उस समय हमारा मतलब होता है ‘विनिमय दर’ (rate of exchange) से। किन्तु विदेशी विनिमय का सही रूप में शब्दशः अर्थ होता है—“वह पद्धति जिससे व्यापारी राष्ट्र अपने आपसी ऋणों का भुगतान करते हैं”<sup>१</sup> अर्थात् विदेशी विनिमय वह पद्धति है जिससे अन्तरराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान किया जाता है। विदेशी चलन की माँग एवं पूर्ति किस प्रकार होती है तथा विभिन्न देशों की मुद्राओं की दर किस प्रकार निश्चित की जाती है, इन तथ्यों का इसमें विवेचन किया जाता है।

जहाँ तक देश के आन्तरिक व्यापार का सम्बन्ध है, उस देश में भुगतान देशी चलन द्वारा किया जाता है क्योंकि उस देश की वही असीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। किन्तु विदेशी भुगतान के लिए तो हमको ऐसी ही वस्तुएँ देनी पड़गी जो उस देश में स्वीकृत हों, और ऐसी कोई भी अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा नहीं जो सब देशों में स्वीकृत एवं विधिग्राह्य हो। ऐसी अन्तरराष्ट्रीय वस्तु केवल स्वर्ण ही है जिसके द्वारा भुगतान किया जा सकता है परन्तु प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के समय सोना भेजना अथवा भँगाना सतर्नाक और खर्चीला भी है। इस विदेशी भुगतान किस प्रकार होता है, भुगतान करने की कौनसी क्रियाएँ हैं, किस प्रकार एक देश की मुद्रा की दर दूसरे देश की मुद्रा के साथ निश्चित की जाती है यह जानना आवश्यक है और इसलिए ही विदेशी विनिमय के अध्ययन की आवश्यकता भी है।

<sup>१</sup> *Encyclo Brit*

हार्टले विदस के शब्दों में “विदेशी विनिमय अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-परिवर्तन का विज्ञान एवं कला है”<sup>१</sup>। विदेशी विनिमय का अर्थ है—दूसरे देशों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय, जो उभी प्रकार किया जाता है जैसे कि अन्य वस्तुओं का क्रय एवं विक्रय। इससे यह स्पष्ट हो जाना है कि विदेशी विनिमय निम्न-लिखित विषयों से सम्बन्धित है—

१. वह वस्तु जो खरीदी अथवा बेची जाती है अर्थात् विदेशी विल,
२. उनकी कीमत, जिस दर से वे खरीदी एवं बेची जाते हैं, तथा
३. वे मस्याएँ जिनके द्वारा वे विल खरीदे अथवा बेचे जाते हैं। इसका अध्ययन हम ‘विदेशी विनिमय बैंक’ अध्याय में करेंगे।

अन्तरराष्ट्रीय भुगतान कैसे हो सकता है ?

अन्तरराष्ट्रीय भुगतान के केवल तीन मार्ग किसी भी अन्तरराष्ट्रीय भुगतान को उपलब्ध होते हैं—

१. जो वस्तुएँ किसी देश में आयात की जाती हैं उनके बदले में उस देश की आवश्यक वस्तुएँ देना—किन्तु यह मार्ग सम्भव नहीं है क्योंकि प्रत्येक देश दूसरे देशों को उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में नहीं दे सकता और हो सकता है कि उन वस्तुओं की उपज ही उस देश में न हो। दूसरे, वस्तु-विनिमय की कठिनाइयाँ अन्तरराष्ट्रीय वस्तु-विनिमय में और भी तीव्रतर हो जाती हैं। इसलिए विदेशी व्यापार में वस्तु-विनिमय नम्भव नहीं है।

२. अपनी वस्तुओं के आयात के बदले स्वर्ण देना तथा निर्यात के बदले स्वर्ण लेना। किन्तु यह मार्ग अरिक्त खर्चीला, खतरनाक एवं असुविधाजनक भी है क्योंकि एक देश का भूमने वस के साथ अनेक व्यक्तियों द्वारा लन-देन होता है। उस हालत में प्रत्येक व्यक्ति को माने का आयात एवं निर्यात करना पड़ेगा किन्तु यदि एक देश का कुल लेना और कुल देना निराला जाय तो बहुत कम मात्रा में माने या निर्यात या आयात होगा। अतः माने के लन-देन में होने वाली असुविधाएँ एवं खर्चा बचाने के लिए एवं स्वर्ण के उपयोग में निम्नव्ययिता लाने की दृष्टि से तीसरा मार्ग ही अधिक सुविधाजनक एवं कम खर्चीला है।

३. तीसरा मार्ग है विनिमय-बिलों द्वारा विदेशी ऋणों का भुगतान करना। इस पद्धति में स्वर्ण का उपयोग रोज के लन-देन के लिए न होने हुए सामयिक भुगतान के लिए ही उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे मान लीजिए

<sup>1</sup> *Money Changing by Hartley Withers.*

कि एक साल में हमारे यहाँ २० लाख पौंड का आयात हुआ तथा ३० लाख पौंड का निर्यात हुआ तो केवल १० लाख पौंड का मोना वर्ष के अन्त में हमको इङ्गलैंड चुकाएगा। यदि यह पद्धति न होनी तो भारत ने इङ्गलैंड को २० लाख पौंड का मोना जाना तथा इङ्गलैंड से भारत में ३० लाख पौंड का मोना आता। इस प्रकार १० लाख पौंड के स्वर्ण की आवश्यकता पड़ती एवं उमके लिए वाहन-व्यय भी होता ही। किन्तु गिन्ना के द्वारा केवल १० लाख पौंड मोना ही लगा अर्थात् ४० लाख पौंड मान की वचत तथा वाहन-व्यय की वचत तो हुई ही, इसके अनिर्दिष्ट निर्यात के लिए जो कष्ट एवं अमुविधाएँ दोनों देशों को उठानी पड़नी उनकी भी आवश्यकता न रही। इसीलिए तीसरे मार्ग से ही—अर्थात् विदेशी विलो द्वारा ही—आजकल अन्तरराष्ट्रीय श्रृणों का भुगतान जाना है, और एस विल विनिमय-युक्तों द्वारा खरीद तथा बेचे जाते हैं।

### विदेशी विलो की कार्यप्रणाली

मान लीजिए कि इङ्गलैंड से अमेरिका में कुछ वस्तुओं का आयात होता है तथा उन्हीं प्रकार में कुछ वस्तुओं का निर्यात होता है। ऐसी दशा में दोनों देशों के भुगतान के लिए स्वर्ण का आयात-निर्यात होगा। परन्तु यह पद्धति अमुविधाजनक हान से विलो के द्वारा दोनों देशों का भुगतान किया जायगा। उदाहरणार्थ, अमेरिका हमारा डालर में भुगतान चाहता और अंग्रेजों द्वारा केवल पौंड-स्टर्लिंग ही दिया जा सकता है उन्हीं प्रकार अंग्रेज अपना भुगतान पौंड-स्टर्लिंग में चाहते किन्तु अमेरिकन केवल डॉलर में भुगतान कर सकते हैं। अतः दोनों को ही एक-दूसरे देश की मुद्रा खरीदनी पड़ेगी। जहाँ विदेशी मुद्राओं का क्रय विक्रय होता है उसे विदेशी विनिमय-बाजार (foreign exchange market) कहते हैं। अब यह मुद्रा किस प्रकार खरीदी जायगी यह प्रश्न उठता है। मान लीजिए कि अमेरिका के 'क' ने १०,००० पौंड का निर्यात इङ्गलैंड के 'ख' को किया है और इङ्गलैंड के 'ग' ने अमेरिका के 'घ' को १०,००० पौंड का माल निर्यात किया है। उक्त परिस्थिति में लेन देन की दशा निम्न प्रकार होगी —

#### अमेरिका

#### इङ्गलैंड

'क' (निर्यातकर्त्ता एवं लेनदार)

'ख' (आयातकर्त्ता एवं देनदार)

'घ' (आयातकर्त्ता एवं देनदार)

'ग' (निर्यातकर्त्ता एवं लेनदार)

अब 'ख' ने 'क' को १०,००० पौंड तथा 'घ' ने 'ग' को १०,००० पौंड

देना है। यदि स्वर्ण के द्वारा भुगतान किया जाता है तो दोनों को ही स्वर्ण भेजना पड़ेगा, किन्तु विपणो से यदि भुगतान किया जाय तो केवल एक बिल से ही दोनों ऋणों का भुगतान हो सकेगा। इसलिए 'क' १०,००० पौंड का एक बिल 'ख' पर लिखेगा जो 'ख' स्वीकृत करके 'क' को भेज देगा। अमेरिका में 'क' उस बिल को 'घ' को बचकर डालर में अपना भुगतान ले लेगा। अब 'घ' इस बिल को इङ्ग्लैण्ड के 'ग' के पास भेजेगा जिसका भुगतान वह 'ख' से पौंड अथवा अंग्रेजी चलन में ले सगा। इस प्रकार एक बिल से 'क' तथा 'ग' दोनों के ऋणों का भुगतान उनके देश की मुद्राओं में हो जाता है और न सोन का दो बार निर्यात होता है और न उसमें हानि वाली अमृविधाएँ एवं व्यय ही होता है।

उपर्युक्त उदाहरण में हमने दोनों ऋणों की एक ही रकम (अर्थात् १०,००० पौंड) ली है परन्तु प्रत्यक्ष में ऐसा मन्तुलन बहुत कम होता है। इङ्ग्लैण्ड लाखों पौंड के बिल अमेरिका पर लिखता है और उसी प्रकार अमेरिका इङ्ग्लैण्ड पर लाखों डालरों के बिल लिखता है जो दोनों देशों के देनदारों द्वारा अपने अपने देनदारों के भुगतान के लिए खरीदे जाते हैं तथा इन बिलों द्वारा अन्तरराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान किया जाता है। यदि किसी देश का पावना देने से अधिक हो तो उस देश में पावना वाले देश में स्वर्ण का आयात होता है परन्तु इसमें भी मितव्ययिता लाई जाती है।

यहाँ पर हमने केवल दो देशों का उदाहरण लिया है किन्तु अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में अनेक देश होते हैं और ऐसी हालत में एक देश के कुल ऋणों का मन्तुलन उस देश के कुल पावन के साथ किया जाता है। फिर जो कुछ शेष रहता है उसका भुगतान स्वर्ण के निर्यात द्वारा होता है और यदि स्वर्ण का निर्यात नहीं किया जाता तो वह देश अन्य देशों का उस रकम में ऋणी रहता है।

### विदेशी विनिमय की माँग एवं पूर्ति

विदेशी विनिमय के लिए माँग बँभे होती है तथा उसकी पूर्ति किस प्रकार की जाती है यह भी जानना चाहिए। विदेशी विनिमय की माँग उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है जो विदेशों में माल मँगाना चाहते हों, विदेशी सेवाओं का भुगतान करना चाहते हों अथवा विदेशों में अपनी पूँजी का विनियोग करना चाहते हों। विदेशी विनिमय की पूर्ति उन व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो विदेशी मुद्रा पर किसी न किसी रूप में अधिकार प्राप्त करते हैं, चाहे वह

निर्यात द्वारा, सेवाओं द्वारा, अथवा पूँजी के आयात द्वारा हो। इस प्रकार किसी भी समय वैधानिक माँग एवं पूर्ति निश्चित होती है तथा इनकी परस्पर शक्ति के ऊपर ही अन्य वस्तुओं की कीमतों की माँति बिलों की कीमतें भी निर्भर रहती हैं।

### विनिमय की दर

यह वह दर है जिससे एक देश के बिल दूसरे देश में बेचे जायेंगे। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिस दर पर एक देश की प्रमाणित मुद्रा दूसरे देश की प्रमाणित मुद्रा के साथ बदली जा सके उसे विनिमय दर कहते हैं। भूमि अन्तरराष्ट्रीय भुगतान आचारणत विदेशी विनिमय बिलों द्वारा होते हैं इसीलिए विनिमय दर उस दर को कहते हैं जिस दर पर एक देश के बिलों की बिक्री दूसरे देश में होती है। इनकी कीमत उस देश में बिलों की माँग एवं पूर्ति पर निर्भर रहेगी। यदि किसी भी समय विदेशी मुद्रा के बिलों की माँग एवं पूर्ति का सन्तुलन होगा तो विनिमय-दर में समता होगी। इसके विपरीत यदि बिलों की माँग अधिक है तथा पूर्ति कम, तो उस दशा में विनिमय की दर बढ़ेगी अथवा विदेशी मुद्रा का मूल्य समता से बढ़ेगा अर्थात् विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए हमको पहले से अधिक देनी मुद्राएँ देनी पड़ेंगी। इसी प्रकार यदि विदेशी बिलों की पूर्ति माँग की अपेक्षा अधिक है तो विनिमय की दर गिरेगी अथवा विदेशी मुद्रा का मूल्य दर की समता से नीचे होगा अर्थात् विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए हमको पहले की अपेक्षा कम देनी मुद्राएँ देनी पड़ेंगी।

किन्तु यह विनिमय की दर समता से कहां तक बढ़ेगी अथवा कितनी नीचे गिरेगी—इसकी भी मर्यादाएँ हैं जो भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न होंगी। उसी प्रकार भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में भिन्न-भिन्न देशों की मुद्रा-मान पद्धतियों के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार में समता की दर भी निश्चित की जाती है।

### विनिमय की समता

जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, किसी भी समय विनिमय की दर विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति एवं विदेशी विनिमय बाजार की दशा पर निर्भर रहती है, किन्तु दीर्घकालीन दर दो देशों की मुद्राओं की पारस्परिक क्रयशक्ति पर निर्भर रहती है अथवा दो देशों के बीच मुद्रा का क्रय विक्रय दीर्घकालीन अवधि में दोनों देशों की मुद्राएँ अपने-अपने देश में जो क्रयशक्ति रखेंगी उस पर निर्भर रहेगा। अतः किसी भी समय यह दर क्रयशक्ति-समता का प्रति-

निधित्व करेगी। फिर वह क्रयशक्ति चाहे स्वर्ण में हो, चांदी में हो अथवा वस्तुओं एवं सेवाओं में हो। यह बात उन देशों की मुद्रामान पद्धतियों पर निर्भर रहेगी।

विनिमय की समता निश्चित करने की निम्नलिखित पद्धतियाँ हैं —

१. जब दोनों देश स्वर्णमान पर अथवा रजत मान पर आधारित होने हैं,

२ जब एक देश स्वर्ण पर तथा दूसरा चांदी पर आधारित होना है,

३ जब एक देश स्वर्ण पर तथा दूसरा अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा पर आधारित होता है, तथा

४. जब दोनों देश अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा पर आधारित होने हैं।

१. स्वर्ण पर आधारित देश—जब विभिन्न देशों की मुद्राएँ स्वर्ण पर आधारित होती हैं उस समय स्वर्ण के माध्यम में हम विभिन्न देशों की क्रयशक्ति नाप सकते हैं तथा विभिन्न देशों की मुद्राओं का मूल्य उनकी स्वर्ण में जो क्रयशक्ति होती है उसमें नाप सकते हैं। जब दो देशों की मुद्राओं का विनिमय इस प्रकार से होता है कि वे अपने देशों में एक ही माना में मोना खरीदती हैं उस समय विनिमय-दर की समता होती है। इस समता की स्थिति में दोनों देशों की मुद्राएँ अपने-अपने देश में समान माना में मोना खरीदती हैं। इस परिस्थिति में जब दो देशों की मुद्राओं का विनिमय होता है उस समय न तो देने वाले और न देने वाले को किसी प्रकार में लाभ अथवा हानि होती है। अर्थात् स्वर्णमान पर आधारित राष्ट्रों की मुद्राओं की क्रयशक्ति स्वर्ण क्रयशक्ति है और जब तक स्वर्ण का आयात-निर्यात अनिर्वन्ध है तब तक दो देशों की मुद्राओं का परस्पर विनिमय उन देशों के प्रमाणित सिक्कों की विद्युद स्पर्श की समानता पर निर्भर रहेगा। इसी को टक-समता (mint par) अथवा विनिमय की टक-समता (mint par of exchange) कहते हैं। टॉमस के शब्दों में विनिमय की टक-समता उसे कहेंगे जिसमें “एक देश के प्रमाणित सिक्कों का यथार्थ साम्य दूसरे देश के प्रमाणित सिक्कों में व्यक्त किया जाता है, जो एक ही धातुमान पर होते हैं—यह साम्य दोनों सिक्कों में जो धातु की वैधानिक विद्युद मात्रा होती है उसकी तुलना से निश्चित होता है।” अथवा “टक-समता वह अनुपात है जो एक ही धातुमान पर आधारित राष्ट्रों की प्रमाणित मौद्रिक इकाइयों के वैधानिक धातु-साम्य में व्यक्त होता है।”<sup>१</sup> यहाँ पर एक

<sup>१</sup> *Banking and Exchange by Thomas.*

वात विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी कि स्वर्ण पर आधारित राष्ट्रों की मुद्रा के वैधानिक विशुद्ध स्वर्ण-मूल्य में ही टक-समता निश्चित की जाती है न कि उसके वास्तविक मूल्य में, अर्थात् टक-समता से तात्पर्य है—एक देश की विशुद्ध स्वर्ण-मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के विशुद्ध स्वर्ण में मूल्य तथा रजत-मान वाले राष्ट्रों में चांदी या चांदी में मूल्य ।

भारत में, टक-समता मुद्रा पर निर्भर न रहते हुए उस मुद्रा की वैधानिक व्याख्या पर निर्भर रहनी है, सर्बिरेन की वास्तविकता पर नहीं अपितु सॉवरेन की वैधानिकता पर, और जब तक विधान में परिवर्तन नहीं होता टक-समता में भी परिवर्तन नहीं होगा ।<sup>१</sup>

प्रत्येक देश के कानून द्वारा उसकी प्रमाणित मुद्रा का स्वर्ण-मूल्य अथवा रजत-मूल्य निश्चित किया जाता है । इस स्वर्ण-मूल्य अथवा रजत-मूल्य की विशुद्ध मात्रा के आधार पर ही टक-समता निकाली जायगी, न कि उस सिक्के की घिसावट होने के कारण उसमें जो भूल्य रहता है उस आधार पर । जैसे सॉवरेन का कानून द्वारा निर्धारित विशुद्ध स्वर्ण-मूल्य ११३ ०० १६ ग्रेन है परन्तु सॉवरेन चलन में रहने से घिस जाने के कारण उसमें विशुद्ध स्वर्ण यदि केवल ११२ ०० ग्रेन ही रह जाता है तो हम टक-समता निकालने के लिए उसका विशुद्ध स्वर्ण-मूल्य ११३ ०० १६ ग्रेन लेंगे न कि उसका वास्तविक स्वर्ण-मूल्य ( अर्थात् ११२ ०० ग्रेन ) और जब तक उस देश के विधान द्वारा स्वर्ण-मूल्य में परिवर्तन नहीं किया जाता तब तक टक-समता में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा । टक-समता स्थायी समता होती है ।

इस सिद्धान्त के अनुसार अमेरिका तथा इंग्लैण्ड की विनिमय-दर निम्न प्रकार से माप ली जायगी —

अमरीकी प्रमाणित सिक्का ईगल है जो कि १० डॉलर के बराबर है जिसमें २५८ ग्रेन सोना  $\frac{1}{10}$  विशुद्धता का होता है । इस प्रकार १० डॉलरों में विशुद्ध सोना  $258 \times \frac{1}{10} = 25.8$  ग्रेन होगा तथा १ डॉलर में  $25.8 \times \frac{1}{10} = 2.58$  ग्रेन होगा ।

इसी प्रकार इंग्लैण्ड के एक सॉवरेन में १२३ २४७ ग्रेन स्वर्ण  $\frac{1}{10}$  विशुद्धता का होता है अर्थात् १ सॉवरेन में  $123\ 247 \times \frac{1}{10} = 12\ 324.7$  ग्रेन विशुद्ध सोना होता है इसलिए १ सॉवरेन  $= \frac{12\ 324.7}{25.8} = 477.7$  डॉलर होगा

अर्थात् इङ्ग्लैण्ड व अमेरिका के बीच विनिमय की टक्-समता १ डॉलर = ४.८६६ डॉलर होगी।

जो देश रजत-मान पर आधारित होने हैं उनके बीच भी इसी प्रकार टक्-समता निकाली जायगी।

समता-मूल्य से उतार-चढ़ाव—यह हम बता चुके हैं कि विलों की माँग एवं पूर्ति के अनुसार विलों का मूल्य समता में घटना अथवा बढ़ता है तथा उसकी मर्यादाएँ होती हैं। जब दोनों देश स्वर्ण पर आधारित होते हैं एवं स्वर्ण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है उस समय यह उतार-चढ़ाव की मर्यादा स्वर्ण के भेजने में जो व्यय होता है उस व्यय में निर्दिष्ट की जाती है। अतः किसी भी समय समता की दर में स्वर्ण भेजने के लिए जो व्यय होगा उसको जोड़ देने से हम विलों के मूल्य की उच्चतम मर्यादा पाते हैं तथा समता की दर में से स्वर्ण भेजने का व्यय घटाकर हम विलों के मूल्य की निम्नतम मर्यादा पाते हैं। सामान्यतः विलों के उतार-चढ़ाव की उच्चतम एवं निम्नतम मर्यादाएँ स्वर्ण के भेजने में जो खर्च आता है उस पर निर्भर रहती हैं। उदाहरणार्थ, अमेरिका और इङ्ग्लैण्ड के बीच विनिमय की समता-दर १ पाँड = ४.८६६ डॉलर है एवं गोले के भेजने का मँगाना ०.२४ डॉलर व्यय होता है। जब अमेरिकी पाँड में दर घटती है तो यह दर अधिक से अधिक प्रति पाँड ४.८६ (४.८६६ + ०.२४) डॉलर होगी क्योंकि यदि दर इसमें अधिक बढ़ती है तो अमेरिकी व्यापारियों को विलों में भुगतान करने की अपेक्षा स्वर्ण भेजना सस्ता पड़ेगा। अर्थात् किसी भी समय जब दो देश स्वर्ण पर आधारित होते हैं उस समय उनकी दर 'विनिमय की समता + स्वर्ण-वाहन व्यय' (cost of transmitting specie) में अधिक नहीं बढ़ सकती। इस उच्चतम मर्यादा को उच्चतम स्वर्ण-विन्दु अथवा स्वर्ण-निर्यात विन्दु (upper gold point or gold export point) कहते हैं। अमेरिकी लोगों की दृष्टि से यह स्वर्ण निर्यात-विन्दु है क्योंकि इस दर में अधिक दर बढ़ने पर अमेरिका से स्वर्ण का निर्यात होने लगेगा तथा इङ्ग्लैण्ड की दृष्टि से यह स्वर्ण-आयात विन्दु होगा क्योंकि इस दर से अधिक बढ़ने पर इङ्ग्लैण्ड में गोले का आयात शुरू होगा।

इसी प्रकार दर गिरने की निम्नतम मर्यादा विनिमय की समता में से स्वर्ण मँगाने के लिए जो वाहन-व्यय होगा उसे घटाने से प्राप्त होती है। मान लीजिए कि किसी समय अमेरिका के विलों के लिए पूर्ति की अपेक्षा माँग कम है तो दर गिरने लगेगी। ऐसी अवस्था में दर गिरने की निम्नतम मर्यादा

विनिमय-समता में से स्वर्ण आयात-व्यय घटाकर मालूम होगी। अब स्वर्ण-आयात-व्यय ०२४ डॉलर है तो अमरीकी लेनदार अपने विलो की दर ४८४० (४८६६—०२४) डॉलर प्रति पौंड से नीचे नहीं उतरने देंगे क्योंकि ऐसी अवस्था में अमरीकी व्यापारी विलो में भुगतान लेने की अपेक्षा स्वर्ण में ही अपना भुगतान लेंगे क्योंकि कम डॉलर लेने की अपेक्षा उन्हें यह लाभकर होगा कि बाहन-व्यय देकर स्वर्ण मंगा लें। इस मर्यादा को निम्नतम स्वर्ण-विन्दु अथवा स्वर्ण-आयात-विन्दु कहते हैं। यही निम्नतम मर्यादा इङ्ग्लैण्ड की दृष्टि से स्वर्ण-निर्यात-विन्दु होगी क्योंकि इङ्ग्लैण्ड के व्यापारियों को स्वर्ण में भुगतान करना लाभदायक होगा।

स्वर्ण-आयात-विन्दु एवं स्वर्ण-निर्यात विन्दु विनिमय-दर के उतार चढ़ाव की निम्नतम एवं उच्चतम मर्यादाएँ हैं और सामान्य अवस्था में विनिमय की दर में उतार-चढ़ाव इन मर्यादाओं में सीमित रहता है। इन्हीं मर्यादाओं को स्वर्ण-विन्दु (specie points) कहते हैं किन्तु प्रसाधारण परिस्थिति में जब आयात-निर्यात के लिए स्वर्ण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता उस समय विनिमय की दर इन मर्यादाओं का भी उल्लंघन कर सकती है। हमें यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये स्वर्ण-विन्दु स्थायी नहीं रहते, किन्तु परिवर्तनशील हैं क्योंकि बाहन-व्यय, बीमा-व्यय तथा सोने की खरीद-विक्री में होने वाला व्यय हमेशा व्यापारिक स्पर्धा के कारण बदलता रहता है।

**स्वर्ण-विन्दुओं का निकालना**—निम्नतम एवं उच्चतम स्वर्ण विन्दु निकालने के सम्बन्ध में नीचे दिये हुए नियमों का उपयोग हो सकता है —

१ जब विनिमय की दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त की जाती है तब स्वर्ण-निर्यात विन्दु निकालने के लिए टक-समता में से बाहन-व्यय घटाइए तथा स्वर्ण-आयात-विन्दु निकालने के लिए टक-समता-दर में बाहन-व्यय जोड़िए। उदाहरणार्थ, इङ्ग्लैण्ड के व्यापारियों की दृष्टि से जब १ पौंड का मूल्य डॉलर में ४८६६ व्यक्त किया जाता है तब ४८४२ (४८६६—०२४) स्वर्ण निर्यात-विन्दु होगा एवं ४८६० (४८६६+०२४) स्वर्ण-आयात-विन्दु होगा क्योंकि जब १ पौंड = ४८६६ डॉलर हम कहते हैं उस समय इङ्ग्लैण्ड की दृष्टि से उनके सिक्के का मूल्य विदेशी सिक्के में व्यक्त किया जाता है।

२ जब विनिमय की दर देशी मुद्रा में व्यक्त की जाती है तब स्वर्ण-आयात-विन्दु निकालने के लिए टक-समता-दर में से बाहन-व्यय घटाइए तथा स्वर्ण-निर्यात-विन्दु निकालने के लिए टक-समता-दर में बाहन व्यय जोड़िए।

ऊपर (१) के उदाहरण में अमेरिका में जब पाँड और डॉलर की विनिमय दर डॉलर में बनाई जाती है तब वह दर देगी मुद्रा में है क्योंकि अमरीकी प्रधान सिक्का डॉलर है। इसलिए इस दशा में अमेरिका के लिए ४६६० डॉलर (४६६६ + ०२४) स्वर्ण-निर्यात बिन्दु तथा ४८४२ (४८६६ - ०२४) स्वर्ण-आयात-बिन्दु होगा।

२. जब एक देश स्वर्ण पर तथा दूसरा देश चाँदी पर आधारित होता है—जब एक देश की मुद्रा स्वर्ण से तथा दूसरे देश की मुद्रा चाँदी से सम्बन्धित होती है उस अवस्था में दोनों की मुद्राओं में कितना बिगुल स्वर्ण एवं चाँदी है यह मालूम किया जायगा। फिर चाँदी का स्वर्ण में अथवा स्वर्ण का चाँदी में क्या मूल्य है (यह मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है), यह मालूम किया जायगा तथा चाँदी का स्वर्ण-मूल्य निकाला जायगा। अब दोनों ही मुद्राओं में कितना बिगुल स्वर्ण है इसकी हम तुलना कर सकते हैं और इसी के आधार पर दोनों मुद्राओं का क्या अनुपात होगा यह हम निकाल सकते हैं। जो स्वर्ण-अनुपात होगा वही टक-समता की दर इन दोनों देशों की मुद्राओं की होगी। भारत और इङ्ग्लैण्ड के बीच १८९८ तक रुपये का स्टैलिग मूल्य इसी प्रकार निश्चित किया जाता था। उदाहरणार्थ, टक विधान के अनुसार भारतीय रुपये में (जो १८० ग्रेन का था) १६५ ग्रेन बिगुल चाँदी थी जो उस समय के मूल्य के अनुसार ७५३३४४ ग्रेन स्वर्ण के बराबर थी। इङ्ग्लैण्ड की मुद्रा में—जैसा ऊपर बता चुके हैं—११३००१६ ग्रेन बिगुल स्वर्ण था। इसलिए इङ्ग्लैण्ड के १ पाँड स्टैलिग का भारतीय मुद्रा में ११३००१६—७५३३४४ अथवा १५ रुपये मूल्य था। अर्थात् १ रुपया  $\frac{१६}{१५}$  पाँड के अथवा (  $\frac{३६}{१५}$  शि० ) १ शि० ४ पैसे के बराबर था।

जब रजतमान वाले देश में प्रमाणित सिक्के का स्वर्ण मूल्य निश्चित नहीं होता उस समय इङ्ग्लैण्ड की टकमाल पर चाँदी का मूल्य निश्चित था। अर्थात् इङ्ग्लैण्ड की टकमाल पर चाँदी खरीदने की दर ४३ पैसे प्रति प्रमाणित औंस थी। अब इस दशा में भारतीय रुपये में कितने औंस प्रमाणित चाँदी है यह देखना होगा। जैसे हम देख चुके हैं कि १८० ग्रेन के रुपये में १६५ ग्रेन शुद्ध चाँदी होती है। चूँकि १ औंस में ४२० ग्रेन होते हैं इसलिए १६५ ग्रेन =  $\frac{१६५}{४२०}$  =  $\frac{३३}{८४}$  औंस शुद्ध चाँदी के बराबर। चूँकि ४० औंस शुद्ध चाँदी ३७ औंस प्रमाणित चाँदी के बराबर होती है इसलिए  $\frac{३३}{८४}$  औंस शुद्ध चाँदी  $\frac{३३}{८४} \times \frac{३७}{४०}$  =  $\frac{३३}{८४} \times \frac{३७}{४०}$  औंस प्रमाणित चाँदी के बराबर होगी (  $\frac{३३}{८४} \times \frac{३७}{४०}$  =  $\frac{३३}{८४} \times \frac{३७}{४०}$  )। १ रुपये में  $\frac{३३}{८४} \times \frac{३७}{४०}$  औंस प्रमाणित चाँदी होती है जो इङ्ग्लैण्ड की टकमाल में ४३ पैसे की दर से खरीदी

जाती है। इनलिए १ रुपया ( ४३ पेंस  $\times \frac{1}{4}$  औंस ) १६ पेंस में खरीदा जायगा।

अर्थात् पाँड और रुपये के बीच टक्का समता की दर १ रु० = १६ पेंस अथवा ११ रु० = १ पाँड होगी।

इस स्थिति में भी विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की निम्न एवं उच्च मर्यादाएँ होनी हैं जिसमें कम अथवा अधिक विनिमय दर नहीं हो सकती। इन बिन्दुओं को पहली पद्धति के अनुसार ही निकाला जाता है।

३. जब एक देश स्वर्ण पर तथा दूसरा देश अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा पर आधारित होता है—जब दो देशों में एक स्वर्ण अथवा चाँदी पर आधारित होता है तथा दूसरा अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा पर, तब विनिमय-दर की समता दोनों देशों की मुद्राएँ जितना स्वर्ण अथवा चाँदी खरीद सकती हैं, इससे निर्दिष्ट की जाती है। जो देश स्वर्णमान पर है उसकी मुद्रा का स्वर्ण-मूल्य तो निर्दिष्ट है ही किन्तु अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का मूल्य, स्वर्ण-बाजार में उसका क्या मूल्य है अथवा जितना मोना वह खरीद सकती है, इस पर निर्भर रहता है। ऐसी दशा में विनिमय-दर कितनी गिरेगी अथवा कितनी बढ़ेगी इसके लिए कोई भी निर्दिष्ट बिन्दु नहीं होते, जैसे उपर्युक्त दो परिस्थितियों में होते हैं। हाँ, स्वर्ण पर आधारित राष्ट्र के लिए उच्चतम बिन्दु अथवा स्वर्ण निर्यात-बिन्दु होता है क्योंकि वहाँ निर्यात के लिए स्वर्ण उपलब्ध होने से यदि विनिमय की दर स्वर्ण भेजने के व्यय से भी अधिक हाँ जाती है तो उन्हें स्वर्ण भेजना लाभदायक होगा। प्रतः स्वर्ण पर आधारित देश में विनिमय की दर स्वर्ण-निर्यात-बिन्दु अथवा उच्चतम स्वर्ण-बिन्दु में अधिक नहीं चढ़ सकती किन्तु स्वर्ण का आयात दूसरे देश में न होने के कारण दर गिरने के लिए कोई भी मर्यादा नहीं होती क्योंकि दूसरा देश अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा पर आधारित होता है। ऐसी दशा में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा वाले देश में विनिमय की दर में कभी अथवा अधिकता उस देश में बिलो की माँग एवं पूर्ति पर निर्भर रहेगी और यह दर कितनी घटेगी अथवा बढ़ेगी इसके लिए कोई मर्यादा नहीं होगी। इस प्रकार जब दो देशों के बीच जिनमें से एक धातुमान (स्वर्णमान अथवा रजतमान अथवा द्विधातुमान) पर तथा दूसरा पत्र मुद्रा पर आधारित होता है तब उस देश में धातुमान वाले देश के लिए निर्यात बिन्दु ही केवल रहती है जिससे अधिक विनिमय दर नहीं चढ़ सकती परन्तु आयात बिन्दु नहीं होता। इसी प्रकार पत्र-मुद्रा वाले देश के लिए स्वर्ण-आयात-बिन्दु होगा परन्तु निर्यात बिन्दु

नहीं होगा क्योंकि उस देश की पत्र-मुद्रा का सम्बन्ध किसी धातु के साथ नहीं होगा।

४. जब दोनों देश अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा पर आधारित हैं—इस अवस्था में विनिमय की दर स्वर्ण बिन्दुओं तक सीमित नहीं रहती बिन्दु बिन्दु की माँग एवं पूर्ति पर निर्भर रहती है। फिर भी यह दर निश्चित करना कठिन होता है क्योंकि ये पत्र मुद्राएँ किसी भी अन्य धातु में सम्बन्धित नहीं होती तथा उन देशों में मुद्रा-स्फीति के कारण अथवा अन्य आर्थिक कारणों से मुद्रा की क्रयशक्ति भी पूर्ववत् नहीं रहती। ऐसी अवस्था में मुद्राओं का सम्बन्ध किसी धातु में न होने के कारण क्रयशक्ति के नापने का कोई भी मापन नहीं होता और न हम यह जान सकते हैं कि उनका मूल्य अथवा उनकी क्रयशक्ति कितनी कम हो गई है। ऐसी अवस्था में मुद्राओं के मूल्य की दूसरी मुद्राओं के साथ तुलना करने के लिए हम विभिन्न मुद्राओं की क्रयशक्ति का उपयोग करते हैं अर्थात् अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा पर आधारित देशों की विनिमय दर उनकी क्रयशक्ति-समता पर निर्भर होती है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि इंग्लैण्ड में १ पाँड देकर हम 'क' वस्तुएँ खरीद सकते हैं तथा इतनी ही वस्तुएँ खरीदने के लिए हमको अमेरिका में ५ डॉलर देने पड़ते हैं। ऐसी अवस्था में देनदार एवं लेनदार को किसी भी प्रकार से हानि न होने के लिए इन दोनों देशों के व्यापारियों को परस्पर उतनी ही मुद्रा लेनी होगी जिससे कि वे समान वस्तुओं तथा सेवाओं पर अधिकार प्राप्त कर सकें। अतः इस परिस्थिति में इंग्लैण्ड एवं अमेरिका के बीच की विनिमय-दर क्रयशक्ति समता से निश्चित की जायगी और यह दर १ पाँड = ५ डॉलर होगी क्योंकि १ पाँड में इंग्लैण्ड में तथा ५ डॉलर में अमेरिका में 'क' वस्तुएँ खरीदी जा सकती हैं। इस प्रकार से दर निश्चित करने की विधि को क्रयशक्ति समता सिद्धान्त (purchasing power parity theory) कहते हैं। कोल के शब्दों में "राष्ट्रीय मुद्राओं का परस्पर मूल्य—जो स्वर्ण में सम्बन्धित नहीं है—दीर्घकाल में विशेषतः उनकी वस्तुओं एवं सेवाओं की परस्पर क्रयशक्ति से निश्चित होता है।" टॉमस के शब्दों में "किसी भी विशेष काल में एक मुद्रा की इकाई का दूसरी मुद्रा में मूल्य माँग तथा पूर्ति की बाजार स्थिति पर निर्भर रहता है, फिर भी समीचीन अवधि में अथवा दीर्घकाल में दो देशों की मुद्राओं का परस्पर मूल्य उनकी वस्तुओं तथा सेवाओं की क्रयशक्ति से निश्चित होता है।" अर्थात् विनिमय-दर में उसी बिन्दु पर स्थिर होने की

<sup>1</sup> *What Everybody Wants to Know About Money* by H. Cole.

प्रवृत्ति होती है जहाँ दोनों देशों की मुद्राओं की क्रयशक्ति समान होती है। इस बिन्दु को क्रयशक्ति समता कहते हैं। इस विवेचन में यह स्पष्ट हो जाता है कि दो देशों के बीच धातु मुद्रा की जगह जब अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा का प्रयोग होता है उस समय विनिमय की दर टक समता में निश्चित न होने हुए क्रयशक्ति-समता से निश्चित की जाती है। टक-समता में मुद्रा की स्वर्ण-क्रयशक्ति से एवं क्रयशक्ति-समता में वस्तु एवं सेवाओं की क्रयशक्ति से विनिमय की दर निश्चित की जाती है और यह क्रयशक्ति-समता टक-समता की तरह स्थिर न रहते हुए मूल्य-स्तर-परिवर्तन के कारण अस्थिर होती है।

ऊपर हमने देखा कि अमेरिका में यदि ५ डॉलर से 'ब' वस्तुएँ तथा इङ्ग्लैण्ड में १ पाँ० से 'न' वस्तुएँ खरीदी जा सकती है तो दोनों मुद्राओं का वस्तुओं में मूल्य स्तर १ पाँड एवं ५ डॉलर पर समान रहता है अतः लम्बी अवधि में इन दोनों देशों की विनिमय दर १ पाँड = ५ डॉलर होगी। किन्तु मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से यह दर १ पाँड = ६ डॉलर होती है तो उस परिस्थिति में क्रयशक्ति में परिवर्तन न होने से पाँड के बदले में डॉलर लेना लाभदायक होगा क्योंकि अमेरिका में हम १ पाँड, में इङ्ग्लैण्ड की अपेक्षा अधिक वस्तुएँ खरीद सकेंगे अर्थात् अमेरिका में इङ्ग्लैण्ड में आयात बढेगा। परिणामस्वरूप इङ्ग्लैण्ड में डॉलर की माँग पूर्ति से अधिक होगी और इसका परिणाम विनिमय दर की वृद्धि में होगा अथवा १ पाँड ६ डॉलर से कम डॉलर खरीदेगा। यह प्रवृत्ति तब तक चालू रहेगी जब तक कि विनिमय दर १ पाँड = ५ डॉलर तक अथवा उनकी क्रयशक्ति समता पर नहीं आ जायगी। इस प्रकार अन्त में यह दर १ पाँड = ५ डॉलर पर स्थिर होगी क्योंकि इसी बिन्दु पर क्रयशक्ति-समता आती है। इस प्रकार लम्बी अवधि में विनिमय की दर क्रयशक्ति समता पर निर्भर रहती है।

अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा में मुद्रा प्रसार के साथ मूल्य स्तर में भी परिवर्तन होता रहता है जिसको हम निर्देशांक द्वारा मापते हैं। इस निर्देशांक की सहायता से ही हम विभिन्न मुद्राओं की क्रयशक्ति जान सकते हैं। अब हमको इङ्ग्लैण्ड और अमेरिका के बीच विनिमय दर निश्चित करना है। मान लीजिए कि डॉलर एवं पाँड की टक समता १ पाँड = ४.८६६ डॉलर है। दोनों देशों का मूल्य स्तर बढ़ गया है एवं उनके निर्देशांक १५८ (इङ्ग्लैण्ड) एवं १७८ (अमेरिका) है। अब हमसे यह स्पष्ट है कि पहले की अपेक्षा डॉलर का मूल्य ७८ प्रतिशत तथा पाँड का मूल्य ५८ प्रतिशत घट गया है अथवा अमेरिकी

डॉलर का मूल्य इंगलिश पौंड की अपेक्षा घट गया है क्योंकि उसकी क्रयशक्ति कम हो गई है। इसलिए अब १ पौंड =  $\frac{४८६६ \times १७८}{१५८} = ५४८१$  डॉलर

होगा क्योंकि इङ्गलैण्ड और अमेरिका के बीच अवमूल्यन का अनुपात १७८ : १५८ है। इस प्रकार “जब दो देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन हो रहा है अथवा होता है उस परिस्थिति में टक-समता को दोनों देशों की मुद्रा-स्फीति के अनुपात से गुणा करने से क्रयशक्ति-समता निवाली जाती है”<sup>१</sup> इस क्रय-शक्ति-समता सिद्धान्त को प्रोफेसर मुस्टाव कैसेल ने प्रथम महायुद्ध के बाद, जब सब देशों में अपरिवर्तनीय पत्र चलन था, प्रस्तुत किया। विनिमय-दर निर्दिष्ट करने का यह एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त है।

क्रयशक्ति-समता सिद्धान्त की आलोचना

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि टक-समता की जगह क्रयशक्ति-समता सिद्धान्त के द्वारा विभिन्न देशों की विनिमय-दर दीर्घकाल में निर्दिष्ट की जाती है। इसलिए इस सिद्धान्त के द्वारा मही परिणाम पर पहुँचने के लिए आवश्यक है कि क्रयशक्ति नापने का साधन ठीक हो, जिसमें हम बिलकुल ठीक परिणाम पर पहुँच सकें। किन्तु हमारा क्रयशक्ति नापने का साधन निर्देशांक है जो सर्वथा ठीक न होते हुए केवल औसत (averages) बतलाते हैं तथा वस्तुओं की सूची भी भिन्न-भिन्न देशों में भिन्न भिन्न होती है अतः इन निर्देशांकों द्वारा निवाली हुई क्रयशक्ति-समता कभी भी मही नहीं हो सकती। इसलिए इस सिद्धान्त के बारे में श्री० वॉल्टर लीफ ने कहा है—“शुरू में तो यह एक साधारण वस्तु प्रतीत होती है, परन्तु बठिनाइयाँ आ पड़ती हैं जिनका निवारण करना वास्तव में असम्भव है।

१ सबसे पहला आक्षेप तो इस सिद्धान्त के विरुद्ध यह है कि निर्देशांक की सहायता से निकाली हुई मुद्राओं की क्रयशक्ति केवल औसत बतलाती है और इसलिए इसकी सहायता से निकाली हुई विभिन्न मुद्राओं की क्रयशक्ति सही नहीं होती क्योंकि सब वस्तुओं की कीमतें न एक साथ बढ़ती हैं और न एक साथ घटती हैं।

२ निर्देशांक बनाते समय केवल कुछ चुनी हुई वस्तुओं का ही समावेश किया जाता है न कि उस देश के औद्योगिक जीवन में आने वाली सब

वस्तुओं का । इतना ही नहीं, बल्कि ऐसी चुनी हुई वस्तुओं को केवल अन्तर-राष्ट्रीय व्यापारिक वस्तुओं तक ही सीमित रखने में हम सही परिणाम पर नहीं पहुँचते क्योंकि ऐसी वस्तुओं की कीमत सब देशों में एक ही परिमाण में घटती है या बढ़ती है क्योंकि आयात की हुई वस्तुओं की कीमतें उनकी निर्यात-कीमत, वाहन-व्यय एवं विनिमय-दर से ही निश्चित की जाती है ।<sup>१</sup>

३ विनिमय-दर में माँग एवं पूर्ति के अनुसार तत्कालीन परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से व्यापार पर प्रभाव पड़ता है तथा आयात एवं निर्यात में रुकावटें पैदा होती हैं, परिणामस्वरूप प्रत्येक देश में कीमतों का वास्तविक स्तर ठीक प्रकार में नहीं मालूम हो सकता इसलिए इस सिद्धान्त के द्वारा परिवर्तन पाल में इस सिद्धान्त में हम विनिमय दर के चढ़ाव उतार के कारणों का विशेषण ठीक तरह नहीं कर सकते और न ऐसे समय में क्रयशक्ति-समता ही मालूम कर सकते हैं । हाँ, दीर्घकालीन अवधि में इस सिद्धान्त से क्रयशक्ति समता अवश्य मालूम हो सकती है क्योंकि मौद्रिक परिवर्तनों से क्रयशक्ति पर होने वाले परिणाम इससे जाने जा सकते हैं किन्तु अन्य परिस्थितियों में परिवर्तन होने से विनिमय दर पर जो प्रभाव पड़ता है उसके कारणों का स्पष्टीकरण इस सिद्धान्त द्वारा नहीं हो सकता । आयात निर्यात में कोई ग्रहण्य आयात अथवा निर्यात में परिवर्तन होने से भी विनिमय दर प्रभावित होती है जिसका समावेश इस सिद्धान्त में नहीं हो सकता इसलिए यह सिद्धान्त ठीक परिणाम नहीं दे सकता ।

४ निर्देशांक बनाने में जिन वस्तुओं का समावेश होता है वे वस्तुएँ बहुधा कच्चा मान अथवा खाद्यान्न होती है । किन्तु अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में निर्मित वस्तुओं की कीमता का भी समावेश होता है जिससे क्रयशक्ति समता के माप में त्रुटि आती है । निर्मित वस्तुओं की कीमत केवल वच्चे माल पर निर्भर न रहते हुए मजदूरी, व्याज आदि अन्य वस्तुओं पर भी निर्भर रहती है । इन वस्तुओं की कीमत एक साथ ही नहीं बढ़ती और न एक साथ घटती है, किन्तु मजदूरी आदि की दर कीमत बढ़ने के ६-७ महीने बाद बढ़ती है । अतः इस सिद्धान्त में कावक्षेप की त्रुटि रहती है जिसके कारण हम ठीक नतीजे पर नहीं पहुँच सकते । उगी प्रकार कीमतों की गति में तथा निर्देशांकों के बनाने के बीच भी कुछ गम्य व्यतीत होता है जिसके कारण इस सिद्धान्त में कावक्षेप की त्रुटि रहती है ।

५. राजनीतिक परिस्थिति तथा व्यापार के आयात-निर्यात पर ह्वावटें डालने से भी कीमतों का सही स्तर नहीं मालूम हो सकता क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति जैसे युद्ध आदि के कारण विनिमय की दर बढ़ जाती है परन्तु उस देश के आन्तरिक मूल्य-स्तर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार आयात-निर्यात पर ह्वावटें अथवा प्रतिबन्ध लगाने का हेतु भी विनिमय-दर को स्थिर रखने का होना है। इस कारण भी इस सिद्धान्त में त्रुटि आती है।

६. क्रयशक्ति-समता सिद्धान्त द्वारा निकाली हुई समता स्थिर न रहते हुए अस्थिर रहती है क्योंकि यह निर्देशांकों पर निर्भर रहती है जो सदैव बदलते रहते हैं तथा जिनका मिलान टक्-समता की तरह स्वयंपूर्ण नहीं होता।

इन प्राक्षेपों के होने हुए भी यह सिद्धान्त मार्ग-दर्शक की तरह दो देशों में विनिमय-दर किस प्रकार निश्चित होती है, यह बताता है। इसलिए दीर्घकालीन विनिमय-दर निश्चित करने का यह अच्छा साधन है। यद्यपि इसमें क्रयशक्ति-समता ठीक तरह नहीं निकाली जा सकती और न इसी समता के बराबर विनिमय-दर रहती है और न टक्-समता की तरह विलकुल सही परिणाम देती है। यह सिद्धान्त किसी भी प्रकार की चलन-बढ़ति में लागू होना है और अन्य सिद्धान्तों की अपेक्षा अच्छा है क्योंकि व्यापार का एक किस समय किस दिशा में होगा यह इस सिद्धान्त द्वारा मालूम होता है। इस प्रकार विश्व में मुद्राओं के अवमूल्यन अथवा अधिमूल्यन से विदेशी व्यापार तथा विनिमय-दर पर होने वाले परिणामों को हम जान सकते हैं तथा गत वर्षों में एक आज दुनिया में क्या हो रहा है इनका भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इसलिए इस सिद्धान्त का ज्ञान तीन दृष्टियों से आवश्यक है —

पहिले, दीर्घकालीन अवधि में विनिमय-दर क्रयशक्ति-समता के अनुसार क्या होगी यह हम जान सकते हैं।

दूसरे, विभिन्न देशों के ऋणों का शेष किन बातों पर निर्भर रहता है तथा उस पर विनिमय-दर का क्या प्रभाव होता है यह मालूम होता है क्योंकि ऋणों का शेष विनिमय-दर, विभिन्न देशों में होने वाली वस्तुओं की आवश्यक-जावक तथा उनके मूल्यों के परस्पर प्रभाव पर निर्भर रहता है।

तीसरे, यह भी मालूम होता है कि मूल्य-स्थायी का कोई भी योजना आन्तरिक एवं अन्तर्देशीय मूल्य-स्तर की जानकारी के बिना मफन नहीं हो सकती।

## विनिमय-दर को प्रभावित करने वाले घटक

हम यह ऊपर बता चुके हैं कि अल्पकालीन विनिमय-दर अनेक कारणों से क्रयशक्ति-ममता से घटती या बढ़ती है—चाहे यह क्रयशक्ति स्वर्ण-मुद्रा वाले देशों के बीच हो अथवा अपरिवर्तनीय पत्र-चलन वाले देशों के बीच हो। वे कौनसे कारण हैं जिनका प्रभाव अल्पकालीन विनिमय-दर पर होता है तथा जिससे विनिमय दर में उतार-चढ़ाव होते हैं ?

**व्यापारिक-शेष सिद्धान्त**—विलो की माँग तथा पूर्ति पर विनिमय-दर निर्भर रहती है। किसी देश से वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात तथा वस्तुओं एवं सेवाओं या जो आयात होना है उससे उस देश की मुद्रा की अन्य देशों में माँग एवं पूर्ति निश्चित होती है। यदि माँग पूर्ति में अधिक होती है तो उस देश के लिए विनिमय-दर पक्ष में होती है अथवा उस देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देशों की मुद्राओं में समता से बढ़ जाता है। इसके विपरीत यदि उस देश की मुद्रा की पूर्ति अधिक एवं माँग कम है तो विनिमय-दर समता से घट जाती है एवं उस देश के विपक्ष में होती है अर्थात् उस देश की मुद्रा विदेशी मुद्राएँ कम खरीदती हैं। अर्थात् किसी भी समय विनिमय-दर का चढ़ाव-उतार उस देश की मुद्रा की माँग एवं पूर्ति पर—जो व्यापारिक कारणों से उत्पन्न होती है—निर्भर रहता है। इसी को व्यापारिक-शेष सिद्धान्त (balance of trade theory) कहते हैं।

इस सिद्धान्त के अनुसार यदि किसी देश में निर्यात से आयात अधिक है तो व्यापारिक शेष प्रतिकूल अथवा विपक्ष में होगा अर्थात् इस देश में विदेशी मुद्राओं की माँग उनकी पूर्ति से अधिक होगी जिसके कारण उस देश और अन्य देशों के बीच विनिमय दर गिरेगी। अतः इस देश की मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में कम होगा। उसी प्रकार यदि आयात से निर्यात अधिक होता है तो व्यापारिक-शेष अनुकूल अथवा पक्ष में होगा अर्थात् इस देश में विदेशी मुद्राओं की पूर्ति माँग से अधिक होगी जिसके कारण इस देश की विनिमय-दर विदेशी मुद्रा में बढ़ेगी, जिससे इस देश की मुद्रा विदेशी मुद्राओं को अधिक खरीदेगी। इस प्रकार इस सिद्धान्त के अनुसार विनिमय-दर व्यापारिक शेष के अनुसार घटेगी अथवा बढ़ेगी।

**खाता-शेष सिद्धान्त**—वास्तव में विदेशी विनिमय की माँग एवं पूर्ति केवल व्यापारिक वस्तुओं के आयात-निर्यात पर ही निर्भर न रहत हुए ऐसी अन्य बातों पर निर्भर रहती है जिनमें विदेशी मुद्रा की माँग तथा पूर्ति उत्पन्न होती

है। विनिमय-दर दृश्य तथा अदृश्य आयात-निर्यात से भी प्रभावित होती है। दृश्य आयात एवं निर्यात में उन सब व्यापारिक वस्तुओं का समावेश होता है जिनके आँकड़े उपलब्ध होते हैं। किन्तु विदेशी मुद्रा की माँग एवं पूर्ति उन सेवाओं के भुगतान के लिए भी होती है जिनके आँकड़े उपलब्ध नहीं होते—जैसे जहाजरानी की सेवाएँ, बैंक तथा बीमा की सेवाएँ, एक दूसरे देश को दिये जाने वाले ऋण, एक-दूसरे देश में होने वाले विनियोग, विदेशी यानियों के व्यय, विदेशी-विनिमय का भट्ठा, आदि। दूसरे, आजकल अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के भुगतान केवल दो देशों में न होते हुए विभिन्न देशों के गेन देन का शेष निकाल कर किये जाते हैं और इस खाता शेष (balance of accounts) के अनुसार कोई भी देश दीर्घकालीन अवधि में उनना ही निर्यात कर सकता है जितना वहाँ पर आयात होता है। कारण यह है कि यदि स्वर्ण के आयात-निर्यात पर किसी भी प्रकार के प्रतिबन्ध न हो तो एक देश में दूसरे देश के भुगतान में जो स्वर्ण जायगा उसमें वहाँ के आन्तरिक मूल्य बढ़ेंगे। परिणाम-स्वरूप वहाँ में निर्यात कम होगा तथा आयात अधिक। इसके विपरीत यदि उस देश में स्वर्ण आता है तो वहाँ के आन्तरिक मूल्य बढ़ेंगे। अतः आयात अधिक होगा एवं निर्यात कम। इस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में स्वर्ण की अप्रतिबन्धित गति होती है और उस समय खाता-शेष का अपने आप समायोजन हो जाता है तथा विनिमय-दर भी क्रयशक्ति-समता के आसपास आ जाती है। इस प्रकार खाता-शेष सिद्धान्त के अनुसार देश-विदेशों की विनिमय-दर प्रभावित होती है तथा निम्न खातों का मन्तुलन हो जाता है। शरारत में इस सिद्धान्त के अनुसार यदि खाता-शेष हमारे पक्ष में है अर्थात् यदि हमको विदेशियों से भुगतान लेना है तो विनिमय-दर हमारे पक्ष में होगी। इसके विपरीत यदि खाता-शेष हमारे प्रतिबल है अर्थात् यदि हम विदेशियों के ऋणी हैं तो विनिमय-दर हमारे विपक्ष में होगी।

इस सिद्धान्त के अनुसार अल्पकालीन अवधि में एक देश का खाता शेष उसके अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। परन्तु दीर्घकालीन अवधि में खाता-शेष का मन्तुलन होता ही चाहिए क्योंकि कोई भी देश अपने निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ, यदि गरी मामिक आय (१००) ६० है तो मैं एक महीने में (१०५) खर्चा कर लूँगा, दूसरे महीने में कर लूँगा परन्तु तीसरे महीने में मुझे आय-व्यय का मन्तुलन करना ही पड़ेगा नहीं तो मरा दिवाना निकलने में दर न लगगी। जो बात एक व्यक्ति के लिए लागू होती है वही एक देश के लिए भी लागू होनी है।

इससे यह स्पष्ट है कि विनिमय-दर मुख्यतः तीन कारणों से प्रभावित होती है .—

- १ विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थिति
- २ किसी देश के चलन की परिस्थिति तथा
३. राजनीतिक परिस्थिति

१. विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति—यह तीन कारणों में प्रभावित होती है .—

- (क) व्यापारिक परिस्थिति
- (ख) बैंकिंग परिस्थिति
- (ग) स्कन्ध-विनिमय परिस्थिति

**व्यापारिक परिस्थिति**—देश-विदेश की व्यापारिक परिस्थिति का परिणाम देश के आयात-निर्यात पर होता है जिसके कारण विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति प्रभावित होती है तथा विनिमय-दर भी । जैसा ऊपर बताया गया है, यदि निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक होता है तो विदेशी मुद्रा की मांग पूर्ति की अपेक्षा बढ़ती है और विनिमय-दर भी हमारे विपक्ष में होता है अर्थात् इस परिस्थिति में हमारे देश की मुद्रा विदेशी मुद्राओं को कम खरीदेगी । इसके विपरीत परिणाम आयात से निर्यात की अधिकता होने पर होते हैं अर्थात् विदेशी मुद्रा की पूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होने से विनिमय-दर हमारे पक्ष में होती है तथा हमारी मुद्रा विदेशी मुद्राओं को अधिक खरीद सकती है अर्थात् विदेशी मुद्राओं में हमारी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है ।

**बैंकिंग परिस्थिति**—बैंकों की कार्य-प्रणाली से भी विनिमय-दर प्रभावित होती है । बैंकिंग परिस्थिति में बैंकों की व्याज की दर अथवा अपहार-दर ( discount rate ), उनके साख्मन्त्रों का विदेशी में क्रय-विक्रय तथा लाभ के लिए किया हुआ विदेशी मुद्राओं के क्रय विक्रय का समावेश होता है । अधिकोष के इन सब व्यवहारों से विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति पर प्रभाव होने से विनिमय-दर भी प्रभावित होती है । किसी भी देश में यदि बैंक दर अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा बड़ा दी जाय तो इस देश में विदेशी व्यक्तियों को अपना पैसा लगाना लाभदायक होता है । परिणामस्वरूप विदेशों में उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ जाती है जिसके कारण देशी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में बढ़ जाता है अर्थात् देशी मुद्रा पहिले की अपेक्षा विदेशी मुद्रा अधिक खरीद सकती है । इसके विपरीत यदि बैंक-दर अन्य राष्ट्रों की तुलना में कम कर दी जाय तो उस देश

से विदेशों को पूँजी जाने लगती है। परिणामस्वरूप उस देश की मुद्रा की पूर्ति माँग की अपेक्षा बढ़ जाती है जिसके कारण विनिमय-दर विदेशी मुद्रा में घट जाती है, अर्थात् देशी मुद्रा अब विदेशी मुद्राएँ कम खरीदती है।

इसी प्रकार साख-पत्रों के क्रय-विक्रय का परिणाम भी विनिमय-दर पर होता है। जिस समय हमारे देश के बैंक विदेशों में जाने वाले यात्रियों को साख-पत्र बेचने हैं उसका मतलब यह होता है कि विदेशी मुद्रा को हम खरीदते हैं। विदेशी मुद्रा की माँग पूर्ति की अपेक्षा अधिक होने से विनिमय-दर गिर जाती है अथवा देशी मुद्रा विदेशी मुद्राएँ कम खरीदती है। इसके विपरीत जब विदेशों से हमारे देश में भुगतान के लिए साख-पत्र दिये जाते हैं उन समय हमारी मुद्रा की माँग पूर्ति की अपेक्षा अधिक होने से विनिमय-दर बढ़ जाती है अथवा हमारी मुद्रा विदेशी मुद्राएँ अधिक खरीदती है।

लाभार्जन के हेतु भी विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय होता है जिसे अन्तर-पणन व्यवहार ( arbitrage dealings ) कहते हैं। इस प्रकार के व्यवहार दो प्रकार के होते हैं - एक साधारण एवान्तरपणन ( simple arbitrage ) तथा दूसरे बहु-अन्तरपणन ( compound dealings )। पहिले व्यवहारों में दो देशों की मुद्रा का क्रय-विक्रय दो मौद्रिक केन्द्रों में किया जाता है जिसका हेतु यह होता है कि दोनों केन्द्रों की दर में जो अन्तर हो उसमें लाभ कमाया जाय। उदाहरणार्थ, बम्बई में यदि रुपये का स्टनिंग-मूल्य १८ पैसे प्रति रुपया है और इङ्ग्लैण्ड में उभी समय प्रति रुपया १८½ पैसे की दर है, तो इन दोनों दरों के अन्तर से ½ पैसे प्रति रुपया लाभ हो सकता है। इसलिए हम तार द्वारा इङ्ग्लैण्ड से १८½ पैसे प्रति रुपये की दर से स्टनिंग खरीदेंगे जिनको भारत में १८ पैसे प्रति रुपये की दर से बेच देंगे जिससे हमको ½ पैसे प्रति रुपया लाभ होगा। परन्तु इस लाभ को देखते समय हमको एक जगह से मुद्रा खरीदकर दूसरी जगह बेचने में तार इत्यादि का जो व्यय होगा वह कम करना होगा। बहु-अन्तरपणन व्यवहारों में विभिन्न मौद्रिक केन्द्रों पर विभिन्न मुद्राएँ खरीदी तथा बेची जाती है और उन केन्द्रों पर विनिमय-दर में अन्तर होने से लाभ कमाया जाता है। ये बहु-अन्तरपणन व्यवहार केवल विशेषज्ञों द्वारा एक बेचो द्वारा ही किये जाते हैं जो इस विषय में अपनी जानकारी रखते हैं तथा विभिन्न मौद्रिक केन्द्रों के सम्पर्क में रहते हैं। इस प्रकार के व्यवहारों से विभिन्न केन्द्रों पर विनिमय-दरों में जो अन्तर होते हैं वे कम हो जाते हैं क्योंकि मुद्राओं की दरों में अन्तर होने से लाभ कमाने के लिए उनकी खरीद बिक्री सदैव होती रहती है।

इस प्रकार के व्यवहार जो बैंको द्वारा किये जाते हैं उनसे एक देश की मुद्रा की माँग पूर्ति की अपेक्षा बढ़ती है तथा दूसरे देश में पूर्ति माँग की अपेक्षा बढ़ती है जिससे विनिमय-दर प्रभावित होती है। उपर्युक्त उदाहरण में टर्नेड में स्टैलिंग की माँग बढ़ जाती है, पूर्ति नहीं। परिणामस्वरूप स्टैलिंग का रुपये में मूल्य गिर जायगा अथवा विदेशी विनिमय-दर बढ़ जायगी। दूसरी ओर भारत में स्टैलिंग की पूर्ति अधिक होने से विदेशी विनिमय-दर गिर जायगी अर्थात् रुपया पहिले की अपेक्षा अधिक पैस खरीद सकेगा। यह विनिमय-दर की अस्थिरता तब तक रहेंगी जब तक दोनों ही केन्द्रों में विनिमय-दर समान नहीं होती। इस प्रकार बैंको द्वारा किये जाने वाले अन्तरपणन व्यवहारों से विनिमय-दर प्रभावित होती है।

**दीर्घकालीन ऋण**—बैंको द्वारा एक-दूसरे देशों को जो ऋण दिये जाते हैं उनका प्रभाव भी विनिमय-दर पर होता है। दीर्घकालीन अवधि में विनिमय की दर साहूकार राष्ट्र के विपक्ष में होगी क्योंकि उनकी मुद्रा की पूर्ति अधिक होती है। परन्तु तत्कालीन अथवा अल्पकालीन परिणाम उम ऋण के उपयोग पर निर्भर रहेगा। यदि उम ऋण का उपयोग उसी देश में माल खरीदने के लिए किया जाय तो विनिमय-दर पर कोई प्रभाव नहीं होगा किन्तु उम ऋण में यदि दूसरे राष्ट्रों में माल खरीदा जाय तो उन राष्ट्रों में इस देश की मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। परिणामतः विनिमय-दर गिर जायगी और साहूकार अथवा ऋण देने वाले देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा को कम खरीदेगी।

**स्कन्ध-विनिमय-परिस्थिति**—स्कन्ध-विनिमय व्यवहारों में विनियोग-पत्र, स्कन्ध आदि का क्रय-विक्रय, ऋणों की लेन-देन, व्याज एवं लाभांश की लेन-देन तथा मर्च के व्यवहारों का समावेश होता है। विनियोग पत्रों को यदि हम दूसरे देशों से खरीदते हैं तो हमको विदेशी मुद्रा में भुगतान करना पड़ता है जिसके कारण हमारे देश में विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ती है, परिणामस्वरूप विनिमय-दर विदेशी मुद्रा में घटती है। इसके विपरीत हमारे देश के विनियोग एवं स्कन्ध यदि विदेशियों द्वारा खरीदे जाते हैं तो हमारी मुद्रा की माँग बढ़ने से हमारी मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा में बढ़ जाती है।

ऋणों की लेन-देन का परिणाम “दीर्घकालीन ऋणों” की तरह ही होता है, जिसका उत्पन्न ऊपर हो चुका है।

**लाभांश तथा व्याज की लेन-देन**—जहाँ तक लाभांश एवं व्याज की प्राप्ति का सम्बन्ध है उम समय जब लाभांश एवं व्याज हमको मिलता है तब विदेशी

मुद्राओं की पूर्ति बटती है। परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय की दर हमारे पक्ष में हो जाती है अर्थात् हमारी मुद्रा अधिक विदेशी मुद्राएँ खरीद सकती है। इसके विपरीत जब हम दूसरे देशों को व्याज एवं लाभांश का भुगतान करते हैं उस समय भुगतान करने के लिए हमको विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है और विदेशी मुद्रा की माँग हमारे यहाँ बढ़ जाती है। परिणामस्वरूप विनिमय दर विदेशी मुद्रा में पड़ जाती है अथवा हमारे विपक्ष में होती है। उन्नी प्रकार ऋणों के भुगतान का परिणाम भी विनिमय दर पर हमारे प्रतिकूल होने में ही होता है क्योंकि ऋणों के भुगतान के लिए विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ जाती है।

२ चलन परिस्थिति (Currency Conditions)—चलन की परिस्थिति में चलनाधिक्य अथवा मुद्रा संकोच, अवमूल्यन आदि का समावेश होता है। यदि किसी देश में चलनाधिक्य की सम्भावना है तो उस देश के व्यक्ति अपनी पूँजी बाहर लगाना चाहेंगे क्योंकि चलनाधिक्य में मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है अर्थात् उसकी क्रयशक्ति कम हो जाती है। परिणामस्वरूप विनिमय दर उस देश के प्रतिकूल होगी अथवा विदेशी मुद्रा में उस देश की मुद्रा का मूल्य गिर जायगा। किन्तु यदि विन्हीं कारणों से चलन में अधिमूल्यन (appreciation) की सम्भावना है तो उस समय लाभ के हेतु विदेशी लोग भी उस चलन को खरीदने लगेंगे जिसके कारण विदेशी मुद्रा में इस देश की मुद्रा का मूल्य बढ़ जायगा तथा विनिमय-दर अनुकूल एवं पक्ष में होगी।

३ राजनीतिक परिस्थिति—राजनीतिक परिस्थिति में व्यापारिक सन्धियों, देश की व्यापारिक एवं संरक्षण नीति, युद्ध, हड़ताल आदि का समावेश होता है। किसी देश में यदि किसी भी प्रकार में व्यापार में रूकावट डाली जायेंगी तो उनका परिणाम विनिमय-दर पर होगा। इसी प्रकार युद्धजन्य परिस्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन हो जाता है, क्रयशक्ति कम हो जाती है जिसकी वजह से विनिमय दर भी ऐसे देश के प्रतिकूल हो जाती है। राजनीतिक परिस्थिति से देश की मौद्रिक नीति में भी परिवर्तन होता है जिसका परिणाम विनिमय-दर को अधिक प्रभावशाली बना देता है। इसी प्रकार विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण करने से भी विनिमय-दर प्रभावित होती है।

इस प्रकार विनिमय-दर को प्रभावित करने वाले घटक पृष्ठ १४३ पर दी हुई सारणी से पूर्णतः स्पष्ट हो जायेंगे।

विदेशी विनिमय सम्बन्धी शब्द-प्रयोग

अनुकूल तथा प्रतिकूल अथवा पक्ष तथा विपक्ष में विनिमय-दर—जब विनि-

मय-दर अपनी मुद्रा में व्यक्त की जाती है तब गिरती हुई विनिमय-दर हमारे अनुकूल होगी क्योंकि इस दर पर हम विदेशी मुद्रा के बदले में अपनी मुद्रा कम देगे। इसके विपरीत यदि विनिमय-दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त की जाती है तो चढ़ती हुई विनिमय-दर हमारे अनुकूल होगी क्योंकि इस अवस्था में हमारी मुद्रा अधिक विदेशी मुद्राएँ खरीदेगी। उदाहरणार्थ, जब १ र० = १६ पैसे है तो हमको १ पीड ऋण चुकाने के लिए १५ र० देने पड़ेंगे किन्तु जब विनिमय-दर विदेशी मुद्रा में बढ़कर १ र० = १८ पैसे होती है तब हमको १ पीड चुकाने के लिए केवल १३ र० ५ आ० ४ पाई ही देने पड़ेगे अर्थात् हमको १ र० १० आने का लाभ होगा। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि जिस दर पर स्वर्ण हमारे देश में निर्यात होगा वह दर हमारे लिए प्रतिकूल तथा जिस दर पर स्वर्ण हमारे यहाँ आयात होगा वह दर हमारे लिए अनुकूल दर होगी। इसमें यह स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा में जब विनिमय-दर व्यक्त की जाती है तब ऊँची दर अनुकूल तथा गिरती हुई दर प्रतिकूल होती है और जब हमारी मुद्रा में विनिमय-दर व्यक्त की जाती है तब नीची दर अनुकूल तथा ऊँची दर प्रतिकूल होती है।

इस प्रकार अनुकूल एवं प्रतिकूल विनिमय-दर से भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर भिन्न-भिन्न प्रभाव होता है।

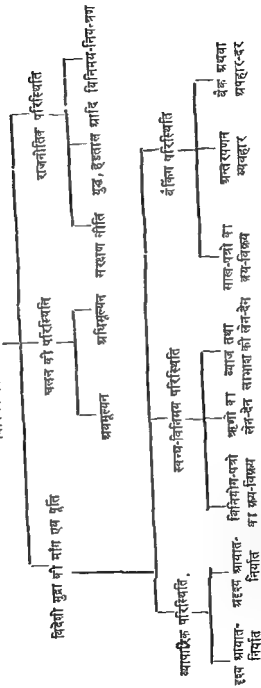
जब विनिमय-दर हमारे अनुकूल होती है उस समय विदेशों में हमारी मुद्रा की क्रयशक्ति बढ़ती है अर्थात् उमी रकम से हम पहिले की अपेक्षा अधिक माल विदेशों में खरीद सकते हैं। इसलिए आयातकर्त्ताओं को लाभ होता है तथा विदेशी माल हमारे देश में सस्ता होने से उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है।

इसके विपरीत इस दर पर निर्यातकर्त्ताओं को हानि होती है क्योंकि विदेशों में हमारी मुद्रा मँहगी होने से विदेशी मुद्रा की क्रयशक्ति हमारे यहाँ कम होती है अर्थात् हमारे यहाँ की खरीद उनको मँहगी पड़ती है। अतः निर्यात कम हो जाता है जिससे उत्पादक वर्ग को हानि होती है, उत्पादन कम हो जाता है तथा यह दर अधिक काल तक रहने से कारखाने बन्द हो जाते हैं और बेकारी बढ़ने लगती है।

विनिमय-दर की प्रतिकूल परिस्थिति में इसके विपरीत परिणाम होते हैं अर्थात् आयातकर्त्ताओं को हानि तथा निर्यातकर्त्ताओं को लाभ होता है और निर्यात बढ़ता है जिससे उत्पादन कार्य तथा रोजगारी भी बढ़ती है। इसलिए प्रतिकूल दर देश की आर्थिक उन्नति की दृष्टि से लाभदायक होती है।

# विनिमय-दर को प्रभावित करने वाले घटक

विनिमय-दर में उच्चावचन के कारण



ऊँची दर खरीदो, नीची दर बेचो—जब देशी मुद्रा की विनिमय-दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त की जाती है तब ऊँची दर हमारे लिए अनुकूल होती है। इसलिए जब विनिमय-दर बढ़ती है उस समय विदेशी विनिमय अथवा विदेशी मुद्राएँ खरीदना हमारे देशवासियों को लाभकर होता है। ऐसे समय में देशवासियों को अपने ऋणों या भुगतान करना लाभकर होगा क्योंकि अपने ऋणों में भुगतान के लिए उनको देशी मुद्राएँ कम देनी पड़ेंगी। इसके विपरीत जब दर नीची होती है उस समय हमारी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्राएँ कम मिलती हैं, इसलिए ऐसे समय अधिक देशी मुद्रा खमाने के लिए देशवासियों को अपना भुगतान लेना लाभदायक होना है क्योंकि इससे उनको प्रति विदेशी मुद्रा के बदले अधिक देशी मुद्रा मिलेंगी। इसलिए जब विनिमय दर विदेशी मुद्रा में बढ़ती है तब विदेशी मुद्रा को खरीदना लाभदायक तथा बेचना हानिकर होता है।

इसी प्रकार जब विदेशी मुद्रा की विनिमय-दर हमारी मुद्रा में व्यक्त की जाती है उस समय ऊँची दर हमारे प्रतिफल होती है तथा नीची दर अनुकूल। ऊँची दर पर यदि हम विदेशी मुद्राएँ बेचें तो हमको अधिक रुपये मिलेंगे तथा ऊँची दर पर विदेशी मुद्रा को खरीदने के लिए हमको अधिक रुपये देने पड़ेंगे। अर्थात् इस समय विदेशी मुद्रा बेचना लाभदायक होगा। जब यह दर नीची हो जाती है तो हमारी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में बढ़ जाता है अर्थात् यदि इस समय विदेशी मुद्रा हम खरीदें तो हमको कम रुपये देने पड़ेंगे तथा हमको रुपये में बचत होगी। अतः नीची दर पर विदेशी मुद्रा खरीदना लाभदायक होगा। इसलिए जब विदेशी मुद्रा में हमारी मुद्रा की दर व्यक्त की जाती है उस समय “नीची दर खरीदो तथा ऊँची दर बेचो” यह कहना यथार्थ होगा।

इसीलिए यह भी कहा जाता है कि जितना अच्छा बिल होगा उतनी नीची विनिमय-दर पर वह विकेगा अर्थात् जितना अच्छा बिल होगा उतनी ऊँची कीमत उसकी विदेशी में लगेगी—जब विनिमय दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त की जाती है। इसके विपरीत जब विनिमय दर देशी मुद्रा में व्यक्त की जाती है उस समय जितना अच्छा बिल होगा उतनी ऊँची विनिमय दर होगी अर्थात् विदेशी में उस बिल के बदले अधिक देशी मुद्राएँ मिलेंगी।

विनिमय-दर की वृद्धि तथा कमी—जब अपनी मुद्राओं का मूल्य विदेशी मुद्राओं में व्यक्त किया जाता है उस समय दर की वृद्धि का अर्थ है विदेशी मुद्राओं का अवमूल्यन अर्थात् हमारी मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा अधिक मात्रा

मे मिलेगी। दर की कमी का मतलब है हमारी मुद्रा के सम्बन्ध में विदेशी मुद्राओं का अधिमूल्यन अर्थात् हमारी प्रत्येक मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा कम मिलेगी। कभी-कभी इन शब्दों का प्रयोग विपरीत अर्थ में भी होता है अर्थात् जब विदेशी मुद्रा का मूल्य हमारी मुद्रा में व्यक्त होता है उस समय दर की वृद्धि का अर्थ होता है हमारी मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिमूल्यन तथा दर की कमी का अर्थ है हमारी मुद्रा का विदेशी मुद्रा की तुलना में अधिमूल्यन।

### विनिमय-दरों का वर्गीकरण

विनिमय-दर विधेयन दो प्रकार की होती हैं —

१. अल्पकालीन दर तथा २. दीर्घकालीन दर। इसमें तारप्रेषण-दर (telegraphic transfer rate), दर्शनी अथवा माँग ड्राफ्ट की दर तथा कृत्रिम निर्दिष्ट काल बाद शोषण होने वाले ड्राफ्ट की दर का समावेश होता है जिसमें ने पहिली दो अल्पकालीन दरें तथा तीसरी दीर्घकालीन दर होती है जिनको क्रमशः तारप्रेषण दर, बैंक दर तथा दीर्घकालीन दर कहते हैं।

तारप्रेषण-दर—यह दर जितनी समय बाजार में जो विनिमय दर होती है उसी के बराबर होती है। इस पद्धति में मुद्रा लेनदार को उतनी जल्दी प्राप्त हो सकती है जितनी जल्दी नार एक दिन में दूसरे दिन को पहुँचता है। यह दर सब दरों में सस्ती होती है तथा अन्य दर इसी दर के आधार पर निकाली जाती है। इसमें तार का व्यय, जो व्यक्ति मुद्रा का परिवर्तन करता है उसमें लिया जाता है। बहुधा तार-व्यय का समावेश तारप्रेषण दर में कर दिया जाता है।

बैंक-दर अथवा दर्शनी ड्राफ्ट दर—घनादेन-दर तारप्रेषण-दर से निकाली जाती है। जब कोई भी बैंक दूसरे देश में—मान लीजिए इंग्लैण्ड में—बैंक भेजता है उस समय या तो उस बैंक का स्वयं इंग्लैण्ड में जमा रहता है या वह तार द्वारा इंग्लैण्ड में वहाँ की मुद्रा खरीद कर इंग्लैण्ड की बैंक में जमा कर देगा। अब इस रजम पर वहाँ उसे अल्पकालीन व्याज-दर से व्याज मिलेगा। अब बैंक-दर उन अल्पकालीन व्याज-दर तथा तारप्रेषण-दर पर निर्भर रहती है। बैंक वहाँ से इंग्लैण्ड में एक द्वारा ७ दिन में पहुँचेगा अर्थात् बैंक जिन दर से बैंक भेजेगा वह दर तारप्रेषण-दर में ७ दिन व्याज कम करके बनेगी। इसी प्रकार जब विदेशी बैंक खरीदे जाते हैं तो तारप्रेषण-दर में से व्याज की दर कम करके बैंक-दर निकाली जायगी।

**दीर्घकालीन दर**—दीर्घकालीन दर बिलों के उस मूल्य को कहते हैं जो साधारणतया ३०, ६० अथवा ९० दिन बाद चुकाये जाते हैं। इनकी दर तारप्रेषण-दर में, जितनी अवधि के वे हैं उतनी अवधि का व्याज, वहाँ का स्टाम्प कर (stamp duty) तथा आकस्मिक व्यय जोड़कर निकाली जाती है। जितनी कम अवधि का बिल होगा उतनी ही उसकी दर भी सस्ती होगी। यदि विनिमय-दर देशी मुद्रा में व्यक्त की जाती है तो तारप्रेषण-दर में से सामयिक व्याज, स्टाम्प-कर तथा आकस्मिक व्यय घटा कर दीर्घकालीन दर निकाली जाती है।

**टेल-क्वेल-दर (Tel-quel Rate)**—यह सामयिक बिलों की वास्तविक दर होती है। मान लीजिए एक बिल तीन महीने बाद देय है परन्तु उसके दो महीने व्यतीत हो चुके हैं तो उस बिल की विनिमय-दर विदेशी मुद्रा में निकालने के लिए तारप्रेषण-दर में १ माह का व्याज जोड़ दिया जायगा तथा यदि देशी मुद्रा में विनिमय-दर व्यक्त की जानी है तो तारप्रेषण-दर में से यह व्याज घटा दिया जायगा।

### अग्र विनिमय (Forward Exchanges)

मुद्रा के बाद जब विभिन्न देशों में अपरिवर्तनीय पत्र-मुद्रा का चलन प्रारम्भ हुआ उस समय विनिमय-दर में देशों की मौद्रिक, राजनीतिक एवं बैंकिंग परिस्थिति के अनुसार उच्चावचन भी होने लगे जिससे विनिमय-दर में अनिश्चितता रहने लगी। विनिमय-दर की अनिश्चितता से व्यापार में भी रुकावटें आने लगी जिनका निवारण करने के लिए विदेशी मुद्राओं का अग्र विनिमय अथवा पहले से ही क्रय-विक्रय करना शुरू हुआ जिससे व्यापारियों की विनिमय-दर के उतार-चढ़ाव से होने वाली हानियों से सुरक्षा हो सके। अग्र विनिमय का मुख्य हेतु विनिमय-दर के उच्चावचन में होने वाली हानियों को विदेशी मुद्रा के अग्र क्रय-विक्रय द्वारा कम करना है। अग्र विनिमय के व्यवहार विनिमय बैंकों द्वारा ही किये जाते हैं।

उदाहरणार्थ, मान लीजिए एक भारतीय व्यापारी को, जो माल आयात करता है, इंग्लैण्ड के किमी निर्यातकर्ता को १००० पाँड देना है जिनका भुगतान वह तीन या चार महीने बाद करेगा। ऐसी परिस्थिति में वह यह ठीक तरह नहीं जान सकता कि उसे तीन महीने बाद १००० पाँड के बदले कितने रुपये देने पड़ेंगे क्योंकि विनिमय-दर में अनिश्चितता होती है। इसलिए वह अपने आयात माल की कीमत भी नहीं निश्चित कर सकता। इसी प्रकार

भारतीय निर्यातकर्त्ता यदि १००० पौंड का माल इङ्ग्लैण्ड को भेजता है तो वह ठीक से नहीं जानता कि उसे ३ महीने बाद कितने रुपये मिलेंगे तथा उसको निर्यात से लाभ होगा अथवा हानि। इसलिए ऐसी अवस्था में वह विनिमय-बैंक के पास जाकर विदेशी मुद्रा अर्थात् पौंड तीन महीने पहिले ही निश्चित दर पर बेच देगा जिस दर पर उसे तीन महीने बाद रूपों में भुगतान मिल जायगा। इसी प्रकार भारतीय आयातकर्त्ता विनिमय-बैंक के पास जाकर तीन महीने पहिले ही उसको जितनी विदेशी मुद्राओं की आवश्यकता है उतनी खरीद लेगा, जिसका भुगतान वह इस निश्चित दर पर तीन महीने बाद करेगा। इस प्रकार अग्र क्रय एवं अग्र विक्रय से आयातकर्त्ता तथा निर्यातकर्त्ता, उनको कितनी रकम देना है अथवा लेना है, यह निश्चित कर लेते हैं क्योंकि इनके मौदे जिस दर पर हो गये हैं उसी दर पर उनको भुगतान करना पड़ेगा, जिसमें विनिमय-दर के उच्चावचन का कोई भी परिणाम इन व्यापारियों के लेन-देन पर नहीं होगा। इस प्रकार के अग्र विनिमय व्यवहार प्रतिदिन करोड़ों के होते रहते हैं।

अग्र विनिमय-दर विनिमय की चासु दर होती है जिस दर पर विदेशी मुद्रा का तत्कालीन क्रय-विक्रय होता है। यदि अग्र विनिमय में देशी मुद्रा के बदले में कम विदेशी मुद्रा मिलती है तो विदेशी मुद्रा प्रव्याजि पर होती है। इसी प्रकार जब देशी मुद्रा के बदले में अधिक विदेशी मुद्रा मिलती है उस समय विदेशी मुद्रा अपहार पर होती है। दूसरे शब्दों में, जब विदेशी मुद्रा में दर गिरती है तब देशी मुद्रा अपहार पर होती है तथा जब विदेशी मुद्रा में दर चढ़ती है तब देशी मुद्रा प्रव्याजि पर होती है। अग्र विनिमय में विदेशी मुद्रा का प्रव्याजि अथवा अपहार होना तीन बातों पर निर्भर है :—

१. देश-विदेशों की व्याज की दर,
२. देश-विदेशों की चलन की स्थिति,
३. विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय के परस्पर सम्बन्ध जोड़ना।

१. देश-विदेश की व्याज की दर—हम यह बता चुके हैं कि यदि किसी देश में बैंक-दर अथवा व्याज की दर अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है तब उस देश में पूँजी लगाना विदेशियों को लाभकर होगा क्योंकि इससे वे अपनी पूँजी पर अधिक लाभ कमा सकते हैं। इसी प्रकार यदि विदेशों में व्याज की दर हमारे देश से अधिक है तो हमारे यहाँ की पूँजी उन देशों में लगाना लाभदायक है। इसलिए अग्र विनिमय-दर प्रव्याजि पर अथवा अपहार पर होगी, यह व्याज की दर से निश्चित होता है। यदि विदेशों की व्याज दर हमारे यहाँ की दर से

अधिक है तो हमारे यहाँ की पूँजी वहाँ जाना लाभदायक होगा इसलिए अग्र विनिमय-दर अपहार पर होगी अर्थात् देशी मुद्रा के बदले अधिक विदेशी मुद्रा खरीदी जा सकती है। इसी प्रकार यदि विदेशों की व्याज की दर हमारे देश से कम होगी तो पूँजी हमारे देश में भायगी। ऐसे समय अग्र विनिमय की दर प्रव्याजि पर होगी अथवा देशी मुद्रा के बदले में कम विदेशी मुद्रा मिलेगी।

२. चलन की स्थिति—किसी भी देश की मुद्रा के अवमूल्यन अथवा अधिमूल्यन पर भी विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय की अग्र विनिमय-दर निर्भर रहती है। यदि विदेशी मुद्रा में अवमूल्यन होने की सम्भावना है तो बैंक उन मुद्रा का अग्रिम क्रय करने के लिए अनिच्छुक होते हैं इसलिए अग्र विनिमय में विदेशी मुद्रा की दर प्रव्याजि पर होती है। यदि अधिमूल्यन होने की सम्भावना है तो अग्र विनिमय में विदेशी मुद्रा अपहार पर होगी क्योंकि बैंक ऐसी मुद्रा को खरीदने के लिए इच्छुक होंगे।

३. विदेशी मुद्रा के क्रय-विक्रय के परस्पर सम्बन्ध जोड़ना—जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं, कुछ लोग विदेशी मुद्रा बेचना चाहते हैं तथा कुछ विदेशी मुद्रा अग्रिम खरीदना चाहते हैं। ऐसे समय में बैंक बीच में आकर एक जगह विदेशी मुद्रा खरीदते हैं तथा दूसरे देश में वही मुद्रा बेच देते हैं और ऐसे क्रय-विक्रय से वे लाभ कमाते हैं। इन प्रकार एक देश का क्रय दूसरे देश के विक्रय में सम्बन्धित किया जाता है। ऐसे परस्पर सम्बन्ध की सम्भावना जितनी अधिक होती है उतनी ही अग्र विनिमय में विदेशी मुद्रा अपहार पर होगी अर्थात् देशी मुद्रा के बदले में अधिक विदेशी मुद्रा मिलेगी और परस्पर क्रय-विक्रय के सम्बन्ध के जितने कम अवसर होंगे उतनी ही विदेशी मुद्रा प्रव्याजि पर होगी।

इस प्रकार से अग्र विनिमय होते रहने के कारण विनिमय-दर में उच्चावचन कम होते हैं। इस प्रकार के व्यवहार केवल व्यापारिक कार्यों के लिए ही न होने हुए परिकल्पनिक कार्यों की दृष्टि से भी किये जाते हैं।

**विनिमय-दर का संशोधन (Correction of Exchanges)**

विनिमय-दर में उच्चावचन होने के मूलतः तीन कारण होते हैं—१. चलन में अवमूल्यन अथवा अधिमूल्यन होने से, २ व्यापारिक सन्तुलन विपक्ष में अथवा पक्ष में होने से, तथा ३ व्याज एवं अधिकोप-दर में वृद्धि अथवा कमी होने से। जब चलन में अवमूल्यन के कारण विनिमय-दर समता से नीचे गिरने

लगती है उस समय चलन में सुधार करने से विनिमय-दर स्थिर की जाती है। दूसरे, जब व्यापारिक सन्तुलन विपक्ष में होने से विनों की पूर्ति की अपेक्षा मांग बढती है और विनिमय-दर गिरने लगती है तो विनिमय-दर का मशोधन स्वर्ण के निर्यात से दीर्घवालीन अवधि में स्वयं ही हो जाता है। किन्तु स्वर्ण-निर्यात की जब सम्भावना ही नहीं होती उस समय नियन्त्रण द्वारा विनिमय-दर में स्थिरता लाई जाती है। तीसरे, विनिमय-दर में जब व्याज अथवा अधिकोप-दर की वृद्धि अथवा कमी के कारण उच्चावचन होता है उस समय विनिमय-दर का मशोधन मौद्रिक बाजार में अथवा मुद्रामण्डी में व्याज अथवा अधिकोप-दर के नियमन में किया जाता है। इस प्रकार भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में विनिमय-दर के उच्चावचन का मशोधन किया जाता है।

### विनिमय-नियन्त्रण<sup>१</sup>

विनिमय-दर में जब अधिक उतार-चढ़ाव होने लगता है तथा उसमें स्थिरता नहीं रहती, उस समय सरकार द्वारा विनिमय पर नियन्त्रण लगाया जाता है जिसकी दो पद्धतियाँ हैं — एक तो देश के आयात-निर्यात का विभिन्न उपायों द्वारा इस प्रकार नियमन करना जिससे दर की वृद्धि अथवा कमी सीमित रहे। दूसरे, विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय सरकार द्वारा निश्चित दरों पर किया जाना। इन दोनों पद्धतियों में से पहिली पद्धति में सरकार स्वयं विनिमय बाजार में आकर विदेशी मुद्राओं की खरीद-बिक्री करती है तथा विनिमय-दर को स्थिर करने का प्रयत्न करती है। विनिमय नियन्त्रण की इस पद्धति को हस्त-क्षेप कहते हैं। इस पद्धति से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इनमें विनिमय बाजार का काम बढता है क्योंकि कृत्रिमता से विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री सरकार करती है। इनके विपरीत दूसरी पद्धति में सरकार विदेशी मुद्राओं की खरीद-बिक्री पर रोक लगा देती है, मुद्राओं का क्रय-विक्रय स्वयं नहीं करती। इसलिए इस पद्धति को विनिमय प्रतिबन्ध कहते हैं। जहाँ तक विनिमय बाजार का सम्बन्ध है इस प्रकार के प्रतिबन्धों से विनिमय व्यवहार कम हो जाते हैं क्योंकि सरकार जनता के स्वतन्त्र प्रवेश में हस्तक्षेप करती है। इन दोनों ही पद्धतियों के नियन्त्रण का मूल हेतु विनिमय-दर के उच्चावचन को सीमित रखना होता है। इसके अतिरिक्त विनिमय-नियन्त्रण के अन्य हेतु निम्न-लिखित हैं —

<sup>१</sup> भारत में विनिमय-नियन्त्रण के लिए देखिए “भारतीय चलन का इतिहास”

१. देश से पूंजी के बाहर जाने पर प्रतिबन्ध लगाना अथवा अधिकोपो में स्वर्ण-निधि को स्वर्ण-निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाकर कम न होने देना, तथा

२. विदेशी मुद्रा की चळती हुई माँग पर प्रतिबन्ध लगाकर उसकी पूर्ति बढ़ाना ।

विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण लगाने की भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ हैं :—

१. विदेशी व्यापार का नियन्त्रण—देश में आयात वस्तुओं पर सरक्षक कर लगाने से आयात कम हो जाता है । ऐसे कर अनावश्यक वस्तुओं पर लगाये जाते हैं अथवा देश के उत्पादन का निर्यात अधिक हो सके इसलिए आर्थिक सहायता द्वारा उनका निर्यात बढ़ाया जाता है । आयात एवं निर्यात के लिए व्यापारियों को सनद लेनी पड़ती है जिनके बिना वे न आयात कर सकते हैं और न निर्यात । प्रत्येक वस्तु के आयात-निर्यात की निश्चित मात्रा अथवा निश्चित वजन ठहरा दिया जाता है जिससे अधिक न किसी वस्तु का आयात हो सकता है और न किसी वस्तु का निर्यात । इस प्रकार व्यापार में रुकावटें डालने से व्यापारिक क्षेत्र अपने पक्ष में करके विनिमय-दर में स्थिरता लायी जाती है तथा विनिमय-दर अनुकूल बनाई जाती है ।

२. विदेशी विनिमय का नियन्त्रित वितरण—ऐसी परिस्थिति में सरकार अथवा केन्द्रीय अधिकोप विदेशी विनिमय का निश्चित दरो पर क्रय-विक्रय करती है और कुछ अधिकृत कार्यों अथवा व्यवहारों के लिए ही विदेशी विनिमय बेचा जाता है । यह कार्य मुद्रा-काल में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया का था ।

३. विनिमय-समकरण कोष—विनिमय-दर में जब अधिक उच्चापन होते हैं उस समय विनिमय-दर को निश्चित स्तर पर स्थिर रखने के लिए इस कोष की सहायता से विदेशी मुद्राओं का क्रय-विक्रय किया जाता है । इस प्रकार की कोष का निर्माण इंग्लैंड में १९३२ में १५०० लाख पौंड कोष विपन्न तथा स्वर्ण में रखकर किया गया था । १९३३ में यह रकम ३५०० लाख पौंड तथा १९३७ में ५५०० लाख पौंड कर दी गई थी । किसी भी समय स्टैलिंग की माँग पूर्ति की अपेक्षा अधिक होने से जब स्टैलिंग की विनिमय-दर बढ़ने लगती थी तो इस कोष द्वारा विदेशी में विदेशी मुद्राएँ खरीदी जाती थी जिससे विनिमय-दर बढ़ने से रोक दी जाती थी और जो विदेशी मुद्रा खरीदी जाती थी उसे विदेशी अधिकोषों में निधि के रूप में जमा कर दिया जाता था । इसके विपरीत जब स्टैलिंग की पूर्ति अधिक होती थी एवं माँग कम, और

स्टर्लिंग-दर गिरने लगती थी, उस समय विदेशी निधि में से स्टर्लिंग खरीदा जाता था जिसमें स्टर्लिंग की मांग बढ़ जाती थी और विनिमय-दर गिरने से रोक दी जाती थी। इस प्रकार इस कोष की कार्य पद्धति द्वारा विनिमय-दर के उच्चावचन सीमित किये जाते थे। इस प्रकार की कोष अमेरिका, फ्रान्स आदि देशों में भी रखी गई थी।

४. **बैंक-दर का नियमन**—बैंक-दर का प्रभाव पूँजी के आयात-निर्यात पर किन प्रकार होता है इसका वर्णन हम पहलें कर चुके हैं। पूँजी के आयात-निर्यात में आवश्यकतानुसार बैंक दर को कम या अधिक करने से विनिमय दर के उच्चावचन का रोकड़ा जाता था।

५. **विदेशी लेखाओं का बन्द करना**—हमारे देश में विदेशी व्यापारियों की कुछ न कुछ पूँजी लगी रहती है। उसी प्रकार उनकी रकम हमारे बैंकों में भी जमा रहती है। ऐसे विदेशी लेखाओं को बन्द कर दिया जाता है तथा विदेशी पूँजी के बाहर जाने पर रोक लगा दी जाती है जिससे विदेशी हमारे देश से अपनी रकम नहीं निकाल सकते। हमारे देश में जो रकम जमा है उसका उपयोग विदेशी लोग कुछ विशेष कामों के लिए ही कर सकते हैं, जिनके लिए सरकार उन्हें अनुमति देती है। इस प्रकार संस्था बन्द करने से विदेशी पूँजी हमारे देश से बाहर नहीं जा सकती जिससे विनिमय-दर के उच्चावचन भी रोके जा सकते हैं।

६. **‘जैसे थे’ समझौते**—‘जैसे थे’ समझौते के अनुसार एक देश से दूसरे देश में जो पूँजी का आवागमन होता है उसको उन देशों में आपसी समझौता होने से रोक दिया जाता है जिसमें विनिमय-दर स्थिर रखने में सहायता होती है। इन समझौतों में विदेशी व्यापारियों के क्रमशः भुगतान किस प्रकार होंगे इसका भी स्पष्टीकरण होता है। इन पद्धति का उपयोग जर्मनी में १९३१ के बाद किया गया था।

७. इसके अतिरिक्त विनिमय-नियन्त्रण की एक और पद्धति है जिसके अनुसार विदेशियों के ऋणों का भुगतान देश के अधिकृत बैंक को देशी मुद्रा में ही किया जाता है, जिसका भुगतान विदेशियों को कुछ निश्चित अवधि के बाद—जो समझौते से ठहराई जाती है—किया जाता है। इसको परिवर्तन विलम्बकाल कहते हैं।

८. **समाशोधन समझौते**—इसमें दो देशों में आपसी समझौते द्वारा एक-दूसरे के ऋणों का भुगतान समझौते की शर्तों के अनुसार किया जाता है। इस

पद्धति में दोनों देशों में आयातकर्त्ता अपने भाल का भुगतान उस देश के अधिकृत बैंको को देशी मुद्राओं में करते हैं। यही बैंक देशी निर्यातकर्त्ताओं को उनका भुगतान कर देते हैं। इस प्रकार मुद्राओं का स्थानान्तरण न होने हुए दोनों का भुगतान हो जाता है। ममभौने द्वारा विनिमय-दर निश्चित होती है तथा व्यापारिक सन्तुलन सरकार के हस्तक्षेप द्वारा आवश्यकतानुसार ठीक किया जाता है अर्थात् दोनों देशों के आयात एवं निर्यात मूल्यों का जो अन्तर होता है उसी का भुगतान एक देश दूसरे देश को करता है।

६ विनिमय कीलन—विनिमय-दर को बढे हुए विनिमय-मूल्य पर स्थिर रखने के लिए जब सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो उसे विनिमय-कीलन कहते हैं। इस प्रकार का विनिमय-कीलन ही आजकल विनिमय-नियन्त्रण का प्रधान रूप है।<sup>१</sup> इस स्थिति में सरकार अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा में निश्चित दर पर कील देती है। उदाहरणार्थ, प्रथम विश्वयुद्ध काल में स्टर्लिंग मूल्य ४.७६ $\frac{1}{2}$  डालर पर कील दिया गया था। इसी प्रकार भारत में भी १९२७ से रुपये का गठबन्धन स्टर्लिंग से १८ पैसे प्रति रुपये की दर से किया गया था, जिसको स्थायी रखने का सरकार प्रयत्न करती थी। यह कार्य देश की सरकार अथवा केन्द्रीय अधिकोप विदेशी मुद्राओं का निश्चित दरो पर क्रय-विक्रय करके पूरा करती है।

विनिमय-स्थिरता तथा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष

१९४४ की ब्रोटेनवुड्स् परिपद् के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की स्थापना से विनिमय-दर की स्थिरता का कार्य अधिक सरल हो गया है। इस कोष का मूल उद्देश्य ही अपने सभासद राष्ट्रों के बीच विनिमय-दर को स्थिर रखना, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय-धनमूल्यन को रोकना और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि करना है। कोष का मुख्य कार्य अपने सभासद राष्ट्रों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय निश्चित दर पर करना है। इसके लिए सभासद राष्ट्रों की मुद्रा का मूल्य स्वर्ण अथवा डॉलर से सम्बन्धित कर दिया गया है। एक वर्ष में ऋणी राष्ट्रों को उनका जो कोटा जमा है उससे दूनी रकम के बराबर दूसरे देश की मुद्रा मिल सकती है किन्तु इससे अधिक विदेशी ऋण होने पर उनको आयात पर रोक लगानी पड़ेगी। इस प्रकार स्वर्ण-निर्यात नहीं होने दिया जाता।

इस कोष के भारत और पाकिस्तान भी मदम्य है। कोष किसी भी देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा किन्तु किसी भी देश की मुद्रा का अवमूल्यन अथवा मूल्य-वृद्धि बिना कोष की अनुमति के नहीं हो सकती। इस कोष की स्थापना से अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान के सब लाभ सदस्यों को प्राप्त हो गये हैं।

### सारांश

विदेशी विनिमय यह पद्धति है जिससे अन्तरराष्ट्रीय ऋणों का भुगतान किया जाता है। हार्टले बिट्स के शब्दों में 'विदेशी विनिमय अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा परिवर्तन का विज्ञान एवं कला है।' यह तीन बातों से सम्बन्धित है,— विदेशी बिल, विनिमय-दर तथा विदेशी विनिमय बैंक।

अन्तरराष्ट्रीय भुगतान के तीन साधन हो सकते हैं—(१) स्वर्ण बेकर भुगतान करना, (२) आयात के बदले में वस्तुएँ निर्यात करना, (३) विनिमय बिलों द्वारा भुगतान करना। तीसरी पद्धति ही अधिकतर उपयोग में आती है जिससे स्वर्ण के आयात-निर्यात में होने वाली असुविधाएँ तथा खसरे नहीं रहते।

जिस दर पर एक देश के बिल दूसरे देश में खरीदे या बेचे जाते हैं उस दर को विदेशी विनिमय-दर कहते हैं। दूसरे शब्दों में, दो देशों की प्रमाणित मुद्राओं के परस्पर अनुपात को विनिमय-दर कहते हैं। चूँकि भिन्न-भिन्न देशों की मोद्रिक प्रणाली भिन्न-भिन्न हो सकती है इसलिए विदेशी विनिमय-दर निश्चिन करने की चार पद्धतियाँ हैं :—

(१) जब दो देश स्वर्णमान पर होते हैं तो उन देशों की विनिमय-दर प्रमाणित मुद्रा के वैधानिक स्वर्ण मूल्य की समानता के साथ निश्चित होती है। इसे टक-समता कहते हैं।

(२) जब एक देश स्वर्णमान पर और दूसरा देश रजतमान पर आधारित हो तो दोनों देशों की विनिमय-दर प्रमाणित मुद्राओं के वैधानिक स्वर्ण मूल्य की समानता के साथ निश्चित होगी। जब रजतमान वाले देश की प्रमाणित मुद्रा का स्वर्ण मूल्य निश्चित नहीं होता तो स्वर्णमान वाले देश पर चाँदी का टकसाली मूल्य होता है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों की प्रमाणित मुद्राओं के वैधानिक रजत मूल्य समता के आधार पर विनिमय-दर निश्चित होगी।

(३) जब एक देश स्वर्ण या रजतमान पर एवं दूसरा देश अपरिवर्त्य

पत्रमुद्रा पर आधारित हो तो दोनों मुद्राओं के स्वर्ण-मूल्य-समता पर विनिमय-दर निश्चित होगी। हाँ, अपरिवर्त्य मुद्रा वाले देश की मुद्रा का स्वर्ण मूल्य टकसाती न होते हुए बाजारी मूल्य होगा।

धातुमान पर आधारित देशों के विनिमय-दर के उतार-चढ़ाव की जो सीमाएँ होती हैं उसे निम्नतम स्वर्ण बिन्दु एवं उच्चतम स्वर्ण बिन्दु कहते हैं। टकसाती समता में स्वर्ण का वाहन व्यय जोड़कर स्वर्ण निर्यात बिन्दु अथवा उच्चतम दर तथा वाहन व्यय घटाकर स्वर्ण आयात बिन्दु या निम्नतम दर मालूम की जा सकती है।

(४) जब दोनों देश अपरिवर्तनीय पत्रमुद्रा पर हो तो उनकी विनिमय-दर परस्पर मुद्राओं की क्रयशक्ति-समता पर निर्भर होगी।

क्रयशक्ति-समता सिद्धान्त से विनिमय-दर निकालने के लिए निदेशांको से सहायता लेनी होती है। अतः यह दर वास्तविक दर न होते हुए औसत दर होती है जो निदेशांको के साथ बदलती है। इस सिद्धान्त के विरोध में आलोचनाएँ होते हुए भी यह सिद्धान्त विनिमय-दर निकालने के लिए महत्वपूर्ण है।

विनिमय-दर में उतार-चढ़ाव साधारणतः विदेशी मुद्रा की माँग एवं पूर्ति पर निर्भर होता है और विदेशी मुद्रा या बिन्नी की माँग एवं पूर्ति निम्न बातों से प्रभावित होती है —

व्यापारिक शेष सिद्धान्त के अनुसार किसी भी समय विनिमय दर का उतार-चढ़ाव दूसरे देश की माँग एवं पूर्ति पर जो व्यापारिक कारणों से उत्पन्न होती है—निर्भर रहता है। किन्तु वास्तव में विदेशी विनिमय की माँग एवं पूर्ति केवल व्यापारिक वस्तुओं के आयात निर्यात पर ही निर्भर न रहते हुए अन्य बातों पर निर्भर रहती है जो विदेशी मुद्रा की माँग एवं पूर्ति पर प्रभाव डालती हैं। इसमें दृश्य एवं अदृश्य दोनों ही प्रकार के आयात एवं निर्यात का समावेश होता है। फिर अन्तरराष्ट्रीय आधार पर एक देश ने दूसरे देश को कितना लेना देना है जिसका खाता तैयार किया जाता है। इसे खाता-शेष सिद्धान्त कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार कोई भी देश दीर्घकालीन अवधि में उतना ही निर्यात कर सकेगा जितना वहाँ आयात होगा। परन्तु अल्पकालीन अवधि में यदि खाता-शेष हमारे पक्ष में है तो विनिमय दर भी पक्ष में रहेगी अन्यथा विपक्ष में रहेगी।

अल्पकालीन अवस्था में विनिमय-दर में निम्न कारणों से उतार-चढ़ाव

होते हैं — व्यापारिक स्थिति, बैंकिंग स्थिति, स्कच विनिमय की स्थिति, चलन की स्थिति एवं राजनीतिक स्थिति आदि ।

जब विनिमय-दर अपनी मुद्रा में बनाई जाती है तब गिरती हुई विनिमय-दर पक्ष में अथवा अनुकूल होती है । इसके विपरीत यदि विनिमय-दर विदेशी मुद्रा में व्यवत की जाती है तो गिरती हुई विनिमय-दर हमारे प्रतिकूल अथवा विपक्ष में होती है ।

जब देशी मुद्रा की विनिमय-दर विदेशी मुद्रा में व्यक्त की जाती है तब ऊँची दर हमारे अनुकूल होती है इसलिए ऊँची दर पर विदेशी मुद्राएँ खरीदना लाभकर होता है । इसी प्रकार जब विदेशी मुद्रा की विनिमय-दर हमारी मुद्रा में व्यक्त होती है तब ऊँची दर हमारे प्रतिकूल होती है ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा बेचना लाभकर होगा ।

अप्र विनिमय विनिमय-दर में होने वाले भविष्यकालीन उतार-चढ़ाव से होने वाली संभावित हानि से बचने के लिए जब व्यापारी विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय के पहिले से ही समझौता कर लेते हैं तब उसे अप्र विनिमय कहते हैं । ये विदेशी विनिमय बैंको द्वारा किये जाते हैं । इन लेन-देनो में विदेशी मुद्रा की दर प्रव्याजि अथवा कटौती पर होगी । यह तीन बातों पर निर्भर होता है —

- (अ) देश-विदेश की बैंक-दर,
- (आ) देश-विदेश की चलन की परिस्थिति, तथा
- (इ) विदेशी मुद्रा के क्रय विक्रय का परस्पर सन्तुलन ।

विनिमय नियन्त्रण जब विनिमय-दर में स्थिरता नहीं रहती उस समय देश की सरकार विनिमय-दर में स्थिरता लाने के लिए माँग एवं प्रदाय में कृत्रिम कमी-वृद्धि करती है । इसे विनिमय नियन्त्रण कहते हैं । ये नियन्त्रण दो प्रकार से लगाये जाते हैं—(१) आयात-निर्यातों के नियमन द्वारा तथा (२) विदेशी विनिमय का निश्चित दरों पर क्रय विक्रय करने से ।

विनिमय नियन्त्रण के दो हेतु—(१) देशी पूँजी अथवा स्वर्ण को बाहर जाने से रोकना, (२) विदेशी मुद्रा की बढ़ती हुई माँग पर रोक लगाकर उसकी शक्ति बढ़ाना ।

विनिमय नियन्त्रण की निम्न पद्धतियाँ हैं —

विदेशी व्यापार का नियमन, विदेशी विनिमय का नियन्त्रित वितरण,

विनिमय समकरण लेखा, बैंक-दर का नियमन, विदेशी लेखाओं का बन्द करना, 'जैसे थे' सम्झौते, परिवर्तन विलम्ब-काल, समाशोधन सम्झौते तथा विनिमय-कीलन ।

१९४५ में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना से विनिमय-दर की स्थिरता का कार्य सरल हो गया है क्योंकि इसका मूल उद्देश्य विनिमय-दर को स्थिर रखना, प्रतिस्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन न होने देना तथा अन्तर-राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि करना है ।

## अध्याय १२

# भारतीय चलन का इतिहास (१)

(१८६३ से १९१४ तक)

भारतीय चलन के इतिहास का विवेचन करने से पहिले यहाँ की गत कुछ शताब्दियों की चलन-पद्धति का मन्दभ देना आवश्यक है। हमारे यहाँ हिन्दू काल में भी स्वर्ण तथा चाँदी की मुद्राओं का उपयोग बहुलता में होता था तथा मुसलमानों के आगमन के बाद उन्होंने भी यहाँ की प्राचीन पद्धति का ही अपनाया किन्तु अकबर के शासनकाल में भारत में रजतमान का अपनाया गया तथा चंदन में एकता लाई गई। मुगल बादशाह के अन्त के बाद इस एकता का भी विनाश हुआ तथा भिन्न भिन्न राज्यों की स्वतन्त्रता के साथ-साथ उन्होंने अलग अलग टकनालाएँ स्थापित की जिसमें भिन्न भिन्न मुद्राओं का जगम हुआ। फिर भी आन्तरिक एवं विदेशी व्यापार में विशेषतः चाँदी का रूप ही मूल्य-मापन काय करना रहा। इस रूप की शुद्धता तथा वजन में भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्नता थी। अतः व्यापारिक व्यवहार का भुगतान चाँदी की शुद्धता तथा वजन से होता था। इसके बाद जब ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत की राजकीय बागडोर संभाली उस समय भारत में स्वर्ण तथा रजत के मिलाकर लगभग १६४ प्रकार के सिक्के चलन में थे, जिनका परिवर्तन एक दूसरे से वजन तथा शुद्धता के अनुसार सराफ-साहूकारों द्वारा किया जाता था। इस कारण व्यापारिक व्यवहार में एकावट अनुभव होती थी।

इन एकावटों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम १८१८ में मद्रास में चाँदी के तथा स्वर्ण के नये सिक्के बनाये गए। चाँदी के रूपये का वजन १८० ग्रेन था जिसमें  $\frac{1}{12}$  भाग अर्थात् १५ ग्रन शुद्ध चाँदी होती थी। १८३५ में मद्रास के रूपये की तरह अपने राज्य में मुद्रा में एकावटाला के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने रूपये की मुद्रा का चलन प्रारम्भ किया तथा इस रूप को असीमित विधिग्राह्य घोषित किया गया। १८३५ से यही भारत का प्रमाणित सिक्का बनाया गया जिसका मुक्त टकण होना था। स्वर्ण के सिक्के ब्रिटिश भारत में

अवैध घोषित किये गये। परन्तु फिर भी १८३५ के टकण-विधान के अनुसार जनकी ढलाई हो सकती थी। इस प्रकार ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत में रजतमान का अवलम्बन किया जो १८७१ तक ठीक तरह कार्यरूप में रहा किन्तु १८७१ में विश्व की परिस्थिति में महान् परिवर्तन हुए जिनके कारण रुपये का स्वर्ण-मूल्य गिरने लगा। यह मूल्य १८७१ में २ सि० प्रति रपया से गिरकर १८६२ में १ सि० २ पें० प्रति रपया रह गया।

रुपये का स्वर्ण-मूल्य गिरने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे —

१ इस अवधि में १८४८ में पाई गई आस्ट्रेलिया और कैलीफोर्निया की खानों का स्वर्ण लगभग निराल चुका था जिससे स्वर्ण अब बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता था। स्वर्ण की इस कमी के कारण स्वर्ण का मूल्य बढ़ने लगा तथा दूसरी ओर स्वर्ण की तुलना में चाँदी का मूल्य गिरने लगा।

२ हमारे, अमेरिका के नेवादा में चाँदी की समृद्ध खानों की खोज हुई जिससे बहुत अधिक मात्रा में चाँदी निकाली गई तथा बाजार में आई। परिणामतः चाँदी की बहुलता से उसका मूल्य और भी गिरने लगा।

३ इसी समय १८७०-७१ में जर्मनी की फ्रांस पर युद्ध में विजय हुई तथा हानि पूर्ति के लिए फ्रांस ने स्वर्ण देना तय किया। जर्मनी ने अपनी विजय रजत का परित्याग एवं स्वर्ण धातुमान अपना कर भनाई। परिणाम यह हुआ कि जर्मनी में चाँदी बाजार में बिकने के लिए आई। यह मात्रा १८७३ से १८७६ तक लगभग ११ करोड़ औंस से अधिक थी। जर्मनी के स्वर्णमान घटाने के साथ इटली, स्वीडन, आस्ट्रिया आदि देशों ने भी उसका अनुकरण किया जिसके कारण चाँदी का मूल्य अधिकाधिक गिरता गया।

४ इसके अतिरिक्त सीसा नामक धातु से रसायनिक क्रिया द्वारा चाँदी का धुवस्करण किया जाने लगा तथा रीप्य बनने लगा जो बाजारों में बिकने के लिए आने लगा जिसके कारण स्वर्ण और चाँदी का परस्पर मूल्य सम्बन्ध बिगड़ने लगा एवं चाँदी का मूल्य स्वर्ण में गिरने लगा।

५ अमेरिका के डेरमन एक्ट में सशोधन—डेरमन एक्ट के अनुसार अमेरिका अपनी मौद्रिक आवश्यकताओं के लिए प्रति वर्ष ५४० औंस चाँदी खरीदा करता था परन्तु इसी समय अमेरिका ने डेरमन एक्ट में सशोधन करके चाँदी का खरीदना बन्द कर दिया। परिणामस्वरूप चाँदी रजतमान वाले देशों में भेजी जाने लगी जिससे उसका स्वर्ण मूल्य गिरने लगा।

इन कारणों से चाँदी का मूल्य १८६१ में १ सि० २ पेंस रह गया जो

भारतीय व्यापारियों की दृष्टि से तथा सरकार के राजस्व की दृष्टि से हानिकारक था क्योंकि सरकार को प्रति वर्ष गृह-व्यय के रूप में लम्बी रकम इङ्ग्लैण्ड को देनी पड़ती थी<sup>१</sup> जिससे भारत सरकार को अब पहिले की अपेक्षा अधिक रुपये देने पड़ते थे, जिसके लिए कर बढ़ाने की आवश्यकता थी जो प्रतिवर्ष बढ़ाना असम्भव था ।

६. इसके साथ ही, व्यापारियों की दृष्टि से, चाँदी का स्वर्ण-मूल्य गिरने से विदेशी मुद्रा में भी भारतीय सिक्के का मूल्य गिर गया, जब विनिमय दर गिरने लगती है तो निर्यात बढ़ते हैं तथा आयात कम होते हैं । जब यह विनिमय-दर १ सि० २ पेंस रह गई तब इसका मतलब था उतना ही माल इङ्ग्लैण्ड से खरीदने के लिए अधिक रुपया देना । अब आयात मान यहाँ पर महंगा होने से आयात घट गया और विदेशी व्यापारियों को भारत में अब उतनी ही मुद्रा में अधिक माल उपलब्ध होने के कारण निर्यात बढ़ने लगा । यह बढ़ता हुआ निर्यात-व्यापार विदेशियों को खटकने लगा । इनके अलावा विनिमय-दर की अनिश्चितता के कारण व्यापार में भी अनिश्चितता आ गई ।

७. विनिमय दर गिरने के कारण भारत में ब्रिटिश पूँजी का आना बन्द हो गया ।

८. भारत सरकार की सेवा में जो अंग्रेज नौकर थे उनको इङ्ग्लैण्ड में उतने ही पौण्ड अपने कुटुम्बियों को भेजने के लिए अधिक रुपये की आवश्यकता थी परन्तु उन्हें वही वेतन मिलता था जिसमें उन्हें भी हानि होने लगी । इसलिए उनमें असन्तोष फैलने लगा और उन्होंने अपने वेतन में वृद्धि करने की माँग की ।

९. विदेशी पूँजी—विनिमय-दर में गिरावट आने की वजह से भारत में आने वाली विदेशी पूँजी भी रुक गई क्योंकि इस गिरावट के कारण विनियोगकर्ताओं को लाभान्वित अथवा व्याज के रूप में कीमती पौण्ड मिलते । इधर देश के औद्योगिक विकास के लिए तो विदेशी पूँजी की आवश्यकता थी ही, जो न आने के कारण औद्योगिक विकास में भी रुकावट आ गई ।

इन सब कारणों से १८७३ की विद्रव्यमन्दी ने भी जोर पकड़ा । सरकार

<sup>१</sup> यह गृह-व्यय की राशि १७ मिलियन पौण्ड के लगभग थी जो १४,२६,५७,००० रुपये के बराबर पहले थी, परन्तु चाँदी का भाव गिरने के कारण उसी राशि के मुगलान के लिए २६,४७,८४,१५० रुपये आवश्यक थे ।

को अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अधिकाधिक रुपये की आवश्यकता पड़े और अड़चने अनुभव होने लगी। फलस्वरूप जनता ने स्वर्णमान के अव-  
लम्बन के लिए आवाज बुलन्द की और सरकार ने १८७८ में ब्रिटिश पार्लिया-  
मेण्ट में स्वर्णमान अपनाने का प्रस्ताव भेजा, जो बेकार साबित हुआ। १८६१  
में भारत सरकार ने फिर प्रस्ताव भेजा जिसमें यह कहा गया कि चाँदी का  
मुक्त टक्का बन्द कर दिया जाय जिससे रुपये की कमी सी होगी और उनका  
स्वर्ण-मूल्य तथा विनिमय-दर बढ़ने लगेंगी, इसके साथ ही स्वर्णमान अपनाने  
का प्रस्ताव भी किया गया था। इस प्रस्ताव पर कोई विचार न होते हुए यह  
आश्वासन दिया गया कि १८६२ में अन्तरराष्ट्रीय द्विधातुमान अपनाने के  
सम्बन्ध में विचार करने के लिए जा परिषद होने वाली है, वह व्यर्थ साबित  
होने पर तब विचार किया जायगा। परन्तु यह परिषद असफल रही और  
द्विधातुमान की चर्चा हमेशा के लिए समाप्त हो गई।

### हर्शल समिति

इसलिए १८६२ में भारत सरकार के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए  
चलन समिति लार्ड हर्शल की अध्यक्षता में नियुक्त की गई जो हर्शल कमेटी के  
नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने कुछ सुधार के साथ भारत सरकार के प्रस्ताव का  
समर्थन निम्नलिखित सिफारिशों में किया —

१ चाँदी का मुक्त टक्का बन्द किया जाय जिससे जनता अपनी आव-  
श्यकतानुसार टक्काला पर लाकर चाँदी का रुपये में परिवर्तन न करा सके,  
किन्तु सरकार का यह अधिकार होगा कि वह रुपये की ढलाई सोने के बदले  
प्रति रुपया १ सि० ४ पस अथवा ७५३३.६४ ग्रेन के हिसाब से करे।

२ स्वर्ण की मुद्राएँ मरकाही कोपी में १ सि० ४ पे० की दर से स्वीकृत  
की जायें, यही विनिमय-दर स्थायी हो।

३ रुपये की अमीमित विधिवाह्यता बनी रहे।

इन सिफारिशों में स्वर्णमान के अपनाने के लिए कोई योजना नहीं थी।  
किन्तु यह विचार था कि जब रुपये की १ सि० ४ पेंस की दर स्थापित हो  
जाय तब स्वर्णमान को अपनाया जाय। इस बीच भारत सरकार स्वयंनिधि  
का नियोजन करे।

इन सिफारिशों को कार्यरूप में लाने के लिए १८६३ में एक अधिनियम  
स्वीकृत किया गया जिससे १८७० के कॉइनेज एक्ट तथा १८८२ के हण्डियन  
ऐक्ट करैन्सी एक्ट या सशोबन किया गया। टक्कालाएँ जनता के लिए बन्द

करदी गयी तथा रुपये की ढलाई का एकाधिकार सरकार ने लिया। इसके सिवा सरकार ने निम्न घोषणाएँ की —

१. सावरेन तथा अर्धसावरेन, सरकार को उनके भुगतान में १५ र० तथा ७।। की दर से दिये जा सकते थे।

२. स्वर्ण एव स्वर्ण के सिक्कों का प्रति रुपया ७ ५३३४४ ग्रेन स्वर्ण प्रथवा १ सि० ४ पेंस की दर से रुपये में परिवर्तन हो सकता था।

३. स्वर्ण एव स्वर्ण मुद्राओं के बदले उपर्युक्त दर पर पत्र-मुद्राएँ चलाने का अधिकार बम्बई तथा नल्लक्का की टकशानाओं को दे दिया गया जिससे पत्र-मुद्राओं का चलन भी हो। ये पत्र-मुद्राएँ भी स्वर्ण के बदले में १ सि० ४ पेंस प्रति रुपये की दर से ही दिय जायग।

इस प्रकार भारत में स्वर्ण एव चाँदी के सिक्कों की ढलाई जनता नहीं करा सकती थी तथा केवल चाँदी के रुपये ही धनीमन विधिप्राप्त थे।

रुपये की ढलाई का एकाधिकार अपने पास रखने में सरकार का हेतु मुद्रा बाजार में रुपये की पूर्ति कम करना था, जिससे उनका स्वर्णमूल्य बढ़ जाय और विनिमय-दर १६ पन पर स्थायी हो जाय। परन्तु सरकार का यह अनुमान गलत था क्योंकि मुद्रा-बाजार में रुपय आवश्यकता से भी अधिक थे। इससे विनिमय-दर १=२६ तक १८ पन पर न आ सकी। १=२६ में बढ़ते हुए नियात एव रुपये की अधिक मांग के कारण रुपये की विनिमय-दर बढ़ने लगी तो १=२७ में १५ पन हो गई। यही दर १=२६ में १३ पन थी।

अब चाँदी के मूल्य में रुपये में चाँदी की कमी होने हुए भी उनका मूल्य बढ़ गया जिससे सरकार को रुपये के टक्का से लाभ बढ़ गया। दूसरे, मुद्रा का प्रसार तथा महोच्च का एकमेव अधिकार सरकार को मिल गया जिससे मुद्रा-पद्धति की स्वयं कार्यशीलता गढ़ हो गई। किन्तु विनिमय-दर की स्थिरता के लिए तथा रुपय की मूल्य-वृद्धि के लिए यह आवश्यक था। इस प्रकार रुपये का मूल्य क्रमशः १=२८ में १ सि० ४ पेंस हो गया। परन्तु रुपये की कमी फिर भी बनी रही तथा व्यापारियों को असुविधाएँ होती रही।

इसलिए जनवरी १=२८ में रुपय की कमी को दूर करने के लिए १=२८ का दूसरा अधिनियम स्वीकृत किया गया। इसके अनुसार २१ जनवरी को घोषणा की गई कि भारत सरकार भारत सचिव के पास जो सोना जमा है उसके बदले में ७ ५३३४४ ग्रेन स्वर्ण प्रति रुपये की दर से पत्र-मुद्रा चलाएगी। इस घोषणा के अनुसार भारत में भुगतान के लिए रुपये के बिल क्लकता,

मदास तथा बम्बई पर भेजे जाने लगे । इसका एक उद्देश्य यह भी था कि भारत में भारतीय लेनदारों के भुगतान के लिए स्वर्ण का निर्यात न हो । किन्तु बहाना यह किया गया कि इससे भारत सरकार के मृद्-व्यय के लिए भारत-सचिव को खम मिलेगी । यह कार्य-पद्धति पहिले केवल ६ महीने के लिए ही थी, फिर इसकी अवधि दो वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी । इस प्रकार परिषद-बिल (council bills) बेचने से जो स्वर्ण भारत सचिव के पास आता था वह 'पत्र-चलन निधि' में बैंक ऑफ इङ्ग्लैंड के पास रखा जाने लगा ।

### फाउलर समिति (१८६८)

इस प्रकार विनिमय-दर में स्थिरता आ जाने के बाद (जो हंशल समिति का मूल उद्देश्य था) १८६८ में सर हेनरी फाउलर की अध्यक्षता में दूसरी समिति बनाई गई जो पहिली सिफारिशों के कार्यों का अध्ययन कर स्वर्णमान के अवलम्बन की निश्चित योजना प्रस्तुत करे तथा अभी तक अपनी राय देते हुए एक निश्चित मौद्रिक अथवा चलन नीति अपनाने में मार्ग प्रदर्शन करे । साथ ही रुपये की कमी का जो अनुभव हो रहा था उसे दूर करने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करे ।

भारत में स्वर्ण अथवा स्वर्ण मुद्राएँ विधिग्राह्य नहीं थी किन्तु सरकारी भुगतान में स्वर्ण अथवा स्वर्ण-मुद्राएँ १ शि० ४ पैसे अथवा ७ ५३३४४ ग्रेन प्रति रुपये की दर से ली जाती थी । रुपये एवं स्वर्ण में किसी प्रकार से बंधानिक सम्बन्ध न था किन्तु सरकारी घोषणा के अनुसार उक्त दर से स्वर्ण के बदले रुपये खरीदे जा सकते थे, रुपया ही भारत की एकमेव प्रमाणित एवं असीमित विधिग्राह्य मुद्रा थी । भारतीय चलन-पद्धति की यह स्थिति फाउलर समिति की नियुक्ति के समय थी । समिति के सामने तीन मुख्य बातें विचारार्थ थी —

१. भारत सरकार का वह प्रस्ताव, जिसमें कहा गया था कि भारत में रुपये की आवश्यकता से अधिक बहुलता है जिसे रुपये गलाकर चाँदी में बेच कर कम किया जा सकता है । इसमें रुपये का मूल्य १६ पैसे पर स्थिर रह सकेगा, तथा इङ्ग्लैंड में ऋण द्वारा एक स्वर्ण-निधि बनाना, जिससे रुपये को गलाकर चाँदी के रूप में बेचने से जो हानि हो उसकी पूर्ति हो सके, तथा स्वर्णमान को अपनाना ।

२. इस प्रस्ताव के अनुसार भारत में स्वर्णमान अथवा रजतमान हो तथा स्वर्ण और चाँदी के बीच क्या सम्बन्ध हो ?

३. बैंक ऑफ बंगाल के उपसचिव श्री ए० एम० लिडसे की स्वर्ण-विनिमय मान की योजना । “इस योजना के अनुसार १० करोड़ पौंड का ऋण इङ्ग्लैंड से लेकर उसे इण्डिया आफिस अथवा बैंक ऑफ इङ्ग्लैंड में जमा किया जाय । इस निधि का नाम स्वर्ण-मान-निधि हो और इसका उपयोग ‘स्वर्णमान कार्यालय’ जो सन्दन में स्थापित हो उसके द्वारा किया जाय । यह कार्यालय इङ्ग्लैंड के आयातकर्त्ताओं को रुपया-विल १५,००० रु० के ऊपर स्टर्लिंग के बदले १ सि० ४ १/४ पेंस प्रति रुपये की दर से बेचे । वे विपन्न भारतीय टकशालाओं पर अथवा दम्बई, कलकत्ता के पत्र-चलन कार्यालयों द्वारा चुकाये जायें ।”

फाउलर समिति ने इन सब प्रस्तावों पर विचार किया तथा उन्होंने रुपये के मुक्त टकण सम्बन्धी प्रस्ताव को अथवा रजतमान अपनाने के प्रस्ताव को अस्वीकृत किया । उसी प्रकार श्री लिडसे की योजना को भी ठुकरा दिया । समिति की राय थी कि लिडसे-योजना को अपनाने से भारत में विदेशी पूँजी का आना रुकेगा जिससे देश के औद्योगिक विकास को घटका लगेगा । समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं ।—

१. रुपये का विनिमय-मूल्य १ सि० ४ पेंस अथवा १५ रु० प्रति सॉवरेन हो ।

२. ब्रिटिश सॉवरेन को विधिग्राह्य चालू मुद्रा बनाया जाय तथा भारतीय टकशालाओं में स्वर्ण-मुद्रा का स्वतन्त्र टकण हो । ये स्वर्ण-मुद्राएँ रुपये के साथ-साथ १५ रुपये प्रति सॉवरेन की दर से चलन में लाई जायें, परन्तु रुपये का टकण-स्वातन्त्र्य जनता को न मिले । अर्थात् रुपया गौणमुद्रा का कार्य करे, परन्तु प्रसीमित विधिग्राह्य रहे ।

३. सरकार रुपये के टकण से होने वाला लाभ ‘स्वर्णमान-निधि’ में जमा करे । यह रुपये का १६ पेंस मूल्य स्थिर रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर विदेशी भुगतान के लिए भी उपयोग में लाई जाय ।

४. जब तक स्वर्ण जनता की आवश्यकता से अधिक न हो तब तक रुपये के नये सिक्के न ढाले जायें ।

५. सरकार उपरोक्त दर पर स्वर्ण अथवा स्वर्णमुद्राओं के बदले रुपये दिया करे परन्तु रुपये के बदले में स्वर्ण अथवा स्वर्णमुद्राएँ देने के लिए बाध्य न हो ।

इस प्रकार फाउलर समिति ने अपूर्ण द्विधातुमान पद्धति अपनाने की

सिफारिश की थी हालाँकि उसका ध्येय स्वर्ण-मुद्राओं का चलन तथा स्वर्णमान अपनाना ही था<sup>१</sup> क्योंकि इसमें दोनों ही धातुओं की मुद्राएँ प्रमाणित होती किन्तु टक्का-स्वातन्त्र्य केवल स्वर्ण को ही था। समिति का यह विश्वास था कि भारत में जब तक स्वर्णमान नहीं अपनाया जाता तब तक विनिमय-दर को स्थिर नहीं बनाया जा सकता।

भारत-नचिव ने समिति की इन सब सिफारिशों को स्वीकृत किया किन्तु उनका प्रयोग कुछ निराले दग पर ही किया गया —

१ १८६६ के भारतीय टक्का अधिनियम से सॉवरेन और प्रथमसॉवरेन १५ रु० प्रति पौण्ड की दर से भारत में विधिग्राह्य बनाये गये। स्वर्ण-टक्का के लिए नई टक्काला खोलने की सिफारिश पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि शाही टक्काला ने इसके लिए अनुमति नहीं दी। इन सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार ने कहा कि भारत में स्वर्ण की छलाई के लिए टक्काला खोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और न भारत में स्वर्ण की मुद्रा-टलाई के लिए किसी मात्रा में स्वर्ण ही मिल सकता है। इसलिए भारत सरकार को १६०२ में स्वर्ण-टक्काला सम्बन्धी अपना विचार छोड़ देना पड़ा।

२ रुपये के टक्का सम्बन्धी चौथी सिफारिश के विरुद्ध रुपये का १६०० ई० में टक्का शुरू किया गया क्योंकि सरकार जनता को स्वर्ण-मुद्राओं के उपयोग के लिए लालाचिन न कर सकी जिसने मुद्रा-भण्डारी में रुपये की कमी अनुभव होने लगी क्योंकि १८६३ से नम रुपये की टलाई बिलकुल बन्द थी। इसके साथ बढ़ते हुए व्यापार के कारण रुपये की आवश्यकता भी बड़ गई थी।

३ रुपये के टक्का लाभ से जा स्वर्णनिधि बनाया गया था उसको भारत-नचिव ने इंग्लैण्ड में रखा तथा उसका विनियोग स्टॉक एक्सचेंज प्रविधियों को खरीदने में किया गया और उनका कुछ अंश भारत में रुपये में रखा गया। साथ ही इस निधि में से १० लाख पौण्ड कीमत का स्वर्ण रेलवे के पूंजी-व्यय के लिए लिया गया, जो सब समितियों की सिफारिशों के विरुद्ध था।

४ भारतीय व्यापारिक शेष अनुकूल होने हुए भी भारत-नचिव ने रुपये विपन्नो के चित्रण द्वारा भारत में स्वर्ण नहीं धान दिया। इन सब कारणों से १६०७-०८ में अकालजन्य परिस्थिति से भारत का व्यापारिक शेष प्रतिकूल हुआ और विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण की माँग बढ़ी तब भारत

सरकार न अपनी कमबختता दिनाई। परिणामस्वरूप भारत-सचिव ने भारत में स्टर्लिङ्ग-विल अथवा उन्टी हुण्डियाँ प्रति रुपया १५ $\frac{3}{4}$  पैसे की दर से बेचने के लिए अनुमति दी। इनका भुगतान इंग्लैण्ड के व्यापारियों को भारत-सचिव द्वारा स्टर्लिङ्ग में किया गया।

इन प्रकार परिस्थितियों से विवश होकर सरकार को वही कदम उठाने पड़े जो लिसे योजना में थे। फलतः हमारी चमन पद्धति में स्वर्ण विनिमय-मान का उपयोग पूरी तरह हानि लगा। इस प्रकार फाउन्डर समिति की स्वर्ण-मान को स्वर्ण-मुद्रा-चमन के नाथ अपनाने की सिफारिश के स्थान पर रुपया-विल तथा स्टर्लिङ्ग-विलों की ऐसी पद्धति का उपयोग हुआ जिसको हम स्वर्ण-विनिमय-मान नहीं मन्ते हैं। वास्तव में हमारा रुपया देश में प्रतीक मुद्रा की भाँति था किन्तु विदेशों में वह स्वर्ण मुद्रा की भाँति था जिसका स्वर्ण-मूल्य १ लि० ४ पैसे अथवा ७५३३४४ ग्रैन् निश्चित किया गया था। स्वर्ण-मुद्राएँ चलन में नहीं थीं तथा प्रति-परिपद दिनों का भुगतान करने के लिए इंग्लैण्ड में स्वर्णमान निधि रखा था, जिसमें इंगलिस लेनदारों को स्टर्लिङ्ग में भुगतान दिया जाता था। इस पद्धति में भारत-सचिव तथा भारत सरकार दो बड़े बैंकों का कार्य करने थे और इन दोनों के हाथों हमारी चलन-पद्धति का नियन्त्रण होता था।

**स्वर्ण-विनिमय-मान की कार्य-प्रणाली ( रुपया-विल और स्टर्लिङ्ग विल )**

भारत का विदेशी व्यापार नदी अनुकूल ही रहता था किन्तु भारत को प्रति वर्ष इंग्लैण्ड को गृह-व्यय तथा उनकी पूँजी की लागत पर कुछ वार्षिक व्याज चुकाना पड़ता था। अर्थात् एक ओर तो भारत को इंग्लैण्ड से पावना हाता था तथा दूसरी ओर देना, जिसके लिए केवल दो ही मार्ग थे। एक तो भारत सरकार इंग्लैण्ड से अनुकूल व्यापारिक शेष के बक्ते खोना ले और फिर गृह-व्यय तथा व्याज के रूप में इंग्लैण्ड को स्वर्ण भेजे। इस प्रकार स्वर्ण के आयाग-निर्यात में अनेक अनुविचार्य होतीं इसलिए दूसरी पद्धति अपनाई गई जिसके अनुसार भारत में अग्रेज गृही व्यापारियों से स्टर्लिङ्ग लेकर बदले में भारत-सचिव उन्हें रुपया-विल अथवा परिपद मिल दें, जिसका भुगतान भारत सरकार भारतीय लेनदार व्यापारियों को चुकाये। इस प्रकार भारत-सचिव के पास जो रकम आती थी उसमें से भारतीय गृह-व्यय तथा व्याज की रकम निकाल कर जो शेष रहता था वह भारत सरकार के नाम, आगामी वर्षों में उपयोग के

लिए जमा किया जाता था। अब अंग्रेज व्यापारी ये परिषद-बिल अपने भारतीय लेनदारों के पास भेज देते थे जिनका भुगतान वे भारतीय कोष से अपने-अपने बैंकों की मार्फत प्राप्त करते थे। इस प्रकार दोनों के ऋणों का भुगतान परिषद-बिलों द्वारा होता था और दोष रकम जो भारत सरकार के नाम इंग्लैण्ड में जमा रहती थी उसका उपयोग भारत सरकार औद्योगिक माल की खरीद में करती थी।

किन्तु यह तब तक ठीक चलता रहा जब तक व्यापारिक दोष भारत के अनुकूल रहा। जब व्यापारिक दोष भारत के प्रतिकूल होता था तब भारतीय व्यापारी अपने अंग्रेज लेनदारों के भुगतान के लिए भारत सरकार से रुपयों के बदले स्टर्लिंग मांगते थे। भारत सरकार उन्हें स्टर्लिंग-बिल अथवा प्रति-परिषद बिल देती थी जिनका भुगतान इंग्लैण्ड में भारत-सचिव अंग्रेज व्यापारियों को करता था। जब ऐसे प्रति-परिषद बिलों की आवश्यकता भारत के व्यापारियों को होनी थी तब वे रुपयों के बदले सरकारी कोषों से अपने बैंकों की मार्फत इन्हें खरीदते थे। ये बिल वे अपने लेनदारों को इंग्लैण्ड में भेजते थे जिनके बदले भारत-सचिव इन्हें स्टर्लिंग देता था।

इस प्रकार व्यापारिक दोष की अनुकूल एवं प्रतिकूल अवस्था में इंग्लैण्ड और भारत का परस्पर भुगतान, परिषद तथा प्रति-परिषद बिलों द्वारा होता था तथा एक-दूसरे देश को स्वर्ण का आयात निर्यात नहीं करना पड़ता था।

अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत सरकार को भारत-सचिव पर प्रति-परिषद बिलों के धाहरण का अधिकार था? इसका उत्तर यह है कि रुपय के टकण से जो लाभ होता था उसको स्वर्णमान निधि में जमा किया जाता था एवं उसका उपयोग सकट काल में पाउलर समिति की सिफारिश के अनुसार हो सकता था। इसीलिए उसको इंग्लैण्ड में रखा गया था जिससे सकट काल में इस प्रकार उसका उपयोग हो सके।

यह स्वर्णमान-पद्धति सन् १९१४ तक ठीक प्रकार चलती रही किन्तु बाद में मुद्राजन्य परिस्थिति के कारण इसमें भी बाधाएँ आ गईं जिससे यह विनिमय मात पद्धति भी कारगरूप में न रह सकी।

**स्वर्ण विनिमय मान की आलोचना**

वैसे यह कार्य पद्धति बड़ी ही सरल एवं सुविधापूर्ण मालूम होती थी किन्तु वास्तव में देखने से यह भ्रमपूर्ण है। भारत-सचिव की नीति हमेशा से यही रही कि भारत में कम से कम स्वर्ण जावे इसलिए वह हमेशा ऐसे ही उपायों

की खोज में रहते थे जिससे उनकी कार्य-सिद्धि हो। इस हेतु से भारत-सचिव का इसी दशा में प्रयत्न रहा जिससे हमारे देश की कीमतें ऊँची बनी रहें तथा इङ्गलैंड से होने वाला आयात बड़े और इस कारण फाउलर समिति की सिफारिशों के विरुद्ध उक्त कार्यवाही की गई।

(१) इस पद्धति के विरुद्ध प्रथम आक्षेप यह है कि भारत-सचिव ने स्वर्ण का निर्यात जो हमारे देश में होना उने नहीं होने दिया। हमारा व्यापार-व्यय सदैव ही हमारे अनुभूत रहता था क्योंकि जितने रुपये का आयात होता था उससे निर्यात अधिक था इसलिए इस आधिक्य के मूल्य का स्वर्ण हमारे देश में आता। किन्तु जब १८६८ के बाद यह बात भारत-सचिव के ध्यान में आई तब उसने कहा कि भारत सरकार से इङ्गलैंड को गृह-व्यय तथा व्याज के रूप में रुपये लेना है जो हम यही पर (इङ्गलैंड में) स्टर्लिंग-बिल बेचकर रख लिया करेंगे तथा जो अधिक रकम आयेगी वह भारत सरकार के नायक जमा कर देंगे। इस प्रकार भारत में स्वर्ण का आयात नहीं होने दिया। खैर, जहाँ तक एक-दूसरे के भुगतान का सम्बन्ध था यह ठीक है, परन्तु जो रकम हमारे गृह-व्यय आदि से अधिक होती थी वह तो हमारे यहाँ स्वर्ण में आनी चाहिए थी किन्तु भारत-सचिव ने उसे यहाँ नहीं आने दिया और कहा कि यदि यह स्वर्ण भारत की जाता है तो वह या तो भूमिगत हो जायगा या उसके गहने बनाये जायेंगे जिससे वह भारत सरकार के काम में आ सकेगा तथा जब चाँदी और रेलवे के लिए सामान आदि इङ्गलैंड में खरीदा जायगा तब उसके काम में न आ सकेगा। इसलिए इस अतिरिक्त स्वर्ण का भी इङ्गलैंड में रखना ही उचित है। किन्तु यह युक्ति-प्रवाद सर्वथा सही नहीं है क्योंकि इस बात में भारत में स्वर्ण की चाह होने लगी थी और यदि चाह नहीं भी थी और यह स्वर्ण यदि भूमिगत भी हो जाता तो भी भारत-सचिव को क्या आवश्यकता थी कि वह भारत सरकार की अनधिकार उपदेस करे? यह विषय तो केवल भारत सरकार का था।

(२) रुपये के टक्का से होने वाले लाभ से स्वर्ण निधि बनाया गया था जो समिति की सिफारिश के अनुसार भारत में ही रहना चाहिए था। क्या अधिकार था भारत-सचिव को कि वह उसका स्थानान्तरण इङ्गलैंड में करे? यदि यह स्वर्ण भारत में रहता तो भारत सरकार के काम में आ सकता था अथवा हमारे उद्योग धन्धों की उन्नति के लिए काम आता। किन्तु उसे इङ्गलैंड में रखने में तो भारत सरकार को सर्वथा भारत-सचिव पर ही निर्भर होना पड़ा।

(३) इस निधि को स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ खरीदने के लिए उपयोग में लाया

गया तथा इंग्लैंड के उद्योगपतियों को मृण के रूप में कम व्याज पर दिया गया जिससे वहाँ के उद्योगों की तो उत्तति हुई किन्तु हमारे यहाँ उत्तति न हो सकी। इसका उत्तर यह दिया गया कि यदि यह निधि इंग्लैंड में न रहता तो भारत सरकार व्यापारिक शेष की प्रतिपूर्ति के लिये भारत सचिव पर प्रति परिपद विन नहीं देच सकती थी और अग्रेय ग्राहकों को भुगतान करने के लिए उसे अमुविधा होती। किन्तु क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि भारत सरकार को ऐसे समय में कुछ पौंडों का भुगतान करने के लिए भारत सचिव सहायक होता अथवा बैंक ऑफ इंग्लैंड से अपनी जिम्मेदारी पर भारत सरकार को पौंड उधार दिलवा सकता? परन्तु यह सब न हुआ और न किया गया।

स्वण विनिमय-भान की स्थापना क २ वर्ष बाद १९०३ में विनिमय दर गिरने लगी और १ जि० ४ पस से कम हो गई तथा भारतीय व्यापारिक शेष भी हमारे प्रतिफल हुआ जिसके लिए दो कारण प्रमुख थे — एक तो भारत में अनावृष्टि एक अकाल और दूसरे विश्व की मोद्रिक वसा तथा इसी समय में हान बाग अमेरिका का आर्थिक मन्द। इसलिए स्वस प्रथम भारतीय व्यापारियों ने भारत सरकार से विदेशी विनिमय की बड़ी मात्रा में माग की। परन्तु इस मांग की पूर्ति करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में न तो स्वर्ण ही था और न वह दे सकती थी। इस पूर्ति के लिए व्यापारियों ने प्रति परिपद विल भी मागे किन्तु भारत सचिव ने उसके लिए भी अनुमति नहीं दी जिससे दो बातें स्पष्ट होती हैं — एक तो निश्चित नीति का अभाव और दूसरा भारतीय व्यापार एवं व्यापारियों की भलाई की ओर पूर्ण अन्याय। प्रथम स्वण निधि इंग्लैंड में इसीलिए रखा गया था कि जब विनिमय दर गिरने लगे तो वहाँ से प्रति परिपद विल का भुगतान भारत सचिव द्वारा किया जाय किन्तु ऐसा न होने से प्रतिफल विनिमय दर होने के कारण भारतीय व्यापार कर्तव्यों की बहुत भारी हानि हुई और सरकार की नीति की बुरी तरह आलोचना होने लगी। इसलिए पहिले तो भारत सरकार ने विदेशी भुगतान के लिए पत्र चलान निधि से स्वण निवाल कर देचना शुरू किया ताकि विनिमय दर न गिरे। परन्तु परिस्थिति बिगड़ती गई जिससे विनिमय दर भी गिरती गई। इसके फलस्वरूप २६ मार्च १९०८ को इस प्रकार के प्रति परिपद विल चलान की अनुमति दी गई तथा वे विल भारतीय व्यापारिक कर्तव्यों को १ जि० ३ ३/४ पस प्रति रुपये की दर से विक्रय लगे। इस समय स्वण निधि ४०० लाख पौंड में अधिक हो गया था जिसमें से ३०० लाख पौंड में अधिक भारत-सचिव द्वारा

इंग्लैंड के उद्योगों में लगाया गया था जो स्वयं प्रति-परिपद-विलो के भुगतान के लिए उनमें नहीं ली जा सकती थी और यही वास्तविक कारण था जिसके लिए स्वर्ण-निधि इंग्लैंड में रखा गया था। इन प्रकार जो स्वर्ण निधि फाइनर समिति ने भारतीय हिन के लिए बनाया था उसको इंग्लैंड में रखकर अंग्रेजी व्यापार एवं उद्योगों की उन्नति के नाम में लाया गया तथा इसके भारत-सचिव ने ध्यान रखा जो नष्ट काल में भारत के काम में आ सके।

### १९१३ के दाद

इन आलोचकों में से कुछ तो दृष्टान्तों को खोल देने के पक्ष में थे तथा कुछ परिपद-विलो की धनीमिन विलो के विरुद्ध थे। किन्तु विनिमय-दर की स्थिरता तथा भारतीय व्यापारिक रोप में १९०० के दाद अनुकूलता आने के कारण आलोचकों की आवाज पर विशेष ध्यान न दिया गया क्योंकि विनिमय-दर प्रति रुपया १ दि० ४ पम पर स्थिर हो गई थी। फिर भी कुछ लोगों ने सामूहिक रूप में लन्दन के भारत कार्यालय की भारत के प्रति जानकीय नीति को बड़ी आलोचना की जो मुख्यतः निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में थी —

१ स्वर्ण-निधि को भारत में रखने के बदले उत्तका उपयोग इंग्लैंड में स्टैलिग प्रतिभूतियों के विनियोग में किया जाना,

२ स्वर्ण-निधि में से रेलवे-व्यय के लिए स्वर्ण का विनियोग करना,

३ रुपया को टक्का-मुविधा के बढ़ाने स्वर्ण-निधि का कुछ भाग चाँदी में रखा जाना

४ पत्र-चलन निधि का कुछ भाग भारत में दण्डों में स्थानान्तरित करना तथा

५ भारत को स्वर्ण-निर्यात न हो इन दृष्टि के परिपद-विलो का ऐसी दर पर धनीमिन विज्ञापन करना, जिसके कारण भारत में रुपया ही केवल चलन में रहे जो अग्रिम माना में हो तथा जिसमें भारतीय कीमतें ऊँची बनी रहें।

### चेम्बरलेन समिति (१९१३)

उक्त नीति के परिणामस्वरूप भारत से १८९८ में १९१३ तक ७०० लाख पाँउ से अधिक स्वर्ण इंग्लैंड में जा चुका था जो कि इंग्लैंड में कम व्यापार पर अंग्रेजी बैंकों एवं व्यापारियों को ऋण के रूप में दिया जाता था और दूसरी ओर भारत में मुद्रा की कमी रहती थी। इन आलोचनाओं को और अधिक काल तक दुर्लक्ष किया जाना भारत सरकार को अनन्त-सा प्रतीत होने

लगा। अतः १९१३ में सर मॉस्टिन चेम्बरलेन की अध्यक्षता में एक नई समिति नियुक्त की गई। इस समिति के सामने निम्न बातें विचारार्थ रखी गई थी —

१. भारत सरकार के सामान्य शेषों के स्थान एवं व्यवस्था सम्बन्धी जाँच,

२. पाउण्डर समिति की सिफारिशों के बाद रुपये की विनिमय-दर स्थिर रखने के लिए भारत सरकार एवं भारत-सचिव ने जो उपाय किये उनकी और विशेषतः स्वर्ण-निधि एवं पत्र-चलन-निधि के स्थान और उपयोग की जाँच तथा जो पद्धति १८९८ के बाद काम में लाई गई वह भारत के लिए लाभदायक थी अथवा नहीं इस सम्बन्ध में सिफारिश करना, तथा

३. अन्य बातें।<sup>१</sup>

समिति की सिफारिशों की मुख्य बात सारांश रूप में निम्नलिखित है—

१. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब यह निश्चित हो जाना चाहिए कि भारतीय चलन-पद्धति का लक्ष्य क्या है। १८९८ की समिति की सिफारिश के अनुसार स्वर्णमान की यथास्थिता के लिए स्वर्ण-चलन आवश्यक है। परन्तु पिछले १५ वर्षों के इतिहास से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वर्ण-चलन के बिना स्वर्णमान की स्थापना हो गई है।

२. इसलिए देश में स्वर्ण-चलन को प्रोत्साहन देना भारत के लिए हितकर न होगा और इसलिए स्वर्ण-टंकशाला की भी कोई आवश्यकता नहीं है।

३. देश के चलन की पुष्टि के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण और स्टलिंग रहना चाहिए जिससे विदेशी विनिमय में सुविधा होगी।

४. इस समय स्वर्णमान निधि के लिए निश्चित सीमा नहीं लगाई जा सकती किन्तु रुपये के टंकण में जो लाभ हो वह सब टम निधि में जमा किया जाय। किन्तु इस निधि में अभी स्वर्ण की अधिक आवश्यकता है जो १५० लाख पाँड तक हो, इसके बाद आधा निधि स्वर्ण में रखा जाय।

५. यह स्वर्णमान निधि इङ्ग्लैण्ड में ही रखा जाय तथा सरकार यह जिम्मेदारी ले कि स्टलिंग की माँग बढ़ने पर वह भारत-सचिव पर १५३½ पैन प्रति रुपये की दर से प्रति-परिपद-वित्त बेचे।

६. भारतीय पत्र-चलन अधिक मोचदार बनाया जाय।

७. स्वर्णमान की रजत-शाखा का अन्त किया जाय और उसकी सम्पूर्ण राशि इङ्ग्लैण्ड में रखी जाय।

८ भारत कार्यालय की राजस्व-समिति में दो भारतीय सभासद हों ।

उन्होंने यह भी कहा कि रुपये के विनिमय मूल्य में स्थिरता रहना भारत के लिए अति आवश्यक है । इसलिए जो मार्ग अपनाय गये वे १८६८ की समिति की सिफारिशों के खिलाफ होते हुए भी आवश्यक थे जिन्होंने १६०७-०८ के सत्र में अपनी सफलता का परिचय दिया ।

इन सिफारिशों से स्पष्ट है कि समिति ने स्वर्ण विनिमय-मान की गत १५ वर्षों की कार्य प्रणाली पर स्वीकृति की मोहर लगा दी । इस समिति ने अपनी रिपोर्ट २४ फरवरी १६१४ को पेश की जो कि सरकार के विचाराधीन थी । इसी समय १६१४ में प्रथम विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ तथा भारत और इंग्लैण्ड के सामने नई-नई एव जटिल जटिल समस्याएँ उपस्थित हुईं । फलतः समिति की सिफारिशों पर कोई वायबाही न हो सकी ।

### सारांश

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने जब भारत का शासन संभाला तब भारत में सोने तथा चांदी के ६६४ सिक्के थे जिनका परिवर्तन शुद्धता के अनुसार सराफ करते थे । इस कठिनाई को दूर करने के लिए १८१८ में मद्रास में स्वर्ण तथा चांदी के नये सिक्के चलाये गये । १८३५ में १७० ग्रैन का ३६ शुद्धता वाला चांदी का रुपया भारत में वैधानिक प्रमाणित सिक्का घोषित किया गया । इस प्रकार १८३५ में भारत में रजत प्रमाण को अपनाया गया जो १८७१ तक ठीक कार्य करता रहा । इसके बाद विश्व की परिस्थिति के कारण रुपये का स्वर्ण मूल्य जो १८७१ में २ शि० प्रति रुपया था वह गिरकर १८६२ में १ शि० २ पेंस रह गया । इसके निम्न कारण थे —

(१) १८४८ में प्रायः आस्ट्रेलिया और कैलिफोर्निया की स्वर्ण खानों से स्वर्ण मिलना बन्द होना ।

(२) नेवादा (अमेरिका) की नई रजत खानों से चांदी की पूर्ति बढ़ना ।

(३) १८७०-७१ में जर्मनी की फ्रांस पर जीत के कारण जर्मनी ने स्वर्ण प्रमाण अपनाकर रजत प्रमाण का त्याग किया ।

(४) शीने (Lead) से चांदी का निकलना ।

(५) अमेरिका के शेरमन एक्ट में संशोधन ।

इससे भारत सरकार को हानि होने लगी क्योंकि रुपये का स्वर्ण मूल्य गिरने से—

(१) भारत सरकार को गृह-व्यय के लिए इङ्ग्लैण्ड को अधिक रुपये देने पड़ते थे इस हेतु प्रति वर्ष कर बढ़ाना असम्भव था ।

(२) भारतीय आयात कम हो गये और निर्यात बढ़ने लगे जो विदेशी व्यापारियों को खटवने लगा । विनिमय-दर की अनिश्चितता के कारण व्यापार भी अनिश्चितता का गई,

(३) भारत में ब्रिटिश पूँजी का आयात रुक गया ।

(४) भारत में जो अग्रज नौकर ने उन्होंने बेंतन वृद्धि की माँगी ।

(५) विदेशी पूँजी न आने से औद्योगिक विकास रुक गया ।

इस स्थिति को सुलभाने के लिए १८६२ में हर्शल समिति की नियुक्ति हुई जिसने निम्न सिफारिशों को—

(१) रुपये का स्वतंत्र टकरा न रहे किन्तु वह गंसीमित वैधानिक ग्राह्य रहे ।

(२) स्वर्ण मुद्राएँ सरकारी सजाने में १ शि० ४ पें० की दर पर ली जायें । इसको स्वीकार किया गया तथा १८६३ के टकरा-अधिनियम के अनुसार देश में अपूर्ण द्विधातुमान अपनाया गया ।

फलस्वरूप मुद्रामंडी में रुपये की कमी होने लगी । इस स्थिति पर विचार करने एवं सुभाव देने के लिए १८६७ में फाउलर समिति की नियुक्ति हुई । इस समिति के सामने तीन प्रस्ताव विचारार्थ थे परन्तु समिति ने उनको ठुकरा दिया और सिफारिशों की जि—

(१) देश में स्वर्ण मुद्राएँ चलवाई जायें जिनकी स्वतंत्र ढलाई हो ।

(२) चाँदी की मुद्रा अस्सीमित विधिग्राह्य रहे ।

(३) विनिमय-दर १ शि० ४ पें० निश्चित की जाय तथा इस दर पर भारत सरकार स्वर्ण के बदले रुपये देने के लिए बाध्य रहे परन्तु रुपये के बदले स्वर्ण देने के लिए बाध्य न हो ।

(४) रुपये की ढलाई सरकार तब तक न करे जब तक स्वर्ण जनता की आवश्यकता से अधिक न हो । ऐसी ढलाई से होने वाला लाभ 'स्वर्णनिधि' में भारत में जमा किया जाय ।

सरकार ने इन सिफारिशों को मान लिया तथा १८६६ के टकरा-अधिनियम द्वारा रुपये की विनिमय दर १ शि० ६ पें० निश्चित की गई । परन्तु इन पर कार्यवाही निराले ढग से हुई जिससे १९०७ में स्वर्णमान के स्थान पर स्वर्ण विनिमय-मान की स्थापना हो गई ।

परन्तु १९०८ में परिस्थिति ने कुछ ऐसी करवट ली कि इस पद्धति के विरुद्ध आलोचनाएँ होने लगी और भारत सरकार और भारत-सचिव में गति-अवरोध हो गया। फलतः १९१३ में चेम्बरलेन समिति की नियुक्ति की गई। समिति ने निम्न प्रमुख सिफारिशें कीं—

(१) देश में स्वर्ण-दिनमय मान ही हो।

(२) स्वर्ण-मुद्राओं का टकस भारत में न हो।

(३) स्वर्णनिधि की कोई निश्चित सीमा न हो तथा इसे इंग्लैण्ड में ही रखा जाय।

(४) स्टैलिंग की भाग छाने पर सरकार विनिमय-दर की स्थिरता के लिए प्रति-परिषद-वित्त १५,३६८ पौंस प्रति रुपये की दर में बंधे।

(५) भारतीय पत्र चलन अविन लॉघदार बनाया जाय।

इस प्रकार चेम्बरलेन समिति ने सरकार द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली पर स्वीकृति की मुहर लगा दी। ये सिफारिशें सरकार के सामने विचारार्थ थीं कि प्रथम विश्व युद्ध आरम्भ हो गया और इन पर कोई कायदाही न हो सनी।

## अध्याय १३

# भारतीय चलन का इतिहास (२)

(१९१४ से १९३६ तक)

### युद्ध-काल

युद्ध के आधार तो पहिले से ही स्पष्ट होने लगे थे जिससे उस समय परिस्थिति को काबू में रखने के लिए भारत सरकार एवं भारत-सचिव ने उपाय सोच रहे थे। ऐसी अवस्था में वे विनिमय-दर को स्थिर रखने के लिए परिपद एवं प्रति-परिपद-विल बेचने को तत्पर थे। ४ अगस्त १९१४ को इङ्ग्लैण्ड में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध का ऐलान किया तो एकदम विनिमय-दर में गिरावट दिखाई दी क्योंकि इङ्ग्लैण्ड उस समय मौद्रिक जगत में एक साहूकार देश था और वहाँ के लोगो ने अपने ऋणों का भुगतान दूसरे देशों से माँगना शुरू किया।

प्रारम्भ में हमारे व्यापार को घक्का लगा और व्यापारिक शिथिलता आ गई, विनिमय-दर में भी कमजोरी आई तथा भारतीय जनता ने अपनी-अपनी जमा रकमे (deposits) बैंको से निवालना शुरू किया, पत्र-मुद्रा को भी लोग परिवर्तित कराने लगे तथा स्वर्ण की चाहने लगे। इस कमजोरी को दूर करने के लिए भारतीय डाकखानो ने जमा रकमे फौरन ही वापिस कीं, पत्र-मुद्राओं का परिवर्तन भी चासू रखा तथा विनिमय-दर की कमजोरी को दूर करने के लिए प्रति-परिपद-विल भी बेचना आरम्भ किया। पहिले दो महीने में ही करीब ६ करोड़ रुपये की जमा रकमे निकाली गई और ३१ जुलाई १९१४ से मार्च १९१५ तक लगभग १० करोड़ रुपये की पत्र-मुद्राओं का परिवर्तन हुआ तथा इस परिमाण में पत्र-मुद्रा-चलन कम हो गया। इसी के साथ ६ अगस्त १९१४ से २८ जनवरी १९१५ तक ८७,०७,००० पाँड के प्रति-परिपद-विलो का भारत में विक्रय हुआ। पत्र-मुद्रा के बढ़ते स्वर्ण की माँग बढ़ती ही गई और केवल १ अगस्त १९१४ से ४ अगस्त १९१४ तक १८ लाख पाँड मूल्य के स्वर्ण की हानि हुई जिसके कारण १ अगस्त १९१४ से स्वर्ण का नोटो के

मदले देना भारत सरकार ने बन्द नर दिया<sup>१</sup> और चाँदी के रुपये देने लगी ।

इसके बाद स्थिति सुधरने लगी और जनता को हमारी चलन पद्धति में विश्वास हो आया जिससे इस संकट का सामना सफलता से हो सका ।

स्वर्ण विनिमय का अन्त—परन्तु १९१६ के अन्तिम महीनों में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई वह अच्छे-बच्छे राजनीतिज्ञों के लिए भी कल्पनातीत थी । विनिमय-दर कुछ महीनों तक कमजोर रहने के बाद ठीक होने लगी और युद्ध के ६ महीने बाद ही काफी मजबूत हो गई, जिसके अनेक कारण थे —

१. इङ्गलैंड तथा दूसरे यूरोपीय देश जो माल भारत में युद्धपूर्व भेजते थे वह अब नहीं भेज सकते थे । फलस्वरूप हमारा व्यापार कम हो गया था । दूसरी ओर मित्रराष्ट्रों को अच्छा माल तथा धान्यादि की आवश्यकता के लिए भारत से माल भेजना पड़ता था । अतः हमारे निर्यात बढ़ गये और व्यापारिक शेष हमारे अनुकूल हुआ । इससे हमारे रुपये की माँग विदेशों में बढ़ी ।

२. इङ्गलैंड की ओर से भुगतान करने की जिम्मेवारी भी भारत सरकार पर आई और इस प्रकार का भुगतान १९१४ से १९१९ तक कुल २४०० लाख पाँड का किया गया । इसके अतिरिक्त अन्य युद्ध सामग्री का भी बहुत परिमाण में क्रय करने की जिम्मेवारी भारत सरकार पर थी । इससे भारत सरकार को इङ्गलैंड से अधिक पावना हो गया अर्थात् हमारा खाना-पेय हमारे अनुकूल था जिससे रुपये की माँग बढ़ गई थी ।

३. भारत में पत्र-चलन अधिक हो जाने से, तथा अच्छे माल की माँग बढ़ जाने से हमारी कीमतें उँची हो गई, जिससे हमारा निर्यात वस्तुओं में अधिक न बढ़ने हुए भी निर्यात का मूल्य बढ़ गया । इसका प्रभाव भी भुगतान शेष हमारे अनुकूल होने में रहा । इन दोनों कारणों से हमारी मुद्रा की माँग बढ़ती गई ।

४. इन सब का भुगतान करने के लिए भारत-सचिव से अधिकाधिक परिपक्वित माँगे जाने लगे और उनका भुगतान भारत में करने के लिए अधिकारिक रूपों की आवश्यकता थी । इसलिए भारत-सचिव को भारत सरकार की ओर से रूपों के टक्का के लिए बड़ी मात्रा में चाँदी खरीदने की आवश्यकता हुई । इससे चाँदी का मूल्य बढ़ने लगा । चाँदी का मूल्य बढ़ने से भारत सरकार का रूपों के टक्का से होने वाला लाभ कम होता गया ।

<sup>१</sup> *Indian Currency, Banking and Exchange by Chhabalani, p. 91.*

५. इसके सिवा चाँदी का मूल्य बढ़ाने के लिए अन्य परिस्थिति भी कारण हुई।

स्वर्ण एवं चाँदी के आयात में साधारण स्थिति में भारतीय अनुकूल व्यापारिक शेष का सन्तुलन हो जाता था किन्तु युद्धजन्य स्थिति के कारण इन धातुओं का आयात न हो सका क्योंकि—

१. स्वर्ण को प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयाँ प्रतीत होनी लगी क्योंकि अभी तक इङ्ग्लैण्ड में स्वर्ण बाजार खुला होने से स्वर्ण प्राप्त करने के लिए भारत को कोई कठिनाई न थी किन्तु स्वर्ण के निर्यात पर प्रतिबन्ध लग जाने से अब यहाँ से स्वर्ण प्राप्त करना सम्भव न था।

२. अन्य राष्ट्रों ने भी अपने स्वर्ण सचय को युद्धोपभोग के लिए रखने के लिए स्वर्ण-निर्यात पर रोक लगा दी। १९१७-१८ में कुछ स्वर्ण भारत में अवश्य आया लेकिन उस समय विनिमय-बाजार में रुपयों की कमी के कारण अमेरिका तथा जापान को स्वर्ण भेजकर ही अपना काम करना पड़ा। स्वर्ण न मिलने के कारण चाँदी के लिए माँग बढ़ गई, जो १९१७ तक अनियन्त्रित रही।

३. विभिन्न देशों की केन्द्रीय बैंकों को अपने-अपने कानून के अनुसार अपने निधि का कुछ भाग चाँदी में रखना पड़ता था, सामान्य परिस्थिति में यह न रखा गया। किन्तु युद्ध-काल में अपनी परिस्थिति की मजबूती के लिए प्रत्येक बैंक अपने निधि में चाँदी दिखाने की कोशिश करने लगा और चाँदी खरीदने लगा, जिससे चाँदी के लिए माँग बढ़ गई।

४. १९१४ से १९१७ तक चीन चाँदी को बेचता था, किन्तु अब उसने भी चाँदी खरीदना शुरू किया क्योंकि यहाँ के दो बड़े-बड़े प्रान्तों ने चाँदी को मौद्रिक धातु के रूप में ग्रहण किया। फलतः चाँदी की माँग और भी बढ़ गई।

५. जहाँ एक ओर चाँदी के लिए माँग बढ़ रही थी, दूसरी ओर चाँदी का उत्पादन कम हो रहा था क्योंकि ब्रिनाडा की कोबाल्ट की खानों से चाँदी कम निकलती थी। इसी प्रकार चाँदी के बड़ा उत्पादक मैक्सिको में गृह युद्ध के कारण चाँदी की खानों का उत्पादन भी बन्द हो गया, जिससे चाँदी की विश्वपूर्ति प्रभावित हुई।

इन कारणों से चाँदी का मूल्य बढ़ता ही गया तथा भारत सरकार का रुपयों के टक्का से अब कोई लाभ न रहा। साथ ही विनिमय-दर १ शि० ४ पेंस पर स्थिर रखना असम्भव हो गया तथा विनिमय-दर का अपना मार्ग

लेने के लिए मुक्त छोड़ दिया गया। अतः विनिमय दर चादा के मूल्य के साथ तर्जो से वृद्धि होगी। उसकी वृद्धि निम्न प्रकार हुई —

वर्ष	चादी का मूल्य	विनिमय दर
१९१५	२७½ पेंस प्रति औंस	१६ पम प्रात रुपया
१९१६ अप्रैल	५½	१६
१९१६ दिसम्बर	७	१८
१९१७ अगस्त	४३	१७
१९१७ सितम्बर	५५	१७
१९१८ मई	५८	२०
१९१९ १७ दिसम्बर	७८	२८

### युद्धकालीन सरकारी प्रयत्न

इस परिस्थिति का वास्तविक मूल्य की दृष्टि से भारत सरकार ने निम्न प्रयत्न किये —

(१) चादा के व्यक्तिगत आयात पर प्रतिबंध लगा दिया जिससे चादा का भाग का प्रभाव कुछ कम हो और भारत सरकार ने अमेरिका से चादी खरीदने का फैसला किया। इस फैसले से भारत में पत्र मुद्रा का रूपों में परिवर्तनमानता रूढ़ि में बड़ा सहायता मिला अन्यथा यहाँ पर भी सकटमय स्थिति हो जाता तथा हमारा मौद्रिक टांचा नस्तनावृद्ध हो जाता।

(२) चादा तथा सान की मुद्राभा को गिरावट से रोकने के लिए अथवा अन्य उपयोग से रोकने के लिए २६ जून १९१७ से चादा तथा सान के सिक्के गलाना अथवा मुद्रा के अतिरिक्त उनका उपयोग करना अवैधानिक घोषित किया गया।

(३) चादा की मितव्ययिता की दृष्टि से २॥) २० तथा १ रु० की पत्र मुद्राएँ बनाई गई तथा १ अप्रैल १९१८ से निकेल की दुधनिया आदि चलाई गई। इनको सितम्बर १९१८ से विधान द्वारा स्वीकृत किया गया लेकिन ये केवल १ रुपय तक ही विधिबद्ध थी।

(४) रुपया का भारत में कमी होने से भारत सचिव ने परिपद बिलों की बिक्री भा लुगित कर दा तथा ये केवल कुछ ऐसे व्यापारियों को देने जाने थे जो केवल युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री का आयात करते थे। अर्थात् विनिमय नियंत्रण लगाया गया।

(५) १९१७ में जब चांदी का मूल्य ४३ पेंस प्रति औंस हो गया तब भारत सरकार को रुपये के ढालने से कोई लाभ न रहा अतः १९१७ में विनिमय-दर १७ पेंस प्रति रुपया कर दी गई। परन्तु जब इससे भी काम न चला तब भारत-सचिव ने घोषणा की कि रुपये की विनिमय-दर चांदी के स्टर्लिंग मूल्य पर आधारित कर दी गई है जिससे चांदी का स्टर्लिंग मूल्य जैसे-जैसे बढ़ता गया वैसे-वैसे रुपये की विनिमय-दर भी बढ़ती गई।<sup>१</sup>

(६) चांदी की कमी को दूर करने के लिए स्वर्ण को प्राप्त कर उसका उपयोग भी भारत सरकार को करना पड़ा। स्वर्ण की प्राप्ति के लिए १९१७ में एक अध्यादेश निवाला गया जिसके अनुसार सरकार भारत में होने वाला स्वर्ण का आयात रुपये के स्टर्लिंग मूल्य की दर में खरीद लेती थी, जो पत्र-चलन-निधि में पत्र-मुद्रा के चलन के अधिक प्रसार के हेतु सुरक्षा के लिए रखा जाता था।

(७) १९१८ में मौद्रिक कमी को दूर करने के लिए इस सोने से १५ करोड़ मूल्य की स्वर्ण मोहरें भी ढाली जाने लगी जिसके लिए शाही टंक-शाला की एक शाखा बम्बई में स्थापित की गई जो अप्रैल १९१९ में बन्द कर दी गई। इसमें मोहरें और सौवरेन मिलाकर कुल ३४,०५,००० स्वर्ण-मुद्राएँ ढाली गई थी।

(८) परिपक्व-बिलों के भुगतान के लिए भारत में अधिकाधिक पत्र-मुद्रा का प्रसार होने लगा तथा अरक्षित पत्र-चलन की मर्यादा १४ करोड़ में बढ़ते-बढ़ते १२० करोड़ हो गई थी। ये नोट परिवर्तनशील थे और इनका रुपये में परिवर्तन भी होता रहा किन्तु शासकीय कठिनाइयों की वजह से १९१६ में पत्र-मुद्रा का परिवर्तन भी मर्यादित कर दिया गया। इससे कई जगह पत्र-मुद्रा बढ़ने से भी बँची गई। इस प्रकार मार्च १९१४ में जहाँ ६६\*१२ लाख रुपये की पत्र-मुद्राएँ चलन में थी वहाँ नवम्बर १९१९ में १७९६७ लाख रुपये की पत्र-मुद्राओं का चलन हो गया।

(९) साथ ही सरकार ने अपने कम खर्च करने तथा नये-नये करो द्वारा एवं जनता से ऋण लेकर अपनी आय बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किये जिनमें सरकारी मौद्रिक आवश्यकताएँ पूरी होती रहे।

१९१७ से विनिमय-दर क्रमशः बढ़ती गई जिसका हमारे व्यापार पर क्या

<sup>१</sup> देखिए तालिका पृष्ठ १७७।

प्रभाव हुआ, यह देखना है। सामान्यतः विनिमय-दर की वृद्धि से आयात बढ़ते हैं तथा निर्यात कम होते हैं। किन्तु हमारे यहाँ के कृषिजन्य पदार्थों की माँग बढ़ती हुई कीमतों के होते हुए भी युद्ध के कारण अधिक ही रही और निर्यात-व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। फलतः हमारा व्यापारिक शेष युद्ध के अन्तिम तीन वर्षों में अनुकूल हो रहा। इसके भुगतान के लिए भारत-सचिव परिषद्-विन वेचते थे और उनका भुगतान भारत में रुपये तथा पत्र मुद्राओं में होता था। इसलिए हमारे यहाँ की टक्कालाओं में दिन-रात रुपये ढलते थे और पत्र-मुद्रा का प्रसार भी बहुत बढ़ चुका था और उसकी परिवर्तनशीलता भी मर्यादित कर दी गई थी क्योंकि जो रुपये हमारे किसानों के हाथ पड़ते थे उनके पास तो वे गहने बनवाते थे या उन्हें भूमिगत करते थे। इस कारण भारत सरकार को अनेक कठिनाइयाँ प्रतीत होने लगी और हमारी चलन-पद्धति पूर्णतया विचलित होने को ही थी कि भारत के मौभाम्य में १९१८ में युद्ध-समाप्ति की घोषणा कर दी गई। फलतः अमेरिका, आस्ट्रेलिया, इङ्गलैण्ड आदि युद्धग्रस्त देशों ने स्वर्ण-निर्यात से प्रतिबन्ध उठा लिये तथा भारत में स्वर्ण आने लगा और हमारा आर्थिक ढाँचा टूटने से बच गया।

### युद्धोपरान्त

बैंकिंगटन स्मिथ समिति—युद्ध समाप्त होते ही विनिमय-दर को स्थिर बनाने के लिए ३० मार्च १९१९ की बैंकिंगटन स्मिथ समिति की नियुक्ति की गई। इस समिति का कार्य था —

भारतीय चलन तथा विनिमय-पद्धति पर युद्ध का प्रभाव आकना,

भारतीय पत्र-चलन की परिस्थिति देखना,

भारतीय व्यापार की आवश्यकतानुसार चलन में हेर-फेर की सिफारिश करना, तथा

स्वर्ण-विनिमय-मान की स्थिरता के लिए भुक्ताव रखना। इस कार्य की मर्यादा में ही उन्होंने स्वर्ण-विनिमय-मान को स्थायी रखने के लिए फरवरी १९२० में अपनी रिपोर्ट में निम्न सिफारिश की —

१. स्वर्ण की विनिमय-दर २४ ग्रेन स्वर्ण हो, न कि २५ ग्रेन स्टर्लिंग, क्योंकि इस काल में स्टर्लिंग, जो इङ्गलैण्ड की पत्र-मुद्रा थी, उसका स्वर्ण-मूल्य गिर रहा था। इस दर से साँवरेन की कीमत पहिले की अपेक्षा ५ रुपये घट कर १० रुपये होती। एसा करने का एकमात्र कारण यही बताया गया कि स्टर्लिंग का स्वर्ण-मूल्य कितना गिरेगा यह निश्चित नहीं है और भारतीय मुद्रा के

विनिमय मूल्य की स्थिरता के लिए यह आवश्यक है कि उसका सम्बन्ध किसी ऐसी वस्तु से जोड़ा जाय जिसका मूल्य स्थायी हो और ऐसी वस्तु केवल स्वर्ण ही है। इस प्रकार विनिमय-दर की स्थिरता के लिए यह सम्बन्ध जोड़ा गया। इस प्रकार रुपये का स्वर्ण-मूल्य ११ ३०००१६ ग्रेन होता है।

२ भारतीय चनन की कार्य-पद्धति स्वयंपूर्ण ( automatic ) बनाई जाय।

३. सरकार पर रुपये का परिवर्तन साँवरेन में करने की जिम्मेदारी न रहे।

४ स्वर्ण के आयात-निर्यात में प्रतिबन्ध हटा लिये जायें।

५ चाँदी के आयात से प्रतिबन्ध हटा लिया जाय तथा आयात-कर भी, किन्तु चाँदी के निर्यात पर कुछ समय के लिए प्रतिबन्ध रहें।

६ विनिमय की कमजोरी की दशा में व्यापारिक माँग की पूर्ति के लिए प्रति-परिपद-बिल बेचे जायें।

७ स्वर्ण-मान-निधि की राशि के लिए सीमा न हो और इस निधि का पर्याप्त भाग विनियोग किया जाय।

८ पत्र-चलन पद्धति अधिक लोचदार बनाई जाय तथा किसी प्रकार उसकी परिवर्तनशीलता रक्षी जाय।

९ मौसमी माँग की पूर्ति के लिए निर्यात-बिलों के आधार पर ५ करोड़ रुपये की अधिक पत्र-मुद्रा चलाई जाय।

१०. भारत सरकार भारत-सचिव की पूर्व अनुमति के बिना साप्ताहिक प्रति-परिपद-बिलों की बिक्री की रकम घोषित करे।

११ सरकार जनता को वही मुद्रा देने का यत्न करे जिसकी माँग है, चाहे वह रुपया पत्र-मुद्रा अथवा स्वर्ण हो। किन्तु जहाँ तक सम्भव हो स्वर्ण को सरकारी निधि में ही रखा जाय जिससे वह समय पड़ने पर विदेशी भुगतान के काम आ सके।

१२ शाही टकशाला की बम्बई शाखा पुनः स्थापित हो जिसमें माँवरेन तथा अर्धसाँवरेन ढाले जायें और जनता को भी स्वर्ण को इन मुद्राओं में परिवर्तन कराने के लिए सुविधाएँ दी जायें।

१३ नई दर की स्थापना के बाद साँवरेन का मूल्य १५ रु० से १० रु० हो जायगा इसलिए सरकार यह घोषणा करे कि अमुक तिथि तक माँवरेन का पुराने दर ( प्रति साँवरेन १५ रु० ) पर परिवर्तन हो सकेगा। इसी प्रकार

का अवसर उनको भी दिया जाय जिनके पाम स्वर्ण मोहरें हैं। इनके बाद उनका टक्का न हो।

१४. सॉवरेन के बदले रुपये देने की जिम्मेदारी सरकार में हटा ली जाय।

१५. अरक्षित पत्र-चलन १२० करोड़ रुपये हो रहे किन्तु अरक्षित भाग में केवल २० करोड़ रुपये की भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ रह नया १० करोड़ उन देशों में विनियोग किये जायें जो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत हों और शेष प्रत्यावालीन प्रतिभूतियाँ हों जिनकी अवधि एक वर्ष में अधिक न हो।

इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और २१ जून १९२० को सॉवरेन और अर्धसॉवरेन की ब्रिजग्राह्यता हटा ली गई। १९२० में भारतीय टक-विधान का समीक्षण हुआ तथा स्वर्ण के आयात निषेध और चांदी के आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों को रद्द किया गया। पत्र-मुद्रा की रूपों में परिवर्तनशीलता रद्द करने के लिए भी सुविधाएँ दी गई। नमिति की सिफारिश के अनुसार अरक्षित पत्र-चलन की मर्यादा भी १२० करोड़ रुपये कर दी गई तथा चलन नियन्त्रक (controller of currency) को अच्छे निर्णय-बिलों के बदले आवश्यकता के समय ५ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्रा अधिक चलाने का अधिकार दिया गया।

### सरकारी नीति की आलोचना

हम यह धना चुनते हैं कि रुपये की विनिमय दर स्टैबिलिटी में न आने हुए ० सि० स्वर्ण के बराबर करने की सिफारिश की गई थी। यह दर स्वीकार करने का परिणाम यह हुआ कि रुपये की दर, जो पहिले २ सि० ४ पेंस थी उसने बन्दर ० सि० १०- $\frac{1}{2}$  पेंस हो गई।

इन नमिति के एकमेव भारतीय सदस्य दादाभाई नौरोजी ने दर की वृद्धि के विरुद्ध अपना मत प्रकट किया और कहा कि इस प्रकार की अनिश्चित परिस्थिति में विनिमय-दर निश्चित करना एक भारी भूल होगी और यही श्रेयस्कर है कि अभी विनिमय-दर को माँग एवं पूर्ति पर ही निर्भर रहने दिया जाय। उन्होंने यह भी निश्चित किया कि विनिमय-दर में, जो १६ पेंस प्रति रुपया निश्चित हो चुकी थी, किसी प्रकार परिवर्तन नहीं होना चाहिए क्योंकि परिस्थिति के सुघरते ही चांदी का मूल्य और उसके साथ ही विनिमय-दर भी गिरने लगेगी। किन्तु उनके विरोधी मत पर कोई ध्यान न दिया गया और विनिमय-दर ० सि० स्वर्ण के बराबर निश्चित कर दी गई जो उस समय २ सि० १० पेंस के बराबर थी।

विनिमय-दर को ऊँचा करने का परिणाम होता है निर्यात में कमी तथा आयात में वृद्धि होना । जब तक युद्ध-काल था और हमारे यहाँ के माल की युद्ध-ग्रस्त देशों को आवश्यकता थी, तब तक हमारे विदेशी व्यापार पर उसका प्रभाव न हुआ । किन्तु अब लड़ाई खतम हो चुकी थी जिससे विदेशों में हमारे माल की माँग कम हो गई एवं निर्यात गिरने लगे थे । दूसरी ओर युद्ध-काल में इङ्ग्लैण्ड आदि देश युद्ध के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करने में लगे हुए थे किन्तु अब उन्होंने भी अन्य माल तैयार करना प्रारम्भ कर दिया तथा अपने विदेशी बाजारों को, जोकि युद्ध-काल में दूसरे देशों ने हस्तगत कर लिये थे, पुनः प्राप्त करने की कोशिश करने लगे ।

दूसरी ओर भारतीय लोग विदेशी माल के लिए तड़प रहे थे क्योंकि उन्हें युद्धकाल के चार वर्षों में वह नहीं मिल रहा था । दूसरे, बहुत से उपभोक्ता यहाँ पर वस्तुएँ महँगी होने के कारण अपनी आवश्यकताओं को, जहाँ तक सम्भव हो, स्थगित कर रहे थे क्योंकि उनका विचार था कि शान्ति होते ही मूल्य-स्तर गिर जायगा । तीसरे, भारतीयों को विनिमय-दर की अनिश्चितता के कारण रुपये का विश्वास न रहा था । इससे वे यथासम्भव स्टर्लिंग खरीदना चाहते और यदि विनिमय-दर कम भी हो जाती तो वे स्टर्लिंग बेचकर लाभ भी कमा सकते थे । ये तीनों कारण ऐसे थे जिनसे विदेशी मुद्रा की माँग बढ़ गई तथा सरकार को उसकी पूर्ति करना असम्भव हो गया ।

चौथे, जो अंग्रेजी कारखाने भारत में थे उन्होंने युद्धकाल में जो लाभ कमाया उसे इङ्ग्लैण्ड में भेजना शुरू किया क्योंकि ऊँची दर पर उनको इंग्लैण्ड में अधिक स्टर्लिंग मिल रहे थे ।

पाँचवे, विनिमय-दर ऊँची होने के कारण भारतीय व्यापारियों को अंग्रेजी माल सस्ता पड़ रहा था इसलिए आगे भी यह दर बनी रहेगी इस आशा पर उन्होंने इङ्ग्लैण्ड में बड़ी मात्रा में सामान खरीदने के आदेश दिये ।

इसका परिणाम यह हुआ कि स्टर्लिंग की माँग बढ़ती ही गई । जब यह भाग विनिमय बैंक पूरी न कर सके तब उन्होंने भारत सरकार से प्रति-परिपद-बिल माँगना शुरू किया तथा सरकार ने प्रति-परिपद-बिल बेचना । यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जब विनिमय-दर कमजोर हो गई थी तभी प्रति-परिपद-बिल बेचने के लिए सिफारिश की गई थी । दूसरे, जनता की राय भी प्रति-परिपद-बिल इस समय बेचने के विरुद्ध थी क्योंकि जनता का मत यह था कि भारतीय धन संचिति, जो इङ्ग्लैण्ड में रखी गई है, उसे बँसा

ही रखा जाय। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, परिणामस्वरूप विनिमय-दर गिरने लगी और उसे २४ पेंस स्वर्ण रखना असम्भव हो गया। तब सरकार ने विनिमय दर २ शि० स्टलिंग पर स्थिर करने की कोशिश २० जून १९२० से की। इसमें भी जब सरकार असफल रही तो २७ सितम्बर १९२० से प्रति-परिपद-बिलो की विक्री बन्द कर दी गयी क्योंकि स्टलिंग की माँग एक ओर तो असीमित थी और दूसरी ओर इसकी पूर्ति करने की सरकार की शक्ति सीमित थी। फलतः विनिमय-दर, जो १ जनवरी १९२० को २७½ पेंस स्टलिंग थी, अगस्त १९२० में केवल २२½ पेंस स्टलिंग रह गई तथा घाटे भी गिरनी गई। सरकार ने इन दो वर्षों में (१९१९ से १९२१ तक) कुल ५,५५,३२,००० स्टलिंग के प्रति परिपद-बिल बेचे। इतने स्टलिंग के बदले सरकार को कुल ४,७१४ लाख रुपये मिले किन्तु अगर यही दर १६ पेंस स्टलिंग होती तो उसे कुल ३१,४२,६६६ पौण्ड इतने रुपये में बेचने पड़ते जिससे इस नई दर से भारत सरकार की अनिश्चित एवं अदूरदर्शी नीति के कारण १४० लाख पौण्ड की हानि हुई। कहा जाता है यह हानि भारत-सचिव की प्रेरणा एवं दबाव के कारण ही हुई थी। २८ सितम्बर १९२० के बाद सरकार ने विनिमय-दर स्थिर रखने की कोशिश भी छोड़ दी और रुपये का व्यापारिक परिस्थिति के अनुसार विनिमय-दर प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र छोड़ दिया। यह दर १ अगस्त १९२१ को १६ पेंस स्टलिंग पर आ गई थी तथा स्वर्ण-मूल्य ११½ पेंस था। फिर भी बंधानिक दर वही २४ पेंस स्वर्ण बनी रही। इन सब अनिश्चित कार्यावहियों से जनता का विश्वास सरकारी नीति से उठ गया। परिणामतः व्यापारिक शिथिलता आई, आयातकर्ताओं को विनिमय-दर गिरने से हानि उठानी पड़ी एवं निर्यातकर्ताओं के पास जो माल था उसके लिए कोई खरीदार भी न रहा।

जब दर १ शि० ४ पेंस स्टलिंग आ गई तब सरकार ने हमसे नीची दर न होने देने के लिए कोशिश करना प्रारम्भ किया जिसके लिए कर-वृद्धि, छद्मनी, मुद्रा-सङ्कोच आदि उपाय काम में लाये गये। इससे सितम्बर १९२४ में विनिमय-दर १ शि० ४ पेंस स्वर्ण अथवा १ शि० ६ पेंस स्टलिंग तक पहुँच गई और श्री दलाल ने जैसा अपना मत दिया था वही होकर रहा। इसके बाद सरकार का यही रख रहा कि विनिमय-दर १ शि० ६ पेंस स्टलिंग में ऊँची न जाने पाये क्योंकि यह दर करीब-करीब स्थिर रही। इस प्रकार १९२१ से १९२५ तक का समय घोर उदासी का समय रहा क्योंकि

सरकार रुपये की विनिमय-दर २ शि० स्वर्ण पर स्थिर रखने में अनेक प्रयत्न करने पर भी असफल रही ।

इसके बाद अग्रेज १९०५ में स्टर्लिंग और स्वर्ण का मूल्य समान हो गया अर्थात् १ शि० ६ पे० स्वर्ण १ शि० ६ पे० स्टर्लिंग के बराबर हो गया । तब सरकार ने यह माँग की गई कि वह १ शि० ६ पे० दर को स्थायी कर ले ।

हिल्टन यंग कमीशन (१९२५-१९३६)

१ जनवरी १९२५ का सरकार ने एक नई समिति की नियुक्ति सम्बन्धी अपना विचार प्रवृत्त किया और २५ अगस्त १९२५ को हिल्टन यंग की अध्यक्षता में नई समिति की नियुक्ति हुई । इस समिति के चार सदस्य भारतीय थे तथा इसके अतिरिक्त इस समिति के सभासदों ने भारत में अनुसन्धान करके गवाहियों की जाच के बाद अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, यह इसकी विशेषताएँ थी । समिति की रिपोर्ट १ जुलाई १९२६ को दी गई । यहाँ एक बात ध्यान में रखना जरूरी है कि जून १९२५ में विनिमय-दर १ शि० ६ पे० स्वर्ण हो गई जो ८४७५१ ग्रेन स्वर्ण के बराबर थी और लगभग १ वष म्यूर रह चुकी थी । इस काल में इङ्ग्लैंड ने भी स्वर्णमान अपना लिया था और अन्य देशों के चलन में भी स्थिरता आ गई थी । समिति के विचाराय जो बात थी उनमें से मुख्य बात निम्नलिखित थी —

१ स्वर्ण-विनिमय-मान की कार्य-पद्धति का परीक्षण तथा स्थिर मान अपनाने सम्बन्धी योजना जिससे रुपये की विनिमय-दर स्थिर रखी जा सके,

२ चलन एवं बैंकिंग पद्धति का समन्वय (co-ordination) करने की योजना, तथा

३ उसकी कार्यान्वित करने के लिए सुझाव ।

उक्त आधार पर समिति ने अनेक गवाहियों का परीक्षण किया । इसी प्रकार भारतीय चलन एवं विनिमय नीति के अध्ययन के उपरान्त भारतीय चलन एवं विनिमय पद्धति के पुनर्गठन, चलन एवं बैंकिंग के समन्वय के हेतु अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जो कुल ३१ थी । उनमें से मुख्य सिफारिशें तीन विभागों के अन्तर्गत विभाजित की जा सकती हैं —

१ भारत के लिए चलन-पद्धति अपनाने सम्बन्धी सिफारिशें,

२ रुपया और स्वर्ण के बीच विनिमय के अनुपात सम्बन्धी सिफारिशें ;

तथा

३ चलन अधिकारी सम्बन्धी चुनाव अथवा चलन एवं धैर्य का समन्वय करन के लिये केन्द्रीय बैंक की स्थापना का सुझाव ।

### चलन-पद्धति के दोष

मामूनी न भारतीय चलन-पद्धति के विवेचन के उपरान्त वर्तमान चलन पद्धति के दोष बताये । उद्देश्य मौद्रिक मान अपनाने के सम्बन्ध में स्वीकृत-विनिमय-मान, स्वयं-विनिमय मान, स्वयं मुद्रा मान तथा स्वयं-वृद्ध-मान पर भी विचार किया । चिन्म पहिले तीन मान उन्होंने खान दिया तथा चौथा स्वयं-वृद्ध मान, अपनाने की निशानिधि थी । वर्तमान चलन पद्धति सम्बन्धी निम्न दोष बताये गए (१) दोष भारतीय स्वयं-विनिमय-मान के हैं (दोष ४) —

१ जटिल चलन-पद्धति—चलन-पद्धति साधारण न होने से रुपये के मूल्य की स्थिरता का आधार आसानी से सम्भल न नहीं आता था क्योंकि इसमें चारों व रुपये तथा पत्र-मुद्राएँ चलन में थीं । ये दोनों प्रकार की मुद्राएँ असीमित विधिबद्ध थीं । इनके निवा नावरेन (स्वयं मुद्रा) एक ऐसी मुद्रा थी जो विधिबद्ध हान हुए न चलन में नहीं थी । इसी प्रकार इन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष उद्देश्य यह बताया कि रुपये का मूल्य चारों व मूल्य पर निर्भर हान में चारों का सीमन बढन ही खपा धानु के रूप में बचा जान लगता है । यह विनिमय-दर की स्थिरता के लिए खतरनाक था ।

२ बोहरी विधि पद्धति—जो निधि रचे जा रहे थे उनमें भी बाहरी पद्धति थी जम स्वयंमान निधि तथा पत्र-चलन निधि । इसमें से पहला निधि रुपये की उलाह न था नाम न था उन नाम से बनाया जाकर विनिमय-दर को स्थिर रखन के लिए उपना में आता था । इसी निधि में से भारत मन्त्रि प्रणि परिषद निधि की निधि न मुक्तान करता था । दूसरा निधि पत्र-मुद्रा चलन में सुरक्षा के लिए रखा जाता था । हानाकि ये दोनों ही निधि अलग आता व परन्तु दोनों की इन मित जान न डर बना रखा था जिसमें उनमें का उनमें उद्देश्य का सम्बन्ध में अतिरिक्त तथा उनमें होती थी ।

३ लोच एवं स्वयंपूर्णता की कमी—स्वयं विनिमय मान की काम पद्धति स्वयंपूर्ण (auto-nomous) नहीं थी और न चलन पद्धति लोचदार ही थी । इसमें बिना सरकारी हस्तक्षेप के व्यापारिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार मुद्रा की पूर्ति भगाद बढन नहीं जा सकती थी । इसके अलावा मुद्रा की पूर्ति वन वन के लिए सरकार को प्रति परिषद बिला की विधि करना आवश्यक था जो कवन नहीं हो सकती थी जब भारत का व्यापारिक दोष हमारे प्रणि-

कूल हो। इससे इस पद्धति में स्वयंपूर्ण कार्यशीलता के अभाव के माय ही लोच का भी अभाव था।

४ साख एवं चलन पर दुहरा नियन्त्रण—सरकार चलन का नियन्त्रण करती थी तथा साख का नियन्त्रण इम्पीरियल बैंक द्वारा होता था जो देश के व्यापार एवं अर्थ-नियोजन की दृष्टि से अहितकर था।

५ चलन-पद्धति में अनिश्चितता थी एवं वह सरल नहीं थी, जिसकी वजह से उसमें जनता का विश्वास सम्पादित नहीं होता था।

इसलिए उन्होंने निम्नलिखित सिफारिशों की जो १६ जनवरी १९२७ को भारत सरकार ने स्वीकार की—

१ रुपये के विनिमय मूल्य को १८ पैसे पर स्थिर किया जाय।

२ चलन में पत्र-मुद्रा तथा रुपये रहे और चलन के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए उसे स्वर्ण में परिवर्तनशील बनाया जाय। किन्तु यह इस रूप में हो कि इस स्वर्ण का मुद्रा के रूप में उपयोग न हो सके। इस प्रकार इङ्गलैण्ड के नमूने पर भारत में भी स्वर्ण-क्षण्ड-मान का सुभाव ही पैदा किया गया, क्योंकि स्वर्ण-विनिमय-मान में ऊपर बताये गये दोष थे तथा स्वर्ण मुद्रा-मान को अपनाते के लिए स्वर्ण का अभाव था।

३ चलन सम्बन्धी व्यवस्था किसी बड़े बैंक के हाथ में दी जाय और ऐसे बैंक की तुरन्त स्थापना की जाय जिसका नाम 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' हो। यह बैंक जनता से निश्चित दरो पर स्वर्ण का ख़य-विक्रय करे।

४ सौवरेन एवं अर्धसौवरेन को विधिग्राह्य न रखा जाय जिससे उमें लेने के लिए कोई बाध्य न किया जा सके। वैसे तो उनका चलन काफी पहिले ही बन्द हो चुका था।

५ एक रुपये की पत्र-मुद्रा फिर से चलाई जाय तथा उसे विधिग्राह्य बनाया जाय तथा चलन-विभाग को यह अधिकार हो कि वह बड़ी पत्र-मुद्रा के बदले रुपये की पत्र-मुद्रा अथवा चाहे तो रुपये भी दे। परन्तु एक रुपये की पत्र-मुद्रा के बदले चांदी का रुपया न दिया जाय।

६ रुपये के लेन-देन के लिए लोग बाध्य बने रहें परन्तु जब तक उनकी मरुआ काफी कम न हो जाय तब तक नये रुपये न ढाले जायें।

७ पत्र-चलन-निधि तथा स्वर्णमान-निधि को मिलाकर उसमें स्वर्ण, रजत एवं प्रतिभूतियों का परिमाण विधान द्वारा निश्चित कर दिया जाय।

समिति की राय थी कि इस निधि में स्वर्ण एवं स्वर्ण प्रतिभूतियाँ ४०% से कम न हों और शेष ६०% भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियों में तथा व्यापारिक बिलों में हो। भारत सरकार की रुपया-प्रतिभूतियाँ कुल निधि के २५% अथवा ५० करोड़ रुपये की, इनमें जो कम हो, उसके बराबर होनी चाहिए।

८. पत्र-चलन पद्धति में परिवर्तन करने की दृष्टि में समिति ने सिफारिश की कि देश में आनुपातिक-निधि-पद्धति अपनाई जाय तथा निश्चित प्राथमिक चलन पद्धति (fixed fiduciary system) का अन्त किया जाय।

९. बिलों तथा घनादेशों पर जो मुद्राक-कर (stamp duty) है उसे उठा दिया जाय।

१०. निधि की स्वर्ण एवं चाँदी के अतिरिक्त रकम भारतीय बिलों तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में रखी जाय।

सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदाम ने समिति की रिपोर्ट पर अपना विरोधी मत प्रकट किया तथा उन्होंने अपनी राय यह दी कि विनिमय-दर १८ पेंस के बढ़ने १६ पेंस—जो २० साल से रही है—होनी चाहिए क्योंकि १८ पेंस की दर कृत्रिम रूप से स्थिर की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि “पाउलर समिति की राय भी पूर्णरूप से स्वर्णमान अपनाने के सम्बन्ध में थी, परन्तु अंग्रेजी अर्थ-प्रधिकारियों ने उस उद्देश्य को कभी भी पूरा नहीं होने दिया और उन्होंने सदा भारतीय मुद्रा के सम्बन्ध में वही नीति अपनाई जो इङ्ग्लैंड के व्यापारियों या पूँजीपतियों के लिए लाभदायक थी, न कि इस देश की जनता के लिए। इस नीति-रीति का उद्देश्य होता आया था भारतवर्ष का दोहन करके इङ्ग्लैंड के मुँह में घारोण पहुँचा देना।”<sup>१</sup> इसलिए सर पुरुषोत्तमदास ने सुझाया कि अब भी ऐसे उपायों का अवलम्बन किया जाय जिससे आज नहीं तो कल स्वर्णमान का अवलम्बन पूर्णरूपेण हो सके। परन्तु उनके इस सुझाव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया तथा रुपये की विनिमय-दर १८ पेंस पर ही निश्चित की गई। रिजर्व बैंक की स्थापना सम्बन्धी सुझाव पर सर पुरुषोत्तमदास का यही मत था कि कोई नई मस्या खड़ी न करते हुए यह काम इम्पीरियल बैंक को ही दे दिया जाय।

विनिमय-दर सम्बन्धी वाद-विवाद

विनिमय-दर १८ पेंस हो अथवा १६ पेंस, यह समस्या वादग्रस्त बन गई

<sup>१</sup> घनश्यामदास विडला कृत ‘रुपये की कहानी’ पृ० १८५

थी । १८ पेंस वाली दर जनता को आपत्तिजनक जैसी तथा एक अभूतपूर्व देशव्यापी आन्दोलन खड़ा हो गया जिसमें सरकार की ओर से १८ पेंस की दर सम्बन्धी दलीलें तथा जनता की ओर से १६ पेंस की दर सम्बन्धी दलीलें सामने रखी गईं, जिनको देखना परम आवश्यक है ।

१६ पेंस के पक्ष में

१ १८ पेंस प्रति रुपये की दर भौतिक न होते हुए कृत्रिम है तथा इसकी दो वर्षों स्थिर रखने में सरकारी कार्यवाही का हाथ रहा है । अगर यह दर, जो ऊँची है, निश्चित की जाती है तो भारतीय निर्यात-व्यवसाय कम हो जायगा तथा आयात को प्रोत्साहन मिलेगा जो भारत के हित में नहीं है क्योंकि इसमें भारतवर्ष के उत्पादकों एवं करोड़ों किसानों को हानि थी—लाभ था केवल ब्रिटिश व्यवसायियों, आयातकर्त्ताओं तथा अंग्रेज कर्मचारियों का ।

२ रुपये का मूल्य उसकी वास्तविक दर से अधिक निश्चित कर देने में भारतीय उद्योगों की हानि होगी क्योंकि वे विदेशी से स्पर्धा में टक्कर न ले सकेंगे । इसी प्रकार एशियाई बाजारों में भी भारतीय मान इङ्ग्लैंड, जापान आदि देशों के माल से टक्कर न ले सकेगा ।

३ यहाँ की कीमतों का समायोजन अभी ठीक प्रकार में नहीं हुआ है बल्कि घाम अभी गिरने वाले हैं जो १९३३ प्रतिशत तक ही गिरेंगे ( क्योंकि १८ पेंस और १६ पेंस की दर में भी यही अन्तर है ) । इसलिए अगर १६ पेंस की दर रखी जाय तो आर्थिक स्थिति में जो परिवर्तन होंगे वह नगण्य होंगे किन्तु १८ पेंस की दर अगर कर दी गई तो घोर आर्थिक संकट आघात बिगा न रहेगा । इसके अतिरिक्त १८ पेंस की दर से हमारे यहाँ का स्वर्ण-आयात एक जायगा क्योंकि हमारे यहाँ के निर्यात की कीमतें ऊँची होने से हम विदेशी बाजारों में न जा सकेंगे जिससे हमारे यहाँ के उत्पादकों को तथा किसानों को भारी हानि होगी ।

४ सरकार के अर्थ-विभाग को गृह-व्यय आदि के भुगतान में जो इङ्ग्लैंड की वार्षिक रकम देनी पड़ती है उसमें १६ पेंस की दर में अधिक हानि अवश्य होगी किन्तु उसकी पूर्ति सरकार की आय में वृद्धि द्वारा हो जायगी क्योंकि बढ़ते हुए निर्यात के कारण लोगों का लाभ बढ़ेगा तथा आय-कर और निराक्राम्य-कर (custom duties) की आय में वृद्धि हो जायगी । इस प्रकार १६ पेंस की दर निश्चित करने से सरकारी अर्थ-विभाग को भी कोई हानि नहीं होगी ।

५ समिति के सभान्तो का कहना था कि १६ पेंस की दर रखने में मजदूरी की दर बढ़ने में हानि होगी परन्तु यह बात बिल्कुल गलत है क्योंकि मजदूरी की दर उसी समय काफी ऊँची थी तथा १६ पेंस की दर अगर निश्चित कर दी जाती तो उद्योगों की उन्नति होती जिसमें बेकारी कम होती और देश के किसानों एवं उद्योगपतियों को अधिक लाभ होता ।

६ मजदूरी का अभी तक १८ पेंस की दर में मिलान अथवा समायोजन (adjustment) नहीं हो पाया था । अगर यह दर निश्चित कर दी जायगी तो मजदूरी की दर कम करनी पड़ेगी जिसकी वजह से पूँजीपतियों और श्रमिकों में सद्भावना न रहते हुए भगडा पैदा हो जायगा तथा देश के आर्थिक ढाँचे को बुरी तरह धक्का लगगा ।

इन सब कारणों को बदलते हुए सर पुरपोत्तमदास का कहना था कि जो दरगत २० वर्षों में अच्छी तरह काम कर रही है उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता ही क्या है, जबकि अन्य देशों में भी युद्धोपरान्त वही दर अपनाई गई है जो युद्धपूर्व थी । इस दर (१६ पेंस) पर हमारे स्वर्ण-मान-निधि में व्यापारिक रोप की प्रतिकूलावस्था में अधिक स्वर्ण भी नहीं जायगा । इसी प्रकार, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, सरकार के अर्थ-विभाग को कोई हानि होने की सम्भावना नहीं है इसलिए १६ पेंस की दर ही निश्चित की जानी चाहिए । लेकिन अगर रुपये की दर १८ पेंस निश्चित की गई तो केवल हमारे आर्थिक ढाँचे को ही धक्का न लगेगा बल्कि ऐसे भीषण परिणाम होंगे, जिनकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती ।

### १८ पेंस के पक्ष में

१८ पेंस के पक्ष में तथा १६ पेंस के विरुद्ध समिति के अन्य सदस्यों की ओर से निम्न दलीलें पेश की गईं —

१ उपर्युक्त विचारों के विरुद्ध यह दलील दी गई कि सर पुरपोत्तमदास सारे देश के हित की दृष्टि न रखते हुए केवल बम्बई के उद्योगपतियों की दृष्टि में इन समस्या पर विचार करते हैं । देश के लिए वास्तव में न तो ऊँची दर और न नीची दर हानिकारक है बल्कि विनिमय-दर में उच्चावचन होना ही हानिकारक अधिक है क्योंकि कोई भी दर—ऊँची या नीची—निश्चित की जाय फिर भी मजदूरी तथा कीमतों का मिलान अथवा समायोजन हो ही जाता है और इसलिए यह दर निश्चित करने समय मात्र प्रकार की नाबधानी रखी जा रही है । उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि यह दर दो वर्ष से स्थिर है इसलिए

मजदूरी और कीमतों का समायोजन इस दर पर हो चुका है और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना अब भारतीय व्यापार एवं आर्थिक संगठन के लिए हानिकर होगा ।

२ मुद्रा-कान के पूर्व जो आदेश विदेशों में दिये गये होंगे वह १६ पेंस की दर पर थे, यह मान भी लिया जाय तो भी ऐसे आदेशों की मर्यादा बहुत कम होगी क्योंकि मुद्रा के बाद जो आदेश दिये गये होंगे वही अधिक होंगे तथा उस समय दर भी १८ पेंस से अधिक न थी, इसलिए व्यापारियों को हानि होने की सम्भावना नहीं है ।

३ किसानों को ऊँची दर से १२½% की हानि होगी यह कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि कृषिजन्य वस्तुएँ आवश्यकता की वस्तुएँ होने के कारण उनकी माँग में कोई भी परिवर्तन होना असम्भव है और इसलिए ऐसी वस्तुओं की कीमतों में किसी प्रकार की गिरावट नहीं आयेंगी ।

४. समिति सर पुरुषोत्तमदास के इस मत से असहमत थी कि १६ पेंस नैसर्गिक दर है तथा १८ पेंस कृत्रिम, क्योंकि उनका कहना था कि १९१७ से १९२५ तक १६ पेंस की दर रही ही नहीं और जब भी यह दर रही, उसको कृत्रिमता से स्थिर करने के प्रयत्न होते रहे । अगर रुपये की दर स्वतन्त्र छोड़ दी जाती तो वह कहाँ तक स्थिर रहती यह कहना असम्भव है । इसलिए १८ पेंस की दर ही इस स्थिति में रहना ठीक है क्योंकि दर १६ पेंस कर देने से आन्तरिक वस्तुओं की कीमतें बढ़ जायेंगी जो उपभोक्ताओं तथा मजदूरों की दृष्टि से हानिकर है ।

५ यदि दर १६ पेंस कर दी जाय तो सरकार के अर्थ-विभाग को अधिक हानि होगी और उसकी पूर्ति के लिए कर इत्यादि बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि भारत सरकार को इस दर पर १८ पेंस की दर की अपेक्षा अधिक रुपये देने पड़ेंगे ।

यह दलील, जो हमारे अर्थ-सचिव सर वेसिल ब्लैकेट ने दी, बड़ी ही कामयाब रही जिसका उन्होंने बड़ी ही चालाकी से उपयोग किया तथा १८ पेंस की दर का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय इसके लिए और भी कार्यवाहियों की गई जिनके परिणामस्वरूप १८ पेंस की दर सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत हो गया ।

स्वर्ण खण्ड-मान अपनाने के लिए भी भारतीय टकण-विधान (१९२७) स्वीकृत हुआ जो १ अप्रैल १९२७ से लागू हुआ । विनिमय-दर १८ पेंस स्वर्ण

अथवा ८ ४७५१२ ग्रेन विद्युद्ध स्वर्ण प्रति रुपया निश्चित की गई। सरकार की जिम्मेवारी हो गई कि वह २१ $\frac{3}{4}$  रु० प्रति तोले की दर से न्यूनतम ४० तोले स्वर्ण की छोड़े बम्बई टंकाल में जनता से खरीदे तथा विधिग्राह्य चलन के बदले २१ $\frac{3}{4}$  रु० प्रति तोले की दर से स्वर्ण अथवा विदेशी मुद्राएँ (स्टर्लिंग) ४०० ग्राँम अथवा १०६१ तोले अथवा इससे अधिक मात्रा में वेचे। स्वर्ण देना अथवा स्टर्लिंग देना सर्वथा सरकार की इच्छा पर था। स्टर्लिंग बेचने की दर १ शि० ५३ $\frac{3}{4}$  पैसे निश्चित की गई थी। इसी विधान के अनुसार माँवरेन एव अर्से-साँवरेन की विधिग्राह्यता भी छीन ली गई।

इस प्रकार वास्तव में देखा जाय तो समिति की सिफारिश के अनुसार जनता को स्वर्ण अथवा स्टर्लिंग मिलना सरकार पर निर्भर था न कि जनता पर। इसलिए हमें वास्तव में स्वर्ण-खण्ड-मान न कहते हुए स्टर्लिंग-विनिमय-मान कहना ही अधिक उपयुक्त होगा किन्तु स्टर्लिंग स्वर्ण में परिवर्तनशील होने के कारण हम इसे स्वर्ण-विनिमय-मान कह सकते हैं। इस प्रकार जिस मान-पद्धति को सद्योप बनावर समिति ने त्याग दिया उसी को दूसरे रूप में फिर से अपनाया गया।

१९२७ से १९३६

१९२७ में १९३६ तक की अवधि में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ घटी —

१ १९३१ में इङ्गलैण्ड ने स्वर्णमान का परित्याग किया, जिससे भारतीय मुद्रा-प्रणाली पर घोर परिणाम हुए क्योंकि एक प्रकार से रुपये का गठबन्धन स्टर्लिंग में था।

२ १९३४ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम पास हुआ तथा १९३५ में इस बैंक की स्थापना की गई, जिससे इसे मुद्रा तथा साख के नियन्त्रण का अधिकार दिया गया और चलन-निधियों का एकीकरण किया गया। इसी के साथ विनिमय-दर की स्थिरता की जिम्मेवारी भी इसी बैंक की हो गई।

भारतीय व्यापार की स्थिति अप्रैल १९२७ से १९२९ तक हमारे अनुकूल रही तथा आयात एवं निर्यात के मूल्यों में वृद्धि होती गई। किन्तु इस अवधि में विनिमय-दर में कमजोरी आ गई जो प्रति-वर्ष बनी ही रही। विनिमय-दर में मजबूती लान तथा उसे १८ पैसे पर स्थिर रखने के लिए सरकार ने कुछ कभी न की और उसने इम्पीरियल बैंक का विरोध होते हुए भी बैंक-दर को ७ प्रतिशत में बढ़ाकर ८ प्रतिशत कर दिया और कोष-विस्तो (treasury

bulls) को विक्री को भी दृढ़ाकर मुद्रा-संकोच द्वारा पूँजी का निर्यात (outflow) रोकना चाहता। कोष-विलो की अविकाधिक विक्री तथा ऊँचे व्याज-दर द्वारा मुद्रा-संकोच करना, यह सरकार की मुद्रा-नीति का एक मुख्य अंग बन गया।

१९२७-२८ तथा १९२८-२९, इन दो वर्षों में व्यापार का विस्तार काफी हुआ तथा हमारी विनिमय-दर में स्थिरता बनी रही। यह स्थिरता हमारे व्यापार के विस्तार की वजह से न होने हुए विश्व-व्यापार का विस्तार तथा विश्व-मूल्य की स्थिरता के कारण रही। भारत-सरकार को प्रति वर्ष गृह-व्यय का भुगतान करना पड़ता था जिसके लिए उनके सानन दो मार्ग खुले थे—१. स्वर्ण का निर्यात करना तथा २. भारतीय मुद्रा के आन्तरिक मूल्य को बढ़ा देना। इनमें से हमारी सरकार ने दूसरे मार्ग का अवलम्बन किया। इन प्रकार सरकार का मुद्रा-पद्धति में हस्तक्षेप करना ही हमारी मुद्रा-पद्धति की कमजोरी को दिग्दर्शित करता था। १९२६ में दुनिया की मुद्रा पद्धति में उलट-फेर होने लगे, विश्व-व्यापार में मन्दी आई और कीमत धड़धड़ गिरने लगी। इंग्लैण्ड ने १९२५ में स्वर्णमान अपनाया था तथा कृत्रिम नीर में पौंड का स्वर्ण-मूल्य ऊँचा रखने की कोशिश की थी किन्तु १९२६ के बाद स्टर्लिंग का भी स्वर्ण-मूल्य गिरने लगा और पौंड का अवमूल्यन होने लगा। भारतीय रुपये की विनिमय-दर भी स्थिर नहीं हो पाई थी, वह स्टर्लिंग से बँधा होने के कारण हमारे रुपये की विनिमय-दर में भी १९३० में कमजोरी आने लगी जो फरवरी १९३१ तक चालू रही। इस कमजोरी के लिए एक कारण यह भी था कि उस समय सन्धन में जो गोलमेज परिषद होने वाली थी उसमें १६ पेंस की दर की निफारिश होगी, यह वाग्णा बन चुकी थी। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि १९२६-२७ से १९३०-३१ तक विनिमय दर को १८ पेंस पर स्थिर रखने के लिए कुल १०२५० करोड़ की पत्र-मुद्रा चलन से हटा ली गई थी। इससे व्यापारिक क्षेत्रों में बड़ा असन्तोष था किन्तु भारत सरकार ने इस ओर दुर्लक्ष किया। इतना ही नहीं, बल्कि फरवरी १९३१ में भारत-मन्त्रि ने भारत सरकार को यह आदेश भेजा कि दर १८ पेंस स्थिर करने के लिए वह अपने प्रयत्नों में किसी प्रकार की कमी न करे। इस प्रकार भारत की जो स्थिति १९२७ से १९३१ तक रही उससे यह स्पष्ट है कि १८ पेंस विनिमय-दर स्थिर रखने में सरकार की अदूरदर्शिता ही थी क्योंकि इस अवधि में न तो भारतीय व्यापार की उन्नति हुई और न विनिमय-दर ही स्थिर रही। इस प्रकार एक ओर तो १९२६ के बाद की विश्व मन्दी की मार पड़ रही थी और दूसरी ओर भारत में जो राजनीतिक आन्दोलन चल रहा

या उसने इस समय आग में घी का काम किया जिससे भारतवासियों को विशेषतः किसानों को अधिक हानि हुई क्योंकि वस्तुओं के दाम घडाघड गिरते ही जा रहे थे। दूसरे, सरकार को गृह-व्यय भेजने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्टलिंग भी नहीं मिल रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि नवम्बर १९३१ तक परिस्थिति ऐसी भयंकर रही कि सरकार को ५६ लाख स्टलिंग बेचने पड़े और सितम्बर १९३१ तक रुपये की दर स्थिर रखने के लिए १४० लाख स्टलिंग फिर बेचने पड़े। ये सब बातें यह प्रमाणित करती हैं कि विनिमय-दर १८ पैसे स्थिर रखने में भारतीयों की कितनी हानि हुई और इस भद्ररक्षिता के कितने भयंकर परिणाम हुए जो न होने यदि सर पुरुषोत्तमदास आदि भारतीयों के मत पर सरकार विचार करती।

१९३१ का चलन संकट तथा रुपये का स्टर्लिंग से सम्बन्ध

इंग्लैण्ड ने १९२५ में फिर स्वर्णमान अपनाया था तथा स्टलिंग का स्वर्ण-मूल्य बढ़ाने की क्रिया मुद्रा-सङ्गोच द्वारा वहाँ भी कार्यान्वित हो रही थी। परिणामस्वरूप मई १९२५ में इंग्लैण्ड के स्टलिंग का मूल्य—जो फरवरी १९२० में ३ ३८२ डॉलर था—बढ़ते-बढ़ते ४ ८५ डॉलर हो गया। और जब स्टलिंग ने अपना स्वर्ण-मूल्य प्राप्त किया तो बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने स्टलिंग पत्र-मुद्रा के बदले स्वर्ण देना शुरू किया जो अल्पकालीन रहा क्योंकि थोड़ी ही अवधि में इन बैंक के स्वर्ण-निधि में बहुत कमी आ गई अब उस कमी को पूरी करने में बैंक असमर्थ रहा। परिणामस्वरूप इंग्लैण्ड को २१ सितम्बर १९३१ में स्वर्ण का परित्याग करना पड़ा और क्रमशः स्टलिंग का स्वर्ण में अवमूल्यन होने लगा। हमारा रुपया स्टलिंग से सम्बन्धित होने के कारण हम भी उससे बच न सके और रुपये का स्वर्ण-मूल्य भी गिरने लगा और उस परिमाण में मन्दी भी बढ़ने लगी जो इंग्लैण्ड के स्वर्णमान-परित्याग के कारण तीव्रतर हो गई। १९३१-३२ में विश्व-व्यापार में १९२६ की अपेक्षा ३३% कमी आ गई थी। भारतीय कृषिजन्य पदार्थों की कीमतें भी बुरी तरह गिर रही थी जिससे यहाँ पर भयंकर असन्तोष था जिस वजह से इस संकट के परिणामों में और भी भीषणता आ गई। इस अवधि में परिस्थिति में सुधार करने के लिए किसानों को लगान में छूट दी गई। सरकार को भी आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ने लगी जिसके लिए अल्पकालीन कोष-बिलों द्वारा सरकार ने भी ऋण लिया। विनिमय-दर बहुत कमजोर हो गई तथा १९३१ में वह निम्नतम स्वर्ण-विन्दु पर आ गई तथा विनिमय-दर को निम्नतम स्वर्ण-विन्दु पर स्थिर रखने के लिए,

जैसा कि ऊपर कहा गया है, बड़ी मात्रा में स्टर्लिंग बेचने पड़े क्योंकि भारत से पूंजी बाहर जाने लगी थी।

इंग्लैण्ड के स्वर्णमान परित्याग करने के कारण भारत सरकार को रुपये के स्टर्लिंग के साथ गठबन्धन पर फिर से विचार करना पड़ा। १९२७ के विधान द्वारा जब रुपया १ सि० ६ पैस स्टर्लिंग के बराबर कर दिया गया था तब स्टर्लिंग का स्वर्ण-मूल्य भी उतना ही था, किन्तु अब स्वर्ण-परित्याग के बाद स्टर्लिंग का ३० प्रतिशत अवमूल्यन हो गया था। इसलिए अब प्रश्न यह था कि रुपये की विनिमय-दर क्या हो तथा उसका स्वर्ण से सम्बन्ध जोड़ा जाय अथवा स्टर्लिंग से ?

इसलिए सबसे पहिले स्वर्ण का इंग्लैण्ड में परित्याग होते ही एक आदेश (Ordinance No VI of 1931) द्वारा सरकार ने रुपयों के बदले स्वर्ण या स्टर्लिंग देने की व्यवस्था हटा दी। इसका तात्पर्य यही हो सकता है कि सरकार रुपये का सम्बन्ध न तो स्वर्ण से और न स्टर्लिंग से ही रखना चाहती थी तथा रुपये के बन्धन को पूर्णतया स्वतन्त्र छोड़ देना चाहती थी। किन्तु उसी दिन भारत-सचिव ने यह ऐलान किया कि भारत की वर्तमान चलन-व्यवस्था स्टर्लिंग के आधार पर रहेगी अर्थात् भारतीय रुपये का मूल्य १८ पेंस स्वर्ण के बदले अब १८ पैस स्टर्लिंग रहेगा। यह आदेश १९३१ के आदेश न० ६ के विपरीत था। भारत-सचिव के इस आदेश के अनुसार अब स्टर्लिंग प्रति रुपया १७½ पेंस की दर पर कुछ विशेष विनिमय-बैंकों को मिल सकता था, सर्वसाधारण को नहीं—और वह भी कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए ही। इस प्रकार रुपये को स्टर्लिंग से बाँध देने के कारण भारत का भाग्य भी इंग्लैण्ड के भाग्य पर निर्भर हो गया। स्टर्लिंग के मूल्य-परिवर्तन के साथ रुपये के मूल्य में भी परिवर्तन होने लगे और रुपये के अवमूल्यन के कारण हमारे यहाँ की कीमतें और भी गिरने लगी जिनसे एक प्रकार से रुपये का अकाल पड़ गया तथा जो स्वर्ण अभी तक भूमिगत अथवा गहनों के रूप में या वह विकने लगा। इसी के साथ उन लोगों ने भी, जो स्वर्ण की बड़ी हुई कीमतों से लाभ कमाना चाहते थे, अपना सोना बचना शुरू किया, जो बाढ़ में बिदेसों में भेजा जाने लगा।

भारत-सचिव का रुपया-स्टर्लिंग गठबन्धन का आदेश आने ही ऋणों की नई दर पर समायोजन करने की दृष्टि से बैंकों की तीन दिन की छुट्टी की गई। २४ सितम्बर १९३१ को नया आदेश—१९३१ का आदेश न० ७—निकाला गया जिसके अनुसार, जैसा हम ऊपर कह चुके हैं, स्वर्ण की विक्री

अथवा स्टर्लिंग की बिक्री विशेष व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित कर दी गई क्योंकि अगर असोमित बिक्री की जाती तो चायद यहाँ पर स्वर्ण का आयात होता, जिसे रोकने के लिए यह कदम उठाया गया था। इसके अनिर्दिष्ट इसका उद्देश्य विनिमय दर १८ पेंस पर स्थिर करना भी था। इस कार्य में विनिमय-बैंकों ने सरकार को पूर्ण सहयोग दिया जिसकी वजह से सरकार रुपये की दर १८ पेंस पर स्थिर करने में सफल रही। फिर भी माघारण जनता इस दर के विरोध में ही रही।

**रुपया-स्टर्लिंग गठबन्धन क्यों ?**

रुपये का जब स्टर्लिंग में गठबन्धन किया गया उन समय भी इसके सम्बन्ध में विवाद हुआ। कुछ लोगों के मत से स्टर्लिंग के साथ रुपये का गठबन्धन होना देश के लिए हानिकार था क्योंकि रुपये के गठबन्धन के साथ भारत का आर्थिक भाग्यचक्र भी इंग्लैण्ड के भाग्य से बँध जायगा और भारत इंग्लैण्ड की राजनीतिक गुलामी के साथ ही आर्थिक गुलामी में जकड़ा जायगा। रुपया स्टर्लिंग से बँड़ा होने के कारण उसका स्वतन्त्र अस्तित्व खतम होगा तथा उसके मूल्य में जो उतार-चढ़ाव होंगे वे देश की आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार होते हुए स्टर्लिंग के उतार-चढ़ाव के साथ होंगे। दूसरे, स्वर्णमान वाले देशों से जो माल हमारे यहाँ आयात होगा वह हमको महँगा पड़ेगा क्योंकि १९३१ में स्टर्लिंग का ३०% अवमूल्यन हो गया था। तीसरे, रुपये का स्टर्लिंग से गठबन्धन होते ही रुपय का स्वयं-मूल्य भी गिर जायगा जिससे भारत से स्वर्ण का निर्यात होगा जो देश के लिए हितकर नहीं कहा जा सकता और यही हुआ भी।

इसके विपरीत रुपय का स्टर्लिंग में गठबन्धन होना जो लोग चाहते थे उनका कहना था कि पहले तो रुपये की स्वतन्त्र छोटने से विनिमय-दर में उतार-चढ़ाव अधिक होंगे जिसमें विदेशी व्यापार को सदैव खतरा बना रहेगा। दूसरे, स्टर्लिंग का स्वर्णमान वाले देशों की मुद्राओं के सम्बन्ध में अवमूल्यन होने से रुपये का भी अवमूल्यन होगा, जिससे स्वर्णमान वाले देशों के साथ भारत का निर्यात व्यापार बढ़ेगा। तीसरे, भारत का अधिकतर व्यापार इंग्लैण्ड के साथ है और साथ ही भारत को प्रतिवर्ष इंग्लैण्ड को गृह-व्यय की लगभग ३२ मिलियन पाउंड की राशि देनी पड़ती है इसलिए इन दोनों ही दृष्टि से रुपये का स्टर्लिंग में गठबन्धन भारत को लाभकर होगा। परन्तु ये सब दलीले थोड़ी थी जिसने भारत में स्वर्ण निर्यात होने लगा।

## भारत से स्वर्ण-निर्यात

ऊपर कहा गया है कि रुपये के अकाल के कारण स्वर्ण की बिक्री होने लगी तथा उमका निर्यात भी किया जाने लगा जिससे निर्यात की वस्तुओं में स्वर्ण का भी समावेश हो गया जिससे १८ पैसे की दर स्थिर रहने में काफी सहायता मिली, किन्तु भारत का स्वर्ण बाहर जाने लगा जो हमारी आर्थिक परिस्थिति का द्योतक था। इस स्वर्ण-निर्यात के कारण हमारा व्यापारिक शेष भी हमारे अनुकूल रहने लगा और स्टर्लिंग की अधिकता हो जाने से स्टर्लिंग की बिक्री पर जो प्रतिबन्ध (१९३१ के आदेश न० ७ द्वारा) लगाये गये थे, वे ३१ जनवरी १९३२ से हटा लिये गये तथा स्टर्लिंग की बिक्री बिना रोक-टोक के होने लगी। यह स्वर्ण-निर्यात की क्रिया १९३१-३२ से द्वितीय महायुद्ध तक चालू रही और इन ६ वर्षों में भारत से ४१७.८ लाख औंस सोना विभिन्न कीमतों पर निर्यात हुआ जिसकी कुल कीमत ३६२.४५ करोड़ रुपये थी। इस निर्यात पर केवल महायुद्ध प्रारम्भ होने के बाद ही प्रतिबन्ध लगाये गये।

स्वर्ण के इस निर्यात पर भारतीय प्रतिनिधियों ने बड़ी आलोचना की किन्तु फिर भी स्वर्ण-निर्यात को रोकने के लिए सरकार ने किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं किये। इन लोगों का कहना यह भी था कि पहले, १८ पैसे स्टर्लिंग की दर भी भारत के लिए हानिकारक है क्योंकि यह दर केवल शासकीय अधिकारियों द्वारा धारासभा की राय के बिना निश्चित की गई थी। दूसरे, स्टर्लिंग के साथ रुपये का गठबन्धन होने से रुपये के भाग्य का निर्णय स्टर्लिंग पर पूरी तरह निर्भर हो गया था। तीसरे, यह विनिमय-दर ऊँची होने तथा स्टर्लिंग का अवमूल्यन होने के कारण स्वर्ण का मूल्य बढ़ गया था और स्वर्ण की ये कीमतें स्टर्लिंग में और भी अधिक थी। स्वर्ण की कीमतों में अन्तर होने के कारण स्वर्ण का भारत से निर्यात होगा—जैसा कि हुआ भी—इससे भारत का स्वर्ण-निधि कम हो जायगा। चौथे, जो देश स्वर्णमान पर आधारित हैं उनसे होने वाले भारतीय आयात-व्यापार को धक्का लगेगा क्योंकि उन देशों का भाल यहाँ पर मँहगा पड़ेगा। पाँचवें, इस विनिमय-दर की वजह से भारत से केवल अक्टूबर १९३१ से मार्च १९३२ तक के ६ महीनों में ही ५८ करोड़ रुपये का स्वर्ण निर्यात हो चुका है। छठे, रुपये का स्टर्लिंग से १ सि० ६ पैसे की दर पर गठबन्धन होने में हमारे व्यापारिक शेष में भी गिरावट आ गई और उसमें कमी होने के आसार दिखाई देने लगे। जहाँ

१९३७-३८ में भारत का व्यापार मन्तुनम ३० ६० करोड़ रुपये में हमारे पक्ष में था यह १९३८-३९ में केवल १७ ३९ करोड़ रुपये रह गया ।

इस प्रकार स्वर्ण-निर्यात के कारण भारत में किसानों के पास मेहनत से कमाया हुआ जो मकड़ी स्वर्ण ( distress gold ) था, वह विदेशों में जाने से देश में स्वर्ण को कमी हो गई । स्वर्ण की कमी का मतलब होता है मुद्रा शक्ति का हान । इस स्वर्ण को सरकार खरीद कर स्वर्ण निधि में रोकने के साथ ही अपना स्वर्ण-निधि बढ़ा सकती थी । परन्तु सरकार विदेशी थी, उसको क्या पड़ी थी ?

इस प्रकार भारत में १९३१ से वास्तव में स्टर्लिंग-विनिमय-मान अपनाया गया हालाँकि भारतीय टकरा-विधान में इसका नाम स्वर्ण-खण्ड-मान ही रहा, क्योंकि स्टर्लिंग स्वर्ण से बँधा न होने के कारण हम रुपये से केवल स्टर्लिंग ही प्राप्त कर सकते थे । यह थी रिजर्व बैंक की स्थापना के समय की परिस्थिति ।

### रिजर्व बैंक की स्थापना

ऐसी मकदमय परिस्थिति में १९३१ की केन्द्रीय बैंकिंग जाँच-समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में रिजर्व बैंक की स्थापना पर जोर दिया और सरकार इसकी स्थापना पर विचार करने लगी और अन्त में ६ अगस्त १९३४ को रिजर्व बैंक की स्थापना का विधेयक स्वीकृत हुआ और १ अप्रैल १९३५ को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई जिसे मुद्रा चलन एवं साख-नियन्त्रण का अधिकार दिया गया ।

इस बैंक की स्थापना में भारतीय चलन की स्थिति में होने वाले निम्न-लिखित परिवर्तन महत्वपूर्ण हैं —

१ भारतीय मुद्रा-चलन तथा साख-नियन्त्रण करने का एक पत्र-मुद्रा-चलन का एकाधिकार इस अधिकोष को है तथा इसी अधिकोष के पास अन्य आवश्यक अधिकोषों के शेष जमा रहेंगे ।

२ अब इसकी स्थापना से पत्र-चलन निधि, भवर्ण-निधि तथा अधिकोष-निधि का एकीकरण हो गया ।

३ रुपये की विनिमय-दर १८ पैसे पर स्थिर रखने की वैधानिक जिम्मेदारी इस अधिकोष पर है और यह अधिकोष स्वर्ण के क्रय-विक्रय द्वारा विनिमय-दर के उच्चावचन को १७ ३/४ पैसे तथा १८ ३/४ पैसे की मर्यादा में रखता है ।

इसी समय फिर रुपये और स्टर्लिंग के अनुपात ने विवाद का रूप धारण किया और विनिमय-दर को १६ पैसे पर स्थिर करने के लिए जनता की ओर से प्रयत्न किये गये। भारतीय कांग्रेस ने भी ४ दिसम्बर १९३८ को श्री मुभाष चन्द्र बोस की अध्यक्षता में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत किया :—

“जब मेरे रुपये की दर १८ पैसे निश्चित कर दी गई है तब से यहाँ का व्यवसायी वर्ग और मार्जनिंग सस्याएँ इसका विरोध करते आ रहे हैं। उनकी माँग यही रही है कि चूँकि हुण्डी की यह दर आर्थिक दृष्टि से भारतवर्ष के लिए अहितकर है, इसमें रद्दोबदल होना जरूरी है। भारत सरकार इस लोकमत की उपेक्षा करती आई है।” ६ जून (१९३८) को कांग्रेस ने इस विषय पर एक वक्तव्य निष्काश कर कहा कि यह हुण्डी की दर में कोई भी हेरफेर करना नहीं चाहती और दलील यह पेश की कि हेरफेर करने में परिस्थिति इतनी डाँवाँडोल हो जायगी कि लोगों को लाभ के बदले हानि उठानी पड़ेगी।

“समिति की राय में १८ पैसे की दर से यहाँ के किसानों की गहरी हानि हुई है। इसने उनकी पैदावार की कीमत गिरा दी है और बाहर से आने वाले माल को अनुचित फायदा पहुँचाया है।” पिछले ७ वर्षों में यह सिर्फ सोने के बड़े पैमाने पर निर्यात के कारण ही टिक सकी है। इस निर्यात से देश को बड़ी क्षति हुई है। “भारतवर्ष के पास सोने और स्टर्लिंग के रूप में जो सम्पत्ति बच गई है उसको बरबाद करके ही हुण्डी की यह दर कायम रखी जा सकती है।” देश की भलाई इन्हीं में है कि हुण्डी की दर को टिकाने का प्रयत्न छोड़ दिया जाय और सरकार इसे सीधे १६ पैसे कर देने की दिशा में अग्रसर हो।”<sup>१</sup>

लेकिन इस प्रस्ताव पर भी कोई ध्यान न दिया गया और सरकार यही कहती रही कि इस विमर्श हुई व्यापारिक परिस्थिति की दशा में अगर विनिमय-दर को गिरा दिया जायगा तो इससे किसानों को बड़ी हानि होगी और अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति को देखते हुए इस दर में कोई भी परिवर्तन होना असम्भव है। दूसरे, सरकार की अर्थ-व्यवस्था पर भी इस परिवर्तन से बुरा परिणाम होगा इसलिए १८ पैसे की दर ही रहना ठीक है क्योंकि दर गिराने में केवल मर्दवाजों को ही लाभ होगा, जनमाधारण को नहीं।

इस प्रकार भारत में स्टर्लिंग-विनिमय-मान स्थापित किया गया जो

<sup>१</sup> ‘रुपये की कहानी’—घनश्यामदास विडला

पूर्णरूप से नियन्त्रित था। रुपया ही भारत की प्रमाणित एवं प्रतीक मुद्रा थी और साथ में पत्र-मुद्रा भी, जो असमीमित विधिग्राह्य थी। हमारा रुपया इस समय भी १८० ग्रेन का था जिसमें १/३ भाग चांदी थी और अठन्नियों में भी १/३ भाग चांदी थी और ये दोनों ही मुद्राएँ असमीमित विधिग्राह्य थी। विदेशी भुगतान के लिए चलन-अधिकारी अथवा रिजर्व बैंक की यही जिम्मेदारी थी कि वह रुपये और पत्र-मुद्रा के बदले स्टर्लिंग १८ पेंस प्रति रुपय की दर से बेचे तथा रुपयों और पत्र-मुद्रा के बदले स्टर्लिंग इसी दर से खरीदे। इस दर को १७३६ पेंस और १८६६ पेंस के बीच रखने की जिम्मेदारी भी रिजर्व बैंक विधान की धारा ४० व ४१ के अनुसार इसी बैंक पर थी। इस रुपया-स्टर्लिंग-गठबन्धन के कारण स्टर्लिंग ही हमारा भाग्य-निर्माता है क्योंकि इंग्लैंड की आर्थिक परिस्थिति की झलक भारतीय आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ती है।

यह भी देन की स्थिति तथा देश का मौद्रिक मान, जिन समय द्वितीय महायुद्ध का आह्वान किया गया।

### सारांश

प्रथम बिद्वद्युद्ध आरम्भ होते ही जनता एवं देश के व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में गड़बड़ी हो गई। जनता ने मोटो का परिवर्तन स्वर्ण में करना तथा अपनी जमा राशि बैंकों से निकालना शुरू किया। यह स्थिति युद्ध के प्रथम साल में रही परन्तु फिर विनिमय-दर में मजबूती आने लगी। इसके अनेक कारण थे —

१. आयात में सभी एवं निर्यात में वृद्धि हुई।
२. कीमतों में वृद्धि होने से निर्यात वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ा।
३. इन्फ्लेशन की ओर से भुगतान करने की जिम्मेदारी भारत पर आई।

४. प्रति-परिपद-बिलों के भुगतान के लिए अधिक रुपये की आवश्यकता थी जिसकी क्लार्ई के लिए फिर चांदी की मांग बढ़ी। इन कारणों से व्यापारिक सन्तुलन भारत के पक्ष में हो गया। दूसरी ओर स्वर्ण को प्राप्त करने में कठिनाईयाँ तथा चांदी की बढ़ती हुई मांग से चांदी की कीमतें बढ़ने लगीं। इससे विनिमय-दर भी बढ़ने लगी जो १९१५ में १६ पेंस प्रति रुपया से १९१६ में २८ पेंस प्रति रुपया हो गई। फलतः भारत में स्वर्ण-विनिमय प्रभाव दृष्ट गया।

इन विषय परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए सरकार ने निम्न पण उठाए—१ चांदी का क्रय, २. सिक्कों को चलाने पर रोक ३ चांदी को मितव्ययिता के लिए १ रु० तथा २॥) रु० के नोट चलाना, ४ स्वर्ण-मुद्रा की ढलाई, ५ पत्रमुद्रा का प्रसार, ६ विनिमय नियन्त्रण, ७ सरकारी धातु बढ़ाने एवं व्यय कम करने के प्रयत्न, ८ स्वर्ण के व्यक्तिगत आयात पर रोक ।

इससे भारतीय मौद्रिक कलेवर की स्थिति सँभल गई । युद्ध समाप्त होने पर सरकार ने वॉर्बिंगटन स्मिथ समिति की नियुक्ति की । इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं —

- १ रुपये की विनिमय-दर २ शि० स्वर्ण रखी जाय ।
- २ स्वर्ण के आयात निर्यात से प्रतिबन्ध हटाए जायें ।
- ३ सरकार पर रुपये को सॉवरेन में परिवर्तन करने की जिम्मेदारी न रहे ।
- ४ भारतीय चलन पद्धति को स्वयंपूर्ण बनाया जाय ।
- ५ चांदी के आयात से प्रतिबन्ध एवं आयात कर हटा दिये जायें तथा निर्यात पर कुछ समय तक प्रतिबन्ध रहे ।
- ६ मौसमी मुद्रा की पूर्ति के लिए निर्यात बिलों के आधार पर १ करोड़ रुपये की पत्रमुद्रा अधिक ढलाई जाय ।
- ७ भारत सरकार साप्ताहिक रूप में प्रति-परिषद-बिलों की बिक्री की राशि घोषित करे ।
- ८ सॉवरेन और अर्धसॉवरेन विधिग्राह्य घोषित किये जायें, इनकी ढलाई के लिए शाही टंकशाला की बम्बई शाखा फिर से खोली जाय ।
- ९ अरक्षित पत्र-चलन की सीमा १२० करोड़ रुपये रहे, आदि ।

इन सिफारिशों को सरकार ने मान लिया तथा क्षेत्र में कॉइनेज एक्ट ने संशोधन हुआ जिससे विनिमय दर २ शि० स्वर्ण घोषित की गई । परन्तु सरकार अनेक प्रयत्नों के बावजूद भी इस दर को स्थायी न बना सकी जिससे देश के उद्योग एवं व्यापार में उथल-पुथल हुई । अतः सरकार ने विनिमय-दर को मुक्त छोड़ दिया जो १९२५ में १ शि० २ पैसे पर स्थिर हो गई ।

हिल्टन यंग कमिशन (१९२५)—१९२५ की हिल्टन यंग कमिशन की स्थापना की गई जिसकी तीन विषयों के सम्बन्ध में सिफारिशें करनी थीं —

- १ विनिमय दर, २ केन्द्रीय बैंक की स्थापना तथा ३ मौद्रिक मान ।

इस कमोशन ने देश की वर्तमान मौद्रिक प्रणाली की आलोचना की तथा स्वर्ण खंड प्रमाण अपनाने की सिफारिश की, केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की तथा रुपये की विनिमय-दर १ शि० ६ पैसे स्वर्ण कायम करने की सिफारिश की। विनिमय-दर १८ पैसे हो अथवा १६ पैसे, इस सम्बन्ध में काफी वाद रहा परन्तु फिर भी सरकार ने १८ पैसे विनिमय-दर ही निश्चित की। इसी प्रकार सरकार ने कमोशन की अन्य सिफारिशों स्वीकार कीं तथा १९२७ के अधिनियम द्वारा देश में स्वर्ण-खंडमान को अपनाया।

१९२७ से १९२९ तक के दो वर्षों में हमारे आयात निर्यात बड़े परन्तु १९२९ की आर्थिक मन्दी से देश में व्यापारिक शिथिलता आ गई। सरकार ने बैंक रेट बढ़ाकर इसे रोकने का प्रयत्न किया परन्तु वह असफल रही। १९३१ में इङ्ग्लैण्ड ने स्वर्णमान का स्थापन किया तथा भारत सचिव के ऐलान से रुपये का मूल्य १ शि० ६ पैसे स्थिर निश्चित किया गया। हालाँकि रुपया-स्टैलिग-गठबन्धन का विरोध हुआ परन्तु वह बेकार ही रहा। इस गठबन्धन का परिणाम यह हुआ कि जैसे १९३१ में सोने का भाव बढ़ने लगा वैसे ही भारत से स्वर्ण का निर्यात होने लगा क्योंकि एक ओर कीमतें गिर रही थीं और दूसरी ओर सरकार मुद्रा-संकोच कर रही थी। स्वर्ण का यह निर्यात १९३९ तक बेरोक-टोक होता रहा जबकि दूसरे विश्वयुद्ध का भीगणेश हुआ।

## अध्याय १४

### भारतीय चलन-पद्धति (१९३६ से १९४५)

३ मितम्बर १९३६ को जब द्वितीय महायुद्ध की घोषणा की गई उस समय भारत में स्टर्लिंग-विनिमय मान था। भारत की प्रमाणित और प्रतीक मुद्रा के रूप में रुपया, पत्र-मुद्रा तथा भठन्त्रियाँ चलन में थीं, जो विदेशी भुगतान के लिए १८ पत्र स्टर्लिंग की दर से बेची अथवा खरीदी जा सकती थी। रुपया, अठन्नी तथा पत्र-मुद्रा अमीमित विधिग्राह्य मुद्राएँ थीं और देश में छोटी रकम के भुगतान के लिए निकेल की चर्कन्त्रियाँ, टुन्त्रियाँ, इकन्त्रियाँ एवं नावे के पैसे चलन में थे जो केवल एक रुपये तक विधिग्राह्य थे।

युद्ध आरम्भ होते ही ब्रिटिश साम्राज्य का अंग होन न भारत को भी युद्ध में भाग लेना पड़ा जिससे हमारी चलन एवं विनिमय-पद्धति पर बुरा परिणाम हुए तथा उनको दूर करने के लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन भी करना आवश्यक हुआ। युद्ध आरम्भ होते ही भारतीय चलन-पद्धति में कुछ अल्पवस्था भी आन लगी किन्तु बाद में इस युद्ध के दुष्कर परिणामों का अन्दी तरह सामना किया गया। हमारी चलन-पद्धति ने बदली हुई परिस्थिति से सीधे ही अपना मिलावट कर लिया। युद्ध के फलस्वरूप हमारी आर्थिक परिस्थिति पर बुरी तरह खिचाव पडा परन्तु फिर भी हमारी अर्थ-व्यवस्था को विशेष हानि नहीं हुई बल्कि फायदा ही हुआ। युद्ध के कारण हमारे उद्योग-धन्धों का प्रोत्साहन मिला, व्यापारिक गेय अनुकूल रहा और इस अनुकूलता के कारण बहुत बड़ी मात्रा में हम इङ्गलैण्ड से लेनदार रहे जो रकम पौंड-पावने (sterling balances) के रूप में इङ्गलैण्ड में जमा है। इस प्रकार इन महायुद्ध के कारण हमारी चलन-पद्धति पर निम्नलिखित परिणाम हुए —

१. युद्ध की सामग्री की पूर्ति करने के लिए सबसे प्रथम हमारे यहाँ के चलन का बड़ी मात्रा में विस्तार हुआ जिसमें पत्र मुद्रा का चलन १८२ ३६ करोड़ रुपये ने—जो १९३८-३९ में था—बढ़कर अर्ध १९४६ में १२७३ ७३ करोड़ रुपये हो गया। इससे हमारे यहाँ का मूल्य-स्तर भी बढ़ गया क्योंकि

जिस अनुपात में चलन का विस्तार होता गया उसी अनुपात में हमारे यहाँ उत्पादन वृद्धि नहीं हुई।

२ हमारी स्टलिङ्ग-प्रतिभूतियाँ बड़ी मात्रा में एकत्रित हो गईं क्योंकि इङ्ग्लैंड की ओर से भारत में युद्ध चलाने के लिए बड़ी मात्रा में सामान खरीदा गया था। ये पौट-पावने स्टलिङ्ग-प्रतिभूतियों में रिजर्व बैंक द्वारा खरीदे गये थे। इनकी रकम १९३८-३९ में ६६.६५ करोड़ रुपये थी जो मार्च १९४४ में ६४५ करोड़ तथा अप्रैल १९४६ में ११२५.३२ करोड़ रुपये हो गई थी। इसी प्रकार रुपये की प्रतिभूतियाँ १९३६ में १९४६ तक की अवधि में ३२.१६ करोड़ में ५७.८४ करोड़ रुपये हो गई थी।

३ युद्ध के कारण चलन-पद्धति एवं परिस्थिति में जो परिवर्तन हुए उनमें हमारे सामाजिक ऋण (public debt) का ढाँचा भी बदल गया।

### (क) युद्ध के तत्कालीन परिणाम

युद्ध प्रारम्भ होने ही तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि भारतीयों को मुद्रा-पद्धति में मन्य प्रतीत होने लगा जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा डाकघर-प्रमाणपत्र खचना शुरू किया और अपने डाकघर-वचत-बैंक लेले (P O savings bank a/c) में में तथा अन्य बैंकों से अपनी रकम निजालना शुरू किया। इस अविश्वास का कारण उन समय भारत रक्षण विधेयक (Defence of India Bill) का विचाराधीन होना भी था क्योंकि जनता का ऐसा खयाल था कि इन विधेयक के स्वीकृत होते ही वैयक्तिक सम्पत्ति पर सरकार का अधिकार हो जायगा। इस बदन्ता का सरकार की ओर से खण्डन किया गया तथा बैंकों और डाकघरानों में अपनी जमा राशि के भुगतान के लिए समुचित व्यवस्था की गई। इसमें हमारी चलन-पद्धति में नीध्र ही जनता का विश्वास हो गया। परिणामस्वरूप जनता ने बैंकों में रुपये निजालना बन्द कर दिया तथा बड़ी मात्रा में राष्ट्रीय सचय प्रमाणपत्र खरीदना शुरू किया।

इस अविश्वास के कारण लोगों ने अपनी पत्र-मुद्रा का रुपये में परिवर्तन कराना शुरू किया और जून १९४० तक प्रति सप्ताह १ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्रा के बदले रुपये दिये गये। मई १९४० में युद्ध का पासा इङ्ग्लैंड के विरुद्ध फलटता हुआ दिखलाई देने लगा और जून १९४० में फ्रांस की हार के साथ भारतीय जनता का अविश्वास फिर से जाग्रत हुआ। इस कारण प्रति सप्ताह ४ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्रा चाँदी के रुपये में बदली जाने लगी

जिससे रिजर्व बैंक के चलन-विभाग में ७१'४७ करोड़ रुपये की जगह, जो मुद्रा के आरम्भ में थे, ५ जुलाई १९४० को केवल ३२ करोड़ रुपये रह गये। इस प्रकार पत्र-मुद्रा के बदले में जो चाँदी के रुपये जनता के पास जाते थे वे चलन में न रहते हुए भूमिगत होने लगे अथवा उनको गलाया जाने लगा फलतः रुपये का अभाव भी हो गया। इस अभाव में सरकार की ओर से सुरक्षा के लिए जो व्यवस्था किया जा रहा था उसमें और भी तीव्रता आई तथा मूल्य गिरने की एवं व्यापारिक अव्यवस्था (trade dislocation) की सम्भावना प्रतीत होने लगी। इसलिए सरकार द्वारा भारत-सुरक्षा विधान के अन्तर्गत एक आदेश निचाला गया कि कोई भी व्यक्ति ऋण अथवा अन्य भुगतान में पत्र-मुद्रा तथा रुपये लेना अस्वीकार नहीं कर सकता। २५ जून १९४० को रुपये के नियन्त्रण की योजना शुरू हुई जिसके अनुसार घोषणा की गई कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक रुपये या मुद्राएँ लेगा वह भारत-सुरक्षा विधान के अन्तर्गत दण्ड का अधिकारी होगा—व्यक्ति अथवा व्यापारिक आवश्यकता। कितनी है, इसका निर्णय रिजर्व बैंक करेगा। परिणामतः पत्र-मुद्रा के बदले अब कम रुपये माँगे जाने लगे, लेकिन रुपये की माँग अब अन्य उपायों से पूरी की जाने लगी और पत्र-मुद्रा कई स्थानों पर बट्टे से बिकने लगी। रुपये की कमी को दूर करने के लिए २४ जुलाई १९४० के आदेश द्वारा भारत सरकार को एक रुपये की पत्र-मुद्रा चलन में खाने का अधिकार दिया गया जो सब कार्यों के लिए रुपये के बराबर घोषित की गई।

२६ जुलाई १९४० के भारतीय टकन-संशोधन विधान के द्वारा चवन्नियों तथा अठन्नियों की चाँदी का परिमाण २½ से ३ कर दिया गया। २५ दिसम्बर १९४० के आदेशानुसार रुपये में भी चाँदी के परिमाण में ऐसी ही कमी की गई। इसके बाद १९४२-४३ में छोटी प्रतीक मुद्राओं की भारी कमी का अनुभव हुआ क्योंकि तब के पैसे भी गलाये जाने लगे या भूमिगत किये जाने लगे। इस अभाव को दूर करने के लिए बम्बई, कलकत्ता, कानपुर आदि बड़े-बड़े शहरों में टाक टिकटो का भी उपयोग किया गया। इस प्रकार छोटी मुद्राओं का चलन से बाहर जाना रोकने के लिए भारत-सुरक्षा विधान के अन्तर्गत अधिक रेजगारी का सचय एवं अपने पास रखना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया। इस प्रकार रेजगारी की माँग को पूरा करने के लिए सरकार ने १९४२ में गिल्ट का अवज्ञा, द्वान्नियाँ, दुन्नियाँ भी चलाई। १९४३ में नया पैसा भी चलाया गया जिसका वजन कम था तथा बीच में

देद या परन्तु इसका उपयोग वासर की तरह किया जाने लगा । इस कारण सरकार ने इसका चलन बन्द कर दिया । इसके सिवा रजगारी के अभाव को मिटाने के लिए बम्बई और कलकत्ता की टक्कालाओं में पैसे ढाले जाने लगे जिनका औसत ७२० लाख प्रति मास था । ( यही औसत १९३३ में १६० लाख था । ) फिर भी पैसे का अभाव रहा और लाहौर में एक नई टक्काला स्थापित की गई जहाँ अगस्त १९४२ से सिक्के डालना प्रारम्भ हुआ ।

फिर भी रुपये का अभाव रहा जिसे दूर करने के लिए १ फरवरी १९४३ से दो रुपये की पत्र-मुद्राओं का चलन भी प्रचलित किया गया तथा १९४३ के अन्त तक १४० लाख रुपये की २) ६० की पत्र-मुद्राएँ बम्बई, कानपुर, लाहौर और कलकत्ता से चलन में आईं । इस प्रकार की अथवा इनके सहित अन्य पत्र-मुद्राएँ बनाना एवं चलाना भी दण्डनीय अपराध घोषित किया गया । १९४० के भारतीय टक्का-मसोधन विधान के अन्तर्गत विक्टोरिया की मुद्रा के रुपये तथा अठन्नियाँ भी ३१ मार्च १९४१ के बाद विधिप्राप्त न रहेंगी, यह भी घोषित किया गया और उनको चलन से निकालने के हेतु ३० सितम्बर १९४१ तक उनकी स्वीकृति डाकघर तथा सरकारी कार्यों में होगी, यह भी घोषित किया गया । ३० दिसम्बर १९४० को टक्का-विधान में लीमरा मसोधन हुआ जिसके अनुसार नये रुपये, जिनके किनारे किटकिटीदार तथा बीच में रस्ता बाने थे, चलाये गये । इनमें चाँदी का परिमाण ६० ग्रैन् अथवा ३ भाग रहा तथा इस 'नई किटकिटी' के कारण जाली सिक्के बनाना कठिन हो गया । ८ दिसम्बर १९४१ को एडवर्ड सप्तम की मुद्रा वाले रुपये तथा अठन्नियाँ १ जून १९४२ से अवैधानिक घोषित कर दी गईं तथा यह भी घोषित किया गया कि इनकी स्वीकृति ३० सितम्बर १९४२ तक सरकारी कार्यों एवं डाकघरों में की जायगी, एवं मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में रिजर्व बैंक में ये तब तक लिये जायेंगे जब तक इनकी अस्वीकृति की सूचना घोषित नहीं होगी । इसी प्रकार १ अक्टूबर १९४२ से जॉर्ज षष्ठम् एवं एडवर्ड की मुद्रा वाली अठन्नियाँ एवं रुपये जो ३ भाग चाँदी के थे, उनका चलन से हटाने के लिए १ मई १९४३ से उन्हें भी अवैधानिक घोषित कर दिया गया । फिर भी ये सरकारी कार्यों में एवं डाकघरों में २१ अक्टूबर १९४३ तक तथा बम्बई, मद्रास व कलकत्ता की रिजर्व बैंक की शाखाओं में आगामी सूचना तक दिव्य जा सकते थे । इन रूपों के बदले जॉर्ज एडवर्ड के नये रूप जिनमें ३ भाग चाँदी थी, चलन में लाये गये ।

१ मई १९४२ से विक्टोरिया तथा एडवर्ड मण्टम् के रुपये एवं अठन्नियाँ तथा १ नवम्बर १९४३ से जॉर्ज पचम् और जॉर्ज षष्ठम् के रुपये एवं अठन्नियाँ ( जिनमें ३/३ भाग चाँदी थी ) भारत में अवैध घोषित किये गये । १९४३ से १९४६ तक कुल ५६८ २६ करोड़ रुपये चलन में निकाल लिये गये तथा नये रुपये और पत्र-मुद्राएँ चलन में आईं ।

युद्ध के प्रारम्भ होते ही जो मुद्राओं की कमी परिवर्तन के कारण प्रतीत होने लगी थी वह समय-समय पर आवश्यक आदेशानुसार पूरी की गई तथा सामयिक परिस्थिति से मिलान करने के लिए, चलन-पद्धति में भी परिवर्तन किया गया । युद्ध-काल के पाँच वर्षों ( १९३९-४० में १९४३-४४ ) में ही हमारे यहाँ का चलन ६१ ७४ करोड़ से ८८४ ६३ करोड़ हो गया । इसके विपरीत रिजर्व बैंक के पास जो स्वर्ण था वह ४४ ४१ करोड़ ही रहा तथा चाँदी की मात्रा ७५ ८७ करोड़ से केवल १५ ६ करोड़ रुपये की ही रह गई । इसी प्रकार प्रतिभूतियों का परिमाण अपरिमित बढ़ गया । इन प्रतिभूतियों में अधिकतर स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ थी जिनका अवमूल्यन हो रहा था और स्टर्लिंग का स्वर्ण-मूल्य न होने के कारण हमारे देश में मुद्रा-स्फीति के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगे ।

### (ख) व्यापारिक स्थिति

युद्ध के फलस्वरूप हमारी व्यापारिक स्थिति में भी काफी परिवर्तन हुआ तथा विदेशी व्यापार में हमारे आयातों से निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ने लगे । इसका प्रमुख कारण तो यह था कि हमारे यहाँ की आयात-वस्तुओं में बहुत कमी हो गई क्योंकि युद्धग्रस्त देश युद्ध के लिए माल बनाने में लगे हुए थे । दूसरे, युद्ध-सामग्री के स्थानान्तरण के लिए यातायात का उपयोग पूर्णरूप से किया जा रहा था इसलिए उपभोग की वस्तुओं के स्थानान्तरण पर भी यातायात की कमी के कारण प्रतिबन्ध लगाये गये थे । तीसरे, विदेशी भुगतान के लिए विदेशी मुद्राओं की प्राप्ति भी युद्ध-परिस्थिति के कारण उतनी आसानी से नहीं हो सकती थी । इसके अतिरिक्त हमारे निर्यातों पर प्रतिबन्ध लगाये गये थे जिनसे कि वे विशिष्ट मार्गों द्वारा ही निर्यात किये जा सकें और उनका पूर्ण उपयोग केवल मित्र राष्ट्रों द्वारा ही हो सके । इस वजह से इस काल में भारत से निर्यात बढ़ता ही गया तथा हमारे व्यापारिक शेष में जो १९३८-३९ में केवल १७ करोड़ रुपये की अनुकूलता थी वह १९३९-४० में ४६ करोड़ रुपये, १९४०-४१ में ४२ करोड़ रुपये तथा १९४३-४४ में ६० करोड़ रुपये

हा गई। इस बड़ी मात्रा में विदेशी निर्यात के कारण हमारे यहाँ कीमतों में वृद्धि हुई तथा व्यापारिक शेष की अनुकूलता के कारण रुपये की १८ पैसे की दर में भी स्थिरता आने लगी। व्यापारिक शेष की अनुकूलता के कारण हमारा इंग्लैंड पर बहुत बड़ी मात्रा में 'पौड-पावना' है जो 'स्टर्लिङ वेलेन्सेज' के नाम से इंग्लैंड में भारत सरकार की ओर से जमा है।

### (ग) विनियम-नियन्त्रण

भारत-मुराहा विधान के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वह विदेशी विनियम के सब प्रकार के व्यवहारों का, स्वयं एक प्रतिभूतियों का, नियन्त्रण करे। परिणामस्वरूप रिजर्व बैंक में 'विनियम-नियन्त्रण विभाग' विभाग खोला गया जो विनियम-नियन्त्रणों की सामग्रीय कार्यवाही को करता था। यह अधिकार १९३६ में प्रदान किये गये थे। इस अधिकार द्वारा रिजर्व बैंक ने अनुज्ञापन (licence) प्राप्त किये बिना, स्वयं का आयात एक निर्यात करने पर प्रतिबन्ध लगा दिये जो ४ मितम्बर तथा १६ अक्टूबर १९४० से लगाये गये तथा मार्च १९४१ के बाद रिजर्व बैंक की पूर्ण अनुमति प्राप्त किये बिना स्वयं के किसी भी रूप में निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया। इसी प्रकार जो देश ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं थे उनकी मुद्राओं के क्रय-विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाये गये जिसके अन्तर्गत इन मुद्राओं का क्रय-विक्रय केवल व्यापारिक कार्यों के लिए, प्रवास-व्यय के लिए तथा कुछ वैधानिक भुगतान के लिए ही किया जा सकता था और इस प्रकार के सब व्यवहार 'धन के विनियम-नियन्त्रण' की आधारभूत दूरों पर ही किये जा सकते थे। ब्रिटिश साम्राज्य के देशों की मुद्राओं का क्रय-विक्रय केवल अधिकृत बैंकों द्वारा ही किया जा सकता था जिससे इन मुद्राओं का क्रय-विक्रय भी नियन्त्रण में रहे। विनियम-नियन्त्रण की कार्यशीलता के लिए निम्न नियन्त्रण लगाये गये—

१ स्वतन्त्र स्टर्लिङ क्षेत्र का विस्तार—यह क्षेत्र उन देशों का बना हुआ है जो ब्रिटिश साम्राज्य में हैं तथा इन देशों में पूँजी का आयात-निर्यात अप्रतिबन्धित अर्थात् बिना किसी रोक-टोक के हो सकता है। इस क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत देशों—सिन्ध, सीरिया, मेडागास्कर, ईराक आदि—का समावेश होता है।

२ विदेशी विनियम के उपयोग पर नियन्त्रण—इस योजना के अनुसार हमारे निर्यात का विदेशी मुद्रा में जो मूल्य होता था उसका उपयोग ब्रिटिश राज्य-सम की अधिक से अधिक हो, इस हेतु इस प्रकार प्राप्त की हुई विदेशी

मुद्राओं का उपयोग रिजर्व बैंक के मतानुसार होना था। इस योजना के अन्तर्गत १० मई १९४० से विनास की वस्तुओं के आयात पर नियन्त्रण लगाया गया तथा उपभोग-वस्तुओं का आयात केवल स्टलिंग-क्षेत्रों तक ही मर्यादित किया गया। इसी प्रकार विदेशी मुद्राओं के विव्रय—विशेषतः दुर्लभ मुद्राओं के विक्रय—पर नियन्त्रण लगाये गये। इन नियन्त्रणों का हेतु यही था कि युद्ध-जन्य सामग्री जो अमेरिका आदि देशों से आयात की जाती थी, उनकी प्राप्ति बिना कठिनाई के हो सके। विदेशी मुद्रा का युद्ध-कार्य के लिए अधिकाधिक उपयोग करने के हेतु रिजर्व बैंक से अनुज्ञापत्र प्राप्त किये बिना चाँदी के आयात पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये। राष्ट्रीय हित की दृष्टि से डॉलर का अन्धे से अचछा उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय लाभ के लिए, जो प्रवासी जाते थे उनको ही डॉलर बेचे जा सकते थे। इन प्रतिबन्धों में १९४४-४५ में युद्ध की समाप्ति के बाद ही छूट दी गई जिससे विद्यार्थियों, व्यापारियों तथा प्रवासियों को सुविधा एवं उपभोग-वस्तुओं का आयात हो सके।

३. डॉलर एवं डॉलर प्रतिभूतियों पर अधिकार (Acquisition of Dollar Balances and Securities)—इसी प्रकार डॉलर का अधिकाधिक उपयोग करने के हेतु भारतीयों की जो रकमे अमेरिका में डॉलर-क्षेप के रूप में अथवा अमरीकी प्रतिभूतियों में थी उन पर भी रिजर्व बैंक ने अधिकार किया तथा उनके बदले रुपये में भारत में भुगतान किया गया।

४. मुद्रा, पत्र-मुद्रा आदि के आयात-निर्यात पर रोक—किसी भी प्रकार की भारतीय मुद्रा को रिजर्व बैंक के अनुज्ञापत्र के बिना निर्यात करने पर, नवम्बर १९४० से प्रतिबन्ध लगाया गया जिससे भारतीय मुद्रा चलन से निकल कर बाहर न बेची जा सके। उसी प्रकार नितम्बर १९४३ से भारतीय मुद्रा, ईरानी रॉयल, अफगानी रॉयल तथा लका की पत्र-मुद्रा के अतिरिक्त सब प्रकार की मुद्रा के आयात पर भी प्रतिबन्ध लगाये गये और जनवरी १९४४ से भारतीय पत्र-मुद्रा के अतिरिक्त अन्य सब पत्र-मुद्राओं के आयात पर भी रोक लगा दी गई। इसका हेतु शत्रु-राष्ट्रों द्वारा चलाई गई पत्र-मुद्रा को रोकना तथा अपनी मुद्रा का उपयोग शत्रु-राष्ट्रों को न होने देने का था।

५. विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर भी अक्टूबर १९४१ से प्रतिबन्ध लगा दिये गये जिससे जो कम्पनियाँ भारत से अपने लाभ स्टलिंग क्षेत्र के बाहर भेजना चाहती थी वे लाभ को न भेज सकें। ऐसे लाभों को स्टलिंग क्षेत्र से बाहर भेजने के लिए रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना जरूरी था। इन नियन्त्रणों

का हेतु विदेशी मुद्राओं का उपयोग युद्धकार्यों के लिए भरी भाति करना था। य प्रतिबन्ध १९४३ ४४ में टोन कर दिया गया जिसमें अमरीकी कम्पनिया अपना लाभ भेज सक।

६ शत्रु सम्पत्ति पर अधिकार—इसी प्रकार जुनाइ १९४१ में भारत मित जापानी कम्पनिया तथा व्यवसायों का सम्पत्ति का भी भारत सरकार ने सुरक्षा विधान के अन्तर्गत अपने अधिकार में ले लिया तथा उनका व्यवस्था शत्रु सम्पत्ति-नरक्षक (custodian) का सापेक्ष किया गया जिसमें इस सम्पत्ति का उपयोग मित्रराष्ट्रों के विरुद्ध नहीं हो सक। इस प्रकार विदेशी नागरिकों का जो धन भारतीय बैंकों में था उसका भुगतान पर भी कुछ विधायक कार्यों के अनिर्दिष्ट रिजर्व बैंक ने राख रखा।

इसके अनिर्दिष्ट युद्ध-काल के सम्पत्ति-नरक्षण तथा उसके भुगतान और रुपये की ऋण प्रतिभूतियाँ में परिवर्तन किया गया। यद्वा ऋण १९२८-२९ में १९६५ कराड़ रुपये था जो १९४३ ४४ में केवल १४ कराड़ रुपये रह गया। रिजर्व बैंक की १९४५ ४६ की रिपोर्ट के अनुसार ३०० कराड़ पौंड के ऋण का भुगतान किया गया तथा बाकी ऋणों का रुपये की ऋण प्रतिभूतियाँ में जिनका मूल्य ४३५३ कराड़ रुपये है बढ़ा दिया गया।

इस प्रकार युद्ध-काल में विविध नियन्त्रण की नयी पद्धति चालू की गयी तथा कुछ हद तक राज भी विविध नियन्त्रण चालू है।

### (घ) कर-वृद्धि

देश की रक्षा के हेतु तथा युद्ध-संचालन के लिए भारतीय रक्षा पर प्रति दिन २० लाख रुपये का व्यय होना था जिसकी पूर्ति करने के लिए भारत सरकार का नय-नय कर लगान पड़े तथा करा में वृद्धि भी करना पड़ा। १९४० से आय-कर के साथ २५ प्रतिशत अनिर्दिष्ट कर (surcharge) लगा दिया गया तथा पाय् काट आदि के मूल्यों में भी वृद्धि की गयी। १९४० में अधिक-लाभ कर (excess profit tax) का भा ५० प्रतिशत में बढ़ा कर ६६ २/३ प्रतिशत कर दिया गया तथा अनिर्दिष्ट-कर भी २५ प्रतिशत में २७ ३/४ प्रतिशत हो गया। अनेक वस्तुओं जैसे शक्कर, दिव्यमानाई आदि, के चुल्हा करा (excise duty) में वृद्धि की गयी। इस प्रकार करा से होने वाला आय भी ८६ ६३ कराड़ रुपया (१९३६ ४०) में वर्ष १९४५ ४६ में ४३ ३४ कराड़ रुपये हो गया।

युद्ध-व्यय की पूर्ति के लिए सरकार को विभिन्न प्रकार के ऋणपत्र भी

निकालने पड़े और इन ऋणपत्रों के द्वारा सरकार ने लगभग २८४ करोड़ रुपया उधार लिया। इन ऋणपत्रों के द्वारा लोगों के हाथ में जो अतिरिक्त क्रयशक्ति थी वह सरकार के पास आ जाने से कुछ हद तक मुद्रास्फीति से होने वाले परिणाम भी न हो सके।

### (द) युद्धकालीन मुद्रा-स्फीति

हमने देखा कि युद्ध-काल में रुपयों का चलन बहुत अधिक बढ़ गया था, परन्तु देश की उत्पादन-शक्ति उसी अनुपात में न बढ़ी। इसके अलावा भारत सरकार ने युद्ध को चलाने के लिए इङ्ग्लैंड के आदेशों के अनुसार माल का निर्यात भी किया, जिससे भारत में आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गयी थी। इन दोनों कारणों का परिणाम यह हुआ कि मुद्रा की न्ययशक्ति घट गयी अर्थात् वस्तुओं के भाव बढ़ने लगे। इसका प्रमुख कारण यह था कि युद्ध-काल में मुद्रा और माल दोनों का ही इतना अधिक प्रसार हुआ जिससे जनता की त्रयशक्ति तो बढ़ गयी थी परन्तु वस्तुओं का प्रदाय (supply) घट गया था। युद्धकालीन पत्र-चलन में कितना प्रसार हुआ तथा उसके साथ ही वस्तुओं के मूल्य किस प्रकार बढ़े इसकी यथार्थ कल्पना निम्न तालिका में की जा सकती है —

वर्ष	पत्रमुद्रा जो चलन में थी <sup>१</sup> (करोड़ रुपयों में)	मूल्य-निर्देशांक <sup>२</sup>
अगस्त १९३६	१७६	१००
मार्च १९३६-४०	२३८ ५५	१२५ ६
„ १९४०-४१	२५७ ६६	११४ ८
„ १९४१-४२	४१० ०७	१३७ ०
„ १९४२-४३	६४३ ५८	१७१ ०
„ १९४३-४४	८८२ ४६	२३६ ५
„ १९४४-४५	१०८४ ८८	२४४ २

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब और तो देश में पत्र-मुद्राओं का चलन बढ़ता जा रहा था और दूसरी ओर वस्तुओं की कीमत बढ़ती जा रही थी। इस प्रकार कुछ समय तक देश में मुद्रास्फीति का

<sup>१</sup> See Statements 36 and 15 Report of the Reserve Bank of India on Currency & Finance for 1951-52

<sup>२</sup> Economic Adviser's Index Numbers (नियंत्रित मूल्यों के अनुसार)

भारत न हुआ परन्तु देश के अर्थशास्त्रियों ने, प्रमुखतः प्रो० सी० एन० वकील ने, १९४३ में इस बात की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि देश में मुद्रास्फीति के स्पष्ट चिह्न दिखाई देने लगे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि समय रहते इस पर नियन्त्रण न किया गया तो भीषण परिणाम होंगे। इस पर भी १९४३-४४ का बजट-भाषण देने हुए अथमनी सर आर्चिबाल्ड रोनेड ने कहा कि "भारत में मुद्रास्फीति नहीं है।" उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि "वर्तमान स्थिति केवल मुद्रा प्रसार की है जिसका कारण है जनता द्वारा रोकड़ की बढ़ी हुई माँग।" इसका बाद मुद्रास्फीति को लेकर विभिन्न लोगों ने विभिन्न विचारधाराएँ प्रकट की। श्री घनश्यामदास बिडला के अनुसार कीमते घटने का कारण भारत में मुद्रास्फीति न होने हुए वस्तुओं की कमी थी और अर्थशास्त्रियों के अनुसार मुद्रास्फीति हानि का कारण कीमत बढ़ रही थी। इण्डियन चैम्बर ऑफ कामर्स ने सरकार का ध्यान मुद्रास्फीति की ओर आकर्षित किया। रिजर्व बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में यह मान लिया कि मुद्रा-प्रसार के कारण मुद्रास्फीति हो रही है परन्तु मुद्रा-प्रसार का रोकने में रिजर्व बैंक ने अपनी असमर्थता प्रकट की। इस प्रकार मुद्रास्फीति भारत को द्वितीय विश्वयुद्ध की प्रमुख दान है।

युद्धकालीन मुद्रास्फीति के निम्नलिखित कारण थे —

१. मित्रराष्ट्रों की सहायता—युद्ध काल में भारत सरकार इंग्लैण्ड और मित्रराष्ट्रों की सहायता के लिए भारत में माल खरीद-खरीद कर भेजती रही जिससे युद्ध-संचालन में सहायता हो। इस माल के भुगतान में भारत को स्वर्ण मिलना चाहिए था अथवा माल, परन्तु इंग्लैण्ड आदि देशों के युद्ध में फँस होने के कारण भारत को माल नहीं मिल सकता था और इंग्लैण्ड स्वर्ण देने की स्थिति में नहीं था। इसलिए इसकी राशि बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में भारत सरकार के खाते में जमा होती रही जिसके बदले में रिजर्व बैंक को स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ मिलती थीं। भारतीय व्यापारियों को उनके माल का भुगतान करने के लिए रिजर्व बैंक इन स्टर्लिंग प्रतिभूतियों के आधार पर पत्र-मुद्राएँ छाप कर उनका भुगतान करता रहा, जिससे स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ बढ़ने के साथ ही माध्यम-चलन भी बढ़ता जा रहा था। इन्हीं स्टर्लिंग प्रतिभूतियों को पौंड-पावनों (sterling balances) के नाम से जाना जाता है।<sup>१</sup> यदि भारत को स्वर्ण अथवा वस्तुएँ मिलती रहनी तो भारत में मुद्रास्फीति न होती।

<sup>१</sup> देखिये अध्याय १६।

२. अनुकूल व्यापार सन्तुलन—युद्ध-काल में विदेशी व्यापार का सन्तुलन भारत के पक्ष में हो गया अथवा भारत के अनुकूल रहा। क्योंकि भारत से निर्यात तो अधिक हो रहे थे परन्तु यूरोपीय देशों के युद्ध में फँसे हुए होने के कारण आयात कम हो गया। इस प्रकार युद्ध-काल में भारत का व्यापार-सन्तुलन हमारे पक्ष में रहा —

वर्ष	व्यापार-सन्तुलन* (करोड़ रुपया में)
१९३८-३९	+ १७.६९
१९३९-४०	+ ४८.८१
१९४०-४१	+ ४१.९६
१९४१-४२	- ७९.६०
१९४२-४३	- ८४.२५
१९४३-४४	+ ९१.३०
१९४४-४५	+ २६.०८

इसके अतिरिक्त भारत का रटलिंग प्रतिभूतियाँ मिली और इनके आधार पर पत्र-मुद्राओं का चलन बढ़ता गया।

३. सुरक्षा-व्यय में वृद्धि—युद्ध-काल में भारत सरकार का रक्षा व्यय भी बढ़ता गया। १९३८-३९ में जो व्यय ४८.१८ करोड़ रुपय था, वह १९४५-४६ में ३९५.४९ करोड़ रुपय हो गया। इस व्यय को पूरा करने के लिए भी पत्र-चलन बढ़ाया गया। युद्ध-काल में रक्षा-व्यय जितना हुआ वह निम्न तालिका से स्पष्ट होगा —

वर्ष	रक्षा-व्यय (करोड़ रुपया में)
१९३८-३९	४६.१८
१९३९-४०	४९.६४
१९४०-४१	७३.६१
१९४१-४२	१०३.९३
१९४२-४३	२१४.६०
१९४३-४४	३५८.४०
१९४४-४५	३९५.४९

योग १०४१.८७

\* Reports on Currency & Finance (1938-39 onwards) of the Reserve Bank of India for respective years

इस व्यय को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ने स्टैनिंग प्रतिभूतियाँ के आधार पर पत्र-मुद्राएँ छापीं, परन्तु माय ही कोष-विपत्रों (treasury bills) के आधार पर भी पत्र-मुद्राएँ चलायीं। इस प्रकार कोष-विपत्रों के आधार पर पत्र चलन करने की क्रिया को प्रो० सी० एन० वकील ने 'नग्न मुद्रास्फीति' (inflation in its naked form) कहा है, जिसके परिणाम भारतीय ग्रथ-व्यवस्था पर भीषण हुए हैं। इस प्रकार जहाँ १९३८-३९ में रिजर्व बैंक के 'चलन-विभाग' में ३७४४ करोड़ रुपये के कोष-विपत्र थे वे बढ़ने-बढ़ते १९३९-४०, १९४०-४१, १९४१-४२ और १९४२-४३ में क्रमशः ३७४४, ४८४६, ७५१९ और १३९९८ करोड़ रुपये के हो गए थे।<sup>१</sup> यही कोष-विपत्रों की राशि युद्ध समाप्त होने के समय १९४४-४५ में घटकर ५७६५ करोड़ रुपये रह गयी थी।

४ वस्तुओं की दुर्लभता—एक ओर तो पत्र-मुद्रा-प्रसार के कारण जनता की क्रयशक्ति बढ़ती जा रही थी और दूसरी ओर आवश्यकता की वस्तुओं का निर्यात युद्ध-कार्यों के लिए होना रहने के कारण वे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रही थी जिसमें माँग एवं पूर्ति का मन्तुलन नष्ट हो गया तथा आवश्यक वस्तुओं का अकाल पड़ गया। इसी कारण बगाल का भीषण अकाल भी हुआ जिसमें किसी भी दामो पर अन्न नहीं मिल रहा था और मुद्रा-प्रसार होने हुए भी जनता के पास उसे खरीदने के लिए क्रयशक्ति नहीं थी।

समस्या की हल करने के प्रयत्न—मुद्रास्फीति के जो परिणाम होने थे वही हुए। सरकार ने युद्ध आरम्भ होने ही मूल्य-वृद्धि को रोकने के लिए मुरझा-विधान के अनुसार ३ मितम्बर १९३९ को प्रान्तीय सरकारों को खाद्यान्न, दवाइयाँ, रसायन, कपड़ा आदि आवश्यकता की वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निश्चिन करने का आदेश दिया था, जिसमें इन वस्तुओं की कीमते १ मितम्बर १९३९ के मूल्यों में १०% से अधिक न बढ़ने पायें। इस आदेश पर तुरन्त कार्यवाही भी की गयी परन्तु मूल्य-वृद्धि को न रोका जा सका और बगाल में जो भीषण अकाल हुआ उस पर सरकार की निष्प्रियता की बुरी तरह आलोचना होने लगी। इसलिए सरकार न उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों, श्रमिक-संघ आदि समाज के विभिन्न वर्गों की सभाएँ की जिनमें इस समस्या के हल पर विचार

<sup>१</sup> See Statement 40 Report of Reserve Bank of India on Currency & Finance for 1951-52

किया गया। विभिन्न वर्गों ने गमस्या को हल करने के लिए अलग-अलग उपाय बताये परन्तु सब ने एकमत में यह कहा कि वस्तुओं की कीमतें बढ़ गयी हैं और उन्हें रोकना आवश्यक है। कीमतें बढ़ जाने से जीवन-व्यय बढ़ गया था परन्तु आम जनता की आय वहीं रहने से जीवन-निर्वाह कठिन हो गया था। वस्तुओं की कीमतों के कारण कीमत और अधिक बढ़ने लगी और व्यापारिक समाज और सेवक वर्ग में चोरबाजारी, भ्रष्टाचार, सट्टा, अनैतिकता आदि का धोलबाता हो गया था। अतएव

(१) सरकार ने सभी वर्गों के मुभावों पर विचार कर मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण लगाकर वितरण का प्रबन्ध भी अपने हाथ में ले लिया। फलस्वरूप दिसम्बर १९४२ से अन्न-वितरण का श्रोगणश हुआ, जिसमें हम सभी परिचित हो चुके हैं। इसी समय देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए 'अधिक घन उपजाऊ भूमि' का आरम्भ किया गया जिसमें देश में अन्न की कमी न रहे।

(२) सरकार ने जनता की अनिश्चित क्रयशक्ति को अथवा मुद्रा को वापिस लेने के लिए वचत बैंकों में प्रति व्यक्ति निक्षेप (deposit) की सीमा भी ₹००० रु० से बढ़ाकर ₹१०००० रु० कर दी। नये-नये कर भी लगाय गये।

(३) कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश भी सीमित कर दिये गये जिसके अनुसार कोई भी कम्पनी ६% में अधिक लाभांश का वितरण नहीं कर सकती थी।

(४) जनता के पास की मुद्रा खींचने के लिए सरकार ने जनता से ऋण लेना शुरू किया तथा रिजर्व बैंक द्वारा स्वर्ण की बिक्री भी की गयी।

(५) केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों ने अपने अपने व्यय कम करके बजट को संतुलित करने के प्रयत्न भी किये तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्तीय सरकारों को दी जाने वाली सहायता भी कम कर दी गयी।

(६) देश में उपभोग्य माल के अभाव को मिटाने के लिए सरकार ने अपनी आयात नीति भी ढीली कर दी जिससे देश में अधिक माल का आयात होकर जनता की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सरकार ने उद्योगों को अनेक सुविधाएं दी, जिसके अनुसार उद्योगों को आवश्यक माल जैसे लोहा, सीमेंट आदि नियन्त्रित कीमतों पर देने का प्रबंध किया गया। नये उद्योगों की स्थापना के लिए उनको बाहर से पूंजीगत माल आयात करने के लिए सुविधाएं दी गयी तथा पूंजीगत माल के आयात को

आयात-कर में मुक्त कर दिया गया। नये उद्योगों को ५ वर्ष तक आयात-कर से भी मुक्त कर दिया गया।

इन विविध प्रयत्नों में देश में नये-नये उद्योग खुले तथा उन में देश का उत्पादन भी बढ़ा परन्तु मुद्रास्फीति बनी ही रही और कीमतें भी बढ़ती ही रहीं। मितम्बर १९४५ में युद्ध की समाप्ति हुई जिससे जनता को यह आशा हुई कि अब स्थिति सुधर जायगी परन्तु वह सुधरने की बजाय बिगड़ती ही गयी। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि मुद्रास्फीति के जितने बुरे परिणाम ब्रिटिश साम्राज्यान्तर्गत राष्ट्रों को भुगतन पड़े, उतने इंग्लैंड को नहीं। इंग्लैंड अब अमेरिका में जहाँ मूल्यस्तर नमम ७०% तथा ३९% में बढ़े, वहाँ भारत में १९४४ में लगभग २०० प्रतिशत में मूल्यस्तर बढ़े। इसका कारण यह था कि भारत ने (जैसा कि हमने देखा) स्टलिंग प्रतिभूतियों को खरीदकर उनके आधार पर यहाँ पत्र-चमन बढ़ाया। स्टलिंग प्रतिभूतियों में हमारा यह विनियोग गच्छिक्क न होने हुए जबरदस्ती था।<sup>१</sup> इस प्रकार इंग्लैंड की मुद्रास्फीति का प्रभाव साम्राज्य के अधीन देशों में बाँट दिया गया।

### माराण

दूसरा युद्ध आरम्भ होते ही भारत को भी ब्रिटिश साम्राज्य का अंग होने के कारण उत्तम भाग लेना पड़ा जिससे हमारी चलन एवं विनिमय-पद्धति पर घोर परिणाम हुए। आरम्भ में कुछ अन्वयवस्था सी आने लगी परन्तु चलन-पद्धति में अपना मिलान परिस्थिति के साथ किया। युद्ध के कारण निम्न परिणाम हुए :—

- १ चलन का विस्तार हुआ जिससे कीमतें बढ़ीं।
- २ स्टलिंग प्रतिभूतियों की राशि में वृद्धि हुई।
- ३ सामाजिक ऋण के ढाँचे में परिवर्तन हुआ।

युद्ध के तत्कालीन प्रभाव—युद्ध के कारण जनता का चलन-पद्धति में अविश्वास हो गया जिससे जून १९४० तक साप्ताहिक १ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्रा का रूपों में परिवर्तन हुआ। ये रुपये भूमिगत होने लगे। सरकार का सुरक्षा व्यय बढ़ने लगा। इसलिए भारत सुरक्षा कानून के अन्तर्गत सरकार ने घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति पत्रमुद्रा का रूपों में भुगतान लेने से इन्कार नहीं कर सकता। इसी प्रकार आवश्यकता से अधिक रुपये या मुद्राएँ लेना

<sup>१</sup> *Eastern Economist*—July 5, 1941 quoted from *War & Indian Policy* by D. R. Gadgil, p. 5

दण्डनीय घोषित किया गया। साथ ही रुपये की कमी को दूर करने के लिए १ रु० के नोट चलाने का अधिकार सरकार को मिला। फरवरी १९४३ में २ रु० के नोट भी चलाये गये।

जुलाई १९४० में अठन्नी और चवन्नियों में तथा दिसम्बर १९४० में रुपये में चाँदी का अंश  $\frac{1}{2}$  से  $\frac{1}{4}$  कर दिया गया। ११ अक्टूबर १९४० से विक्टोरिया के तथा १ नवम्बर १९४३ से जॉर्ज पचम् एव षष्ठम् के  $\frac{1}{2}$  भाग चाँदी वाले रुपये बन्द किये गये। रजमारी की कमी को दूर करने के लिए गिलेट के अधने, इकप्रियां तथा दुअप्रियां १९४२ से और १९४३ से छेदवाला पैसा चलाया गया।

युद्ध के कारण भारतीय आयात में कमी हुई, पातायात साधनों का उपयोग युद्ध के लिए होने लगा, तथा विदेशी भुगतान के लिए विदेशी मुद्राएँ बुर्लभ हो गयीं। इससे हजारे निर्यात बड़े तथा व्यापारिक शेष अनुकूल होता रहा। फलतः इंग्लैंड में हमारे पौंड-पावने इकट्ठे हो गये।

विदेशी मुद्रा का युद्ध-कार्य के लिए अधिकतम उपयोग करने के लिए विनिमय-नियन्त्रण लगाये गये। यह कार्य रिजर्व बैंक को अपने विनिमय-नियन्त्रण विभाग द्वारा करना था। इन नियन्त्रणों के अनुसार विदेशी मुद्रा में लेन-देन केवल रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त बैंक ही कर सकते थे तथा इस हेतु निम्न नियन्त्रण लगाये गये —

१ स्वतन्त्र स्टॉलिंग क्षेत्र का विस्तार, २ विदेशी विनिमय में उपयोग पर नियन्त्रण, ३ डॉलर एवं डॉलर प्रतिभूतियों पर अधिकार, ४ मुद्रा, पत्र-मुद्रा, आदि के निर्यात पर रोक, ५. विदेशी मुद्रा में भुगतान करने पर रोक, ६ भारत-स्थित शत्रु सम्पत्ति पर अधिकार।

सुरक्षा रम्य में वृद्धि होने से सरकार ने अनेक नये नये कर लगाये तथा ऋणपत्र चालू किये।

मुद्रास्फीति—युद्ध-काल में सरकार युद्ध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नोटों का चलन बढ़ाती रही जो १९३६ के १३६ करोड़ रुपये से १९४४-४५ में १०८४ करोड़ रुपये हो गया। परन्तु इसी अनुपात में उत्पादन न बढ़ने से कीमतें बढ़ने लगी जिनका निर्देशांक १९३६ के १०० से १९४४-४५ में २४४२ हो गया। इसके निम्न कारण थे :—

१ अनुकूल व्यापारिक शेष, २ भारत द्वारा मित्रराष्ट्रों की सहायता,

३ सुरक्षा का बढता हुआ व्यय, ४ वस्तुओ की दुर्लभता । इसको रोकने के लिए सरकार ने निम्न उपाय काम मे लिये —

१ कीमतो पर नियन्त्रण, २ बचत को प्रोत्साहन एव नये कर, ३ कम्पनियो के लाभांश को सीमित करना ४ जनता से ऋण लेना ५ सरकारी व्यय मे कमी तथा बजट सतुलन के प्रयत्न, ६ जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी को दूर करने के लिए आयात-नीति मे ढिलाई ।

परन्तु फिर भी मुद्रास्फीति बनी रही । सितम्बर १९४५ मे युद्ध-समाप्ति की घोषणा से यह आशा थी कि स्थिति सुधरेगी परन्तु वह न हुआ ।

## ग्रन्थाय १५

# भारतीय चलन-पद्धति (१९४६ से १९६०)

युद्ध समाप्त होने के बाद जनता को आशा थी कि वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी तथा जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी दूर होगी, परन्तु ये सब आशाएँ बेकार रही। कारण युद्धोत्तरकात में तेजी पर स्थिति हुई जिससे मुद्रा-प्रसार बढ़ता ही गया और उसके साथ कीमत भी। युद्ध समाप्त होने के समय (अगस्त १९४५ में) भारतीय मूल्य-निर्देशक २४४१ थे जो क्रमशः बढ़ते-बढ़ते नवम्बर १९४६ में २८६६, दिसम्बर १९४६ में ३११६ मार्च १९४७ में ३४४०, अगस्त १९४८ में ३८३० तक पहुँच गये। इन सब में अन्नधान्यादि के भाव सबसे अधिक बढ़े जिसके निर्देशक मितम्बर १९४५ में २६४२ से मार्च १९४८ में ४०२४ हो गये। कीमता की यह प्रवृत्ति बराबर चालू रही। युद्धोत्तर मुद्रा-स्फीति के कारण

१ मुद्रा एवं चलन का प्रसार—युद्ध के बाद भी भारत सरकार इंग्लैंड सरकार के लिए भारत में धन्य करती रही। इसलिए भारत सरकार को अधिक रुपये की जरूरत थी जिसको पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ने पत्र मुद्राएँ चलायीं, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार से इसके भुगतान में भारत को केवल स्टलिंग प्रतिभूतियाँ ही मिलती रही। स्टलिंग प्रतिभूतियों के आधार पर जून १९४६ तक पत्रमुद्रा-प्रसार होता रहा और इस अवधि में रिजर्व बैंक के कोष में स्टलिंग प्रतिभूतियाँ भी बढ़ती रही —

	कुल पत्रमुद्रा जो चलायी गयी (करोड़ ५० में)	पत्रमुद्रा जो चलन में थी (करोड़ ५० में)	रिजर्व बैंक के कोष में स्टलिंग प्रतिभूतियाँ (करोड़ ५० में)
सितम्बर १९४५	११६२.७४	११३१.८४	१०४२.३३
अप्रैल १९४६	१२४५.६५	१२३५.१२	११२४.७०
मई १९४६	१२४६.९३	१२३७.०५	११२९.३२
जून १९४६	१२५४.३३	१२४१.६७	११३५.१२
सितम्बर १९४६	१२५७.३२	११६८.३५	११३५.३२
दिसम्बर १९४६	१२५८.५६	१२१८.७८	११३५.३२
मार्च १९४७	१२५७.४७	१२४३.०३	११३५.३२

इनके बाद भी पत्र चलन बढ़ता रहा परन्तु स्टलिंग प्रतिभूतियों की राशि जून १९४६ में स्थायी रही। अर्थात् १९४६ के बाद जो भी मुद्रा-प्रसार हुआ वह भारत सरकार की निजी आवश्यकताओं के लिए किया गया।

२ बजट में घाटा—केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बुद्धोपगन्ध बजट देखने में पता चलना है कि दोनों ही के बजटों में आय की अपेक्षा व्यय ही अधिक होगा रहा। इसको पूरा करने के लिए सरकार ने रिजर्व बैंक की धरण ली और रिजर्व बैंक ने इस कमी को पूरा करने के हेतु पत्र-मुद्राएँ चलायीं। अगस्त १९४७ से बजट में अधिक घाटे रहने लगे जिसके लिए अनेक बाहरी कारण जिम्मेदार थे। य कारण है —(अ) भारत का विभाजन और विस्थापितों का पुनर्वास, (आ) अन्न, धान्य एवं कच्चे माल की कमी, (इ) काश्मीर की लड़ाई, (ई) हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही (उ) भारतीय दूतावासों पर खर्चा आदि। इन समस्याओं में भारत सरकार का व्यय बढ़ गया और बजट में घाटा होने लगा —

केन्द्रीय बजट\* (करोड़ रुपये में)

वर्ष	आय	व्यय	घाटा
१९४५-४६	२६१ १६	४६४ ६१	— १२३ ४३
१९४६-४७	३४२ ८२	३६३ ४६	— ० ६०
१९४७-४८	१७८ ७७	१८५ ०९	— ६ ५२ <sup>१</sup>
१९४८-४९	३७१ ७०	३२० ८६	— ५० ८४
१९४९-५०	२५० ३२	३१७ १२	— ३३ २७
१९५०-५१	४१० ६६	३५१ ४४	+ ५९ २२
१९५१-५२	५१५ ३६	३८७ ३७	+ १२८ ०६

इसी प्रकार प्रांतीय बजटों में भी घाटा ही रहा जिसमें मुद्रा-प्रसार तो होता गया परन्तु उग के अनुपात में उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ी।

३ अन्न-वस्त्रादि वस्तुओं के नियन्त्रण—युद्ध-काल में अन्न-वस्त्रादि आवश्यक वस्तुओं की कीमता पर सरकार द्वारा नियन्त्रण लगाये गये थे तथा उनका वितरण भी सरकार ही करती थी। परन्तु युद्ध के बाद कुछ व्यक्तियों ने नियन्त्रण के विरुद्ध आक्षेप उठाये तथा इस नीति की आलोचना होने लगी।

\* R B I Reports on Currency & Finance

१ १५ अगस्त १९४७ से ३१ मार्च १९४८ के लिए।

महात्मा गांधी ने भी अन्न-वस्त्रादि से नियन्त्रण उठाने के लिए आग्रह किया। परन्तु सरकार ने खाद्यान्न-नीति समिति की नियुक्ति की। इसकी सिफारिशों के अनुसार दिसम्बर १९४७ में नियन्त्रण उठा लिये गये। इससे विनियन्त्रित आवश्यक वस्तुओं की कीमते बढ़ने लगी, जिनके मूल्यक दिसम्बर १९४७ में ३२१ थे जो बढ़ते-बढ़ते मार्च १९४८ में ३४७, जून १९४८ में ३७७ तथा अगस्त १९४८ में ३९८ हो गए। इस परिस्थिति को वायू में लेने के लिए सरकार की विवश होकर अक्टूबर १९४८ में फिर नियन्त्रण लगाने पड़े, परन्तु अन्न धान्यादि की कीमतों में विशेष सुधार नहीं हुआ।

४. अन्न-संकट—मुद्रास्फीति को दबाने के अन्न-संकट से भी काफी दल मिलता है। यह अन्न-संकट बढ़ती हुई जनसंख्या तथा देश में अन्न-उत्पादन की कमी के कारण तो हुआ ही, साथ ही भारत का गेहूँ तथा चावल आदि कच्चा माल उपजाने वाला प्रदेश पाकिस्तान को मिल जाने से हमारी अन्न परिस्थिति को काफी धक्का लगा है, जिससे भारत को विदेशों से गेहूँ आदि अन्न का आयात करना पड़ा। इस आयात से हमारी भुगतान-शेष-परिस्थिति भी प्रभावित हुई। अन्न आयात के आँकड़े इस प्रकार हैं—

वर्ष	आयात (लाख टनों में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)
१९४७-७८	२३	६४
१९४८-४९	२८	१५०
१९४९-५०	२७	१४४
१९५०-५१	२१	८०
१९५१-५२	४०	१४०

परन्तु इससे परिस्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ है और आज हम यह आशा करते हैं कि तीसरी योजना के अन्त तक हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जायेंगे।<sup>१</sup>

५. उत्पादन में कमी—युद्ध के बाद भी देश में उपभोग्य-वस्तुओं का अभाव बना रहा क्योंकि जनता की माँग बढ़ती जा रही थी और देश का उत्पादन कम हो रहा था। देखिये निम्न तालिका<sup>१</sup>।

<sup>१</sup> *Eastern Economist Index Numbers*

<sup>२</sup> नवभारत टाइम्स, २२ अक्टूबर १९५६

वर्ष	वृषि-उत्पादन निर्देशांक	औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक
१८४३-४४	—	१२६ ८
१८४४-४५	—	१२१ ७
१८४५-४६	८४	१२० ०
१८४६-४७	८६	१०५ ०
१८४७-४८	८७	१०५ २
१८४८	—	१०५ ७

उत्पादन गिरने के कारण वस्तुओं की कीमत बढ़ रही थी। युद्ध के बाद उत्पादन कम होने के अनेक कारण हैं, जैसा हड़ताल, कच्चे माल की महंगाई, पूँजीगत वस्तुओं के प्राप्ति करने में कठिनाई, विनियोग के लिए पूँजी की कमी आदि।

### मुद्रास्फीति का प्रभाव

युद्धकालीन मुद्रास्फीति से युद्धोपरान्त मुद्रास्फीति भिन्न थी क्योंकि युद्ध-काल में मुद्रास्फीति होने से वस्तुओं की कीमत बढ़ गयी जिसमें व्यापारियों, विमानों और उद्योगपतियों ने खूब लाभ कमाया। उन्होंने चोरबाजारी से अपनी आय बढ़ाई और उसे छिपाकर आय-कर में भी बचने लगे। इस अवधि में जायात की कमी के कारण देश में उपभोग्य-वस्तुओं की पूर्ति देशी व्यापारियों एवं उद्योगों द्वारा ही होती थी इसलिए उनको युद्ध काल में असीमित लाभ मिले। यही बात किसानों के लिए भी लागू होती है। नियंत्रण होने के बावजूद भी उन्होंने चोरबाजारी से लाभ वेचा। इससे अलावा कच्चे माल आदि की कीमते बढ़ जाने से उन्हें लाभ हुआ परन्तु इस अवधि में कृषि वस्तुओं की कीमतें इतनी अधिक नहीं बढ़ी थी जितनी निर्मित वस्तुओं की, इससे उनको लाभ मिला परन्तु कम। भजदूरा को और स्थायी जाय वाले कर्मचारियों का बहुत हानि हुई एवं कठिनाइयाँ भलनी पड़ी क्योंकि वस्तुओं की कीमतें आदि बढ़ जाने से जीवन-व्यय अधिक हो गया था परन्तु महंगाई भत्ते के रूप में उनकी आय उतनी नहीं बढ़ी थी जितनी की कीमतें।

युद्ध के बाद जो मुद्रास्फीति हुई उसके परिणाम कुछ भिन्न हो गए। युद्ध के बाद अन्न तथा अन्य कृषि वस्तुओं की कीमतें बहुत बढ़ गयी थी जिससे किसानों ने खूब लाभ कमाया। परन्तु उद्योगपतियों ने लाभ कम हो गये क्योंकि एक ओर तो कच्चे माल की कीमतें बढ़ गयी थी और दूसरी ओर हड़तालों के

कारण उत्पादन की हानि हो रही थी। इसके अलावा मजदूरों की आय भी बढ़ गयी थी जिससे मजदूरों अधिक देनी पड़ती थी। इन कारणों से उद्योग पतिया के लाभ कम हो गए थे। परन्तु मध्यम वर्गीयों के साथ इस चक्की में बुरी तरह पिसे क्योंकि वे अपनी आय से अपना खर्चा भी पूरा नहीं कर पाते थे तो फिर बचत कहाँ करतें? फलतः देश की पूँजी निर्माणशक्ति घट जानी। देश में औद्योगिक विनियोग के लिए पूँजी का अभाव प्रतीत होना लगा। इस अवधि में जिन लोगों की—कृषक जयदा मजदूरों की—आय बढ़ी उन लोगों में बचत करने की प्रवृत्ति कम है और जो बचत करते भी हैं उस बचत का मन रखत हुए अपने पास ही खर्च करने हैं जिससे वह राशि औद्योगिक विनियोग के लिए नहीं मिल सकती।

### मुद्रास्फीति रोकने के लिए प्रयत्न

इसीलिए बढ़त हुए मूल्यों का रोकना एवं मुद्रास्फीति का निवारण के लिए सरकार चिन्तित हो उठी। उसने देश के उद्योगपतियों, बैंकों अधिकाधिकारियों आदि के साथ विचार विनियम करने के बाद अक्टूबर १९४८ में मुद्रास्फीति रोकने की एक योजना बनायी। इस योजना में अन्न वस्त्रादि अन्य आवश्यक वस्तुओं पर नियंत्रण लगाना बजट को संतुलित रखना एवं इसलिए अधिक करा आदि से आय बढ़ाना व सरकारी व्यय कम करना देश के कृषि उत्पादन एवं औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना कंपनियों द्वारा दिये जाने वाले लाभांश को सीमित रखना तथा बैंकिंग प्रसार द्वारा छोटी आय वाले व्यक्तियों में बचत कराना जिससे वह उत्पादन कार्य में लगायी जा सके, आदि सम्मिलित थे।

इस योजना पर कार्यवाही की गयी जिसके अनुसार सितम्बर १९४८ से खाद्यान्न वितरण योजना मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुओं का वितरण करने के लिए कार्यरूप में लायी गयी। लाभांश ९% से अधिक नहीं दिया जा सके इस हेतु लाभांश बर्बादीकरण विधान (Dividend Imputation Act) स्वीकृत हुआ। देश का उत्पादन बढ़ाने तथा उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए उनके करों में कमी करके उनका अनेक प्रकार से सुविधाएँ दी गयीं। ये सुविधाएँ क्रमशः १९४८-४९, १९४९-५० तथा १९५०-५१ में दी गयीं। इनके साथ साथ देश की औद्योगिक पूँजी बढ़ाने के लिए अगस्त १९४९ से अनिवार्य बचत योजना लागू की गयी जिसके अनुसार २५० रुपये तथा इससे अधिक पाने वाले को नियमित रूप से बचत करना अनिवार्य हो गया। इसी प्रकार कृषि उपज के दाम बढ़ाने से बहुत सा धन देहाता में इकट्ठा हो गया था जो या तो भूमिगत हो चुका

या अथवा गहना में परिवर्तित हो चुका था। इस धन का खींचने के लिए नवम्बर १९४२ में 'ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति' की नियुक्ति की गयी। इसकी रिपोर्ट के अनुसार इस धन को खींचने के लिए उन्होंने डाकघर बैंक का प्रचार देहातो में होना आवश्यक बताया है। इसके अनुसार देहातो में डाकघर बैंको की सत्या बढ़ाई गयी है। इसी प्रकार बजट में हान वाले घाटा की पूर्ति भी नये नये करों से की जा रही है जिसके अनुसार १९४९-५० से १९५२-५३ के बजट में क्रमशः ३३-७५ ५९-७७ १२८०८ तथा ३७८२ करोड़ रुपये का आधिक्य रहा। इस प्रयत्नों के कारण मूल्यस्तर भी गिर परन्तु धीरे-धीरे फिर कीमतें बढ़ने लगी।

१९५०-५१ से कीमतें बढ़ने के लिए तीन कारण जिम्मेदार थे—(१) कारिवाई गुड (२) अमेरिका द्वारा कच्चे माल का संग्रह करने का कार्यक्रम (American stock piling programme) तथा (३) इंग्लैण्ड आदि यूरोपीय देशों द्वारा अपनायी गयी पुनः क्षत्रीकरण की योजना। इन तीन कारणों से माल की विनियमित कच्चे माल की मांग बढ़ गयी थी जिससे कृषि वस्तुओं की कीमतें अधिक बढ़ी।

	साखाने के मूल्यांक	औद्योगिक कच्चे माल के मूल्यांक	सामान्य निर्देशांक
१९४८-४९	३८२८	८४८८	३७६०
१९४९-५०	३८१३	४७१७	३८५४
१९५०-५१	८१-४	५२३१	४०८७

इस स्पष्ट है कि साखाने तथा औद्योगिक कच्चे माल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ी और अन्य वस्तुओं की कीमतों की प्रवृत्ति चलाव की ओर ही रही। इसलिए अगस्त १९५० में सरकार ने अपनी आर्थिक एवं राजस्व नीति में परिवर्तन किया जिसमें स्फीतिजन्य परिस्थिति बाधों से बाहर न आने पाये। इस हेतु सरकार ने देश का उत्पादन वृद्धि अपने सर्वोच्च स्तर पर करने एवं आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति वृद्धि के प्रयत्न किये। इसलिए सरकार ने आयाम-नीति टोली कर दी तथा इमेशल सप्लाइज (टैम्पोररी पावर्स) एक्ट १९४६ (Essential Supplies (Temporary Powers) Act 1936) में संशोधन करके आवश्यक वस्तुओं के संग्रह पर रोक लगा दी। दूसरे वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण तथा कीमतों का नियन्त्रण दसव्यापी आधार पर है। इसलिए सरकार ने एक वर्ष के लिए (१) व्यापार एवं वाणिज्य तथा (२) वस्तुओं के

उत्पादन पूर्ति एवं वितरण सम्बन्धी विधान बनाने का अधिकार भी अपने हाथ में लिया, और (३) आन्तरिक एवं बाहरी कीमतों की विषमता को दूर करने तथा मुद्रास्फीति को रोकने के लिए अनेक वस्तुओं पर निर्यात-कर बढ़ाये तथा जिन वस्तुओं पर नहीं थे उन पर नये निर्यात-कर लगा दिये। इसमें मूल्य-स्तर में कुछ स्थिरता रही परन्तु यह स्थिरता कायम न रह सकी और मूल्य फिर बढ़ने लगे।

### मन्दी की लहर (Dis-inflationary Trends)

परन्तु अप्रैल १९५१ से मूल्य-स्तर गिरने लग और यह गिरावट नवम्बर १९५१ से अधिक तीव्र गति से हुई। वैसे तो व्यापार-चक्र-मिथान्त (Theory of trade cycle) के अनुसार यह मन्दी दस वर्ष बाद अर्थात् १९४९-५० में ही आ जानी चाहिए थी परन्तु कोरिया का युद्ध, यूरोपीयन देशों की पुन-रास्त्रीकरण की योजना तथा अमेरिकन स्टॉक-पाइलिंग प्रोग्राम के कारण यह मन्दी कुछ काल के लिए रूक गयी थी। मन्दी की लहर वास्तव में तीव्र गति से जून १९५१ में ही शुरू हो गयी थी जब कि कारियाई सधि-वार्ता शुरू हुई। इन मन्दी के लिए अन्तरराष्ट्रीय कारण तो जिम्मेदार थे ही परन्तु सरकार ने मुद्रास्फीति को रोकने के लिए जो कदम उठाये वे भी जिम्मेदार थे। अन्तर-राष्ट्रीय कारणों में निम्नलिखित कारणों का समावेश होता है —

- (१) जून १९५१ में कोरियाई सधि-वार्ता का आरम्भ,
- (२) यूरोपीय देशों के पुन-रास्त्रीकरण की अवधि बढ़ायी जाना,
- (३) अन्तरराष्ट्रीय कच्चा माल सम्मेलन (International Raw Materials Conference) के प्रयत्नों के कारण कच्चे माल की दुर्लभता की समस्या का हल,
- (४) दुर्लभ कच्चे माल का सम्पूर्ण विश्व का उत्पादन बंद जाना, तथा
- (५) अमेरिका द्वारा कच्चे माल के भण्डार (American stock-piling programme) की अवधि बढ़ायी जाना।

इन कारणों से अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में कीमता में गिरावट आयी जिससे भारतीय बाजार भी प्रभावित हुआ और हमारे यहाँ भी कीमतें गिरने लगी। इसी समय सरकार ने भी मुद्रास्फीति को रोकना शुरू कर मूल्यों को स्थिर रखने के लिए अनेक कदम उठाये। सरकारी व्यापारिक नीति में संशोधन किया गया जिससे देश में वस्तुएँ सुलभता से मिल सकें। इसी के साथ देश में भी उत्पादन बढ़ा जिससे वस्तुएँ सुलभता से मिलने लगी। दूसरे, सरकार द्वारा दुर्लभ वस्तुओं

पर नियंत्रण भी चालू रखा गया। तीसरे अनेक वस्तुओं के निर्यात करा गए वृद्धि की गयी तथा कुछ वस्तुओं पर निर्यात-कर लगाय गया। चौथे, सरकार के बजट में आधिक्य। पाँचवें साख्त का नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा १४ नवम्बर १९५१ में बैंक-दरम भी वृद्धि की गयी। बैंक-दर का वृद्धि से तथा मुद्रा बाजार की क्रियाओं सम्बन्धी नयी नीति की घोषणा होने ही के बाद अपने ऋण वापिस लेना शुरू किया तथा साख्त का काम किया। उसमें व्यापारियों को महत्व-वृद्धि के लिए बाजार में वस्तुओं की पूर्ति करने लगी। उससे अलावा आगामी फसल के अन्तर्गत होने सम्बन्धी समाचारों तथा वस्तुओं के अन्तर-प्रान्तीय लायात निर्यात की सुविधाओं के कारण कीमतें गिरने लगी। निम्न तालिका में जून १९५१ से मार्च १९५२ तक मूल्यों में किस तरह गिरावट आयी, यह स्पष्ट हो जायगा —

		औद्योगिक		सामान्य
		व्यापक-वस्तुएं	कच्चा माल	निर्देशांक
जून	१९४७	४१२ ८	६८८ ७	४५६ ५
सितम्बर	१९५१	४१० २	५६७ ६	४३५ १
दिसम्बर	१९५१	३६८ १	५७४ १	४३३ १
जनवरी	१९५२	३६३ ०	५८० ६	४१० ३
फरवरी	१९५२	३५८ ८	५४५ ८	४१५ ८
मार्च	१९५२	३४२ ७	४२४ २	३७७ ५

यदि मदी आई जरूर परन्तु यह मदी स्थायी न रहे सकी क्योंकि जून १९५२ के बाद के मूल्यों में पना चढ़ता है कि वस्तुओं के भाव फिर से घटने लगे। इसमें सरकार की ओर से कुछ ढिलाई भी करती गयी क्योंकि उसमें कुछ शक्कर आदि के निर्यात करने पर छूट थी तथा जूट वनहन आदि वस्तुओं के निर्यात-करों का भी काम कर दिया। इससे वस्तुओं के भाव घटने लगे। इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से यह दलील दी गयी थी कि यह सब भूगतान की कमी को दूर करने के लिए किया गया था मदी दूर करने के लिए नहीं। परन्तु कुछ भी हा सरकार का यह अवसर खोना न चाहिए था।

पंचवर्षीय योजना काल — १९५१ के मध्य से भारत में पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा आर्थिक विकास कार्यक्रम अपनाया गया। पहली योजना पर २३५६ करोड़ रुपये का आयोजन था जिसमें ४१५ करोड़ रुपये के हीनाय प्रवर्धन का आया जल था। इसी प्रकार दूसरी योजना का कुल व्यय ४८०० करोड़ रुपये था

जिमसे से १२०० करोड़ रुपये की व्यवस्था हीनार्थ प्रबन्धन से तथा ४०० करोड़ रुपये देण के विभिन्न स्रोतों से करा आदि द्वारा उपलब्ध करने की योजना थी जिसके बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है।

प्रथम योजना में अतिरिक्त करोड़ों से जहाँ २७६ = करोड़ रुपये प्राप्त किये गये थे वहाँ दूसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में ४५३३ करोड़ रुपये प्राप्त हुए। इसके अलावा पहली योजना में ४१७ करोड़ रुपये का हीनार्थ प्रबन्धन हुआ। फिर भी कीमतों का स्तर स्थिर रहा। इसमें दूसरी योजना से अधिक माना में हीनार्थ प्रबन्ध की गुंजाइश थी। दूसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में ६१७ करोड़ रुपये का हीनार्थ प्रबन्धन किया गया तथा शेष २ वर्षों में २०० से ३०० करोड़ रुपये का हीनार्थ प्रबन्धन होने का अनुमान है। इस हीनार्थ प्रबन्धन का प्रभाव हमारे मूल्य-स्तर पर हो रहा है। जहाँ पहली योजना की अवधि में मूल्यस्तर में ७% गिरावट आयी वहीं दूसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में ही १५% से मूल्यस्तर बढ़ और उनमें बढ़ने की ही प्रवृत्ति है। यह इस ओर संकेत करती है कि प्रथम योजना में जहाँ हीनार्थ प्रबन्धन विकासोन्मुख था वहीं दूसरी योजना में वह मुद्रास्फीति-जन्य है।<sup>१</sup> देखिये निम्न तालिका—

थांब कीमतों के निर्देशांक\* (आधार १९३६=१००)

वर्ष	खाद्यान्न	औद्योगिक कच्चा माल	निर्मित माल	साधारण
१९५०-५१	४१६.४	५२३.१	३४५.२	४०६.७
१९५१-५२	३६८.६	५६१.६	४०१.५	४३४.६
१९५२-५३	३५७.८	४३६.६	३७१.२	३८०.६
१९५३-५४	३८४.४	४६७.७	३६७.४	३६७.५
१९५४-५५	३३६.८	४३६.२	३७७.३	३७७.४
१९५५-५६	३१३.२	४१६.७	३७२.६	३६०.३

अतः इसकी राखतम व लिए क्षीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है।

### चलन-पद्धति में परिवर्तन

मुद्रा के बाद जनवरी १९४६ में हमारे यहाँ की चलन एवं बैंकिंग पद्धति में तीन निम्नलिखित उल्लेखनीय परिवर्तन हुए —

(१) पहले आदेश के अनुसार जो ११ जनवरी १९४६ को दिया गया,

<sup>१</sup> *Modern Review*, April 1959, p. 288

<sup>२</sup> *India*—1958

समस्त बैंक तथा सरकारी कोषों का ११ जनवरी तक के व्यवहारा के बाद के उनके पास सुरक्षित १०० रुपये और उसमें ऊर्ची पत्र मुद्रा के पूर्ण विवरण (statement) देने के लिए बाध्य किया गया। इसका हनु यह जानना था कि कितनी पत्र मुद्रा चलन में है तथा कितनी बका एवं सरकारों काया में है।

(२) दूसरे आदेश के अनुसार १०० रुपये से अधिक रुपये की पत्र मुद्रा की विधिग्राह्यता १० जनवरी १८६६ में हटा ली गयी। इसके लिए एक विनय पत्रों अपनाने ली गयी जिसके अनुसार १०० रुपये से ऊर्ची पत्र मुद्रा का १०० रुपये जयरा के पत्र मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता था। इसका हनु बाजारों में व्यापारियों द्वारा कमाय गये अनिश्चित लाभ को जानना था।

(३) तीसरे आदेश के अनुसार जो १६ जनवरी १८६६ का दिया गया कानून सरकार को यह अधिकार दिया गया कि वह रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी बैंक की सहाय कर उसका कार्यवाही पत्र रिपॉजिट मांगे। इस आदेश का हनु मुख्य आधार पर बैंकिंग का प्रसार करना था।

(४) १८६७ में भारतीय टकरा विधान में संशोधन किया गया तथा चांदी के बदले निकट के नये सिक्के बनाये गये जिसमें २ ६ करोड़ औंस चांदी का वजन हुआ।

(५) मौद्रिक व्यवस्था के एकीकरण के साथ १ अप्रैल १८५५ के ऐशराबाद के हाली सिक्के की विधिग्राह्यता हटा दी गयी। फिर भी भारतीय मुद्रा में उसके परिवर्तन करने का मुनिवाए दी गयी है।

(६) मुद्रा का दाममन्वीकरण करने के लिए २८ जुलाई १८५५ का एक अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार ७ अप्रैल १८५७ में भारतीय मुद्रा का विभाजन १०० नये पैसा में हुआ गया। तदनुसार इन समय में १ ५ १० ५४ और ५० नये पैसा के सिक्के प्रचलन में लाये गये। ये पुराने सिक्के के साथ तीन वर्ष तक चलन रह्ये। इस अवधि के बाद पुराने सिक्के चलन से हटा लिये जायेंगे।

(७) नियोजित अथ व्यवस्था के विकास की आवश्यकता और सुगमता में हनु के त्रिपक्ष परीक्षित तथा विद्वानों विनिमय की कमी को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक एक्ट में १८५५ में संशोधन किया गया। इस संशोधन के अनुसार नया चलन की आनुपातिक विधि पद्धति का त्याग कर यूनितम विधि पद्धति को अपनाया गया है। इस संशोधन के अनुसार रिजर्व बैंक के नाट चलन विभाग में यूनितम ११५ करोड़ रुपये का स्वयं तथा ४०० करोड़ रुपये की विदेशी प्रति

भूतियाँ रखना आवश्यक है। इस हेतु स्वर्ण का मूल्यांकन नवीन दरो पर अर्थात् ६२ रु० ५० न० ५० प्रति तोले पर किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर रिजर्व बैंक विदेशी प्रतिभूतियों की राशि केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से प्रथम बार अधिकतम ६ मास के लिए तथा इसके बाद तीन मास के लिए घटा सकता है। परन्तु किसी भी दशा में विदेशी प्रतिभूतियाँ २०० करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार विदेशी प्रतिभूतियों को कम करने की स्थिति में रिजर्व बैंक के पास न्यूनतम ११५ करोड़ रुपये का स्वर्ण तथा २०० करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ होनी चाहिए।

विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अक्टूबर १९५७ में इसमें पुनः संशोधन किया गया जिसके अनुसार रिजर्व बैंक का पत्र-चलन कोष में स्वर्ण, स्वर्ण के मिक्चे एवं विदेशी प्रतिभूतियाँ मिलाकर कुल २०० करोड़ रुपये रखना अनिवार्य है। इसमें न्यूनतम ११५ करोड़ रुपये का स्वर्ण होना चाहिए। इस प्रकार अब रिजर्व बैंक को स्वर्ण के अलावा केवल ८५ करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ रखने की आवश्यकता है।

**रुपये का अवमूल्यन**

१८ मितम्बर १९४९ को अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुमति से स्टर्लिङ्ग के साथ रुपये का भी ३०.५ प्रतिशत में अवमूल्यन किया गया। यह अवमूल्यन अन्य २४ देशों की मुद्राओं का भी हुआ।<sup>१</sup> ३१ जुलाई १९५५ को पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन होने से भारतीय एवं पाक मुद्रा समान स्तर पर आ गयी है। हमारे चलन की वर्तमान स्थिति

१ जब से भारत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बना तब से रुपये का स्टर्लिङ्ग से नाता टूट गया तथा उसका स्वर्ण-मूल्य = २६.८०१ ग्राम निश्चित कर दिया गया है जिसमें १८ मितम्बर १९४९ से ३० प्रतिशत की कमी की गयी है जिससे उसका स्वर्ण मूल्य ०.१८६२१० ग्राम रह गया है।

२ देश की प्रमाणित मुद्रा रुपया ही है, वास्तव में वह प्रतीक मुद्रा है और स्वर्ण में परिवर्तनीय नहीं है। इसी प्रकार १ रुपये की पत्र-मुद्रा भी प्रमाणित मुद्रा है। रुपये का विभाजन १०० नये पैसे में किया गया है तथा इस समय १, ५ तथा १० नये पैसे के सिक्के चाँदु किये गये हैं। पुरानी चवन्नी एवं अठन्नी का मूल्य क्रमशः २५ और ५० नये पैसे हैं।

३ विदेशी भुगतान के लिए विदेशी मुद्राओं के त्रय-विश्रय का एकाधिकार

<sup>१</sup> देखिये अध्याय २०।

रिजर्व बैंक को है तथा यह कार्य वह अन्य बैंकों की सहायता एवं सहयोग से करता है ।

४ भारत के अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का सम्भार हो जाने से रुपये का स्टैबिलिटी में सम्बन्ध बिच्छेद हो गया है और रुपया अन्तरराष्ट्रीय प्राप्ति में स्वतन्त्र है । परन्तु रुपये और स्टैबिलिटी की विनिमय दर १ सि० ६ पम प्रति रुपया ही है । रिजर्व बैंक की धारा ४०-४१ का रद्द कर दिया गया है जो रुपये का स्टैबिलिटी मूल्य १ सि० ८ पम रखने के सम्बन्ध में थी । विदेशी मुद्रा के अग्र-विक्रय को अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निश्चित दरा पर ही करने का प्रतिबन्ध रिजर्व बैंक पर है । फिर भी भारत के राष्ट्रमन्त्र का मद्द्दय होने के कारण रुपया और स्टैबिलिटी का घनिष्ठ सम्बन्ध आज भी है ।

५ मुद्रा-काल में लागू किये गये विनिमय-नियन्त्रण आज भी लागू हैं किन्तु इनमें कुछ छूट दे दी गयी है तथा आयात-निर्यात प्रतिबन्धों में नियोजित अर्ध-व्ययस्या के अनुसार ट्रेड-फैर किये जाते हैं ।

६ रुपये का सम्बन्ध अब अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी सदस्य देशों की मुद्राओं के साथ है । इसलिए अब भारत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा मान पर है और चूंकि विभिन्न देशों की मुद्राओं का मूल्य स्वर्ण में है अतएव हम इस मान को अन्तरराष्ट्रीय स्वर्णमान भी कह सकते हैं ।

### मांगदा

मुद्रा समाप्त हो गया परन्तु मूल्यस्तर फिर भी बढ़ता ही गया । मुद्रांतर मुद्रास्फीति के निम्न कारण थे

१ मुद्रा एवं चलन का प्रसार, २ बजट में घाटा, ३ अन्न, वस्त्र आदि वस्तुओं का विनिमय, ४ अन्न सङ्कट एवं अन्न का आयात, ५ उत्पादन में कमी ।

मुद्रांतर मुद्रास्फीति से व्यापारियों के लाभ कम हो गये क्योंकि औद्योगिक कच्चे माल की कीमतें बढ़ गयी थी । श्रमिकों की माँदहूरी बढ़ी, मध्यम वर्ग बुरी तरह प्रभावित हुआ जिससे पूँजी-निर्माणशक्ति घट गयी और औद्योगिक पूँजी की कमी महसूस होने लगी अतः सरकार ने मुद्रास्फीति रोकने के लिए निम्न कार्यवाही की—

कम्पनियों के लाभालाभ सीमित किये, खाद्यान्न विवरण योजना एवं अनिवार्य बचत योजना लागू की, ग्रामीण क्षेत्रों का भूमिगत वन निकासने के लिए ग्रामीण बैंकिंग जाच समिति की नियुक्ति की तथा इसकी सिफारिशों पर कार्यवाही की ।

इन प्रयत्नों से मूल्यस्तर स्थिर हो रहा था किन्तु कोरियाई मुद्रा, अमेरिका की स्टॉक एक्ज़ीक्यूशन योजना, यूरोप की पुनःशस्त्रीकरण योजना के कारण पुनः कीमतें बढ़ने लगीं। अतः १९५१ में रिजर्व बैंक ने बैंक-दर बढ़ा दी जिससे मूल्यस्तर घिरने लगे। इसके लिए कोरियाई सवि-वार्ता, पुनःशस्त्रीकरण योजना एवं अमरीकी स्टॉक एक्ज़ीक्यूशन योजना की अवधि बढ़ना आदि कारण भी जिम्मेदार थे। इसके साथ ही विश्व का कृषि-उत्पादन बढ़ रहा था। यह स्थिरता अस्थायी रही क्योंकि भारत में १९५१ से योजनाओं का शीघ्रारंभ हुआ। इनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हीनार्थ प्रबन्धन अपनाया गया। प्रथम योजना काल में कीमतें कुछ गिरी परन्तु दूसरी योजना के प्रथम तीन वर्षों में ही कीमतें तेजी से बढ़ने लगीं जो हीनार्थ प्रबन्धन की अधिकता की ओर संकेत है। अतः इसको रोकथाम शीघ्र होना आवश्यक है।

युद्धोत्तर काल में चलन-पद्धति में निम्न परिवर्तन हुए :—

- १ १२ जनवरी १९४६ से १०० रु० से ऊपर के नोटों का विमुद्रीकरण;
- २ रिजर्व बैंक को किसी भी बैंक के परीक्षण का अधिकार;
३. १९४७ से निकेल के सिक्कों का चलन;
- ४ हैदराबाद के सिक्कों की विधिग्राह्यता का अन्त;
- ५ १ जुलाई १९५७ से भारतीय मुद्रा का दशमलवीकरण;
- ६ नोट प्रणाली की आनुपातिक निधि पद्धति का त्याग एवं भूततम निधि पद्धति का अपनाना;
- ७ सितम्बर १८, १९४६ को भारतीय रुपये का तथा ३१ जुलाई, १९५५ को पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन।

भारतीय चलन की वर्तमान स्थिति—

- १ भारतीय मुद्रा का स्टैबिलिटी में सम्बन्ध विच्छेद हो गया है और वह देश की प्रमाणित मुद्रा है। इसका स्वर्ण-मूल्य १८६२१० ग्राम स्वर्ण है।
- २ एक रुपये के नोट भी रुपये के सिक्के के बराबर ही हैं।
- ३ देश को प्रधान एवं गौण मुद्राएँ निकेल की हैं।
- ४ विदेशी मुद्राओं के क्रय-विक्रय का एकाधिकार रिजर्व बैंक को है तथा युद्धकालीन नियंत्रण आज भी कुछ हेरफेर के साथ लागू है।
- ५ रुपये का सम्बन्ध अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी देशों के साथ है।

## भारतीय पत्र-चलन का इतिहास

भारत में अंग्रेजों के आगमन के पूर्व कुछ हद तक हुण्डिया ही पत्र-मुद्रा की तरह चलन में थी। इनको वास्तव में पत्र-मुद्रा नहीं कहा जा सकता और न ये विधिग्राह्य अथवा मबंगान्य ही थी। भारत में सबसे पहले पत्र-मुद्रा का चलन प्रेसीडेन्सी बैंकों की स्थापना, जो क्रमशः १८०६ में बंगाल में, १८४० में बम्बई में तथा १८४३ में मद्रास में हुई, के बाद ही प्रारम्भ हुआ। इन बैंकों को पत्र-मुद्रा-प्रसार का अधिकार दे दिया गया था और यह अधिकार ५ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्रा तक सीमित था। इसके अतिरिक्त ७ अन्य बैंकों को भी पत्र-मुद्रा-प्रसार का अधिकार १८६४ तक था।<sup>१</sup> इन प्रेसीडेन्सी बैंकों को पत्र-चलन के लिए कुल ३३,३३,००,००० स्वर्ण-निधि रखना अनिवार्य था। ये पत्र-मुद्राएँ केवल प्रेसीडेन्सी क्षेत्र तक ही सीमित होने के कारण विधिग्राह्य न थी।

१८६१ में पेपर करमी एक्ट में भारत सरकार ने पत्र चलन का एकाधिकार लिया तथा प्रेसीडेन्सी बैंकों से पत्र-मुद्रा-प्रसार का अधिकार छीन लिया गया। इसलिए भारत के सत्र प्रदेशों की बम्बई, कनकता, मद्रास, इन तीन विभागों में बाँट दिया गया। पत्र-चलन के लिए पत्र-चलन विभाग की स्थापना की गयी। इन तीनों विभागों में अलग-अलग पत्र-मुद्राएँ चलन में आयी जो वैधानिक रीति में एक-दूसरे के क्षेत्र में प्रमाणित मुद्रा में अपरिवर्तनीय थी तथा ये पत्र-मुद्राएँ भाँग पर भुगनाये जाने वाले प्रतिज्ञा-पत्र की तरह ही थी। निश्चित अरक्षित पत्र-मुद्रा (fixed fiduciary) की मर्यादा ४ करोड़ रुपये तक सीमित थी लेकिन इससे अधिक चलन के लिए बराबर के मूल्य में स्वर्ण या चाँदी रखना अनिवार्य था। इस प्रकार प्रचलित पत्र-चलन-पद्धति में न तो लांच थी और न थी धातु की मितव्ययिता, परन्तु चलनाधिक्य से सुरक्षा थी।

१८६३ में हर्शल मण्डि की सिफारिश के अनुसार अब रुपये का मुक्त

<sup>१</sup> *Paper Currency in India* by H. B. Das Gupta

टक्का बन्द किया गया जग समय अरक्षित पत्र-चलन (fiduciary paper money) की मर्यादा ४ करोड़ से बढ़ाकर ८ करोड़ रुपये कर दी गयी क्योंकि रुपया अब प्रतीक मुद्रा हो गया था तथा रुपये में चाँदी बाजार भाव में कम होने के कारण १० रु० की पत्र-मुद्रा के बदले केवल ६ रु० की चाँदी ही निधि में रखने की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार पत्र-चलन-निधि था।

आरम्भ में १०, २०, ५०, १००, ५००, १००० तथा १०,००० रुपये की पत्र-मुद्राएँ बनायी गयी थी लेकिन १८६१ में ५ रु० की पत्र-मुद्रा भी चलाई गयी। तमज ये पत्र-मुद्राएँ सरकारी कोषों में स्वीकृत होने लगी तथा सरकारी कोषों में इनका रुपये में परिवर्तन भी होने लगा। आरम्भ में पत्र-चलन-निधि में केवल रुपये की प्रतिभूतियाँ ही रखी जाती थी किन्तु १८०५ में स्टतिग प्रतिभूतियाँ भी रखी जाने लगी और शाकी निधि चाँदी में, भारत में ही, रखी जाती थी। किन्तु १८६८ से पत्र-चलन-निधि का कुछ अंश स्वर्ण में भारत-मन्त्रि के पास रखा जाने लगा जिसके बदले यहाँ पर पत्र-चलन हो सकता था। इसका उद्देश्य यह था कि रुपया को डालने के लिए जब चाँदी की आवश्यकता हो तो भारत-मन्त्रि इस निधि का उपयोग करे तथा स्वर्ण विनिमय-मान में वह रुपये का विनिमय मूल्य स्थिर रखने के भी काम आये।

१८०३ में पत्र मुद्राएँ बर्मा को छोड़कर समस्त भारत के लिए विधिप्राप्त बनायी गयी तथा १८०६ में बर्मा के लिए भी। १८१० में १० और ५० रुपये की तथा १८११ में २०० रुपये की पत्र-मुद्राएँ इसी प्रकार विधिप्राप्त घोषित की गयी। १८१० में काठपुर, लाहौर, ग्गून और कराँची भी पत्र चलन क्षेत्र में आ गये। इस प्रकार १८१० में बम्बई, मद्रास, कलकत्ता को मिलाकर पाँच नोट-चलन क्षेत्र हो गये।

१८१३ में कुल ६८ ६८ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्रा चलन में थी जिसके लिए धानु निधि ६५ ८३ करोड़ रुपये भारत में तथा ६ १५ करोड़ रुपये का इंग्लैंड में पत्र-चलन-निधि में था एवं अरक्षित निधि (invested portion) में १० करोड़ रुपये की प्रतिभूतियाँ भारत में तथा ४ करोड़ की इंग्लैंड में थी। इस प्रकार कुल पत्र-चलन का केवल २०% भाग अरक्षित था जिसमें हमारी पत्र-चलन-पद्धति में धानुओं की भिन्नव्ययिता एवं लोच का अभाव था। इस समय अरक्षित पत्र-चलन की मात्रा १४ करोड़ रुपये कर दी गयी थी।

**चेम्बरलेन समिति**

१८१३ में चेम्बरलेन समिति ने पत्र-मुद्रा को अधिक सौचदार बनाने के

लिए निवारित की तथा उन्होंने अरक्षित निधि को १४ करोड़ में २० करोड़ रुपये कर दिया। देश की मौद्रिक आवश्यकताएँ अधिक थीं इस हेतु उन्होंने आगे के लिए अरक्षित निधि का जितना अधिकतम सरकार कोप-निधि था उसमें ३ अधिक पत्र-मुद्रा चलाने का मत भी प्रकट किया। इस प्रकार कुल अरक्षित पत्र-चलन की मात्रा बढ़ा देने पर जोर दिया।<sup>१</sup> उन्होंने यह भी सिफारिश की कि सरकार को यह अधिकार हो कि वह इस अधिकतम अरक्षित भाग का भारत तथा इंग्लैंड में विनियोग करे तथा ऋण ले। यह ऋण भारत में केवल प्रेमीटेन्सी बैंकों द्वारा निश्चित शर्तों पर दिये जायें। इसी प्रकार भारत-मन्त्रि को यह अधिकार हो कि वह लन्दन में जो परिपक्व-विन वेश्चर स्वर्ण प्राप्त करे उसको भी ऋणों में विनियोग करे। लेकिन किसी भी परिस्थिति में रोकड़ निधि कुल चलन के ३ में कम न हो। ५०० १० के नोटों में सर्व-प्राप्तता लानी जाय, पत्र-मुद्रा को सर्वमान्य बनाने के लिए वैधानिक कार्यवाही की जाय तथा पत्र-मुद्रा के परिवर्तन के लिए अधिक गुरिधाएँ प्रदान की जायें।

समिति ने इस पद्धति में अनेक लाभ दिखाये थे क्योंकि सर्वप्रथम तो आवश्यकता के अनुसार पत्र-चलन की परिवर्तनशीलता अवाधित रहने हुए अरक्षित पत्र-चलन बढ़ाया जा सकता था। सरकारी आय भी विनियोग के व्याज की आय में बढ़ जाती। किसी प्रकार के कानून के बिना पत्र-चलन बढ़ाने के साथ-साथ सरकार निधि का विनियोग कर सकती थी, तथा पत्र-चलन निधि के होने में इंग्लैंड में भारत-मन्त्रि परिपक्व-विन वृद्ध भवता था।

ये सिफारिशें सरकार के सामने विचारार्थ प्रस्तुत की गयीं परन्तु उन्नीसवें प्रथम महायुद्ध की घोषणा होने से इन पर कोई कार्यवाही न हो सकी।

### प्रथम विश्वयुद्ध-काल (१९१४-१९१८)

महायुद्ध शुरू होने ही जनता का पत्र-मुद्रा में विश्वास उठ गया और पत्र-मुद्रा के बदले स्वर्ण की माँग होने लगी। सरकार को केवल अप्रैल के पहले ही चार दिनों में १८ लाख पौंड का स्वर्ण देना पड़ा जिसमें सरकार ने पत्र-मुद्रा के बदले स्वर्ण देने पर रोक लगा दी। तदुपरान्त पत्र-मुद्रा के बढ़ने रुपये मँगे जाने लगे और केवल ८ महीने में ही १० करोड़ रुपये की पत्र-मुद्रा का परिवर्तन हुआ। १९१५ में तम्र पत्र-चलन-पद्धति में जनता की विश्वास होना गया तथा

<sup>१</sup> इसका अर्थ यह था कि अरक्षित पत्र-चलन उतना हो जितना कि उस समय कुल चलन में से कोप-निधि घटा कर रह जाता था।

वृद्धते हुए व्यापार के कारण मुद्रा की माँग भी बढ़ने लगी, जिसको पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में चाँदी न होने से पत्र चलन बढ़ाना पड़ा और अरक्षित भाग को १९१९ में १४ करोड़ में बढ़ाकर १२० करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके अलावा २॥) ₹० और १) ₹० की नई पत्र मुद्राएँ नमग दिमस्वर १९१७ और जनवरी १९१८ में चलन में लायी गयी। फिर भी बढ़ती हुई मौद्रिक माँग की पूर्ति के लिए १९१८ में रुपये के टुकण के लिए अमेरिका में २० करोड़ ऑन चाँदी खरीदी गयी। १९१९ में एक विधान स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार पत्र-चलन का अरक्षित भाग १२० करोड़ रुपये कर दिया गया जिसमें से १०० करोड़ रुपये का विनियोग ब्रिटिश कोप-विला में हो सकता था। इस प्रकार धातु-निधि जो १९१४ में ७८६ प्रतिशत था वह १९१९ में केवल ३५८ प्रतिशत रह गया और प्रतिभूतियाँ २१ प्रतिशत में ५४ प्रतिशत हो गयी। इन विनियोगों के मूल्यों के उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि की पूर्ति करने के लिए पत्र-चलन निधि अवमूल्यन-कोष (Paper currency reserve depreciation fund) का निर्माण किया गया जिसमें विनियोग एवं प्रतिभूतियों की आय जमा होती थी। इसी प्रकार मार्च १९१४ में जहाँ ६६१२ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्राएँ चलन में थी वहाँ १९१८ में यह सख्या बढ़त-बढ़ते १८२'६१ करोड़ रुपये हो गयी।

सारांश में युद्ध के कारण पत्र मुद्रा में निम्नलिखित उल्लेखनीय परिवर्तन हुए —

- (१) पत्र मुद्रा चलन की सख्या युद्ध-काल में लगभग तिगुनी हो गयी,
- (२) पत्र-चलन निधि का धातु का भाग जो १९१४ में ७८९ प्रतिशत था वह कम होकर १९१९ में केवल ३५८ प्रतिशत रह गया।
- (३) पत्र-चलन निधि में प्रतिभूतियों का भाग जो १९१४ में २१ प्रतिशत था वह बढ़कर १९१९ में ५४ प्रतिशत हो गया।

**बेविंगटन स्मिथ कमेटी (१९१९-१९२५)**

युद्ध समाप्ति के बाद बेविंगटन स्मिथ समिति ने पत्र चलन को लोचदार बनाने के लिए तथा मूल्य स्थिरता के हेतु निम्नलिखित सिफारिशों की —

१ अरक्षित पत्र-चलन को १२० करोड़ रुपये किया जाय जिसमें २० करोड़ रुपये में अधिक भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ न हों।

२ पत्र चलन में परिवर्तनशीलता लाने के लिए पत्र चलन निधि में धातु

का भाग ( अथवा स्वर्ण एवं चांदी ) कुल चलन के ४० प्रतिशत के बराबर रखा जाय ।

२ रुपये का विनिमय-मूल्य २ शिलिंग हो जाने से पत्र-चलन निधि के स्वर्ण का उस दर से पुनर्मूल्यन किया जाय ।

४ मौसमी मौद्रिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए अरक्षित भाग के अनि-रिक्त ५ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्रा निर्यात विलों के आधार पर चलायी जाय जो प्रेमीहेल्मी धंको को ऋण दी जाय । इन निर्यात विलों की अवधि ९० दिन से अधिक न हो ।

५ पत्र-चलन निधि के कुल स्वर्ण एवं चांदी का भारत में ही रखा जाय । इसमें से इङ्ग्लैंड में केवल उतना ही रखा जाय जितना वहाँ चांदी खरीदने के लिए आवश्यक हो ।

६ परिस्थिति ठीक होने ही पत्र-मुद्रा के परिवर्तन की अधिकाधिक सुविधाएँ दी जायें तथा परिवर्तन सम्बन्धी युद्धकालीन प्रतिबन्ध उठा लिये जायें । सरकार को अधिकार रहे कि वह पत्र-मुद्रा के बदले रुपये अथवा स्वर्ण दे ।

७ अरक्षित पत्र-चलन किसी भी समय कुल चलन के ६० प्रतिशत से अधिक न हो ।

इन सुझावों से यह स्पष्ट होना है कि जहाँ की जनता अतृप्त है तथा पत्र मुद्रा को अविश्वास की दृष्टि से दमती है वहाँ केवल ४० प्रतिशत धानु-निधि बहुत कम है । इस सुझाव के अनुसार पत्र-मुद्रा की पद्धति का लोचदार अवश्य बनाया गया । इसी दृष्टि से अरक्षित पत्र-मुद्रा-चलन को कुल चलन के ६० प्रतिशत रखना भी बहुत अधिक था । सरकार ने इन सुझावों में मशोधन किया एवं उन्हें लागू करने के लिए १९२० में पत्र-चलन-मशोधन अधिनियम स्वीकृत किया । इसके अनुसार—

१ कुल पत्र-चलन-निधि के ५० प्रतिशत धानु-निधि किया गया अर्थात् अरक्षित भाग धानु-निधि के मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए । इसको समिति की सिफारिश ने अधिक करने का कारण पत्र-मुद्रा के बदले रुपये की मांग होने पर रुपये दिये जा सकें तथा मौसमी आवश्यकता के समय पत्र-चलन को रुपये में बदलने की जो मांग होती है उसकी पूर्ति करना था ।

२ इस निधि का जो स्वर्ण भारत-मन्त्रि के पास रहना था वह ५० लाख पाँट (५ करोड़ रुपये) तक सीमित किया गया ।

३ २० करोड़ रुपये की प्रतिभूतियाँ जो भारत में रखी जाती थी उनके अतिरिक्त शेष निधि का विनियोग इंग्लैंड में प्रतिभूतियों में किया जाय जिनके भुगतान की अधिकतम अवधि १२ मास हो ।

४ मौममी मुद्रा की माँग की पूर्ति के लिए चलन-नियन्त्रक (controller of currency) को यह अधिकार दिया गया कि वह ५ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्रा को चलन में लाय । यह चलन कटौती किय गये विलो अथवा निर्यात के आधार पर चलाया जाय, जिनका भुगतान ९० दिन में हो ।

५ यह अतिरिक्त पत्र चलन इम्पोरियल बैंक को ८ प्रतिशत की दर से ऋण दिया जाय ।

६ मौममी माँग की पूर्ति के लिए ५ करोड़ रुपये की पत्र-मुद्राएँ तभी चलायी जायें जब पत्र-चलन निधि का ५० प्रतिशत भाग धातु (स्वर्ण चाँदी) में तथा शेष ५० प्रतिशत भाग प्रतिभूतियों में हो जाय ।

इस अधिनियम को तभी कार्यरूप में लाया जा सकता था जब कि पहली गर्त के अनुसार पत्र-चलन निधि में धातु का भाग ५० प्रतिशत हो जाय । इसका मुख्य कारण यह था कि निधि के स्वर्ण एवं स्टैलिङ्ग प्रतिभूतियों को प्रति रुपया २ गिलिंग की दर से मूल्यांकन करने से धातु भाग का मूल्य रुपये में कम हो गया था क्योंकि अब स्टैलिङ्ग का मूल्य १५ के बदले १० रुपये ही रह गया था । इसलिए अन्तरिम काल के लिए निम्न नियोजन किया गया—

(अ) निधि में भारत सरकार की जो प्रतिभूतियाँ रखी जाती थी, उनकी राशि ८५ करोड़ रुपये कर दी गयी ।

(आ) निधि के पुनर्मूल्यान में होने वाली हानि की पूर्ति के लिए भारत सरकार रुपये की नयी प्रतिभूतियाँ (ad-hoc rupee securities) पत्र-चलन निधि को दे और इनकी जगह क्रमशः स्टैलिङ्ग प्रतिभूतियाँ को रखे ।

१९२१ में बंगाल मद्रास तथा बम्बई इन तीनों प्रमोडेन्सी बैंकों को मिलाकर इम्पोरियल बैंक की स्थापना हुई । इसकी स्थापना होते ही सकटी पत्र चलन (emergency paper issue) की जिम्मेदारी इसको दे दी गयी तथा बढ़ती हुई मौद्रिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए १९२३-२४ में इसकी मर्यादा भी ५ करोड़ रुपये में १२ करोड़ रुपये कर दी गयी । इसलिए १९२३ में मध्याह्निक विधान स्वीकृत किया गया । १९२५ में फिर संशोधन विधान स्वीकृत हुआ जिसके अनुसार भारत सरकार की निधि में जो प्रतिभूतियाँ थी उनकी मर्यादा ८५ करोड़ में बढ़ाकर १०० करोड़ रुपये कर दी गयी । लेकिन

किसी भी दशा में भारत सरकार की जनिन प्रतिभूतियाँ<sup>१</sup> ५० करोड़ रुपये में अधिक नहीं हो सकती थी। इस विधान द्वारा पत्र-चलन और भी बढ़ा दिया गया। जनवरी १९२६ में (१) ६० और (२॥) २० की पत्र-मुद्राओं को जो युद्ध-काल में चलायी गयी थी, चलन से हटा लिया गया।

### हिल्टन यंग कमिशन (१९२५-१९३१)

१९२५ में हिल्टन यंग समिति ने भारतीय चलन-स्थिति का अध्ययन कर यह मुभाषा दिया कि पत्र-मुद्रा का चलन केन्द्रीय बैंक करे। शीघ्र ही केन्द्रीय बैंक की स्थापना हो। एव रुपये की पत्र-मुद्राएँ फिर से चलायी जायें जिनके बदले में रुपये न दिए जायें। इसी प्रकार समिति ने यह भी सिफारिश की कि बड़ी-बड़ी रकमों की पत्र-मुद्रा का परिवर्तन रुपये में न होने हुए स्वर्ण में हो। लेकिन कम से कम १०६५ तोले अथवा ४०० औंस स्वर्ण ही पत्र-मुद्रा के बदले २१ रु० ३ आ० १ पाई की दर से केन्द्रीय बैंक अथवा इम्पीरियल बैंक में मिल सकेगा। केन्द्रीय बैंक को मुद्रा-चलन का एकाधिकार २५ वर्ष तक हो। चलन के मूल्य में स्थिरता एव सौच लाने के लिए वह तरल प्रतिभूतियों के आधार पर पत्र-चलन करे इसलिए समिति ने पत्र-चलन के लिए आनुपातिक निधि पद्धति की सिफारिश की। इसी के साथ जो पत्र मुद्रा भारत सरकार द्वारा चलायी गयी थी उसकी विधिवानुसृतता हटा ली जाय। पत्र चलन-निधि तथा स्वर्णमान-निधि को मिला दिया जाय एव उनका अनुपात तथा उनकी रखने का स्थान विधान से निश्चित किया जाय। निधि में चाँदी का जो वर्तमान अनुपात है उसे क्रमशः कम कर दिया जाय जिससे उसमें १० वर्ष में ८५ करोड़ में २५ करोड़ रुपये की चाँदी रह जाय। केन्द्रीय बैंक के दो विभाग हों—(१) बैंकिंग, तथा (२) चलन-विभाग।

इन सिफारिशों में से बहुत सी सिफारिशों को सरकार ने मान्यता दी तथा १९२७ के विधान के अनुसार रुपये का स्वर्ण मूल्य ८४७५ ग्रेन अथवा १३ रु० १ आ० ६ पाई प्रति सॉवरेन निश्चित किया गया। इस दर में स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ, जो पत्र-चलन-निधि में थी, उनका पुनर्मूल्यन हुआ जिससे उनका मूल्य १२० लाख रुपये में बढ़ गया। इसलिए इस रकम से कोष विलास कमी कर दी गयी। इसी विधान के अनुसार सरकार ने २१ रु० ३ आ० १० पाई प्रति

<sup>१</sup> जो कोष-विल भारत सरकार लिखती है तथा उनकी वादावधि में वाद स्वयं ही भुगतान करती है, उन्हें जनिन प्रतिभूतियाँ (created or ad-hoc securities) कहते हैं।

तोले की दर से कम से कम ४० तोले स्वर्ण खरीदन की जिम्मेदारी ली। लेकिन इसी समय रिजर्व बैंक की स्थापना का विधेयक अस्वीकृत हो गया, अतएव रिजर्व बैंक की स्थापना न हो सकी। १९२७ के विधान से सरकार पर कम से कम ४०० अथवा १०६५ तोले स्वर्ण २१ रु० ३ आ० १० पाई की दर से वचने की जिम्मेदारी थी परन्तु सरकार विदेशी भुगतान के लिए स्वर्ण अथवा स्टलिंग दे यह उसकी इच्छा पर निर्भर रहा। इसी विधान के अनुसार रुपये की विनिमय दर भी १ शि० ६ पैसे स्थापित कर दी गयी परन्तु १९३१ तक स्टलिङ्ग स्वर्ण से सम्बन्धित हानि के कारण हमारे यहाँ स्वर्ण-खण्ड-मान था। १९३१ में स्टलिङ्ग का स्वर्ण से विच्छेद हो गया जिससे रुपये अथवा पत्र-मुद्रा के बदले भारत सरकार ने स्वर्ण बना बन्द किया और विदेशी भुगतान के लिए केवल स्टलिङ्ग ही प्राप्त हो सकना था।

१९३४ में रिजर्व बैंक की स्थापना सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत हुआ। १ अप्रैल १९३५ से रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने कार्यवाही शुरू की तथा पत्र-चलन का एकाधिकार इसे मिला। इसी दिन पत्र-चलन-निधि तथा स्वर्णमान-निधि को एकत्रित किया गया। भारत सरकार की पत्र-मुद्रा इस प्रारम्भिक काल में विधिग्राह्य मानी गयी थी। पत्र-चलन के लिए स्वतन्त्र चलन-विभाग था जो बैंकिंग-विभाग से अलग था। इस बैंक को ५, १०, ५०, १००, ५००, १००० तथा १०,००० रुपये की नयी पत्र-मुद्राएँ चलन में लानी थी, किन्तु ५० और ५०० रुपये की नयी पत्र-मुद्राएँ उनका चलन कम होने में नहीं चलायी गयी, किन्तु इन मूल्य की जो पत्र-मुद्राएँ चलन में थी वे विधिग्राह्य बनीं रहीं। इस बैंक का पत्र-चलन ब्रिटिश भारत के लिए विधिग्राह्य बनाया गया तथा बैंक को इन पत्र-मुद्राओं पर मुद्राक-कर (stamp duty) से भी मुक्त किया गया। इस बैंक ने १९३८ में ५, १०, १०० तथा १००० रुपये की पत्र-मुद्राएँ चलन में लायीं।

रिजर्व बैंक के चलन-विभाग का लेखा भी बैंकिंग विभाग से अलग रखा जाता है तथा उसी प्रकार चिट्ठा भी। इस चिट्ठे के सम्पत्ति-पक्ष में दो विभाग होते हैं—'अ' विभाग में स्वर्ण-मुद्रा तथा जो स्वर्ण देश में और देश के बाहर रखा जाता है वह तथा स्टलिङ्ग प्रतिभूतियाँ होती हैं। 'ब' विभाग में चाँदी, चाँदी की मुद्रा, रुपये की प्रतिभूतियाँ तथा अन्य व्यापारिक विल दिखाये जाते हैं। देय पक्ष में बैंकिंग-विभाग में रखी हुई पत्र-मुद्राएँ तथा चलित पत्र-मुद्राएँ दिखायी जाती हैं।

चलन-विभाग की सम्पत्ति स्वर्ण, स्वर्ण मुद्रा, रुपये, चाँदी, स्टलिङ्ग और रुपये की प्रतिभूतियों में होती है, जो किसी भी समय कुल देनदारी (देय) से कम

नहीं हानी चाहिए। इस सम्पत्ति में स्वर्ण मुद्राएँ स्वर्ण अथवा स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ ४० प्रतिशत अथवा कुल दाय के  $\frac{3}{4}$  से कम नहीं हानी चाहिए। लेकिन स्वर्ण अथवा स्वर्ण-मुद्रा अथवा दोनों मिश्रकर ४० करोड़ रुपये हान ही चाहिए। शेष सम्पत्ति यथा  $\frac{3}{4}$  या ६० प्रतिशत भाग रुपये का मुद्राओं रुपये की प्रतिभूतियों तथा व्यापारिक वित्त में रखी जाती है। इस ६० प्रतिशत में से रुपये की प्रतिभूतियाँ कुल सम्पत्ति के  $\frac{3}{4}$  से अधिक अथवा ५० करोड़ रुपये से अधिक (जो भी अधिक हो) नहीं हानी चाहिए। गवर्नर जनरल की पूर्व अनुमति से ये प्रतिभूतियाँ १० करोड़ रुपये से अधिक हो सकती हैं (अर्थात् ६० करोड़ रुपये की हो सकती हैं)। = फरवरी १८६१ के आदेशानुसार यह नियम समाप्त कर दिया गया है तथा रुपये की प्रतिभूतियाँ के सम्बन्ध में कोई मर्यादा नहीं है। स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ में तीन प्रकार की प्रतिभूतियाँ का समावेश होता है —

१ वह शेष जो बैंक ऑफ इंग्लैण्ड में भारत के नाम जमा है

२ वे प्रतिज्ञा-पत्र जिन पर दा या दा में अधिक व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं ९० दिन की अवधि में अधिक न हो तथा समुक्त राज्य में आहरित (drawn) हो या जिनका भगतान समुक्त राज्य में हो तथा

३ पांच वर्ष की अवधि में भगतान किया जाने वाले समुक्त राज्य की सरकार के ऋणपत्र।

स्वर्ण तथा स्वर्ण मुद्राओं का २५ प्रतिशत अथवा  $\frac{1}{4}$  भाग भारत में रिजर्व बैंक अथवा उसके प्रतिनिधि के पास रहना चाहिए। उसके शेष  $\frac{3}{4}$  भाग देश के बाहर भी रखा जा सकता है। ४० प्रतिशत के नियम को गवर्नर जनरल की अनुमति से प्रथम ३० दिन की अवधि के लिए और उसके बाद १५, १५ दिन के लिए भंग किया जा सकता है। इस परिस्थिति में अगर सम्पत्ति का अविभाज्य कुल सम्पत्ति के ३२½ प्रतिशत से कम न हो तो गवर्नर जनरल का बन्द-बंदी १ प्रतिशत अधिक की बन्दी पर कर देना होगा तथा ३२½ प्रतिशत से भी कम हो तो प्रथम ११ प्रतिशत अथवा उसके भाग की बन्दी पर पहले की अपेक्षा १½ प्रतिशत की वार्षिक दर से अधिक कर (tax) देना होगा।

सम्पत्ति में स्वर्ण अथवा स्वर्ण मुद्रा का मूल्यांकन २६७७ ग्राम प्रति रुपये की दर से रुपये का मूल्य उसके व्यक्ति मूल्य से तथा प्रतिभूतियों का मूल्य बाजार-दर से किया जायगा।

देय पारस्व में कुल पत्र मुद्रा जो चलन में है तथा जो रिजर्व बैंक के वित्त विभाग में है उसका समावेश किया जाता है।

### द्वितीय विश्वयुद्ध-काल (१९३९-१९४६)

द्वितीय युद्ध प्रारम्भ हात ही जनता में आतंक फैल गया जिसकी तीव्रता प्रथम विश्व युद्ध की अपेक्षा कम थी। आरम्भ में जनता ने पत्र मुद्रा के बदले रुपये मागना शुरू किया, फलस्वरूप अगस्त १९४० तक रिजर्व बैंक के पास लगभग २२ करोड़ रुपये की पत्र मुद्राएँ वापिस आ गयीं। इनके बदले रिजर्व बैंक ने जनता का रुपये दिये। परन्तु फिर भी पत्र मुद्रा के बदले रुपये की माग घटती ही गयी जिस राकने के लिए सरकार ने जून १९४० में एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पास आवश्यकता से अधिक रुपये नहीं रख सकता था। इस आदेश का परिणाम यह हुआ कि पत्र मुद्रा के बदले अब छोटे छोटे सिक्कों की माग घटने लगी। इसी प्रकार पत्र मुद्रा के बदले जो रुपये की मांग थी उसे पूरा करने के लिए जुलाई १९४० से १ रु० की पत्र मुद्राएँ चलायी गयीं जो सभी कार्यों के लिए रुपये के सिक्कों के बराबर घोषित की गयीं। रुपये की कमी को दूर करने के लिए फरवरी १९४३ में शुरू की पत्र मुद्राएँ रिजर्व बैंक द्वारा चलायी गयीं।

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उर्तखनीय है —

१ ११ जनवरी १९४६ के अध्यादेश से सरकारी कोषों में तथा बैंकों के पास जितनी पत्र-मुद्राएँ इस तारीख का व्यापार के अन्त में रहनी उनका विवरण रिजर्व बैंक को १२ जनवरी को २ वजे तक भेज देना था। इस विवरण में १००, ५००, १००० तथा १०,००० की पत्र मुद्राओं का परिमाण (quantity) अलग-अलग देना था। इसका हेतु यह था कि रिजर्व बैंक को १०० रु० एवं इससे अधिक राशि की पत्र-मुद्राओं का पूरा पूरा विवरण मिल सके।

२ असर अध्यादेश के अनुसार १०० तथा इससे अधिक मूल्य की पत्र-मुद्राएँ १२ जनवरी १९४६ का चलन से निकाल दी गयीं तथा उनका परिवर्तन कुछ विशेष शर्तों पर ६० दिनों के अन्दर छोटी पत्र मुद्राओं में हो सकता था। यह आदेश १२ जनवरी १९४६ को निकाला गया। इसके बाद परिवर्तन की अवधि २६ अप्रैल १९४६ तक बढ़ा दी गयी। यह आदेश केवल ब्रिटिश भारत के लिए ही लागू था। इसके बाद यह आदेश कुछ गुजरात के बाद अन्य साम-कीय विभागों में भी लागू कर दिया गया तथा परिवर्तन की अन्तिम तिथि ६ मार्च १९४६ घोषित की गयी। इस आदेश का हेतु बड़ी-बड़ी राशि की पत्र-मुद्राओं का चलन बन्द करना तथा चोरबाजारी को रोकना था क्योंकि

सरकार के अनुसार बड़ी-बड़ी रकमा के नाटा स चोरवाजारी करन म सुविधा होनी है। इसका दूसरा उद्देश्य व्यापारिया द्वारा चोरवाजारी स प्राप्त की हुई रकम एक लाभ का पता लगाना था।

इसके बलावा मुद्रा-काल म पत्र-चलन की सस्या म काफी वृद्धि हुई। १९३६ म जहाँ १७८ करोड रुपय की मुद्राएँ चलन म थी वहा व दिसम्बर १९४७ म १२४२ कराड रुपय की हा गयी।

उस प्रकार एक ओर पत्र मुद्रा का चलन बढ रहा था और दूसरी ओर उत्पादन का परिमाण घट रहा था, जिसके कारण भारत म मुद्रास्फीति हुई और वस्तुओं की कीमत बढन लगी। पत्र मुद्रा का चलन किम प्रकार बढता गया यह निम्न तालिका से स्पष्ट होगा —

वर्ष	पत्र-मुद्रा चलन (कराड रुपया म)
अगस्त १९३९	१७८
अगस्त १९४१	१७७
अगस्त १९४२	४७४
जनवरी १९४३	५६३
जनवरी १९४४	८५६
जून १९४५	११५२
दिसम्बर १९४५	११५४

युद्ध के बाद (१९४६-१९६०)

युद्ध के बाद भी पत्र मुद्रा की सस्या बढती ही जा रही थी जा जनवरी १९४८ म बढकर १२७७ कराड रुपय और जून १९६६ म १०५४ करोड रुपय हो गयी। इस प्रकार युद्ध के बाद जा पत्र-मुद्राएँ चलन म थी उनक आकड़े निम्न तालिका मे दिय हैं —

वर्ष	पत्र मुद्रा चलन (कराड रुपया मे)
१९४५-१९४६	११६७६४
१९४६-१९४७	१२२२६०
१९४७-१९४८	१२२७८०
१९४८-१९४९	१०३१८४
१९४९-१९५०	११०८८६
१९५०-१९५१	११६३०१
१९५१-१९५२	११८८८५
१९५२-१९५३	१११४८४
१९५३-१९५४	११३३८४

<sup>1</sup> R B I Report on Currency and Finance 1953-54, p 137.

इस पत्र-चलन की सुरक्षा के लिए रिजर्व बैंक के चलन-विभाग में केवल स्टलिङ्ग प्रतिभूतियाँ बँडती गयी परन्तु स्वर्ण वा परिमाण वही रहा —

वर्ष	स्वर्ण एवं विदेशी स्वर्ण-मुद्राएँ (लाख रुपये में)	स्टलिङ्ग विदेशी प्रतिभूतियाँ (लाख रुपये में)	रुपया प्रतिभूतियाँ (लाख रुपये में)
१९४५-४६	४,४४०	१,०६,१२६	५७,८४
१९४६-४७	४,४४२	१,१३,३८८	५७,८४
१९४७-४८	४,४४०	१,१३,५३०	६०,८४
१९४८-४९	४,२४९	६०,७४७	७६५,६२
१९४९-५०	४,०००	६४,७०४	४१५,३६
१९५०-५१	४,००२	६४,४७०	४५८,४७
१९५१-५२	४,००२	६२,५२७	४८८,३६
१९५२-५३	४,०००	५६,८४०	४५८,०८
१९५३-५४	४,००२	५२,४००	४३०,११

१९४७ में भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का सदस्य बन जाने से चलन-विभाग में मुद्रा-कोष के किसी भी सदस्य देश की प्रतिभूतियाँ रखी जा सकती हैं। इस हेतु रिजर्व बैंक विधान की ३३वीं धारा का संशोधन कर दिया है।

नये नोट—१९४६ में १०० रुपये से अधिक मूल्य की पत्र-मुद्राओं के विमुद्रीकरण का जान से जनता को काफी अमृविधाएँ हो रही थी। इसलिए रिजर्व बैंक एक्ट में १९५३ में संशोधन किया गया जिससे उसे पुन ५००, १०००, ५००० और १०००० रुपये की पत्र-मुद्राएँ बनाने का अधिकार मिला। रिजर्व बैंक ने १ अप्रैल १९५४ से १०००, ५००० और १०००० रुपये के नोटों का चलन आरम्भ किया। ये नोट विमुद्रीकृत (demonetised) नोटों से पृथक् डिजाइन और रंग के हैं। इस प्रकार अब रिजर्व बैंक २, ५, १०, १००, ५००, १०००, ५००० और १०००० रुपये के नोट चला सकता है।

न्यूनतम निधि पद्धति—इसके बाद १९५६ में रिजर्व बैंक एक्ट में पुन संशोधन किया गया जिसमें नोट-चलन की न्यूनतम निधि पद्धति अपनायी गयी है। इस हेतु रिजर्व बैंक के स्वर्ण वा पुनर्मूल्यन ६२ रु० ५० न० ५० प्रति तोले की दर से किया गया है। इस संशोधन से रिजर्व बैंक को नोट-चलन विभाग में न्यूनतम ११५ करोड़ रुपये का स्वर्ण वा स्वर्ण के सिक्के तथा ४००

करोड़ रुपये की विदेशी प्रतिभूतियाँ रखना अनिवार्य है। किन्तु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रथम ९ मास के लिए तथा इसके बाद प्रति तीन मास के लिए विदेशी प्रतिभूतियों की राशि ३०० करोड़ रुपये तक रखी जा सकेगी।

देश में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण २१ अक्टूबर १९५७ के अध्यादेश से न्यूनतम निधि की राशि घटा दी गयी है। अब स्वर्ण एवं विदेशी प्रतिभूतियाँ मिलाकर २०० करोड़ रुपये न्यूनतम निधि होनी चाहिए, परन्तु किसी भी स्थिति में स्वर्ण एवं स्वर्ण मिश्रण की राशि १२५ करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति से इस निधि को कम किया जा सकेगा।

### पत्र-चलन पद्धति के दोष

१ एक निश्चित मूल्यमापक का अभाव है क्योंकि पत्र-मुद्रा किसी भी निश्चित धातु में परिवर्तनीय नहीं है किन्तु फिर भी असीमित विधिप्राप्त है जो हमारे देश की स्थिति को देखने हुए बहुत बड़ी कमजोरी है।

२ पत्र-मुद्रा की परिवर्तनशीलता रखने के लिए हम विदेशी प्रतिभूतियों पर निर्भर हैं जिनकी राशि पत्र-चलन निधि में बहुत कम है। अतः इस पर आधारित हमारा पत्र-चलन भी अपरिवर्तनीय है, जो बड़ी कमजोरी है।

३ लोच का अभाव है, अर्थात् व्यापारिक आवश्यकता का अनुसार मुद्रा का प्रसार एवं सकोच नहीं होता क्योंकि जो ग्राह्य चलन में साथ जाते हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाने पर वे वापस रिजर्व बैंक में नहीं आते जिससे मुद्रा सकोच भी आसानी से नहीं हो सकता। जब तक हमारी चलन-पद्धति प्रत्यक्ष रीति से देश के उत्पादन-संगठन तथा वितरण-व्यवस्था में सम्बन्धित नहीं होनी तब तक मुद्रास्फीति अवश्य हो सकती है, और आज है।

४. यद्यपि भारत में न्यूनतम निधि पद्धति अपनायी गयी है फिर भी उसमें अत्यधिक प्रसार के विरुद्ध सुरक्षा का कोई आयोजन नहीं है, क्योंकि पत्र-चलन की अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की गयी है।

५. पत्र-चलन के इतने अधिक प्रसार होने पर भी पाश्चात्य देशों की तरह हमारे यहाँ निक्षेप-चलन (deposit currency) का उपयोग नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि हमारी कुल राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के चलन में परस्पर सम्बन्ध नहीं है।<sup>१</sup>

<sup>१</sup> See Report of the National Planning Committee on Currency and Banking, pp. 33-36

## वर्तमान पत्र-चलन व्यवस्था

रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व भारत में सरकार द्वारा चलन-सिद्धान्त (currency principle) के अनुसार पत्र-मुद्रा चलाई जाती थी। परन्तु १९३५ से बैंकिंग अधिकोपण सिद्धान्त तथा आनुपातिक निधि पद्धति के अनुसार पत्र-मुद्राएँ चलाई जाती हैं। इसके अनुसार रिजर्व बैंक को पत्र-मुद्रा के बदले ४० प्रतिशत निधि स्वर्ण, स्वर्ण मुद्राओं एवं विदेशी प्रतिभूतियों में रखना पड़ता है। इस भाग को स्वर्ण भाग (gold portion) कहते हैं जिसमें किसी भी समय ४० करोड़ रुपये से कम कीमत का स्वर्ण नहीं होना चाहिए। दूसरे भाग में रुपये एवं रुपये की प्रतिभूतियाँ आदि रखी जाती हैं जो कुल पत्र-चलन के ६०% तक रखी जा सकती हैं। विदेशी प्रतिभूतियाँ उन सभी देशों की रखी जा सकती हैं जो अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य हैं।

२. भारत में परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय दोनों ही प्रकार की पत्र-मुद्राएँ चलन में हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा चलाये हुए २, ५, १०, १००, ५००, १०००, ५००० एवं १०००० रुपये के नोट परिवर्तनीय तथा भारत सरकार द्वारा चलाय गये १ रुपये के नोट अपरिवर्तनीय हैं।

३. १९५८ से न्यूनतम निधि पद्धति के अनुसार पत्र-मुद्राओं का चलन होता है इसलिए हमारी पत्र-चलन पद्धति में लोच भी रहती है। अर्थात् वह व्यापारिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुसार घटाई बढ़ाई जा सकती है।

## सारांश

सर्वप्रथम भारत में बैंक ऑफ बंगाल को १८०६ में, तथा इसके बाद बम्बई, बंगाल और मद्रास के प्रेसीडेंसी बैंकों को नोट चलाने का अधिकार मिला। ये नोट इनके प्रेसीडेंसी क्षेत्र में ही चलने थे तथा इनके लिए ३३⅓% स्वर्ण-निधि रखना अनिवार्य था।

१८६१ में भारत सरकार ने नोट-चलन का एकाधिकार लिया। इस हेतु भारत को बम्बई, कलकत्ता और मद्रास इन तीन विभागों में बाँट दिया गया और एक नोट-चलन विभाग की स्थापना की गयी। भारत सरकार ४ करोड़ रुपये के नोट प्रतिभूतियों के आधार पर चला सकती थी। इससे अधिक चलन के लिए शत प्रतिशत स्वर्ण रखना अनिवार्य था। इस कारण इसमें लोच एवं मितव्ययिता नहीं थी।

१८६३ में अस्तित्व नोट-चलन की सीमा ८ करोड़ रुपये की गयी तथा

वर्मा को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में नोटों की विधिप्राप्त बनाया गया। १९१० में कानपुर, रंगून, लाहौर और कराची भी पत्र-चलन क्षेत्र में आ गये।

१९१३ में अरक्षित पत्र-चलन की सीमा १४ करोड़ रुपये की गयी जिसमें १० करोड़ रुपये की प्रतिभूतियाँ भारत में तथा ४ करोड़ रुपये की इंग्लैंड में रखी जाती थी। चेम्बरलेन समिति की सिफारिश के अनुसार अरक्षित नोट-चलन की सीमा २० करोड़ रुपये की गयी परन्तु अन्य सिफारिशों पर कार्यवाही न हो सकी।

१९१४ में महायुद्ध आरम्भ होते ही सरकारी कठिनाइयों को हल करने के लिए (२) व २१) रुपये के नोट चलाये गये तथा १९१९ में अरक्षित नोट चलन की सीमा १२० करोड़ रुपये की गयी। युद्ध के कारण पत्र-चलन में निम्न प्रमुख परिवर्तन हुए—(१) नोटों की संख्या तिगुनी हो गयी।

(२) पत्र-चलन निधि का धातु-भाग ७६ ६% से १९१९ में ३५ ८% रह गया।

(३) पत्र-चलन निधि में प्रतिभूतियों का भाग ३१% से ५४% हो गया।

१९१९ में बेबिंगटन स्मिथ समिति ने नोट-व्यवस्था का अध्ययन किया तथा नोट-चलन कोष में ४०% धातु निधि रखने की सिफारिश की। इस सिफारिश के अनुसार १९२० में पत्र-चलन-संशोधन कानून बना तथा धातु निधि ५०% रखा गया। १९२१ में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों के एकीकरण से इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई तथा इसे सकटी नोट-चलन का अधिकार मिला। १९२३-२४ में सकटी नोट-चलन की सीमा १२ करोड़ रुपये की गयी।

१९२५ में हिट्टन यंग समिति ने केन्द्रीय बैंक की स्थापना कर उसे नोट-चलन का एकाधिकार देने तथा नोट चलन को आनुपातिक कोष प्रणाली अपनाने की सिफारिश की। इस हेतु १९२७ में करेंसी एक्ट स्वीकृत हुआ।

१९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना से स्वसंभाल निधि एवं पत्र-चलन निधि का एकीकरण होकर नोट चलन का एकाधिकार इसे मिला। नोट-चलन की आनुपातिक कोष प्रणाली भी अपनायी गयी। रिजर्व बैंक इस समय २, ५, १०, १००, ५००, १००० और १०,००० रुपये के नोट चलता है। १९५६ से नोट चलन की न्यूनतम कोष प्रणाली अपनायी गयी है। इससे वर्तमान नोट-प्रणाली लोचदार एवं मितव्ययी हो गयी है।

## हमारे पौंड-पावने

द्वितीय युद्ध की भारतवर्ष को सबसे बड़ी देन स्टर्लिंग-पावने अथवा पौंड पावने है, जिनके आधार पर हमारे यहाँ पत्र-मुद्रा प्रसार बढ़ाया गया। इस काल में भारत ने अपने स्टर्लिंग ऋण को तो चुका ही दिया, इसके अतिरिक्त भूखे पेट और नंगे बदन रह कर ब्रिटेन को करोड़ों रुपये का माल भेजा तथा ब्रिटेन को युद्ध-ज्यय में मदद दी। जो माल हम भेजते थे उसके बदले में हमारे पौंड पावने इंग्लैंड में जमा होते रहते थे। इस प्रकार हम इंग्लैंड के ऋणी की जगह अब उसके लेनदार बन गये। इनकी वृद्धि में दो बातें उल्लेखनीय हैं —

१ भारत में भारत सरकार ने ब्रिटेन की ओर से जो युद्ध-सामग्री खरीदी उसका मूल्य (यह सामग्री नियन्त्रित मूल्यों पर खरीदी गयी थी), तथा

२ भारत सरकार द्वारा ब्रिटिश सरकार के नाम वह राशि जो मुद्रा-मन्त्रालय के निग व्यय की गयी।

यह सब रकम हमारे रिजर्व बैंक में पौंड प्रतिभूतियों के रूप में है। इसकी वृद्धि किस प्रकार हुई यह निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट हो जायगी —

( करोड़ रुपयों में )

१९३६-४०	१४७
१९४०-४१	१४४
१९४१-४२	७८४
१९४२-४३	५११
१९४३-४४	६४१
१९४४-४५	१४७२
१९४५-४६	१६८०

रिजर्व बैंक की जनवरी १९४७ की पत्रिका के अनुसार ये पावने १६७१ ३२ करोड़ रुपये के थे जिसमें से ११३५ ३२ करोड़ रुपये की स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ चलन-विभाग में तथा ४८६ करोड़ रुपये की बैंकिंग विभाग में थी। इससे

स्पष्ट है कि नवम्बर १९४६ के बाद पौड-पावनो की रकम हमारे आयात के भुगतान के कारण कम हो गयी। लेकिन १९४७ के अन्त तक हमारे पौड पावने फिर से बन्दर १६५७ करोड रुपये के हो गये।

### पौड-पावनो का भुगतान

१९४४ की ब्रेटनवुड्स परिषद में स्पर्गीय लॉर्ड वीन्स ने कहा था कि पौड-पावनो का भुगतान पूर्ण न्याय रूप में होना चाहिए। इनका उच्चतम आकडा अप्रैल १९४५ में १७३३ करोड रुपये था किन्तु बाद में युद्ध सम्बन्धी व्यय कम होने तथा खाद्यान्न आदि के आयात के कारण यह कम होने लग्य और जुलाई १९४७ में केवल १५४७ करोड रुपये के रह गये। युद्ध-काल में भारत ने जो त्याग किये, उत्पादक यन्त्रों की जो क्षिमावट हुई, उसी का फल हमारे पौड-पावने थे, जो डा० हिक्स के मतानुसार हमारे 'अवमूल्यन षण्ड' के रूप में जमा होने रहे तथा इन पर भारत का अधिकार न्यायोचित है। युद्ध के बाद हमारे औद्योगीकरण के लिए इसका पूर्ण एवं समुचित उपयोग होना चाहिए था। किन्तु युद्ध के समय जो भारत की उदारता एवं त्याग का उल्लेख करते थे वे युद्ध समाप्त होते ही उन्ही बात करने लगे और इनकी कमी करने के लिए दलीलें पेश करने लगे।

१ चूँकि भारत की रक्षा के लिए यह व्यय करना पडा था इसलिए इस ऋण में कमी की जानी चाहिए।

२ पौड-पावना को युद्ध-सम्बन्धी ऋण समझना चाहिए और जैसे अमरीका ने उधार-पट्टा ऋण से इगनैण्ड की मुक्त कर दिया वैसे ही भारत को मुक्त कर देना चाहिए।

३ रुपये की दर कृत्रिम रूप में ऊँची रखी गयी थी इसलिए ब्रिटेन भारत का ऋणी हो गया, वैसे तो रुपये का मूल्य स्टर्लिंग में केवल ६ पस ही रह गया था।

४ ब्रिटेन की वर्तमान आर्थिक स्थिति तथा ऋण-भुगतान की शक्ति बहुत घट गयी है इसलिए भी इन ऋणों में कमी हो जानी चाहिए।

ये सभी इंगलैंड के राजनीतिज्ञों द्वारा इसलिए भी प्रस्तुत की गयी होगी जिनसे इस ऋण में किसी तरह छुटकारा मिले। क्योंकि इस समय इंगलैंड स्वयं भी आर्थिक सहायता के लिए अमरीका का मँह तक रहा था।

परन्तु नूतन दृष्टि में विचार करने पर इन दलीलों में कोई भी तथ्य नहीं दिखाई देता। इसके साथ ही ब्रिटेन में जो राजनीतिर परिवर्तन हुए तथा

धन-पक्षीय सरकार आयी उसने हमारे पौड-पावनों का भुगतान करने का निर्णय लिया।

### पौड-पावनों का महत्व

यह विदेशों में हमारी सबसे बड़ी पूंजी है जिसका समुचित उपयोग हमारी आर्थिक समस्याओं का सरलता से समाधान कर सकता है। हमारे उद्योगीकरण के लिए इनसे हमको यन्त्र सामग्री मिल सकती है किन्तु इसकी पूर्ति करने में ब्रिटेन अथवा स्टलिङ्ग-क्षेत्र के देण असमर्थ ही नहीं हैं अपितु ब्रिटेन स्वयं ही आर्थिक संकट से मुक्त होने के लिए मार्शल योजना पर अभी तक निर्भर रहा है। अतएव हमको भी यन्त्रादि की पूर्ति के लिए समुक्त राष्ट्र अमेरिका पर ही निर्भर रहना पड़ेगा इसलिए यहाँ के चलन में इन पावनों का परिवर्तन होना आवश्यक है। जब तक यह हमारी आवश्यकतानुसार नहीं होता, हमारी योजनाएँ कार्यान्वित नहीं हो सकती। हमारे पास इतना स्वर्ण भी नहीं है जिसके आधार पर हम विदेशों से आयात कर सकें। इसलिए इन पावनों के भुगतान सम्बन्धी ब्रिटेन के साथ समझौते हुए जिनके अनुसार ब्रिटेन हमको सब भुगतान एक नाथ नहीं करेगा।

### पौड-पावने सम्बन्धी भारत और ब्रिटेन के समझौते

१ जनवरी १९४७ में पहला समझौता हुआ, जिसके अनुसार भारत अपनी आवश्यकताएँ स्टलिङ्ग-क्षेत्र से खरीद सकता था तथा उसको यदि दुर्लभ चलन अथवा डॉलर क्षत्र से ही वस्तुओं की आवश्यकता हो तो पौड पावनों का परिवर्तन डॉलर अथवा अन्य मुद्राओं में कराने का भी उसे अधिकार था। यह समझौता अधिक दिन तक न चल सका क्योंकि इसी बीच ब्रिटेन और अमरीका के बीच आर्थिक समझौता होने में परिस्थिति बदल गयी।

२ अगस्त १९४७ को दूसरा समझौता हुआ जिसकी अवधि दिसम्बर १९४७ एवं क्षेत्र विदेशी विनिमय तक ही सीमित था। इस समझौते से स्टलिङ्ग-पावने दो ग्वातों में बाँटे गये—एक चम लेखा तथा दूसरा स्थिर लेखा (blocked accounts) जो भारत के नाम बैंक ऑफ इंग्लैंड में खोले गये। चल-ग्वाता ८६६ करोड़ रुपये में खोला गया जिसमें में केवल ३ करोड़ का उपयोग दुर्लभ चलन की प्राप्ति के लिए हो सकता था तथा नये पौड पावने की कमाई भी इसी में जमा हो सकती थी। दोष १४६६६ करोड़ रुपये के पावने स्थिर ग्वाते में विशेष पूँजी, प्रॉविडेण्ट फण्ड पूर्व-सेवा वेतन (pension) आदि के भुगतान के लिए रखे गये। इस प्रकार चल-ग्वाते के ८३२ करोड़ रुपये के स्टलिङ्ग क्षेत्र

मे ऋय के लिए तथा शेष ३ करोड डॉनर-क्षेत्र से ऋय के लिए रखे गये । इस समझौते की अवधि ६ मास तक (३० जून १९६८ तक) और बटा दी गयी थी लेकिन भारत के विभाजन मे स्टलिङ्ग-पावनों का विभाजन पाकिस्तानी लेगा और भारतीय लेखा मे कर दिया गया जिसके अनुसार पाकिस्तानी चल-खाते मे १३३ करोड रुपये के पावने डाले गये जिसका केवल १५ भाग दुर्लभ चलन की प्राप्ति करने के लिए उपलब्ध था ।

३ तीसरा समझौता चेद्री-रिफ्ल समझौते नाम मे प्रसिद्ध है । यह १५ जुलाई १९६८ को प्रकाशित हुआ तथा इसके अनुसार हमारे कुल पौड-पावनों के ४८% का भुगतान चेद्री की अमीम उदारता के कारण हों चुका तथा हमारे पौड-पावने १५४७ करोड रुपये की जगह केवल ८०० करोड रुपये के ही रह गये । इस समझौते की मुख्य शर्तें निम्नलिखित है —

(क) भारत मे छोडा गया फौजी सामान १ अप्रैल १९४७ को भारत ने अपने अधिकार मे ले लिया जिसका पुस्तक मूल्य (book value) ५०० करोड रुपये दिया गया । इस सामान का भुगतान करने के लिए भारत १३३ करोड रुपये के पावने देगा ।

(ख) संयुक्त राज्य के भारतीय सेवा निवृत्त व्यक्तियों को पूर्व-सेवा वेतन देने का भार भारत सरकार पर है जो ६२५ लाख पौड अथवा ८ करोड रुपये वार्षिक है । इसलिए इस रकम का पूंजीकरण (capitalisation) करने के लिए इंग्लैंड को १९७ करोड रुपये के पौड-पावने दिये जाएं जिसमे से संयुक्त राज्य उनको पूर्व-सेवा-वेतन का जो शर्तें-शर्तें कम होना आयगा, भुगतान करेगी । यह केवल केन्द्रीय सेवा-निवृत्त व्यक्तियों के लिए ही था ।

इसके अतिरिक्त २७ करोड पौड-पावनों का नियोजन प्रांतीय सेवा-निवृत्त व्यक्तियों के भुगतान के लिए किया गया है । इस प्रकार १९७ करोड तथा २७ करोड रुपये की दो वार्षिकी (annuity) भारत सरकार ने सहीद ली है जिस पर हमको केवल १ प्रतिशत व्याज मिलेगा । (अन्य पावनों पर ८ प्रतिशत व्याज है ।)

(ग) पिछले समझौते के अनुसार १११ करोड रुपये के पौड-पावने उठाने का अधिकार भारत को था जिसमे से केवल ४ करोड का उपयोग हो सका है । अब शेष १०७ करोड उठाने का अधिकार तो है ही, इसके अतिरिक्त अगले तीन वर्षों मे ब्रिटेन १०७ करोड रुपये के पौड-पावने चुकाने के लिए तैयार

था। इस प्रकार कुल २१४ करोड़ रुपये के पावने उपलब्ध थे। नाब ही व्यापा, रिब शेप की अनुकूल राशि भी प्राप्य थी।

(घ) उक्त १०७ करोड़ रुपये के पौड-पावनों में से हम प्रथम वर्ष में २० करोड़ रुपये के पावनों का परिवर्तन डॉलर में कर सकते थे।

(ङ) हमारे अतिरिक्त २०० मिलियन स्टर्लिंग अथवा २६७ करोड़ रुपये के पौड-पावने चलन-निधि के रूप में रखे जायेंगे, जिनके भुगतान सम्बन्धी प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

इस समझौते की बटु आलोचना की गयी फिर भी क्या हो सकता था। हाँ, इसमें भारत को आयात के लिए जिनकी राशि की आवश्यकता थी वह उसे अवश्य मिल गयी।

४ चौथा समझौता अर्थ-मन्त्री श्री जॉन मथाई ने जुलाई १९४६ में किया जिसकी अवधि भी जून १९५१ तक है। इसके अनुसार गत वर्षों में स्थिर लेखों में लिए हुए १० करोड़ के पावनों का अपलेखन (written off) किया गया तथा निश्चय हुआ कि इस लेख में जून १९५१ तक निश्चित रकम के अतिरिक्त पावने नहीं ले सकेंगे। दूसरे, स्थिर लेखों से अगले दो वर्षों में अर्थात् १९४६-५० एवं १९५०-५१ के लिए प्रति वर्ष ६६.६ करोड़ रुपये अथवा ५० मिलियन पौड के पावने प्रति वर्ष भारत निकाल सकता है (पिछले वर्ष के लिए यह मर्यादा ४० मिलियन पौड अथवा ५३ करोड़ रुपये थी)। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन ने यह भी स्वीकार किया कि हमारे धान्य आयात के लिए जुलाई १९४६ के पूर्व जो आदेश आ चुके हैं उनके भुगतान के लिए भी स्टर्लिंग पावने दिए जायेंगे। इसके अलावा डॉलर क्षेत्रों से आयात में २५% कटौती करना तय हुआ था।

इस प्रकार जॉन मथाई द्वारा किया हुआ समझौता खेटी-बिज्ज समझौते की अपेक्षा अधिक लाभदायक था। कारण १९४६ के समझौते में तो भारत को केवल २० करोड़ रुपये के स्टर्लिंग ही (अथवा ६ करोड़ डॉलर) डॉलर में परिवर्तन के लिए मिल सकते थे, जहाँ इस समझौते से भारत को प्रति वर्ष १५ करोड़ डॉलर मिलने की व्यवस्था हो गयी। परन्तु मितम्बर १९४६ में स्टर्लिंग का अवमूल्यन होने से हमारे स्टर्लिंग का मूल्य ३०.५ प्रतिशत में कम हो गया था जिससे हमको कम डॉलर मिलने लगे।

५ पाँचवाँ समझौता फरवरी १९५२ में हुआ जब श्री चिन्तामणि देवमुत्त राष्ट्रीय-अर्थमन्त्री सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंग्लैंड गये थे।

यह समझौता २० जून १९५७ को समाप्त होने वाले ६ वर्षों के लिए हुआ ।<sup>१</sup> इस समझौते के अनुसार हमारे स्थिर खाते में से प्रति वर्ष ३५ मिलियन स्टर्लिंग पावने चल खाने में जमा लिए जाएंगे, जो भारत प्रति वर्ष खर्च कर सकेगा । इसके अलावा स्थिर खाते में से चल खाने में ३१० मिलियन पौंड की एक और राशि जमा की जायेगी । यह राशि रिजर्व बैंक के पाम चलन निधि ( currency reserve ) के रूप में रहेगी जिसका उपयोग केवल मकद-काल में ही किया जा सकता है ।

चल-खाने में ३५ मिलियन पौंड की राशि तभी जमा की जावेगी जब कि चल-खाने की राशि २५० मिलियन पौंड में अथवा जो राशि भारत और ब्रिटिश सरकार के आपसी समझौते में तय हो जाय—रुम हो । इसी प्रकार यदि किसी वर्ष में ३५ मिलियन स्टर्लिंग का उपयोग भारत न कर सके तो उस राशि का उपयोग आगामी वर्षों में किया जा सकता है । वैसे ही यदि किसी वर्ष में भारत के खर्च ३५ मिलियन पौंड में अधिक होने की आशंका हो तो अगले वर्ष की राशि में से ५ मिलियन पौंड का उपयोग करने के लिए भारत स्वतंत्र है । परन्तु यदि यह राशि दोगे अधिक होती है तो उस दना में ब्रिटिश सरकार के साथ विचार-विमर्श करके अधिक राशि का उपयोग हो सकता था ।

इस प्रकार इस समझौते के अनुसार भारत २० जून १९५७ तक १०५ मिलियन पौंड की राशि का उपयोग कर सकता है । इसके बाद जो भी पौंड-पावनों की राशि शेष रहेगी, वह अपने आप चल-खाने में जमा कर दी जावेगी ।

इस समझौते में पौंड-पावने के भुगतान सम्बन्धी सभी शर्तें दूर हो गयी हैं ।

६ यह वार्ता जुलाई १९५२ में हुई तथा तत्कालीन वित्त मंत्री श्री देशमुख ने घोषित किया कि १९५२ के समझौते के अनुसार ३० जून १९५७ तक पौंड-पावनों का भुगतान होना रहेगा । मार्च १९५२ में ७२५ करोड़ रुपये के पौंड-पावने थे जिनका भुगतान भारत २० जून १९५७ तक ने लेगा । उनमें से २६० करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था प्रथम योजना के लिए की गई थी । यह आशा है कि योजना-युग में इनका अधिकतम सदुपयोग करने के प्रयत्न होंगे ।

७ यह समझौता १९५५ में हुआ था । इस समझौते के अनुसार भारत सरकार ने ब्रिटिश सेना निवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के लिए जो वार्षिकी ( annuity ) १९४७ में सरोदी थी उसकी अधिक रकम वापिस देने के लिए

<sup>१</sup> R. B. I. Report on Currency & Finance 1951-52.

तैयार हो गयी है। यह अतिरिक्त राशि लगभग ४ करोड़ पौंड है। इस समझौते के अनुसार इंग्लैंड ने अप्रैल १९५५, १९५६ और १९५७ में प्रति वर्ष ४० लाख पौंड तथा अप्रैल १९५७ में १०६० करोड़ पौंड की वापसी की। इस वर्ष (१९५६) में १ करोड़ पौंड वापस करेगा। इस प्रकार सरकार को जो वार्षिकी खरीदने में घाटा था उसका कुछ भाग वापिस मिल गया है।<sup>१</sup>

दूसरी योजना की अवधि में २०० करोड़ रुपये की राशि पौंड पावनों में निकालने का आयोजन है। १९५५ के आरम्भ में भारत के ७३१ करोड़ रुपये के पौंड पावने शेष थे।

### माराश

पौंड-पावने द्वितीय विश्व-युद्ध की भारत को देन है क्योंकि युद्ध-काल में भारत में इंग्लैंड को युद्ध संचालन की सामग्री की पूर्ति की तथा सुरक्षा-व्यय किया। इसकी राशि के बदले हमको पौंड प्रतिभूतियाँ मिलीं जिसे पौंड-पावना कहते हैं। इनकी राशि १९३६ ४० में १४२ करोड़ रुपये थी जो १९४५ ४६ में १६८० करोड़ रुपये हो गयी।

युद्ध-काल में इनके भुगतान का कोई सवाल न था परन्तु युद्ध के बाद इस सम्बन्ध में वार्ताएँ हुई। कुछ लोगों के अनुसार इनका भुगतान नहीं होना चाहिए था और कुछ लोग जैसे प्रो० हिक्स आदि भुगतान करने के पक्ष में थे।

भुगतान के सम्बन्ध में प्रथम समझौता १९४७ में हुआ और तत्पश्चात् क्रमशः १९४७, १९४८, १९५२ एवं १९५३ में समझौते हुए। अन्तिम समझौते की अवधि ३० जून १९५७ तक है। १९५५ के आरम्भ में हमारे पास ७३१ करोड़ रुपये के पौंड-पावने शेष रहे। १९५५ के समझौते के अनुसार भारत सरकार ने वार्षिकी खरीदने में १९४७ में जो अधिक राशि ब्रिटेन को दी थी उसकी वापसी होगी। इस राशि में से ३७० करोड़ रुपये भारत को अप्रैल १९५७ तक वापिस मिल गये हैं।

## अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक संस्थाएँ

युद्धोत्तरकालीन असीमित पत्र-मुद्रा-प्रसार के कारण विश्व के सभी देशों की चलन-व्यवस्था बिगड़ चुकी थी। इस कारण विदेशी विनिमय में अस्थिरता आ गयी थी तथा आन्तरिक मूल्य भी बढ़ गये थे फलतः विदेशी व्यापार में अनेक असुविधाएँ प्रतीत होने लगी थी तथा विनिमय दर की अस्थिरता के कारण अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति होना अमम्भव हो गया था। इसी प्रकार आन्तरिक बाजार में भी कीमते अधिक बढ़ जाने से देशी व्यापार का संचालन भी ठीक तरह से नहीं हो रहा था। इस प्रकार देशी एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की प्रगति भुगतान-विषमताओं को दूर करने एवं विनिमय दर की स्थिरता के लिए अमरीका, ब्रिटेन, कनाडा आदि यूरोपीय देशों ने अनेक मौद्रिक योजनाएँ प्रस्तुत कीं। इन योजनाओं के आधार पर संयुक्त राष्ट्रसंघ की मौद्रिक तथा आर्थिक परिषद् ने १९४४ में एक योजना स्वीकार की जो ब्रटन-वुड्स समझौते के नाम से जानी जाती है। इस योजना को विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने मान्यता दी और यह निश्चित किया गया कि अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं अन्तरराष्ट्रीय बैंक की स्थापना की जाय जिससे अन्तरराष्ट्रीय सहयोग में सभी देशों का आर्थिक विकास हो सके। इस योजना को बाद में सभी देशों की सरकारों ने मान्यता दी। इन दोनों संस्थाओं का हम क्रमशः अध्ययन करेंगे।

**अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (I M F)**

कोष की स्थापना का मुख्य हेतु अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक सहाय्य बढ़ाना है जिससे अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक समस्याओं का हल सुगमता से हो सके। कोष के अन्य उद्देश्य निम्न हैं —

१ अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के समुचित विकास एवं प्रगति करने में सहाय्य होना जिससे वार्षिक आय बढ़े एवं पूर्ण रोजगारी को बढ़ावा मिले।

इस हेतु की पूर्ति के लिए कोष अपने सदस्यों को दूसरे राष्ट्रों की मुद्राएँ उधार देती है अथवा बेचती है जिससे वे अपनी भुगतान-विषमताओं का दूर कर सकें तथा जहाँ विदेशी व्यापार में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

फिर भी अपन दश की पूंजी का निर्यात-आयात रोकन के लिए सदस्य देशों को विनिमय नियन्त्रण लगान की स्तन्नता है ।

२ विनिमय दरा में स्थिरता लाकर उस कायम रखना । इसी प्रकार सदस्य देशों के बीच विनिमय सुलभता में हा सब इसीलिए समुचित विनिमय व्यवस्था स्थापित करना ।

इस हेतु कोप सदस्य देशों की मुद्राओं का स्वर्ण अथवा डॉलर मूल्य निश्चित करती है जिन दर पर ही वे आपस में अथवा काप से विदेशी मुद्राओं अथवा स्वर्ण का नये विनय करेंगे ।

३ मध्यस्थ विनिमय-अवमूल्यन का न हान देना ।

इस हेतु के अनुसार वार्ड भी सदस्य कोप की अनुमति बिना अपनी मुद्राओं का स्वर्ण अथवा डॉलर मूल्य कम-अधिक नहीं कर सकता ।

४ सदस्य देशों के चालू व्यवहारों के लिए बहुपक्षिक भुगतान (multilateral payment) सुविधाएँ बन के लिए सहायक होना ।

इस हेतु की पूर्ति के लिए सदस्य देशों द्वारा लगाय गये विनिमय नियन्त्रणों को हटान में काप सहायक होगा ।

५ सदस्य देशों के बीच होने वाली भुगतान विषमता की तीव्रता एवं अवधि को कम करना । इस हेतु की पूर्ति के लिए कोप उन्हें विदेशी मुद्राएँ देकर सहायता करेगा ।

इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि कोप का उद्देश्य अपन समस्या का विनिमय सम्बन्धी सुविधाएँ देकर उनके आर्थिक विकास के हेतु अंतरराष्ट्रीय व्यापार का बढ़ावा देना है ।

कोप की सदस्यता एवं पूंजी

कोप की कुल पूंजी १० ००० मिलियन डॉलर है, जिसमें प्रत्येक देश का कोटा निर्धारित है जो निम्नलिखित है —

देश	कोटा (मिलियन डॉलर में)
अमेरिका	२ ७५०
इंग्लैण्ड	१ २५०
रूस	१ २००
चीन	५५०
फ्रांस	६५०
भारत	६००
कनाडा	३००
नीदरलैंड्स	२७५

देश	कोटा (मिलियन डॉलर में)
आस्ट्रेलिया	२००
द० अफ्रीका	१००
ग्रीस	४०
ईरान	२५
बेल्जियम	२२५
ब्राजील	१०५
जेकोब्सबर्ग	१२५
इटली	१५०
पाकिस्तान	१००
अन्य देश	१०० से कम

जिन देशों के प्रतिनिधियों ने ब्रिटनबुद्धि परियोजना में भाग लिया था एवं २१ दिसम्बर १९८५ से पहले कोप की सदस्यता स्वीकार की है व देश मौलिक सदस्य माने जायेंगे ।

प्रत्येक देश को अपना कोटा स्वर्ण में तथा देशी मुद्राओं में देना पड़ता है । स्वर्ण का भाग कोटे के २५% प्रतिशत अथवा उम देश के 'कुल स्वर्ण एवं डॉलर-निधि' के १० प्रतिशत—दोनों में जो कम हो—और शेष भाग देशी मुद्राओं में तथा प्रतिभूतियों में देना पड़ता है । प्रत्येक सदस्य अपने कोटा का पटा-बड़ा सकता है । उसी प्रकार कोप का भी अधिकार है कि वह सदस्य देश की सम्मति से अपने कोटे को घटाये अथवा बढ़ाये ।

यदि कोई भी देश कोप का सदस्य नहीं रहना चाहता तो वह सूचना देकर कोप की सदस्यता छोड़ सकता है । इसी प्रकार कोप को भी अधिकार है कि यदि कोई सदस्य देश कोप के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता अथवा उसके नियमों की उल्लंघन करता है तो वह उम देश की सदस्यता छीन ले ।

सदस्य राष्ट्रों को अपनी मुद्रा का मूल्य स्वर्ण में अथवा १ जुलाई १९४४ को जो यू० एन० ए० डॉलर था उसमें व्यक्त करना था । इस प्रकार मुद्रा-कोप के माध्यम से विदेशी विनिमय अथवा स्वर्ण के सभी व्यवहार इन मूल्यों के आधार पर होतें हैं जिससे विनिमय दर में उतार-चढ़ाव न होतें हुए वह स्थायी बनी रहती है ।

अपनी मुद्रा के स्वर्ण कोप अथवा डॉलर मूल्य में कोई भी देश यदि चाहता तो कोप की अनुमति में परिवर्तन करा सकता है । ऐसी परिवर्तन की निम्न शर्तें हैं ।

१. कोई भी सदस्य अपनी मुद्रा के स्वर्ण अथवा डॉलर मूल्य में १०% तक परिवर्तन कर सकता है। ऐसे परिवर्तन का आवेदन प्राप्त होने पर कोप उस देश को ४८ घंटे में निर्णय देगा।

२. इससे अधिक परिवर्तन करने के लिए कोप की अनुमति आवश्यक होती है जिस सम्बन्ध में कोप अपना निर्णय तीन दिन में देगा।

३. इस प्रकार के परिवर्तन सभी किये जा सकते हैं जब उस देश की भुगतान विपन्नता एवं अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की रुकावट दूर करने के लिए आवश्यक हो।

४. कोप की सम्मति बिना परिवर्तन करने वाले देश को दण्ड देना पड़ता है।

**कोप के साथ व्यवहार**—सदस्य देश कोप के साथ निम्न शर्तों पर व्यवहार कर सकते हैं।

१. सदस्य देश कोप के साथ अपने-अपने खजानों (treasuries), केन्द्रीय बैंको अथवा अन्य आर्थिक अभिवृत्तियों के माफ़त करेंगे।

२. कोई भी सदस्य देश कोप से किसी अन्य देश की मुद्राएँ अपनी मुद्राओं के अथवा स्वर्ण के बदले में खरीद सकता है। यदि—

(क) सदस्य देश को भुगतान करने के लिए उस मुद्रा की आवश्यकता है और वह उसका उपयोग कोप के उद्देश्यों के अनुसार ही करेगा।

(ख) कोप के पास ऐसी मुद्रा की कमी हो।

(ग) यदि किसी देश-विशेष के मुद्रा की अत्यधिक माँग है जिससे उस मुद्रा का स्टॉक खत्म होने की सम्भावना है तो कोप उस देश की मुद्राएँ उधार लेगा अथवा उसे स्वर्ण के बदले में खरीदेगा। परन्तु यदि फिर भी उस देश की मुद्रा की माँग वैसे ही बनी रहती है तो उस देश की उपलब्ध मुद्राओं का विभाजन सदस्य देशों की आवश्यकतानुसार अन्तरराष्ट्रीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर किया जायगा।

(घ) कोप में यदि किसी भी समय किसी देश की मुद्रा की कमी हो तो कोप उस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा घोषित करेगा। परन्तु ऐसा करने से पूर्व किन कारणों से वह दुर्लभ मुद्रा घोषित कर दी गयी है, इस सम्बन्ध में कोप रिपोर्ट बनाकर सदस्य देशों को भेज देगा। इसमें दुर्लभता हल करने के सुझाव भी दिये जाएंगे।

(ङ) कोई भी सदस्य देश एक वर्ष में अपने कोटा के २५% में अधिक

राशि की विदेशी मुद्राएँ न खरीद सकेगा और न वह कुल मिलाकर अपने कोटा के २००% से अधिक राशि ही खरीद सकेगा ।

सदस्य देशों पर प्रतिबन्ध

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदस्य देशों पर निम्न प्रतिबन्ध है—

१. कोप से ली जाने वाली राशि उसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही काम में लाई जावेगी ।

२ सदस्य देश स्वर्ण का क्रय-विक्रय कोप द्वारा निश्चित दर पर ही करेंगे ।

३ चालू अन्तरराष्ट्रीय भुगतान के सम्बन्ध में दूसरे सदस्य देशों के लिए भुगतान सम्बन्धी किसी प्रकार के प्रतिबन्ध न लगावें ।

४ कोप की अनुमति बिना अपनी मौद्रिक नीति में किसी प्रकार का पक्षपात न करें ।

५ कोप द्वारा निर्धारित दरों पर ही किसी सदस्य देश के विनिमय-बाजार में विदेशी मुद्राओं के व्यवहार हो ।

परन्तु कोप ने सन्नान्ति काल में सदस्य देशों को विनिमय नियन्त्रण लगाने की स्वीकृति केवल ५ वर्ष के लिए दी थी जिसके बाद विनिमय सम्बन्धी सभी प्रकार के निर्बन्ध हटाने थे । परन्तु फिर भी आज सदस्य देशों में विनिमय नियन्त्रण किसी न किसी रूप में कार्य कर रहे हैं । इतना ही नहीं प्रत्युत उनके स्वरूप में विभिन्न देशों में भिन्नता होने के साथ ही तीव्रता भी है । अधिकांश में प्रतिबन्धों का प्रमुख लक्षण यह है कि अधिकांश देशों ने अपने भुगतान का स्तर सीमित रखने के लिए अथवा उसे कम करने के लिए विवेचनात्मक प्रतिबन्ध लगाये हैं, विशेषतः “दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र” के सम्बन्ध में । कोप के वृत्तलेख में यह भी कहा गया है कि “अभी सम्पूर्ण विश्व इस स्थिति में नहीं पहुँचा है, जहाँ प्रतिबन्धों का निवारण सम्भव प्रतीत हो ।”

कोप का प्रबन्ध

कोप का कार्यालय वाशिंगटन (अमेरिका) में है । इसके प्रबन्ध के लिए एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, संचालक समिति तथा प्रबन्ध संचालक होता है । बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य देश के प्रतिनिधित्व के लिए प्रत्येक देश का एक निर्वाचन तथा एक स्थानापन्न गवर्नर होता है, जिनकी अवधि ५ वर्ष की होती है । इस अवधि के बाद उनका पुनः निर्वाचन हो सकता है । संचालक समिति में १२ संचालक होते हैं जिनमें से सबसे अधिक कोटा वाले देशों के एक-एक (अर्थात्

कुल ५) अन्य सदस्य देशों द्वारा निर्वाचित ५ तथा गेप २ अमरीकी गणतन्त्र द्वारा चुने हुए होते हैं। यह सचानक एक प्रबन्ध सचालक चुनते हैं जो कोप के दिन प्रतिदिन के काय की देखभाल करता है। प्रबन्ध सचालक को मत देने का अधिकार नहीं होता परन्तु आवश्यकता पड़ने पर वह निर्णयात्मक मत (cast ing vote) दे सकता है।

**कोप का मौद्रिक क्षत्र में महत्त्व**

उपरोक्त असफलताओं के होने हुए भी कोप ने गत वर्षों में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की उन्नति करने एवं भुगतान विपमताओं को दूर करने में विभिन्न देशों को काफी सहायता दी है। इतना ही नहीं प्रत्युत अभी तक कोप के अधिकारियों ने अपने सदस्य देशों को भेंट दी तथा तांत्रिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्न विषयों पर सक्रिय सहायता भी दी है —

- (१) आर्थिक सांख्यिकी (statistics) तथा रिपोर्ट की पद्धति में सुधार
- (२) विनिमय दर में परिवर्तन एवं स्थापन
- (३) विनिमय नियन्त्रण पद्धति में संशोधन
- (४) वजत के नियन्त्रण सम्बन्धी सुधार
- (५) नये एवं आद्यवत मौद्रिक तथा बैंकिंग विधान तथा
- (६) भुगतान विपमताएं एवं मुद्रास्फीति की समस्याओं को दूर करने के लिए सुझाव।

इस कार्यक्रम के अनुसार कोप ने दो देशों में केंद्रीय बैंकिंग तथा कृषि बैंकिंग पद्धति के निर्माण में तथा एक देश में बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अपने कार्यालय में सुयोग्य व्यक्ति देने में सहायता की। कोप को अधिक उपयोगी बनाने के लिए एवं उसके साधनों की सदस्य देशों को अधिकतम उपयोगिता देने के लिए नवम्बर १९५१ से कोप ने व्यवहारों पर जो सेवाशुल्क (service charges) लिया जाता था उसमें कमी की है। इसके अनुसार एक वर्ष के लिए कोप से उधार मुद्राएं कम व्याज पर मिलनी परन्तु दो वर्ष एवं इससे अधिक समय के लिए मुद्राएं उधार ली जाती हैं तो उन पर अधिक व्याज लगेगा। इसी प्रकार व्याप स्वयं की कृता एवं विरुद्ध देशों का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न भी करता है जिससे स्वयं के क्रय विक्रय व्यवहारों के खर्चे कम हो जाएंगे। इन सुधारों से आशा है कि कोप के साधनों का अधिकतम उपयोग सदस्य देशों को होगा।

**कोप की स्वयं-नीति—**कोप ने सदस्य राष्ट्रों के महयोग से स्वयं को

मौद्रिक जगत में फिर से महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सदस्य राष्ट्रों ने स्वर्ण की खरीद-विक्री न करने का आश्वासन दिया है। यह त्रय-विक्रय ३५ डॉलर प्रति औंस की दर से होगा तथा इससे अधिक दर पर अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में स्वर्ण का त्रय-विक्रय नहीं होगा, स्वर्ण-उत्पादक देशों को भी इसी दर से स्वर्ण का त्रय-विक्रय करना पड़ेगा।

दक्षिणी अफ्रीका ने १९४६ एव १९५० में स्वर्ण को बाजार-मूल्य अथवा कोप से निश्चित मूल्य से अधिक दर पर बेचने के लिए प्रयत्न किया था किन्तु कोप की कार्यकारिणी ने इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। इस प्रकार कोप की स्वर्ण-सम्बन्धी कड़ी नीति के कारण तथा सभासद राष्ट्रों के सहयोग से स्वर्ण-नीति प्रभावशाली रूप से कार्य कर रही है जिससे अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक जगत में स्वर्ण को फिर से सिंहामनाम्न किया गया है।<sup>1</sup> परन्तु कोप को विवश हो कर स्वर्ण-नीति में परिवर्तन करना पड़ा जो सितम्बर १९५१ में किया गया। इससे तय-निर्मित स्वर्ण का स्वर्ण-उत्पादक देश बाजार में कोप की निश्चित दर की अपेक्षा अधिक दर पर बेच सकेंगे। इस निर्णय से कोप की स्वर्ण-नीति प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती।

भारत और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोप—ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि भी थे जिन्होंने इस योजना को मान लिया तथा इस पर भारत सरकार ने अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। दिसम्बर १९४५ में भारत ने अपने कोटे की राशि कोप को नियमानुसार चुका दी। कोप में इस समय भारत के अपरकाम्य एव व्याजरहित प्रतिज्ञा अर्थ-पत्र २२४,९६,४०,००० रुपये (अथवा ४७२.४२ मिलियन डॉलर) जमा हैं, जो एशियाई देशों में सबसे अधिक है। भारत कोप का चौथा मौलिक सदस्य है। इससे भारत को कोप पर अपना एक शासकीय गवर्नर नियुक्त करने का अधिकार है।

कोप का सदस्य होने के नाते भारत ने रुपये का सममूल्य स्वर्ण में एव डॉलर में क्रमशः ०.२६८६१ ग्राम एव ३०.२५ सेंट निश्चित किया। रुपये के अवमूल्यन के बाद अब यही स्वर्ण एव डॉलर में क्रमशः ०.१८६६२१ ग्राम एव २१ सेंट हो गया है। इसके अलावा हमारी मौद्रिक पद्धति में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए रिजर्व बैंक विधान में १९४७ में संशोधन किया गया।

इस संशोधन के अनुसार भारतीय चलन की सदस्य देशों के चलन से बहुधाधिक परिवर्तनशीलता के लिए रिजर्व बैंक अपनी निधि में स्टैबिलि

<sup>1</sup> For details see 'Commerce', 30th Sept. 1950, p 370

के साथ अन्य देशों का चलन भी रखेगा एवं इनका क्रय-विक्रय कोप की निश्चित दरों पर करेगा ।

(२) कोप की सदस्यता के साथ हमारा स्टर्लिंग का नाता भी टूट जाता है इसलिए मूल विधान की धारा ४०, ४१ को रद्द किया गया तथा रिजर्व बैंक को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोप से निश्चित दरों पर विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय करने का भार सौंपा गया । लेकिन विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय २ लाख रुपये से कम मुद्राओं का नहीं होगा ।

(३) स्टर्लिंग में रुपये का अधिकतम एवं न्यूनतम मूल्य  $1\frac{1}{4}$  पेंस तथा  $1\frac{3}{4}$  पेंस निश्चित किया गया है ।

(४) विदेशी मुद्राओं में भारतीय रुपय की अधिकतम एवं न्यूनतम दर में कोप की निश्चित दरों के आधार पर तत्क्षण व्यवहारों में १% से अधिक अन्तर न होगा ।

(५) हमारे विदेशी विनिमय को वर्तमान स्थिति में नियन्त्रित करने एवं उसका अधिकाधिक उपयोग करने की दृष्टि से १९४७ में विदेशी-विनिमय-नियमन विधान लागू किया गया है जिसके अनुसार भारत तथा स्टर्लिंग क्षेत्रों में विदेशी विनिमय का हस्तान्तरण रिजर्व बैंक की पूर्व-अनुमति के बिना नहीं हो सकता ।

(६) रिजर्व बैंक कोप के सदस्य देश के सरकार की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय कर सकता है ।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोप की सदस्यता से भारत को निम्न लाभ हुए हैं —

(१) भारत को कोप से उसकी आवश्यकतानुसार विदेशी मुद्राएँ मिलती रहेगी जिससे हमारे आर्थिक विकास के लिए आवश्यक पूँजीगत माल हमको मिलता रहेगा ।

भारत ने जनवरी १९५७ में विदेशी विनिमय की कमी को दूर करने के लिये १२७ ½ मि० डॉलर का ऋण लिया । इसी प्रकार १९५७ में २०० मि० डॉलर की अस्थायी साक्ष (standing credit) भी स्वीकृत करायी । इसमें से फरवरी १९५७ में ६० मि० डॉलर, मार्च १९५७ में ६७ ½ मि० डॉलर तथा जून १९५७ में ७२ ½ मि० डॉलर का उपयोग किया । इसके अतिरिक्त दिसम्बर १९५७ तक भारत ने देशी मुद्राओं के बदले कोप से ३०० मि० डॉलर खरीदे थे । इसमें से ६६ ६ मि० डॉलर की पुनः खरीद की गयी ।<sup>१</sup>

(२) रुपये का सममूल्य स्वर्ण में निश्चित हो जाने से रुपया अन्तरराष्ट्रीय प्राणण में स्वतन्त्र हो गया तथा अब उसका स्टैलिग से कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे भारत मौद्रिक दासता से मुक्त हो गया।

(३) भारत को शासकीय मंचालक नियुक्त करने का अधिकार होने के कारण भारत कोष की नीति निर्माण में हिस्सा ले सकता है। इससे उसकी अन्तरराष्ट्रीय महत्ता भी बढ़ेगी।

(४) रुपये का सम्बन्ध स्वर्ण से होने के कारण रुपये का परिवर्तन अब किसी भी देश की मुद्रा के साथ हो सकता है। इस कारण अब भारत का विदेशी व्यापार अन्य देशों के साथ—जो स्टैलिग क्षेत्र में नहीं है—बढ़ने में सहायता मिलेगी।

(५) हम अपने घरेलू मामलों में कोष की सहायता ले सकेंगे।

इस प्रकार की सहमति कोष से भारत ने ली है। फरवरी १९५३ में कोष का प्रतिनिधिमंडल भारत की मौद्रिक एवं आर्थिक नीति पर अपनी रिपोर्ट देने के लिए आया था जो Economic Development with Stability नाम से प्रकाशित की गयी है। इसी प्रकार फरवरी १९५८ में कोष के प्रबन्ध मंचालक भारत की आर्थिक स्थिति का परीक्षण कर मुभाव देने के लिये भारत में आये थे। दिसम्बर १९५७ में कोष के एसियाई विभाग का दल भारत की आर्थिक स्थिति आकलन के लिये भारत में रहा।

### अन्तरराष्ट्रीय बैंक

ब्रेटनवुड्स सम्मेलन के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय बैंक की स्थापना अविकसित एवं युद्ध-व्यस्त देशों के पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए की गयी है। इससे सदस्य देशों में परस्पर सहयोग द्वारा विनियोग हाँकर सदस्य देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए पूँजीगत वस्तुएँ प्राप्त करने में सुगमता होगी।

उद्देश्य—१ अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को उत्तम करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय ऋण द्वारा विनियोग क्रियाओं में स्थिरता लाना,

२. अन्तरराष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग क्रियाओं में स्थिरता लाने के लिए बैंक द्वारा निजी ऋणों तथा विनियोगों की जमानत देना,

३ आर्थिक विकास के लिए अपने निजी साधनों से सदस्य देशों को ऋण देना,

४ उपलब्ध पूँजी का अधिकतम उपयोग करने के लिए सदस्य देशों

में पूंजी का लेन-देन प्रोत्साहित करना, जिससे उपयुक्त योजनाओं की पूर्ति को प्राथमिकता मिले।

इस प्रकार बैंक का प्रमुख हेतु अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में पूंजी, ऋण एवं विनियोगों द्वारा मुद्रोत्तर विकास एवं पुनर्निर्माण योजनाओं की प्रगति कर अन्तरराष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि करना है।

**बैंक की पूंजी एवं सदस्यता**—बैंक की पूंजी १०,००० मिलियन डॉलर है। इनमें से ६१०० मिलियन डॉलर उन देशों के लिए निश्चित की गयी थी जिन्होंने ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में बैंक का सदस्य होना स्वीकार कर लिया था। शेष पूंजी आगे होने वाले सदस्यों के लिए थी। जिन देशों ने ३१ दिसम्बर १९४५ को अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की सदस्यता स्वीकार की वे इस बैंक के भी मौलिक सभासद होंगे। जो सदस्य अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का सभासदत्व त्याग देता है वह बैंक का सभासद भी नहीं रह सकता। परन्तु मुद्रा-कोष का सभासदत्व त्यागने पर भी वह ७५% मत से बैंक का सभासद रह सकता है। इसी प्रकार जो सदस्य बैंक की शर्तों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करेगा वह भी सदस्य न रह सकेगा। निश्चित सूचना देने पर कोई भी देश बैंक की सदस्यता छोड़ सकता है।

बैंक की अधिकृत पूंजी १ लाख डॉलर के १,००,००० अंशों में भाजित है। मूल सभासदों का कोटा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की तरह निश्चित है अर्थात् समुक्त राष्ट्र ३१५० मिलियन डॉलर, संयुक्त राज्य १३०० मिलियन डॉलर, रूस १२०० मिलियन डॉलर, चीन ६०० मिलियन डॉलर, फ्रान्स ४५० मिलियन डॉलर तथा भारत ४०० मिलियन डॉलर। इन सभासदों में से रूस ने इसकी सदस्यता स्वीकार नहीं की। बैंक की पूंजी ७५ प्रतिशत सभासदों के बहुमत से बढ़ाई जा सकती है।

अधिकृत पूंजी का २० प्रतिशत भाग सभासदों को देना पड़ेगा जिसमें से ५% भाग अमरीकी डॉलर अथवा स्वर्ण में तथा १५% भाग सभासद अपनी मुद्रा में देगा। शेष प्राप्ति पूंजी माँग पर स्वर्ण में, अमरीकी डॉलर में, अथवा जिस चलन-कार्य के लिए पूंजी माँगी गयी है उस चलन में, देनी पड़ेगी। यह हिस्सा केवल उनी समय यथाया आवेगा जब बैंक को उसकी आवश्यकता होगी। इस समय बैंक की कुल चुकता पूंजी ६४२.३ मिलियन डॉलर है।

**प्रबन्ध**—बैंक का कार्य गवर्नर्स की समिति द्वारा चलाया जाता है। इनको सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति है जिसमें औद्योगिक, आर्थिक, कृषि,

बैंकिंग आदि विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व है। यह सलाहकार समिति बैंक की सामान्य तथा ऋण-नीति पर सलाह देती है। बैंक की चुकता पूंजी ऋण आदि देने के कार्य में तथा धोप पूंजी बैंक द्वारा ऋणों के अथवा अभिगोपन (underwriting) के लिए उपयोग में ली जायगी। याचित पूंजी ऋण देने के लिए बैंक को उपलब्ध रहेगी।

**ऋण-नीति**—बैंक अपने मभासद देश को किसी भी औद्योगिक अथवा विकास कार्य के लिए ऋण अथवा ऋण की जमानत देगा। लेकिन इसके पूर्व वह कार्य ठोस है अथवा नहीं, इसकी जाँच वह अपनी सलाहकार समिति तथा ऋण-समिति द्वारा करा लेगा। यह ऋण बैंक नहीं देगा जब उधार लेने वाले देश को अन्य किसी देश से अथवा व्यक्ति से पूंजी न मिल रही हो एवं ऋण जिस कार्य के लिए दिया जा रहा है उसी कार्य में उसका उपयोग किया जायगा इस सम्बन्ध में बैंक को विश्वास हो।

बैंक या तो अपनी पूंजी में से ऋण देगा अथवा अन्य किसी देश अथवा वैयक्तिक वित्तियोगकर्ताओं से अपनी जमानत पर ऋण दिलवायगा। इस प्रकार बैंक की ऋण देने सम्बन्धी चार शर्तें हैं —

१ अगर ऋण-कर्ता को कहीं से ऋण नहीं मिल रहा है,

२ अगर सदस्य देश के किसी उद्योग को अथवा किसी प्रान्त को ऋण दिया जा रहा है तो सदस्य देश की सरकार को उस ऋण की जमानत देनी होगी,

३ अगर परीक्षण के बाद यह प्रमाणित होता है कि ऋणकर्ता उन ऋण का भुगतान करने की परिस्थिति में है, तथा

४ ऋणकर्ता अपनी असमर्थता प्रमाणित करे कि उसे अन्तरराष्ट्रीय बैंक की जमानत के बिना अन्य स्रोतों से ऋण नहीं मिल रहा है।

बैंक अपने प्रत्यक्ष ऋण पर व्याज ( जो दर निश्चित की जाय ) लेगा तथा उसकी भुगतान सम्बन्धी शर्तें भी बैंक के निर्णय पर ही निर्भर रहेंगी। जिन ऋणों की जमानत बैंक द्वारा दी जाती है उन ऋणों पर प्रथम दस वर्षों के लिए बैंक १ से १½ प्रतिशत कमीशन लेगा तथा इनको एक अलग निधि में जमा करेगा जिसमें किसी राष्ट्र से ऋणों का भुगतान न होने पर उसका उपयोग हो सके। ऋण की पूर्ति के लिए अथवा अन्य कार्यों के लिए बैंक को अपनी प्रतिभूतियाँ बेचने का अधिकार है।

**बैंक की क्रियाएँ**—३० जून १९५८ तक अन्तरराष्ट्रीय बैंक ने ३७२६

मिलियन डॉलर के २०४ ऋण स्वीकृत किये। १९५७-५८ में कुल ७११ मिलियन डॉलर के ऋण विभिन्न देशों को दिये गये जो निम्न थे —

एशियाई देश	३७६ मि० डॉलर
लेटिन अमरीका	१२१ "
अफ्रीका	११२ "
यूरोप	६६ "

३० जून १९५८ तक कुल स्वीकृत ऋणों में से एशियाई देशों को ९४८ मि० डॉलर, अफ्रीका को ४७६ मि० डॉलर, आस्ट्रेलिया को ३१८ मि० डॉलर, यूरोप को ११८६ मि० डॉलर तथा पश्चिमी गोलार्द्ध (western hemisphere) को ७६८ मि० डॉलर के ऋण स्वीकृत हुए। इन ऋणों में से ४६७ मि० डॉलर पुनर्निर्माण तथा ३२३२ मि० डॉलर विकास-कार्य के लिए दिये गये थे। विकास-ऋणों का विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार से विवरण है :

विद्युत निर्माण एवं वितरण	११०६ मि० डॉलर
यातायात	१०३६ "
मवादवाहन	२४ "
कृषि एवं वन-विकास	३१५ "
उद्योग	५४५ "

यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय बैंक का मूल स्वरूप आर्थिक है फिर भी उसने कार्य-क्षेत्र का अन्यत्र विस्तार भी किया है। राजनीतिक विवादों को सुलझाने में भी यह योग देता है। जैसे स्वेज नहर कम्पनी के हिस्सेदारों की क्षतिपूर्ति के मामले में इसने एक ओर संयुक्त अरब गणतंत्र तथा दूसरी ओर ब्रिटेन एवं फ्रांस में मध्यस्थता की। इसी प्रकार भारत-पाक-नहरी विवाद में भी इसी के प्रयत्नों से समझौता सम्भव हुआ। इसी प्रकार इटली में अणुशक्ति से विद्युत-उत्पादन की सम्भाव्यता का अध्ययन भी बैंक के प्रतिनिधि इस समय कर रहे हैं।<sup>१</sup>

अन्तरराष्ट्रीय बैंक एवं अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की वार्षिक बैठक १९५८ में दिल्ली में हुई जो एशियाई देशों के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण थी। इस बैठक में दोनों ही संस्थाओं के सदस्य देशों का कोटा बढ़ाने का निर्णय किया गया।

**अन्तरराष्ट्रीय बैंक और भारत**

भारत अन्तरराष्ट्रीय बैंक का भी मौलिक सदस्य है। बैंक की पूंजी में

भारत का कोटा ४०० मि० डॉलर है तथा पाँचवाँ सदस्य होने से इसे बैंक की कार्यकारिणी में भी स्थायी स्थान प्राप्त है। बैंक की सदस्यता से भारत को विभिन्न विकास-कार्यों के लिए निम्न ऋण मिले हैं :—

१ पहला ऋण १८ अगस्त १९४६ को भारत ने ३४ मिलियन डॉलर का संयुक्त राष्ट्र तथा केनाडा से रेलवे इंजन खरीदने के लिए लिया था। यह ऋण १५ वर्ष की अवधि के लिए तथा ३ प्रतिशत वार्षिक व्याज पर है। इसके अतिरिक्त १ प्रतिशत बैंक कमीशन भी भारत देगा। इस ऋण का भुगतान भारत ने अगस्त १९५० से आरम्भ किया।

भारत ने इस ऋण का मितव्ययिता से उपयोग कर १२ मिलियन डॉलर का ऋण रद्द करा लिया है। इस प्रकार अब इस ऋण के व्याज एवं कमीशन के अतिरिक्त कुल ३२८ मिलियन डॉलर भारत को भुगतान करना है। इस ऋण में से भारत ने अभी तक ३५ मिलियन डॉलर का भुगतान किया है।

२ दूसरा ऋण १० मि० डॉलर का २६ मितम्बर १९४६ को कृषि-विकास एवं मुद्यार के लिए स्वीकृत हुआ है। इस ऋण की अवधि ७ वर्ष तथा व्याज एवं बैंक कमीशन क्रमशः २½% और १% है। इसका भुगतान १ जून १९५२ से आरम्भ हो गया जिसके अनुसार भारत ने १९५२ में ८,५०,००० मि० डॉलर की पहली किस्त चुकाई। इस ऋण से भारत अगरीका में ट्रेक्टर खरीदेगा जिसमें बीस लगी हुई बजर भूमि को कृषि-कार्यों के लिए उपयोग में लाया जायगा। इस ऋण में से भी भारत ने १५ मिलियन डॉलर निरस्त करा दिये हैं जिससे अब इस ऋण के लिए केवल ८४,१५,००० डॉलर का भुगतान और करना पड़ेगा।

३ तीसरा ऋण १५ अप्रैल १९५० को १८५ मिलियन डॉलर का बामोदर घाटी-योजना के लिए स्वीकृत हुआ है। इस योजना के अन्तर्गत "बोकारो बोनार धर्मल स्टेशन" बनाने के लिए अमेरिका से धर्मल प्लाट खरीदा जायगा। इस ऋण की अवधि २० वर्ष तथा व्याज एवं बैंक कमीशन ३ प्रतिशत एवं १ प्रतिशत प्रतिवर्ष है। ऋण का भुगतान १ अप्रैल १९५५ से शुरू होगा।

४ चौथा ऋण १६ दिसम्बर १९५२ को ३१५ मिलियन डॉलर का स्वीकृत किया गया है। यह ऋण पंचवर्षीय योजना के अनुसार लोहा एवं इस्पात उद्योग विकास के लिए इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कॉम्पनी के आधुनिकीकरण के हेतु लिया गया है। इस ऋण की अवधि १५ वर्ष तथा व्याज एवं कमीशन की वार्षिक दर ४½% है। इस ऋण का भुगतान १९५६ में आरम्भ हो गया है।

५ यह ऋण २६ जनवरी १९५३ को दामोदर घाटी विकास योजना के लिए १९५ मि० डॉलर का स्वीकृत हुआ है। इसकी अवधि २५ वर्ष तथा व्याज एवं कमीशन की वार्षिक दर ४ $\frac{1}{2}$ % है। इस ऋण का भुगतान १९५६ में आरम्भ होगया। यह ऋण सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण योजनाओं की पूर्ति के लिए लिया गया था जिसमें माइयाल, पचेट और दुर्गापुर बाध सम्मिलित हैं।

६. यह ऋण नवम्बर १९५४ में टाटा ग्रुप को ट्राम्वे में विजलीघर के विकास के लिए १६२ मि० डॉलर का दिया गया है।

७. यह ऋण १९५५ में औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम को १० मि० डॉलर का विदेशी माल एवं सेवाओं का आयात करने के लिए दिया गया है। इसकी अवधि १५ वर्ष तथा व्याज एवं कमीशन की वार्षिक दर ४ $\frac{1}{2}$ % है।

८ १६ सितम्बर १९५९ को भारतीय रेलों के मुधार एवं विस्तार के लिए ८५० मि० डॉलर का यह ऋण स्वीकृत हुआ है।

जुलाई १९५० में भारत को रेलों की माल-बहन क्षमता बढ़ाने के लिए ६० मि० डॉलर का ऋण मिला था।

९ कलकत्ता और मद्रास में जहाजों और माल ढोने की सुविधाएँ बढ़ाने के लिए तथा एयर इंडिया इन्टरनेशनल को नये विमान खरीदने के लिए दो ऋण क्रमशः ४३ मि० और ५६ मि० डॉलर के स्वीकृत किये गये हैं।<sup>१</sup>

१० दामोदर घाटी योजना के अन्तर्गत बोकारा में चीथा विद्युत निर्माण-गृह बनाने के लिए जुलाई १९५८ में २५० मि० डॉलर का ऋण स्वीकृत किया गया है।

११ इसी प्रकार लोहा एवं इस्पात उद्योग की उत्पादनक्षमता बढ़ाने के लिए इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को क्रमशः ५१५ मि० और १०७५ मि० डॉलर के ऋण स्वीकृत किये गये हैं।<sup>१</sup>

इस प्रकार भारत को अन्तरराष्ट्रीय बैंक से अभी तक कुल ५०७ मि० डॉलर के २० ऋण (निरस्त ऋणों को छोड़कर) स्वीकृत किये गये और आज बैंक के ऋणियों में भारत सबसे अधिक ऋणी है। इन ऋणों में निजी क्षेत्र एवं सरकारी क्षेत्र का भाग क्रमशः १९५ मि० और ३२० मि० डॉलर है। ये ऋण भारत की दृष्टि से अन्तरराष्ट्रीय बैंक की उपयोगिता सिद्ध करते हैं। इसी हेतु

<sup>१</sup> भारतीय समाचार—अक्टूबर १५, १९५८।

<sup>२</sup> भारतीय समाचार—अक्टूबर १५, १९५८।

बैंक के वित्त विरोध भारतीय समस्याओं की जानकारी के हेतु भारत आते रहते हैं तथा उनका एक प्रतिनिधि दिल्ली में भी रहता है।

बैंक का महत्त्व—उक्त क्रियाओं से विश्व के आर्थिक विकास एवं पुन-निर्माण में बैंक का कितना महत्त्वपूर्ण भाग है यह स्पष्ट होता है। यह केवल आर्थिक सहयोग प्राप्त करने वाली सस्था न होते हुए इसने राजनीतिक विवादों को हल करने में भी मध्यस्थता की है। इस प्रकार अन्तरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर विश्व-शान्ति की ओर ले जाने वाली ये प्रथम दो सस्थाएँ हैं जो विश्व में अपना मौलिक स्थान रखती हैं। यदि सभी सदस्य देश अपनी नियत साफ रख-कर कार्य करें तो निश्चय ही ये सस्थाएँ अपनी मौलिकता का परिचय देती रहगी ऐसा विश्वास है।

अन्तरराष्ट्रीय बैंक से भारत द्वारा प्राप्त ऋणों की राशि एवं उपयोग

( ३१ जुलाई १९५८ तक )<sup>१</sup>

मि० डॉलर में—

मन्त्रालय	विषय	स्वीकृत ऋण	उपयोगित राशि
खाद्य एवं कृषि	कृषि विकास	१० ००	७ २० <sup>१</sup>
रेलवे	रेलवे—(अ) डजन	३० ८०	३२ ८० <sup>१</sup>
	(ब) माल-बहन क्षमता	२० ००	१० ००
	(ग) विकास	८५ ००	८५ ००
	(द)	५० ००	—
विद्युत एवं सिंचाई (१)	दामादर घाटी योजना		
	(a) बोकारो थर्मल स्टेशन	१६ ७२	१६ ७२
	(b) सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	१० ५०	१० ५० <sup>१</sup>
	(c) विद्युत ग्रह	२५ ००	१० ४९
	(ii) वीयना प्रोजेक्ट	२५ ००	—
मातापान	(१) एअर इंडिया इंटर-नेशनल	५ ६०	५ ०९
	(२) मद्रास बन्दरगाह	१४ ००	१ ०१
	(३) बलकत्ता बन्दरगाह	२९ ००	२ २१
योग		३९० ८०	२६१ ०२

<sup>१</sup> Eastern Economist—Aug 1959

<sup>२</sup> शेष ऋण निरस्त किया गया। सरकारी क्षेत्र के ऋणों की तालिका है।

## परिशिष्ट

### अन्तरराष्ट्रीय बैंक एवं अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष (नवीन विकास)

अन्तरराष्ट्रीय बैंक—अन्तरराष्ट्रीय बैंक एवं मुद्रा-कोष की दिल्ली की बैठक में, जो अक्टूबर १९५९ में हुई, यह निर्णय लिया गया था कि मुद्रा-कोष एवं बैंक के सदस्य देशों का कोटा बढ़ाया जाय। तदनुसार बैंक के सचिवों ने यह निर्णय किया था कि अन्तरराष्ट्रीय बैंक की अधिकृत पूंजी ७००० मि० डॉलर से बढ़ाया जाय। परन्तु प्रायित्व पूंजी की वास्तविक राशि को भाई उत्तमसे अधिकृत पूंजी में ८८०० मि० डॉलर की वृद्धि हो गयी। इसलिए १६ मितम्बर १९५९ से बैंक की अधिकृत पूंजी १०००० मि० डॉलर से बढ़ाकर २१००० मि० डॉलर कर दी गयी।

इस पूंजी की वृद्धि होने से पूर्व बैंक की प्रायित्व पूंजी ९५५६५० मि० डॉलर थी जिसमें से १९११ मि० डॉलर चुकता पूंजी और शेष ७६४५ मि० डॉलर माँग पर देय थी जो बैंक के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए सयोगिक देय के रूप में थी। पूंजी में वृद्धि होने के कारण अब बैंक की प्रायित्व पूंजी १७२५७ मि० डॉलर हो गयी है जिसमें से १९७३ मि० डॉलर चुकता पूंजी तथा शेष माँग पर देय है। बैंक की पूंजी में वृद्धि सचरय देशों के हिस्से को वृद्धा करके की गयी है, तथा बहुत से सदस्य देशों ने अपनी प्रायित्व पूंजी में विशेष अतिरिक्त वृद्धि की है। ऐसे १७ देश हैं जिनमें पश्चिमी जर्मनी, जापान तथा केनाडा भी हैं।

इस वृद्धि में बैंक अपनी ऋण देने की क्रियाएँ बढ़ा सकता है और साथ ही अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इसकी ऋण देने की क्षमता भी वृद्धि हो गयी है।

अन्तरराष्ट्रीय बैंक की पूंजी में भारत का मूल हिस्सा ४०० मि० डॉलर या जो अब ८०० मि० डॉलर हो गया है। इसमें से २०% अर्थात् ८० मि० डॉलर की पूंजी चुकता है तथा शेष ७२० मि० डॉलर माँग पर देय है। विश्व बैंक के सदस्यों में पहिले भारत का चौथा क्रमांक था परन्तु अब पाँचवाँ हो गया है तथा फ्रांस एवं जर्मनी संयुक्त रूप से चौथे क्रमांक पर हैं।

२५ जनवरी १९४६ से, जबकि अन्तरराष्ट्रीय बैंक ने अपनी क्रियाएँ आरम्भ की, ३१ अगस्त १९५९ तक बैंक ने ४६०४३ मि० डॉलर के ऋण स्वीकृत किये। इसमें से २७४ मि० डॉलर का भुगतान बैंक को किया जा चुका है तथा ११२३ मि० डॉलर के ऋणों को निरस्त किया गया है। बैंक ने ७८३

मिलियन डॉलर अन्य विनियोगों को वेचे है। २१ अगस्त १९५९ को बैंक का कुल कोषवृत्त ऋण (funded debt) १९०५ मि० डॉलर था।

बैंक के ऋणियों में भारत का उच्चांक है जिसने ३० जून १९५६ तक ५५०.६१ मि० डॉलर का ऋण लिया। इसके बाद क्रमशः आस्ट्रेलिया और फ्रांस हैं जिनकी ऋण-राशि क्रमशः ३१७.७३ एवं ३००.५० मि० डॉलर है। १९५८-५९ में भारत को रेलवे विकास के लिए ८५ मि० डॉलर, दामोदर घाटी योजना के लिए ७५ मि० डॉलर तथा कोयना विद्युत योजना के लिए २५ मि० डॉलर का ऋण विश्व बैंक से मिला है।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष—अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की राशि में भी विश्व बैंक की तरह ही वृद्धि की गयी है। इसकी राशि में ५०% से वृद्धि की गयी है, तदनुसार सदस्य देशों के कोटा में भी ५०% की वृद्धि की गयी है। परन्तु गत वर्षों में तेजी से आर्थिक प्रगति होने के कारण पश्चिमी जर्मनी, जापान तथा कनाडा ने अपन कोटा में विशेष वृद्धि की है जिससे अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की राशि ५१०० मि० डॉलर में बढ़ गयी है अर्थात् कुल कोष १०५१० मि० डॉलर का हो गया। फलस्वरूप इसका स्वण २३०० मि० डॉलर से ४६०० मि० डॉलर हो जायगा।<sup>१</sup>

### सारान

विनिमय दर में स्थिरता लाने तथा मुद्रणवृद्ध देशों के पुनर्निर्माण एवं आर्थिक विकास के लिए ब्रैटनवुड्स परिषद ने अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं अन्तरराष्ट्रीय बैंक की स्थापना का निर्णय लिया। तदनुसार १९४५ में इन दोनों सस्थाओं का निर्माण हुआ।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की कुल राशि १०००० मि० डॉलर है तथा इसमें प्रत्येक सदस्य देश का कोटा निश्चित है। भारत भी इसका मौलिक सदस्य है। इसका उद्देश्य—अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के समुचित विकास में सहायक होना, विनिमय दरों की स्थिरता के लिए समुचित विनिमय व्यवस्था स्थापित करना, स्पर्धात्मक विनिमय अवमूल्यन न होने देना, सदस्यों को बहुपक्षिक भुगतान-सुविधाएँ देना, सदस्य देशों की भुगतान-विषयमताओं को विदेशी मुद्रा की सहायता से दूर करना, तथा विनिमय नियन्त्रणों को हटाना है।

<sup>१</sup> Modern Review, Nov. 1959

प्रत्येक देश को अपने कोटे का २५% स्वर्ण में अथवा अपने स्वर्ण एवं डॉलर निधि के १०% (जो भी कम हो) में तथा शेष देशों मुद्राओं या प्रतिभूतियों में देना पड़ता है।

सदस्य देशों को अपनी मुद्रा का स्वर्ण या डॉलर मूल्य व्यक्त कर दिया गया है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर सदस्यों में मुद्राओं का क्रय विक्रय होगा। इन मूल्यों में परिवर्तन कोष की सम्मति से किये जा सकते हैं।

सदस्य देशों को कोष के साथ केन्द्रीय बैंक अथवा देश के खजाने के माध्यम से व्यवहार करने होंगे। कोई भी सदस्य देश कोष से अपनी मुद्राओं अथवा स्वर्ण के बबले विदेशी मुद्राएँ खरीद सकता है तथा उसे इन मुद्राओं का उपयोग उसी कार्य के लिए करना पड़ेगा जिस हेतु वे ली गयी हो। कोई भी सदस्य १ वर्ष में अपने कोटे के २५% से अधिक अथवा कुल निताकर अपने कोटे के २००% से अधिक की विदेशी मुद्राएँ नहीं खरीद सकता।

कोष किसी देश की मुद्रा का अभाव होने पर उसे 'दुलभ' घोषित कर सकता है। ऐसी दशा में वह उस मुद्रा को उस देश से स्वर्ण के बदले में खरीदेगा तथा उपलब्ध मुद्राओं में सभी सदस्य देशों में उचित वितरण करेगा।

भारत भी कोष का सदस्य है जिससे उसका स्टैलिङ्ग से सम्बन्ध विच्छेद हो गया है तथा रुपये का परिवर्तन सदस्य देशों की मुद्राओं में सम्भव हो गया है। भारत ने दिसम्बर १९५८ तक कोष से १२७ ५ मि० डॉलर का ऋण तथा २०० मि० डॉलर की अस्थायी सहायता प्राप्त की।

अन्तरराष्ट्रीय बैंक — इसका उद्देश्य ऋण एवं विनियोग क्षेत्र में मुद्रा-व्यवस्था देशों के पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त कर सहायता देना है। इसकी पूंजी १०००० मि० डॉलर है जो १०००० डॉलर के १०००० अंशों में है। मुद्रा कोष के सदस्य देश इस बैंक के भी सदस्य होते हैं। प्रत्येक देश की पूंजी का कोटा निर्धारित है जिसका २०% सदस्य को जमा करना पड़ता है। इस २०% का  $\frac{1}{3}$  भाग स्वर्ण अथवा डॉलर में तथा शेष  $\frac{2}{3}$  भाग अपनी मुद्रा में जमा करना होता है।

बैंक सदस्य देशों को निम्न शर्तों पर ऋण देता है —

- (१) यदि उन्हे अन्यत्र उचित शर्तों पर ऋण न मिले,
- (२) सदस्य देश की सरकार उस ऋण की जमानत दे, तथा
- (३) ऋण जिस हेतु लिया गया है उसी के लिए उपयोग में आवे।

ऋण देने के पूर्व बँक ऋण देने वाले देश की विकास योजनाओं एवं उसकी आर्थिक स्थिति का अध्ययन करता है।

बँक ने ३० जून १९५८ तक विभिन्न देशों को ३७२६ मि० डॉलर के २०४ ऋण स्वीकृत किये हैं जिनमें से ४६७ मि० डॉलर पुनर्निर्माण तथा ३२३२ मि० डॉलर विकास के लिए हैं।

भारत ने इसी तिथि तक बिहव बँक से ५०७ मि० डॉलर के २० ऋण लिए हैं जिनमें से सरकारी क्षेत्र के लिए ३२० मि० तथा निजी क्षेत्र के लिए १८५ मि० डॉलर हैं। इस प्रकार भारत इसकी सदस्यता में लाभान्वित हुआ है।

## रुपये का अवमूल्यन एवं पुनर्मूल्यन

### पृष्ठभूमि

१९३८-३९ में इंग्लैंड के स्वर्ण-निधि (gold reserve) पर सकट के बादल छा गये। इस विशेष परिस्थिति के कारण इंग्लैंड का स्वर्ण-निधि केवल १ वर्ष में ही ८०० मि० स्टर्लिंग से घटकर केवल ५०० मि० स्टर्लिंग रह गया। इस प्रकार ३०० मि० स्टर्लिंग का स्वर्ण इंग्लैंड को १९३८-३९ में अपने अल्पकालीन ऋणों के भुगतान में देना पड़ा जो वर्तमान मूल्यों की तुलना में लगभग १००० मि० पौंड का होता परन्तु फिर भी इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति अच्छी थी क्योंकि विदेशों में उसकी काफी पूंजी लगी हुई थी और अनेक देशों को ऋण दिये हुए थे। परन्तु युद्ध के बाद इस परिस्थिति में गम्भीर परिवर्तन हो गये जिससे "१९४१ में हमने अपना स्वर्ण-निधि तो खर्च कर ही दिया, साथ ही हमने विदेशों से अल्पकालीन ऋण भी युद्ध-काल में एकत्र किया जिससे अमरीका से सहायता प्राप्त करते हुए भी हम अपने आयात का भुगतान करने में असमर्थ हो गये। इंग्लैंड स्थित अमरीकी कौजो पर होने वाले व्यय के कारण १९४५ तक हमने स्वर्ण-निधि फिर से इकट्ठा कर लिया जो हमारे कुल विदेशी अल्पकालीन ऋणों के  $\frac{1}{2}$  के बराबर था। सारास में हमने ६०० मि० पौंड का स्वर्ण एवं डालर का व्यय तो कर ही दिया परन्तु साथ ही ३३०० मि० पौंड का अल्पकालीन ऋण भी लिया जो पौंड-भावनों में है"।<sup>१</sup> १९४५ से १९४८ तक इंग्लैंड कर्जदार होता गया और उसका स्वर्ण-निधि भी कम होता गया। इस कमी को दूर करने के लिए इंग्लैंड को अपनी विदेशी सम्पत्ति बेचनी पड़ी जिससे उसकी विदेशी से व्याज एवं लाभान के रूप में होने वाली आय भी कम हो गयी। अतः इंग्लैंड अपने विदेशी व्यापार की भुगतान-विषमता मिटाने में असमर्थ हो रहा था। युद्ध के बाद 'मार्शल एड' के अनुसार इंग्लैंड को अमरीका

<sup>१</sup> *The Sterling Area Crisis* by F. W. Paish from "International Affairs", 1952

से सहायता मिल रही थी जिसकी अवधि १९५२ तक थी।<sup>१</sup> इस अमरीकी सहायता के कारण इंग्लैंड किनी तरह अपना काम चलाता रहा, परन्तु उसके सामने इन योजना के समाप्त होने के पहले अपने पैरों पर खड़े होने की समस्या थी।

इसलिए यह आवश्यक था कि इंग्लैंड अपनी भुगतान विषमताओं को दूर करता, जिसके लिए केवल दो ही मार्ग थे। या तो उसे अपने आयात कम करने चाहिए थे अथवा देश का उत्पादन बढ़ाकर निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिए था। परन्तु आयात कम करना सरल नहीं था क्योंकि इंग्लैंड का अधिकतर आयात खाद्य और कच्चे माल का था, जिम्मे देश में वक़ारी और भुलमरी होती। पहला मार्ग कठिन तो था ही, माघ ही इसमें डॉलर मकट की समस्या का हल भी नहीं हो सकता था क्योंकि इंग्लैंड तथा स्टर्लिंग क्षेत्र के सदस्य-देशों ने १९४८ में २५% से डॉलर आयात कम कर दिये थे। फिर भी डॉलर की कमी बढ़ती ही जा रही थी। १९४९ की पहली तिमाही में जहाँ ३२८ मि० पौंड की कमी थी वहाँ दूसरी तिमाही में ६०७ मि० पौंड की कमी हो गयी, जिससे स्टर्लिंग क्षेत्र का स्वर्ण एवं डॉलर निधि जून १९४९ के अन्त में ४०.५ मि० पौंड रह गया था और वह कम होना जा रहा था। इसलिए निर्यात को बढ़ाकर अधिकाधिक डॉलर कमाना ही समस्या का समुचित हल था क्योंकि इंग्लैंड अमरीकी सहायता के बल पर कब तक जीता। परन्तु यह निर्यात स्टर्लिंग के उग समय प्रचलित डॉलर या स्वर्ण मूल्य पर नहीं हो सकता था क्योंकि अमरीका में इंग्लैंड का माल महँगा पड़ता था। इसलिए निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी बाजारों में इंग्लैंड का माल मस्ता होना चाहिए था, जिसके लिए भी दो ही उपाय थे—पहला उपाय यह था कि देश में मजदूरी आदि की दर घटाकर उत्पादन व्यय को कम करना अथवा डॉलर क्षेत्रों में इंग्लैंड का माल सस्ता हो इसलिए डॉलर के बढ़ने में पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुएँ देना। पहले उपाय की अपेक्षा दूसरे उपाय को ही चुना गया। दूसरे मार्ग को अपनाने का प्रमुख कारण यह था कि स्टर्लिंग का विनिमय मूल्य खोरबाजार में घट रहा था जिससे स्टर्लिंग का परिवर्तन डॉलर में अधिक होने लग गया था।

इस स्थिति का काबू में लाने के लिए तत्प्रथम सर स्टेफ़र्ड किप्प ने ७ जुलाई १९४९ को जुलाई, अगस्त, सितम्बर १९४९ इन तीन महीनों के लिए डॉलर-

<sup>१</sup> मार्शल एड, उद्योग पट्टा तथा अन्य प्रकार में १९४१ से १९५२ तक इंग्लैंड को कुल ३५,९१३ मि० डॉलर की सहायता अमरीका द्वारा दी गयी।

नय स्थगित करने का आग्रह दिया। इसी प्रकार आर्थिक सहायता के अलावा अन्य उपायों की आवश्यकता के सम्बन्ध में एक संयुक्त वक्तव्य (सर स्टैफर्ड क्रिप्स अमरीका के सनायडर (Snyder) तथा केनाडा के अथ मंत्री डगलस एबट द्वारा) १० जुलाई १९४६ को निकाला गया। इसके चार दिन पश्चात् ही (१४ ७ १९४६) इंग्लैंड ने डालर आयात २५% से अर्थात् प्रति वष १० मिलियन डालर से कम करने की घोषणा की। १८ जुलाई १९४६ को राष्ट्रसंघीय अथ मंत्री सम्मेलन में डालर की अधिक प्राप्ति एवं डालर प्रदेशों के आयात कम करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। फिर भी समस्या हल न हो सकी। इसलिए ७ सितम्बर से १२ सितम्बर १९४६ तक बार्निंगटन में अमरीका ब्रिटेन और केनाडा का त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ जिसमें ब्रिटेन की डालर समस्या को १९५२ तक हल करने के सम्बन्ध में समझौता हुआ। इसी समझौते के अनुसार सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने १७ सितम्बर को स्टर्लिंग के अवमूल्यन की घोषणा की। इससे स्टर्लिंग का डालर मूल्य ३०.५% से कम हो गया अर्थात् स्टर्लिंग का डालर मूल्य ४०३ के स्थान पर २८० डालर रह गया। इस सम्बन्ध में सर स्टैफर्ड क्रिप्स ने अपने वक्तव्य में स्पष्ट किया कि हालांकि यह समस्या केवल ब्रिटेन की है जो स्टर्लिंग क्षेत्र का बकर है किंतु उसके साथ स्टर्लिंग क्षेत्र के सदस्यों को भी सहयोग देना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि स्टर्लिंग का अवमूल्यन इंग्लैंड ने अपनी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए किया।

### रुपये का अवमूल्यन

स्टर्लिंग अवमूल्यन के २४ घंटे बाद ही भारत ने भी रुपये का डालर एवं स्वर्ण मूल्य ३०.५ प्रतिशत से घटा दिया। अर्थात् रुपये का डालर मूल्य ३०.२२५ सेंट से २१ सेंट रह गया। इससे अमरीका में होने वाले आयात भारत का महंगे पड़ें क्योंकि भारत को प्रति १०० डालर पीछे ३२.६० के बदन ४७६ रु० चुकाने पड़े। इसके विपरीत अमरीका को भारत की वस्तुएँ सस्ती मिलने लगी क्योंकि अमरीका अब १०० डालर देकर भारत से ३३२ रु० की वस्तुओं की अपेक्षा ४७६ रु० की वस्तुएँ खरीद सकता था। परंतु रुपये का स्टर्लिंग मूल्य पूर्ववत् ही रहा (१ गि० ६ प० प्रति रुपया)।

अवमूल्यन क्यों? हमारे अध्यक्ष श्री ज्ञान ग्याई ने अपने वक्तव्य में स्टर्लिंग अवमूल्यन से जो परिस्थिति निर्माण हुई उसके सम्बन्ध में यह कहा था कि—

‘ अवमूल्यन के बाद की विनिमय दर इस अध्याय के अंत में दी है।

भारतीय रुपये का अवमूल्यन परिस्थिति से विवश होकर करना पड़ा। स्टर्लिङ्ग का एव उसके साथ स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के अन्य सदस्य देशों की मुद्राओं का अवमूल्यन होने ही भारत सरकार के सामने स्टर्लिङ्ग के अनुपात में ही रुपये का अवमूल्यन करने के सिवाय दूसरा उपाय न था। क्योंकि सरकार के सामने केवल तीन मार्ग थे —

१ रुपये का अवमूल्यन न करना—यह मार्ग भारत के हित में नहीं था क्योंकि भारत का अधिकतर विदेशी व्यापार (लगभग  $\frac{2}{3}$ ) स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के साथ होने से हमारे निर्यात स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के लिए महँगे हो जाते, जिससे स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के देशों के साथ होने वाला व्यापार ठप्प पड़ जाता। इसके अलावा विदेशी बाजारों में हमारा माल वैसे ही महँगा था, और यदि रुपये का अवमूल्यन न होता तो वह और भी महँगा हो जाता। १९४७-४८ में भारत का व्यापार सन्तुलन ३२ करोड़ रुपये से अनुकूल था जो १९४८-४९ में ६५ करोड़ रुपये में भारत के प्रतिफल हो गया। इसमें भारत और अमरीका के बीच भारत का व्यापार सन्तुलन ३८ ०६ करोड़ रुपये से प्रतिफल रहा क्योंकि १९४८-४९ में अमरीका ने भारत से केवल ७० ६८ करोड़ रुपये की वस्तुएँ आयात की जबकि यही आयात १९४७-१९४८ में ८० करोड़ रुपये का था। अवमूल्यन न करने का परिणाम यह होता कि भारत की वस्तुएँ स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के देशों के लिए महँगी होने के कारण वहाँ उनका आयात न होता और साथ ही अमरीका का अवमूल्यन वाले देशों से भारत की अपेक्षा सस्ते दर पर माल मिल जाता, जिससे भारत की स्थिति, न घर का न घाट का, ऐसी हो जाती।

२. रुपये का स्टर्लिङ्ग मूल्य कम करना—मुद्रास्फीति के कारण रुपये की न्ययक्ति कम हो गयी थी इसलिए उसका स्टर्लिङ्ग मूल्य घटाना आवश्यक था। यदि स्टर्लिङ्ग अवमूल्यन के बाद भारत रुपये की स्टर्लिङ्ग दर कम कर देता तो स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के साथ हमारा जो व्यापार था वह अबाधित रहता परन्तु इससे भारत की स्टर्लिङ्ग क्षेत्र के आयात अधिक महँगे हो जाते, क्योंकि स्टर्लिङ्ग अवमूल्यन ने इंग्लैंड में थोड़े बहुत अक्ष में कीमतेँ बढ़ती और वे बड़ी भी, जिससे भारत का मूल्य-स्तर ऊँचा हो जाता और जनता को कठिनाई होती। साथ ही स्टर्लिङ्ग का डॉलर मूल्य कम होने से रुपये का डॉलर मूल्य वर्तमान मूल्य से भी कम हो जाता जो हमारे हित में नहीं था।

३ रुपये का डॉलर मूल्य घिसाना—रुपये का डॉलर मूल्य स्टर्लिङ्ग के अनुपात में ही अर्थात् ३० ५ प्रतिशत से अवमूल्यन करना। यही मार्ग स्टर्लिङ्ग

क्षेत्र के अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया। इससे अमरीकन आयात हमारे लिए महँगे हो जाते परन्तु हमारे निर्यात बढ़कर १९४८-४९ में जो डॉलर की कमी हो रही थी और बढ़ती जा रही थी वह मिट जाती। डॉलर प्रदेशों के आयात महँगे होने से भारत को अधिक हानि न होती क्योंकि डॉलर क्षेत्र से होने वाले आयात पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण था। इसीलिए वही मार्ग अपनाया भी गया।

भारत को डॉलर की कमी का अनुभव १९४६ से होने लगा और यह कमी प्रति वर्ष बढ़ती ही जा रही थी। भारत को १९४५-४६, १९४६-४७, १९४७-४८ एवं १९४८-४९ इन चार वर्षों में क्रमशः ५ करोड़, ८६ करोड़, ६३ करोड़ और ३७ करोड़ रुपये के डॉलर की कमी रही। इस कमी की पूर्ति के लिए भारत ने स्टलिंग का परिवर्तन डॉलर में कराने के साथ-साथ अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष से एवं अन्तरराष्ट्रीय बैंक से १०० मि० डॉलर खरीदे एवं ४४ मि० डॉलर के ऋण लिये। इसके अलावा अमरीकी सहायता मिलती ही थी। फिर भी डॉलर की समस्या हल नहीं हो सकी। इस समस्या का एकमात्र हल था डॉलर क्षेत्रों को निर्यात बढ़ाना और साथ ही साथ स्टलिंग क्षेत्र का व्यापार अबाधित रखना। फलस्वरूप अवमूल्यन का कदम उठाया गया।

प्रवमूल्यन के बाद—रुपये का अवमूल्यन होते ही डॉ० पी० जे० थॉमस ने अवमूल्यन से होने वाले लाभों के सम्बन्ध में अनिश्चितता बतलायी। उनके मत से यदि विदेशी व्यापार पर अच्छी तरह नियंत्रण न रखा गया तो अवमूल्यन लाभदायक होने की जगह हानिकर होगा। कारण भारत से अमरीका को होने वाला निर्यात अधिकतर वच्चे माल तथा जूट में है जिनकी मांग में न लोच है और न उनकी पूर्ति में ही लोच है। इसलिए उनकी मांग अबाधित रहेगी। दूसरे, हमारे औद्योगीकरण के लिए हमका पूँजीगत वस्तुओं एवं खाद्यान्न के लिए अमरीका पर निर्भर रहना पड़ता है। इनके आयात के लिए हमको ४४% प्रतिशत मुद्राएँ और अधिक देनी पड़ेंगी। अवमूल्यन से देश में मूल्यस्तर बढ़ेगा जिसको रोकने के लिए सरकार को प्रयत्न करना चाहिए। इसी प्रकार खाद्यान्न के सम्बन्ध में आत्म-निर्भर होने तथा निर्यात बढ़ाने के लिए देश का कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना होगा। फिर भी डॉलर प्रदेशों को निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनकी मांग में लोच न होने के कारण वह स्थायी बनी रहेगी तथा उनके मूल्य बढ़ने से निर्यात-व्यापार अबाधित रहेगा। ऐसी वस्तुओं पर सरकार को निर्यात-कर बढ़ाकर ऊँची कीमत का लाभ लेना चाहिए।

अवमूल्यन का तत्कालीन परिणाम यह हुआ कि भारत को डॉलर क्षेत्रों के आयात ४४% से मंहेंगे हो गये जिसके लिए भारत को देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाकर या तो आत्म-निर्भर बनना होगा अथवा उसे अन्न एवं पूँजीगत वस्तुओं का आयात स्टॉलिंग क्षेत्र से करना होगा। जूट के निर्यात बढ़ाकर भारत को यह आशा थी कि वह अधिक डॉलर कमा सकेगा परन्तु पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन न होने से हमको जूट निर्यात से होने वाला लाभ कच्चे जूट (raw jute) की ४४% कीमत बढ़ जाने से गमाप्त हो जायगा।

इस प्रकार अवमूल्यन में निर्माण होने वाली परिस्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने ५ अक्टूबर १९४८ को एक आठ-मूनी योजना अपनाई। इसका उद्देश्य आन्तरिक मूल्यों को स्थिर रखना एवं देश के विदेशी विनिमय साधनों को सुरक्षित रखना था। इसके निम्नलिखित पहलू<sup>१</sup> थे :—

(१) देश की विदेशी व्यापार-नीति ऐसी बनाना जिससे विदेशी विनिमय का न्यूनतम व्यय हो। इसमें देश की अनिवार्य आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जायगा।

(२) भारतीय मुद्रा के साथ जिन देशों की मुद्राओं का मूल्य बढ़ गया है, उन देशों से होने वाला औद्योगिक आयात ममुचित मूल्यों पर हो इसलिए भारत की व्यवसाय-शक्ति (bargaining power) का उपयोग करना।

(३) साव्य-नियन्त्रण तथा वैधानिक एवं सामकीय उपायों से मूल्यों की परिकल्पनिक वृद्धि (speculative rise) रोकना।

(४) देश की विदेशी मुद्राओं की आय अधिकतम करने के लिए डॉलर क्षेत्रों को निर्यात होने वाली वस्तुओं पर अविवेचनात्मक (non-discriminatory) चुँगी लगाना, जिससे अवमूल्यन से होने वाला लाभ विदेशी आयातकर्त्ता, भारतीय निर्माता तथा भारतीय कोष को हो।

(५) देश का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना तथा विनियोग को प्रोत्साहन देना ( जो साधारणतः अवमूल्यन से बढ़ता है )। जनता को बचत करने के लिए अवसर एवं बचत-अन्दोलन द्वारा प्रोत्साहित करना।

(६) मुद्रा-काल में कमाये हुए भारी लाभों को छिपाकर जिन्होंने आय-कर

<sup>१</sup> Reserve Bank of India—Report on Currency & Finance 1949-50 and *Patrika*, 8-10-59

की चोरी की उनसे ऐच्छिक समझौते करना जिससे छिपी आय ओद्योगिक विनियोग में लगायी जा सके ।

(७) १९४६-५० में सरकारी खर्च लगभग ४० करोड़ से कम करने के लिए तथा १९५०-५१ में कम से कम ८० करोड़ रुपये की बचत करने के लिए आवश्यक उपायों को काम में लाना ।

(८) निर्मित-वस्तुएँ, अन्न-धान्य तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के फुटकर मूल्य कम से कम १०% कम करना ।

इस प्रकार सरकार ने अवमूल्यन के कारण देश की आन्तरिक कीमतें बढ़ने में रोकने के लिए तथा जिन वस्तुओं की माँग कीमतें बढ़ने से स्थायी रहेगी उनका लाभ उठाने के लिए आवश्यक कार्य किया ताकि वह अवमूल्यन से होने वाले लाभ पूरी तरह उठा सके । इसलिए सरकार ने एक आदेश द्वारा निर्यात-कर लगाने के अधिकार अपने पास लिये । पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन न होने से भारत की जूट की समस्या थी, इसलिए देश में जूट तथा रई की उपज बढ़ाने के लिए सरकार ने आवश्यक कदम उठाये । साथ ही देश की जूट की पैदावार कलकत्ते के कारखानों को शीघ्रता से पहुँचाने के लिए आवश्यक कार्यवाही की । पाकिस्तान का आयात महँगा होने के कारण पाकिस्तानी माल के आयात सम्बन्धी ओपन-जनरल-लाइसेंस को रद्द कर दिया गया ।

**आस निरास भई (पाकिस्तानी चाल)**

आशा थी कि भारतीय और पाकिस्तानी अर्थ-व्यवस्था परस्पर सम्बन्धित होने से पाकिस्तान भी स्टलिंग क्षेत्र के अन्य देशों की भाँति अपने रुपये का अवमूल्यन करेगा । परन्तु २० सितम्बर १९४६ को पाकिस्तान ने अपने रुपये का अवमूल्यन न करने की घोषणा की, जिससे पाकिस्तानी रुपये का डॉलर मूल्य वही रहा और स्टलिंग मूल्य २५.६ पेंस हो गया एवं १ स्टलिंग ६.२६ पाकिस्तानी रुपये के बराबर हो गया । इससे भारतीय १०० रुपये पाकिस्तानी ६६.५० रुपये के अथवा पाकिस्तानी १०० रुपये भारतीय १.४४ रुपये के बराबर हो गये । पाकिस्तान ने इस निर्णय में उसकी स्टलिंग क्षेत्र की सदस्यता में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुँची । यहाँ पर हमको भारत-पाक का व्यापार ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि भारत पाकिस्तान से लगभग १०७ करोड़ रुपये के माल का वार्षिक आयात तथा लगभग ७३ करोड़ का वार्षिक निर्यात करता था (अवमूल्यन के समय) । स्टलिंग क्षेत्र में पाकिस्तान ही एक देश था जिसने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन नहीं किया ।

पाकिस्तान के इन निर्णय से भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार विलकुल बन्द हो गया क्योंकि भारत ने पाकिस्तानी रुपये की इस दर को स्वीकार नहीं किया।<sup>1</sup> रुपये का अवमूल्यन न करके पाकिस्तान ने भारत के ३०० करोड़ रुपये के ऋण को ८० करोड़ रुपये से कम कर दिया। दूसरे जो शरणार्थी भारत से पाकिस्तान गये थे उनको उनकी भारत स्थित सम्पत्ति के बदले में भारत से अधिक राशि मिलती जिससे उनकी राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि हो गयी। परन्तु पाकिस्तान ने ऐसा करने समय अपने निर्यात-व्यापार की ओर किंचित् भी ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान ने इस सम्बन्ध में यह विज्ञप्ति निकाली कि "अवमूल्यन केवल देन की भुगतान विषमताओं को दूर करने अथवा देन के निर्यात व्यापार में वृद्धि का ही साधन है परन्तु न तो पाकिस्तान के विदेशी व्यापार में भुगतान विषमताएँ हैं और न पाकिस्तान के निर्यात व्यापार में—जो अधिकतर कच्चे माल का है—अवमूल्यन में वृद्धि होने की सम्भावना ही है।"

कुछ भी हो पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन न होने में भारत को आर्थिक धक्का लगा क्योंकि इससे पाकिस्तान से आने वाले जूट और रई के बदले भारत को अधिक रुपये देने पड़ेंगे। उसी प्रकार पाकिस्तानी आयात हमारे लिए महँगा पड़ेगा। इसलिए भारत ने इस परिस्थिति से टक्कर लेने के लिए पाकिस्तानी आयात सम्बन्धी ओपन जनरल लाइसेंस (O.G.L.) रद्द कर दिया। भारतीय जूट मिल एसोसिएशन ने पाकिस्तानी जूट की खरीद स्थगित कर दी। इससे भारत की आवश्यक वस्तुओं का, विशेषतः रई एवं जूट का, आयात बन्द होने से हमारे कपड़े और जूट के कारखाने कच्चे माल के अभाव में कम समय काम करने लगे। फलतः जूट और कपड़े का उत्पादन प्रभावित हुआ। अन्त में इस समस्या को अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सामने रखा गया परन्तु मुद्रा-कोष के अधिकारियों ने इस समस्या की ओर किंचित् भी ध्यान नहीं दिया। अन्ततः भारत न विवश होकर २५ फरवरी १९५१ को पाकिस्तान से व्यापारिक समझौता किया और पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर को मान लिया।

इस समझौते के अनुसार रिजर्व बैंक ने २७ फरवरी १९५१ से चम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली तथा बानपुर के कार्यालयों पर पाकिस्तानी रुपये का

<sup>1</sup> According to "Article I of Payments Agreement between India and Pakistan"

खरीदना एवं बेचना प्रारम्भ किया। अब रिजर्व बैंक पाकिस्तानी ६६॥॥)। रुपये को प्रति १०० भारतीय रुपये की दर से खरीदता है और ६९।२॥)। रुपये प्रति १०० भारतीय रुपये के बढ़ने अधिकृत व्यक्तियों को बेचता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी भारतीय रुपये की खरीद बिक्री १४४ रु० ९ पाई तथा १४३।१॥)। प्रति १०० भारतीय रुपये की दर से अपने कराँची, लाहौर, चटगाँव तथा ढाका के कार्यालयों पर करता है। इस समझौते के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार फिर से आरम्भ हो गया है। भारत अब पाकिस्तान को लोहा, कोयला, सीमेंट आदि वस्तुएँ भेजेगा तथा उससे चाँदी, जूट, चमड़ा, चावल और गेहूँ आदि वस्तुएँ खरीदेगा।

आश्चर्य की बात तो यह रही कि भारत द्वारा पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर मानते ही १६ मार्च १९५१ को अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष ने भी पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर को मान लिया, जिससे हमको कोष की निष्प्रियता एवं साहसहीनता का परिचय मिलता है क्योंकि भारत ने तो आर्थिक स्थिति को देखकर ही यह दर स्वीकार की थी।

**अवमूल्यन के परिणाम**—अवमूल्यन के कारण स्टलिंग क्षेत्र के अन्य देशों और भारत के डॉलर क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि हुई जिससे स्टलिंग क्षेत्र का स्वर्ण एवं डालर निधि नमश बढने लगा। इस कोष में १९४६ के अन्त में निधि का कुल डॉलर मूल्य १६८८ मि० था जो जून १९५० में २४२२ मि० डॉलर तथा दिसम्बर १९५० में ३३०० मि० डॉलर के लगभग हो गया था जिससे स्टलिंग क्षेत्रीय देशों की डॉलर क्षेत्र के साथ जो भुगतान विपमता थी वह कम होने लगी। १९४६ में स्टलिंग क्षेत्र की डॉलर क्षेत्र के साथ १५३२ मि० डॉलर की भुगतान विपमता थी जो १९५० में कम होकर ८०५ मि० डॉलर रह गयी। परन्तु १९५१ में परिस्थिति फिर बिगड़ी जिसके तीन प्रमुख कारण थे—(१) स्टलिंग क्षेत्रीय देशों में कीमतें कम होना, (२) अमरीका द्वारा स्टॉक पाइलिंग प्रोग्राम में शिथिलता लाना, तथा (३) यूरोपियन पुनः शस्त्रीकरण में शिथिलता। इन कारणों की वजह से स्टलिंग क्षेत्रीय (संयुक्त राज्य को छोड़कर) भुगतान स्थिति में जनवरी जून १९५१ के ६ महीने में ४३३ मि० डॉलर की जो अधिकता थी वह जून-दिसम्बर १९५१ में १९२ मि० डॉलर की विपमता में परिणत हो गयी। इसी प्रकार केन्द्रीय स्वर्ण एवं डालर निधि भी जून दिसम्बर १९५१ में कम होता गया (देखिए तालिका) और दिसम्बर १९५१ के अन्त में केवल २३३५ मि० डॉलर रह गया।

स्टर्लिंग क्षेत्रीय डॉलर-निधि

(मिलियन डॉलरों में)

	१९५०	१९५१	१९५६
जनवरी-मार्च	१,६८४	३,७५८	१,८१२
अप्रैल-जून	२,४२२	३,८६७	१,६५१
जुलाई-दिसम्बर	२,७५६	३,०६६	१,४२५
अक्टूबर-दिसम्बर	३,३००	२,३५५	१,६८८

इस समस्या को सुलझाने के लिए १९५१ में राष्ट्रसंघीय अर्थ मन्त्री सम्मेलन बुलाया गया जिसमें यह निर्णय किया गया कि स्टर्लिंग क्षेत्र के सभी सदस्य १९५२ के मध्य तक अन्य क्षेत्रों के साथ भुगतान-मतुलन प्रस्थापित करने का प्रयत्न करें, जिसमें स्टर्लिंग को परिवर्तनशील बनाया जा सके। कुछ भी हो, 'अवमूल्यन' भुगतान-विषमताओं को दूर करने का अस्थायी (temporary) साधन है, स्थायी साधन तो यही है कि उत्पादनशीलता बढ़ाकर वैदेशिक व्यापार में वृद्धि करना।

रुपये के अवमूल्यन से भारत को भी लाभ हुआ क्योंकि भारत के निर्यात बढ़ते गये और भारत ने अधिक डॉलर कमाये। १९४९ में भारत के डॉलर क्षेत्रीय भुगतान में जो ५३ करोड़ रुपये की कमी थी वह १९५० में पूरी होकर भुगतान मतुलन २६ करोड़ रुपये से भारत के अनुकूल रहा। पाकिस्तान से रुई एवं जूट न मिलने के कारण भारत को वस्त्र उद्योग के लिए रुई प्राप्त करने की तथा जूट मिलों के लिए कच्चा जूट प्राप्त करने की समस्या के कारण काफी अमुविधाएँ रही जिनको हल करने के लिए भारत ने अमरीका, मिस्र आदि देशों से रुई मगाने का काम किया। जनवरी-जून १९५० में डॉलर क्षेत्रों से कुल ६६ करोड़ रुपये का आयात हुआ जिसमें केवल ३१ करोड़ रुपये की रुई आयात की गयी। निर्यात होने वाली वस्तुओं में जूट के माल की अधिकता रही और अमरीकी स्टॉक पाइलिंग प्रोग्राम तथा जूट की ऊँची कीमतें होने से निर्यात मूल्य में और भी अधिकता रही। जूट के जो निर्यात १९५० की दूसरी तिमाही में ३५.७ करोड़ रुपये के थे, वे तीसरी एवं चौथी तिमाही में क्रमशः ३६.८ तथा ४९.६ करोड़ रुपये के हो गये। इसी प्रकार व्यापारिक वस्तुओं ने आयात १९५० की तीसरी एवं चौथी तिमाही में कम हो गये क्योंकि १९५० की दूसरी तिमाही में जो आयात ३७.८ करोड़ रुपये के थे वे तीसरी और चौथी तिमाही में केवल १५.५ और १६.८ करोड़ रुपये के हुए। तीसरी तिमाही में

डॉलर प्रदेशीय निर्यात घटने का एक कारण यह भी है कि बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी तथा स्विट्जरलैण्ड ये तीन देश ३० जून १९५० से डॉलर क्षेत्र से निकलकर स्टलिग क्षेत्र में आ गये। दूसरे डॉलर प्रदेशीय—विशेषतः अमेरिका से—वस्तुओं के आयात में कठिनाई होने लगी क्योंकि अमरीकी सरकार ने अनेक वस्तुओं का निर्यात सम्बन्धी नियन्त्रण अपने हाथ में लिया, जैसे रूई, नॉनफेरस धातु। डॉलर एवं स्टलिग क्षेत्रीय आयात-निर्यात व्यापार की पूरी कल्पना निम्न लिखित तालिका में हो जानी है —

### भारत का व्यापार-संतुलन<sup>१</sup>

(करोड़ रुपये में)

	स्टलिग क्षेत्रीय	डॉलर क्षेत्रीय	अन्य क्षेत्र
	निर्यात आयात	निर्यात आयात	निर्यात आयात
अक्टू०-दिस०	१९४९ ७२२ ६३५	४२९ २६१	१८२ १६६
जन०-दिस०	१९४९ २२७३ ३१२५	१२५४ १७२०	७२१ १४३९
जनवरी-मार्च	१९५० ६६१ ५७७	४५३ ४०१	१८० २१४
अप्रैल-जून	१९५० ६१९ ६५१	३५७ ४८४	१४९ १९५
जुलाई-सित०	१९५० ७०१ ७४२	३९८ १८४	१८२ २८६
अक्टू०-दिस०	१९५० ९३५ ७३६	४९९ ३३४	२६६ २९१
जन०-दिस०	१९५० २९१६ २७०६	१७०७ १४०३	७७७ ९८६

अवमूल्यन के बाद के पाँच महीनों के डॉलर क्षेत्रीय आयात निर्यात के आँकड़े इस बात का प्रमाण देते हैं कि अवमूल्यन से भारत को लाभ रहा।

### भारत के डॉलर क्षेत्र से आयात-निर्यात

(करोड़ रुपये में)

	आयात	निर्यात	आधिक्य अथवा कमी
नवम्बर १९४९	८८६	१३५३	+ ४६७
दिसम्बर १९४९	६३३	११०४	+ ४७१
जनवरी १९५०	५९१	९७४	+ ३८३
फरवरी १९५०	४४२	११४९	+ ६०७
मार्च १९५१	५९१	१०८५	+ ४९४

अवमूल्यन के पश्चात् भारत के डॉलर क्षेत्रीय निर्यात बड़े और आयात कम हो गये। इसके विपरीत अवमूल्यन के पूर्व के ६ मास के आयात का

<sup>१</sup> Figures include trade on Government and Private accounts

मासिक औसत १० करोड़ रुपये था जो अवमूल्यन के बाद ७ करोड़ रुपये हो गया, जो १९४९ में राष्ट्रसंघीय अर्थमन्त्री परिषद् के सम्मेलन के अनुसार २५% से भी घट गया। निर्यात की तुलना यदि अवमूल्यन से पूर्व के निर्यातों से की जाय तो भी स्पष्ट हो जाता है कि हमारे निर्यात भी काफी घट गये क्योंकि मई और जून १९४९ में भारत से डॉलर क्षेत्रों में कुल ५.६२ करोड़ रुपये तथा ४.८३ करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। इस प्रकार नवम्बर १९४९ में मार्च १९५० के अन्त तक भारत ने २४.२३ करोड़ रुपये के डॉलर कमाये।

परन्तु १९५१ में १९५० की भाँति परिस्थिति न होने में भारत की डॉलर क्षेत्रीय भुगतान सतुलन की परिस्थिति प्रभावित हुई और इन वर्ष आधिक्य की जगह ७६.७ करोड़ रुपये की प्रतिफलता रही। १९५१ की पहली छमाही में भुगतान का आधिक्य १४.६ करोड़ रुपये में भारत के पक्ष में था परन्तु जुलाई-दिसम्बर १९५१ की छमाही में ६१.६ करोड़ की कमी रही। इस कमी की पहली छमाही के आधिक्य से पूरा करने पर ७६.७ करोड़ की कमी भुगतान परिस्थिति में रही। इस प्रकार १९५१ की अन्तिम छमाही में डॉलर की कमी हो गयी। इस कमी का परिणाम यह हुआ कि इस अवधि में भारत के व्यापारिक आयात २५.२ करोड़ (१९४०) में बढ़कर ४५.७ करोड़ के हुए। इसके अलावा यत्र तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के आयात में भी वृद्धि हुई। १९५० में हमारे डॉलर क्षेत्रीय आयात १५.७ करोड़ रुपये के थे जो १९५१ में बढ़कर २८.४ करोड़ रुपये के हो गये। आयात बढ़ने के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा डॉलर क्षेत्रों में ७६ करोड़ रुपये का गेहूँ यू० एन० व्हीट लोन समझौते के अन्तर्गत आयात किया गया तथा ६६.५ करोड़ रुपये का अन्य आयात सरकार ने किया। डॉलर क्षेत्र में गेहूँ इसीलिए आयात किया गया क्योंकि स्टर्लिंग क्षेत्र से गेहूँ मिल नहीं रहा था। दूसरी ओर भारत से डॉलर क्षेत्रीय निर्यात भी १९५१ की दूसरी छमाही में कम हुए। १९५१ की पहली छमाही में भारत ने डॉलर क्षेत्रों को ११.६ करोड़ रुपये का कुल निर्यात किया जहाँ दूसरी छमाही में कुल निर्यात ८.४ करोड़ रुपये का ही हुआ। इस प्रदेश की होने वाली निर्यात वस्तुओं में जूट के निर्यात भी कुछ कम हुए परन्तु अन्य वस्तुओं के निर्यात में—जैसे चाय, मसाले, कपड़ा, वीज आदि के निर्यात—काफी कमी हो गयी क्योंकि इन वस्तुओं के लिए डॉलर क्षेत्रों में माँग कम हो गयी। विशेष रूप से उपभोग्य वस्तुओं की माँग में काफी कमी रही। माँग की कमी का प्रमुख कारण इन प्रदेशों द्वारा १९५० एवं जून १९५१ तक इन वस्तुओं का काफी

आयात कर लेना था। दूसरे, जुलाई-दिसम्बर १९५१ के व्यापार की गति में अनिश्चितता भी आगयी थी जिस वजह से भारतीय वस्तुओं की माँग डॉलर क्षेत्रों में प्रभावित हुई। तीसरे, १९५१ के बाद मूल्यों की गिरावट के कारण वस्तुओं के निर्यात मूल्य भी काफी कम हो गये जिससे हमको कम डॉलर मिले। चौथे, दक्षिण, स्विट्जरलैंड और पश्चिमी जर्मनी के डॉलर क्षेत्रों से निकल कर स्टलिंग क्षेत्रों में आजाने से भी हमारी डॉलर की कमाई प्रभावित हुई। परन्तु इससे एक लाभ यह भी हुआ कि इन देशों के डॉलर क्षेत्रों में निकल जाने के कारण भुगतान सन्तुलन में कम विपमना रही जो संभवतः वर्तमान आँकड़ों में भी अधिक हो जाती।

इस प्रकार डॉलर धन के साथ भुगतान की कमी को निर्यातों में वृद्धि करके दूर करने के लिए भारत सरकार ने जूट, तेलहन आदि वस्तुओं के निर्यात-कर (export duties) आधे कर दिये जिससे १९५२ की पहली छमाही में भुगतान परिस्थिति में कुछ सुधार हुआ और यह आशा की जा सकती थी कि १९५२ के अन्त के आँकड़े जब हमारे सामने आएँगे उस समय डॉलर क्षेत्रों के साथ भारत के भुगतान सन्तुलन की वर्तमान प्रतिकूलता दूर हो जायगी। १९५२ की पहली छमाही के जो आँकड़े प्रकाशित हुए हैं<sup>१</sup> उनसे पता लगता है कि भारत का भुगतान-सन्तुलन ७४४ करोड़ से प्रतिकूल रहा। जनवरी-मार्च १९५२ में ७६ करोड़ रुपये की प्रतिकूलता रही परन्तु अप्रैल-जून १९५२ की तिमाही में २२ करोड़ रुपये का आधिक्य रहा जो जुलाई-दिसम्बर १९५१ के प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन से (६२४ करोड़ रु०) कम हो गया है। परन्तु अब की बार भुगतान-सन्तुलन की एक विशेषता यह थी कि भारत की पाकिस्तान के साथ जो भुगतान-विपमना अभी तक रही वह जनवरी-जून १९५२ की छमाही में मिट गयी, इतना ही नहीं अपितु २३२ करोड़ रुपये का आधिक्य रहा। जुलाई-दिसम्बर १९५१ में पाकिस्तान के साथ हमारा भुगतान-सन्तुलन २७४ करोड़ रुपये से प्रतिकूल था। डॉलर क्षेत्र के साथ भारत का सन्तुलन प्रतिकूल रहा। केवल चालू खाते (current account) पर भारत को डॉलर क्षेत्र के साथ ११४६ करोड़ रुपये की प्रतिकूलता रही जो १९५१ की अन्तिम छमाही में ८६७ करोड़ रुपये की थी। इस प्रकार १९५२ की प्रथम छमाही में हमारे आयात जुलाई-दिसम्बर १९५१ की अपेक्षा बड़े और निर्यात में कमी हुई —

१ Reserve Bank of India Bulletin, Nov 1952.

(करोड़ रुपये में)

		आयात	निर्यात
जुलाई-दिसम्बर	१९५१	१६६.१	७८.१
जनवरी-जून	१९५२	१६८.६	७५.२

हमारे आयातों में रुई का बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि जुलाई-दिसम्बर १९५१ में रुई का आयात ५२.९ करोड़ रुपये का था जो जनवरी-जून १९५२ में ७६ करोड़ रुपये का हुआ। परन्तु यदि १९५२ की पहली व दूसरी तिमाही को देखा जाय तो हमारे आयात ६०.२ करोड़ रुपये से घटकर १८ = करोड़ रुपये के हो गये। इन आँकड़ों में स्पष्ट है कि १९५१ में डॉलर क्षेत्रीय व्यापार में भारत को जो प्रतिबलता रही उसमें इस वर्ष की छमाही में सुधार आता दिखायी देता है। इस सुधार का प्रमुख कारण हमारे अन्न आयात की कमी है और १९५२ की दूसरी तिमाही में रुई के आयात का कम होना भी है। इस लिए आशा की जा सकती है कि दिसम्बर १९५२ के अन्त में भारत की भुगतान-परिस्थिति में सुधार हो जायगा। साथ ही, इंग्लैंड के सामने भी डॉलर समस्या फिर से खड़ी हो गयी है और उसके लिए नवम्बर १९५२ में राष्ट्रीय मंत्रियों का सम्मेलन भी हो चुका है। देखना है कि आगे क्या होगा है।

### पुनर्मूल्यन की समस्या

रुपये के अवमूल्यन ने एक वर्ष बाद ही स्टॉकिंग और रुपये का पुनर्मूल्यन की चर्चा खड़ी हो गयी। १९५० में पाकिस्तान अन्तरराष्ट्रीय कोष का सदस्य बना और उसके रुपये का सममूल्य कोष द्वारा स्वीकार करने से पुनर्मूल्यन के समर्थकों और विरोधियों में चर्चा छिड़ गयी। पाकिस्तानी रुपये की विनिमय-दर की मजबूती ने हमें और भी जोर दिया। समर्थकों का कहना था कि भारत के निर्यात में जो वृद्धि हुई वह अवमूल्यन के कारण न होने हुए कौरियाई युद्ध तथा अमरीकी स्टॉक-पाइलिंग प्रोग्राम के कारण थी। वास्तव में केवल एक ही कारण ने निर्यात-व्यापार में वृद्धि हुई, वह सोचना एक बड़ी भूल होगी क्योंकि हम एक कारण को दूसरे कारणों से अलग नहीं कर सकते। समर्थकों का कहना था कि “अवमूल्यन में हमारे आयात ४४% बढ़ेंगे हुए। सरकारी प्रयत्नों के होते हुए भी मूल्यस्तर को स्थायी न रखा जा सका, जूट, रुई और अन्न की समस्या अधिक जटिल हो गयी, औद्योगिक विकास के लिए पूँजीगत वस्तुओं के आयात बढ़ेंगे होने से उनको हम सुगमता से नहीं भेजा सकते, आदि। इसलिए रुपये का पुनर्मूल्यन जल्दी ही होना चाहिए।” पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर की मान्यता एवं उसकी मजबूती ने इस मत की पुष्टि की। पाकिस्तानी

रुपये की मजबूती के लिए उसके भुगतान के सतुलन की अनुकूलता ही एकमात्र कारण न होते हुए “व्यापार की शर्तों” (terms of trade) का सुधार एक प्रमुख कारण है जिससे आस्ट्रेलिया, पाकिस्तान तथा दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को लाभ हुआ—जो कच्चे माल का निर्यात अधिक करते हैं। इस लाभ के साथ आशा थी कि यदि रुपये का पुनर्मूल्यन किया जाय तो हानि होने की अपेक्षा व्यापार-सतुलन का आधिक्य और भी बढ़ेगा।

रुपये के पुनर्मूल्यन के पक्ष में आवाज उठायी जाने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियाँ भी जिम्मेदार थी —

(१) भारत द्वारा पाकिस्तानी रुपये की विनिमय-दर न मानी जाना, जिससे भारत-पाक व्यापार लगभग ठप्प-सा हो गया था और भारतीय कारखानों को चलाने के लिए कूट एवं रुई की कमी अनुभव हो रही थी। इसलिए रुपये का यदि पुनर्मूल्यन किया जाय तो भारत-पाक व्यापारिक समस्या का समुचित हल हो सकेगा।

(२) अन्तरराष्ट्रीय गेहूँ समझौते के अनुसार भारत को आस्ट्रेलिया से प्रति वर्ष १ लाख टन गेहूँ आयात करना था, जिसकी दर इस समझौते के अनुसार निर्दिष्ट कर दी गयी थी। परन्तु आस्ट्रेलिया अवमूल्यन पूर्व दर पर भारतीय मुद्रा के बदले गेहूँ देने के लिये तैयार नहीं था जिससे भारत को गेहूँ का आयात करने के लिए निर्धारित दरों से ४४% रुपये अधिक चुकाने पड़ते। रुपये के पुनर्मूल्यन से यह समस्या हल हो जाती।

(३) भारत की विकास योजनाओं की प्रगति में भी अवमूल्यन से बाधा पहुँची क्योंकि हमारे तांत्रिक सलाहकर तथा पूंजीगत वस्तुओं का अधिकतर आयात डालर शत्रु से ही हाना था।

(४) अवमूल्यन से भारत का निर्यात-व्यापार बढ़ेगा किन्तु यह आगामि भी वृथा साबित हुई क्योंकि हमारी निर्यात-वस्तुओं की माँग में लोच नहीं है।

(५) भारत के प्रयत्नों के बावजूद भी भारत अपने आयात में कमी करने में अक्षम रहा है क्योंकि भारत में होने वाला अघनिष्ठ आयात आवश्यक वस्तुओं का है जिनका उत्पादन देश में कम है।

(६) भारत को परिस्थिति से विवश होकर अवमूल्यन करना पड़ा और अब परिस्थिति बदल चुकी है अतः रुपये का पुनर्मूल्यन होना आवश्यक है।

पुनर्मूल्यन से हमारे निर्यात बढ़ेंगे और उनका मूल्य बढ़ जाने से हमारे भुगतान-सतुलन की स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ ही अधिक अन्न के

आयात से हमारे स्तुलन में वर्तमान विनिमय-दर पर अधिक विषमता आयेगी और उसका निवारण भी हो जायगा। इस प्रकार पुनर्मूल्यन से भारत को आयात-निर्यात व्यापार दोनों में ही लाभ होगा। ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट के अनुसार पाकिस्तान के साथ रुई, पटसन, चमड़ा इत्यादि के जून १९५२ तक के आयात का भुगतान करने में रुपये के पुनर्मूल्यन से (३०.५%) ४१.२६ करोड़ रुपये की बचत होगी। इसी प्रकार एक यह मत भी प्रकट किया गया था कि भारत में जीवन-व्यय के मूल्यांकन रुपये के अवमूल्यन से बढ़ते जा रहे हैं जो रुपये के पुनर्मूल्यन से कम हो जायेंगे क्योंकि पुनर्मूल्यन होते ही थोक कीमतों में ७ से १०% प्रतिशत गिरावट आ जायगी तथा मुद्रा-स्फीति की तीव्रता भी कम होगी।

इस प्रश्न को विक्षेपित जून १९५१ में जब डॉ॰ जॉन मथाई ने उठाया तो फिर से इस सम्बन्ध में चर्चा होने लगी क्योंकि अवमूल्यन के समय भारत के अर्थ-सचिव यही थे।

पुनर्मूल्यन के विरोध में

(१) रुपये के पुनर्मूल्यन से हमारे आयात सस्तें हो जाएंगे क्योंकि विदेशी मुद्राएँ हम अधिक खरीद सकेंगे। इससे या तो हमारे यह आयात अधिक मात्रा में बढ़ेंगे जिससे निर्यात-करो द्वारा सरकारी-आय कम होगी। उसी प्रकार आयात सस्ते मिलेंगे ही यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि जूट, रुई, खाद्यान्न की हमको अतीव आवश्यकता है जिसको कहीं न कहीं से आयात किया बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता। इस कमजोरी को सभी दल जानते हैं जो इनके निर्यात मूल्य बढ़ाकर हमारी त्रिव्यवस्था का लाभ उठा सकते हैं। यदि मान भी लिया जाय कि आयात सस्ते होंगे तब भी यह असम्भव-सा प्रतीत होता है कि समर्थकों द्वारा आँका गया १८३ करोड़ रुपये का लाभ होगा ही। दूसरे, विरोधियों द्वारा दी जाने वाली दलील कि सरकार की आय कम होगी यह भी संशयास्पद प्रतीत होती है।

(२) जहाँ तक हमारे निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा कमाने का सम्बन्ध है हम यह नहीं भूल सकते कि हमारा निर्यात महँगा है। फिर इस दत्त का निर्यात बढ़ेगा कैसे? मान लिया जाय कि जूट में भारत का एकाधिकार है फिर भी

\* "Revaluation and India's Balance of Trade"—*Eastern Economist*, 16-3-1951 and issues of *Eastern Economist* of 20th and 27th April, 1951, "Revaluation by Degree"—17th Aug., 1951

यदि उसकी कीमतें महँगी हो जाती है तो अमरीका आदि देश प्रतिवस्तु का उपयोग करने लगेंगे।

(३) पाकिस्तानी आयात सस्ते पड़ेंगे और भारत को पाकिस्तान-भारत व्यापार में लाभ होगा यह भी भ्रम है क्योंकि पाकिस्तान से होने वाले आयातों में जूट, अन्न और रई की प्रमुखता है। इनमें से जूट उत्पादन में पाकिस्तान को एकाधिकार है। ऐसी अवस्था में पाकिस्तान सस्ते आयात द्वारा भारत को लाभ नहीं उठाने देगा। १९५२ के आँकड़ों से जैसा स्पष्ट होता है बिना पुनर्मूल्यन के ही भारत-पाकिस्तान व्यापार में अनुकूलता आने लगी है। अतः रुपये के पुनर्मूल्यन की पुष्टि नहीं मिलती।

(४) जीवन-व्यय कम करने तथा मुद्रास्फीति की तीव्रता को रोकने के लिए भी पुनर्मूल्यन करने पर जोर दिया गया था। मुद्रा-स्फीति रोकने के लिए विरोधियों ने अन्य मार्ग गुभाये जैसे करो में वृद्धि, बचत का प्रोत्साहन एवं उसका विकास-कार्यों के लिए उपयोग, सरकारी खर्चों में कमी, मूल्य-नियंत्रण आदि। इन सगो की राय थी कि आये दिन विनिमय-दर से खिलवाड़ करना भारत के लिए लाभनास्पर्द है।

(५) जिस परिस्थिति से विवश होकर हमने अवमूल्यन किया था (अर्थात् स्टर्लिंग क्षेत्र से अधिक व्यापार होने के कारण) वह परिस्थिति आज भी है। तो अब रुपये के पुनर्मूल्यन से हमारे स्टर्लिंग क्षेत्रीय व्यापार में कमी आ जायगी जो हमारी अदूरदर्शिता होगी। इसके अलावा रुपये के पुनर्मूल्यन से हमारे पाँड-पावने में भी कमी होगी।

(६) इसी प्रकार जिस परिस्थिति में हमने १९५१ में पाकिस्तान की विनिमय दर मान ली, वह परिस्थिति रुपये के पुनर्मूल्यन से फिर उपस्थित हो जायगी और फिर से भारत-पाक व्यापार सम्बन्ध टूट जायेंगे।

(७) आज के विश्व में परस्पर आधिक-निर्भरता बढ़ती ही जा रही है। अतः रुपये के पुनर्मूल्यन के लिए अकेले भारत का ही कदम उठाना उसके अंतर-राष्ट्रीय हित सम्बन्धों को खराब कर देगा। फिर आज विश्व की आर्थिक स्थिति बड़ी डाँवाडोल हो रही है और उसका पेण्डुलम किस ओर धूमेगा यह निश्चित नहीं कहा जा सकता।

अतः ऐसी अवस्था में विनिमय-दर को कम अथवा अधिक करने की जल्दवाजी भारत को नहीं करनी चाहिए। फिर पुनर्मूल्यन किस देश की मुद्रा के साथ हो?

(1) डालर के साथ अथवा (ii) स्टर्लिंग क्षत्र के दगा का मुद्रा के साथ तथा (iii) पुनर्मूल्यन कितन प्रतिशत म किया जाय ?

इस सम्बन्ध म था० चिन्तामणि देसमुख न भी स्पष्ट कहा है कि कोई भी व्यक्ति जो इस प्रश्न की परीक्षा करन की क्षमता रखता है उसन यही तात्पर्य निकाला है कि अवमूल्यन लाभकर हुआ है तथा कोरियाई युद्ध के आरम्भ तक मूल्य वृद्धि रोकन म कठिनता नही आई। यदि हम पुनर्मूल्यन करत हैं ता सम्भवत हमारी स्थिति सुधरन क बचाय बिगट जायगी। इस प्रकार का समस्या कभी ताव म न रखी जायगी किन्तु इस पर हम समय समय पर निगय लग जा वृद्धिमानों का काम होगा।

प्रो० बी० आर० जेनाय न अप्रन १८५८ म पुन रुपय व पुनर्मूल्यन पर पार दिया था परन्तु तत्कालान विदेशी विनिमय क सकट के कारण इसका तीव्र विरोध हुआ।

### पाकिस्तानी रुपय का अवमूल्यन

३१ जुलाई १९५५ का पाकिस्तान न भा अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया जिसमे वह भारतीय रुपय के स्तर पर आ गया। उसका स्वण मूल्य ० १८६६२१ ग्राम हो गया परन्तु उसका स्टर्लिंग मूल्य १ नि० ६ पेंस हा रहा। पाकिस्तान द्वारा यह निगय आर्थिक आधार पर लिया गया है। इसका प्रमुख हतु पटसन एवं रई उत्पादका का उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना तथा पाकिस्तान की विदेशी विनिमय आय बढान के लिए निमाता की वृद्धि का प्रोत्साहन देना है। इस निगय क गूब अंतरराष्ट्रीय बाजार म पटसन और रई की कीमत गिरन के कारण पाकिस्तानी किसान आर्थिक कठिनाइयों म न। इस निगय स पाक रुपय के अय चित्रय का अपिष्टत दरा म परिवर्तन किया गया है जो कमदा १०० = ६ पाक रुपय तथा ९९, १५ ६ पाक रुपय प्रति भी भारतीय रुपय है।

इस निगय का तत्कालीन प्रभाव भारताय जूट व्यवसाय पर होता इसलिए भारत सरकार न १ अगस्त १९५५ से जूट को निर्यात करन से मुक्त कर दिया है। क्याकि अब विदेशी बाजार म भारतीय और पाकिस्तान जूट निमित वस्तुओं म तीव्र प्रतियोगिता होगी। परन्तु अन्य व्यापार पर कोई बिगड प्रभाव नहा होगा।

### सारांश

डालर सकट को हल करने के लिए ब्रिटन ने स्टर्लिंग का डालर मे अव मूल्यन करते ही भारत ने भी १६ सितम्बर १९४६ को अपने रुपये का अव

मूल्यन किया। स्टर्लिंग क्षेत्र के अन्य देशों की भांति भारत भी डॉलर सकट में था। इसे हल करने के उसके पास तीन मार्ग ही थे—

(i) रुपये का अवमूल्यन न करना, (ii) रुपये का स्टर्लिंग मूल्य कम करना तथा (iii) रुपये का डॉलर मूल्य स्टर्लिंग के अनुपात में ही कम करना।

पहला उपाय सम्भव न था क्योंकि भारत का विदेशी व्यापार स्टर्लिंग क्षेत्र से अधिक होने से वह प्रभावित हो जाता। यदि रुपये का स्टर्लिंग मूल्य कम किया जाता तो हमारे स्टर्लिंग क्षेत्र के आयात में हानि होगी। इसलिए तीसरा उपाय ही काम में लाया गया।

इसके तीन तत्कालीन परिणाम हुए—हमारे लिए डॉलर क्षेत्र के निर्यात में हानि होगी, स्टर्लिंग पावनों का डॉलरों में मूल्य गिर गया तथा पाकिस्तानी रुपये का अवमूल्यन न होने से हमारे उद्योगों के लिए कच्चा जूट एवं रई प्राप्ति करने की समस्या आ गयी। साथ ही पाकिस्तान के साथ व्यापार ठप्प सा हो गया।

इस स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार ने एक आठ वृत्तीय योजना काम में लायी। देश में उत्पादन बढ़ाना, आयात कम करना, विदेशी व्यापार नीति में विदेशी विनिमय का न्यूनतम व्यय करने की दृष्टि से मिलान करना आदि योजना के प्रमुख अंग थे।

अवमूल्यन के बाद के १४ मास में यद्यपि हमारी स्थिति में सुधार हुआ, फिर भी इस समस्या का स्थायी हल उत्पादन वृद्धि द्वारा निर्यात वृद्धि करने में ही है।

१९५१ में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तानी रुपये का स्वर्ण मूल्य स्वीकार करते ही डॉ० जॉन मेथार्ड आदि अर्थशास्त्रियों ने रुपये के पुनर्मूल्यन की आवाज उठायी। पुनर्मूल्यन के समर्थकों ने निम्न बल्लोत्ते की। आयात सस्ते होंगे, निर्यात से अधिक डॉलर प्राप्त होंगे, पाकिस्तान के साथ व्यापार में लाभ, विदेशी व्यापार में वृद्धि, मुद्रास्फीति रोकने के लिए आदि। परन्तु विरोध में यह कहा गया कि डॉलर क्षेत्र से आयात करने में डॉलरों की कमी होगी, पुनर्मूल्यन करना अदूरदर्शी नीति होगी, निर्यात घटेंगे तथा विदेशी व्यापार में बाधा आयेंगी।

इस प्रश्न को १९५५ में प्रो० बी० आर० सेनॉय ने उठाया था परन्तु तत्कालीन विदेशी विनिमय सकट के कारण उसका सीधा विरोध हुआ। ३१ जुलाई १९५५ को पाकिस्तान ने आर्थिक परिस्थिति से विवश होकर पाक रुपये का ३० ५% से अवमूल्यन किया जिससे वह भारतीय रुपये की समता में आ गया है।

## परिशिष्ट

अवमूल्यन के पश्चात् विभिन्न देशों की मुद्राओं के सममूल्य

देश का नाम	मुद्रा	भारतीय रुपये में मूल्य	अमरीकी डॉलर में मूल्य	अवमूल्यन का प्रतिशत
१ अमेरिका	डॉलर	४ ७६१	—	
२ इंग्लैंड	पौण्ड-स्टर्लिंग	१ = ३३२	२ ८०	३० ५ %
३ भारत	रुपया	—	० २१ सेट	"
४ म्यूजीलैंड	पौण्ड	१३ ३८८	२ ८०	"
५ आयरलैंड	"	१३ ३३३	"	"
६ दक्षिण अफ्रीका	"	१३ ३३३	"	"
७ आस्ट्रेलिया	"	१० ६-६	० २४	"
८ ईजिप्ट (मिस्र)	"	१२ - ७४	२ ८३१	"
९ ब्रह्मा	रुपया	१ ००	० २१	"
१० लका	"	१ ००	"	"
११ पाकिस्तान	"	१ ००	०१ सेट	३० ५ %
१२ कनाडा	डालर	८ ३२२	१ - १ १०	१० ०० %
१३ फ्रांस	फ्रांक	० ११८	कनाडा-डालर	
१४ लक्सम्बर्ग	"	० ६५२	१ = ३५० फ्रांक	५ ६० ०/०
१५ बेल्जियम	"	० ६५२३		१२ ३४ ०/०
१६ डेनमार्क	क्रोनर	० ८८६	१ = ६ ६० ७१४	१२ ३४ ०/०
१७ आइसलैंड	"	० ५०९	क्रोनर	
१८ नार्वे	"	० ६६६	१ = ७ १४२	१२ ३४ ०/०
१९ फिनलैंड	मार्क	० ६६६	(croners)	
२० इराक	दीनार	१२ = ३३	२ ८०	३० ५ %
२१ नीदरलैंड	गिल्डर	१ ७५३		३० ५२ %
२२ ग्रीस	ड्रामा (drachmas)	००० = १७	१ = १५०००	३३ ३ %
२३ स्वीडन	क्राउन		१ = ५ ७८ नाउन	३० ५ %
२४ ईरान	दीनार		१ = ४० दीनार	
२५ इण्डोनेशिया	गिन्डर		८० रियास	
			१-३ = ० गिन्डर	

## भारत में दाशमिक मुद्रा प्रणाली

विश्व के लगभग १४० देशों में अपनी-अपनी मुद्रा है, जिनमें १०५ देशों ने दाशमिक मुद्रा प्रणाली अपना ली है। अमेरिका ने सन् १७८६ व १७९२ में दाशमिक मुद्रा प्रणाली अपनायी। उसकी देखादेखी सन् १७९९ व १८०३ में फ्रांस ने भी दाशमिक मुद्रा प्रणाली अपनायी। इसके बाद जर्मनी, आस्ट्रिया, इंगेरी आदि देशों ने इस प्रणाली को १८वीं शताब्दी के अन्त तक अपना लिया। इंग्लैंड ने इस प्रणाली को नहीं अपनाया क्योंकि इस प्रणाली को अपनाने में उसे अनेक कठिनाइयाँ थी। वहाँ पर जो स्वयं-चालित काउंटिंग मशीनें प्रयोग में थी उनको बदलने में अनेक कठिनाइयाँ थी। भारत अभी औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। अतः उसके लिए यह आवश्यक था कि वह दाशमिक मुद्रा प्रणाली का अनुसरण करे। क्योंकि आने वाले वर्षों में भारत की हर दिशा में प्रगति होगी, चाहे वह व्यापारिक, औद्योगिक अथवा बैज्ञानिक दक्ष नवो न हो। इसलिए भविष्य कालीन सुविधाओं की दृष्टि से भारत के लिए यह आवश्यक समझा गया कि वह दाशमिक मुद्रा प्रणाली को अपनाय।

तदनुसार १ अप्रैल, १९५७ से भारत ने भी यह प्रणाली अपनायी है। यद्यपि नये सिक्के दाशमिक प्रणाली पर आधारित हैं फिर भी इनने वंशमूलक सिद्धान्त का पालन कठोरता से नहीं किया गया। रूढ़िवादी परिभाषा के अनुसार दाशमिक मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें सारे सिक्के एक प्रमाणित सिक्के के दस, सौ या हजार गुने होते हों। दूसरे शब्दों में, यदि प्रमाणित सिक्का १ है तो उसमें बड़े सिक्के १०, १००, १००० आदि और छोटे सिक्के १, ०१, ००१ आदि होंगे। पूरी तरह इस सिद्धान्त पर आधारित प्रणाली में इनके बीच के सिक्के नहीं होते, पर इस सिद्धान्त का कठोरता से पालन नहीं किया गया है क्योंकि भारत में २, ५ तथा १५ नये पैसे के सिक्के चलन में लाये गये हैं।

पूर्व-इतिहास — दाशमिक सिक्कों में कुछ ऐसी विशेषताएँ होती हैं जो अन्य

सिक्कों में नहीं होती। इसीलिए भारत में काफी समय से विशेषज्ञ दशमिक सिक्के चालू करने के लिए प्रयत्नशील थे। इस दिना में १८६७ में पहिला प्रयत्न हुआ था तथा काफी विचार के बाद सरकार ने निर्णय किया था कि धीरे-धीरे दशमिक सिक्के चालू किये जायें। इस हेतु १८७१ में एक मेट्रिक अधिनियम भी बनाया गया, परन्तु विविध कारणों से वह कार्यान्वित न हो सका। इसके बाद १८४० में भारत में दशमिक समाज (Indian Decimal Society) की स्थापना हुई जिसने भारतीय नापनीय एवं विनिमय प्रणाली दशमिक आधार पर कायम करने पर बल दिया। तदनुसार १८४६ में पुनः इस पर विचार हुआ तथा केन्द्रीय समझ में एक बिल पेश किया गया, किन्तु तत्कालीन राजनीतिक परिवर्तनों के कारण वह बिल पार न हो सका। इसके बाद १८४६ में भारतीय प्रतिमान मन्त्रालय की एक विशेष समिति ने इस सम्बन्ध में विचार कर अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। इस रिपोर्ट में दशमिक आधार पर नापनीय एवं मुद्रा प्रणाली को १० से १५ वर्ष की अवधि में क्रमशः लागू करने की सिफारिश की। १८५५ में एक बिल इस सम्बन्ध में गन्तव्य मिला गया जो मिनस्वर १८५५ में पारित हो गया। भारतीय सिक्का (मणोघन) अधिनियम से १८०६ का भारतीय सिक्का अधिनियम का मन्सोधन हुआ तथा दशमिक सिक्के चालू करने का अधिकार भारत सरकार को मिला।

दशमिक सिक्के क्यों? — भारत औद्योगिक उन्नति के युग में प्रवेश कर रहा है। इससे आगामी १०-१५ वर्षों में भारत की अर्थ-व्यवस्था काफी जटिल हो जायगी और यहाँ हिमाव-किताव की हजारों-लाखा मशीनों का प्रयोग होने लगेगा। भारत में अभी तक स्वचालित सिक्का टालने वाली मशीनों की संख्या बहुत कम है। वैज्ञानिक यन्त्र बनाने वाले उद्योग भी अभी शैशव-काल में ही हैं। यदि कुछ समय के लिए यह प्रणाली लागू न होती तो पुरानी सिक्का प्रणाली के अनुस्यू बहुत अधिक यन्त्र बर्तन भुके होने, जिनको बदलने में बड़ी अधिक व्यय होना।

दशमिक सिक्का का पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके साथ नाप और तौल के पैमाने भी दशमिक प्रणाली के अपनाये जायें, क्योंकि वर्तमान नाप-तौल की विविधता से बहुत मजबूत होती है। इस हेतु दशमिक सिक्कों का चलन आवश्यक था।

इसके सिवा दशमिक सिक्का प्रणाली हिमाव-किताव की जटिलता को दूर करने के लिए भी आवश्यक थी।

भारतीय टक्कण अधिनियम १९५५—उक्त सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने १९०६ का टक्कण अधिनियम मशौघिन करने तथा दाशमिक मुद्रा प्रणाली अपनाने के लिए ७ मई १९५५ को लोक सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया। यह विधेयक २६ जुलाई १९५५ को पारित होकर १७ नवम्बर १९५५ को राष्ट्रपति से स्वीकृत हुआ।

यह अधिनियम १ जनवरी १९५७ से भारत में लागू हो गया है। तदनुसार भारत की प्रमाणित मुद्रा रुपया हो गई, परन्तु इसका विभाजन १६ आने, ६४ पैसे या १६२ पाइयो में न होकर १०० सेंट में होगा। प्रत्येक सेंट को नया पैसा कहते हैं। वर्तमान अठन्नियाँ एवं चबन्नियाँ क्रमशः ५० और २५ नये पैसे के बराबर होंगी। वर्तमान दुअन्नियाँ, इकन्नियाँ, अघल्ले तथा पैसों के गम मूल्य का कोई भिन्नता नयी दाशमिक प्रणाली में नहीं होगी। अपितु १०, ५, २ और १ नये पैसे के नये सिक्के रहेंगे जो चलन में आगये हैं।

पुराने और नये दाशमिक सिक्के संक्रमण काल में साथ साथ चलन में रहेंगे, परन्तु क्रमशः भिन्न-भिन्न सिक्कों को चलन से हटाया जायेगा। यह संक्रमण काल तीन वर्ष अर्थात् ३१ मार्च १९६० तक है जिसके बाद केवल नये दाशमिक सिक्के ही चलन में रहेंगे। परन्तु यदि आवश्यकता हुई तो इस अवधि को थोड़ा बहुत बढ़ाया जा सकता है। यह केवल इसीलिए किया गया है जिससे जनता नये सिक्कों से अच्छी तरह परिचित हो जाय।

यह प्रणाली भारत में १ अप्रैल १९५७ से चालू हो गयी है तथा क्रमशः पुराने सिक्के चलन से हटाये जा रहे हैं।

दाशमिक मुद्रा प्रणाली का परिचय—दाशमिक मुद्रा प्रणाली का प्रचार जनसाधारण में करने के लिए भिन्न-भिन्न साधन सरकार ने अपनाये। इसको लोकप्रिय बनाने के लिए समाचार पत्रों में परिवर्तन तालिकाएँ दी गईं, प्रमुख-प्रमुख स्थानों पर पोस्टर चिपकाये गये तथा दाशमिक मुद्रा प्रणाली का परिचय देने वाली लघु पुस्तिकाओं का नि:शुल्क वितरण किया गया। इसका हेतु जनसाधारण को पुराने सिक्कों के स्थान पर नये सिक्कों का प्रयोग किम प्रचार किया जाय, यह बताना था। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भी यह निर्णय लिया कि पाठ्य पुस्तकों में पुराने सिक्कों के स्थान पर नये सिक्कों का व्यवहार किया जाय। इसीको राज्य सरकारों ने भी मान्यता दी जिससे आने वाली पीढ़ी नये सिक्कों से भलीभाँति परिचित हो सके तथा उसे दाशमिक मुद्रा प्रणाली में नवीनता का आभास न मिले।



डाकखानों ने भी इस काम में योग दिया तथा पुराने मिक्को के स्थान पर नये मिक्को में डाक टिकट चलाये गये। इस प्रकार इस प्रणाली को शीघ्र प्रसारित करने में डाक एवं तार विभाग ने उत्तरेक्षणीय कार्य किया। रेल मंत्रालय द्वारा भी रेल-टिकटों पर भाड़े की दरे नये मिक्को में दी जाने लगी। और केवल ये दो विभाग ही ऐसे हैं जिनका सर्वसाधारण जनता से अत्यन्त घनिष्ठ सम्पर्क होता है। इस कारण निरक्षर जनता भी इस नवीन प्रणाली से भलीभाँति परिचित हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों ने भी इस दिशा में काफी कार्य किया।

हिसाब-किताब के लिए कार्टाटिंग मशीन-निर्माताओं से भारत सरकार ने तय किया है कि वे नई मशीनें हमारी नवीन सिक्का प्रणाली के अनुसार बनायें। क्योंकि इस समय ऐसी मशीना का भारत में बहुत कम प्रयोग होता है।

दाशमिक मुद्रा प्रणाली के लाभ

केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने इस प्रणाली को अपनाने में निम्न लाभों की ओर सकेन किया है —

- (१) सरल तथा शीघ्र हिसाब-किताब की पद्धति का निर्माण।
- (२) व्यय तथा मूल्य निर्धारण की सही और प्रभावी पद्धति।
- (३) घरेलू कार्यों एवं उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों के माप का सरल उपाय।
- (४) कीमतों के लघु परिवर्तनों का अधिक सही नाप सम्भव होगा, जिससे मुद्रा का व्यय उपयुक्तता में हो सकेगा।
- (५) शिक्षा-मन्थ्याओं में गणित के पठन-पाठन में समय एवं श्रम की बचत।
- (६) अनावश्यक तथा विविध मुद्रा इकाइयों का अन्त।

कठिनाइयाँ

इसी प्रकार इस नवीन मुद्रा प्रणाली से होने वाली कठिनाइयों का भी भारत सरकार ने अनुमान किया है, जो निम्न है —

(१) जटिलता—प्रारम्भिक अवस्था में जनता को अपनी परम्परागत मुद्रा प्रणाली को त्यागने एवं दाशमिक प्रणाली को अपनाने में कठिनाई होगी। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए प्रारम्भिक तीन वर्षों के लिए दोनों प्रणालियाँ एक साथ चालू रहेंगी जिससे जनता नई प्रणाली में भलीभाँति परिचित हो जाय।

(२) जनता से ठमी—नई और पुरानी प्रणाली साथ-साथ चालू रहने में चालाक और वेईमान लोग जनता में धोखा देही करेंगे। इसीलिए भारत सर-

कार ने जगह-जगह पर नई और पुरानी मुद्राओं की परिवर्तन तालिकाएँ प्रदर्शित की हैं। परन्तु फिर भी अन्तरिम-काल में अशिक्षित लोगों के ठगे जाने की सम्भावना है।

(३) कीमतों के आधार में परिवर्तन—नई प्रणाली का तत्कालीन परिणाम यह होगा कि वर्तमान कीमतों का एक दूरो का जो आधार है वह बदल जायगा। इससे जनता का असुविधा होगी। परन्तु यह असुविधा अल्पकालीन होगी क्योंकि अन्ततोगत्वा नई मुद्राएँ ही चलन में रहेंगी। ध्यान में रहे कि रुपये के आधारभूत मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

यद्यपि इस प्रणाली को अपनाने में आरम्भ में कुछ कठिनाइयाँ हुईं परन्तु अब यह प्रणाली जनता की समझ में आ गई है। इस प्रकार भारत आज विश्व के उन १०५ देशों में से एक है जहाँ पर दशमिक मुद्रा प्रणाली का चलन है। भारत ने इस वैज्ञानिक एवं अन्तरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को अपनाने में दूरदर्शिता में कार्य किया है तथा भावी विकास का द्वार खोल दिया है।

### सारांश

दशमिक मुद्रा प्रणाली अपनाने के प्रथम प्रयत्न १८७० में तथा १९४६ में हुए। परन्तु १९४५ में सफल हुए जबकि भारतीय संसद ने भारतीय दफ्तर अधिनियम १९४५ में पास हुआ। यह कानून १ अप्रैल १९५७ से लागू हो गया है। इसके अनुसार रुपये का विभाजन एवं मूल्य निम्नवत है—

१ रुपया = १०० न० पैसे

२ रुपया = ५० „

३ रुपया = २५ „

इसके सिवा १०, ५, २ और १ नये पैसे का सिक्का चलाया गया है। रुपया, अठ्ठी तथा चवथी निकेल की, १०, ५ और २ नये पैसे के सिक्के क्युप्रो-निकेल के तथा १ न० पैसे का सिक्का ब्रॉन्स का बना है। ३१ मार्च १९६० तक नये एव पुराने सिक्के साथ-साथ चलेंगे जिसके बाद केवल दशमिक सिक्के ही चलन में रहेंगे।

इससे हिमाचल में शीघ्रता एवं सरलता, मौद्रिक इकाइयों की विभिन्नता का अन्त, शिक्षा में भ्रम एवं समय की बचत, कीमतों का सही माप एवं निर्धारण में सुविधा होगी।

साथ ही अन्तरिम काल में परिवर्तन में जटिलता, कपट तथा कीमतों के आधार में परिवर्तन में कठिनाइयाँ प्रतीत होंगी।

फिर भी १ अप्रैल १९५७ से नये सिक्के चलन में आ गये हैं।

## द्वितीय भाग

## बैंक—विकास, परिभाषा एवं कार्य

### बैंको का विकास

बैंको का विकास बहुत पूर्वकाल से होन-होते वर्तमान स्तर पर पहुँचा है। बैंक की उत्पत्ति 'बैंको' (banco) से हुई जिसका अर्थ है—“बच के जाम-पास बैठना” अर्थात् सर्राफ या धनी लोग विभिन्न मुद्राओं का परिवर्तन बचा पर बैठकर किया करते थे, ऐसा अनुमान करना स्वाभाविक भी है। इस प्रकार सर्राफ विभिन्न मुद्राओं को बदलने का प्रमुख कार्य आरम्भ में करते थे जिसमें परदेस के यात्रियों तथा व्यापारियों को सुविधा होती थी। इनकी साख में जनता का विश्वास होने के कारण कुछ समय बाद अपने पास की अधिक मुद्राएँ सुरक्षा की दृष्टि से इन्हीं सर्राफों के पास धरोहर के रूप में रखने लग। इस रकम को जिन समय वे चाह अपने उपयोग के लिए वापस ले सकते थे। इस धरोहर के बदले सर्राफ उन्हें रसीद देते थे तथा आरम्भ में कुछ शुल्क भी लिया करते थे। साथ ही साथ ये सर्राफ अपने पाम का अनिश्चित घन ऋण के रूप में दूसरी को ब्याज पर देते थे। कुछ काल बीतने पर उन्हें यह अनुभव हुआ कि लोग जितना धन इनके पास धरोहर अथवा निक्षेप (deposit) के रूप में जमा करते थे, उसमें से बहुत ही कम वे निकालते थे और शेष सर्राफों के पाम बेकार पड़ा रहता था। यह देखकर क्रमशः उन्होंने इस अनिश्चित घन को भी ब्याज पर देना आरम्भ किया और निक्षेपों पर शुल्क लेना शब्द बर उल्टा ब्याज देना शुरू किया। इससे उनके पाम निक्षेप बढ़ने लगे। ब्याज देने की दर ब्याज लेने की दर से कम होती थी और इस प्रकार सर्राफ लाभ उठाते थे। यही से निक्षेप (deposit) बैंकिंग का आरम्भ हुआ।

जनता को निक्षेपों के बदले सर्राफ जो रसीद देते थे, वह उनकी साख के कारण क्रमशः उनके क्षेत्र में ऋण आदि व्यवहारों के भुगतान में स्वीकृत होने लगी। उनकी साख के कारण उनकी रसीद चल सकती है यह देखकर उन्होंने सोचा कि आगे किसी को ऋण देना हो तो मुद्रा में न देकर 'माँग भुगतान करने का वचन' (promise to pay the bearer on demand) बोलने पर

देना अधिक लाभप्रद होगा और ऐसे ही पत्र देना आरम्भ कर दिया। इन्हीं पत्रों से पत्र-मुद्रा का आरम्भ हुआ तथा पहली रसीदों में भुगतान करने की पद्धति से चैक पद्धति का आरम्भ हुआ।

इस व्यापार में अधिकाधिक नाम देखकर अनेक नय-नये व्यक्ति भी यह व्यापार करने लगे और क्रमशः बैंकिंग का विकास होता गया। आधुनिक बैंक निक्षेप स्वीकार करने हैं, तथा ऋण देते हैं। निक्षेपों की राशि जमा करने वाला व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय चैक द्वारा उसे निकाल सकता है। यही आधुनिक बैंकों का मुख्य कार्य है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के लिए आभूषण, स्वर्ण आदि रखना, पत्र-मुद्राएँ चलाना, साख का नियन्त्रण एवं नियमन करना तथा अपने ग्राहकों को मुद्रा-सम्बन्धी अनेक प्रकार की सुविधाएँ देना, ये कार्य भी बैंक करते हैं।

### भारतीय बैंकिंग का विकास एवं उत्क्रान्ति

भारत की जितनी भी वर्तमान वस्तुएँ हैं उनमें अधिकतर बातें हमने या तो अँग्रेजों से अथवा विदेशियों से अपनाई हैं। उसी प्रकार शायद यह भी सोचा जा सकता है कि आज जो अनेक बैंक भारत में हैं उनका उद्गम भी अँग्रेजी शासन का प्रतीक है। भारत में पहले बैंकिंग प्रणाली न हो, वास्तव में ऐसी बात नहीं है, हाँ बैंकिंग व्यापार के ढंग जरूर विदेशियों की देखा देखी अपनाये गये हैं और वे हैं भी उपयोगी।

मगर अनेक क्षतादियों से भारत में किसी न किसी रूप में बैंकिंग रहा है, इसके अनेक प्रमाण हैं। उदाहरण के लिए चार्वाक का 'ऋण कृत्वाष्टु पिवेत्'—यह श्लोकाङ्क स्पष्ट बतलाता है कि भारत में ऋण दिये जाते थे। इसी प्रकार छूतनीडा के समय ऋण का आदान-प्रदान होता था, इसके उदाहरण भी महाभारतादि में उपलब्ध हैं। बारहवीं शताब्दी में जैनो द्वारा बैंकिंग का कार्य किया जाता था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आवू पर्वत पर स्थित और ११६७-१२४७ ई० के बीच बनवाया हुआ दिनवारा देवालय है। तेरहवीं शताब्दी में द्वेबनियर नामक फ्रांसीसी यात्री भारत के विषय में लिखता है कि बहुधा प्रत्येक देहात में एक मुद्रा-परिचलनकर्ता रहता था, जिसे सर्राफ कहते थे और ये सर्राफ बैंकों का कार्य भी करते थे अर्थात् मुद्राओं का स्थानान्तरण, बिल देना इत्यादि। ये लोग ज्यू जाति से—जो इसी काल में बैंकिंग का कुछ कार्य करते थे—भी बड़े-बड़े थे। बैंकिंग की पर्याप्त विकास मनुस्मृति से पहले भी हो चुका था, ऐसा स्पष्ट है। क्योंकि मनुस्मृति में स्मृतिकार 'रहन् तथा निक्षेप' के विषय

पर लिखता है, "एक भुज व्यक्ति को अपना धन ऐसे व्यक्ति के पास निक्षेप रखना चाहिए जो कुलीन, सन्चरित, विधान का जानन वाला, माननीय एवं धनी हो।" कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वैकिंग पद्धति का उल्लेख मिलता है किन्तु उस काल में बैंकों के कार्य निक्षेप को लेने एवं ऋण देने तक ही सीमित थे। हर्षिण्या के चलन का उल्लेख भी बहुत प्राचीन काल से हमारे साहित्य में मिलता है, फिर भी अंग्रेजी पद्धति पर बैंकिंग-संगठन का विकास अंग्रेजों के आगमन के बाद ही हुआ।

### बैंक की परिभाषा

हमने देखा कि आधुनिक बैंक निक्षेप स्वीकार करता है, दूसरों से ऋण लेता है तथा दूसरों को ऋण देता है। साथ ही अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ देते हैं—जैसे उनके आभूषण आदि की सुरक्षा, बैंकों का संग्रहण (collection), बॉन्ड की किश्त भेजना, गुप्त रूप से किसी भी ग्राहक के आर्थिक स्थिति की जानकारी लेना, देना आदि। इन विविध प्रकार के कार्यों को करने वाली संस्था अर्थात् बैंक की ठीक-ठीक परिभाषा करना एक कठिन तथा महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि भिन्न-भिन्न लेखकों ने बैंक की भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ दी हैं।

बैंक शब्द का अर्थ—'अपने ग्राहकों ने अथवा ग्राहकों द्वारा प्राप्त मुद्राभा की सुरक्षा करने वाली संस्था'। इसका महत्वपूर्ण कार्य उसके ऊपर लिखे गए ड्राफ्ट (drafts) का भुगतान करना उनका जो पैसा निरूपयामी रह जाता है, उसके उपयोग से उस लाभ होता है।<sup>1</sup> इस अर्थ से हम केवल यह समझते हैं कि बैंक निक्षेप स्वीकार करता है जिनका भुगतान उन्हें ग्राहकों से ड्राफ्ट द्वारा माँग होने पर करना पड़ता है। १७७२ तक बैंक की कोई भी वैधानिक परिभाषा नहीं थी। इंग्लैंड के विनिमय पत्र विधान १८८२ (Bills of Exchange Act, 1882), में सबसे पहले बैंक की परिभाषा की गई जिसके अनुसार "बैंकर के अन्तर्गत कोई भी व्यक्तियों का समूह जो वैकिंग व्यापार करता है—फिर चाहे संगामित (incorporated) हो अथवा नहीं—आता है"। लेकिन इस परिभाषा में न तो इसका उल्लेख है और न ही स्पष्टीकरण है कि बैंकिंग क्या है अथवा बैंकिंग-व्यापार किस कहा जा सकता है। अतः यह परिभाषा ठीक नहीं कही जा सकती।

समुक्त राष्ट्र में बैंक शब्द का प्रयोग निश्चित रूप में किया जाता है,

<sup>1</sup> A Shorter Oxford English Dictionary

<sup>2</sup> The Bills of Exchange Act, 1882

जिसके अन्तर्गत उन सब कार्यों का समावेश होता है जिन्हें वह सामान्यतः करत है। संयुक्त राष्ट्र का परिभाषा के अनुसार कोई भी संस्था जो साख का व्यवहार करता है वह है। साख क्या है इसका स्पष्टीकरण उनका विधान में किया गया है वह एक अतर्गत प्रत्येक व्यक्ति फर्म एवं कम्पनी का समावेश होता है जहाँ निम्न अथवा मुद्रा संग्रहण द्वारा साख खोली जाती है एवं जिसका भुगतान डाफ्ट चक अथवा आदेश द्वारा होता है अथवा माल आदि की जमानत पर मुद्राएं अथवा ऋण दिए जाते हैं तथा जिसका व्यापारिक स्थान होता है।<sup>१</sup>

इस परिभाषा में बैंकों के प्रमुख कार्य स्पष्ट होते हैं—(१) उन्हें निक्षेप स्वीकृत करना चाहिए जिसका चक आदि द्वारा माग पर भुगतान हो। (२) उसका साख में व्यवहार होना चाहिए। किन्तु इस परिभाषा में जब तक साख क्या है? इसका स्पष्टीकरण नहीं होता तब बैंकों के कार्यों का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। बैंक की परिभाषा डा० हाट ने इस प्रकार की है बैंक वह है जो अपने सामान्य व्यवहार में उस पर लिखे हुए उन चकों का भुगतान करता है जिनके द्वारा वह चल-सखा (current account) पर मुद्राएं (धन) प्राप्त करता है। यह परिभाषा भी अपूर्ण है क्योंकि बैंक केवल उन्हीं लोगों के बैंकों का भुगतान नहीं करता जिनके कदल चल निक्षेप (current deposits) उनके पास हैं बल्कि इसमें अतिरिक्त अनेक कार्य करता है जिनका समावेश इसमें नहीं होता। फिर भी जहाँ तक बैंक के मुख्य कार्य का सम्बन्ध है—निक्षेप स्वीकार करना एवं उनका माग पर भुगतान करना उनका समावेश इस परिभाषा में होता है। इसलिए यह परिभाषा कोई भी वैधानिक आधार नहीं होती हुए भी संतुष्ट है। क्योंकि मर जान पगट के अनुसार कोई व्यक्ति अथवा संस्था चाहे वह सामान्य हो अथवा नहीं बैंक नहीं कही जा सकता जो निक्षेप-लेख स्वीकार नहीं करती जो चल लेख नहीं सता और अपने ग्राहकों के बैंकों का भुगतान एवं संग्रहण नहीं करती चाहे वे रेखांकित (crossed) हो या अनारेखांकित (uncrossed) हों। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कोई भी संस्था जब तक कि जनता में निक्षेप स्वीकार न करे एवं उनका भुगतान चक डाफ्ट जपटा आदेश द्वारा न करे तब तक उसे बैंक नहीं कहा जा सकता। जहाँ तक ऋण देने का सम्बन्ध है कोई भी व्यक्ति एवं संस्था अथवा बिना कदलाल अथवा ऋण दाता यह कार्य करने है। इसलिए निक्षेपों का स्वीकार

करना एवं उनका चँको अथवा अन्य प्रकार से भुगतान करना, यह बैंक का प्रमुख कार्य है।

इसी महत्वपूर्ण कार्य को देखकर भारतीय कम्पनी अधिनियम, १९३६ में बैंक की परिभाषा की गई है। इस विधान के अनुसार 'बैंकिंग कम्पनी वह है जिसका प्रमुख व्यापार चल अथवा अन्य लेखों पर पण्ड निक्षेपों का स्वीकार करना है जो चँक, ड्राफ्ट अथवा आदेश द्वारा निकाल जा सकें।' इसमें यह भी उल्लेख है कि इस परिभाषा के लिए उसके अन्य कार्यों का किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है, जो बैंक अपने दैनिक व्यवहारों में करते हैं। इस परिभाषा के अनुसार हम उन मस्याओं को बैंक नहीं कह सकते जो 'बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग कम्पनी' आदि शब्दों का उपयोग अपने नाम के साथ करती हो और इस विधान के पास होने के पूर्व कार्य कर रही थी। ऐसी मस्याओं द्वारा अपन लिए बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग कम्पनी शब्दों के प्रयोग करने पर बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, १९४९ के अनुसार सजा लगा दी गई है। इस नए विधान में बैंक की परिभाषा भी पुन बनाई गई है जिसमें ऐसी मस्याएँ जो समय पर भुगतान होने वाले निक्षेप न लेती हों, अपने नाम के साथ 'बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग कम्पनी' आदि शब्दों का उपयोग नहीं कर सकती। इस परिभाषा के अनुसार 'सृष्टि देने अथवा विनियोग के लिए जनता से मुद्रा निक्षेप की स्वीकृति करना जो माँग पर अथवा अन्य प्रकार में वापिस ली जा सके, तथा चँक, ड्राफ्ट, आदेश अथवा अन्य प्रकार से निकाली जा सके।' 'यह बैंकिंग की परिभाषा की गई, और केवल इन कार्यों को करने वाली मस्या ही 'बैंक', 'बैंकर' तथा 'बैंकिंग कम्पनी' शब्दों का प्रयोग अपने नाम के साथ कर सकती है।

इन परिभाषाओं में निम्न कार्य करने वाली मस्या को ही बैंक कह सकते हैं —

जनता में निक्षेपों की स्वीकृति कर जिसका भुगतान बैंक, ड्राफ्ट अथवा आदेश द्वारा किया जाय। अर्थात् काष्ठ भी मस्या निक्षेपों की स्वीकृति करते हुए भी अगर उनका भुगतान चँक आदि में न करे तो वह बैंक नहीं है। इसी प्रकार कोई भी मस्या जो निक्षेप स्वीकार नहीं करती सिन्तु बैंक आदि द्वारा

<sup>1</sup> 'Banking' has been defined as "the accepting for the purpose of lending or investment, of deposits of money from the public repayable on demand or otherwise, and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise" (*Indian Banking Companies Act, 1949*)

पैसे देती है तो वह भी बैंक नहीं है। इस प्रकार निक्षेपों की स्वीकृति एवं बैंक आदि-द्वारा उनका भुगतान बैंक का प्रमुख कार्य है। इस कार्य के साथ बैंक मुद्रा एवं साख सम्बन्धी अन्य व्यवहार करने में पूर्ण स्वतन्त्र है। परन्तु बैंकों पर ऐसे कुछ कार्यों के सम्बन्ध में, जो बैंकिंग व्यवसाय की दृष्टि से खतरनाक हैं, उनके करने पर रोक लगा दी गई है।

### बैंकों का वर्गीकरण

वर्तमान आर्थिक विश्व में बैंक भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और उन कार्यों के अनुसार उनका वर्गीकरण भी किया गया है। इन बैंकों में से कुछ बैंक किन्हीं विशेष प्रकार के कार्य करते हैं तथा कुछ सामान्य काम करते हैं, जैसे वैयक्तिक बैंक अथवा बैंकिंग फर्म जो सामान्य बैंकिंग अर्थात् निक्षेप लेना, ऋण देना आदि कार्य करते हैं। इसके विपरीत कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो विशेष प्रकार के ही कार्य करते हैं जैसे औद्योगिक बैंक, विनिमय बैंक आदि। विशेष क्रियाओं के अनुसार निम्न प्रकार के बैंक पाये जाते हैं —

(१) औद्योगिक बैंक—य बैंक उद्योगों का औद्योगिक विस्तार तथा स्थायी सम्पत्ति खरीदने के लिए दीर्घकालीन ऋण देते हैं। इसीलिए ये दीर्घकालीन अवधि के निक्षेप भी स्वीकार करते हैं। उद्योगों द्वारा चालू किये गये अग्रे एवं ऋणपत्रों का अभिग्राहण (underwriting) भी ये बैंक करते हैं। भारत में 'दी वनारा बैंकिंग एण्ड इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन, उदीपी' यह कार्य करता है। इसके अतिरिक्त १९४७ में इण्डस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन की स्थापना भी इसी उद्देश्य से की गई है।

(२) विनियोग बैंक—विनियोग बैंकों का उद्देश्य नई-नई कंपनियों के असा एवं ऋणपत्र खरीदकर उनकी योजनाओं में आर्थिक सहायता देना होता है। भारत में इस कार्य के लिए इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई है।

(३) कृषि-बैंक—कृषि बैंक कृषि कार्यों के लिए तथा भूमि के स्थायी सुधार के लिए दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन ऋण देते हैं। भारत में ग्रीन बैंकों को कृषि बैंक कहा जा सकता है।

(४) विनिमय बैंक—ये विदेशी व्यापार के लिए आर्थिक सुविधाएँ देते हैं तथा अन्तरराष्ट्रीय भुगतान को सुलभ बनाते हैं। इससे देश के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का विकास होता है। यह कार्य व्यापारिक बैंक नहीं कर सकते क्योंकि विनिमय दरा के उतार-चढ़ाव का सदैव खतरा बना रहता है। अतः इस कार्य

को ऐसे ही बैंक कर सकने हैं जिनका जनरराष्ट्रीय बैंकिंग क्षेत्र में घनिष्ट सम्पर्क हो तथा विनिमय-दरों के परिवर्तनों का विशेष अनुभव एवं ज्ञान हो।

(१) भू-रहन बैंक—ये कृषि भूमि की रहन पर स्थायी कृषि सुधारों के लिए तथा कृषकों के पुराने ऋणों के मुगनान के लिए दीर्घकालीन ऋण देते हैं।

(६) सहकारी बैंक—य सहकारिता मिद्धान्न जववा परम्पर महायता देने के मिद्धान्न पर निर्मित हुए हैं तथा जनता में वचन की आदत डालने में उपयोगी मिद्द हुए हैं। भारत में इनका प्रसार पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास में विशेष उल्लेखनीय है। ये कृषि, घरलू-उद्योग आदि का अल्पकालीन एवं मध्यकालीन अवधि के ऋण देते हैं।

(७) देशी (Irredeemable) बैंकर—य आन्तरिक व्यापारिक आवश्यकताओं तथा कृषि आवश्यकताओं के लिए ऋण देते हैं। इनका प्रसार भारत के देशों में बहुत अधिक है। विनोपत कृषक अपनी-अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए इन्हीं पर निर्भर हैं।

(८) वचत बैंक—ये बैंक छोटी आय वाले व्यक्तियों में वचत की आदत डालने के लिए छोटी-छोटी रकम निक्षेप के लिए स्वीकार करते हैं तथा उनकी सुरक्षा करते हैं, जैसे भारत में डाकघर वचत बैंक।

(९) केन्द्रीय बैंक—यह देश का प्रमुख बैंक होता है। यह देश के अन्य बैंकों का बैंकर, सरकार का जादतिया, मुद्रा एवं मास का चलन एवं नियन्त्रण कर देश की मुद्रा का आन्तरिक एवं बाह्य मूल्य स्थिर रखता है। देश की बैंकिंग व्यवस्था के नियन्त्रण एवं सुदृढ़ विकास की जिम्मेदारी भी इसी बैंक पर होती है जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (१९२५)।

(१०) व्यापारिक बैंक—देश की बैंकिंग व्यवस्था में इनका स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है और सभी देशों में इस वर्ग के बैंक अधिक होते हैं। ये देश के व्यापारी वर्ग को अल्पकालीन आर्थिक सुविधाएँ तथा रकमों का स्थानान्तरण, भुगतान, सुरक्षा आदि की सुविधाएँ देते हैं। अतः देश के आन्तरिक व्यापार के विकास के लिए ये बैंक आधारभूतता का कार्य करती हैं। इनमें से पाँच बड़े बैंक निम्नलिखित हैं —

(१) नेट्रल बैंक ऑफ इण्डिया लि०, (२) बैंक ऑफ बडोदा लि०, (३) पंजाब नेशनल बैंक लि०, (४) इलाहाबाद बैंक लि०, तथा (५) बैंक ऑफ इण्डिया लि०।

## बैंको के कार्य एवं सेवाएँ

हम यह बता चुके हैं कि देश में अधिकांश व्यापारिक बैंक होते हैं और ये महत्वपूर्ण भी हैं क्योंकि इन्हीं से देश के व्यापार एवं उद्योग को चल-पूँजी प्राप्त होती है। अतः जब भी 'बैंक' शब्द का प्रयोग होता है तब वह 'व्यापारिक बैंक' के अर्थ में ही किया जाता है। व्यापारिक बैंक निम्न कार्य करते हैं —

(१) जनता में निक्षेप अथवा जमा-राशि स्वीकार करना अथवा अन्य किन्हीं स्रोतों से ऋण देना-लेना, जैसे अग्रा पूँजी या ऋणपत्रों के प्रचलन से।

(२) ग्राहकों के एजेंट का कार्य करना।

(३) सामान्य उपयुक्त सेवाएँ।

(१) ऋण लेना तथा ऋण देना—यह बैंको का प्रमुख कार्य है। ऋण लेने का कार्य बैंक दो मार्गों से करता है, एक तो अग्रा पूँजी (share capital) द्वारा, तथा दूसरे निक्षेप की स्वीकृति द्वारा। निक्षेप तीन प्रकार के होते हैं— (१) वचत निक्षेप (deposits), (२) स्थायी निक्षेप (fixed deposits), तथा (३) चल निक्षेप (current deposits)। इन तीन प्रकार के निक्षेपों में से चल-निक्षेपों को अमेरिका में माग देनदारी तथा वचत (संचय) एवं स्थायी निक्षेपों को समय देनदारी (time liabilities) कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग आजकल इसी अर्थ में किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक बैंक दूसरी बैंक से ऋण लेकर भी रकम खड़ी कर सकता है।

ऋण देने का कार्य भी महत्वपूर्ण है। बैंक तीन प्रकार से ऋण देते हैं— (१) ऋण लेने वाले की वैयक्तिक जमानत पर, (२) ऋण लेने वाले की वैयक्तिक जमानत के अतिरिक्त दो अन्य व्यक्तियों की जमानत पर, तथा (३) प्रतिभूतियाँ, अग्रा, स्कन्ध आदि के रहन पर। इसके अतिरिक्त बैंक अपने विशेष ग्राहकों को रोक-ऋण (cash credit), ओवर ड्राफ्ट (overdraft) की सुविधाएँ भी देते हैं तथा विनिमय बिलों के बट्टे की सुविधाओं द्वारा व्यापारियों को ऋण लेना सुलभ करते हैं। इस प्रकार बैंको के मुख्य निम्न कार्य हैं —

(अ) निक्षेपों की स्वीकृति,

(आ) ऋण देना,

(इ) विनिमय बिलों का अपहरण (discounting) तथा

(ई) पत्र मुद्रा चलाना (आजकल यह अधिकार केवल केन्द्रीय बैंक को ही होता है)।

(२) एजेंसी कार्य—एजेंट का कार्य करते समय बैंक को ग्राहकों की लिखित

अनुमति प्राप्त होनी चाहिए, तभी वह कार्य कर सकता है, क्योंकि उसके द्वारा एजेंट के रूप में किये हुए कार्य ग्राहक को वाध्य होकर स्वीकार करने पड़ते हैं। एजेंसी-कार्य निम्न है—

(अ) बैंकों का संग्रह एवं भुगतान करना—ग्राहक जो बैंक उसके लेने के विरुद्ध बैंक पर लिखे, उनका भुगतान करना। उममें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, इसकी सावधानी रखना तथा ग्राहक को, जो दूसरा से बैंक मिलते हैं, उनको सम्बन्धित बैंकों में भुनवाना।

(आ) बिल प्रतिज्ञा-पत्र, साभास आदि संग्रह करना—बैंक के ग्राहकों को जो बिल, प्रतिज्ञा-पत्र, साभास आदि अन्य व्यक्तियों, फर्मों या कम्पनियों से लेने होते हैं, उनका रूपया ग्राहक की ओर में सम्बन्धित बैंकों अथवा कम्पनियों से लेना।

(इ) बीमे की वित्तो आदि का भुगतान—ग्राहक की ओर में जो बीमे की वित्तो आदि नियमिन रूप से देनी पड़ती है, उनका भुगतान ग्राहक की ओर से करना।

(ई) ट्रस्टी—एक्सीक्यूशनर (executioner), व्यवस्थापक आदि कार्यों को करने के लिए ग्राहक की जगह प्रतिनिधित्व करना।

(उ) प्रतिभूतियों का प्रय-विक्रय—ग्राहक की ओर में उसके लिए भद्र, निक्वोरिटी आदि का प्रय-विनय करना तथा ग्राहक की ओर में इस सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करना।

(१) सामान्य सेवाएँ—उक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंक ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ देता है। इन सेवाओं में आकर्षित होकर उसकी ग्राहक-संख्या तथा निक्षेप (deposit) में वृद्धि होती है। य मतिमाएँ निम्न हैं -

(अ) मुद्रा का स्थानान्तरण—डाक अथवा अन्य मार्गों से रकम भेजने की अपेक्षा बैंकों द्वारा एक शहर से दूसरे शहर को पैसा भेजने में कम खर्च होता है। अतः इस प्रकार की सुविधाएँ बैंक अपन ग्राहकों को देते हैं। 'उदाहरणार्थ' मुझे २००) रुपये वम्बई भेजने की आवश्यकता है और मेरा ग्वाना मेट्रल बैंक में है। इस दशा में अगर मैं २००) ५० पनीआर्डर या बीमा-डाक में भेजता हूँ तो मेरा खर्च ३ ५० तथा १=) लगेंगे। यही अगर मैं मेट्रल बैंक द्वारा भेजता हूँ तो मेट्रल बैंक मुझे उस व्यक्ति के नाम एक ड्राफ्ट अपनी वम्बई स्थित शाखा पर देगा और इसके बदले मुझे केवल १० नये पैसे कमीशन लेगा। इस प्रकार मे रूपया भेजकर मैं खर्च में बचत कर सकता हूँ।

(आ) साख पत्र, परिपत्र आदि देना—बैंकों की विभिन्न स्थानों पर शाखाएँ तथा एजेंट होने के कारण वे अपने विधेय ग्राहकों को रकम प्राप्त करने के लिए साख-पत्र आदि देते हैं, जिसके आधार पर वे किसी भी स्थान पर आवश्यक रकम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार परिपत्र भी दिय जाते हैं। बैंक इस कार्य के लिए कमीशन लेते हैं। इस मुविधा में ग्राहक को अपने पास अधिक रकमा रखने की आवश्यकता नहीं होती।

(इ) विदेशी विनिमय प्राप्त करने की सुविधाएँ—विनिमय बैंक की शाखाएँ ऐसे देशों में अविकाशित होती हैं जहाँ वा व्यापारिक सम्बन्ध उस देश से घनिष्ठ होता है। इस कारण वे ग्राहकों को विदेशी विनिमय की सुविधाएँ भी देते हैं।

(ई) जवाहरात, स्वर्ण आदि की सुरक्षा—बैंक अपने यहाँ ग्राहकों के गहने, आभूषण मूल्यवान् वागज आदि रखने की सुविधा देते हैं जिससे चोरी आदि से उनकी रक्षा हो सके। ये सेवाएँ कई बैंक निशुल्क करते हैं तथा कुछ इन सेवाओं के बदले ग्राहक में शुल्क लेते हैं। सर जॉन पिंगट के अनुसार बैंक को ये सेवाएँ निशुल्क देनी चाहिए। भारत में ऐसी सभी सुविधाओं के लिए बैंक कमीशन लेते हैं।

(उ) बिलों की स्वीकृति—बैंक अपने ग्राहकों पर लिखे हुए बिलों की स्वीकार करते हैं, जिनके लिए वे कमीशन लेते हैं। ऐसे बिल केवल कुछ माननीय एवं विश्वसनीय ग्राहकों की ओर से ही बैंक स्वीकार करता है जिससे आहर्ता (drawer) को उन बिलों के बारे में पूर्ण विश्वास हो जाता है। यह प्रथा हमारे देश में प्रचलित नहीं है किन्तु विदेशों में इस प्रथा का पर्याप्त प्रचार है जहाँ इस कार्य के लिए विधेय मस्याएँ 'स्वीकृति-गृह' नाम से हैं।

(ऊ) आर्थिक परिस्थिति की जानकारी देना—बैंक अपने ग्राहकों को उनके भावी ग्राहकों की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी जानकारी प्राप्त कर उनकी सूचना देते हैं। अर्थात् जिनसे उनके ग्राहक व्यवहार करना चाहते हैं उनकी वास्तविक स्थिति कैसी है उनको साख दी जाय उसकी सीमा क्या हो आदि बतलाते हैं। इसमें उनके ग्राहकों को बड़ी सुविधा होती है।

बैंकों की उपयोगिता

इस विवेचन से बैंकों के कार्य तथा सेवाओं का महत्व स्पष्ट हो जाता है। "बैंक साख पत्रों का चलन नियन्त्रित एवं संगठित करते हैं वे अग्रिम एवं ऋण के रूप में बैंक निर्मित साख का नियमन करते हैं। ऋणदा पूंजी (Loanable Capital) को गति देते हैं तथा उसका वितरण एवं सदुपयोग सम्भव करते

है। वे चलन की जड़ और जहाँ आवश्यकता होनी है वहाँ राशि स्थानान्तरण द्वारा नियोजित करते हैं तथा अधिक चलन के क्षेत्रों में शुभ क्षेत्रों में मुद्रा-चलन का स्थानान्तरण करते हैं।<sup>1</sup>

संक्षेप में बैंकों की निम्न उपयोगिताएँ हैं —

(१) देश के विखरे हुए एवं निष्क्रिय धन को बैंक एकत्र करके उसे देश के औद्योगिक एवं व्यापारिक कार्यों में लगाने हैं।

(२) मरुता के माधमों को प्रोत्साहित कर जनता में वचन की भावना का निर्माण करते हैं। इससे देश में पूँजी-निर्माण का प्रोत्साहन मिलता है।

(३) बैंक एजेंटों एवं अन्य सेवाओं द्वारा व्यापारिकों के समय की वचन करती हैं। उनके मूल्यवान् आभूषण महत्वपूर्ण बागजों आदि की सुरक्षा द्वारा उनकी जर्जरता रोक करती हैं।

(४) ग्राहकों में ईमानदारी नियमितता तथा विश्वसनीयता का निर्माण पर उनकी मास बढ़ाना है।

(५) जिनके पास अधिक धन है परन्तु जो विनियोग नहीं कर सकते तथा जिनको धन या ऋण की आवश्यकता है, इन दोनों में मध्यस्थ का कार्य बैंक करते हैं।

(६) बैंकों से सुविधा एवं उम्र-याज पर ऋण मिलने के कारण देश का व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास होता है।

(७) बैंक अपनी मौलिक सेवाओं द्वारा समाज में मुद्रा की आवश्यकता कम करते हैं तथा सावधानी के उपयोग को प्रोत्साहन देते हैं। इससे धन, समय एवं श्रम की वचन होती है।

(८) बैंक राजकीय अर्थ प्रवर्धन में भी सहायक होती हैं। क्योंकि सरकारी ऋणों का निगमन बैंकों के माध्यम से ही किया जाता है।

इन लाभों के कारण ही मुनगठित एवं गुमनामित बैंकिंग पद्धति प्रत्येक देश में आवश्यक है। इसीलिए समुचित एवं मनुजित आर्थिक विकास के हितों को आर्थिक प्रणाली में बैंकों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

### सारांश

बैंक शब्द की उत्पत्ति 'बैंको' शब्द से हुई, जिसका अर्थ है बैंक के आसपास बैठना। सर्राफ लोग बैंक के आसपास बैठकर मुद्राओं का विनिमय करते थे। इनकी साज के कारण जनता इनके पास धन भी जमा करने लगी,

<sup>1</sup> *Principles of Banking* by S. E. Thomas

जिनके बदले ये रसीद देने थे तथा उनसे शुल्क लेते थे। ये ऋण भी देते थे। आगे चमकर जनता की धरोहरें आकर्षित करने के लिए ये जनता की जमा रकमों पर ब्याज देने लगे। ब्याज देने की दर ब्याज लेने की दर से कम होनी थी। यहाँ से निक्षेप बैंकिंग का आरम्भ हुआ।

कमरा सर्राफों की रसीदें उनकी सारा के कारण इनके क्षेत्र में ऋणों के प्रचारा अन्य भुगतानों में स्वीकृत होने लगे। इसीसे आगे बैंक पद्धति का आरम्भ हुआ।

भारत में बैंकिंग प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल में विकसित थी जिनके प्रमाण प्राचीन ग्रन्थों में हैं। परन्तु आधुनिक पद्धति पर बैंकिंग का विस्तार अंग्रेजों के आगमन के बाद ही हुआ।

परिभाषा—बैंकों की अनेक परिभाषायें हैं। भारतीय बैंकिंग अधिनियम, १९४६ के अनुसार 'बैंक का बैंकिंग कम्पनी कहूँ है जो उधार देने या विनिमयों के लिए जनता में निक्षेप स्वीकार करे जो माँग पर या अन्य किसी प्रकार से तथा बैंक, ड्राफ्ट या आदेश पर देय हो'। इस परिभाषा से बैंक निम्न कार्य करती है यह स्पष्ट होता है —

ऋण देना, विनिमय करना, जनता में निक्षेप स्वीकार करना जो माँग पर देय हों।

आधुनिक काल में बैंकों की क्रियाओं के अनुसार बैंकों का वर्गीकरण किया गया है जो निम्न है —

- १ औद्योगिक बैंक—उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देना।
- २ विनिमय बैंक—ये नये नये औद्योगिक कम्पनियों के अशों एवं ऋण-पत्रों की रसीद द्वारा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देते हैं।
- ३ कृषि बैंक—कृषि के स्थायी मुधार के लिए दीर्घ कालीन ऋण देने हैं।
- ४ विनिमय बैंक—विदेशी व्यापार को आर्थिक सुविधायें देते हैं।
- ५ भूमि बचक बैंक—कृषि भूमि की रहन पर कृषि के स्थायी मुधारों के लिए ऋण देते हैं।
- ६ सहकारी बैंक—परस्पर सहायता मित्रान्त के आधार पर सदस्यों में वचन की आधन निर्माण करना एवं उन्हें आर्थिक सुविधायें देना इसका उद्देश्य है।
- ७ दानी बैंक—आन्तरिक व्यापारिक आवश्यकताओं के लिए आर्थिक सुविधायें देने हैं। भारत में ही पाये जाते हैं।

- ८ वचत बैंक—ये जनता से वचत की आदत डालने के लिए छोटी रकमों की जमा स्वीकार करते हैं ।
- ९ केन्द्रीय बैंक—ये देश का प्रमुख बैंक होने के साथ ही सरकार एवं बैंकों का बँकर होता है ।
- १० व्यापारिक बैंक—देश के आन्तरिक व्यापार को अल्पकालीन आर्थिक सुविधाएँ देते हैं । साधारणतः इसी प्रकार के बैंक अधिक सख्या में हैं ।

बैंक के कार्य एवं सेवाएँ—१ जनता से जमा-राशि स्वीकार करना, २ ऋणों का लेन-देन, ३ बिजो का अपहरण करना, ४ पत्र मुद्रा चलाना, ५ ग्राहकों के एजेंट का कार्य करना, तथा ६ सामान्य उपयुक्त सेवाएँ देना ।

बैंक की उपयोगिता—१ देश के बिजरे धन को एकत्रित कर व्यापार एवं उद्योगों में विनियोजित करना,

२ जनता से वचत की आदत डालना,

३ पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन देना,

४ व्यापारियों आदि की समय की वचत एवं सुरक्षा साधनों में जोखिम कम करना,

५ ग्राहकों की सख्त बढ़ाना,

६ धन एवं साहस को सम्बन्धित करना,

७ व्यापार एवं उद्योग के विकास को प्रोत्साहन,

८ मुद्रा की आवश्यकता कम कर साख्त साधनों को प्रोत्साहन देना,

९ राजकीय अर्थ-प्रबन्धन में सहायक होना ।

## अध्याय २

# बैंकिंग का स्वरूप

बैंक के कार्यों में बैंकों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं—(१) विनियोग (investment) बैंकिंग तथा (२) व्यापारिक बैंकिंग। विनियोग बैंक विशेषतः उत्पादन कार्य के लिए दीर्घकालीन ऋण देते हैं तथा उनके निक्षेप भी दीर्घकालीन होते हैं। इसके विपरीत व्यापारिक बैंक उत्पादन कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण देते हैं तथा उनके निक्षेप (deposits) भी अल्पकालीन होते हैं।

इस दृष्टि से व्यापारिक बैंकिंग का स्वरूप देखने से यह स्पष्ट होगा कि किसी भी बैंक में जनता का विश्वास होना आवश्यक है। इस विश्वास के साथ ही बैंक को लाभ भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वह लाभ नहीं कमाता तो उसको शीघ्र ही अपने दरवाजे बन्द करने पड़ेंगे। अतः विश्वास को कायम रखने के लिए बैंक का लाभ की अपेक्षा सेवाओं की तत्परता पर अधिक ध्यान होता है। इस दृष्टि से अन्य व्यापारों की अपेक्षा बैंकिय व्यापार में अधिक सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि जनता का विश्वास डगमगाते ही निक्षेप निकालना आरम्भ हो जाता है और ऐसी अवस्था में सुव्यवस्थित एवं सुमचालित बैंकों को भी अपने दरवाजे बन्द करने पड़ते हैं। जनता में वृद्धि की आदत डालने के साथ ही ईमानदारी, विश्वास एवं नैतिक स्तर के निर्माण की ओर बैंक को अधिक ध्यान देना पड़ता है। इस दृष्टि से निक्षेप के रूप में लिया हुआ ऋण अच्छे प्रकार से विनियोग में लगाना उसका पहला ध्येय होना चाहिए। अतः लाभ की अपेक्षा वित्त की सुरक्षा का ध्यान रखना तथा सेवाएँ देना बैंकिंग का पहला मूलसिद्धान्त है।

धन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अल्पकालीन ऋणों की अपेक्षा दीर्घकालीन ऋण देना अपने व्यापार को खतरे में डालने का चिह्न है। अतः बैंक को सर्वत्र इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके विनियोग एवं ऋण ऐसे हों जो किसी भी समय मुद्रा में परिवर्तित हो सकें। इस दृष्टि से अपने देय (liabilities) को ध्यान में रखते हुए उसे अपने विनियोग एवं सम्पत्ति में तरन्तता रखनी आवश्यक होती है।

इस व्यापार में यशस्वी होने के लिए बैंक-व्यवस्थापक एवं संचालकों को अच्छा ज्ञान, अनुभव एवं न्याय की दृष्टि होनी चाहिए, जिससे वे जनता के विश्वास को सम्पादन करने में साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत रख सकें। इसी दृष्टि में बैंकों को अधिक लाभ कमाने की अपेक्षा अधिक सेवा देने की दृष्टि तथा अपने वित्त की सुरक्षा को सदैव ध्यान में रखना पड़ता है।

भारत में बैंक का व्यापार जनता के विश्वास पर निर्भर रहता है, इसलिए उसे अपनी व्यापार की स्याति बनाये रखने के लिए नीम सिद्धान्तों पर काम करना पड़ता है —

- (१) लाभ की अपेक्षा जनता को अधिकाधिक सेवाएँ देना।
- (२) सम्पत्ति की तरसता।
- (३) आर्थिक स्थिति मजबूत रखने के लिए निधि की समुचित व्यवस्था एवं सुरक्षा।

### एकक बैंकिंग तथा शाख बैंकिंग

बैंकिंग के भिन्न प्रकारों में स्पष्ट है कि इस व्यापार में भी भ्रम-विभाजन पूर्ण रूप में है। किन्तु आजकल बैंकिंग व्यापार में केन्द्रीकरण की अधिक प्रवृत्ति बढ़ गई है। अर्थात् बैंक केवल एक प्रमुख कार्यालय रखने हुए अपनी शाखाएँ विभिन्न स्थानों में रखते हैं जिसमें व्यवस्था का केन्द्रीकरण होने के साथ ही व्यवस्था-व्यय कम तथा कार्य-क्षमता की वृद्धि होती है। आजकल बैंकिंग नीति का निर्धारण विशेषतः केन्द्रीय बैंक करते हैं जिसमें देश के अन्य बैंक भी प्रभावित होते हैं क्योंकि केन्द्रीय बैंक, बैंकों का बँकर होने के नाते, देश के अन्य बैंकों को उसकी नीति का पालन करना पड़ता है। इस प्रकार निम्न में बैंकिंग के दो प्रकार देखने को मिलते हैं —

- (१) एकक बैंकिंग (Unit Banking), और
- (२) शाख बैंकिंग (Branch Banking)।

एकक बैंकिंग का प्रचलन संयुक्त राष्ट्र में अधिक है जहाँ पर प्रत्येक बैंक व्यवस्था आदि के बारे में स्वतन्त्र है और उन सब पर वहाँ के केन्द्रीय बैंक की देख-रेख रहती है। अन्य देशों जैसे इंग्लैंड, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, भारत में नाथ बैंकिंग ही है। इन दोनों में कौन-सी पद्धति अच्छी है, यह विवादग्रस्त प्रश्न हो गया है।

शाख बैंकिंग के पक्ष में—(१) धन का आवश्यकतानुसार वितरण—शाख बैंकिंग में एक जगह का अधिक धन कम धन वाले स्थानों में स्थानान्तरित

हो सकता है तथा मौममी आवश्यकताओं के अनुसार धन का वितरण हो सकता है ।

(२) व्याज दरों में समानता—देश में एक ही बैंक की अनेक शाखाएँ होने के कारण बैंकों के व्याज की दर में भिन्न स्थानों पर समानता रहती है जो एकक बैंकिंग में सम्भव नहीं । क्योंकि उसमें समृद्ध तथा पुराने भागों में व्याज की दर कम एवं अधिकमिता एवं नये क्षेत्रों में धन की औद्योगिक एवं आर्थिक आवश्यकताएँ अधिक होने से व्याज दर अधिक रहती है ।

(३) हानि का समान वितरण—शाख बैंकिंग में अधिक शाखाएँ होने के कारण हानि का समान वितरण सम्भव होने में बैंकों में स्थायित्व रहता है, क्योंकि एक स्थान की हानि को पूर्ति दूसरी शाखाओं के लाभ से की जा सकती है । यह एकक बैंकिंग में असम्भव है ।

(४) कार्य-क्षमता में वृद्धि—इसमें व्यवस्था का केन्द्रीकरण होने के कारण मुख्य कार्यालय से सब शाखाओं का मन्चालन होता है जिससे कार्य-क्षमता बढ़ती है, आन्तरिक एवं विदेशी विनिमय व्यापार में भित्तव्ययता होती है तथा अन्य नये-नये स्थानों पर शाखाएँ खोली जा सकती है । यह एकक बैंकिंग में सम्भव नहीं है ।

एकक बैंकिंग के पक्ष में—उपर्युक्त लाभ सैद्धान्तिक दृष्टि से तो ठीक है परन्तु उनमें से कुछ व्यावहारिक नहीं है । जैसे, जिन स्थानों में बैंकों की सुविधाएँ नहीं हैं वहाँ भी शाखा खोलना, भिन्न-भिन्न स्थानों के व्याज-दर में समानता रहना आदि अन्य लाभ एकक बैंकिंग में भी है । शाख बैंकिंग में अनेक त्रुटियाँ हैं जो एकक बैंकिंग में नहीं हैं । एकक बैंकिंग के समर्थकों के अनुसार,

(१) कार्यक्षमता में हानि—शाख बैंकिंग में प्रत्येक शाखा के व्यवस्थापक का स्थानान्तरण होता रहता है जिसमें वह एक क्षेत्र की परिस्थिति का पूर्णतः अध्ययन नहीं कर पाता और आवश्यकतानुसार सुविधाएँ नहीं दे सकता ।

(२) समय की हानि—उसे प्रमुख कार्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे समय की हानि होती है, जो एकक बैंकिंग में नहीं होती ।

(३) एकाधिकार—बैंकिंग का केन्द्रीकरण होने से देश की आर्थिक स्थिति कुछ व्यक्ति विशेषों के एकाधिकार में चली जाती है जो देश की आर्थिक दृष्टि से खतरनाक होती है । इसकी सम्भावना एकक बैंकिंग में किंचित भी नहीं है ।

किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से एकक बैंकिंग अयशस्वी हुआ है । अमेरिका के एकक बैंकिंग के इतिहास में सबसे बड़ा बैंक-संकट १९२८-१९३३ का था । इसी

अवधि में इंग्लैंड में शासक बैंकिंग होने से वहाँ का बैंकिंग-व्यापार प्रभावित नहीं हुआ। यही बात भारत के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। भारत के विभाजन के कारण जो उपद्रव एवं हानि देश को हुई उन खतरों से पंजाब नेशनल बैंक और मेट्रोल बैंक आदि को हानि होती हुई भी उन्होंने अपना अस्तित्व टिकाये रखा क्योंकि उनकी सम्पत्ति एवं विनियोग देश के अन्य भागों में फैले हुए थे। परन्तु कुछ अन्य बैंकों का व्यवसाय केवल पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी पंजाब में केन्द्रित था जिन्हें वचान के लिए रिजर्व बैंक एवं भारत सरकार को विशेष सहायता देनी पड़ी, जैसे ट्रेडन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इण्डिया आदि। इसलिए देश की आर्थिक स्थिरता की दृष्टि में शासक बैंकिंग ही अधिक उपयोगी है। लेकिन कुछ व्यक्ति विशेषों के हाथ में बैंकिंग-व्यापार का केन्द्रीकरण न हो सके, इस ओर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। साथ ही शासक बैंकिंग में अच्छे एवं योग्य व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रम बैंकिंग का अवलम्ब होता है एवं व्यापारिक बहु-प्रमाण उत्पादन को दबने हुए शासक बैंकिंग का विकास होना ही उचित है। इससे देश के विभिन्न भागों का बैंकिंग मुविषाएँ मिलकर समुचित आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हो सकेगा और विनियोग के लिए नये-नये स्रोतों का उद्गम होगा।

**मिश्रित बैंकिंग (Mixed Banking)**—व्यापारिक बैंकिंग के साथ ही जब बैंक विनियोग बैंक के भी कार्य करते हैं उस समय उस मिश्रित बैंकिंग कहते हैं। प्रथम विश्व-युद्ध के बाद मंदी आने में व्यापारिक बैंकों के अल्प-कालीन विनियोग के अंत में सुख गया, इस कारण उनको व्यापारिक बैंकिंग के सिद्धान्तों का कड़ाई से पालन करना असम्भव हो गया और वे अपनी राशि का विनियोग व्यापार एवं उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देने में भी लगने लगे। इतना ही नहीं, प्रत्युत व्यापारिक बैंक अधिक राशि में विनियोग कार्यों के लिए उद्योगों एवं व्यापारों को ऋण देने लगे। चूंकि व्यापारिक बैंक उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देकर औद्योगिक विकास में सहायता देने लगे, इसलिए इस पद्धति को हम न तो शुद्ध रूप से व्यापारिक बैंकिंग कह सकते हैं और न विनियोग बैंकिंग ही। इसलिए इस पद्धति का मिश्रित बैंकिंग कहते हैं। इस पद्धति में डेन्मार्क, स्विट्जरलैंड, जर्मनी आदि देशों में अच्छे परिणाम हुए। क्योंकि उद्योगपति बैंकों में अपने सामान्य सम्बन्ध रखने के कारण देश के विनियोग व्यापार की गहरी पहिचान नकता है। बैंक अपना व्यवसाय भली-भाँति जानते हैं और इस अनुभव के कारण वे अपने उद्योगपति ग्राहकों को औद्योगिक विकास के लिए पूर्णों प्राप्त कराने में अधिक सहायक होते हैं।

“वे ग्राहक को विनियोग-बाजार की स्थिति की जानकारी देकर असो एवं ऋण-पत्रों का चलन बंद किया जाय, इस सम्बन्ध में सलाह देने हैं। इसी प्रकार जब उद्योगपति द्वारा ऐसे असो एवं ऋणपत्रों का चलन किया जाता है, उम समय विनियोग-बाजार पर अपन प्रभाव के कारण उन्हें ज़रूर विक-याते हैं।”<sup>१</sup>

परन्तु यह पद्धति खतर से खाली नहीं है और ऐसे खतर विशेष रूप से आर्थिक मंदी के समय बैंक के क्लेवर को ड्रावाडोन कर सकते हैं, क्योंकि (१) आर्थिक मंदी के समय प्रतिभूतियों का अवमूल्यन होता है जिसमें बैंकों की सम्पत्ति घट जाती है, और (२) बैंक अपनी दीर्घकालीन ऋण नीति के कारण कभी-कभी सुरक्षा की ओर की ओर ध्यान न देते हुए अधिक दीर्घकालीन ऋण देकर अथवा औद्योगिक प्रतिभूतियाँ खरीदकर ख़तरे को निमन्त्रण देने हैं। क्योंकि अल्पकालीन निक्षेपों के आधार पर दीर्घकालीन सख्त देना व्यापारिक बैंकिंग के सिद्धान्तों के विपरीत है। इसीलिए भारत में बैंकिंग अधिनियम, १९४६ की धारा के अनुसार मिश्रित बैंकिंग नहीं चपनाया जा सकता।

**भारत में शाख बैंकिंग**—भारत में बैंकों का विकास इसी पद्धति पर हुआ है। परन्तु फिर भी भारत में बैंकों की वर्तमान माग्याएँ हमारी जनमख्या की दृष्टि से बहुत ही कम हैं। विशेष रूप से १९३६ के विन्च-युद्ध के कारण भारत में अनेक बैंकों की स्थापना हुई और पुराने बैंकों ने अपनी शाखाओं का विस्तार भी किया। परन्तु यह विस्तार अश्वस्थित टंग से होता गया। भारत में बैंकिंग-विकास के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक के भूतपूर्व गवर्नर सर जेम्स टेलर ने कहा था कि “भारत में शाख बैंकिंग का विकास हो रहा है परन्तु समूचे देश में मयुक्त स्कन्ध बैंकों का जाल फैलाने के लिए इस दिशा में अधिक प्रगति होना आवश्यक है।” इसके बाद १९३६ से बैंकों का विस्तार द्रुत गति से होता गया, जिससे १ मार्च १९४७ के अन्त में सूची-बद्ध बैंकों की संख्या ६३ एवं उनकी शाखाएँ ३१७३ तथा सूची-बद्ध एवं असूची-बद्ध बैंकों के कार्यालयों की संख्या १८०० (१९३६) में ६००० हजार होगई। इस अनियन्त्रित विस्तार को रोकने के लिए १९४६ में बैंकिंग कम्पनी (शाख-नियन्त्रण) अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार शाखाएँ खोलने में पूर्व रिजर्व बैंक से अनुमति लेना आवश्यक हो गया। इस नियन्त्रण का ममावेश बैंकिंग कम्पनी अधिनियम १९४६ में हो गया है। इस कारण तथा युद्ध के बाद आर्थिक मंदी से रक्षा

करने के लिए बैंक ने अपनी नाम्बाछा का कम करना शुरू किया, जिससे उनका आर्थिक स्तर मजबूत हो सके। रिजर्व बैंक नई नाम्बाछा खोलने की अनुमति दो बातों को देखकर ही देता है—

(१) ऐसे स्थानों पर बैंकों की नाम्बाछाएँ खोली जायें, जहाँ बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है अथवा जहाँ वे सुविधाएँ काफी नहीं हैं।

(२) जहाँ पर पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएँ हैं परन्तु मुसंचालित एवं बड़ा बैंक नहीं है, वहाँ रिजर्व बैंक केवल मुसंचालित बैंकों का नाम्बाछा खोलने के लिए अनुमति देता है, जिससे उस क्षेत्र में मुदूट बैंकिंग-विकास सम्भव हो।

इस प्रकार भविष्य में बैंक का जो नाम्बाछा-विस्तार होगा वह देश की आवश्यकतानुसार होगा, जिससे देश के सभी क्षेत्रों का समुचित आर्थिक विकास हो सकेगा।

**मुसंचालित बैंकिंग की आवश्यकताएँ**—बैंकिंग का स्वरूप एवं उसका आधुनिक आर्थिक ढाँचे में जो महत्व है उसमें स्पष्ट है कि देश में मुसंचालित एवं मुनगठित बैंकिंग होना चाहिए। अब बैंक का अधिकार एस व्यक्ति या वे हाथ में होना चाहिए जिनमें इस व्यापार के लिए पर्याप्त योग्यता तथा सचाई हो। इसी के साथ, ऐसे लोगों का व्यापारिक क्षमता का भी अनुभव होना आवश्यक है जिससे वे जनता का विश्वास प्राप्त करने में सफल हो सकें। साथ ही देश विदेश में बैंकिंग विज्ञान तथा अन्य व्यापारिक एवं औद्योगिक विभागों का ज्ञान भी होना आवश्यक है इसलिए मंचालक की नियुक्ति केवल उनकी उपाधियों की दृष्टि से नहीं बल्कि उनकी मारामार विचारमूर्ति तथा योग्यता के आधार पर हानी चाहिए। दूसरे देश की बैंकिंग नीति व्यापार एवं उद्योग-धन्धा की पापक हानी चाहिए जिसमें देश अधिभर प्रगति कर सके। देश की बैंकिंग प्रगति के लिए सरकारी नीति भी ऐसी हानी चाहिए जिसमें बैंकिंग का समुचित एवं मुसंचालित ढंग पर विकास हो सके।

### सारांश

बैंकिंग व्यवस्था को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—विनियोग बैंकिंग तथा व्यापारिक बैंकिंग। विनियोग बैंकिंग में बैंक दीर्घकालीन साधन देते हैं तथा उनके निक्षेप भी दीर्घकालीन होते हैं। व्यापारिक बैंक अल्पकालीन निक्षेप लेते हैं तथा अल्पकालीन ऋण देते हैं। इस दृष्टि से व्यापारिक बैंकिंग का स्वरूप ऐसा हो जिसमें जनता का विश्वास होना चाहिए और साथ ही बैंक को लाभ भी। अतः इस विश्वास को कायम रखने के लिए बैंकों को लाभ को

अपेक्षा सेवाग्राहों पर अधिक ध्यान देना चाहिए। दूसरे, जनता में वचन की श्रद्धा निर्माण करने के साथ ही ईमानदारी, विश्वास एवं नैतिक स्तर निर्माण करने की ओर बैंक को अधिक ध्यान देना चाहिए। तीसरे, प्राप्त निक्षेपों को अच्छे एवं सुरक्षित विनियोगों में लगाना चाहिए। चौथे, अल्पकालीन ऋणों की अपेक्षा दीर्घकालीन ऋण देना व्यापार को खतरे में डालने की निशानी है, यह बैंक को संबंध ध्यान में रखना चाहिए। सुरक्षा के लिए उसे अपने विनियोग एवं सम्पत्ति में तरलता रखनी होती है। इस तरलता के साथ ही बैंक की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए।

यद्यपि बैंकिंग में थम विभाजन पूर्ण रूप से है फिर भी आजकल केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इस प्रवृत्ति के अनुसार दो प्रकार की बैंकिंग पद्धति है—एकक बैंकिंग तथा शाख बैंकिंग। एकक बैंकिंग अमरीका में अधिक है परन्तु इंग्लैंड, ८० अफ्रीका, भारत आदि देशों में शाख बैंकिंग ही है।

- शाख बैंकिंग के पक्ष में—१ क्षत्रीय एवं मौसमी आवश्यकता के अनुसार धन का वितरण,  
 २ व्याज दरों में समानता,  
 ३ हानि का समुचित वितरण, तथा  
 ४ कार्यक्षमता में वृद्धि एवं मितव्ययिता।

एकक बैंकिंग के पक्ष में—१ व्यवस्थापकों के स्थानान्तरण से कार्यक्षमता में हानि।

- २ समय की हानि, तथा  
 ३ एकाधिकार की त्रुटियाँ शाख बैंकिंग में हैं जो एकक बैंकिंग में नहीं हैं। परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से एकक बैंकिंग असफल रहा है।

मिश्रित बैंकिंग—जब व्यापारिक बैंकिंग के साथ ही बैंक विनियोग बैंकिंग क्रियाएँ करते हैं तब उसे मिश्रित बैंकिंग कहते हैं। इस पद्धति का विकास प्रथम विश्व युद्धोत्तर काल में हुआ था, जबकि अल्पकालीन विनियोग के साधन सूख गये थे। किन्तु इस पद्धति में खतरा है, क्योंकि—

१ आर्थिक मन्दी के समय प्रतिभूतियों का अवभूत्यन होने से बैंक की सम्पत्ति कम हो जाती है।

२ अल्पकालीन निक्षेपों के आधार पर दीर्घकालीन ऋण देना व्यापारिक बैंकिंग के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। भारत में इस पद्धति पर बंधानिक रोक है,

भारत में शाखा-बैंकिंग ही प्रचलन में है। यहाँ पर दूसरे युद्धकाल में बैंकों की शाखाओं में तेजी से वृद्धि हुई जिससे बैंकिंग का अव्यवस्थित विकास हुआ है। अतः १९४६ में एक अधिनियम द्वारा शाखाएँ खोलने के पूर्व सम्बन्धित बैंक को रिजर्व बैंक से पूर्व-अनुमति लेना आवश्यक हो गया। यह अनुमति दो शर्तों पर दी जाती है—

१ शाखाएँ वहीं खोली जायें जहाँ बैंकिंग सुविधाएँ अपर्याप्त हों अथवा अस्तित्व न हो।

२ जहाँ बैंकिंग सुविधाएँ हैं परन्तु अच्छी बैंक नहीं हैं, वहाँ बड़ी बैंक को शाखा खोलने की अनुमति मिल सकती है।

सुसंचालित बैंकिंग के विकास के लिए योग्य एवं अनुभवी व्यवस्थापक होना आवश्यक है। उसको विभिन्न व्यापारिक क्षेत्रों का अनुभव होना चाहिए। दूसरे अर्थी बैंकिंग नीति का पालन करना चाहिए जो देश के आर्थिक विकास की पोषक हो।

## अध्याय ३

# बैंक स्थिति-विवरण

भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक समामेलित (incorporated) बैंक को अपना स्थिति-विवरण (balance sheet) निश्चित सामयिक अवधि में फॉर्म 'एफ' के अनुसार<sup>१</sup> प्रकाशित करना पड़ता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी जनता को हो। इसमें उम निश्चित तिथि को उसकी सम्पत्ति कितनी है तथा विन-विन बातों का उमम समावेश है, उसका देय कितना है एवं किस प्रकार वह बना हुआ है, आदि बातों को स्पष्ट बताया जाता है। इन विवरण पर ही जनता का विश्वास निर्भर रहता है क्योंकि इनसे तुलनात्मक आलोचना द्वारा बैंकों की आर्थिक परिस्थिति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।

स्थिति-विवरण के दो विभाग होते हैं—पहला देय तथा दूसरा सम्पत्ति, जो उमस वाय एवं दाये दिखाये जाते हैं। देय भाग में विभिन्न विषयों के जो ऍकडे बनाय जाते हैं, वे यह बताते हैं कि स्थिति विवरण के दिन बैंक की कुल दनदारी कितनी है तथा उसका कितना भाग हिस्सेदारों को पूँजी के रूप में देना है तथा कितना भाग उसने डिपॉजिट आदि के रूप में लिया है जिसके ढुगदान की जिम्मेदारी उस पर है। इसी प्रकार सम्पत्ति भाग से हम यह जानते हैं कि बैंक के पास कितनी सम्पत्ति है, जिसके आधार पर वह अपना देय ढुगता सकता है तथा यह सम्पत्ति निम प्रकार से बनी हुई है। बैंक के पास कितनी रोकड है, कितना ऋण उसको लेना है तथा कितनी स्थायी सम्पत्ति उमके पास है, आदि सम्पत्ति भाग के अध्ययन में जाना जा सकता है।

देय भाग—देय भाग से हमको समुचित रूप से यह गानूम होता है कि बैंक को कार्यशील पूँजी कहां से मिलती है।

(१) पूँजी—समामेलित बैंक में अनक हिस्सेदार होते हैं जो कुछ निश्चित रकम के अग खरीदते हैं। बैंक को कुल व्यापार-संचालन के लिए जितनी पूँजी की

वक का स्थिति विवरण (दिनांक ३१ दिसम्बर १९ )

रकम	योग
सम्पत्ति (Assets)	योग
१ हस्तस्थ रोड अथ बैंक ग रोड (Cash and Banks including Reserve Bank of India)	१ अधिभूत पूँजी
२ मौग पत्र एवं जलसायोग पत्र (M : 0) and other (liac)	२ निगमित पूँजी
३ ऋण तथा अग्रिम	३ प्राशित पूँजी
४ विनिर्माण	४ सुरक्षा पूँजी
५ प्राप्य रिज (प्रति प्रतिदिन अनुसार) (15 per contra)	५ मचित बाल आदि (Reserve 1 : 1)
६ ग्राहकों का सीजत रिज पर दायित्व (प्रति प्रतिदिन अनुसार) (Constitute 15 liability for acceptance endorse ments etc 15 per contra)	६ निभेप (तथा अ य माल)
७ बैंक भूगृहादि	७ अ य बैंक से ऋण
८ बैंक फर्मायर	८ अ य रिज
९ अ य सम्पत्ति	९ गग्रहण क रिज प्रा त रिज (प्रति प्रतिदिन)
१० सान वर्गिग सम्पत्ति	९ अ य देय
	१० रीजुल विपना का अ य (प्रति प्रतिदिन)
	१० (Liabilities for acceptance etc per contra)
	१० ग्राभ हाणि चला (P/A account)
	१० मयोगिग नन्दारिया
	१० योग

आवश्यकता होती है उतनी पूँजी के अंश सर्वप्रथम निम्नित किये जाते हैं जिसकी राशि सीमा-नियम (memorandum of association) में रहती है। इस सीमा नियम से कम्पनी का कार्य-क्षेत्र सीमित रहता है, अतः इसमें जो पूँजी को रकम होती है, उसे अधिकृत पूँजी कहते हैं। किसी भी समय बैंक को यह पूँजी न्यायालय की पूर्व-प्रनुमति के बिना नहीं बढ़ाई जा सकती। इस पूँजी का कुछ भाग बैंक अपनी आवश्यकतानुसार चल-पूँजी की प्राप्ति के लिए जनता को खरीदने के लिए देते हैं। जितनी रकम के अंश जनता को खरीदने के लिए दिए जायेंगे उसे निर्गमित (issued) पूँजी कहते हैं। इस निर्गमित अंश में से जनता जितने अंश खरीदगी एवं खरीदने के लिए मान्य करेगी, उस भाग को प्राप्ति (subscribed) पूँजी कहते हैं। इस प्राप्ति पूँजी का बितना भाग चुकता हो जायगा उसे चुकता पूँजी कहते हैं।

भारत में ५० प्रतिशत पूँजी संचित पूँजी अथवा सुरक्षित देय के रूप में हो रही है जिससे वह आवश्यकता के समय काम आ सके। भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम, १९४६ (धारा १२) के अनुसार प्रत्येक बैंक को यह अनिवार्य है कि अधिकृत पूँजी की ५० प्रतिशत प्राप्ति पूँजी हो, तथा प्राप्ति पूँजी की ५० प्रतिशत चुकता पूँजी हो। भारत के सभी समानेखित बैंकों को, मिली स्थापना १५ जनवरी १९३७ अथवा उसके पहले हो चुकी थी, इस धारा का पालन कम्पना अनिवार्य है। इसी प्रकार यदि किसी बैंक ने अपनी अधिकृत पूँजी बढ़ाई है तो उसकी पूँजी दो वर्ष के भीतर अपना रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत प्रवधि में इस नियम के अनुसार हानी चाहिए। इसी प्रकार (धारा ७५) अधिकृत एवं प्राप्ति पूँजी के अंकड़े प्रकाशित करते समय प्रत्येक बैंक को अपनी चुकता पूँजी के अंकड़े भी प्रकाशित करने पड़ेंगे। इस प्रकार नए पूँजी प्रारम्भ में अंशों द्वारा एकत्र की जाती है। इसी प्रकार प्रत्येक बैंक ओ एक से अधिक प्रान्त में व्यापार करता है, उसकी चुकता पूँजी एवं संचित निधि ५ लाख रुपये न्यूनतम होना अनिवार्य है। परन्तु यदि उसका व्यापार बम्बई या कलकत्ता या दोनों स्थानों पर हो तो उसकी यही राशि न्यूनतम १० लाख रुपये होना चाहिए। (सर्जन, १९१), १. ब्रिटिश बैंकों की भारतीय व्यापारियों के लिए यही राशि क्रमशः १५ और २० लाख रुपये होना अनिवार्य है।

(२) संचित निधि—देय भाग में पूँजी के बाद 'संचित निधि' आती है। 'संचित निधि' 'संचित देय' (reserve liability) में भिन्न है। संचित निधि का निर्माण अविवरित लाभ से किया जाता है जिससे वह आरुस्मिक हानि को

पूर्ति में अथवा प्रतिवर्ष दिये जाने वाले लाभ को समान रखने के लिए उपयोगी हो सके। ऐसी निधि प्रत्येक ममाभिलिखित बैंक को रखना विधान से अनिवार्य है। भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अनुसार मन्त्रित निधि की रकम चुकता पूँजी के बराबर होनी चाहिए। इस हेतु प्रत्येक बैंक को अपने लाभ का २० प्रतिशत भाग संचित निधि में, जब तक यह चुकता पूँजी के बराबर न हो, स्थानान्तरित (transfer) करना अनिवार्य है (धारा १७)। यह निधि वास्तव में हिस्सेदारों की होती है, क्योंकि अवितरित लाभ में इसका निर्माण किया जाता है। इसलिए किसी भी समय यह उनके हित के लिए उपयोग में लाई जा सकती है, जैसे हिस्सेदारों के लाभांश (dividends) की दर समान रखने अथवा उनको अधिताभाज (bonus) देने के लिए। यह वास्तव में बैंक की कुल सम्पत्ति चुकता पूँजी तथा अन्य देय में कितनी अधिक है, यह बताती है जिससे ग्राहकों को सुरक्षा तथा संचालकों की बुद्धिमत्ता का परिचय भी मिलता है। यह कार्य-क्षम व्यवस्था के कारण शीघ्र ही निर्माण हो सकती है। इस निधि में कभी-कभी नये अथ निर्गमन पर जो प्रीमियम मिलती है वह भी जमा की जाती है।

अपनी आर्थिक स्थिति की मजबूती के लिए कुछ बैंकों के संचालक गुप्त निधि भी बना लेते हैं, जिसका उल्लेख स्थिति-विवरण में नहीं होता। यह निधि बैंक की स्थायी सम्पत्ति को वास्तविक मूल्य में कम मूल्य पर ख़ाता-बही में दिखाकर बनाई जाती है। उदाहरणार्थ, बैंक के स्थिति विवरण में खान्दा रूपों का फर्नीचर होते हुए भी नहीं दिखाया जाता, जो एक प्रकार में गुप्त निधि है। इसका उपयोग आर्थिक सफ़ट में किया जाता है।

इस प्रकार प्रारम्भ में कार्यशील पूँजी चुकता पूँजी में प्राप्त होती है और तमन संचित निधि के निर्माण के साथ कार्यशील पूँजी बढ़ती है। वह निधि प्रथम श्रेणी की भिन्न-भिन्न स्थितियों में विनियोग की जाती है जिससे किसी भी समय बैंक के काम आ सके।

(३) निक्षेप—यह देय भाग में आने वाला महत्वपूर्ण पद है। निक्षेपों के आधार पर बैंक में जनता का विश्वास किनता है तथा उसका इस विषय में कितना देय है, यह मासूम होता है। ये निक्षेप तीन प्रकार के होते हैं —

(क) चल निक्षेप—यह जनता की वह जमा रकम है जो किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के बैंक द्वारा निकाली जा सकती है। इसलिए इन निक्षेपों के विनियोग में बैंक को अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है।

(ख) संचय निक्षेप—यह जनता की वह जमा रकम है जो निश्चित मामलिक अवधि में कुछ निश्चित रकम में अधिक नहीं निवाली जा सकती।

(ग) स्थायी निक्षेप—यह जनता की वह जमा रकम है जो एक निश्चित अवधि के लिए जमा की जाती है तथा निश्चित अवधि के पट्टे बिना पूर्व सूचना के नहीं निकाली जा सकती ।

इन तीनों प्रकार के निक्षेपों में बैंक को कार्यशील पूँजी मिलती है तथा इसकी ऋण आदि देने से बैंक अपना लाभ कमाते हैं । इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंक पर रहती है । अतः इसका विनियोग बैंक को इस प्रकार करना पड़ता है जिसमें उसे लाभ भी मिले तथा माँग होने पर किसी भी समय इसका भुगतान करने में भी मुश्किल न हो । यदि बैंक निक्षेपों की माँग पर भुगतान नहीं कर सका तो वह जनता का विश्वास खो बैठता है, जिससे उसका व्यापार भी क्षुब्ध होने की सम्भावना रहती है । अतः इस सम्बन्ध में बहुत सावधान रहना पड़ता है ।

व्यापारिक मन्दी के समय लाभकर विनियोगों के साधन न होने में अन्य निक्षेपों की अपेक्षा चल निक्षेपों में कम रकम होती है । इसके विपरीत व्यापारिक उन्नति के काल में लाभकर विनियोगों के साधन होने से चल निक्षेपों की जमा अधिक होती है क्योंकि व्यापारिक विस्तार के लिए उनको अधिकाधिक रकम की आवश्यकता होती है । इस प्रकार व्यापारिक मन्दी के समय अन्य निक्षेपों का अनुपात चल निक्षेपों के अनुपात में घटता है तथा व्यापारिक तेजी (boom) के समय चल निक्षेपों के अनुपात में अन्य निक्षेपों की तुलना में वृद्धि होती है । इस प्रकार निक्षेपों के अनुपात देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक स्थिति की गति-विधि की ओर संकेत करते हैं ।

भारतीय बैंक अपने स्थिति-विवरण में भिन्न-भिन्न निक्षेपों की रकम भिन्न-भिन्न नहीं बताते थे, परन्तु अब विभिन्न प्रकार के निक्षेपों की रकम अलग-अलग बताना अनिवार्य है । इन निक्षेपों की राशि में बैंक के व्यापार की पूरी-पूरी वृद्धि होती है ।

(४) सग्रहण के लिए आये हुए बिल—इस पद में उन बिलों का तथा परिपत्रों का समावेश होता है जो बैंक अपने ग्राहकों से सग्रहण के लिए लेता है । क्योंकि इन बिलों की राशि उनके स्विकर्ता से लेने के बाद ग्राहक के खाने में जमा कर दी जाती है । यह राशि किसी भी समय सग्रहण होने की सूचना पाते ही ग्राहक निकाल सकता है, इसलिए यह बैंक की देनदारी होती है । परन्तु वास्तव में इन बिलों की राशि बैंक को हमारे बैंकों अथवा व्यक्तियों से लेनी होती है । इसलिए यह बैंक की वास्तविक देनदारी नहीं रहती । सम्पत्ति भाग

में इसकी प्रति प्रविष्ट (contra entry) 'प्राप्य बिल' पद में होती है। अतः इस पद पर बैंक का विशेष दायित्व नहीं रहता।

(५) स्वीकृत बिलों पर देय—इस पद में उन बिलों का नाम-पत्रों का समावेश होता है जो बैंक अपने ग्राहकों की ओर से स्वीकार करते हैं अथवा जिन पर वे वचन (endorsement) करते हैं। इस प्रकार ग्राहक द्वारा लिखे गये बिलों को अथवा उनके दिये हुए बिलों पर बैंक की स्वीकृति की मुहर लग जाने से उनका चलन बढ़ जाता है और ग्राहक की मान्य भी। इसलिए स्वीकृत बिलों के भुगतान की प्रारम्भिक जिम्मेदारी बैंक की होती है। परन्तु वचन किये हुए बिलों के भुगतान की आकस्मिक जिम्मेदारी (contingent) बैंक की होती है। अतः यह पद देय भाग में दिखाया जाता है।

परन्तु वास्तव में बैंक इनकी देनदारी से सुरक्षित होने के लिए अपने ग्राहकों से प्रतिज्ञा-पत्र अथवा प्राप्य बिल आदि लिखवा लेता है, जिसका ग्राहक स्वीकार करने के तथा इन बिलों का भुगतान भी वे ही करते हैं। इसलिए इनकी राशि सम्पत्ति पक्ष में भी 'स्वीकृत बिलों पर ग्राहकों की देनदारी' इस पद में दिखाई जाती है।

(६) लाभ-हानि लेखा—बहुत से बैंक इस पद के अन्तर्गत उनका वर्ष में जो लाभ होता है उसे बताते हैं, तथा उसका विभाजन किस प्रकार किया गया इसका दिग्दर्शन कराते हैं। यह लाभ अनुधारियों को देना होता है इसलिए बैंक के लिए भी देय होता है।

सम्पत्ति-भाग—सम्पत्ति भाग से बैंक अपने देय राशि का विनियोग किस प्रकार करते हैं, यह मासूम होता है। अपनी देयता के भुगतान के लिए बैंक के पास कितनी रोकड निधि (cash reserves) तथा कितनी तरल सम्पत्ति है, इसका ज्ञान होना है। सम्पत्ति भाग में सम्पत्ति उनकी तरलता के अनुसार दी जाती है।

बैंक निक्षेपों के रूप में प्राप्त धन का विनियोग करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होने हुए भी उसको इसका विनियोग सुरक्षित रीति में करना पड़ता है क्योंकि एक ओर निक्षेपों की सुरक्षा एवं माँग पर भुगतान करने की शक्ति तथा दूसरी ओर लाभ कमाने के हेतु उनका विनियोग इस दुहरी कैंची में बँक होना है। इसलिए बैंक को अपने देय एवं निक्षेपों के भुगतान के लिए मर्दव कुछ रोकड अपने पास रखनी पड़ती है तथा अन्य धन का विनियोग वह इस प्रकार करता है जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उसे तुरन्त ही धन प्राप्त हो सके। बैंक

की मफलता धन की तरलता पर निर्भर रहती है। अतएव हमारे लिए सम्पत्ति भाग के विभिन्न पक्षों का समुचित अध्ययन महत्वपूर्ण है।

(१) हस्तस्थ तथा बैंको में रोकड़—इस पद के अन्तर्गत बैंक की रोकड़ एवं अन्य बैंकों तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के पास जमा धन का समावेश होता है। अपना धन एक बैंक दूसरे बैंक के पास रखता है तथा निक्षेप की रकम जो केन्द्रीय बैंक के पास होती है, बैंक को बंधानिधि रीति में रखना अनिवार्य है। जो रकम इस प्रकार अन्य बैंकों एवं केन्द्रीय बैंक में जमा रहती है, 'हस्तस्थ रोकड़' की तरह ही होती है, क्योंकि समय आने पर बैंक इन निक्षेपों की रकम अपने देश के भुगतान के लिए उपयोग में ला सकता है। इस रोकड़ को हस्तस्थ रोकड़ से भिन्न दिखाने की प्रथा आधुनिक है जिससे ग्राहकों को बैंक की तरलता का पूर्ण ज्ञान हो सके। इसको 'रोकड़ निधि' कहते हैं। यह बैंक की सुरक्षा का पहला साधन है।

(२) याचित तथा अल्पकालीन सूचना वाले ऋण—इस पद के अन्तर्गत उन ऋणों का समावेश होता है जो बैंक विभिन्न व्यक्तियों को देता है। ये ऋण तीन प्रकार के होते हैं—

(अ) वह ऋण जो बैंक अपने व्यापार के अन्त में केवल राशि के उपयोग के लिए देते हैं और जिनका भुगतान दूसरे दिन बैंक के कार्यालय में समय हो जाना है। ऐसे ऋण विशेषण मद्धे अथवा स्वल्प विनिमय व्यवहार के लिए दिए जाते हैं।

(ब) वे ऋण जो बैंक इस शर्त पर देता है कि ऋणी भुगतान माग पर बिना किसी पूर्व-सूचना के करेगा। ऐसे ऋणों को 'माग' पर भुगतान होने वाले ऋण (money at call) कहते हैं।

(स) वे ऋण जो बैंक इस शर्त पर देते हैं कि उनका भुगतान सूचना पाने ही २४ घण्टे में सात दिन के अन्दर होगा। इन ऋणों में कुछ ऐसे होते हैं जिनका भुगतान भिन्न भिन्न प्रकार की सूचनाओं की प्राप्ति पर उस अवधि में होना चाहिए।

इस प्रकार के अल्पकालीन ऋण बिल दलाल कटौती गृह (discount house), स्वल्प विनिमय तथा मटोरीरियों आदि को देते हैं। इन ऋणों पर व्याज की दर बहुत कम होती है जो  $\frac{1}{2}\%$  से  $1\%$  प्रति वर्ष होती है। इसी प्रकार ये ऋण अन्य अच्छे बैंकों को भी दिये जाते हैं। ये ऋण प्रतिभूतियाँ की रहन पर दिये जाते हैं। अगर किसी भी समय बैंक के पास रोकड़ न रहे तो भुगतान के लिए यह सुरक्षा का दूसरा साधन है।

(३) क्रीत एव कटौती किये हुए बिल—यह तीसरा पद है जो तरलता की दृष्टि से बैंक के स्थिति विवरण में आता है। इस शीर्षक में वह विनियोग आता है जो बैंक बिलों की कटौती द्वारा दूसरों को देते हैं। इसमें बैंक केवल प्रथम श्रेणी के बिलों की ही कटौती करता है अथवा उन्हें खरीदता है। बिलों की कटौती उम क्रिया को कहते हैं जिसमें बैंक बिलों का तत्कालीन मूल्य बिल-धारी (holder) को चुकाते हैं। उदाहरणार्थ, एक बिल १००० रुपये का ६० दिन बाद देय है तथा इसे बिल-धारी कटौती के लिए लाता है। अर्थात् इस बिल पर बैंकर १००० रुपये का ९० दिन का मूद इस रकम में से तत्कालीन दर में कम करके दोष मूल्य धारी को चुकायगा। अब यह बिल बैंक की सम्पत्ति है जिसका ६० दिन बाद उसे भुगतान मिलेगा। इन बिलों में उमका विनियोग इस प्रकार होता है कि एक के बाद दूसरा बिल चुकता होता रहे जिसमें किसी भी समय उम रोकड़ की कमी न रहे। यह बैंक की सुरक्षा का तीसरा गारन्टी है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर बैंक इन बिलों को बिल-बाजार में बचकर अपना केन्द्रीय बैंक से पुनः कटौती करा कर धन ले सकता है।

बिलों की कटौती बैंक का प्रमुख कार्य है और इसीलिए इसमें उमके अधिक धन का विनियोग होता है। कभी-कभी इन बिलों में कंप बिलों का भी समावेश होता है जो सरकार की दैनिक आवश्यकताओं के लिए केन्द्रीय बैंक बेचता है। इन बिलों की अवधि ६० दिन से अधिक नहीं होती तथा इन पर व्याज भी कम मिलता है।

भारत में बिल-बाजार मुम्बई में ही होने के कारण इस पद के अन्तर्गत बहुत कम विनियोग होता है, परन्तु विदेशों में, जहाँ बिल-बाजार का संगठन एव संचालन बहुत ही अच्छा है, बैंक के अधिक विनियोग बिलों की कटौती में होता है। विदेशों में इस शीर्षक में बैंक की कायशील पूँजी का २०% से २५% विनियोग होता है, जहाँ भारत में २% से ३% होता है। इसीलिए भारतीय बैंकों के स्थिति विवरण में इस शीर्षक को 'अग्रिम तथा ऋण' के अन्तर्गत दिखाया जाता है।

(४) विनियोग—यह सुरक्षा का चौथा साधन है। इसमें बैंक के उम विनियोग का समावेश होता है जो सरकारी एव अर्ध-सरकारी (semi-government) मिक्चरिटी, जन-उपयोगी और प्रथम श्रेणी की कंपनियों के असा अथवा ऋण-पत्रों में किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियाँ, ऋण-पत्र आदि पर व्याज तथा कंपनी के असा पर लाभांश मिलता है जिससे बैंक को लाभ होता है। किन्तु

सकट-काल में इनका परिवर्तन रोकड़ में असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य है। जिस समय मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है उस समय ये प्रतिभूतियाँ बेची भी नहीं जा सकती, क्योंकि उस समय मुद्रा-मटी में पैसों की कमी रहती है। ऐसे समय यदि प्रत्येक बैंक अपने विनियोग पत्र बेचेगा तो विनियोग पत्रों के मूल्य गिर जायेंगे और बैंक में जनता का विश्वास उठ जायेगा। अतः उक्त तीनों पदों के विनियोगों की अपेक्षा इसमें तरलता कम रहती है। किन्तु ये विनियोग प्रथम श्रेणी के होने के कारण सकट-काल में इनके रहन पर केन्द्रीय बैंक से ऋण मिला सकता है।

(५) **अग्रिम तथा ऋण (Loans & Advances)**—बैंक अपना धन ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम के रूप में देकर सबसे अधिक लाभ कमाता है। इन ऋणों की व्याज-दर ६% से १०% प्रति वर्ष तक होती है। व्यापारिक बैंक इस प्रकार के ऋण ६ से ९ महीने की अवधि के लिये इस शर्त पर देते हैं कि माँग पर उनका भुगतान होगा। किन्तु बैंक इन पर अधिक निर्भर नहीं रह सकता क्योंकि सकट-काल में यदि सब ग्राहकों में ऋण का भुगतान माँग जायगा तो एक ओर बैंक में जनता का विश्वास उठेगा तथा दूसरी ओर जो लोग ऋण चुकाने में अममय होंगे, वे दिवालिये हो जायेंगे। इससे देश की व्यापारिक स्थिति को घबरा लगेगा। इसीलिए डॉ० वाल्टर लीफ ने इस पद को बैंक की क्रिया का केन्द्रीय भाग कहा है क्योंकि इस पर बैंकों को सबसे अधिक लाभ मिलता है। इस मद को बैंक की सुरक्षा का पाँचवाँ माधन कहा जाता है।

(६) **प्राप्य बिल**—यह पद “भग्नहण के लिए प्राप्त बिल” की प्रति प्रविष्टि है। इसलिए यह बिल वास्तव में न तो सम्पत्ति ही है और न देनदारी है बल्कि आपस में मन्तुगिन हो जाती है।

(७) **ग्राहकों का स्वीकृत पर दायित्व**—यह पद भी उपरोक्त पद की भाँति “स्वीकृत बिलों पर देय” की प्रति-प्रविष्टि है। अतः इस पद का सन्तुलन देय भाग में होता है।

(८) **भू-गृहादि (Land, Buildings etc)**—यह पद स्थिति-विवरण में सब के अन्त में आता है क्योंकि यह सबसे कम तरल है जिसका परिवर्तन रोस्ट में केवल बैंक बन्द होने पर ही किया जाता है। बैंक की जो स्थायी सम्पत्ति होती है उसका मूल्य वास्तविक मूल्य में बहुत कम दिखाया जाता है ताकि सकट-काल में अथवा मयोगिक हानि पूर्ति के लिए “गुप्त निधि” का निर्माण हो। इस पद में प्रति वर्ष जो नवीन सम्पत्ति खरीदी जाती है वह अलग बताई

जानी है। उसी प्रकार प्रति वर्ष सम्पत्ति का जितना अवमूल्यन किया जाय वह भी दिखाया जाता है।

**निष्कर्ष—**स्थिति-विवरण के अध्ययन एवं विश्लेषण में हमको निम्न बात समझ में आती है —

(१) प्रत्येक समय बैंक की सम्पत्ति एवं देय का मन्तुलन होता है।

(२) स्थिति-विवरण के दो भाग में जो देय होने ह उन सब का भुगतान बैंक को एक साथ नहीं करना पड़ता। अपितु कुछ देय ऐसे होते हैं जिनका भुगतान करना ही नहीं पड़ता, किन्तु भुगतान की जिम्मेदारी होती है, उदाहरणार्थ बिलो बिपत्रों पर देय। दूसरे, कुछ देय ऐसे होते हैं जिनका भुगतान करने की कभी आवश्यकता नहीं होती और न उसका भुगतान ही होता है, जैसे संचित निधि एवं छुट्टा पूँजी। तीसरे, निक्षेप के रूप में जो देय दिखाया जाता है उसके भुगतान की वास्तविक जिम्मेदारी बैंक की होती है किन्तु इसमें भी कुछ निक्षेप ऐसे होते हैं जो स्थायी होते हैं एवं जिनको निश्चित अवधि के बाद निदाना जा सकता है जिसका पूर्व-ज्ञान होने में समय पर भुगतान हो सकता है। इसी प्रकार मन्थ निक्षेप की रकम भी कुछ निश्चित मात्रा में ही निकाली जा सकती है तथा यह रकम कितनी होगी, इसका अनुभव बैंकों का होता है। परन्तु चल-निक्षेपों के भुगतान की वास्तविक जिम्मेदारी बैंक पर होती है। इन निक्षेपों की रकम भी अन्य निक्षेपों की राशि में अंकित होती है। ये निक्षेप किसी भी समय किसी भी राशि में ग्राहकों द्वारा निकाले जा सकते हैं। अब इस सम्बन्ध में बैंक का तत्कालीन दायित्व महत्वपूर्ण है जिसके भुगतान के लिए उसको मर्देव धपने पास रोक्ड निधि रखनी पड़ती है।

(३) सम्पत्ति भाग में निम्न-भिन्न प्रकार की सम्पत्ति तरलता के अनुसार लिखी जाती है तथा धन का विनियोग अधिक तरल एवं सुरक्षित हो तथा अधिकाधिक लाभ भी कमाया जा सके, इस दृष्टि में करना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जिसकी सफलता मन्थालकों की बुद्धिमत्ता एवं अनुभव पर रहती है।

**स्थिति-विवरण में लाभ**

स्थिति-विवरण में बैंक की लाभ देने की शक्ति, धन की तरलता एवं सुरक्षा, उसकी आर्थिक स्थिति तथा बैंक में जनता का विश्वास कितना है यह ज्ञात हो सकता है।

(१) लाभ देने की शक्ति—जिसी भी बैंक के पिछले स्थिति-विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन से हम यह जान सकते हैं कि लाभार्जन गिर रहे हैं अथवा बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार चुकता पूंजी एवं निक्षेपों का अनुपात क्या है? क्योंकि जैसे-जैसे लाभ देने की शक्ति बढ़ती जायेगी, उम्मी हिमाय में उससे निक्षेप में भी वृद्धि होगी और चुकता पूंजी की अपेक्षा निक्षेप का अनुपात बढ़ता जायेगा। इसी प्रकार मचित निधि को देखकर हम बैंक की आर्थिक स्थिति समझ सकते हैं क्योंकि सुगमचालित बैंकिंग में मचित निधि जमना बढ़ती ही जाती है।

(२) सम्पत्ति की सुरक्षा एवं तरलता—सम्पत्ति की सुरक्षा एवं तरलता जानने के लिए कुछ निक्षेप एवं विनियोग का अनुपात देखना होगा। तरलता के लिए विनियोग को भी ध्यान में रखा जा सकता है अथवा नहीं, यह देखना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से ऋणों की राशि निक्षेपों की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर है तो मचित निधि उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं, यह देखना होगा। इसी प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से विनियोग किस प्रकार की मिश्रितियाँ हैं यह भी देखना चाहिए। विनियोग-जन ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव हो अथवा आय की स्थिरता न हो।

(३) व्यापार की गति-विधि—बैंक का व्यापार बढ़ रहा है अथवा नहीं, यह देखने के लिए निक्षेप का पूंजी से अनुपात बढ़ रहा है या नहीं, यह देखना होगा। इसी प्रकार अगर ऋणों, विनियोगों तथा निक्षेपों में वृद्धि हो रही हो तो यह निश्चित है कि बैंक का व्यापार प्रगति पर है। लेकिन इस वृद्धि के साथ ही साथ तरलता एवं सुरक्षा को देखना आवश्यक है। बैंक की आर्थिक दृष्टि स्थिति एवं सम्पत्ति की तरलता जानने के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो लागू किये जा सकें। किन्तु इनके स्थिति-विवरण की तुलना प्रथम श्रेणी के बैंक में करने पर कौन-सा बैंक अधिक अच्छा है, यह जाना जा सकता है। हमारे देश में बिजेपत प्रथम श्रेणी के बैंक निक्षेपों पर बहुत कम व्याज देते हैं। इसी प्रकार उनके विनियोग तथा ऋण भी कम व्याज पर ही होते हैं क्योंकि जितनी ही विनियोग एवं ऋणों की व्याज-दर कम होगी उतनी ही उनकी सुरक्षा अधिक होगी।

(४) सम्पत्ति की सुरक्षा एवं तरलता पर ही बैंक में जनता का विश्वास बढ़ रहा है या घट रहा है यह मापन हो सकता है। जितना अधिक जनता का विश्वास बैंक में होगा उतने ही उमंग निक्षेपों में वृद्धि होगी। इससे उनकी वारंशील पूंजी बढ़कर लाभ भी बढ़ेगा।

गठितन  
भारतीय बैंक एंव  
अनुभव

Capital & Liabilities	Rs	सम्बन्ध
1 Capital		ध्यान में
Authorized Capital—		नृपात में
shares of Rs each		माण नहीं
		ए पदों के
Issued Capital—		परिपत्र में
shares of Rs each		निशपा स
		मकना कि
Subscribed Capital—		शील स्थिति
shares of Rs each		कड अथवा
		पार अत्यन्त
Amounts called up at Rs per sh	५ है।	भारतीय
Less calls unpaid		वक का प्रत्येक दिनांक में
		कड, स्वण अथवा मान्य प्रति-
		५५ है। अन्य पदाक सम्बन्ध में बाद भी वैधानिक वधन

सारांश

प्रत्येक सम्मानित बैंक को वर्षान्त में अपना स्थिति विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य है। इन स्थिति-विवरण में दो पक्ष होते हैं दाहिना एवं बायाँ। दाहिने पक्ष में बैंक की वर्षान्त में सम्पत्ति कितनी है तथा उसका क्या स्वरूप है और बाये पक्ष में बैंक की देनदारियाँ कितनी हैं तथा उनका स्वरूप आदि, देना होता है। इन दोनों पक्षों का समुलन हो जाता है।

दया भाग—इसकी देखने से यह मालूम होता है कि बैंक को कार्यशील पूँजी कहाँ से मिलती है। इसके विभिन्न पद निम्न हैं —

(१) लाभ देने की शक्ति—बैंक के पिछले स्थिति-विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन से हम यह जान सकते हैं कि लाभान्वित गिर रहे हैं अथवा बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार चुकता पूँजी एवं निक्षेपों का अनुपात क्या है? क्योंकि जैसे-जैसे लाभ देने की शक्ति बढ़ती जायेगी, उसी हिसाब में उसके निक्षेप में भी वृद्धि होगी और चुकता पूँजी की अपेक्षा निक्षेप का अनुपात बढ़ता जायगा। इसी प्रकार संचित निधि को देखकर हम बैंक की आर्थिक स्थिति समझ सकते हैं क्योंकि सुमंचालित बैंकिंग में संचित निधि नमूना बढ़ती ही जाती है।

(२) सम्पत्ति की सुरक्षा एवं तरलता—सम्पत्ति की सुरक्षा एवं तरलता जानने के लिए कुल निक्षेप एवं विनियोग का अनुपात देखना होगा। तरलता के लिए विनियोग को धीमे-धीमे बढ़ा जा सकता है अथवा नहीं, यह देखना होगा। सुरक्षा की दृष्टि से ऋणों की राशि निक्षेपों की राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, अगर है तो संचित निधि उनकी पूर्ति के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं, यह देखना होगा। इसी प्रकार सुरक्षा की दृष्टि से विनियोग किस प्रकार की निवृत्तियों में है यह भी देखना चाहिए। विनियोग-पर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव हो अथवा आय की स्थिरता न हो।

(३) व्यापार की गति-विधि—बैंक का व्यापार बढ़ रहा है अथवा नहीं, यह देखने के लिए निक्षेप का पूँजी में अनुपात बढ़ रहा है या नहीं, यह देखना होगा। इसी प्रकार अगर ऋणों, विनियोगों तथा निक्षेपों में वृद्धि हो रही हो तो यह निश्चित है कि बैंक का व्यापार प्रगति पर है। लेकिन इस वृद्धि के साथ ही साथ तरलता एवं सुरक्षा को देखना आवश्यक है। बैंक की आर्थिक शब्दों में स्थिति एवं सम्पत्ति की तरलता जानने के लिए कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो लागू किये जा सक। किन्तु इनके स्थिति-विवरण की तुलना प्रथम श्रेणी के बैंक में करने पर कौन-सा बैंक अधिक अच्छा है, यह जाना जा सकता है। हमारे देश में विशेषतः प्रथम श्रेणी के बैंक निक्षेपों पर बहुत कम व्याज देते हैं। इसी प्रकार उनके विनियोग तथा ऋण भी कम व्याज पर ही होते हैं क्योंकि जितनी ही विनियोग एवं ऋणों की व्याज-दर कम होगी उतनी ही उनकी सुरक्षा अधिक होगी।

(४) सम्पत्ति की सुरक्षा एवं तरलता पर ही बैंक में जनता का विश्वास बढ़ रहा है या घट रहा है यह मालूम हो सकता है। जितना अधिक जनता का विश्वास बैंक में होगा उतने ही उसके निक्षेपों में वृद्धि होगी। इसमें उसकी कार्यशील पूँजी बढ़कर लाभ भी बढ़ेगा।

## बैंकिंग अनुपात (Ratios)

बैंकिंग व्यापार आजकल उत्तमि पथ पर है और उमम आय दिन परिवर्तन हान रहन हे । अतः उनक विभिन्न पदा की राशि किनमी हा अथवा उनका एक दूसर स क्या अनुपात हा यह निश्चित नहीं है । किमी बान का दीध अनुभव ही भविष्य म मिद्वान्त हा जाता है । कुछ भी हा प्रत्येक बैंक का इस सम्बन्ध म कुछ मिद्वान्ता का पालन करना हाता है । उनक माय ही यह भी ध्यान म रखना हागा कि मिद्वान्ता क अनुसार विभिन्न पदा का निश्चित अनुपात म सम्बन्ध हाता ही बैंक की सम्पत्ति की तरतना अथवा मुदन्ता का प्रमाण नहीं हाता । इसलिए दस काल ग्व परिस्थिति क अनुसार ही विभिन्न पदो क अनुपात का रक्खना चाहिए ।

भारत म विनियोग पत्रा क सम्बन्ध म रिजर्व बैंक न एक परिपत्र म लिखा था कि भारतीय मूची-बद्ध बैंक क विनियोग पत्रा का निक्षेप म औमत अनुपात ५०% है परन्तु टम बान म इकार नहीं किना ना मक्ता कि छात्र बैंक का यह अनुपात इनसे भी कम है । भारत की परिवर्तनशील स्थिति म बका का अपनी माग एक काल इनवारी क ३० % से कम रोकड अथवा माय प्रतिभूतिया रखना अवाञ्छनीय हागा । यदि बैंक का व्यापार अत्यन्त तरल स्वरूप का नहीं है ता इसम अधिक अनुपात हा वाडनाय है । <sup>१</sup> भारतीय बैंकिंग अधिनियम क अनुसार (धारा ५८) प्रत्येक बक का प्रत्येक दिनात म अपनी माग एक काल इनवारी क २०% राकड स्वरण अथवा माय प्रति भूतिया रखना अनिवार्य ह । अन्य पदा क सम्बन्ध म बक भी बैधानिक बधन नहीं है ।

## सारांश

प्रत्येक समावेसित बैंक का वर्षान्त में अपना स्थिति विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य ह । इस स्थिति विवरण में दो पक्ष होते हैं दाहिना एव बाया । दाहिने पक्ष में बैंक की वर्षान्त में सम्पत्ति कितनी है तथा उसका क्या स्वरूप है और बाय पक्ष में बक की देनदारिया कितनी हैं तथा उनका स्वरूप आदि, देना होता है । इन दोनों पक्षों का सतुलन हो जाना ह ।

द्वय नाग — इसकी देखने से यह मालूम होता ह कि बक को कार्यशील पूँजी कहा से मिलती है । इसक विभिन्न पद निम्न हैं —

**पूँजी**—बैंक की अधिकृत, निर्गमित, प्राथित एवं चुकता पूँजी कितनी है। बैंकिंग अधिनियम के अनुसार अधिकृत पूँजी के ५०% प्राथित पूँजी तथा प्राथित पूँजी के ५०% चुकता पूँजी होना अनिवार्य है। इसी प्रकार प्रत्येक बैंक को जो कलकत्ता अथवा बम्बई अथवा दोनों स्थान पर व्यवसाय करता है उसकी चुकता पूँजी एवं निधि मिलाकर १० लाख रुपये से अथवा ५ लाख रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। यही राशि विदेशी बैंकों के लिए क्रमशः २० और १५ लाख रुपये है।

**संचित कोष**—संचित कोष बैंक की चुकता पूँजी के बराबर होना चाहिए। जब तक संचित कोष चुकता पूँजी के बराबर न हो, तब तक उस बैंक को अपने धन का २०% संचित कोष में स्थानान्तरित करना अनिवार्य है। इस कोष में कभी-कभी अक्षों के निर्गमन पर मिलने वाली प्रीमियम भी जमा की जाती है। कुछ बैंक मुक्त-कोष भी निर्माण करते हैं जिसका उल्लेख स्थिति-विवरण में नहीं होता। इस कोष में बैंक की कार्यशील पूँजी गठती है।

**निक्षेप**—सबसे महत्वपूर्ण देनदारी है। ये निक्षेप तीन प्रकार के होते हैं—स्थायी, बचत एवं चल निक्षेप। इनमें बैंक की सबसे बड़ी जिम्मेवारी चल निक्षेपों की होती है क्योंकि ये किसी भी समय किसी भी राशि में निकाले जा सकते हैं। इन निक्षेपों से बैंक को कार्यशील पूँजी मिलती है। परन्तु इनका माँग पर भुगतान होना चाहिए अन्यथा बैंक से जनता का विश्वास टूट जाता है तथा उसका व्यवसाय खतरे में पड़ जाता है। इन निक्षेपों के आपसी अनुपात से व्यापारिक तेजी-मन्दी की जानकारी होती है।

**संग्रहण के लिए प्राप्त वित्त**—इसमें ग्राहकों से संग्रहण के लिए आये हुए चैक, बिल आदि दिखाये जाते हैं जो बैंक संग्रह करके ग्राहकों के खाते में जमा करता है। इनकी राशि बैंक को दूसरे बैंकों से लेनी होती है अतः वास्तव में ये उसकी देनदारी नहीं होती। इसकी राशि सम्पत्ति पक्ष में 'प्राप्य बिल' के पद में दिखायी जाती है।

**स्वीकृत बिलों पर देय**—बैंक ग्राहकों की ओर से जो बिल इत्यादि स्वीकार करता है अथवा बेचान करता है उसकी सयोगिक देनदारी बैंक पर होती है। परन्तु बैंक इस हेतु ग्राहकों से प्रतिज्ञा पत्र आदि ले लेता है, इसलिए यह उसकी वास्तविक देनदारी नहीं होती। इसका सतुलन सम्पत्ति पक्ष में

कम हानि लेता—इस से यह धन में होने वाला लाभ तथा उसका विभाजन किस प्रकार किया गया यह बताते हैं।

सम्पत्ति पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण पद "हस्तस्य एव बैंक में रोकड़" होती है। यह धन बैंक निक्षेपों के भुगतान के लिए अपने पास रखता है तथा अतिरिक्त रोकड़ अन्य बैंकों में तथा रिजर्व बैंक के पास रखता है जिससे आवश्यकता के समय वह काम में लगे जा सके।

याचन एवं अल्पकालीन भुगतान ऋण—ये ऋण बैंक सटोरियों तथा स्टॉक ब्रोकर्स आदि को प्रतिभूति के रूप में रखन पर देते हैं। कुछ ऋण ऐसे होते हैं जो केवल रात के उपयोग के लिए ही दिये जाते हैं तथा अन्य अल्पकालीन ऋण ऐसे होते हैं जिनका भुगतान कंपनी को माँग पर अथवा सूचना पाते ही २४ घण्टे से ७ दिन में करना होता है। बैंक की सुरक्षा का यह दूसरा साधन है।

ऋति एवं कटौती किये हुए ऋण—बैंक जो बिल आदि बाजार से खरीदता है अथवा जिनकी कटौती पर धन देता है उनका समावेश इसमें होता है। इन बिलों को बैंक इस प्रकार खरीदता है जिससे एक के बाव दूसरे बिल का भुगतान मिलता रहे। इससे उसने पैसे रोकड़ का आवागमन बना रहता है। भारत में बिल बाजार विकसित होने में बैंकों की कुल २-२० राति का विनियोग इनमें होता है।

विनियोग—यह बैंक की सुरक्षा का चौथा साधन है। बैंक अपनी राशि का विनियोग प्रथम श्रेणी की सिक्यूरिटियों की खरीद में करता है। जिससे उससे क्षति भी होती रहे तथा सकट समय इनकी जमानत पर अथवा चेक पर धन भी प्राप्त किया जा सके।

ऋण एवं अधिम—इस पद में उन ऋणों का समावेश होता है जो साधारणतः ६ से ६ मास की अवधि के लिए व्यापारियों को दिये जाते हैं। सकट काल में बैंक इन पर निर्भर नहीं रह सकता क्योंकि इनकी माँग करने से एक ओर तो जनता के विश्वास को ठेस लगेगी और दूसरी ओर व्यापारियों को आर्थिक घक्का लगेगा।

प्राप्य बिल तथा स्वीकृत विला पर दायित्व—इन दो पदों का समुलन देय पक्ष के संप्रहण के लिए प्राप्त बिल तथा स्वीकृत बिलों पर दायित्व इन पदों में हो जाता है।

भू-गृहादि—इस शीपेंक में बैंक के भूमि, मकान, फर्नीचर आदि दिये जाते हैं ।

निरूपण—बैंक के स्थिति विवरण से निम्न बातों की जानकारी होती है—

- १ बैंक की आर्थिक स्थिति,
- २ बैंक की व्यापारिक प्रगति,
- ३ सम्पत्ति की सुरक्षा एवं तरलता
- ४ बैंक में जनता का विश्वास, तथा
- ५ देश की व्यापारिक स्थिति ।

## अध्याय ४

# बैंकों की विनियोग नीति

बैंकिंग के स्वरूप से स्पष्ट है कि बैंक का धन की सुरक्षा एवं तरलता का ध्यान रखा जाता है जिससे वह मांग बनदारों का भुगतान किसी भी समय कराने में समर्थ हो सके। यदि बैंक बैंक आता ही उसका भुगतान नहीं करता तो उससे जनता का विश्वास उठ जायगा तथा आर्थिक स्थिति अच्छी हाँत हुए भी उसे व्यापार वन्द करना होगा। साथ ही बैंक सारे धन का अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि उस लाभ भी कमाना होता है। इसलिए वह अपने धन का अन्यत्र विनियोग करता है जिससे उसे अनेक प्रकार की सावधानी की आवश्यकता होती है।

## विनियोग नीति का आधार

साधारणतः बैंक की विनियोग नीति निम्न सिद्धान्तों पर आधारित होती चाहिए —

(१) सम्पत्ति की तरलता—बैंकिंग व्यापार के लिए सम्पत्ति का विनियोग करते समय तरलता का ध्यान रखना अत्यावश्यक है जिससे समय पड़ने पर तत्काल सम्पत्ति को बचकर रोकड़ प्राप्त हो सके। अतएव बैंक को अपने विनियोग अल्पकालीन ऋणों में ही करना चाहिए तथा दीर्घकालीन ऋण नहीं देना चाहिए। अतएव बैंकों का अल्पकालीन निष्पत्ति के धन से दीर्घकालीन ऋण नहीं देना चाहिए। श्री टैनन के अनुसार यथास्वी बकर वह है जो विनिमय बिल तथा रहन का अन्तर जान सकता है।<sup>1</sup> क्योंकि अगर बैंक अपने धन का विनियोग भू-गृहादि के रहन अथवा दीर्घकालीन ऋणों में करता है तो वह संकट काल में तत्काल ही रोकड़ में नहीं बदले जा सकत। इतना ही नहीं अपितु बुद्धिमान बैंक अपने धन का विनियोग निम्न निम्न प्रकार से ऐसा करता है जिससे उसका पास सदैव रोकड़ रहे और विनियोगों के बचने से किसी प्रकार की हानि भी न हो।

<sup>1</sup> *Banking Law & Practice in India* by Tannan

(२) केन्द्रीय बैंक की विनियोग-नीति का पालन—बैंक की विनियोग नीति केन्द्रीय बैंक की विनियोग नीति के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि केन्द्रीय बैंक ये कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर ही वह ऋण देता है। अतः सकट-काल के लिए केन्द्रीय बैंक से ऋण प्राप्त हो सके, इस हेतु बैंक को उन्हीं विनियोग-पत्रों तथा प्रतिभूतियों में धन का विनियोग करना चाहिए जो केन्द्रीय बैंक द्वारा स्वीकृत हों। इसके सकट-काल में केन्द्रीय बैंक से सहायता ली जा सके।

(३) सुरक्षा एवं आय—अपने धन का विनियोग करते समय बैंक को सदैव दूर-दृष्टि से काम लेना चाहिए, उसको अपने धन का विनियोग इस प्रकार के पत्रों एवं प्रतिभूतियों में करना चाहिए, जिनसे उसे अच्छा लाभ मिल सके तथा साथ ही धन भी सुरक्षित रहे। क्योंकि यह धन उसका निजी न होते हुए, निक्षेप रूप में धाहको से उधार लिया हुआ है जिसकी सुरक्षा एवं भुगतान की जिम्मेदारी उस पर है। अतः उसे कभी भी सट्टा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा और तरसता से ही बैंक की आर्थिक स्थिति मजबूत रहती है।

(४) विनियोगों की विविधता—बैंक को अपने धन का विनियोग किसी एक ही प्रकार के उद्योग अथवा व्यापार में नहीं करना चाहिये क्योंकि अगर ऐसा व्यापार या उद्योग घाट में आ जाय तो विनियोगों को खतरा रहता है। इसी प्रकार बैंक अपने सारे ऋण एक ही व्यक्ति को भी न दे क्योंकि उममें भी बराबर भय रहता है। इसीलिए बैंक को चाहिए कि वह अपने विनियोग भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यापार एवं उद्योगों में करे तथा व्यक्तिगत ऋणों में भी इसी नीति का अवलम्ब करे।

(५) निधि की व्यवस्था—बैंक की सफलता निधि की व्यवस्था (management of reserves) पर निर्भर रहती है। बैंक को सदैव अपने पास इतनी रोकड़ रखनी चाहिए जिससे वह उमके ऊपर लिखे गये बैंकों का भुगतान करने में समर्थ हो। इसी प्रकार उसके पास रोकड़ इतनी अधिक भी नहीं होनी चाहिये जो उसके पास बेकार पड़ी रहे और आय न बमाई जा सके।<sup>1</sup>

विनियोग की पद्धति—बैंक अपने धन का विनियोग दो प्रकार से करते हैं—

(१) अन्तर्भूत विनियोग—वह विनियोग जिसमें बैंक को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होता परन्तु जो व्यापार-संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरणार्थ, फर्नीचर, भू-गृहादि, तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का नय। इसी

में रोकड़निधि का भी समावेश होता है क्योंकि यह राकड़ बैंक को सर्वत्र अपने पास मांग देनदारी के भुगतान के लिए रखना आवश्यक है।

(२) लाभकर विनियोग—धन का इस प्रकार का विनियोग जिससे वह लाभ कमा सके। इस प्रकार के विनियोगों में याचित एवं अल्पकालीन ऋण, बिलों की बटौती, प्रतिभूतियों का नया तथा ऋण एवं अग्रिमों का समावेश होता है।

य भिन्न भिन्न प्रकार के विनियोग बैंक किस प्रकार से करत है तथा सुरक्षा की किस धोणी के माध्यम हैं, इसका उल्लेख पहिले किया गया है। परन्तु इन सबमें महत्वपूर्ण एवं प्रथम धोणी का सुरक्षा-साधन राकड़ निधि है।

रोकड़ निधि—रोकड़ निधि वह रोकड़—हस्तान्य एवं बैंक में—है जो बैंक सर्वत्र अपने एवं अन्य बैंकों के पास मांग देनदारियाँ के भुगतान के लिए रखता है। निक्षेपों में स्वामी निक्षेपों के भुगतान के विषय में उम पूरा ज्ञान होता है जिसके लिए उम समय वह अपने पास पर्याप्त राकड़ रख सकता है। इसी प्रकार मजबूत निक्षेपों के विषय में भी उमे पर्याप्त जानकारी होती है, क्योंकि इन निक्षेपों की रकम प्रति सप्ताह कुछ निश्चित राशि में ही निकाली जाती है। किन्तु चल-निक्षेपों की रकम किसी भी समय किसी भी परिमाण में निकाली जा सकती है अतः इन निक्षेपों का दायित्व महत्वपूर्ण होता है जिसके भुगतान के लिए बैंक को पर्याप्त रोकड़ रखनी पड़ती है।

रोकड़ निधि का आधार—रोकड़ निधि कितनी रखनी चाहिए इस सम्बन्ध में विषय नियम नहीं हैं। यह बैंक के पूर्व-अनुभव, दूरदर्शिता तथा उम क्षेत्र की व्यापारिक स्थिति पर निर्भर रहता है। इस सम्बन्ध में निम्न दान विचारणीय है<sup>1</sup> —

(१) निक्षेपों का स्वरूप—जिस स्थान पर निक्षेपों की रकम विनियमित किसी सूचना द्वारा निकाली जाती है उम स्थान पर बैंक का राकड़ निधि की कम आवश्यकता होगी। इसके विपरीत अगर चल-निक्षेपों की रकम अधिक परिमाण में है तो ऐसी स्थिति में ये मांग देनदारी हान के कारण राकड़ निधि अधिक रखनी पड़ेगी।

(२) ग्राहकों की विशेषता—अगर बैंक के ग्राहकों में एक ग्राहक के लिये अधिक है जो सट्टा अथवा स्वयं-विनियमित व्यवहारों में मरत हैं तथा लघु की रकम में बड़ी-बड़ी रहती है तो बैंक को अधिक राकड़ निधि रखनी पड़ती है।

<sup>1</sup> *Banking Law & Practice by Tannan*, pp 196-199.

इसी प्रकार जिन बैंकों ने पास दूसरे बैंकों के निक्षेप रखे हैं उन्हें भी अधिक परिमाण में रोकड़ निधि रखनी होगी।

(३) विनिमय माध्यम का स्वरूप—विनिमय माध्यम के लिए मुद्रा, बैंक या साखपत्रा के उपयोग पर भी रोकड़ निधि की रकम निर्भर रहती है। जिस देश में अधिकतर मुद्रा के माध्यम से विनिमय होता है, उस देश के बैंकों को रोकड़ निधि अधिक रखनी पड़ेगी। इसके विपरीत जिस देश में बैंक का प्रचार हो एवं बैंकों द्वारा ही बहुतायत विनिमय व्यवहारों का भुगतान होता हो वहाँ दैनिक रोकड़ की आवश्यकता कम होगी तथा रोकड़ निधि कम रखनी पड़ेगी।

(४) समाशोधन गृहों ( Clearing Houses ) का विकास—समाशोधन गृहों के होने से बैंक द्वारा हानि वाली बैंकों की देनदारी का आपस में मिलावट हो जाता है। अब जहाँ पर अधिकतर भुगतान बैंकों द्वारा होता है और समाशोधन गृह विकसित है उस देश में बैंकों का भुगतान परस्पर सन्तुलन से हो जाता है। इस कारण रोकड़ की आवश्यकता कम पड़ती है। इसलिए ऐसे देशों में रोकड़ निधि भी कम रखी जाती है, अन्यथा अधिक।

(५) व्यापारिक स्थिति—देश की व्यापारिक स्थिति का रोकड़ निधि में घनिष्ट सम्बन्ध है। जिस देश में विविध प्रकार के कारखाने तथा अन्य प्रकार के व्यापार हैं जिनकी दैनिक रोकड़ की आवश्यकताएँ अधिक हैं, ऐसे देश के बैंकों को रोकड़ निधि अधिक रखनी पड़ती है। इसके विपरीत कृषि प्रधान देशों जहाँ जहाँ दोनो में केवल मौसम में ही रोकड़ की आवश्यकता प्रतीत होती है। इसीलिए ऐसे स्थानों पर मौसम के समय रोकड़ निधि अधिक तथा अन्य काल में कम रोकड़ निधि रखनी पड़ती है।

(६) निक्षेपों की औसत रकम—जिस क्षेत्र अथवा देश में निक्षेपों की औसत रकम अधिक होती है, उस देश में बैंक को अधिक रोकड़ निधि रखनी पड़ती है क्योंकि जब निक्षेप में अधिक रकम रखने वाले ग्राहकों की संख्या कम होती है। इसके विपरीत जहाँ पर ग्राहक अधिक हैं तथा निक्षेपों की औसत रकम कम होती है वहाँ रोकड़ निधि कम रखनी पड़ती है, क्योंकि पड़ती अवस्था में रोकड़ के लिए भी अधिक माँग होगी।

(७) कटौती किये गये बिलों की रकम तथा अग्रिमों (Advances) का स्वरूप—इस पर भी रोकड़ निधि की रकम निर्भर रहती है क्योंकि जो बैंक अपने विनियोग प्रथम श्रेणी के बिलों की कटौती करता है उसको किसी भी समय रोकड़ की आवश्यकता पड़ने पर उन बिलों की पुनः कटौती द्वारा केन्द्रीय

बैंक में रकम मिल सकती है। ऐसी अवस्था में रोकड़ निधि कम रखी जाती है। इनके विपरीत अगर कटौती विलो में कम धन का उपयोग किया जाता है तथा ऋणों के लिए अधिक, तो बैंक को रोकड़ निधि अधिक रखनी पड़ती है, क्योंकि ऋणों का तत्काल ही भगतान उसे नहीं मिल सकता।

(८) जनता की आदतें—जिम देन के लोग अपने पास कम धन रखना ठीक समझते हैं तथा अधिकाधिक धन विनियोग करते हैं या निक्षेप में रखते हैं, वहाँ बैंक के पास सदैव निक्षेप के रूप में धन आता रहेगा तथा कुछ निकाला भी जायगा। इन प्रकार धन के सदैव आते-जाते रहने के कारण उसे रोकड़ निधि कम रखनी होगी। इसके विपरीत जहाँ के लोग विनियोग नहीं करना चाहते तथा अपनी रोकड़ अपने पास ही अधिक रखते हैं, ऐसे स्थान पर रोकड़ निधि अधिक रखनी पड़ेगी।

(९) अन्य बैंको की रोकड़ निधि—बैंको की रोकड़ निधि की रकम अन्य बैंको की रोकड़ निधि की रकम पर निर्भर रहेगी। क्योंकि जिन बैंको के पास रोकड़ निधि अधिक है उनमें जनता का विश्वास अधिक होगा। इसलिए प्रतिस्पर्धा एवं जन-विश्वास सम्पादन करने की दृष्टि से जिनकी रोकड़ निधि कम है, उनको भी अपनी रोकड़ निधि उन्हीं अनुपात में बढ़ानी होगी।

(१०) वैधानिक आवश्यकताएँ—बैंक की रोकड़ निधि सम्बन्धी देश की वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना अनिवार्य है। भारत में मूखीयद बैंक की रिजर्व बैंक के पास अपनी मांग देनदारी का ५०% तथा काल देनदारी का २०% रोकड़ निधि रखना अनिवार्य है। अन्य बैंको को यह रकम अपने पास ही रखनी पड़ती है। इसका उद्देश्य ग्राहकों के निक्षेपों की सुरक्षा करना है।

लाभकर उपयोग—बैंक को लाभ निम्न माधन में मिलता है —

(१) सर्वप्रथम बैंक अपनी पूँजी का अधिकांश भाग विभिन्न प्रकार के ऋण देने में उपयोग करते हैं जिम पर व्याज मिलता है, वह लाभ ही है।

(२) चल-नेत्रों पर अच्छे बैंक व्याज नहीं देने अपितु ग्राहकों में उनके कुल-व्यवहारों (turnover) पर कमीशन लेते हैं यह लाभ होता है। वहीं-वहीं चल-नेत्रों पर व्याज दिया जाता है। भारत में चल निक्षेपों पर साधारणतः १% व्याज प्रत्येक बैंक देना है।

(३) बैंक जिन विलो की कटौती करता है उन पर बट्टा लेता है। यह उसका लाभ होता है।

(४) बैंक अपने ग्राहकों को अनेक प्रकार की सेवाएँ देता है, उसके बदले में वह उनसे कमीशन लेता है। यह भी उसका लाभ होता है।

इस प्रकार जो लाभ बैंक कमाता है उसमें से अन्य बैंकों को दिया हुआ व्याज, रमीशन, निक्षेपों पर व्याज, कर्मचारियों का वेतन एवं धिसावट आदि व्यय निकालने के पश्चात् जो शेष बचता है, वह उसका मुक्त लाभ होता है। जिसमें से कुछ भाग संचित निधि तथा आय-कर एवं जागामी वर्ष के लिए स्थानान्तरित करने के बाद शेष को लाभदायक रूप में बाँटा जाता है।

बैंक के लाभकर विनियोग निम्न है —

(१) याचित एवं अल्पकालीन ऋण—इनका विवेचन अध्याय ३ में किया गया है। भारत में ऐसे ऋणों का परिमाण बहुत ही कम है क्योंकि स्वन्ध-विनिमय तथा बिल-बाजार विकसित न होने से व्यापारिक बिलों का अभाव है। ऐसे ऋण भारत में केवल बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों में ही दिये जाते हैं, जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि। इस रकम में बैंक एक दूसरे से जो ऋण लेते हैं उनका भी समावेश होता है क्योंकि ये ऋण बैंक अपने स्थिति विवरण में आर्थिक स्थिति की मजबूती दिखाने के लिए भी लेते हैं। इस प्रकार के ऋणों पर व्याज की दर बहुत कम अर्थात् ३% से ३½ प्रति वर्ष होती है। ऋण का माँग पर भुगतान न होने पर बैंक अपने पास ऋणी की रहन या बंधक प्रतिभूतियों को देखकर रोकड़ में परिवर्तित कर लेता है।

(२) बिलों का क्रय एवं कटौती—इस प्रकार के ऋणों में प्रथम श्रेणी के प्रतिज्ञा पत्र, व्यापारिक एवं कोप बिल तथा अन्तरराष्ट्रीय एवं देशी बिलों का समावेश होता है। इन बिलों का व्यवहार भी यहाँ बहुत कम होता है क्योंकि भारत में विकसित बिल-बाजार का अभाव है। विनिमय बैंक अवश्य कुछ हद तक अन्तरराष्ट्रीय बिलों का क्रय-विक्रय करते हैं। प्रतिज्ञा पत्रों की कटौती द्वारा भारत में बहुत कम ऋण दिये जाते हैं। बैंक अधिकतर ऐसे ही बिलों को कटौती करते हैं अथवा खरीदते हैं जिनको आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय केन्द्रीय बैंक पुनः कटौती कर देगा, अथवा जिनको स्वन्ध-विनिमय में बिना किसी प्रकार की हानि के बेचा जा सकता है। इस प्रकार विनिमय-बिलों में विनियोग के कारण बैंकों को अपने पास अधिक रोकड़ नहीं रखनी पड़ती। दूसरे, इन बिलों की कटौती एवं क्रय भी बैंक इस प्रकार करते हैं कि एक के बाद दूसरे का भुगतान मिलता रहे और उनके पास रोकड़ की कमी न रहे।

(३) विनियोग-पत्र—यह बैंक की सुरक्षा का तीसरा साधन है। इसमें बैंक अपने धन का बहुत बड़े परिमाण में विनियोग करते हैं। किन्तु विनियोग-पत्रों को खरीदते समय बैंक ऐसे ही विनियोग-पत्रों का क्रय करते हैं जो प्रथम श्रेणी

की प्रतिभूतियाँ हैं। ऐसी प्रतिभूतियों को किसी भी समय बिना किसी हानि के स्वन्ध-विनिमय में बेचकर रोकड़ में बदला जा सकता है अथवा इनकी रहन पर केन्द्रीय बैंक में ऋण लिया जा सकता है। इन प्रतिभूतियों पर ऋण की अपेक्षा व्याज तो कम मिलता है लेकिन विनियोग सुरक्षित एवं तरल होता है। विनियोग-पत्रों में विनियोग का अनुपात भारत में कुल निक्षेपों का ४०%, मनुक्त राष्ट्र अमेरिका में ६०% तथा इंग्लैंड में २७% है। इंग्लैंड में अन्तर-राष्ट्रीय विल-बाजार एवं मुद्रा-मण्डी होने के कारण वहाँ पर अधिकतर विनियोग बिलों की कटौती एवं क्रय में किया जाता है जिसका भारत में अभाव होने से हमारे बैंक अधिकांश घन प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियाँ, कोप-बिलों आदि में लगाने हैं।

विनियोग-पत्रों से लाभ—(अ) स्थिति-विवरण में इनका परिमाण जितना ही अधिक होगा उतनी ही ग्राहकों को निक्षेप की सुरक्षा होनी है तथा विश्वास बढ़ता है।

(आ) बैंक को स्थायी एवं निश्चित आय मिलने का विश्वास रहता है।

(इ) मूल्य में स्थिरता रहती है क्योंकि ये प्रतिभूतियाँ प्रथम श्रेणी की होती हैं।

(ई) आवश्यकता पड़ने पर बैंक इनको किसी भी समय बेचकर रोकड़ में बदल सकता है या केन्द्रीय बैंक में इनकी रहन पर ऋण ले सकता है।

(उ) इनका बाजार-मूल्य आसानी से किसी भी समय मालूम हो सकता है।

(ऊ) इनके स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई वाद उपस्थित नहीं होता।

विनियोग-पत्रों का आधार—बैंक सुरक्षा, स्थायी प्राप्ति, मूल्य के उतार-चढ़ाव की कम सम्भावना तथा किसी भी समय रोकड़ में बदलने की सरलता के कारण अपना विनियोग प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों में करने हैं।

बैंक विनियोग-पत्रों को खरीदते समय निम्न बातों का विचार करता है<sup>1</sup>—

(अ) धन की सुरक्षा—विनियोग-पत्रों को खरीदते समय उसे दूर-दृष्टि से काम लेना चाहिए क्योंकि उसे अपने धन की सुरक्षा और अपने ग्राहकों का विश्वास अग्रिम रखना पड़ता है। उसे इन पत्रों का क्रय कभी तत्कालीन लाभ अथवा मद्दे की दृष्टि में नहीं करना चाहिए।

(ब) विजयशीलता (Marketability)—जो विनियोग-पत्र अथवा प्रतिभूतियाँ बैंक खरीदता है उनको किसी प्रकार की हानि से बेचना भी सम्भव

<sup>1</sup> *Banking Law & Practice in India* by Tannan, pp. 202-204

होना चाहिए। क्योंकि ये विनियोग-पत्र इसलिए खरीदे जाते हैं जिससे कि मकद के समय उनको रोकड़ में बदला जा सके।

(स) मूल्य-स्थिरता—बैंक को यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रतिभूतियाँ वह केवल लाभार्जन की दृष्टि से न खरीदने हुए अपने धन की सुरक्षा के लिए खरीदता है। इसलिए उनको वही प्रतिभूतियाँ खरीदनी चाहिए जिनके मूल्यों में उतार-चढ़ाव शी सम्भावना न हो। क्योंकि बैंकार का उद्देश्य सट्टे में लाभ कमाने का नहीं होता अपितु आरम्भिकता पड़ने पर ही विक्रय करना होना है। मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव होने वाली प्रतिभूतियों से जनता का विश्वास डिंग जाता है जिसमें हानि की सम्भावना अधिक रहती है।

(ब) विनियोग आय—बैंक को विनियोग पत्र खरीदते समय यह देखना चाहिए कि विनियोजित धन पर उसे समुचित एवं स्थायी रूप से लाभान्वित अथवा व्याज मिलता रहे। इसके साथ ही विनियोग-पत्रों की आय की गणना (calculation) भी उसे ठीक से करना चाहिए। इस प्रकार उसे आय का स्थायित्व देखते हुए आय का हिसाब भी लगाना चाहिए। आय का हिसाब लगाते समय उन पर दिया जाने वाला आय-कर, खरीदते समय मिलने वाला बट्टा अथवा दी जाने वाली अपहार प्र-याजि, इसी प्रकार उनके भुगतान पर मिलने वाली प्रव्याजि अथवा लगने वाले बट्टे आदि का समावेश होना चाहिए।

प्रतिभूतियों का वर्गीकरण—सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार होगा —

(अ) सरकारी प्रतिभूतियाँ तथा ऋण-पत्र—इनमें सरकारी कोप-पत्र, राज्य तथा केन्द्र सरकारों के ऋण-पत्र आदि का समावेश होता है। सरकारी कोप-पत्रों की अवधि बहुधा ३ में ६ महीने की होती है तथा इस प्रकार की प्रतिभूतियों एवं ऋण-पत्रों के मूल्यों में उतार चढ़ाव भी सामान्यतः नहीं होते। इसीके साथ उनको किसी भी समय बेचकर रोकड़ में बदला जा सकता है तथा प्रायः में भी स्थिरता रहती है।

(आ) स्रध-सरकारी प्रतिभूतियाँ—इनमें स्थानीय अधिकारियों द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियाँ बॉण्ड आदि का समावेश होता है। ये प्रतिभूतियाँ नगर-पालिका, जिला समिति (district boards), नगर-नियम आदि निर्गमित करती है। सरकारी प्रतिभूतियों के बाद ये सबसे अच्छी प्रतिभूतियाँ होती हैं।

(इ) रेलवे की प्रतिभूतियाँ—इसके बाद रेलवे कम्पनियों द्वारा निर्गमित बॉण्ड, प्रतिभूतियाँ तथा ऋण-पत्रों का क्रमांक आता है। विशेषतः रेलवे कम्प-

नियों की प्रतिभूतियों पर सरकार की गारण्टी होती है जिसमें इनमें विनियोग सुरक्षित होता है तथा इन प्रतिभूतियों के लिए रेन्वे की स्थायी सम्पत्ति जमानत के रूप रहती है।

(ई) जन-उपयोगी सस्थाओं की प्रतिभूतियाँ—जन-सेवा करने वाली कम्पनियों द्वारा निर्गमित प्रतिभूतियों ऋण पत्र आदि का मभावेस होता है। उदाहरणार्थ जन बिजली कम्पनी आदि, जिनको एक स्थान की पूर्ति का एकाधिकार होता है। इनमें विनियोग सुरक्षित होता है क्योंकि एकाधिकार प्राप्त होने में इनको लाभ अवश्य ही होगा, जिसमें आय में भी स्थायित्व रहता है।

(उ) औद्योगिक एवं व्यापारिक कम्पनियों के प्रश, ऋण-पत्र आदि—ये सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अल्प में आते हैं क्योंकि इनके मूल्य में व्यापारिक स्थिति के अनुसार उतार-चढ़ाव होने हैं। इस प्रकार की प्रतिभूतियों में ऋण-पत्र सबसे अधिक सुरक्षित एवं स्थायी आय देने वाला विनियोग होता है। ऋण-पत्रों के लिए कम्पनी की सम्पत्ति रहन रहती है। इसी प्रकार कम्पनी की दिवालिया स्थिति में भी ऋण पत्रधारियों की रकम पहले चुकाई जाती है। ऋण पत्रों के बाद पूर्वाधिकार अथ सामान्य अथ तथा अस्यमित अथ आते हैं। इनके मूल्य में अधिक उतार-चढ़ाव होते रहते हैं अत इनमें बैंक को अपना धन कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरे व्यापारिक स्थिति के अनुसार इनके लाभ घटने-बढ़ने रहन हैं जिसमें आय में स्थिरता नहीं रहती।

(४) ऋण एवं भ्रमि—यह बैंक के धन का चौथा लाभकर उपयोग है। ये ऋण व्यक्ति फर्म तथा कम्पनियों को भिन्न भिन्न रूप में दिये जाते हैं। ऋण देने के कार्य में बैंक का जनता से मोधा सम्बन्ध होता है। इसी समय वह अपनी कुशल नीति एवं समुचित व्यवहार से जनता का विश्वास सम्पादन कर सकता है। इसीके साथ उमकी ऋण-नीति ऐसी होनी चाहिए जिसमें उसे डूबने ऋण के रूप में हानि न उठानी पड़े। बैंक को सबसे अधिक लाभ इसी पद से मिलता है क्योंकि य ऋण ६% में ६% प्रति वर्ष व्याज पर दिये जाते हैं। इसलिए अधिकतर रकम का उपयोग ऋण देने में किया जाता है। इन ऋणों का निक्षेपों से अनुपात ५० में ६० प्रतिशत रहता है। किन्तु इन ऋणों में उतनी मरलता नहीं होती जितनी ऊपर बताये गये विनियोगों में होती है। यद्यपि ऋण इस शर्त पर दिये जाते हैं कि माँग पर भुगतान हो, फिर भी मरुत-काल में ऐसा भुगतान केवल असम्भव ही नहीं, अपितु आर्थिक मरुत को घोरतम बना देता है। इसमें बैंक की आर्थिक स्थिति भी गम्भीर हो जाती है।

इसीलिए इस मद में अपना विनियोग करते समय बैंक की सुरक्षा एवं तरलता के साथ ही ऋणों की माँग पर उनका भुगतान करने की शक्ति और लाभ किस प्रकार अधिक मिलेगा, यह भी देखना पड़ता है। ऋण एवं अग्रिम देते समय निम्न बातों पर विशेष रूप में ध्यान देना पड़ता है —

- (घ) ऋण की सुरक्षा,
- (आ) ऋण की तरलता,
- (इ) ऋण एवं ऋण की जमानत में पर्याप्त अन्तर हो,
- (ई) ऋण अल्पकालीन ही हो,
- (उ) ऋण में अधिक लाभ की सम्भावना,
- (ऊ) माँग पर ऋणों का भुगतान प्राप्त होने की सम्भावना, तथा
- (ए) ऋण का समुचित वितरण, जिसमें एक ही उद्योग अथवा व्यापार में ऋण का केन्द्रीकरण न हो।

ऋण के प्रकार एवं स्वरूप — बैंक दो रूप में ऋण देते हैं—सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण।

सुरक्षित ऋण बैंक किसी न किसी प्रकार की सहायक प्रतिभूतियों (collateral securities) की जमानत पर अथवा अन्य सम्पत्ति के रहन पर देते हैं। व्यापारिक बैंक केवल अल्पकालीन ऋण ही देते हैं, परन्तु उनकी सुरक्षा के लिए वे किसी न किसी प्रकार की जमानत अवश्य लेते हैं। जिन ऋणों पर वैयक्तिक जमानत होती है, उन्हें असुरक्षित ऋण अथवा सामान्य अग्रिम (clean advances) कहते हैं, तथा जिन ऋणों के लिए सहायक प्रतिभूतियाँ अथवा अन्य किसी प्रकार की सम्पत्ति रहन में होती है, उन्हें सुरक्षित ऋण कहते हैं।

सुरक्षित ऋणों पर बैंक कम व्याज लेता है क्योंकि उनमें हानि की सम्भावना बहुत कम होती है तथा उनके मग्न पर भुगतान न होने पर वह प्रतिभूतियों को बेचकर रोकड़ में बदल सकता है। इसके विपरीत असुरक्षित ऋणों पर बैंक अधिक व्याज लेता है।

असुरक्षित ऋण दो प्रकार से दिये जाते हैं—(१) ऋणों के प्रतिज्ञा-पत्र के आधार पर, (२) ऋणों के प्रतिज्ञा-पत्र पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर के आधार पर, जो उस ऋण के भुगतान की जमानत (guarantee) दे। भारत में प्रथम प्रकार के ऋण विशेषतः नहीं दिये जाते किन्तु पाश्चात्य देशों में ऐसे ऋणों का प्रचार बहुत अधिक है। इसी भाँति दूसरे प्रकार के दो नामधारी

प्रतिज्ञा-पत्रों के आधार पर भी ऋण देने की प्रथा हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है। दो नामधारी पत्रों तथा महायक प्रतिभूतियों की रहन के आधार पर ऋण दिया जाता है। क्योंकि,

(१) भारत में ऐसी मात्र एक व्यापारिक मस्याएँ नहीं हैं जो ऋणी की आर्थिक स्थिति की जानकारी दें। इसीलिए बैंकों को ऋण देने में अधिक मावधानी आवश्यक होती है। ऐसी मस्याएँ विदेशों में होन के कारण एक-नामधारी पत्रों के आधार पर भी ऋण दिये जाते हैं।

(२) 'एक व्यक्ति एक बैंक की नीति का अभाव' अर्थात् एक व्यक्ति का लेता एक ही बैंक में हो तथा उस व्यक्ति के सब आर्थिक व्यवहार उसी बैंक के द्वारा हो तो उसे ग्राहक की आर्थिक स्थिति की जानकारी पूर्णरूपेण रहती है।

(३) मुद्रा-मण्डी में ऋणी तथा ऋण देने वालों में परस्पर सम्पर्क का अभाव रहता है।

(४) भारतीय बैंकों की प्रवृत्ति—बड़ी-बड़ी कंपनियों को भी बैंक प्रबन्ध-अधिकर्ता की जमानत के बिना ऋण नहीं देते, जिसमें आर्थिक क्षेत्र में इनका महत्व बढ गया है।

असुरक्षित ऋण दो प्रकार के होते हैं —

(अ) नगद-साख—रोक-ऋण बैंक अपने ग्राहक को अथवा अन्य व्यक्ति को भी देता है। इन ऋणों का चलन सर्वप्रथम स्क्वॉटमैण्ड में हुआ। इन ऋणों को देते समय बैंक ऋणी से प्रतिज्ञा-पत्र लेता है जिस पर ऋणी के तथा अन्य दो मान्य व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं, जिन्हें बैंक जानता हो। इसके साथ ही बैंक ऋणी में अपने गोदाम में व्यापारिक माल वन्धक या रहन रख लेता है और जैसे-जैसे ऋण का भुगतान होता है वैसे-वैसे ऋणी को धान मिलता रहता है। ऋण की राशि एवं अवधि के सम्बन्ध में बैंक एवं ऋणी में समझौता हाता है परन्तु बैंक ऋणी द्वारा केवल वास्तविक ली गयी रकम पर ही व्याज लेता है। किसी भी स्थिति में बैंक न्यूनतम निश्चित व्याज ऋणी से लेता है। यह माधारणतः स्वीकृत ऋण की  $\frac{1}{2}$  राशि पर लिया जाता है। ऋण की रकम ग्राहक के पत्र खाते में जमा नहीं की जाती।

(ब) अधिविकर्ष (Overdraft)—इसमें बैंक और ग्राहक में अधिविकर्ष की राशि एवं अवधि के सम्बन्ध में समझौता होता है। इसके लिए बैंक माधारणतः ग्राहक से प्रतिज्ञा-पत्र लेता है परन्तु अन्य किसी प्रकार की जमानत नहीं लेता। इसमें ग्राहक अपनी जमा राशि में अधिक राशि के चैक काट सकता है

जो राशि उमके चल खाते में नामे (debit) की जाती है। इसमें ऋणी के नाम पर जितनी रकम जमा रहती है उस पर बैंक व्याज लेता है। किसी भी स्थिति में बैंक, अधिविर्ष की न्यूनतम राशि पर व्याज लेना ही है क्योंकि इसमें बैंकर को अपने पाम अधिक रोकड़ निधि रखनी पड़ती है।

अन्य ऋण—अन्य प्रकार के ऋण बैंक केवल प्रतिभूतियों की जमानत अथवा रहन पर देता है। साधारण ऋण ऋणी के लेखे में जमा कर दिया जायगा और ऋण लेने वाला इस रकम को रोकड़ में लेगा। इस पर ऋणी को पूर्ण रकम पर व्याज देना होगा। ऋण की रकम ऋणी मर्दव अपने पास ही रखे, ऐसी बात नहीं है। विशेषतः इस रकम को ऋणी बैंक में अपने खाने में जमा करते हैं तथा आवश्यकतानुसार बैंक वाटते हैं। इसीलिए ग्राहक की दृष्टि से रोकड़-ऋण तथा अधिविर्ष अधिक लाभकर होते हैं। दूसरे रोकड़-ऋण तथा अधिविर्ष में लिए हुए ऋण अल्पकालीन होते हैं तथा अन्य ऋण कुछ दीर्घकालीन होते हैं। तीसरे, अधिविर्ष अथवा रोकड़-ऋण की रकम पर जब तक अवधि पूरी नहीं होती, तब तक बैंक तिखे जा सकते हैं तथा लेखे में समय-समय पर रकम भी जमा की जाती है। तेरी जमा की गयी रकम से रोकड़-ऋण अथवा अधिविर्ष की राशि कम होती है। परन्तु सामान्य ऋणों में यह नहीं होता अपितु पुनः दूसरा ऋण लेना होता है।

भारत में बैंक बिना दो अन्य व्यक्तियों की जमानत के ऋण नहीं देते। कभी-कभी इन ऋणों की सुरक्षा के लिए ऋणी की प्रतिभूतियाँ, स्वर्ण, व्यापारिक माल अथवा अन्य वस्तु-अधिकार-पत्र (documents of title to goods) आदि रहन रखने हैं। इस प्रकार बैंक के अरक्षित ऋण ऋणी की साथ, उनके व्यापार की स्थिति आदि का पूर्ण विचार करने के बाद दिये जाते हैं। ऋणों की सुरक्षा की दृष्टि में बैंक ग्राहक के गत वर्षों के स्थिति-विवरणों का अध्ययन करते हैं तथा ऋणी की वाजार में कितनी मायब है, इसकी जानकारी लेते हैं। भारत में ऐसी कोई भी मस्था नहीं है जो विभिन्न क्षेत्रों के व्यापारियों की मायब का पूर्ण ज्ञान दे सके। इसीलिए भारत में इस प्रकार के ऋण किसी अन्य व्यक्ति की जमानत के बिना नहीं दिए जाते।

व्यक्तिगत जमानत के साथ ही सहायक प्रतिभूतियाँ भी रहन रखी जाती हैं, जिसने किसी भी कारण ऋण का भुगतान न हो तो बैंक इन प्रतिभूतियों को बेचकर अपनी राशि चुका लेता है। भारत में अधिकतर इस प्रकार की प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण दिये जाते हैं।

## सारांश

बैंक की दुहरी जिम्मेवारी होती है। एक ओर तो उसे ग्राहको से भाग होने पर भुगतान करना होता है, दूसरी ओर सम्पूर्ण धन को वह अपने पास भी नहीं रख सकता, क्योंकि उसे लाभ कमाना होता है। अतः उसे विनियोग करना आवश्यक होता है।

बैंक की विनियोग नीति निम्न बातों पर आधारित होती है —

(१) सम्पत्ति की तरलता, (२) केन्द्रीय बैंक की विनियोग नीति का पालन, (३) सम्पत्ति की सुरक्षा एवं आय, (४) विनियोगों की विविधता, (५) निधि की व्यवस्था।

बैंक अपने विनियोग दो प्रकार से करता है—लाभकर एवं अलाभकर। अलाभकर विनियोगों में भू गृहादि, फर्नीचर एवं फिटिंग्स आदि तथा रोकड़ निधि का समावेश होता है।

रोकड़ निधि बैंक को ग्राहको के बैंको का भुगतान करने के लिए अपने पास रखनी पड़ती है जो निम्न बातों पर निर्भर रहती है —

निक्षेपों का स्वरूप ग्राहको की विशेषता, विनियम माध्यम का स्वरूप, समाशोधन गृहों का विकास, व्यापारिक स्थिति, निक्षेपों की औसत राशि, कटौती किये गये बिलों की राशि एवं अग्रिम का स्वरूप, जनता की आदतें, अन्य बैंको की रोकड़ निधि तथा वैधानिक रोकड़ निधि की आवश्यकता।

लाभकर विनियोग—(१) याचित एवं अल्पकाशीन ऋण, (२) बिलों का क्रय एवं कटौती, (३) विनियोग पत्रों का क्रय (४) ऋण एवं अग्रिम।

भारत में वित्त बाजार विकसित न होने से एवं स्कंध-विनियम कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही सीमित होने से बैंक का विनियोग पहिली दो मही में बहुत कम होता है। विनियोग-पत्रों को खरीदने से बैंक में जनता का विश्वास रहता है, उसे आय की निश्चितता तथा तरलता रहती है और साथ ही इनके बाजार मूल्य आसानी से मातृम किये जा सकते हैं।

विनियोग-पत्र खरीदने में बैंक को निम्न बातों की ओर ध्यान देना चाहिए—सुरक्षा, विनियोग पत्रों की विषयशीलता, मूल्यस्थिरता तथा आय।

इस दृष्टिकोण से क्रमशः सरकारी प्रतिभूतियाँ, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियाँ, रेलवे एवं जनउपयोगी कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ आती हैं। औद्योगिक एवं व्यापारिक कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ में सुरक्षा का अभाव रहता है।

ऋण एवं अग्रिम देते समय बैंक को इनकी सुरक्षा, तरलता, ऋण एवं जमानत में अन्तर, अल्पकालीन अवधि, अधिक लाभ एवं ऋणों का माँग पर भुगतान होने की सम्भावना एवं विविधता पर अधिक ध्यान देना चाहिए।

बैंक सुरक्षित एवं असुरक्षित ऋण देता है परन्तु भारत में असुरक्षित ऋण नहीं के बराबर दिये जाते हैं। असुरक्षित ऋणों में रोक ऋण एवं अधिविकर्ष का ही प्रचलन है।

सुरक्षित ऋण व्यक्तिगत जनता के अलावा अन्य सम्पत्ति अथवा प्रति-भूतियों को जमानत पर दिये जाते हैं।

## जमानत-अनुबंध तथा सहायक प्रतिभूतियाँ

बैंक ऋण देने के पूर्व ऋण की सुरक्षा के लिए जमानत लेते हैं जो दो प्रकार की होती है —

(१) व्यक्तिगत जमानत—जब ऋणी अपने प्रतिज्ञा-पत्र के अनिर्विण्ण अन्य किसी व्यक्ति अथवा न्यक्तिया की जमानत बैंक का दना है, तब उसे व्यक्तिगत प्रतिभूति कहत हैं।

(२) सहायक जमानतें—व्यक्तिगत जमानत के अतिरिक्त जब ऋणी कम्पनियों के अत, ऋण-पत्र अथवा अन्य किसी प्रकार की प्रतिभूतिया बैंक के पाम जमानत के लिए रखता है, तब उन्हें सहायक प्रतिभूतियाँ कहत है।

व्यक्तिगत जमानत—इसमें ऋणी अथवा उसके माफत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बैंक को जमानती अनुबंध दिया जाता है। यह जमानत दो प्रकार की होती है—(१) निश्चित (specific) जमानत में जमानतदार किसी विशेष एव निश्चित रकम की ही जमानत देता है। (२) चल (continuing) जमानत में ऋणी की पूर्ण या कम-अधिक होन वाली राशि के लिए जमानत दी जाती है। इस प्रकार की जमानत में जमानतदार पर ऋण के सम्पूर्ण भुगतान की जिम्मेदारी रहती है, किसी निश्चित रकम की नहीं।

भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुमार बैंक जा जमानत लेता है वह मौखिक तथा लिखित हो सकती है। किन्तु बैंक का सदैव लिखित जमानत लेनी चाहिए जिससे जमानत की शर्तों में परिवर्तन न हो सके। बैंक को जमानत स्वीकार करन के पूर्व जमानतदार की मास एव आर्थिक स्थिति की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

जमानती अनुबंध—जमानती अनुबंध में 'किसी तीसरे व्यक्ति के दोषों रहन पर उमका वायदा पूर्ण करन का, अथवा उसके ऋण व भुगतान की जिम्मेदारी कोई व्यक्ति लेना है। इन अनुबंधों में ऋणी की ओर में यदि जमानतदार किसी ऋण का भुगतान करता है ता उसको ऋणदान के अधिकार प्राप्त हो जाते है। अर्थात् मूल ऋणी स वह अपनी रकम का भुगतान कानून स

ले सकता है। इन अनुबन्धा में जो व्यक्ति जमानत देता है उसे जमानतदार, जिसके लिए जमानत दी जाती है उसे ऋणी, तथा जिसको जमानत दी जाती है उसे (बैंक को) ऋणदाता कहते हैं। इन अनुबन्धों में जमानतदार की जिम्मेदारी तभी होती है जब मूल ऋणी दोषी है, इसलिए प्राथमिक जिम्मेदारी मूल ऋणी की तथा गौण जिम्मेदारी जमानतदार की होती है। स्पष्ट है कि इन अनुबन्धा में तीन पक्ष होते हैं—पहला ऋणी, जिसकी ऋणदाता के प्रति प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, दूसरा जमानतदार, तथा तीसरा ऋणदाता।

**जमानती अनुबन्ध लेना**—बैंक का अपन ऋण की सुरक्षा के लिए जमानती-पत्र (form of guarantee) अच्छे ढङ्ग से—जिसमें कोई वैधानिक दोष न रहे—बनाना चाहिए। यथासम्भव इस पत्र में जमानत की रकम साफ-साफ होनी चाहिए कि जमानत ऋणी के पूरे ऋण अथवा ऋण के किसी विशेष भाग के लिए दी गई है, अथवा उसकी क्या सीमा है। यथासम्भव इस प्रकार की जमानत ऋणी के पूरे ऋण के लिए लेनी चाहिए जिसमें ऋणी की मृत्यु अथवा उसके विवालिया होने पर जमानतदार में पूरा ऋण वसूल हो सके। इसलिए बैंक छपे हुए जमानती अनुबन्ध पत्र रखते हैं, जिसको जमानतदार द्वारा भरवाया जाता है, जिससे वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त न हो सके।

**जमानत लेते समय सावधानी**—(१) बैंक का जमानतदार की सात एवं आर्थिक स्थिति की पूरा रूप से जांच करा लेनी चाहिए जिसमें उसको किसी हानि की सम्भावना न रहे।

(१) भारतीय अनुबन्ध विधान के अनुसार नावालिंग, पागल तथा जिनका अनुबन्ध के समय दिमाग खराब था, ऐसे व्यक्तियों के साथ अनुबन्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें अनुबन्ध करने की योग्यता नहीं होती। दूसरे, इनके साथ होने वाले अनुबन्ध व्यर्थनीय (voidable) होते हैं।

(२) विवाहित स्त्रियों की जमानत स्वीकार करने समय भी उसे यह सावधानी रखनी चाहिए कि 'जमानत किसी दवाव के कारण नहीं दी गई है' इसका स्पष्ट उल्लेख जमानती-अनुबन्ध में होना चाहिए।

(४) जमानत उसी विवाहित स्त्री की होनी चाहिए जिसके पास स्वतन्त्र निजी सम्पत्ति हो एवं जिस पर उसका ही अधिकार हो, जैसे भारत में 'स्त्री धन'।

(५) सामेदारी फर्मों की जमानत करने के पूर्व उनके व्यापार का स्वरूप तथा फर्म अपने सामान्य व्यापार में जमानती अनुबन्ध कर सकता है या नहीं

यह दाय नत्ता चाहिए । दूसरे साभेदारी विधान के अन्तर्गत किसी साभेदार की मृत्यु अथवा अवकाश से साभेदारी का सविधान (constitution) भी बदल जाता है । इसलिए उस किसी भी साभेदार की मृत्यु अथवा अवकाश की सूचना मिलन ही उस फर्म से नया जमानती अनुबन्ध लेना चाहिए और जब तक यह नहीं मिलता तब तक मूल ऋणी का खाना बन्द कर देना चाहिए ।

(६) रजिस्टर्ड कम्पनियाँ जमानत दत्त समय तक की कम्पनी के मीमानियम तथा अन्तर्नियमों का दाय नत्ता चाहिए कि इस प्रकार का अधिकार उन्हें है अथवा नहीं । अगर उनको ऐसा अधिकार नहीं होगा तो जमानत के लिए केवल कम्पनी के मंचालक ही जिम्मेदार रहेगें न कि कम्पनी ।

बैंकर की जिम्मेदारी—(१) जमानती अनुबन्ध में इस अनुबन्ध के सम्बन्ध में किसी भी बात को जमानतदार से छिपाना नहीं चाहिए और न इस प्रकार का कोई व्यवहार बैंक के निम्न जमानतदार की गलत धारणा (misrepresentation) हो जाय क्योंकि उसी स्थिति में जमानतदार अपनी जिम्मेदारी की पूर्ति के लिए विधान द्वारा वाज्य नहीं होता । वास्तव में बैंक का ऋणी की स्थिति के विषय में जमानतदार का किसी भी प्रकार की सूचना देने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु ऐसी सूचना जो जमानती अनुबन्ध या प्रत्यक्ष सम्बन्धित एवं गहत्व की है उसे जमानतदार का बताना की जिम्मेदारी बैंक की है ।

(२) अगर ऋणी की आर्थिक स्थिति के बारे में जमानतदार कोई भी सूचना बैंक से पूछता है तो वह भी उस इस प्रकार खताना चाहिए जिसमें ऋणी की सख्त का धक्का न पहुँचे तथा वास्तविक स्थिति का ज्ञान भी हो ।

(३) जमानत में जमानतदार की अनुमति बिना अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो जमानतदार परिवर्तन के बाद के ऋणा एवं व्यवहार के दायित्व में मुक्त हो जाता है । इसलिए अनुबन्ध में निम्न प्रकार के परिवर्तन जमानतदार से सूचना दिए बिना तथा उसके सम्मति बिना नहीं करने चाहिए । परन्तु अगर जमानतदार न इस प्रकार परिवर्तन करने का अधिकार बैंक को दिया हो तो परिवर्तन हो सकन है । ऐसे परिवर्तन की सूचना जमानतदार को दी जाना चाहिए ।

जमानतदार के अधिकार—(१) जमानती अनुबन्ध में जमानतदार का जमानत देने समय अपना दनदारी के सम्बन्ध में बैंक से पूरी जानकारी प्राप्त करने का पूरा अधिकार होगा है । परन्तु वह ऋणी के खान का नहीं दाय सकता और न उसके खान का हिमाय ही न सकता है ।

(२) जमानती अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार चल-जमानत सूचना देने के वाद स्थगित करा सकता है जिससे उसका उत्तरदायित्व सीमित हो जाता है। इस प्रकार जब चल-जमानत का अन्त जमानतदार की ओर से किया जाता है, तब बैंक को अपने ऋणी को उसकी सूचना देनी चाहिए, जिससे उसके ऋण सुरक्षित रहे, अन्यथा सूचना की अवधि समाप्त होते ही बनेटन का नियम लागू हो जाता है। इस नियम के अनुसार ऋणी द्वारा किया गया भुगतान ऋण को कम करता है।

(३) मृत्यु की सूचना के दिन से भी जमानतदार की जिम्मेवारी का अन्त हो जाता है।

(४) जब किसी ऋण का भुगतान ऋणी की ओर से जमानतदार करता है तो उसको ऋणदाता के (अर्थात् बैंक के) सब अधिकार प्राप्त हो जाते हैं तथा बैंक के पास जो प्रतिभूतियाँ आदि जमानत के रूप में जमा हों उन पर भी जमानतदार का अधिकार हो जाता है। ऋण की जमानत अगर आंशिक है तो उस अनुपात में ही उसे प्रतिभूतियों पर अधिकार मिलेगा। इसी प्रकार अगर जमानतदार अधिक है तो उनको उनकी जमानत के अनुपात में ऐसे अधिकार मिलेंगे। इसी प्रकार यदि किसी एक जमानतदार को ऋण के भुगतान में अधिक रकम देनी पड़ती है तो जितनी रकम उसने अधिक दी है वह उस रकम को अन्य जमानतदारों से प्राप्त कर सकता है।

### सहायक प्रतिभूतियाँ

सहायक प्रतिभूतियाँ उस मूर्त (tangible) सम्पत्ति को कहते हैं जो बैंक के पास ऋण की सुरक्षा के लिए रखी रहता है, ताकि ऋण के भुगतान न होने पर उस सम्पत्ति के विक्रय द्वारा ऋण का भुगतान प्राप्त किया जा सके। इसलिए बैंक अपने ऋण की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत जमानत के अतिरिक्त इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ जमानत के रूप में लेते हैं। ये प्रतिभूतियाँ देश एवं व्यापारिक स्थिति के अनुसार भिन्न-भिन्न स्थान में भिन्न-भिन्न होती हैं। उदाहरणार्थ बतकत्ता, वस्त्र-भंड आदि बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों में परम प्रतिभूतियाँ (guilt edged securities) तथा कंपनियों के हिस्से आदि जमानत में लिए जाते हैं। किसी निर्माण केन्द्र में कंपनियाँ ऋण प्राप्त करने के लिए अपना कच्चा मान अथवा स्थायी सम्पत्ति जमानत में देते हैं। अन्य व्यापारी वर्ग जीवन बीमा, वस्तु अधिकार-लेख (documents of title to goods) आदि जमानत में देते हैं। इस प्रकार जितने प्रकार की प्रतिभूतियाँ होंगी, उतनी ही बैंक को कम

हानि की सम्भावना रहणी । जो ऋण वैयक्तिक जमानत व अनिरिक्त सहायक प्रतिभूतिया में प्रशुत सुरक्षित रहने ह उन ऋणा का रक्षित (secured) ऋण कहते हैं ।

सहायक प्रतिभूतियों का स्वरूप—यह तीन प्रकार से सहायक प्रतिभूतिया पर अधिकार लेता है —

(१) ग्रहणाधिकार (Lien)—यह जोर ग्राहक के सम्बन्ध का एक विनिर्देश है कि वह का ग्राहक के बात के सामान्य तथा का (ऋण की) जमानत के लिए ग्राहक द्वारा रखी हुई प्रतिभूतिया सम्पत्ति आदि पर सामान्य ग्रहणाधिकार मिलता है । ग्रहणाधिकार के लिए किन्ना प्रकार के समझौते की आवश्यकता नहीं रहती बल्कि यह ध्वनि (implied) होता है ।<sup>१</sup> वह का ग्रहणाधिकार ग्राहक की उन सब प्रतिभूतिया पर रहता है जो उसके पास सामान्य वैविध व्यापार में आती है । परन्तु यदि यही प्रतिभूतिया उसके पास किसी विनिर्दिष्ट हस्त के लिए आता है तो उन पर उस ग्रहणाधिकार नहीं होता । परन्तु वह उह ग्राहक की सम्पत्ति बिना बच नहीं सकता । इनका विक्रय करने करने के लिए उसे ग्राहक के विरुद्ध न्यायालय से ऋण भुगतान के लिए विनय पत्र (decree) प्राप्त कर लेना चाहिए । ग्रहणाधिकार ध्वनित अधिक हानि के कारण वह के ग्रहणाधिकार में आइ हुई प्रतिभूतिया अथवा वस्तुआ का अपने ग्राहक का पर्याप्त सूचना देने के बाद ऋण के भुगतान में बच सकता है एवं इसके लिए वैधानिक स्वीकृति भी है ।

जो वस्तुएं अथवा प्रतिभूतिया उसके पास सुरक्षा के लिए रखा जाती है उन वस्तुआ पर उस ग्रहणाधिकार नहीं होता क्योंकि ये वस्तुएं उसके पास एक विनिर्दिष्ट हस्त सुरक्षा के लिए रखी जाती है । परन्तु अगर वह के मान बचाने साध्य (regouable) प्रतिभूतिया में व्यापार करने का अधिकार ग्राहक का आर स है तो उन पर ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है । बचाने साध्य प्रतिभूतिया उसके पास भद्रहण के लिए दी जाती है—जैसे विनिर्भय विना चक्र बाह्य बंध (bearer bonds) प्रतिष्ठापन आदि—उन पर भी उस ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है । इसके विपरान अगर उसने पास बाह्य बंध अथवा लाभदा रूपन कबल सुरक्षा के लिए रखे गये हैं किन्तु वह का भद्रहण के लिए उह कानून का अधिकार न हो तो उस पर ग्रहणाधिकार नहीं होगा । इसी प्रकार अगर किन्ना ग्राहक के सामान्य तथ के अनिरिक्त अन्य विनिर्दिष्ट हस्त के लिए

<sup>१</sup> Sec 171, Indian Contract Act

निक्षेप लेखे (deposit accounts) है तो इस दृष्टि में विनिष्ठ लेखों पर उसे ग्रहणाधिकार नहीं होता। उन प्रतिभूतियों पर भी जो किसी विशिष्ट ऋण के जमानत के रूप में रखी गयी हैं, बैंक का सामान्य ग्रहणाधिकार नहीं होता, किन्तु उसका ग्रहणाधिकार उस विशिष्ट ऋण के भुगतान तक ही सीमित रहता है। उस ऋण के भुगतान के बाद यदि वही प्रतिभूतियाँ बैंक के पास रहे तथा ग्राहक उनको वापिस न ले तो उन प्रतिभूतियों पर भी उसे ग्रहणाधिकार मिलता है। इसी प्रकार बैंक के पास दैनिक व्यापार में ग्राहक का जो धन बिना किसी विशिष्ट उद्देश्य के आयेगा उस पर भी उस ग्रहणाधिकार है। किन्तु अगर ग्राहक किसी फर्म का भागी है तो फर्म के ऋण के लिए बैंक का उसके वैयक्तिक लेखों पर ग्रहणाधिकार नहीं मिलता। दूसरे, ग्राहक की मृत्यु के बाद उसके प्रतिनिधि द्वारा लिये हुए ऋण अथवा अधिविक्रय का भुगतान करने के लिए मृत ग्राहक के लेखों का ग्रहणाधिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार ग्राहक के ऋणों के लिए ग्राहक द्वारा संचालित प्रत्यास लेखे (trust account) पर भी बैंक को ग्रहणाधिकार प्राप्त नहीं होता।

बैंक का यह ग्रहणाधिकार काल-मर्यादा नियम से बाधित नहीं होता।

(२) रहन—जिस समय किसी सम्पत्ति का ऋण की जमानत के लिए बन्धक किया जाता है उस समय उसे रहन कहते हैं। इस प्रकार रहन में सम्पत्ति का अधिकार प्राधायक (mortgagor) द्वारा हस्तान्तरित किया जाता है। रहन दो प्रकार का होता है—वैधानिक (legal), तथा न्याय्य (equitable)। वैधानिक रहन में सम्पत्ति के अधिकार प्राधायक (mortgagor) से प्राधिमान (mortgagee) को मिल जाते हैं तथा ऋणी के दोषी रहने पर बैंक उसे बेच सकता है। उसी प्रकार ऋण के पूर्ण भुगतान पर प्राधायक को रहन सम्पत्ति पर पुनः पूर्ण अधिकार मिल जाता है। इस प्रकार प्राधायक के पुनः अधिकार को “भुगतान की समता” (equity of redemption) कहते हैं। न्याय्य रहन में बन्धक वस्तु का अधिकार प्राधायक (ऋणी) के पास ही रहता है किन्तु न्यायालय में विक्रय प्राप्त करने पर ही प्राधिमान (mortgagee) बैंक रहन सम्पत्ति को बेच सकता है। इस प्रकार का न्याय्य रहन वस्तु-अधिकार प्रलेख अथवा किसी स्थायी सम्पत्ति के अधिकार प्रलेखकी जमानत निर्माण में होता है जिसमें उसकी जमानत ली जा सके। न्याय्य रहन लेखों की स्वीकृति के लिए १००) १० अथवा इनसे अधिक ऋण के लिए मुद्रा-कर लगता है तथा दो गवाहों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। इस प्रकार अस्थायी सम्पत्ति का न्याय्य

रहना अधिक परिमाण में बैंक को स्वीकृत नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें उमकी अधिक रकम का विनियोग होने में सुरक्षा की सम्भावना कम होती है।

(३) बन्धक (Pledge)—बन्धक में किसी वचन की पूर्ति अथवा ऋण के भुगतान के लिए वस्तुएँ जमानत के रूप में रखी जाती हैं।<sup>1</sup> बन्धक अनुबन्धों में सम्पत्ति अथवा प्रतिभूतियों का अधिकार बन्धकदाता (pledgor) के पास रहता है किन्तु सम्पत्ति बन्धकी (pledgee) के पास जमानत के लिए रहती है। इन अनुबन्धों में वस्तुओं का बन्धकी के पास जमानत की तरह रहना आवश्यक है। वचन में बन्धकी निश्चित तिथि के बाद अपने ऋण के भुगतान की अनुचित सूचना के बाद बन्धक सम्पत्ति का वच सकता है। अथवा ऋण के भुगतान के लिए ऋणी दावा कर सकता है जिस दाना में सम्पत्ति उसी के अधिकार में रहनी चाहिए। अगर ऋण के भुगतान के लिए सम्पत्ति का मूल्य कम पड़ता है तो शेष रकम का भुगतान ऋणी (बन्धकदाता) को करना होगा और यदि वास्तविक ऋण में अधिक रकम (सम्पत्ति के विक्रय से) प्राप्त होनी है तो बन्धकी को यह रकम बन्धकदाता को लौटानी होगी। किन्तु यदि इस प्रकार की बन्धक सम्पत्ति पर उसे ग्रहणाधिकार है तो इस अतिरिक्त रकम को वह अन्य ऋणा के भुगतान के लिए उपयोग में ले सकता है।

(४) उपप्राधीयन (Hypothecation)—उपप्राधीयन का बन्धक में बहुत कुछ साम्य है। इसमें न स्वामित्व और न अधिकार ही ऋणदाता को दिया जाता है किन्तु उपप्राधीयन पत्र (letter of hypothecation) द्वारा बैंक को उपप्राधीयित वस्तुआ पर प्रभार (charge) मिलता है। इस प्रकार की जमानत में ऋणदाता को समान प्रभार मिलता है क्योंकि इन वस्तुआ से विनय द्वारा ऋणदाता अपने ऋण का भुगतान प्राप्त कर सकता है। अगर वस्तु का मूल्य ऋण के भुगतान के लिए कम रहे तो ऋणों का कमी पूरी करनी पड़ती है। सहायक प्रतिभूतियाँ लेते समय सावधानी

बैंक ऋण की जमानत के लिए प्रतिभूतियाँ स्वीकार करते समय निम्न सावधानी रखना चाहिए—

१ उपाधि की सरलता (सुगमता)—जो प्रतिभूतियाँ बैंक स्वीकृत करता है वे ऐसी हों जिसकी उपाधि अथवा स्वामित्व बिना किसी प्रकार की अड़चना के प्राप्त हो सके।

२ हस्तांतरण की सुगमता—प्रतिभूतियाँ गम्भीर होनी चाहिए जो उनके

<sup>1</sup> Indian Contract Act 1892

अथवा किसी अन्य के नाम पर बिना किसी प्रकार के व्यय अथवा अडचनों के हस्तान्तरित हो सके।

३. **समुचित मूल्य-स्थिरता**—प्रतिभूतियाँ जो जमानत में ली जायें वे ऐसी हों जिनके मूल्य में स्थिरता रहे तथा अवमूल्यन की सम्भावना कम हो। क्योंकि प्रतिभूतियाँ के अवमूल्यन में बैंक को हानि की सम्भावना रहती है।

४. **विक्रयशीलता**—बैंक जो प्रतिभूतियाँ जमानत में लेता है उन्हें ऋण के भुगतान में होने पर बेचना है जिसमें ऋण दी हुई रकम प्राप्त कर सके। अतः उनके पास रखी हुई प्रतिभूतियाँ ऐसी होंगी चाहिए जो बाजार में बिना हानि के सुगमता से बेची जा सकें।

५. **ऋण एवं जमानत के मूल्य में पर्याप्त अन्तर**—ऋण तथा जमानत रखी हुई प्रतिभूतियाँ के मूल्य में पर्याप्त अन्तर होना आवश्यक है जिसमें अवमूल्यन आदि से होने वाली हानि पूरी हो सके। इसलिए प्रतिभूतियाँ लेते समय उनका मूल्यांकन सावधानी से करना चाहिये। ऋण की राशि तथा प्रतिभूतियों के मूल्य में इतना अन्तर रखना चाहिए जिसमें मूल धन तथा ध्याज दोनों की सुरक्षा हो सके।

६. **बैनदारी का अभाव**—जमानत रखी हुई प्रतिभूतियाँ अन्य किसी प्रकार के प्रभार (charges) में मुक्त होनी चाहिए जिससे बैंक को उन पर पूर्ण अधिकार मिले। इसलिए अशुद्ध ऋण-पत्र आदि लेते समय उसे यह देखना चाहिए कि वे पूर्ण चुकता हैं तथा स्थायी सम्पत्ति की रहन में वे किसी दूसरे के पास रहन नहीं है।

७. **उपाधि (Title) की सुरक्षा**—जमानती वस्तु पर जो उपाधि बैंक को मिलती है वह पूर्णतः वैधानिक है, यह भी देखना चाहिए। यदि शाहूक अथवा ऋणी की उपाधि सदोप है, तो उनके हस्तान्तरण में बैंक की सदोप उपाधि ही रहेगी। इसलिये बैंक को उपाधि की सुरक्षा की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

**प्रतिभूतियों के प्रकार**

उक्त सावधानियों के अतिरिक्त कुछ प्रतिभूतियाँ ऐसी हैं जिनमें उनकी भिन्नता के कारण अन्य बातें विचारणीय होती हैं। ये प्रतिभूतियाँ निम्न हैं—

१. **स्कन्द विनिमय प्रतिभूतियाँ**

इन प्रतिभूतियाँ में उन सब परम प्रतिभूतियों का समावेश होता है जो सरकार, मम सरकारी सस्थाओं तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा नियमित होती

हैं। औद्योगिक गस्त्याओं द्वारा निर्गमित कम्पनियों के अश्रु ऋण-पत्र आदि का इनमें समावेश होना है। इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ बैंक के पास जमानत के लिए अधिन आती हैं।

**लाभ—(अ) दिव्यशीलता—**स्कन्ध विनिमय प्रतिभूतियाँ सुगमता से किसी भी समय स्कन्ध विनिमय में बेची जा सकती हैं। विशेषतः परम प्रतिभूतियाँ, अच्छी कम्पनियों के अश्रु ऋण-पत्र आदि। इसी प्रकार आवश्यकता पड़ने पर इनकी जमानत पर अन्य बैंकों में ऋण लिया जा सकता है। इस प्रकार की सुविधा अन्य वस्तुओं की जमानत में नहीं होती।

**(ब) मूल्यस्थिरता—**स्कन्ध विनिमय में विभिन्न प्रतिभूतियों की दर जानी जा सकती है। क्योंकि ये नियमित रूप से खरीदी अथवा बेची जाती हैं। साथ ही उनके मूल्यों में उतार-चढ़ाव की सीमा भी मालूम हो सकती है। अच्छी प्रतिभूतियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव सीमित होते हैं जिसमें बैंक को ऋण एवं जमानत के मूल्य में अन्तर निश्चय करने में सुगमता होती है।

**(स) उपाधि की सुगमता—**ऐसी प्रतिभूतियाँ की उपाधि स्पष्ट होने के कारण बैंक को उपाधि की सुरक्षा रहती है और वचानसाध्य प्रतिभूतियों के विषय में जमानतदार की उपाधि मद्देन रहते हुए भी मूल्य-धारी (holder for value) होने कारण बैंक को पूर्ण एवं वैधानिक उपाधि मिलती है। इसी प्रकार अपरकाम्य प्रतिभूतियों के हस्तान्तरण में भी विशेष अमुविबाध नहीं आती क्योंकि उनका हस्तान्तरण, हस्तान्तरण-लेख द्वारा किया जा सकता है तथा जमानतदार की उपाधि मद्देन अथवा निर्दोष है श्रद्धा भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है।

**(द) ये प्रतिभूतियाँ बैंक के ऋणा के लिए अच्छे सुरक्षा के माधन का कार्य करती हैं।**

**प्रुदियाँ—(अ) आशिक चुकता—**अगर इस प्रकार प्रतिभूतियाँ जगत चुकता हैं तो उनमें अदत्त भाग की खम माग होने (call) पर बैंक को देनी पड़ेगी। इसलिए बैंक को पूर्णतः चुकता प्रतिभूतियाँ ही स्वीकार करनी चाहिए।

**(ब) हस्तान्तरण में कष्ट—**प्रतिभूतियों का हस्तान्तरणी (transferee) होने के कारण यदि हस्तान्तरक (transferor) के हस्ताक्षर जाली हों तो बैंक क्षति-पूर्ति के लिए उत्तरदायी होना है। इसलिए बैंक को हस्तान्तरण-लेख पर हस्तान्तरक के हस्ताक्षर अपने कार्यालय में बरखाने चाहिए।

**(स) ग्रहणाधिकार की सूचना—**बैंक के पास प्रतिभूतियाँ आने ही यदि वह अपने ग्रहणाधिकार की सूचना प्रतिभूतियों के निर्गमन करने वाली कम्पनी का

नहीं देता तो उसका ग्रहणाधिकार कम्पनी के ग्रहणाधिकार में बाधित हो जाता है। पारंपद-अन्तनियमों के अनुसार कम्पनी को याचित (called) पूँजी का भुगतान न होने पर उन अशा एवं प्रतिभूतियों पर ग्रहणाधिकार मिलता है। इसलिए ऐसे अशों की जमानत लेने समय बैंक को अपने ग्रहणाधिकार की सुरक्षा के लिये ग्रहणाधिकार की सूचना सम्बन्धित कम्पनी को देनी चाहिए।

(४) मूल्यों में उतार-चढ़ाव—जिन प्रतिभूतियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव होते हैं उन पर ऋणी द्वारा ऋण-जमानत-अन्तर पर्याप्त रखा जा रहा है, यह भी उसे देखना चाहिए। अन्यथा इस अन्तर की कमी से उसे हानि होने की सम्भावना रहती है। अतः बैंक को सभी कम्पनियों की प्रतिभूतियाँ नहीं लेनी चाहिए जिनके मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव होने है। दूसरे, ऋण-जमानत-अन्तर पर्याप्त रखने के लिए उसको प्रतिभूति के मूल्यांकन में सावधानी में काम लेना चाहिए।

(५) उपाधि की स्पष्टता—अपरनाम्य प्रतिभूतियों के हस्तान्तरण के समय यदि हस्तान्तरण की उपाधि सदोष है तो हस्तान्तरिणी की उपाधि भी सदोष रहती है। अतः इस सम्बन्ध में सावधानी बरतनी चाहिये।

## २ वस्तु अथवा वस्तु-अधिकार प्रलेख

व्यापारिक अथवा आयात-निर्यात केन्द्रों में बैंक विशेषतः उत्पादन (produce), वस्तु (goods) अथवा वस्तु अधिकार प्रलेख (documents of title to goods) आदि की जमानत पर ऋण देते हैं। इस प्रकार की जमानत स्वीकार करने के लिए बैंक को इनके सम्बन्ध में विशेष अनुभव एवं ज्ञान होना चाहिए। बैंक को ऐसी प्रतिभूतियाँ स्वीकार करने के पूर्व निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए—

(१) वस्तु का प्रकार—सर्वप्रथम बैंक को वस्तु का प्रकार देखना चाहिए। बैंक किसी भी वस्तु के प्रत्येक सवेष्ट (package) को नहीं देख सकता और न देखने के लिए उसके पास समय ही रहता है। अतः बैंक को देखना चाहिए कि उसका भावी ऋणी जो इन वस्तुओं की जमानत दे रहा है ईमानदार है तथा उसकी माय अच्छी है। ऐसी वस्तुओं को स्वीकार करते समय प्रत्येक सवेष्ट का सवेष्टन-पत्र (packing note) देख लेना चाहिए। अच्छी कम्पनियाँ माल भेजने समय इस प्रकार के सवेष्टन पत्र अथवा बीजक की प्रति प्रत्येक सवेष्ट में रखते हैं।

(२) विक्रयशीलता एवं टिकाऊपन—वस्तुएँ ऐसी हैं जिनमें किसी भी प्रकार

में खराबी होने की सम्भावना नहीं है, यह जानने के लिए उसे उत्पाद-विनिमय सम्पर्क रखना चाहिए तथा उनके मूल्यों की भी जानकारी रखनी चाहिए, जिसमें अचमूल्यान में हानि की सम्भावना न रहे। इसलिए उसे विशेषतः गम्भी वस्तुओं की जमानत लेनी चाहिए जो विक्रयशील हो एवं जिनकी माँग में मोच न हो, जिसमें वे आसानी से बेची जा सकें।

(३) सामयिक मूल्यांकन—वस्तुओं के सामयिक मूल्य की भी उसे जानकारी होनी चाहिए जिसमें जमानत का मूल्यांकन समुचित हो। ऐसी वस्तुओं का मूल्यांकन सामयिक होना चाहिए जिसमें हानि की सम्भावना कम हो।

(४) वैधानिक अधिकार—बैंक को वस्तुओं पर पूर्ण वैधानिक उपाधि प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि वे वस्तुएँ ऋणी के पास रहती हैं तो गोदाम की व्यवस्था समुचित है, यह भी देख लेना चाहिए, जिसमें वस्तु की खराबी न हो। विशेषतः बैंक को बन्धक वस्तुएँ अपने गोदाम में ही रखनी चाहिए। यह सम्भव न हो तो ऋणी के भण्डार की कुञ्जी अपने अधिकार में लेकर नाम पर अपनी मोटर लगानी चाहिये जिसमें हानि न हो।

(५) इस प्रकार के व्यवहार वस्तुओं के स्वामी अथवा उनके अधिकृत अधिकर्ता के साथ ही होने चाहिए।

(६) वस्तुओं की वापसी—जो वस्तुएँ बैंक के पास रखी हुई हैं उनको देने समय उसको यह देख लेना चाहिए कि ऋणी में उनके ऋण का भुगतान हो चुका है तथा दोष वस्तुएँ दोष ऋण के भुगतान के लिए पर्याप्त हैं। इस प्रकार अपने किसी जिम्मेदार अधिकारी के निरीक्षण में ही ऋणी का वस्तुएँ वापिस करना चाहिए।

लाभ—(१) इस प्रकार की प्रतिभूति भूत जमानत (tangible security) होती है। (२) इनके मूल्यों में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होने। (३) इनमें विक्रयशीलता होने के साथ ही बचने में सुगमता होती है। (४) उनका मूल्यांकन करने में अधिक सुगमता होती है। (५) गम्भी जमानत पर विश्व जान जाने ऋण बहुधा अल्पकालीन होने हैं जिसमें हानि की सम्भावना भी कम होती है। (६) सामाजिक दृष्टि में इस प्रकार के ऋणों में समाज को भी लाभ होता है क्योंकि इसमें जीवन की आवश्यकताओं के व्यापार में सुविधा होती है। (७) सामान्यतः ये ऋण व्यापार एवं वाणिज्य की प्रगति में महायक हानि है।

ध्रुष्टियाँ—(१) वस्तुओं के खराब होने की सम्भावना अधिक होती है। (२) अगर वस्तुएँ आवश्यकता में न होने हुए त्रिलामिता की वस्तुएँ हैं तो

उनके मूल्या में उतार-चढ़ाव अधिक होने से हानि की सम्भावना रहती है, क्योंकि उनकी माँग नोचदार रहती है। (३) घोंघे की भी सम्भावना रहती है, क्योंकि वेक प्रत्येक सवेष्ट को नहीं देव सकता जिसमें वस्तुओं के गुणों में भी अन्तर होने की सम्भावना रहती है।

भारत में इस प्रकार की जमानत पर विरोध नष्ट नहीं दिये जाते जिसमें निम्न कारण हैं —

(१) गोदामों की कमी है जिसमें ऐसे वस्तु-अधिकार प्रलेखों के प्रयोग को प्रोत्साहन नहीं मिलता।

(२) यातायात की सुविधाओं की भी बहुत कमी है जिसकी वजह से भाव के स्थानान्तरण में मुगमता नहीं होती जिससे इनका प्रयोग बढ़ाया जा सके।

(३) क्वाम, बूट को छोड़कर अन्य वस्तुओं के ऋष-विषय के लिए सुस-गठित बाजार नहीं है, जिसमें उन वस्तुओं की कीमतों में समानता नहीं रहती तथा विभिन्न स्थानों में उनके मूल्य भी मासूम नहीं किये जा सकते।

(४) वस्तु-अधिकार प्रलेखा के उपयोग के लिए वस्तुओं के श्रेणीयन तथा प्रमाणीकरण का अभाव है, जिसमें ऐसी वस्तुओं का व्यापार क्षेत्रीय रहता है। वस्तु-अधिकार प्रलेखों के प्रकार

(१) जहाजी बिल्टी (Bill of Lading)—प्रो० शेल्डन के अनुसार “यह प्रलेख जहाज के कप्तान अथवा उसके अधिकृत व्यक्ति द्वारा निर्गमित तथा हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र होता है, जिसमें यातायात के लिए वस्तुओं की प्राप्ति स्वीकृत की जाती है तथा यह जिम्मेदारी ली जाती है कि उम पत्र में लिखित भाड़े तथा अन्य ध्ययों का भुगतान होने पर वे वस्तुएँ उमी दशा में परेषणी (consignor) अथवा उसके हस्तक को अथवा उसके आदेशित ध्यक्ति को दी जावेंगी।

(२) डॉक-अधिकार पत्र (Dock Warrants)—यह प्रलेख नौवहन कम्पनी के अधिकारी द्वारा दिया जाता है। इस पत्र में लिखित वस्तुओं का प्रदान, जिसका नाम उस पत्र में लिखा होता है, उसे अथवा उसके हस्ताक्षर को किया जा सकता है। इस प्रलेख से तात्पर्य यही है कि उसमें निहित वस्तुओं की रजिस्ट्री वहन कम्पनी की पुस्तकों में हो गयी है।

(३) रेलवे रसीद—जिम समय कोई भी प्रेषक (consignor) यातायात के लिए रेलवे कम्पनी को वस्तुएँ देता है उम समय उसे एक रसीद दी जाती

है जिसको रेलवे रसीद कहते हैं। यह रसीद परेपणी को भेज दी जाती है जिसको वह स्थानीय रेलवे स्टेशन पर देकर माल प्राप्त कर लेता है।

(४) गोदाम की रसीद—गोदाम में जिस समय वस्तुएं सुरक्षा के लिए रखी जाती हैं उन समय भण्डारी एक रसीद देता है जिसमें वस्तुओं के गुण, वजन आदि का उल्लेख रहता है। यह हमान्तरित नहीं होती क्योंकि यह सुरक्षा-निक्षेप प्राप्ति की गारंटी है।

इस प्रकार में सुरक्षा के लिए रखी हुई वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वस्तुओं का स्वामी भण्डारी के नाम एक प्रदान (delivery) आदेश भेजता है। इसमें जिस व्यक्ति को वस्तुएं प्रदान करनी होती हैं उसका नाम लिखा जाता है। वस्तुओं की पुनः प्राप्ति के लिए गोदाम की रसीद को लौटाने की आवश्यकता नहीं होती।

### ३. जीवन बीमा पॉलिसी

जीवन बीमे के आधार पर जो ऋण दिये जाते हैं, वे विनाशित बीमे के अर्पण (surrender) मूल्य के १० प्रतिशत से अधिक नहीं दिये जाते। इनकी प्रतिभूतियों पर विदेशों में ऋण बेत की प्रथा अधिक है, किन्तु भारत में इनकी जमानत पर विशेष रूप से ऋण नहीं दिये जाते क्योंकि बीमे में कई बुद्धिर्मा भी रहती है।

लाभ—(अ) मूल्य वृद्धि—इनके मूल्य के समय के साथ वृद्धि होती जाती है क्योंकि बीमित जितनी अधिग्रह प्रवृत्ति देता है उतना ही बीमे का अर्पण मूल्य बढ़ता है।

(ब) अधिकार में सुगमता—बीमे का हस्ताङ्कन (assignment) बैंक के नाम समुचित रूप में हो तो बैंक किसी प्रकार की अडचनो बिना उस पर अपना अधिकार प्राप्त कर सकता है। ऐसे बीमे को वह आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य व्यक्ति का भी हस्ताङ्कित कर सकता है। इसलिए उसे अपना अधिकार प्रमाणित करने के लिए वैधानिक अडचन नहीं होती।

बुद्धिर्मा—(अ) विशेष बातें छिपाना—बीमित व्यक्ति यदि बीमा कंपनी में उस बीमे के सम्बन्ध में कोई विशेष बात मान्य होने हुए भी छिपाना है तो उस दशा में उस बीमे का वास्तविक बीमा कंपनी पर नहीं रहता।

(ब) बीमा पत्र के नियम—यदि बीमित व्यक्ति आत्महत्या करता है तो शर्तों के अनुसार कंपनी अपना वास्तविक अस्वीकार कर सकती है। इसलिए बैंक

को बीमा लेख की शर्तों को ठीक से देख लेना चाहिए जिससे उसे किसी प्रकार की हानि न हो।

(स) प्रव्याजि का भुगतान न होना—किसी भी कारण से बीमा करने वाला प्रव्याजि का भुगतान नहीं करता है तो उस बीमा लेन को चानू रखने के लिए बैंक को प्रव्याजि देनी पड़ती है जिसमें बीमिन व्यक्ति का ऋण बरता जाना है।

#### ४. भवन आदि

व्यापारिक बैंक जम्पफालोन ऋण देने हैं इसलिए वे विप्रेणत भू-सृष्टिदि अथवा अचल सम्पत्ति के आधार पर ऋण नहीं देते। क्योंकि इन पर अधिकार प्राप्त करने में भी अनेक प्रकार की वैधानिक अडचनें होती हैं तथा इनकी रकम में भी अधिक ध्यय करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त ऐसी प्रतिभूति में निम्न श्रुटियाँ रहती हैं —

(अ) उपाधि जानने में कठिनाई—जो व्यक्ति ऐसी सम्पत्ति की जमानत देता है उसकी उपाधि (title) अथवा अधिकार उस सम्पत्ति पर क्या एवं किस प्रकार में है यह जानने की पहली अडचन उपस्थित होती है।

(ब) विक्रयक्षोभता का अभाव—इसमें विक्रयक्षोभता नहीं होती, इसलिए इनके बेचने में अनेक अवधिघाएँ हाती हैं। अचल सम्पत्ति के विक्रय के समय अनेक वैधानिक कार्यवाहियाँ की पूरी करनी पड़ती हैं तथा इसके मूल्यांकन में कठिनाई होती है।

(स) मूल्यों में उतार-चढ़ाव—ऐसी सम्पत्ति के मूल्यों में उतार-चढ़ाव अधिक होते हैं जिसमें बैंक को हानि की भी सम्भावना रहती है। इसके अतिरिक्त उस सम्पत्ति से आय की प्राप्ति होती रहे तथा मूल्यों में कमी न हो इस हेतु बैंक का समय-समय पर मरम्मत कराने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आय की स्थिरता रखने के लिए किरायेदार को खोज में रहना पड़ता है।

(द) तरलता का अभाव—ऐसी सम्पत्ति को बैंक अन्य प्रतिभूतियों की तरह चाहे जब रोकड़ में परिवर्तित नहीं कर सकता।

#### सारांश

बैंक ऋण के लिए दो प्रकार की जमानत लेते हैं—(१) व्यक्तिगत तथा (२) सहायक जमानतें। जब ऋणी के सिवा अन्य व्यक्तियों की जमानत बैंक लेता है तब उसे व्यक्तिगत जमानत तथा जब ऋणी तथा अन्य व्यक्तियों की

जमानत के साथ ही वह प्रतिभूतियाँ, स्वर्ण आदि की जमानत लेना है तब ऐसी जमानत को महायक जमानत कहते हैं ।

व्यक्तिगत जमानत में बैंक जमानत देने वाले से जमानती अनुबन्ध लेता है जो सुरक्षा की दृष्टि से लिखित होना चाहिए । जमानती अनुबन्ध में ऋणी के दोषी होने पर उसका वायदा पूर्ण करने की अथवा ऋण का भुगतान करने की जिम्मेवारी कोई व्यक्ति लेता है ।

बैंक को जमानत लेते समय निम्न सावधानी रखना चाहिए .—

(१) जमानतदार की साख एवं आर्थिक स्थिति की जाँच करना ।

(२) अनुबन्ध के लिए अक्षम व्यक्तियों से जमानत न लेना ।

(३) विवाहिता से जमानत लेते समय वह किसी दयाव के कारण नहीं है इसकी स्पष्टता एवं उसका स्वतन्त्र स्वीयम होना चाहिए ।

(४) साकेदारी पत्रों से जमानत लेते समय उनके व्यापार का स्वरूप एवं फर्म जमानत दे सकती है या नहीं यह देखना ।

(५) रजिस्टर्ड कम्पनियों की जमानत में उनके सीमानियम एवं अत-नियमों का अध्ययन ।

बैंकर की जिम्मेवारी—(१) जमानतदार से अनुबन्ध सम्बन्धी महत्वपूर्ण बात न छिपाना ।

(२) जमानतदार द्वारा पूछ जाने पर ऋणी की आर्थिक स्थिति की सूचना देना ।

(३) जमानती अनुबन्ध में जमानतदार की सम्मिलित बिना कोई परिवर्तन करना ।

जमानतदार के अधिकार—अपनी देनदारी के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना, जमानती अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार चल जमानत को सूचना देकर स्थगित कराना, ऋणी की मृत्यु की सूचना से जमानतदार की जिम्मेवारी का अंत तथा जमानतदार द्वारा ऋण का भुगतान होने पर उसे बैंकर के सब अधिकार प्राप्त होना ।

सहायक प्रतिभूतियाँ—ऋणी द्वारा व्यक्तिगत जमानत के साथ जो मूर्त्त सम्पत्ति बन्धक में रखी जाती है उसे सहायक प्रतिभूति कहते हैं । सहायक प्रतिभूतियों के निम्न स्वरूप हैं —

(१) ग्रहणाधिकार—इस हेतु कोई समझौते की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बैंकर और ग्राहक के सम्बन्ध में यह ग्रहणाधिकार पब्लिश होता है ।

बैंकर का ग्रहणाधिकार केवल उन प्रतिभूतियों पर होता है जो बैंकिंग व्यवहार में आयी हो तथा किसी विशेष उद्देश्य से न रखी गई हो। यह काल मर्यादा नियम से बाधित नहीं होता।

(२) रहन—इसमें रहन रखी हुई सम्पत्ति का अधिकार ऋणी द्वारा ऋण दाता को दिया जाता है। रहन दो प्रकार के होते हैं—

(अ) वैधानिक रहन में सम्पत्ति का अधिकार ऋणदाता बैंकर के पास होने से वह ऋणी के दोषी होने पर उसे बेच सकता है, और ऋण का भुगतान होने पर ऋणी की सम्पत्ति पर पुन अधिकार मिल जाना है।

(आ) न्याय रहन में सम्पत्ति का अधिकार ऋणी के पास होता है तथा बैंकर न्यायालय से डिग्री लेने के बाद ही उसे बेच सकता है। इन अनुबन्धों में १०० रुपये से अधिक ऋण के लिए स्टाम्प कर तथा दो गवाहों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।

(३) वधक—इसमें किसी वचन की पूर्ति अथवा ऋण के भुगतान के लिए वस्तुएँ जमानत में रखी जाती हैं। इसमें वस्तुओं का अधिकार वचनदाता के पास किन्तु वस्तुएँ बैंकर के पास रहती हैं। ऋणी के दोषी होने पर बैंकर समुचित सूचना देने के बाद उस सम्पत्ति को बेच सकता है।

(४) उपप्राधीयन—इसमें न तो वस्तुएँ और न उन पर अधिकार ही बैंकर को मिलता है परन्तु केवल एक पत्र मिलता है जिससे बैंकर को उसमें लिखित वस्तुओं पर प्रभाव मिलता है।

महायक प्रतिभूतियाँ लते समय मावधानी—उपाधि की सरलता, हस्तान्तरण की सुगमता समुचित मूल्य स्थिरता, विक्रयशीलता ऋण एवं जमानत मूल्य में अन्तर देनदारी का अभाव, उपाधि की सुरक्षा,

प्रतिभूतियों के प्रकार (१) स्वल्प विनिमय प्रतिभूतियाँ—साम विक्रय शीलता मूल्य स्थिरता, उपाधि की सुगमता एवं ऋण की सुरक्षा।

हानि—ग्रहणाधिकार की सूचना, मूल्यों में उतार चढ़ाव, उपाधि की स्पष्टता का दोष।

(२) वस्तु या वस्तु अधिकार पत्र—इनमें बैंकर को निम्न बातें देखना चाहिए—वस्तु का प्रकार टिकाऊपन एवं विक्रय शीलता, सामयिक मूल्यकन वैधानिक अधिकार लेना, स्वामी या उसके अधिकृत अभिकर्ता के साथ व्यवहार होना, वस्तुओं की वापसी।

लाभ—मूर्त जमानत, मूल्य स्थिरता, विक्रयशीलता, मूल्यांकन में सुगमता, हानि की कम सम्भावना, जीवनावश्यक व्यापार में सुविधा ।

हानि—सराब होने का खतरा, विलासिता की वस्तुओं में मूल्यों के उतार-चढ़ाव का भय, कषट की सम्भावना ।

ऐसी प्रतिभूति पर भारत में निम्न कारणों से अधिक ऋण नहीं दिये जाते—गोदानो, घाताघात सुविधाएँ, संगठित बाजार तथा श्रेणीयन एवं प्रमापीकरण का अभाव ।

वस्तु अधिकार प्रलेखों में जहाजी बिल्टो, डॉक वारंट, रेलवे की रसीद, तथा गोदान की रसीद का समावेश होता है ।

(३) जीवन बीमा—जीवन बीमा पालिसी की जमानत पर उसके सगर्पण मूल्य के ६०% तक ऋण देते हैं ।

लाभ—समय के साथ मूल्य वृद्धि, एवं अधिकार की सुगमता ।

घोष—विशेष बातें छिपाने एवं बीमे की विशेष शर्तें होने की सम्भावना तथा प्रव्याज का भुगतान न होने की दशा में बैंक को प्रव्याज देना पड़ती है ।

(४) भवन आदि—बैंक इनकी जमानत पर साधारणतः ऋण नहीं देते क्योंकि निम्न कठिनाइयाँ हैं—उपाधि जानने में कठिनाई, विवक्षालता का अभाव, तरलता का अभाव तथा मूल्यों में उतार-चढ़ाव ।

## अध्याय ६

# बैंक और ग्राहक

हम यह देख चुके हैं कि बैंक विभिन्न प्रकार के निक्षेपों द्वारा जनता से ऋण लेता है जिसका भुगाना वह बैंक आदि से मांग होने पर करता है।

ग्राहक—अभी तक 'ग्राहक' की कोई भी वैधानिक परिभाषा नहीं है। फिर भी अर्थशास्त्रियों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को ग्राहक होने के लिए दो बातें आवश्यक हैं —

(१) वह व्यक्ति बैंक से कुछ समय तक बैंकिंग स्वरूप के व्यवहार करता रहा हो, तथा

(२) ये व्यवहार केवल बैंकिंग में सम्बन्धित हो।

बैंकिंग व्यवहार होने के लिए यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति का निक्षेप लेखा बैंक में हो। अर्थात् समय-समय पर वह अपनी राशि जमा करता हो एवं उसको वह बैंक द्वारा निकालना हो। स्पष्ट है कि ग्राहक होने के लिए उस व्यक्ति का किसी न किसी प्रकार का लेखा बैंक में होना आवश्यक है किन्तु यह लेखा किस प्रकार का हो, इस विषय में कोई भी वैधानिक शर्त नहीं है। फिर भी उस व्यक्ति एवं बैंक के बीच जो व्यवहार हो उनके सम्बन्ध में ग्राहक एवं बैंक दोनों द्वारा मान्य निश्चित कार्य-प्रणाली होनी चाहिए।

जहां तक 'अवधि' सम्बन्धी शर्त है वह आजकल आवश्यक नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति जो बैंक में अपना लेखा खोलता है तथा उसमें बैंक आदि संग्रहण के लिए देता है तथा बैंक उन्हें संग्रहण के लिए स्वीकार करता है तो वह व्यक्ति उस बैंक का ग्राहक होगा। किन्तु यह व्यवहार पहिला और अन्तिम नहीं होना चाहिए।

बैंकर और ग्राहक का सम्बन्ध

बैंकर और ग्राहक का सम्बन्ध तीन प्रकार का होता है —

(१) ऋणी एवं ऋणदाता—यह बैंक और ग्राहक का प्रमुख सम्बन्ध है। बैंक अपने ग्राहकों से निक्षेप स्वीकार करके ऋण लेता है और अपना सम्बन्ध स्थापित करता है। इस अवस्था में बैंक ऋणी और ग्राहक ऋणदाता होता है।

परन्तु कभी-कभी जब ग्राहक वक स ऋण लता है अथवा अधिविक्रय की सुविधा लता है तब यह सम्बन्ध उलटा हो जाता है। अर्थात् ग्राहक ऋणी तथा बैंकर ऋणदाता हो जाता है।

बैंक और ग्राहक के इस प्राथमिक सम्बन्ध की निम्न विशेषताएँ हैं —

(अ) बैंकर यह ऋण बचल उसी अवस्था में लौटाता है जब बैंक आदि द्वारा ऋण की मांग हो। अन्य व्यापारिक ऋणा की भाँति ग्राहक की मांग के बिना ऋण लौटाने के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है। परन्तु यदि ग्राहक ऋणी है तो उस अपना ऋण बैंक का ऋण की अवधि में तथा बिना मांग के लौटाना पड़ेगा।

(आ) स्थायी एवं संचय निक्षेपों के सम्बन्ध में बैंकर सदैव ऋणा और ग्राहक ऋणदाता रहता है। संचय निक्षेपों की राशि की मांग निश्चित क्षण पर हान पर ही बैंकर उसकी वापसी के लिए जिम्मेदार है। स्थायी निक्षेपों की राशि अवधि के पूरा होने पर अथवा निश्चित सूचना पान पर ही मांगी जा सकती है।

(इ) बैंकर अपने पास आय हुए निष्पत्तियों का उपयोग किसी भी प्रकार से कर सकता है तथा इस राशि पर उसका पूर्ण अधिकार होता है। क्योंकि यह राशि उसका पास किसी विज्ञापन के लिए ग्राहक नहीं देता।

(ई) बैंकर के दिवानिया हान पर ग्राहक का सामान्य ऋणदाताओं की भाँति अपनी राशि के लिए अधिकार प्रमाणित करना पड़ता है। परन्तु यदि यह राशि किसी विज्ञापन के लिए दी गई हो तो पूर्ण राशि को लौटाने की जिम्मेदारी बैंकर पर होगी।

(उ) ग्राहक द्वारा नियमानुसार बैंक आदि में ऋण की मांग होने पर भुगतान करने की जिम्मेदारी बैंक की होती है। भगतान न होने पर ग्राहक की साधन का जो हानि होगी उसका निषेध बैंकर स्वयं जिम्मेदार होगा। परन्तु ग्राहक के खान में पर्याप्त राशि होना चाहिए अथवा उसका अधिविक्रय स्वीकृत होना चाहिए।

(ऊ) बैंक द्वारा निष्पत्ति रूप में लिये हुए ऋणों का काल मर्यादा नियम (Law of Limitation) लागू नहीं होता अर्थात् यह ऋण बैंकर के पास किसी भी समय तक रह सकता है। भारत में यह अवधि ३ वर्ष है परन्तु स्थायी निष्पत्तियों में निष्पत्ति रम्योद लौटाकर धन की मांग करते ही यह नियम लागू हो जाता है। इसी प्रकार अधिविक्रय एवं ऋणा में इनका स्वीकृत करने की तिथि में काल मर्यादा नियम लागू हो जाता है।

(ए) निक्षेप-राशि का नियोजन—यदि किसी ग्राहक के एक ही बैंक में अनेक खाते हों तो बैंकर उनका एक दूसरे से मिलान कर सकता है। परन्तु बैंकर यह तभी कर सकता है जब वे खाते एक ही स्थिति (capacity) में हों। ऐसा मिलान करने से पूर्व उसकी सूचना ग्राहक को अवश्य देनी चाहिए। यह नियम केवल चल-निक्षेपों के सम्बन्ध में ही लागू होता है।

(ए) लेखा बन्द करने का अधिकार—बैंक किसी भी ग्राहक के खाते की सूचना दबकर बन्द कर सकता है। परन्तु ग्राहक अपना खाता बिना सूचना के भी बन्द कर सकता है। यदि ग्राहक ने अपना खाता बन्द न किया हो तो बैंक ग्राहक के खाते के लिये होने वाले आकस्मिक व्यय ग्राहक से ले सकता है।

(ओ) ग्राहक की आर्थिक स्थिति की गोपनीयता—बैंक ग्राहक की आर्थिक स्थिति बिना किसी उचित कारण के किसी व्यक्ति का नहीं बता सकता। अन्यथा ऐसा करने से ग्राहक की साख को होने वाली हानि की पूर्ति के लिए वह जिम्मेदार होगा।

बैंक केवल निम्न स्थिति में ही ग्राहक का आर्थिक स्थिति की जानकारी बिना किसी उत्तरदायित्व के दे सकता है —

- (१) न्यायालय से किसी ग्राहक के खाते का विवरण भेजने का आदेश हो।
- (२) सरकार, देश एवं सामाजिक हित के लिए ग्राहक के लेने की जानकारी देना आवश्यक हो।
- (३) बैंक द्वारा दिये गये ऋण की प्राप्ति अथवा उसके निजी हित के लिए ऐसी जानकारी देना आवश्यक हो।
- (४) जब ग्राहक ने बैंकर का सन्दर्भ किसी व्यक्ति को दिया हो। इस स्थिति में जानकारी देते समय उसे ग्राहक की आर्थिक स्थिति इस सावधानी से देनी चाहिए जिससे ग्राहक की साख को और न तग और उसकी सही आर्थिक स्थिति की जानकारी भी हो।
- (५) जब बैंक का एक ग्राहक उसी बैंक के दूसरे ग्राहक की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में पूछे। इस स्थिति में भी बैंकर को उपरोक्त सावधानी से काम लेना चाहिए।

(ओ) बैंकर का ग्रहणाधिकार ध्वनित बंधक है (Banker's Right of Lien is an Implied Pledge)—ग्राहक एवं बैंक का प्राथमिक सम्बन्ध होते समय दोनों में जो अनुबन्ध होता है उस अनुबन्ध से ही बैंकिंग व्यवहार में आई हुई राशि एवं अन्य ग्राहक की वस्तुओं पर बैंक का ग्रहणाधिकार ध्वनित

रहता है। इस प्रकार ग्राहक की प्रतिभूतियाँ, संग्रहण के लिए जाय हुए बैंक विल आदि का ऋण की जमानत के लिए बैंक को अपने पास रखन का अधिकार होता है। इसको बैंक का ग्रहणाधिकार कहते हैं। इस ग्रहणाधिकार पर कान मर्यादा नियम लागू नहीं होगा।

(२) बैंक ग्राहक का प्रयासी होता है—बैंक ग्राहक के आभूषण तथा प्रतिभूतियाँ आदि सुरक्षा के नियम रखन की सुविधा देता है। जिस समय बैंक अपने ग्राहकों से सुरक्षा के लिए वस्तुएँ स्वीकार करता है न वस्तुएँ या तो बैंक का माहिरबंद मजदूरन में जयवा लाता ली हुई पटी में ग्राहक देता है तथा उन सबवस्तुन अथवा पटी में ग्राहक न क्या रखा है इसका ज्ञान भी बैंक का नहीं होता। एसी जा वस्तुएँ ग्राहक की ओर से बैंक अपने पास रखता है उन्हें सुरक्षा निक्षेप कहते हैं। इन वस्तुओं का स्वीकार करने पर बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह ग्राहक का वही वस्तुएँ उसी देता में जिस देता में वह रखी गई थी लौगाय। इस समय बैंक ग्राहक का प्रयासी होता है तथा उन वस्तुओं का स्वामित्व ग्राहक का ही होता है। जिस समय वस्तुएँ सुरक्षा के लिए बैंक स्वीकार करता है उस समय ग्राहक को सुरक्षा निक्षेप की रसीद देता है तथा रसीद पुस्तिका (receipt book) पर ग्राहक से हस्ताक्षर करा लेता है। जब एसी वस्तुएँ ग्राहक का लौगाई जानी हैं उस समय ग्राहक वह रसीद बैंक का लौगाकर उस पर वस्तुओं की प्राप्ति के हस्ताक्षर करता है।

इन वस्तुओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व बैंक का होता है। अतः ये वस्तुएँ बैंक अपने भवन में ही रखता है और इन वस्तुओं की सुरक्षा के लिए पूर्ण सावधानी रखता है। किन्तु फिर भी यदि वहाँ जाय अथवा उनका किसी प्रकार की क्षति पहुँच जा उसकी पूर्ति की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होती। बैंक उम्मी देता में सुरक्षा निक्षेप की हानि पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा जब उसने उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की उपेक्षा की हो। उनके विपरीत यदि बैंक सुरक्षा निक्षेप का अपने भवन में न रखने हुए किसी अन्य स्थान पर रखता है तो उनकी किसी प्रकार की हानि आदि के लिए बैंक उत्तरदायी होगा न कि वह उसने पूर्ण सावधानी में काम किया हो अथवा उपेक्षा न की हो।

इस सवाल-जाय के लिए भारतीय बैंक गुल्फ नन ह परतु पाश्चात्य राष्ट्रा में ग सुविधाएँ नि गुल्फ दी जाती हैं।

(३) प्रधान एवं अभिज्ञा का सम्बन्ध—बैंक ग्राहक में अधिकृत हान पर ग्राहक की ओर से प्रतिभूतियाँ, अग आदि का तय विनय करता है उसक

आय-कर, बीमा प्रव्याजि, चन्दा आदि का भुगतान करता है। इन प्रकार के कार्य वह ग्राहक की ओर में एवं उसने अधिकार से करता है। अतः इस दृष्टि में बैंक ग्राहक का अभिकर्ता होना है एवं ग्राहक प्रधान। ऐसे कार्य करने से पूर्व बैंक को ग्राहक से लिखित अधिकार-पत्र लेना चाहिए तथा उसे वे ही कार्य करने चाहिए जो अधिकार-पत्र में हों। अन्यथा वह अपने कार्यों के लिए अपने प्रधान को—ग्राहक को—उत्तरदायी नहीं बना सकता। जिस समय बैंक ग्राहक के बिल, चैक आदि का संग्रहण करता है उस समय भी वह अभिकर्ता का ही कार्य करता है तथा इन सब कार्यों के लिए उसका प्रधान (ग्राहक) ही उत्तरदायी होगा।

### सारांश

बैंक—वह व्यक्ति कर्म या कम्पनी है जो जनता से निक्षेपों से ऋण लेती है तथा चैक आदि द्वारा मांग होने पर उनका भुगतान करती है।

ग्राहक की वैधानिक परिभाषा नहीं है परन्तु ग्राहक होने के लिए दो बातें आवश्यक हैं—बैंक से कुछ समय तक व्यवहार होना तथा ऐसे व्यवहार बैंकिंग के सम्बन्ध में होना। परन्तु आजकल अवधि सम्बन्धी शर्तें आवश्यक नहीं हैं। अर्थात् जो व्यक्ति बैंक में निक्षेप देना चाहता है तथा चैक आदि संग्रहण लिए देता है जिसे बैंक स्वीकार करता है तो वह बैंक का ग्राहक होगा। यह व्यवहार प्रथम एवं अंतिम नहीं होना चाहिए।

बैंकर और ग्राहक का सम्बन्ध

(१) ऋणी एवं ऋणदाता—यह बैंक और ग्राहक का मूल सम्बन्ध होता है जब बैंक ग्राहक से निक्षेप राशि—ऋण लेता है। परन्तु जब बैंक से ग्राहक ऋण या अधिविकल्प लेता है तब बैंक ऋणदाता एवं ग्राहक ऋणी हो जाता है। इस प्राथमिक सम्बन्ध की निम्न विशेषताएँ हैं—

(अ) बैंकर ग्राहक से निक्षेप के द्वारा लिये गये ऋण को केवल मांग पर लौटाने के लिए ही जिम्मेवार है।

(आ) स्थायी एवं सद्यः निक्षेपों की दृष्टि में बैंक सदैव ऋणी और ग्राहक ऋणदाता होगा।

(इ) बैंकर दिवालिया होने पर ग्राहक को सामान्य ऋणदाता की भाँति अपने अधिकार प्रमाणित करना होता है।

(ई) बैंकर निक्षेप राशि का उपयोग करने में स्वतन्त्र है।

(उ) ग्राहक के खाते में पर्याप्त राशि होने अथवा अधिविकर्ष स्वीकृत होने की दशा में ग्राहक के प्राप्त चेकों का भुगतान बैंक को करना होगा ।

(ऊ) बैंक द्वारा प्राप्त निक्षेपों को कालमर्यादा नियम लागू नहीं होता ।

(ए) बैंक ग्राहक की एव ही स्थिति के दो निक्षेप खातों का नियोजन कर सकता है ।

(ऐ) बैंक सूचना देकर किसी ग्राहक का लेखा बन्द कर सकता है ।

(ओ) ग्राहक की आर्थिक स्थिति की गोपनीयता के लिए बैंक जिम्मेवार है, परन्तु निम्न अवस्था में वह आर्थिक स्थिति की जानकारी दे सकता है —  
न्यायालयीन आदेश पर, सरकार, देश एवं सामाजिक हित के लिए अपने ऋण की प्राप्ति के लिए, ग्राहक द्वारा बैंकर का सबर्भ दिये जाने पर ।

(औ) बैंकर का ग्राहक को बैंकिंग व्यवसाय में प्राप्त प्रतिभूतियों आदि पर ग्रहणाधिकार होता है ।

बैंक ग्राहक का प्रणामी है—जब बैंक ग्राहक से सुरक्षा के लिए वस्तुएं स्वीकार करता है तब वह ग्राहक का प्रणामी होता है । ऐसी वस्तुओं की सुरक्षा का उत्तरदायित्व बैंक पर होता है ।

(३) प्रधान एवं अभिकर्ता का सम्बन्ध—जब बैंक ग्राहक की ओर से चेक आदि का सग्रहण, भुगतान, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय आदि करता है तब वह ग्राहक का एजेंट होता है । ऐसी स्थिति में उसे वे ही कार्य ग्राहक की ओर से करने चाहिए जिनके लिए वह अभिकृत हो ।

## अध्याय ७

## साख और साख-निर्माण

आधुनिक आर्थिक जगत में साख का स्थान महत्वपूर्ण है। सामान्य ग्राहक से लेकर निर्माता तक साख की आवश्यकता होती है, इसीलिए आजकल औद्योगिक एवं व्यापारिक जिम्मेदारों की आवागमिता साम्य है।

**परिभाषा—**साख किसी भी व्यक्ति की वह शक्ति है जिससे वह अन्य व्यक्तियों से किसी अवधि के उपयोग के लिए धन अथवा आर्थिक वस्तुएँ लेता है। अर्थात् साख किसी भी व्यक्ति की वह विशेषता है, जिसके आधार पर वह अन्य व्यक्तियों से निश्चित अवधि के लिए उनकी आर्थिक वस्तुओं का उपयोग ले सकता है तथा जिन्हें वह उस अवधि की समाप्ति के बाद लौटाता है। जिस व्यक्ति को यह साख प्राप्त होती है उसे ऋणी, एवं जो साख देता है उसे ऋणदाता कहते हैं। उदाहरणार्थ, अ ने व से ५०० रु० की साख प्राप्त की, अर्थात् अ ने व से ५०० रु० ऋण लिये। इसमें अ ऋणी तथा व ऋण दाता है। जीड के अनुसार "साख एक ऐसा विनिमय है जो कुछ निश्चित समय बाद भुगतान होने पर पूर्ण होता है।" स्पष्ट है कि साख विनिमय उन व्यवहारों को कहेंगे जिनमें वर्तमान आर्थिक वस्तुओं का विनिमय भविष्य की आर्थिक वस्तुओं के साथ होता है। किन्तु नगदी व्यवहार में ऐसा न होते हुए वर्तमान वस्तुओं का विनिमय रोकड़ के बदले होता है। इस प्रकार रोकड़ व्यवहारों में तथा साख-व्यवहारों में यह मूल भेद है कि रोकड़ व्यवहारों में रोकड़ के बदले वस्तुएँ दी जाती हैं परन्तु साख व्यवहारों में वर्तमान वस्तुओं का भुगतान किसी आगामी काल में निश्चित अवधि के बाद किया जाता है। अर्थात् साख व्यवहारों में समय का तत्व (element of time) है।

ये साख-व्यवहार वस्तुओं के तथा रोकड़ के भी हो सकते हैं। जहाँ वस्तुओं की बदले उनका भुगतान आगामी काल में किया जाता है, उन्हें केवल 'साख व्यवहार' कहते हैं। जहाँ वर्तमान उपयोग के लिए धन-राशि प्राप्त की जाती है एवं जिसका भुगतान भविष्य में किया जाता है, उन व्यवहारों को ऋण व्यवहार कहते हैं।

साख के तत्व

१ विश्वास—डगमे यह स्पष्ट है कि साख केवल उनी व्यक्ति को मिलती है जिसकी आर्थिक स्थिति में विश्वास किया जा सकता है एव जो ईमानदारी है। अर्थात् मात्र लेने के लिए पहले उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, ईमानदारी तथा ऋण-भुगतान की योग्यता में ऋणदाता का विश्वास होना आवश्यक है। इस विश्वास की आवश्यकता 'क्रेडिट' शब्द में भी स्पष्ट है। इस शब्द की उत्पत्ति 'credo' (अर्थात् विश्वास) शब्द से हुई।

२ समय तत्व—मात्र में समय का तत्व होता है। अर्थात् मात्र हम तभी कह सकते हैं जब वर्तमान आर्थिक वस्तुओं का भुगतान भविष्य की आर्थिक वस्तुओं में किया जाय और यह अर्ध ऋणी और ऋणदाता में निश्चित हो जानी है।

३ राशि—मात्र कितनी चाहिए अथवा मात्र में कितनी राशि का आदान-प्रदान होता है वह राशि भी माप्युम होनी चाहिए। इस प्रकार मात्र में तीन बातों की आवश्यकता होती है —

(१) समय—वर्तमान वस्तुओं का भविष्य में भुगतान होना।

(२) निश्चित राशि—मात्र की राशि अथवा मूल्य निश्चित होना।

(३) विश्वास—ऋणी की आर्थिक स्थिति एव ऋण-भुगतान की क्षमता एव ईमानदारी में विश्वास होना।

४ जमानत—बैंक के मात्र-व्यवहारा में आजकल किसी न किसी प्रकार की जमानत आवश्यक होती है, अतः मात्र में जमानत का तत्व भी होता है। परन्तु इसका होना आवश्यक नहीं है क्योंकि सामान्यतः बैंक ऋणी की वैयक्तिक जमानत पर भी ऋण देने हेतु तथा दूकानदार अपने ग्राहक की वैयक्तिक मात्र पर। मात्र के प्रकार

(अ) उपभोग्य एव उत्पादी मात्र—मात्र दो कार्यों के लिए प्राप्त की जाती है। जिस समय मात्र का उपयोग उपभोग के लिए होता है, वह उपभोग्य (consumption) मात्र होता है, तथा जिस मात्र का उपयोग व्यापारिक अथवा औद्योगिक प्राप्ति के लिए होता है एव जिससे उत्पादन बढ़ता है, उसे उत्पादी (production) मात्र कहते हैं। उपभोग्य मात्र का निमाण अथवा संचार जहाँ तक उत्पादन कार्यों में सहायक होता है वही तक हम उपभोग्य मात्र का दिया जाना उचित समझते हैं, जैसे क्रय-विक्रय पद्धति (hire-purchase system) अथवा किश्त पद्धति (instalment system)। परन्तु

अन्य मास्य जगमे उत्पादन कार्य म महायन्त्रा नही मिलती, वह देश हिन म नही होनी ।

(ब) व्यापारिक साख—जय काई व्यक्ति अपनी व्यावसायिक मास्य के आधार पर उधार मान लेना है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को उसकी व्यापारिक मास्य पर मान उधार देना है तब उसे व्यापारिक साख (commercial credit) कहत है । यह मास्य उमी क्षेत्र तक गीमिन रहती है, जिम क्षेत्र म व्यापारियों का विशेष आदान प्रदान हाता है । इसके लिए बैंक व्यापारियों म व्यापारिक मास्य आदि की जमानत लेते है ।

(स) औद्योगिक साख—औद्योगिक विकास के लिए जय उद्योगपति अपनी स्थायी या अस्थायी सम्पत्ति की जमानत पर दीर्घकालीन या अल्पकालीन ऋण लेते है तब उसे औद्योगिक मास्य कहत है ।

(द) राष्ट्रीय साख—उसे कहने हैं जिमके आधार पर सरकार जनता म ऋण आदि लेती है एवं उसके बदले म अपने रिल आदि देती है । सरकार की इस मास्य का राष्ट्रीय साख कहते है तथा जिन पत्रा को देकर सरकार यह राशि उधार लेती है उन पत्रा का साख विलेख (instruments) कहते हैं । सरकार की साख वैयक्तिक मास्य से अधिक एवं महत्वपूर्ण होती है ।

(य) बैंक साख - बैंक साख सब म अधिक महत्वपूर्ण होती है । जब व्यापारी अपनी मास्य बढ़ाने क लिए अपनी साख बचकर बैंक से साख प्राप्त करत है उस समय उस व्यापारी की साख बैंक की साख के कारण बढ जाती है । इसके सिवा बैंक साख विलेखों के निर्गमन द्वारा भी साख देती है ।

मास्य से लाभ

(१) पूँजी की उत्पादन-शक्ति मे वृद्धि—अनेक व्यक्ति ऐसे होते है जिनके पास पूँजी होती है परन्तु वे उसका समुचित उपयोग नही कर सकते । मास्य के कारण ऐसी निम्निय पूँजी उन लोग का मिलती है जा उसका उपयोग उत्पादन कार्यों के लिए कर सकते है । इससे देश म उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है तथा पूँजी की वृद्धि होनी है ।

(२) विनियोग साधनों मे वृद्धि—बैंक आदि मास्य-संस्थाएँ विनियोग के विभिन्न साधनों को खोजकर विनियोग साधन बढ़ाते है तथा उनका अधिक प्रभाव करत है । इसम जनता को अपनी संचित राशि का विनियोग करने की पर्याप्त सुविधाएँ मिलती है तथा वे विनियोग के लिए अधिक मात्रा म धन मचय करत है जिमसे देशी पूँजी की वृद्धि होनी है ।

(३) विनिमय माध्यम में वृद्धि तथा मुद्रा की अतिव्ययता—मात्र में जनता विशेषतः अपना भुगतान बैंक आदि मात्र पथों द्वारा करनी है जिसमें मुद्रा की कम आवश्यकता होती है तथा मुद्रा एवं मात्र की गति बढ़ती है। इस कारण आधुनिक व्यापार एवं उद्योग की अनिश्चित पूँजी की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं, जो स्वयं अथवा अन्य किसी प्रकार की धानु-मुद्रा में सम्भव न होती। साथ ही, मात्र की वृद्धि एवं उपयोग में बैंक आदि का उपयोग होता है तथा धानु-मुद्रा की आवश्यकता कम होगी है जो अन्य उपयोगी कार्यों में तथा उत्पादन के उपयोग में आती है।

(४) साख-निर्माण से स्थगित भुगतान (*deferred payments*) करना सम्भव होता है जिसमें ऋणी एवं ऋणदाना दोनों को ही सुविधाएँ होती हैं।

(५) बड़ी-बड़ी राशियों का भुगतान करने के लिए भानु पत्र सुगम साधन होते हैं जिनकी प्राप्ति मात्र-निर्माण में जनता एवं देश को होती है। मात्र की सुविधा में देशी वाणिज्य, व्यवसाय एवं उद्योगों की तथा अन्तरराष्ट्रीय एवं विदेशी व्यापार में प्रगति होती है।

(६) आर्थिक सकट का सामना—मात्र निर्माण के कारण सरकार आर्थिक सकट के समय मात्र के प्रसार में आर्थिक सकट का सामना कर सकती है। साथ ही मात्र के व्यवस्थित नियन्त्रण में मुद्रा प्रणाली में लोच एवं मूल्य स्थिरता रखने में सहायता होती है।

साख से हानि .

(१) फिडल्लिटी को प्रोत्साहन—उपभोग कार्यों के लिए मात्र प्राप्त होने में समाज में फिडल्लिटी बढ़ती है जिसमें समाज में जालसाजी एवं असत्य व्यवहारों की ओर प्रवृत्ति होकर समाज तथा व्यापारियों का नैतिक स्तर गिर जाता है।

(२) सट्टे को प्रोत्साहन—उत्पादन कार्यों के लिए यदि आवश्यकतानुसार एवं सीमित परिमाण में मात्र न दी जाय तो व्यापारियों एवं उद्योगपतियों में सट्टे की प्रवृत्ति होती है। इसमें व्यापारियों एवं उद्योगपतियों का वैज्ञानिक हानि होती ही है साथ ही देश के अनेक उद्योग एवं व्यवसायों का अन्न होता है, जिनसे देश की आर्थिक हानि होती है।

(३) उत्पादनाधिक्य का भय—अधिक मात्रा में मात्र मिलने में देश का उत्पादन बढ़ता है परन्तु इसमें कभी-कभी उत्पादनाधिक्य (*over-production*) हो जाता है। उत्पादनाधिक्य में मूल्य-स्तर गिरने लगने है और देश का आर्थिक ढाँचा अस्त-व्यस्त हो जाता है।

(४) उत्पादन में अपव्यय—साग से अनेक अयोग्य व्यापारी एवं उद्योगपति भी व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं जिसमें उत्पादन में फिन्नूलसर्चों (wastage) अधिक हानी है। साथ ही वे अपनी औद्योगिक अक्षमता को ठिपाने में सफल हो जाते हैं।

(५) पूँजी का केन्द्रीकरण—सामान्य पूँजी का केन्द्रीकरण कुछ इने गिने व्यक्तियों के हाथ में हो जाता है। इसमें दण में संयोग (combinations) एवं एकाधिकार की प्रवृत्ति बढ़ जाती है जो साधारण जन हित के लिए हानिकार होती है। इस प्रवृत्ति के पनपने में देश की सरकार का नियन्त्रण भी दे ही लोग अपनी इच्छानुसार करन में सफल होते हैं।

(६) औद्योगिक अक्षमता को प्रोत्साहन—अयोग्य एवं अदक्ष व्यापारियों एवं उद्योगपतियों को साल्म सुविधाएँ मिलने से वे ऋण पूँजी पर अपना व्यापार चलाने रहते हैं जिसमें देखने में ता आर्थिक प्रगति होती है परन्तु वह खोखली रहती है। मन्दी के समय देश को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। उदाहरणार्थ, न्यूयार्क का आर्थिक संकट।

**बैंक द्वारा साख्त-निर्माण**

बैंक अपने ग्राहकों में विभिन्न प्रकार के एवं विभिन्न शर्तों पर निक्षेप लेता है जो उसकी कार्यशील पूँजी का एक भाग रहता है। इस प्रकार निक्षेपों के रूप में प्राप्त विय हुए धन एवं साख्त को वह अन्य व्यक्तियों को ऋण देता है। यह बैंक का प्रमुख कार्य है। इसलिए प्रो० सेलिंगमेन ने कहा है कि "बटौती, निक्षेप तथा ऋण इन तीन कार्यों का आधुनिक साख्त व्यवहारा में समावेश होता है।" बैंक निक्षेपों द्वारा अनन्तता में ऋण लेते हैं तथा उनकी माँग पर भुगतान करन की जिम्मेदारी लेते हैं। इन निक्षेपों की सब रकम एक साथ नहीं माँगी जाती और न कोई व्यक्ति अपनी सब रकम एक साथ लेता ही है। इस लिए बैंक इस धन में से कुछ रकम निक्षेपों के भुगतान के लिए रोकड़ निधि में रखता है तथा शेष रकम वह ऋण देने के उपयोग में लाता है। बैंक इस रकम में से कितना ऋण दे सकता है, यह ग्राहकों द्वारा कितना रुपया निकाला जायगा, इस पर निर्भर रहता है। प्रगतिशील राष्ट्रों में लगभग निक्षेपों की ६० प्रतिशत तथा भारत में ८० प्रतिशत रकम ऋण-कार्यों में लगाई जाती है। इसलिए यह कहना ठीक ही है कि निक्षेपों द्वारा ऋण निर्माण किये जाते हैं अथवा ऋण निक्षेपों के बच्चे होते हैं।

निक्षेपों के दो प्रकार—बैंक के पास निक्षेप तीन रूप में आते हैं—स्थायी, मध्य तथा चल । इन निक्षेपों के अतिरिक्त बैंक अपने ऋणों द्वारा भी नये निक्षेपों का निर्माण करते हैं अथवा उन ऋणों से नये निक्षेप लेने खोलते हैं । अर्थात् कुछ निक्षेप इस प्रकार के होते हैं जो केवल बैंक में ऋण लेकर उन ऋण की रकम में खोले जाते हैं । दूसरे मन्दा में, बैंक अपनी मात्र उन व्यक्तियों को कुछ निश्चित सीमा तक उधार देने के लिये आधार पर नये निक्षेप खोलते जाते हैं । इस प्रकार निक्षेप दो प्रकार के होते हैं—रोकड़ निक्षेप (deposits), तथा मात्र निक्षेप । मात्र निक्षेप दो प्रकार से खोले जाते हैं—अपने ग्राहकों को अधि-विकल्प तथा रोकड़-ऋण (cash credit) की सुविधाएँ देकर । इन मात्र निक्षेपों का आधार रोकड़ निक्षेप होना है, इसलिए यह कहा जाता है कि निक्षेप ऋणों द्वारा निर्माण होते हैं अथवा निक्षेप ऋणों के बच्चे हैं ।<sup>1</sup>

बैंक की कार्य-पद्धति के विवरण में स्पष्ट है कि बैंक के पास जितने भी निक्षेप होते हैं उनका बहुत कम भाग ऐसा होता है जिसमें वास्तव में ग्राहक रोकड़ जमा करते हैं । अधिकतर निक्षेप बैंक अपनी मात्र अथवा ऋण देकर ही निर्माण करता है । अतः प्रारम्भिक काल में बैंक केवल रोकड़ निक्षेप ही रखने होंगे, किन्तु आधुनिक बैकिंग में मात्र निक्षेप विशेष रूप से होते हैं । क्योंकि बैंक जो ऋण अपने ग्राहकों का देता है वह सब रकम ग्राहक अपने पास न रखते हुए बैंक में ही जमा कर देते हैं तथा उस पर समय-समय पर चैक आदि लिखते हैं । इस प्रकार ऋणों के परिमाण में बैंक के निक्षेप भी बढ़ जाते हैं ।

### मात्र निक्षेपों का निर्माण

मात्र निक्षेपों का निर्माण भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता है । मान लीजिए किसी ग्राहक को १००० रुपये की आवश्यकता है और वह बैंक के पास जाता है तो वह उस व्यक्ति के साथ की जाँच करके उसमें प्रतिज्ञा-पत्र लेकर उसकी कटौती करेगा । अर्थात् १००० रुपये के प्रतिज्ञा-पत्र के बदले उस रकम पर जिस अवधि का प्रतिज्ञा-पत्र होगा, उस समय का व्याज घटाकर दोष रुपये से उसका मुक्त निक्षेप-लेखा खोल देगा जिस पर ग्राहक चैक लिख सकेगा । इस प्रकार बैंक ने प्रतिज्ञा-पत्र के रूप में ग्राहक की मात्र को स्वर्गदा तथा उसके

<sup>1</sup> Deposits are created by Loans and Loans are created by deposits or Loans are children of deposits and deposits are the children of Loans

आधार पर उसका नया लेगा खोलकर चैक लिखने का अधिकार दिया, अथवा अपनी मात्रा उसे बेच दी। इस प्रकार व्यापारिक बैंकिंग में विशेषतः मात्रा का कय-विनय होना है तथा ऋणों या कटीती द्वारा निक्षेपों की रकम बढ़ाई जाती है। इन निक्षेपों का समय-समय पर बैंकों द्वारा भुगतान होते रहने के कारण मात्रा पत्रों का विनिमय-माध्यम के रूप में पर्याप्त उपयोग होता है। इसलिए बैंक को मात्रा का निर्माता (creator of credit) कहा जाता है।

बैंक मात्रा निर्माण दो प्रकार से करते हैं—(१) पत्र मुद्रा चलन में तथा (२) ग्राहकों को ऋण देकर उनके नाम निक्षेप-लेखे खोलकर।

(१) जहाँ तब पत्रमुद्रा-चलन का सम्मुख है आजकल यह अधिकार केवल केन्द्रीय बैंक को ही है। इसलिए अन्य बैंक पत्र मुद्रा-चलन नहीं कर सकते। किन्तु मान लीजिए कि १०,००० रुपये की पत्र मुद्रा-चलन में लाई गई एवं उसकी परिवर्तनशीलता के लिए धातु-निधि में केवल ४००० रु० का ही स्वर्ण तथा चाँदी रहती है। बैंक ने  $10,000 - 4,000 = 6,000$  रुपये की मात्रा निर्माण की। इस प्रकार मात्रा निर्माण करने की शक्ति बैंक को परिवर्तनशीलता के लिए जो धातु निधि रखनी पड़ती है उससे सीमित होती है।

(२) बैंक ऋण द्वारा मात्रा-निक्षेपों की वृद्धि कर मात्रा निर्माण करते हैं। इन निक्षेप लेखा पर कर्जदारों द्वारा चैक लिखे जाते हैं जिनसे व्यापारिक व्यवहारों का विवेकत भुगतान होता है। भारत में सा चैकों का चलन बहुत कम है किन्तु विदेशों में दैनिक व्यवहार में चैकों का ही अधिकतर उपयोग होता है एवं वास्तविक रोकड़ की आवश्यकता बहुत कम होती है। इसलिए श्री हार्टने विदर्स ने कहा है कि 'आधुनिक ब्रिटिश व्यापार एवं अर्थ की मुद्रा चैक है तथा लन्दन मुद्रा-मण्डी में जिस मात्रा में व्यवहार होता है वह है चैक लिखने का अधिकार,' और यह सब मात्रा बैंक द्वारा ऋण देने में निर्माण होती है।

**मात्रा-निर्माण की सीमा**

किन्तु मात्रा निर्माण कार्य बैंक असीमित मात्रा में नहीं कर सकते। उनकी मात्रा-निर्माण-शक्ति की निम्न सीमाएँ हैं—

१ रोकड़-निधि—बैंक को निक्षेपों के भुगतान के लिए कुछ रोकड़-निधि रखनी पड़ती है। यह रोकड़-निधि कुछ विवेक अनुपात से कम नहीं हो सकती। अतः रोकड़-निधि न्यूनतम सीमा पर आने की दशा में बैंक मात्रा निर्माण नहीं कर सकते।

(२) कन्द्रीय बैंक के पास बंधानिक कोष—इसी प्रकार प्रत्येक बैंक को अपने पास या रिजर्व बैंक के पास कुछ राकड़ निधि रखना अनिवार्य होना है। इस निधि में बैंक की मात्र निमाण शक्ति सीमित होती है।

(३) निक्षेपकों की इच्छा—गर वाल्टर नीप्प व अनुसार बैंक का मात्र निमाण शक्ति निक्षेपकों की इच्छा पर निर्भर रहता है। क्योंकि यदि जनता बैंक के पास अपने निक्षेप रखना बन्द कर दे तो बैंक मात्र निमाण नहीं कर सकत।<sup>१</sup>

(४) जमानतों की किस्म—बैंक अधिकांश रूप प्रतिभूतियाँ की जमानत पर देता है। अतः प्रतिभूतियाँ किस प्रकार की हैं इस पर बैंक का मात्र निमाणशक्ति सीमित होती है।<sup>२</sup>

(५) कन्द्रीय बैंक के साथ नियन्त्रण के साधन—बैंक का मात्र निमाण शक्ति कन्द्रीय बैंक के साथ नियन्त्रण-साधन से सीमित होती है क्योंकि कन्द्रीय बैंक अपने साधन द्वारा मुद्रा एवं मात्र का प्रसार एवं सकुचन करता है।

(६) धातु निधि—पत्रमुद्रा चलन द्वारा मात्र निमाण पत्र मुद्रा के परिवर्तन के लिए जो धातु निधि रखना पड़ती है उसमें सीमित रहता है। किन्तु भी देश में यह न्यूनतम धातु निधि कम बना होना चाहिए।

(७) मात्र-पत्रों का उपयोग—बैंक की मात्र निमाण शक्ति सामान्यतः के उपयोग पर निर्भर रहता है। जितना अधिक मात्र पत्रों का उपयोग होगा उतना कम राकड़ निधि बैंक को रखना होगा जिसमें उसकी मात्र निमाण शक्ति होगी। इसके विपरीत अवस्था में मात्र निमाण शक्ति घटती है।

उपरोक्त सीमाओं का दखन हुए यह ठीक हो कहा गया है कि बैंक मात्र का निभाता नहीं है और न वह मुद्रा का निभाता है। किन्तु वह उन व्यक्तियों की राशि का जो उनका समुचित उपयोग नहीं कर सकत उनमें उबर अन्य व्यक्तियों का जो उनका उत्पादन के लिए उपयोग कर सकत हैं उनका रूप की मुद्रियाँ बनवाना व्यक्ति है। अतः निक्षेपकता एवं रूपा हो मात्र का निमाण करत है न कि बैंक।

साथ ही पजी है—आधुनिक व्यापार एवं वाणिज्य क्षेत्र में उत्पादन में

<sup>१</sup> Banking by Walter Leaf, p 101.

<sup>२</sup> Banking credits are manufactured not by banks, but by the customers who apply to them and by the security that the customers bring

<sup>३</sup> Prof Kannan

उपभोग तथा की सब क्रियाएँ मात्र पर ही निर्भर है, अतः कतिपय अर्थशास्त्रियों का यह भ्रम हो गया है कि 'साख ही पूँजी है।' इतना ही नहीं, अपितु मैकनाइड का कथन है कि "साख पूँजी का निर्माण करती है। मात्र एवं मुद्रा दोनों ही पूँजी हैं, व्यापारिक साख पूँजी है।" किन्तु यह केवल भ्रम है सत्य नहीं, क्योंकि साख की वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की धन-राशि अथवा वस्तुएँ अपने उपयोग के लिए प्राप्त कर सकता है। परन्तु यदि वे वस्तुएँ उसे प्राप्त न हों तो उसकी साख उसको उत्पादन में सहायक नहीं हो सकती। अर्थात् उत्पादन के अन्य घटकों की भाँति साख केवल उत्पादन नहीं कर सकती क्योंकि साख उत्पादन का स्वतन्त्र घटक नहीं है अपितु साख में मनुष्य अन्य व्यक्ति से उत्पादन के साधन प्राप्त कर सकता है। अतः मात्र साधन है साध्य नहीं। मात्र अन्य व्यक्तियों की पूँजी उपयोग करने की आज्ञा है, पूँजी नहीं। प्रो० मिल ने इसको प्रमाणित करने हुए कहा है कि 'ऋण में नई पूँजी का निर्माण नहीं होता किन्तु ऋणदाता की पूँजी ऋणी के धन हस्तान्तरित होती है।' इस हस्तान्तरण से यह नहीं कहा जा सकता कि देश की पूँजी दुगुनी हो गई है। हाँ, उत्पादन के साधन प्राप्त करने के लिए देश की पूँजी बढ़ाने के लिए मात्र सहायक अवश्य होती है। प्रो० रिचार्डों ने भी कहा है कि "साख पूँजी का निर्माण नहीं करती, उससे केवल यह निश्चित होता है कि पूँजी का उपयोग किसके द्वारा होगा।" अतः साख ही पूँजी है अथवा मात्र में पूँजी का निर्माण होता है, यह धारणा भ्रममूलक है। इतना ही नहीं अपितु किसी व्यक्ति अथवा व्यापारी की साख उसकी धन-राशि अथवा पूँजी पर निर्भर रहती है तथा उसकी हानि होने से उसकी मात्र भी घट जाती है। अतः साख पूँजी न होता है, किसी अन्य व्यक्ति की पूँजी का उपयोग करने की अनुमति मात्र है।

**साख और मूल्य**—साख और कीमतों के सम्बन्ध में भी अर्थशास्त्रियों में एकमत नहीं है। प्रो० मिल के अनुसार साख के प्रसार एवं संकुचन प्रभाव कीमतों पर मुद्रा की ही भाँति होता है क्योंकि साख द्वारा क्रय विव्रण होता है। इसलिए मुद्रा की कुल मात्रा में वास्तविक चलन तथा साख-चलन दोनों का समावेश होता चाहिए। इसीलिए मूल्य स्थिरता के हेतु केन्द्रीय बैंक साख-नियंत्रण करते हैं जिससे मात्र का प्रसार आवश्यकता से अधिक न हो सके।

इसके विपरीत प्रो० बॉवर और लाँग्लिन (Laughlin) के अनुसार मात्र का कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं होता क्योंकि मात्र में अंतिम भुगतान न होने हुए मुद्रा से ही अंतिम भुगतान होता है। साख-पत्रों के भुगतान के लिए मुद्रा

की आवश्यकता होगी इस कारण साख से मुद्रा की मात्रा में वृद्धि नहीं हाती और न उसका कीमती पर ही बाड़ प्रभाव होता है।

प्रा० की म व अनुसार साख का प्रभाव सामान्य मूल्यस्तर पर होता है परन्तु उतना नहीं जितना कि चलन का होता है। क्योंकि मात्र की वृद्धि के साथ बैंक के राकड़ निधि में भी वृद्धि हाती है। राकड़ निधि में वृद्धि से वास्तविक चलन घट जाता है। परन्तु वास्तविक चलन उना अनुपात में कम नहीं हाता जितनी की मात्र में वृद्धि होती है। इस कारण मात्र की वृद्धि के साथ मूल्यस्तर में वृद्धि हाता है परन्तु मुद्रा की वृद्धि की अपेक्षा कम अनुपात में। इस प्रकार साख एक मूल्यस्तर का घनिष्ट सम्बन्ध है।

साख का प्रभावित करने वाला बात

साख के आर्थिक विज्व में मात्र का महत्व अत्यन्त हात के कारण हमना यह जानना आवश्यक है कि क्या साख में मात्र का विस्तार किन घटका से प्रभावित होता है। ये प्राप्ति निम्न है —

(१) लाभ की दर—जितनी अधिक सुरक्षा विनियोगों में हाता तथा उन पर जितना अधिक लाभ मिलना उतना ही अधिक ऋण देने का प्रवृत्ति विनि यात्ताओं में हागी।

(२) आर्थिक स्थिति आर्थिक तन्त्रा एक मंदी का प्रभाव भी साख पर पडाता है। आर्थिक तन्त्रा के समय व्यापार एवं उद्योग का अधिक घटन का आवश्यकता हाता है। इसमें व्याज दर एवं लाभ दर घट जाती है। अतः दान में साख का प्रसार अधिक होता है। इसमें विपरीत स्थिति में साख का प्रसार कम हो जाता है।

(३) स्वध विनिमय परिस्थिति—स्वध विनिमय में जब मद्रु का प्रवृत्ति अधिक हाती है तब मगरिया का अधिक धन का आवश्यकता हाता है। अतः साख का प्रसार हाता है। परन्तु जब स्वध विनिमय में मंदी रहता है तथा सट्टा कम हा जाता है तब साख का प्रसार कम हात पाता है।

(४) केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति—केन्द्रीय बैंक साख का नियंत्रण हात के कारण उसकी मौद्रिक नीति का इरिणाम साख के प्रसार एवं अभाव पर हाता है। जब दान के आर्थिक विकास अथवा मूल्य स्तर ऊचा करने के हेतु केन्द्रीय बैंक मुलभ मुद्रा नीति अपनाती है तब साख का प्रसार हाता है। जब विपरीत जब केन्द्रीय बैंक मूल्य स्तर कम करने के लिए अथवा अधिक न घटने देने के लिए दुर्गम मौद्रिक नीति अपनाता है तब साख का अभाव हाता है।

(५) बैंकिंग का विकास—दश में जिनकी बैंकिंग प्रणाली जितनी अधिक विनियमित होगी उतनी ही मुद्रा में स्थानान्तरण में सुगमता होगी तथा बैंक मान्यता का निर्माण अधिक कर सकेंगे। इसके विपरीत स्थिति में साख का निर्माण कम होगा।

(६) विनिमय माध्यम का स्वरूप—दश में विनिमय माध्यम के लिए यदि सामान पत्रों का अधिक चयन होगा तो बैंकों को कम राकड़ निधि रखनी होगी। फलतः साख का अधिक प्रसार न हो सकेगा। परन्तु यदि विनिमय माध्यम के लिए सामान पत्रों का अधिक उपयोग होता है तो बैंकों को रोक निधि कम रखनी होगी। इसमें साख का अधिक निर्माण होगा।

(७) देश की आर्थिक नीति—दश की आर्थिक नीति यदि उद्योगों का उत्साह बढ़ाती है तो दश का औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास होगा। ऐसी दशा में साख का अधिक प्रसार होगा। परन्तु यदि आर्थिक नीति में अनिश्चितता होगी तो उद्योगों का विकास का अवसर नहीं रहेगा तथा साख की वृद्धि नहीं होगी।

(८) राजनीतिक स्थिति—दश की राजनीतिक स्थिति सुरक्षित है तो उद्योग एवं व्यापारिक विकास का चलन मिलता है तथा साख की मांग अधिक होने से साख का प्रसार होता है। परन्तु राजनीतिक अस्थिरता एवं अस्थिरता की स्थिति से व्यापार एवं उद्योगों में अनिश्चितता एवं भय का वातावरण रहता है। इस कारण ऋण की मांग अधिक न होने से साख का संकुचन होता है।

संक्षेप में राजनीतिक स्थिरता, मुद्रा एवं उत्साहबोधक आर्थिक नीति, केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति एवं आर्थिक विकास की स्थिति पर देश में साख का प्रसार या संकुचन निर्भर रहता है।

### सारांश

‘साख किसी भी व्यक्ति की वह शक्ति है जिससे वह अन्य व्यक्तियों से धन अथवा आर्थिक वस्तुओं किसी अवधि के उपयोग के लिए लेता है।’ साख व्यवहार में चरमान आर्थिक वस्तुओं का विनिमय भविष्य की आर्थिक वस्तुओं के साथ होता है। जोड़ के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय है जो कुछ निश्चित समय के बाद भुगतान होने पर पूरा होता है।’

साख में चार तत्व होते हैं (१) समय (२) विकास, (३) निश्चित राशि, (४) जमानत।

साख कई प्रकार की होती है—उपभोग के लिए ली गई उपभोग्य साख

उत्पादन कार्यों के लिए जाने वाली उत्पादी साख, व्यापारिक कार्यों के लिए ली जाने वाली व्यापारिक साख, व्यक्ति द्वारा ली जाने वाली व्यक्तिगत साख, सरकार द्वारा जनता से लिए जाने वाले ऋण—राष्ट्रीय साख, बैंक द्वारा निर्माण की जाने वाली बैंकसाख होती है।

साख से लाभ—पूँजी की उत्पादन शक्ति में वृद्धि, विनियोग साधनों में वृद्धि, विनिमय माध्यम में वृद्धि तथा मुद्रा की मितव्ययिता, रथगिन भुगतान संभव, बड़ी राशि के भुगतान में सुगमता, आर्थिक सकट का सामना सम्भव।

मात्र में हानि—फिजूलखर्चों को प्रोत्साहन, सदृष्ट को प्रोत्साहन, उत्पादन में अप्रवृत्ति, औद्योगिक अक्षमता को बढ़ावा।

बैंक द्वारा साख निर्माण—बैंक ग्राहकों से निक्षेप-राशि लेते हैं जो उनकी कार्यशील पूँजी होती है। इसमें से वह भाग पर भुगतान के लिए कुछ राशि रोकड़ निधि में रखकर शेष ऋण देने के काम में लाते हैं। इस प्रकार निक्षेपों से ऋणों का निर्माण होता है। ऋण लेने वाली बैंक के ग्राहक हो होने हैं जो स्वीकृत ऋण की राशि अपने पास न लेते हुए अपने खातों में जमा करते हैं जिससे निक्षेपों में वृद्धि होती है। अतः ऋणों से निक्षेपों का निर्माण होता है। इस प्रकार बैंक के पास दो प्रकार के निक्षेप होते हैं—रोकड़-निक्षेप एवं साख-निक्षेप। साख निक्षेपों का निर्माण दो प्रकार से होता है—(१) पत्र-मुद्रा चलाने पर जो अधिकार आजकल केवल केन्द्रीय बैंक को है, (२) ऋण देकर।

बैंक साख निर्माण-शक्ति निम्न बातों से सीमित होती है—(१) रोकड़ निधि (२) निक्षेपों की इच्छा (३) जमानतों की किस्म (४) केन्द्रीय बैंक के साख नियंत्रण के साधन (५) धातुनिधि (६) केन्द्रीय बैंक के पास बंधानिक कौष (७) साखपत्रों का उपयोग।

साख एवं पूँजी—भी मेक्लाइड के अनुसार साख ही पूँजी है परन्तु यह भ्रम है। क्योंकि साख पूँजी का निर्माण नहीं करती उससे केवल यह निश्चित होता है कि पूँजी का उपयोग कौन करेगा।

साख और मूल्य के सम्बन्ध के बारे में दो विचारधाराएँ हैं। मेक्लाइड के अनुसार साख के प्रसार एवं संकोच का प्रभाव मूल्य-स्तर पर होता है। अर्थात् साख प्रसार के साथ कीमतें बढ़ती हैं और संकोच के साथ कीमतें गिरती हैं। इसके विपरीत वॉकर आदि का कथन है कि साख का प्रभाव मूल्य स्तर पर नहीं होता। परन्तु दोनों ही बातें सही नहीं हैं। प्रो० बीन्स ने इसकी स्पष्ट किया है जिनके अनुसार निक्षेपों के आधार पर साख निर्माण होता है।

अतः निक्षेपो से कुछ मुद्रा रोकड़ निधि में बैंक रखकर साख निर्माण करते हैं। अतः मुद्रा जितनी चलन से कम होती है उसके अनुपात में साख अधिक बढ़ती है। इसलिए मूल्य-स्तर प्रभावित होते हैं परन्तु उनका अनुपात चलन के प्रसार या सकोच से मूल्य-स्तर पर होने वाले प्रभाव से कुछ कम होता है।

किसी देश में साख का प्रसार निम्न बातों पर निर्भर है—(१) लाभ की दर (२) देश की आर्थिक स्थिति (३) स्कन्ध विनिमय परिस्थिति (४) केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति, (५) बैंकिंग का विकास (६) विनिमय माध्यम का स्वरूप (७) देश की आर्थिक नीति तथा (८) देश की राजनीतिक स्थिति।

## अध्याय ८

### साखपत्र

साख का पूरी तरह उपयोग करने के लिए साखपत्र का प्रयोग किया जाता है। साखपत्र उन सब पत्र या साधना का कहते हैं जिनका उपयोग मन्त्र के स्थान पर कृपा के लेन-देन या मौज के समनान में किया जाता है। इन पत्रों में विधिब्राह्मता नहीं होना अपितु ये कानून द्वारा मान्य होना हैं। इनका कृपा या लेन-देन में स्वीकार करना या न करना व्यक्ति का कर्तव्य पर निर्भर होता है। साखपत्र दो प्रकार के होते हैं—(१) वचनमाध्य (परक्राम्य—perpetual) तथा (२) उचानरहित (अपरक्राम्य)।

वचनमाध्य साखपत्र वचनमाध्य विनियम के अनुसार वचनमाध्य विलख लिखित विनियम होता है जिसका सम्पत्ति हस्तांतरण एवं उचान से अथवा कबल हस्तान्तरण में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तांतरित होगा है जो हस्तान्तरक का उपाधि के रूप में वावजूत पूर्ण सम्भावना में उसे स्वीकार करता है एवं जिसका यथाविधि धारण अपने नाम पर उसका सम्पत्ति के लिए किया गया कार्यवाही कर सकता है। इसकी विनियमताएँ निम्न हैं—

(१) उचानमाध्य विलख लिखित होता है। (२) विनियम कबल दोन से अथवा वचन महिन दोन में उनका सम्पत्ति का स्वामित्व हस्तान्तरिनी एवं पुष्पाविका का प्राप्त होता है। (३) वचनमाध्य साखपत्र में हस्तान्तरिका का चक्र का धारा होना के नाते दावा करने का अधिकार है। (४) हस्तान्तरक (transferor) को उपाधि मन्त्र होना हुआ है या उसे विलख का स्वामित्व मुख्य के धारा (holder for value) का अर्थ किमा के अधिकार के दिना प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ में एक धारण वचन जिसका समनान में मन्त्र चक्र द्वारा दिया गया या वाहक (bearer) था। वाच में मान्य हुआ कि वह चक्र उस व्यक्ति का चराया हुआ था या उन व्यक्ति के विरुद्ध वधानिक कार्यवाही होगा परन्तु मन्त्र विरुद्ध नहीं होगा क्योंकि उस चक्र का मूल्य जयान् अपना धारण में उस दिया है। परन्तु वचनरहित साखपत्र में यह बात नहीं होगी।

**धारी** -वचनसाध्य विलेख अधिनियम (धारा ८) के अनुसार 'किसी प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय-विल अथवा चैक का धारी वह है जिसका अपन ही नाम से उस पर अधिकार है तथा उसके पक्षकारा से वह राशि प्राप्त (recover) कर सकता है।' इस परिभाषा के अनुसार धारी वह है जिसे निम्न अधिकार हैं —

- (१) उस विलेख की सम्पत्ति का अपन नाम में लेन का अधिकार हो,
- (२) आदाता बाहक तथा पृष्ठाधिकी के नाते विलेख के पक्षकारा के विरुद्ध वैधानिक कायवाही करने का अधिकार प्राप्त हो, तथा
- (३) उसकी उपाधि वैधानिक रीति से उस प्राप्त हुई हो।

किसी भी वचनसाध्य मागपत्र का धारी वह है जिसका अपन नाम उनकी सम्पत्ति लेन का अधिकार है तथा उसका पक्षकारों में उसकी सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। किन्तु किसी विलेख का किसी व्यक्ति के पास होना उसको धारी नहीं बनाता जब तक कि उसकी सम्पत्ति प्राप्त करने का अधिकार उस में न हो। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जिसे छाया हुआ विलेख जो बाहक है मिला है अथवा चोरी किया हुआ विलेख जिस व्यक्ति के पास है वह उस विलेख का धारी नहीं होगा। क्योंकि उसका न तो उस पर वैधानिक अधिकार है और न वह उस विलेख के पक्षकारा से उसकी सम्पत्ति ही प्राप्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जब तक वह विलेख का स्वत्वधारी स्वामी नहीं है, अथवा जो आदाता (payer) नहीं है अथवा वचन में आदाता नहीं बनाया गया है अथवा बाहक विलेख में बाहक आदाता नहीं है तो वह विलेख के पक्षकारा के विरुद्ध वैधानिक कायवाही नहीं कर सकता।

**यथाविधि धारी**— किसी बाहक चैक विनिमय विल अथवा प्रतिज्ञा पत्र का यथाविधि धारी वह व्यक्ति है जो किसी प्रतिफल के लिए अधिकारी होता है अथवा आदेना विलेखा में वह आदाता अथवा पृष्ठाधिकी होता है तथा यह अधिकार उसे इन विलेखा के भुगतान होने के पूर्व ऐसे व्यक्ति में प्राप्त हुआ हो जिसकी उपाधि मदीय होने के लिए कोई विश्वसनीय कारण न हो। इस परिभाषा से यथाविधि धारी की निम्न विशेषताएँ हैं —

१ विलेखों के अनादरण एवं भुगतान की अवधि के पूर्व यह अधिकार प्राप्त किया हो।

२ किसी मूल्य के विनिमय में पूर्ण सद्भावना से विलेखा का प्राप्त किया हो।

३ जिस समय विलेख का वचन हुआ उस समय वचनकर्ता की उपाधि किसी प्रकार के दूषित (defective) होने की जानकारी न हो।

४ विलेख की प्राप्ति किसी प्रतिफल (consideration) के बदले को गयी हो एवं प्रतिफल मूल्यवान हो ।

५ विलेख पूर्ण एवं नियमी (regular form) हो ।

ऐसा यथाविधि-धारी उन विलेखों की सम्पत्ति के लिए अन्य पक्षों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा ।

कपट तथा चोरी अथवा अन्य अशुद्ध मार्गों से प्राप्त आदेश विलेखों का हस्तान्तरण तथा पृष्ठांकन से हस्तान्तरित अथवा पृष्ठांकन की हस्तान्तरण एवं पृष्ठांकन से अच्छी उपाधि नहीं देता । इसके विपरीत वाहक विलेखों से हस्तान्तरित यदि विलेखों को मद्भावना एवं मूल्य के विनिमय में लेता है तो उसकी उपाधि में कोई भी दोष नहीं रहता ।<sup>१</sup>

वेचान साध्य मान्य विलेखों में चैक, विनिमय-बिल तथा प्रतिज्ञा-पत्रों का समावेश होता है ।

चैक

परिभाषा—“चैक किसी विशेष बैंक पर लिखा हुआ विनिमय-बिल है, जिसका मांग पर भुगतान हो । इस धारा में जिन अपवादों को दिया है, उनके अतिरिक्त मांग पर भुगतान होने वाले विनिमय-बिलों की सब धाराएँ चैक को भी लागू होंगी ।”<sup>२</sup> किन्तु विनिमय बिल क्या होता है ? विनिमय बिल लेखक का किसी व्यक्ति के लिए गर्व-रहित लिखित आदेश होता है कि वह किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा उसके वाहक का निश्चित मुद्रा दे । इस आदेश पर लेखक के हस्ताक्षर होने हैं ।<sup>३</sup>

इन दोनों परिभाषाओं के समन्वय में यह स्पष्ट है कि चैक एक व्यक्ति द्वारा किसी निश्चित बैंक को दिया हुआ लिखित एवं गत रहित आदेश है, जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं; जिसमें कोई निश्चित रकम किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार अथवा वाहक को देने के लिए आदेश होता है । हम परिभाषा में हम केवल उमी प्रलेख को चैक कह सकते हैं जिनमें निम्न विशेषताएँ हों<sup>४</sup> —

(१) लिखित आदेश—अर्थात् किसी व्यक्ति का केवल जवानी आदेश

<sup>१</sup> Sec १८ of the Negotiable Instrument Act

<sup>२</sup> Sec ७३ of the Negotiable Instruments Act

<sup>३</sup> Sec १ of the Negotiable Instruments Act

<sup>४</sup> Banking Law & Practice in India by Tannan

चैक नहीं होगा। यह आदेश किसी भी वागज के टुकड़े पर पेंसिल अथवा स्याही से लिखा हुआ हो। यह आदेश टंक-मुद्रित (type written) अथवा मुद्रित भी हो सकता है। किन्तु सुरक्षा की दृष्टि से बैंक चैको के छपे हुए फॉर्म रखने हैं जिन्हें पर चैक लिये जा सकते हैं। इसी प्रकार ग्राहक का हिमाव सोलने गमय बैंक यह हिगाज लगाने है कि चैक स्याही से लिखे हुए या टंक-मुद्रित होना चाहिए।

(२) शर्त-रहित आदेश—जिम्मे को आदेश दिया गया है उस पर भुगतान करने सम्बन्धी किसी प्रकार की शर्त न हो। उदाहरणार्थ, किसी भुगतान के लिए रसीद आदि देने की शर्तें लगा दी जाय तो वह चैक नहीं होगा।

(३) किसी निश्चित बैंक के नाम आदेश—यह आदेश निश्चित बैंक के अनिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। उदाहरणार्थ, 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया' पर लिखे हुए चैक में स्टेट बैंक का कौन-सा कार्यालय है यह निश्चित नहीं होता। अतः यह निश्चितता लाने के लिए उसका पूरा नाम तथा स्थान होना चाहिए।

(४) माँग पर भुगतान देने का आदेश—विशेष में कोई ऐसी बात न हो जिसमें उस आदेश या चैक का भुगतान बैंक को प्रस्तुत करने पर न मिले। इसमें 'माँग पर भुगतान हो' ये लिखना।

(५) चैक लिखने वाले के हस्ताक्षर उस पर होना आवश्यक है। अन्यथा उस आदेश का कोई मूल्य नहीं रहेगा और न वह आदेश ही होगा।

(६) रकम के भुगतान की राशि निश्चित हो—यदि मुद्रा के अनिरिक्त अन्य किसी वस्तु के भुगतान का आदेश दिया है तो उसमें निश्चितता नहीं होगी और न ऐसा आदेश चैक ही होगा। अगर बैंक किसी विदेशी बैंक को दिया जाता है और उसमें किसी विशेष विनियम दर का उल्लेख नहीं किया गया है, तो उसका भुगतान तत्कालीन विनियम दर से होगा। इसी प्रकार भारतीय परब्राम्य-विशेष अधिनियम के अनुसार यदि विदेशी मुद्रा में चैक हो एवं उसका विनियम दर दिया गया हो अथवा उसमें दी हुई व्याज-दर से भविष्य के व्याज का समावेश करना हो तो सब बातें निश्चित होने के कारण आदेश की रकम भी निश्चित रहती है। इसलिए वह आदेश चैक ही होगा।

(७) जिस व्यक्ति को भुगतान करना है उसका निश्चित एवं स्पष्ट उल्लेख हो अथवा उसके आदेशानुसार अथवा वाहक को भुगतान होगा, यह भी निश्चित होना चाहिए ताकि पाने वाले की निश्चितता हो जाय।

उक्त बातों के साथ ही नियमी बैंक में निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, अन्यथा बैंक भुगतान नहीं देगा.—

(१) तिथि—बैंक पर जिस तिथि को वह लिखा गया है, वह तारीख होनी चाहिए। परन्तु बैंको पर तिथि न होने पर भी बैंक अथवा धारी उस पर तिथि डाल सकता है किन्तु सामान्य रूप में बैंक ऐसे बैंको वा भुगतान नहीं करते। बैंक उत्तर-तिथीय (post-dated) अथवा पूर्व-तिथीय (anti-dated) भी होने हैं। पूर्व-तिथीय (anti-dated) बैंक वे होते हैं जिन पर जिस दिन वे भुगतान के लिए उपस्थित किए जाते हैं उससे पहले की तिथि होती है। इस दशा में उनका भुगतान होता है किन्तु यदि वह तिथि उपस्थिति के ६ महीने पहले की है तो बैंक उनका भुगतान नहीं करेगा। क्योंकि वे बीतकाल (stale) हो जाते हैं। उत्तर-तिथीय (post-dated) बैंको का भुगतान बैंक उस तिथि के पहले नहीं करते। वास्तव में ऐसे उत्तर तिथीय-धनादेश बैंक नहीं कहे जा सकते क्योंकि उस तिथि में पहले उपस्थित करने पर उनका भुगतान नहीं मिल सकता।

(२) पाने वाले का नाम (Payee's Name)—बैंको पर पाने वाले का नाम स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। उस पर उसकी उपाधियाँ, जैसे राय साहब, राय बहादुर आदि लिखन की आवश्यकता नहीं होती। पाने वाले का नाम बैंक में 'pay to' ('भुगतान करो') के आगे जो रखा होती है उस पर लिखा जाता है। अवैयक्तिक व्यक्तियों के नाम के बैंक सामान्यतः वाहक बैंक होते हैं, किन्तु वैधानिक व्यक्तियाँ (legal or corporate persons) के नाम दिये जाने वाले बैंक आदेश बैंक (order) होते हैं। वाहक बैंको में बैंक पर दिये हुए "आदेश वाहक" शब्दों में 'आदेश' शब्द को काट देना चाहिए। इसी प्रकार आदेश बैंक पर में वाहक शब्द को काट देना चाहिए। किन्तु यदि बैंक केवल किसी विशेष व्यक्ति के भुगतान के लिए ही हो तो 'भुगतान करो' के आगे की रेखा पर पाने वाले के नाम के साथ 'बस' (only) शब्द लगा देना चाहिए तथा 'आदेश वाहक' इन दोनों शब्दों को काट देना चाहिए।

(३) राशि—बैंक पर राशि न लिख दो स्थान होने हैं जिनमें से एक पर अंकों में तथा दूसरे पर शब्दों में राशि लिखी जाती है। ये दोनों राशियाँ निम्नलिखित समान उमंगें किसी प्रकार का अन्तर न हो, यह ध्यान रखना चाहिए। राशि इस प्रकार में लिखनी चाहिए जिसमें कोई अन्य व्यक्ति राशि को बढ़ा न सके। क्योंकि यदि ग्राहक की भूल में ऐसी गड़बड़ रह जाय तथा व्यक्ति 'दा

मौ रुपये' के पहिले 'एक हजार' शब्द बढाकर 'एक हजार दो मौ' करदे और वैंक पूर्ण मानधानी रखने हुए भी इस परिवर्तन का न पकड़ सके तो उस भुगतान में यह ग्राहक का डेबिट कर सकता है । इसलिए इस सम्बन्ध में ग्राहक को मानधानी रखनी चाहिए ।

(४) लिखने वाले के हस्ताक्षर—चैंक लिखने वाले के हस्ताक्षर वैंक के पाम जो नमूना हस्ताक्षर (specimen signature) होते हैं उसी प्रकार होने चाहिए । चैंक पर लिखने वाला स्वयं हस्ताक्षर करता है अथवा उसका अधिकृत अभिवर्त्ता हस्ताक्षर करता है । चैंक पर कोई भी हस्ताक्षर करे, उसके हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर में मिलने चाहिए तभी वैंक उनका भुगतान करेगा । ऐसे हस्ताक्षर अधिकृत व्यक्ति को स्वयं ही स्थायी से करने पड़ते हैं, हस्ताक्षर की मोहर लगाने में काम नहीं चलता, क्योंकि वैंक ऐसे हस्ताक्षर को मान्य नहीं करता ।

अनपढ़ ग्राहको के अँगूठे की निशानी (thumb impression) वैंक मान्य करना है किन्तु इसकी गवाही के लिए यैंक किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाने हैं । इसी प्रकार यदि कोई ग्राहक बीमारी की हालत में अपने हस्ताक्षर ठीक नहीं कर सकता, उस समय उसके हस्ताक्षर उसके डॉक्टर द्वारा प्रमाणित होने चाहिए ।

चैंक के पक्ष—चैंक में तीन पक्ष होते हैं—(१) लिखने वाला, (२) पाने वाला तथा (३) देने वाली वैंक (drawee) । लिखने वाला वह व्यक्ति होता है जो चैंक लिखकर आदेश देता है, जिस वैंक का यह आदेश दिया जाता है उसे भुगतान देने वाली वैंक, तथा जिस व्यक्ति का आदेश की राशि का भुगतान होता है अथवा जिस व्यक्ति के नाम चैंक लिखा जाता है उसे पानेवाला (आदाना) कहते हैं । चैंक का लिखने वाला देने वाली वैंक का ग्राहक होता है तथा उसका डेक में चल-लेखा होना चाहिए जिसमें उसके आदेशों का पालन किया जा सके । यदि वचत लेखा पर चैंक काटने का अधिकार हो तो ग्राहक नियमानुसार चैंक लिख सकता है ।

प्रतिफल (Consideration)—प्रत्येक वेचनामाध्य विलेख का आधार प्रतिफल होना है और बिना प्रतिफल के किसी भी विलेख का लिखना, बचान या हस्तान्तरण किसी व्यवहार के पक्षकारों का उत्तरदायी नहीं बनाता । यह प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए ।

इस प्रकार चैंको में मूल देनदारी देने वाली वैंक की होती है परन्तु उसका

प्राथमिक दायित्व लिखन बाने का होता है। क्योंकि बैंक द्वारा भुगतान न होने पर उमका भुगतान लिखन बान को ही करना होगा। अथवा यदि वह बैंक वचान द्वारा अन्य पक्षकारा के हाथ में होगा तो यथाविधि धारी को यह अधिकार होगा कि उस बैंक के मूल्य का दायित्व वह सम्बन्धित पक्षा पर प्रमाणित कर। लेकिन इसमें यह बात है कि अनादरण यथाविधि धारी द्वारा बैंक की मदद उपस्थिति के कारण अथवा लिखन बाने के लक्ष में अप्रयाप्त धन के कारण न हुआ है। इसी प्रकार अनादरण हान पर अनादरण की सूचना बैंक के सब पक्षकारा का दनी चाहिए। यदि बैंक मदद उपस्थिति के कारण अनादरित होता है तो उसकी जिम्मेदारी उसी व्यक्ति की होगी तथा लिखन बाने अथवा वचनकारा का किसी प्रकार का दायित्व न होगा।

**महत्वपूर्ण परिवर्तन ( Maternal Alterations )**—बैंक में किसी भी प्रकार के परिवर्तन पर उस लिखन बान के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। महत्वपूर्ण परिवर्तन उस कहते हैं जिसमें बैंक की मूल वैधानिक भाषा में अथवा पक्षकारा के दायित्व में परिवर्तन हो जाता है चाहे ऐसा परिवर्तन पान बाल का दण्ड में हानिकर हो अथवा न हो। महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्न हैं —

१ **तिथि का परिवर्तन**—जिससे भुगतान का समय अथवा अवधि बढ़ाई जा सके।

२ **स्थान का परिवर्तन**—बैंक की गाँवा में अथवा भुगतान के स्थान में परिवर्तन।

**राशि का परिवर्तन**—उसमें राशि का घटना अथवा वृद्धि माध्यम अथवा पौंड की जगह रुपया अथवा डॉलर का परिवर्तन विनिमय दर दी हुई तो उसमें परिवर्तन तथा व्याज की दर का हूट हो तो उसमें परिवर्तन आदि।

६ **पाने वाले के नाम में परिवर्तन**—पान बाला की मर्यादा में वृद्धि करना अथवा इस प्रकार का परिवर्तन करना जिससे उनका वैधानिक सम्बन्ध प्रभावित हो।

५ **विशेष रेखांकन का सामान्य रेखांकन में परिवर्तन।**

सामान्य रेखांकन बैंक का मुला बैंक बनाना।

७ **आदम बैंक का बाह्य बैंक में परिवर्तन।**

इस प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन बैंक के पक्षकारा की सम्मति में किया जा सकत हैं तथा इन परिवर्तन पर लिखन बान के हस्ताक्षर होना आवश्यक

है। किन्तु अगर किसी चैन की सुरक्षा के लिए सामान्य वेंचान अथवा सामान्य रेखांकन का विशेष वेंचान अथवा विशेष रेखांकन में परिवर्तन किया जाता है तो यह महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता। क्योंकि उसमें वैधानिक सम्बन्ध अथवा भाषा में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए बैंक को किसी भी चैन का भुगतान करने के पूर्व महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है, यह देय सेना आवश्यक है जिसमें उस पर किसी प्रकार का दायित्व न रहे। परन्तु यदि महत्वपूर्ण परिवर्तन ऐसा है जो सूक्ष्म परीक्षण में भी नहीं जाना जा सकता तथा बैंक पूर्ण मावधानी एवं सद्भावना में भुगतान करता है तो वह भुगतान यथेष्ट समझा जायगा।

### चैको का वार्डिकरण

१. आदेश बैंक तथा वाहक बैंक—आदेश बैंक की राशि पाने वाले को अथवा उसके आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करने वाले बैंक द्वारा दी जाती है किन्तु आदेशित व्यक्ति का भुगतान तभी हो सकता है जब मूल पाने वाला उस व्यक्ति का नाम उसका वेंचान करे। वाहक बैंक की राशि उस व्यक्ति को जिसके पास वह है एवं जो इसे भुगतान के लिए बैंक को उपस्थित कर दी जाती है। किन्तु ऐसे चैको पर भी बैंक राशि देने वाले के हस्ताक्षर करा लेते हैं।

२. खुला चैन तथा रेखांकित चैन—खुला चैन उन चैको को कहते हैं जो देने वाले बैंक के कार्यालय में पाने वाले अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा भुगतान जा सकते हैं। ऐसे चैन खो जाने पर कोई भी पाने वाला व्यक्ति उनकी राशि ले सकता है यदि वह वाहक बैंक है। इसी प्रकार आदेश बैंक होने पर भी पाने वाले अथवा वेंचान प्राप्त व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर द्वारा उनका भी भुगतान लिया जा सकता है। अतः खुले चैन यातायात के लिए अनुविधानजनक हैं क्योंकि उनमें कपट की सम्भावना रहती है। कपट से सुरक्षा के लिए चैको को रेखांकित किया जाता है।

रेखांकन—रेखांकित चैन वे हैं जिन पर दो समानान्तर रेखाएँ खींची जाती हैं तथा जिसका भुगतान पाने वाले को किसी बैंक के माध्यम से उपस्थित करने पर ही मिल सकता है, सीधे बैंक के कार्यालय से नहीं। रेखांकन तीन प्रकार का होता है—सामान्य रेखांकन बेचान रहित तथा विदोष रेखांकन।

सामान्य रेखांकन में चैन पर केवल दो समानान्तर रेखाएँ खींची जाती हैं जिससे उसका भुगतान पाने वाले को केवल किसी अन्य बैंक के द्वारा ही मिल सकता है। इस प्रकार की रेखाओं के बीच कभी-कभी 'E. Co.' शब्द लिखे जाते

है। हमसे बैंक का भुगतान किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं हो सकता जिसको उसका वैधानिक अधिकार नहीं है। रेखांकन से बैंक को केवल यह ध्वनि आदेश होता है कि वह उसका भुगतान अन्य बैंक के माध्यम से ही करे।

**वेचान-रहित रेखांकन**—सामान्य रेखांकन में जब गमानान्तर रेखांकन के बीच (Not negotiable) 'वेचान रहित' के शब्द लिखे जाने हैं तब उसे 'वेचान रहित रेखांकन' कहते हैं। वेचान रहित रेखांकन में बैंक का हस्तान्तरक हस्तान्तरिणी को अपनी उपाधि में अच्छी उपाधि नहीं दे सकता। इन बैंकों का हस्तान्तरण हो सकता है किन्तु वेचानमाध्यता नहीं रहती। उदाहरणार्थ यदि किसी हस्तान्तरक ने बैंक चुराया है और किसी मात्र के भुगतान में वह बैंक हस्तान्तरिणी को देता है तो हस्तान्तरिणी उसको मूल्य के बदले एवं पूर्ण मद्-भावना में लेने हुए भी अच्छी उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता तथा इस कपट का ज्ञान होने पर उस बैंक की रकम उस बैंक के स्वव्यवधारी स्वामी को लौटानी होगी। इसलिए वेचान रहित रेखांकित बैंक केवल घनिष्ठ व्यक्तियों में ही हस्तान्तरित हो सकता है।

## रेखांकन के उदाहरण सामान्य रेखांकन

बैंक १

बैंक २

& Co

बैंक ३

वेचान-रहित  
(Not Negotiable)

बैंक ४

पाने वाले के लेखे में  
(Payee's account)

**विशेष रेखांकन**—विशेष रेखांकन में बैंक पर दो समानान्तर रेखाओं के बीच किसी विशेष बैंक का नाम लिख दिया जाता है, जिसमें उस बैंक का भुगतान केवल उस बैंक के माध्यम से ही हो सकता है। बैंक का नाम तभी लिखा जाता है जब लिखने वाले अथवा वेचानकर्ता को पाने वाले अथवा वेचान प्राप्त-व्यक्ति (endorsee) के बैंक का नाम मालूम हो। दूसरे, इन समानान्तर रेखाओं के बीच 'p/c payee only' शब्द लिख दिये जाते हैं, जिससे बैंक की रकम केवल पाने वाले के बैंक के खाते में ही जमा की जाती है, उसकी तगद राशि उसे नहीं मिल सकती।

### विशेष रेखांकन

चैक १

इलाहाबाद बैंक लिमिटेड

चैक २

इलाहाबाद बैंक लिमिटेड

चैक ३

इलाहाबाद बैंक लिमिटेड  
केवल पाने वाले के खाते में

चैक ४

वेचानरहित  
इलाहाबाद बैंक लिमिटेड

**रेखांकन कौन कर सकता है ?**—बैंक का रेखांकन लिखने वाला अथवा यदि वह बैंक रेखांकित नहीं है तो पाने वाला अथवा वेचानकर्ता कर सकता है। यदि कोई बैंक सामान्य रेखांकित है तो उसका विशेष रेखांकन पाने वाला अथवा वेचानकर्ता भी कर सकता है। इसी प्रकार विशेष रेखांकित बैंक को कोई भी वेचानकर्ता वेचान-रहित रेखांकन में बदल सकता है। विशेष-रेखांकित बैंक को कोई भी बैंक दूसरे बैंक के नाम—जो उसका मग्राहक अभिकर्ता

(collecting agent) है, पुन बिशेष रखाकित नर मकता है। परन्तु उस प्रवार का रखावन एव बैंक द्वारा उसक मग्राहक अभिकता क नाम म ही पुन हो सकता है किमी अन्य बैंक क नाम स नही।

रेखाकित बैंक का भुगतान बैंक का रखाकन क अनुमार ही करना चाहिए अन्यथा दन वाला बक स्वत्वधारी पान वाल (rightful payee) क प्रति उत्तरदायी हाता है। इसलिए रखाकिन बैंक यदि किमी एम व्यक्ति का प्राप्न हाता है जिमका बैंक म लखा नही है ता उस बह बैंक मम व्यक्ति का हम्मानरित करना चाहिए जिमका लखा बैंक म हा तभी उसका भुगतान उस मिल सकता है।

बैंक खोना—किमी धारी स बैंक खा जाता है ता उसक लिए वह उत्तरदायी हाता है तथा उसका भुगतान बैंक क लिखन वाल अथवा बचानकता म लन ना अधिकार नही है। इसलिए बैंक क खान ही उनकी मूचना भुगतानकता बैंक तथा बचानकता का दनी चाहिए जिमम किमी अन्य व्यक्ति का उसका भुगतान न हा मक। क्योंकि भुगतान राकन का अधिकार केवल लिखन वाल का हाता है। किमी भी बैंक का भुगतान हान पर बैंक उसकी राशि क लिए धारी क प्रति उमी दना म उत्तरदायी होगा जब उसन उनका भुगतान नियमित रूप म न किया हो। मझेप म यदि बक सामान्य रेखाकित बैंक का भुगतान बैंक क अनिरित किमी अन्य व्यक्ति का तथा बिशप रखाकिन बैंक का भुगतान बैंक पर रखाकिन बक अथवा उसके अभिकता का न करत हुए किमी अन्य प्रकार स करता है ता यह बक बैंक क स्वत्वधारी स्वामी क प्रति उत्तरदायी हाता है।<sup>1</sup> इसी प्रकार लिखन वाला किमी बैंक क खा जानपर तभी उत्तरदायी हागा जब बैंक पान वाल की मूचनाआ के प्रतिकूल रूप म भजा गया हा। उदाहरणाय यदि मैं चाहता ह कि मेरा भुगतान आगर म रजिस्टर्ड पास्ट द्वारा हा और वह मुभ सामान्य पास्ट द्वारा भजा जाता है और वह खा जाता है ता मेरी मूचना क प्रतिकूल यह काय हान म लिखन वाला मेरा रुणी हो रहा। क्याकि बैंक मेरी गमती न खान हुए लिखन वाल की गलती म खाया है। इस प्रकार से बचानकता भी यदि बैंक का बचानप्राप्ति की मूचना क प्रतिकूल भजना है ता वह भी धारी क प्रति उत्तरदायी हाता है।

चिह्नित चक (Marked Cheques)—चिह्नित बैंक वह है जिस पर दन वाला बैंक नान स्वाही म अपन हम्मानर कर दना ह। इसका अय है कि जिम

<sup>1</sup> Sec 126 of the Negotiable Instruments Act

दिन यह हस्ताक्षर किये गये थे उस दिन लिखने वाले ग्राहक के लेखे में भुगतान के लिए पर्याप्त राशि थी। इस प्रकार चिह्नित करते समय बैंक कभी-कभी “यदि इस तिथि (?) तक उपस्थित किया गया तो भुगतान-योग्य” शब्द लिख दत्त है। इससे वह बैंक यदि उस दिन तक उपस्थित न किया गया और किसी कारण से उसका अनादरण हुआ अथवा बैंक का दिवाला निकल गया तो उस बैंक का दायित्व न तो लिखने वाले और न भुगतानकर्ता बैंक का होता है। अतः बैंक में भुगतान के लिए नियमित एवं यथामय (in due course) उपस्थिति होनी चाहिए। यदि भुगतान के लिए किसी प्रकार की तिथि नहीं लिखी गई है तो धारी को समुचित समय पर बैंक के कार्य-समय (office time) में उसको प्रस्तुत करना चाहिए।

इस चिह्न में बैंक पर बैंक की साख जोड़ दी जाती है जिससे बैंक का चलन बढ़ जाता है। बैंक चिह्नित तीन प्रकार से होता है —

(अ) आदाता (धारी) की इच्छा पर—आदाता अथवा धारी के आवेदन पर जब बैंक किसी बैंक को चिह्नित करता है तो उसका अर्थ है कि उस तिथि को लिखने वाले के लेखे में भुगतान के लिए पर्याप्त राशि थी। परन्तु यदि उसका समुचित समय के बाद भुगतान के लिए उपस्थित नहीं किया गया अथवा उसका अनादरण हो गया हो तो उसका उत्तरदायित्व पान वाले अथवा धारी का होगा।

(ब) ग्राहक की इच्छा से—जब भुगतानकर्ता बैंक लिखने वाले ग्राहक की प्राथना पर बैंक चिह्नित करता है तो ग्राहक उस बैंक का भुगतान रोक नहीं सकता। यदि किसी कारणवश वह रोक देता है तो भुगतान रोकने के कारण बैंक का होने वाली हानि के लिए वह उत्तरदायी होगा।

(ग) सग्राहक बैंक की इच्छा से—जब सग्राहक बैंक की इच्छा से भुगतानकर्ता बैंक को चिह्नित करता है उस समय उसका अर्थ बैंक के भुगतान के समान ही होता है। क्योंकि ऐसे बैंक का भुगतान रोकने का अधिकार लिखने वाले का नहीं रहता। इस प्रकार का चिह्न जब बैंक भुगतान के निश्चित समय के बाद (अर्थात् साधारणतः ३ बजे बाद) आते हैं तभी किया जाता है।

इस प्रकार जब ग्राहक तथा सग्राहक बैंक की इच्छा से बैंक को चिह्नित किया जाता है तब उसका भुगतान ग्राहक नहीं रोक सकता। परन्तु पहली स्थिति में चिह्नित बैंक बैंक की साख जुड़ जान से चलन में अधिक रह सकता है। किसी भी स्थिति में बैंक भुगतान के लिए समुचित समय पर ही उपस्थित किया जाना चाहिए।

उपस्थिति का समुचित समय (यथाविधि उपस्थिति)—उपस्थिति क लिए समुचित समय कौन सा है यह भिन्न भिन्न परिस्थितियाँ व अनुमार निर्दिष्ट किया जाता है। उच्चानसाध्य विलस अधिनियम (धारा १०१) क अनुसार समुचित समय तीन बातों पर निर्भर रहता है। (१) पान वाला लिखन बातों तथा इन बातों की परस्पर तथा (२) इस प्रकार क बिलसा क व्यवहारा की सामान्य पद्धति तथा (३) विनियम का चर्चा। स्थान उरी ग तात्पर्य है कि यदि ये तीनों भिन्न भिन्न स्थान पर हों तो उम स्थान से चक भजन क लिए कितना समय लगाया।

उदाहरणार्थ—(१) चक अगर बादमल आगरा से १ जनवरी को भेजा है और ३ जनवरी को रामनारायण नाम बम्बई का प्राप्त होता है तो वह चक संग्रहण क लिए (जब तक दूर क लिए कोई अन्य समुचित कारण न हो) उसके दूसरे दिन दना चाहिए। इसी प्रकार संग्रहण चक का उसका भगनान प्राप्त करने के लिए उसी दिन अथवा दूसरे दिन आगरा स्थित अधिकारी क पास भगनान लेन क लिए भेजना चाहिए। उमा स्थिति में चक का यथाविधि उपस्थिति होगी।

(२) विनियम का उम बात का पद्धति क अनुसार उपस्थित करना चाहिए।

(३) यदि बिलसा का स्वरूप ऐसा है किम अधिक कान तक चर्चन में रहने में कष्ट या सम्भावना हो तो उनका उपस्थिति प्राप्तिगीति होना चाहिए।

उपस्थिति का समुचित समय निकालने में सुविधा का समावेश नहीं होगा। सामान्य चक का भगनान प्राप्त करने क लिए जादना अथवा चर्चन प्राप्त यक्तियाँ का जिस दिन मित्रता है उमा दिन अथवा दूसरे दिन अपन चक में संग्रहण क लिए दना चाहिए।

विहृत (Mutilated) चक—विहृत चक उन चकों का कहते हैं जो जाक स्मिकता से पट गये हैं अथवा खराब हो गये हैं। एम कट हुए तथा बिपकाए हुए चकों का भगनान चक नहीं करना किन्तु उम विहृत चक के लिए दना है। एम विहृत एवं बिपकाए हुए चकों पर जाकस्मिक विहृत (accidentally mutilated) लिखने पर चक क हस्ताक्षर होना आवश्यक है। कयाकि कभी-कभी लिखन वाला चक निरस्त करने क लिए भी उम फाट दता है। यदि चक संग्रहण चक द्वारा अथवा पान बात क द्वारा फट जाता है तो भगनान क

पूर्व सग्राहक उन की जमानत बना आवश्यक है जिससे उन वार वक पर किसी प्रकार का दायित्व न रहे ।

यदि कोई चक इस प्रकार विकृत हो जाता है जिसमें उसकी राशि अथवा पान वार का नाम अथवा अ य महचपूण बात अस्पष्ट हो जाती है तो इस दशा में भा भुगतानकता वक उसका भुगतान नहीं करेगा जब तक उसका स्पष्टीकरण लिखन वाला अपन हस्ताक्षर व साथ न बरे ।

**जाली चक (Forged Cheques)**—जाली चक उन चक को कहते हैं जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर न हात हुए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जाली हस्ताक्षर बनाये गये हैं । इस चक का भुगतान वक को नहीं भुगताना चाहिए । क्योंकि यदि वह पूरा सावधानी एवं सद्भावना के साथ जाली चक का भुगतान करता है तो वह अपन ग्राहक का नुखा डेबिट नहीं कर सकता । कारण जाली चक ग्राहक का वास्तविक आगम नहीं होता । किन्तु यदि लिखन वाल की भूल अथवा अमावधाना से इस प्रकार का जाली चक बनाया गया हो तो लिखन वाल का नुखा डेबिट किया जायेगा । परन्तु वक को यह प्रमाणित करना होगा कि लिखन वाल न चक पुस्तक को अमावधानी से रखा था ।

जाली वेचान में यदि भुगतानकता वक पूरा सावधाना के साथ उनका भुगतान करे तो इस गलत भुगतान का दायित्व उस पर नहीं होता क्योंकि वक प्रत्येक आदाता अथवा वचानकता के हस्ताक्षर को नहीं पहचान सकता । वह केवल लिखने वाले (ग्राहक) के हस्ताक्षर को पहचान सकता है क्योंकि उसका नमूना हस्ताक्षर उसके पास हात है ।

**वेचान (Endorsements)** ✓

**परिभाषा**—कोई व्यक्ति चक अथवा किसी भी वचानसाध्य विलख की सम्पत्ति का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को देने के लिये उस पर हस्ताक्षर करता है तथा इस हस्ताक्षर करते समय वह स्वयं उस विलख का स्ववधारी स्वामी तथा धारी होता है । वचान में वचानसाध्य विलख का वचान होता है जो केवल हस्ताक्षरण में नहीं होता । दूसरे शब्दों में वचान से किसी वचान साध्य विलख का लेने वाला व्यक्ति उसका वास्तविक अधिकारी हो जाता है किन्तु हस्ताक्षरण में विलख की सम्पत्ति का वास्तविक अधिकार हस्ताक्षरकर्ता का नहीं मिलता । इस प्रकार जो व्यक्ति वेचान के लिये हस्ताक्षर करता है उसे वेचानकर्ता जिसके नाम वेचान किया जाता है उसे वचान प्राप्त कहते हैं ।

विनियम वचान चक को पोढ़े किया जाता है । वचान से चक भर जाने पर

चैव क आकार का अन्य कागज चिपका कर उस पर बचान हा सकता है । जिस समय कागज चिपका कर बचान होता है उस समय बचानकर्ता का चाहिए कि वह अपन हस्ताक्षर चैक एव वागज दोनों पर कर । इससे किसी प्रकार क कपट की सम्भावना नही रहती । इस प्रकार चिपकाय हुए कागज का अनुपर्ची (allonge) कहत ह ।

बेचान कौन कर सकता ह ?—किसी भी बचानमाध्य विनख का आदाता स्वयं अथवा उसका अधिकृत अभिकर्ता बचान कर सकता है । अधिकृत अभिकर्ता का सदैव बचान करत समय अपन प्रधान क लिए (for principal) लिखकर बचान करना चाहिए जिसमें ऐसे बचान किय हुए विनख का का. दायित्व उस पर न रह । इसी प्रकार मस्याआ द्वारा बचान उनक अधिकृत व्यक्तिया द्वारा होना चाहिए । बचान करत समय पान बान का उमा प्रकार हस्ताक्षर करना चाहिए जिस तरह विनख के निम्न बान न उसका नाम लिखा हो । उदाहरणार्थ यदि चैक पर पान बान का नाम पा० एन० गोलवालकर लिखा है तो बचान करत समय भी पी० एल० गोत्रवालकर ही लिखना चाहिए । अगर बचान करत समय पी० एन० गोलवालकर हस्ताक्षर किय गया तो बचान ठाक नही माना जायगा क्याकि नाम में अन्तर पड जाता है । किन्तु यदि पान बाने का नाम गलत लिख गया है तो पढ़न गलत हस्ताक्षर करन क बाद नाचे अपन सही किय जा सकन है । दूसर बचान म्याहा स जयवा पमिल स हा सकता है परंतु पमिल के बचान में कपट की सम्भावना हान क कारण वह सामान्यतया पमिल का बचान स्वीकार नही करत ।

### बचान के प्रकार

१ सामान्य बेचान (Blank Endorsement)—इसमें बचानकर्ता केवल अपन हस्ताक्षर कर दता है । इस प्रकार क बचान से चैक का मूल स्वरूप बन्त कर वह बाह्य चैक हा जाना है तथा उगक भुगतान क लिए किसी अन्य व्यक्ति का बचान की आवश्यकता नही पडता ।

२ विशेष बेचान (Special Endorsement)—इसमें बचानकर्ता अपन हस्ताक्षर क अतिरिक्त जिसका वह सम्पत्ति वा बचान करना ह उसका नाम अथवा जिसका वह सम्पत्ति वा चवार्निक अधिकारा बनाना है उसका नाम अपन हस्ताक्षर क पूर लिख दता ह । उदाहरणार्थ—

Pay to Harihar Nath or order

हरिहरनाथ अथवा उनक आग्र पर

P L. Golwalkar

पा० एल० गोलवालकर

10 1 11

१० १ ५१

इन प्रकार से वचान किए हुए बैंका का आग वचान (negotiation) एवं हस्तान्तरण (transfer) होन के लिए हरिहरनाथ द्वारा वचान का आवश्यक्ता होगी। उसी प्रकार यदि हरिहरनाथ स्वयं ही भुगतान नाना चाहतव भी उनको हस्ताक्षर करन पडग।

३ सीमित वचान (Restrictive Endorsement)—यदि वचान कता किसी व्यक्ति विशेष के नाम वचा करता ह जिससे उस चक का वचान आग न हो ता उसे सीमित वचान कहग। उदाहरणार्थ—

Pay to Harihar Nath only

बयन हरिहरनाथ का ही

भुगतान हा

P L Golwalkar

पी० एल० गोलवलकर

10 11 59

१० ११ ५६

इस चक का वचान हरिहरनाथ किसी अन्य व्यक्ति का नहीं कर सकत।

४ दायित्व रहित वचान (Sans Recourse Endorsement)—जब वचानकता बैंक के अनादरण से आने वाला दायित्व स्वयं नहीं लेना चाहता उस समय वह दायित्व रहित अथवा बिना दायित्व के शब्द लिखकर हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार के वचान में वचानकर्ता बैंक का भुगतान न होने पर भी किसी प्रकार से देनदार नहीं रहता किंतु इसके पूर्व के सप्त वचानकर्ता तथा लिखने वाले का दायित्व रहता है। उदाहरणार्थ—

Sans Recourse

दायित्व रहित

P L Golwalkar

पी० एल० गोलवलकर

10 1 59

१० १ ५६

अथवा

Without Recourse to me

बिना मेरे दायित्व के

P L Golwalkar

पी० एल० गोलवलकर

५ ऐच्छिक वचान (Facultative Endorsement)—इसका चलन नहीं है इसमें वचानकता अपन हस्ताक्षर करन के पूर्व अनादरण सूचना अनावश्यक लिख देना ह। इसमें चक का भुगतान न होने पर ऐस वचानकता को अनादरण की सूचना जो नियमानुसार धारी को सब पक्षा को देनी चाहिए तब की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे वचानकता की उस चक को संपादिक देनदारी रहती है। उदाहरणार्थ—

Notice of Dishonour waived

अनादरण की सूचना अनावश्यक

P L Golwalkar

पी० एल० गोलवलकर

बेचान करते समय सावधानी—वचानरता का किसी ना वचान साध्य विरल का वचान करन समय निम्न सावधानी रखना चाहिए —

१ पहिल उसना नाम जिंगप्रकार मे लिखा गया हा उसी प्रकार वह हस्ताक्षर कर । परन्तु यदि यह चाह ता नीचे अपन सही हस्ताक्षर भी कर सकता है ।

२ उचान उमा विरल अथवा अनुपर्वी (allonge) पर करना चाहिए ।

३ यदि मामूहिक आदता ह ता उचान करन समय सब व्यक्तिना क हस्ताक्षर होन चाहिए ।

४ किसी कम्पना अथवा मस्या क नाम आय हुए चैरा पर वचान करन समय कम्पनी क नाम क साथ क लिए लिखकर अपने हस्ताक्षर एव पद का उल्लेख करना चाहिए । उदाहरणाय जयाजी राव काटन मिम्स लि० ग्वानियर क अभिवक्ता को हस्ताक्षर निम्न प्रकार म करना चाहिए —

Per Pro } Jivaji Rao Cotton जयाजी राव काटन मिम्स लि० के लिए  
or for } Mills Ltd

D P Mandelia

Managing Director

डी पी मडलिया

प्रबन्ध संचालक

५ यदि चैन म ममी स्त्रा का नाम ह तिसका विवाह हा चुका है परन्तु चैव मिलन क समय वह अविवाहित थी ता उस अपन हस्ताक्षर विवाहित नाम स करन चाहिए तथा साथ हा म अपना पहला नाम भी लिखना चाहिए ।

उदाहरणाय रमा गोखले जिसका विवाहिता नाम उपा दाडकर है उसका उपा दाडकर ( उक्त रमा गोखले ) इस प्रकार हस्ताक्षर करना चाहिए ।

६ वचान क समग्र उपाधिया नहीं लिखनी चाहिए ।

७ विवाहिता स्त्री का वचान करन समय अपने नाम स हस्ताक्षर करन चाहिए और बाद म वह किसी पत्नी ह इसका उल्लेख कर देना चाहिए ।  
उदाहरणाय —

Rama Gokhale

रमा गोखले

(Wife of G D Gokhale)

(श्री गा दा गोखले का पत्नी)

८ मामूहिक आदता क नाम क चैव पर काट पत्र व्यक्ति आर वह अधिष्ठन है ता अपन हस्ताक्षर म वचान कर सकता है । इसी प्रकार अपन प्रचान का उगह अविच्छिन्न अभिवक्ता वचान कर सकता है ।

चक्र पर दिया हुआ पाने वाले का नाम	गतत वेचान	सही वेचान	कारण
<b>वैयक्तिक :</b> श्री रुपराम गुप्ता श्री सतीन्द्रसिंह पंडित नेहरू श्रीमती रमा गोखले कुमारी रमा रानडे कुमारी रमा मंबटे ( अत्र विवाहित )	रुपराम गुप्ता मतीन्द्रसिंह पंडित नेहरू श्रीमती रमा गोखले कुमारी रमा रानडे रमा मंबटे	रुपराम गुप्ता सतीन्द्रसिंह जवाहरलाल नेहरू रमा गोखले (जी डी गोखले की पत्नी) रमा रानडे रमा अभ्यकर (पूर्वनाम रमा मंबटे)	नाम भेद " अणु नाम किसकी पत्नी यह उल्लेख नहीं था । उपाधि अनावश्यक । दोनों नामों का उल्लेख आवश्यक ।
<b>सार्व</b> डोगरे ब्रदर्स सस्थाएँ विक्टोरिया कालेज ग्वास्तियर प्रशिक्षित व्यक्ति . रामावतार शुक्ल पर्नस प्रॉडक्ट्स लिमिटेड, कानपुर मृत व्यक्ति . सरदार पटेल (अत्र परजीवामी)	विदग्गाय लक्ष्मण डोगरे शिवसहाय सबसेना निशानी अंगूठा (रामावतार शुक्ल) जी० एस० नाथरे, व्यवस्था मंचालक पर्नस प्रॉडक्ट्स, कानपुर माराभाई पटेल	विदग्गाय लक्ष्मण डोगरे डोगरे ब्रदर्स के लिए शिवसहाय, प्रिंसीपल, विक्टोरिया कालेज निशानी अंगूठा रामावतार शुक्ल गवाह पी० एस० गोन्वलकर पर्नस प्रॉडक्ट्स कानपुर के लिए जी० एस० नाथरे व्यवस्था मंचालक सरदार पटेल की संपत्ति का रिकससायक माराभाई पटेल	जिससे सार्व का अभिवर्ती अथवा भागी है यह स्पष्ट हो । सस्था के लिए पृष्ठांकन होनी चाहिए । किंगी गवाह के हस्ताक्षर होना आवश्यक । वैयक्ति रूप से हस्ताक्षर नहीं होना चाहिए । सार्व साधक के नाम हस्ताक्षर होना चाहिए ।

## चैको से लाभ

वर्तमान आर्थिक स्थिति में चैका का स्थान महत्वपूर्ण है। पश्चिमी देशों में विनिमय व्यवहारों का भुगतान विशेषतः चैको से ही किया जाता है। परन्तु चैक द्वारा अन्तिम एवं पूर्ण भुगतान नहीं होता अपितु चैक का भुगतान मिलने पर ही वह पूर्ण भुगतान समझा जाता है। फिर भी चैक भुगतान का माध्यम होने से समाज को बहुत लाभ होगा है।

१ धन की सुरक्षा—चैका में मुद्रा रहने के कारण वह धन सुरक्षित रहता है एवं उसका उपयोग दैनिक भुगतान के लिए चैको के माध्यम से होता है।

२ हानि की सम्भावना नहीं—चैक पुस्तिका यदि असावधानी के कारण खो जाय तो चैक को उसकी मूचना देने से कोई भी अनधिकृत व्यक्ति उन चैका का उपयोग नहीं कर सकता। किन्तु यदि अपने पास रखा हुआ धन खो जाय अथवा चोरी चला जाय तो हमेशा हानि ही होती है।

३ रसीद प्रभावशालक—चैका में बड़ी से बड़ी रकम का भुगतान किया जा सकता है तथा बैंक चैका के भुगतान के समय पाने वाले के हस्ताक्षर कराते हैं जो रसीद का काम देते हैं। इसमें ग्राहक को असग रसीद की आवश्यकता नहीं रहती क्योंकि किसी समय न्यायालय में ये हस्ताक्षर अवलंब्य प्रमाण माने जाते हैं।

४ आय-व्यय का हिासब—बैंक में समय-समय पर जा रकमा जमा किया जाता है अथवा निकाला जाता है उसका हिासब बैंक अपने पास रखता है। इसमें ग्राहक को अपने आय-व्यय का अलग हिासब रखने की आवश्यकता नहीं होगी। यह हिासब उसकी पामबुक से उसे मिल जाता है।

५ मुद्रा की मितव्ययता—चैका के उपयोग में मुद्रा की कम आवश्यकता होती है जिसमें चैका को नगद राशि कम रखनी पड़ती है। इससे बहुतमूल्य धातुओं की बचत होती है जिनका उपयोग व्यापारिक एवं औद्योगिक कार्यों के लिए किया जा सकता है।

६ भुगतान में सुगमता—एक मुद्रा की अपेक्षा चैको में भुगतान करना अधिक सुगम और सुरक्षित होता है।

७ माल-निर्माण—चैको में मुद्रा के उपयोग में मितव्ययता होती है

व्यापार एवं उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है क्योंकि बैंक अधिक माल-निर्माण कर सकते हैं।

भारत में बैंको का उपयोग केवल बड़े-बड़े शहरों में ही देखने को मिलता है। भारत में बैंक का उपयोग न होने के प्रमुख कारण बैंको का पर्याप्त विस्तार न होना, अधिकतर जनसंख्या का निरक्षर होना, तथा विदेशी भाषा में बैंक लिखने की प्रथा आदि हैं।

### विनिमय-बिल (Bills of Exchange)

विनिमय बिलों का उपयोग अन्तरराष्ट्रीय तथा आन्तरिक व्यापार में अधिक सुविधाजनक होता है। क्योंकि इनके उपयोग में प्रेषक (consignors) तथा निर्यातक (exporters) को माल भेजते ही बटौती द्वारा बिल का रूपया प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार आयातकों (importers) तथा प्रेषणी (consignees) को भी लाभ होना है क्योंकि उनको उक्त बिल का भुगतान करने के लिए कुछ अवधि मिल जाती है। इस अवधि में वे अपना माल बेचकर रूपया चुका सकते हैं। ये बिल दो प्रकार के होते हैं—विदेशी विनिमय बिल (foreign bills of exchange) तथा देशी विनिमय बिल (inland bills of exchange)। इनमें पहले विनिमय बिलों का विदेशी व्यापार में तथा दूसरे विनिमय बिलों का उपयोग देशी व्यापार में होता है।

**विनिमय बिल की परिभाषा**—बेचानमाध्य विनैम्ब अविनियम (धारा ५) के अनुसार “विनिमय बिल लेखक का किसी व्यक्ति के लिए लिखित गत-रहित आदेश होता है, जिस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर हो, जिसमें वह किसी निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा उसके वाहक को निश्चित मुद्राएँ दे।

**विनिमय बिल की विशेषताएँ —**

- १ तिथित आदेश हो।
- २ इस आदेश में किसी प्रकार की शर्तें न हो।
- ३ आदेश देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर हो।
- ४ आदेश किसी निश्चित व्यक्ति का हो।
- ५ भुगतान की रकम निश्चित हो।
- ६ जिस व्यक्ति को भुगतान देना है वह व्यक्ति निश्चित हो।
- ७ भुगतान का समय निश्चित हो।

इनमें से पहली ६ वांता का विस्तृत विवेचन पट्टिन किया जा चुका है।

‘भुगतान व निश्चित समय के सम्बन्ध में बिना स्पष्ट दिया जाना चाहिए कि जहाँ भुगतान माग पर अथवा मजिप्य में किसी निश्चित समय पर हो। बिना के बिचन में बिनेपत दखन पर (at sight) उपस्थिति पर (on presentation) अथवा देखने के बाद’ (after sight) आदि शब्दों का प्रयोग होता है। वचनमाध्य विलम्ब अधिनियम (धारा २१) के अनुसार दखन पर तथा उपस्थिति पर शब्दों का अर्थ माग पर भुगतान होना है किन्तु देखने के बाद का अर्थ यह होता है कि भुगतान की अवधि बिना दखन व बिना के अथवा स्वीकृति (acceptance) के दिन में निकालनी होगी। जहाँ पर इनमें से किसी भी प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं किया है अथवा भुगतान का समय नहीं दिया है उस बिना अथवा प्रतिपादन का भुगतान माग पर होगा तथा गमना जायगा (धारा १६)।

विलों के प्रकार— बिनों का वर्गीकरण अनेक प्रकार में किया गया है।

(१) स्थानीय वर्गीकरण के अनुसार बिन दो प्रकार के होते हैं—(अ) बिदेशी विनिमय बिल तथा (ब) देशी विनिमय बिल। जो भारत में बनाये गये हैं एवं जिनका भुगतान भारत में हो अथवा भारतीयों पर बिन गये हैं (धारा ११) तथा जो बिल इस प्रकार में नहीं बनाये गये हैं व बिदेशी विनिमय बिन होते हैं (धारा १२)।

## बिनों के नमूने

### १ (देशी) देशी अथवा माग बिल

२/०) ₹० मात्र

कलकत्ता १ अगस्त १९१०

माग पर श्री रामनारायण माल एण्ड सन्स इलाहाबाद का अथवा उनके आदेशानुसार प्राप्त मूल्य के बाद मो रूपायों का भुगतान कीजिए।

मन्ना म—

श्री भागामन जैन

कानपुर

हरिहरनाथ

## २ (देशी) मुद्रती विनिमय बिल

मुद्राक =)	बलवत्ता, १ जनवरी १९४१
रु० ५००) मान	
तीन मास के उपरान्त, प्राप्त मूल्य के पाँच शौ रुपये का श्री रामनारायण माल. अन्नाहावाद अथवा उनके आदेशानुसार भुगतान कीजिए।	
मेवा मे—	
श्री भागामल जैन	हरिहरनाथ
कानपुर	

## ३ विदेशी विनिमय बिल

मुद्राक	वम्बई, १ जनवरी १९४१
पीड ५० मान	
देखने के बाद नब्बे (९०) दिन, इस प्रथम प्रति के (इसी तिथि एवं अवधि की अन्य प्रतियाँ अदेय) प्राप्त मूल्य के मात नौ पचाम रुपये तन्दन स्थित इम्पीरियल बैंक को भुगतान कीजिए।	
मेवा मे—	
जॉन गिलवर्ट एण्ड कम्पनी,	
पुस्तक प्रकाशक एवं विनिता,	दिनेशकुमार
१० नोम्बाई स्ट्रीट, लंदन।	

विदेशी विनिमय बिल तीन प्रतियो मे लिखे जाते है जिनकी प्रत्येक प्रति भिन्न-भिन्न डाक द्वारा भेजी जाती है, जिससे उनके खो जाने की सम्भावना न रहे। इसमे केवल एक ही प्रति का भुगतान होता है एक अन्य दो प्रतियाँ निरस्त हो जाती है। ऐसे बिल के तीनों प्रतियाँ पर एक ही अव होता है तथा प्रत्येक प्रति का तब तक भुगतान हो सकता है जब तक उनमे किसी भी एक प्रति का भुगतान न किया गया हो। परन्तु यदि प्रत्येक प्रति पर चेचान अथवा स्वीकृति भिन्न व्यक्तियों के पक्ष मे की जाती है तब प्रत्येक व्यक्ति एवं चेचानकर्त्ता उस बिल की प्रति पर उसी प्रकार दायी होगा जैसेकि वे भिन्न-भिन्न बिल है।<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Bills of Exchange may be drawn in parts, each part being numbered and containing a provision that it shall continue payable so long as the others remain unpaid. All the parts together make a set, but the whole set constitutes only one

(२) (अ) बाह्य बिल : किसी भी व्यक्ति को इनकी राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है, यदि उनके अधिकार में बिल है। (आ) आदेश बिल : इनकी राशि बेचान एवं हस्तान्तरण द्वारा किसी व्यक्ति के नाम दी जा सकती है, अन्यथा नहीं।

(३) अवधि के अनुसार बिल दो प्रकार के होते हैं—(१) दर्शनी अवधि माँग बिल : इनका भुगतान बिज की उपस्थिति पर होता है। (२) सामयिक अवधि मुद्दती बिल : इनका भुगतान बिज में लिखी हुई अवधि के पूर्ण होने पर ही किया जाता है।

(४) बिलों के व्यवहार के अनुसार—(अ) व्यापारिक बिल जो केवल किसी व्यापारिक व्यवहार के लिए लिखे एवं स्वीकृत किये गये हों, तथा (आ) अनुग्रह (accommodation) बिल जो किसी व्यापारिक हेतु के लिए लिखे एवं स्वीकृत न होने हुए किसी व्यक्ति पर आर्थिक महायता द्वारा उपकार करने के लिए लिखे अवधि स्वीकृत किये जाते हैं।

बिलों के पक्ष—बिलों में तीन पक्ष होन हैं —

लिखने वाला (Drawer)—उस व्यक्ति को कहते हैं जो बिल लिखकर उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। यह बिल उस व्यक्ति पर लिखा जाता है जो उसका ऋणी होता है एवं निम्नन वाला ऋणदाता।

भुगतान कर्ता (Drawee)—वह व्यक्ति है जिसको बिल में लिखित रकम का भुगतान करना पड़ता है। यह विशेषतः ऋणी होता है।

प्रादाता (Payee)—जिसके पक्ष में बिल लिखा जाता है एवं जो इस लिखित आदेश के अनुसार राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

बिलों की स्वीकृति (Acceptance of Bills)

माँग एवं दर्शनी बिलों में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती किन्तु मुद्दती बिलों में भुगतानकर्ता तब तक उत्तरदायी नहीं होता, जब तक वह बिल पर अपनी लिखित स्वीकृति न दे। जिस बिल पर भुगतानकर्ता की स्वीकृति नहीं

bill, and is extinguished when one of the parts, if a separate bill, would be extinguished.

*Exceptions* When a person accepts or endorses different parts of the bill in favour of different persons, he and subsequent endorsees of each part are liable on such part as if it were a separate bill

—Sec 132, Negotiable Instruments Act, 1881

होती उम बिल का विकल्प (draft) कहते हैं तथा स्वीकार हुआ जाने पर उमे स्वीकृत-बिल (acceptances) कहते हैं। यह स्वीकृति भुगतानकर्ता बिल क बीच में 'स्वीकृत' शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर से दना है। यदि देने वाला केवल हस्ताक्षर ही करता है तो भी वह बिल स्वीकृत समझा जायगा।

मेरी स्वीकृति अगर फर्म कम्पनी अथवा अन्य मस्या के लिए की गई है तो अपने हस्ताक्षर के पश्चात् क लिए (for or per pro) लिखना आवश्यक है अथवा स्वीकृत करने वाला व्यक्ति नैयतिक रूप में उस बिल के लिए दायी होगा।

स्वीकृति का प्रकार की हानी है—(१) सामान्य स्वीकृति जिसमें बिना किसी शर्त के बिल स्वीकार किया जाता है तथा (२) विशेष (qualified) स्वीकृति, जिसमें देने वाला बिल का स्वीकार करने के पूर्व स्थान, रकम समय अथवा अन्य किसी प्रकार की शर्त लगा देने पर हस्ताक्षर करता है। लिखन वाला यदि विशेष स्वीकृति मानता है तो उसको उन शर्तों का पालन करना पड़ेगा अन्यथा बिल का अमान्यता समझा जायगा।

बिल स्वीकार हुआ जाने पर भुगतानकर्ता को स्वीकृता (acceptor) कहा जाता है।

मुदती बिना की भुगतान की तिथि को पक्व तिथि (date of maturity) तथा बिल का पक्व बिल कहते हैं। इन दिनों में भुगतान के लिए पक्व तिथि के बाद तीन दिन और दिए जाने हैं। इस तीन दिन की अवधि का अनुग्रह दिवस (days of grace) कहते हैं।

बिलो से लाभ—बिल के धारी को यदि राशि की आवश्यकता है तो वह बैंक में बिल की कटौती कराकर राकड़ प्राप्त कर सकता है। बैंक कटौती करते समय, जितनी अवधि का बिल है उस अवधि का व्याज बिल की राशि में काट कर दोष रकम धारी को दे दता है तथा बिल अपने पास रख लेते हैं। इस कार्य को बिलो की कटौती कहते हैं जो बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है। कटौती की राशि बिना की पक्व तिथि एवं बढ़े की दर पर निर्भर रहती है।

बैंक का बिना की कटौती में निम्न लाभ हैं —

(१) बिना की कटौती अथवा कटौती बिल बैंक की सुरक्षा का साधन होते हैं तथा बैंक इन बिलों को बचकर अथवा केन्द्रीय बैंक में कटौती कराकर किसी भी समय इतना विनियोजित संपत्ति प्राप्त कर सकता है।

(२) कटौती करने में बैंक जो बढ़ा काय्य है वह उनका लाभ होता है एवं जिसकी प्राप्ति निश्चिन्त रूप में आती है।

(३) बैंक को यह निश्चितता होती है कि प्रथम श्रेणी के बिलों का भुगतान पश्च-तिथि पर मिलेगा। इसलिङ्ग उसका धन सुरक्षित रहता है।

(४) बिना के मून्या में उतार-चढ़ाव की सम्भावना न होने में उसे किसी प्रकार की हानि की आशंका नहीं रहती।

(५) बिनों के साथ कभी-कभी रेलवे रसीद अथवा जहाजी रिट्टी अथवा अन्य किसी प्रकार की प्रतिभूतियाँ रहने में इसमें विनियोग किया हुआ धन पूर्ण सुरक्षित रहता है।

(६) कटौती द्वारा ग्राहक का रोकड प्राप्त करने की सुविधा देने वाली बैंक ग्राहकों की कृपा पत्र बनती है जिसमें ग्राहक-मून्या में भी वृद्धि होती है। व्यापारियों को लाभ

(१) ऋणी के हस्ताक्षर सहित ऋण का निश्चित वैधानिक प्रमाण प्राप्त होता है।

(२) इसमें भगतान की विधि निश्चिन दी हुई होने में ऋणी एवं ऋणदाता दोनों को ही सब भगतान करना होगा अथवा मिदमा यह निश्चिन मानूम होता है।

(३) बिल की अवधि में ऋणी अपनी वस्तुएँ बेचकर भुगतान की व्यवस्था कर सकता है।

(४) ऋणदाता अथवा निम्नने वाला रोकड की आवश्यकता पडने पर इन बिल की बैंक से कटौती कराकर रोकड प्राप्त कर सकता है। साथ ही बिल बेचानमाध्य होने में अपने ऋणा के भुगतान में इनका उपयोग किया जा सकता है।

(५) देश-विदेशों के ऋणा का भुगतान करने का यह सुरक्षित एवं सुविधाजनक माध्य है जिसमें रोकड की आवश्यकता कम हो जाती है। विदेशी व्यापार में विदेशी विनिमय बिना द्वारा भी भुगतान होने में जिसमें स्वर्ण के आयात निर्यात व्यव में भी वचन होती है।

स्टाम्प कर (Stamp Duty)—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ के अनुसार प्रत्येक भुटनी बिल पर राशि के अनुसार स्टाम्प लगाना आवश्यक है। विदेशी बिनों में निम्नने वाले के देश का स्टाम्प एव देने वाला (अगर विदेश में है) अथवा जहाँ भुगतान होता है (विदेश में) उस देश का—दोनों देशों का स्टाम्प लगाना आवश्यक है। किन्तु दर्शनी बिनों पर स्टाम्प की आवश्यकता नहीं होती।

**बिलो का बेचान**—बिल बेचानमाध्य होने के कारण इनका बेचान एवं हस्तान्तरण उसी प्रकार में होता है जिस प्रकार में चैको का ।

**बिलो की उपस्थिति (Presentation)**—भुगतान के लिए बिलो की उपस्थिति भुगतानकर्ता के निवास अथवा व्यापार स्थान पर एवं व्यापारिक अवधि में करना चाहिए । तभी बिल की यथाविधि एवं समुचित समय में उपस्थिति मानी जाती है । यदि इस प्रकार उपस्थिति न होने से बिल का अनादरण होता है अर्थात् बिल की राशि का भुगतान नहीं होता तो उस बिल के पूर्व-पक्षों (previous parties) का दायित्व प्रमाणित नहीं किया जा सकता । इसके विपरीत यदि उपस्थिति यथाविधि एवं समुचित होने पर बिल का भुगतान हो जाता है तो बिल के सब पक्षों का दायित्व समाप्त हो जाता है ।

इसी प्रकार जिन विषयों की स्वीकृति होनी है उनकी भी स्वीकृति के लिए भुगतानकर्ता को प्रस्तुत करना चाहिए अन्यथा धारी के प्रति बिल के अन्य पक्ष उत्तरदायी नहीं रहते क्योंकि धारी ने स्वीकृति के लिए बिल की उपस्थिति करने में उपेक्षा (negligence) की है (धारा ६१) ।

**बिलो का अनादरण**—यदि कोई बिल यथाविधि स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने पर भुगतानकर्ता उसे स्वीकार न करे अथवा भुगतान के लिए यथाविधि उपस्थित करने पर उसका भुगतान न करे तो उसे बिल का अनादरण कहते हैं । बिल का अनादरण होने पर इसकी सूचना बिल के समस्त सम्बन्धित पक्षों को देनी चाहिए अन्यथा वे उत्तरदायी नहीं रहेंगे ।

बिल का अनादरण होने पर बिल निरीक्षक (notary public) द्वारा उसके अनादरण का वैधानिक प्रमाण प्राप्त करना चाहिए । इसमें जो व्यय होगा इसके भुगतान के लिए भुगतानकर्ता बाध्य होगा ।

**हुण्डी**

हुण्डियों का प्रयोग भारत में बहुत प्राचीन काल से भारत के सभी प्रांतों में है । ये सभी भाषाओं में लिखी जाती हैं तथा लिखने का ढंग भी समान है । हुण्डियों के भुगतान एवं चलन की पद्धति अधिकतर स्थानीय व्यापारिक व्यवहार पर निर्भर है । हुण्डियों और बिलों में मूल भेद यह है कि हुण्डियों का चलन भारतीय बेचनामाध्य विलेख अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होता तथा ये केवल देशी भाषाओं में प्रचलित पद्धति के अनुसार लिखी जाती हैं । इनका उपयोग बेचनामाध्य विलेख अधिनियम के अनुसार तभी हो सकता है जब इसका स्पष्ट उल्लेख हुण्डी में किया जाय । हुण्डिया पर स्टाम्प-कर नहीं लगता ।

हुण्डिया म भी दिला का तरह तीन पक्ष होत है—लिखने वाला (drawer) दन वाला (drawee) एव पाने वाला (payee) ।

हुण्डिया का वर्गीकरण अवधि तथा भुगतान की पद्धति के अनुसार किया जा सकता है । अवधि के अनुसार हुण्डिया दो प्रकार की होती है—(१) दशमो हुण्डो जिसका भुगतान हुंडी का दखत ही करना पड़ता है । (२) मितो अथवा मुहूर्तो हुण्डो जिसका भुगतान हुंडिया में दी हुई निश्चित अवधि के बाद होता है । इनके भुगतान की अवधि विशेषण ४१, ६१ एव ८० दिन होती है या भिन्न भिन्न प्राप्ति की पद्धति पर निर्भर है ।

भुगतान के अनुसार हुंडिया चार प्रकार की होती है —

१ धनी जोग हुण्डो—जिनका भुगतान हुंडी में लिखित व्यक्ति का ही किया जाता है । इस प्रकार की हुंडिया का दूसरा कोई व्यक्ति वचान द्वारा नहा मुना सकता और न एसी हुण्डिया का हस्तान्तरण ही हो सकता है ।

२ बाह जोग हुण्डो जिनका भुगतान बहर उस ग्राह (धनीमानी व्यक्ति) का ही होता है जिसका नाम हुंडी में दिया होता है । यह हुंडा बिनाप रखावित चैक के समान होता है ।

३ फरमान हुण्डो—फरमान या अथ है आदग । अर्थात् य वह हुंडिया है जिनका भुगतान हुंडी में निम्नित व्यक्ति अथवा उमक आदगानुसार किसी अन्य व्यक्ति का होता है । यह हुण्डिया आदग चैक एव आदग दिला के समान होती है ।

४ देखनदार जोग हुण्डो—जिनका भुगतान किसी भी उम व्यक्ति को होता है जो उम हुंडी का उपस्थित करे । यह हुण्डिया बाहक चक की तरह होती है ।

इनके अतिरिक्त प्राचीन काल में आंगमी हुंडिया भी प्रचलित था जिनका अब चलन नहीं है । इस प्रकार की हुंडिया में नाविक एक स्थान में दूसरे स्थान का या माल ले जाता था उसका बीमा करता था एव हुंडिया का रुपया माल भजन वाल को उसी स्थान में दे देता था अथवा हुंडा को वह स्वयं हा खरीद लेता था । माल प्रपणी के स्थान पर पहुंचने पर वह उमम हुंडी का भुगतान ले लेता था ।

हुण्डा से सम्बन्धित शब्द प्रयोग

१ सहै करना=स्वाकार करना ।

२ भरी पाना=भुगतान करना ।

३ वचान करना=पृष्ठान्न करना (to endorse a bill) ।

४ मोत्या हुंडा=हुंडी जिनका भुगतान हा चुना है ।

- ५ फेरी आना = भुगतान न होना ।
- ६ लेखीवाला = बिल लिखने वाला ।
- ७ छोटी हूडी = जिसमें किसी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हों  
एवं उस पर लेखीवाले (आहर्ता) के हस्ताक्षर न हों ।

### प्रतिज्ञा-पत्र (Promissory Notes)

**परिभाषा**—“प्रतिज्ञा-पत्र” वह लिखित विलेख है (इसमें पत्र-मुद्रा नहीं आती), जिसमें लिखने वाला अपने हस्ताक्षर सहित यह प्रतिज्ञा करता है कि वह उसमें दी हुई निश्चित राशि, बिना किसी शर्त के, जिस व्यक्ति के नाम वह लिखा गया है उस निश्चित व्यक्ति अथवा उसके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति अथवा उसके वाहक को देगा ।<sup>1</sup>

**उदाहरणार्थ**—१ मैं ‘ब’ को अथवा उसके आदेशानुसार ५०० रुपये देने की प्रतिज्ञा करता हूँ ।

२ मैं प्राप्त मूल्य के लिए ‘ब’ का ऋण मान्य करता हूँ तथा उसे माँग पर देन की प्रतिज्ञा करता हूँ ।

३ श्री ‘ब’ आपके प्रति १०००) रुपये का ऋण मुझे देना है, अथवा श्री व धारयामित (I. O. U) १०००) रुपया ।

४ मैं व को ५०० रु० तथा अन्य जो राशि गप होगी, उसे देन की प्रतिज्ञा करता हूँ ।

५ मैं ‘ब’ को अपना ऋण की राशि घटाकर ५००) रु० देन की प्रतिज्ञा करता हूँ ।

६ मरा ‘घ’ के साथ विवाह हुआ जाने के ७ दिन पश्चात् मैं ‘ब’ का ५००) रुपये देन की प्रतिज्ञा करता हूँ ।

७ मैं ‘घ’ की मृत्यु के बाद ‘ब’ को ५००) रु० देने की प्रतिज्ञा करता हूँ, यदि वह भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि छोड़ता है ।

८ मैं आगामी वर्ष की १ जनवरी को ५००) रु० तथा अपना घोड़ा देने की प्रतिज्ञा करता हूँ ।

उक्त उदाहरणों में केवल पहले एवं दूसरे विलेख को प्रतिज्ञा-पत्र कहेंगे क्योंकि उसमें पाने वाला व्यक्ति तथा रकम निश्चित है । किन्तु उदाहरण ३ से ८ को हम प्रतिज्ञा-पत्र नहीं कहेंगे क्योंकि उनमें से तीसरे में केवल स्वीकृति है प्रतिज्ञा नहीं, चौथे और पाँचवें में रकम निश्चित नहीं है छठे में न रकम

निश्चित है और न प्रतिज्ञा ही भन रहित है। मातृपत्र में प्रतिज्ञा भन रहित नहीं है, तथा आठवें में केवल स्वेच्छा दान की प्रतिज्ञा न हान हुए। धाडा दान की भी प्रतिज्ञा है।

इन उदाहरणों में स्पष्ट है कि प्रतिज्ञा-पत्र उसी बिलम्ब की वहेग जिसमें भगवान की गति एवं व्यक्ति निश्चित रूप में दिय गये हैं तथा वह एक निश्चित प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा पत्र पर उनकी राशि के अनुसार स्टाम्प कर लगता है। प्रतिज्ञा पत्रों में दो पक्ष हान हैं—एक प्रतिज्ञा पत्र निम्न वाना तथा दूसरा जिसका प्रतिज्ञा दी जाती है अथवा जिसके नाम भुगतान करन का प्रतिज्ञा होती है। अर्थात् इनमें में एक लेखीवाला (ऋणी) हाना है तथा दूसरा दान वाला (ऋणदाता) हाना है।

प्रतिज्ञा पत्र यदि ला जाय ता धानी क्षति पूर्ण का पूरा उत्तरदायित्व लेकर लेखीवान में दूसरा प्रति ल सकता है।

वचान भुगतान आदि सम्बन्धी वही नियम इसमें भी लागू होत है जा बिला में लागू होत है।

**प्रतिज्ञा-पत्र के तीन प्रकार**

१ **व्यक्तिक प्रतिज्ञा पत्र**—जिनमें केवल एक ही लेखीवाना हाना है तथा भुगतान करन का दायित्व भी उमा का हाना है। यदि बिलम्ब का वह भुगतान नहीं करना तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही ला जाती है। परन्तु इसके अनादरण हान पर बिना की तरह प्रमाण (noting and protesting) की आवश्यकता नहीं होती।

२ **सामूहिक (Joint) प्रतिज्ञा पत्र**—जिनमें प्रतिज्ञा करन वान एवं लेखीवान उनकी राशि के भुगतान का दायित्व सामूहिक रूप में स्वीकार करन है। हम दसा में यदि धारी का प्रतिज्ञा पत्र का भुगतान नहीं हाना ता प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध सामूहिक रूप में वैधानिक कार्यवाही करनी चाहिए जिसमें यह सब व्यक्तियां में भुगतान प्राप्त कर सकें। किन्तु यदि वह लेखीवाला के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही न करते हुए किसी एक ही व्यक्ति के विरुद्ध करता है एवं उसकी सम्पत्ति में पूरा भुगतान प्राप्त नहीं होता तो शेष राशि के लिए वह अन्य लेखीवानों की दायी नहीं बना सकता और न उनमें स्वयं वसूल कर सकता है। इसलिए सामूहिक प्रतिज्ञा पत्र के अनादरण में लेखीवाला के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी सामूहिक ही करना चाहिए।

३ **सामूहिक एवं व्यक्तिक (Joint & Several) प्रतिज्ञा-पत्र**—इन

प्रतिज्ञा पत्रों के लेखीवाले विनियम की राशि के भुगतान का दायित्व सामूहिक एवं वैयक्तिक रूप से स्वीकार करत है। अतः अनादरण होने की दशा में इनका धारी जब तक वह पूर्ण राशि प्राप्त न करल तब तक प्रत्येक व्यक्ति को विरुद्ध अलग-अलग वैधानिक कार्यवाही कर सकता है।

### अन्य सार-पत्र

१ बैंक-बिल (अ) बैंक ड्राफ्ट—यह बैंक द्वारा अपनी शाखा को अथवा अन्य बैंक को किसी निश्चित व्यक्ति का जिसका नाम उमम दिया जाता है अथवा उसके आदेशानुसार एक निश्चित रकम मांग पर देने का लिखित आदेश होता है। यह पत्र कोई भी व्यक्ति जिनका बैंक-ड्राफ्ट चाहता है उसकी राशि जमा करने पर बैंक से ले सकता है।

बैंक ड्राफ्ट रेखांकित भी किया जा सकता है अथवा उनका भुगतान आदेश पर किया जा सकता है। बैंक ड्राफ्ट देश के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा देश में विदेश में राशि भेजने के लिए उपयोग में आता है तथा इनकी दम में बैंक कमीशन लेता है जो उसका लाभ होता है। विदेशी बैंक ड्राफ्टों में यह कमीशन विनिमय दर में ही जोड़ दिया जाता है। बैंक ड्राफ्ट के धन का स्थानान्तरण सुगम होता है।

इसमें किसी भी प्रकार के कपट की सम्भावना नहीं रहती क्योंकि जिस बैंक का ड्राफ्ट भेजा जाता है उस इसकी सूचना दी जाती है। फिर भी विरोध ऐसा अनुभव है कि देने वाली बैंक ड्राफ्ट का भुगतान उस व्यक्ति का राकड़ में नहीं करती। परन्तु उसके लक्ष्य में वह राशि जमा करती है यदि उसका लक्ष्य है अन्यथा उस किसी अन्य व्यक्ति से प्रमाणित करवाकर उसकी गवाही लेती है।

(ब) बैंक स्वीकृति (Bank Acceptances)—सभी व्यापारी एक दूसरे से परिचित नहीं होते। अतः व्यापारिक बिल बिना जाच के कोई भी व्यापारी ऋण के भुगतान में स्वीकार नहीं करता। ऐसी अवस्था में ऋणी व्यापारी बैंक पर बिल लिखता है जिसकी राशि उस पत्र में लिखित व्यापारी को अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को देने वाला द्वारा दी जाती है। यह बिल जब बैंक अपने ग्राहक की ओर से स्वीकार करता है तो उसे बैंक स्वीकृति कहते हैं। बैंक पर इन बिलों के भुगतान करने का दायित्व नहीं रहता क्योंकि ग्राहक पत्र तिथि के पूर्व ही बिल की राशि बैंक को देता है।

ऐसे बिलों से ग्राहक की साख बढ़ती है तथा धन का स्थानान्तरण सुगम होता है। दूसरे, जब तक ऐसे बिलों का भुगतान पाने वाला उस बैंक से नहीं

मांगता तब तब उसके निशेपा में वृद्धि होती है। क्योंकि आदरण के लिए बिल की राशि पक्व-तिथि के पूर्व ही ग्राहक द्वारा बैंक को दी जाती है।

इन बिलों की स्वीकृति बैंक देता है अतः इन्हें 'बैंक स्वीकृति' भी कहते हैं। इस प्रकार बैंक बिलों में बैंक ड्राफ्ट एवं बैंक स्वीकृति दोनों का समावेश होता है।

रोक ऋण (cash credits) के प्रचार से भारत में इनका उपयोग नहीं होता। इसमें अनिश्चित बिलों का स्टाप्प कर, वस्तु अधिकार-पत्रों का प्रभाव, बिलों के सर्वमान्य रूप का अभाव के कारण भी इस प्रकार के बिलों का चलन हमारा यहाँ नहीं है।

२ साख-पत्र (Letters of Credit)—बैंक साख-निर्माण करते हैं। वे साख द्वारा ग्राहकों को दो प्रकार की सुविधा देते हैं, व्यापारिक तथा अध्यापारिक।

व्यापारिक साख-पत्रों में बैंक के उन पत्रों का समावेश होता है जो बैंक केवल व्यापारिक कार्यों के लिए तथा व्यापारियों की सुविधाओं के लिए देते हैं। इनमें से साख पत्र बैंक ड्राफ्ट तथा बैंक-स्वीकृति महत्वपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त व्यापारियों एवं अध्यापारिक व्यक्तियों की सुविधाओं के लिए साखपत्र दिये जाते हैं। ये साखपत्र उन व्यक्तियों के लिए दिये जाते हैं जो विदेशों में यात्रा के लिए जाते हैं तथा अपने साथ रुपया ले जाना नहीं चाहते अथवा विदेशों में उसके बदला-बदली की अमुविधाएँ नहीं उठाना चाहते हैं।

साखपत्र उन्हें कहते हैं जो एक बैंक दूसरे विदेशी बैंक का अथवा विदेश स्थित अपने अधिकृतता का किसी निश्चित व्यक्ति को, जिसका उस पत्र में नाम है, निश्चित राशि देन का आदेश देता है अथवा प्रायत्न करता है। यह पत्र कोई विदेश में जान वाला व्यक्ति, जिनकी राशि की आवश्यकता हो उतनी राशि बैंक में जमा कर ले सकता है। इस सुविधा के लिए बैंक शुल्क लेते हैं। ये साखपत्र हस्तान्तरणीय एवं वचानमय नहीं होते तथा इनको बैंक अपनी इच्छा से निरस्त नहीं कर सकता। जब विदेशों में उन व्यक्ति को राशि की आवश्यकता होती है, वह इस पत्र की उपस्थिति पर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के पत्रों के साथ बैंक एक निर्देश-पत्र (letter of indication) देता है, जिस पर किन-किन बैंकों को वह साखपत्र उपस्थित किया जा सकता है यह दिया जाता है तथा इसी पत्र पर ग्राहक के नमूने के हस्ताक्षर भी होते हैं। उसे रुपया लेते समय विदेशों में हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, जो नमूने के हस्ताक्षर के

समान होने चाहिए । जब ग्राहक रपया चाहता है उस समय उसे साखपत्र एवं निर्देश-पत्र दोनों ही दिखाने पड़ते हैं और उसे अपने हस्ताक्षर करने पर रपया प्राप्त हो जाता है । साखपत्र देन वाला बैंक अन्त में जिन-जिन बैंकों से राशि ली गई है उनको भुगतान कर देता है । ऐसे पत्र जब यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिये जाते हैं, उन्हें अभियात्री साखपत्र (traveller's letter of credit) कहते हैं, तथा कितनी राशि उन्हें प्राप्त हो सकती है यह इस पत्र में लिखा होता है । उसमें अधिक राशि यात्री प्राप्त नहीं कर सकता ।

ये साखपत्र तीन प्रकार के होते हैं —

(१) सीधिन साखपत्र—ये किन्हीं विशेष अभिकर्ताओं अथवा बैंकों के नाम होते हैं, केवल उन्हीं से उस व्यक्ति को राशि मिल सकती है, अन्य किसी बैंक से नहीं । अतः ऐसे पत्रों पर ही धारी के नमूने के हस्ताक्षर और माल की राशि दी जाती है जिससे निर्देश-पत्र की आवश्यकता नहीं रहती ।

(२) परि-साखपत्र—ये किसी विशेष बैंक या अभिकर्ता को नहीं लिखे जाते हैं । परन्तु इस पत्र के आधार पर किन-किन बैंकों अथवा अभिकर्ताओं से राशि प्राप्त की जा सकती है यह जानने के लिए इन पत्रों के साथ एक निर्देश-पत्र होता है । इस निर्देश-पत्र पर साखपत्र की कुल राशि एवं धारी के नमूने के हस्ताक्षर रहते हैं । जो बैंक अथवा अभिकर्ता राशि देता है, वह दो हुई राशि निर्देश-पत्र पर लिख देता है । इस प्रकार यह साखपत्र धारी के पास तब तक रहता है जब तक उसने साखपत्र की पूर्ण राशि न ली हो । जब धारी पूर्ण राशि से लेता है तब जो व्यक्ति, बैंक या अभिकर्ता अन्तिम राशि लेता है इस परि-साखपत्र को अपने पास रख लेता है ।

(३) यात्री व्यापार-साखपत्र—ये पत्र उन व्यापारियों को ही दिये जाते हैं जो माल खरीदने के हेतु यात्रा करते हैं । ये पत्र बैंक किन्हीं विशेष बैंकों के नाम ही लिखता है जहाँ से इन पत्रों के आधार पर राशि ली जा सकती है । परन्तु धारी को राशि तभी मिलती है जब वह वस्तुएँ खरीदने का पर्याप्त प्रमाण दे अर्थात् इन पत्रों में सधारक को जहाजी बिल्टी आदि दिखाने पर ही राशि मिल सकती है ।

व्यापारिक साखपत्रों में केवल उन पत्रों का समावेश होता है जो केवल व्यापारियों की सुविधा के लिए दिये जाते हैं । इनमें बैंक स्वीटन बिल का विशेष प्रचार होता है । इसके अतिरिक्त दो प्रकार से सुविधा दी जाती है— निरस्तनीय (revocable) साखपत्र जो ग्राहक या बैंक द्वारा किसी भी समय

रद्द किया जा सकता है, तथा अनिरस्तनीय (irrevocable) साखपत्र, जिसको दूसरे पक्ष की अनुमति बिना रद्द नहीं किया जा सकता है। अनिरस्तनीय साखपत्रों में वेब यह आश्वासन देता है कि जिस व्यक्ति के पक्ष (favour) में पत्र लिखा गया है, उसका ड्राफ्ट अथवा बिलों का आदरण एवं स्वीकृति बैंक करेगा। इस पत्र के आधार पर विदेशी निर्यातकर्ता, जिस व्यक्ति के पक्ष में पत्र दिया गया है उसका माल भुगतान में किसी भी नहीं उगमगाता। क्योंकि आयातकर्ता द्वारा भुगतान न होने पर उस बैंक से भुगतान मिल सकता है। अतः ये पत्र आयात निर्यात व्यापार में जबिक उपयोगी होते हैं।

निरस्तनीय साख पत्रों में याजना उपयुक्त ही होती है किन्तु इन साख-पत्रों का ग्राहक या बैंक अपनी इच्छा में निरस्त कर दत्त है। अतः ये अधिक विश्वसनीय नहीं हैं और न विदेशी व्यापार में इनका विशेष प्रचार ही है।

य साखपत्र, राशि के अनुसार तीन प्रकार के हो सकते हैं —

(अ) स्थायी साखपत्र—इनमें व्यापारी द्वारा लिखे गये बिलों की स्वीकृति का उत्तरदायित्व किसी निश्चित राशि एवं अवधि तक ही बैंक पर होता है।

(ब) घूर्ण साखपत्र (Revolving Credits)—जिनमें एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित राशि के बिल लिखे जा सकते हैं। परन्तु उसी अवधि में यदि एक बिल का भुगतान हो जाय तो पुनः उस राशि तक दूसरा बिल लिखा जा सकता है।

३ कोष बिल (Treasury Bills)—उन साखपत्रों का कहते हैं जिनके धन स किसी देश की सरकार जनता से जुट लती है। ये बिल भिन्न भिन्न अवधि के होते हैं किन्तु अधिकतम अवधि ३ मास की होती है। ये विशेषतः सरकार की दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक रूपसे प्राप्त करने के लिए चलाये जाते हैं तथा विज्ञापन द्वारा इनका सरीदने के नियम सभ्य सभ्य पर अलखारा में प्रकाशित किये जाते हैं। ये राज्य अथवा केन्द्र सरकारों द्वारा (२५०००) रु०, १ लाख ५ लाख तथा १० लाख रुपये के मूल्य के चलाये जाते हैं।

४ अर्थ बिल (Finance Bills)—ये बिल भविष्य में उत्पादन अथवा निमाण होने वाली वस्तुओं के आधार पर तैयार किये जाते हैं। अतः एम बिलों को अग्रिम बिल (anticipatory bills) भी कहते हैं। ये बिल विशेषकर कृषि-कार्यों के लिए अधिक उपयोगी हैं क्योंकि इनका भुगतान उत्पादन की बिक्री (sale of produce) पर होता है। भारत में किसानों का अल्पकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए इन बिलों का उपयोग हो सकता है।

## हुण्डी तथा प्रतिज्ञा-पत्र के नमूने

## १. दर्शनी हुण्डी

सिद्ध श्री कलकत्ता शुभस्थान भाई श्री० श्रीनारायण अग्रवाल  
जोग लिखी गवासियर से पिंडीलाल कचोडीमल की जयगोपाल  
वचना । अपरच हुंडी कीन्ही एक आप ऊपर रु० २०००), अकेन  
दो हजार रुपया के नीमे एक हजार के दूने पूर यहा राख्या भाई  
मानकचन्द नयमल जैन कानपुर वालो के मिती कातिक बदी ५ से  
पहुँचे । दाम धनी जोग बिना जास्ता रुपया बाजार चलन हुण्डी की  
रीति ठिकाने लगाय दाम चोकस कर देना । मिती कातिक बदी ५  
संवत् २००१ ।

लिखी पिंडीलाल कचोडीमल की जयगोपाल वचना ।

## हुण्डी का पिछला भाग—

रुपया २०००)

नीमे के नीमे पाँच सौ का  
चोगुना पूरा रुपया दो हजार कर देना

ठिकाना—भाई श्री श्रीनारायण अग्रवाल, २४ बलाइव स्ट्रीट  
स्ववेयर, कलकत्ता ।

## २ मुद्दी हुण्डी

मिद्ध श्री बम्बई युगस्थाने भाई श्री गोवर्धनदास लक्ष्मणदास मिश्रा जोग लिखी कलकत्ता से पूरनचन्द कजोडीमल की जंगोपाल वचना जी । अपरच हुण्डी चीन्ही आप पर नग एक रुपया २०००) अकेन रुपया दो हजार के नीमे एक हजार के दूने पूर यहाँ राख्या थी भारत बैंक लिमिटेड कलकत्ता वालो के पाम मिती बैसाख सुदी १२ से दिन ६१ इकसठ पीछे नामे साहजोग हुडी खलन कलदार देना । मिती बैसाख सुदी १० मवत २००५ ।

लिखी पूरनचन्द कजोडीमल की जंगोपाल वचना जी ।

## उपरोक्त हुण्डी का पिछला भाग—

रुपया २०००)

नीमे के नीमे पाँच सौ का बीगुना  
पूरा रुपया दो हजार भर देना

ठिकाना—भाई श्री गोवर्धनदास लक्ष्मणदास मिश्रा, फोर्ट,  
बम्बई ।

## ३. वैयक्तिक प्रतिज्ञा-पत्र

मुद्रांक २५०) रुपये

वर्धा

तिथि १ जुलाई १९४६

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपर्युक्त तिथि के तीन मास पश्चात् मैं श्री० गिरिराज प्रसाद गुप्त को ढाई सौ रुपये प्रदान करूँगा।

हस्ताक्षर चन्द्रमोहन पचोरी

## ४. सामूहिक प्रतिज्ञा-पत्र

मुद्रांक ६० १०००)

कानपुर १० जुलाई १९४६

हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इस तिथि के दो मास उपरान्त श्री० गिरिराज प्रसाद गुप्त को एक हजार रुपये, प्राप्त मूल्य के, प्रदान करेंगे।

हस्ताक्षर

{ रामचन्द्र पद्मलाल कटक  
बिक्रमाजीतमिह

## ५. सामूहिक एवं वैयक्तिक प्रतिज्ञा-पत्र

मुद्रांक ६० १०००)

कानपुर, ५ नवम्बर १९४६

हम व्यक्तिगत तथा सामूहिक प्रतिज्ञा करते हैं कि इस तिथि के तीन मास उपरान्त श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव को एक हजार रुपये, प्राप्त मूल्य के प्रदान करेंगे।

हस्ताक्षर

{ हरिहरमहाय अग्रवाल  
रामचन्द्र पद्मलाल अग्रवाल

## सारांश

साखपत्र के दो प्रकार—बेचान साध्य एवं बेचान रहित । बेचान-साध्य साखपत्रों का स्वत्व एवं स्वामित्व किसी व्यक्ति को हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण एवं बेचान से मित जाता है । इसकी विशेषताएँ लिखित होना, हस्तांतरण अथवा हस्तांतरण एवं बेचान से हस्तांतरित या पृष्ठांकिकी को स्वत्व मिलना, धारी को दावा करने का अधिकार, मूल्य के लिए धारी को विलेख का स्वामित्व बिना किसी दोष के मिलना । बेचान-रहित साखपत्रों में ऐसा नहीं होता ।

धारी—वह व्यक्ति है जिसे १ विलेख की सम्पत्ति अपने नाम से लेने का अधिकार हो ।

२ आदाता, ग्राहक या पृष्ठांकिकी के नाते विलेख के पक्षकारों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार हो ।

३ उपाधि वैधानिक रीति से प्राप्त हो ।

यथा विधि धारी वह व्यक्ति है जिम्मे—१ विलेख के अनादरण एवं भुगतान के पूर्व उसका अधिकार प्राप्त किया हो ।

२ पूर्ण सम्भावना से किसी मूल्य के विनिमय में विलेख लिया हो ।

३ विलेख के बेचान के समय बेचानकर्ता की उपाधि दूयित न हो ।

४ विलेख की प्राप्ति प्रतिफल के बदले में हो ।

५ विलेख पूर्ण एवं नियमी हो । ऐसा यथाविधि धारी उस विलेख की सम्पत्ति के लिए अन्य पक्षों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा । बेचान-साध्य साख विलेखों में चंक, विनिमय बिल तथा प्रतिज्ञापत्रों का समावेश होता है ।

चंक—चंक किसी बैंक विशेष पर लिखा गया विनिमय बिल होता है । इसकी विशेषताएँ हैं—लिखित आदेश हो, शर्त रहित हो, निश्चित बैंक के नाम हो, माग पर भुगतान देने का आदेश हो, चंक लिखने वाले के हस्ताक्षर हो, राशि निश्चित हो, आदाता का नाम निश्चित एवं स्पष्ट हो । इन बातों के साथ ही चंक लिखने में निम्न सावधानी रखनी होगी तिथि देना, अर्को एवं शब्दों में राशि भेद न होना, लिखने वाले के हस्ताक्षर बैंक के पास के नमूने के हस्ताक्षर के समान होना ।

चंक में तीन पक्ष—लिखने वाला (ग्राहक), भुगतानकर्ता (बैंक), आदाता । तिथि के हिसाब से चंक तीन प्रकार के होते हैं—(१) पूर्व तिथीय, जिनपर वास्तविक तिथि के पहिले की तिथि हो, (२) उत्तरतिथीय, जिनपर वास्तविक तिथि हैं

अगली तिथि हो। (३) बीतकालीन, जिस पर ६ मास पहिले की तिथि हो। इनमे से बैंक बीतकालीन बैंक का भुगतान ग्राहक की अनुमति बिना नहीं करते, पूर्व तिथीय बैंक यदि ६ मास से कम अवधि के हो तो उनका भुगतान करते हैं। परन्तु उत्तरतिथीय बैंक का भुगतान उसमे लिखित तिथि को अथवा उसके बाद करते हैं। आदेश बैंक का हस्तांतरण बिना बेचान के नहीं हो सकता और न उसका भुगतान ही मिल सकता है। वाहक बैंकों का भुगतान एवं हस्तांतरण उसके धारी को होता है। खुला बैंक—उसे कहते हैं जिसका भुगतान बैंक में जाकर उसका धारी ले सकता है। रेखांकित बैंक का भुगतान धारी को केवल किसी बैंक के माध्यम से प्रस्तुत करने पर ही मिल सकता है।

रेखांकन—बैंक पर सुरक्षा के लिए जब दो समानांतर रेखाएँ खींची जाती हैं तब उसे रेखांकन कहते हैं। ऐसा बैंक किसी बैंक के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है। रेखांकन तीन प्रकार का होता है—(१) सामान्य रेखांकन, जिसे किसी बैंक के माध्यम से भुनाया जा सकता है। (२) विशेष रेखांकन, इसमें समानांतर रेखाओं के बीच किसी बैंक विशेष का नाम लिखा जाता है; जिससे उसे केवल उसी बैंक के माध्यम से भुनाया जा सकता है। (३) बेचान रहित रेखांकन इसमें समानांतर रेखाओं के बीच “नॉट निगोशिएबल” शब्द लिखे जाते हैं। ऐसे बैंक का बेचान फिर नहीं हो सकता और यदि होता है तो हस्तांतरिती को हस्तांतरक से अच्छी उपाधि नहीं मिल सकती।

कोई भी धारी, लिखने वाला या बेचानकर्ता खुले बैंक को रेखांकित, रेखांकित बैंक को विशेष रेखांकित तथा बेचानरहित रेखांकन में परिवर्तन कर सकता है।

महत्वपूर्ण परिवर्तन—बैंक के उन परिवर्तनों को कहते हैं जिससे उसकी मूल वैधानिक भाषा में परिवर्तन हो जाय। ये परिवर्तन निम्न होते हैं—तिथि, भुगतान का स्थान, राशि अथवा आदाता के नाम में परिवर्तन, सामान्य रेखांकन को निदान करना, विशेष रेखांकित बैंक का सामान्य रेखांकित बैंक में तथा आदेश बैंक का वाहन बैंक में परिवर्तन। ऐसे सब परिवर्तनों पर लिखने वाले के हस्ताक्षर हुए बिना बैंक का भुगतान नहीं होगा।

बैंक खोने पर—उसकी सूचना भुगतानकर्ता बैंक, लिखने वाले को तथा बेचानकर्ता को देना चाहिए जिससे उसका भुगतान बैंक लिखने वाला रोक सके।

चिह्नित बैंक—उसे कहते हैं जिस पर भुगतानकर्ता बैंक साल स्याही से हस्ताक्षर करता है। ऐसा करते समय कभी-कभी बैंक बैंक को उपस्थित करने

को अंतिम तिथि भी दे देता है जिस अवधि में धारी ने उसे भुनाना चाहिए। सप्राहक बैंक, धारी अथवा लिखने वाले ग्राहक की प्रार्थना पर भुगतानकर्ता बैंक बैंक को चिह्नित करता है। पहिली तथा तीसरी दशा में ग्राहक उस बैंक का भुगतान नहीं रोक सकता परन्तु दूसरी दशा में यदि समुचित समय में बैंक प्रस्तुत न होने के कारण यदि अप्रतिष्ठित हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी आदाता अथवा धारी की होगी।

उपस्थिति का समुचित समय निम्न बातों का ध्यान में रखकर निश्चित होना है—(१) बैंक लिखने वाले एवं पाने वाले की स्थान-दूरी, (२) विलेख को उपस्थित करने की पद्धति, (३) विलेख का स्वरूप।

विहृत बैंक—आकस्मिक रूप से जो बैंक फट जाता है तब उसे विहृत बैंक कहते हैं। ऐसे बैंक का भुगतान बैंक ग्राहक की लिखित अनुमति बिना नहीं करेगा।

जाली बैंक एवं जाली बचान - जाली बैंक उसे कहते हैं जिस पर ग्राहक के जाली हस्ताक्षर हो तथा जाली बचान में बैंक पर बचानकर्ता के हस्ताक्षर जाली होते हैं। पहिली दशा में यदि बैंक ऐसे बैंक का भुगतान करे तो यह उसकी रकम ग्राहक से वसूल नहीं कर सकता क्योंकि यह ग्राहक का आदेश नहीं था। परन्तु जाली बचान में यह प्रत्येक बचानकर्ता के हस्ताक्षर जानने के लिए बाध्य नहीं होता, इस कारण ग्राहक के खाने को डेबिट कर सकता है।

बचान—इसमें बचानसाध्य विलेख का स्वत्वधारी स्वामी अथवा धारी उस विलेख की संपत्ति का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को देने हेतु उस विलेख पर अपने हस्ताक्षर करता है। ऐसा बचान आदाता, धारी अथवा पृष्ठांकिकी अथवा इनके अधिकृत अभिकर्ता कर सकते हैं। बचान पाँच किस्म के होते हैं—सामान्य, विशेष, सीमित, दायित्व रहित तथा ऐच्छिक जिनमें से प्रथम तीन ही प्रचलन में हैं।

बैंक के लाभ—धन की सुरक्षा, हानि की संभावना नहीं, रसीद अनावश्यक, भुगतान में सुगमता, आय-व्यय का हिसाब, साख निर्माण।

विनिमय बिल की विशेषताएँ—लिखित एवं शतं रहित आदेश, आदेशकर्ता के हस्ताक्षर, किसी निश्चित व्यक्ति को आदेश निश्चित रकम के भुगतान का आदेश, भुगतान पाने वाला व्यक्ति एवं भुगतान का समय निश्चित हो।

बिलों का वर्गीकरण—(१) स्थानीय—देशी बिल जो भारत में बनाये गये हों या भारतीयों पर लिखे गये हों या उनका भुगतान भारत में हों। जो बिल

ऐसे नहीं होते उन्हें विदेशी बिल कहते हैं। विदेशी बिल तीन प्रतियों में लिखे जाते हैं जिनमें से किसी एक का भुगतान होने पर शेष निरस्त हो जाते हैं।

(२) भुगतान—वाहक बिल की राशि किसी भी व्यक्ति को, जिसके पास वह वैधानिक रीति से हो, भुगतान होती है।

आदेश बिल की राशि आदाता अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान होती है।

(३) अवधि-दर्शनी बिल—जिसका भुगतान उपस्थिति पर हो तथा मुद्रती बिल जिसका भुगतान बिल में लिखित अवधि की समाप्ति पर हो।

(४) व्यवहार—व्यापारिक बिल जो व्यापारिक कार्यों के लिए लिखे गये हो तथा अनुग्रह बिल जो केवल एक दूसरे की आर्थिक सहायता के लिए लिखे जायें।

बैंक की भांति बिलों के भी तीन पक्ष होते हैं—लिखने वाला (ऋणदाता), आदाता तथा भुगतानकर्ता (ऋणी) जो बिल को स्वीकार करता है।

बिलों की स्वीकृति—दर्शनी बिलों में स्वीकृति आवश्यक नहीं होती। मुद्रती बिलों में आवश्यक होती है। जब तक वे स्वीकृति नहीं होते तब तक उन्हें ड्राफ्ट तथा स्वीकृति होने पर बिल कहा जाता है। स्वीकृति सामान्य एवं विशेष होती है तथा स्वीकृति के लिए बिल को भुगतानकर्ता के व्यापारिक स्थान पर व्यापारिक समय में प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। स्वीकृति न होने पर भी बिलों का अनादरस्य समझा जाता है।

बिलों में लाभ—बिलों की कटौती से बैंक के लाभ बढ़ते हैं, सुरक्षा का साधन, भुगतान की निश्चितता, धूसर्यों में उतार चढ़ाव नहीं, जहाजी बिल्टी या अन्य प्रतिभूतियाँ सलग्न होने से सुरक्षित ऋण, ग्राहकों का कृपापात्र।

व्यापारियों को बिलों की कटौती में लाभ—ऋण का वैज्ञानिक प्रमाण, भुगतान की व्यवस्था में सुगमता, रोकड़ प्राप्त करने में सुगमता, देश-विदेशों को भुगतान में सुगमता।

हुण्डियाँ—ये प्राचीन काल से भारतीय क्षेत्रों में स्थानीय परम्पराओं के अनुसार एवं स्थानीय भाषाओं में प्रचलित हैं तथा इनका सम्यक्देश भारतीय बेचान साध्य विलेख अधिनियम के अन्तर्गत नहीं होता।

अवधि के अनुसार हुण्डियाँ दर्शनी एवं मुद्रती तथा भुगतान की पद्धति के अनुसार धनीजोग, शाहजोग, फर्मानजोग तथा देखनहारजोग होती हैं। क्रमशः ये बेचान-रहित, विशेष रेखांकित आदेश एवं वाहक बनादेश की भांति

होती हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन काल में भारत में जोखमी हुण्डी भी चलन में थी।

प्रतिज्ञा पत्र—इसमें लिखने वाला (ऋणी) यह शर्त रहित प्रतिज्ञा करता है कि वह उसमें लिखित निश्चित राशि, उसमें लिखित निश्चित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार देगा। इनमें दो पक्ष होते हैं—एक लिखने वाला तथा दूसरा पाने वाला जो साधारणतः ऋणदाता होता है। प्रतिज्ञा-पत्र खोने पर धारी क्षतिपूर्ति की जिम्मेवारी पर लिखने वाले से दूसरी प्रति ले सकता है।

प्रतिज्ञा पत्र के तीन प्रकार—(१) वैयक्तिक—जिसमें एक ही प्रतिज्ञाकर्ता होता है एवं भुगतान की जिम्मेवारी उसी की होती है।

(२) सामूहिक—जिसमें एक से अधिक व्यक्ति प्रतिज्ञा करते हैं एवं भुगतान की सामूहिक जिम्मेवारी लने हैं।

(३) वैयक्तिक एवं सामूहिक—इसमें लिखने वाली व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप में प्रतिज्ञापत्र के भुगतान के लिए जिम्मेवार होते हैं।

रेखाकन आदि सम्बन्धी अन्य नियम चंक्र के समान ही इनको भी लागू होते हैं।

अन्य मात्रपत्र—बैंक ड्राफ्ट, एच बैंक द्वारा अपनी शान्ता अथवा अन्य बैंक पर लिखा हुआ चंक्र होता है। ड्राफ्ट देने वालो बैंक इसके लिए कमीशन लेते हैं तथा यह अधिक राशि स्थानांतरण का सुगम एवं सुरक्षित साधन है।

बैंक स्वीकृति—बैंक जब अपने को ग्राहक की ओर से अथवा ग्राहक द्वारा लिखे गये बिल स्वीकार करना है तब उसे बैंक स्वीकृति कहते हैं। इन बिलों का संपौगिक दायित्व बैंक पर होता है। साधारणतः इनकी राशि भुगतान तिथि के पूर्व ग्राहक बैंक में जमा कर देता है।

मात्रपत्र—जब एक बैंक विदेशी बैंकों या अपने विदेशी अभिकर्ताओं को किसी निश्चित व्यक्ति को (जिसका नाम पत्र में हो) निश्चित राशि भुगतान करने की प्रार्थना करता है तब उसे मात्रपत्र कहते हैं। यह कोई भी व्यक्ति बैंक में जितनी राशि का मात्रपत्र चाहता है, उतनी राशि जमाकर प्राप्त कर सकता है। इन पत्रों के साथ निर्देशपत्र भी रहता है जिस पर ग्राहक के नमूने के हस्ताक्षर तथा किन बैंकों से रुपया लिया जा सकता है, उनका नाम रहता है। जो मात्रपत्र व्यापारिक सुविधाओं के हेतु होते हैं उन्हें व्यापारिक मात्रपत्र तथा जो यात्रियों की सुविधा के लिए दिये जाते हैं उन्हें अभियात्री मात्रपत्र कहते हैं।

साखपत्र के तीन प्रकार—(१) सीमित साखपत्र—ये किन्हीं विशेष बंको या अतिरिक्तों के नाम होते हैं ।

(२) परि-साखपत्र—ये परिपत्रों की भाँति होते हैं तथा जिन बंकों से राशि प्राप्त हो सकती है उनके नाम एक पृथक् निर्देश पत्र में होते हैं ।

(३) यात्री व्यापार साखपत्र—ये उन व्यापारियों को दिये जाते हैं जो माल खरीदने के हेतु यात्रा करते हैं । व्यापारिक साखपत्र निरस्तनीय तथा अनिरस्तनीय होते हैं । राशि के अनुसार साखपत्र व्यापी एवं चल दो प्रकार के होते हैं ।

बोप बिल—जो राज्य या केन्द्र सरकारें अपनी बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वासूल करती हैं वे प्रतिज्ञापत्र होते हैं । इनको अवधि ६० दिन से अधिक नहीं होती ।

अर्थ बिल—ये भविष्यकालीन कृषि अथवा औद्योगिक उत्पादन की जमानत पर लिखे गये बिल होते हैं तथा कृषि की अल्पकालीन अर्थ-व्यवस्था के लिए उपयोगी होते हैं ।

## बैंक लेखों के प्रकार

बैंक जनता, मध्याह्न, कम्पनियों आदि से तीन प्रकार के निक्षेप स्वीकार करते हैं —

१. चल-निक्षेप—इस लेख में व्यापारिक समय में राशि जमा करने अथवा निकालने पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं होता। इसलिए व्यापारी विनोद अपनी रोकड़ चल-निक्षेप में ही जमा करते हैं। श्री टैनन के अनुसार प्रथम श्रेणी के बैंक चल-निक्षेपों पर कोई व्याज नहीं देने तथा इस लेख की न्यूनतम मर्यादा निश्चित करते हैं। इस मर्यादा के अनुसार इस लेख का शेष कुछ निश्चित राशि में कम नहीं होना चाहिए, किन्तु यदि वह कम होता है तो बैंक ग्राहक में मयोगिक व्यय लेने हैं, जो उनका लाभ होता है। इस लेख में जा राशि होती है वह किसी भी समय बैंक द्वारा निकाली जा सकती है तथा बैंक पर इन पर लिखे हुए बैंकों का आदरण करने की जिम्मेवारी होती है। भारत में कुछ बैंक निक्षेप (deposited) राशि की न्यूनतम मर्यादा निश्चित कर उस पर २% प्रतिशत वार्षिक व्याज देने हैं किन्तु इस प्रकार दिये हुए त्रैमासिक व्याज की रकम ३) से ५) से कम नहीं होनी चाहिए। इस न्यूनतम राशि का उपयोग बैंक स्वतन्त्रता से कर सकते हैं।<sup>1</sup> जो ग्राहक १,००,००० रुपय से अधिक राशि रखते हैं उनके लिए बैंक विशेष व्यवस्था करता है।

इस लेख पर बैंक की जिम्मेवारी अधिक होती है क्योंकि ग्राहक प्रतिदिन बैंक में चाहे जितनी राशि ले सकता है, जिसका अनुमान बैंक का नहीं होता। इसलिए बैंकों का अपनी जिम्मेवारी के लिए सदैव अधिक रोकड़-निधि रखनी पड़ती है। इस प्रकार के सारे व्यापारियों को अधिक लाभदायक होते हैं।

चल-लेखा खोलने की विधि—बोर्ड भी लेखा खोलने के पूर्व बैंक को यह

<sup>1</sup> Joint Stock Banking in India by D S Savarkar

ज्ञान लेना चाहिए कि भावी ग्राहक का व्यापार कौन-सा है एवं किस प्रकार का लेखा यह गोलना चाहता है। साथ ही बैंक को उस व्यक्ति से परिचित व्यक्तियों अथवा मस्थाओं से सन्दर्भ लेना चाहिए जिससे वह ग्राहक की आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यापारिक व्यवहारों आदि बातों की पूर्ण जानकारी ले सके। इससे बैंक यह निश्चित कर सकता है कि वह व्यक्ति ग्राहक बनाने योग्य है अथवा नहीं। इन सन्दर्भों से अपने भावी ग्राहक को पूर्ण जानकारी देने के बाद ही बैंक का लेखा खोलना चाहिए। इससे ग्राहक के जाली दुर्यों में वह अपनी सुरक्षा कर सकता है तथा उसे आर्थिक हानि की सम्भावना नहीं रहती। दूसरे, ग्राहक की आर्थिक स्थिति के विषय में उसे अन्य ग्राहकों अथवा बैंक की गोपनीय जाँच का उत्तर देना पड़ता है, जिसके लिए यह ज्ञान उसे आवश्यक होता है। तीसरे, लेखा खोलने के पूर्व यदि वह इन बातों की जानकारी नहीं लेता है तो उस बेचनासाध्य विलेख विधान के अन्तर्गत वैधानिक सुरक्षण नहीं मिल सकती, क्योंकि लेखा खोलने में उसने उपेक्षा में काम किया है। अतः ग्राहक एवं बैंक दोनों की दृष्टि में ग्राहक की आर्थिक स्थिति एवं आर्थिक व्यवहारों के सम्बन्ध में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना बैंक के लिए आवश्यक है।

इन प्रारम्भिक (preliminary) कार्यों की पूर्ति के बाद बैंक दो कार्डों पर ग्राहक के नमूना हस्ताक्षर लेता है। ये कार्ड पत्र-सूचक मजूपा (card index cabinet) में अक्षर-क्रम (alphabetical order) में रचे जाते हैं, जिससे बैंक आदि पर किये गये ग्राहक के हस्ताक्षरों को इन हस्ताक्षरों से मिलाया जाता है। अतः बैंक पर किये हुए हस्ताक्षर इन हस्ताक्षरों से मिला देने चाहिए अन्यथा बैंक का आदरण नहीं होगा। यदि ग्राहक किसी अन्य व्यक्ति को बैंक आदि लिखने का अधिकार देता है तो उसके नमूने के हस्ताक्षर तथा उसके नाम का अधिकार-पत्र बैंक अपने पास रखेगा।

चल-लेखों में प्रथम बार राशि जमा करने पर बैंक अपने ग्राहक का तीन पुस्तिकाएँ देता है—(१) निक्षेप-पर्ची पुस्तिका (pass-in-slip book), (२) बैंक पुस्तिका (cheque book), तथा (३) ग्राहक पुस्तिका (pass book)।

निक्षेप पर्ची पुस्तिका—इसमें राशि जमा कराने की बहुत सी पर्चियाँ (विशेषतः २५) रहती हैं। कभी-कभी बैंक इन पर्चियों को पुस्तिका में न रखते हुए शिथिल रखते हैं। बैंक में राशि जमा करते समय इन पर्ची को भर कर राशि भेजी जाती है। पर्ची का उदाहरण —

श्री पञ्चाव नेशनल बँक लिमिटेड कानपुर । तिथि		साता क्रमाङ्क श्री पञ्चाव नेशनल बँक लिमिटेड कानपुर १९६६	
निष्पत्ति	खाता न०	राशि विवरण	
	र० न प		र० न प
पञ मुद्रा स्वण मुद्रा रजत मुद्रा मिक्क (अ य) चैक बिल आदि		पञ मुद्रा स्वण मुद्रा रजत मुद्रा मिक्क (अ य) चैक बिल आदि	श्री क बल-लख म समा कलित काजिए राशि
याग		याग	निक्षेपक
खजाची	नेपाल	खजाची	रम्पता
अभिकर्ता		अभिकर्ता	

यह पर्ची दा भाग में होना है जिसमें से बाय भाग को प्रतिपर्ची (counterfoil) तथा दाहिने भाग को प्रमुख पर्ची कहते हैं। इस पर्ची में जमा करने के लिए कब कितनी राशि भेजी गई है उसका विवरण दिया जाना है तथा दाहिने भाग पर निक्षेप (depositor) एवं अभिकर्ता दोनों के हस्ताक्षर हात हैं। यह पर्ची राशि के साथ भेजी जाती है। इस बँक का खजाची पूरा मिलान करने के बाद राशि जमा कर लेता है तथा प्रमुख पर्ची अपने पास रखकर प्रतिपर्ची पर हस्ताक्षर करके बँक की मोहर लगा देता है। प्रतिपर्ची पर बिनापत केवल खजाची हस्ताक्षर करता है जो प्राप्ति का पदार्थ प्रमाण होता है।

**ग्राहक पुस्तिका ( Pass Book )**—ग्राहक का लखा बँक की साताबही में जिस प्रकार से रखा जाता है उसी का नक्कल ग्राहक पुस्तिका में होता है। ग्राहक अपने बैंक में समय समय पर जो राशि जमा करता है एवं निकालता है ग्राहक का नाम ब्याज आदि मिलता है जैसा वा बमीगन गृह आदि बँक ग्राहक में होता है उसका जानकारी तिथिक्रम से ग्राहक पुस्तिका में लिखा जाता है। जो राशि ग्राहक जमा करता है वह ग्राहक पुस्तिका के बाय भाग में तथा जो राशि वह निकालता है दाहिने भाग में लिखा जाता है। यह पुस्तिका बँक

द्वारा लिखी जाती है। अतः इसमें प्रत्येक व्यवहार के लेख का उत्तरदायित्व बैंक का रहता है। फिर भी ग्राहक को इस पुस्तिका के लेख ठीक है या नहीं, यह देखना चाहिए। इस पुस्तिका को बैंक से प्राप्त करने के उपरान्त यदि वह उसे रख लेता है तो इससे यह तात्पर्य है कि उसमें की गई प्रत्येक प्रविष्टि उसने सही मान ली है।

इस पुस्तिका को ग्राहक समय-समय पर विनियमित महीने में एक बार बैंक में भेजता है जिससे लेख अद्यावधि रह सकें। इस पुस्तिका में वह अपनी खाता-बही के "बैंक लेखों" को मिलाता है। परन्तु फिर भी ग्राहक के बैंक लेखों का शेष ग्राहक-पुस्तिका से मिलेगा ही, यह बात नहीं है। क्योंकि ऐसी कई बातें होती हैं जो इन दोनों पुस्तकों के शेषों में अन्तर डालती हैं —

(१) मग्नहण के लिए भेजे गये बैंकों की राशि से ग्राहक अपनी बही में बैंक लेखा डेबिट करता है। परन्तु ग्राहक-पुस्तिका में इसको तब तक नहीं लिखा जाता जब तक बैंक की राशि बैंक प्राप्त न कर सके।

(२) बैंक ग्राहक में जो शुल्क, कमीशन आदि लेता है उसे वह केवल ग्राहक पुस्तिका में लिखता है। इसकी जानकारी ग्राहक को केवल इस पुस्तिका में ही होती है क्योंकि इसकी सूचना बैंक ग्राहक को नहीं देता और न देने की आवश्यकता होती है।

(३) कटौती किये गये विला के अनादरण का उल्लेख केवल ग्राहक पुस्तिका में ही होता है किन्तु ग्राहक के बैंक लेखों में नहीं होता।

(४) ग्राहक द्वारा लिखे गये बैंकों का लेख ग्राहक-पुस्तिका में तब तक नहीं होता जब तक उनका भुगतान न हो जाय। किन्तु ग्राहक बैंक काटते ही अपनी खाता बही में बैंक लेखा क्रेडिट कर देता है।

(५) निक्षेप पर व्याज का लेख केवल ग्राहक-पुस्तिका में ही होता है और ग्राहक को उसकी जानकारी नहीं होती।

अतः जब ग्राहक अपनी बही के बैंक लेखों का मिलान ग्राहक-पुस्तिका में करता है, उस समय दोनों के शेषों में अन्तर होने पर उसे बैंक समाधान विवरण (reconciliation statement) बनाना पड़ता है जिससे ग्राहक-पुस्तिका के शेष का मिलान खाता बही के बैंक लेखों से हो सके।

अतः ग्राहक एवं बैंक दोनों की दृष्टि से ग्राहक-पुस्तिका महत्वपूर्ण होती है। इस पुस्तिका में सब लेख बैंक द्वारा होता है, इसलिए यदि इन लेखों की गलती पर ग्राहक किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करता तो यह प्रमाण है कि इस

पुस्तिका के सब लेख ग्राहक का मान्य है। इसलिए इस पुस्तिका के लेख अत्यन्त सावधानीपूर्वक एवं ठीक ठीक करना चाहिए। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि बैंक ने ग्राहक पुस्तिका में १००) रुपया क्रेडिट न करत हुए भूल से १५०) रुपया क्रेडिट किया है एवं ग्राहक का क्रेडिट अर्प १००) से न वगन हुए १५०) रुपय से वगन दिया। यदि ग्राहक इसका ठीक समझ कर अपने लेख पर उस रकम का बैंक लिखता है तो वह उस अन्यायपूर्ण नहीं कर सकता अर्थात् अन्यायपूर्ण करने पर वह ग्राहक की हानि-पूर्ति का उत्तरदायी होगा। इसलिए ऐसी भूल जब किसी भी बैंक जान न उसकी सूचना तुरन्त ही ग्राहक को देनी चाहिए तथा उसका समाधान करना चाहिए। एवं जब तक ग्राहक की अनुमति प्राप्त न हो तब तक उसको ग्राहक के सभी बैंक का आदरण करना चाहिए। ग्राहक भी अपना ग्राहक-पुस्तिका रखने के लिए उत्तरदायी है क्योंकि यदि किसी प्रकार का ऐसा गमती ग्राहक-पुस्तिका में होती है जो ग्राहक का मासूम हो सकती है अथवा उस मासूम को परन्तु फिर भी ग्राहक ने उस ठीक नहीं करवाया तो बैंक की जो हानि होगी उसकी पूर्ति करने के लिए ग्राहक जिम्मेदार होगा। फिर भी भूल से किसी राशि का लफ्फा यदि ग्राहक-पुस्तिका में नहीं हुआ और उसका जानकारी ग्राहक किसी कारणवश न कर सका तो ऐसी राशि किसी भी दशा में बैंक अपने पास ग्राहक की उपाधि के बहाल नहीं रख सकता। (ग्राहक-पुस्तिका का नमूना पृष्ठ ४३४ पर।)

**बैंक पुस्तिका (Cheque Book)**—बैंक पुस्तिका में १० २५ ५० अथवा १०० बैंक रखे हैं। लम्बा खालन के बाद यह पुस्तिका ग्राहक को दी जाती है जिसमें वह अपनी राशि इन बैंकों से निकालेगा। यह पुस्तिका बैंक बिना किसी शुल्क के देता है तथा एक पुस्तिका समाप्त होने पर हमारा देना है। बैंक भी निश्चय पत्रों का तरह दो भागों में होता है जिसमें से बाय भाग का प्रतिपत्र कहते हैं। यह प्रतिपत्र ग्राहक अपने पास सदैव के लिए रखता है तथा दाहिना भाग बैंक को देना है जिस प्रमुख बैंक कहते हैं। यह बैंक पूर्ण रूप से एक ठीक पद्धति पर भरोसा में हो बैंक द्वारा आदरित किया जाता है अथवा नहीं।

बैंक द्वारा दिए गए फार्मों पर ही बैंक लिखे जाने चाहिए अन्यथा उनका अन्यायपूर्ण हो जाता है। यह सब बैंक ग्राहक पर चलने के लिए बैंक आवेदन-पत्र में गत रहते हैं जो ग्राहक और बैंक के बीच अनुबंध होता है। इन मुद्रित चेकों में बैंक एवं ग्राहक दोनों का ही लाभ होता है।

## ग्राहक-पुस्तिका

नाम . श्री पिण्डीलाल मटक्यल, कचडे के ध्यापारी,  
पता जनरलज, कानपुर ।

हिन्दुस्तान कर्मशायन बैंक, मेस्टन रोड लाखा के साथ  
चल-लेखा

तिथि ( Date )	विवरण ( Particulars )	राशि विवरण		हस्ताक्षर	राशि समावन्त		विव० अथवा समा०	शेष	
		रुपया	आ पा		रुपया	आ पा		रुपया	आ पा
१ जनवरी ५१	शेष	५,०००	—	अ व क	—	—	डे०	५,०००	—
१ जनवरी ५१	रोकट	—	—	अ व क	१,००००	—	क्रे०	५,०००	—
२ जनवरी ५१	चैक लिखे	३,०००	—	अ व क	—	—	क्रे०	२,०००	—
शेष जनि ले जाया गया							क०	२,०००	—

(१) कोई भी व्यक्ति जो ग्राहक के जारी हस्ताक्षर कर सकता है, उस कपट करना अममभव हो जाना है क्योंकि वह ग्राहक का बैंक पत्र प्राप्त नहीं कर सकता। ग्राहक स्वयं भी कपट से बचने के लिए बैंक पुस्तिका की सुरक्षा रखता है।

(२) बैंक विरोध प्रकार के कागज पर छप हुए हान से इन पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन मरलता से मान्य हो जाता है।

(३) प्रत्येक ग्राहक की बैंक पुस्तिका पर विशेष अंक होता है जिससे बैंक उस अंक से दस्तावेज में ग्राहक का नाम अथवा अन्य आवश्यक सन्दर्भ शीघ्र प्राप्त कर सकता है।

(४) ग्राहक का वधानिक रूप एक निश्चयी बैंक लिखन का कपट नहीं होता।

(५) प्रत्येक बैंक पर क्रमांक (serial number) हान से ग्राहक का व्यक्तता पत्र पर अथवा किसी प्रकार के कपट का ज्ञान हान पर बैंक का बैंक क्रमांक देकर उसका भुगतान राक सकता है। इस बैंक की राशि अन्य गलत व्यक्तियों के हाथ में नहीं जा सकती। इसलिए यह पुस्तक विशेष महत्व की है जो ग्राहक को बहुत सावधानी में रखनी चाहिए।

२. बचत लेखा—यह विनियमन कम आय वाले व्यक्तियों के लिए अधिक उपयोगी होता है। इस प्रकार की सुविधा देने से जनता में बचत का आदत निर्माण की जाता है। इसमें मासिक न्यूनतम राशि पर व्याज देते हैं जो आजकल १२% से २२% वार्षिक है। इस प्रकार के लेख में आहरण (withdrawal) पत्र भरने पर राशि निकाली जा सकती है। इस प्रकार की राशि सप्ताह में कबन एक बार अथवा दो बार निकाली जा सकती है तथा सप्ताह में निश्चित राशि में अधिक राशि नहीं निकाला जा सकती। यदि राशि अधिक निकालनी हो तो बैंक का नियमानुसार सूचना देनी पड़ती है। इस प्रकार के खाते में प्रति वर्ष १०,००० से अधिक राशि नहीं जमा की जा सकती परन्तु इस सम्बन्ध में प्रत्येक बैंक के नियम अलग-अलग होते हैं।

किसी व्यक्ति का यह लेखा खोलने के पूर्व प्रायः पत्र भरना पड़ता है जिसमें ग्राहक अपना नाम व्यवसाय पता आदि लिखता है तथा कितनी राशि वह प्रथम बार निक्षेप में रखना चाहता है यह भी प्रत्येक प्रकार के लेखा खोलने के पूर्व ग्राहक का आवेदन भरना पड़ता है। इसकी स्वीकृति एवं प्रथम निक्षेप राशि जमा करने पर ग्राहक को ग्राहक-पुस्तिका दी जाती है। स्थायी निवासन समय ग्राहक का अपना हस्ताक्षर सहित आहरण-पत्र बैंक का ग्राहक-

पुस्तिका के साथ देना पड़ता है जिससे वह राशि, निश्चित शर्तों के अनुसार, उसे प्राप्त हो जाती है। इस आहरण-पत्र के हस्ताक्षर नमूना-हस्ताक्षर में मिलने चाहिए अन्यथा रपया नहीं मिल सकता। आहरण की राशि लिखने के बाद यह पुस्तिका ग्राहक को वापिस दी जाती है।

ग्राहक-पुस्तिका में ग्राहक की जमा राशि, निकाली हुई राशि तथा शेष प्रमानुसार दी जाती है।

अनेक बैंक वचन लेखों पर बैंक लिखने की सुविधा देते हैं, परन्तु बैंकों द्वारा उपर्युक्त शर्तों के अनुसार ही राशि निकाली जाती है। परन्तु यह सुविधा सभी दी जाती है जब न्यूनतम जमा-राशि १०० से २५० रु तक हो। इस प्रकार के लेख पर अधिविक्रय (overdraft) की सुविधा नहीं दी जाती किन्तु बैंक ग्राहक के बैंक आदि के समग्रण एवं सुरक्षा के लिए वस्तुएँ स्वीकार करने की सुविधा देते हैं। यदि यह लेखा किसी कारणवश ६ महीने के पूर्व बन्द किया जाय तो बैंक ग्राहक से ग्राहक-पुस्तिका का मूल्य लेते हैं, अन्यथा यह पुस्तिका निशुल्क दी जाती है। इसी प्रकार यदि ६ वर्षों में किसी भी प्रकार का व्यवहार इस लेख पर न किया जाय तो लेखा बन्द समझा जाता है।

३ स्थायी (Fixed Deposit) निक्षेप लेखा—जो व्यक्ति किसी निश्चित अवधि के लिए अपनी राशि जमा कराना चाहते हैं वे इस लेख में करते हैं। इस लेख पर व्याज की दर अधिक होती है। यह राशि जिस अवधि के लिए जमा की जाती है, उस अवधि के अन्त में ही निकाली जा सकती है। परन्तु यदि ग्राहक समय के पूर्व इसकी राशि निकालना चाहता है तो उसे बैंक के नियमानुसार सूचना देना आवश्यक है। इस लेख पर व्याज की दर ३ से ६ प्रतिशत प्रति वर्ष तक दी जाती है। भिन्न-भिन्न बैंक भिन्न-भिन्न दरों से व्याज देते हैं, विशेषतः अच्छी ख्याति के बैंक कम व्याज देते हैं। साधारणतः स्थायी निक्षेप ६ महीने से ३ वर्ष की अवधि तक के होते हैं।

इस प्रकार के निक्षेपों से बैंक की कार्यशील पूँजी बढ़ती है क्योंकि वे निक्षेप कम निकाले जायेंगे, इसका पूर्ण ज्ञान बैंक को होता है। आवेदन-पत्र स्वीकृत हो जाने पर निक्षिप्त राशि के लिए बैंक 'निक्षेप-रसीद' देते हैं। इसका हस्तान्तरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं हो सकता। इस रसीद में राशि जमा करने की तिथि, निक्षेप-कर्ता का नाम, राशि, अवधि एवं व्याज की दर रहती है।

इन निक्षेपों की निकालने के पूर्व ग्राहक को निक्षेप-रसीद लौटानी पड़ती

है। किन्तु जब तक ऐसी लिखित शर्त न हो तब तक वापिस करने की आवश्यकता नहीं है। निक्षेप की अवधि समाप्त होने पर यदि ग्राहक पुनः किसी अवधि के लिए राशि रखना चाहता है तो वह निक्षेप-रसीद का नवकरण (renewal) कराकर स्थायी निक्षेप में राशि जमा कर सकता है।

## निक्षेप-रसीद का नमूना

### अन-हस्तान्तरणीय

श्री० कृष्णराम बलदेव बैंक लिमिटेड, प्वालियर।

नमांक ५३६

श्री० रामचन्द्र श्रीवास्तव से ५००० रु० उनके लेखे में २ वर्ष निक्षेप के लिए, १ जनवरी १९५१ से ३१ दिसम्बर १९५२ तक के लिए, प्राप्त हुए। यह राशि १ जनवरी १९५३ को देय है। इस पर ३% प्रति वर्ष की दर से व्याज दिया जायगा।

केवल ५०००) रुपये

कृष्णराम बलदेव बैंक के लिए,

अमृतलाल दुवे

जाल एन वरोचा

लेखापाल

अध्यक्षपाक

जब व्यापारियों के पास निष्क्रिय पूँजी होती है तब वे उसे स्थायी निक्षेप लेखे में जमा करते हैं जिससे उनको निश्चित लाभ मिलता रहे। अन्य व्यक्ति भी इसमें राशि जमा करते हैं जिनके पास अतिरिक्त धन होता है।

४ डाकघर संचय निक्षेप लेखा (P O. Saving Deposit A/c) खोलने की विधि भी लगभग ऐसी ही है। जो व्यक्ति लेखा खोलना चाहता है उसे आवेदन-पत्र अपने नमूने के हस्ताक्षर के माध्य देना पड़ता है जिसकी स्वीकृति एवं राशि जमा करने के बाद उसे ग्राहक-पुस्तिका मिल जाती है। रुपया निबालते समय उसे डाकघर में प्राप्त होने वाला आहरण-पत्र भरना पड़ता है तथा अपने हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर के समान कर, यह पत्र ग्राहक-पुस्तिका के माध्य देने से उसको राशि प्राप्त होती है एवं ग्राहक-पुस्तिका में लिखी जाती है। इन लेखों में केवल प्रति सप्ताह दो बार राशि निकाली जा सकती है तथा मरताह में अधिकतम राशि निबालन की मर्यादा नियत होती है। इसमें अधिक राशि की आवश्यकता पड़ने पर ग्राहक को पर्याप्त गूचना देनी पड़ती है। इन पर

चैंक निम्नने की सुविधा नहीं मिलती, परन्तु प्रयोग के लिए बड़े शहरों में हान ही में चैंक पद्धति का आरम्भ किया गया है।

चैंक ग्राहक की पूर्ण जानकारी एवं सम्बन्ध प्राप्त कर देने के बाद ही चला लेना सौलता है। विविध ग्राहकों के सम्बन्ध में वह विविध मावधानी लेता है जैसे निवाहिता स्त्री सम्पत्ती, माभेदारी आदि।

### सारांश

चैंक जनता आदि से तीन प्रकार के निक्षेप स्वीकार करती हैं—१ चत निक्षेप, २ वचन-निक्षेप तथा ३ व्यापी-निक्षेप।

चत निक्षेप से चैंक के व्यापारिक समय में राशि जमा करने एवं निकालने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इन लेखों पर प्रथम भेली के बँक व्याज नहीं देते और यदि देते हैं तो बहुत कम देते हैं। परन्तु यदि निश्चित राशि से कम राशि खाने में हो जाय तो उस पर चैंक सयोगिक व्यय लेते हैं। इस लेख के सम्बन्ध में चैंक की सबसे अधिक, विम्वेवारी होती है क्योंकि ग्राहक कितनी भी राशि चैंक से निकाल सकता है। चल-लेखा खोलने के लिए चैंक को प्रार्थनापत्र देना पड़ता है जिससे अपना व्यापार एवं खेले का प्रकार देना पड़ता है। इसके साथ ही चैंक ग्राहक से कुछ विश्वासनीय व्यक्तियों के सदर्भ भी लेता है जिनसे पुष्टता करने पर, यदि वह व्यक्ति ग्राहक बनाने योग्य हो, तो वह उसका लेखा खोलता है। ऐसी स्थिति में लेखा खोलने के पूर्व वह अपने ग्राहक के समूहा-हस्ताक्षर लेता है तथा उसे तीन पुस्तकें देता है—पास बुक, चैंक बुक तथा निक्षेप पर्ची। निक्षेप पर्ची भरकर राशि जमा की जाती है चैंक से राशि निकाली जाती है तथा ग्राहक पुरितका में ग्राहक का चैंक में जो लेखा है उसकी प्रतिलिपि ग्राहक को दी जाती है। पास बुक को चैंक ने अत्यन्त सावधानी से लिखना चाहिए अन्यथा उसकी गलती से ग्राहक द्वारा अधिक राशि के चैंक काटे जाने की दशा में वह स्वयं उत्तरदायी होगा। क्योंकि वह ग्राहक के नियमों चैंको का अनुसरण नहीं कर सकता।

वचन निक्षेप लेखा—छोटी आय वाले व्यक्तियों के लिए यह अधिक उपयोगी है। इस पर व्याज अधिक मिलता है तथा राशि निकालने के सम्बन्ध में चैंक की शर्तों का पालन करना होता है, साधारणतः सप्ताह में १ या २ बार राशि निकालने की सुविधा रहती है। कुछ चैंक इन लेखों पर चैंक काटने की तथा चैंक आदि के संग्रहण की सुविधा भी देते हैं जिस दशा में उनको चल लेख की भाँति

ग्राहक से सन्दर्भ लेना आवश्यक होता है। अन्यथा आवेदन-पत्र, नमूने के हस्ताक्षर तथा प्रथम जमा राशि देने के साथ किसी व्यक्ति का लेखा बैंक में खोला जा सकता है। ग्राहक द्वारा बैंक अथवा आदरण-पत्र से राशि निकालते समय बैंक उसके हस्ताक्षरों का मिलान नमूना हस्ताक्षरों से कर लेता है। इसमें भी बैंक से पास-युक्त मिलती है।

स्थायी निक्षेप लेखा—साधारणतः ६ मास से अधिक अवधि के लिए खोला जाता है। इस पर ब्याज की दर अवधि एवं राशि के अनुसार बढ़ती है जो साधारणतः ३ से ६% होती है। इस प्रकार राशि जमा करते समय ग्राहक को आवेदन देना पड़ता है तथा स्वीकृति होने पर उसे राशि जमा करने के बाद स्थायी निक्षेप रसीद मिलती है। अवधि समाप्त होने पर इस रसीद को लौटा कर वह राशि प्राप्त कर सकता है। अवधि के पूर्व राशि की आवश्यकता होने पर नियमानुसार सूचना देकर राशि वापिस ली जा सकती है, जिस दशा में बैंक या तो ब्याज नहीं देते या कम ब्याज देते हैं।

ड्राफ्ट पर बचत लेखा खोलने में भी इसी प्रकार की कार्यवाही करनी पड़ती है, परन्तु ड्राफ्ट पर बचत लेखों पर बैंक की सुविधाएँ केवल कुछ बड़े केन्द्रों के अलावा अन्यत्र नहीं हैं।

विशेष ग्राहकों के सम्बन्ध में बैंक को लेखा खोलते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है।

## भुगतानकर्ता एवं संग्राहक बैंक

### १ भुगतानकर्ता बैंक

बैंक में ग्राहक का चल रेखा होने पर उसे अपने ग्राहक के सभी नियमित बैंक उसके खाने में पर्याप्त राशि होने पर, भुगतान करना पड़ते हैं। यह बैंक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। वंचानसाध्य विलेख अधिनियम के अनुसार "भुगतानकर्ता बैंक के पास बैंक लिखने वाले की पर्याप्त राशि यदि ऐसे बैंकों के भुगतान के लिए है तो ऐसा आदेश प्राप्त होने ही बैंक को उसका भुगतान करना चाहिए। अन्यथा भुगतान न करने पर लिखने वाले को जो हानि अपना धनि हो उसकी पूर्ति उसे करनी पड़ेगी।" (पारा ३१)। इसके अनुसार बैंक को निम्न बातों के अनुसार ग्राहक के बैंकों का भुगतान करना पड़ेगा —

(१) ग्राहक या बैंक में खाता होना चाहिए जिस पर उसे बैंक लिखने का अधिकार हो।

(२) उसने खाते में बैंक के भुगतान के लिए पर्याप्त धन होना चाहिए। यदि बैंक ने उसे अधिविकर्ष (overdraft) दिया हो तो अधिविकर्ष की राशि का भी सम्बन्ध होगा।

(३) बैंक समुचित एवं नियमित रूप में होना चाहिए।

(४) बैंक के कार्यालय में भुगतान की निश्चित अवधि में तथा समुचित रीति से बैंक उपस्थित होना चाहिए।

(५) बैंक में कोई अवैधानिकता न हो।

यदि उक्त बातों में कोई भी दोष होता है तो बैंक उस पर का भुगतान नहीं करेगा। इसी प्रकार बैंक के भुगतान के सम्बन्ध में जो बातें रेखाचन, वंचान आदि के सम्बन्ध में देखी उनका भी बैंक को पालन करना पड़ता है।

ग्राहक उसके पास आये हुए बैंक अपने बैंक का संग्रहण के लिए भजना है तथा उनकी राशि पर बैंक लिखता है। ऐसे बैंक लिखने के पूर्व ग्राहक को चाहिए कि वह उन बैंकों के संग्रहण के लिए बैंक को पर्याप्त समय दे अन्यथा उसके बैंक का अनादरण करने पर उसकी जिम्मेदारी बैंक पर नहीं होगी।

समग्रण के लिए आये हुए मासपत्रों की राशि बैंकर ग्राहक के खाते में तब तक जमा (credit) नहीं करना जब तक उनकी राशि बैंकर को न मिले। यदि बैंकर ऐसे मासपत्रों की राशि प्राप्त करने के पूर्व ही ग्राहक के खाते में जमा कर देता है और ग्राहक उस राशि को निकाल लेता है, फिर यदि बैंकर को उनमें से किसी मासपत्र का भुगतान नहीं मिलता तो वह हानि उसे भुगतनी पड़ेगी। ग्राहक के विरुद्ध वह कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं कर सकेगा।

• अब ग्राहक को उक्त बातों का पूर्ण रूप से ध्यान करना चाहिए। साधारण बैंक को भुगतान करने समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए —

१. बैंक खुला है अथवा रेखांकित है, तथा रेखांकन सामान्य अथवा विशेष है क्योंकि रेखांकन के भी भिन्न-भिन्न अर्थ होने हैं। रेखांकन के अनुसार बैंक यदि बैंक का भुगतान नहीं करता तो वह स्वयं उस बैंक की राशि के लिए उत्तरदायी होगा।<sup>१</sup>

२ जहाँ बैंक उपस्थित किया गया है उसी शाखा पर वह लिखा गया है अथवा नहीं?—सामान्यतः कोई भी ग्राहक बैंक की जिस शाखा में लेखा है उस शाखा के सिवा अन्य शाखा पर बैंक नहीं लिख सकता। किन्तु यदि ऐसा विशेष अधिकार ग्राहक को हो तो बैंक को उन बैंकों का भुगतान करते समय ऐसे अधिकार का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इस दशा में उसका अधिकार एक उत्तरदायित्व नहीं रहता है जैसा कि ग्राहक के लेने वाली शाखा पर बैंक लिखा गया है।

३ विकृत, बीतकालीय, पूर्वतिथीय (ante dated) अथवा उत्तरतिथीय बैंक—इस सम्बन्ध में हम पर्याप्त विवेचन कर चुके हैं। बीतकालीय बैंक का भुगतान बैंक ग्राहक की अनुमति प्राप्त करने पर ही कर सकता है अन्यथा उसे 'बीतकालीय' लिखकर लौटा देना चाहिए।

उत्तरतिथीय बैंक का भुगतान बैंक की बैंक की तिथि के पहले नहीं करना चाहिए। यदि वह बैंक की तिथि के पहले उसका भुगतान करता है और ग्राहक दिवालिया हो जाता है तो बैंक ग्राहक से वह राशि वसूल नहीं कर सकता।

४ बैंक का नियमो (सही) रूप में होना—बैंक का जो स्वरूप हम बता चुके हैं उसी रूप में वह लिखा हुआ है यह देख लेना चाहिए। उसका भुगतान नहीं करना चाहिए।

<sup>१</sup> बैंकानामा-य विनियम अधिनियम, धारा १२६, १२७ और १२८।

५ ग्राहक के हस्ताक्षर—चैक लिखने वाले के हस्ताक्षर जाली नहीं हैं, यह भी पूर्ण मावधानी से नमूने के हस्ताक्षर के आधार पर देख लेना चाहिए।

क्योंकि जाती चैकों का भुगतान होना पर उनकी राशि में बैंक ग्राहक का लेखा डेबिट नहीं कर सकता, जब तक वह यह सिद्ध न कर दे कि जाली चैक के लिए ग्राहक ही जिम्मेदार है अथवा ग्राहक की अमावधानी से जाली चैक लिखा गया है।

६ राशि में अन्तर—किसी भी प्रकार से चैक के अमो तथा धारों में किसी हुई राशि में अन्तर नहीं होना चाहिए। यदि इनमें अन्तर है तो बैंक ऐसे चैक को “राशि भेद” लिखकर लौटा देते हैं।

७ चैक में किसी प्रकार में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं है, और यदि ऐसे परिवर्तन है तो उनके लिए लिखने वाले के पूर्ण हस्ताक्षर किये गये हैं। यदि ऐसे परिवर्तन के लिए ग्राहक के हस्ताक्षर नहीं हैं तो बैंक ऐसे चैको का भुगतान नहीं करेगा तथा उन्हें “महत्वपूर्ण परिवर्तन अनहस्ताक्षरित” लिखकर लौटा देगा।

८. सही वेचान—चैक पर वेचान नियमित रूप में है यह भी देख लेना होगा। ग्राहक चैको पर विशेष वेचान होते हुए भी उनका भुगतान बाहक चैको की तरह ही किया जायगा। वेचानसाध्य विनियम अधिनियम (धारा ८५ (२)) के अनुसार “यदि एक चैक मुक्त बाहक को देय है, तो उसका यथाविधि भुगतान करने पर देने वाला उन्मुक्त (discharge) हो जाता है। इसका किसी भी प्रकार से ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं कि उस पर वेचान सामान्य है अथवा विशेष तथा वेचान का तात्पर्य आगे वेचान रोकने का है अथवा सीमित करने का।”<sup>१</sup> आदेश चैको पर वेचान ठीक एक नियमित रीति से होना चाहिए, अन्यथा बैंक ऐसे चैक “अनियमित वेचान” लिखकर लौटा देते हैं।

यथाविधि भुगतान<sup>२</sup>—‘यथाविधि भुगतान वह भुगतान है जो पूर्ण विश्वास के साथ बिना किसी उपक्षा के विलख के स्पष्ट स्वरूप (Tenor) के अनुसार जिसके पास वह विलख है ऐसे किसी भी व्यक्ति को ऐसी स्थिति में किया गया हो जिसमें यह विश्वास करने के लिए कोई भी आधारभूत कारण न हो कि उसकी (विलख की) राशि का भुगतान प्राप्त करने का वह अधिकारी नहीं है।’ इस परिभाषा के अनुसार—

१ उस विलख पर पक्षकारों के गुप्तानों के अनुसार भुगतान हो।

<sup>१</sup> Sec 85 (2), Negotiable Instruments Act, 1881.

<sup>२</sup> Sec 10, Negotiable Instruments Act, 1881

२ यह भुगतान पूर्ण विद्वाम सहित एवं बिना किसी प्रकार की उपक्षा के हो।

३ भुगतान उम व्यक्ति को हो जिमक पास विलख है।

४ यह विद्वाम करने के लिए कोई आधारभूत कारण न हो कि उम व्यक्ति का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।

यदि उक्त बात विलख में है तो बैंक द्वारा किया गया भुगतान यथाविधि भुगतान होगा। इस परिभाषा के अनुसार किसी भी बिना रेखित बैंक का भुगतान किसी बैंक के द्वारा न दन हुए काउन्टी (counter) पर देना यथाविधि भुगतान नहीं होगा। इसी प्रकार उत्तरनिधीय बैंक का भुगतान निधि के पूरा करना अथवा बीनकारीय बैंक (stale cheque) का भुगतान ग्राहक की सम्मति बिना करना यथाविधि भुगतान नहीं होगा।

बैंकों को लौटाते समय—बैंक भुगतान न करने का कारण देने है। ऐसे कारण प्रत्येक बैंक पर अलग-अलग निम्न के स्थान पर व सब कारणा की एक मुद्रित पर्ची रखते हैं। जिम कारण में बैंक लौटाया जाता है उस कारण के अंक पर यह चिह्न (✓) लगा दते हैं। इस हेतु निम्न शब्दों का प्रयोग होता है।

- १ R D (Refer to drawer) लखीवाले में पूछिए—
- २ E N C (Effects not cleared) मग्राहण नहीं हुआ।
- ३ N S F (Not Sufficient Fund) अस्वाप्त राशि।
- ४ W & F D (Words & Figures differ) राशि में अन्तर।
- ५ E I (Endorsements Irregular) अनियमित वचान।
- ६ D D (Drawer Deceased) मृत लखीवाला।
- ७ N A (No Account) लेखा नहीं है।
- ८ Post-dated or Stale Cheque उत्तरनिधीय या बीनकारीय बैंक।
- ९ Drawer's Signatures Differ लखीवाने के हस्ताक्षर में अन्तर।
- १० Endorsement requires confirmation वचान का प्रमाण आवश्यक।
- ११ Material alteration not confirmed महत्वपूर्ण परिवर्तन अनिष्ठाकरित।

अभी तक अंग्रेजी का प्रयोग ही बैंक-व्यवहारा में होने का कारण अंग्रेजी शब्द प्रयोग ही दिया गया है तथा उनका हिन्दीवरण भी दिया गया है।

बैंक की जिम्मेदारी—बैंक का भुगतान करने समय बैंक को उन बातों की बिना सावधानी रखनी पड़ती है अथवा गलत भुगतान का दायित्व उम पर आता है। मग मगन भुगतान किये हुए बैंक की राशि में वह ग्राहक का

लेखा रेबिट नहीं कर सकता । किन्तु यदि ग्राहक की अभावधानी के कारण बैंक का वह यथाविधि भुगतान कर देता है तो उसकी जिम्मेदारी ग्राहक की होगी । इसी प्रकार जानी बैंक बैंक को भुगतान के लिए उपस्थित हो रहा हो तथा इसका ज्ञान ग्राहक को हो तो उसे बैंक को सूचना देनी चाहिए अन्यथा ग्राहक का दायित्व रहेगा । यही बात महत्वपूर्ण परिवर्तनों की है । इसलिए बैंक को बैंक का भुगतान करने समय पूर्ण सावधानी में काम लेना पड़ता है क्योंकि वह लेखी बैंकी में फैसला है जिसमें एक ओर अभावधानी से अन्याय करने पर वह ग्राहक की हानि-पूर्ति के लिए तथा दूसरी ओर दोषपूर्ण बैंकों का भुगतान होने पर स्वयं जिम्मेदार होता है ।

बैंक ग्राहक के बैंकों का भुगतान कब रोक सकता है ?—बैंक ग्राहक के बैंक का भुगतान बिना किसी दायित्व के निम्न परिस्थितियों में रोक सकता है —

(अ) भुगतान रोकने के लिए ग्राहक का आदेश हो ।

(ब) आहर्ता की मृत्यु, दिवालियापन एवं पागलपन—इन बातों की सूचना पाते ही बैंक का ग्राहक के किसी भी बैंक का भुगतान रोकने का अधिकार है । किन्तु ग्राहक की मृत्यु की सूचना यदि बैंक को न मिली हो तो ग्राहक द्वारा मृत्यु के पूर्व लिखे गये बैंक का भुगतान वह कर सकता है तथा उस राशि को वह ग्राहक के लेखे मंडविट कर सकता है । इसी प्रकार ग्राहक के पागल होने के पूर्व लिखे हुए बैंक का भुगतान भी वह सूचना पाने के पूर्व कर सकता है ।

(स) ग्यापालपोन आदेश (Garnishee's Order)—यदि किसी ग्राहक के मित्र उमके लेखे का वन्द करने का न्यायालय से आदेश प्राप्त होता है तो उस दिन से बैंक का उमके बैंकों का भुगतान रोक देना चाहिए ।

(द) यदि बैंक को यह ज्ञान हो कि बैंक उपस्थित करने वाला व्यक्ति उसका स्वत्वधारी स्वामी नहीं है तो बैंक का भुगतान रोक देना चाहिए ।

(य) यदि ग्राहक खपन लेखे की किसी अन्य व्यक्ति के नाम हस्ताक्षरित करता है एवं उसका ज्ञान बैंक को हो जाना है अथवा सूचना आ जाती है ।

(ज) ग्राहक किसी मत्स्या का प्रत्यासी होने के बाद, प्रत्याम लेखे का निजी कार्यों के लिए उपयोग कर रहा है तो बैंक उमके बैंकों का भुगतान रोक सकता है ।

## २ सग्राहक बैंक

ग्राहक द्वारा उमके नाम आये हुए बैंकों के सग्रहण की वैधानिक जिम्मेदारी बैंक की न होने हुए भी ग्राहक के बैंक विस आदि का सग्रहण बैंक करता है ।

यह कार्य वह ग्राहक के अभिवृत्ता के नाते करता है। सग्राहक चक्र के नाते उसका कुछ विशेष जिम्मेदारी होती है।

(१) वह जब ग्राहक के नाम के रखावृत्त चक्र का सग्रहण करता है तथा बाद में यह ज्ञात होता है कि उस चक्र पर जाली बचान है तो वह उस चक्र के स्वत्वधारी स्वामी के प्रति उत्तरदायी होता है। क्योंकि वह चक्र का स्वत्वधारा स्वामी नहीं होता। किन्तु ऐसे चक्र का रूपया वह अपने ग्राहक से प्राप्त करने का अधिकारी होता है क्योंकि वह केवल अन्तिम बचानकर्ता में ही हानि-पूर्ति ले सकता है।

(२) यदि वह अपने ग्राहक के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के नाम के चक्र सग्रहण करता है तो वह राशि उस अन्य व्यक्ति का देती पड़ेगी। क्योंकि खुला चक्र हानि के नाते उसका अपने ग्राहक में अच्छी उपाधि नहीं मिल सकती।

(३) खुले चक्र का भुगतान धारी द्वारा भुगतानकर्ता चक्र में प्राप्त किया जा सकता है। उनका भुगतान किसी चक्र द्वारा होना चाहिए ऐसा कोई बंधन नहीं है। परन्तु रखावृत्त चक्र के लिए सग्राहक चक्र पूर्ण रीति से सुरक्षित है यदि वह पूर्ण विद्वान् के साथ एवं बिना किसी उपस्था के सग्रहण करता है तथा ऐसा सग्रहण कबल ग्राहक के लिए ही किया जाता है। यदि वह सग्रहण के लिए आय हुए चक्रों का स्वाकार करने के पूर्व उनका बचान का प्रमाणित नहीं कर लेता अथवा रखावृत्त के अनुसार कार्य नहीं करता अथवा जिन चक्रों का पान वाला ग्राहक नहीं होता हुआ अन्य व्यक्ति है तो वह उपस्था में कार्य करता हुआ समझा जायगा। इसलिए वह का अपना पूर्ण बधानिक सुरक्षा की दृष्टि से कबल उन्हीं रखावृत्त चक्रों का पूर्ण विद्वान् एवं बिना किसी प्रकार की उपस्था के सग्रहण करना चाहिए जिनमें ग्राहक पान जाता है जिसमें उस बचानमाध्य विनियम अधिनियम (धारा १२१) में सुरक्षण मिले। इसी प्रकार यदि सग्रहण के लिए प्राप्त चक्र का अनाकरण होता है उस अपने ग्राहक को तुरन्त सूचना देना चाहिए जिसमें वह चक्र के अन्य सम्बन्धित पक्षा से चक्र की राशि प्राप्त कर सके।

बिलों का सग्रहण—ग्राहक से सग्रहण के लिए प्राप्त बिलों के सम्बन्ध में ग्राहक का स्वयं एवं उपाधि दोषरहित है यह वह का ज्ञान लेना चाहिए। ग्राहक की दोषपूर्ण उपाधि होने पर वह उस बिल के स्वत्वधारा स्वामी के प्रति जिम्मेदार होता है क्योंकि बिला के सग्रहण की जिम्मेदारी में भूक्त हानि के लिए

उसे कोई भी वैधानिक मरक्षण नहीं है। सम्राटक बैंक की स्वीकृति या भुगतान के लिए बिलों को यथाविधि उपस्थित करना होगा। साथ ही उनके अनादरण की सूचना तत्काल ही सम्बन्धित ग्राहकों को देना चाहिए जिसमें वह अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सके।

### सारांश

भुगतानकर्ता बैंक के पास यदि चैक लिखने वाले की पर्याप्त राशि है तो बैंक को चैक छोड़ते ही भुगतान करना चाहिए। अन्यथा भुगतान न करने से ग्राहक की हानि प्रति के लिए वह उत्तरदायी होगा। इस हेतु उपस्थित किया गया चैक सही रूप में तथा यथाविधि उपस्थित किया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का दोष होने पर बैंक भुगतान नहीं करेगा। चैक भुगतान करते समय बैंक को निम्न बातें देख लेनी चाहिए—

चैक रेखांकित या खुला है, जिस शाला पर वह उपस्थित किया है उसी पर लिखा गया हो, विकृत बीतरकारीन या उत्तरतियोध न हो, बैंक का प्रपत्र सही हो, महत्वपूर्ण परिवर्तन ग्राहक के हस्ताक्षर सहित हो, ग्राहक के हस्ताक्षर जाली न हों, शब्दों एवं अंकों में लिखित राशि में अंतर न हो तथा बेचान सही हो।

यथाविधि भुगतान उसे कहेंगे जिसमें चैक आदि का भुगतान,

(१) विलेख पर पसकारो के सुझावों के अनुसार भुगतान हो,

(२) भुगतान पूर्ण विश्वास सहित एवं बिना किसी उपेक्षा के से,

(३) भुगतान उस विलेख के धारी हो,

(४) यह विश्वास करने के लिए कोई कारण न हो कि विलेख के धारक को भुगतान लेने का अधिकार नहीं है।

चैको का भुगतान किसी दोष के कारण न करने की दशा में बैंक उसका कारण देते हैं जिसके छपे हुए फार्म बैंक के पास होते हैं। कारणों की सूची संक्षेप में होती है तथा सम्बन्धित कारण पर बैंक चिह्न लगा देता है।

बैंक की जिम्मेदारी—बैंक के गलत भुगतान होने पर बैंक जिम्मेदार रहता है अतः उसे उक्त बातों को ध्यान में रखकर ही चैको का भुगतान करना चाहिए। अन्यथा गलत भुगतान से वह ग्राहक का लेखा (debit) नहीं कर सकता। ग्राहक की असावधानी से गलत चैक का यथाविधि भुगतान किसी गलत व्यक्ति को होने पर बैंक जिम्मेदार न होते हुए ग्राहक ही जिम्मेदार होगा।

निम्न दशाओं में बैंक ग्राहक के चंको का भुगतान बिना किसी जिम्मेदारी के रोक सकता है—

(१) ग्राहक के आदेश से, (२) ग्राहक की मृत्यु दिवालियापन या पागलपन की सूचना मिलने पर, (३) न्यायालय से आदेश मिलने पर, (४) चंक उपस्थित करते वाला उसका स्वत्वधारी स्वामी न होने पर उसकी सूचना या जानकारी बैंक को हो, (५) ग्राहक प्रन्यासी होने के नाते प्रन्यास लेखे का निजी कार्य के हेतु उपयोग करता हो तो ।

सप्राहक बैंक—(१) जाली बेचानवाले चंको का सप्राहण करने के बावजूद यदि उसका स्वत्वधारी स्वामी उस राशि पर अधिकार प्रमाणित करे तो बैंक उत्तरदायी होगा । किन्तु उसका खर्चा वह ग्राहक से वसूल कर सकता है ।

(२) जुले चंको का सप्राहण करने पर बैंक उसके साक्षात्कारी स्वामी के प्रति दायी होगी क्योंकि इस स्थिति में उसे बंधानिक संरक्षण नहीं है ।

इसलिए बैंक को जुली चंको का सप्राहण नहीं करना चाहिए । बिलों के सप्राहण के सम्बन्ध में उसे कोई बंधानिक संरक्षण नहीं है अतः उसे बिलों का सप्राहण करते समय ग्राहक का साख बोध रहित है, यह देख लेना चाहिए ।

## अध्याय ११ केन्द्रीय बैंक

केन्द्रीय बैंक देश की मुद्रा एवं माप का समुचित सम्बन्ध स्थापित कर देश हित में साख-नियन्त्रण द्वारा देशी एवं अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में स्थिरता लाती है। यह देश के बैंकिंग विभास का अपनी नीति द्वारा सुरक्षित एवं संगठित बनाती है तथा भिन्न भिन्न प्रकार के बैंक का आपस में मगठन एवं सहकार्य बढ़ाती है। अतः स्पष्ट है कि केन्द्रीय बैंक के कार्य अन्य सब बैंकों से भिन्न एवं महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसे देश के मौद्रिक एवं बैंकिंग ढाँचे का प्रमुख अंग माना जाता है। केन्द्रीय बैंक यह कार्य समुचित रूप से कर सके, इसलिए उसे कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं, जैसे पत्र मुद्रा का एकाधिकार, सरकारी शेषों को रखना, सरकार की ओर से मुद्रा सम्बन्धी कार्यों पर देख-रेख, राष्ट्रीय निधि एवं बैंकों की निधि वैधानिक अनुपात में अपने पास रखना, तथा सकट-काल में बैंकों को आर्थिक सहायता देना।

जब जहाँ देश हित एवं बैंकिंग विकास के लिए इस बैंक को विशेष अधिकार दिये जाते हैं वहाँ उस पर नियन्त्रण भी आवश्यक है जिससे विशेषाधिकार का दुरुपयोग न हो। भी सेधर्म के अनुसार केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य लाभ बनाना नहीं होता है जनता एवं देश हित की सुरक्षा करना है। इसी हेतु व्यापारिक बैंकों पर नियन्त्रण करने का अधिकार इसे है, उनसे स्पर्धा करने के लिए नहीं। तीसरे, सरकार के अधिकार अथवा नियन्त्रण में होने से सरकारी मौद्रिक नीति को सफल बनाना भी इसका लक्ष्य होना चाहिए।<sup>1</sup>

### सरकार और केन्द्रीय बैंक

केन्द्रीय बैंक सरकारी मौद्रिक नीति की सफलता के हेतु साख और मुद्रा का देश-हित के लिए समुचित सम्बन्ध स्थापित करता है और साख एवं मुद्रा का नियन्त्रण करता है। इसलिए इस बैंक को सरकारी आदेशानुसार कार्यवाही करनी पड़ती है। इसीके माध् यदि केन्द्रीय बैंक मजबूतस्थित हो एवं योग्य

व्यक्तियों के हाथ में उनका मचालन हो तो देश की मौद्रिक एवं आर्थिक नीति बनाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अतः सरकार और केन्द्रीय बैंक दोनों में आर्थिक अथवा मौद्रिक समस्याओं पर मतभेद होना राष्ट्र के लिए अहितकर होता है। क्योंकि यह मतभेद तभी हो सकता है जब सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैंकिंग सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्यवाही करे जो बैंकिंग एवं मौद्रिक विकास की दृष्टि से हानिकर हो। फिर भी केन्द्रीय बैंक को सरकार के आधीन होने से सरकारी आदेशों का पालन करना होता है।

**केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता—**बैंक साख-निर्माण करते हैं जिसका देश-हित में नियन्त्रण होना अधिक आवश्यक है। किन्तु यह नियन्त्रण कौन करे? साधारणतः प्रत्येक बैंक अपनी सुरक्षा की दृष्टि से साख का निमाण उसी सीमा तक करता है जिससे उसकी रोकड़-निधि पर्याप्त रह तथा उसे सकट-काल में रोकड़ की कमी न रहे। फिर भी इस कार्य में यदि प्रत्येक बैंक को पूरी स्वतन्त्रता रहे तो वह लाभ के मोह से सुरक्षा की ओर कुलंक कर सकती है। इससे उस बैंक के साथ ही अन्य बैंकों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। अतः किसी विशेष मस्या द्वारा साख का नियन्त्रण होना आवश्यक है। यह मस्या बैंक ही हो सकती है क्योंकि जनता की साख सम्बन्धी आवश्यकताएँ वह सही-सही आँक सकती है। जो बैंक यह कार्य करती है उसे केन्द्रीय बैंक कहते हैं। इसका महत्वपूर्ण कार्य देश की बैंकिंग मस्याओं एवं साख पर नियन्त्रण करना होता है। इस प्रकार केन्द्रीय बैंक देश की रोकड़ निधि के केन्द्रीकरण से साख का निर्माण भी बढ़ाती है। क्योंकि केन्द्रीय बैंक के अभाव में प्रत्येक बैंक को अपनी स्वतन्त्र निधि रखनी पड़ती है। इससे आवश्यकता पड़ने पर कोई भी राशि किसी भी बैंक को दी जा सकती है एवं समय पड़ने पर दी जाती है। इससे देश की निधि की राशि में वृद्धि कर मुद्रा की गति बढ़ती है।

उक्त लाभों की दृष्टि से केन्द्रीय बैंक देश के बैंकिंग क्लेवर की सुरक्षा के लिए अत्यन्त आवश्यक है, जिसका महत्व आधुनिक मौद्रिक जगत में पूर्णतः प्रमाणित हो गया है।

### केन्द्रीय बैंक के कार्य

१ **बैंकों का बैंकर—**देश के अन्य बैंक जनता को जो कार्य एवं सुविधाएँ देने हैं वही केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों को देता है। इसलिए यह केन्द्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों के विशेष स्वीकार करता है जिन पर व्याज नहीं दिया जाता। इसी प्रकार बैंकों को वह राशि के स्थाना-

स्तरण (remittances) की सुविधाएँ देता है जिसे वह सस्ते दरों पर करता है तथा पुनः कटौती की सुविधाएँ देकर अन्य बैंक को सात अथवा प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण आदि देता है जो बैंक के लिए सकट-काल में अधिक उपयोगी होते हैं। इसलिए केन्द्रीय बैंक को अन्तिम ऋण-दाता (lender of the last resort) भी कहते हैं। साथ ही बैंकिंग क्लेवर को सुरक्षा के लिए अथवा लाभ के लोभ से साख का निर्माण अधिष्ठा न हो, इसलिए वह माँग एवं काल-ब्रेनदारीय का कुछ अनुपात अपने पास रखने के लिए अन्य बैंक पर वैधानिक बन्धन डालता है। इस अनुपात में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार निधि रखने का बन्धन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा भारत में है किन्तु इंग्लैंड में कोई वैधानिक बन्धन नहीं है।

२. पत्र-मुद्रा चलाने का एकाधिकार (Monopoly)—देश की पत्र-मुद्रा चलाने का एकाधिकार इस बैंक का होता है जिससे वह मुद्रा को आवश्यकता-नुसार घटा-बढ़ा सके। आजकल बहुधा सब देशों में पत्र-मुद्रा का एकाधिकार वहाँ के केन्द्रीय बैंक को ही है। इस अधिकार के कारण देश की साख का समुचित नियन्त्रण करने में सुविधा होती है क्योंकि मुद्रा एवं साख का घनिष्ठ सम्बन्ध होने से उनका नियन्त्रण तभी प्रभावशाली हो सकता है जब मुद्रा एवं पत्र-मुद्रा-चलन का अधिकार एक ही संस्था के हाथ में हो। इस प्रकार साख के समुचित नियन्त्रण से देश के मूल्य-स्तर का नियमन किया जा सकता है।

३. साख का नियन्त्रण—केन्द्रीय बैंक की स्थापना का मूल ध्येय साख का समुचित नियन्त्रण रहा है। साख का नियन्त्रण केन्द्रीय बैंक तीन प्रकार से करता है—बैंक-दर की कमी एवं वृद्धि से, खुली बाजार क्रियाओं (open market operations) से, तथा निधि अनुपात के परिवर्तन (alteration of the reserve ratios) से। इसका विवेचन आगे होगा।

४. सरकार का बैंकर—सरकार की ओर से सरकारी कोषों की व्यवस्था रखना, भुगतान करना, राशि प्राप्त करना तथा सरकार को अन्य मौद्रिक सुविधाएँ देना आदि भी इस बैंक का एक कार्य है। सरकार द्वारा जो ऋण-पत्र अथवा कोष विपत्र आदि निकाले जाते हैं उनका नियमन एवं भुगतान यही करता है। सरकार की ओर से कर आदि वसूल करना, ऋण-एवं व्याज का भुगतान करना अथवा देश एवं विदेशों के मौद्रिक व्यवहार (monetary transactions) यही बैंक करती है। इन कार्यों को करने से मुद्रा एवं साख का समुचित संकुचन एवं प्रसार करने में केन्द्रीय बैंक को सहायता मिलती है।

५ आन्तरिक एवं विदेशी विनिमय दर में स्थिरता रखना—आन्तरिक एवं विदेशी विनिमय दर में स्थिरता रखने की जिम्मेदारी भी केन्द्रीय बैंक पर होती है। इसके अनुसार विदेशी विनिमय के लिए विदेशी विनिमय अथवा स्वयं में देशी मुद्रा का निश्चित दरा पर परिवर्तन करने का एकाधिकार इसे हाता है। इसी दर पर दरा के अन्य विनिमय बैंक देशी मुद्रा का स्वयं अथवा विदेशी विनिमय में परिवर्तन करने के लिए बाध्य हान है। इस कार्य में विदेशी विनिमय दर में स्थिरता रहती है। दूसरे, आवश्यकतानुसार मुद्रा एवं साख का नियन्त्रण कर आन्तरिक मूल्य में स्थिरता रखने की जिम्मेदारी भी इसी बैंक की होती है।

६ सरकारी मौद्रिक नीति को सफल बनाना—वह अपनी विभिन्न क्रियाओं द्वारा सरकारी मौद्रिक नीति का सफल बनाने में प्रयत्नशील रहता है। जहाँ तक अन्य बैंक का सम्बन्ध है वह उनकी क्रियाओं का नियन्त्रण बैंक-दर से करता है एवं उनमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करता है। क्योंकि बैंक दर को घटाने-बढ़ाने से वह मुद्रा मंडी की ऋण राशि पर प्रभाव डालता है। उदाहरणार्थ अगर केन्द्रीय बैंक बैंक दर घटा दे तो अन्य बैंक उससे कम ऋण लगे जिससे उनकी ऋण अथवा साख निर्माण शक्ति संकुचित होगी। इसके विपरीत यदि बैंक-दर कम की जाय तो अन्य बैंक केन्द्रीय बैंक से अधिक ऋण ले सकेंगे जिससे उनका साख निर्माण शक्ति भी बढेगी।

७ समाशोषण गृह की सुविधा देना—केन्द्रीय बैंक दरा की बका का समाशोषण गृह की सुविधा देता है जिससे राकड़ के हस्तांतरण बिना ही उनका आगसी गुगतान हो जाता है।

८ देश के धातु-कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष रखना—दरा की पत्र मुद्रा की सुरक्षा के लिए धातु-कोष तथा विदेशी विनिमय दर की स्थिरता के लिए विदेशी मुद्राओं का कोष रखने की जिम्मेदारी इसी बैंक पर होती है।

केन्द्रीय बैंक के कार्यों के सम्बन्ध में अध्यात्मिकता में एकमत नहीं है। प्रा० प्रग के अनुसार केन्द्रीय बैंक के विशेष कार्यों का उल्लेख तीन भागों में किया जा सकता है। वे सरकार के आर्थिक अभिकता का कार्य करते हैं। पत्र मुद्रा-चलन का सम्पूर्ण अथवा अपूर्ण एकाधिकार हान में इनका चलाय के नियन्त्रण की बड़ी शक्ति होती है। अन्तिम रूप में अर्थव्यवस्था के कोष का एक बहुत बड़ा भाग केन्द्रीय बैंक के पास हान में वे साख के सम्पूर्ण कानवर के आधार के लिए जिम्मेदार हाते हैं। और यह कार्य केन्द्रीय बैंक का अधिक

महत्वपूर्ण कार्य है।" इसी प्रकार बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने शाही समिति (Royal Commission on Indian Currency & Finance, 1926) के सामने गवाही देते हुए केन्द्रीय बैंक के निम्न कार्य बताये थे—“उसको पत्र-चलन का एकाधिकार होना चाहिए, वह विधिग्राह्य चलन का प्रसार करने अथवा उसे चलन से निकालने का एकमात्र अधिकारी होना चाहिए। सरकारी कोषों का सभारक भी वही होना चाहिए, तथा देश की अन्य सब बैंकों की शाखाओं के शेष धन का वही धारी होना चाहिए। वह अभिकर्ता होना चाहिए जिसके द्वारा सरकार को देशी एवं विदेशी ऋणियाँ की जायें। इसीके साथ आन्तरिक एवं विदेशी भूत्यों के स्थिरता लाने के हेतु समुचित रीति से यथा सम्भव मुद्रा सकुचन एवं प्रसार कार्य भी केन्द्रीय बैंक को करना चाहिए। आवश्यकता के समय वही एकमेव स्रोत होना चाहिए जिससे सरकारी प्रतिभूतियों अथवा मान्य अल्पकालीन प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्राप्त कि जा सके अथवा मान्य बिलों की कटौती से सफ्टकालीन साध प्राप्त की जा सके। कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार केन्द्रीय बैंक का महत्वपूर्ण कार्य देश की साख-व्यवस्था का संगठन करना है।

परन्तु इन विभिन्न कार्यों के होते हुए भी केन्द्रीय बैंक का कोई एक ही कार्य महत्वपूर्ण है यह कहना ठीक न होगा। क्योंकि उक्त सब कार्य समान महत्व के एवं परस्पर निर्भर हैं तथा उसको ये सब क्रियाएँ देश एवं जनता के हित में करनी चाहिए, अपने लाभ की दृष्टि से नहीं और न अन्य बैंकों से प्रतिस्पर्धा करने की दृष्टि से। इसी हेतु केन्द्रीय बैंक ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकता जो देश के अन्य बैंक करते हैं। उदाहरणार्थ, जनता से निक्षेप स्वीकार करना, ऋण देना अथवा उनको कटौती की सुविधाएँ देना आदि। परन्तु यदि देश की वैयक्तिक प्रणाली को शक्तिशाली बनाने और अपने कार्यों की सफलता के लिए ऐसा किया जाय तो वह वाञ्छनीय होगा।

केन्द्रीय बैंक द्वारा साख-नियन्त्रण—साख नियन्त्रण का अर्थ है साख की पूर्ति का व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार सन्तुलित समायोजन। यदि व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार साख का समायोजन नहीं होता तो मूल्य स्तर या तो गिरते हैं या बढ़ते हैं। जैसे यदि साख की आवश्यकता कम होने लगे मुद्रा-मण्डी में साख अधिक होती है तो मूल्य स्तर बढ़ता है जिसका प्रभाव उत्पादन पर होता है। इसके विपरीत यदि मुद्रा मण्डी में आवश्यकता से कम साख रहती है तो मूल्य-स्तर गिरने लगता है तथा उत्पादन कार्यों में शिथिलता

आती है। अतः साख का आवश्यकतानुसार सकुचन एवं प्रसार ही राष्ट्र के लिए लाभकर है। इसीलिए वर्गर्ड साँ ने कहा है कि केन्द्रीय बैंक की एक ही निया सबसे आवश्यक है, और वह है देश की साख-व्यवस्था का समन्वय कर देन की मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। साख-नियन्त्रण के ये मुख्य उद्देश्य हैं—आन्तरिक मुन्वों में स्थिरता लाना, विनिमय दर को स्थायी रखना, उत्पादन कार्य एवं रोजगारी में स्थिरता लाना, तथा देश की स्वर्ण-निधि को बाहर जाने से अथवा आन्तरिक व्यय होन से बचाना।

किन्तु साख-नियन्त्रण में केन्द्रीय बैंक पूर्णतः सफल नहीं हो सकता। क्योंकि साख केवल बैंक द्वारा ही प्राप्त न होते हुए व्यापारिक कार्यों में भी निर्मित होती है, जैसे विनिमय-बिल आदि। इस प्रकार की व्यापारिक साख का नियन्त्रण केन्द्रीय बैंक नहीं कर सकता। दूसरे, जिन देशों में ऐसी मस्याएँ हैं जो केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण में नहीं हैं, उन मस्याओं द्वारा निर्मित साख पर केन्द्रीय बैंक नियन्त्रण नहीं कर सकता। जैसे भारत में स्वदेशी बैंकर जो यहाँ ६० प्रतिशत साख का निर्माण अपने ऋण-कार्यों द्वारा करते हैं। इन पर रिजर्व बैंक का कोई नियन्त्रण नहीं है।

### साख-नियन्त्रण के साधन

१ बैंक-दर (Bank Rate)—इसको हम कटौती (discount rate) दर भी कह सकते हैं। यह वह दर है जिस पर केन्द्रीय बैंक अन्य व्यापारिक बैंकों को बिलों के पुनः कटौती (re-discounting) की सुविधाएँ अथवा जिस दर पर प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देता है। यह दर बाजार-दर से भिन्न होती है जो बहुधा बैंक-दर में कम होती है। बाजार-दर उम दर को कहते हैं जिस पर अन्य ऋण देने वाली मस्याएँ मुद्रा मण्डी में बिलों की कटौती करती हैं अथवा ऋण देती हैं। इन दोनों ही दरों का घनिष्ठ सम्बन्ध होता है। जब बैंक-दर बढ़ा दी जाती है उम समय बाजार-दर भी बढ़ जाती है। इसी प्रकार बैंक-दर में कम होने पर बाजार दर भी कम हो जाती है। बैंक-दर में कमी अथवा वृद्धि करने से मुद्रा की माँग एवं पूर्ति प्रभावित होती है। यदि बैंक-दर बढ़ा दी जाय तो उमके साथ बाजार दर भी बढ़ जायगी तथा जो व्यापारी अथवा ऋण लेने वाले व्यक्ति हैं वे कम ऋण लेंगे तथा अपनी अतिरिक्त राशि बैंकों में जमा करने लगेंगे, जिससे चलार्थ मुद्रा (circulating money) का परिमाण घट जायगा तथा उमी परिमाण में साख भी कम हो जायगी। इसके विपरीत यदि बैंक-दर घटा दी जाय तो बाजार-दर कम हो जायगी तथा व्यापार

की दर कम होने से लोग अधिक रुपया उधार लेते हैं जिससे मुद्रा का परिमाण बढ़ जाता है और मास की वृद्धि होती है। इतना ही नहीं अपितु बैंक-दर का प्रभाव विदेशी मुद्रा-मण्डी पर भी पड़ता है क्योंकि बैंक-दर अधिक होने से बाहरी पूँजी हमारे यहाँ आने लगती है तथा यह दर कम होने पर हमारे यहाँ से पूँजी बाहर जाने लगती है। इस प्रकार बैंक-दर मुद्रा-मण्डी के अल्पकालीन व्याज-दरों को प्रभावित करती है और इन मुद्रा-मण्डी के दरों से विदेशी विनिमय मण्डी प्रभावित होती है। अर्थात् देश में विदेशी पूँजी का विनिमय प्रभावित होता है जिसका परिणाम दीर्घकालीन पूँजी पर होता है। सान् के नियन्त्रण से आन्तरिक मूल्य-स्तर भी प्रभावित होता है क्योंकि साख के संचयन के समय व्यापारिक एवं औद्योगिक कार्यों में शिथिलता आ जाती है एवं मूल्य-स्तर गिरने लगता है। साख का प्रसार होने के समय व्यापारिक एवं औद्योगिक कार्यों को प्रोत्साहन मिलता है और मूल्य-स्तर बढ़ने लगता है। और जहाँ तक आन्तरिक मूल्य-स्तर का हमारे विदेशी व्यापार पर प्रभाव होना है, विदेशी व्यापार एवं विनिमय दर को स्थायी रखने में भी इस दर का बहुत अधिक उपयोग होता है। इस प्रकार बैंक-दर मुद्रा-मण्डी, आन्तरिक मूल्य स्तर एवं विदेशी व्यापार पर प्रभावी रूप से कार्य करती है, इसीलिए इस दर को मुद्रा-मण्डी का मापदण्ड कहा गया है। जिस समय बैंक-दर ऊँची हो जाती है उस समय बैंक निक्षेप आकर्षित करने के लिए निक्षेपों पर दिये जाने वाले व्याज की दर बढ़ा देते हैं क्योंकि ऊँची व्याज दर होने पर अधिक देना भी उनको लाभदायक होता है। कारण बाजार-दर तथा बैंक द्वारा ऋणा पर ली जाने वाली व्याज की दर भी बढ़ जाती है। इस प्रकार बैंक-दर की कमी अथवा वृद्धि से तीन बातें प्रभावित होती हैं —

१ साख का संचयन अथवा प्रसार,

२ देश का आन्तरिक मूल्य-स्तर, तथा

३ स्वर्ण अथवा पूँजी का आयात-निर्गत। इसीलिए यह कहा जाता है कि बैंक-दर विदेशी विनिमय मण्डी को तीन ओरों से प्रभावित करती है। बैंक-दर में कल्प वृद्धि अथवा कमी की जाती है ?

(१) मास नियन्त्रण का एक मात्र उद्देश्य देश की स्वर्ण निधि की सुरक्षा करना होता है। अतः जिस समय देश से स्वर्ण बाहर जाने लगता है उस समय स्वर्ण-निर्गत रोकने के लिए बैंक-दर में वृद्धि की जाती है।

(२) जब अन्य देशों में बैंक-दर बढ़ रही हो, तब देश की विनियोग एवं

अन्य पूँजी का बाहर निर्यात होने लगता है। अतः इन निर्यात को रोकने के लिये बैंक-दर में वृद्धि की जाती है जिससे अधिक व्याज देकर बाहर जाने वाले धन का विनियोग देश में ही हो।

(३) जिस समय विनिमय-दर देश के विपक्ष में हो उस समय विनिमय-दर को ठीक करने के लिए बैंक-दर में वृद्धि की जाती है।

(४) देश में जब मट्टे का जोर होने लगता है उस समय मट्टोरिये ध्रुवों से ऋण लेते हैं। इन ऋणों की पूर्ति करने के लिए बैंक केन्द्रीय बैंकों से ऋण लेते हैं। बढ़ते हुए मट्टे में देश के उद्योगों को भी, जहाँ तक विनियोग का सम्बन्ध है, हानि होनी है। अतः मट्टे को रोकने के लिए भी बैंक-दर में वृद्धि की जाती है।

इसके विपरीत (१) जब रुपया केन्द्रीय तथा अन्य बैंकों के पास एकत्रित हो रहा हो, परन्तु उसके लिए मुद्रा-मण्डी में माँग न हो उस समय माँग निर्माण करने के लिए बैंक-दर कम कर दी जाती है। (२) ऋण-प्रदायक राशि की मुद्रा-मण्डी में कमी हो और माय ही केन्द्रीय बैंक के पास ऐसी राशि हो, उस समय बैंक-दर कम कर दी जाती है। (३) जब विदेशी पूँजी का आयात पर्याप्त मात्रा में हो रहा हो, जो देश के हित में न हो अथवा जब देश में उसका समुचित उपयोग न हो सकता हो, उस समय देश को ऋण-भार से बचाने के लिए बैंक-दर कम की जाती है।

**बैंक-दर का महत्त्व**—बैंक-दर का मुद्रा-मण्डी से घनिष्ठ सम्बन्ध होने से मुद्रा-मण्डी में बैंक-दर का विशेष महत्त्व है। यह बैंक-दर केन्द्रीय बैंक की मंचालक सभा साप्ताहिक अथवा आवश्यकता के समय बीच में भी निश्चित करती है। इसका प्रकटन वर्तमान पत्रो (अखबारों) में नियमित रूप में होना रहता है।

(१) बैंक-दर से गांव निश्चित होती है, अतः इसको मुद्रा मण्डी का मापदण्ड कहते हैं। इसके साथ ही यह देश की सामान्य आर्थिक स्थिति की दिग्दर्शक भी होती है।

(२) बैंक-दर में मुद्रा-मण्डी की बाजार-दर तथा अन्य ऋण-शक्ती नस्थाओं की दरें भी प्रभावित होती हैं। जैसे बैंक-दर के उत्तार-चढ़ाव के साथ बाजार-दर, दीर्घकालीन ऋण की दर आदि प्रभावित होती हैं, उसी प्रकार बैंक द्वारा दिये जाने वाले अल्पकालीन ऋणों की व्याज-दर (जिसे माँग दर अथवा call rate कहते हैं) भी प्रभावित होती है।

(३) बैंक-दर से ऋण-प्रदायक राशि की कमी एवं अधिकता का अन्दाज भी किया जा सकता है, अतः इस दर का महत्व बहुत अधिक है।

बैंक-दर का महत्व कम होने के कारण—वर्तमान स्थिति में बैंक-दर का साख-नियन्त्रण में महत्व कम हो गया है एवं वह उतनी प्रभावशाली नहीं रही, क्योंकि,

(क) आर्थिक कलेवर में लोच—सामान्यतः बैंक-दर तभी प्रभावी हो सकती है जब बाजार की भिन्न-भिन्न व्याज-दरों में भी उसके साथ परिवर्तन हो तथा देश की अर्थ-व्यवस्था में लोच हो। अगर अर्थ-व्यवस्था में लोच नहीं है तो माख की कमी एवं अधिकता के साथ उत्पादन, मजदूरी आदि बातों का मिलान नहीं हो सकेगा। इससे बैंक-दर भी प्रभावी नहीं रहेगी। प्रथम महायुद्ध-पूर्व काल में देशों की अर्थ-व्यवस्था में लोच थी जो युद्धोत्तर काल में जाती रही जिससे बैंक दर प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकी। यह बैंक-दर के वर्तमान महत्व को कम करने का पहला कारण है। क्योंकि मुद्रा के मूल्य-परिवर्तन के साथ अर्थ-व्यवस्था में, जैसे मजदूरी, उत्पादन आदि में परिवर्तन नहीं होता।

(ख) बैंकों की निर्भरता—बैंक-दर तभी प्रभावी हो सकती है जब देश के बैंक आवश्यकता के समय ऋणों के लिए केवल केन्द्रीय बैंक पर ही निर्भर रहें। परन्तु वास्तव में प्रथम श्रेणी के बैंक केन्द्रीय बैंक से ऋण आदि नहीं लेते जिससे बैंक-दर का परिवर्तन उनकी कार्य-प्रणाली में बाधक नहीं होता।

(ग) विनिमय बिलों का कम महत्व—आजकल आन्तरिक व्यापार में मुद्रा की आवश्यकता की पूर्ति रोक-ऋण अथवा अधिविक्रयों पर ऋण लेकर की जाती है जिससे प्रत्यक्ष व्यवहारों में विनिमय-बिलों का महत्व भी कम हो गया है। इसलिए बैंक-दर प्रभावी नहीं होती।

(घ) अन्य साख-नियन्त्रण साधनों का अधिक उपयोग—खुले बाजार की क्रिया तथा अन्य साख नियन्त्रण की क्रियाओं के गत २५ वर्षों से उपयोग सफल होने के कारण भी बैंक-दर का वर्तमान महत्व कम हो गया है।

(ङ) सुलभ मुद्रा नीति अपनाना—विश्व के सभी देशों द्वारा युद्धोत्तर काल में सुलभ मुद्रा-नीति अपनाने में बैंक-दर का महत्व कम हो गया है।

(च) बैंकों की सम्पत्ति में तरलता—गत १५ वर्षों से बैंकों की सम्पत्ति अधिक तरल रहने लगी है जिससे अन्य बैंकों को केन्द्रीय बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं होती अपितु मुद्रा मण्डी की आवश्यकताओं की पूर्ति वे स्वयं ही कर सकते हैं। अतः बैंक-दर के महत्व का कम होना सहज ही है।

(घ) बैंक-दर तत्कालीन प्रभावी नहीं—बैंक-दर में परिवर्तन होते ही मुद्रा-मण्डी पर तत्काल प्रभाव नहीं होता। प्रभाव के होने के लिए कुछ समय लगता है, जिस बीच में साल-नियन्त्रण की आवश्यकता भी खतम हो जाती है। इस कारण बैंक-दर महत्वपूर्ण नहीं रही।

(ज) बैंक-दर वृद्धि के साथ साल निर्माण में वृद्धि—बैंक-दर की वृद्धि में मान नीजिए कि लोग उधार लेना कुछ समय के लिए कम कर देने हैं। परन्तु इस वृद्धि के साथ ही बैंक निक्षेपों पर बिये जाने वाले व्याज की दर बढ़ा देते हैं जिसमें निक्षेपों में वृद्धि होती है। और यह वृद्धि होने ही बैंक अधिक माध्य-निर्माण करते हैं जो बैंक-दर को अप्रभावी कर देती है।

(२) खुले बाजार की क्रियाएँ (Open Market Operations)—जिस समय केन्द्रीय बैंक बाजार में एक सामान्य व्यक्ति की भाँति साल के मकोच अथवा प्रसार के हेतु प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करता है, उस समय इस क्रिया को खुले बाजार की क्रियाएँ कहते हैं। इस क्रिया का प्रारम्भ प्रथम महायुद्ध के बाद हुआ जिससे केन्द्रीय बैंक को माध्य-नियन्त्रण का एक नया माधन प्राप्त हुआ। यह साधन केन्द्रीय बैंक उसी समय उपयोग में लाता है जब बैंक-दर प्रभावी नहीं होती।

जिस समय मुद्रा-मण्डी में मुद्रा-राशि की अधिकता होती है और केन्द्रीय बैंक उसको कम करना चाहता है उस समय वह बाजार में प्रतिभूतियाँ, बिल आदि बेचने लगता है। इसके बदले में उसे धन प्राप्त होता है तथा मुद्रा-मण्डी में ऋण-प्रदायक राशि कम हो जाती है जो बैंक की निधि में आ जाती है तथा माध्य का मकोच हो जाता है। इसी प्रकार जब मुद्रा-मण्डी में धन का अभाव रहता है उस समय साल बढ़ाने के लिए मुद्रा-राशि बढ़ाना आवश्यक होता है। इसे बढ़ाने के लिए केन्द्रीय बैंक बाजार से प्रतिभूतियाँ, बिल आदि क्रय करता है जिसके बदले में वह मुद्रा देता है। इससे मुद्रा-मण्डी में मुद्रा अधिक होकर माध्य का प्रसार होता है। प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय से बैंक देश की राश्व नियन्त्रित कर माध्य एवं मुद्रा-राशि का कृषि, व्यापार एवं औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ सन्तुलित मिलान करता है। इस प्रकार देश में मूल्य-स्तर, उत्पादन एवं उत्पादन व्यय, रोजगार तथा व्यापार में गन्तुनन स्थापित करता है तथा देश के आर्थिक ढाँच को मजबूत बनाता है।

ये क्रियाएँ तभी सफल हो सकती हैं जब केन्द्रीय बैंक द्वारा क्रय विक्रय की गई प्रतिभूतियों की उस समय बाजार में माँग एवं पूर्ति हो तथा ये प्रतिभूतियाँ

मात्र नियन्त्रण का एक प्रमुख भाग हो। इसीके माय जिम बाजार में इन प्रतिभूतियों का जय-विजय हो, वह संगठित एवं कार्यक्षम हो अन्यथा मुद्रा-मण्डी पर कोई भी प्रभाव न होगा।

इसी प्रकार जिम समय देश में अधिक मुद्रा-राशि हो एवं वह विनियोग के लिए बाहर जा रही हो, उस समय भी इस क्रिया का उपयोग बैंक करना है। अर्थात् ऐसी दशा में वह प्रतिभूतियों के विनियम में मुद्रा-राशि चलन में सींचकर अपने कोष में ले लेता है।

इस क्रिया में मुद्रा-मण्डी प्रत्यक्ष प्रभावित होती है। यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिम समय केन्द्रीय बैंक मात्र का सुकोष करता है उस समय अन्य बैंकों के निक्षेप कम होते हैं तथा मुद्रा एवं साख को प्रसार के समय बैंकों के निक्षेप बढ़ते हैं। इस निक्षेप-राशि की कमी एवं अधिकता पर ही अन्य बैंकों की साख-निर्माण-शक्ति निर्भर रहती है।

साख-नियन्त्रण का यह प्रत्यक्ष एवं मरल साधन है। किन्तु जब बैंक-दर से साख-नियन्त्रण नहीं हो सकता, उस समय इस क्रिया का उपयोग किया जाता है। परन्तु बैंक-दर एवं खुले बाजार की क्रियाएँ इन दोनों में दूमरी अधिक प्रभावशाली हैं क्योंकि इन क्रियाओं से अन्य बैंकों के निक्षेप, निधि तथा साख-निर्माण-शक्ति तत्काल ही प्रभावित होती है।

भारत में मुद्रा-मण्डी पूर्ण रूप में संगठित न होने तथा विभिन्न ऋण-प्रदायक संस्थाओं पर केन्द्रीय बैंक का नियन्त्रण न होने से बैंक-दर प्रभावी नहीं होती। इसलिए विशेषतः खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा ही साख का नियन्त्रण होता है। साख-नियन्त्रण में, बैंक-दर के घटते हुए महत्व एवं मर कारी प्रतिभूतियों के अधिक प्रयोग के कारण खुले बाजार की क्रियाओं का सभी देशों में अधिक प्रयोग होने लगा है।

(३) वैधानिक रोकड़ निधि में परिवर्तन—व्यापारिक बैंक यथासम्भव अपने पास कम रोकड़ निधि रखते हैं। परन्तु उनको कानून से निक्षेपों का कुछ अनुपात केन्द्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है। इस निधि के अनुपात से उनकी साख-निर्माण शक्ति भीमित रहती है। इसलिए ऋण द्वारा निक्षेप बढ़ाने का परिमाण इस वैधानिक निधि से मर्यादित होता है क्योंकि जितने ही अधिक निक्षेप होंगे उतनी ही अधिक राशि उनको केन्द्रीय बैंक के पास रखनी होगी। अतः जब उक्त दो साधन भी पूर्णतः प्रभावी नहीं होते तब केन्द्रीय बैंक इस साधन का उपयोग करती है। इसके अनुसार जब साख तथा मुद्रा-राशि की कम

करने की आवश्यकता होती है। उम समय रोकड़ निधि का वैधानिक अनुपात बढ़ा देता है जिससे केन्द्रीय बैंक के पास अधिक राशि आती है तथा अन्य बैंकों की रोकड़ निधि कम हो जाती है। इससे उनकी साख-निर्माण-शक्ति घट जाती है। इसके विपरीत जब साख एवं मुद्रा की अधिक आवश्यकता होती है उम समय केन्द्रीय बैंक वैधानिक अनुपात का कम कर अन्य बैंकों की रोकड़ निधि को बढ़ा देती है जिससे उनकी साख-निर्माण शक्ति बढ़ जाती है तथा जनता का साख अथवा ऋण अधिक सुलभता से मिल सकते हैं। इस पद्धति का मूभाव प्रो० कोन्स ने दिया था।

(४) साख का अञ्जन (Rationing) करना—इस पद्धति के अनुसार केन्द्रीय बैंक विलो की कटौती अथवा पुनः बढ़ावों का परिमाण प्रनियमित कितना होगा, निर्दिष्ट कर लेता है। हम निर्दिष्ट राशि में अधिक के विल कटौती के लिए आने पर केन्द्रीय बैंक प्रत्येक बैंक को ऋण देने की राशि कम कर देता है। परिणामस्वरूप अन्य बैंकों की ऋण प्रदायक राशि भी कम हो जाती है जिससे साख की भी कमी हो जाती है। इस निया को साख का अञ्जन कहते हैं।

(५) प्रत्यक्ष कार्यवाही (Direct Action)—जब केन्द्रीय बैंक खुले बाजार की क्रियाया अथवा बैंक-दर में मुद्रा मण्डी में साख का नियन्त्रण करने में असफल होता है उम समय वह अन्य बैंकों के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करता है। इसके अन्तर्गत साख का विस्तार या संकोच करने के हेतु वह अन्य बैंकों को अधिक अथवा कम ऋण देने के लिए आदेश देता है, विशेषतः साख के संकोच के लिए ही, जिससे साख का सतुलित प्रसार हो। जब साख नियन्त्रण की आवश्यकता होती है और साख का उपयोग उत्पादन कार्य के लिए न होकर सट्टे के लिए होता है अथवा देश हित के लिए नहीं होता उम समय केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों को आदेश द्वारा कुछ सीमित माना में ऋण देने को बाध्य कर देता है अथवा कुछ विशेष प्रकार की प्रतिभूतिवा पर ही ऋण देता है। इससे आवश्यकतानुसार साख का समायोजन होता है।

(६) नैतिक प्रभाव (Moral Persuasion)—केन्द्रीय बैंक अन्य बैंकों का पालक होने के नाते तथा मुद्रा मण्डी में विशेष प्रभावशाली होने के कारण सामनियन्त्रण के समय अन्य बैंकों एवं ऋण प्रदायक संस्थाओं पर नैतिक प्रभाव डालकर अपनी साख सम्बन्धी नीति का पालन करने के लिए बाध्य कर देता है। इसमें वे बैंक केन्द्रीय बैंक की इच्छानुसार देश हित की दृष्टि में साख का संकोच एवं विस्तार करते हैं।

विभिन्न साधनों के उपयोग से केन्द्रीय बैंक साख्त-नियन्त्रण करता है। यह आवश्यक नहीं कि इनमें से केवल किसी एक साधन का उपयोग किया जाय। परन्तु यदि किसी एक ही मार्ग का अवलम्ब किया जाता है तो वह उतना प्रभावशाली नहीं हो सकता, जितना सब साधनों का सन्तुलित उपयोग प्रभावशाली हो सकता है। क्योंकि, बाजारल, बैंक-दर दीर्घवाक में प्रभावी होने के कारण इसका महत्व कम हो गया है। इसलिए अन्य साधनों का उपयोग भी साथ ही साथ होना चाहिए। दूसरे, यदि केवल नैतिक प्रभाव से ही साख्त-नियन्त्रण करने का प्रयास किया जाय तो वह भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि सभी बैंक अपना उत्तरदायित्व भली भाँति नहीं निभा सकते। इस प्रकार साख्त के अंशतः (rationing of credit) से केवल सट्टे का ही नियन्त्रण किया जा सकता है। प्रो० कीम्स के अनुसार अनुपात-निधि में एकदम परिवर्तन कर देने से साख्त का नियन्त्रण तो होता है परन्तु उससे बैंकिंग कलेबर को गहरा धक्का लगने की सम्भावना होती है। खुलेबाजार की क्रियाओं का प्रभाव तो तत्काश होता है किन्तु ये सब क्रियाएँ अविवेकात्मक (indiscriminate) होती हैं। अतः सब क्रियाओं के समुचित सामंजस्य एवं सन्तुलित उपयोग से ही केन्द्रीय बैंक को साख्त नियन्त्रण करना चाहिए।

### सारांश

केन्द्रीय बैंक देश की मुद्रा एवं साख्त नियन्त्रण द्वारा देशी एवं अन्तर-राष्ट्रीय धूलियों में स्थिरता लाती है। देश के बैंकिंग कलेबर को अपनी नीति द्वारा संगठित एवं सुरक्षित करती है तथा बैंकों में परस्पर सहयोग बढ़ाती है। इसलिए केन्द्रीय बैंक देश के मौद्रिक एवं बैंकिंग कलेबर का प्रमुख अंग है। इन कार्यों को सफलतापूर्वक करने के लिए केन्द्रीय बैंक को कुछ विशेष अधिकार होते हैं वहीं इस पर सरकारी अंकुश भी होता है। अतः इसका सख्त सरकारी नीति की सफल बनाना भी होता है।

सरकार और केन्द्रीय बैंक का महत्वपूर्ण सम्बन्ध होता है क्योंकि इस का सरकारी मौद्रिक नीति की सफलता की जिम्मेवारी होती है। इसलिए इसे सरकारी आदेशानुसार कार्यवाही करनी पड़ती है क्योंकि सरकार एवं केन्द्रीय बैंक में आर्थिक या मौद्रिक समस्याओं पर मतभेद होना देश के हित में नहीं होता।

केन्द्रीय बैंक निम्न कार्यों के लिए आवश्यक होती है—(१) साख्त नियन्त्रण, (२) देश की बैंकिंग सस्थाओं पर अंकुश रखना, (३) देश की रोकड़-निधि का केन्द्रीकरण, (४) बैंकों को सकलकालीन सहायता देना।

केन्द्रीय बैंक के कार्य—(१) बैंको का बैंकर, (२) पत्रमुद्रा चलाने का एकाधिकार, (३) साख का नियन्त्रण, (४) सरकार के बैंकर का कार्य, (५) आंतरिक एवं विदेशी विनिमय-दर में स्थिरता रखना, (६) सरकारी मौद्रिक नीति को सफल बनाना, (७) समाशोधन गृह की सुविधा देना, (८) देश के धातुकोष तथा अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष रखना। इन कार्यों में कौनसा महत्त्वपूर्ण है इस सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। परन्तु वास्तव में ये सभी कार्य परस्पर पूरक हैं। कौनसा महत्त्वपूर्ण है और कौनसा नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

केन्द्रीय बैंक द्वारा साख नियन्त्रण—साख नियन्त्रण का अर्थ है साख की व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार सकोच एवं प्रसार। यदि ऐसा नहीं हो तो मूल्यस्तर में उतार-चढ़ाव होते हैं जिसका परिणाम देश की आर्थिक स्थिति पर होता है। साख नियन्त्रण का हेतु आंतरिक मूल्यस्तर एवं विदेशी विनिमय दर स्थिर रखना, देश की स्वयं-निधि एवं विनियोग पूंजी को बाहर न जाने देना। परन्तु इस कार्य में केन्द्रीय बैंक पूर्णतः सफल नहीं होता क्योंकि वह व्यापारिक साख का नियन्त्रण नहीं कर सकता। दूसरे, केन्द्रीय बैंक के नियन्त्रण में जो समस्याएँ नहीं हैं उनके द्वारा निर्मित साख पर वह नियन्त्रित नहीं कर सकता। केन्द्रीय बैंक निम्न साधनों से साख नियन्त्रण करता है—(१) बैंक-दर, (२) खुले बाजार की क्रियाएँ, (३) वैधानिक रोकड़-निधि में परिवर्तन, (४) साख का अशन, (५) प्रत्यक्ष कार्यवाही, (६) नैतिक प्रभाव।

## अध्याय १२

### समाशोधन गृह

रोकड़ निधि समाशोधन गृहों के अस्तित्व एवं विकास पर भी निर्भर रहती है। इन संस्थाओं द्वारा बैंकों के एक दूसरे पर लिये गये चैका का सन्तुलन होकर केवल शेष राशि का भुगतान केन्द्रीय बैंक पर चैक लिजकर हो जाता है। इस कार्य की सुविधा के लिए प्रत्येक बैंक के कर्मचारी उन पर लिखे गये चैकों का भुगतान देने तथा लेने के लिए अन्य बैंकों के पास न जाते हुए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, जहाँ एक दूसरे पर लिये गये चैका का सन्तुलन होकर केवल शेष राशि एक दूसरे को देनी पड़ती है। यह निया जिस स्थान पर की जाती है उसे समाशोधन गृह कहते हैं। समाशोधन गृह वह संस्था है जो बैंकों के आपसी भुगतान को सुविधाजनक बनाती है। डॉमिंग के शब्दों में समाशोधन गृह "किसी एक स्थान के बैंकों का एक सामान्य संगठन है, जिसका मूल हेतु बैंकों द्वारा निमित परस्पर दायित्व (cross obligations) का भुगतान करना होता है।" अर्थात् समाशोधन गृह किसी भी स्थान में एक ऐसे महाद बैंक का कार्य करते हैं जिसमें वहाँ के निवासियों के लिये होत हैं तथा निक्षेप जमा किये जाते हैं और जब वे योग आपसी भुगतान चैका द्वारा करते हैं तब उनकी राशि व्यक्ति को न दी जाकर केवल एक लम्बे से दूसरे लम्बे में हस्तांतरित (transfer) की जाती है। इस प्रकार वास्तविक उपयोग में मुद्रा कम लगती है।

**समाशोधन गृहों का विकास**—समाशोधन गृहों का उगम मक्खन इंग्लैंड में हुआ। यहाँ की वैकिंग व्यवस्था अधिक उन्नत होने से विशेषतः बैंकों द्वारा ही श्रृणों का भुगतान होता था। अतः सबसे पहिला गृह लन्दन में १७७५ में तथा १८५३ में न्यूयार्क में स्थापित हुआ। इस पद्धति का विकास एवं उगम उसी काल में होना चाहिए जिस समय निक्षेप वैकिंग तथा चैकों का पर्याप्त प्रसार एवं उपयोग होना आरम्भ हुआ। इसके विकास की तीन सीढ़ियाँ होंगी चाहिए —

१ जिस समय बैंकों का भुगतान अन्य बैंकों के पास अपना स्वयं के भेजकर

प्राप्त किया जाता था तथा बैंक अपनी देनदारी का पृथक् पृथक् भुगतान करते थे, इस स्थिति में बैंक केवल अन्य बैंकों से परस्पर लेने देन का विवरण वनावर ही यह भुगतान करते होंगे।

२. जब इन बँकों की पर्याप्त जानकारी नहीं थी तथा उन्होंने प्रत्येक बैंक के पास जाकर अपने भुगतान करने की अपेक्षा, अपने धर्म और समय बचाने के हतु आपस में एक जगह पर मिलना तथा किया तथा वहीं पर लनी देनी निकाल कर आपस में भुगतान करने लग। इस पद्धति में उनको प्रत्येक बैंक के पास जान की आवश्यकता न रही। किन्तु इस स्थिति में आपसी शंका का भुगतान मुद्रा द्वारा ही होता था। इस पद्धति का बका न मान्यता नहीं दी परन्तु इसकी सुविधा एवं सरलता के कारण १७७२ में मान्यता दी। और यह कार्य करना सम्भव हो इसलिए स्थान भी दिया।

३. इस पद्धति का सत्र बैंकों की मान्यता मिलने पर इसमें संचालन एवं नियमन के लिए विषय नियम बनाये गये तभी तीसरी भाग आरम्भ होती है। इस स्थिति के बाद हम आज की दृश्य स्थिति पर समाशोधन गृह का देखन है जिसका संचालन केन्द्रीय बैंक द्वारा होता है तथा बैंक के आपसी भुगतान के लिए केन्द्रीय बैंक में 'समाशोधन गृह लेखा' भी रखा जाता है। इस लेखे पर बैंक लिखकर बैंक अपने परस्पर दायित्व का भुगतान करते हैं।

कार्य प्रणाली—बैंक समाशोधन गृह के सदस्य बनते हैं जिन्हें 'समाशोधक बैंक' कहते हैं तथा निश्चित समय पर प्रतिदिन इनके बतक समाशोधन-गृह में एकत्रित होते हैं। यहाँ पर प्रत्येक सदस्य बैंक का प्रतिनिधि प्रत्येक बैंक की लनी-दनी का हिसाब विषय मुद्रित पत्रा पर बनाते हैं। इन पत्रों को बाह्य-पुस्तक (out book) तथा आन्तरिक यह लेखा बनाने हैं उन्हें 'बाह्यसाधक' (out-clearers) कहते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रत्येक बैंक के छूट हुए बैंकों को जान हैं उन्हें धावक (runners) कहते हैं। ये प्रत्येक बैंक पर लिखे गये बैंकों का वर्गीकरण कर उनको समाशोधन गृह में उचित स्थान पर रखते हैं। बाह्यसाधकों के अतिरिक्त आन्तरिक (in-clearers) भी होते हैं जो आन्तरिक पुस्तक (in book) के मुद्रित पत्रों का भरते हैं। प्रत्येक बैंक की आन्तरिक पुस्तक एवं बाह्य पुस्तक की प्रविष्टियाँ पूर्ण होने पर उनका मन्तव्य कर प्रत्येक बैंक की लनी दनी निकाली जाती है जिसका विवरण प्रत्येक सदस्य बैंक के स्थिति विवरण में लिखा जाता है। यह स्थिति विवरण भी सदस्य बैंक के नाम मुद्रित पत्रा पर बनाया जाता है। प्रत्येक बैंक के लिए इसमें दो खान

होने है—क्रेडिट, तथा डेबिट। इन स्थिति-विवरणों के मन्तुलन से प्रत्येक बैंक को कितना देना है अथवा लेना है यह ज्ञात हो जाता है। यदि किसी बैंक को देना है तो वह केन्द्रीय बैंक के अपने समाशोधन गृह लेखे पर, जिस बैंक को देना है उसके नाम बैंक लिख देता है। इससे देने वाली बैंक के समाशोधन गृह लेखे की राशि कम तथा दूसरे बैंक के समाशोधन गृह लेखे की राशि अधिक हो जाती है।

### स्थिति-विवरण का नमूना

सदस्य बैंक	कुल लेनी	देनी					
		अ	ब	स	द	घ	र
अ	५००००	—	२७०००	१००००	५०००	८०००	—
ब	४००००	१००००	—	५०००	५०००	१००००	१००००
स	३००००	५०००	३०००	—	७०००	६०००	६०००
द	२००००	३०००	१२०००	१०००	—	२०००	२०००
घ	२५०००	७०००	८०००	३०००	२०००	—	५०००
र	३५०००	१००००	४०००	८०००	७०००	६०००	—
योग	२०००००	३५०००	५४०००	२७०००	२६०००	३२०००	२६०००

उक्त विवरण को देखने से प्रत्येक बैंक को एक दूसरे से क्या लेना-देना है इसका स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। जैसे अ की कुल लेनी ५०,००० है तथा उसकी देनी ३५,००० है। इस प्रकार उसे अन्य बैंक से १५,००० रु० प्राप्त होगा जो ऋणी बैंक समाशोधन गृह के नाम देगे तथा समाशोधन गृह उसका भुगतान अ को करेगा जो वह केन्द्रीय बैंक के अपने लेखे में जमा कर देगा। इस प्रकार दिन के अन्त में समाशोधन गृह लेखे का देना-लेना सन्तुलित होकर कुछ भी शेष नहीं रहता। क्योंकि समाशोधन गृह को जो राशि मिलती है उससे अन्य बैंकों की लेनी का भुगतान हो जाता है। इस प्रकार समाशोधन गृह के निर्माण का मूलभूत सिद्धान्त व्यक्तिगत व्यवहार न होते हुए सामुदायिक व्यवहार है तथा परस्पर राशि के आदान प्रदान के बदले उनका मिलान करना है।

समाशोधन गृह से लाभ

(१) सामुदायिक भुगतान—प्रत्येक सदस्य बैंक के लेने-दने का भुगतान सामुदायिक रूप से करता है जिससे आपसी भुगतान सुविधाजनक एवं शीघ्र होता है।

(२) असदस्य बैंकों को लाभ—जो बैंक सदस्य नहीं है वे भी इसका लाभ उठा सकते हैं। कभी-कभी जो बैंक समाशोधन गृह के सदस्य नहीं हैं,

उनके नौको का भुगतान प्राप्त करने के लिए सदस्य बैंक मुल्क भी लेते हैं, जैसे भारत में कनकसे का मेट्रोपोलिटन बैंकिंग एसोसिएशन। जो बैंक सदस्य नहीं हैं यह सप उनसे मुल्क लेता है। उतना ही नहीं, अपितु जो सदस्य नहीं हैं उनके बैंक आदि का भुगतान के लिए लेने में भी इनने सदस्य इन्कार कर देते हैं।<sup>1</sup>

(३) मुद्रा के उपयोग में मितव्ययिता—प्रत्येक सदस्य बैंक की परस्पर देनदारी का सन्तुलन हान से केवल शेपों का ही आदान-प्रदान होता है, और वह भी केन्द्रीय बैंक में जो समाशोधक बैंक हैं, उनके निम्न पर बैंक आदि लिखकर। इससे मुद्रा के उपयोग में मितव्ययिता होती है।

(४) रोकड़ निधि में कमी—समाशोधन गृहों के अस्तित्व एवं विकास के कारण मुद्रा के उपयोग में मितव्ययिता होती है। इससे बैंक को रोकड़ निधि भी कम रखनी पड़ती है तथा वे साख का अधिक निर्माण कर सकते हैं। साख-प्रधान अर्थ-व्यवस्था से ही व्यापारिक व्यवहारों का आदान प्रदान होता है जिससे देश के व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग का विकास होता है।

भारतीय समाशोधन गृह—समाशोधन गृहों के अभाव में किसी भी देश की बैंकिंग पद्धति उन्नत नहीं हो सकती। और न किसी भी देश में समाशोधन गृहों की आवश्यकता ही होती है जब तक उस देश में बैंकिंग का विकास तथा बैंकों का पर्याप्त उपयोग न हो। भारत में समाशोधन गृहों की आवश्यकता १९२० तक प्रतीत नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर बैंकों का उपयोग ही अल्प परिमाण में था। इम्पीरियल बैंक की स्थापना (१९२०) के बाद ही भारत में बैंकिंग को भी अच्छा आधार मिला जिससे स्वतन्त्र पद्धति पर कलकत्ता, बम्बई, रंगून, दिल्ली तथा मद्रास में इम्पीरियल बैंक के निरीक्षण में समाशोधन गृह कार्य करने लगे। सदस्य बैंकों का आपसी भुगतान इम्पीरियल बैंक की स्थानीय शाखा पर लिखे गये बैंकों द्वारा होता था। १९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद मूचीवद्ध बैंकों का रिजर्व बैंक के पास अपने लेखे खोलने पड़े। क्योंकि उनके निक्षेप देनदारी का उ प्रतिशत इम बैंक में रखने का वैधानिक बन्धन लगाया गया तथा उपयुक्त समाशोधन केन्द्रों के सदस्य बैंकों का भुगतान इन लेखा पर बैंक द्वारा हुआ करे यह भी बन्धन लगाया गया। इसीके साथ रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वह समाशोधन गृहों

<sup>1</sup> *A Study of Indian Money Market* by Bimal C. Ghosh, p 135.

के समुचित नियमन के हेतु नियम भी बनाये । यह कार्य रिजर्व बैंक के नियंत्रण में ही होता है ।

भारत में कुल २२ समाशोधन गृह तथा पाकिस्तान में ४ समाशोधन गृह हैं ।

भारत में—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कानपुर, आगरा, अहमदाबाद, अमृतसर, प्रयाग, कालीकट, कोयम्बटूर, पटना, नागपुर, शिमला, बगतौर, देहरादून, जालन्धर, लखनऊ मडुरा, गंगसौर इत्यादि ।

पाकिस्तान में—रावलपिण्डी, साहोर, पेशावर तथा कराँची ।

समाशोधन गृहों की सदस्यता—भारतीय समाशोधन गृह स्वतन्त्र सस्था के रूप में कार्य करने हैं तथा उनके नियम भी स्वतन्त्र हैं । विनियम बैंक, सूचीबद्ध समुक्त रकब बैंक तथा स्टेट बैंक तथा समाशोधन गृहों के सदस्य हैं । अन्य कोई भी बैंक इनका सदस्य तभी बनाया जाता है जब ३ सदस्यों की अनुमति प्राप्त हो । अथवा यदि सदस्यता के लिए पूंजी सम्बन्धी नियम है, तो उतनी चुकता पूंजी होने पर कोई बैंक सदस्य बनाया जा सकता है । परन्तु सदस्य बनाने के पूर्व सदस्य बनने वाले बैंक के स्थिति-विवरण की बिरोपज्ञा द्वारा जाँच करा ली जाती है जिससे उस बैंक की धार्थिक दशा का सदस्य बैंको को समुचित ज्ञान हो सके । कलकत्ता तथा बम्बई जो भारत के प्रमुख समाशोधन गृह हैं, उनके सदस्य वे ही बैंक बनाये जा सकते हैं जिनकी चुकता पूंजी ५ या १० लाख रुपए हो । फिर भी ३ सदस्यों की अनुमति सदस्यता स्वीकार करने के लिए आवश्यक है । जिस बैंक की पूंजी कम होती है वह किसी अन्य बैंक की सिफारिश से आवेदन भेजकर उप-सदस्य बन सकता है । उप-सदस्य के लिए सिफारिश करने वाली बैंक उत्तरदायी होती है जिसे समर्थक बैंक (sponsor bank) कहते हैं । विभिन्न स्थान के समाशोधन गृहों के सदस्यता सम्बन्धी नियम भिन्न भिन्न हैं ।

व्यवस्था—समाशोधन गृहों का प्रबन्ध एक प्रबन्ध समिति करती है । इसमें यदि वहाँ रिजर्व बैंक या उसकी शाखा है तो उसका एक सदस्य, स्टेट बैंक का एक सदस्य तथा विनियम बैंक एवं समुक्त रकब बैंक के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं । किन्तु जहाँ तक नवीन सदस्यों के प्रवेश तथा व्यवस्था का सम्बन्ध है, वहाँ कलकत्ता, बम्बई, मद्रास आदि निर्यात केन्द्रों में विनियम बैंको का अधिक प्रभाव रहता है, जिससे नये बैंको को सदस्य बनने में कठिनाई होती है । समाशोधन गृहों का निरीक्षण जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखा है वहाँ रिजर्व बैंक करता है अन्यथा स्टेट बैंक करता है । प्रत्येक सदस्य बैंक को

समाशोधन गृह के संचालन के लिए निरीक्षक बैंक के पास एक निश्चित राशि जमा करनी होती है, जिस पर समाशोधन गृह के बैंक आदि लिखकर पारस्परिक भुगतान हो सके। जहाँ पर समाशोधन गृह नहीं है वहाँ पारस्परिक भुगतान स्टेट बैंक के माध्यम से किया जाता है।

समाशोधन गृह के कार्य के लिए आवश्यक क्लर्कों की पूर्ति स्टेट बैंक तथा रिजर्व बैंक करते हैं।

भारत के सबसे अधिक समाशोधन गृह बम्बई तथा कलकत्ता में हैं जहाँ दिन में दो बार पारस्परिक भुगतान होता है किन्तु रविवार को एक बार ही होता है। भारत में सबसे विकसित समाशोधन गृह कलकत्ते का है जहाँ दो समाशोधन गृह हैं। प्रथम कलकत्ता समाशोधन बैंक संघ (Calcutta Clearing Bank Association) जो केवल वहाँ के बड़े-बड़े बैंकों को ही पारस्परिक भुगतान की सुविधाएँ देता है जो इसके सदस्य हैं तथा कुछ उप-सदस्यों को जिनकी शाखा कलकत्ते में है एवं धुक्ता पूंजी १० लाख रुपये है। इसका नाम "कलकत्ता समाशोधन गृह" है।

दूसरे समाशोधन गृह का नाम "मेट्रोपॉलिटन समाशोधन गृह" है। यह उन बैंकों के संचालन में है जो कलकत्ता समाशोधन गृह के सदस्य एवं उप-सदस्य नहीं हैं। यह १९२९ में खोला गया था एवं इसके सदस्य सूची-बद्ध बैंक नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त पिछले ८-१० वर्षों से कलकत्ता में पारस्परिक भुगतान की एक और पद्धति प्रचलित है जिसे 'प्रारम्भिक समाशोधन' (pioneer clearing) गृह कह सकते हैं। इस पद्धति को कोई भी शासकीय मान्यता नहीं है। इसमें जो बैंक समाशोधन गृह का सदस्य नहीं हैं वह सदस्य बैंक के साथ एक समझौता कर लेता है जिसके अनुसार गैर-सदस्य बैंक पर लिखे गये सब बैंकों आदि का भुगतान सदस्य बैंक समाशोधन गृह से करा सकता है। गैर-सदस्य बैंक के बैंक पर जिस सदस्य बैंक द्वारा भुगतान होगा यह भी छपा रहता है।<sup>१</sup> भारतीय समाशोधन गृह के दोष

(१) असन्तोषप्रद व्यवस्था—भारत में अभी तक परस्पर भुगतान की सन्तोषजनक व्यवस्था नहीं है क्योंकि वर्तमान व्यवस्था स्थानीय बैंकों आदि तक ही सीमित है। अन्य स्थान के बैंकों का सग्रहण आदि उन्हीं स्थानों से प्राप्त

<sup>१</sup> A Study of Indian Money Market by Bimal C Ghosh, p. 138

किया जा सकता है जिससे बैंकों के संग्रहण एवं भुगतान में असुविधा एवं विलम्ब होता है।

(२) बड़े व्यापारिक केन्द्रों में समाशोधन गृह की कमी—अनेक बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों में पर्याप्त बैंकों के होते हुए भी वहाँ पर समाशोधन गृह की अभी तक स्थापना नहीं हुई है जो व्यापारिक उन्नति के लिए आवश्यक है।

(३) कार्य-प्रणाली में विविधता—समाशोधन गृह की कार्य प्रणाली एवं संचालन में भिन्न भिन्न केन्द्रों में विविधता है जो वैकिण-विकास की दृष्टि से समान होना आवश्यक है।

(४) सदस्यता सम्बन्धी कठोर नियम—समाशोधन गृहों की सदस्यता के नियम अधिक कठोर हैं, जिससे अनेक अच्छे अच्छे बैंक भी सदस्य नहीं हो सकते। अतः इनमें मशोधन की आवश्यकता है।

रिजर्व बैंक पर समाशोधन गृह सम्बन्धी कार्यवाही की वैधानिक जिम्मेदारी होती है। उसने अभी तक इस दिशा में उल्लेखनीय कार्यवाही नहीं की। अतः वैकिण विकास की दृष्टि से रिजर्व बैंक को चाहिए कि वह इन दोषों का निवारण एवं पारस्परिक भुगतान के लिए समुचित सुविधाएँ प्रदान करे। इससे मुद्रा के उपयोग में मितव्ययता आकर रोकथाम का परिमाण भी घटेगा एवं व्यापार को अधिक सख्त-सुविधाएँ भी मिल सकेंगी।

### सारांश

समाशोधन गृह किसी एक स्थान के बैंकों का ऐसा सामान्य संगठन है जिसका मूल हेतु बैंकों द्वारा निमित्त परस्पर देनदारी का भुगटान करना होता है। इनका विकास सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ जहाँ पहला समाशोधन गृह १७७५ में तथा न्यूयार्क में १८५३ में स्थापित हुआ। इनके विकास की तीन सीढ़ियाँ हैं—

(१) बैंक अपने-अपने बलक भेजकर अपनी देनदारी का पृथक् पृथक् भुगटान करते थे।

(२) उच्च एवं बलकों की अच्छी जानकारी होने लगी तथा इन्होंने अपने धन एवं गन्धर्व वस्तुओं के लिए एक स्थान पर मिलना निश्चित किया और वहाँ वे अपनी परस्पर लेनी देनी निकाल कर भुगटान करने लगे। इस पद्धति को १७७३ में बैंकों ने मान्यता दी।

(३) उक्त पद्धति बैंकों द्वारा स्वीकृत होने पर इस हेतु आवश्यक नियम भी

बनाये गये तथा तीसरी सीढ़ी आरम्भ हुई जहाँ से उसकी वर्तमान स्तर पर उन्नति हुई ।

कार्य-प्रणाली—समाशोधन गृह के बैंक सदस्य होते हैं जिनके बलक निश्चित समय पर समाशोधन गृह में आते हैं तथा अपनी लेनी-देनी का हिसाब निश्चित छुपे हुए फॉर्मों पर बनाते हैं । इनसे प्रत्येक बैंक की गृथक् लेनी एवं देनी निकाल कर उसे प्रत्येक सदस्य बैंक के स्थिति-विवरण में लिखा जाता है । इनसे प्रत्येक बैंक की अन्य बैंकों से कितना लेना तथा देना है यह मालूम होता है; जिस राशि के बैंक वे अपने समाशोधन गृह पर काटते हैं तथा आपसी भुगतान करते हैं ।

लाभ—सामुदायिक भुगतान, असहाय बैंकों को भी लाभ, मुद्रा के उपयोग में मितव्ययिता, बैंकों की कम रोकड़ निधि की आवश्यकता ।

भारतीय समाशोधन गृह—इम्पीरियल बैंक की स्थापना के बाद भारत में बैंकिंग विकास को बल मिला जिससे इम्पीरियल बैंक के मार्गदर्शन में बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बिल्ली तथा रगून में समाशोधन गृह कार्य करने लगे । १९३५ में रिजर्व बैंक ने यह कार्य अपने हाथ में लिया । इस समय भारत में २२ समाशोधन गृह कार्य कर रहे हैं । जो रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में हैं ।

इनके सदस्यता एवं कार्य-प्रणाली सम्बन्धी स्वतन्त्र नियम हैं तथा सूची-बद्ध बैंक, विनिमय बैंक एवं स्टेट बैंक इनके सदस्य हैं, नये सदस्य का समावेश के बहुमत से होता है परन्तु सदस्यता के लिए बैंक को चुकता पूंजी सम्बन्धी नियम पालन करना बाध्य है । इनकी व्यवस्था प्रबन्ध समिति करती है जिसमें रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, विनिमय बैंक, सयुक्त स्कंध बैंकों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं । पारस्परिक भुगतान हेतु प्रत्येक सदस्य बैंक को रिजर्व बैंक के पास अपना एक समाशोधन गृह लेखा खोलना पड़ता है । और जहाँ समाशोधन गृह नहीं हैं वहाँ स्टेट बैंक के माध्यम से पारस्परिक भुगतान होता है । समाशोधन गृह के आवश्यक कार्य के लिए बलकों की पूर्ति स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक करती है । भारत में बम्बई एवं कलकत्ते में सबसे अधिक समाशोधन गृह हैं ।

भारतीय समाशोधन गृहों में निम्न दोष हैं—(१) परस्पर भुगतान की असन्तोषजनक व्यवस्था, (२) बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्रों में समाशोधन गृह का अभाव, (३) कार्य-प्रणाली में विविधता, (४) सदस्यता सम्बन्धी कठोर नियम । इन दोषों का निवारण रिजर्व बैंक को करना चाहिए जिससे मुद्रा के उपयोग में मितव्ययिता होकर बैंकों की रोकड़ निधि में मितव्ययिता हो ।

## अध्याय १३

# भारतीय बैंकिंग का विकास

व्यापारिक बैंक अथवा मयुक्त स्वस्थ बैंक उनको कहते हैं जो देश की व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रगति के लिए अल्पकालीन ऋणों तथा साव की पूर्ति करते हैं। भारत में यह कार्य केवल व्यापारिक बैंको तक ही सीमित नहीं है बल्कि स्टेट बैंक, विनिमय बैंक तथा अन्य स्ववैधीय बैंक भी यह कार्य करते हैं। इनकी कार्यशील पूँजी का अधिकतर भाग जनता के निक्षेपों से तथा कुछ भाग अश पूँजी के निर्गमन से प्राप्त होता है। यह हम कह सकते हैं कि भारत में रिजर्व बैंक भी, सूचीबद्ध बैंक के साथ जहाँ तक ऋणों का लेन देन करता है, व्यापारिक बैंकिंग का कार्य करता है। व्यापारिक बैंक का आजकल पत्र चालन का अधिकार नहीं है तथा वे केवल अल्पकालीन ऋण एवं साव की ही पूर्ति करते हैं।

## संयुक्त स्वस्थ बैंको का भारत में विकास

प्रथम युग (१८०६ तक)—भारत में बैंकिंग व्यापार प्रगति पर था तथा स्वदेशीय बैंक भारत की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। इनके व्यापार को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आने से ब्रह्मा समा क्योंकि अंग्रेजी तथा अंग्रेजी व्यापार पद्धति से अपरिचित होने से वे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सके। इससे अंग्रेजी व्यापार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर अभिकर्ता गृहों (agency houses) की स्थापना की गई। ये अन्य व्यापार के साथ ही जनता में निक्षेप स्वीकार करते थे तथा व्यापारिक एवं औद्योगिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते थे। प्रारम्भ काल में अभिकर्ता गृहों की कोई पूँजी नहीं थी परन्तु वे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नौकरों की राशि से, जो निक्षेप रूप में जमा रहती थी, बैंकिंग व्यवसाय करते थे। दूसरे स्वदेशीय बैंकिंग को मुगल साम्राज्य के पतन में भी गहरी हानि हुई क्योंकि नबावों और बादशाहों को जो ऋण उन्होंने दिये थे वे डूब गये। इससे जनता के निक्षेपों की माँग आने पर वे भुगतान न कर सके तथा उनसे जनता का

विश्राम भी उठ गया। फलतः अंग्रेजी अभिकर्ता गृहों की जड़ें मजबूत होने लगी। इन्हीं को भारत में मयुक्त स्कन्ध बैंकों की स्थापना का ध्येय है।

इन्हीं में से कुछ अभिकर्ता गृहों ने अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए भारत में मयुक्त स्कन्ध बैंकिंग की स्थापना का नेतृत्व किया, जिसमें से अलेग्जेंडर एण्ड कम्पनी ने १७७० में सर्वप्रथम यूरोपीय बैंक “दी बैंक ऑफ हिन्दुस्तान” की स्थापना की। इसी प्रकार पामर एण्ड कम्पनी ने ‘क्लक्ता बैंक’ की स्थापना की। इन दोनों में से बैंक ऑफ हिन्दुस्तान का १८३२ में विलियन (failure) हुआ। इस प्रकार १८ की शताब्दी में अनेक बैंकों की स्थापना हुई परन्तु सब का अन्त ही गया।

१७८५ के पूर्व-स्थापित बैंकों में ‘बंगाल बैंक’ ही एक ऐसा बैंक था जिसका अभिकर्ता गृहों में कोई सम्बन्ध न था तथा इसकी पत्र-मुद्राएँ भी चलन में थी। १७८६ में सीमित देनदारी (limited liability) पर आधारित ‘दी जनरल बैंक ऑफ इण्डिया’ नामक पहला बैंक स्थापित हुआ।<sup>1</sup> इसे पत्र-मुद्रा-चलन का अधिकार भी था। ये दोनों ही बैंक एक दूसरे के प्रतियोगी थे तथा इनमें तीव्र स्पर्धा थी। १७८७ में ‘जनरल बैंक ऑफ इण्डिया’ को सरकार का बैंकर नियुक्त किया गया तथा उसकी पत्र-मुद्रा को सरकार ने मान्यता दी। इससे बंगाल बैंक को व्यापारिक क्षति पहुँची। इसके साथ ही लॉर्ड कनिंघम के आदेश ने बंगाल बैंक को एक और धक्का दिया, जिससे कोई भी सरकारी कर्मचारी, बैंक का कर्मचारी अथवा व्यवस्थापक मचालक आदि नहीं हो सकता था। किन्तु आगे चलकर ये बैंक भी डूब गये। इस प्रकार यूरोपीय बैंकिंग की स्थापना का पहला युग समाप्त हुआ।

१८१३ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार का अन्त हुआ, जिसमें अभिकर्ता गृहों के व्यापार को भी चोट पहुँची तथा निक्षेपों के अधिक निबालने में इन गृहों का १८३२ के लगभग अन्त होने लगा।

द्वितीय युग (१८०६-१८६०)—प्रीमीडेंगी बैंकों की स्थापना से मयुक्त स्कन्ध बैंकिंग का दूसरा युग आरम्भ होता है। इस युग में केवल हिन्दुस्तान बैंक ही ऐसा बैंक था जिसकी १८०६ तक अप्रतिस्पर्धात्मक प्रगति होती रही। १८०६ में अवमूल्यित चलन पद्धति के दोष दूर करने के लिए ‘बैंक ऑफ क्लक्ता’ नाम का पहला बैंक ईस्ट इण्डिया कम्पनी के आज्ञापत्र (charter) द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद क्रमशः १८४० और १८४३ में बैंक ऑफ बम्बई तथा बैंक

<sup>1</sup> *Law & Practice of Banking in India* by M. L. Tannan.

ऑन मद्रास की स्थापना हुई। ये तीनों प्रेसीडेंसी बैंक ईस्ट इण्डिया कम्पनी की आर्थिक आवश्यकताओं तथा देश के अन्तर्गत व्यापार की पूर्ति के लिए स्थापित हुए। इन बैंकों को पत्रमुद्रा-चलन का अधिकार था किन्तु १८६२ में यह अधिकार उनसे छीन लिया गया। किन्तु इनकी सरकार की ओर से पत्र चलन-व्यवस्था तथा प्रेसीडेंसी शहरों में सरकारी कोषों की व्यवस्था का भार सौंपा गया। ये बैंक अनेक शक्तों के होने हुए भी १९२० तक पूर्ण सफलता से कार्य करते रहे तथा १९२१ में इम्पीरियल बैंक में तीनों ही प्रेसीडेंसी बैंकों का समावेश हो गया।

**तृतीय युग (१८६०-१९१३)—**१८६० में भारत में सर्वप्रथम सीमित देनदारी सिद्धान्त को वैधानिक मान्यता मिली। इसके पूर्व १७८६ में स्थापित जनरल बैंक ऑफ इण्डिया ही अपवाद के लिए एक सीमित देयता वाली बैंक थी वह भी यूरोपीय व्यवस्था में। इस प्रकार १८६३ से यूरोपीय व्यवस्था में बैंक ऑफ़ अपर इण्डिया (१८६३), अलाहाबाद बैंक (१८६५), अलाहम बैंक ऑफ़ हिमाला (१८७४) आदि बैंकों की स्थापना हुई जिनमें अलाहम बैंक ऑफ़ हिमाला का विलियन १६२३ में हुआ। १८७४ तक सीमित देनदारी वाली बैंकिंग कम्पनियों की संख्या १४ हो गई किन्तु इनमें से अधिकांश बैंक यूरोपीय व्यवस्था में ही थे। भारतीय व्यवस्था में संचालित सबसे पहला बैंक अवध कमिशनर्स बैंक था, जिसकी स्थापना १८८१ में हुई। इसके बाद क्रमशः १८८४ और १९०१ में पंजाब नेशनल बैंक तथा पीपुल्स बैंक ऑफ़ इण्डिया की स्थापना हुई। इनमें दूसरे बैंक का विलियन १९१२ में हुआ, इस समय इसकी कुल धावाएँ १०० तथा निक्षेप १२५ लाख रुपये से अधिक थे। १९०५ में स्वदेशी आन्दोलन हुआ, जिससे अनेक नये बैंकों की स्थापना हुई। इनमें बम्बई का बैंक ऑफ़ इण्डिया, दी इण्डियन बैंक ऑफ़ मद्रास, दी मेट्रोल बैंक ऑफ़ इण्डिया, दी बैंक ऑफ़ बड़ोदा तथा बैंक ऑफ़ मैसूर आज के सात बहुत बड़ी बैंकों में हैं।

इस अवधि (१९०५-१९१३) में जिन बैंकों की चुकता पूंजी तथा निधि मिलाकर ५ लाख रु० से अधिक थी, उनकी संख्या ६ से बढ़कर १८ हो गई। इसके अतिरिक्त अनेक छोटे-छोटे बैंकों की भी स्थापना हुई, जिनकी संख्या १६१३ में ५०० थी। इसी अवधि में स्थापित अन्य बैंकों के नाम नीचे दिये हैं, जिनका विलियन १९१३-१७ के बैंकिंग-मकट में हुआ—

दी इण्डियन स्पेशी बैंक, दी बंगाल नेशनल बैंक, क्रेडिट बैंक ऑफ़ इण्डिया, दी स्टैंडर्ड बैंक, दी बाम्बे मर्चेंट्स बैंक तथा बैंक ऑफ़ अपर इण्डिया लि०।

## १९१३-१७ का बैंकिंग-संकट एवं उसके कारण

१९१२ में भारतीय मुद्रा-मण्डी की अस्थिरता के कारण बैंकिंग मकट का आरम्भ हुआ क्योंकि १९१२-१३ के लगभग हमारी मुद्रा-मण्डी में कमजोरी के चिह्न प्रतीत होने लगे। उस समय प्रेसीडेन्सी बैंको की व्याज दर ७%—८% थी। इस कमजोरी का प्रमुख कारण मुद्रा मण्डी के विभिन्न अंगों में मगड़न का अभाव तथा साख एवं मुद्रा-पद्धति में लोच की कमी था। इस काल में मुद्रा प्रारम्भ होने में सरकार ने मुद्रा-मण्डी से धन खींचना शुरू किया। परिणामस्वरूप मुद्रा एवं माय की कमी हो गई तथा व्याज की दर ऊँची हुई, जो स्वाभाविक ही था। व्याज दर बढ़ने से बैंको ने असीमिति मात्रा में ऋण देना प्रारम्भ किया जिससे अधिक लाभ कमाया जाय। बैंकिंग पद्धति पर इसका प्रभाव बुरा हुआ क्योंकि असीमित ऋण के कारण रोकड़ निधि कम हो गई। माय ही युद्ध के कारण बैंको के स्थायित्व में जनता का बिस्वास कम होने लगा तथा निक्षेपो की माँग होने लगी। इसका पहिला घक्का पीपुल्स बैंक ऑफ इण्डिया को लगा जिसने अपने दरवाजे मिनम्बर १९१३ में बन्द किये। इस बैंक के विलियन में जनता के बिस्वास को और भी घक्का लगा, और एक के बाद दूसरा बैंक बन्द होने लगा। यह मकट १९१७—१८ तक अबाधित रूप से चलता रहा। यह मकट भारत के बैंकिंग इतिहास में सबसे बड़ा संकट था, जिसमें अनेक बैंक बूब गये जिनकी कुल सख्या ३७ थी। इनकी चुक्ता पूँजी एवं निधि १७५ लाख रुपये थी। यह पूँजी १९१७ के भारतीय बैंको की चुक्ता पूँजी की ५०% थी।

## बैंक विलियन के कारण

१ अयोग्य प्रबन्ध—स्वदेसी आन्दोलनों के परिणामस्वरूप बैंका की स्थापना ऐसे व्यक्तियों द्वारा हुई जिनको इस क्षेत्र का न तो पूर्ण अनुभव ही था और न वे भूतपूर्व बैंकिंग-मकटों से परिचित थे। इन्होंने बैंकिंग सिद्धान्तों का पूर्णतः पालन नहीं किया। उदाहरणार्थ, दो क्रेडिट बैंक ऑफ इण्डिया, जिसका मैनेजर यह भी नहीं जानता था कि वित्त क्या होता है।

२ पूँजी की कमी—इन्होंने जनता को धाखा देने के लिए अपनी अधिकृत पूँजी के बड़े-बड़े आकड़े प्रकाशित किये तथा प्राथित और चुक्ता पूँजी को छिपाकर रखा जिसका अनुपात अधिकृत पूँजी में बहुत ही कम था। अतः वायसील पूँजी के लिए उन्हें जनता के निक्षेपो पर निर्भर रहना पड़ा। उदाहरणार्थ पूना बैंक पूना, जिसके विज्ञापन में अधिकृत पूँजी तथा प्राथित पूँजी के आँकड़े ₹३ करोड़ और ५० लाख रुपये क्रमशः दिये गये थे परन्तु १०० रु० के

प्रत्येक अंश पर ८५ रु० अदत्त थे।<sup>१</sup> इसी प्रकार अन्य बैंकों के निक्षेप चुकता पूंजी स कई गुने अधिक थे एवं उन्होंने अपने थोड़े से काल में ही अनेक शाखाएँ खोल रखी थी, जैसे अमृतसर नेशनल बैंक लि०, पायोनियर बैंक लि०, हिन्दुस्तान बैंक लि० मुल्तान आदि।

३ गलाकाट स्पर्धा—अधिकाधिक निक्षेपों को आकर्षित करने के लिए इनको निक्षेपों पर अधिक व्याज देना और अधिक व्याज देने के लिए अधिक लाभ कमाना भी आवश्यक था। इसलिए इन बैंकों ने अपनी राशि का विनियोग दीर्घकालीन तथा औद्योगिक ऋणों की पूर्ति में किया। परिणामस्वरूप निक्षेपकों की ओर से ज़र माँग होना लगी तब भुगतान करने में बैंक असमर्थ रहे और उन्हें अपने दरवाज़े बन्द करने पड़े। अर्थात् उन्होंने अल्पकालीन निक्षेपों से दीर्घकालीन औद्योगिक ऋणों का प्रदाय किया। उदाहरणार्थ, दी पीपुल्स बैंक ऑफ़ लाहौर, टाटा इण्डस्ट्रियल बैंक तथा अमृतसर बैंक जो क्रमशः १९१३, १९२३ और १९१४ में बिलीन हुए। यह व्यापारिक बैंकिंग सिद्धान्तों के विरुद्ध था।

४ निक्षेपों का सट्टे में विनियोग—अनेक बैंकों ने निक्षेपों का विनियोग सट्टे में किया जो बैंकिंग व्यापार के लिए खतरनाक एवं अवाछनीय है। जैसे वी इण्डियन स्पेशी बैंक लिमिटेड, सचालको ने सोने, चाँदी, मोती आदि के सट्टे किये। इसके अतिरिक्त इस बैंक ने ऐसे अनेक ऋण दिये जो वास्तव में व्यापार की सुरक्षा की दृष्टि से देना अवाछनीय था। विभिन्न कारणों से होने वाली इसकी हानि निम्न प्रकार थी —

चाँदी के सट्टे में हानि	१११ लाख
मोती से रक्षित ऋणों में हानि	३६ लाख
बदला व्यवहारों में हानि	१४ लाख
अवाछनीय ऋणों में हानि	४ लाख

कुल हानि १६५ लाख<sup>२</sup>

इस बैंक के विषय में आरम्भ से ही मालूम था कि यह सट्टे में फँसा है किन्तु इसके मचालक यह ठिपकते रहे। इतना ही नहीं अपितु उन्होंने १९०९ से

<sup>१</sup> *Modern Banking in India* by S K Muranjan, pp 336-362

<sup>२</sup> *Modern Banking in India* by S K Muranjan, p 353

बैंक को कोई लाभ न होते हुए भी पूंजी में से लगभग २२ लाख रुपये का लाभ वितरण किया जो लेखापालन (accounting) सिद्धान्तों के विरुद्ध था।

५ संचालकों द्वारा बैंक के साधनों का निजी स्वार्थ में उपयोग—  
अनेक संचालक एवं प्रबन्धक स्वार्थी भी थे, जिन्होंने अपने द्वारा संचालित बैंकों की राशि में अन्य स्वचालित उद्योगों को ऋण दिये थे। इतना ही नहीं, अपितु उन्होंने कपट एवं बेईमानी से, झूठे हिमाव दिखाकर अपने बैंक की स्थिति अच्छी दिखाई थी। उदाहरणार्थ, काठियावाड़ एण्ड अहमदाबाद कार्पोरेशन। इसके विलियन के लिए जब न्यायालय में आज्ञा दी गई तो अन्वेषकों (auditors) ने रिपोर्ट देने में मना किया और जब न्यायालय की ओर से अन्य अन्वेषकों की नियुक्ति की गई तो वे इस बैंक की लेखा पुस्तकें आदि भी प्राप्त न कर सके। दूसरे, बी मायोनियर बैंक बम्बई की चुकना पूंजी भी काल्पनिक थी क्योंकि जो पूंजी चुकना दिखाई गई थी वह अगपारियों को ऋण दी गई थी। तीसरे, क्रेडिट बैंक ऑफ इण्डिया का व्यवस्थापक जाफर ओमव था। इसने १९१३ में विलियन के समय न्यायालय में यह भाग्य किया कि उसे बैंकिंग एवं लेखा-पालन के सिद्धान्तों का किञ्चि भी ज्ञान न था। इसने यह भी कहा कि बैंकिंग व्यवसाय की प्रगति के लिए यह दिखावा (window-dressing) किया गया था जिसके लिए अन्वेषक जिम्मेदार थे।

६ अनेक बैंक केवल दुर्भाग्य के कारण बन्द हुए— क्योंकि किसी न किसी कारण से जनता का विश्वास उनसे उठ गया किन्तु इनमें भी व्यवस्था की किञ्चित् गिरिलता थी ही। इस प्रकार केवल उद्भव से निम्न बैंकों का विलियन हुआ।

बैंक ऑफ अपर इण्डिया, मेरठ (१८६३)—यह १९१३ तक प्रगति दिखाने के बाद भी १९१४ में विनीत हो गया। इसके अगपारियों एवं निक्षेपकों को पूर्ण राशि मिली। इस बैंक के दिये हुए सब ऋण सुरक्षित थे परन्तु पीपुल्स बैंक के विलियन में इसको भी धक्का लगा जिसमें ७८ लाख रुपये के निक्षेपों का भुगतान किया गया। परन्तु युद्ध प्रारम्भ होने ही जो हमारा धक्का लगा उसे यह सहन न कर सका और अक्टूबर १९१४ में इसने भुगतान रोक दिया।

अलायंस बैंक ऑफ शिमला (१८७४)—इसका प्रमुख कारण इसके लदन स्थित अभिकर्ता बोन्टन ब्रदर्स की अविद्विमान्यता थी। १२० लाख का ऋण नहीं दिया, इस बचनानी के पैमाने ही इनको अप्रैल १९२३ में भुगतान रोकना पड़ा तथा विलियन हुआ।

उक्त कारणों से अनेक बैंक इस मकद में विलीन हुए। इसके अतिरिक्त बैंक विनियम के निम्न कारण भी हैं —

७ समुचित बैंकिंग अधिनियम का अभाव—यह भी बैंकिंग के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, जिससे जनता का बैंकों में विश्वास बढ़ जाता है तथा व्यवस्था भी अच्छी रहती है।

८ केन्द्रीय बैंक न होना—देश में समुचित बैंकिंग विकास के लिए केन्द्रीय बैंक का अभाव या जो इन अवाधनीय प्रवृत्तियों को नियन्त्रित कर सके तथा सबट के समय डूबते हुए बैंकों को सहायता प्रदान करे।

९ अशायरियों का अज्ञान एवं अरक्षि—अधिकतर बैंकों के हिस्सेदार बैंकिंग व्यापार में अनभिज्ञ थे तथा उन्होंने अपने बैंकों की समुचित प्रगति की ओर न ध्यान ही दिया और न उनके कष्ट को जानने का कष्ट उठाया।

बैंकिंग-मकद का परिणाम—बैंकिंग-मकद के कारण कुछ समय के लिए बैंकों में जनता का विश्वास उठ गया परन्तु युद्ध के द्वितीय अर्द्धभाग में परिस्थिति सुधरने लगी। इस मकद का सबसे अच्छा परिणाम यह हुआ कि देश की जनता एवं सरकार को यह अनुभव हुआ कि समुचित बैंकिंग विकास के लिए बैंकों का नियन्त्रण बहुत आवश्यक है। फिर भी १९२६ तक इस दशा में कोई कार्यवाही नहीं हुई। १९३० में बैंक विनियम के कारणों की जाँच के लिए केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति की नियुक्ति हुई। इस समिति का उद्देश्य बैंकों के विलियन के कारणों की जाँच कर बैंकिंग क्लेवर को मजबूत बनाने के लिए निपारिर्ण करना था।

इस समिति ने (१) केन्द्रीय बैंक की स्थापना तथा बैंकिंग विधान बनाने पर जोर दिया। फलतः १९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना की गयी जो देश का केन्द्रीय बैंक बना।

(२) भारतीय कम्पनी अधिनियम में १९३६ में संशोधन किये गये। इन संशोधनों के अनुसार बैंकिंग की परिभाषा, उनके निषिद्ध कार्य, उनका नियन्त्रण, प्रबन्ध अभिकर्ता एवं संचालकों की नियुक्ति आदि सम्बन्धी नई धाराएँ जोड़ी गईं।

(३) समुक्त स्कन्ध बैंकों के संचालकों एवं प्रबन्धकों को भी यह शिक्षा मिली कि बैंकिंग विकास की प्रारम्भिक अवस्था में अधिक रोकड़ निधि तथा सम्पत्ति में तरलता रखने की अत्यन्त आवश्यकता है, विशेषतः भारत जैसे देश में, जहाँ बैंकों का प्रसार बहुत कम है।

प्रथम महायुद्ध के प्रथम अर्द्ध भाग में बैंकिंग संकट आया जिससे जनता का विश्वास घँका सा उठ गया। इससे अधिक राशि में निक्षेप लिए जाने लगे तथा ऋणपूर्ति की राशि घट गयी। परिणामस्वरूप साम्य का नियन्त्रण भी हा गया। परन्तु इस विश्वास का क्रम अन्त हुआ तथा वक्का में पुनः जनता का विश्वास आ गया। द्वितीय अर्द्ध भाग में देश की आर्थिक प्रगति भी सन्तोषजनक हुई जा १९२१ तक रही। युद्ध के कारण कुछ मात्रा में मुद्रा-स्फीति हुई, जनता के पास अधिक धन हा गया और वक्का के निक्षेपों में वृद्धि होने लगी। इससे बैंक की स्थापना को पुनः प्रोत्साहन मिला तथा नव-नव वक्का की स्थापना होने लगी। इस अवधि में वित्तपन ओद्योगिक वक्का की स्थापना हुई जिसमें टाटा इण्डस्ट्रियल बैंक का नाम उल्लेखनीय है। इसका विलियन १८२३ में हुआ। १९०१ तक जिन बैंकों की चुक्ता पूँजी एवं निधि ५ लाख रुपये से अधिक थी उनकी संख्या २५ हा गई और चुक्ता पूँजी एवं निधि तथा निक्षेपों की राशि क्रमशः ११ करोड़ और ७१ करोड़ रुपये हा गई। इसी समय केन्द्रीय बैंक का अभाव दूर करने तथा साक्ष्य नियन्त्रण करने के लिए १९२१ में बम्बई, मद्रास और बङ्गाल के प्रसीडमी बैंकों का एकीकरण से इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई। इसकी चुक्ता पूँजी एवं निधि ६७ करोड़ तथा निक्षेप (जनता ६० करोड़ + सरकार ७ करोड़) ७३ करोड़ ६० के ध एवं ७० लाखों थी।

१८२१ के बाद आर्थिक मन्दी आई और मुद्रा-स्फीति भी किया जाने लगा जिससे पुनः बैंकिंग संकट आया तथा वक्का का विलियन होने लगा। आर्थिक मन्दी के कारण निक्षेप भी घटने लगे। ६० करोड़ ६० (१९२१ में) से घटकर १९२४ में केवल ५५ करोड़ ६० रह गये। इस अवधि में छोट वक्का में बचत मिला कर ८६७ धक वन्द हुए जिनकी चुक्ता पूँजी लगभग ६ करोड़ ६० थी। इन अवधि में टूटने वाले बैंकों में टाटा इण्डस्ट्रियल बैंक तथा अवध कमर्शियल बैंक प्रमुख थे। इनमें में पहल का समावेश अलाहाबाद बैंक में हुआ। १९२४ में १९३० तक बैंकिंग स्थिति में कुछ सुधार हुआ परन्तु निक्षेपों में उल्लेखनीय प्रगति न हुई अतः वक्का को कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा। १९३२ के बाद बैंक के निक्षेपों में वृद्धि होने लगी तथा बैंकिंग परिस्थिति भी समुचित रूप से सुधरती गई। १९३२ में पोपुल्स बैंक ऑफ नादन इण्डिया तथा १९३६ में ट्रावन्कोर नेशनल बैंक एवं क्वीलोम नेशनल बैंक वन्द हुए। इन बैंकों के विलयन में अन्य बैंकों पर बुरा प्रभाव हुआ तथा निक्षेप कम होने लगे किन्तु बैंकों की शाखाओं का विस्तार ही होता गया। १९२० से १९३९ तक १७ वर्षों में कुल बैंकों की शाखाएँ तिगुनी हा गई।

यह दूसरा वैकिंग मकट था परन्तु इसकी तीव्रता १९१३-१७ के सकट से कम थी। इस सकट के कारण केवल दक्षिण भारत के बैंकों का ही विलियन हुआ जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण ट्रावनकोर नेशनल बैंक तथा कवीलोन बैंक थे।

इन बैंकों के विलियन से यह प्रमाणित हो गया कि १९३६ में किये गये संशोधन बैंकों का विलियन रोकने के लिए अधूरे थे। इसलिए १९४२ और १९४४ में भारतीय कम्पनी अधिनियम में पुन संशोधन किया गया।

**बैंकों का अव्यवस्थित विकास**

यहाँ यह अवश्य मानना पड़ेगा कि इस अवधि में जो वैकिंग विकास हुआ वह अव्यवस्थित था क्योंकि देश में माहसी व्यक्तियों का अभाव था जो इस व्यापार को अपनाते। जो लोग इस व्यवसाय में थे भी उन्होंने बैंकिंग बिनाम क्षेत्र का समुचित अध्ययन नहीं किया था, फलतः उन्होंने उन्हीं स्थानों पर शाखाएँ खोली, जहाँ पहिले से ही अन्य बैंकों की शाखाएँ थी। अथवा जहाँ पांच महान् बैंकों की शाखाएँ थी वहीं पर अन्य छोटे बैंकों ने भी अपनी शाखाएँ खोली। दूसरे, देश के पांच महान् अथवा अन्य बड़े-बड़े बैंक ने इम्पीरियल बैंक का अनुकरण किया अर्थात् जहाँ-जहाँ इम्पीरियल बैंक ने अपनी शाखाएँ खोली, वही पर बड़े-बड़े बैंकों ने अपनी शाखाएँ खोली। तीसरे, भारत में जो विदेशी बैंक थे, उन्हें भारत के व्यवस्थित बैंकिंग विकास से तो मतलब था ही नहीं, उन्हें तो मतलब था अपने लाभ से। अतः उन्होंने लाभ का उद्देश्य सामने रखकर उन्हीं स्थानों पर शाखाएँ खोली जो बड़े-बड़े व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र थे।

इस अव्यवस्थित विकास से देश में बैंकों की संख्या उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास, बंगाल और पंजाब में तो बढ़ती गई परन्तु बिहार उड़ीसा, मध्य प्रदेश में इनकी भारी कमी रही और विशेषतः देशी रियासतों में। क्योंकि बैंक बैंधानिक अडचनों के कारण देशी रियासतों में शाखाएँ खोलने में हिचकते थे। और सम्भव था कि अगर इम्पीरियल बैंक को देशी रियासतों में सुविधाएँ न दी जाती तो इन रियासतों में आधुनिक ढङ्ग का कोई भी बैंक न होता।<sup>1</sup> किन्तु छोटे-छोटे शहरों में भी अनेक शाखाएँ खोली गई जो विशेषतः छोटे-छोटे बैंकों की ही थी। डॉ० मुरैबन के अनुसार पांच महान् बैंकों में से बैंक ऑफ़ इण्डिया की ६०% प्रतिशत शाखाएँ ऐसे शहरों में थी जिनकी जनसंख्या २०,००० से कम है। फिर भी यह बैंक किसी बहुत बड़ी बैंक से कम नहीं, उसकी सम्पत्ति भी उतनी

<sup>1</sup> *Banking in India by S. G. Panandhler.*

हो सुरक्षित है एवं उसके लाभ में भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं। टॉम पानन्दीकर के अनुसार १०,००० जनमर्या वाल गाँवा में २७% गाँवा में छोटे छोटे बैंकों की शाखाओं का विस्तार हो गया है जो पहले केवल १४% था। किन्तु भारत में यह विकास अब भी ठीक नहीं कहा जा सकता। १९४५ में भारत के कुल २५०० शहरों में से केवल १६५० शहरों में एक या उनकी शाखाएँ थी और अखिल भारत में केवल ५५६७ बैंक एवं उनकी शाखाएँ हैं। यह विकास अन्य राष्ट्रों की तुलना में नहीं के बराबर है। भारत में जहाँ प्रति ८०,००० व्यक्ति एक बैंक है वहाँ अमेरिका में प्रति ३७३८ व्यक्ति जापान में ६४६१ व्यक्ति तथा इंग्लैण्ड में ४६१५ व्यक्तियों के लिए एक बैंक है। इसी प्रकार स्टेट बैंक की शाखाएँ भी आज तक ४६२ निसर में नहीं हैं। इसमें स्पष्ट है कि बैंकों की शाखाएँ केवल शहरों तक ही सीमित हैं परन्तु ग्रामीण भारत में अभी तक बैंकों की मुविधाएँ नहीं हैं।

### दूसरे युद्ध का बैंकिंग पर परिणाम

१ निक्षेपों में वृद्धि—दूसरा युद्ध आरम्भ होने ही पहिले ही निक्षेप काफी मात्रा में निकाले गए जो ५ १२ करोड़ ६० स. कम हो गए। किन्तु नमस्त वक्त में जनता का विश्वास स्थापित होने ही निक्षेप घटने लग गये। राशि १९३८ के २४६४५ करोड़ ६० स. १९४३ में ६५५.०७ तथा १९४६ के अन्त में १०६७ करोड़ ६० स. हो गई। निक्षेपों की वृद्धि के लिए यत्र सामग्री के आयात की असम्भवता मान चाँदी एवं स्थायी सम्पत्ति के मूल्यों में अधिक उतार चढ़ाव मुद्रा स्फीति तथा रिबन बन् की मुख्य मुद्रा नीति—य प्रमुख कारण थे। मुद्रा-स्फीति के कारण १९४८ में पत्र मुद्रा की राशि ७०१४ करोड़ ६० स. अधिक हो गई थी।

२ निक्षेपों के स्वरूप में परिवर्तन—इस अवधि में निक्षेपों के स्वरूप में भी परिवर्तन हुआ जो बैंकों के भाग निक्षेप एवं स्थिर निक्षेपों के अनुपात से स्पष्ट होता है। इस अवधि में स्थायी निक्षेप कम हुए परन्तु भाग निक्षेप बढ़े। इसका प्रमुख कारण स्थायी निक्षेपों की अपना भाग निक्षेपों पर दिया जाने वाला व्याज की अधिकता थी। दूसरे सान चाँदी के मूल्यों में उतार-चढ़ाव होने से इनके मूल्य गिरते ही इनको खरादने के लिए किसी भी समय राशि निकाली जा सके, इसलिये जनता चालू खाना में अपने निक्षेप रखना ही अधिक पसन्द करती थी।

३ नये बैंकों की स्थापना एवं शाखाओं का विस्तार—घन की अधिकता

एक लाभकर विनियोगों के साधनों का अभाव होने से उद्योगपतियों ने नये बैंक स्थापित करना आरम्भ किया। इसके साथ ही पुराने बैंकों ने अपनी शाखाएँ बढ़ाना आरम्भ किया। युद्ध के प्रथम दो वर्षों (१९३९-४१) में इसकी गति धीमी रही। परन्तु १९४० से १९४८ की अवधि में इस दिशा में तीव्र गति से प्रगति हुई जिनमें छोटे बैंकों की सख्या अधिक थी। फलतः बैंकों की सख्या जो १९३९ में १९५१ थी वह १९४६ में ५५२१ हो गई। युद्ध-काल में स्थापित नये बैंकों की युनाइटेड कमर्शियल बैंक, हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक, हबीब बैंक हिन्दुस्तान मर्केन्टाइल बैंक आदि उल्लेखनीय हैं। १९३९ में सूची-बद्ध एवं विनियम बैंक की संख्या ५३ थी जो १९४६ में ९३ हो गई तथा इनके कार्यालयों की संख्या ११२८ से ३१०६ हो गई। सूचीबद्ध बैंकों की संख्या १९३९ में २३१ थी जो १९४६ में ७७ हो गई। इस बैंकिंग विकास में कुछ दोष थे फिर भी बैंकिंग बलेबर मजबूत होता गया।

४. बैंकों की विनियोग नीति में परिवर्तन—युद्ध-काल में सूचीबद्ध बैंकों द्वारा दिये जान वाले ऋणों में भी कमी हुई जो पहिले कुल सम्पत्ति के ६२% होते थे वे अब केवल २५% रह गये। पाँच बड़े बैंकों के ऋणों का यही अनुपात ५३% से ३०% तथा इम्पीरियल बैंक का ५५% से ३०% रह गया।

फलस्वरूप सरकारी प्रतिभूतियों में बैंक अधिक विनियोग करने लगे जिससे उनकी सम्पत्ति में तरतता आ गई जो वाछनीय ही था। सूचीबद्ध बैंकों के विनियोगों का अनुपात युद्ध-पूर्व की कुल सम्पत्ति के ५४% से ६१% तथा इम्पीरियल बैंक का यही अनुपात ४३% से ५१% हो गया। बैंकों की इस प्रवृत्ति का प्रमुख कारण व्यापारियों के पास धन की अधिकता थी, जिससे उन्हें बैंक में ऋण लेने की आवश्यकता न थी।

५. बैंकों के लाभ में वृद्धि—बैंकों के अपनी राशि का सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक विनियोग करने से उनकी सम्पत्ति में तरतता आई। इसलिए यह न सोचना चाहिए कि बैंकों का लाभ कम हो गया। क्योंकि ऋण-प्रदाय में कमी तथा सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग के कारण बैंकों के लाभ में जो कमी हुई उसकी पूर्ति बैंकों द्वारा निक्षेपों पर दिये जाने वाले ब्याज दर की कमी से हुई। इसके साथ ही शाखाओं के विस्तार के कारण बैंकों के लाभ भी बढ़ गये।

६. रोकड़ निधि में वृद्धि—इसी अवधि में बैंकों की देनदारी के अनुपात में

रोकड-निधि में वृद्धि हुई। सूचीबद्ध बैंकों की युद्ध-पूर्व रोकड-निधि देनदारी की ११% थी जो १९४६ में २५% हो गई। इम्पीरियल बैंक की रोकड-निधि का यही अनुपात १९३६ में १५% था जो १९४६ में २६% हो गया। यह भारतीय स्थिति एवं समुचित बैंकिंग विकास के लिए लाभकर ही रहा। इसमें बैंकों की रिजर्व बैंक पर निर्भरता कम हो गई तथा देश में केवल थोड़े से बैंक ऐसे थे जिन्होंने रिजर्व बैंक से सहायता प्राप्त की। रिजर्व बैंक द्वारा दी जाने वाली सहायता का युद्धकालीन वार्षिक औसत १ करोड़ ८० से ४ करोड़ ८० तक था।

■ योग्य एवं अनुभवी बैंक कर्मचारियों की कमी—युद्ध-काल में बैंकों का अमीमित विस्तार होने से उनको अनुभवी एवं कुशल कर्मचारियों की कमी प्रतीत होने लगी। अतः अनेक नये बैंकों ने पुराने बैंकों के अनुभवी कर्मचारियों को अधिक वेतन देकर आकर्षित किया। फिर भी आज बैंकों में अनुभवी एवं कुशल कर्मचारियों का अभाव है। हम हेतु रिजर्व बैंक ने बैंकिंग शिक्षा के लिए आवश्यक कार्यवाही की है।

८ अनुचित प्रतियोगिता—इस अवधि में बैंकों की माया और उनकी शाखाओं का अमीमित विस्तार हुआ। बैंकों की शाखाएँ ऐसे अनेक स्थानों पर खोली गईं जहाँ या तो कोई आवश्यकता नहीं थी अथवा पर्याप्त बैंकिंग सुविधाएँ थीं। इस कारण बैंकों में अनुचित प्रतियोगिता बढ़ गई। परिणाम-स्वरूप अनेक बैंकों का विनियम हुआ —

१९३६	८०	१९४३	५१
१९४०	१००	१९४४	२०
१९४१	३३	१९४५	२६
१९४२	४६	१९४६	२७

### युद्धकालीन बैंकिंग विकास के दोष

युद्धकालीन बैंकिंग विकास मजबूत स्तर पर होने हुए भी दोष-रहित नहीं था क्योंकि,

(१) शाखाओं का अव्यवस्थित विकास—बैंकों ने उन क्षेत्रों की ओर ध्यान नहीं दिया जहाँ बैंकिंग सुविधाओं की आवश्यकता थी अपितु अपनी शाखाएँ ऐसे स्थानों में खोली जो उनके प्रमुख व्यवसाय क्षेत्र में बहुत दूर थे। इससे प्रबन्ध-व्यय बढ़ गया।

(२) बैंक ऋणों में सट्टा—युद्ध-काल में बैंकों के लाभ बड़े और उन्होंने

अधिक लाभान (dividend) का वितरण किया। इससे बैंकों के अगो में मद्दत होने लगा।

(३) लाभ का अवाञ्छित उपयोग—सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्य बढ़ने से बैंकों का जो लाभ हुआ उसका उपयोग “मचित बोप” के लिए न करने हुए लाभान-वितरण के लिए किया गया जो बैंकिंग मिष्ठान्तों के विरुद्ध है।<sup>1</sup>

(४) बैंकिंग के साथ अन्य व्यापारों का सम्बन्ध—बैंकों का मंचालन एवं नियन्त्रण ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया जो अन्य व्यापार या उद्योग में अधिक भाग ले रहे थे। यह युद्धकालीन बैंकिंग विकास का सबसे बड़ा दोष था। उदाहरणार्थ, जिरला, मिचामिया तथा डालमिया द्वारा मंचालित क्रमशः युनाइटेड कर्मागियल, हिन्दुस्तान कर्मागियल तथा भारत बैंक (जिसका समावेश पञ्जाब नेशनल बैंक में हो गया है।)

(५) लेखा पुस्तकों में हेर-फेर—बैंकों की अव्यवस्था एवं दोषों को छिपाने के लिए लेखा-पुस्तकों में हेर-फेर करना। इससे सट्टे के लिए दिये गये तथा अरक्षित ऋणों को छिपाया गया।<sup>1</sup> इस कारण अनेक बैंकों का विलिप्तन हुआ।

(६) सुयोग्य एवं कुशल कर्मचारियों की कमी।

(७) अनुचित प्रतिस्पर्धा।

मुद्रोत्तर काल में—मुद्रा मगापत होते ही बैंकों की सम्पत्ति एवं देनदारी का स्वरूप पुनः पूर्व-स्तर पर आ गया अर्थात् स्थायी निक्षेपों में वृद्धि और चल निक्षेपों में कमी होने लगी। साथ ही बैंक द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में भी वृद्धि होने लगी जिससे बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियों तथा रोकड़ निधि में कमी आ गई। मुद्रा-स्फीति तथा मूल्य-स्तर में वृद्धि होने से बैंकों का प्रबन्ध व्यय बढ़ा परन्तु ऋणों में वृद्धि होने से उनके लाभ प्रभावित नहीं हुए।

फलस्वरूप बैंकों ने कार्यक्षमता एवं योग्य कर्मचारियों की कमी होने हुए भी नई-नई शाखाएँ खोलना आरम्भ किया। इससे अल्प रूप से बैंकिंग संकट आया जिसका परिणाम विशेषतः बंगाल के बैंकों पर हुआ क्योंकि इन्होंने अगो की जमानत पर अधिक ऋण दिये थे जिनके मूल्य गिर रहे थे। इसका प्रभाव अन्य बैंकों पर नहीं हुआ। इस संकट के कारण रिजर्व बैंक ने सट्टे के लिए ऋण न देने का आदेश दिया तथा १९५६ में शाखाओं का विस्तार रोकने के लिए बैंकिंग कम्पनीज (साख-नियन्त्रण) कानून स्वीकृत हुआ। इसका प्रभाव बैंकिंग कलेक्टर पर अच्छा हुआ।

## भारत विभाजन का बैंकिंग पर प्रभाव

१५ अगस्त १९४७ को भारतीय स्वतन्त्रता के साथ भारत का विभाजन हुआ। इसमें पंजाब और बंगाल में भीषण कृत्यों का नाडव-नृत्य शुरू हुआ, जिसमें देश के उत्पादन और आयात-निर्यात व्यापार में कमी आई तथा करोड़ों की सम्पत्ति का नाश हुआ। इससे विशेषतः पंजाब में बैंकों को अधिक हानि हुई जिसका ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। १९४७ में विभाजन के कारण मद्रास की वृद्धि तथा पाकिस्तानी क्षेत्रों में भगदड़ के कारण १९४७ में ३० बैंकों का विलियन हुआ जिनमें अधिकतर अमूर्चीबद्ध बैंक थे। साथ ही मूर्चीबद्ध बैंकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

विभाजन की घातों आने ही पंजाब के बहुत-से बैंकों ने, जैसे पंजाब नेशनल बैंक आदि, अपने प्रमुख कार्यालय दिल्ली अथवा पूर्वी पंजाब के सुरक्षित स्थानों पर हटा लिए तथा पश्चिमी पंजाब की शाखाओं द्वारा ऋण देना कम किया गया। परन्तु यह कुछ सीमा तक ही हो सकता था। विभाजन होते ही पश्चिमी पंजाब के अनेक बैंकों को अपनी जियाएँ बन्द करनी पड़ी जिसमें उनको बहुत हानि हुई। इस मकड़ को रोकने के लिए रिजर्व बैंक एक्ट की १७ की धारा का मशायन किया गया जिसमें मूर्ची-बद्ध बैंकों को योग्य प्रतिभूतियों के आधार पर रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करने की सुविधाएँ दी गईं। दूसरे, पूर्वी पंजाब तथा दिल्ली आदेश (१९४७) भी लागू किया गया। इसमें जिन बैंकों के प्रमुख कार्यालय दिल्ली या पूर्वी पंजाब में हैं उनके विरुद्ध तीन मास तक कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकती थी। इसी के साथ इस स्थगित मोचन काल (moratorium period) में बैंक अपने भारतस्थित चल-निक्षेपा का केवल १० प्रतिशत अथवा २५० रु० (जो भी कम हो) का भुगतान कर सकते थे। सरकार ने विस्थापित बैंकों के पुनर्निवास के लिए भी १ करोड़ रुपए की सहायता दी। फलतः इस मकड़ में अन्य बैंकों की सुरक्षा हुई जिन्हें विलियन में बचाया जा सका।<sup>१</sup> १९४८ में बैंकिंग कम्पनी (परीक्षण) आदेश भी लागू किया गया। इसमें रिजर्व बैंक सरकारी आदेश पर किसी भी बैंक का परीक्षण कर उसकी रिपोर्ट सरकार को देने के लिए उत्तरदायी था। फलतः जिन बैंकों की स्थिति अच्छी नहीं थी, उनका विलियन किया गया तथा अन्य बैंकों को बचाया जा सका।

<sup>१</sup> इस प्रकार १९४६ में २७, १९४७ में २२, १९४८ में ३६, १९४९ में ४४, १९५० में ३१ तथा १९५१ में २३ बैंकों का विलियन हुआ।

रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जिन बैंकों का स्वेच्छा से विनियन हुआ अथवा जिन्होंने अपना कार्य बन्द किया, उनका तालिका निम्न है.—

	बैंक	चुक्ता पूँजी
१९३६-१९४७ का वार्षिक औसत	५६	₹ २८ करोड़ ८०
१९४८	४२	१'७५ "
१९४९	५३	१'०८ "
१९५०	४६	१'५६ "
१९५१	६७	२'५२ "

विभाजन में जो बैंकिंग मकद आया उसका हमारी बैंकिंग स्थिति पर जचड़ा परिणाम हुआ क्योंकि इसमें रिजर्व बैंक का उत्तरदायित्व बढ़ गया। बैंकों के नियन्त्रण एवं समुचित विकास के लिए कुछ वैधानिक संशोधन तथा नये अधिनियम बनाये गये (जिनका समावेश बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम, १९४९ में हो गया) तथा बैंकों के व्यवस्थापक भी अपनी जिम्मेदारी के प्रति सतर्क हो गये। इन मकदों के कारण अनेक अवाछनीय प्रवृत्तियों एवं अव्यवस्थित शाख-विस्तार को रोका गया। इसमें बैंकिंग कार्य-क्षमता का स्तर उन्नत हुआ तथा आजकल बैंक अपनी शाखाओं का विस्तार न करने हुए आर्थिक स्थिति एवं व्यवस्था को सुदृढ़ करने में प्रयत्नशील हैं। रिजर्व बैंक भी समुचित रूप में इनका नियन्त्रण कर रहा है।

भारतीय बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम १९४९ में रिजर्व बैंक को असीमित अधिकार मिल गये हैं जिसमें देश का बैंकिंग विकास समुचित ढंग पर हो रहा है। आजकल अनेक बैंक बढ़ते हुए धन के कारण अपनी अनाभर शाखाओं को बन्द करने लगे हैं तथा एकीकरण की ओर प्रयत्नशील हैं। इस अवधि में नाथ बैंक, दी एंशंसिएटेड बैंकिंग कम्पनी, इण्टरनेशनल बैंक ऑफ इण्डिया, दी एक्सचेंज बैंक ऑफ इण्डिया एंड अफ्रीका, कलकत्ता नेशनल बैंक एवं जवाला बैंक का विनियन हो चुका है। इसी प्रकार १९५० में बङ्गाल के चार बैंकों का—कोमिल्ला बैंकिंग कारपोरेशन कोमिल्ला युनियन बैंक, हुंगली बैंक तथा बङ्गाल सेंट्रल बैंक के एकीकरण में श्री युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया लि० का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार जुलाई १९५५ में इम्फोरियल बैंक तथा अन्य राज्य बैंक के एकीकरण से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का निर्माण किया गया है। इसमें हमारा बैंकिंग व्यवसाय अब मजबूत नींव पर आधारित है।

भारत में बैंकों का एकीकरण

१९८९ के बैंकिंग अधिनियम में बैंकों के एकीकरण का आयोजन किया गया। इसमें बम्बोर एवं अव्यवस्थित बैंकों का एकीकरणमु दृढ़ एवं बड़े बैंकों के

माय हाकर अवाञ्छनीय प्रतियोगिता का निवारण हो सकेगा तथा बैंकिंग क्लबों में मजबूत होगा। क्योंकि कमजोर बैंक की सहाय्य अधिक हान की अपेक्षा मुद्रा एवं सुव्यवस्थित बैंकों की कम सहाय्य हान अधिक वाछनीय है इसलिए बैंक की भी आजकल एकीकरण की आर प्रवृत्ति हो चली है।

एकीकरण से लाभ—(१) बैंक के एकीकरण में प्रबन्ध का केन्द्रीकरण होकर प्रबन्ध व्यय में मित्ययना आती है और उनका आर्थिक माधन मजबूत एवं अधिक हो जान है।

(२) बैंक के एकीकरण में कमजोर बैंक का समावेश अच्छे एवं मुद्रा बैंक में हो जान में उनका अनुभवों कमचारियों की सेवाओं का लाभ होता है। इसमें बैंकों की उपयोगिता बढ़ती है तथा इन का बैंकिंग सुविधाओं में किसी प्रकार की कमी नहीं आती। अच्छे एवं बड़े बैंक की शाखाओं की कार्य शैली में समानता रहती है तथा उनका शाख-बैंकिंग में सभी लाभ मिलते हैं। एकीकरण अधिक मजबूत तथा मजबूत की समय शक्ति एवं सुव्यवस्था का माधन होता है।

(३) अवाञ्छित स्पर्धा का अन्त—छोट-छोट बैंक का बड़े बैंक में समावेश हो जान से उनमें निक्षेप आकर्षित करने के लिए जो अवाञ्छनीय प्रतिस्पर्धा होती है उसका अन्त हो जाता है। देश में बैंक के विलियन का राकन का एकीकरण अच्छा माधन है।

(४) व्यवस्था में कुछ पहलू जैसे सम्पत्ति एवं आय का वितरण बैंक की कार्य नीति एवं नियम, कमचारियों की नियुक्ति आदि विभिन्न कार्यों के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति करना सम्भव हो जाता है जिससे कुशलता बढ़ती है।

(५) प्रत्येक शाखा में रखी जाने वाली रोकड़-निधि के परिमाण में मितव्ययता होती है क्योंकि उनका राकड़ की कमी हान पर ब दूर शाखाओं में राकड़ भेजकर पूरा कर सकते हैं।

(६) खतरे का प्रादेशिक वितरण—बैंक के लिए व्यवसाय में जो खतरा होता है उनका भौगोलिक अथवा प्रादेशिक वितरण हो जाता है।

(७) नियन्त्रण में सुविधा—छोट-छोट अनेक बैंकों का नियन्त्रण करने की अपेक्षा बड़े-बड़े बैंकों पर नियन्त्रण रखने में केन्द्रीय बैंक का भी सुविधा होती है जिसमें मुद्रा मण्डी में व्याज दरों तथा ऋण इन की गति में समानता आ सकती है।

(८) ग्रामीण बैंकिंग का विकास—एकीकरण से शाख बैंकिंग का गति मिलगी तथा ग्रामीण बैंकिंग विकास सम्भव होकर राकड़-निधि की आवश्यकताएं

कम हो जायगी। इस प्रकार बचाया हुआ धन देश के व्यापारिक एवं औद्योगिक विकास के लिए उपसब्ध हो सकेगा।

परन्तु जहाँ एकीकरण से अनेक लाभ हैं वहाँ एकीकरण में कुछ दोष भी हैं क्योंकि एकीकरण से बैंकों के आर्थिक शक्ति एवं आर्थिक शक्ति का केन्द्रीकरण कुछ इन गिने व्यक्तियों के हाथ में हो जाता है। ये व्यक्ति अपने एकाधिकार के कारण जनता का शोषण कर सकते हैं। इसके साथ ही सट्टा, अपने व्यापार का अत्यधिक विस्तार, भ्रष्टाचार इत्यादि बुराइयाँ भी बैंकिंग क्षेत्र में आ जाती हैं। कुछ लोगों का मत यह भी है कि एकीकरण से छोटनी हाकर बेकारी फैलने की सम्भावना रहगी। परन्तु यह धारणा गलत है क्योंकि एक ओर अलाभकर शाखाएँ बन्द होंगी, वहाँ दूसरी ओर जिन क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ नहीं हैं नई शाखाएँ भी खोली जाएँगी। साथ ही एकीकरण से शाख बैंकिंग के दोष भी आ जायगें।

एकीकरण की प्रवृत्ति केवल भारत में ही है, यह बात नहीं है। इंग्लैंड में भी प्रथम विश्व युद्ध के बाद जा मन्दी आई, उस काल में अनेक बैंकों का एकीकरण हुआ। एकीकरण योजनाओं को सफल बनाने के लिए तथा समुचित एवं वांछित एकीकरण को प्राप्त करने के लिए भारतीय बैंकिंग अधिनियम में भी १९५० में संशोधन किया गया। (इसके पूर्व एकीकरण का सबसे पहला उदाहरण इम्पीरियल बैंक का है।) रिजर्व बैंक की १९३५ में स्थापना होने के उपरान्त रिजर्व बैंक ने भी बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढता के लिए बैंकों के एकीकरण में सहायता की है। रिजर्व बैंक ने १९३७ में क्वीबेन बैंक तथा ट्रावनकोर नेशनल बैंक के एकीकरण से दी ट्रावनकोर नेशनल एण्ड क्वीबेन बैंक के निर्माण में सहायता दी। परन्तु यह बैंक १९३८ के बैंकिंग संकट में विलीन हो गया। दूसरा एकीकरण जिसमें रिजर्व बैंक ने इसी प्रकार सहायता दी, वह था १९४५ में कोमिल्ला बैंकिंग कारपोरेशन लि० में दी न्यू स्टैंडर्ड बैंक का समावेश। बंगाल में विभाजन के कारण वहाँ के चार बैंकों के एकीकरण से—कामिल्ला बैंकिंग कारपोरेशन, कामिल्ला यूनिवर्सल बैंक, हुगली बैंक तथा बंगाल सेंट्रल बैंक—१९५० में दी युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया लि० का निर्माण हुआ। एकीकरण का दूसरा उदाहरण मार्च १९५१ में पंजाब नेशनल बैंक में भारत बैंक लि० के समावेश का है। यह समावेश सम्पूर्ण न होते हुए आंशिक हुआ। आंशिक समावेश (partial merger) में एक बैंक दूसरे बैंक की निश्चित सम्पत्ति लेकर निश्चित देनदारी के भुगतान की जिम्मेदारी लेता है। इस प्रकार का आंशिक समावेश केवल अच्छे एवं सुदृढ बैंकों का ही हो सकता है।

क्याकि कमजोर बैंक की सम्पत्ति एवं देनदारी का आग्रह रूप में लेना गतरे से सली नही होना । एकीकरण का तीगरा उदाहरण १ जुलाई १९५५ को निर्मित स्टेट बैंक आफ इण्डिया है जा इम्पीरियल बैंक तथा राज्यों से सम्बन्धित बैंक के एकीकरण से हुआ ।

### भारतीय बैंकिंग का भविष्य

इस प्रकार भारतीय बैंकिंग कचवर संगठित हो रहा है तथा उनका विकास रिजर्व बैंक के प्रभावों ननृन्व म हो रहा है । यद्यपि वका की साम्वाएँ कम हो गई है फिर भी उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हा गई है । इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण स्टेट बैंक आफ इण्डिया एवं बैंकिंग कानून के निर्माण से देश के बैंकिंग जलवर की एक भारी कमी दूर हो गई है । रिजर्व बैंक पर दम के भुट्ट एवं कार्यभम बैंकिंग प्रणाली की जिम्मेदारी हान के नाने सहकारी बैंकिंग तथा व्यापारिक बैंकिंग की शिक्षा का आयोजन भी उमने किया है । इससे कुशल कर्मचारिया की कमी दूर हानी । साथ ही औद्योगिक बैंकिंग की कमी को दूर करने के लिए राष्ट्रीय सरकार न अनक फाइनेंसियल कारपोरेशन की स्थापना की है ।

इन प्रवृत्तियों से स्पष्ट है कि देश में बैंकिंग का भविष्य उज्ज्वल है जो अधिक गन्तिगाली एवं कायक्षम रहगा । जंसा कि श्री जॉन मयार्ड ने कहा था कि "भारतीय बैंकिंग कलेवर की शक्ति एवं कार्यक्षमता में समुक्त राज्य (U K.) तथा समुक्त राष्ट्र अमेरिका (U S A) की पद्धति से तुलना की जा सकनी है" "एव उसकी वर्तमान स्थिति आगामय है ।"

### सारांश

व्यापारिक बैंक या समुक्कन स्कध बैंक सामान्यतः ये होते हैं जो देश के उद्योग एवं व्यापार को अल्पकालीन साख-सुविधाएँ देते हैं । इनकी कार्यशील पूंजी जनता के निक्षेपों से तथा स्वायी पूंजी अशो के निर्गमन से प्राप्त होती है । भारत में इनके विकास के तीन युग हैं . —

प्रथम युग—स्वदेशी बैंक के व्यवसाय को ईस्ट इण्डिया कम्पनी के घाने से घक्का लगा, क्योंकि वे आधुनिक व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सके । इसलिए विदेशी अभिक्ता गृहो ने बैंकिंग व्यवसाय आरम्भ किया । इसके साथ ही देशी बंकरों ने मुगल नवाबो आदि को जो ऋण दिये थे उनके दूबने से ये जनता में प्राप्त धन को लौटाने में असमर्थ रहे, इससे ब्रिटिश अभिक्ता गृहो की नौब मजबूत होने लगी । नूद्य अभिक्ता गृहों ने समुक्कन स्कध बैंको की

स्थापना की जिसमें अलेक्जेंडर एंड क० ने १७७० में सबसे पहिले “दो बैंक ऑफ हिन्दुस्तान” की स्थापना की। यह बैंक १८३२ में समाप्त हो गया। १७८५ के पहिले जो बैंक खोले गये थे उनमें केवल “बंगाल बैंक का त्रिभुक्तार्ता गृहो से कोई सम्बन्ध न था और इसके नोट भी चलन में थे। १७८६ में “सीमित देनदारी” सिद्धान्त पर “जनरल बैंक ऑफ इण्डिया” स्थापित हुआ, जो १७८७ में सरकारी बैंक नियुक्त हुआ। किन्तु आगे चलकर ये बैंक भी बूब गये।

दूसरा युग प्रेसीडेंसी बैंको की स्थापना से आरम्भ हुआ, जब १८०६, १८४० और १८४३ में क्रमशः बैंक ऑफ बसकत्ता, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। ये ईस्ट इण्डिया क० तथा आन्तरिक व्यापार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थापित किये गये। इन्हें नोट चढ़ाने का अधिकार १८६२ तक रहा। इन तीनों के एकीकरण से १९०१ में इम्पेरियल बैंक का निर्माण हुआ।

तीसरा युग में (१८६०-१९१३) सीमित देनदारी सिद्धान्त की वैधानिक मान्यता मिली जिससे बैंक ऑफ इण्डिया, इलाहाबाद बैंक आदि की स्थापना हुई। १९०५ में स्वदेशी आन्दोलन के साथ घनेक नये बैंको की स्थापना हुई जिनमें बैंक ऑफ बडोदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ मैसूर आज के प्रमुख ७ बैंको में से हैं। फलतः १९०५ से १९१३ की अवधि में जिनकी चुकता पूँजी एवं निधि ५ लाख २० से अधिक थी ऐसे बैंको की संख्या ६ से १८ तथा छोटे बैंको की संख्या १३०० हो गई।

बैंकिंग संकट (१९१२-१३) में मुद्रा-मण्डी की कमजोरी तथा सरकार की मुद्रा नीति के कारण बैंकों ने अधिक ऋण देना शुरू किया और उनकी रोकड़-निधि कम हो गई। १९१४ में युद्ध आरम्भ होते ही जनता से निक्षेपों की मांग हुई, जिसे भुगतान करने में बैंक असमर्थ होने के कारण फेल होने लगे। यह क्रम १९१६ तक चालू रहा तथा इस अवधि में ८७ बैंक फेल हुए, जिनकी चुकता पूँजी एवं निधि १७५ लाख रुपए थी जो कुल बैंकों की चुकता पूँजी की ५०% थी।

इस संकट के प्रमुख कारण थे—अयोग्य प्रबन्ध, पूँजी की कमी, परस्पर गला-काट स्पर्धा, निक्षेप-राशि का सदृष्ट में विनियोग, संचालकों द्वारा बैंक के साधनों का निजी स्वार्थ में उपयोग, बैंको का दुर्भाग्य, समुचित बैंकिंग कानून एवं केन्द्रीय बैंक का अभाव, बैंकिंग प्रबन्ध में अशुद्धारियों की अरुचि।

इस संकट के परिणाम अच्छे हुए, क्योंकि सरकार को बैंको के नियन्त्रण

की आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए १९२६ में कन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति की नियुक्ति सरकार ने की। समिति ने केन्द्रीय बैंक एंव बैंकिंग कानून के निर्माण पर जोर दिया। फलस्वरूप १९३५ में रिजर्व बैंक का निर्माण तथा १९३६ में भारतीय कम्पनी अधिनियम में बैंकिंग-नियन्त्रण के हेतु संशोधन किये गये। साथ ही बैंक के प्रबन्धक एंव संचालकों की शिक्षा मिली कि बैंकों की प्रारम्भिक अवस्था में अधिक रोज़ड निधि तथा सम्पत्ति की तरलता की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए।

प्रथम महायुद्ध का पहला अर्धभाग बैंकिंग संकट काल रहा जिससे जनता में बैंकों के प्रति अविश्वास रहा, अधिक निक्षेप निकाले जाने लगे। परन्तु युद्ध के अन्तिम वर्षों में जनता का विश्वास बैंक में जमने लगा और आर्थिक प्रगति सन्तोषप्रद रीति से १९२१ तक होती रही, जिससे बैंकों के निक्षेप बढ़े और नये बैंकों की स्थापना की गति मिली। इस अवधि में विशेषतः औद्योगिक बैंकों की स्थापना हुई जो दोषपूर्ण नीति के कारण १९२३ तक बन्द हो गये। फिर भी १९२५ तक जिनकी चुकता पूँजी एंव निधि ५ लाख रुपये से अधिक थी, ऐसे बैंकों की संख्या २५ हो गई। इसी काल में केन्द्रीय बैंक की कमी को दूर करने के लिए १९२१ में इम्पीरियल बैंक का निर्माण हुआ। १९२१ के बाद पुनः मन्दी आई, जिसके भोके में १९२४ तक कुल ४४७ बैंक फेल हुए, जिनकी चुकता पूँजी लगभग ८ करोड़ ८० थी। १९२४ से १९३० तक बैंकिंग स्थिति में कुछ सुधार हुआ फिर भी बैंकों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। १९३२ के बाद बैंकों की स्थिति में सुधार हुआ जिससे १९३६ तक उनकी शालाएँ तिगुनी हो गई।

इस अवधि में बैंकिंग विकास अन्यत्रस्थित टंग पर होता गया क्योंकि (१) बैंकिंग विकास के क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया गया था, (२) देश में साहसी व्यक्तिता की कमी थी, (३) बैंक छोलेते समय आवश्यकता की अपेक्षा लाभ पर दृष्टि रखी गई। इस कारण शालाएँ या बैंक व्यापारिक एंव औद्योगिक केन्द्रों में ही छोले गये, जहाँ पहले से ही बैंकिंग सुविधाएँ थीं। इससे ग्रामीण भारत में सुविधाओं का अभाव रहा, जो आज भी है।

युद्ध (१९३६-१९४५) का बैंकिंग पर परिणाम—(१) निक्षेपों में वृद्धि, (२) उनके स्वरूप में परिवर्तन, (३) नये बैंकों की स्थापना एंव शाखाओं का विस्तार, (४) बैंकों की विनियोग नीति में परिवर्तन, (५) बैंकों का लाभ में वृद्धि, (६) रोज़ड-निधि में वृद्धि, (७) योग्य एंव अनुभवी कर्मचारियों की कमी, (८) परम्परा अनुचित प्रतियोगिता।

युद्धवालीन (१९३६-४४) बैंकिंग के विवास के दाय—(१) शाखाओं का अव्यवस्थित विकास, (२) बैंक के अंशों में सट्टा, (३) लाभ का अवांछित उपयोग, (४) बैंकिंग के साथ अन्य व्यापारों का सम्बन्ध, (५) लेखा पुस्तकों में हेरफेर, (६) कुशल कर्मचारियों की कमी तथा (७) अनुचित प्रतिस्पर्धा।

युद्धोत्तर काल—युद्धोत्तर काल में बैंक के दिये जाने वाले ऋणों में वृद्धि हुई तथा सम्पत्ति एवं ऋणदात्री का स्वरूप पूर्व स्तर पर आ गया। सरकारी प्रतिभूतियों एवं रोकड़ निधि में कमी हो गई। फिर भी उनके लाभ बड़े। फलतः कुशल कर्मचारियों की कमी होते हुए भी नई शाखाएँ खोली गईं। अल्प रूप में बैंकिंग संकट आया, इसलिए बैंकिंग विस्तार रोकने के लिए १९४६ में बैंकिंग कम्पनीज (साख नियंत्रण) कानून स्वीकृत हुआ। १९४७ में भारत विभाजन हुआ तथा उत्पात होने लगे, जिससे ३० बैंक फेल हुए। इनमें अधिकांश असूचीबद्ध थे। बड़े-बड़े बैंकों ने अपने कार्यालय पूर्व पंजाब अथवा दिल्ली के सुरक्षित स्थानों में हटा दिये तथा उपद्रव क्षेत्र में ऋण देना कम किया। इस स्थिति में बैंकों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये। विभाजन के कारण बैंकिंग स्थिति पर अच्छा परिणाम हुआ क्योंकि देश में बैंकिंग काग्रण बना, जिससे रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी बढ गई। इस अधिनियम के बाद बैंकों ने भी अपनी स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किये जिससे बैंकों के एकीकरण की बल मिली।

एकीकरण में लाभ—प्रबंध का केन्द्रीकरण, अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं का लाभ, अवांछित स्पर्धा का अन्त, विशेषज्ञों की नियुक्ति सम्भव, रोकड़ निधि में मितव्ययता, खतरो का प्रादेशिक वितरण, नियंत्रण में सुविधा, प्रामाण्य बैंकिंग का विकास।

एकीकरण के दोष—आर्थिक खोतों का केन्द्रीकरण, बेकारी की सम्भावना, भ्रष्टाचार, सट्टा आदि की बल।

एकीकरण की प्रवृत्ति बैंकिंग सुदृढ़ता की दृष्टि से गतिशील है जिसका ताजा उदाहरण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया है। इन प्रवृत्तियों से बैंकिंग के उज्ज्वल भविष्य का संकेत मिलता है।

## भारतीय मुद्रा-मण्डी

किन्ती भी दान का आर्थिक एवं औद्योगिक विकास कहा की मुद्रा मण्डी क मुमकालिन सगुन पर निर्भर रहता है जिसमें व्यापारिक, कृषिज तथा आद्योगिक मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति समुचित प्रकार से हो सके । अतः मुद्रा मण्डी किन्ती भी दान की आर्थिक वनवर का एक महत्वपूर्ण अङ्ग है । मुद्रा मण्डी उम बाजार का गृह है जहाँ पर मुद्रा एवं माख के रता तथा क्रिस्ता परस्पर मिलन है तथा जहा मुद्रा की माग एवं पूर्ति का आवश्यकतानुसार आदान प्रदान होना है । इस बाजार में विशेषतः व्यापारिक तथा अथ आर्थिक उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए मुद्रा एवं माख की पूर्ति होती है । यह पूर्ति पयाप्त माना में तथा उचित व्याज पर हा जानी है । मुमकालिन मुद्रा मण्डी से व्यवसायियों को सुगमता से माख प्राप्त हानी रहनी चाहिए जिसमें व औद्योगिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए उमरा महत्तम उपयोग कर सकें । मुद्रा मण्डी का हम एक दृष्टि से सामाजिक वैक भी कह सकत हैं क्योंकि जा लाभ एवं उपयोग किमी बैंक में व्यक्ति का होना है वही लाभ मुद्रा मण्डी में समाज का होता है । दाना से ही अल्पकालीन माख-आवश्यकताओं की पूर्ति होती है । इसमें आवश्यकतानुसार मुद्रा एवं माख का प्रसार एवं संचालन चाहिए तथा विनियाम के पयाप्त माधन उपलब्ध हान चाहिए जिसमें जनता की वचन मुद्रा मण्डी में आती है ।

इसीलिए मुद्रा मण्डी में बिल-बाजार विनिमय एवं विनियाम बाजार का विशेष महत्व है । मुद्रा मण्डी पूँजीमण्डी से भिन्न हानी है । पूँजी-बाजार दीर्घ कालीन ऋणा की पूर्ति करता है तब मुद्रा मण्डी अल्पकालीन ऋणा की पूर्ति करती है । फिर भी इन दाना का सम्बन्ध घनिष्ठ है । दूसरे, पूँजी-बाजार में काम करने वाली संस्थाएँ भिन्न हानी हैं ।

मुद्रा मण्डी में मुद्रा एवं माख का उचार लन वाल (१) व्यापारी, उद्योग-धन्धे वाल व्यक्ति एवं सामाजिक तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए ऋण लन वाल व्यक्ति (२) वरु एवं राज्य सरकारें तथा अरु-सरकारी संस्थाएँ जैसे नगर

पालिका आदि, (३) वृषक वगैरे जो फसल के समय ऋण लेता है, आदि होते हैं। दूसरी ओर ऋण एवं साख देने वाली संस्थाएँ होती हैं, जैसे स्वदेशी बैंक, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, माहूँकार, महाजन आदि।

मुद्रा-मण्डी में साख का नियन्त्रण इस प्रकार होना चाहिए जिससे आन्तरिक मूल्य में स्थिरता रहे। इस कार्य में केन्द्रीय बैंक का विशेष हाथ रहता है क्योंकि उस पर देश-हित के लिए साख का समुचित नियन्त्रण करने की जिम्मेदारी होती है। मुसज्जुठित मुद्रा-मण्डी में यह नियन्त्रण समुचित रूप से होता है। परन्तु भारतीय मुद्रा-मण्डी का सज्जुठन सदोप होने से रिजर्व बैंक यह नियन्त्रण पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है।

**भारतीय मुद्रा-मण्डी दोषपूर्ण होने के कारण**

१ आर्थिक समूह भारतीय आवश्यकतानुसार नहीं—भारत का आर्थिक समूह २०वीं शताब्दी के आरम्भ में अंग्रेज व्यापारियों द्वारा उनकी निजी आवश्यकताओं के अनुसार किया गया। इससे आर्थिक संस्थाएँ जो भारतीय मुद्रा-मण्डी में कार्यशील हैं, उनका समूह भारतीय आवश्यकताओं के अनुसार नहीं हुआ।

२ दोषपूर्ण चलन-पद्धति—भारतीय चलन-पद्धति का विकास १९३५ के बाद अंग्रेजों की आवश्यकताओं के अनुसार किया गया, न कि भारतीयों की। इससे चलन पद्धति दोषपूर्ण थी। (अ) प्रारम्भिक अवस्था में भारत सरकार स्वतन्त्र खजान रखती थी जिसमें मालगुजारी दी जाती थी और मुद्रा-मण्डी में धन की कमी होती थी। (ब) १९२१ में इम्पीरियल बैंक की स्थापना के बाद वह साख का नियन्त्रण करता था और मुद्रा का नियन्त्रण सरकार करती थी, जिससे मुद्रा एवं साख में सामंजस्य नहीं था।

३ यूरोपीय एवं भारतीय भाग—भारत के विदेशी शासन ने भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य को किसी प्रकार प्रोत्साहन नहीं दिया। फलस्वरूप भारतीय मुद्रा-मण्डी का समूह भी पृथक् यूरोपीय एवं भारतीय भाग में हुआ।

४ केन्द्रीय बैंक एवं बैंकिंग कानून का अभाव—१९२५ तक देश में केन्द्रीय बैंक का तथा १९४६ तक भारतीय बैंकिंग कानून का अभाव था, जिससे मुद्रा-मण्डी का समूह मजबूत आधार पर न हो सका।

५ पृथक् अधिनियमों से मुद्रा-मण्डी का नियन्त्रण—आज भी मुद्रा-मण्डी के कुछ भाग में रिजर्व बैंक समानता में नियन्त्रण नहीं कर सकता क्योंकि सहकारी बैंक तथा मयुक्त स्वयंसेवक बैंकों का नियन्त्रण पृथक् पृथक् अधिनियमों में होता है और स्वदेशी बैंकों पर तो कोई नियन्त्रण ही नहीं है।

## भारतीय मुद्रा-मण्डी के भाग

- १ रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया
- २ स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
- ३ विनिमय बैंक
- ४ समुक्त स्कम व्यापारिक बैंक
- ५ सहकारी बैंक
- ६ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम
- ७ राज्य औद्योगिक वित्त निगम
- ८ राष्ट्रीय औद्योगिक मान्य एवं विनियोग निगम
- ९ पुनर्वित्त निगम (Refinance Corporation)
- १० स्वदेशी बैंक

इनमें पहले तीन अंगों का संचालन भारतीय स्वतन्त्रता तक यूरोपीय हाथों में रहा, परन्तु १९८६ में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण तथा १९५५ में स्टेट बैंक का निर्माण होने से ये दोनों अब राष्ट्रीय संस्थाएँ हो गई हैं। यूरोपीय प्रबन्ध में अब केवल विनिमय बैंक ही है जिन पर भी भारतीय बैंकिंग अधिनियम में रिजर्व बैंक का नियन्त्रण हो गया है।

## भारतीय मुद्रा-मण्डी के दोष

१ परस्पर सङ्गठन एवं सहयोग का अभाव—भारतीय मुद्रा-मण्डी विभिन्न भागों में विभाजित है। इतना ही नहीं, अपितु हमारी जो दो प्रमुख मुद्रा-मण्डियाँ बम्बई तथा कलकत्ते में हैं उनके भी स्थानीय दो भाग हैं—केन्द्रीय मुद्रा-मण्डी तथा बाजार मुद्रा-मण्डी।<sup>१</sup> इसमें मुद्रा-मण्डी का न तो आपस में गगल है और न सहयोग की भावना ही है। मुद्रा मण्डी के कुछ भाग तो ऐसे हैं जिनमें परस्पर सहयोग तो एक ओर रहा, उन्दी प्रतियोगिता ही है, जैसे स्वदेशीय बैंक तथा अन्य बैंकों में प्रतियोगिता है। ये विभिन्न घटक स्वतन्त्र रूप में नष्ट होने का कार्य करते हैं जिसमें व्याज-दरों में समानता नहीं रहती और न बैंक-दर का बाजार-दर अथवा अन्य दरा से कोई सम्बन्ध ही स्थापित हो सका है। रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व तो ऐसी कोई मुद्रा मण्डी थी ही नहीं, जिसे हम वास्तव में मुद्रा-मण्डी कह भी सकते थे। प्रेमीटगी महाराज भी जो मुद्रा-मण्डियाँ थी उनका व्यापार क्षेत्र भी यूरोपीय तथा विनिमय बैंक तक ही सीमित था। इसीके साथ इम्पीरियल बैंक भी अन्य व्यापारिक बैंकों का प्रतिस्पर्धी था,

<sup>१</sup> Indian Central Banking Enquiry Committee, Vol IV, p 367

क्योंकि उसे इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया अधिनियम के अन्तर्गत कुछ विशेष अधिकार एवं सुविधाएँ थीं। किन्तु रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद भी वह मुद्रा के विभिन्न अंगों को एकीकृत कर मगठन करने में असफल रहा।

मुद्रा-मण्डी के मगठन के लिए केन्द्रीय बैंकिंग ऑथरिटी का मुभाव था कि भारत में अगिल भारतीय बैंक संघ (All Indian Banker's Association) स्थापित किया जाय जिसके स्वदेशीय बैंक सहित सभी बैंक सदस्य हों। यह संघ छोटे-छोटे बैंकों का एकीकरण करे तथा बैंकों का पारस्परिक कार्य भी निश्चित करे। बैंकिंग पद्धति को अधिक कार्यक्षम बनाने के साधना की सिफारिश करे तथा विभिन्न बैंकों का केन्द्रीय बैंक के साथ सम्पर्क बढ़ाये। इस सब के कार्यालय विभिन्न स्थानों पर हों जिसमें स्थानीय बैंकों की कठिनाइयों का निवारण करने के लिए प्रयत्न किया जाय। इस प्रकार का संघ १९४६ में चम्बई में स्थापित हुआ तथा इसके सदस्य सभी मूचीबद्ध (स्टेट बैंक को छोड़कर) बैंक हैं।

परन्तु मुद्रा-मण्डी में जब ६० प्रतिशत मुद्रा एवं माध्य की पूर्ति स्वदेशी बैंकरो द्वारा हो रही है, तब तब विभिन्न भागों में परस्पर सहयोग नहीं हो सकता। अतः इस संघ के सदस्यों में स्वदेशी बैंकरो का समावेश होना आवश्यक है।

२. ऋण देने वाली विशेष संस्थाओं का अभाव—हमारे यहाँ पारचाय देणों की तरह ऐसी कोई भी ऋण देने वाली संस्थाएँ नहीं हैं जो विभिन्न उद्योगों की आवश्यकतानुसार ऋण दे सकें। जैसे, कृषि व्यवसाय का तीन प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है—अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन। परन्तु मुद्रा-मण्डी केवल अल्पकालीन ऋण ही दे सकती है। दीर्घकालीन ऋण देने का कार्य विशेषतः स्वदेशी बैंकरो, महाजनो तथा साहूकारों तक ही सीमित है, जिनके व्याज की दर बहुत ऊँची है। ऐसी विशेष ऋण देने वाली संस्थाओं का अभाव मुद्रा मण्डी के संकलन की दृष्टि से शीघ्र ही दूर होना चाहिए, जिसमें उद्योग एवं कृषि की दीर्घकालीन माध्य-आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हाँ, स्वतन्त्रता के बाद औद्योगिक ऋण देने वाली संस्थाओं का निर्माण हो चुका है तथा कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति योजना के अन्तर्गत की जा रही है।

३. ऋण देने के लिए राशि की कमी—ऋण कार्यों के लिए आवश्यकतानुसार धन भी नहीं मिलता क्योंकि राशि विशेषतः उन लोगों में जाती है जो वचत करते हैं। परन्तु भारत में विशेषतः वचत की राशि भूमिगत जथा स्वर्ण तथा अचल सम्पत्ति में बदली जाती है। इसके तीन कारण हैं—पर्याप्त

विनियोग माधनों का अभाव, बैंकिंग पद्धति का अपर्याप्त विनाम, बैंकों के विलियन में उनमें अविश्वास तथा भारतीय जनता की गरीबी एवं बेसिधा। उमे इसका भी ज्ञान नहीं है कि बैंक में किस प्रकार में खाने खाने जाने हैं। डाकघर मचय बैंक का भारतीय ग्रामों में प्रसार नहीं है और न इनके व्यवहार ही ग्रामीण भाषाओं में होते हैं।

ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति की विफाग्न के अनुसार देशों में डाकघर मचय बैंकों की सुविधा देन की व्यवस्था की जा रही है। नये डाकघर योजना की योजना कार्यान्वित हो चुकी है। इसलिए ऋण-प्रदायक राशि का अभाव दूर करने के लिए ग्रामीण बैंकिंग विभाग होना चाहिए तथा फिल्मों द्वारा प्रचलन एवं बैंकों का महत्व समझाकर बैंकिंग प्रवृत्ति का निर्माण करना चाहिए। रिजर्व बैंक भी इस दिशा में प्रयत्न कर रहा है। रिजर्व बैंक के पास नई शाखाएँ खोलने के लिए जो प्रार्थना-पत्र आते हैं उनको वेबग दा गतों पर अनुमति दी जाती है —

(अ) यदि ग्रामीण क्षेत्र में शाखाएँ खोलना चाहते हैं।

(ब) जहाँ वे शाखाएँ खोलना चाहते हैं उस स्थान अथवा क्षेत्र में बड़ बैंकों की शाखाएँ नहीं हैं। माघ ही १९५५ में स्टेट बैंक पर ग्रामीण बैंकिंग विकास की जिम्मेदारी आ गयी है।

४ चलन पद्धति में लोच एवं स्थायित्व का अभाव तथा फसल पर धन की कमी—१९२० में इम्पीरियल बैंक की स्थापना तक की मुद्रा-मण्डी में मौसमी आवश्यकता के समय धन का अभाव रहता था। क्योंकि पत्र-मुद्रा का अधिकार सरकार के पास था तथा बैंकों की मास्य निर्माण शक्ति उनकी रोकड़-निधि में सीमित थी। इम्पीरियल बैंक की स्थापना के बाद भी इस लोच का अभाव बना रहा क्योंकि मास्य का नियन्त्रण इम्पीरियल बैंक और मुद्रा का नियन्त्रण सरकार पर ही था। हाँ, मौसमी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इम्पीरियल बैंक नकटवर्नीन साख (emergency credit) निर्माण के लिए सरकार में केवल १२ कराड़ रुपए ऋण ले सकता था। यह राशि आवश्यकता की तुलना में कम थी कि मुद्रा-मण्डी में मौसमी धन की कमी रहती थी तथा व्याज की दर ८ से ९% तक हा जाती थी। इस तनाव का मुख्य कारण चलन-पद्धति में लोच का अभाव था। इसी प्रकार हमारा यहाँ बैंकों का स्वतन्त्रता में उपयोग भी नहीं होता था। अब रिजर्व बैंक ने (१९३५ में) इस कमी को काफी दूर कर दिया है।

५ मुद्रा-मण्डी में व्याज-दरों की भिन्नता एवं अधिकता—भारतीय मुद्रा-मण्डी के भिन्न भिन्न अङ्गों का किसी भी प्रकार सहयोग एवं नियन्त्रण न होने से विभिन्न मुद्रा-मण्डियों की व्याज दरें भिन्न-भिन्न एवं ऊँची हैं तथा बाजार-दर, बैंक-दर, कटौती-दर आदि के उतार-चढ़ाव में समानता नहीं है। दूसरे, बाजार के विभिन्न अङ्गों में प्रतियोगिता होने से भी यह समानता नहीं आती। चिन्तु उन्नत राष्ट्रों के बाजार में बैंक-दर के घटने-बढ़ने के साथ अन्य दर भी उसी अनुपात में घटती-बढ़ती हैं क्योंकि वहाँ पर बैंक एवं मुद्रा मण्डी के विभिन्न अङ्गों में परस्पर सहयोग की भावना है।

व्याज-दर में समानता लाने के लिए बैंकों के कार्यक्षेत्र का प्रादेशिक विनियमन होना चाहिए तथा उस क्षेत्र में व्याज-दर के नियन्त्रण का उत्तरदायित्व भी उन्हीं बैंकों पर होना चाहिए जिसमें उस क्षेत्र के बैंक अधिक दर न लें अथवा मुद्रा-मण्डी के विभिन्न जगों पर वैधानिक रूप में प्रभावी नियन्त्रण रखा जाय। हम कार्य को रिजर्व बैंक को करना चाहिए परन्तु अभी तक उसने ऐसा नहीं किया जिसमें मुद्रा मण्डी में बैंक-दर का महत्व नहीं के बराबर है।

६ बैंकिंग सुविधाओं का अभाव—देहातों में जहाँ बचन की राशि स्वर्ण अथवा भूमि में रक्खी जाती है वहाँ पर बैंक का अभाव है। द्वितीय महायुद्ध-काल में अनेक बैंक न नई-नई शाखाएँ खोली परन्तु ये शहरों में खोली गयीं तथा गाँवों में अभाव ही है। जनसंख्या के हिसाब से भी हमारे यहाँ प्रति १३० हजार व्यक्तियों के पीछे केवल एक बैंक है। कृषकों की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र के भूमि-बैंकों (land bank) के नमूने पर भारत में भी कृषि तथा भूमि-बैंकों की स्थापना होनी चाहिए, जिससे कृषि—जा हमारा बड़ा उद्योग है—का भी मुद्रा-मण्डी क्षेत्र में समावेश हो। अभी भारत में कुछ सहकारी कृषि-संस्थाएँ तथा भूमि-वन्धक बैंक हैं परन्तु उनका कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित है एवं वे प्राथमिक अवस्था में ही हैं। अतः दम और रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक को कार्य करना चाहिए।

७ बिल-बाजार का अभाव—अन्य देशों की भाँति हमारे यहाँ बिलों का उपयोग बहुत ही कम होता है तथा बिलों की वृद्धि भी सीमित ही है। क्योंकि रिजर्व बैंक केवल उन्हीं बिलों की कटौती करता है जो मान्य हों तथा नियत शर्तों के अनुसार हों। मुद्रा मण्डी में तो कटौती सुविधाएँ हैं ही नहीं, जिसमें हमारे यहाँ गिनों का उपयोग नाममात्र को ही है और बिल-बाजार का अभाव है।

## विलो की कमी के कारण

(अ) बैंको को अधिक रोकड़-निधि रखनी पड़ती है जिससे वे अपनी राशि का विनियोग अतिरिक्त परम-प्रतिभूतियाँ में ही करने पड़े, जिससे उनकी सम्पत्ति में गिरावट आये। परन्तु आजकल परम-प्रतिभूतियों की अपेक्षा रिजर्वों की कटौती में आय अधिक होती है, इसलिए आशा है कि भविष्य में रिजर्वों का उपयोग बढ़ेगा।

(ब) देश में ऐसी समस्याओं का अभाव है जो रिजर्वों के स्वीकर्ता की आर्थिक स्थिति की पूर्ण जानकारी दे सके। इस कारण बैंक रिजर्वों की कटौती करने में हिचकते हैं। इसलिए ऐसी समस्याओं की स्थापना होना आवश्यक है।

(ग) रिजर्व बैंक की स्थापना (१९२५) होने के पूर्व भारत में ऐसा कोई भी बैंक नहीं था और न कोई ऐसी समस्या ही थी जहाँ आवश्यकता पड़ने पर रिजर्वों की कटौती हो सके। इम्पीरियल बैंक अन्य बैंकों की प्रतियोगिता में था, इसलिए उसमें रिजर्वों की पुनः कटौती कराना वे समुचित नहीं समझते थे और आवश्यकता पड़ने पर परम-प्रतिभूतियों की जमानत पर इम्पीरियल बैंक से ऋण लेते थे।

(द) बैंक व्यापारिक दृष्टि से इसलिए भी नहीं लेते थे क्योंकि उनमें यही मालूम नहीं होता था कि वे व्यापार-विनियोग है अथवा अनुग्रह विनियोग। बैंक विशेषतः व्यापारिक विनियोग में ही लेन-देन करना समुचित समझते हैं। इसलिए भी रिजर्वों का उपयोग कम होता था।

(य) रिजर्वों पर अधिक स्टाम्प-कर लगने के कारण मुद्रा-दृष्टि का प्रयोग कम होता था। केन्द्रीय बैंकिंग अधिनियम (१९२६) की विफारिश के अनुसार १९४० से स्टाम्प कर कम हो गया है।

(ब) भारत में दृष्टिपूर्ण प्रान्तीय भाषाओं में प्रान्तीय ऋणियों के अनुसार रिजर्वें जाती हैं जिससे रिजर्वों में विविधता होती है। इस कारण एक स्थान की दृष्टिपूर्णता का उपयोग अन्य स्थानों में करने में अनेक प्रसूचितियाँ होती हैं, विशेषतः उनके अनादरण के समय। इसलिए भी दृष्टिपूर्णता का उपयोग कम होता है।

(घ) भारत में रिजर्वों की कटौती की अपेक्षा बैंक रोकड़-ऋण देना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि इसको किसी भी समय बैंक रद्द कर सकता है तथा ग्राहकों को भी कम व्याज देना पड़ता है।

(ज) कुछ वर्षों से राज्य एवं केन्द्र सरकार अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लिए कोष-विनियोगों का निर्माण करती हैं जिनकी अवधि २० से २५ दिन होती है। इन विनियोगों अधिक सुरक्षित एवं तरल समझा जाता है

क्योंकि ये बिम्बी भी समय-समय विनियम में बेचे जा सकते हैं। अतः व्यापारिक विमो के उपयोग में इनका प्रयोग भी वांछक मिष्ट हुआ।

**रिजर्व बैंक द्वारा बिल-बाजार का निर्माण**

हमारी मुद्रा-मण्डी में बिल-बाजार का अभाव बहुत दिनों से था। इस अभाव को दूर कर मुद्रा मण्डी में खाम को सोचदार बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने सूची-बद्ध बैंको के प्रतिनिधियों के परामर्श में २६ जनवरी १९५२ से बिल-बाजार योजना लागू की है।

इस योजना के अनुसार रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा १७ (४) (c) के अन्तर्गत सूची-बद्ध बैंको के प्रतिज्ञा-पत्रों की जमागत पर उनको माँग-ऋण (demand loans) देगा। ये प्रतिज्ञा-पत्र मुहूर्ती बिल अथवा सूची-बद्ध बैंक के ग्राहको के बिम्बी अथवा प्रतिज्ञा-पत्रों के आधार पर निम्ने जाने चाहिए। इस योजना के अनुसार रिजर्व बैंक के पास कम से कम १ लाख रुपये के बिल (individual bills) देना अनिवार्य है। इसी प्रकार एक बैंक को इन बिलों के आधार पर कम से कम २५ लाख रुपये का ऋण लेना होगा। परन्तु अब यही राशि १० लाख रुपये है तथा प्रत्येक बिल की राशि ५० हजार रुपये से कम नहीं होना चाहिए।

प्रारम्भिक काल में इस योजना से केवल उन्हीं बैंकों का लाभ मिल सकेगा जिनकी चुकता पूँजी एवं निधि ३१ दिसम्बर १९५१ को १० करोड़ ८० से कम नहीं है। अब यह सीमा केवल ५ करोड़ ८० की गई है।

इस योजना को बैंक में लोकप्रिय बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने उन्हें यह ज्ञापन दिया है कि इस योजना के अनुसार जो ऋण दिए जायेंगे उन पर बैंक-दर में ३/० की छूट मिलेगी। हमारे माँग बिलों का मुहूर्ती बिलों में परिवर्तन कराने के लिए जो स्टाम्प कर लगेगा उसका आधा भाग रिजर्व बैंक देगा।

इस योजना में बिल-बाजार का विकास हाकर बैंको को अपनी मज्जति में तरलता रखने में सहायता होगी। इसके अलावा हमारी मुद्रा मण्डी में मौसमी आवश्यकता के समय माँग में जा तोर का अभाव था, वह नहीं रहेगा। साथ ही बैंको की साम्ब निर्माण शक्ति बढ़कर ऋण-प्रदायक राशि बढ़ेगी तथा माँग एवं मुद्रा-पद्धति सोचदार हो जायेगी। इसमें हमारी मुद्रा मण्डी के अनेक दोषों का निवारण हो सकेगा। इस योजना में समय के अनुसार आवश्यक परिवर्तन किये जायेंगे।

१९५२, ५३, ५४ तथा १९५५ में इस योजना के अन्तर्गत बैंको ने बिलों

के आधार पर प्रमग ८२ ६६ १४७ तथा १३५ करोड रु० के ऋण लिये जो योजना की सफलता की आर मकेन है ।

### भारत

किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ की मुद्रा-मण्डी पर निर्भर रहता है । मुद्रा-मण्डी उसे कहते हैं जहाँ मुद्रा एवं साख के क्रेता-विक्रेता परस्पर मिलकर साख एवं मुद्रा का लेन-देन करते हैं । इसीलिए मुद्रा मण्डी के बिल बाजार, विनिमय एवं विनियोग बाजार का विशेष स्थान है । किन्तु पूँजी बाजार से मुद्रा-मण्डी भिन्न होती है क्योंकि पूँजी बाजार में जहाँ दीर्घकालीन ऋण एवं साख का लेन देन होता है वहाँ मुद्रा-मण्डी में अल्पकालीन ऋण एवं साख में लेन-देन होता है ।

मुद्रा मण्डी में उधार लेने वाले व्यापारी, उद्योगपति एवं सामाजिक तथा व्यक्तिगत कार्यों के लिए ऋण लेने वाले व्यक्ति, केन्द्र एवं राज्य सरकारें, अर्थ सरकारी संस्थाएँ, कृषक आदि होते हैं । दूसरी ओर ऋण देने वाले अर्थात् स्वदेशीय बैंक, सहकारी बैंक, व्यापारिक बैंक, महाजन आदि होते हैं ।

भारतीय मुद्रा मण्डी दोष-पूर्ण है क्योंकि—(१) वहाँ का आर्थिक संगठन भारतीय आवश्यकतानुसार नहीं हुआ, (२) भारतीय चलन-पद्धति दोष-पूर्ण रही, (३) मुद्रा मण्डी में भारतीय एवं यूरोपीय दो प्रथक भाग हैं, (४) १९३५ तक केन्द्रीय बैंक का तथा १९४६ तक बैंकिंग कानून का अभाव रहा, तथा (५) मुद्रा-मण्डी के विभिन्न अंगों का नियन्त्रण प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष अधिनियमों से होता है ।

मुद्रा-मण्डी के ये दोष निम्न हैं—(१) विभिन्न अंगों में परस्पर संगठन एवं सहयोग का अभाव (२) ऋण देने वाली विशेष संस्थाओं का अभाव (३) ऋण देने के हेतु राशि की कमी, (४) चलन-पद्धति में लोच एवं स्थायित्व का अभाव तथा कसल घर धन की कमी, (५) मुद्रा-मण्डी में व्यापारियों की भिन्नता एवं अधिकता, (६) पर्याप्त बैंकिंग सुविधाओं का अभाव (७) बिल बाजार का अभाव ।

बिल-बाजार का अभाव होने के कारण व—देश में स्वोक्तता की आर्थिक स्थिति की जानकारी देने वाली संस्थाओं का अभाव बैंकों का परम प्रतिभूतियों में अधिक विनियोग, १९३५ तक बिलों की पुन कटौती करने वाली केन्द्रीय बैंक का अभाव व्यापार बिल एवं अनुग्रह बिल पहिचानने में कठिनाई, बिलों पर अधिक स्टाम्प-कर, बिलों की कटौती की अपेक्षा रोक ऋण एवं ओवरड्राफ्ट की प्राथमिकता ।

इस कमी को दूर करने के लिए २६ जनवरी १९५२ में रिजर्व बैंक ने बिल बाजार योजना लागू की है। इसके अन्तर्गत जिन बैंकों की चुकता पूंजी एवं निधि ५ करोड़ की है वे बैंक बिलों के आधार पर १० लाख रुपये तक ऋण ले सकते हैं किन्तु बिल की राशि ५०,००० रुपये से कम नहीं होना चाहिए। इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए रिजर्व बैंक मांग बिलों के मुद्रतो बिलों में परिवर्तन के लिए लगने वाली ५०% स्टाम्प छूटी देगा तथा ऐसे ऋणों पर बैंक दर से १% की छूट देगा। इस योजना के अन्तर्गत १९५२ से १९५५ तक बैंकों ने क्रमशः ८२, ६६, १४७ तथा १३५ करोड़ रुपये के ऋण लिए जो योजना की लोकप्रियता का संकेत है।

## अध्याय १५

# स्वदेशीय बैंकर

**परिभाषा—**स्वदेशीय बैंकर को परिभाषा करना आसान नहीं है। उनका माहूकार अथवा सामान्य ऋण दाता स पृथक् करने की कोई सामा नहीं है। केन्द्रीय बैंकिंग ऑथ सभिति के अनुसार 'इम्पोरियल बैंक, विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक एवं सहकारी बैंकों को छोड़कर जो हुण्डियो का व्यवहार करते हो, जनता से निक्षेप लेते हो एवं ऋण देते हो वे स्वदेशीय बैंकर हैं। एक सामान्य घनी व्यक्ति स नगर बैंकिंग साभदारी कुटुम्ब भागिता (family partnership) तथा व्यापारी-बैंकर (merchant bankers), जिनकी भिन्न-भिन्न स्थाना पर गाछाएँ भी हानी है उन सबका समावश स्वदेशीय बैंकर म हाता है। डा० एल० सी० जैन के अनुसार "स्वदेशीय बैंकर कोई भी व्यक्ति अथवा निजी फर्म है जो ऋण देने क साथ ही निक्षेप स्वीकार करे अथवा हुण्डियो मे व्यवहार करे अथवा दोनों ही काम करे। माधारणत स्वदेशीय बैंकर य दाना ही काम करत हैं।

सामान्य ऋणदाता एवं स्वदेशीय बैंकर मे भेद

(१) महाजन अथवा ऋणदाता जनता स निक्षेप नहीं लत किन्तु स्वदेशीय बैंकर निक्षेप स्वीकार करत हैं।

(२) महाजन हुण्डिया म व्यवहार नहीं करत परन्तु स्वदेशीय बैंकर विदाप रूप स हुण्डिया म व्यवहार करत ह।

(३) महाजन ऋण दन के साथ ही अन्य व्यापार भी करत है जो उनका प्रमुख भाग होता है। परन्तु स्वदेशीय बैंकर बैंकिंग-व्यापार विदाप रूप स करत हैं तथा उम ही व अपन व्यवसाय का प्रमुख अग मानत है अथात् उनकी दष्टि म बैंकिंग व्यापार का विशेष महत्व ह।

(४) महाजन कवन अपन निजी घन स ही ऋण दता है। किन्तु स्वदेशीय बैंकर जनता स लिय टुए निक्षेप तथा निजी पूजी से ऋण देत है।

(५) महाजन केवल कृषि-कार्यों क लिए ऋण दत है परन्तु उत्पादन की अपक्षा उपभोग के लिए व अधिक ऋण दत है। इसक विपरीत स्वदेशीय बैंकर

विशेषतः उत्पादन कार्यों के लिए, व्यापार एवं छोटे-छोटे उद्योगों के लिए ऋण देते हैं तथा ऋण का उद्देश्य जानने के लिए सावधान रहते हैं। किन्तु महाजन 'ऋण लेने के उद्देश्य' का ज्ञान आवश्यक नहीं समझता। महाजनों के व्याज की दर स्वदेशीय बैंकरो से अधिक होती है।

(६) महाजनों अथवा ऋण देने का कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह किसी जाति का हो। परन्तु बैंकिंग व्यापार निश्चित जातियों द्वारा ही किया जाता है, जैसे उत्तरी भारत में जैनी और मारवाड़ी तथा दक्षिणी भारत में मद्रासवासी चेन्नैयार। इसके अतिरिक्त शिवापुरी, मुस्तानी, खत्री तथा तथा बंश्य भी स्वदेशी बैंकिंग व्यापार करते हैं।

**संयुक्त स्कन्ध बैंक और स्वदेशीय बैंकर**

(१) संयुक्त स्कन्ध बैंक का समावेशन भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत होना आवश्यक है तथा उन्हें अधिनियम के अनुसार अपने लेख, स्थिति-विवरण आदि समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने पड़ते हैं। इसके विपरीत स्वदेशी बैंकर स्वतन्त्र होते हैं तथा वे विशेषतः अपने लेख एवं लेखा-पुरतबें गुप्त रखते हैं।

(२) संयुक्त स्कन्ध बैंक का पूर्ण व्यापार अर्ध पूंजी के अतिरिक्त विशेषतः निधियों पर निर्भर रहता है, परन्तु स्वदेशीय बैंकर अपनी निजी पूंजी पर निर्भर रहता है एवं उसकी निक्षेप राशि बहुत थोड़ी होती है।

(३) ग्राहकों का निक्षेप-राशि बैंक द्वारा निकालने की सुविधा संयुक्त स्कन्ध बैंक देते हैं परन्तु स्वदेशीय बैंकर चेक लिखने की सुविधा नहीं देते।

(४) स्वदेशीय बैंकर का अपने ग्राहकों के साथ वैयक्तिक एवं घनिष्ठ सम्पर्क रहता है, परन्तु संयुक्त स्कन्ध बैंकों में वैयक्तिक सम्पर्क एवं घनिष्ठता का अभाव है।

(५) संयुक्त स्कन्ध बैंक केवल अल्पकालीन ऋण सुविधा देते हैं, किन्तु स्वदेशीय बैंकर अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन दोनों ही प्रकार के ऋण देते हैं।

(६) स्वदेशीय बैंकर बैंकिंग व्यापार के साथ अन्य व्यापार भी करते हैं। इतना ही नहीं, अपितु वे मद्रा भी करते हैं, परन्तु संयुक्त स्कन्ध बैंक बैंकिंग के सिवा न अन्य व्यापार करते हैं और न अधिनियम के अनुसार कर ही सकते हैं।

(७) स्वदेशीय बैंकर की कार्य-प्रणाली संयुक्त स्कन्ध बैंकों से सरल एवं सुगम होती है, किन्तु संयुक्त स्कन्ध बैंकों की अपेक्षा इनकी व्याज-दर अधिक होती है।

(८) स्वदेशीय बैंकर बिना किसी प्रकार की जमानत के ऋण दे देते हैं, किन्तु समुक्त स्तब्ध बैंक नहीं देते ।

(९) स्वदेशीय बैंकर ऋणों की जमानत के लिए किसी भी प्रकार की चल एवं अचल सम्पत्ति को बन्धव रखते हैं, किन्तु समुक्त स्तब्ध बैंक केवल ऐसी ही चल प्रतिभूतियाँ स्वीकार करते हैं जो सरलता से किसी भी समय बाजार में बेची जा सकती हैं ।

**स्वदेशीय बैंकरों की कार्य-प्रणाली**

इनकी कार्य-प्रणाली अत्यन्त सरल एवं कम स्वर्चाली होती है क्योंकि इनका कोई भी कार्यालय नहीं होता । ये लेन-देन के सत्र व्यवहार विशेषतः अपने स्थान पर ही करते हैं । हा, लेखे इत्यादि लिखन का काम मुनीम करते हैं, जो बहुत ही ईमानदार तथा परित्यग्भी होते हैं । ग्रामीण क्षेत्र में इनके बड़े ही अच्छे बैंकिंग सम्बन्ध हैं तथा इनका अपन क्षेत्र के ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के विषय में पूर्ण ज्ञान होता है । इसमें कोई भी व्यक्ति बिना किसी विशेष अनुमति के शीघ्र ही ऋण प्राप्त कर सकता है ।

**निक्षेप**—ये जनता से निक्षेप स्वीकार करते हैं एवं उन पर व्याज देते हैं । इनकी निक्षेप-राशि पर व्याज की दर सहकारी तथा अन्य समुक्त स्तब्ध बैंकों से अधिक होती है जो ३% से ६% होती है । परन्तु ऐसा कहा जाना है कि स्वदेशीय बैंकर अधिक परिमाण से निक्षेप नहीं लेते क्योंकि निक्षेप-राशि ग्राहकों द्वारा किसी भी समय निकाली जा सकती है जिससे वे छतरे में पड़ सकते हैं । अतः वे केवल अपने मित्रों के ही निक्षेप लेते हैं । यद्वास्तव में तदुक्तोक्ति चेष्टिपर समस्त स्वदेशीय बैंकरों से अधिक चतुर एवं व्यवहार-कुशल है । ये जनता में अधिक परिमाण से निक्षेप स्वीकार करते हैं ।

**निक्षेप राशि के लिए वे प्रायः रसीद भी देते हैं परन्तु अधिकतर नहीं देते ।** आजकल कुछ बैंकर रसीद तथा बैंकों से राशि निकालने की सुविधाएँ भी देने लगे हैं जो भोमिन क्षेत्र में चलत हैं ।

**ऋण**—इनका प्रमुख कार्य ऋण देना है । ये अविकतर व्यापारिक तथा कृषि-कार्यों के लिए ऋण देते हैं परन्तु कभी-कभी उपभोग के लिए भी ऋण देते हैं । विशेषतः ऋण किसी न किसी प्रकार के प्रतिज्ञा-पत्रों के आधार पर देते हैं, किन्तु ऋण की राशि अधिक होने पर अच्छी-बुरी प्रतिभूतियाँ की जमानत लेते हैं । ये ऋणों पर अन्य बैंकों में अधिक व्याज लेते हैं । व्यापारिक कार्यों के लिए दिये जाने वाले ऋण विशेषतः हुण्डियों की कटीती से अथवा खरीद करके भी देते हैं । सुरक्षित ऋणों पर इनकी व्याज की दर ६% से १८%

होती है व अरक्षित ऋणों पर व्याज की दर अधिक होती है, जो १८% से ३६% तक होती है।

**ऋण देने की पद्धति**—इनकी ऋण देने की पद्धति सरल एवं सुविधाजनक है, जिससे किसी ऋण लेने वाले को कोई औपचारिक बातें नहीं करनी पड़ती। ऋण प्राप्त करने में भी किसी व्यक्ति को विनम्र नहीं होता। ऋण केवल वैयक्तिक प्रतिज्ञा-पत्र व आधार पर दिये जाते हैं अथवा कभी-कभी अन्य व्यक्तियों की जमानत की भी आवश्यकता होती है। साधारणतः ये केवल एक कामज पर (ऋण रसीद पर) ऋणी के हस्ताक्षर ही ले लेना पर्याप्त समझते हैं जिसे 'रक्का' कहते हैं। इस रक्के पर कभी-कभी ऋण पर व्याज की दर, अवधि आदि देते हैं तथा कुछ बैंकर वैधानिक 'रक्का' लिखवाते हैं। कभी कभी ये रक्का न लिखवाते हुए अपनी लेखा पुस्तक पर ही स्टाम्प लगाकर ऋणी के हस्ताक्षर करवाते हैं। इस पुस्तक में ऋण लेने की कार्ड भी शर्त नहीं लिखी रहती। किसी अचल सम्पत्ति, जैसे भू-गृहादि, रहन रखते समय ऋणी से वैधानिक लेख, जिसे रहन-बन्ध (mortgage bond) कहते हैं, लिखवा लेते हैं।

**हुण्डियों**—स्वदेशी बैंकर हुण्डियों में भी व्यवहार करते हैं तथा आजकल इनके व्यवहार में विशेषतः चार प्रकार की हुण्डियों का उपयोग होता है—दर्शनी हुण्डी, मुहूर्ती हुण्डी, धनीजोग हुण्डी और शाहजोग हुण्डी। इन हुण्डियों का अनादरण बहुधा नहीं होता क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा हुण्डियों का अनादरण लेखीवाल का दिवालिया होना माना जाता है। हुण्डियों के आधार पर भी ऋण दिये जाते हैं तथा इन ऋणों पर व्याज की दर भिन्न-भिन्न स्थानों पर ४% से १२% तक स्थानीय प्रधानुसार भिन्न-भिन्न होती है। इस दर को 'बाजार-दर' कहते हैं। ये हुण्डियाँ का खय-विक्रय एवं कटौती भी करते हैं।

**कृपि-साख**—स्वदेशीय बैंकर व्यापारिक ऋण के अतिरिक्त कृपकों को ऋण देते हैं, परन्तु विशेषतः इनका कृपकों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। ये महाजनों एवं छोटे-छोटे व्यापारियों के माध्यम से कृपकों को ऋण देते हैं जिससे इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। ग्रामीण साख जाँच समिति के अनुसार ये लगभग ६०% ग्रामीण साख की पूर्ति करते हैं।

**अन्य व्यापार**—इसके अतिरिक्त ये अन्य व्यापार भी करते हैं, जैसे अनाज की दलाली, सट्टा आदि। आजकल तो इनकी इस व्यापार की ओर प्रवृत्ति और भी बढ़ गई है जिससे इनका वर्गीकरण निम्न रीति से किया गया है—

(१) वे स्वदेशीय बैंकर जो केवल बैंकिंग व्यापार ही करते हैं।

(२) वे स्वदेशीय बैंकर जिनका प्रमुख कार्य व्यापार है, परन्तु उन्हीं के साथ बैंकिंग व्यापार भी करत हैं।

(३) वे स्वदेशीय बैंकर जो व्यापारी तथा बैंकर दोनों ही कार्य करत हैं परन्तु उनका कौन सा व्यापार प्रधान है यह निश्चित नहीं कहा जा सकता।

इनका वर्तमान महत्व—अभी तक स्वदेशीय बैंकरों का कोई भी नियमित संगठन नहीं है तथा वे जाग स्वतन्त्र रूप से अपना-अपना व्यापार करत हैं। आजकल कुछ नहरा में इन लोगों में अपने-अपने जातीय मज्जा (guilds) बना लिये हैं जिनका स्वरूप विशेषतः सामाजिक है, 'व्यापारिक' नहीं। जैसे बम्बई में मारवाडी चेम्बर ऑफ कामर्स, मुल्तानी तथा शिकारपुरी बैंकिंग सङ्घ, थाक सङ्घ आदि। ये मध्य 'व्यापार' की दृष्टि में समानता लाने जयवा सुविधाएँ देन का प्रयत्न नहीं करत। इसी प्रकार बैंकिंग व्यापार की समुचित शिक्षा का भी कोई प्रबन्ध नहीं करत। विशेषतः इनका 'व्यापार' परम्परागत एवं आनुवंशिक होता है जिसमें उनका इस व्यापार की शिक्षा वैज्ञानिक व्यवहार में घर में ही मिल जाती है। संगठन के इन दावा के रहन हुए भी इनका ग्रामीण स्थिति एवं आवश्यकताओं का अध्ययन पूर्ण है एवं इनका अपने ग्रामीण ऋणी आदिक साथ अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसी कारण सहकारी एवं अन्य बैंकों के हात हुए भी ये लोग ६६% ग्रामीण एवं व्यापारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कहीं-कहीं तो ये लोग कारखानों के मालिक भी हैं एवं बम्बई तथा अहमदाबाद के सूती कारखानों को भी ये निक्षेप के रूप में साख देते हैं। इनके द्वारा कारखानों में रखे हुए निक्षेपों की अवधि दो मास से अधिक नहीं होती। आन्तरिक व्यापार की साख की पूर्ति, ग्रामीण साख की पूर्ति तथा छोटे छोटे उद्योगों की सहायता करने के कार्य में आज भी भारत में इन्हीं का एक प्रकार से एकाधिकार है। इनमें से कुछ बैंकों का बैंकिंग पद्धति का ज्ञान इतना गहरा है एवं वे इतने चतुर हैं कि देश में बैंकिंग पद्धति के एकीकरण की किसी भी योजना में इनका महत्वपूर्ण मानना होगा।<sup>1</sup>

स्वदेशीय बैंकों की वर्तमान अवस्था का कारण—पिछले कुछ वर्षों में स्वदेशीय बैंकों का व्यापार का गहरा चालू पड़ेचा है जिससे उनकी व्यापार दर कम हो गई है तथा व्यापार क्षेत्र भी सीमित हो गया है। इसका प्रमुख कारण सहकारी एवं संयुक्त स्वदेशीय बैंकों का विकास है। इनकी वर्तमान अवस्था के मुख्य कारण निम्न हैं —

<sup>1</sup> 'Agricultural Economist', Sept 1950, p 5

१ सयुक्त स्वध व्यापारिक बैंक तथा सहकारी बैंको की प्रतिधोगिता—इन प्रतियोगी बैंका में स्टेट बैंक का नाम विशेष उल्लेखनीय है क्योंकि उसको सरकारी शेषों (balance) की व्यवस्था तथा राशि स्थानान्तरण की विशेष सुविधाएँ उपलब्ध हैं। इसी प्रकार अन्य सयुक्त स्वध बैंका का भी स्टेट बैंक राशि-स्थानान्तरण की तथा रिजर्व बैंक ऋण आदि सम्बन्धी सुविधाएँ देता है। इनमें स्वदेशीय बैंकर इनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। सहकारी बैंका के विकास के लिए रिजर्व बैंक की विशेष जिम्मेदारी है तथा प्रान्तीय एवं कन्द्रीय सरकारों से भी सहायता प्राप्त है, इससे स्वदेशी बैंकरों का धन संचुचित हुआ है।

२ आधुनिक बैंकिंग को अपनाते की अरुचि—कुछ बैंकगो न आधुनिक पद्धति को अपनाना प्रारम्भ कर दिया है तथा निक्षेपों को बैंक द्वारा निकालने की सुविधा ग्राहकों को दी है। फिर भी अधिकांश बैंक आधुनिक बैंकिंग पद्धति नहीं अपनाते। इसलिए ऐसे स्वदेशीय बैंको को अपना व्यापार सगठित रूप से करना चाहिए अथवा कुछ बैंक मिलकर नये बैंक की स्थापना करें, जैसा कि नेटुकोट्टाई चेट्टियो ने १९२६ में 'बैंक ऑफ चेट्टीनाड लिमिटेड' की स्थापना से किया था। इसी प्रकार जमनी के कमाडिट (commandit) सिद्धान्त के अनुसार य परम्परा बैंकिंग माभदारी बना ल। अर्थात् अन्य व्यापारिक बैंक देहाता में अपनी शाखा-स्थापन न करते हुए स्वदेशीय बैंकरों को उस स्थान का अपना प्रतिनिधि बनाकर उन्हें सुविधाएँ देते रहें तथा लाभ का वितरण आपस में कर लें। किन्तु यह अभी सम्भव हो सकता है जब स्वदेशीय बैंकर परम्परागत पद्धति को छोड़कर आधुनिक पद्धति का अपनाये।

३ अन्य व्यापार की ओर प्रवृत्ति—देश की व्यापारिक उन्नति होने के कारण इन बैंकरों को अन्य व्यापार क्षेत्र में अधिक लाभ मिलने की सुविधा हो गई है जिससे वे बैंकिंग को छोड़ कर अन्य व्यापार करने लगें हैं।

४ वैधानिक अडचनें—बैंकिंग पद्धति आधुनिक न होने से इनको व्यापार में अनेक वैधानिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इनके अतिरिक्त भारतीय प्रांता न कृषक ऋणग्रस्तता को दूर करने के लिए अनेक विधान बना दिये हैं, जिससे इनका कार्य-क्षेत्र सीमित हो गया है। इन विधानों द्वारा अधिकतम ग्याज दर निश्चित कर दी गई है। कहीं-कहीं कृषकों के भोजार आदि बेचने पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं, लेखा पुस्तकें आदि रखने के प्रतिबन्ध लगाकर ऋणी की सम्पत्ति (assets) की भी रक्षा की गई है। उसने इनका व्यापार एवं साख क्रियाएँ कम हो गई हैं।

## स्वदेशीय बैंकर एवं व्यापारिक बैंकों का सम्बन्ध

स्वदेशीय एवं व्यापारिक बैंकों का परस्पर सम्बन्ध भी मन्तोपप्रद नहीं है। व्यापारिक बैंकों ने कुछ स्वदेशीय बैंकों का मान्य बैंक की मूची में ल लिया है, एव उनको ऋण देने की मर्यादा निश्चिन कर ली है, फिर भी इनको नियमित एव अनिवन्ध सहायता नहीं मिलती। इसमें स्वदेशीय बैंकर आवश्यकता पड़ने पर अन्य मार्गों से ऋण प्राप्त करने हैं परन्तु व्यापारिक बैंकों के पाम नहीं जाते। दूसरे, इनमें परस्पर प्रतियोगिता भी है। ऋण देने की मर्यादा भिन्न-भिन्न बैंकों की आर्थिक स्थिति को जाँच के बाद निश्चित की जाती है जो भिन्न-भिन्न बैंकों के लिए भिन्न-भिन्न होती है। निश्चित मर्यादा में हुण्डिया की कटौती की सुविधाएँ भी व्यापारिक बैंक देते हैं परन्तु यह सुविधा केवल नाममात्र की ही है। क्योंकि स्वदेशीय बैंक विशेषतः छाट-छोट व्यापारियाँ एव हृपकों की स्वीकृत हुण्टी पर उन्हें ऋण देता है, जो हुण्डिया व्यापारिक बैंक की दृष्टि में केवल इसीलिए अयोग्य होती है कि वे व्यापारी अथवा हृपक कार्ड मूर्त (tangible) जमानत नहीं दे सकते। इतना ही नहीं अपितु व्यापारिक बैंक स्वदेशीय बैंकों के नाम के रेखांकित अथवा अन्य बैंक भी स्वीकार नहीं करते और न उन्हें राशि-स्थानान्तरण की हो सुविधाएँ स्टेट बैंक में प्राप्त हैं। इसके साथ ही स्वदेशीय बैंकों को व्यापारिक एव स्टेट बैंक के विरुद्ध यह भी शिकायत है कि वे इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते।

### स्वदेशीय बैंकों के दोष

(१) परम्परागत कार्य पद्धति—य अपन पुरान ढग पर ही अपना कार्य करते हैं तथा आधुनिक पद्धति का नहीं अपनाना चाहते। इसमें जनता का यिनवास इनको प्राप्त नहीं होता। जनविश्वास प्राप्त करने के लिए अपने व्यापार का गोपनीय स्वरूप न रखने हुए इन्हें समुचित लखा का प्रकाशन करना चाहिए जिससे इनकी आर्थिक स्थिति की पूण जानकारी जनता को प्राप्त हो सके।

(२) संगठन का अभाव—इनका ऐसा कार्ड भी संगठन नहीं है जो व्यापारिक सुधार एवं परस्पर सहकार्य बढ़ाने में प्रयत्न करे। अतः इनमें आपस में भी व्यापारिक प्रतियोगिता रहती है और ये संगठित रूप से अपना व्यापार नहीं कर पाते। इसीके साथ इनमें तथा व्यापारिक बैंकों में परस्पर सम्बन्ध एवं सहकारिता का अभाव है जिससे मुद्रा-मण्डो का दो भागों में विभाजन हो गया है, जिनको लेन-देन की पद्धति तथा व्याज-दरों में भिन्न-भिन्न है। इस

सहकारिता के अभाव के कारण रिजर्व बैंक का भी इन पर कोई नियन्त्रण नहीं है जिससे सामूहिक शक्ति एवं समानता से कार्य नहीं हो सकता ।<sup>1</sup>

(३) निक्षेप बैंकिंग न अपनाता—दुन्होंने निक्षेप बैंकिंग को विशेष महत्व नहीं दिया जिससे जनता में वचत की आदत नहीं पड़ी और न देश की संचित एवं निष्प्रिय राशि का उत्पादन कार्यों में ही उपयोग हो सका । ये केवल अपने धन का ही ऋण-कार्यों के लिए उपयोग करते रह जिससे उनकी आधुनिक बैंको की भांति उन्नति नहीं हुई ।

(४) ऋण देने की दोषपूर्ण पद्धति एवं अधिक व्याज दरें—इनकी ऋण देने की पद्धति दोषपूर्ण तथा व्याज दर भी बहुत अधिक रही । इतना ही नहीं, अपितु इन्होंने ऋणी के अज्ञान का अनुचित लाभ उठाया तथा कपट द्वारा अपन को पूंजीपति बनाया । यह आरोप इन पर किया जाता है, परन्तु ऐसा सभी बैंक नहीं करते थे यह मानना पड़ेगा ।

(५) बैंकिंग के साथ अन्य व्यापार करना—स्वदेशीय बैंक बैंकिंग-नियमों एवं कार्य-पद्धति का पालन नहीं करते क्योंकि वे बैंकिंग के साथ अन्य व्यापार तथा सट्टा भी करते हैं । इससे उनको किसी भी प्रकार में हानि होने की दशा में निजी हानि तो हाती ही है परन्तु साथ ही साथ उनके पास जिन व्यक्तियों के निक्षेप होते हैं उनकी भी हानि होती है । इससे जनता में उनके प्रति अविश्वास हो गया है ।

(६) नये विनियोग साधनों की खोज नहीं की—स्वदेशीय बैंकरो ने विनियोगों के नये-नये स्रोतों की भी खोज नहीं की जो आधुनिक बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण कार्य है । ये केवल अपन ही लाभ में लगे रहे और आवश्यकतानुसार साख का प्रसार एवं सकुचन करने में भी असफल रह ।

**स्वदेशीय बैंकरो के सुधार के लिए सुझाव**

इन दोषों के होते हुए भी आधुनिक ग्रामीण बैंकिंग व्यवस्था में इनका विशेष महत्वपूर्ण स्थान है । साथ ही इनका ग्रामीण साख की आवश्यकताओं तथा ग्राहकों से इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि आज भी बैंकिंग की किसी भी योजना में इनका समावेश होना चाहिए, जिससे ये किसी न किसी प्रकार से देश के अन्य बैंकों के साथ सम्बन्धित हो सकें और इन पर नियन्त्रण करने में रिजर्व बैंक सफल हो । इनको अधिक उपयोगी बनाने के लिए निम्न सुझाव हैं—

<sup>1</sup> *Indigenous Banking in India* by Dr. L C Jain, pp 185-189

केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति (१९२६)—यह समिति इनको जबरदस्ती नियन्त्रण में रखने के विरुद्ध थी। ३,१०,००० बैंकरो को (१९४१ में) जबर-दस्ती नियन्त्रण में लाना एक तो सम्भव भी नहीं था। हमारे अनिवार्य वैधानिक नियन्त्रण में आने के स्थान पर सम्भवतः ये व्यापारों की छड़ देने जिम्मे धामीण एक कृपि माख को भयंकर हानि होती। इसलिए समिति ने यह प्रस्ताव किया कि—

१ रिजर्व बैंक नया व्यापारिक बैंक उनका उपयोग बैंक एवं विला के मग्नहण के लिए उसी प्रकार करे जिम प्रकार सहकारी बैंक एवं अन्य मयुक्त स्वध बैंकों का किया जाता है। इनको उसी प्रकार में राशि स्थानान्तरण, बिल और हुण्डियों की कटौती की सुविधाएँ भी दी जायें। इसलिए इन बैंकों पर अन्य व्यापार न करने का नियन्त्रण भी लगाया जाय जिससे मुद्रा-मण्डी में इनका स्थान महत्वपूर्ण होगा।

२ स्वदेशीय बैंकर, जो अन्य कोई भी व्यापार नहीं करते, रिजर्व बैंक से अपना सीधा सम्बन्ध स्थापित करें तथा उनका नाम 'स्वदेशीय बैंकों की मान्य मूखी' में लिखा जाय और उन्हें जिनो की कटौती की सुविधाएँ दी जायें।

३ स्वदेशीय बैंकर लेखा रखने की पुस्तकें तथा उनके अकेशन (auditing) में सुधार कर तथा बिल एवं बैंकों का उपयोग बढाय।

४ स्वदेशीय बैंकर एवं मयुक्त स्वन्ध बैंक का गयामम्भव एकीकरण किया जाय।

५ स्वदेशीय बैंकर अपना सहकारी बैंकिंग सध बनायें जो अपन गवम्पा के बिलो की कटौती करे तथा पुन कटौती की सुविधाएँ रिजर्व बैंक उन्हें द।

६ स्वदेशीय बैंकर नमरा अपन व्यवसाय का स्थान्तर विलों की बलाली में करें तथा मुद्रा मण्डी में भी यही कार्य करे जिमने बिल बाजार का विकास हो।

७ जो स्वदेशीय बैंकर रिजर्व बैंक के गवस्य हा व अपन निक्षेधों के कुछ धनुपात में रिजर्व बैंक के पास निक्षेप रखें। किन्तु जिन बैंकों के निक्षेप उनकी पूंजी में पाँच गुने नहीं हैं उन पर प्रथम पाँच वर्ष के लिए ऐसी कोई शर्त न हो। इससे रिजर्व बैंक माख नियन्त्रण अच्छी प्रकार में कर संवगा।

८ देश की सभी बैंकिंग संस्थाओं में महयाग वज्ञान के लिए एक अविल भारतीय बैंकिंग सध' की स्थापना हो।

इसी प्रकार प्रांतीय बैंकिंग जांच समितियों ने भी निम्न सुभाष दिये थे—

१ रिजर्व बैंक स्वदेशी बैंकरो को अपना सदस्य बना ले तथा उन पर

कुछ व्यापारिक शर्तें लगा दे। साथ ही जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक अथवा स्टेट बैंक की शाखा नहीं है वहाँ वे उनके अभिकर्ता का कार्य करें। इन सदस्यों को कुछ विशेष अधिकार एवं उत्तरदायित्व दिया जाय। रिजर्व बैंक से ये अपने निक्षेपों के अनुपात में रोकड़-निधि रखें जिसके बदले में उन्हें बिलों के पुनः कटौती की सुविधाएँ मिलें।

२ स्वदेशीय बैंकर जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिए अपने व्यवसाय को आधुनिक पद्धति पर संगठित करें तथा अपने लेखे भी आधुनिक ढङ्ग पर रखें जिसका निरीक्षण करने का अधिकार रिजर्व बैंक को हो।

३. स्टेट बैंक तथा व्यापारिक बैंक स्वदेशीय बैंकरों के व्यापारिक बिलों की बिना शर्त कटौती करें।

४ आवश्यकतानुसार रिजर्व बैंक स्वदेशीय बैंकरों को अपना सदस्य बनाने के लिए कुछ शर्तों के माध्यम से लाइसेंस दे। इन लाइसेंस प्राप्त बैंकरों को बिलों के पुनः कटौती की अन्य सुविधाएँ दी जायें।

**स्वदेशीय बैंकर तथा रिजर्व बैंक**

रिजर्व बैंक अधिनियम की धारा ५५ (१) (अ) के अनुसार रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी थी कि वह अधिनियम की उस धारा को, जो सूचीबद्ध बैंकों के लिए है, ब्रिटिश भारत में वैध बनाने वाली अन्य संस्थाओं पर लागू करे और इस सम्बन्ध में अपनी रिपोर्टें गवर्नर-जनरल को तीन वर्ष में दे।

इस धारा का सम्बन्ध और किसी भी बैंकिंग संस्था से न होते हुए केवल स्वदेशीय बैंकरों से ही था। रिजर्व बैंक ने १९३७ में जो रिपोर्टें दी उसमें निम्न सुझाव है —

१ रिजर्व बैंक से सम्बन्धित होने के पूर्व देशी बैंकर अपनी श्रियाएँ भारतीय कम्पनी अधिनियम की धारा २७७ (फ) तक ही सीमित रखें तथा समुचित समय में अन्य व्यापार का अन्त करें।

२ स्वदेशीय बैंकरों को अपने व्यापार का स्वरूप एवं कार्य सयुक्त स्कंध बैंकों के समान ही रखना चाहिए, विशेषतः निक्षेप-स्वीकृति के व्यवहार में वृद्धि करनी चाहिए।

३ जिन स्वदेशीय बैंकरों की पूँजी २ लाख रुपए है वे ५ वर्ष में अपनी पूँजी ५ लाख रुपए करें तथा रिजर्व बैंक की सदस्य-मूची में मगामेलित करने के लिए आवेदन दें।

४ स्वदेशीय बैंकरों के निक्षेप यदि उनकी पूँजी से ५ गुने हों तो निक्षेप का कुछ अनुपात रिजर्व बैंक के पास रखें।

४ उनको अपनी लेखा-पुस्तकें माली-भांति रखकर विरोधों में निरीक्षण कराना चाहिए तथा रिजर्व बैंक को उन्हें देखने का अधिकार होना चाहिए ।

६ अन्य सूचीबद्ध बैंकों की भांति रिजर्व बैंक के पास समय-समय पर वे अपने कार्यों का आवश्यक विवरण भेजें तथा स्थिति-विवरण भी प्रकाशित करें ।

इन बातों का पूरा करने पर स्वदेशीय बैंकर रिजर्व बैंक में मान्य होंगे एवं सरकारी प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण प्राप्त कर सकेंगे । इसमें उन्हें सूची-बद्ध बैंकों की भांति राजि-स्थानान्तरण की सुविधाएँ भी दी जायेंगी ।

रिजर्व बैंक की यह योजना सफल न हो सकी तथा इस सम्बन्ध में स्वदेशीय बैंकों की ओर से जो उत्तर दिये गये वे भी मनोरंजक हैं । श्री चुन्नीलाल मेहता ने वम्पर्ड थ्रॉफ मघ की ओर से लिखा था कि भारतीय अधिनियम की २७७ (फ) धारा के अन्तर्गत आने वाले अनेक कार्यों को वे अब भी कर रहे हैं तथा रिजर्व बैंक ने उन्हें अपना परम्परागत अन्य व्यवसाय छोड़ देने के लिए कहने के पूर्व उनमें व्यवहार आरम्भ करना चाहिए था । इसके बाद यह निश्चित किया होता कि अन्य व्यापार करने के कारण बैंकिंग व्यवसाय को क्षति होनी है क्या ? यह देखने के उपरान्त उस व्यापार को छोड़ने के लिए कहा होता । इसी प्रकार एक मुल्तानी बैंकर ने लिखा था कि वे इस मुद्दाव से महत्त्व हैं कि स्वदेशीय बैंकर बैंकिंग के प्रतिरिक्त अन्य व्यवसाय न करें परन्तु लेखों के निरीक्षण एवं अकंक्षण (auditing) का उन्हें घोर विरोध है । दूसरे एक पत्र में यह भी लिखा गया था कि यदि रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों की भांति स्वदेशीय बैंकों से व्यापार करना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं । किन्तु जो बातें नगार्द गई हैं उनमें होने हुए कोई भी स्वाभिगानी बैंकर बिना की पुन कठौती के लिए आपसे दरवाजे नहीं आयेगा ।<sup>1</sup>

अब यह समझ में नहीं आता कि रिजर्व बैंक निक्षेप बढ़ाने के लिए इन बैंकों पर क्या दबाव डालता है जब ये स्वयं ही देश की बैंकिंग प्रणाली में अपना स्थान उत्तम करना चाहते हैं । हाँ, समय की माँग के अनुसार स्वदेशीय बैंकर अपनी कार्य-प्रणाली में अवश्य परिवर्तन करें जिसमें वे जनता का विश्वास प्राप्त कर सकें एवं मुद्रा-मण्डी के विभिन्न अंग मगठित हों । परन्तु इनको किसी अधिनियम में नियन्त्रित करके मगठित नहीं किया जा सकता और न

<sup>1</sup> *A Study of Indian Money* by Bimal C Ghosh, pp 153-154.

देश के बैंकिंग-क्लेवर से इनको हटाया जा सकता है। अतः इनका मगठन एवं नियन्त्रण केवल तीन मार्गों में ही हो सकता है —

१ रिजर्व बैंक विल-बाजार बढ़ाये तथा विलों की पुनः कटौती की सुविधाएँ सभी स्वदेशीय बैंकरो को दे, जो रिजर्व बैंक की मददस्पर्ता स्वीकार करें, इससे विल-बाजार का विकास हो सकेगा। इन सुविधाओं को देते समय ऐसे व्यापारिक दन्धन न लगाये जायें जो उनको अमान्य न हो।

२ रिजर्व बैंक इनके साथ मदभावता का व्यवहार करे तथा अपने मेल-जोल में इनकी कार्य-प्रणाली नियत करे। इन्हें उसी प्रकार सब सुविधाएँ दे जो अन्य बैंकों को है और जमना इनके व्यापार को नियन्त्रण में लाया जाय।

३ देश का बैंकिंग-क्लेवर इतना संगठित किया जाय जिसमें जनता की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अविलम्ब एवं बिना किसी औपचारिकता (formality) के पूर्ण हो सके, विशेषतः कृषि माल की, जिसमें स्वदेशीय बैंकरो की आवश्यकता ही न रहे।

रिजर्व बैंक से सम्बन्धित होने से लाभ

(१) रिजर्व बैंक एवं स्वदेशीय बैंकरो के सम्बन्धित होने से देश की मुद्रा-मण्डी के विभिन्न अंगों का मगठन हो जायगा एवं वह सात-नियन्त्रण में सफल हो सकेगा।

(२) संयुक्त स्कन्ध तथा महकारी बैंकों की प्रतिस्पर्धा के कारण स्वदेशीय बैंकरो की जो अवनति हो रही है एवं व्यापार घट रहा है, वह इनके सम्बन्धित हो जाने पर नहीं होगा। अपितु इनको ग्रामीण परिस्थिति का विशेष ज्ञान होने के कारण, ग्रामीण क्षेत्र में साव-निर्माण करने का एकाधिकार प्राप्त हो जायगा।

(३) इनको अन्य व्यापार करने की आवश्यकता भी प्रतीत नहीं होगी क्योंकि रिजर्व बैंक से सम्बन्धित होने के कारण इनका बैंकिंग व्यापार बढ़ेगा।

(४) रिजर्व बैंक से सम्बन्धित होने पर इन्हें राशि-स्थानान्तरण, पुनः कटौती आदि की सुविधाएँ मिल सकेंगी तथा रिजर्व बैंक को भी इनमें कुछ विवरण, जो वे देने के लिए तैयार हैं, प्राप्त हो सकेगा। इससे देश की बैंकिंग प्रगति एवं आर्थिक स्थिति का सही ज्ञान हो सकेगा।

(५) इस परस्पर सम्बन्ध में वे जनता एवं देश के अन्य बैंकों का विश्वास प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें देश के बैंकिंग क्लेवर में इनका महत्वपूर्ण स्थान हो जायगा।

### माराश

इंपोरियल बैंक (स्टेट बैंक), विनिमय बैंक, व्यापारिक बैंक एवं सहकारी बैंकों को छोड़कर जो हुण्डियो का व्यवहार करते हो, जनता से निक्षेप लेते हो एवं ऋण देते हो वे स्वदेशीय बैंकर हैं। सामान्य ऋणदाता से स्वदेशीय बैंकरो में भिन्नता है; क्योंकि महाजन निक्षेप नहीं लेते, हुण्डियो में व्यवहार नहीं करते ऋण देने के साथ अन्य व्यापार को प्राथमिकता देते हैं, केवल निजी धन से ही ऋण देते हैं तथा कृषिकार्यों के लिए ही विशेषतः उपयोग के लिए ऋण देते हैं। महाजनो का कार्य कोई भी कर सकता है परन्तु स्वदेशीय बैंकिंग केवल विशेष जानियों द्वारा ही किया जाता है।

समुक्त स्वयं बैंक और स्वदेशीय बैंकर में निम्न भेद है—

- |                                                          |                                                                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| १ भारतीय सम्पत्ती अधिनियम के अन्तर्गत समामित्तन अनिवार्य | १ समामित्तन अनावश्यक                                                         |
| २ लेखों का प्रकाशन—अनिवार्य                              | २ लेखे गोपनीय                                                                |
| ३ निक्षेप राशि को चक में निकालने की सुविधा देते हैं      | ३ ऐसी सुविधा नहीं                                                            |
| ४ व्यक्तिगत सम्पर्क का अभाव                              | ४ व्यक्तिगत सम्पर्क धनिष्ठ                                                   |
| ५ केवल अल्पकालीन ऋण प्रदाय                               | ५ अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदाय                                         |
| ६ केवल बैंकिंग व्यवसाय ही करते हैं                       | ६ अन्य व्यवसाय भी बैंकिंग के साथ करते हैं परन्तु बैंकिंग की प्रधानता रहती है |
| ७ ऋण की जमानत आवश्यक                                     | ७ जमानत लेना, न लेना इनकी इच्छा पर निर्भर                                    |
| ८ औपचारिकता अधिक                                         | ८ औपचारिकता नहीं कार्य प्रणाली सरल, व्याज दर अधिक                            |
| ९ केवल तरल सम्पत्ति की जमानत लेते हैं                    | ९ चल एवं अचल सम्पत्ति की जमानत मान्य करते हैं                                |

कार्य प्रणाली—इनकी कार्य-प्रणाली सरल होती है तथा लेन-देन अपने घर पर ही करते हैं। ये जनता से निक्षेप लेते हैं, ऋण देते हैं, हुण्डियो में व्यवहार करते हैं। इनका महत्व ग्रामीण कृषि-माद्य में अधिक है क्योंकि ये लगभग ६०% ग्रामीण साध देते हैं। इसीलिए इनको बैंकिंग विकास की किसी भी योजना से छूट नहीं किया जा सकता।

दुनवी वर्तमान अवनाति के कारण—(१) समुक्त स्पर्ध व्यापारी बैंकों एवं सहकारी बैंकों के साथ प्रतियोगिता, (२) आधुनिक बैंकिंग को न अपनाना, (३) अन्य व्यापार की ओर प्रवृत्ति, (४) वैधानिक छटछनें (ऋण की वसूली में) ।

स्वदेशी बैंकों के दोष—(१) परम्परागत कार्य पद्धति, (२) आपसी संगठन का अभाव (३) निक्षेप बैंकिंग न अपनाना, (४) ऋण देने की बोधपूर्ण पद्धति, (५) अधिक व्याज दरें, (६) बैंकिंग के साथ अन्य व्यवसाय करना, (७) नये विनियोग साधनों की खोज नहीं की, इनके सुधार एवं रिजर्व बैंक से सम्बन्धित करने के लिए केन्द्रीय व राज्य बैंकिंग जाँच समितियों ने अनेक सुझाव दिये तथा रिजर्व बैंक ने भी इनकी सम्बन्धित करने की योजना बनाई थी । इसकी शर्तें थीं कि—(१) ये केवल बैंकिंग व्यवसाय ही करें, (२) निक्षेपों में वृद्धि करें, (३) पूँजी से पाँच गुने निक्षेप होने पर रिजर्व बैंक के पास उसका कुछ अनुपात रखें, (४) लेखा पुस्तकों का अन्वेषण करायें तथा वे रिजर्व बैंक के परीक्षण के लिए खुली रहे, (५) रिजर्व बैंक के पास अन्य बैंकों की भाँति सामयिक विवरण भेजें तथा स्थिति विवरण प्रकाशित करें । परन्तु इनकी ये शर्तें मान्य न होने से ये अभी तक रिजर्व बैंक से सम्बन्धित नहीं हो सके हैं, जिससे मुद्रा-मन्त्री का एक महत्वपूर्ण अंग अनियन्त्रित है ।

## अध्याय १६ व्यापारिक बैंक

व्यापारिक बैंक साधारणतः उन मयुक्त स्क्व बैंको को कहते हैं जो भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ के अनुसार भारत में स्थापित किये गये हैं। मयुक्त स्क्व बैंक वास्तव में किसी भी बैंक को कहते हैं जो कम्पनी के रूप में समायोजित हुआ हो फिर चाहे वह विनिमय बैंकिंग, कृषि बैंकिंग अथवा किसी भी प्रकार का बैंकिंग व्यवसाय क्यों न करे। परन्तु मयुक्त स्क्व बैंक विशेषतः व्यापारिक बैंकिंग कार्य करते हैं अतः इन्हें ही सर्वसाधारण रूप में व्यापारिक बैंकिंग कहा जाता है। इनका कार्य जनता से माय पर देय अल्पकालीन निक्षेप स्वीकारना तथा व्यापारिक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋणों की पूर्ति करना है। इस प्रकार भारत में स्टेट बैंक और रिजर्व बैंक को छोड़कर जितने भी अन्य सीमित देनदारी वाले बैंक हैं वे सब व्यापारिक अथवा मयुक्त स्क्व बैंक हैं। स्टेट बैंक भी व्यापारिक बैंकिंग कार्य करता है परन्तु इसका निर्माण स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट से हुआ है अतः यह इस सामान्य नियम का अपवाद है। इसी प्रकार विदेशी विनिमय बैंको का मुख्य कार्य विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता देना है परन्तु वे भी व्यापारिक बैंकिंग नियामक करते हैं तथा उनका सम्मेलन विदेशों में हुआ है।

३१ मार्च १९५८ के अन्त में भारत में कुल सूचीबद्ध बैंको की संख्या ८९ तथा उनके कुल कार्यालयों की संख्या ३४५५ थी। उनके कुल निक्षेपों की राशि १ अप्रैल १९५६ को १०१९ ५९ करोड़ रुपये थी। इस प्रकार असूचीबद्ध बैंकों की संख्या १९५३ के अन्त में ४३७ तथा उनके निक्षेपों की राशि ६२ ७६ करोड़ रुपये तथा कार्यालय संख्या १२६८ थी।

### व्यापारिक बैंको का वर्गीकरण

साधारणतः व्यापारिक बैंको को दो श्रेणियाँ में हम बाँट सकते हैं—

१ सूचीबद्ध बैंक (Scheduled Banks)—इनका समावेश रिजर्व बैंक एक्ट के अनुसार दूसरी सूची में होता है। इस हेतु व्यापारिक बैंक को रिजर्व बैंक एक्ट की धारा ४२ (६) की शर्तें पूर्ण करनी पड़नी हैं, जो निम्न हैं —

(अ) जो बैंक भारतीय राज्यों में व्यवसाय करता है ।

(आ) जिस बैंक की चुकता पूंजी एवं निधि मिलाकर ५ लाख रुपये में कम नहीं है ।

(इ) जिनको अपनी माँग एवं समय देनदारी के तमाम ५% व २% कांफ रिजर्व बैंक के पास जमा करना पड़ता है ।

(ई) जिन बैंको के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को विश्वास है कि उनकी क्रियाएँ निक्षेपकर्त्ताओं के हित में हो रही हैं ।

२ असूचीबद्ध बैंक (Non-Scheduled Banks)—जिन व्यापारिक बैंकों का समावेश रिजर्व बैंक की दूसरी सूची में नहीं होता उन्हें असूचीबद्ध बैंक कहते हैं । इनका वर्गीकरण चुकता पूंजी एवं निधि के अनुसार चार वर्गों में होता है —

‘अ’ (a) श्रेणी—जिनकी चुकता पूंजी एवं निधि मिलाकर ५ लाख रुपये से अधिक है ।

‘ब’ (b) श्रेणी—जिनकी चुकता पूंजी एवं निधि मिलाकर १ लाख से ५ लाख रुपये तक है ।

‘स’ (c) श्रेणी—जिनकी चुकता पूंजी एवं निधि मिलाकर ५०,००० रुपये से १ लाख रुपये तक है ।

‘द’ (d) श्रेणी - जिनकी चुकता पूंजी एवं निधि मिलाकर ५०,००० रु० तक है ।

### व्यापारिक बैंको की कार्य-प्रणाली

व्यापारिक बैंको के प्रमुख कार्य नीचे हैं\* —

(१) जनता से निक्षेप स्वीकार करना,

(२) साख-निर्माण तथा ऋण-प्रदाय द्वारा जनता की वित्त शक्ति का संचार करना, तथा

(३) अन्य कार्य, जैसे अधिकर्ता की सेवाएँ, ग्राहकों को आभूषण, प्रलेख आदि की सुरक्षा के लिए सुविधाएँ देना, आदि ।

यहाँ केवल यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि व्यापारिक बैंक जनता में स्थायी, संचय तथा चल निक्षेप लेकर उम्मीद से जनता की व्यापारिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण देते हैं जिससे व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रगति को गति मिलती है ।

\* देखिए अध्याय १ ।

ऋण देना—व्यापारिक ऋण दो प्रकार में ऋण दत्त है। एक तो केवल ऋणी की वैयक्तिक जमानत पर तथा दूसरे ऋणी की वैयक्तिक जमानत के साथ ही अन्य दो व्यक्तियाँ तथा सहायक प्रतिभूतियाँ की जमानत पर। जो ऋण बिना किसी सहायक तथा अन्य व्यक्तियों की जमानत पर दिय जाते हैं और जिनमें केवल ऋणी की ही वैयक्तिक जमानत होती है उनको अरक्षित ऋण, तथा जिन ऋणों के लिए वह सहायक प्रतिभूतियाँ की जमानत लता है उन्हें रक्षित ऋण कहते हैं। भारत में बचन ऋणा की जमानत पर विशेषतः ऋण नहीं दिय जाते। ऋणा की जमानत बैंक के धातु खजाने पर निर्भर रहती है। यदि किसी बन्दरगाह में बैंक कार्यालय है तो उस स्थान का विशेषतः विदेशी व्यापार होगा एवं ऐसे स्थानों पर व्यापारियों का जो ऋण आदि दिय जायगा वे वस्तुओं (goods) की जमानत पर अथवा जहाजों विल्टो आदि की जमानत पर दिय जायगा। परन्तु विशेषतः विदेशी व्यापार के लिए ऋणा की सुविधाएँ दत्त का कार्य विदेशी विनिमय बैंक करने है। व्यापारिक बैंकों को विनिमय बैंक जैसी सुविधाएँ न हान से यह कार्य व्यापारिक बैंक पूर्ण रीति में नहीं कर पाते। जैसा कि केन्द्रीय बैंकिंग बोर्ड समिति ने कहा है कि भारत के विदेशी व्यापार को आर्थिक सुविधाएँ दत्त में वह कोई भी प्रत्यक्ष कार्य नहीं करते—उस स्तर पर जहाँ बन्दरगाह में माल बाहर जाता है अथवा जिन बन्दरगाहों पर माल आता है। स्पष्ट है कि व्यापारिक बैंक केवल देशी व्यापार एवं उद्योग की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जहाँ पर विनिमय बैंक के व्यवहार अधिक मात्रा में है वहाँ पर व्यापारिक बैंक बैंक विनिमय प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देते हैं। इसी प्रकार कृषि क्षेत्र में, जहाँ इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ नहीं हानी वे कृषि वस्तुओं (agricultural produce) की जमानत पर ऋण दत्त हैं। औद्योगिक अल्पकालीन साख की पूर्ति व मालों के विभिन्न प्रकार की वित्तियोगीन प्रतिभूतियों की जमानत पर अथवा कच्चे माल की जमानत पर करते हैं।

भारतीय व्यापारिक बैंक केवल वैयक्तिक जमानत पर ऋण नहीं दत्त। बैंक तो केवल ठेका आह्वान का जिनकी साख में उन्हें पूर्ण विश्वास है उनका प्रतिशोधन पर अथवा बिल एवं हुण्डियाँ पर ऋण देते हैं। परन्तु अपनी राशि का सुरक्षा के लिए वे अन्य दो मालदार व्यक्तियों की जमानत इनके रूप में वित्तियोग पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं।

य अधिविषय एवं रोक ऋण (cash credit) की भी सुविधाएँ देते हैं जिनकी जमानत के लिए वे आह्वानों से बन्ध, अर्थात् ऋण पत्र अथवा अन्य प्रति

भूतियाँ लेते हैं। औद्योगिक आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति ये कभी-कभी करते हैं परन्तु यह कार्य ये बहुत ही कम मात्रा में करते हैं क्योंकि इनके निक्षेप अल्पकालीन होने के कारण अल्पकालीन ऋणों की सुविधा देना इनके व्यापारिक स्वरूप के अनुसार आवश्यक होता है। यदि वे ऐसा न करें तो किसी भी समय उनकी आर्थिक स्थिति खतरनाक हो सकती है।

व्यापारिक बैंक प्रथम श्रेणी के व्यापारिक विलों की कटौती भी करते हैं परन्तु हगारे यहाँ बिल-बाजार निश्चित न होने से यह कार्य भीमित है। परन्तु आशा है कि भविष्य में विलों की कटौती अधिक परिमाण में हो सकेगी।

व्यापारिक बैंक वित्तपत्र कृपि को साख सुविधाएँ नहीं देते क्योंकि एक तो किसानों के पाम जमानतों आदि का अभाव रहता है तथा उनकी भुगतान-शक्ति अनेक कारणों से सीमित रहती है। अतः कृपि साख में इनका स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, ये थोड़ी-सी साख की पूर्ति केवल कृषिज वस्तुओं की विक्री (marketing) के लिए करते हैं जो वित्तपत्र स्वदेशीय बैंको अथवा सहकारी बैंको के माध्यम से दी जाती है। ये कृषि-साख की पूर्ति कर सक, इसलिए यह आवश्यक है कि कृषिज-वस्तुओं की विक्री-संगठन में मुधार किया जाय क्योंकि देहातों में साइमंसधारी भाण्डारों का तो अभाव ही है। इस दशा में अब प्रयत्न हो रहे हैं।

संक्षेप में व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं में चल एवं अन्य निक्षेप लेखों का रखना, विलों की कटौती से व्यापार एवं उद्योगों को आर्थिक सहायता देना तथा साख खोलना एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यों का समावेश होता है। प्रो० गिलबर्ट के अनुसार व्यापारिक बैंकों को निम्न कार्य नहीं करने चाहिए<sup>१</sup>—

- (१) ग्राहकों को व्यापार संपालन के लिए पूँजी देना।
- (२) स्थायी ऋण देना।
- (३) एक ही ग्राहक को अधिक परिमाण में ऋण देना।

अन्य कार्य—उक्त कार्यों के अतिरिक्त व्यापारिक बैंक अनेक सहायक कार्य करते हैं। ये ग्राहकों को राशि-स्थानान्तरण (remittance) की सुविधाओं के साथ आर्थिक एवं व्यापारिक मामलों में भी सलाह देते हैं। ग्राहकों की ओर से प्रतिभूतियों का रूप-विन्यास करते हैं तथा उनके बैंक, कृषिज-वस्तुओं का संग्रहण तथा उनकी बीमे की किस्त, आय-कर आदि का भुगतान करते हैं। अपने ग्राहकों को अन्य ग्राहकों के सम्बन्ध में आर्थिक जानकारी देते हैं तथा उनको आवश्यक साख-प्रदाय करते हैं।

पाँच महान् बैंक तथा सात महान् बैंक—भारत के वर्तमान सूची-बद्ध बैंको में निम्न महत्वपूर्ण हैं, जो 'सात महान् बैंको' में आते हैं एवं इनके निशेष २५ करोड़ रुपए से अधिक हैं —

बैंक का नाम	स्थापना	कार्यालय एवं शाखाएँ	कुल निशेष
		(१९४५ में)	(१९४५) साल रु०
*१ पंजाब नेशनल बैंक	१८८४	१६७	५१५२४६
*२ बैंक ऑफ इण्डिया	१९०६	३०	५६०१'५४
३ बी इण्डियन बैंक	१९०७	६३	?
*४ बैंक ऑफ बड़ौदा	१९०८	३३	२९६७६५
*५ सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया	१९११	३०८	१०५२३४१
६ बैंक ऑफ मैसूर लि०	१९१२	३१	?
*७ अलाहाबाद बैंक लि०	१९२३	७५	२८७४६०

उक्त बैंको में जिन बैंको पर \* यह चिह्न है उनकी गणना "पाँच महान् बैंको" में हानी है। इनके अतिरिक्त युद्ध-काल में स्थापित युनाइटेड कमर्शियल बैंक (१९४३) की गणना भी वर्तमान महान् बैंको में है। इसकी शाखाएँ ६२ हैं।

### व्यापारिक बैंको की विदेशी शाखाएँ

भारतीय व्यापारिक बैंको की शाखाएँ विदेशों में भी काय करती हैं तथा देश के व्यापारियों का कुछ हद तक विदेशी विनिमय की सुविधाएँ प्रदान करती हैं। इनकी शाखाएँ जिन देशों में हैं उन देशों के साथ विदेशी व्यापार के लिए आर्थिक सुविधाएँ भी देती हैं।

भारतीय व्यापारिक अमूचीबद्ध एवं सूचीबद्ध बैंकों की १९४६ में जमना १८३ एवं ६२८ विदेशी शाखाएँ थी। ये शाखाएँ अब कम होती जा रही हैं।

सूचीबद्ध बैंक	अमूचीबद्ध बैंक
१९४६	६२८
१९४७	४६३
१९४८	२२६
१९४९	१४७
१९५०	१०५
१९५१	१११

इन कार्यालयों में पाकिस्तान का भी समावेश है। वका की विदेशी शाखाओं की मर्यादा पाकिस्तान की शाखाएँ बढ़ाने के कारण कम हुई है। १९४७ से १९५१ की अवधि में मूचीबद्ध एवं जमूचीबद्ध वका ने अपने उम्मा ३५६ एवं ५१ कार्यालय बढ़ा किये। ये सभी कार्यालय पाकिस्तान में थे। इसके विपरीत अन्य देशों में नये कार्यालय खाने लगे हैं। इससे स्पष्ट है कि भारतीय व्यापारिक वक कुठ अज न विदेशी विनिमय क्षेत्र में अधिक हिस्सा लेने लगे हैं। यह व्यापारिक वको का मुद्राढता का परिचय देती है।

**व्यापारिक वको की प्रगति—**जैसा कि हम देख चुके हैं व्यापारिक वका की शाखाएँ कार्य क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि में अत्यन्त की अपभ्या बहुत ही कम हैं। जो प्रगति द्वितीय महायुद्ध से हुई है वह केवल बड़े बड़े शहरों तक ही सीमित है। अन्य शहरों में वको की शाखाएँ या तो हैं ही नहीं अथवा जहाँ हैं वहाँ अपर्याप्त हैं। अतः तो वक शाखाओं के विस्तार की ओर न रुकते हुए अपना अपना कार्यालय ठोस बनाने में प्रगतिशील हैं जो भविष्य में किसी भी प्रकार के वैश्विक मकट से बचने के लिए निस्सन्देह आवश्यक है। भारतीय वका की उन्नति न होने देने में उनकी कार्यकारी की अनवरत त्रुटियाँ हैं तथा अनेक बाह्य कठिनाइयाँ बाधक हैं जिससे वे अपना कार्य क्षेत्र न बढ़ा सकें।

**कार्यकारी की त्रुटियाँ—**भारतीय व्यापारिक वका की कार्यकारी की त्रुटियाँ निम्नलिखित हैं —

(१) सबसे पहला दोष इनकी कार्य पद्धति में यह है कि ये वक अधिकतर पूँजी का विनियोग सरकारी प्रतिभूतियों में करते हैं जिससे व्यापारिक बिला का अधिक प्रचार एवं उपयोग नहीं हो सका।

(२) भारत में वक स्वीकृति बिलों (bank acceptances) का अभाव है। वक व्यापारियों को इनकी सुविधा नहीं देने तथा वे रोक-टोक की सुविधाएँ अधिक परिमाण में देते हैं जिससे प्रथम धनी के व्यापारिक बिला का अभाव है। इससे वैश्विक विकास में बाधा होती है और उनकी निधि विनियोजित इस प्रकार के ऋणों में ही समाप्त हो जाती है।

(३) भारतीय वक अपने ग्राहकों को व्यक्तिगत साक्ष पर ऋण नहीं देते जैसा कि पाश्चात्य राष्ट्रों में होता है। इससे इनकी व्यापारिक प्रगति नहीं हो पाती। इसका प्रमुख कारण भारत में पाश्चात्य दशा की तरह सड़ (seds) दून (duns) जादि जैसा मर्यादा नहीं है जो वका का उनके ग्राहकों की आर्थिक स्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान दे।

(४) भारत में एक व्यक्ति एक वक प्रथा नहीं है जो पाश्चात्य देशों

म है। इसमें वक् एवं ग्राहक व परस्पर सम्बन्ध में घनिष्टता नहीं आती। इतना ही नहीं अपितु पादचात्य दशा में ग्राहक अपने वक् का अपनी आर्थिक स्थिति का पूरा विवरण भी नामयिक (periodically) भजत रहत है। इसमें वक् उन्हें वैयक्तिक भास पर ऋण दत्ता है। परन्तु भारतीय व्यापार अपनी आर्थिक स्थिति की पूर्ण जानकारी बैंको का भी दना पसन्द नहीं करत। इसमें ऋणा की व्यक्तिगत भास पर ऋण इन की प्रथा वक् नहीं अपना पात।

(५) भारतीय वक् न विदेशी बैंको की शान शोकत की झूठी नकल की पदस्तु उनकी भाति काय शक्ती अपनाने का यत्न नहीं किया। इसमें उनकी कायधनता न वृद्ध हुए काय व्यय अवश्य वृद्ध गये जिसमें व अपने ग्राहकों को अधिक मुविधाएँ नहीं दे सक। इस कारण ग्राहक इनकी श्रार आकर्षित न हुए और उन्होंने अपने जैसे उनमें अधिक कायधन विदेशी बंका में रख कुछ व्यक्ति ऐसे ग्राहकों पर अराष्ट्रीयता का दाप लगात है परन्तु वास्तविक स्थिति नहीं दत्त।

(६) भारतीय बैंका न आर्थिक सिद्धान्तों का पूरा रूप में पालन नहीं किया। उन्होंने अपनी राशि ऐसे कार्यों में लगाई जिन कार्यों में उनकी नहीं लगाना चाहिए थी जैसे चादी मान का सट्टा आदि। इतना ही नहीं अपितु नये नये बैंका न अपनी आर्थिक परिस्थिति अच्छी एवं लाभप्रद बनान की दृष्टि से कुछ मुल्क में अच्छे राभाग भी दिय तथा मचित निधि (reserve fund) का निमाण नहीं किया। इसमें राभाग की दर स्थायी रखन में उन्हें कम्तिदया का सामना करना पडा। परिणामस्वरूप अनेक बैंका का विलियन हुआ। इनके मुख्य दाप निम्न है —

(अ) निम्न व अनुपात में राव निधि की कमा।

(ब) निक्षेप का आकर्षित करन के लिए अधिक व्याज देना।

(ग) अधिकृत प्राधिकृत एवं चुकता पूजी में समचित अनुपात न होना।

(७) कायधन वक्चारियों योग्य सचालकों एवं व्यवस्थापकों का अभाव होने से ये अपने वक् व प्रति जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सके। जैसे विलियन नेटि बैंक का व्यवस्थापक जिसका लेखा-कर्म के सिद्धान्त तथा वैयक्तिक का तनिक भी ज्ञान नहीं था और न वह यह जानता था कि विनिमय बिल किसे कहते हैं।

(८) बैंको में परस्पर सहयोग का अभाव होने से उनमें गलाकाट प्रति स्पर्धा होती है तथा प्रतियोगिता के कारण व्याज दर भी अधिक होती है। इतना ही नहीं अपितु भिन्न भिन्न प्रदशा में भिन्न-भिन्न व्याज दर होती है

जिससे सकट-समय पर परस्पर सहायता का अभाव रहता है एवं समठित नीति का निर्माण नहीं हो सकता।

(६) देश में अव्यवस्थित एवं आवश्यक स्थानों पर बैंकों की शाखाएँ खोली गई हैं तथा जहाँ पर साख-साधनों की अधिक आवश्यकता है वहाँ पर बैंकिंग सुविधाएँ नहीं हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इन बैंकों का विकास न होते हुए स्वदेशीय बैंकरों का स्थान महत्वपूर्ण बना रहा।

(१०) बैंकों का सम्पूर्ण व्यवहार अंग्रेजी में होता है जिसे भारत के १०% लोग भी कठिनाई में जानते हैं। उदाहरणार्थ, चैक, प्रतिज्ञा-पत्र आदि अंग्रेजी में ही गिने जाते हैं तथा बैंकों की सारी क्रियाएँ भी अंग्रेजी में ही होती हैं। इस कारण बैंकों का विकास ग्रामीण क्षेत्रों में न हो सका।

### वाहरी कठिनाइयाँ

(१) बैंकिंग-सकट—पुनः पुनः बैंकिंग-सकट आने के कारण देश में अनेक बैंकों का विलयन हुआ, जिनमें बैंकिंग-व्यवसाय में साधारण जनता पूँजी का विनियोग करना समुचित नहीं समझती। इतना ही नहीं, अपितु आज भी बैंकों के असा में मट्टा होता है, जिससे जनता का विश्वास इनमें नहीं जम पाता।

(२) जनता की सकुचित मनोवृत्ति—भारतीय जनता स्वभावतः ही अपने धन को अपने पास ही रखना अधिक सुरक्षित समझती है, उसका विनियोग करना पसन्द नहीं करती और न विनियोग के लिए अच्छे साधन ही उपलब्ध होते हैं। इससे बैंकों को निक्षेप रूप में पर्याप्त मात्रा में कार्यशील पूँजी नहीं मिल पाती।

(३) वैधानिक कठिनाइयाँ—हमारे देश में हिन्दू और मुसलमान उत्तराधिकार सम्बन्धी नियम ऐसे हैं जिनसे बैंकों को ग्राहकों से ऋण भुगतान के समय अनेक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। रहन-सम्बन्धी भी अनेक वैधानिक अड़चनें होती हैं जिस कारण रहन पर ऋण देने के लिए बैंक सहज में तैयार नहीं होते।

(४) सरकारी प्रोत्साहन का अभाव—भारतीय बैंकों को देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने तक सरकार एवं अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं की ओर से किसी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिला। यदि सरकारी एवं अर्द्ध-सरकारी संस्थाएँ इन बैंकों से लेन-देन करती तो इनकी साख बढ़ती, व्यापारिक उन्नति होती तथा निक्षेप भी बढ़ते। परन्तु देश की तत्कालीन विदेशी सरकार ने सर्वत्र यूरोपीय बैंकों को ही अपने लेन-देन से प्रोत्साहित किया।

(५) विनिमय एवं यूरोपीय बैंकों की प्रतियोगिता—विनिमय वक् एवं यूरोपीय वक् दश में हानि व कारण तथा सरकार की स्वतन्त्र व्यापारिक नीति हानि व कारण दश का लाभकर व्यवसाय विनिमय बैंक व एकाधिकार में ही था। जो भारतीय वक् विदेशी विनिमय व्यापार करना भी चाहते व व इन वक् की स्पष्टता में ठहर नहीं सकते व अतः इनकी उन्नतनीय प्रगति नहीं हुई। क्योंकि विदेशी बैंक की शाखाएँ ही भारत में थी एवं उनके प्रमुख कार्यालय विदेशों में थे। इस कारण उनके मात्र सम्बन्ध अन्य विदेशी बैंकों से अच्छे व।

(६) विनिमय वक् द्वारा आन्तरिक व्यापार में प्रतियोगिता—(विनिमय बैंक का व्यापार केवल आपात निर्यात वन्ना तक ही सीमित न रहने हुए देश के प्रमुख व्यापारिक कन्द्रों में भी उनकी शाखाएँ थीं। अतः व आन्तरिक व्यापार में सुविधाएँ देकर भारतीय वक् की प्रतियोगिता करने व।) विनिमय वक् अधिक संगठित एवं अच्छी आर्थिक स्थिति में होने से जनता का विश्वास शीघ्र प्राप्त कर लेते थे जिससे उनके पास अधिक निधि प्राप्त व। इस प्रकार विनिमय बैंकों की स्पर्धा में भारतीय बैंकों के न केवल सक्तीकरण का कारण उनका व्यापार क्षेत्र भी सीमित हो गया। इतना ही नहीं अपितु विदेशी बैंकों के कमचारी भारतीय बैंकों के विरुद्ध जनता में भी अविश्वास उत्पन्न कर देते थे जिससे नये वक् पनपने नहीं पाते व और न पुराने वक् का काम क्षेत्र ही बढ़ पाता था। साथ ही विदेशी वक् की समाशोधन गृहों में अधिक सदस्यता होने के कारण वे भारतीय वक् की समाशोधन-गृहों की सदस्यता से भी वंचित रहते थे। इस कारण से भारतीय बैंकों की प्रगति में अनेक बाधाएँ थीं।

(७) विदेशी व्यापारियों की पक्षगतपूर्ण नीति—देश के व्यापार का अधिकांश भाग विदेशियों के हाथ में था तथा बहुत ही सीमित व्यापार भारतीयों के हाथ में रहने के कारण विदेशी व्यापारी विदेशी वक् से ही अपना लन-देन रखते थे जिससे भारतीय वक् नहीं पनप सका।

(८) इम्पीरियल वक् और स्वदेशी बैंकों की प्रतियोगिता—भारतीय वक् को एक ओर इम्पीरियल बैंक से तथा दूसरी ओर स्वदेशी वक् से प्रतियोगिता करनी पड़नी थी। इम्पीरियल वक् को सरकार की ओर से अनेक सुविधाएँ थीं तथा अनेक सरकारी मस्या हानि व कारण उनके माधन भी अमायित थे जिससे उन्हे सहज में जनता का विश्वास प्राप्त था। अतः उनकी प्रतिस्पर्धा अन्य भारतीय बैंक नहीं कर सकते थे। दूसरी ओर स्वदेशी बैंक अपनी निजी पूँजी से जनता से लेन-देन करते हैं एवं उनसे ऋण प्राप्त करने में

किमी भी प्रकार की औपचारिकता (formalities) नहीं करनी पड़ती। इसी प्रकार उनकी कार्य-पद्धति भी सरल होन से ग्रामीण क्षेत्रों में उनका अधिक प्रभाव रहा। इससे व्यापारिक बैंकों को ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अमुविधा थी। इन अमुविधाओं को उलटने केन्द्रीय बैंक जांच समिति की रिपोर्ट में भी है

“एक ओर भारतीय व्यापारिक बैंकों को स्वदेशीय बैंकों में प्रतियोगिता करनी पड़ती है तो दूसरी ओर विनिमय बैंक एवं इम्पीरियल बैंक से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जिसकी वजह से वे सकटमय एवं सन्देहात्मक परिस्थिति तथा तीव्र प्रतियोगिता में जीवन-यापन करते हैं।”

(६) शाख बैंकिंग का अभाव—भारत में अभी तक शाख बैंकिंग का अभाव रहा है तथा कमजोर बैंक किसी प्रकार अपना अस्तित्व बनाय रखने का प्रयत्न करते रहे किन्तु अन्त में उनका विलयन हुआ। इसका अभाव हमारे बैंकिंग विकास पर बुरा पड़ा। द्वितीय युद्ध-काल में यह प्रवृत्ति इतनी अधिक हुई कि बैंकों का अपनी अलाभकर शाखाएँ बन्द करनी पड़ी। किन्तु भारतीय बैंकिंग अधिनियम में शाख बैंकिंग को बल मिला है।

(१०) केन्द्रीय बैंक एवं समुचित बैंकिंग अधिनियम का अभाव—भारत में १९३५ तक केन्द्रीय बैंक नहीं था जो इन बैंकों की गति-विधि को देखता तथा उन्हें प्रगति के लिए आवश्यक सलाह देता। इसी प्रकार १९४६ तक समुचित बैंकिंग अधिनियम न होने से बैंकों पर प्रभावी वैधानिक नियन्त्रण नहीं था। इससे इनकी क्रियाओं में भिन्नता एवं अव्यवस्था थी। फलतः वे जनता का विश्वास सम्पादन करने में असमर्थ रहे, जो प्रगति एवं विकास के लिए आवश्यक था।

**व्यापारिक बैंकों की उन्नति के लिए मुभावा**

देश के आर्थिक विकास के लिए बैंकों का समुचित आधार पर विकास होना आवश्यक है। इस हेतु बैंकिंग कलेवर के उक्त दोषों का निवारण भी होना चाहिए। देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन होने से अनेक दोषों का निवारण हो चुका है, जैसे १९४६ में बैंकिंग अधिनियम स्वीकृत होना, १ जनवरी १९४६ का रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होना। फिर कुछ बातों में सुधार आवश्यक है जिनकी ओर केन्द्रीय बैंक जांच समिति ने संकेत किया था —

(१) बैंकों को नई शाखाएँ खोलने के हेतु प्रोत्साहन—बैंकों को अपनी शाखाओं का विस्तार करने में रिजर्व बैंक उनमें अपनी राशि जमा कर सक्रिय

प्रोत्साहन दे। जब ये बैंक कार्यक्षम हो जायें तब उनमें वह अपनी राशि निकाल सके। इसी प्रकार बैंको को मस्ती दरो पर राशि स्थानान्तरण तथा बिलों की कटौती की सुविधाएँ भी रिजर्व बैंक दे। ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति ने भी राशि स्थानान्तरण सुविधाएँ मस्ती दरो पर देने की सिफारिश की थी। यद्यपि राशि स्थानान्तरण शुल्क कम किया गया है फिर भी ये सुविधाएँ केवल उन्हीं स्थानों पर मिलती हैं जहाँ बैंक का कार्यालय है। वित्तवाजार-योजना के अन्तर्गत बिलों के कटौती की सुविधाएँ बैंको को उपलब्ध हो गई हैं। नाबार्ण खोलने में स्टैट बैंक को जो सुविधाएँ दी जानी हैं, वे यदि सभी बैंकों को दी जाय तो बैंकिंग विकास अधिक तेजी में हो सकेगा।<sup>१</sup> साथ ही नये बैंकों की स्थापना की अपेक्षा वर्तमान बैंकों को प्रायः खानना ही अधिक लाभकर होगा क्योंकि इसमें उनके व्यापार एवं प्रायः म वृद्धि होगी।

(२) वैधानिक कठिनाइयों का निवारण—उत्तराधिकार नियमों तथा रहन-सहन सम्बन्धी न्यून देने में जो वैधानिक अड़चनें व्यापारिक बैंको को उपस्थित हानी हैं उनको दूर करने का शीघ्र प्रयत्न किया जाय।

(३) 'एक व्यक्ति एक बैंक' प्रथा को प्रोत्साहन—बैंको का चाहिए कि वे 'एक व्यक्ति—एक बैंक' प्रथा का प्रोत्साहन दे एवं इसके लिए भावी ग्राहकों को, यदि उनका खेला किसी अन्य बैंक में है, ग्राहक न बनायें। इस पद्धति के अपनाने में वे ऋणी की वैयक्तिक नाम पर न्यून दे सकेंगे। इस प्रकार के न्यून को अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। इसीके साथ बैंक रोक न्यून प्रथा को क्रमशः कम कर तथा बिला का उपयोग बढ़ाने के लिए व्यापारिक बिलों की कटौती अधिक कर।

(४) प्रांतीय भाषाओं में बैंक व्यवहार को प्रोत्साहन—बैंकिंग विकास में सबसे बड़ी बाधा अंग्रेजी भाषा की है। उसे दूर करने के लिए प्रांतीय भाषाओं का उपयोग आरम्भ करना चाहिए तथा विदेशी व्यवहार के लिए ही अंग्रेजी का उपयोग न किया कर। इससे मागान्य जनता भी उनमें लेन-देन कर सकेगी तथा उनका व्यापारिक क्षेत्र बढेगा।

(५) सरकार की ओर से प्रोत्साहन—व्यापारिक बैंको के विकास के लिए भारत सरकार को चाहिए कि वह सरकारी बैंको को भाँति इनको

<sup>१</sup> भारतीय बैंक मध के २० मार्च १९५६ के अधिवेशन में श्री० सी० एच० भाभा का भाषण।

<sup>२</sup> *The Monetary Problems of India* by Dr L. B. Jain

प्रोत्साहन देने के लिए समुचित नीति अपनावे तथा इनसे लेन-देन सम्यन्ध प्रस्थापित करे। इसी प्रकार इन बैंकों को करो आदि की सुविधाएँ भी देनी चाहिए। अपने ऋण-कार्यों के कुछ भाग का संचालन भी इन बैंकों के हाथ में देना चाहिए जिससे वे अपनी उन्नति कर सकें।

(६) कार्यप्रणाली की त्रुटियों का निवारण—बैंकों को चाहिए कि वे अपनी कार्य-शैली की त्रुटियों का निवारण करें। वर्तमान स्थिति में बैंक हम ओर प्रयत्नशील हैं। उनको चाहिए कि योग्य कर्मचारियों के निर्माण के लिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था का प्रबन्ध सार्वदेशिक बैंकिंग मध्य द्वारा किया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वे स्वदेशीय बैंकों को अपना-अपना अभिवृत्ता बना लें, जिससे स्वदेशीय बैंकों के क्षेत्र में भी इनका कार्य निस्तार सफल हो सकेगा।

(७) औपचारिकता कम एवं अधिक सुविधाएँ—बैंकों को अपनी कार्य-शैली का औपचारिक भाग यथासम्भव टानना चाहिए तथा जनता को अधिक-अधिक सुविधाएँ देने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें कृपि एक औद्योगिक आवश्यकताओं की उन्नति में भी वे हाथ बटा सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की शाखाओं में कार्यालय-समय भी जनता की दृष्टि में सुविधाजनक होना चाहिए। कार्यक्षमता एवं सुविधा की दृष्टि में स्वदेशीय बैंकर तथा स्टेट बैंक से आवश्यक शिक्षा लेनी चाहिए।

(८) बैंकों में परस्पर सहयोग की वृद्धि—वर्तमान अखिल भारतीय बैंकिंग मध्य को चाहिए कि वह देश के सब बैंकों को अपना सदस्य बनाये तथा उनमें पारस्परिक सहयोग एवं सहकारिता की वृद्धि करे। इससे गलाकाट-प्रतिस्पर्धा का निवारण होकर बैंकिंग की समुचित उन्नति होगी। इस मध्य की आवश्यकतानुसार अपनी शाखाएँ विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित करनी चाहिए तथा उनकी अमुविधाओं का निवारण करने का प्रयत्न करना चाहिए। सरकार को भी इस मध्य की मान्यता देकर उसके सुझावों पर सहानुभूति से विचार करना चाहिए।

(९) व्यापारिक बैंकों के प्रतिस्पर्द्धियों का नियन्त्रण—व्यापारिक बैंकों के प्रतिस्पर्द्धियों का समुचित रूप से नियन्त्रण करना चाहिए जिससे विनिमय बैंकों का कार्य-क्षेत्र केवल आयात-निर्यात केन्द्रों तक ही सीमित रहे। इसी प्रकार स्वदेशीय बैंकों का भी नियन्त्रण करने के लिए रिजर्व बैंक को प्रयत्न करना चाहिए जिससे वे प्रतिस्पर्द्धा न कर सकें। विदेशी विनिमय बैंकों को अपनी शाखाएँ देश के अन्य भागों में हटाने के लिए तथा नयी शाखाएँ खोलने के लिए

प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। इसी प्रकार की शर्तें व्यापारिक बैंक की पारस्परिक स्पर्धा के निवारणार्थ भी होनी चाहिए। अच्छा हो, यदि रिजर्व बैंक इन बैंकों की निक्षेप-न्याय-दर का नियन्त्रण करे जिसमें अधिक निक्षेप आकर्षित करने के लिए व्याज-दर का प्रबोधन न दिया जा सके। स्वदेशीय बैंकों का नियन्त्रण इस मावधानी में होना चाहिए जिसमें ग्रामीण माग्य-मुविधाओं में बाधा न हो। भारतीय बैंकिंग अधिनियम विनिमय बैंकों की क्रियाओं पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण हो गया है।

(१०) निक्षेप बीमा प्रथा को लागू करना—निक्षेप-कर्ताओं की सुरक्षा के लिए बैंकों को विनियम ध्यान देना चाहिए तथा निक्षेपों की सुरक्षा के लिए अमेरिका की भांति हमारे यहाँ निक्षेपों का बीमा एक निक्षेप बीमा कम्पनियों की स्थापना होनी चाहिए जिसमें बैंकिंग व्यवसाय की अवस्था ही अच्छी उन्नति होगी।<sup>१</sup> इससे दो प्रमुख लाभ होंगे —

(अ) बैंकों की ऋण नीति में समानता आएगी, तथा

(ब) बीमा कम्पनियों द्वारा बैंकों की ऋण नीति पर कुछ अंग में प्रतिबन्ध रहेगा। इस देश के बैंकिंग मकड़ों का निवारण हो सकेगा। परन्तु अर्थ-मन्त्रि ने २० नवम्बर १९५० को मसद में कहा है कि “यह देखा गया कि इस योजना का उपयोग में लाना बहुत कठिन है जब तक कि देश के बैंकिंग स्तर में अधिक सुधार होकर उसकी अममानता कम नहीं जाती, इसके बाद ही बीमे का भार देश के बैंक में समान रूप में रहेगा।” अतः निक्षेपों की सुरक्षा के लिए बैंकों में सहयोग होना ही आवश्यक है।

उपर्युक्त मुद्दों के अतिरिक्त जनता भी समुचित बैंकिंग विज्ञान एवं उन्नति में अपना सहयोग दे तथा बैंक योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी एवं अधिकारी प्राप्त करने के लिए हिन्दुस्तान कॉमर्शियल बैंक की भांति प्रशिक्षण योजना लागू करे। भारत की राजनीतिक परिस्थिति बदल जाने से गत वर्षों में बैंकिंग स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है एवं हो रहा है। इसी प्रकार एकीकरण (amalgamation) एवं विलियन के लिए बैंकिंग अधिनियम में अधिक सुविधाएँ दी गई हैं। एकीकरण एवं शासक-विस्तार के नियन्त्रण के लिए रिजर्व बैंक को भी अधिक अधिकार दिये गये हैं, जिससे वह व्यापारिक बैंकिंग की समुचित उन्नति की देख-रेख कर सकता है। रिजर्व बैंक बैंकों का परीक्षण करता

<sup>१</sup> Commerce, 30-9-50

<sup>२</sup> Hindustan Times, 24-11-50.

है तथा उनके मुद्रा के लिए आवश्यक सुभाव भी देता है। छावाओ के समुचित विस्तार पर भी रिजर्व बैंक का नियन्त्रण है। अतः हम कह सकते हैं कि ये वांछित भारतीय बैंकिंग के उज्ज्वल भविष्य की परिचायक है।

### साराश

व्यापारिक बैंक साधारणतः उन समुचित स्वस्थ बैंको को कहते हैं जो भारतीय कम्पनीज अधिनियम १९५६ के अन्तर्गत समामेलित हो तथा व्यापारिक बैंकिंग क्रियाएँ करें। इन बैंको को साधारणतः दो श्रेणियों में बाँटते हैं—

(१) मूचीबद्ध बैंक—इनकी ये विशेषताएँ होती हैं—रिजर्व बैंक की दूसरी सूची में समावेश, भारतीय क्षेत्र में व्यवसाय, चुकता पूँजी एवं निधि ५ लाख रुपये से अधिक, इनके सम्बन्ध में रिजर्व बैंक को विश्वास होना है कि निक्षेप-कर्ताओ के हित में उनकी क्रियाएँ हो रही हैं, तथा जो अपनी माँग एवं समय देनदारी का ५०% व २% रिजर्व बैंक के पास निक्षेप रखते हो।

(२) अमूचीबद्ध बैंक—जिनका समावेश रिजर्व बैंक की दूसरी सूची में नहीं होता वे अमूचीबद्ध बैंक होते हैं। चुकता पूँजी एवं निधि के अनुसार इनकी चार श्रेणियाँ हैं—

‘अ’ जिनकी चुकता पूँजी एवं निधि ५ लाख रुपये से अधिक है।

‘ब’ ” ” १ लाख से ५ लाख रुपये तक है।

‘स’ ” ” ५० हजार से १ लाख रुपये तक है।

‘द’ ” ” ५० हजार से कम है।

व्यापारिक बैंक तीन प्रमुख कार्य करते हैं—(१) जनता से निक्षेप लेना, (२) साख निर्माण तथा ऋण प्रदाय द्वारा जनता की वित्त-शक्ति का संचार करना तथा (३) अन्य कार्य, जैसे अभिकर्ता की सेवाएँ, ग्राहको के आभूषण आदि की सुरक्षा।

ऋण देने का कार्य ये तीन प्रकार से करते हैं—ग्राहको वैयक्तिक साख पर अथवा वैयक्तिक तथा अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण देना, रोकऋण एवं अधिविवरण देना, व्यापारिक बिलों की कटौती या क्रय द्वारा ऋण सुविधाएँ देना। ये सुविधाएँ देने में व्यापारिक बैंक को निम्न कार्य नहीं करना चाहिए—

(१) ग्राहको को व्यापार संचालन के लिए पूँजी देना, (२) स्थायी या दीर्घ-कालीन ऋण देना (३) एक ही ग्राहक को अधिक परिमाण में ऋण देना।

अन्य कार्य—ग्राहको को राशि-स्थानान्तरण सुविधाएँ देना, आर्थिक स्थिति की जानकारी देना आदि।

व्यापारिक बैंक विदेशी शाखाओं द्वारा विदेशी विनिमय कार्य भी करते हैं। व्यापारिक बैंकों की शाखाएँ जनसह्या की दृष्टि से बहुत ही कम हैं जिनकी संख्या ३४५५ है। क्योंकि इनके विकास में अनेक बाधाएँ हैं।

(अ) कार्यशीली व दाग—(१) अधिक पूँजी का सरकारी प्रतिनूतियों में विनियोग, (२) बैंक स्वीकृति बिलों का अभाव (३) व्यक्तिगत साख पर ध्यान न देना, (४) एक व्यक्ति एक बैंक प्रथा का अभाव, (५) विदेशी बैंकों के शान्तोत्त की झूठी नकल, (६) बैंकिंग सिद्धान्तों का पूर्ण रूप से पालन न करना, (७) कुशल कर्मचारियों का अभाव, (८) बैंकों में परस्पर सहयोग का अभाव, (९) शाखाओं का अव्यवस्थित विकास, (१०) अंग्रेजी में व्यवहार।

(आ) बाहरी कठिनाइयाँ—(१) बैंकिंग सफ्ट, (२) जनता की लघुचित मनोवृत्ति, (३) वैधानिक अडचनें, (४) सरकारी प्रोत्साहन का अभाव (५) विनिमय एवं यूरोपीय बैंकों की प्रतियोगिता, (६) विनिमय बैंकों की आन्तरिक व्यापार में स्पष्टता, (७) विदेशी व्यापारियों की पक्षपातपूर्ण नीति, (८) इम्पीरियल बैंक और स्वदेशी बैंकों की प्रतियोगिता, (९) साख-बैंकिंग का अभाव, (१०) केन्द्रीय बैंक एवं समुचित बैंकिंग अधिनियम का अभाव।

सुधार के लिए सुझाव—बैंकों की नई शाखाएँ खोलने के लिए प्रोत्साहन, वैधानिक कठिनाइयों को दूर करना, 'एक व्यक्ति एक बैंक' प्रथा की प्रोत्साहन, बैंक व्यवहार में प्रान्तीय भाषाओं को प्रोत्साहन, सरकारी प्रोत्साहन मिलना, बैंक कार्यशीली की श्रुतियों को दूर करें, औपचारिकता कम तथा सुविधाएँ अधिक दें, बैंकों में परस्पर सहयोग की वृद्धि हो व्यापारिक बैंकों के प्रतिपक्षियों पर नियंत्रण किया जाय तथा निक्षेप-बीमा योजना लागू की जाय।

देश में राजनीतिक परिवर्तनों के साथ केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण, बैंकिंग अधिनियम का निर्माण, सुदृढ़ बैंकिंग क्लेवर के हेतु एकीकरण की ओर प्रवृत्ति—ये सब बैंकिंग के सुदृढ़ विकास की ओर सकेत करती हैं।

## अध्याय १७ विनिमय बैंक

स्टेट बैंक थोर रिजर्व बैंक को छोड़कर आज भी भारत का बैंकिंग व्यवसाय विशेष रूप से सूचीबद्ध तथा विनिमय बैंको के हाथ में है। इतना ही नहीं अपितु विनिमय बैंकों की स्थापना भारतीय बैंको में बहुत पहले होने के कारण वास्तव में 'आधुनिक बैंकिंग के प्रणेता' विनिमय बैंक ही है। विदेशी व्यापार को साग-मुविधाएँ एवं आर्थिक सहायता देना इनका प्रमुख कार्य है। परन्तु ये व्यापारिक बैंकिंग कार्य भी करते हैं, जिसमें ये भारतीय समुक्त स्वयं बैंकों की प्रतियोगिता में हैं। ये बैंक विदेशी हैं तथा इनके प्रमुख कार्यालय इंग्लैण्ड, पूर्वी एशिया अथवा अमेरिका (समुक्त राज्य) में हैं। इनकी प्रमुख कार्यशील पूंजी बाहर में ही आती है जिसके लिए ये अपने प्रमुख कार्यालयों में अधिक निक्षेप आकर्षित करने के लिए व्याज भी अधिक देते हैं। ऐसे तो विनिमय बैंक का कार्य कुछ मात्रा में भारतीय बैंक भी करते हैं, अतः इनको विदेशी विनिमय बैंक कहना ही अधिक उचित होगा।

**विकास—**इनका उगम ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन-काल में हुआ जिस समय विदेशी व्यापार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत में कुछ अभिवर्त्ता-गृहों की स्थापना की गयी। ये गृह विदेशी विलां के लिखने, कटीनी तथा स्वीकृति का कार्य करते थे तथा वे विनिमय बैंकों की स्थापना के मद्दा विरोधी रहे। १८३३ में केवल एक ही विदेशी विनिमय बैंक था, परन्तु १८५३ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन तथा विशेष विरोधी मानावरण का अन्त होने पर नये बैंकों की स्थापना होने लगी। अभिवर्त्ता-गृहों में थॉमस कुक एण्ड मन्स का नाम उल्लेखनीय है जो आज भी यात्रियों (tourist) को आर्थिक सुविधाएँ देते हैं। १८५३ में चार्टर्ड बैंक ऑफ इण्डिया आस्ट्रेलिया एण्ड चायना एवं स्कॉटलैंड बैंक की तथा १८६६ में नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना हुई। नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया का प्रमुख कार्यालय आगे लन्दन में ले जाया गया। १८५३ के पूर्व जो एकमेव विदेशी विनिमय बैंक था उसका नाम ओरिएण्टल बैंकिंग कॉर्पोरेशन था, जिसकी स्थापना १८४२ में एवं विलियम १८८४ में हुआ। इसके बाद अन्य देशों के बैंकों की स्थापना भारत में

होने लगी जिनके साथ भारत के विदेशी व्यापार सम्बन्ध थे एवं हैं। केवल इटली और बेल्जियम दो ऐसे देश हैं जहाँ के बैंक भारत में नहीं हैं। भारत में १४ विदेशी विनिमय बैंक (१९५९ में) हैं।

### प्रधान कार्यालय

१	चार्टर्ड बैंक ऑफ इण्डिया, आस्ट्रेलिया एण्ड चायना (१८५३)	लन्दन
२	ईस्टर्न बैंक लिमिटेड (१९०६)	"
३	मर्केंटाइल बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड (१८५८)	"
४	नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया (१८६६)	"
५	हॉंगकांग एण्ड चायना बैंकिंग कॉर्पोरेशन	हॉंगकांग
६	एण्ड्रुस एण्ड कम्पनी लिमिटेड (नेशनल प्राविन्सियल बैंक के नियन्त्रण में)	लन्दन
७	बैंक ऑफ चायना लिमिटेड	"
८	लीडरलैंड्स इण्डियन कॉमर्शियल बैंक लि०	अमस्टर्डम
९	थॉमस कुक एण्ड मग्न (प्रवासगमन की सुविधाएँ देता है)	—
१०.	नेशनल मिटी बैंक ऑफ न्यूयार्क	न्यूयार्क
११.	लीडरलैंड्स ट्रेडिंग सोसाइटी	अमस्टर्डम
१२	अमेरिकन एक्सप्रस बैंक (प्रवासगमन की सुविधाएँ देती है)	न्यूयार्क
१३.	सायड्स बैंक लिमिटेड	लन्दन
१४	कामटॉयरे नेशनल डी एस्कॉम्प्टी (Escompte) ऑफ पेरिस	पेरिस

विदेशी विनिमय बैंकों का वर्गीकरण

व्यापार की दृष्टि में वर्तमान विनिमय बैंक दो श्रेणियों के हैं—

(१) ऐसे बैंक जिनके प्रधान कार्यालय विदेशों में हैं और व्यवसाय भारत में होता है एवं जिनके कृत्य निक्षेपों का २५ प्रतिशत अथवा इसमें अधिक भाग भारतीयों का है। उदाहरणार्थ, चार्टर्ड बैंक ऑफ इण्डिया आस्ट्रेलिया एण्ड चायना नेशनल बैंक ऑफ इण्डिया, मर्केंटाइल बैंक ऑफ इण्डिया लिमिटेड, ईस्टर्न बैंक लिमिटेड, थॉमस कुक एण्ड मग्न। इस श्रेणी के बैंक १९४६ में केवल ३ ही रह गये।

(२) ऐसे बैंक जिनके प्रधान कार्यालय विदेशों में हैं एवं वे भारत में केवल उनके अभिकर्ता का कार्य करते हैं। इनका अधिकतर व्यापार विदेशों में है तथा भारतीय निक्षेप राशि २५% में कम है। इस श्रेणी में प्रथम श्रेणी के बैंकों की छोड़कर अन्य बैंकों का समावेश होता है। १९४६ में ऐसे बैंकों की संख्या १२ थी।

इनकी वर्तमान स्थिति—विदेशी विनिमय बैंको के हाथ में ही भारत के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का अधिक भाग है। भारत के विभिन्न भागों में इन बैंकों की १९५६ में ६६ शाखाएँ थीं। इनके निक्षेप भारत में कितने हैं इस सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती, और जो जानकारी मिलती भी है वह केवल रिजर्व बैंक के पाम भेजे जाने वाले विवरण में ही मिलती है। उनकी कार्यशील पूँजी अधिकतर भारत से ही प्राप्त होती थी तथा गत ३० वर्षों में भारत की मुद्रा-मण्डी पर इनकी विशेष आर्थिक परिस्थिति तथा विदेशी मुद्रा मण्डियों में प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने के कारण बहुत अधिक प्रभाव रहा है। ये बैंक अभी तक रिजर्व बैंक के पूर्ण नियन्त्रण में नहीं आये हैं क्योंकि इनके प्रधान कार्यालय विदेशों में समामेलित होने के कारण बैंकिंग अधिनियम के सिवा भारत के कोई भी विधान लागू नहीं होते। अतः इनकी यहाँ की आर्थिक स्थिति सम्बन्धी कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। इनके निक्षेप भारतीय सूचीबद्ध बैंक की अपेक्षा अधिक है जो मार्च १९५६ में २०१ करोड़ रुपए थे तथा अधिक निक्षेपों को आवर्षित करने के लिए ये चल निक्षेपों पर भी ब्याज देते हैं। इसमें भारतीय बैंकों के व्यापार पर प्रभाव पड़ता है तथा वे इनकी प्रतियोगिता करते हैं। इसी कारण भारत के विदेशी व्यापार पर इन्हीं का एकाधिकार है। रिजर्व बैंक के अनुसन्धान के अनुसार ये भारतीय आयात व्यापार को ६०% तथा निर्यात व्यापार को ७०% अधिक सहायता देते हैं। भारतीय बैंकों ने विदेशी व्यापार क्यों नहीं अपनाया ?

(१) भारतीय बैंक की कुछ शाखाएँ विदेशों में थी और वे विनिमय बैंकिंग करत थे। परन्तु विदेशों में अपनी शाखाएँ खोलने के पहले उनको अडचनों का सामना करना पड़ता है जो अधिक एवं गम्भीर स्वरूप की है। फिर दीर्घकालीन व्यापारिक सफलता में आने वाली बाधाएँ और भी गम्भीर हैं। इस कथन में सत्यापन भी है। विदेशी बैंकों की स्थापना पहले होने के कारण इनका मुद्रा-मण्डी पर अधिक प्रभाव था तथा ये कार्यशील पूँजी के लिए आरम्भ विदेशी निक्षेपों पर निर्भर रहते थे।

(२) विदेशी होने के कारण इनका विदेशी मुद्रा-मण्डियों में अधिक सम्पर्क था जिससे ये भारतीय बैंकों की प्रतियोगिता में नहीं टिकने देते थे।

(३) विदेशी बैंक की कार्यशील पूँजी भी भारतीय बैंकों की अपेक्षा अधिक थी तथा आर्थिक साधन भी बहुत थे। इससे भारतीय बैंक इनकी प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे और न वे इस स्थिति में ही थे कि अपनी शाखाएँ विदेशों में खोलने। न उनकी विदेशों में शाखाएँ ही थी जिनके द्वारा वे

विदेशी व्यापार कर पाया । दश म केवल एक ही बैंक इम्पीरियल बैंक, ऐसा था जिसके आर्थिक साधन एवं कार्यशील पूँजी अधिक थीं जो इस कार्य का कर सकती थी । परन्तु १९३५ तक इसका यह कार्य करने की वैधानिक अनुमति नहीं थी । अतएव यह कार्य नहीं कर सका । रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद विदेशी विनिमय व्यापार करने का इस स्वतन्त्रता दी गई फिर भी इम्पीरियल बैंक ने इस कार्य पर ध्यान नहीं दिया । १९३६ में सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने अपनी एक शाखा विदेशी विनिमय कार्य के लिए लन्दन में सेंट्रल एक्सचेंज बैंक आफ इण्डिया नाम से खोली थी परन्तु १९३८ में उसका समावेश ब्रिटेन बैंक में हो गया । १९४६ में बैंक आफ इण्डिया ने कार्य को आरम्भ किया तथा लन्दन में एक शाखा स्थापित की एवं १९५० में इसने अपनी एक शाखा जापान में खोली है । परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय बैंक का काम यह व्यापार केन्द्रित रह जिससे राजस्व स्वयं का अन्वय आयात (invisible imports) राखा जा सके । इन कारणों के अनिर्दिष्ट निम्न कारणों में भी भारतीय बैंक इस कार्य का न अपनाये —

(१) कुशल कर्मचारियों की कमी— विदेशी विनिमय कार्य करने के लिए कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता थी । परन्तु जहाँ भारतीय व्यापार के लिए कुशल कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे वहाँ विदेशी विनिमय के विरापड़ भारत में प्राप्त होना असम्भव हो गया ।

(२) विदेशी बैंकों की तुलना में कार्यक्षमता कम—यदि भारतीय बैंक विदेशों में अपना शाखाएँ खोलने में तैयार थे अपनी कार्यशील पूँजी के लिए अधिक निक्षेप प्राप्त नहीं कर सकते थे । क्योंकि भारतीय बैंक का कार्यक्षमता विदेशी बैंकों की तुलना में कम थी । इसके अनिर्दिष्ट विदेशियों में राष्ट्रीय भावना अधिक तीव्र होनी है जिसका भारतीयों में आज भी अभाव है । साथ ही भारतीय बैंक का विदेशों में पूर्व-स्थापित एवं बड़े बैंक में प्रति योगिता करना पड़नी जिसके लिए वे पूर्ण रूप में तैयार नहीं थे ।

(३) विदेशी मुद्रा-मण्डियों के सम्पर्क का अभाव—कन्द्रीय बैंकिंग ऑफ़ मॉर्निंग के अनुसार भारतीय बैंक अन्तराष्ट्रीय मुद्रा मण्डियों में सम्पर्क नहीं रख सकते थे क्योंकि उनका प्रधान कार्यालय भारत में था । इस कारण उनका न तो अन्तराष्ट्रीय मुद्रा मण्डियों का अन्तर्वाधि जान ही हो सकता था और न उन्हें आयात नियम विलेन ही मग्नहण के लिए मिल सकता था । विदेशी बैंकों के प्रधान कार्यालय विदेशों में होने में उन्हें ये सुविधाएँ प्राप्त हैं ।

(४) सीमित आर्थिक साधन—भारतीयों बैंक के आर्थिक साधन बहुत

कम था तथा उनका व्यापार क्षेत्र अविश्व था, जिससे विदेशी विनिमय व्यापार की अपेक्षा उनके साधना का भारत में ही अधिक लाभदायक उपयोग हो सकता था। इससे भारतीय बैंकों ने विदेशी विनिमय व्यापार की ओर दुलक्ष किया।

(५) अधिक कायशील पूँजी—भारतीय बैंकों को विदेशों में शाखाएँ स्थापित करने के लिए अधिक कायशील पूँजी की आवश्यकता थी और है भी। इसके साथ ही वह शाखा कुछ वर्षों तक हानि हात हुए भी चालू रहनी चाहिए परन्तु ऐसा करने के लिए आज भी अधिकांश बैंकों के पास पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं हैं। इस कारण भारतीय बैंक इस व्यापार को न अपना सकें।

(६) विदेशी बैंकों की कट्टर प्रतियोगिता—इनका सामना भी उन्हें करना पड़ता था।

(७) समान सुविधाओं का अभाव—भारतीय बैंकों का विदेशों में वे सुविधाएँ उपलब्ध नहीं होती थी जहाँ वहाँ के बैंकों को उनके देश के अधिनियम से मिलती थी। इतना ही नहीं अपितु अनेक वैधानिक अड़चन भी थी।

(८) भारत सरकार की अपेक्षापूर्ण नीति—भारत सरकार की ऐसी नीति रही जिससे भारतीय बैंकों का विदेशों में शाखाएँ खोलने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता था।

### भारतीय बैंकों की विदेशी विनिमय क्रियाएँ

भारतीय बैंकों ने कुछ हद तक विदेशों में विनिमय क्रियाएँ भी तथा भारतीय बैंकों की उन देशों में शाखाएँ थी जिनके साथ भारत के विदेशी व्यापारिक सम्बन्ध थे। १८४० में भारतीय मूचीवद्ध एवं अमूचीवद्ध बैंकों की शाखाएँ क्रमशः ६२८ और १८३ थीं। विभाजन के फलस्वरूप भारत की पाकिस्तान में स्थित शाखाएँ भी विदेशों में ही गिनी जान लगीं। देश के विभाजन के बाद भारतीय बैंकों के विदेशी कार्यालयों की संख्या कम होती गई जिसके आंकड़े निम्न हैं—

	मूचीवद्ध बैंक	अमूचीवद्ध बैंक
१९४६ में	६२८	१८३
१९४७ (अंतिम)	४९३	६८
१९४८	२२६	४६
१९४९	१४७	३१
१९५०	१२५	२२
१९५१	१११	१९

१९४८ के बाद भारतीय बैंको की मस्या कम होन का मूल कारण यह है कि पाकिस्तान स्थित भागतीय बैंका की धाम्माएँ वहा की परिस्थिति क कारण बन्द हुई । १९४७ स १९५१ तक मूचीवद्ध तथा अमूचीवद्ध बैंका न कमरा अपनी ३५६ और ५७ शाखाएँ बन्द की, परन्तु इमगी आर अन्य दशा मे नई शाखाएँ खाली गई —

	बैंक	मस्या	कार्यालय	निक्षेप	सरकारी प्रतिभूतियाँ
श्रीलंका (३०-४-५०)	१	३	८ कराड ४०	८ कराड	
संयुक्त राज्य ,	—	०	५ ,	५ ,	
बर्मा ,	५	८	८ ,	३	
मलाया	४	१५	४	—	
फ्रेंच भारत	५ <sup>१</sup>	६ <sup>१</sup>	६१ लाख ६०	—	
थाइलैंड	—	१	५३ कराड ६०	—	
जापान	—	१			
हांगकाँग	—	१			
पाकिस्तान	३० <sup>१</sup>	८८	४८ कराड ६०	१६ कराड ६०	

भारतीय बैंका क विदेशी कार्यालयों की सम्पत्ति दनदारी एवं विदेशी विनिमय क्रियाएँ पृष्ठ ५३६ पर दी हुई तालिका में स्पष्ट होती है ।

भारतीय बैंको का ध्यान इस व्यवसाय की आर गत वर्षों में हो गया है । परन्तु इनका वर्तमान कार्यक्षेत्र विशेषतः दक्षिण-पूर्व एशिया एवं सुन्दरपूब तक ही सीमित है । भारतीय बैंकिंग अधिनियम के कारण अब यह आना है कि भारतीय बैंक इस व्यवसाय की आर अधिक ध्यान देंगे ।

### विनिमय बैंका के कार्य

(१) विदेशी व्यापार का विदेशी विनिमय बिलों का लखन, स्वीकृति तथा कटौती द्वारा आर्थिक सहायता देना, जिससे भारतीय बन्दरगाहों से विदेशी बन्दरगाहों पर तथा विदेशी बन्दरगाहों में भारतीय बन्दरगाहों पर वस्तुओं का आयात-निर्यात हो सके ।

(२) बन्दरगाहों में आन्तरिक शहरों एवं व्यापार-केन्द्रों में माल पहुँचाना तथा व्यापारिक केन्द्रों एवं आन्तरिक शहरों से निर्यात के लिए बन्दरगाहों पर माल पहुँचाने के लिए आर्थिक सुविधाएँ देना ।

<sup>१</sup> इनमें १ अमूचीवद्ध बैंक है ।

<sup>२</sup> इनमें ६ अमूचीवद्ध बैंक तथा उनके १२ कार्यालयों का समावेश है ।

## विदेश स्थित भारतीय बैंको की सम्पत्ति एवं देनदारो (लाभ हानियों में)

वर्ष	निक्षेप	१	२	३	४	५	६	७	८
सूचीबद्ध बैंक	१९४६	१३१.१३	३०.००	२३.६०%	१८१	१८३६	५६२१	४३.७०%	६२८
	१९४७	११०.७५	२६.०१	१३.५०%	१६३	१३०१	४६६४	४०.६०%	४६३
	१९४८	१०६.१२	२६.६३	२८.१०%	२१६	३१००	३६१८	३४.००%	२२६
	१९४९	७३.२१	१०.८१	५८.४०%	१८६	११४८	२३४२	३०.००%	१४७
	१९५०	५१.११	१५.८४	२८.७०%	३६६	२८१५	३०११	१६.००%	१२४
	१९५१	७८.०७	२५.६०	३०.८०%	८१२	२६००	३७५२	४८.१०%	१११
असूचीबद्ध बैंक	१९४६	६८६	१६६	२८.४०%	८	२५२	४३०	६२.४०%	१८३
	१९४७	१११	४३	३८.७०%	१	१०३	१०६	६३.७०%	६८
	१९४८	१५१	३६	२३.०१%	२	१५३	१५५	१०.६०%	४६
	१९४९	१६८	१६	८.३%	१	२५३	२५६	१५.१२%	३६
	१९५०	१४३	१३	६.१%	२	२१७	२१६	१५.३१%	२२
	१९५१	१४१	१६	६.६%	०	१६४	१६६	१३.६०%	१६

(३) अन्य बैंकिंग क्रियाएँ, जैसे विद्वानों से राशि-रधानान्तरण की सुविधाएँ देना, विद्वानों से राशि की कटौती, निष्काप की स्वीकृति तथा आन्तरिक व्यापार की सुविधाएँ देना, स्वर्ण एवं चादी की खरीद बिना आदि ।

इनकी कार्य पद्धति—इनमें पहलू काय व अनुसार आर्थिक सुविधाएँ निम्न रीति में दी जाती हैं —

१. विनयन विद्वानों आयात-कर्ता अपने लन्दन बैंक से साख-सुविधाएँ प्राप्त करता है जिसकी सूचना वह भारत स्थित विनिमय बैंक द्वारा निर्यात-कर्ता को देता है । इस नाम पर निर्यात-कर्ता उस व्यापारी के नाम बिना का लेखन करता है, जिसके साथ जहाजी बिण्टी वीमा लेख बाँजक तथा कभी कभी पैकिंग नाट भी लगा देता है । यह बिण वह भारत स्थित विनिमय बैंक का वच कर राशि प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार भारतीय व्यापारी को उनकी नियाम वस्तुओं का मूल्य मिल जाता है ।

इस प्रकार के बिण देना बिण हान है जिसकी अवधि २० दिन की होती है तथा दो प्रकार में लिख जान है ।

(अ) भुगतान बिण (document against payment) तथा

(ब) स्वीकृति बिण (documents against acceptance) ।

भुगतान बिण—उनकी राशि विनिमय बैंक की लन्दन स्थित शाखाओं को व्यापारी से तत्काल ही मिल जाती है जिसमें जो रकम उन्हीं भारत में दिया उसका भुगतान इन्डोर्समेंट में मिल जाता है । इन बिणों पर राज दर कम लगती है ।

स्वीकृति बिण (D/A)—यदि स्वीकृति बिण हुआ तो भारतीय व्यापारी को तत्काल ही ध्यान आदि काटकर राशि दे दी जाती है । इस बिण का विनिमय बैंक अपनी लन्दन स्थित शाखा में भेज देता है जहाँ पर वह व्यापारी के बैंक द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है । इस प्रकार स्वीकृति प्राप्त करने पर उस बिण का लन्दन मुद्रा मण्डी में बिक्री कराने के स्टैंडिंग में राशि मिल जाती है । यह बिण दो अवस्थाओं में हस्ताभर हान पर बैंक ऑफ इन्डोर्समेंट से भी भनाय जा सकता है ।

इस प्रकार दोनों दस्तावेजों में विनिमय बैंक को अपनी भारत में दी हुई राशि का भुगतान इन्डोर्समेंट में मिल जाता है । दूसरे प्रकार के बिणों पर व्यापार-दर अधिक होती है क्योंकि उनका भुगतान स्वीकृत हान के ६० दिन बाद मिलता है । अब इन अवधि के लिए विनिमय बैंक व्याज लेता है ।

कभी-कभी जब इन्डोर्समेंट का आयात-कर्ता इन्डोर्समेंट के बैंक से अनिश्च-

नीय माल-पत्र (irrevocable letter of credit) प्राप्त नहीं करता तो निर्यात-कर्ता बिल का लेखन कर उसे विदेशी विनिमय बैंक के माध्यम से मग्रहण के लिए भेजता है। इससे व्यापारी को बिल की अवधि समाप्त होने तक राशि नहीं मिलती, यदि वह स्वीकृति प्रलेख है। परन्तु यह पद्धति विशेष चलन में न होने हुए, इङ्गलैण्ड के सभी आयातकर्ता अनिरस्तनीय साख-पत्र (irrevocable credit) प्राप्त कर लेते हैं। इन व्यवहारों के लिए आयात एवं निर्यात बैंडों में विनिमय बैंक की शाखा होना आवश्यक है, जिसमें इस प्रकार के व्यवहारों में सुगमता हो।

२ (अ) जब कोई भारतीय व्यापारी इङ्गलैण्ड से माल आयात करता है तो उस दशा में भी ६० दिनों के भुगतान बिल (D/P) निर्यातकर्ता, भारतीय आयातकर्ता का नाम लिखता है तथा उनकी कटौती वह लन्दन के किसी ऐसे बैंक में करा लेता है जिसकी शाखा भारत में है। इस बिल का 'विनिमय बैंक' के नाम में उपप्रावीयन (hypothecation) कराकर लन्दन बैंक इसे भारत स्थित विनिमय बैंक का पाम भेज देता है। यदि यह भुगतान बिल है तो भारतीय आयातकर्ता में तुरन्त ही उम भुगतान मिल जायगा तथा भारतीय व्यापारी को माल मिल जायगा। परन्तु यदि स्वीकृति बिल हुआ तो स्वीकृति करने के बाद उसे मिल जायगा तथा पक्का तिथि पर विनिमय बैंक उसमें राशि ले लेगा। ये बिल ६० दिन की अवधि के होने से भारतीय व्यापारी को भुगतान बिल का भुगतान करने के लिए ६० दिनों की अवधि मिलती है जिसमें वह राशि की व्यवस्था कर सकता है। परन्तु यदि वह भुगतान करने के पूर्व माल लेना चाहता है तो उस दशा में उसे ग्रन्याम रसीद लिखकर विनिमय बैंक को देनी पड़ेगी जिससे भुगतान समय पर न होने पर वह व्यापारी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर सकेगा। यह पद्धति भारतीय आयात-कर्ताओं में विशेष रूप से प्रचलित है। इस मुविधा के लिए व्याज देना पड़ता है।

(ब) यह पद्धति यूरोपीय फर्मों में विशेष प्रचलित है। इस पद्धति के अनुसार यदि माल का आयात किसी ऐसी व्यापार-मस्था ने किया हो जिसकी शाखा इङ्गलैण्ड में भी है तो निर्यात-कर्ता लन्दन मुद्रा मण्डी अथवा लन्दन के किसी विनिमय बैंक पर बिल लिखेगा। इसकी स्वीकृति होने पर निर्यात-कर्ता बिल की कटौती करा कर निर्यात माल का मूल्य प्राप्त कर लेगा। जिस बैंक ने इस बिल को स्वीकार किया है वह बैंक उस बिल को अपनी भारतीय शाखा में भेजेगा। यह शाखा इसकी राशि निर्यात कर्ता के भारतीय कार्यालय से प्राप्त कर लेगी। इस प्रकार इस पद्धति में आयात-कर्ता को भुगतान के लिए ६०

दिन मिल जाने है तथा निर्यात-कर्ता को तत्काल राशि मिल जानी है। भारत स्थित विनिमय बैंक इस प्रकार मध्यहीन राशि को अपने लन्दन कार्यालय में भज देगा जिसमें वह उस बिल का भुगतान पक्के तिथि पर कर सकता है। इस प्रकार के व्यवहार तभी सम्भव होता है जब आयात-कर्ता और निर्यात-कर्ता एक ही हों, जैसे मैमन ग्रीफिन एण्ड टैटलर, लन्दन तथा ग्रीफिन एण्ड टैटलर, कलकत्ता।

बन्दरगाहों से आन्तरिक व्यापार केन्द्रों में माल पहुँचाना तथा व्यापारिक केन्द्रों से बन्दरगाहों पर माल ले जाने में आर्थिक सहायता देना।

इनका यह कार्य करना उसीलिए सम्भव होता है कि इन्होंने अपनी शाखाएँ केवल बन्दरगाहों तथा आयात निर्यात केन्द्रों तक ही सीमित न रखी हों वरन् वे व्यापारिक केन्द्रों में भी खोल रखी हों। १९५१ में विनिमय बैंक की भारत में निम्न शाखाएँ थी —

लायटन बैंक	१८ कार्यालय सदस्या
ग्रिण्डल बैंक	१४ " "
नगराल बैंक ऑफ इण्डिया	११ " "
चार्टर्ड बैंक ऑफ इण्डिया	६ " "
मैकैण्टीश बैंक	५ " "
अन्य विनिमय बैंक	८ " "

इसके अतिरिक्त कुछ विदेशी विनिमय बैंक न. भारतीय बैंक के जगह खरीद कर उन पर भी अपना प्रभुत्व एवं नियन्त्रण कर रहा है। जैसे चार्टर्ड बैंक ऑफ इण्डिया, आस्ट्रेलिया एण्ड चार्ल्स न. अनाहावाद बैंक के अधिकांश अंश खरीद लिए हैं जिनकी सहायता केन्द्रीय बैंकिंग जाच-मैमिनि की रिपोर्ट के अनुसार १९५० में १,९६,०१६ बी. जे. कि. कु. अंशों की सहायता २,१६,८१६ थी। इससे दम के आन्तरिक व्यापार का भी बहुत-सा भाग उनको मिल जाता है।

अब मान लीजिए कि कानपुर का कोई व्यापारी लन्दन में आयात करता है तो उसके नाम लिखा हुआ बिल चार्टर्ड बैंक की कानपुर शाखा का भज दिया जायगा जहाँ पर उसे जहाजी बिन्टी आदि मिल जायगा तथा वह भुगतान भी कर देगा। इसी प्रकार यदि उसे निर्यात करना है तो वह अपना लन्दन के व्यापारी अथवा बैंक पर लिखा हुआ बिल स्थानीय शाखा को देकर अपना भुगतान वही पर प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार इनकी शाखाएँ होने में व्यापारी का आयात निर्यात में व्यय भी कम होता है तथा सुगमता भी होती है,

क्योंकि उनकी वही रहते हुए आयात-निर्यात एवं विदेशी विनिमय की सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं और बन्दरगाहों तक जान की आवश्यकता नहीं पड़ती।

३ **अन्य बैंकिंग क्रियाएँ**—इन कार्यों के अतिरिक्त ये भारतीय जनता से माँग पर दिये जाने वाले निक्षेप भी लेते हैं तथा इन पर व्याज देते हैं। अभिवृत्त सुविधाएँ देते हैं तथा भारतीय व्यापारियों को ऋण आदि की सुविधाएँ देते हैं। आन्तरिक व्यापार को भी ये अधिक महायत्ना देते हैं जिससे ये भारतीय बैंक के प्रतियोगी बन बैठें हैं तथा इनके आर्थिक साधन अधिक मुट्ट होने में भारतीय बैंक इनकी प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। यही कारण है कि इनके निक्षेप भारतीय बैंकों की अपेक्षा बहुत अधिक हैं, क्योंकि भारतीय जनता का विश्वास आज भी इनमें बहुत अधिक है। ये स्वर्ण चाँदी का क्रय-विनय करते हैं तथा आन्तरिक बिलों की बटौती करते हैं और अन्य सभी कार्य करते हैं जो भारतीय मयुक्त स्वयं बैंक के हैं। इन्होंने कई व्यापारों को तो आर्थिक सहायता देने का एकाधिकार सा स्थापित कर लिया है जो इनको विदेशी विनिमय व्यापार में भी अधिक लाभदायक होता है, जैसे दिल्ली तथा अमृतसर का वस्त्र व्यवसाय, वामपुर का चमड़ा व्यवसाय आदि।

**विनिमय बैंकों के कार्य पद्धति की त्रुटियाँ**—इनकी कार्य पद्धति एवं क्रियाओं के विरुद्ध अनेक आक्षेप हैं जो भारतीय दृष्टि से अहितकर हैं। उन्होंने अपना व्यापार केवल विदेशी विनिमय तक ही सीमित न रखत हुए अन्य बैंकिंग कार्यों को भी अपनाया। इससे भारतीय बैंक पनप नहीं सके। इतना ही नहीं, अपितु इन्होंने भारतीय बैंक की कट्टर प्रतियोगिता की। केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति<sup>१</sup> के सामने जो भारतीय व्यापारियों एवं बैंकों की गवाही हुई उसमें उनकी कार्य पद्धति एवं बाधा पर प्रकाश पड़ता है। ये त्रुटियाँ निम्न हैं —

(१) विदेशी विनिमय बैंकों के प्रधान कार्यालय विदेशों में हैं जहाँ से उनकी नीति का संचलन होता है, जो भारतीयों के हित में कभी नहीं हो सकती और न उसमें भारत का विदेशी व्यापार ही पनपने पाया है। क्योंकि ये भारतीय परिस्थिति से सदा अनभिज्ञ बन रहे हैं। इनकी नीति-निर्धारण में भारतीयों का कोई हाथ न रहा।

(२) इनकी रजिस्ट्री एवं समामेलन विदेशों में होने से उनकी शाखाएँ स्वतन्त्र रूप से यहाँ काम करती हैं तथा उन पर भारतीय अधिनियम के कोई भी नियन्त्रण लागू नहीं होते थे।

( ) भारतीयों को उनकी आर्थिक स्थिति का पूरा पूरा विवरण भी प्राप्त नहीं होता क्योंकि उनका भारत व काय सम्बन्धी कोई भी अलग स्थिति विवरण आदि प्रकाशित नहीं होता । इसमें भारतीय निम्नेषकनाओं की पूर्ण सुरक्षा नहीं हो सकती ।

(४) आयात निर्यात बिन्दु का लेखन स्टलिंग अथवा विदेशी मुद्रा में हानि में उनकी कटौती केवल विदेशी मणियाँ में ही होती है । हमारे भारत की मुद्रा मणियों का इन बिन्दु में किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन नहीं मिलता और न बिल-बाजार का ही विकास होना है । यदि ये बिल भारतीय मुद्रा में निम्न जायें तो भारतीय आयात-व्यय का अवश्य ही लाभ होगा जो आजकल केवल विदेशियों को ही मिलता है ।

(५) विदेशी विनिमय बैंक भारतीय आयात-व्ययों को विशेष सुविधा नहीं देते क्योंकि इनके ऊपर निम्न ज्ञान वान ब्रिज भुगतान बिल हानि है । परन्तु विदेशियों पर निम्न ज्ञान वान बिल स्वीकृति बिल हानि है । हा यह बात अवश्य है कि भारतीय आयात-व्ययों को प्रत्यक्ष रसीद लिख देने पर तत्काल मिल जाता है । इस प्रकार की रसीद में वस्तुओं पर वैधानिक अधिकार विनिमय बैंकों का ही रहता है क्योंकि इस रसीद के आधार पर वे वैधानिक कार्यवाही कर सकते हैं । इसमें उनका लाभ बढ़ता है ।

( ) विनिमय बैंक भारतीयों को साख्तपत्र की सुविधाएँ नहीं देते और यदि देते हैं तो उन्हें जिस राशि की सुविधाएँ दी जाती हैं उसकी १५ से २५% राशि विनिमय बैंक के पास जमा करनी पड़ती है । क्योंकि विनिमय बैंकों की दृष्टि में इनके आर्थिक मायन पर्याप्त नहीं होते । परन्तु यह बात विदेशी आयात-व्ययों के लिए लागू नहीं है ।

(७) केन्द्रीय बैंकिंग आच-समिति को ऐसे प्रमाण भी दिये गये हैं कि विनिमय बैंक भारतीय व्यापारियों के साथ का सत्य एवं पूर्ण विवरण नहीं देते । इतना ही नहीं अपितु भारतीयों की आर्थिक स्थिति के विषय में विरोधी आर्थिक दत्ता बताने हैं तथा विदेशियों का विवरण गृही-गृही देते हैं । हमारे भारतीय व्यापारियों का विदेशी व्यापार में अनेक अनुमानाएँ होती हैं जिसका पूरा प्रभाव भारत के विदेशी व्यापार पर पड़ता है ।

(८) विनिमय बैंक ने विदेशी व्यापार का भारतीयों के हाथ में निकाल

कर विदेशियों को देने में भी अनेक अनुचित कार्यों का उपयोग किया, जिससे विदेशी व्यापार में भारतीयों का भाग केवल १५% ही रहा।

(६) विनिमय बैंकों की कार्य-पद्धति ऐसी रही जिससे भारतीय जहाजों उद्योग तथा बीमा कम्पनियों की इन्होंने प्रगति नहीं होने दी तथा विदेशी कम्पनियों को प्रोत्साहित किया। क्योंकि जो भारतीय इनसे अधिक व्यवहार करते हैं उनको ये बाध्य करते हैं कि वे अपना माल विदेशी जहाजों द्वारा भेजें तथा बीमा भी विदेशी बीमा-कम्पनियों से करवायें। इसमें भारतीय बीमा कम्पनियों को होने वाली हानि २ से ३ करोड़ तक आंकी गई है।<sup>१</sup>

(१०) विनिमय बैंक भारतीयों से अधिक परिमाण में निक्षेप लेते हैं जिसमें वे विदेशी व्यापार करते हैं। इसमें भारतीय समुक्त स्वतन्त्र बैंकों को व्यापारिक हानि तो होती ही है, इसके अतिरिक्त उससे होने वाला लाभ विदेशियों को मिलता है। इसका बुरा प्रभाव भारतीय भुगतान-मन्तुलन पर पड़ता है।

(११) इन्होंने भारतीय मुद्रा-मण्डी को भी दो भागों में विभाजित किया है जिनसे विदेशी विनिमय बैंकों का विदेशी भाग पर अत्यधिक प्रभाव रहा। इनका विदेशी मुद्रा-मण्डियों में सम्पत्ति होने से ऋण राशि का भी कभी अभाव नहीं रहा। इसमें मुद्रा-मण्डी के इस अंग पर रिजर्व बैंक का विशेष प्रभाव न होने से मुद्रा-मण्डी का सगठन एवं नियन्त्रण न हो सका।

(१२) विदेशी बैंक भारतीयों की निक्षेप राशि में विदेशी व्यापार कर विदेशियों को अधिक प्रोत्साहन देते रहते हैं जिससे देशी उद्योग व्यवसाय को हानि होती है तथा देशी पूंजी विदेशियों के हाथ में जाती है।

(१३) विदेशी विनिमय बैंक पिछली एक दशक से यहाँ काम करते हैं परन्तु इन्होंने भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं की और भारतीयों को विदेशी विनिमय-व्यापार की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधाएँ नहीं दी। इसमें भारतीय बैंक इस व्यापार को अपनाने में हमेशा कार्यक्षम कर्मचारियों को प्राप्त न कर सके। इससे भारत की असंमित हानि हुई।

(१४) भारतीय व्यापारी जब विदेशों को माल निर्यात करते हैं तो उनके बिलों की कटौती किया किसी पर्याप्त जमानत लिए विदेशी विनिमय बैंक नहीं करते। परन्तु विदेशीय निर्यातकों में इस प्रकार की जमानत न लेते हुए उनके बिलों की कटौती करते हैं।

(१५) विदेशी विनिमय बैंकों की भारतीय समाशोधन-गृहों में अधिक मददगार होने में अधिक प्रभाव रहता है जिससे वे भारतीय बैंकों को सदस्यता

में वचित करने का प्रयत्न करते हैं। इसी प्रकार "विनिमय बैंक संघ" (Exchange Banks Association) की सदस्यता भी भारतीयों को नहीं मिलती। इन गण के नियमों में भारतीय व्यापारियों के परामर्श बिना परिवर्तन करते रहने हैं, तथा ये नियम विरोध में ही हैं जिनमें भारतीय व्यापारियों का विशेष अमुविधान है।

(१०) विदेशी विनिमय बैंक भारत में व्यापारिक केंद्रों में अपनी शाखाएँ खोल कर मधुक्त स्वयं बैंकों की प्रतियोगिता करत हैं। इसमें भारत को आर्थिक हानि होनी है तथा बैंकिंग विकास समुचित रूप में नहीं हो पाता। इसमें भारतीय व्यापारियों एवं बैंकों ने इनके विरुद्ध अनेक आक्षेप किये हैं।

विदेशी विनिमय बैंकों की भारत को देन

इन आक्षेपों के होन हुए भी मानना पड़ेगा कि इन्होंने ही भारत में आधुनिक बैंकिंग पद्धति का बीज बोया, भारतीयों में बैंकिंग प्रवृत्ति का निर्माण कर बैंकों में जनता का विश्वास निर्माण किया। इन्होंने प्रथम महायुद्ध तक एवं प्रथम युद्ध-काल में अपनी विशेष स्थिति के कारण विदेशी विनिमय मुविभागों की तथा भारत का अन्तर्राष्ट्रीय एवं विदेशी व्यापार बढ़ाने में प्रोत्साहन दिया। यह ऐसी विपम एवं विराधी परिस्थितियों में किया, जब देश में न तो कोई भारतीय बैंक ही थे, न जनता का बैंकों में विश्वास ही था और न विदेशी व्यापार के लिए विशेष आर्थिक मुविधान ही थी।

किन्तु १९०५ में स्थिति बदल चुकी है। देश में अनेक बैंकिंग मस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं तथा उनमें कई तो विदेशी-विनिमय व्यापार करने के लिए पूर्णतः समर्थ हैं। परन्तु यह काम अभी हो सकता है जब विदेशी विनिमय बैंकों की प्रतियोगिता में भारतीय बैंकों को बचाया जाय तथा विनिमय-व्यापार के लिए अधिक मुविधान मिले। भारतीयों में राष्ट्रीय जागरण हो जिसमें वे विदेशियों की अपेक्षा भारतीय व्यापारियों तथा भारतीय बैंकों को प्रोत्साहन देने के लिए उनसे पाम ही अपने निक्षेप रखकर, उनके आर्थिक माधन सुदृढ़ बनाय।

विदेशी विनिमय बैंकों का नियन्त्रण—देश की स्वतन्त्रता एवं गिजबैंक बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने में यह आशा थी कि भारत स्थित विदेशी विनिमय बैंकों पर कुछ वैधानिक नियन्त्रण लगाया जाय परन्तु वेद है कि ऐसा १९४६ तक न हुआ।

इस प्रतियोगिता को नियन्त्रित करने के लिए केवल दो ही मार्ग हैं—

(१) वर्तमान विदेशी विनिमय बैंकों के व्यापारिक कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जायें।

(२) भारतीयों को विदेशी विनिमय क्षेत्र में जाने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिले ।

इस हेतु केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने मुक्त व्यापार नीति (free trade policy) का परित्याग करने के लिए सुझाव रखा था जिससे कोई भी विदेशी बैंक अपनी शाखा भारत में न खोल सके । दूसरे, भारत स्थित विदेशी बैंकों को केन्द्रीय बैंक से जर्मनी, इटली, कनाडा आदि देशों की भांति लाइसेंस प्राप्त किये बिना व्यापार करने की स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिए । यह लाइसेंस देने का अधिकार भी केन्द्रीय बैंक को होना चाहिए । इस सम्बन्ध में समिति का मत था कि ऐसा करने से विदेशों में भारतीय बैंकों के साथ परस्पर अच्छा व्यवहार होगा, निक्षेपकों का हित होगा तथा रिजर्व बैंक को देश के विनिमय बैंक पर नियन्त्रण करने का अधिकार मिलेगा ।<sup>1</sup> कुछ गवाहा का कहना था कि विदेशी बैंकों का व्यापारिक क्षेत्र सीमित कर देना चाहिए जिसमें वे भारतीयों के निक्षेप न ले सकें परन्तु समिति इस सुझाव के विरुद्ध थी । इनके अतिरिक्त अधिकांश सदस्यों का मत था कि वर्तमान बैंकों को लाइसेंस दे देना चाहिए तथा उनको भविष्य में शाखा खोलने के लिए नियन्त्रित कर देना चाहिए । इन सुझावों का विरोध विदेशी विशेषज्ञों तथा इम्पीरियल बैंक के प्रतिनिधियों ने किया, क्योंकि उनका कहना था कि विदेशी बैंकों के पास पर्याप्त साधन होने से उनको इस विषय में पूर्ण स्वतन्त्रता होनी चाहिए । दूसरे, समिति भी इस विचार में महत्तम नहीं थी क्योंकि इसका प्रभाव विदेश स्थित भारतीय बैंकों पर भी पड़ता, जो उस समय तक इस क्षेत्र में नहीं थे । इस समिति के अन्य सुझाव निम्न हैं —

(१) विनिमय बैंक एवं भारतीय बीमा कम्पनियों का समझौता—भारतीय बीमा कम्पनियों को प्रोत्साहन देने के लिए विनिमय बैंक भारतीय बीमा कम्पनियों के साथ समझौता कर ले जिसमें उनके बीमा लेख वे मान्य किया करें तथा उनकी आर्थिक परिस्थिति की जाँच-पड़ताल के लिए उनसे स्थिति-विवरण अथवा अन्य किसी प्रकार के सामयिक विवरण लिया करें ।

(२) अधिकार पदों पर भारतीयों की नियुक्ति—विदेशी बैंकों का उच्च अधिकारियों के पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करनी चाहिए तथा इस व्यवसाय की शिक्षा के लिए भारतीयों को पर्याप्त मुविषाएँ देनी चाहिए । इसमें उनका भारतीयों के साथ अच्छा सम्बन्ध हो सकता है ।

(३) इन्हे भारतीय बैंको के साथ भी समझौता कर लेना चाहिए जिससे भारतीय बैंक इस व्यापार को कर सकें। ऐसी दशा में विनिमय व्यापार में होने वाला लाभ विदेशी एवं देशी बैंको में बाँट लिया जाय जिसमें परस्पर सहयोग बढ़ेगा।

(४) विदेशी विनिमय बैंको की जाय्याओ पर एक 'स्थानीय सलाहकार समिति' हो जो इन बैंकों की श्रृंखला नीति निश्चित करे तथा उन्हें भारतीय आवश्यकताओं की दृष्टि में रखते हुए सलाह दिया करे। यह आवश्यक नहीं है कि सलाहकार समिति की सलाह बैंको को मान्य ही हो। इस प्रकार की स्थानीय समितियों में भारतीय व्यापारियों के साथ उनके अच्छे सम्बन्ध हो सकते हैं।

(५) 'विनिमय बैंक संध' की सदस्यता भारतीय बैंको के लिए खुली रहे तथा मध्य के नियमों का परिवर्तन अथवा संशोधन भारतीय व्यापारियों के परामर्श में हो। इससे भारतीयों को उनकी सूचना मिलती रहेगी और भारतीय आवश्यकताओं को ध्यान में भी रखा जा सकेगा। इन नियमों की प्रति करने में भारतीय व्यापारियों को जानकारी होने की वजह से सुविधा होगी।

(६) विदेशी बैंक अपनी कार्य-प्रणालि में भारतीयों को अधिक सुविधाएँ दें अर्थात् वे भारतीयों का उनकी इच्छानुसार निर्यातकर्ताओं को देशी मुद्रा में बिल लिखने की सुविधाएँ दें जिनकी भारत में कटौती हो सके। इससे भारतीय बिल-बाजार का विकास हो सकेगा। इसी प्रकार आयात व्यापारियों के बिल खरीदने के स्थान पर स्वीकृत किया कर जिसमें उनकी कटौती सन्तान मुद्रा-मण्डी में हो सके तथा भारतीयों को वहाँ की सस्ते व्याज दरों का लाभ प्राप्त हो सके। इतना ही नहीं, अपितु इन प्रकार की स्वीकृति एवं सुविधाएँ भारतीय व्यापारियों को बिना किसी प्रकार की जमानत के देनी चाहिए।

**विदेशी-विनिमय बैंकों पर नियन्त्रण**

भारतीय बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम १९४९ के अनुसार विदेशी विनिमय बैंकों पर निम्न नियन्त्रण लगाय गये हैं—

(१) यह अधिनियम भारत-स्थित सभी बैंकों पर लागू होगा, जिसमें अब इन बैंकों पर भी नियन्त्रण रहता।

(२) भारत स्थित सभी बैंकों को रिजर्व बैंक में साइमेम लेना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार नामाएँ खोलने के लिए भी पूर्ण अनुमति लेनी होगी। यह निम्न बातों पर दी जायगी—

- (अ) बैंक अपने निक्षेपको के निक्षेप भुगतान करने योग्य है एवं उसकी व्यवस्था उनके हित में हो रही है।
- (ब) जिन देशों में बैंक का सम्मेलन हुआ है उस देश में भारतीय बैंकों के विरुद्ध किसी प्रकार के बंधानिबन्ध प्रतिबन्ध नहीं है।
- (म) वह बैंक इस विधान की धाराओं का पालन करता है।

यह लाइसेंस प्राप्त करने पर यदि कोई विदेशी बैंक इन शर्तों का पालन नहीं करता तो रिजर्व बैंक उसका लाइसेंस निरस्त करने का अधिकारी है।

(३) प्रत्येक विदेशी विनिमय बैंक को, जो बम्बई तथा बलकत्ता के अलावा अन्य स्थान पर व्यवसाय करता है, उसकी चुकता पूंजी एवं संचित निधि कम से कम १५ लाख रुपये रखनी होगी। यदि उसका व्यवसाय बम्बई अथवा बलकत्ता अथवा दोनों शहरों में हो तो उसकी चुकता पूंजी एवं संचित निधि कम से कम २० लाख रुपये होनी चाहिए।

(४) प्रत्येक विदेशी बैंक को भारत-स्थित शाखाओं के निक्षेपों की ७५% सम्पत्ति भारत में रखनी होगी। इसी प्रकार माँग एवं काल निक्षेपों की ५% एवं २% राशि रिजर्व बैंक के पास रखनी होगी।

(५) इनको अपना वार्षिक स्थिति-विवरण एवं लाभ-हानि खातों का योग्य अंशको से अवेक्षण कराना होगा एवं उसे उनकी रिपोर्ट सहित अपने प्रमुख एवं अन्य कार्यालयों में दूम्बर स्थिति विवरण के प्रकाशन तक प्रदर्शित करना होगा। यह स्थिति विवरण भारतीय मुद्रा में होना चाहिए।

(६) नियत विवरणों के अतिरिक्त अन्य आवश्यक विवरण भी रिजर्व बैंक इनसे माँग सकता है।

इस अधिनियम में रिजर्व बैंक का जो अधिकार मिले है उनसे रिजर्व बैंक इन पर अच्छा नियन्त्रण रख सकता है। इस अधिकार का उपयोग रिजर्व बैंक ने १९५२ में सर्वप्रथम किया। (भारतीय बैंक को गोआ (Goa) में कार्यालय खोलने की अनुमति वहाँ की सरकार ने नहीं दी। इस कारण रिजर्व बैंक ने 'बैंको नेशनल अल्ट्रांमरिनो, बम्बई' का लाइसेंस निरस्त किया।) रिजर्व बैंक द्वारा अपने अधिकार के उपयोग के कारण रिजर्व बैंक की धाक अब विदेशी विनिमय बैंकों पर बली-मोती जम गई है।

**भारतीय विनिमय बैंक**

भारतीय व्यापारियों की अमुविधाओं एवं भारतीय विदेशी व्यापार की उन्नति की दृष्टि से केन्द्रीय बैंकिंग जाँच समिति ने यह मुद्दा भी किया कि जो भारतीय बैंक अच्छी स्थिति में हैं उन्हें विदेशों में शाखाएँ खोलनी चाहिए।

यदि वे अपनी शाखाएँ न खोल सकें तो विदेश स्थित बैंकों से अपने सम्बन्ध स्थापित कर लेने चाहिए जिससे वे अपने ग्राहकों को विदेशी व्यापार की सुविधाएँ दे सकें तथा नई शाखाएँ खोलने में जो प्रारम्भिक व्यय होता है वह भी न हो। उन्होंने यह भी सुझाव रखा कि रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद इम्पोरियल बैंक लन्दन में स्थापना होने में यह कार्य कर सकता है, अतः उन्हें इस व्यापार की ओर ध्यान देना चाहिए तथा रिजर्व बैंक इस कार्य में उसे आवश्यक सहायता एवं सहयोग दे। कुछ सदस्यों का यह भी मत था कि भारतीय तथा विदेशी मिलकर संयुक्त विनिमय बैंको की स्थापना कर, जिसकी पूंजी सम्मिश्रित हो तथा लाभ-वितरण भी समान हो। इसके अतिरिक्त कुछ सदस्यों का यह मत था कि विदेशी बैंकों की प्रतियोगिता भारतीय विनिमय बैंक नहीं कर सकते, इसलिए सरकार ही इस कार्य को अपनाये तथा एक भारतीय विनिमय बैंक की स्थापना करे जिसकी पूंजी तीन करोड़ हो तथा यह तीन वर्षों में भारतीय बैंकों से प्राप्त की जाय।

परन्तु इस प्रकार अनेक सुझावों के इति दृष्ट भी इस दिशा में प्रत्यक्ष कार्य नहीं हो सका है, अपितु विदेशी विनिमय बैंकों का आज भी देश के बैंकिंग व्यवसाय पर पूर्ण प्रभाव है। विदेशी बैंकों ने भी इस सुझाव की ओर न तो कोई ध्यान दिया है और न कार्य-प्रणाली में ही परिवर्तन किया है। हाँ बैंकिंग अधिनियम के अनुसार विदेशी बैंकों को अब रिजर्व बैंक से धारा २२ के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करना होगा तथा यह उन्हें तभी प्राप्त हो सकता है जब वे इसका पूर्णतः पालन करें। स्टेट बैंक ने भी अभी तक इस व्यवसाय को नहीं अपनाया है। गत कुछ वर्षों में भारतीय बैंकों ने विदेशी बैंकों में समझौते कर सम्बन्ध प्रस्थापित कर लिए हैं, जैसे बैंक ऑफ़ मैम्बूर ने ईस्टर्न बैंक में पंजाब नेशनल बैंक ने मिडलैंड बैंक में आदि। अतः रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सरकार को इस ओर भविष्य में ध्यान देना आवश्यक है।

### सारांश

विदेशी व्यापार के लिए विदेशी विनिमय की मांग एवं आर्थिक सुविधाएँ देने वाले बैंकों को विनिमय बैंक कहते हैं। परन्तु भारत में जो विनिमय बैंक हैं उनके प्रमुख कार्यालय विदेशों में होने के कारण विदेशी विनिमय बैंक कहना उचित होगा क्योंकि आजकल भारतीय बैंक भी इस कार्य को करने लगे हैं। इनका विकास १९५३ के बाद हुआ तथा मार्च १९५६ में ऐसे १५ बैंक भारत में थे जिनकी ६६ शाखाएँ थीं। निम्नो के अनुसार विदेशी विनिमय बैंक दो प्रकार के हैं :—

(१) वे बैंक जिनके प्रधान कार्यालय विदेशों में हैं परन्तु उनके कुल निक्षेपों के २५% से अधिक भाग भारतीयों का है। (२) वे बैंक जो अपने विदेश स्थित प्रमुख कार्यालय के अधिकर्ता का कार्य करने हैं एवं जिनके भारतीय निक्षेप २५% से कम हैं।

विदेशी विनिमय बैंकों के कुल निक्षेपों की राशि ३१ मार्च १९५६ को २०१ करोड़ ८० तथा ऋणों एवं अग्रिमों की राशि १६६ करोड़ ८० थी। रिजर्व बैंक के अनुसंधान के अनुसार भारतीय व्यापार व्यापार के ६०% तथा निर्यात व्यापार के ७०% भाग को ये आर्थिक सुविधाएँ देते हैं।

भारतीय बैंक द्वारा विदेशी विनिमय बैंकिंग न अपनायने के कारण थे— विदेशी मुद्रा मण्डियों पर विदेशी बैंकों का अधिक प्रभाव विदेशी बैंकों की कार्यशील पूँजी अधिक थी तथा विदेशों में शाखाएँ खोलने में बाधाएँ थीं, कुशल वृत्तचरियों की कमी, अधिक निक्षेप प्राप्त करने में कठिनाई, विदेशी मुद्रा-मण्डियों से सम्पर्क का अभाव, सीमित आर्थिक साधन, विदेशी बैंकों की कठोर प्रतिस्पर्धिता समान सुविधाओं का अभाव तथा भारत सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति।

भारतीय बैंकों ने कुछ सीमा तक विदेशी विनिमय क्रियाएँ की तथा विदेशों में शाखाएँ भी हैं। १९५१ के अग्न में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएँ १२७ थीं। परन्तु इनका कार्यक्षेत्र विशेषतः दक्षिणपूर्व एशिया एवं सुदूरपूरव तक ही सीमित है।

विनिमय बैंक तीन कार्य करते हैं—(१) विदेशी व्यापार को आर्थिक सुविधाएँ देना, (२) बन्दरगाहों से आन्तरिक व्यापारिक केन्द्रों में माल पहुँचाने के लिए तथा आन्तरिक व्यापारिक केन्द्रों से बन्दरगाहों तक माल पहुँचाने के लिए आर्थिक सुविधाएँ देना, (३) अग्न व्यापारिक बैंकिंग क्रियाएँ करना।

विनिमय बैंक की कार्य पद्धति के दोष—(१) भारतीय स्थिति का अज्ञान, (२) भारतीय अधिनियमों का नियन्त्रण नहीं (३) उनके आर्थिक स्थिति का विवरण भारतीयों को नहीं मिलता, (४) विदेशी मुद्राओं में रिलों का लिपना, (५) भारतीय आयातकर्ताओं को सुविधा नहीं देते (६) भारतीयों को साखपत्र की सुविधाएँ नहीं देते, (७) भारतीय व्यापारियों के साख का सत्य एवं पूर्ण विवरण न देना (८) विदेशी व्यापार में भारतीयों की उपेक्षा, (९) भारतीय जहाजरानों एवं बीमा उद्योग को प्रोत्साहन न देना, (१०) भारतीय निक्षेप अधिक परिमाण में लेना, (११) भारतीय मुद्रा-मण्डली का दो भागों में विभाजन, (१२) भारतीय निक्षेपों में विदेशियों को आर्थिक प्रोत्साहन (१३) भारतीयों की उच्च स्पर्धा पर निपुणता न करना, (१४) भारतीयों के बिना की कटौती बिना जमानत

के नहीं करते, (१५) समाशोधन-गृहों की मददस्वता से भारतीय बैंको को वधित रखना, (१६) समुक्त स्कन्ध बैंको से प्रतियोगिता। इन दोषों के होने हुए भी इन्होंने भारतीयों से बैंकिंग प्रवृत्ति का निर्माण कर बैंकिंग में जनता का विश्वास स्थापित किया—विशेषतः उस स्थिति में जब भारत में आधुनिक बैंक भी न थे।

• विदेशी विनिमय बैंका पर दा प्रद्वार से नियन्त्रण हा मक्न है—(१) उनको ज़ियाओ पर प्रतिबन्ध लगाने से, तथा (२) भारतीय बैंको को विदेशी विनिमय बैंकिंग के लिए अधिक प्रोत्साहन देकर। इस हेतु केन्द्रीय जाँच समिति की प्रमुख सिफारिशें हैं —

(अ) विनिमय बैंक भारतीय बीमा कम्पनियों के साथ समझौता कर उन्हें प्रोत्साहन दें, (आ) अधिकार-पत्रों पर भारतीयों को नियुक्ति करें, (इ) भारतीय बैंको के साथ से विदेशी विनिमय बैंकिंग सम्बन्धी समझौता करें, (ई) विदेशी विनिमय बैंको की स्थानीय सत्ताहकार समिति हो जो उनकी प्रण-नीति निर्धारित करे, (उ) विनिमय बैंक सघ की सदस्यता भारतीय बैंको के लिए खुली रहे, (ऊ) विदेशी बैंक अपनी कार्य-प्रणाली से भारतीयों को अधिक सुविधाएँ दें।

भारतीय बैंकिंग अधिनियम से विदेशी विनिमय बैंक पर निम्न नियन्त्रण लगाय गय हैं —

(अ) रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

(आ) पूँजी सम्बन्धी नियन्त्रण—बम्बई तथा कलकत्ते के सिवा अन्य स्थान पर शाखा होने पर न्यूनतम चुक्ता पूँजी एव निधि १५ लाख रुपए अथवा २० लाख रुपए।

(इ) भारत स्थित शाखाओं के निक्षेपों की ७५% सम्पत्ति भारत में रखना अनिवार्य।

(ई) भाग एव समय देनदारी के ५% व २% राशि रिजर्व बैंक के पास जमा करनी होगी।

(उ) रिजर्व बैंक के पास सामयिक विवरण भेजने होंगे तथा रिजर्व बैंक द्वारा माँगी गई अन्य जानकारी या विवरण भी भेजने होंगे।

भारतीय विनिमय बैंक की कमी को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक तथा भारत सरकार को सामूहिक कार्यवाही करनी चाहिए जिससे अन्य बैंको को इस दिशा में प्रोत्साहन मिले।

## रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया

प्रथम युद्ध-काल (१९१४-१९१६) में विश्व के समस्त राष्ट्रा द्वारा स्वर्ण-मान का त्याग हो चुका था, अतः स्वर्णमान के पुनः स्थापन के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-परिषद् वुमर्स में १९२० में हुई। इसमें "जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं है वहाँ पर शीघ्र ही केन्द्रीय बैंक की स्थापना की जाए" यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, जिसका सब देशों ने ममर्शन किया। कुछ अंश में स्वर्णमान की योजना को सफल बनाने एवं केन्द्रीय बैंक का अभाव दूर करने के लिए ही भारत में १९२० में इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई। परन्तु यह बैंक इस कार्य को नहीं कर सका और न कर ही सकता था। इस हेतु केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। वैसे तो चेम्बरलेन समिति (१९१३) की रिपोर्ट के साथ ही प्रो० कीन्स की केन्द्रीय बैंक योजना प्रकाशित हुई थी। किन्तु हमारी विदेशी सरकार ने उस ओर दुर्लक्ष किया। इसीकी पुनरावृत्ति १९२७ में हिल्टन यंग समिति ने की तथा उन्होंने सिफारिश की कि चगन एवं साख का समुचित नियन्त्रण करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र केन्द्रीय बैंक की स्थापना होनी चाहिए। अधिकांश भारतीय अर्थशास्त्रियों का यह विचार था कि बैंक एवं साख-व्यवस्था के सुमंचासन के लिए ऐसे बैंक की आवश्यकता है।

रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों ?

१ रुपये के अन्तर्बाह्य मूल्य में स्थायित्व—यह कार्य केवल रिजर्व बैंक ही कर सकता था क्योंकि रुपये के मूल्य में आन्तरिक परिवर्तन होने का कारण मुद्रा का आवश्यकतानुसार सकुचन एवं प्रसारण न होना था, जिसकी आवश्यकता-नुसार पूर्ति अथवा सकुचन रिजर्व बैंक पत्र-मुद्रा-चलन एवं सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय का एकमात्र अधिकारी होने के रूप में कर सकता था।

इसी प्रकार रुपये की आन्तरिक मूल्य-स्थिरता पर उसका बाह्य मूल्य निर्भर रहता है तथा मुद्रा की माँग एवं पूर्ति पर भी। अतः विदेशी विनिमय की माँग एवं पूर्ति का आवश्यकतानुसार मिलान एवं स्वर्ण का विदेशों में क्रय-विक्रय करने का एकाधिकार रिजर्व बैंक को दिया जाने से यह कार्य वह कर सकता था। परिणामतः रुपये के अन्तर्बाह्य मूल्य में स्थायित्व रहता।

२ भिन्न-भिन्न बैंको की निधि का केन्द्रीकरण—रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व भिन्न भिन्न बैंका का अपन पाम कुद् राकड निधि रखनी पडती थी जो निष्क्रिय थी अथवा जिसका अन्य बैंका द्वारा उपयोग नहीं हा सकता था, क्योंकि उनम पारस्परिक सहायता नहीं था । किन्तु रिजर्व बैंक की स्थापना से भिन्न भिन्न बैंक अपनी निधि रिजर्व बैंक व पाम रखेग सवा उनका अपन पाम नहीं रखनी पड़ेगो जिसम राकड निधि का केन्द्रीकरण हागा । इसका उपयोग रिजर्व बैंक अन्य बैंका का सहायता दन म करेगा जिसम निष्क्रिय धन का अधिकतम उपयोग हाकर देश की मुद्रा एव भाख पड्डिनि नाचदार एव गतिशील हागी । इससे हमारे वाक्व-बन्दवर म भी सुवस्था का निमाण हागा ।

३ देश मे मुद्रा एव साख-नीति का न्यायपूर्ण एव समुचित प्रबन्ध—यह बैंक व्यापारिक आवश्यकताभा व अनुसार दन की मुद्रा एव साख का मिलान करेगा, जिसम व्यापारिक तथा आर्थिक क्षेत्र एव मुद्रा मण्डी म समुचित सन्तुलन स्थापित हा भवेगा । यह काय अभी तक नहीं हा रहा था क्योंकि मुद्रा का नियन्त्रण सरकार करती थी और साख का नियन्त्रण इम्पीरियल बैंक । इस दुह्न नियन्त्रण क कारण दन की मुद्रा एव साख-प्रवस्था म समुचित सम्बन्ध नहीं था । इसी काय व लिए रिजर्व बैंक का साख एव मुद्रा नियन्त्रण का एकाधिकार मिलना था, जिसम

(अ) मुद्रा का चलन का एकाधिकार मिलना था

(ब) अन्य बैंका की निधि (२ अनुसार) इसक पाम रहती

(म) बैंक दर खुद बाजार की क्रियाभा जादि द्वारा साख नियन्त्रण का अधिकार मिलना था जिसम वह बिना की कटौती सरकारा लन दन एव लने की व्यवस्था, सरकारी प्रतिभनिया का क्रय विक्रय आदि काय समुचित गति म कर सक ।

४ सरकार के बैंकर का काय—सरकार की ञार म जन नण (public debts) की व्यवस्था, सरकार क बैंकर का काय एव सरकार का आवश्यकता व समय आर्थिक सहायता दन का काय करने के उद्देश्य म एव सरकार की मुद्रा एव आर्थिक नीति पर सलाह दन व लिए इस बैंक की आवश्यकता थी । क्योंकि अभी तक सरकार की ञार स विदनी लन-दन विदनी विनिमय-व्यवहार करने वाली कोई भी अधिकृत मस्था नहीं थी । इसम स कतिपय काय इम्पीरियल बैंक करता था परन्तु उसका दिय गय विनाय अधिकार दन एव जनता व हित म न थ ।

५ कृषि-साख—भारतीय कृषि की आर्थिक आवश्यकताभा की पूर्ति करन

के लिए भी इसकी आवश्यकता थी इसीलिए इस बैंक में कृषि-माल विभाग (agricultural credit department) स्थापित किया गया। कृषि मात्र के पूर्ति के लिए उमक आवश्यक जा—अर्थात् महकारी एवं स्वदानीय व—का नियन्त्रण कर समुचित आर्थिक सहायता देने की जिम्मेदारी इस पर होती।

६ बैंकिंग प्रणाली का नियन्त्रण—देश की बैंकिंग प्रणाली के समुचित नियन्त्रण तथा भारतीय मुद्रा मण्डी के विभिन्न अङ्गों के संगठन के लिए भी इस बैंक की आवश्यकता थी निम्न प्रक्रिया के तहत का मुद्रा संगठन सम्भव है। भारतीय मुद्रा मण्डी के विभिन्न शाखा में परस्पर सहायता के अभाव में तथा स्वदानीय बैंक अनियन्त्रित होने में बैंकिंग मुद्धार एवं विकास के सही-सही आँकड़ (statistics) बनाना का उपलब्ध नहीं था।—इसीलिए मुद्रा-मण्डी के विभिन्न अंगों को नियन्त्रित कर उनमें पारस्परिक सहायता निमाण कर देश की मुद्रा मात्र एवं बैंकिंग व्यवस्था का सुदृढ़ बनाने के लिए भी इस बैंक की आवश्यकता थी।

७ मौद्रिक सम्पर्क एवं कार्य—अब राष्ट्रीय के साथ मौद्रिक सम्पर्क बनाने एवं मौद्रिक कार्य संचालन के लिए भी इस बैंक की आवश्यकता थी। विधान इसलिए कि मद्र देश में कन्द्रीय बैंक स्थापित हो चुक था जिनमें मौद्रिक सम्पर्क बनाने के लिए भी इसकी अधिक आवश्यकता थी।

इन उद्देश्यों को लेकर इसकी स्थापना के लिए १८२७ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया विधेयक विधान-सभा में रखा गया किन्तु उस समय विधान सभा के अध्यक्ष (President) द्वारा इसको प्रस्तुत करने की आज्ञा न देने में यह विधेयक वापिस ले लिया गया। १९२४ में जब प्रांतीय स्वायत्तता (provincial autonomy) में प्रान्तों का १९३५ में मिलन वाली थी उस समय कन्द्रीय बैंक का अभाव आवश्यकता थी जिसमें विभिन्न प्रान्तों की आर्थिक नीति का नियन्त्रण मध्य के हित में किया जा सके। इसलिए १९४४ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया विधेयक स्वीकृत हुआ तथा १ अप्रैल १९३५ को इसकी स्थापना की गई। अशुभारिया का बैंक अथवा सरकारी बैंक ?

विधेयक की स्वीकृति के पहले यह अशुभारिया का बैंक ही अथवा सरकारी बैंक हो गये की चर्चा हुई जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील पेश की। इनमें में कुछ नीचे दी गई हैं—

सरकारी बैंक के पक्ष में—(१) पत्र-मुद्रा आदि के संचालन में होने वाला लाभ जनता के हित में ही उपयोग में जाना चाहिए और वह तभी हो सकता है जब कन्द्रीय बैंक सरकार का हो।

(२) जनघारिया का बैंक मंदैव अधिकधिक लाभ कमान के लिए प्रयत्न नील हागा । उस विशेषधिकार प्राप्त हान के कारण इसका व्ययति नियन्त्रण हान में जनता का हित न हागा और न यही सम्भव है कि मंदैव राष्ट्र के हित में इसकी नीति रहगी ।

(३) भारत में यूरोपीय पूँजी अधिक है तथा इसके अतिरन्तर अने यूरोपीय खरीदग । इसमें इस पर उनका प्रभुत्व रहगा एवं मन्त्रालय नीति भी वहीं अपनाएगा जो उन्हें एवं उनका देश के हित में हागी निम्न दश हित की हानि हागी ।

(४) अन्य दशा के कन्द्रीय बैंक जनघारिया के हान हुए भी गरकारी नियन्त्रण में हान है तथा उनका गवर्नर एवं उप-गवर्नर सरकार नियुक्त करती है जिसको बैंक की नीति निर्धारण में असीमित अधिकार हान है । अन हिम्मत-दारा का बैंक हाना अथवा न हागा एक-सा ही है इसलिए सरकारी बैंक ही स्थापित किया जाय ।

(५) जग्न रत्न, टाकघर आदि अन हित व्यवसाया का नियन्त्रण एवं मन्त्रालय सरकार कर रही है तब इस महत्वपूर्ण काम का मन्त्रालय भी सरकार का करना चाहिए क्योंकि जनता का उस पर अधिक विश्वास है ।

उपयुक्त दलीला और कन्द्रीय बैंक के अधिकार एवं उत्तरदायित्व का दखत हुए उनका नियन्त्रण सरकार द्वारा हाना चाहिए क्योंकि 'भरकार का कन्द्रीय बैंक की कार्यक्षमता में अत्यन्त महत्वपूर्ण सम्बन्ध हाना है तथा उसकी नीति की ओर वह दृष्टि नहीं कर सकती ।' विशेषतः युद्ध-काल में उनका कन्द्रीय बैंक पर पूरा नियन्त्रण हाता है ।

जनघारियों के बैंक के पक्ष में—(१) दश में आर्थिक हित की दृष्टि में यह बैंक किसी भी राजनीतिक प्रभाव से दूर हाना आवश्यक है जिसमें वह अबाधित रूप से अपना महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व निभा सके । अतः वह सरकार का बैंक हागा ता राजनीतिक प्रभाव रहगा निम्न उसकी कार्यक्षमता में राजनीतिक पक्ष भेद के कारण बाधा हागी ।

(२) विश्व के विभिन्न देशों के बैंक अतिरन्तर जनघारिया के हैं और जहाँ भी सरकारी नियन्त्रण में है ऐसे नियन्त्रण मौजिब हैं, जिससे देश का अधिकाधिक हित हा । अन जनघारिया का बैंक ही हा ।

( ) जनघारिया के बैंक में निम्न भिन्न हितों का प्रतिनिधित्व हा सकता

है तथा उसकी नीति एवं अन्वधारियों की सुरक्षा का दायित्व सचालका पर होता है। इनकी कार्यक्षमता अविक होती है जा सरकारी बैंक में सम्भव नहीं होनी।

(४) जहाँ तक यूरोपीय पूँजीपतियों अथवा अन्य पूँजीपतियों के प्रभाव का भय है—प्रत्येक अन्वधारियों के लिए अधिकतम अन्व-मर्यादा विधान से निश्चित कर देना चाहिए जिसमें यह भय न रहे। उमी प्रकार अन्वधारियों के लिए अधिकतम लाभान सीमित कर देना चाहिए, जिससे अधिक लाभ होने पर वह सरकारी आय में जमा किया जाय।

उपर्युक्त दलीला में उस समय यह निर्णय किया गया कि कोई भी मुद्रा सम्बन्धी सस्था या बैंक राजनीतिन हस्तक्षेप से दूर रहना चाहिए। इस दलील न प्रभावी कार्य किया एवं रिजर्व बैंक अन्वधारियों का बैंक बनाया गया जो ३१ दिसम्बर १९८८ तक रहा। १ जनवरी १९४९ में उसका राष्ट्रीयकरण हो गया है।

### रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण

उपर्युक्त में स्पष्ट है कि आरम्भ में ही उसके राष्ट्रीयकरण में एक पक्ष था, परन्तु उस समय इसका राष्ट्रीयकरण न होने हुए अन्वधारियों के बैंक के रूप में यह प्रकाश आया। परन्तु १९४७-४८ के वजट की बहस के समय इस बात का प्रभावी प्रतिपादन किया गया कि देश में स्वतन्त्रता एवं राष्ट्रीय सरकार के होने हुए ऐसी महत्वपूर्ण सस्था का शीघ्र राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इसके पश्चात् १९८८ में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण विधेयक भारतीय समद में प्रस्तुत किया गया, जो ३ सितम्बर १९८८ को स्वीकृत हुआ। फलतः १ जनवरी १९४९ से रिजर्व बैंक राष्ट्रीय व्यवस्था में आया तथा उसके सारे अन्व सरकारने १९८८) प्रति १०० रु० के अंश के खरीद लिये हैं।

राष्ट्रीयकरण क्यों ?—(१) मुद्रोत्तर पुनर्निर्माण एवं आर्थिक योजनाओं की सफलता के लिए आवश्यक था कि केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण हो। क्योंकि केन्द्रीय सरकार के अधिकार में जो थोड़े से कार्य हैं उनको छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रान्ता को पूर्ण स्वतन्त्रता हाती है। अतः प्रान्तीय सरकारें अपनी स्वतन्त्र आर्थिक-नीति अपना सकती थीं जिससे यह सम्भव था कि केन्द्रीय सरकार की आर्थिक योजनाएँ सफल न हो पाती। केन्द्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण होने में उनकी एवं केन्द्रीय सरकार की नीति में समानता रहनी जिससे आर्थिक योजनाओं की सफलता में बाधा न आती।

(२) सन्तोषजनक मुद्रा नीति की व्यवस्था—रिजर्व बैंक के ऊपर यह

आश्रय था कि उसकी मुद्रा नीति सन्तापप्रद नहीं रही, विगपत युद्धकाल में, जिससे पत्र-मुद्रा का चलन अविघ्न हुआ तथा मूल्यस्तर बढ़ गया। इसे स्थिर रखने के लिए रिजर्व बैंक न कोई प्रयत्न नहीं किया। अतः रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हान में यह दाप दूर हो सकता था। इसके अनिश्चित कोई भी समस्या जो माघ एवं मुद्रा का नियन्त्रण करती है उसका राष्ट्रीयकरण हाना देश-हित में होता है।

(३) आर्थिक नीति एवं राजनीति में समानता—किसी भी देश की अर्थ-व्यवस्था का राजनीति में घनिष्ठ सम्बन्ध होता है क्योंकि आर्थिक परिस्थिति के अनुसार राजनीति में आवश्यक परिवर्तन होना है। इसी प्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार अर्थ-व्यवस्था में परिवर्तन किए जाते हैं। देश में स्वतन्त्र सरकार की स्थापना से हम यहाँ की अधिक आवश्यकता थी कि इन दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध हो जिससे आर्थिक नीति राजनीति में विमर्श न हो। इसलिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हाना आवश्यक था।

(४) सरकारी आर्थिक नीति का संचालन—अन्य देशों में, विगपत इंग्लैण्ड में बैंक ऑफ इंग्लैण्ड का राष्ट्रीयकरण हो चुका था, जहाँ सरकार की मौद्रिक एवं आर्थिक नीति का केंद्रीय बैंक ही कार्यान्वित करता था। भारत के लिए यह भी सम्भव होगा यदि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हाना।

(५) सरकार एवं केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति में समानता—केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति से देश का राजस्व प्रभावित होता है। युद्ध के बाद वकारी की समस्या बहुत तीव्र हो गई थी। इसका समुचित हल अभी हो सकता था, जब देश की केन्द्रीय सरकार के इच्छानुसार केंद्रीय बैंक की मुद्रा-नीति होती। इसलिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक समझा गया।

(६) आर्थिक विषमता का निवारण—भारत में सामान्य जनता के वर्तमान जीवन-स्तर को ऊँचा करने के लिए आर्थिक विषमता का निवारण, आय-वृद्धि तथा उत्पादन-वृद्धि की आवश्यकता थी। इसलिए सरकारी अर्थ-नीति एवं मौद्रिक-नीति के अनुसार केन्द्रीय बैंक की नीति हाना आवश्यक था।

(७) अन्तरराष्ट्रीय सहयोग—युद्ध के कारण सभी देशों के आर्थिक-कनेक्ट अस्त-व्यस्त हो गए थे तथा प्रत्येक देश के सामने नई-नई आर्थिक समस्याएँ थीं। उदाहरणार्थ, विदेशी व्यापार की स्थिरता विनिमय-दर की स्थिरता भुगतान का समुचित आदि। इनका समुचित हल करने के लिए अन्तरराष्ट्रीय सहयोग में देशों की आगामी आर्थिक नीति निर्धारित हाना आवश्यक था। अतः रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था। इनके माध्यम-साध

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष अन्तर्राष्ट्रीय बैंक में किसी भी देश के व्यवहार केन्द्रीय बैंक द्वारा ही हाने है। उन व्यवहारों का दान की आर्थिक नीति से सम्बन्ध हान के लिए यह आवश्यक समझा गया कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो।

(८) बैंकिंग क्लेवर में विश्वास निर्माण करने के लिए—दण के बैंकिंग स्तर का सुधारने के लिए दण के उपलब्ध गुणा (talents) का समुचित उपयोग होकर कार्यक्षमता में वृद्धि तभी सम्भव थी, जहाँ रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होता। इसके साथ ही भारतीय जनता का स्वयं की सरकार में अधिक विश्वास हान के कारण बैंक में अधिक विश्वास उत्पन्न हान एवं बैंकिंग विकास के लिए भी रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था।

(९) मुद्रा-भण्डों एवं बैंकिंग के संगठन के लिए—रिजर्व बैंक अपने १४ वर्ष के जीवन में भारतीय मुद्रा-भण्डों को न तो संगठित ही कर सका, न वित्त-बाजार की स्थापना में सफल रहा और विगणित स्वदेशीय बैंकों को तो वह अपनी अनेक योजनाओं में भी नियन्त्रित न कर सका। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि रिजर्व बैंक को इन कार्यों की पूर्ति के लिए बड़े निवेन्दा में कार्य करना पड़ता था। अतः कार्यों के संगठन के लिए सुधार एवं उन्नति के लिए, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक था।

(१०) रिजर्व बैंक को दण की बैंकिंग-स्थिति का समुचित एवं सही ज्ञान हान के लिए उम अन्य बैंकों में—जा नियन्त्रित नहीं था—आवश्यक विवरण प्राप्त करने में अनेक मुविधाएँ थी, इसलिए रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक था।

### रिजर्व बैंक का विधान

१ जनवरी १९४२ का रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण होना से रिजर्व बैंक विधान में आवश्यक परिवर्तन हो गया है —

पूँजी—रिजर्व बैंक की पूँजी ५ करोड़ २० ली जा १०० रु० के अंशों में विभाजित थी तथा अभी तक अशघारिया की थी, उसका हस्तान्तरण केन्द्रीय सरकार को हो गया। इसमें वदन में अशघारिया का प्रत्येक १०० रु० के अंश के बदले ११८ रु० १० आ० मिले। इस राशि का १८ रु० १० आ० भुगतान नकद तथा शेष १०० रु० के बदले इन्हें ३% व्याज देते जाने ऋण-प्रतिज्ञापत्र (प्रथम विकास-ऋण (first development loans) वन्ध) दिये गये। इनका भुगतान १५ अक्टूबर १९७० अथवा १९७५ में सरकार की इच्छानुसार तीन भागों की पूर्व-सूचना के बाद होगा।

प्रबंध—रिजर्व बैंक के प्रबंध के लिए केन्द्रीय सरकार बैंक के गवर्नर की

सम्मति से राष्ट्रीय एवं जन हित में उसे आदेश देनी रहती है। इस आदेश के अनुसार केन्द्रीय सभा कार्य करती है। गवर्नर का केन्द्रीय सभा के आदेशों का पालन करना पड़ता है, जिसने साथ ही वह बैंक की व्यवस्था भी करता है। वर्तमान केन्द्रीय सभा के १५ सदस्य हैं, जो भिन्न-भिन्न हितों के अनुसार केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती है—

(अ) एक गवर्नर तथा तीन उप-गवर्नर—इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है तथा ये वेतन प्राप्त कर्मचारी हान हैं। अर्वाधि तथा मतदान सम्बन्धी अधिकार पूर्ववत् ही हैं। वर्तमान गवर्नर मर बी० रामाराव हैं। [ धारा = (१) (१) ]

(ब) चार सचालक—जिनका केन्द्रीय सरकार चार स्थानीय सभा के सदस्यों में से प्रत्येक स्थान में एक के हिसाब में मनोनीत करती है। इनकी अवधि इनकी स्थानीय सभा की सदस्यता में सम्मिलित है। [ धारा = (१) (b) ]

(स) छ सचालक—केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती है। इनकी अवधि ४ वर्ष की होती है। इनमें से दो सचालक जमना अवकाश (retire) ग्रहण करते हैं। [ धारा = (१) (c) ]

(द) एक सरकारी अधिकारी—इसे केन्द्रीय सरकार मनोनीत करती है। यह केन्द्रीय सरकार की इच्छानुसार किसी भी समय तन काम कर सकता है। इसका मतदान का अधिकार नहीं रहता। [ धारा = (१) (d) ]

स्थानीय प्रबन्ध के लिए चार स्थानीय सभाएँ, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में हैं जो केन्द्रीय सभा के आदेशानुसार प्रबन्ध करती हैं तथा पूछे जाने पर आवश्यक मामला पर सलाह देती हैं। प्रत्येक स्थानीय सभा के पाँच सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार यथामुम्भव प्रादेशिक आर्थिक, स्वदेशी बैंकर एवं सरकारी बैंकों के हितों की दृष्टि से करती है।

केन्द्रीय सभा की एक वर्ष में ६ सभाएँ होनी चाहिए, परन्तु तीन महीने में एक सभा अवश्य होनी चाहिए। गवर्नर का यह अधिकार है कि वह केन्द्रीय सभा की सलाह बुलाए, उसी प्रकार कोई भी तीन सचालक गवर्नर से सलाह बुलावे के लिए निवेदन कर सकते हैं।

भ्रान्तरिक समूहों एवं व्यवस्था—केन्द्रीय सचालक सभा का सम्भावित तथा बैंक का प्रमुख अधिकारी गवर्नर है जिसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा मनोनीत उप गवर्नर कार्य करता है। गवर्नर बैंक के सम्पूर्ण अधिकारों का उपयोग करता

है परन्तु उसको केन्द्रीय मन्त्रालय के निर्वहण का पालन करना पड़ना है। गवर्नर की सहायता के लिए तीन उप गवर्नर हैं जो पृथक् कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं। गवर्नर तथा उप गवर्नर अधिकतम ५ वर्ष के लिए (अथवा जिस अवधि के लिए सरकार नियुक्त करे) नियुक्त होते हैं जिसके बाद उनकी पुनः नियुक्त हो सकती है।

बैंक का केन्द्रीय कार्यालय लन्दन में है। देश के विभिन्न भागों में मन्त्रालय जनक रीति में कार्य करने की सुविधा के लिए इसके स्थानीय कार्यालय लाहौर, बम्बई, बंगलूर, कानपुर, मद्रास, नागपुर तथा नई दिल्ली में हैं। अन्य स्थानों पर इसका प्रतिनिधित्व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद बैंक ऑफ मैसूर कर रहे हैं। इसके सिवा रिजर्व बैंक के बैंकिंग विभाग की एक शाखा लन्दन में है।

राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से रिजर्व बैंक किसी भी स्थान पर अपनी शाखा खोल सकता है।

रिजर्व बैंक का कार्य आठ विभागों में विभाजित है—

१ चलन विभाग—इसका प्रमुख कार्य पत्रमुद्रा चलाना है। यह विभाग पत्रमुद्राओं का प्रधान अथवा गौण मुद्राओं में परिवर्तन भी करता है। सर्व प्रथम इसी विभाग ने कार्य करना आरम्भ किया जिससे सरकारी चलन की व्यवस्था का भार इस मिला। इसी प्रकार इसे स्वर्ण निधि का हस्तान्तरण भी भी हुआ जा आजकल चलन विभाग की सम्पत्ति में है।<sup>१</sup>

२ बैंकिंग विभाग—यह १ जुलाई १९३५ को खोला गया। इसी तिथि से सूचीबद्ध बैंकों ने अपनी माँग एवं समय देनदारी का वैधानिक अनुपात ५% तथा २०% इसमें निष्पेक्ष में रखना आरम्भ किया। इसी दिन से समानोपन-गृही का कार्य भी इम्पीरियल बैंक से इसको मिला। इसके अतिरिक्त सरकारी व्यवहारों का लेन-देन, सरकार की ओर से राशि-स्थानान्तरण करना, एवं सरकार का राशि स्थानान्तरण की सुविधाएँ तथा अन्य आर्थिक सहायता देने का कार्य यह विभाग करता है।

३ कृषि-साख विभाग—यह विभाग केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों तथा सहकारी मस्याओं को कृषि-साख सम्बन्धी सुविधाएँ देने के लिए खोला गया है।

1 "The main functions of the Bank is to regulate the issue of bank-notes and the keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit-system of the country to its advantage"—*Ibid*, p 7

इसमें कृषि-सामान के विनिमय का कार्य करने हैं तथा बैंक राज्य सरकारों तथा महकमों मस्याओं को आवश्यक सलाह देने हैं ।

४ साह्यकी एवं खोज विभाग इसका कार्य मुद्रा, कृषि, उत्पादन, लाभान आदि विभिन्न विषयों सम्बन्धी अनुसन्धान करना तथा उनके आँकड़े प्रकाशित करना है ।

५ विनिमय नियन्त्रण विभाग—विदेशी विनिमय-दर स्थिर रखने के लिए विदेशी विनिमय तथा निश्चित दरों पर क्रय-विक्रय करने का कार्य यह विभाग करता है । तृतीय महाभुड-काल में यह विभाग स्वतन्त्र रूप से खोला गया था जिसने विदेशी विनिमय दरों पर बेगड़िन में नियन्त्रण रखा जा सके ।

६ बैंकिंग क्रियाएँ-विभाग—यह विभाग १९४६ में बैंकिंग अधिनियम पास होने पर बनाया गया । १९४६ के बैंकिंग अधिनियम में रिजर्व बैंक को जो अधिकार मिले हैं उनका उपयोग करने एवं देश की बैंकिंग प्रवृत्ति का समुचित नियन्त्रण करने का कार्य यह विभाग करता है ।

७ बैंकिंग विकास विभाग—ग्रामीण बैंकिंग की समस्याओं का अध्ययन करने एवं ग्रामीण बैंकिंग का विकास करने के लिए १९५० में यह विभाग खोला गया ।

८ औद्योगिक वित्त विभाग—एक आरंभ औद्योगीकरण की आवश्यकता तथा दूसरी ओर देशी पूँजी बाजार में पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण रिजर्व बैंक को अपनी क्रियाओं का विस्तार करना पड़ा जिसमें औद्योगिक क्षेत्र की मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन माध्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । इस हेतु आवश्यक मस्याओं की स्थापना तथा सामग्री रखने तथा उनको सलाह देने का कार्य यह विभाग करता है ।

रिजर्व बैंक के कार्य

कुछ कार्य ऐसे हैं जो रिजर्व बैंक विधान की धारा १७ की के अनुसार करना है तथा कुछ कार्य देश का केन्द्रीय बैंक होने के लिये करता है । अतः रिजर्व बैंक के ये कार्य दो भागों में बाँटे जा सकते हैं—

(१) केन्द्रीय बैंकिंग कार्य, तथा (२) सामान्य बैंकिंग कार्य ।

(अ) केन्द्रीय बैंकिंग कार्य—१ पत्र मुद्रा चलन—देश की मात्र एवं मुद्रा का नियन्त्रण करने के लिए इसे अन्य केन्द्रीय बैंकों की भाँति पत्र-मुद्रा-चलन का एकाधिकार है (धारा २२) । यह कार्य पत्र-चलन-विभाग करता है जो बैंकिंग विभाग में अलग है । इसका स्थिति-विवरण बैंकिंग विभाग से अलग बनाया

जाता है जो माप्ताहिक प्रवासित होता है। चलन विभाग की सम्पत्ति स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप ने सदस्य देशों की प्रतिभूतियाँ, रुपये के मिक्के तथा रुपये की प्रतिभूतियों में रखी जाती है। इसे पत्र-मुद्रा-कोप कहते हैं, जो धारा ३३ के अनुसार रिजर्व बैंक के चलन विभाग में होना अनिवार्य है। मूल अधिनियम के अनुसार कुल नोट चलन का ४०% भाग स्वर्ण मुद्राएँ तथा विदेशी प्रतिभूतियों में होना अनिवार्य था, परन्तु किसी भी देश में स्वर्ण एवं स्वर्ण मुद्राएँ दोनों मिलाकर ४० करोड़ रु० से कम मूल्य की नहीं होनी चाहिए थी। कोप ६०% भाग रुपये में, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल तथा देश में भुगतान होने वाले ऐसे विनिमय बिला एवं प्रतिज्ञापनों में रखा जाता था जिन्हें रिजर्व बैंक गरीब मक्का था। स्वर्ण का मूल्यांकन ८ ४७ १/२ ग्रेन प्रति रुपया अथवा २१ २४ रु० प्रति तोले की दर से होना था। यह पद्धति २० वर्ष तक चालू रही जो भूतकालीन अवशेष था। केन्द्रीय बैंकिंग को गुडकालीन एवं गुडोत्तरकालीन प्रवृत्ति नोट चलन से विदेशी कोपों को असम्बद्ध करने की रही। क्योंकि यह मान्य हो चुका है कि विदेशी कोप भुगतान सतुलन की प्रतिकूलता के निवारण के हेतु ही रखे जाते हैं। अन विकास योजनाओं के अन्तर्गत भारत में जो तीव्र गति से होने वाली आर्थिक प्रगति एवं अर्थव्यवस्था के मौद्रिक क्षेत्र के विस्तार के कारण चलन के अधिक विस्तार की आवश्यकता थी। इसलिए ६-१० १९५६ के संशोधन से भारत में अनुपातिक निधि पद्धति के स्थान पर न्यूनतम काप पद्धति अपनाई गई। इस पद्धति के अनुसार रिजर्व बैंक के नोट चलन विभाग में ४०० करोड़ रु० की विदेशी प्रतिभूतियाँ तथा ११५ करोड़ रु० का स्वर्ण एवं स्वर्णमुद्राएँ अथवा दोनों मिलाकर ५१५ करोड़ रु० का कोप रखना अनिवार्य हो गया। इस हेतु स्वर्ण का मूल्यांकन २ ८८ ग्रेन प्रति रुपया अथवा ६२ ५० रु० प्रति तोले की दर से किया गया। फलस्वरूप नोट चलन विभाग के स्वर्ण का (७१ लाख औंस) मूल्य ४०००२ करोड़ रु० से ११७७६ करोड़ रुपये हो गया। ३१ अक्टूबर १९५७ को इसमें पुन संशोधन किया गया। इसके अनुसार रिजर्व बैंक के चलन विभाग में स्वर्ण, स्वर्णमुद्राएँ एवं विदेशी प्रतिभूतियाँ का कुल मूल्य किसी भी समय २०० करोड़ रु० से कम नहीं होना चाहिए तथा इसमें स्वर्ण एवं स्वर्णमुद्राएँ न्यूनतम ११५ करोड़ रु० की होना चाहिए। अर्थात् रिजर्व बैंक के नोट चलन विभाग में ११५ करोड़ रु० का स्वर्ण एवं स्वर्णमुद्राएँ तथा ८५ करोड़ रु० की विदेशी प्रतिभूतियाँ रहना अनिवार्य है। परन्तु किसी भी समय केन्द्रीय सरकार की पूर्ण अनुमति से विदेशी प्रतिभूतियों को धारणे (holdings) सम्बन्धी धर्त से मुक्त हो सकता है। अर्थात् नोट चलन

विभाग में केवल ११५ करोड़ ₹० स्वर्ण रखना होगा। इसमें नोट-चलन-पद्धति में लोन आगर्ड है।

रिजर्व बैंक की ₹ ५, १०, ५०, १००, १०००, ५००० तथा १०,००० ₹० की पत्र-मुद्राएँ चलाने का अधिकार (धारा २४) है। मन् १९४६ में १००० तथा १०,००० की पत्र-मुद्राएँ बन्द कर दी गई हैं। रिजर्व बैंक अधिनियम की इस धारा में नशेज्ज हो गया है जिगये रिजर्व बैंक का ५००० ₹० की पत्र-मुद्रा चलाने का अधिकार मिन्न गया है। इसी प्रकार १९४६ में बड़ी राशि की पत्र-मुद्राएँ बन्द कर दी गई थी, उन राशियों की पत्र-मुद्राएँ चलाने का अधिकार रहेगा।

१९६८ में रिजर्व बैंक ने अपनी पत्र-मुद्राएँ चलाई। इसके पहले केन्द्रीय सरकार की पत्र मुद्राएँ एक विशेष समझौते के अनुसार चलाने में थी।

रिजर्व बैंक के चलन-विभाग की सम्पत्ति में निम्न विदेशी प्रतिभूतियों का समावेश है—

१ वे प्रतिभूतिपां जा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य देशों की केन्द्रीय बैंक द्वारा चलन विभाग की सम्पत्ति की जमानत पर चालू की गई हा अथवा उम देन के किसी अन्य बैंक द्वारा चालू की गई हो।

२ व विल जिनका भुगतान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सभासद देशों में होने वाला हो, जिन पर दो अच्छे हस्ताक्षर हों तथा उनकी पत्र निधि ६० दिन के अन्दर हो।

३ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सभासद देशों की सरकार द्वारा चालू प्रतिभूतिपां जिनकी अवधि ५ वर्ष हो।

२. बैंकों का बैंकर—(क) देन की वैकिंग पद्धति का नियमन करने का उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक पर है। रिजर्व बैंक के पास सूचीबद्ध बैंकों की अपनी कुल माँग देनदारी का ५% तथा समय-देनदारी का २% रखना पड़ता है। वैकिंग अधिनियम के अनुसार प्रत्येक बैंक को, जो सूचीबद्ध बैंक नहीं है अपने पास अथवा रिजर्व बैंक के पास इस प्रकार नशद कोष रखना अनिवार्य है (धारा १८)। मकट काल में यह राशि रिजर्व बैंक स्वतन्त्रता पूर्वक अन्य बैंकों की सहायता या ऋण देने के लिए उपयोग कर सकता है। अर्थात् जिस प्रकार व्यापारिक बैंक जनता में निक्षेप लेकर उनको ऋण आदि देते हैं, उसी प्रकार रिजर्व बैंक अन्य बैंकों में उक्त निक्षेप लेकर उन्हें मकट-काल में ऋण आदि देकर सहायता करता है। रिजर्व बैंक का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उन मात्र बैंकों में रहता है जिनकी पूंजी तथा निधि मिलाकर १ लाख रुपये में अधिक है तथा जिनका समावेश रिजर्व बैंक

की दूसरी मूची में है। ऐसे बैंकों को मूची बद्ध बैंक कहते हैं। इसके अनिश्चित रिजर्व बैंक का बैंकिंग एक्ट के अनुसार जा अधिकार मिले हैं, उनका भी वह उपयोग करता है।

इन बैंकों को सफ्ट-बैंक में रिजर्व बैंक में महायता मिलती रहती है जिससे देश को बैंकिंग मरट में बचावर देश की बैंकिंग व्यवस्था को मज्जित एवं नियमित किया जा सकता है।

(ग) इन निक्षेपों का उपयोग रिजर्व बैंक को मात्र नियन्त्रण करने में सहायक होता है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर वैधानिक अनुपात में परिवर्तन कर मात्र को घटाया लघवा बढ़ाया जा सकता है। यह अधिकार रिजर्व बैंक को हान ही में मिला है।

(ग) इसी प्रकार मात्र का नियन्त्रण खुले बाजार की क्रियाओं तथा बैंक-दर एवं अन्य मार्गों में भी किया जाता है।

३. विनिमय-दर सम्बन्धी उत्तरदायित्व—रिजर्व बैंक की यह जिम्मेदारी है कि वह रुपये के विदेशी मूल्य में स्थिरता रहे। इसलिए निश्चित दरा पर विदेशी विनिमय का त्रय विक्रय करने का भार इस पर है (धारा ४०)। मूलतः इस पर स्टैलिङ्ग का वचन एवं खरीदने की जिम्मेदारी थी जिसकी दर १ मि० ५५ $\frac{1}{2}$  पेंस या १ मि० ६६ $\frac{1}{2}$  पेंस में अधिक या कम नहीं होना चाहिए। परन्तु १९४७ में भारत अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष का मभासद होने से इनमें आवश्यक परिवर्तन कर दिया है। अब रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय का त्रय विक्रय अधिकृत व्यक्तियों का ऐसी दरा पर कर सकता है, जो सरकार अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष के साथ निश्चित करे। इस प्रकार का त्रय विक्रय १ लाख रुपये से कम का नहीं होगा तथा उन्हीं व्यक्तियों से य व्यवहार हो सकते हैं जिन्हें विदेशी विनिमय नियन्त्रण अधिनियम, १९४७ के अनुसार विदेशी विनिमय के त्रय विक्रय का अधिकार है। रिजर्व बैंक अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष की निर्धारित दरा पर कोष के सभी सदस्य देशों की मुद्राओं का त्रय विक्रय अधिकृत व्यक्तियों को कर सकता है। इस प्रकार विदेशी मुद्राओं का त्रय विक्रय बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा दिल्ली के कार्यालयों में होता है।

४. सरकार का बैंकर—धारा २० के अनुसार रिजर्व बैंक केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के निम्न स्वीकार करता है तथा उनके लेखों पर, उनकी जमा राशि तक भुगतान कर सकता है। इसी प्रकार उनके विदेशी विनिमय व्यवहार, राशि-स्थानान्तरण एवं जन ऋण का प्रबंध तथा अन्य क्रियाएँ

करने का उत्तरदायित्व रिजर्व बैंक पर है। यह बैंक सरकार कोष की व्यवस्था भी करता है।

सरकारी निष्पक्ष पर रिजर्व बैंक निम्न भी प्रकार का याज नही देता। सरकार का मासिक मुद्रा एवं आर्थिक नीति सम्बन्धी मन्त्रालय समय-समय पर देता रहता है। रिजर्व बैंक सरकार काप विन जनरल आर्थिक अर्थ अर्थ एवं वित्तियोग पत्रा व चानन व अधिभूत अभिकला का काय भी करता है। रिजर्व बैंक केन्द्राय एवं राज्य सरकारों को अल्पकालीन ऋण न का काय भी करता है।

५. अर्थ वित्तीय बर्किंग काय—रिजर्व बैंक ने का नीति (1957) बैंक होने न अर्थ वित्तीय बर्किंग काय भी करता है निम्न निम्न प्रकार क चलन की पूर्ति राशि स्थानांतरण का सुविधाएं देता समन्वयण गृहा का प्रबंध आर्थिक मामला पर मन्त्रालय तथा बैंकिंग सम्बन्धी आकड़े (statistics) एकत्रित एवं प्रकाशित करने का काय करता है।<sup>1</sup> सरकार कापा का एकमात्र प्रबंधक तथा अभिकला हन व कारण न का अर्थ बैंक एवं जनता की राशि स्थानांतरण का सुविधाएं यह न सकता है। धारा ५८ व अन्तर्गत समन्वयण गृहा का प्रबंध भी यह करता है। नमक अतिरिक्त यह देश की सरकार की तथा बैंक के बैंक का आर्थिक एवं बैंकिंग सम्बन्धी मन्त्रालय-समय पर देता रहता है। बैंक की बैंकिंग स्थिति की जांचिए आर्थिक सरकार का भजन का एवं जनक प्रकाशन का दायित्व भी विधान की धारा ५. ५ (२) तथा ४३ के अनुसार रिजर्व बैंक पर है जिससे जनता का भाग्य की आर्थिक एवं बैंकिंग स्थिति की जानकारी हो सके।

(ब) सामान्य बैंकिंग काय—बैंक काय बैंकिंग कायों व अतिरिक्त रिजर्व बैंक निम्न नियम करता है जिनका उल्लेख विधान का १७ वा धारा में किया गया है—

(१) बैंक राज्य तथा स्थानाय सरकारों व बैंक म तथा अन्य व्यक्तियों में बिना व्याज के निष्पक्ष स्थोकार करना तथा बिना व्याज के निष्पक्ष-नल चलाना।

( ) (अ) व्यापारिक एवं वाणिज्य व्यवहारा व बिना एवं पतिज्ञान-यना का काय निष्पक्ष एवं करीना करना। य बिना ६० दिन का अवधि में अधिक के न

<sup>1</sup> *Function and Working of the Reserve Bank of India* by J B Faylor pp 11 13

हो तथा उन पर दो अन्य अच्छे हस्ताक्षर हो, जिनमें से एक हस्ताक्षर किसी सूची-वृद्ध बैंक का हो।

(ब) कृषि-कार्यों तथा पत्तल को बेचने के हेतु जिन बिलों अथवा प्रतिज्ञा-पत्रों को लिखा गया हो, ऐसे बिलों का नय-विक्रय तथा बटौती करना। ऐसे बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों का भुगतान भारत में हो, १५ महीने की अवधि के हो तथा इन पर दो अच्छे हस्ताक्षर हों, जिनमें से एक हस्ताक्षर सूची-वृद्ध अथवा राज्य महकमारी बैंक के हो।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सम्बन्धित देशों में भुगतान होने वाले ६० दिन अवधि के बिलों का नय-विक्रय तथा बटौती केवल सूची-वृद्ध बैंक के साथ ही कर सकता है।

(द) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों का नय-विक्रय करना। इसमें अवधि सम्बन्धी शर्तें नहीं हैं।

(य) किसी भी विदेशी सरकार की प्रतिभूतियों का नय-विक्रय करना, जिसकी अवधि १० वर्षों में अधिक न हो।

(३) स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण तथा विदेशी विनिमय का नय-विक्रय करना एवं सूची-वृद्ध बैंक को विदेशी विनिमय का नय-विक्रय करना, जिसका न्यूनतम मूल्य १,०० ००० रुपये हो।

(४) (अ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का अधिकतम ६० दिन के लिए ऋण देना।

(ब) सूची-वृद्ध एवं राज्य महकमारी बैंकों एवं स्थानीय सरकारों को मान्य प्रतिभूतियों की जमानत पर ६० दिन के लिए ऋण अथवा अग्रिम देना। इस प्रकार के ऋण माँग पर अथवा किसी निश्चित अवधि के बाद भुगतान होने वाले हों परन्तु इनकी अवधि ६० दिन से अधिक न हो।

(५) धन, प्रतिभूतियों, आभूषण आदि सुरक्षा के लिए स्वीकृत करना, एवं ऐसी सुरक्षा के लिए प्राप्त प्रतिभूतियों के व्याज अथवा लाभांश का संग्रहण करना।

(६) ऐसी किसी भी चल अथवा अचल सम्पत्ति का, जो बैंक के अधिकार में ऋणों के भुगतान स्वरूप आई हो, विक्रय करना और मूल्य वसूल करना।

(७) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य देशों के केन्द्रीय बैंक से लेना खोलना, अभिवर्तृत्व (agency) सम्भालना करना एवं अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के साथ लेन-देन करना।

(८) अपने व्यापारिक कार्यों की आवश्यकता के लिए देश के किसी भी

मूची-वद्ध बैंक अथवा किसी भी अन्य दश क कन्द्रीय बैंक से अधिकतम १ भाग के लिए ऋण लेना । एन ऋणों की राशि बैंक की पूँजी से अधिक नहीं होनी चाहिए । इसलिए रिजर्व बैंक अपनी सम्पत्ति रहन रख सकता है ।

(१) स्थानीय, राज्य एवं कन्द्रीय सरकार व अभिवृत्ता का काम करना तथा उनकी आर से स्वयं धन, चांदी एवं प्रतिभूतिया का ऋण विनय करना, प्रतिभूतिया तथा अंश का व्याज अथवा लाभांश एकत्र करना जन ऋण चालू करना तथा अन्य काम करना जो बैंकिंग अधिनियम १९६६ तथा अन्तराष्ट्रीय मुद्रा-बाप क अनुसार वह कर सकता है ।

(१०) अपन कार्यालयों पर तथा अभिवृत्ताओं द्वारा भुगतान हान वान मांग वित्तीयों (demand drafts) का निगमन करना ।

(११) मुद्रा तथा वैकिम सम्बन्धी अनुमत्यान एवं आवडा का मन्त्र करना तथा उन्हें प्रकाशित करना ।

**रिजर्व बैंक के निषिद्ध काम**

(१) किसी व्यापार का करना अथवा किसी व्यवसाय अथवा उद्योग में विशेष रुचि रखना अथवा भाग लेना

(२) किसी भी बैंक अथवा कम्पनी के अंश खरीदना अथवा उनकी जमानत पर ऋण देना ।

(३) अवल सम्पत्ति की रहन पर ऋण देना अथवा अपन कार्यालयों के लिए आवश्यक सम्पत्ति का छाँवर किसी प्रकार का अवल सम्पत्ति खरीदना ।

(४) १७ की धारा के (अ) अन्तर्गत तय है) अनिश्चित अन्य किसी भी स्थिति में ऋण अथवा अग्रिम देना ।

(५) नि ऋण तथा चल-लखा पर व्याज देना

(६) मांग पर भुगतान हान वान बिला के सिवा अन्य बिला का लिखना अथवा स्वीकार करना ।

**रिजर्व बैंक द्वारा साम्ब-नियन्त्रण**

रिजर्व बैंक दश हिम के लिए मुद्रा एवं साम्ब का समुचित नियन्त्रण कर सब इसलिए मूची-वद्ध बैंक का उनका पान अपन मांग एवं समय-यनदारा के ५०० एवं २०० राकड निधि रखनी पडती है । इसी प्रकार अमूची वद्ध बैंक का वैकिम अधिनियम के अनुसार अपन पाम अथवा रिजर्व बैंक के पाम इसी प्रकार राकड निधि रखना अनिवार्य है । इसीसे मास मान्य बिला की कटौती तय एवं पुन कटौती सम्बन्धी अपनी बैंक-दर समय-समय पर प्रकाशित करता है

तथा इस दर से मुद्रा-मण्डी की व्याज-दरों का भी नियमन होता है। रिजर्व बैंक मास्य एवं मुद्रा का नियन्त्रण रिजर्व बैंक अधिनियम तथा बैंकिंग अधिनियम के अन्तर्गत करता है। पहिले के अनुसार रिजर्व बैंक को अन्य केन्द्रीय बैंकों की भाँति सामान्य अधिकार हैं जो दूसरे के अनुसार व्यापारिक बैंकों की क्रियाओं के प्रत्यक्ष नियमन के लिए विशेष अधिकार हैं।

बैंक दर—मास्य नियन्त्रण के लिए बैंक-दर का मार्ग सबसे प्रथम इस देश में इम्पीरियल बैंक द्वारा ही अपनाया गया था। परन्तु इम्पीरियल बैंक की संयुक्त स्वस्थ बैंक व मास्य प्रतियोगिता होने तथा भारतीय मुद्रा-मण्डी के विभिन्न अंगों में परस्पर असहयोग, प्रतियोगिता तथा असमंजस के कारण मास्य-नियन्त्रण में बैंक-दर अप्रभावी रही। दूसरे, इस दर के अप्रभावी रहने का कारण यह था कि इम्पीरियल बैंक अपने लाभ की दृष्टि से इस दर का अधिक उपयोग करता है। तीसरे विनियम बैंकों का अन्य दत्ता की मुद्रा-मण्डिया में प्रत्यक्ष सम्बन्ध होने के कारण वे अपनी मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति विदेशी बाजारों से कर लेते थे तथा इम्पीरियल बैंक पर कम निर्भर थे। चौथे, मुद्रा एवं मास्य-नियन्त्रण का उत्तरदायित्व विभाजित था अर्थात् सरकार मुद्रा का नियन्त्रण करती थी और मास्य का नियन्त्रण इम्पीरियल बैंक।

किन्तु रिजर्व बैंक की स्थापना होने से यह दुहरा नियन्त्रण अब नहीं रहा। फिर भी रिजर्व बैंक की बैंक-दर प्रभावी रूप से काम नहीं कर सकती। क्योंकि किसी भी केन्द्रीय बैंक की मास्य-नियन्त्रण शक्ति दो बातों पर निर्भर रहती है—(१) माग करने वाले अपनी आवश्यकताओं के लिए बैंकों पर कहाँ तक निर्भर है, तथा (२) बैंक केन्द्रीय बैंक एवं अपने निजी साधनों पर कहाँ तक निर्भर है। परन्तु जैसा कि हम देख चुके हैं, यहाँ बैंकों को रिजर्व बैंक के पास जो वैधानिक खण्ड निधि रखनी पड़ती है वह भारतीय आर्थिक परिस्थिति के अनुसार बहुत कम है। इससे मास्य-निर्माण के लिए अधिकतर बैंक अपने निजी साधनों पर ही निर्भर रहते हैं। तथा इसकी स्थापना के बाद अभी तक ऐसा प्रमाण भी नहीं आया कि इसकी मास्य-नियन्त्रण की परीक्षा हो सके। बाजार की स्थिति अच्छी रहने के कारण वे इसके पास अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी बहुत कम आया। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना से मुद्रा-मण्डी में मौसमी मुद्रा की दुर्लभता के समय व्याज-दर में जो परिवर्तन होते थे, वे नहीं हुए तथा बैंक-दर भी एक-सी रही—जो इस का प्रमाण है कि मुद्रा-मण्डी पर रिजर्व बैंक का प्रभाव रहा।

## रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि

रिजर्व बैंक ने १८ नवम्बर १९४१ को बैंक दर ३% से ३½% कर देा जिससे द्वितीय विश्व युद्ध काल में आ मुन्म मुद्रानीति अपनाई गई था उसका अन्त हा गया । रिजर्व बैंक की स्थापना से १६ वर्ष में बैंक दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ था । द्वितीय महायुद्ध समाप्त होने ही में भी देश का आर्थिक-क्षेत्र में परिवर्तन हो गया व फिर भी वहाँ के बैंक-अधिकारियों की इच्छा मुन्म मुद्रानीति बनाय रखन का हा था जिसमें न भारत और न इंग्लैण्ड पीछ रहा । मुन्म मुद्रानीति में सरकारी ऋण लन में सुविधा रहनी है दूसरे मुद्रापरान आन वाली मदी एवं वकारी की समस्या का निवारण इससे हा सकता था तथा तीसरे युद्ध छेस राष्ट्रा के आर्थिक विकास एवं पुनर्निमाण की योजनाओं का पूरा करन में सहायक हाती । यना इस नीति से लाभ था परन्तु इसका दूसरा पहलू भी था । मुन्म मुद्रानीति में राष्ट्र की पूजी निमाण शक्ति बीमा-व्यवसाय आदि पर बुरा प्रभाव पडता है ।

**बैंक दर में वृद्धि क्या —**(१) विदेशी पूजी प्राप्त करना—भारत के लिए इस समय औद्योगीकरण एवं पंचवर्षीय योजनाओं का पूरा करन के लिए धन की आवश्यकता ता थी ही । अतएव यह अविक पूजा देा का पूरा निमाण शक्ति बनाकर तथा कुछ विदगा में प्राप्त करना था । विदेशी पूजी भारत में आ सकें इस लिए विदेशीया का ऊँच व्याज दर का प्रलाभन देना आवश्यक था ।

(२) मुद्रास्फीति की रोकथाम—भारत में मुद्रास्फीति का तात्रता के कारण जनता नाहि नाहि कर रहा थी जिसमें अन्य उपायों के हात हुए भी कुछ अर नही पता था ।

(३) व्यापार सन्तुलन की प्रतिश्रुतिता का निवारण—१९४१ में विदेशी व्यापार सन्तुलन में विषमता आ रहा थी जिसका निवारण करना भी आवश्यक था ।

(४) साख-नियंत्रण—विगत वर्षों से वकान अमीमिन ऋण दिया था तथा मास का प्रसार किया था जिसको देश हित के लिए नियंत्रित करना आवश्यक था ।

(५) नये ऋण लेने के लिए—सरकारी प्रतिभूतियों के भाव जा १८४६ ५० में १०१ २% से (१९४८ का औसत १०८) से आ इतर नीचे चल गया था । इस अवस्था में सरकार का रिना व्याज-दर बनाय नये ऋण लेना सम्भव न था ।

(८) अन्य देशों में बैंक दर वृद्धि—विश्व के सभी देशों में मुद्रा मण्डो की यही अवस्था रही जिससे विश्व के उनत देशों में भी (जैसे कनाडा

स्वीडन अमरिका फ्रांस इंग्लंड आदि में) १९४९ से बक दर बढ़ाई जान लगी। इन कारणों से विविध हाकर उनका दूर करने के लिए रिजर्व बक ने १४ नवम्बर १९५१ को व्याज दर ३% से ३½% कर दी।

किंतु यदि बक दर न बढ़ाई जाती तो क्या होता? हमका यह ध्यान में रखना होगा कि मुलभ मुद्रानीति सम्बन्धी श्री की में का सिद्धान्त पिछड़े देशों में पूर्णतः लागू नहीं हो सकती। क्योंकि इन देशों में केन्द्राय वारिक प्रणाली पूर्णतः पर नहीं पहुँची है और न केन्द्रीय बैंक का मुद्रा मणिया पर पूर्ण प्रभाव है जिसमें आर्थिक प्रभाव की व्यापकता नहीं है। दूसरे पिछड़े देशों में पूँजी एवं आर्थिक (financial) माधन अभी विघटित अवस्था में है। इसलिए इन देशों में उन्नत एवं उद्योग प्रधान देशों की तरह मुलभ मुद्रानीति का उपयोग उसी प्रकार अनिश्चित काल के लिए होना सम्भव नहीं होता। इसलिए बक दर का बढ़ाना आवश्यक हो गया। परन्तु यह दनभ मुद्रानीति (dear money policy) यदि युद्धोत्तर काल में कमजोर अपनाई जाती तो व्यापारिक प्रतिभितिया के मुख्य गिर जात जिससे रक्षा करने के लिए युद्ध काल के असीमित लाभ का जो भाग उद्योगों में काय में रखा था वह काफी होता। दूसरे बक दर बढ़ाने से उद्योगों को जो निराशा का सामना करना पड़ा वह न करना पड़ता। कारण वे उद्योगों में अधिक विनियोग नहीं करते। तीसरे युद्धोपरांत मुद्रास्फीति को मुलभ मुद्रानीति से जो बल मिला वह न मिलता क्योंकि व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के हाथ में पूँजी कम रहती। परन्तु इंग्लण्ड में बक दर बढ़ाने के साथ भारत में रिजर्व बक की दर बढ़ाई गई जिससे आम जनता की यही धारणा हुई कि भारत इंग्लण्ड के कदमों पर ही चल रहा है जो वास्तव में सही नहीं है। इस सम्बन्ध में श्री चित्तागणि दत्तगुप्त ने पहले ही सूचना दे रखी थी। यह दर १६ मार्च १९५७ से ३½% से ४% की गई है।

(१) बक दर वृद्धि की प्रतिक्रियाएँ—बक-दर बढ़ाने का तत्कालीन प्रतिक्रिया से दो विचारधाराएँ बन गई। एक मत था कि बक दर के बढ़ाने से व्याज के आम दर बढ़ाने जिससे उत्पादन व्यय व्यापारिक व्यय आदि बढ़ जायेंगे और इससे मुद्रास्फीति को बल मिलेगा। दूसरी विचारधारा के अनुसार बक दर बढ़ाने में साहूकार स्वदेशीय बक (indigenous) आदि अपनी व्याज दर बढ़ायेंगे जिससे कृषि-साख महंगी होगी। इससे कृषि वस्तुओं का उत्पादन व्यय उनका स्थानान्तरण एवं क्रय व्यय आदि बढ़गा जिससे निमित्त वस्तुओं का उत्पादन व्यय भी बढ़कर मुद्रा स्फीति का बल मिलेगा। ये दोनों ही विचार धाराएँ अर्थशास्त्र के माय सिद्धान्त के विपरीत हैं क्योंकि उत्पादन-व्यय में

व्याज दर का अनुपात नगण्य (insignificant) होगा है या वनमान स्थिति में  $\frac{1}{4}\%$  से  $\frac{1}{2}\%$  तक होगा। परन्तु कन्द्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति का परिमाण कितना होगा इसको निश्चित करने में बैंक दर का महत्वपूर्ण योग होता है। कारण ऋण लेकर माल संग्रह करने वाला की ऋण लेन का गति सीमित हो जाती है तथा उनका लाभ का अनुपात व्याज दर वृद्धि से घट जाता है। लाभ का अनुपात घटने से वह ऋण लेकर माल संग्रह कम करने लगेगा तथा संग्रहीत माल का वृद्धि है। फलतः माल की गति बढ़ जाती है उसकी पूर्ति अधिक हो जाती है और कीमतें गिरने लगती हैं। यही बात मन्त्र के विषय में होती है जिसमें ऋणी ऋण का भुगतान करते हैं तथा ऋण कम लते हैं जिससे मुद्रा मण्डी में मुद्रा की पूर्ति भी घट जाती है। इसीलिए ऊँची बैंक दर अपस्फीति (disinflation) का नाश करने माना जाता है। दूसरे सरकारी एवं अल्प प्रतिभूतियाँ के मूल्यों में बैंक-दर की वृद्धि में गिरावट आती है जिससे बैंक आदि मन्त्राएँ अपनी प्रतिभूतियाँ को बचना नहीं चाहती जिससे गण एवं मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है। इस प्रकार बैंक दर की वृद्धि का प्रभाव अपस्फीति (disinflationary) का होता है।

बैंक-दर में वृद्धि की प्रतिभूति बाजार में तुरन्त ही हुई। इसमें मुद्रा मण्डी में मुद्रा की पूर्ति कम हो गई ऋण लेना कम हुआ एवं नियमित ऋण बाँपित किया गया। इससे प्रतिभूतियाँ के मूल्य भी बाजार में गिरने लगे जिससे बैंक ने अपने ऋण एवं अपने जमानत का अन्तर (margin) कायम रखने लिए ऋणियों से अधिक जमानत मांगना एवं ऋण का भुगतान लेना शुरू किया। फलतः बाजार में मन्दी या गड़बड़ाव अनेक व्यापारियों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर या अपने दरवाजे बंद करने पड़े। दूसरे नाश प्रदायक मन्त्राएँ जो प्रतिभूतियाँ में अपना अधिक स्पर्धा लगाते हैं उनकी प्रतिभूतियाँ के अवमूल्यन में रक्षा करने का प्रश्न उपस्थित हुआ। उनके लिए रिजर्व बैंक ने २४ दिसम्बर १९५१ का एक सूचना द्वारा प्रतिभूतियाँ के औसत मूल्य स्थिति विवरण में बनाने के लिए अनुमति दे दी। वास्तव में बैंक बीमा मन्त्रायाँ आदि की इनके अवमूल्यन से हानि नहीं हुई क्योंकि ये प्रतिभूतियाँ बचने का दृष्टि में नहीं खराब हैं। परन्तु प्रतिभूतियाँ बचने के लिए, किन्हीं सरकारी थीं उनके इससे हानि हुई। वस्तुओं के मूल्य गिरने में सामान्य निर्देशों भी गिरने लगे जिससे उपभोक्ताओं का भावना हुआ।

बैंक दर का प्रभाव बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने अपनी खुद बाजार की क्रियाओं सम्बन्धी नीति भी बदली। इस नीति के अनुसार रिजर्व बैंक खुद

बाजार में बैंक की सहायता के लिए प्रतिभूतियाँ का त्रय केवल विशेष परिस्थिति में करेगा। परन्तु इन प्रतिभूतियाँ की जमानत पर वह २१% की दर से ऋण देगा। इस नीति में बैंक को अपना ऋण प्रदाय कम करना पड़ेगा। इसका साथ ही रिजर्व बैंक ने विवेचक (selective) साख नियन्त्रण नीति अपनाई जिसमें केवल व्यापारिक कार्यों के लिए ही ऋण दिया जाना लगेगा। सरकारी प्रतिभूतियाँ का अवमूल्यन सीमित रखने के लिए उनका दल दत्ता आरम्भ किया। फलस्वरूप परम-प्रतिभूतियाँ (gold edged securities) में स्थिरता आ गई। इस प्रकार इस नई मुद्रा नीति के फलस्वरूप देश की बैंकिंग पद्धति पर रिजर्व बैंक का पर्याप्त नियन्त्रण हुआ गया है, जो देश के लिए हितकर है।

(२) खुले बाजार की क्रियाएँ—बैंक-दर को अधिक प्रभावी करने के लिए रिजर्व बैंक स्वच्छ विनिमय बाजार में मान्य प्रतिभूतियाँ का त्रय विक्रय कर सकता है। परन्तु उनकी यह त्रय विनय शक्ति भी सीमित है क्योंकि रिजर्व बैंक केवल मान्य प्रतिभूतियाँ एवं बिला का ही त्रय विनय कर सकता है। भारत में बिल बाजार का अभी विकास हो रहा है और फिर यहाँ पर ऐसे स्वच्छ विनिमय भी नहीं है जैसा अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में है। इससे इन क्रियाओं का मुद्रा मण्डी पर इतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता।

खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा रिजर्व बैंक आवश्यकतानुसार मुद्रा एवं साख का सकाच एवं प्रसार कर सकता है। जब रिजर्व बैंक मुद्रा मण्डी में प्रतिभूतियाँ वचनगत्त त्रय बाजार में जा अनिरिक्त त्रय शक्ति है वह रिजर्व बैंक के पास आ जान में मुद्रा का सङ्कुचन हो जायगा। और मुद्रा कम होत ही बैंक की साख निगमन शक्ति भी कम हो जायगी। इसी प्रकार जब रिजर्व बैंक प्रतिभूतियाँ का खरीददत्ता ता जनता एवं बैंक के पास अधिक मुद्राएँ आयेंगी अर्थात् मुद्रा मण्डी में मुद्रा की अधिकता हो जायगी। इसमें बैंक की साख निर्माण शक्ति भी बढ़ेगी और साख की पूर्ति अधिक होगी। इस प्रकार रिजर्व बैंक इन क्रियाओं द्वारा साख का सङ्कोच एवं प्रसार करता है। साख के प्रसार एवं सकाच का व्यापारिक स्थिति राजस्व एवं उद्योग पर बड़ा प्रभाव होता है जो बैंक दर द्वारा साख का नियमन (regulation) करने से हासिल है।

विशेषतः आजकल जब बैंक दर प्रभावी रूप में इच्छित परिणाम नहीं देती, खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा मुद्रा मण्डी पर नियन्त्रण किया जाता है जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण १५ नवम्बर १९५१ में रिजर्व बैंक के बैंक-दर एवं खुले

वाजार का क्रियाआ की नीति व परिवर्तन का है जिसमें उमन बाजार में मन्दी का वातावरण पैदा कर दिया ।

(३) वधानिक रोकड़ निधि में परिवर्तन —प्रत्येक मूची-वृद्ध बैंक का रिजर्व बैंक के पास तथा असूचीबद्ध बैंक का रिजर्व बैंक या अपने पास अपनी मांग दनदारा के १% तथा समय दनदारा के २% राकड़ निधि रखना अनिवार्य है । इस वैधानिक अनुपात में परिवर्तन करने का अधिकार रिजर्व बैंक का १९५५ के गणोद्यम में मिल गया है । बैंक अन्तर्गत रिजर्व बैंक मांग दनदारा राकड़ निधि में ५% से २०% तथा समय दनदारी के राकड़ निधि में ५% से १०% तक परिवर्तन कर सकता है । इस पद्धति का उद्देश्य उन बैंकों के लिए रिजर्व बैंक का यह अधिकार भी है कि वह मूचीवृद्ध बैंकों का उसके पास अनिवार्य राकड़ निधि रखने का आदेश दे कि उनके मांग एवं समय निक्षेप एक घापित तिथि के निष्पत्ति में अधिक हों । परन्तु किसी भी बैंक में वधानिक राकड़ निधि मांग दनदारी के २०% तथा समय दनदारी के ५% से अधिक नहीं होना चाहिए । इस साधन का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है ।

इस नीति में रिजर्व बैंक आवश्यकतानुसार परिवर्तन करता है तथा इस परिवर्तन नवम्बर १९५५ एवं नवम्बर १९५७ में किया गया है ।

(४) निर्वाचक (selective) एवं प्रत्यक्ष नियन्त्रण —उक्त मात्रा मात्र नियन्त्रण के सामा य अथवा मर्यादात्मक साधन हैं जिनमें रिजर्व बैंक बैंक-मात्र के कुल मात्रा के नियन्त्रण करता है न कि आर्थिक क्रियाआ के विविध क्षेत्रों का दी जान वाला मात्रा सुविधाओं का । उक्त विविध हस्त अथवा आर्थिक क्रियाआ के विविध क्षेत्र का दी जान वाली मात्रा सुविधाओं का नियन्त्रण होना है तब उस निर्वाचक अथवा गुणात्मक (qualitative) मात्रा नियन्त्रण कहते हैं । इसका हेतु वाछनीय आर्थिक क्रियाआ का प्रोत्साहन देना तथा अवाछनीय प्रवृत्तियों को निरसाहित करना है । ये साधन निम्न हैं —

(अ) बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम धारा २१ के अन्तर्गत बैंकों की ऋण नीति निर्धारित करना । इसके अनुसार रिजर्व बैंक सभी बैंकों से अथवा किसी बैंक विशेष का ऋण नीति निर्धारित कर सकता है या सुविधान बैंकों का पालन करना होगा ।

(आ) उक्त धारा के अन्तर्गत रिजर्व बैंक सभी बैंकों अथवा किसी बैंक विशेष का ऋण देने का हस्त ऋण एवं गारंटी में अन्तर ऋण पर धारा २१ के अन्तर्गत बैंकों को नुकसान दे सकता है जो सुविधान बैंकों का पालन करना होगा ।

(इ) बैंकिंग अधिनियम धारा २० के अनुसार रिजर्व बैंक किसी भी बैंक का अरक्षित ऋण दन स राक सकता है अथवा अन्य आवश्यक शत लगा सकता है ।

(ई) बैंकिंग अधिनियम, धारा ३२ (१) (a) क अनुसार रिजर्व बैंक सभी बैंका अथवा किसी बैंक विशेष को किसी विराप सौदा का अथवा किसी विशेष श्रणी के सौद करने पर राक लगा सकता है तथा किसी बैंकिंग कम्पनी का सलाह द सकता है ।

(उ) मूलिक प्रभाव—रिजर्व बैंक दद की बैंकिंग सस्याआ पर अपन प्रभाव स उनकी ऋणनीति म मागदशन कर सकता है जिसम वह दशहित म हो । हमन अन्तगत रिजर्व बैंक का गवनर देश के प्रमुख बैंको के प्रतिनिधिया की सभा आयाजिन कर उनकी ऋणनीति सम्बन्धी मागदशन करता है । इसका उपयोग अवमूल्यन क समय सितम्बर १९८६ म तथा जून १९५७ म किया गया था जिसम रिजर्व बैंक सफल रहा ।

हमके सिवा रिजर्व बैंक का बैंकिंग अधिनियम के अन्तगत लाइसेंस देन, निरस्त करन वका का परीक्षण करन आदि के अमीमित अधिकार थ जिसम रिजर्व बैंक की धाक बैंको पर अच्छी जम गई है । इसस व रिजर्व बैंक की नीति क विरुद्ध काय नही कर सकते ।

**रिजर्व बैंक का कृषि-साख विभाग**

**कार्य—**(१) कृषि साख सम्बन्धी समस्याओ क अध्ययन क लिए कृषि-साख विशेषज्ञ रखना तथा समय-समय पर केन्द्र तथा राज्य सरकारा एवं राज्य सहकारी बैंको का तथा अन्य बैंकिंग मस्याओ को सलाह देना तथा उनका माग दशन करना ।

(२) अपनी क्रियाआ का कृषि साख म सम्बन्धित रखना तथा उन क्रियाआ द्वारा राज्य सहकारी बैंको तथा कृषि सम्बन्धित अन्य बैंका एवं सस्थाओ को संगठित करना एवं सामजस्य रखना ।

हमारे देश का मवस बड़ा एवं महत्वपूर्ण व्यवसाय कृषि होने हुए भी रिजर्व बैंक कृषि-साख सुविधाएँ देने मे किसी प्रकार की प्रत्यक्ष सहायता नही कर सकता । यह सहायता वह केवल राज्य सहकारी बैंको एवं सूची बद्ध बैंका के माध्यम स ही दे सकता है । इसी प्रकार कृषि साख का क्षत्र भी सीमित है क्योंकि यह केवल उन्ही कृषि जिला की कटौनी अथवा त्रय कर सकता है जो मौसमी साख की पूर्ति के लिए अथवा फल को बेचन के लिए लिखे गये हा तथा जिनकी अवधि १५ मास से अधिक न हो । इन शर्तों के कारण रिजर्व बैंक

कृषि को पर्याप्त साख-मुविधाएँ देने में तथा उन्हें महाजनो के समुल में छुड़ाने में सफल नहीं हो सका है।

रिजर्व बैंक का कृषि-विभाग तीन उप-विभागों में विभाजित है —

(अ) कृषि-साख उप-विभाग—ग्रामीण साख समस्याओं का (विशेषतः सहकारी आन्दोलन) अध्ययन करता है तथा ग्रामीण ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में विधान का अध्ययन करता है।

(ब) बैंकिंग विभाग—इस विभाग के अधिकारी सहकारी आन्दोलन के सम्पर्क में रह कर तथा भारत के विभिन्न भागों में सहकारी आन्दोलन की विशेषताओं की कार्य-प्रणाली का उन स्थानों पर जाकर अध्ययन एवं अनुसन्धान करते हैं। इस अध्ययन एवं अनुसन्धान का परिणाम प्रकाशित करते हैं।

(स) भौकड़ा तथा अनुसन्धान—इस विभाग के अधिकारी अपनी सेवाएँ राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों को, सहकारी बैंकों को तथा कृषि-साख मुविधा देने वाले अन्य बैंकों को देते हैं, यदि वे इस विभाग में कृषि-साख सम्बन्धी समस्याएँ लें।

इस प्रकार इस विभाग ने कृषि-साख समस्याओं सम्बन्धी अधिक अनुसन्धान किया तथा अन्य देशों में भी इस विभाग की आवश्यक सामग्री एकत्रित की है। इनके समय-समय पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों में सरकार के सामने कृषि-साख-मुविधाएँ देने के लिए स्वदेशीय बैंकों के नियन्त्रण तथा सहकारिता आन्दोलन के पुनर्गठन सम्बन्धी अनेक सुझाव भी रहे। वर्तमान देश में स्वदेशीय साखकार तथा महाजन ही ६० प्रतिशत कृषि-साख की पूर्ति करते हैं परन्तु अभी तक ये रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में नहीं आ सके हैं। इसी प्रकार जैसा कि हम अभी देख चुके हैं, रिजर्व बैंक के कार्य कटे हुए होने के कारण वह कृषि-साख की पूर्ति प्रत्यक्ष नहीं कर सकता।

इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक ने स्वदेशीय बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा कृषि-साख मुविधाएँ पहुँचाने का प्रयत्न किया, परन्तु कोई परिणाम न निकला। रिजर्व बैंक ने १४ मई १९३८ को सहकारी बैंकों की माफ़त कृषि-साख की मुविधाएँ देने के लिए कार्य-यन्त्र एवं पद्धति बनाई, जिसमें राज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक से कृषि-साख सम्बन्धी अधिक मुविधाएँ मिल सकती थी। परन्तु इस योजना से राज्य सहकारी बैंकों ने पूरा लाभ नहीं उठाया। इसी वर्ष जनवरी में महाजनो के माध्यम से कृषि-साख मुविधाएँ देने की भी एक योजना बनाई गई थी, जिसके अनुसार कृषि-उत्पाद की अमानत पर लिये गये बिलों की कटौती सूची-बद्ध बैंकों से ०% की दर से करने की मुविधाएँ दी जाने वाली थी तथा इस मुविधा के अनुसार स्वदेशीय बैंकों एवं महाजन विभागों से ४%

मे अधिक व्याज नहीं ले सकते थे, परन्तु सूची-उद्ध बैंकों के विरोध के कारण यह योजना कार्यान्वित न हो सकी।

इसके बाद सहकारी बैंकों को कृषि-साख सुविधाएँ देने के हेतु १९४२ में रिजर्व बैंक ने धारा १७ (२) (ब) तथा धारा १७ (४) (क) के अनुसार एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार फमल के देवने के लिए कृषि साख सुविधाओं के लिए सहकारी बैंक बैंक दर में १% कम पर रिजर्व बैंक से राशि प्राप्त कर सकते थे। इसके साथ यह धर्त थी कि व्याज की इस छूट का लाभ कृषक-श्रमिकों को प्राप्त हो। परन्तु इस योजना में जो आभाएँ थी वे पूरी न हो सकी क्योंकि केवल एक राज्य सहकारी बैंक ने इस योजना के अन्तर्गत २% दर में राशि प्राप्त की और वह भी उसने कृषकों को ५% व्याज की दर से दी। इसमें कृषकों को इस कम दर का वास्तव में कोई लाभ न मिल सका। १९४४ नवम्बर में इस योजना के विकास के हेतु बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों की पटौती पर भी रिजर्व बैंक ने १% छूट (rebate) देना प्रारम्भ किया। परन्तु ये बिल केवल कृषि साख की मौसमी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही हो। १९४६ में १% से १.२% तक छूट दी जाने लगी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्य सहकारी बैंकों के लिए तो रिजर्व बैंक ने १.३% की विशेष छूट देना स्वीकार किया, जो उन्हें १९४६ मार्च तक मिल सकती थी। परन्तु केवल एक राज्य सहकारी बैंक ने इस योजना के अन्तर्गत १९४७ दिसम्बर तक केवल ३५५ हजार रुपए की सहायता ली। भारतीय स्वतन्त्रता एवं रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने से अधिकाधिक कृषि साख सुविधाएँ देने के लिए रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों को अधिक सुविधाएँ देने लगा है। इनमें कुछ सुविधाएँ ग्रामीण बैंकिंग जोच समिति की सिफारिशों के अनुसार दी गई है। वे ये हैं —

(१) रिजर्व बैंक विधान की धारा १७ (२) (ब) एवं धारा १७ (४) (क) के अनुसार रिजर्व बैंक सहकारी बैंकों के मार्फत सहकारी मस्थाओं की मौसमी कृषि-कार्यों के लिए एवं कृषिज वस्तुओं को बेचने के लिए अरक्षित ऋण दे सकता है। उसी प्रकार धारा १७ (४) (अ) के अन्तर्गत रक्षित ऋण (secured advances) सरकारी प्रतिभूतियों एवं भू-रहन बैंकों के ऋण-पत्रों की रहन पर दे सकता है। इन धाराओं के अनुसार रिजर्व बैंक ने १९४७-४८ के सहकारी मस्थाओं को इन सुविधाओं को प्राप्त करने में काफी छूट दी है तथा ऋण लेने की पद्धति में भी सरलता लाई गई है जिससे सहकारी मस्थाएँ इतने अधिकतम लाभ उठा सकें। फलस्वरूप रिजर्व बैंक से इन मस्थाओं ने काफी ऋण लिया जिसका लाभ भारतीय कृषक-समाज को मिला।

(२) रिजर्व बैंक विधान की १७ दी धारा में भी मशौधन कर दिया गया है जिनमें सरकारी मस्याओं को कृपिज-वस्तुओं के मय एव कृपि-बायों की मौमनी आवश्यकताओं के लिए धारा १७ (२) (ब) के अन्तर्गत ६ मास की षगह १५ मास के लिए ऋण मिल सकने है। परन्तु वास्तव में ऋण केवल १२ मास के लिए ही दिये जाते हैं।

(३) धारा १७ (२) (अ) के अन्तर्गत व्यापारिक बिलों की पुन पटौती की जो सुविधाएँ, सूची-वृद्ध बैंकों को थी वे सुविधाएँ सहकारी बैंकों की भी मिल सकती हैं। ये त्रिल ६० दिन में अधिक अवधि के नहीं होने चाहिए।

(४) रिजर्व बैंक से प्राप्त किये हुए ऋण राज्य बैंक केवल 'अ' एवं 'ब' श्रेणी की सहकारी मस्याओं को ही ऋण दे सकने थे। परन्तु अब 'म' वर्ग की सहकारी मस्याएँ भी राज्य बैंक के माध्यम में ऋण प्राप्त कर सकती हैं, यदि राज्य सहकारी रजिस्ट्रार उनकी आधिक मजबूती के विषय में छानबीन कर उनकी सिफारिश कर। आधिक मुदबना की दृष्टि में सहकारी बैंकों एवं समितियों का वर्गीकरण सब राज्यों में समान आधार पर करने की दृष्टि में रिजर्व बैंक ने एक योजना बनाई थी, जिसे सभी राज्यों ने स्वीकार कर लिया है।

(५) रिजर्व बैंक ने स्वीकृत ऋणा का उपयोग ऋण की अवधि में स्वीकृत राशि तक करने की सुविधा सहकारी बैंकों को दे दी है। यह वास्तव में उन्हें रोक्-ऋण (cash credit) की भाँति सुविधा मिल गई है।

(६) ऋणों के आवेदन-पत्रों में जो वाने (data) देना आवश्यक है उनका प्रमापीकरण कृपि-माग्न-विभाग न कर दिया है। यदि इन बातों का स्पष्ट करते हुए सहकारी मस्याएँ ऋणा के लिए राज्य सहकारिता रजिस्ट्रार की सिफारिश के साथ आवेदन-पत्र भेजगी तो उनकी ऋण-मर्यादा धीछ ही निश्चित की जा सकेगी एवं उन्हें एक मप्ताह में ऋण स्वीकार हो जायेगा।

(७) जो व्याज-दर की छूट रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी मस्याओं को १९४२ में दी जा रही थी व सुविधाएँ उनसे नवम्बर १९५१ में बैंक-दर ४% करने के वावजूद भी मिलती रहगी, अर्थात् उन्हें बैंक-दर में अब २% की छूट व्याज में मिलेगी।

(८) सहकारी बैंकों को मिलने वाली राशि-स्थानान्तरण की सुविधाएँ भी अधिक सुलभ कर दी गई हैं। जिन राज्य सहकारी बैंकों ने रिजर्व बैंक को "राज्य सहकारी बैंकों की राशि-स्थानान्तरण सुविधा विकास" योजना को मान लिया है, उनके राशि-स्थानान्तरण सुविधाओं के अनिश्चित कुछ प्रतिप्रवन्ध भी हटा दिय गये हैं, जो निम्न हैं —

(अ) रिजर्व बैंक के अभिवर्त्ता के पास रखा होना ।

(ब) रिजर्व बैंक के कार्यालयों में १०,००० अथवा इसके गुणक (multiple) में ही राशि-स्थानान्तरित किया जाना । जब १,००० के गुणक (multiple) में वे राशि-स्थानान्तरण कर सकते हैं परन्तु न्यूनतम राशि १०,००० होना चाहिए ।

(म) राशि-स्थानान्तरण मुख्य खाने में होना अथवा रिजर्व बैंक एवं उसके अभिवर्त्ता का जहाँ कार्यालय है वहाँ पर कार्यालय होना, यह धर्म भी हटा दी गई है । अब सहकारी बैंक का कार्यालय अथवा शाखा किसी भी स्थान से जहाँ रिजर्व बैंक का अभिवर्त्ता है, रिजर्व बैंक के पास अपने किसी भी खाने में भेज सकता है ।

(द) राशि-स्थानान्तरण केवल रिजर्व बैंक के पास जो प्रमुख खाता (principle account) है उगी में होना चाहिए । यह प्रतिबन्ध हटा दिया गया है ।

राशि-स्थानान्तरण ५,००० रु० तक  $3\frac{1}{2}\%$  दर से एवं ५,००० से अधिक राशि का स्थानान्तरण  $4\frac{1}{2}\%$  की दर से हुआ करेगा ।

(६) सहकारी शिक्षा का आयोजन भी रिजर्व बैंक द्वारा पूना तथा बम्बई में किया गया है ।

(१०) १९५३ के मशोधन से रिजर्व बैंक कृषि-कार्यों के अधिकतम ५ वर्ष के लिए ५ करोड़ रु० तक ऋण दे सकता है । यह ऋण राज्य सरकारों की गारन्टी पर दिया जायगा । इस पर रिजर्व बैंक ३% व्याज लेगा जिससे राज्य सहकारी बैंक इससे अधिकतम लाभ उठाये । परन्तु वे कृषकों से  $6\frac{1}{2}\%$  से अधिक व्याज नहीं ले सकेंगे ।

(११) ग्रामीण साख सर्वे ममिति की मिफारिस के अनुसार १९५५ रिजर्व बैंक एकट में पुनः मशोधन हुआ है जिससे धाराएं ४६ (अ) व ४६ (ब) नई जोड़ी गई हैं, जिसके अनुसार दो नये कोषों की स्थापना की गई है —

(अ) राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष ।

(घ) राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष ।

राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष ३० जून १९५६ को १० करोड़ रुपये जमा करके स्थापित हुआ है । इसमें रिजर्व बैंक आगामी ५ वर्षों में न्यूनतम ५ करोड़ रुपये वार्षिक जमा करेगा । यह कोष निम्न कार्यों के लिए है —

(अ) राज्य सरकारों को सहकारी समितियों को पूंजी में योग देने के लिए अधिकतम २० वर्ष के लिए ऋण एवं अग्रिम देना।

(ब) केन्द्रीय भूमि वचक बैंकों को अधिकतम २० वर्ष की अवधि के दीर्घ कालीन ऋण देना।

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा केन्द्रीय भूमि वचक बैंकों के ऋण-पत्र खरीदने के लिए राशि उपलब्ध करना।

(द) राज्य सरकारों बैंकों को कृषि कार्यों के लिए १५ मास में ४ वर्ष अवधि के मध्यकालीन ऋण देना।

इसका प्रमुख उद्देश्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन तथा भू-रक्षण बैंकों को दीर्घकालीन आर्थिक सुविधाएँ देना है। जून १९५८ के जून में इस कोष की राशि २५ करोड़ २० बी।

राष्ट्रीय कृषि साख (स्मिरीकरण) कोष—इसका निर्माण १ जुलाई १९४६ को रिजर्व बैंक ने १ करोड़ रुपये जमा करके किया है जिसमें २० जून १९६१ वर्षान्त तक वार्षिक १ करोड़ २० राशि जमा करना होगी। इसका उद्देश्य राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण सुविधाएँ देना है, जिसमें वे आवश्यकता के समय अन्यकालीन ऋणों का मध्यकालीन ऋण में बदल सकें। इन ऋणों की अवधि १५ मास में ५ वर्ष तक होगी तथा राज्य सरकार इनकी गारंटी देगी।

इस विवेचन में स्पष्ट है कि कृषि-साख के विकास के हेतु केन्द्रीय सरकार एवं रिजर्व बैंक काफी प्रयत्नशील हैं। परन्तु राज्य सरकारों बैंकों ने इनका पूर्ण लाभ नहीं उठाया। रिजर्व बैंक एक्ट की धारा १७ (८) (९) के अन्तर्गत रिजर्व बैंक तब तक कृषि-साख सुविधाएँ नहीं दे सकता जब तक देश में लाइसेंस-प्राप्त गोदामों की स्थापना न हो। अब देश में ग्रामीण साख सर्वे समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय सहकारी विकास एवं गोदाम बोर्ड (National Co-operative Development and Warehousing Board) की स्थापना की गई है जिसमें भविष्य में रिजर्व बैंक इसके अन्तर्गत सुविधाएँ दे सकता, यह निश्चित है।

**रिजर्व बैंक तथा सूची-बद्ध बैंक**

रिजर्व बैंक की स्थापना ने देश के मयुक्त स्वयं वा विभाजन सूची-बद्ध तथा अमूची-बद्ध बैंकों में कर दिया है।

**सूची-बद्ध बैंक**—उन मयुक्त स्वयं बैंकों को कहते हैं जिसका समावेस रिजर्व बैंक विधान के अनुसार दूसरी सूची में किया गया है। जो बैंक धारा ४२ (६)

मे दी हुई सब शर्तों की पूर्ति करनी है उनका नाम इस सूची में लिखा जाता है।  
ये शर्तें निम्न हैं—

- (अ) जो बैंक भारतीय प्रान्तों में अपना व्यवसाय करते हों,
- (ब) जिस बैंक की चुकता पूँजी एवं निधि मिलाकर ₹ १००,००० रुपए में कम न हो, तथा
- (म) जिसके विषय में रिजर्व बैंक का यह विश्वास हो कि वे अपने निक्षेपकों के हितों में व्यापार कर रहे हैं।

जिन बैंकों का समावेश इस सूची में नहीं है, उन्हें असूची-बद्ध बैंक कहते हैं। सूची बद्ध बैंकों का रिजर्व बैंक से जा सुविधाएँ उपलब्ध हैं वे उन्हें कुछ शर्तों की पूर्ति के बाद ही मिल सकती है। ये शर्तें निम्न हैं—

१ प्रत्येक सूची बद्ध बैंक को अपनी माँग देनदारी की ५% तथा काल-देन-दारी की २% राशि रिजर्व बैंक के पास निक्षेप में रखना होगी।

[धारा ४२ (१)]

२ प्रत्येक सूची-बद्ध बैंक को निम्न बातों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक के पास माप्ताहिक विवरण भेजना आवश्यक होता है।

[धारा ४२ (२)]

- (अ) माँग तथा काल-देनदारी की राशि
- (ब) पत्र मुद्रा तथा सरकारी पत्र-मुद्राओं की राशि जो भारत में है,
- (म) बैंक के पास भारत में कितने रुपये तथा कितनी अन्य मुद्राएँ हैं,
- (द) अग्रिम, ऋण तथा कटौती किय गये बिन्दु की राशि,
- (य) बैंक के पास रोकड़ कितनी है।

इस पर बैंक के दो मंचालकों के व्यवस्थापकों के अथवा अन्य उत्तरदायी अधिकारियों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

जो बैंक अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण माप्ताहिक विवरण नहीं भेज सकते उन्हें रिजर्व बैंक इस आशय का मासिक विवरण भेजने की अनुमति दे सकता है। इन्हीं विवरणों के आधार पर रिजर्व बैंक धारा ८३ के अनुसार सूची बद्ध बैंकों का एकत्रित विवरण प्रकाशित करता है।

यह विवरण न भेजने पर बैंक के संचालका अथवा दोषी अधिकारियों पर विवरण न भेजने की तिथि तक ₹ १०० रु० प्रति दिन के हिमाच में दण्ड हो सकता है। दूसरे, जो बैंक अपनी माँग एवं काल देनदारी की क्रमशः ५% व २% राशि रिजर्व बैंक में नहीं रख पाते उनमें कमी पर धारा ४३ (३) के अनुसार बैंक दर से कुछ अधिक व्याज रिजर्व बैंक वसूल कर सकता है, उनको

निक्षेप स्वीकार करने में रोक सकता है, अथवा उनके संचालकों को दण्ड दे सकता है। इसके अनिरीक्त अन्य विवरण जा बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम के अनुसार भेजना आवश्यक है वे भी भेजने होंगे।

इन धनों की पूर्ति के बदले सूची-बद्ध बैंकों को रिजर्व बैंक से कुछ विशेष सुविधाएँ मिलनी हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सुविधा उनकी बिलों आदि की कटौती की तथा अन्य मान्य प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्राप्त करने की है। साथ ही बिलों के न्य-विक्रय की भी सुविधाएँ मिलनी हैं। किन्तु ऋण आदि की सुविधाएँ देन के पूर्व रिजर्व बैंक यह देख लेना है कि बैंक की ऋण-नीति बँसी है तथा कितने कार्यों में ऋणा का उपयोग होगा? बैंक जमानत की अच्छाई पर ही ऋण नहीं देना क्योंकि इन ऋणों का दुरुपयोग न हो इसकी जिम्मेदारी बैंकिंग विकास की दृष्टि से रिजर्व बैंक की है। रिजर्व बैंक बिना किसी कारण के किसी भी सूची-बद्ध बैंक को ऋण देने में रोक सकता है। सूची-बद्ध बैंक को राशि-स्थानान्तरण की सुविधाएँ भी प्राप्त होनी हैं।

किसी भी बैंक की चुकता पूँजी तथा निधि मिलाकर ५ लाख रुपये से कम हो, उसकी क्रियाएँ देना हित में न हो, जिसने वैकिंग व्यवसाय करता बन्द कर दिया हो अथवा जिसके परीक्षण में रिजर्व बैंक को नन्नीप न हो ता रिजर्व बैंक उसे इस सूची में अलग कर सकता है।

रिजर्व बैंक का असूची-बद्ध बैंकों से सम्बन्ध—असूची-बद्ध बैंक को हम दो श्रेणियों में रख सकते हैं—एक तो वे जिनकी चुकता-पूँजी एवं निधि मिलाकर ५०,००० रुपये से अधिक हो, तथा दूसरे वे जिनकी पूँजी एवं निधि इस राशि से कम हो। इनमें से रिजर्व बैंक केवल पहले प्रकार के बैंकों से, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो तथा बैंकिंग विभाग के अनुसार बैंकिंग व्यापार करते हैं, सम्बन्ध रखना है। उन्हें समय-समय पर आवश्यक मनाह देना है तथा उनके कार्यों का परीक्षण भी करता है। इन बैंकों को रिजर्व बैंक से राशि-स्थानान्तरण की सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जो १ अक्टूबर १९४० में दी गई है जिससे रिजर्व बैंक का इनमें सम्बन्ध हो गये। इस सम्बन्ध को और भी बढ़ाने के लिए १९४५ में असूची-बद्ध बैंक भी रिजर्व बैंक में अपने लेख खोल सकते हैं, परन्तु उनके निक्षेप १०,००० रु० से कम न होने चाहिए और ये लेख खोलने में न होत हुए केवल परस्पर भुगतान का कार्य कर सकते हैं।

रिजर्व बैंक का भारतीय मुद्रा-मण्डी पर प्रभाव—हमारी मुद्रा-मण्डी अम-दृष्टि है तथा उसके विभिन्न अङ्गों में पारस्परिक मह्योग न होने के कारण रिजर्व बैंक की माय-नियन्त्रण क्रियाओं का अन्य पादस्थान देना की भाँति

प्रभाव नहीं पड़ता, जैसा कि हम देख चुके हैं। अतः रिजर्व बैंक को मुद्रा-मण्टी के मगठन की ओर प्रयत्नशील होना चाहिए जिसमें वह भली-भाँति देश हित में साख नियन्त्रण करने में सफल हो सके।

**रिजर्व बैंक द्वारा विनिमय-नियन्त्रण**—द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होते ही भारत सुरक्षा नियम के अनुसार रिजर्व बैंक को विनिमय नियन्त्रण करने का अधिकार प्राप्त हुआ। इसलिए रिजर्व बैंक ने विनिमय नियन्त्रण विभाग खोला। कोई भी व्यक्ति रिजर्व बैंक से साइसेम लिए बिना विदेशी विनिमय-व्यवहार नहीं कर सकता एवं किन कार्यों के लिए विदेशी विनिमय प्राप्त हो सकता था इस सम्बन्ध में भी नियन्त्रण लगाये गये थे जो ३१ मार्च १९४७ तक रहे। विनिमय-नियन्त्रण में अब ढिलाई कर दी गई है फिर भी भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप का मद्दम्य होने से अब स्टर्लिङ्ग में रुपये का सम्बन्ध विच्छेद हो चुका है। भारतीय रुपया निम्नी भी देश की मुद्रा के साथ-जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के सदस्य है, परिवर्तित हो सकता है। अतः रिजर्व बैंक विधान की धाराएँ ४० व ४१ में आवश्यक मसौदा हो गया है, जिसके अनुसार रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दरो पर कर सकता है। विनिमय-नियन्त्रण के लिए २५ मार्च १९४७ को विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम स्वीकृत हुआ एवं १ अप्रैल से लागू हुआ। इसका उद्देश्य विनिमय के मट्टी को रोकना तथा केवल अधिकृत बैंकों को ही विदेशी विनिमय के व्यवहार करने देना है जिनमें विदेशी विनिमय तथा कुछ मयुक्त स्फुध बैंकों का समावेश है। यह विनिमय-नियन्त्रण किस अण तक रहेगा यह भुगतान मन्तुलन तथा भारत सरकार के अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के प्रति उत्तरदायित्व पर निर्भर रहेगा।<sup>1</sup> अर्थात् सरकार द्वारा निर्धारित आयात-निर्यात नीति के अनुसार विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय होगा। अधिकृत बैंकों को विदेशी विनिमय के क्रय-विक्रय का सामाजिक लेखा भी देना पड़ता है जिनमें विदेशी विनिमय की प्राप्ति एवं भुगतान की पूर्ण जानकारी रिजर्व बैंक को रहे।

**रिजर्व बैंक का साप्ताहिक विवरण**—रिजर्व बैंक को अधिनियम की धारा ५३ के अनुसार चलन एवं बैंकिंग विभाग का पृथक्-पृथक् साप्ताहिक विवरण प्रकाशित करना पड़ता है जिसमें इन विभागों की सम्पत्ति एवं देनदारियों का विवरण होता है। इस विवरण से मुद्रा पूर्ति, बैंक साख, सरकार की बजट क्रियाएँ तथा भुगतान मन्तुलन की गति से देश की आर्थिक अवस्था का परिचय मिलता है। चलन विभाग केवल पत्रमुद्रा तथा उगवे परिवर्तन में तथा बैंकिंग

<sup>1</sup> Report of the Reserve Bank of India on "Currency & Finance 1946-47".

विभाग बैंकिंग त्रियाया एव मास नियन्त्रण स सम्बन्धित हाना है । य मासाहिक विवरण प्रमुख पत्रिकाया एव सासकीय गजट म प्रकाशित होत है । इनकी पूर्ण कल्पना निम्न विवरणा स हागी —

चलन विभाग (४ अप्रैल १९५८) [हजार रुपयो म]

देनदारियां	सम्पत्ति
बैंकिंग विभाग	(अ) स्वर्ण मुद्रा एव स्वर्ण
मे पत्र मुद्रा ७९४४-	(1) भारत म ११७३६०३
चलन म पत्र-मुद्रा १६१९६८८२	(11) भारत के बाहर विदेशी प्रतिभूतियाँ ७१६०६६३ ८३३८२६६
कुल पत्र मुद्रा-चलन १६२७-३२५	(ब) रुपय की मुद्रा १२७५७३८
	रुपय की सरकारी प्रतिभूतिया ११६१२०९१
	आंतरिक विनिमय बिल एव अन्य व्यापारिक पत्र —
	योग १६२७६३२५

बैंकिंग विभाग (४ अप्रैल १९५८)

देनदारियां	सम्पत्ति
चुक्रता पंजी १००,००	पत्र मुद्रा ७६४,४३
संचित काप ८०,०० ००	रुपय की मुद्रा ३,६८
राष्ट्रीय कृषि माल (दीर्घकालीन त्रियाएँ) काप २०,०० ००	महायक मुद्राएँ २,७३
राष्ट्रीय कृषि माल (स्विकरीकरण) कोप २,०० ००	खरीद एव घटौती किए हुए बिल
निक्षप (अ) सरकारी (1) क-द्र सरकार १५,२७,४२	(अ) आंतरिक —
(11) अन्य सरकार ७२३ ८८	(ब) विदेशी —
(ब) बैंक ८१ ०५ ८६	(क) सरकारी काप बिल १२७१,७४
(ग) अन्य ११६,३२,४६	विदेशी म रुपय ६८,३४,२६
माध्य बिल (की पी) ७५ ६६,०६	सरकार की ऋण एव अभिम ३७,६३ ०८
अन्य देनदारिया ४०,३७ ०६	अन्य ऋण एव अभिम ७३,६३,८५
	विनियाम १८,११,०२
	अन्य सम्पत्ति १६,१८,८२
	योग ४३२,६२,५८

१ इसमें नगद राशि एव अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ सम्मिलित है ।

२ इसमें राज्य सरकारों के अध्यायी अधिविकर्ष सम्मिलित है ।

रिजर्व बैंक से आशाएँ—रिजर्व बैंक की स्थापना से यह आशाएँ थी कि वह व्यापारिक बैंक का नियन्त्रण एवं माप-दमन कर देश की बैंकिंग व्यवस्था का ऊँच स्तर पर लायगा। इसीलिए राबर्ट निधि रखन सम्बन्धी विशेष वैधानिक अधिकार भी उस प्राप्त था। रिजर्व बैंक मुद्रा मण्डी के विभिन्न अङ्गों को नियन्त्रित कर उस मण्डलित करेगा तथा व्यापारिक एवं अन्य बैंकों में परस्पर सहयोग निर्माण करेगा। देश में मौममी माय एवं मुद्रा की दुर्लभता को दूर कर देश हित में सफ़ाई तथा साख-नियन्त्रण करेगा जिससे निम्न उसे पत्र चलन का एकाधिकार बैंक दर खुल बाज़ार की नियाआ के उपयोग तथा वैधानिक रोकड़ निधि में परिवर्तन का अधिकार है।

किन्तु रिजर्व बैंक ये आशाएँ पूरी न कर सका। अतः इसके विरुद्ध अनेक आक्षेप भी लगाए जाते हैं कि यह न तो मुद्रा मण्डी को मण्डलित कर सका न विल बाज़ार के विकास बैंक-दर एवं खुले बाज़ार की नियाआ द्वारा साख नियन्त्रण कर सका। साथ ही इसमें रुपये के बाह्य मूल्य की स्थिरता रखन का अविरत प्रयत्न किया परन्तु आन्तरिक मूल्य स्थिर रखन का प्रयत्न नहीं किया जिससे देश की अधिक हानि हुई। वृष्टि साख की व्यवस्था भी यह समुचित रूप से आवश्यकतानुसार करने में असफल रहा जिसकी वैधानिक जिम्मेदारी इस पर थी। परन्तु अब राष्ट्रीयकरण के उपरान्त रिजर्व बैंक ने वृष्टि साख सुविधाएँ देने में अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। यह देश की पूँजी की गति शील बनाकर भूमिगत द्रव्य का बाहर निकाल कर विनियोग कार्यों में लगाने में भी सफल नहीं रहा जिससे देश की औद्योगिक प्रगति न हो सकी।

परन्तु यदि निष्पक्षता से १९४६ तक के कार्यों का अध्ययन कर तो स्पष्ट होगा कि रिजर्व बैंक से जो आशाएँ थी उनको पूर्ण न कर सकने का दोष केवल बैंक का ही नहीं है अपितु उस स्थिति का भी है जिसमें रिजर्व बैंक को कार्य करता पड़ा। दूसरे रिजर्व बैंक का अधिकार विधान से सीमित था जिस कारण वह अनेक कार्य करने में अशक्त रहा। तीसरे १९४६ तक विदेशी सरकार की जिसकी नीति भारत की सम्पत्ति का विदेशीकरण कर इंग्लैंड के व्यवसाय एवं उद्योगों को पुष्ट एवं उन्नत करना थी।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम देखें तो मालूम होगा कि मुद्रा-मण्डी में उसके द्वारा साख नियंत्रण का जहाँ तक प्रयत्न उठता है साख की दुर्लभता निवारण करने में रिजर्व बैंक अशक्त रहा। परन्तु नियन्त्रण पूर्ण न कर सकने का कारण अनेक थे —

(१) वैधानिक रोकड़ निधि का सूची बद्ध बैंक का रिजर्व बैंक के पास

रखनी पड़ती थी वह बहुत थोड़ी थी। इसलिए अतिरिक्त राशि बैंक की निजी निधि में होने के कारण उनका रिजर्व बैंक के पास आर्थिक सहायता के लिए जान की आवश्यकता नहीं हुई। रिजर्व बैंक का आवश्यकतानुसार वैधानिक निधि में परिवर्तन करने का अधिकार भी १९५० तक नहीं था अर्थात् विधान की दृष्टि के कारण रिजर्व बैंक माख नियन्त्रण में असफल रहा।

(२) स्वदेशीय बैंकर तथा महाजन आ विनयन ९०% मात्र की सुविधाएँ दत्त हैं, उन्हें रिजर्व बैंक नियन्त्रण में न ला सका। इसका प्रमुख कारण है कि इनका दान में इतना विस्तार है कि मात्र व्यवस्था का अस्त-व्यस्त किया बिना उनको नियन्त्रित करना सम्भव नहीं। और मात्र व्यवस्था यदि अस्त-व्यस्त होती तो देश की कृषि एवं व्यवसाय का अपरिमित हानि हानी। जैसा कि हम बता चुके हैं रिजर्व बैंक ने प्रयत्न किया योजनाएँ बनाइ परन्तु वह सफल न हो सका यह अवश्य उम्मा दाप माना जा सकता है। इस दाप की वजह से भी माख नियन्त्रण करने में असफल रहा तथा उम्मा बैंक दर अप्रभावी रही।

(३) स्वदेशीय बैंकर विशेषतः अपनी सहायता में ही बैंकिंग व्यापार करते हैं तथा विशेष पर कम निर्भर रहते हैं। इसी प्रकार बिना किसी जमानत पर गृहण सुविधाएँ देते हैं एवं मनचाहा व्याज वसूल करते हैं। इससे भिन्न भिन्न स्थानों पर व्याज दरों में भिन्नता रहती है परन्तु रिजर्व बैंक इन पर तब तक नियन्त्रण नहीं कर सकता जब तक उम्मा दान प्रणय सम्बन्ध स्थापित न हो। इसलिए वह व्याज दरों में समानता लाने में भी असफल रहा। परन्तु यह बात माननी पड़ती है कि रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व व्याज दरों में जा अधिकता थी उम्मा कम करने में वह सफल रहा। साथ ही बैंक दर के साथ मुद्रा मण्डी की विभिन्न व्याज दरों का सम्बन्ध प्रस्थापित हो गया है।

(४) मुद्रा मण्डी में सगठन एवं मुद्रदत्ता लाने में रिजर्व बैंक असफल रहा। इसका प्रमुख कारण यह था कि इसका नियन्त्रण न तो स्वदेशीय बैंकरों पर था और न असूची-वद्ध बैंकों पर। असूची-वद्ध बैंक भी कुछ मात्रा में ही १९४० की योजना के अनुसार उसके नियन्त्रण में आ सके हैं परन्तु ये सब बिला की पुन कटौती की सुविधाओं के लिए न तो रिजर्व बैंक पर ही निर्भर है और न अन्य बैंकों पर। इससे ये अग पूणत अपने कार्यों में स्वतन्त्र रहे। इससे अतिरिक्त बैंकों में परस्पर लान दान होता है, जिससे उनका रिजर्व बैंक से सहायता की क्वचित ही आवश्यकता पड़ती है। इस कारण रिजर्व बैंक मुद्रा-मण्डी में सगठन एवं मुद्रदत्ता न ला सका। इस सुदृन्ता एवं सगठन के लिए कि असूची-वद्ध बैंकों का भी मान्य बैंकों की सूची में समावेश होना आवश्यक

है जो कार्य परीक्षण-योजना (inspection scheme) से अब सम्भव हो गया है।

(५) रुपये का आन्तरिक मूल्य स्थिर रखने में रिजर्व बैंक असफल रहा क्योंकि उसने विशेषतः १९३६ के बाद स्टनिंग प्रतिभूतियों के आवार पर पत्र-मुद्रा देना शुरू किया जिससे मुद्रा-स्फीति हुई एवं देश की हानि हुई। यह दोष उसका नहीं था अपितु विदेशी सरकार के प्रभाव में उसे यह कार्य असाधारण स्थिति में करना पड़ा।

(६) जहाँ तक बैंक-दर एवं खुले बाजार की क्रियाओं का सम्बन्ध है हम देख चुके हैं कि आजकल बैंक-दर विश्व के किसी भी देश में प्रभावशाली नहीं है। हाँ, यह मानना पड़ेगा कि उन देशों में आज भी व्याज की भिन्न भिन्न दरों का उतार-चढ़ाव बैंक-दर के अनुसार होता है। परन्तु भारत में ऐसा नहीं होता अपितु व्याज-दर समान रहने हुए भी भिन्न भिन्न दरें समय समय पर बदलती रहती हैं। इसका एकमात्र दोष स्वदेशीय बैंकों, महाजनो तथा उनकी क्रियाओं पर है जो नियमबद्ध न होने से बैंक-दर को प्रभावी नहीं होने देते।

(७) खुले बाजार की क्रियाओं के सम्बन्ध में भी हम देख चुके हैं कि रिजर्व बैंक केवल कुछ विशेष प्रकार की प्रतिभूतियों का ही क्रय-विक्रय कर सकता है, जिनके लिए देश का स्वध-विनिमय विकसित नहीं है। अतः आवश्यकता यह है कि रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन किये जायें जिनसे रिजर्व बैंक वस्तु-अधिकार-पत्रों आदि पर ऋण तथा अग्रिम दे सके। तभी खुले बाजार की क्रियाएँ यशस्वी हो सकती हैं। परन्तु यह कार्य वह अन्य बैंकों की प्रतियोगिता में न करते हुए केवल आवश्यकता के समय ही राष्ट्र एवं जन-हित की दृष्टि से करे।

(८) कृषि-साख के सम्बन्ध में हम देख चुके हैं कि रिजर्व बैंक ने विधान के अन्तर्गत सुविधाएँ देने के अनेक प्रयत्न किये परन्तु उन सुविधाओं से लाभ न उठाया गया। अतः इसका दोष रिजर्व बैंक का न होते हुए उनका है जिन्होंने इन योजनाओं से समुचित लाभ न उठाया। ऐसा भी आक्षेप किया जाता है कि यह लाभ इसीलिए नहीं उठाया गया कि उसमें रिजर्व बैंक द्वारा अनेक शर्तें लगाई जाती थीं। परन्तु यह न भूलना चाहिए कि रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार बिना निर्बंधों के वह भी तो कृषि-साख सुविधाएँ नहीं दे सकता था। परन्तु राष्ट्रीयकरण के बाद रिजर्व बैंक अधिनियम में भारतीय कृषि को देखते हुए काफी संशोधन किये हुए हैं।

फिर भी रिजर्व बैंक ने बैंक-दर को ऊँचा करने एवं बैंकिंग संगठन को

दृष्ट करने का प्रयत्न किया। अनेक बैंक का वित्तियन से बचाने में भी उमने विभाजन के समय सहायता की। परन्तु कुछ बैंक ऐसे भी थे कि उस स्थिति में उन्हें विधान के अनुसार सहायता नहीं दी जा सकती थी। उसके पूर्व इम्पीरियल बैंक की बैंक-दर, जो अस्थायी रहती थी उसको हमन स्थायी किया। इससे विभिन्न दरों में समानता तो नहीं आई, फिर भी उनके उतार-चढ़ाव बहुत अंश में न होने हुए वे व्याज दर नीची हुई तथा उनमें जो अन्तर था उसमें भी कमी हुई। राज्य एवं केन्द्र सरकारों के ऋणों का निर्गमन भी हमने बड़ी कुशलता से किया तथा कम व्याज-दरों पर ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। देश में बैंकिंग-विकास की प्रगति हुई तथा बैंकिंग सुविधाएँ भी बढ़ी। अनेक बठिमाइयाँ के हाथ हुए भी हमने यह कार्य सफलतापूर्वक किया जिसमें १९५५ में भारत के आर्थिक विकास में एक नये बैंकिंग-युग का विकास हुआ। इसके साथ ही हमने मुद्रा मण्टी में जा मौममी मुद्रा की दुर्लभता रहती थी उसका निवारण किया, हमका भी प्रभाव विभिन्न व्याज-दरों को नीचे लाने में ही हुआ।

### राष्ट्रीयकरण के बाद

१९४९ में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ तथा भारत की सरकार भी स्वतन्त्रता के कारण उत्पन्न हुए वाली समस्याओं में मुक्त हुई। इसका बाव हो यह देखते हैं कि देश में नवीन मौद्रिक नीति का विकास हो रहा है —

(१) देश के बैंकिंग स्तर का उन्नत करने एवं गुदुट बनाने के लिए देश में पृथक् बैंकिंग अधिनियम का निर्माण हो चुका है जिसमें रिजर्व बैंक का अनन्य अधिकार मिले है। इस कारण रिजर्व बैंक बैंकिंग समस्याओं पर-दगी एवं विश्वी—नियन्त्रण करने में तथा सहयोग स्थापित करने में काफी सफल रहा।

(२) १५ नवम्बर १९५१ को रिजर्व बैंक ने बैंक-दर में वृद्धि कर मुलभ मुद्रा-नीति का त्याग किया। इसके साथ ही खुले बाजार की विधाओं की नीति में परिवर्तन किया जिससे वह साख्त-नियन्त्रण में सफल रहा। क्योंकि जहाँ इन्फ्लेशन के केन्द्रीय बैंक ने बार बार बैंक-दर बढ़ाई, वहाँ भारतीय केन्द्रीय बैंक ने केवल एक बार ही बैंक-दर में परिवर्तन किया।

(३) जनवरी १९५२ में रिजर्व बैंक ने विल-बाजार को विकसित करने के लिए विल-बाजार योजना लागू की है। साथ ही जुलाई १९५४ से इसको और सुगम बना दिया है। अब कोई भी सूची-बद्ध बैंक १० लाख १० तक के बिलों की कटौती करा सकता है। परन्तु प्रत्येक विल की राशि ५०,०००

र० होना चाहिए। पहिले यही सीमाएँ उसमें ५ लाख रु० और १ लाख रु० की थी। इसके साथ विल-योजना के लाभ पहिले केवल वे सूची-बद्ध बैंक ही ले सकते थे जिनके निक्षेप न्यूनतम ५ करोड़ रु० के थे परन्तु अब यह शर्त नहीं है।

(४) रिजर्व बैंक कृषि-उपज के विनियम के लिए न्यूनतम १५ मास से ५ साल तक की अवधि की आर्थिक सहायता सहकारी बैंकों के माध्यम से देता है। इससे कृषि की मध्यकालीन एवं अल्पकालीन सास मिल सकेगी।

(५) ३० जून १९५६ को रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि-सास (दीर्घकालीन) त्रियाएँ कोष तथा राष्ट्रीय कृषि सास (स्थिरीकरण) कोष का निर्माण किया है जिससे वह कृषि का भू-रहन बैंक के माध्यम में दीर्घकालीन सास सुविधाएँ दे सकेगा तथा सहकारी आन्दोलन का विकास होगा।

(६) रिजर्व बैंक ने औद्योगिक सास सुविधाएँ देने के हेतु राज्य तथा भारतीय औद्योगिक अर्थ नियमा (Industrial Finance Corporations) की स्थापना में सहयोग दिया है। इस हेतु रिजर्व बैंक में एक पृथक् विभाग भी है।

(७) रिजर्व बैंक ने सितम्बर १९५४ को बैंक के निरीक्षक (super-vising) कर्मचारियों की सुविधा के लिए बम्बई में स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना की है। इससे कुशल कर्मचारियों का अभाव दूर होगा।

(८) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के लिए अनुमानित हीनार्थ-प्रबन्धन करना वर्तमान पत्र-मुद्रा प्रणाली में असम्भव था। इस हेतु जुलाई १९५६ से नई मौद्रिक नीति अपनाने के लिए रिजर्व बैंक एकट में सशोधन क्रिय गये हैं। इससे पत्र मुद्रा-चलन की आनुपातिक पद्धति की जगह न्यूनतम निधि पद्धति (minimum reserve method) अपनाई गई है। फलस्वरूप रिजर्व बैंक किसी भी परिमाण में पत्र-मुद्रा चला सकता है।

(९) बढ़ती हुई कीमती के रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने माँग-ऋणों की व्याज-दर ३½% से ४% कर दी है तथा १६ मई १९५७ से बैंक दर भी ४% कर दी गई है।

इसमें स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक में प्रारम्भिक अवस्था में जो आशाएँ थी उनकी पूर्ति की ओर रिजर्व बैंक दृढ़ता से अग्रसर हो रहा है तथा उसकी क्रियाएँ देश-हित में हो रही हैं।

### सारांश

प्रथम विश्वयुद्धोत्तर काल में स्वर्णमान के पुनः स्थापन के लिए केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। अतः इस हेतु १९२० में

प्रेसीडेन्सी बैंकों के एकीकरण से इम्पीरियल बैंक का निर्माण किया गया। परन्तु यह केन्द्रीय बैंक की कमी को पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए १९२० में हिल्टन यंग कमिशन ने केन्द्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की।

रिजर्व बैंक की आवश्यकता के निम्न कारण थे—(१) रुपए के अन्तर्बाह्य मूल्य में स्थायित्व रखना, (२) भिन्न-भिन्न बैंकों के निधि का केन्द्रीकरण करना, (३) देश में मुद्रा एवं साखनीति का न्यायपूर्ण एवं समुचित प्रवन्ध (४) सरकार के बैंकर का कार्य, (५) कृषिसाख का प्रवन्ध (६) बैंकिंग प्रणाली का नियन्त्रण (७) मौद्रिक सम्पर्क एवं कार्य। इन उद्देश्यों के लिए १९२७ में रिजर्व बैंक विधेयक सदन में रखा गया परन्तु वह पास नहीं सका। १९३४ के राजनीतिक सुधारों के अन्तर्गत रिजर्व बैंक की स्थापना आवश्यक हो गई तदनुसार १९३४ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया स्वीकृत होकर १४-१९३५ को रिजर्व बैंक की स्थापना होगई।

रिजर्व बैंक की स्थापना के समय यह प्रश्न उठा कि यह भ्रष्टाचारियों का बैंक हो अथवा सरकारी बैंक। सरकारी बैंक के पक्ष में एवं विपक्ष में अनेक तर्क उपस्थित किये गये। अन्त में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी मुद्रा सम्बन्धी सस्था या बैंक राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप इसकी स्थापना भ्रष्टाचारियों के बैंक के रूप में हुई किन्तु १ जनवरी १९४६ को इसका राष्ट्रीयकरण हो गया।

रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण निम्न उद्देश्यों से किया गया—(१) युद्धोत्तर पुनर्निर्माण एवं आर्थिक योजनाओं की सफलता, (२) सतोयजनक मुद्रा नीति की व्यवस्था, (३) आर्थिक नीति एवं राजनीति में समानता, (४) सरकारी आर्थिक नीति का संचालन, (५) सरकार एवं केन्द्रीय बैंक की मौद्रिक नीति में समानता, (६) आर्थिक विषमता का निवारण, (७) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग (८) बैंकिंग कलेक्टर में विश्वास निर्माण करना, (९) मुद्रा मण्डी एवं बैंकिंग के समुचित समन्वय के लिए, (१०) बैंकिंग स्थिति के सही एवं समुचित ज्ञान के लिए।

विधान—रिजर्व बैंक की कुल पूंजी ५ करोड़ रुपए थी जो १०० रुपए के अंशों में विभाजित थी। राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप अब सम्पूर्ण पूंजी सरकार ने १९८॥=) प्रति अंश क दर से खरीद ली है। रिजर्व बैंक का प्रबंध १५ सदस्यों की केन्द्रीय सभा करती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। इनमें एक गवर्नर, तीन उपगवर्नर, चार स्थानीय सभाओं में से प्रत्येक का एक एक सचालक, छह सचालक तथा एक सरकारी अधिकारी। स्थानीय प्रबंध के हेतु

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा नई दिल्ली में स्थानीय सभाएँ हैं जो केन्द्रीय सभा के आदेशानुसार कार्य करती हैं तथा पूछे जाने पर आवश्यक मामलों में सलाह देती हैं। केन्द्रीय सभा की वर्ग में ६ सभाएँ हीनी चाहिए परन्तु तीन माह में एक सभा अवश्य होनी चाहिए।

आन्तरिक संगठन एवं व्यवस्था—बैंक का केन्द्रीय कार्यालय बम्बई में तथा स्थानीय शाखाएँ बंगलोर, बम्बई, कानपुर, नागपुर मद्रास तथा नई दिल्ली में हैं। अन्य स्थानों पर इसका प्रतिनिधित्व स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक ऑफ हैबराबाद तथा बैंक ऑफ मंसूर करते हैं।

रिजर्व बैंक की क्रियाएँ ८ विभागों में विभाजित हैं—(१) चलन विभाग, (२) बैंकिंग विभाग, (३) कृषि साख विभाग, (४) सार्वजनिक एवं खोज विभाग, (५) विनिमय नियन्त्रण विभाग, (६) बैंकिंग क्रियाएँ विभाग, (७) बैंकिंग विकास विभाग, (८) औद्योगिक वित्त विभाग। प्रत्येक विभाग अपने-अपने कार्य के लिए उत्तरदायी हैं।

रिजर्व बैंक दो प्रकार के कार्य करता है—(१) केन्द्रीय बैंकिंग कार्य, (२) सामान्य बैंकिंग कार्य।

केन्द्रीय बैंकिंग कार्य—पत्र-मुद्रा चलन बैंको का बैंकर, विनिमय दर को स्थिर रखना, सरकारी बैंकर का कार्य, समाशोधन गृहों का प्रबन्ध तथा अन्य केन्द्रीय बैंकिंग क्रियाएँ करता है।

सामान्य बैंकिंग कार्य—केन्द्र, राज्य, स्थानीय सरकार, बैंक तथा अन्य व्यक्तियों से बिना व्याज के निक्षेप स्वीकारना, व्यापारिक व्यवहारों के बिलों एवं प्रतिज्ञापत्रों का क्रय-विक्रय एवं कटौती, कृषि कार्यों तथा फसल भेजने के लिए लिखे गये बिल एवं प्रतिज्ञापत्रों का क्रय-विक्रय एवं कटौती करना, प्रति भूतियों का क्रय विक्रय, स्वर्ण, विदेशी विनिमय एवं स्वर्ण-मुद्राओं का क्रय-विक्रय, केन्द्र एवं राज्य सरकारों को ६० दिन अवधि के ऋण देना आदि। रिजर्व बैंक को अधिनियम के अन्तर्गत विशेषाधिकार होने के कारण इसकी क्रियाओं पर कुछ प्रतिबन्ध भी हैं।

रिजर्व बैंक द्वारा साख नियन्त्रण—रिजर्व बैंक के साख नियन्त्रण के निम्न साधन हैं—(१) बैंक दर, (२) खुले बाजार की क्रियाएँ, (३) वैधानिक रोकड़ निधि में परिवर्तन, (४) निर्वाचक एवं प्रत्यक्ष नियन्त्रण—जो रिजर्व बैंक बैंकिंग अधिनियम की धारा २१, २०, ३६ (I) (क) के अन्तर्गत करता है, (५) नैतिक प्रभाव।

रिजर्व बैंक का कृषि साख विभाग—कृषि के लिए आवश्यक आर्थिक

सुविधाएँ सहकारी एवं सूचीबद्ध बैंकों के माध्यम से देता है। ग्रामीण साख सर्वे समिति की सिफारिश के अनुसार रिजर्व बैंक ने १९५६ में दो कोषों का निर्माण किया गया है—(१) राष्ट्रीय कृषिसाख दीर्घकालीन कोष, (२) राष्ट्रीय कृषिसाख स्थिरीकरण कोष। ये दोनों कोष कृषि को दीर्घकालीन एवं मध्यकालीन आर्थिक सुविधाएँ देने के लिए बनाये गये हैं।

रिजर्व बैंक और सूचीबद्ध बैंक—सूचीबद्ध बैंक वे हैं जिनका समावेश रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार दूसरी अनुसूची में होता है। इस हेतु बैंक को निम्न शर्तें पूर्ण करनी होती हैं—(१) भारतीय राज्यों में व्यवसाय (२) चुकता पूँजी एवं निधि मिलाकर न्यूनतम ५ लाख रुपए हो, (३) रिजर्व बैंक को उनके सम्बन्ध में यह विश्वास हो कि उनका कार्य निक्षेपकों के हित में है। इन बैंकों को रिजर्व बैंक निम्न शर्तों की पूर्ति पर राशि स्थानान्तरण, ऋण आदि की सुविधाएँ देता है। रिजर्व बैंक के पास भाग एवं समय देनदारी के क्रमशः ५% व २% राशि जमा करना तथा धारा ४७ (क) के अंतर्गत साप्ताहिक विवरण भेजना।

सूचीबद्ध बैंकों के अलावा अन्य बैंक असूचीबद्ध बैंक कहलाते हैं। रिजर्व बैंक केवल ऐसे असूचीबद्ध बैंकों से सम्बन्ध रखता है जिनकी चुकता पूँजी एवं निधि ५०,००० रुपये से कम न हो, जो भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हो तथा बैंकिंग अधिनियम के अनुसार बैंकिंग व्यवसाय करते हो। ये बैंक रिजर्व बैंक के पास अपने लेखे खोल सकते हैं परन्तु उनके निक्षेप १०,००० रुपये से कम न होने चाहिए तथा ऐसे लेखे केवल परस्पर भुगतान का कार्य कर सकेंगे।

रिजर्व बैंक का भारतीय मुद्रा मण्डी पर प्रभाव अन्य उन्नत देशों की भाँति नहीं होता क्योंकि भारतीय मुद्रा मण्डी असंगठित है। अतः इस ओर उसे प्रयत्नशील होना चाहिए। दूसरे पक्ष के आरम्भ से भारत में विदेशी विनिमय के क्रय विक्रय पर नियन्त्रण लगाये गये तथा इन हेतु विदेशी विनिमय नियन्त्रण विभाग रिजर्व बैंक में खोला गया। ये नियन्त्रण ३१ मार्च १९४७ तक रहे तथा बाद में परिस्थिति के अनुसार उनमें हेर-फेर होते रहते हैं।

रिजर्व बैंक से आशाएँ थीं कि (१) वह बैंकिंगस्तर उन्नत करेगा। (२) मुद्रा मण्डी के विभिन्न अंगों का समन्वय करेगा। (३) देश के बैंकों में सहयोग निर्माण करेगा। (४) देश हित में साख नियन्त्रण कर मौतमी साख की दुर्लभता का निवारण करेगा। परन्तु इसमें रिजर्व बैंक को यादगिर सफलता नहीं मिली क्योंकि रिजर्व बैंक को निम्न आघातें थीं—(१) वैधानिक रोक्ड

निधि की मात्रा कम थी तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार उसे १९५६ तक न था । (२) स्वदेशी बैंक और महाजन्यों को नियन्त्रण में लाना तब तक सम्भव नहीं जब तक उनका अभाव सहकारी आन्दोलन दूर न कर सके । (३) स्वदेशी बैंकर अपनी पूँजों से व्यापार करते हैं तथा निक्षेपों पर कम निर्भर हैं । फिर भी रिजर्व बैंक व्याज दरों की अधिकता कम करने में सफल रहा । (४) मुद्रा मण्डी के दो प्रमुख अंगों पर स्वदेशी बैंकर, विदेशी विनिमय बैंकों पर रिजर्व बैंक का कोई नियन्त्रण न था और देश के अन्य बैंक रिजर्व बैंक पर कम निर्भर थे । (५) आंतरिक मूल्य स्थिरता रखने में असफल होने का प्रमुख कारण यह था कि विदेशी सरकार के प्रभाव में उसे मुद्रा प्रसार करना पड़ा । (६) देश में १९४६ तक बैंकिंग विधान का अभाव रहा ।

फिर भी रिजर्व बैंक ने बैंकों को सङ्कट के समय सहायता दी तथा एकीकरण आदि योजनाओं से बैंकिंग कलेक्टर को उन्नत किया । राष्ट्रीयकरण एवं बैंकिंग अधिनियम के पास होने से रिजर्व बैंक निश्चित एवं सुदृढ़ नीति से देश-हित में कार्य करने में सफलता की ओर बढ़ रहा है ।

## स्टेट बैंक और इम्पीरियल बैंक

### (१) इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपनी व्यापारिक सुविधाओं के लिए बंगाल बम्बई तथा मद्रास राज्या में क्रमशः १८०६ १८८० तथा १८८३ में बैंक आफ बंगाल, बैंक आफ बाम्बे तथा बैंक आफ मद्रास नाम से तीन बैंक स्थापित किये। इनकी स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि ये बिना किसी प्रकार की हानि के जनता को बैंकिंग सुविधाएँ दें तथा आवश्यकता के समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भी आर्थिक सहायता दें। सरकार को काम एवं सरकार की आर से उन देन करना भी इनका एकाधिकार था। इनकी पूँजी विदेशी थी तथा ३ भाग ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी दिया था, जिसके बदन उम सचालक-मभा में कुछ सचालक नियुक्त करने का अधिकार था। १८२३ में बैंक आफ बंगाल का पत्रमुद्रा चलन, १८३६ में ग्वाल्हाट्टे ग्वाल्हाट्टे एवं भारतीय विनिमय काम करने की आज्ञा दी गई। पत्रमुद्रा चलन का अधिकार १८२० में इन बैंकों में सरकार ने ल लिया। किन्तु विदेशी विनिमय व्यापार करना तथा ६ मास से अधिक काल के लिए ऋण देना निषिद्ध था।

१८६८ में, जब रई के सट्टे के कारण बैंक आफ बॉम्बे का बहुत हानि हुई, तो उसकी सहायता कर १ करोड़ रुपये की पूँजी में इसी नाम का दूसरा बैंक खोल दिया गया। इस स्थिति में सरकार ने इन बैंकों में अपने जा अग्र प के सब वच दिए जिसमें उसका सचालक चुनने का अधिकार जाता रहा। १८७६ में एक प्रेसीडेंसी बैंक एक्ट स्वीकृत हुआ, जिसके अनुसार प्रेसीडेंसी बैंकों के कार्य पर कुछ प्रतिबंध लगाये गये। इनकी कार्य शैली में अनेक दोष होने से इनके एकीकरण में अखिल भारतीय बैंक बनाने की माँग क्रमशः १८६० तथा १८७६ में रखी गई। इनके मुख्य दोष थे —

१ उन्होंने केवल उन्हीं स्थानों पर अपनी दायगाहें खोली जहाँ अधिक लाभ मिल सकता था।

२ य पूँजी की कमी की वजह से भारतीय व्यापारिक एवं आर्थिक आव-

क्षयिताओं की पूर्ति नहीं कर सकत थे। इस कारण देश में मुद्रा तथा साख की कमी रहती थी और व्याज-दर भिन्न-भिन्न रहती थी। इनको घन-मुद्रा चलन का अधिकार न होने में साख एवं मुद्रा का परस्पर सम्बन्ध भी नहीं था, जो आर्थिक विवास व लिए आवश्यक है।

३ भारतीय बैंकिंग विकास में इन्होंने कुछ भी मन्तोपप्रद कार्य नहीं किया। एकीकरण की इस माँग पर कोई विचार नहीं किया गया। फिर १८६८ में फाउलर समिति तथा १९१३ में चेम्बरलेन समिति ने केन्द्रीय बैंक की आवश्यकताओं को बताया। परन्तु उस समय भी इस दिशा में कुछ नहीं हुआ और न किया गया। परन्तु देश में १९१३-१७ के बैंकिंग मशट से बैंकिंग पद्धति के सुमचालन एवं मजबूती के लिए इसकी आवश्यकता सिद्ध हुई। फलस्वरूप १९२० में इम्पीरियल बैंक एक्ट स्वीकृत हुआ तथा इम्पीरियल बैंक ने २७ जनवरी १९२१ में कार्यारम्भ किया।

**स्थापना के उद्देश्य**

१ सरकार के बैंकर का कार्य करना एवं राशि-स्थानान्तरण सुविधाएँ देना,  
२ कुछ अणु में केन्द्रीय बैंक के कार्य करना अर्थात् बैंकों के बैंकर का कार्य करना, तथा

३ देश की बैंकिंग सुविधाओं में वृद्धि करना एवं देश के बैंकों की सुदृढता की देख-रेख करना।

**इम्पीरियल बैंक ही केन्द्रीय बैंक क्यों नहीं ?**

(१) इम्पीरियल बैंक व्यापारिक बैंकिंग कार्य करता था, तथा उस पर ५ वष में १०० शाल्वाएँ खोलकर बैंकिंग सुविधाएँ बढ़ाने का वैधानिक दायित्व था जिसे उसने पूरा किया। यही एक बात ऐसी थी जो इसे केन्द्रीय बैंक न बनाने के लिए पर्याप्त थी। केन्द्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों का सहयोगी होता है प्रतियोगी नहीं और इम्पीरियल बैंक अन्य बैंकों का प्रतियोगी ही बना रहा।

(२) यदि इसे केन्द्रीय बैंक बनाया जाता तो उसका व्यापारिक स्वरूप नष्ट होने की आवश्यकता थी। अर्थात् उसकी शाखाएँ बन्द करनी पड़ती जिससे देश के बैंकिंग विकास को ऐसे समय धक्का लगता जब देश में अधिकाधिक बैंकों की आवश्यकता थी।

(३) इसके लाभान का नियन्त्रण होना भी आवश्यक था, जो इसके अश-धारी व भी पसन्द नहीं करते।

(४) (अ) इसके केन्द्रीय बैंक के अभाव को दूर करने का उत्तरदायित्व नहीं

निभाया। अन्य व्यापारिक बैंकों का प्रतियोगी होने में यह बैंकों का बैंकर नहीं बन सका। इतना ही नहीं, अपितु अन्य बैंक ऋण की आवश्यकता के समय इम्पीरियल बैंक के दरवाजे गटखटाने में मानहानि समझते थे और जब कभी वे गये भी तो उन्होंने विलो की कटौती से राशि प्राप्त करने की अपेक्षा सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण लिया। (ब) केन्द्रीय बैंक को पत्र-मुद्रा-चलन का एकाधिकार होता है, वह भी इसे नहीं था। (स) इम्पीरियल बैंक की बैंक-दर भी प्रभावी नहीं थी और न देश के अधिकांश बैंक अपनी राशि ही इम्पीरियल बैंक के पास रखते थे। इससे न तो यह बैंकों का ही नियन्त्रण कर सकता था और न मुद्रा मण्डी का ही, जो केन्द्रीय बैंक का प्रमुख कार्य होता है। (द) इसको सरकारी राशि की व्यवस्था आदि की सुविधाएँ केवल भारत के लिए ही उपलब्ध थी तथा यह भारत सरकार की ओर से विदेशों में राशि-स्थानान्तरण नहीं कर सकता था, जो केन्द्रीय बैंक करने हैं। इस प्रकार यह केन्द्रीय बैंक के रूप में सफल न होने हुए केवल व्यापारिक बैंक के रूप में ही कार्य कर सकता था।

(५) इम्पीरियल बैंक अपनी अराष्ट्रीय नीति में भारतीयों की सहानुभूति प्राप्त न कर सका। इसकी नीति मदैव ऐसी ही रही जिसमें भारत एवं भारतियों की अपेक्षा इंग्लैण्ड एवं अंग्रेजा का ही हित हो। इसका संचालन भी प्रारम्भ में ही अंग्रेजा के हाथ में रहा तथा उन्होंने वही नीति अपनाई जो इसके आकाशा की—प्रीमिडेमी बैंकों की—थी। इसके अंग्रेज संचालक देश की आवश्यकताओं की भी न समझ सकते थे और न समझ कर काम ही करते थे, विशेषतः जब उनके देश की ऐसी कार्यों से हानि की सम्भावना थी। इतना ही नहीं, हिटलर-युग सभिति के सामने उस बात के प्रमाण भी दिए गये थे कि साम्य पनों के होते हुए भी इसने भारतीयों को ऋण नहीं दिया किन्तु इसरी और विदेशियों को ऋण दिया।

### इम्पीरियल बैंक का संगठन

१९३४ में, जिस समय रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना का विधेयन स्वीकृत हुआ, उसी समय इम्पीरियल बैंक अधिनियम में भी मनाघन किया गया। इसने उसके व्यापारिक बैंकिंग सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाकर उसे पूर्णतः व्यापारिक बैंक बना दिया गया।

पूँजी—इसकी अधिकृत पूँजी १,१२५ लाख रुपए थी जो ५०० रु० के २२५,००० अंशों में विभाजित थी। अधिकृत पूँजी की ५०% चुकता पूँजी तथा शेष मचित देय थी। इसकी मचित निधि की राशि ६३५ लाख रु० थी।

सन् १९२० में १९३१ तक १६%, १९३१ में १४%, १९३२ में १२.५० तक १०% तथा १९५१ में १६% लाभान्न वितरण किया।

**प्रबन्ध**—बैंक का प्रबन्ध-मचालन तथा उप-प्रबन्ध सचालन द्वारा होता था। इसका निर्वाचन केन्द्रीय मचालकों द्वारा ५ वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए होता था। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सभा के निम्न सदस्य होते थे —

(अ) प्रत्येक स्थानीय सभा (बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता) का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यवाह—६,

(ब) प्रत्येक स्थानीय सभा के सदस्या में निर्वाचन एक-एक सदस्य—३,

(ग) सरकार द्वारा मनोनीत गैर-सरकारी व्यक्ति (non-officials)—२।

यदि नया स्थानीय कार्यालय खोला जाय तो उस दशा में उस सभा के प्रतिनिधित्व के लिए केन्द्रीय सभा में स्थान दिया जायगा, जिनकी संख्या का निर्णय केन्द्रीय सभा द्वारा होगा।

इस प्रकार केन्द्रीय सभा के १६ सदस्य थे। इनके अतिरिक्त सरकार एक और अधिकारी मनोनीत कर सकती थी जो केन्द्रीय सभा की सभाओं में भाग लेता था किन्तु उसे मतदान का अधिकार नहीं होता था। केन्द्रीय सभा बैंक की नीति निर्दिष्ट करने का काम, जैसे व्याज की दर आदि, तथा साप्ताहिक बिकरण की देख-रेख करती थी। केन्द्रीय सभा की सभाएँ त्रैमास्य बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में तीन मास में एक बार होना अनिवार्य था। केन्द्रीय सभा की सभाएँ बार-बार न होने के कारण प्रबन्ध सभा इसका प्रबन्ध करती थी जिसके दो सदस्य होते थे। इस प्रकार केन्द्रीय मचालक-सभा इम्पीरियल बैंक का प्रबन्ध करती थी। केन्द्रीय सभा की बैठकों में स्थानीय सभाओं के मंत्री, उप-प्रबन्ध मचालक तथा सरकारी अधिकारी भाग ले सकते थे, परन्तु इनको मतदान का अधिकार नहीं था।

इसकी स्थानीय सभाएँ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में थी जिनके सदस्य उस कार्यालय क्षेत्र के अजघातियों द्वारा चुने जाते थे। स्थानीय कार्यालयों का प्रबन्ध स्थानीय अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा होता था। स्थानीय सभा के ७ सदस्य होते थे एवं ये सभाएँ स्थानीय कार्यों की देख रेख करती थी।

**कार्य-क्षेत्र**—१९३५ के संशोधन से इम्पीरियल बैंक का कार्य-क्षेत्र भी विस्तृत हो गया तथा उसे व्यापारिक बैंकिंग करने की पूर्ण स्वतन्त्रता मिली। परन्तु फिर भी रिजर्व बैंक का एकमात्र अभिकर्ता होने के कारण उसके कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध थे।

## इम्पीरियल बैंक के कार्य

१. वही भी अपनी मांगों को खानना अथवा अपन अभिरक्षा रखना ।

२. किसी भी क्षेत्र में स्थानीय प्रमुख कार्यालय खान सकता है अथवा नई स्थानीय-मन्त्रालय बना सकता है । अब उसे सरकार का किसी प्रकार की आवधिक सूचनाएँ बन की आवश्यकता नहीं रही ।

रेजर्व प्रतिलभितया स्थानीय सरकारों के ऋण पत्र तथा अन्य प्रतिभूतिया नीमिन कम्पनियों के ऋण-पत्रा पूरा दत्त अथवा स्वीकृत विधियों पर तथा प्रतिष्ठा पत्रों पर इम्पीरियल बैंक ऋण दे सकता है तथा ऋण पत्र एवं प्रतिभूतिया का बच सकता है । वस्तु अधिकार प्रणाली तथा भारत सरकार का स्वीकृत प्राप्त ऋण-पत्रों की जमानत पर ऋण दे सकता था । तब ऋण व्यापारिक कार्यों के लिए खर्च ६ मास तथा वृद्धि कार्यों के लिए ६ मास की अवधि तक ही दे सकता है ।

४. यह देश के बाहर भी जनता में निष्पक्ष एवं ऋणा का जन-सेवा कर सकता है । इसी प्रकार आपसी सम्पत्ति पर ऋण देने की तथा अन्य प्रविष्टि कार्य करने की भी उस पूरा स्वतंत्रता दी गई है ।

५. निमित्त विना का निम्न स्वीकार करना कर्तव्य एवं अन्य विषय विदेशी विना का अन्य विषय स्वयं एवं चाही का अन्य विषय यह कर सकता है । यह क्रियाएँ यह देश में एवं विदेशों में भी कर सकता है ।

गुरुत्वा निष्पक्ष स्वाकार कर सकता है ।

७. रिजर्व बैंक के अन्तर्गत जमानत पर रोक ऋण तथा अन्य ऋण पत्रा तथा अधिनियम में मान अन्य कार्य कर सकता है । इसी प्रकार उपपाधीयित (hypothecated) वस्तुओं की जमानत पर ऋण दे सकता है ।

८. जन्म स्थित कार्यालय भी सब प्रकार के वैध व्यवहार कर सकता है । जन्म के अनिर्दिष्ट अन्य देशों में भी यह मांगों को खान सकता है ।

९. वृद्धि मास का मौज्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृद्धि पत्रों का जमानत पर ६ महीने की अवधि के ऋण दे सकता है ।

गिजर्व बैंक एवं इम्पीरियल बैंक

१९३४ के संशोधित अधिनियम के अनुसार यह रिजर्व बैंक के एकमात्र अधिकार का कार्य करता है । इसी के मास यह अपने अन्य व्यापारिक कार्य भी करता है । इम्पीरियल बैंक में रिजर्व बैंक अधिनियम की ४५ की धारा के अनुसार समझौता हुआ गया जिसकी अवधि १० वर्ष की थी । समझौते का

गतें रिजर्व बैंक अधिनियम की तीसरी अनुसूची में दी हुई हैं। इस समझौते का नवकरण, अवधि की पूर्ति पर होता है।

इस समझौते से जहाँ रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं हैं किन्तु इम्पीरियल बैंक की शाखाएँ हैं वहाँ इम्पीरियल बैंक सरकारी शेषों को रखेगा सरकार की ओर से लेन देन करेगा राशि-स्थानान्तरण कार्य तथा केन्द्रीय बैंक के अन्य कार्य करेगा। इसके बदले इम्पीरियल बैंक को बमीशन मिलेगा।

इस समझौते में इम्पीरियल बैंक रिजर्व बैंक का अभिवर्ता होने के कारण सरकारी लेन दे की व्यवस्था, लेन-देन, राशि-स्थानान्तरण आदि कार्य करता था। इसलिए उसके कार्यों पर निम्न प्रतिबन्ध थे —

१ यह अपने अग्रे पर ऋण नहीं दे सकता।

२ कृषि तथा अन्य कार्यों के लिए क्रमशः ६ तथा ६ मास की अवधि से अधिक ऋण नहीं दे सकता।

३ कोर्ट ऑफ वांड्स तथा उसकी व्यवस्था में जो रियासत है उनको यह बिना स्थानीय सरकार की स्वीकृति के तथा उनकी अच्छल सम्पत्ति की जमानत पर अथवा उनके द्वारा स्वीकृत निर्गमित बिलेखों की जमानत पर ऋण नहीं दे सकता।

**इम्पीरियल बैंक की क्रियाएँ**

इम्पीरियल बैंक १९३५ तक एक व्यापारिक तथा सरकारी बैंक था, जो व्यापारिक कार्यों के साथ साथ सरकारी शेषों का स्थानान्तरण, संचालन, लेन देन आदि करता था। इसके प्रारम्भ में जनता एवं सरकार को इससे बड़ी-बड़ी आशाएँ थी तथा यह भी सोचा गया था कि आगे यह केन्द्रीय बैंक हो जायगा। परन्तु उसकी कार्य शैली में ये आशाएँ पूरी न हो सकी एवं पृथक् केन्द्रीय बैंक की स्थापना करनी पड़ी।

इस बैंक से आशाएँ थी कि (१) यह अनेक नई-नई शाखाएँ खोलकर देश में बैंकिंग का प्रसार करेगा तथा भारतीयों को बैंकिंग की शिक्षा मिलेगी।

(२) सरकारी राशि प्राप्त होने के कारण मुद्रा मण्डी में मुद्रा एवं मास की मौसमी कमी दूर हो जायगी तथा मास एवं मुद्रा का समुचित नियन्त्रण होकर व्याज दर कम होगी जिससे देश की कृषि एवं उद्योग एवं अर्थ व्यवस्था की उन्नति होगी।

(३) इम्पीरियल बैंक देश के अन्य बैंकों का मार्ग दर्शन करेगा एवं सब काल में सहायक होगा तथा सरकार को एवं उन्हें भी राशि स्थानान्तरण की सुविधाएँ मिलेंगी। सरकार, ग्राहकों एवं बैंक की इस प्रकार की कुछ आशाएँ

की पूर्ति इनकी तब तक कुछ की पूर्ति वह नहीं कर सका। इतना ही नहीं अपितु इसकी काय जैसी यूरोपीय व्यवस्था में हान में भारतीया की दृष्टि से सदाप रही।

इम्पीरियल बैंक न पहनी जाया कुछ अंग में पूरी की तथा उसमें अधिक नियमों के अनुसार प्रथम पांच वर्ष में १०० लाखों पौन्डों तथा दस में ब्रकिंग सुविधाएँ बनाने की जाए प्रयत्नशील रहा। प्रा० पाणदीकर के अनुसार<sup>१</sup> इम्पीरियल बैंक की ८ वर्षों में ही १५० में अधिक शाखाएँ हो गईं जा विनिमय बैंकों की समस्त शाखाओं के तुल्य में भी अधिक थी। इस बैंक की शाखाएँ १८४५ में ४.३ थी। परन्तु जहाँ तक भारतीया की बैंकिंग शिक्षा का सम्बन्ध है इम्पीरियल बैंक के कमचारा यूरोपीय रहे जिसमें इम्पीरियल बैंक द्वारा भारतीया का बैंकिंग शिक्षा मिलान में सावधानी निराशा हुई। हा हम यह कह सकते हैं कि इम्पीरियल बैंक का कमचारिया की आवश्यकता हान के कारण कुछ अंग में हमारी बँकरो का निवारण हुआ।

जहाँ तक ग्राहकों का सम्बन्ध है यह कहा जा सकता है कि इम्पीरियल बैंक में ग्राहकों को ऋण सुविधाएँ प्राप्त हुई तथा कुछ अंश में मौसमी मुद्रा तथा साख की आवश्यकता की पूर्ति हुई। इस प्रकार विदेशी विनियामकों ने इस बैंक से पूर्ण लाभ उठाया। विनिमय बैंकों की भी हमने जो खालकर सहायता की। इसी प्रकार अंग्रेज व्यापारियों की जायिक स्थिति का ज्ञान भी यह अपने ग्राहकों को देता रहा क्योंकि इसकी शाखा लन्दन में हान के कारण इसका लन्दन मुद्रा मण्डी में प्रत्यक्ष सम्बन्ध था किन्तु इसके सब कार्य सामित ही रहे। यह पूर्ण रूप से न तो मादिक आवश्यकताओं की पूर्ति हा कर सका और न हमने अपना पक्षपातपूर्ण नीति के कारण भारतीया का हा ऋण का पूर्ण सुविधाएँ दी जिनकी वह अपने यूरोपीय ग्राहकों तथा फर्मों को देता था। इस कारण हमकी तीव्र आलोचना भी हुई।

मुद्रा मण्डी के विभिन्न अंगों का संगठन करने में यह सफल न रहा और न हमने भारतीय बैंकों को ही अपने नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया। इसी प्रकार व्याज दर में भी न समानता रही और न क्या हुई। हा मौसमी आवश्यकताओं के समय व्याज की दर का अधिक ऊँची हो जाती थी उने हमने ऊँचा न हान दिया।

बैंक के माघ दान एवं सहायता सम्बन्धी आशा का कुछ दृढ़ तक इसमें

<sup>१</sup> *Banking in India*, pp 273-75

पूण किया। क्योंकि जब अलायस बैंक जिमला, टाटा इण्डस्ट्रियल बैंक और बंगाल नेशनल बैंक पर सबोट आया तब इसने उस दूर करन का भरसक प्रयत्न किया। परन्तु परिस्थिति की भीषणता से इनको विलियन में न बचाया जा सका। इसी प्रकार १९२६ में कमकत्ता एवं बम्बई स्थित मेट्रल बैंक आप इण्डिया के कार्यालय भी सबोट में थे तब उस दूर करन में इम्पीरियल बैंक सफल रहा। इसने बैंक का राशि स्थानान्तरण की सुविधाएँ दी। इसके लिए १० ००० एवं इससे अधिक रुपया के स्थानान्तरण के लिए जहाँ उन बैंक की शाखाएँ नहीं थी अधिकांश शुल्क ३½ प्रतिशत था। किन्तु बैंक की अपनी एक शाखा से दूसरी शाखा के लिए राशि स्थानान्तरण शुल्क इसका आधा अर्थात् ३¼ प्रतिशत अथवा ३ आना प्रति सैंकड़ा था। वन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति तथा ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति के अनुसार यह शुल्क अधिक है।

इस प्रकार इम्पीरियल बैंक ने अधिकतर जाशाएँ पूण की। फलतः रिजर्व बैंक के होत हुए भी इसका स्थान देश में अत्यन्त महत्वपूर्ण रहा। यह सहकारी बैंक को भी अत्यन्त उदारतापूर्वक ऋण आदि देकर सहायता करता था तथा आवश्यकता के समय उनके निक्षेपों से अधिक राशि निकालने देता था जिससे इन दोनों का सम्बन्ध भी अच्छा ही रहा। इसी प्रकार सरकार को कोषा के व्यय से भी इसने बचाया न्यायिक जिन स्थानों पर इम्पीरियल बैंक की शाखाएँ थी वहाँ सरकारी कोषों का कार्य यही करता था। इसलिए जहाँ इम्पीरियल बैंक की शाखाएँ थी वहाँ के सरकारी खजाने बन्द कर दिए गए। इसने अपनी वायधम कार्य शैली के कारण जनता का विश्वास सम्पादन किया जिससे इसके निक्षेप मयमे अधिक थे। रिजर्व बैंक के अधिकार का एकाधिकार होने के कारण उसको यही विश्वास प्राप्त रहा। इसकी शाखाएँ देश के किसी भी बैंक से अधिक थीं जिनकी सरया १९४५ तथा १९४७ के बीच ४३३ से बढ़कर ४४४ हो गई। यह साप्ताहिक विवरण प्रकाशित करता था जिसमें इसकी मात्र बढ़ती थी।

### इम्पीरियल बैंक के विरुद्ध आक्षेप

१ देश के व्यापारिक बैंकों का प्रतियोगी—केवल एक ही व्यापारिक बैंक को, जिसकी आर्थिक स्थिति अन्य बैंकों की अपेक्षा सुदृढ़ है—रिजर्व बैंक के अधिकार होने के कारण सरकारी काप एवं राशि सम्बन्धी लेन देन का एकाधिकार है। यह न तो देश के हित में ही है और न देश के अन्य बैंकों और जनता के ही हित में है। इन सुविधाओं के कारण वह देश के अन्य व्यापारिक बैंकों का प्रतियोगी हो गया है जिससे वे अपनी उन्नति नहीं कर सके। हा, इस

प्रतियागिता में जनता को कुछ अना में लाभ अवश्य हुआ है। तबकि उन्हें सम्यो व्याज-दरा पर ऋण मिल जाता है।

२ यूरोपीय प्रबन्ध—इम्पीरियल बैंक की पूजी विदगी थी तथा इनका प्रबन्ध भी यूरोपीय मंचानका क हाथ में था। इसमें उनकी व्यवस्था में तो भारतीयों का हाथ ही है और न यह भारतीयों का वैकिंग व्यवसाय की शिक्षा ही दे रहा है। थोड़े गन कुछ वर्षों में विदेशी पूजा हमारा कम हाकर भारतीयों का हाथ में आ रही है। फिर भी विदेशियों का इसकी व्यवस्था में अधिक प्रभाव रहा। समताप यही है कि केंद्रीय मन्त्रालयों की सरकार की ओर में निवाचन आरम्भ कर दिया गया है।

३ पक्षपात पूर्णनीति—यूरोपीय प्रबन्ध हान के कारण इसमें यूरोपीय अधिकारी दत्त की आवश्यकताओं का नहीं समझ सका तथा इनकी नीति पक्षपाती रही है। इसमें भारतीय धन से भारतीय औद्योगिक उन्नति की अपेक्षा यह विदेशियों का ऋण देकर विदेशी व्यवसायों की उन्नति करता है। इसी प्रकार भारतीय अधिकारी भी नियुक्ति नहीं करता।

४ मुद्रा-मण्डी की उन्नति न कर सका—यह मुद्रा मण्डी की भी उन्नतनीय उन्नति नहीं कर सका क्योंकि जिला के उपभाग एवं कटौती का प्राप्ति हान दत्त की अपेक्षा यह रोकता रहा ही अधिक दत्त है।

५ अधिक प्रबन्ध व्यय—यूरोपीय प्रबन्ध हान के कारण इसका प्रबन्ध व्यय बहुत अधिक है तथा इसका अनेक शाखाएं अन्य स्थानों पर हैं जो असाधारण हैं।

६ मौकरशाही का बोलबाला—इम्पीरियल बैंक एक्ट की द्वितीय अनुसूची में नियम ४१ के अनुसार बैंक के व्यवस्थापक अनिवारियों की ओर से मत दे सकते हैं। यह अधिकार इसमें व्यवस्थापकों के लिए महत्वपूर्ण है एवं संचालकों का निवाचन कुछ विषय व्यक्तियों के हाथ में रहता है जिसमें व्यवस्था सम्बन्धी वित्तिक कद्राकरण होता है। इसी हान में मौकरशाही पद्धति का अवलम्ब ही करना है जो दत्त एवं जनता के हित की दृष्टि से अप्राप्तनीय है।

७ व्यापार का केन्द्रीकरण—इम्पीरियल बैंक ने व्यापार का अधिक केन्द्राकरण कर लिया है तथा अविवक्षित क्षेत्रों में वित्तिय सुविधाएं दत्त के लिए इच्छुक नहीं हैं जो सुविधाएं भारत में विमान दत्त के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं।

८ पत्र मुद्राओं के वर्गीकरण में असुविधाएं—इसकी व्यवस्था के विरुद्ध बरा का यह भी आरोप है कि इम्पीरियल बैंक के मुफ्तसित क्षेत्र के वायानमा

एव सरकारी खजानों में कम मूल्यों की पत्र-मुद्राएँ स्थानान्तरण अथवा अन्य कार्यों के लिए स्वतन्त्रता से नहीं ली जाती। इतना ही नहीं अपितु कहीं-कहीं तो ऐसी पत्र-मुद्राएँ सप्ताह में केवल कुछ निश्चित दिनों में ही ली जाती हैं। इससे व्यापारिक बैंकों को राशि-स्थानान्तरण, पत्र-मुद्राओं के वर्गीकरण आदि में अधिक सुविधाएँ होती हैं।

### इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण

गत वर्षों से, विशेषतः भारतीय स्वतन्त्रता के साथ, उपर्युक्त दोषों के निवारणार्थ इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उपस्थित हुआ। इस प्रश्न का रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण करने समय १९४८ में पुनः उपस्थित किया गया था। तत्कालीन अर्थ मन्त्री श्री जान मथाई ने कहा था कि “तान्त्रिक समस्याओं के परीक्षण की दृष्टि से एव विनियोग-बाजार तथा तत्कालीन अव्यवस्थित आर्थिक परिस्थिति पर राष्ट्रीयकरण के जा दुष्परिणाम होंगे उनको देखते हुए वर्तमान परिस्थिति में सरकार इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण करना कुछ ठीक नहीं समझती।” नवम्बर १९५० में बैंकिंग कम्पनीज सशोधन विधेयक (१९५०) की बहस में पुनः राष्ट्रीयकरण का प्रश्न दुहराया गया। उस समय अर्थ मन्त्री श्री चिन्तामणि देशमुख ने कहा कि “इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रयत्न देश के आर्थिक हितों में न होगा।” उन्होंने यह भी कहा कि “इम्पीरियल बैंक की बहुत-सी अश-पूँजी भारतीयों के अधिकार में है तथा उसके कर्मचारियों का राष्ट्रीयकरण हो रहा है तथा कुछ वर्षों में ही इम्पीरियल बैंक हमारे नियन्त्रण में आ रहा है। अतः हमारे निजी हितों की दृष्टि से ऐसा कोई भी कार्य जो शीघ्रतापूर्वक किया जायगा, अहितकर होगा तथा उससे हम माध्यम के उपयोग को भी हानि होगी। “हमारे बैंकिंग कलेवर में इम्पीरियल बैंक एक आवश्यक अङ्ग है तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए जिसमें उसकी उपयोगिता में हानि हो, विशेषकर उस परिस्थिति में जब हम नये बैंकिंग विधान द्वारा अपने बैंकिंग कलेवर का संगठन समुचित भित्ति पर कर रहे हैं।”

### स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

इम्पीरियल बैंक के मुद्धार के हेतु ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति (१९४९) ने अपनी रिपोर्ट (१९५०) में सुझाव दिये थे जिनमें निम्न प्रमुख थे —

(१) इम्पीरियल बैंक को विशेषाधिकार होने के कारण यह व्यापारिक

बैंको का स्पर्धा करता है। अतः उस पर सरकार का कठोर नियन्त्रण हो परन्तु वह दैनिक क्रियाओं में हस्तक्षेप न करे।

(२) इम्पेरियल बैंक एक्ट की धारा २ नियम ५१ के अनुसार मन्त्रालय को अग्राधिकार की शक्ति में मतदान का अधिकार है। उस निरस्त किया जाय तथा बैंकिंग एक्ट की धारा १० को लागू किया जाय। इसमें प्रत्येक अग्राधिकारी कुल मतों का ५०% से अधिक मत न दे सकगा।

(३) बैंक के उच्च पदाधिकारी भारतीयकरण हों।

(४) बैंक रजिस्ट्रार-समानांतरण गुणों को वर्तमान गुणों से आधा करे।

(५) बैंक अपने कार्यालयों का संख्या में वृद्धि करे।

उक्त विधायिका के अनुसार १ सितम्बर १९४७ में स्थानान्तरण गुणों आधा किया गया तथा सुविधाएँ भी बढ़ाई गईं। साथ ही इम्पारियल बैंक ने ३० जून १९४७ तक नव-नवकाशीन काप भूगतान कार्यालयों (Treasurer's offices) का ग्राह्यता में परिवर्तन करना तथा ० नई शाखाएँ खोलना मान्य किया था। इसमें २० जून १९४७ तक उसने १० नई शाखाएँ खोली तथा २२ काप भूगतान कार्यालयों का ग्राह्यता में बदला। १ जुलाई १९४१ से ५ वर्ष में इम्पेरियल बैंक को ११४ कार्यालय खोलने थे जिसमें जून १९४५ तक उसने केवल ६ कार्यालय खोले। यह कार्य सन्तुष्टिपूर्ण नहीं था।

ग्रामीण बैंकिंग विकास समिति का विधायिका के अनुसार ग्रामीण बैंकिंग सुविधाओं की जांच करने एवं उनके विकास हेतु विधायिका करने के लिए १९४१ में रिजर्व बैंक ने ग्रामीण मान्य संवत् समिति नियुक्ति का। इसकी रिपोर्ट १९४४ में प्रकाशित हुई। इसमें उन्होंने कहा कि देश के व्यापारिक बैंक कृषि-माल में बहुत कम रुचि लेते हैं तथा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राह्यता का विस्तार भी नहीं किया। अतः समिति ने विधायिका की कि सरकार मान्य में व्यापारिक बैंकिंग संस्था के रूप में गतिशीली स्टेट बैंक का स्थापना की जाय ता देश भर में बैंकिंग विकास को बढ़ाने देश के महत्वाकांक्षी एवं अर्थ विकास का विस्तृत रजिस्ट्रार-समानांतरण सुविधाएँ देने के लिए अपनी ग्राह्यता खोल तथा मुद्रा बैंकिंग मिश्रता एवं राष्ट्रीय नाति के अनुसार अपनी प्रभावना नानि रखे।

इस विधायिका के अनुसार २० दिसम्बर १९४४ को इम्पारियल बैंक पर उचित एवं प्रभावी सरकारी नियन्त्रण होगा यह घोषणा अर्थ मन्त्री ने की। तन्नुसार १ अप्रैल १९४५ को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विधायक गतिशीलता में

रखा गया जो दाना ही सदना में पाया हो गया तथा ८ मई १९५५ को राष्ट्रपति ने इस पर स्वीकृति की मुहर लगाई।

### स्टेट बैंक का संगठन

इस अधिनियम के अनुसार १ जुलाई १९५५ में इम्पीरियल बैंक के भारत स्थित कार्यालय, एजेंसियाँ तथा शाखाएँ स्टेट बैंक का हस्तान्तरित हो गई हैं। इनमें से कोई भी रिजर्व बैंक की स्वीकृति बिना बन्द नहीं की जा सकती। इन समय स्टेट बैंक का केन्द्रीय कार्यालय बम्बई, तथा स्थानीय कार्यालय बम्बई, बलरत्ता तथा मद्रास में हैं। आवश्यकता के समय केन्द्रीय सरकार बैंक की केन्द्रीय सभा की सलाह से स्थानीय कार्यालयों का खोल सकती है।

१ जुलाई १९५५ में आरम्भ होने वाले आगामी ५ वर्षों में ४०० नई शाखाएँ खोलने की जिम्मेदारी स्टेट बैंक पर है। केन्द्रीय सरकार आवश्यक समयों पर इस अवधि को बढ़ा सकती है। ये शाखाएँ ऐसे स्थानों पर खोली जायगी जो केन्द्रीय सरकार रिजर्व बैंक एवं स्टेट बैंक मिलकर निर्दिष्ट करे। परन्तु ऐसी नई आरम्भ की हुई शाखा रिजर्व बैंक की पूर्व-अनुमति बिना बन्द नहीं होगी।

पूंजी—इसकी अधिकृत पूंजी २० करोड़ रु० है जो १०० रु० के २० लाख अंशों में विभाजित है। इसकी निर्गमित एवं चुकता पूंजी ५६२ ५० लाख रु० ५,६२,५०० पूरा दल अंशों में है। चुकता पूंजी के ४५% अंश निजी अंशधारियों का दिया जा सकता है और शेष ५५% सदैव रिजर्व बैंक के पास रहेंगे। अधिकृत पूंजी बढ़ाने या कम करने का अधिकार भारत सरकार को है। परन्तु स्टेट बैंक का केन्द्रीय बोर्ड अपनी निर्गमित पूंजी १० ५० करोड़ रु० तक बढ़ा सकता है यदि इससे अधिक बढ़ाना हो तो केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य है। किसी भी दशा में रिजर्व बैंक को स्टेट बैंक की निर्गमित पूंजी का ५५% भाग रखना अनिवार्य है।

अंशधारियों के अधिकार—रिजर्व बैंक के ५५% अंशों के सिवा शेष ४५% अंशों के हस्तान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु कोई भी व्यक्ति अपने नाम या सम्मिलित नाम से २०० से अधिक अंश नहीं ले सकता। यह नियम निम्न संस्थाओं पर लागू नहीं है—

- (अ) रिजर्व बैंक।
- (आ) कॉरपोरेशन।
- (इ) बीमा संस्थाएँ।
- (ई) स्थानीय अधिकारी।
- (उ) सहकारी संस्थाएँ।

(क) निजी या सावजनिक सम्पत्ति अथवा धार्मिक सम्पत्ति व प्रणामी ।

उक्त मन्थान, रिजर्व बैंक को छाड़कर, निर्गमित पूंजी के १०% से अधिक अंश पर मत नहीं द सकती । स्टेट बैंक व अंश का सम्भाव्य मान्य प्रतिभूतियां म होता है ।

क्षति पूर्ति—इम्पीरियल बैंक के पुराने असाधारिया का प्रत्यक्ष पूणदत्त अंश के लिए १३-१-४० तथा आंशिक चुस्तता अंश के लिए ४३१-३-४० क्षति पूर्ति के मिला । यह क्षति पूर्ति उन्हें सरकारों प्रतिभूतियां म अवयवा असाधारी चाह तो स्टेट बैंक के अंश म दी जायगी । जिन असाधारिया के नाम १६ दिमम्बर १९५४ का इम्पीरियल बैंक के अंग रजिस्टर म थे उन्हें आवदन दन पर १०,००० रु० तक क्षति पूर्ति का राशि नगद मिलगी ।

प्रबन्ध—स्टेट बैंक का प्रबन्ध कन्द्रीय मभा करती है जिसम ५० सदस्य है —

(१) सभापति एवं उप सभापति—इनकी नियुक्ति रिजर्व बैंक के परामर्श से कन्द्रीय सरकार करती है ।

(२) अधिकतम दो प्रबन्ध सचालक—इनकी नियुक्ति बैंक की कन्द्रीय मभा कन्द्रीय सरकार की अनुमति से करती है ।

(३) ६ सचालक—रिजर्व बैंक का सचालक अन्य असाधारिया द्वारा निर्वाचित २० जून १९५३ के बाद य क्रमश दादा के हिमाद से प्रति वर्ष निवृत्त हंग ।

(४) ८ सचालक—रिजर्व बैंक की सलाह से कन्द्रीय सरकार द्वारा मनानीन हंग । य प्रादेशिक एवं आर्थिक हिला का प्रतिनिधित्व करंग । इनम से ३० जून १९५३ के बाद प्रति वर्ष दा-दो सचालक क्रमश निवृत्त हंग ।

(५) १ सचालक—कन्द्रीय सरकार नियुक्त करगा । इसके लिए समय की मत्त नहीं है ।

(६) १ सचालक—रिजर्व बैंक मनोनीन करेगा । यह किसी भी अवधि तक रह सकती है ।

प्रारम्भिक अवस्था म बैंक का आलाभा पर असाधारिया की सूची न हान से उनक सचालका की नियुक्ति कन्द्रीय सरकार न की थी । अतः सभापति उप-सभापति तथा प्रबन्ध-सचालका को छोड़कर अन्य सचालक २० जून १९५३ को निवृत्त हंगे । सभापति, उप सभापति तथा प्रबन्ध-सचालका की नियुक्ति ५ वर्ष के लिए है जिसके बाद उनकी नियुक्ति पुन हा सकती है ।

स्थानीय सभाएँ—स्टेट बैंक के स्थानीय कार्यालयों का कार्य स्थानीय सभाएँ करेगी, जिनमें—

(अ) केन्द्रीय सभा व के सचालक जो अशधारियों द्वारा निर्वाचित तथा उक्त ४ के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने मनोनीत किये हों। परन्तु इनमें वे ही सचालक हाग जो उम धेन के निवासी हों।

(आ) प्रत्येक स्थानीय कार्यालय की अशधारियों की सूची के सदस्यों द्वारा चुने गए अधिकतम ४ सदस्य।

सामान्य व्यवसायिक मुविधा के लिए केन्द्रीय सभा स्थानीय समितिया बना सकती है जिसकी सदस्य-संख्या का निर्णय केन्द्रीय सभा करेगी।

स्थानीय सभा एवं समितियाँ वही कार्य करेंगी जो केन्द्रीय सभा निर्धारित करे।

बैंक के कार्यों को करते समय केन्द्रीय सभा व्यवसायिक सिद्धान्तों का पालन करते हुए अनहित की ओर ध्यान देगी।

स्टेट बैंक के कार्य

(अ) रिजर्व बैंक का एजेंट—स्टेट बैंक उन सब स्थानों में, जहाँ इसकी शाखाएँ हैं किन्तु रिजर्व बैंक के बैंकिंग-विभाग की शाखाएँ नहीं हैं, रिजर्व बैंक के एजेंट का काम करता है। एजेंट की हैसियत से यह बैंक सरकार (केन्द्र, राज्य तथा स्थानीय) की राशि जमा करता है, उसके लेखे पर राशि का भुगतान, संप्रहण तथा स्थानान्तरण करता है और सरकार के लेखे पर धातु (सोना, चादी) व सिस्चूरिटिया का लेन देन करता है। इसके अतिरिक्त यह वे सब काम कर सकता है, जो रिजर्व बैंक समय समय पर उसे सौंपे। इस काम के लिए रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक में समझौता होना आवश्यक है, जिसमें एजेंसी की शर्तों का उल्लेख हो और स्टेट बैंक को मिलने वाली राशि निर्धारित की गई हो। किसी समय समझौता सम्बन्धी किसी विषय पर रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक में विवाद व झगडा होने पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अन्तिम निर्णय होगा।

(ब) अन्य क्रियाएँ—(१) ऋण व अग्रिम देना तथा रोक्ड-साख (cash credit) के आधार पर राशि स्वीकृत करना। इस प्रकार के ऋण व अग्रिम निम्न जमानता पर दे सकता है—

(अ) उन स्वन्ध (stock), कोष (fund) तथा प्रतिभूतिया की जमानत पर, जिनमें प्रन्यासी (trustee) भारतीय अधिनियम व अन्य किसी वैदेशिक नियम के अनुसार, जहाँ स्टेट बैंक की शाखा हो, प्रन्यास की राशि विनियोग कर सकता हो,

(द) देण तथा अय किसी ऐसे देण में जहाँ बैंक की गाथा हो नगरपालिका, मिस्त्रिट बाड तथा अय किसी स्थानीय अधिकारी द्वारा निगमित ऋण-पत्रा एव अय ऐसी ही प्रतिभूतिया की जमानत पर

(म) भारत में रजिस्टर्ड तथा बैंक के केंद्रीय बाड द्वारा माय किसी भीमिन स्क्वैड कम्पनी व ऋण पत्रा तथा केंद्रीय बाड द्वारा माय दगा की कम्पनिया व ऋण पत्रा की जमानत पर

(न) भारत स्थित कार्पोरेशना व अय एव ऋण पत्रा की जमानत पर

(य) मान तथा माल के अधिकार पत्रा का जमानत पर जो ऋण के पत्रा में बैंक व पास जमा किए गए हैं या उन व नाम बचान किए गए हैं

(फ) केंद्रीय बाड क आदगानुसार उस मान की जमानत पर जो सम्बन्धित ऋण अग्रिम व राकड माय व बदल में बैंक व नाम उपग्राधित (hypothecate) किए गए हैं

(ज) स्वीकृत विनिमय त्रिता आगन (payee) द्वारा बचान किए गए प्रनिता पत्रा तथा सम्मिन एव व्यक्तिगत प्रतिता पत्रा की जमानत पर जो दो या दो से अधिक एव व्यक्तियों ने लिखे हैं तिनमें किसी प्रकार की सामान्य साभीदारी न है

(ह) नीमित कम्पनिया व चकता अगा या अचल सम्पति या उनका अधिकार पत्रा की सम्पत्ति प्रनिभूतिया की जमानत पर

(स्टैंड बैंक महायक प्रतिभूतियों की जमानत पर तभी ऋण दे सकता है जब उनकी मूल जमानत उक्त पत्रों में (अ) से (य) तक है या (फ) तथा (ज) की हो।)

यदि भारत सरकार किसी विदेशी सरकार स्थानीय अधिकारी या राज्य सरकार का इस बाय व लिए मायता दे तो बैंक का केंद्रीय बाड उन्हें बिना किसी उक्त जमानत या अय विशेष जमानत (specific security) के भी ऋण तथा अग्रिम दे सकता है।

(२) यदि किसी ऋणी न बैंक से ऋण अग्रिम तथा राकड-माय तन समय जमानत व रूप में बाड ऋण पत्रा प्रनिता-पत्र स्क्वैड ग्मान (stock receipt) वौण्डम बापिकी (annuities) अग स्क्वैड (stock) प्रतिभूतिया माल या मान के अधिकार-पत्र जमा किए हैं हस्तान्तरित किए हैं अधिकृत किए हैं और फिर समय समाप्त होन पर भी ऋण चुकाकर वापस न लिए हैं तो स्टैंड बैंक एम पत्रा माल व जमानतों को बच सकता है और बचकर गति वमूल वर सकता है

(३) विनियम-विलो नया अन्य वेचानमाध्य विदेशो का लिखना, स्वीकारना कटौती करना एवं क्रय-विनय करना,

(४) अपने कोष का उस्त (१) में निखित (अ) में (द) तक की प्रतिभूतियों में विनियोग करना और फिर उन्हें आवश्यकतानुसार रोकड़ में परिवर्तित करना,

(५) अपने वायलियों, गारंटियों तथा एजेंसियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले मांग-विवरण, टेन्डीग्राफिक ट्रान्सफर तथा अन्य प्रकार के राशि स्थानान्तरण-पत्र खरीदना और आदेश तथा बाह्यक परिमाल-पत्र लिखना, निर्गमित करना तथा प्रचलित करना,

(६) मोना, चांदी तथा मोने-चांदी के मिवके खरीदना व बेचना,

(७) जमाना से जमा राशि लेना तथा अन्य प्रकार में रोकड़ लेने खोलपर राशि स्वीकारना,

(८) सब प्रकार के बंधन (bonds), अश-पत्र, अधिकार-पत्र तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ व कागजात सुरक्षा के लिए स्वीकारना,

(९) ऋण के बदले में प्राप्त हुई अथवा डूबी हुई चन और अचल सम्पत्ति को बेचना और बेचकर उमकी राशि वसूल करना,

(१०) महकारी समिति एक्ट, १९१२ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड महकारी समितियाँ क एजेंट की हैसियत से काम करना,

(११) उक्त धारा (४) के अन्तर्गत अधिकृत ज्ञातों, स्कन्धों, ऋण-पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना,

(१२) कमीशन लेकर एजेंट की हैसियत से काम करना तथा क्षति-पूर्ति जमानती (surety ship) तथा गारण्टी के अनुबन्ध करना,

(१३) अकेले या सम्मिलित रूप में प्रख्यामी के रूप में काम करना तथा किसी बैंकिंग कम्पनी के निस्वारक (liquidator) के रूप में काम करना,

(अ) सार्वजनिक कम्पनी के अश तथा अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों के नय विक्रय, हस्तान्तरण तथा स्वामित्व प्राप्त करने के लिए,

(ब) जगो व अन्य किसी भी प्रकार की प्रतिभूतियों की मूलराशि, व्याज व लाभश वसूल करने के लिए,

(स) उक्त राशि को भारत के अन्तर्गत व भारत के बाहर विनियम विलो द्वारा भेजने के लिए,

(१४) विदेशों में भुगतान होने वाले विनियम विल व परिमाल पत्र लिखना,

(१५) मौममी दृष्टि-कार्यों के हेतु लिखे गये तथा विदेशों में भुकाये जाने वाले विनिमय-विलो का अधिक से अधिक १५ महीने की अवधि के लिए खरीदना तथा अन्य कार्यों के हेतु लिखे गये विगो को अधिक से अधिक ६ माह के लिए खरीदना,

(१६) अपने निर्धारित व्यवसाय के लिए राशि उधार लेना तथा उसकी जमानत में अपनी सम्पत्ति रखना,

(१७) यदि किसी सीमित स्क्वैड कम्पनी या सहकारी समिति का विलयन होने वाला हो तो उसे टालने के लिए उन्हें उधार राशि देना, अग्रिम देना तथा उनका रोकड़-लवा खोलना, तथा वित्तियन के लिए उन्हें राशि की सुविधाएँ देना,

(१८) कोर्ट ऑफ वाईस को उनके सम्पत्ति की जमानत पर शून्य तथा अग्रिम देना, (पर य क्रम तथा अग्रिम राज्य सरकार की आज्ञा बिना नहीं जा सकते ।)

(१९) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्वीकृति में किसी अन्य बैंक के अग प्रार्थित करना, खरीदना, लेना तथा बेचना, तथा कोई बैंक स्थापित करके उसे अपनी सहायक कम्पनी के रूप में चलाना;

(२०) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की धारा ८ में उल्लिखित पदान-कोष में समय-समय पर राशि देकर सहायता करना ।

(२१) अन्य बोर्ड भी व्यवसाय करना, जिसे केन्द्रीय सरकार बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिश पर रिजर्व बैंक की मलाह से निर्धारित कर दे ।

(२२) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट की अन्य धाराओं में निर्धारित व उन धाराओं में सम्बन्धित कोई भी कार्य करना ।

(२३) उक्त व्यवसाय में सम्बन्धित तथा उसके परिपूरक कोई भी कार्य करना एवं विदेशों विनिमय सम्बन्धी व्यवसाय भी करना ।

(स) अन्य बैंकों का व्यवसाय प्राप्त करने का विशेषाधिकार—स्टेट बैंक केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति में या केन्द्रीय सरकार और रिजर्व बैंक के आदेश पर अन्य किसी बैंकिंग मस्या का व्यवसाय (सम्पत्ति एवं देनदारी) अपने अधिकार में ले सकता है । इसकी निम्न पद्धति होगी —

जिन बातों पर स्टेट बैंक प्रस्तावित बैंकिंग मस्या को लेना चाहता हो, वे शर्तें स्टेट बैंक के केन्द्रीय बोर्ड, प्रस्तावित बैंकिंग मस्या की मचालक-सभा तथा रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृति हानी चाहिए । फिर उन्हें केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना चाहिए । यदि केन्द्रीय सरकार उचित समझे

तो अपनी लिखित स्वीकृति देगी। तब वे शर्तें स्टेट बैंक एवं प्रस्तावित बैंकिंग मस्या के अगधारी व ऋणदाताओं को अनिवार्य रूप से मान्य होगी।

इस प्रकार उस बैंकिंग मस्या का व्यवसाय व उमकी लेनदारी तथा देनदारी प्राप्त करने के बढने में स्टेट बैंक उमका प्रतिफल (मूल्य) चाहें तो रोकड में, अथवा कुछ रोकड और धेप राशि के अश देकर चुका सकता है। अपने अग देने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, स्टेट बैंक अपनी निर्गमित पूंजी बडा भी सकता है। ऐसी बैंकिंग मस्या का व्यवसाय चलाने का पूर्ण अधिकार स्टेट बैंक को होगा।

**स्टेट बैंक की निषिद्ध क्रियाएँ**

(१) स्टेट बैंक सामान्यतः ६ मास में अधिक अवधि के ऋण तथा अग्रिम नहीं दे सकता।

(२) अपने ही अगों तथा स्वन्ध की जमानत पर ऋण तथा अग्रिम नहीं दे सकता।

(३) सामान्यतः अचल सम्पत्ति व उमके अधिकार-पत्र की जमानत पर ऋण तथा अग्रिम नहीं दे सकता।

(४) व्यक्ति विशेष या किसी फर्म को किसी एक समय में कुल मिलाकर एक निश्चित मात्रा से अधिक ऋण नहीं दे सकता। निश्चित मात्रा वह स्वयं ही नियत कर सकता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं जहाँ वह निर्धारित राशि में अधिक भी दे सकता है—ऐसा वह अपने एक्ट की धारा ३३ (१) (a) से (c) के अन्तर्गत कर सकता है।

(५) बैंक किसी व्यक्ति विशेष या फर्म के उन वेचानसाध्य विलेखों की कटौती नहीं कर सकता, न उन्हें खरीद सकता है और न उसकी जमानत पर ऋण एवं अग्रिम ही दे सकता है, जिनके प्रति कम से कम ऐसे दो व्यक्तियों या फर्मों का अलग अलग दायित्व न हो, जो एक दूसरे में सामान्य साझीदारे के अर्थों में बिलकुल अलग अलग न हों—ऐसे व्यक्तियों तथा फर्मों में किसी प्रकार की साझीदारी नहीं होनी चाहिए।

(६) बैंक निम्न प्रकार के वेचानसाध्य विलेखों को न कटौती कर सकता है और न उमकी जमानत पर ऋण, अग्रिम, पर रोक-ऋण दे सकता है—

(अ) जो विलेख यदि मौसमी कृषि कार्यों के लिए लिखे गये हैं जो १५ महीने, तथा अन्य कार्यों के निमित्त हैं तो ६ माह से अधिक अवधि के लिए हों और कटौती कराने, ऋण तथा अग्रिम लेने या रोक-ऋण स्वीकृत कराने समय जिनकी अवधि उक्त १५ महीने और ६ महीने से अधिक के लिए धेप हो।

(क) विनिमय-बिल आरम्भ में ही मौलिक रूप में यदि मौसमी कृषि कार्यों के लिए है तो १५ ग्राम से अधिक, तथा अन्य कार्यों के लिए हो तो ६ ग्राम से अधिक अधिक के लिए लिसे गये हो।

(ग) बैंक अपने व्यवसाय, अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास के लिए आवश्यक भूगृहादि तथा धारा ३३ के अन्तर्गत दिये गए ऋणों के डूब जाने के बढ़ने में प्राप्त हुई सम्पत्ति को छोड़ अन्य किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति नहीं रख सकता, न खरीद सकता है और न किसी किसी सम्पत्ति में अपना कोई भाग (अंश) रख सकता है। पर यदि इसके पास आरम्भ में ही ऐसी कोई अचल सम्पत्ति हो, जिसका वह तुरन्त उस समय उक्त कार्यों में उपयोग न कर पा रहा हो तो वह उसे किराये पर दे सकता है।

यदि किसी व्यक्ति का स्टेट बैंक में लेखा हो तो वह उस लेखे पर बैंक द्वारा निर्धारित राशि अधिक राशि का अधिविषय (overdraft) ले सकता है। उस समय उस पर निषिद्ध क्रियाओं की जगह धारा (४) लागू नहीं होगी।

**बैंक के कोष**

बैंक की जिम्मेदारी है कि वह अपने पास दो कोष रखे —

(१) सामंजस्य एवं विकास-कोष (Integration and Development Fund), और

(२) संचित कोष (Reserve Fund)।

विकास-कोष बनाने के लिए बैंक को निम्न राशि जमा करनी आवश्यक होगी—

(अ) रिजर्व बैंक को स्टेट बैंक की निगमित पूँजी के ५५% अंश पर मिलने वाला लाभ।

(ब) रिजर्व बैंक या केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर दी गई अनुदान राशि।

विराम कोष का उपयोग केवल निम्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है—

(अ) अगले पाँच वर्षों में ४०० नई शाखाएँ खोलने और उन्हें चलाने में जो अधिक व्यय होगा और उन पर जो हानि होगी उसकी पूर्ति के लिए।

(ब) अन्य हानियाँ और खर्चों की पूर्ति के लिए जिनकी स्वीकृति केन्द्र सरकार ने रिजर्व बैंक की मलाह से दी हो।

विराम-कोष में जमा राशि रिजर्व बैंक की सम्पत्ति मानी जाती है

और उम पर स्टेट बैंक के अगधारियों या अन्य किसी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता ।

मन्त्रित कोष में बैंक को निम्न राशि जमा करनी होगी —

(अ) वह मन्त्रित कोष जो १ जुलाई, १९५५ को इम्पीरियल बैंक के पास था ।

(ब) वह राशि जो स्टेट बैंक प्रति वर्ष आभाग घोषित करने से पूर्व अपने शुद्ध लाभ में से इस कोष में जमा करे ।

स्टेट बैंक एक्ट में व्यवस्था की गई है कि बैंक की कार्य-प्रणाली एवं व्यवसायिक क्रिया कलापों की जाँच के लिए वर्ष में अगधारियों की एक सामान्य मभा होगी । सामान्यतः यह सभा उन्हीं स्थानों पर होगी, जहाँ बैंक के स्थानीय कार्यालय हो और इसकी सूचना पहले से ही दी जायेगी ।

स्टेट बैंक एक्ट में सशोधन

परन्तु इम्पीरियल बैंक की विदेशी सम्पत्ति एवं देनदारियों का स्टेट बैंक को हस्तान्तरण होने में कुछ वैधानिक अडचनें थी । अतः १९५५ में स्टेट बैंक एक्ट में एक अध्यादेश (ordinance) द्वारा सशोधन किया गया है । इसमें यह व्यवस्था हा गई है कि विदेश-स्थित देनदारी एवं देनदारियों का स्टेट बैंक को हस्तान्तरण करने में यदि इम्पीरियल बैंक को वहाँ के कानूनों के कारण कोई कठिनाई हो तो इम्पीरियल बैंक उन कानूनों के अनुसार ऐसी व्यवस्था करेगी जिसमें वहाँ का व्यवसाय स्टेट बैंक को मिल सके । और यदि इम्पीरियल बैंक चाहे तो उन देशों में अपनी सम्पत्ति को वसूल करे तथा देनदारियों का भुगतान कर जो राशि दीप वचे उसका हस्तान्तरण स्टेट बैंक को करे ।

स्टेट बैंक की क्रियाएँ

स्टेट बैंक ने १ जुलाई १९५६ को चार वर्ष पूरे किये । इस अवधि में बैंक ने नाबख विस्तार की ओर अधिक ध्यान दिया । स्टेट बैंक एक्ट के अन्तर्गत इस बैंक को ५ वर्ष में ६०० शाखाएँ खोलनी हैं । इसके सिवाय इम्पीरियल बैंक ने पिछले कार्य-क्रम के अनुसार ११४ शाखाओं में से १ जुलाई १९५५ तक ६१ शाखाएँ खोलीं अतः अभी हुई ५१ शाखाओं की जिम्मेदारी स्टेट बैंक ने ली है । सरकार ने स्टेट बैंक को १८३ शाखाओं के स्थान बता दिये हैं । तदनुसार स्टेट बैंक न चार वर्ष में १८४ शाखाएँ खोली है जिनमें से ३० जून १९५७ तक ७०२ शाखाएँ खोली गई थी, ३० जून १९५७ एवं १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में क्रमशः १३ एवं ६६ शाखाएँ नई खोली गईं । इसमें स्पष्ट है कि

जिम जिम्मेदारी के साथ स्टेट बैंक कार्य कर रहा है उसमें उसके निर्माण का हेतु निश्चय ही सफल होगा । [स्थिति-विवरण अगले पृष्ठ पर देखिए ।]

३० जून १९५६ को सम्पाद होने वाले वर्ष में सूचीबद्ध बैंकों की कुल मध्या ६३ तथा उनके कार्यालयों की मध्या ३,५०० हो गई ।

दूसरे, इस अवधि में स्टेट बैंक के निक्षेपों में भी आश्चर्यजनक गति में वृद्धि हुई है । हमें स्पष्ट है कि जिम जिम्मेदारी के साथ स्टेट बैंक कार्य कर रहा है उसमें उसके निर्माण के हेतु निश्चय ही सफल होगा । [स्थिति विवरण देखिए ।]

### स्टेट बैंक की आलोचना

(१) स्टेट बैंक को सरकार का विशेष आश्रय प्राप्त है । इस कारण उसके निक्षेपों में आश्चर्य जनक गति में वृद्धि हुई है । इस सम्बन्ध में उसकी स्थिति अन्य सूचीबद्ध बैंकों में अधिक सुविधापूर्ण है । उदाहरणार्थ भारत में अमरीका के पब्लिक लां ४८० के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि स्टेट बैंक में जमा की जाती है जो ३०० करोड़ ५० लाखों का अनुमान है ।<sup>१</sup> इसमें बैंक को दुहरा लाभ होता है । एक तो बिना किसी प्रयास के अधिक निक्षेप मिल जाते हैं । दूसरे उसे इन पर मुद्रामण्टी की सामान्य व्याज दर से कम व्याज देना पड़ता है । अतः उक्त राशि का कुछ अंश देण के सूचीबद्ध बैंकों को भी दिया जाना चाहिए ।

(२) स्टेट बैंक को अन्य बैंकों की अपेक्षा शाखाएँ खोलने की अनुमति अन्य बैंकों की अपेक्षा जल्दी मिल जाती है । साथ ही इस हेतु स्टेट बैंक को अनेक विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं जैसे कर्मचारियों को कर मुक्त प्रेच्युइटी, जो अन्य बैंकों का नहीं है । फिर भी स्टेट बैंक ने प्रथम दो वर्षों में केवल १०२, तीसरे में १३ तथा चौथे वर्ष में ३६ शाखाएँ खोली हैं । मसब में नहीं आता कि ५ वर्ष में वह अपनी ४०० शाखाएँ खोलने की जिम्मेदारी कैसे पूर्ण करेगा जबकि अभी तक केवल १८४ शाखाएँ खोली हैं ।

(३) स्टेट बैंक की ६०% नई शाखाएँ उन्ही स्थानों पर हैं जहाँ पहले से ही बैंकिंग सुविधाएँ थी । एसी स्थिति में भारतीय अर्थ व्यवस्था को अथवा ग्रामीण बैंकिंग विकास को कौन-सा लाभ हुआ ? अतः नई शाखाएँ ऐसे स्थानों पर खोली जाना चाहिए जहाँ बैंकिंग सुविधाएँ नहीं हैं तभी इनको दी जाने वाली विशेष सुविधाओं का लाभ देण को हो सकेगा ।

<sup>१</sup> Presidential address of Shri C H Bhabha at the 15th Annual Conference of the Indian Bankers Association on 3rd April, 1959.

## स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया स्थिति विवरण दिनांक ११ गितम्बर १९५६

पूँजी एवं देनदारियाँ		नेनदारियाँ एवं सम्पत्ति	
अविभूत पूँजी २० लाख अना, प्रत्येक १०० रु० का	२०,००,०००,०००	रोबट हस्ते एवं रिजर्व बैंक में अन्य बैंका में जेप	५८,६८,६६,०००
निर्गमिम, प्राधिकृत एवं चुपत्ता पूँजी—		भांग एवं अल्पकालीन	१,६६,१६,०००
५६२५०० अग प्रत्येक १०० रु० का	५६२,५०,०००	सूचना गाने मृण विनियोग—	३३३,३३,०००
मचित कोप एवं अन्य, कुप निक्षेप एवं अन्य लेने	५६२,५०,०००	सरकारी एवं अन्य प्रग्यामी	
अन्य बैंका एवं एजेंटों आदि में मृण	५६७,०६,२७,०००	प्रतिभूतियाँ	३६५,६६,६०,०००
देय विल	—	अन्य अधिभूत गिनियोग	१०२७,०७,०००
मग्रहण के लिए विल (प्रति प्रविष्ट १)	१०,२३,८०,०००	अमिम—	३७१,७३,८७,०००
स्वीकृति, त्रैबान एवं अन्य उत्तरदायित्व (प्रति प्रविष्ट २)	१८३,७३,०००	मृण, गेक मृण, अधि- विकप आदि	
अन्य देनदारियाँ	१४६२०,०००	मति एवं कटीती विल	१५३,०२,०६,०००
	११०५,३६,०००	प्राप्य विल (प्रति प्रविष्ट १)	६०६,७२,०००
	६०६,३०,८७,०००	स्वीकृति, वंचन आदि पर गाहकों का दायित्व	१८३,७३,०००
		प्रति प्रविष्ट (२)	
		भवन (विभागत वम वने के बाद)	१४६,२०,०००
		पनीचर पितस्वगं (" ")	१२४,१८,०००
		अन्य सम्पत्ति	११५,६३,०००
			२६,५७,६७,०००
			६०५,३०,८७,०००

अतः केन्द्र सरकार को रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक के इन दावा को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे देश की बैंकिंग व्यवस्था विकसित होकर ग्रामीण क्षेत्रों का बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध हो सकें।

### सारांश

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने आर्थिक सहायता प्राप्त करने एवं जनता को बैंकिंग सुविधाएँ देने के लिए बंगाल, बम्बई तथा मद्रास में क्रमशः १८०६, १८४० तथा १८४३ में प्रेसीडेंसी बैंकों की स्थापना की। इनकी सरकार की ओर से लेन देन करने का एकाधिकार था तथा १८६२ तक पत्रमुद्रा चलाने का भी अधिकार था। १८६८ में रुई के सट्टे में बैंक ऑफ़ इंडिया की भारी हानि हुई इसलिए उसका विलियन कर १ करोड़ रुपये की पूँजी से इसी नाम की दूसरी बैंक खोली गयी। इसलिए १८७६ में प्रेसीडेंसी बैंक एक्ट द्वारा इनकी क्रियाओं पर प्रतिबन्ध लगाये गये।

इनमें अनेक दोष थे इसलिए १८६० तथा १८७६ में इनके एकीकरण से एक अखिल भारतीय बैंक बनाने की माँग की गई। ये दोष थे—(१) केवल लाभकर स्थानों में शाखाएँ खोलना। (२) पूँजी की कमी के कारण आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति न करना। (३) भारतीय बैंकिंग विकास में सन्तोषप्रद कार्य न करना। इसका बाद १८६८ तथा १९१३ में काउन्टर और चेम्बरलेन समिति ने केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता पर जोर दिया, फलस्वरूप १९२० में इम्पीरियल बैंक एक्ट स्वीकृत हुआ और १९२१ में इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई। इसकी स्थापना के तीन हेतु थे—सरकारी एवं केन्द्रीय बँकर के नाते काम करना तथा देश में बैंकिंग सुविधाओं का विकास करना। इसलिए इस पर प्रथम ५ वर्ष में १०० शाखाएँ खोलने की जिम्मेवारी थी।

इम्पीरियल बैंक को केन्द्रीय बैंक न बनाने के कारण—(१) व्यापारिक बैंकिंग कार्य करना, (२) केन्द्रीय बैंक बनाया जाता तो इसे अपनी शाखाएँ बन्द करनी पड़तीं, (३) लाभ-नियन्त्रण होना आवश्यक था जिसे अशक्य नहीं मानते, (४) केन्द्रीय बैंक की कमी को दूर करने की जिम्मेवारी भी पूरी नहीं थी, (५) इसकी नीति देश हित में न थी।

इम्पीरियल बैंक का मगडन—बम्बई, मद्रास तथा बंगाल इन तीनों प्रेसीडेंसी बैंकों के एकीकरण से हुआ। इसकी अधिकृत पूँजी ११२५ करोड़ रु० तथा चुकता पूँजी ५६२५ लाख रुपए थी। इसका प्रबन्ध केन्द्रीय सभा करती थी जिसके १६ सदस्य थे तथा एक अतिरिक्त सदस्य केन्द्रीय सरकार मनानीत

करती थी। इसके सिवा बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ते में स्थानीय सभाएँ भी थी जिनके ७ सदस्य थे।

१९३५ में रिजर्व बैंक की स्थापना से इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत हो गया तथा यह वही क्रियाएँ करता था जो वर्तमान स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया करता है। इम्पीरियल बैंक की क्रियाओं में अनेक दोष थे—(१) देश में बैंकिंग विकास एवं बैंकिंग शिक्षा का आयोजन होगा जो यह न कर सका, (२) मुद्रा-मण्डी में मौसमी साख की कमी को दूर कर सकेगा, (३) बैंकों का यह मार्ग दर्शन न कर सका अपितु उनका प्रतियोगी रहा, (४) इसकी नीति भारतीय हितों के विरोध में रही।

फिर भी इम्पीरियल बैंक ने कुछ दिशाओं में निश्चित प्रगति की। उसने स्थापना के प्रथम ५ वर्षों में १०० तथा १९४५ तक ४३३ शाखाएँ खोलीं। कर्मचारियों की उसे आवश्यकता होने के कारण कुछ अंश में बेकारी का निवारण हुआ तथा ग्राहकों को भूल सुविधाएँ देकर आशिक रूप में मौसमी मुद्रा एवं साख आवश्यकताओं की पूर्ति की। ब्याज दर को मौसमी आवश्यकताओं के समय ऊँची न होने देने के लिए भी इसने प्रयत्न किया। फिर भी इसके विशद निम्न आक्षेप रहे—(१) देश के बैंकों का प्रतियोगी, (२) यूरोपीय प्रबन्ध, (३) पक्षपात पूर्ण नीति, (४) मुद्रा मण्डी की उन्नति न कर सका, (५) अधिक प्रबन्ध व्यय, (६) नौकरशाही का बोसवाला, (७) व्यापार का केन्द्रीकरण, (८) पत्रमुद्राओं के वर्गीकरण में असुविधाएँ।

इम्पीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण—इन आक्षेपों के कारण इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की माँग समय-समय पर की गई थी। ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने भी इस पर सरकार के कठोर नियन्त्रण का सुझाव दिया था। १९५४ में ग्रामीणसाख सर्वेक्षण समिति ने अपनी रिपोर्ट में “सरकारी साझे में व्यापारिक बैंक के रूप में स्टेट बैंक के निर्माण” की सिफारिश की थी। तदनुसार ८ मई १९५५ को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया विधेयक स्वीकृत हुआ और १ जुलाई १९५५ से स्टेट बैंक ने कार्यारम्भ किया।

स्टेट बैंक—की अधिकृत पूँजी २० करोड़ रु० १०० रु० के अंशों में है। निर्गमित एवं चुकता पूँजी ५६२५० लाख रु० है जिसको ५५% सदैव रिजर्व बैंक के पास रहेगी तथा शेष निजी अंशधारियों द्वारा दी गई है। स्टेट बैंक अपनी निर्गमित पूँजी १२५० करोड़ रु० तक बढ़ा सकेगा, किन्तु इससे अधिक बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति स्टेट बैंक के २०० से अधिक अंश अपने नाम या सम्मिलित नाम न ले सकेगा। इसके

लिए रिजर्व बैंक कॉरपोरेशन, बीमा एवं सहकारी सस्थाएँ, स्थानीय अधिकारी तथा निजी सार्वजनिक या घासिक सम्पत्ति के प्रत्यासी अपवाद हैं। इसके अंशों का समावेश "मान्य प्रतिभूतियों" की सूची में किया गया है। स्टेट बैंक का प्रबन्ध केन्द्रीय सभा करेगी जिसके २० सदस्य हैं जिनमें से ६ निजी अंशधारियों द्वारा, १३ केन्द्रीय सरकार तथा १ रिजर्व बैंक मनोनीत करता है। इसकी अवधि ५ वर्ष है परन्तु केन्द्रीय सरकार एवं रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त एक-एक सचालक की अवधि सम्बन्धी शर्तें नहीं हैं।

स्टेट बैंक के स्थानीय कार्यालयों का कार्य स्थानीय सभाएँ करती हैं।

स्टेट बैंक के कार्य—(१) रिजर्व बैंक के एजेंट का कार्य करना है जिसके लिए अनुबन्ध के अनुसार उसे कमीशन मिलता है, (२) व्यापारिक बैंकिंग क्रियाएँ, (३) केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति अथवा रिजर्व बैंक या केन्द्र सरकार के आदेश से इसे अन्य बैंकों का व्यवसाय प्राप्त करने का विशेषाधिकार है। परन्तु स्टेट बैंक निम्न कार्य नहीं करेगा—(१) ६ मास से अधिक समय के ऋण पर अग्रिम देना, (२) अपने अंशों या स्कर्षों की जमानत पर ऋण देना, (३) अचल सम्पत्ति या उसके अधिकार-पत्र की जमानत पर ऋण या अग्रिम देना, (४) किसी व्यक्ति या फर्म को एक ही समय एक नियत मात्रा से अधिक राशि के ऋण देना, (५) कुछ शर्तों की पूर्ति बिना बेखानसाध्य विलेखों की कटौती करना या खरीदना, (६) निजी व्यवसाय पर कर्मचारियों के निवार के सिवा अन्य कोई अचल सम्पत्ति खरीदना। स्टेट बैंक पर दो कोष रखने की वैधानिक जिम्मेवारी है—(१) सामान्य एवं विकास कोष, (२) संचित कोष।

इसके सिवा १ जुलाई १९६० तक के ५ वर्षों में इस पर ४०० नई शाखाएँ खोलने की जिम्मेवारी है। स्टेट बैंक ने ३० जून १९५६ को ४ वर्ष पूरे किये। इस अवधि में उसके निशेधों में आश्चर्यजनक गति से वृद्धि हुई है तथा इनमें प्रथम २ वर्षों में १०२, तीसरे वर्ष में १३ तथा चौथे वर्ष में ६६ नई शाखाएँ खोली हैं। यह प्रगति शान्तोषजनक नहीं है क्योंकि—(१) इसे सरकार का विशेष आश्रय प्राप्त है। (२) स्टेट बैंक को अन्य बैंकों की अपेक्षा शाखाएँ खोलने की अनुमति जल्दी मिल जाती है। (३) स्टेट बैंक की शाखाएँ उन्हीं स्थानों पर हैं जहाँ बैंकिंग सुविधाएँ पीछे से हो रही हैं। अतः स्टेट बैंक को इन दोषों का निवारण करना चाहिए।

## अध्याय २०

# औद्योगिक अर्थ-प्रवन्धन

देश के उपलब्ध साधनों का पर्याप्त एवं समुचित उपयोग करने एवं देश की अर्थ व्यवस्था की उन्नति के लिए देश का औद्योगीकरण होना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। परन्तु भारत की वर्तमान स्थिति में जो उद्योग-धन्धे हैं उनको पर्याप्त आर्थिक सुविधाएँ नहीं मिलती जिनसे नैसर्गिक साधनों की बहुलता होते हुए भी भारत का औद्योगिक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो सका है। औद्योगिक आयोग तथा बैंकिंग जांच-मामिनि ने भी इस बात पर जोर दिया है कि यहाँ व उद्योगों को पर्याप्त आर्थिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है, अतः देश में औद्योगिक बैंकों की स्थापना हो।

### औद्योगिक बैंकों की आवश्यकता

१ स्थायी पूँजी—(Fixed Capital)-- स्थायी पूँजी की आवश्यकता विशेषतः नये उद्योगों को हाती है जिनको अपने यन्त्र, सामग्री, भू-गृहादि स्थायी सम्पत्ति खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो उद्योग पहले से ही स्थापित हैं उनको अपनी जाँच सम्पत्ति के विस्थापन अथवा उद्योग के विस्तार के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है।

२ कार्यशील पूँजी—कार्यशील पूँजी उद्योगों का दिन-प्रति-दिन की आवश्यकताओं उत्पादन के विषय, कच्चा माल आदि खरीदने के लिए होती है। इस प्रकार उद्योगों की आर्थिक आवश्यकताएँ दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन होती हैं।

अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति तो व्यापारिक बैंक कर सकते हैं एवं करते भी हैं, परन्तु दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए देश में १९४६ तक कोई भी विशेष समस्या नहीं थी। इससे उद्योगों की प्रगति जैसी होनी चाहिए एवं जिस प्रकार से उपलब्ध साधनों का उपयोग होना चाहिए वह नहीं हो रहा है। अतः देश के औद्योगिक विकास एवं प्रगति के लिए देश में औद्योगिक बैंकों की अतीव आवश्यकता है।

## औद्योगिक बैंक

य व बैंक हैं जा दीर्घकालीन आर्थिक महायत्ना दवर, उद्योगों की स्थापना एवं विकास के लिए स्थायी पूँजी की पूर्ति करत हैं। इस कार्य के लिए वे स्थायी तथा दीर्घकालीन निक्षेप स्वीकारते हैं। इस प्रकार के बैंक नट नड कम्पनियों के अशा अथवा ऋण-पत्रों का अभिग्रापन भी करत हैं।

प्रारम्भिक स्थिति—(अ) प्रबन्ध अभिकर्ता—हमारे औद्योगिक विकास के इतिहास में यह स्पष्ट है कि भारत की वर्तमान औद्योगिक प्रगति का श्रेय ब्रिटिशों का ही है जिन्होंने यहां प्रारम्भिक अवस्था में बड़े बड़े कारखाने जैसे कपड़े, लूट, ऊनी वस्त्र आदि के कारखाने। उनके बाद नमो भारतीय भी इन उद्योगों में अपनी पूँजी वित्तियोग करने लगे तब इन व्यक्तियों अथवा परिवारों ने अपनी लगातार हुई पूँजी नमो जनता का वच डाली। इस तरह हमारे देश में भीमिक कम्पनियों की स्थापना हुई। जिन व्यक्तियों ने यह कार्य प्रारम्भ किया था उन्होंने इनके साथ 'यवस्था सम्बन्धी सम्झौते किए। इस प्रकार प्रबन्ध अभिवृत्ता प्रणाली का उगम हुआ तथा विंगपन इन्हीं लोगों तथा अभिकर्ताओं ने अपनी सचिव राशि में उद्योगों की महायत्ना की जिसमें कम्पनियों एवं अगधारियों का अनेक हातियाँ थी —

- १ प्रबन्ध अभिकर्ताओं का कम्पनियों के ऊपर पूर्ण नियन्त्रण रहना या निम्न तकनीक बातों (technical matters) की ओर पूर्ण दुलभ हाता था तथा लाभ की ही वे अधिक चिन्ता करत थे जिसमें यन्त्रादि की घिमावट गीष्ट हाकर उत्पादनाधिक्य भी हा जाता ह।
- २ इनका प्रभुत्व हान में कम्पनियों का संचालन हम ही कुछ व्यक्तियों द्वारा हाता है जा कबत उनी है परन्तु जिनमें औद्योगिक कार्यधमना का अभाव है। प्रबन्ध अभिवृत्ता के जनक कम्पनियों का प्रभुत्व हान में एक कम्पनी पर हान हाल बुर परिणामों का फल अन्य कम्पनियों का भी भागना पडता है।
- ४ इनका अधिक प्रभुत्व हान के कारण भारत में पजी एवं उद्योगों का कन्द्रीय करण कुछ इन गिन व्यक्तियों के हाथों में ही हा गया है जिसमें पजी का समान वितरण नहीं हाता जो ग न अन्य व्यक्ति जिनमें औद्योगिक योग्यता है उद्योग प्रारम्भ कर सकत है।<sup>१</sup> जैसे भारत के सब महान् उद्योगों का स्वामित्व एवं प्रवन्ध केवल १० व्यक्तियों के हाथ में है।

इन बुराया में आशंकक माधारण जन मन यही है कि इस पडति का

शीघ्रातिशीघ्र अन्त हो जाना चाहिए। नवीन कम्पनी अधिनियम से प्रवन्ध अभिकर्ताओं का अन्त १९६० में हो जायगा।

(व) स्वदेशीय बैंकर—उद्योगों का ऋण दन में इनका हाथ बहुत कम है। अभी गत कुछ वर्षों से य अहमदाबाद-बम्बई की वस्त्र-निर्माणिया का ऋण देने लगे हैं। परन्तु फिर भी ऋण देने की अपेक्षा य उनके पास स्थायी निक्षेप रखना ही अधिक पसन्द करते हैं। इनसे ऋण भी कम राशि में प्राप्त होने है जिससे औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तथा व्याज-दर भी अधिक होती है।

(त) जनता के निक्षेप इनके बावजूद इनकी व्यवस्था तथा सुदृढ़ता में जनता का विश्वास हो गया तब य कम्पनियाँ जनता के स्थायी निक्षेप भी लेती थी, जिसमें बहुतान में इनकी कार्यशील पूँजी का भाग भी पूर्ण हो जाता था तथा कुछ हद तक इनकी स्थायी पूँजी की आवश्यकताएँ भी पूर्ण होती थी। इस प्रणाली का प्रचार बम्बई एवं अहमदाबाद के वस्त्र उद्योग में विशेष रूप में है। परन्तु वर्तमान अवस्था में उद्योग इन पर निर्भर नहीं रह सकते क्योंकि देश में अब वैकिंग विकास अच्छा हो रहा है तथा बैंकों में जनता का विश्वास भी अधिक जम रहा है, जिससे भविष्य में औद्योगिक कम्पनियों के पास निक्षेप नहीं जायगा।

(द) ऋण एवं ऋण-पत्र—औद्योगिक कम्पनियों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति असा तथा ऋण-पत्रों के निर्गमन से पूर्ण होती है, जो भिन्न-भिन्न धेनों के विनियाम-कर्ताओं द्वारा खरीदे जाते हैं। प्रारम्भिक स्थायी पूँजी के लिए उद्योग इन अगो एवं ऋण पत्रों पर निर्भर रहते हैं तथा कम्पनी के प्रारम्भ होने के बाद भी इन दो माधमों पर निर्भर रहते हैं। परन्तु पूँजी बाजार में समुचित विकास के अभाव में इस स्थान में पर्याप्त पूँजी प्राप्त नहीं होती है।

(य) व्यापारिक बैंक—उद्योगों में व्यापारिक बैंक से कोई विशेष सहायता नहीं मिली तथा उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाएँ अल्पकालीन एवं अपर्याप्त थीं। क्योंकि ये अग्न व्यापारिक स्वरूप के कारण औद्योगिक सुविधाएँ दे भी नहीं सकते थे, जिसके निम्न कारण हैं —

(१) व्यापारिक बैंकों के निक्षेप अल्पकालीन होते हैं जिससे वे उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण सुविधाएँ नहीं दे सकते। उन्हें हमेशा अपनी सम्पत्ति तरल रखनी पड़ती है क्योंकि उनके निक्षेप अधिकतर माँग पर दिये होते हैं।

(२) व्यापारिक बैंक कम्पनियों के असा, ऋण-पत्रादि खरीदकर उनको सहायता दे सकते थे तथा इन ऋण-पत्रों एवं अगो का वे क्रमशः हस्तान्तरित

कर सकते थे। परन्तु व्यापारिक बैंक न अपने व्यापारिक स्वम्प का दवर यह नहीं किया। इतना ही नहीं, अपितु उन्होंने अग्रा ऋण पत्रा आदि का अभिगोपन तक नहीं किया जो वे बिना किसी प्रकार के विशेष स्वतन्त्र कर सकते थे। विद्वान् म व्यापारिक बैंक यह कार्य करते भी हैं। इसका कारण यह है कि भारत में अभी तक विकसित पूँजी बाजार नहीं है जिनमें उनका सुगमता से बचा जा सके।

(३) इम्पीरियल बैंक भी इस कार्य का नहीं कर सकता था क्योंकि अधिनियम के अनुसार यह ६ मास से अधिक अवधि के लिए ऋण नहीं दे सकता था। इसका अनुकरण अन्य व्यापारिक बैंक ने भी किया।

(४) व्यापारिक बैंक हमारे देश में व्यक्तिगत जमानत पर ऋण नहीं देते और किसी मान की जमानत देना भारतीय उद्योगपति मान हाँकि सम्भन थे। इसलिए भी व्यापारिक बैंक उद्योगों को आर्थिक सुविधाएँ न दे सके और जा भी सुविधाएँ उन्हाने दी वे केवल अल्पकालीन थीं।

(५) व्यापारिक बैंक अपने ऋणों के लिए तरल जमानत चाहते हैं जो उद्योगों के पास नहीं थी तथा स्थायी सम्पत्ति की जमानत में उस सम्पत्ति का समुचित मूल्यांकन होना आवश्यक होता है जिसमें जमानत एवं ऋण में पर्याप्त अंतर (margin) रखा जा सके। इस प्रकार मूल्यांकन करने के लिए भारतीय बैंकों के पास विशेषज्ञ नहीं थे। जो कुछ भी सहायता उन्हाने का वह केवल कच्चे माल की जमानत तथा अल्पकालीन निक्षेपों के आधार पर की, जिनका नवकरण करना रोकड़ निधि तथा निक्षेप राशि पर निर्भर रहता है। इसमें वे ऋणों का नवकरण नहीं कर सकते थे। इस कारण इनकी ऋण राशि में अनिश्चितता रहती थी। इससे निवा अनक दस्त आता था जा उद्योगों का ऋण देना अपने अस्तित्व को खतरा में डालना सम्भन था। इसमें ये उद्योगों का पर्याप्त आर्थिक सुविधाएँ न दे सकें।

(६) कन्द्रीय बैंकिंग जाच-समिति के सामने इस बात का भी निर्यात की गई थी कि इम्पीरियल बैंक के अधिकारी विशेषण यूरोपीय ज्ञान के कारण यूरोपीय फर्मों एवं कम्पनियों की ही राशि देते थे तथा भारतीय उद्योगों के साथ पर्याप्त से काम करत थे।

केवल दो ही माग—अतः उद्योगों का आर्थिक सुविधाएँ देना में भारतीय व्यापारिक बैंक असमर्थ थे। परन्तु इसका दोष केवल व्यापारिक बैंक पर ही नहीं डाला जा सकता क्योंकि भारत की परिस्थिति ही कुछ ऐसी है जिसमें उनका यह सावधानी रखनी पड़ती है। यहाँ की जनता का विश्वास छोट से छोट

कारण से भी हिल जाता है जैसा कि पीपुल्स बैंक के विलियन के समय हुआ। अतः इस कमी को दूर करने के लिए केवल दो ही मार्ग हैं—

(१) देश के व्यापारिक बैंकों में ही ऐमा परिवर्तन किया जाय जिसमें वे औद्योगिक सहायता कर सकें, तथा

(२) उद्योगों को दीर्घकालीन अर्थ-सुविधाएँ देने के लिए अन्य देशों की भांति औद्योगिक बैंकों की स्थापना हो।

व्यापारिक बैंकों की पद्धति में परिवर्तन—(अ) व्यापारिक बैंक जर्मनी के व्यापारिक बैंकों की तरह उद्योगों की आर्थिक सहायता कर उन्हें स्थायी पूंजी दे सकते हैं। जर्मनी के बैंकों की पद्धति इस प्रकार है —

(i) किसी भी उद्योग के चल-लेखा खोलने पर उसका सन्तुलन दैनिक न होकर मासिक होता है। जो भी लेन-देन बैंक और ग्राहक में होता है वह सब इसी लेख में निरता जाता है। अर्थात् ऋण आदि की राशि तथा निक्षेप की प्रविष्टियाँ भी इसी लेख में होगी, जिसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अथवा,

(ii) जर्मनी के व्यापारिक बैंक उद्योगों को प्रारम्भिक पूंजी देने की दृष्टि से उनके अक्ष बरीद लेते हैं जिससे उद्योगों को प्रारम्भिक पूंजी मिल जाती है। इसके बाद ये अक्ष जनता को बेच दिये जाते हैं। सम्भाव्य हानि के खतरे से बचने के लिए 'कन्सोर्टियम' पद्धति (consortium model) पर अनेक बैंक मिलकर भी उद्योगों को आर्थिक सहायता दे सकते हैं तथा इस कार्य को करने, तान्त्रिक सलाह देने एवं औद्योगिक सम्पत्ति का भूत्याकन करने के लिए विशेषज्ञों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। ऐसे कन्सोर्टियम के निमोण की मिफारिश थ्रॉफ समिति ने भी की थी।

(iii) उद्योगों के साथ अधिक घनिष्ट सम्पर्क स्थापित करने के लिए बैंक अपने प्रबन्धक अथवा अन्य प्रतिनिधि को औद्योगिक कम्पनी की संचालक समिति में भेजता है। इससे अनेक कार्यों का नियन्त्रण होता है तथा ऋण देने वाले बैंकों को भी निश्चिन्तता होती है कि उनकी ऋण-राशि का अपव्यय नहीं हो रहा है।

(iv) बैंक कुछ निश्चित राशि के अक्षों का निर्गमन करें, जिसकी पूंजी से केवल उद्योगों ही को आर्थिक सुविधाएँ दी जायें।

(v) बैंकों को चाहिए कि वे औद्योगिक कम्पनियों की वार्षिक साल पर आर्थिक सुविधाएँ दिया करें जिसमें उनको कार्यशील पूंजी मिलती रहे क्योंकि ये तरल सम्पत्ति की जमानत नहीं दे सकते।

(द) उद्योगों की स्थायी सम्पत्ति तथा पुनः स्थापन के समय अच्छी कम्पनियों द्वारा निर्गमित अक्षो अथवा ऋण-पत्रों का अभिगोपन भी करे। परन्तु इसमें इस मावधानी की आवश्यकता है कि व्यापारिक बैंक ये कार्य मट्टे की दृष्टि में न कर, क्योंकि उनको सर्वप्रथम अपने निक्षेपकों की सुरक्षा की ओर दृष्टि रखनी पड़ती है।

(२) औद्योगिक बैंकों की स्थापना करना —यह दूसरा मार्ग है। उपर्युक्त सुझाव यदि कार्यान्वित हो जायें सब औद्योगिक बैंक औद्योगिक अर्थ-सुविधाएँ पूर्ण रूप में नहीं दे सकने क्योंकि

(१) उनका औद्योगिक क्षेत्र का ज्ञान सीमित होता है तथा भिन्न भिन्न उद्योगों की स्थिति में भिन्न होता है।

(२) औद्योगिक सुविधाएँ देने के लिए बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता है, जो स्थायी हो अथवा उनकी निजी पूँजी ही इतनी हो कि वे यह कार्य कर सकें।

(३) अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन ऋणों की समस्याएँ भिन्न होने से कार्य-क्षमता की दृष्टि में यही अच्छा होगा कि “औद्योगिक बैंक” की स्थापना की जाय। इस समय देश में केवल बनारा इण्डस्ट्रियल एण्ड बैंकिंग मिण्डिकेट लि०, उदीपी एक समस्या है जो गत ३० वर्षों में काम कर रही है। परन्तु केवल एक बैंक में काम नहीं चल सकता, अतः नई बैंकों की स्थापना आवश्यक है। ये बैंक ऐसे हों जिनके पास दीर्घकालीन विनियोग के लिए पर्याप्त साधन हों। अतः औद्योगिक बैंकों को जन-पूँजी तथा ऋण-पत्रों के निर्गमन से पर्याप्त साधन प्राप्त करने चाहिए तथा इसके अनिरीक्त दीर्घकालीन निक्षेपों में भी। इन बैंकों को केवल औद्योगिक अर्थ-सुविधाएँ ही देनी चाहिए, जिसमें व्यापारिक बैंकिंग तथा औद्योगिक बैंकिंग-क्षेत्र भिन्न रहें।

इतना अथन विनियोग एक ही उद्योग में न करत हुए भिन्न-भिन्न उद्योगों में करने चाहिए, जिससे एक उद्योग के डूबने में उनकी राशि न डूब जाय। अतः हाणि की सम्भावना विभिन्न उद्योगों में राशि विनियोग करने में कम हो सकती है। इस कार्य को ठीक रीति में एवं देश-हित के लिए संचालन करने के हेतु उन्हें अपनी संचालक-सभा में ऐसे संचालक नियुक्त करने चाहिए जिनको देश के विभिन्न उद्योगों का समुचित ज्ञान हो, जिससे उनकी ऋण-नीति सुदृढ़ होकर हाणि की सम्भावना कम रहेगी। इस कार्य के लिए उन्हें विभिन्न उद्योगों की जाँच पड़ताल के लिए विशेषज्ञ रखने चाहिए अथवा उनकी सहायता लेनी

चाहिए। परन्तु हमारे देश में जब तक तान्त्रिक मन्त्राह देने वाली स्वतन्त्र मस्थान नहीं है तब तक उन्हें ऐसे विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी ही होगी।

इसके साथ ही देश की भूमिगत एवं निष्क्रिय पूंजी को निकाल कर उसको विनियोग में लगाने का एवं नये नये विनियोग साधन निर्माण करने का कार्य भी इन्हीं बैंकों को करना होगा जिसमें भारतीय पूंजी गतिशील हो सके। औद्योगिक अर्थ-प्रदाय की कमी का दूर करने के लिए हमारी राष्ट्रीय सरकार ने अनेक मस्थाओं का निर्माण किया है जिसमें उद्योगों का काफी दल मिला है।

### माराग

देश के उपलब्ध साधनों के समुचित उपयोग के लिए औद्योगीकरण होना चाहिए, जिन्हे पर्याप्त आर्थिक सुविधाएँ उपलब्ध होना चाहिए। इनको स्थायी पूंजी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्यशील पूंजी व्यापारिक बैंकों से मिल जाती है परन्तु दीर्घकालीन पूंजी देने वाली मस्थाओं की भारत में कमी है। अतः औद्योगिक बैंकों की आवश्यकता है।

प्रारम्भिक स्थिति में उद्योगों को पूंजी प्राप्त करने के निम्न साधन थे—(१) प्रबन्ध अभिकर्ता, (२) देशी बैंकर, (३) जनता के निक्षेप, (४) अन्न एवं ऋणपत्र, (५) व्यापारिक बैंक। परन्तु प्रबन्ध अभिकर्ताओं का आर्थिक प्रभुत्व, देशी बैंकरों की अधिक व्याज दर एवं सीमित साधन, जनता के निक्षेपों की अविश्वासनीयता एवं व्यापारिक बैंकों के स्वरूप के कारण ये औद्योगिक दीर्घकालीन साधन की पूर्ति नहीं कर सकती। इसलिए इस कमी को दूर करने के दो भाग हैं—(१) औद्योगिक बैंक की स्थापना तथा (२) व्यापारिक बैंकों की कार्य प्रणाली में ऐसे परिवर्तन करना जिससे वे उद्योगों को दीर्घकालीन आर्थिक सुविधाएँ दे सकें। इस हेतु ग्रैंफ समिति ने बैंकों और बीमा कम्पनियों का कनसोर्टियम बनाने की सिफारिश की थी। स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्रीय सरकार ने इस कमी को औद्योगिक वित्त प्रमण्डलों की स्थापना से पूरा किया है।

## औद्योगिक अर्थ-प्रबन्धन-विशेष संस्थाएँ

### (१) भारतीय औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल

केन्द्रीय बैंकिंग समिति ने एक अखिल भारतीय औद्योगिक प्रमण्डल स्थापित करने का प्रस्ताव किया था क्योंकि राज्य औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल उद्योगों की आर्थिक सहायता का कार्य ठीक रीति में नहीं कर सकते। इमोनग देन की निष्क्रिय पूँजी का गतिशील बनाकर देन के उद्योगों की उन्नति के लिए अखिल भारतीय मस्था का होना आवश्यक है जो राज्य अर्थ प्रमण्डल के मान सहयोग करे। इसलिए १९४६ में 'औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल विधेयक' विधान सभा में रखा गया जो फरवरी १९४८ में स्वीकृति हो गया तथा १ जुलाई १९४८ से यह औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल कार्य कर रहा है।

(उद्देश्य—इसका प्रमुख उद्देश्य भारतीय औद्योगिक मस्थाओं को दीर्घ कालीन तथा मध्यकालीन आर्थिक सहायता देना है विशेषतः उम स्थिति में जब उनके माधारण बैंकिंग सुविधाएँ अपर्याप्त हों तथा पूँजी प्राप्त करने के अन्य साधन दुर्लभ हों।)

पूँजी—प्रमण्डल की अधिकतम पूँजी १० करोड़ रुपए है जो ५ हजार रुपए के २० हजार अंशों में है। अंशों की मूल राशि तथा न्यूनतम २.१० वार्षिक लाभान की गारन्टी केन्द्रीय सरकार ने दी है। इनमें से केवल १००० अंशों का निर्गमन हुआ है जो निम्न रीति से बँटवारा के लिए निधारित किए गये थे—

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	१ करोड़ रुपया	२००० अंश
भारत सरकार	१ " "	२००० "
मुंबी बजट बैंक	१०५ " "	२५०० "
बीमा कम्पनी	१०५ " "	२५०० "
महवारी बैंक	०५० " "	१००० "
योग	५०० करोड़ रु०	१०,००० अंश

इसमें से अब पूँजी बीमा कम्पनियां न मरीदी परन्तु महवारी बैंक ने

खरीद मचे । इसलिये उनके बोटे के ७६ अग्र रिजर्व बैंक तथा भारत सरकार ने खरीदे । इससे विपरीत मूची-वृद्ध बैंको से अगो के लिए ३०८५ प्रार्थना-पत्र आये परन्तु उनको केवल २,५०० अग्र ही दिये गये ।

(औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल अधिनियम की धारा ५ के अन्तर्गत उपर्युक्त मन्थानों तथा प्रत्याम एवं अन्य आर्थिक मन्थानों के बीच अगो के हस्तान्तरण पर रोक है ।)

अर्थ प्रमण्डल को अग्रे आर्थिक माधन बढ़ाने के लिए बंध (bonds) बेचने का अधिकार है । नवदुमार डमने जून १९५७ तक ७७० करोड़ रु० के ३ $\frac{3}{4}$ % व्याज देने वाले बंध बेचे । इसी प्रकार नवम्बर १९५७ तथा १९५८ में नमदा ४५७ तथा १९५८ में ४३८ करोड़ रु० के ४ $\frac{3}{4}$ % बंध बेचे । जिससे निगम का बंधों सम्बन्धी दायित्व ३० जून १९५६ के अन्त में १६७५ करोड़ रु० हो गया । अक्टूबर १९५६ में निगम ने ५ करोड़ रु० के ४% बंध पुन निर्गमित किये जिनके लिए ६५३ करोड़ रु० के प्रार्थना पत्र आये ।

निगम ने इन बंधों की राशि में रिजर्व बैंक से लिया हुआ २७६ करोड़ रु० का तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त ५ करोड़ रु० ऋण का भुगतान किया । फिर भी अर्थ-प्रमण्डल ने केन्द्र सरकार से ३ करोड़ रु० का ऋण लिया जिसने ३० जून १९५६ केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण की राशि १३ करोड़ रु० हो गई । अर्थ-प्रमण्डल ने अक्टूबर १९५६ में ५ करोड़ रु० के ४% बारह वर्षीय बंध निर्गमित किये जिनके लिए ६५३ करोड़ रु० के प्रार्थना पत्र आए । इन बंधों की राशि में अर्थ प्रमण्डल केन्द्र सरकार के ऋण के कुल भाग का भुगतान करेगा जिससे अर्थ-प्रमण्डल का व्याज की वृद्धि होगी । इन बंधों के मूलधन एवं व्याज के भुगतान की गारन्टी केन्द्र सरकार ने दी है । १९५७ में भारतीय अर्थ-प्रमण्डल अधिनियम में संशोधन हुआ जिससे वह अपनी चुकता पूँजी एवं निधि के १० गुनी राशि तक ऋण ले सकेगा ।

इस प्रमण्डल के दम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली में तीन कार्यालय हैं एवं एक शाखा मद्रास में है । अन्य स्थानों पर केन्द्रीय सरकार की आज्ञा प्राप्त करने पर शाखाएँ खोली जा सकती हैं । इसका प्रधान कार्यालय दिल्ली में है ।

प्रबन्ध—प्रमण्डल के कार्य का संचालन एवं प्रबन्ध संचालक सभा करती है जिसके १२ संचालक हैं । ३ संचालक तथा १ प्रबन्ध-संचालक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार तथा २ संचालकों की नियुक्ति रिजर्व बैंक करता है । शेष ६ संचालकों का चुनाव वैधानिक असाधारणियों (constitutional shareholders) द्वारा होता है । संचालक सभा की सहायता के लिए एक केन्द्रीय समिति है, जिसके ५ सदस्य हैं । इसमें २ सदस्य केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक के

मनोनीत सचालको द्वारा अशवारियों के सचालको द्वारा चुने जाते हैं। मचा लक-मभा का मभापति गामकीय समिति का मभापति हाता ह जा सका ५वा मदम्य है। प्रमण्यन की सामान्य नीति का मचावन के द्रीय सरकार क आदगा नुमार हाता है। यदि मचालक-मभा इस नीति क अनुमार काय नहीं करती ता के द्रीय सरकार इस मभा क बदल मद मभा की नियुक्ति कर सकती है। मचाक मभा का प्रमण्यन का सफरना क लिए विभिन्न ज्ञाना का विचार करन क लिए मताङ्कार-ममिनिया नियुक्त करन का अधिकार है।

प्रबंध म १६५५ म माावन हुआ है जिसक अनुमार वनमान अवैतनिक मभापति और स्थायी प्रबंध-मचाक क स्थान पर वैतनिक मभापति और जनरल मैनेजर नियुक्त हागा।

सरकार एव रिजर्व बैंक के सचालक किसी भी अवधि तक रह सकते हैं। परन्तु अशवारियों द्वारा चुने हुए सचालको की अवधि ४ वष है। प्रबंध सचालक की नियुक्ति ४ वष के लिए होती है परन्तु उसे फिर नियुक्त किया जा सकता है।

प्रमण्डल के काय—१ प्रमण्यन मावजनिक औद्योगिक कम्पनिया तथा सहकारी ममिनिया को अधिकतम २५ वष के लिए ऋण दे सकता है। इसम जहाजी कम्पनिया का भी मभाव है।

२ प्रमण्यन औद्योगिक कम्पनिया तथा जहाजी कम्पनिया क अग तथा ऋण पत्रादि का अभिगोपन कर सकता है तथा अभिगोपन उत्तरदायित्व के कारण रहन वात अग एव ऋण पत्रादि इसका सम्पति का एक भाग हो सकते हैं। परन्तु इन ऋण-पत्रा तथा अग को ७ वष क अन्दर जनता का वच देना हागा। इसम अधिक अवधि क लिए कार्पोरेशन इट के दाय सरकार की पूव अनुमति म रख सकता है।

३ प्रमण्यन ऋण-पत्रा के वात तथा धूल राशि का गारंटी दे सकता है। यदि ऋण-पत्र तथा ऋणा के भुगतान की अवधि २५ वष से अधिक न हो। इस गारंटी क लिए वह कमीशन देने का अधिकारी हागा।

४ प्रमण्यन का ऋणा उद्योगा की सचालक-मभा म अपना प्रतिनिधि मनानीन करन अथवा ऋण की गुर्वों का उत्पन्न करन पर उस उद्योग का अपन बज म तन का अधिकार है।

५ प्रमण्डल जनता म ५ वष की न्यूनतम अवधि क निशेष स्वीकार कर सकता है परन्तु कभी भी निशेष उसकी चुवता पूजी क दून म अधिक नहीं हाता चाहिए।

६ प्रमण्डल किमी ऋणी औद्योगिक कम्पनी को तान्त्रिक मलाह देने के लिए मलाहकार समितियाँ नियुक्त कर सकती है।

७ अर्थ-प्रमण्डल किमी भी वर्ष में १०% में अधिक लाभान का वितरण नहीं कर सकता। इसमें अधिक जो लाभ होगा वह केन्द्रीय सरकार को मिलेगा।

८ अर्थ-प्रमण्डल को अन्य प्रमण्डलों की तरह आय-कर तथा अतिरिक्त-कर (super-tax) देना होगा। परन्तु केन्द्रीय सरकार में लाभान की गारन्टी के कारण मिलने वाली राशि इन करों में मुक्त रहेगी। केन्द्रीय सरकार की अनुमति बिना अर्थ-प्रमण्डल का समापन (winding-up) नहीं हो सकता।

९ अर्थ-प्रमण्डल रिजर्व बैंक में सरकारी प्रतिभूतियों की जमानत पर अधिकतम १० दिन के लिए ऋण ले सकता है। इसी प्रकार वह अपने ऋण-पत्रा एवं बीडा अथवा अन्य प्रतिभूतियाँ की (जो रिजर्व बैंक चाहे) जमानत पर रिजर्व बैंक में अधिकतम १८ मास के लिए ३ करोड़ ₹० तक या ऋण ले सकता है।

१० अर्थ प्रमण्डल किसी एक उद्योग को अधिकतम १ करोड़ ५० ऋण दे सकता है। परन्तु इसमें अधिक ऋण केन्द्रीय सरकार की जमानत प्राप्त करने पर दिया जा सकता है जिसके लिए कंपेरेशन द्वारा ऋण की स्वीकृति की गिफारिश आवश्यक है।

११ अर्थ-प्रमण्डल सरकार अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक द्वारा भारतीय उद्योगों को दिये हुए ऋणों के निरीक्षण के लिए उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है।

१२ यदि किसी उद्योग की विदेशी मुद्रा में ऋण की आवश्यकता हो तो अर्थ-प्रमण्डल केन्द्रीय सरकार की आज्ञा प्राप्त करने के बाद अन्तर्राष्ट्रीय बैंक अथवा अन्य स्रोतों से ऋण ले सकता है। ऐसी ऋणों की गारन्टी केन्द्रीय सरकार देगी तथा ऐसे विनिमय व्यवहारों में अर्थ-प्रमण्डल को जो हानि होगी उसकी पूर्ति केन्द्रीय सरकार करेगी।

१३ रिजर्व बैंक की मलाह में अर्थ-प्रमण्डल अपनी राशि किसी सूची-बद्ध या सहकारी बैंक के पास निक्षेप में रख सकता है। इस मशोधन में अर्थ प्रमण्डल को अपनी राशि सहकारी प्रतिभूतियों में ही विनियोजित करना आवश्यक नहीं है।

१४ (ब) अर्थ-प्रमण्डल जिस ऋणी उद्योग पर अधिकार करेगा उसकी संचालक मभा पर वह अपने संचालकों की नियुक्ति करेगा तथा ऐसी नियुक्ति होने पर पहिले संचालक अपना पद-त्याग करेगा।

(ब) ऐसे उद्योगों का प्रवन्ध अधिकर्ता के माथ जो सम्भव है होगा उसका बिना किसी हानि-पूर्ति के अन्त हो जायगा।

(ग) असाधारण व मनोनीत मन्त्रालयों की नियुक्ति स्वयं निरन्त हो जायगी।

(द) असाधारण्य द्वारा स्वीकृत कोई भी प्रस्ताव अर्थ-प्रमण्डल की अनुमति बिना स्वीकृत नहीं होगा।

(ध) ऐसे उद्योगों का समापन अथ प्रमण्डल की अनुमति बिना नहीं हो सकेगा।

१४ अर्थ प्रमण्डल अपनी स्थायी पूँजी के हेतु उसकी चुनना पूँजी एक मन्त्रिण निधि के १० गुनें तक ऋण ले सकता है।

१५ अर्थ प्रमण्डल आयातकर्त्ताओं के स्थगित भुगतान के लिए गारन्टी दे सकता है, यदि आयातकर्त्ताओं ने विदेशी निर्माताओं के माथ एसी व्यवस्था की है।

१७ अर्थ प्रमण्डल को केन्द्रीय सरकार से ऋण लेने का अधिकार है। इसी प्रकार उसके पास रहन रखी हुई सम्पत्ति की अर्थ प्रमण्डल मद पर दे सकेगा।

**ऋण देने की शर्तें—**औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल किसी सीमित मावज्जनिक कंपनी जहाँगी कंपनी तथा नृकारी समितियों का जो वस्तुओं का निमाण अथवा वस्तुओं का क्रिया कलाप (processing) करती है अथवा उद्योग करती है अथवा विद्युत का निर्माण एवं वितरण तथा अन्य किसी प्रकार की शक्ति का निर्माण एवं वितरण करती हो तथा जिसका कार्य-क्षेत्र औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल विधान द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र में हो—ऋण दे सकता है। ऋण देने की शर्तें निम्न हैं—

(अ) ऋण विवशपन स्थायी एवं अचल सम्पत्ति खरीदने के लिए ही, एवं अचल सम्पत्ति ही, जैसे भूगृहादि, यन्त्रसम्पन्न आदि के प्रथम रहन पर दिया जाता है। नियमानुसार यह प्रमण्डल बच्चे या पक्के माल के उप प्राप्ति पर (hypothecation) पर वापसी पूँजी के लिए ऋण नहीं देता। क्योंकि यह वापसी व्यापारिक वेश का है, जिनमें यह प्रतिपादिता नहीं करना चाहता।

(ब) दिए हुए ऋण का समुचित प्रवन्ध तथा व्यवहारे इस हेतु ऋण की व्ययति तथा सामूहिक गारन्टी औद्योगिक मस्या के मन्त्रालयों से उनकी वैयक्तिक स्थिति में ली जाती है।

- (म) अर्थ-प्रमण्डल ऋणी उद्योग की मंचालक-मभा में दो मंचालकों की नियुक्ति कर सकता है जिसमें उद्योग के प्रबन्ध का निरीक्षण करे तथा देवे कि अर्थ-प्रमण्डल व हित में ही उसकी व्यवस्था हो रही है।
- (द) ऋणी औद्योगिक-प्रमण्डल उद्योगिकीय वर्गों में होने वाले लाभ का लाभान्वेदन में ही वितरण न करे, इसलिए जब तक ऋण का भुगतान नहीं हो जाता तब तक वह ६% में अधिक वार्षिक लाभान्वेदन नहीं दे सकेगा। परन्तु इस दर में दोना की सम्पत्ति में परिवर्तन हो सकता है।
- (प) ऋण-भुगतान की अवधि सामान्यतः १२ वर्ष है, परन्तु अधिकतम १५ वर्ष के लिए ऋण दिये गये हैं। ऋण-भुगतान की अवधि ऋणी कम्पनी के व्यापारिक स्वरूप एवं उसके भविष्य के अनुसार निश्चित की जाती है।
- (क) ऋणा का भुगतान सामान्यतः समान स्थितियों में होना चाहिए, परन्तु विशिष्ट कितनी होगी यह दोना की सम्पत्ति में निश्चित होता है।
- (ग) रहन-सम्पत्ति की, जिस पर ऋण प्राप्त किया जाता है, अग्नि, साम्प्र-वायिक कलहों, विद्रोह आदि में सुरक्षा के लिए किसी अच्छे बीमा कम्पनी से बीमा कराना अनिवार्य है।
- (ह) अर्थ-प्रमण्डल जब ऋण राशि उद्योग का दे देता है तब यह देगने के लिए कि ऋण-राशि जिन कार्यों के लिए ली गई है उसी के लिए उसका उपयोग हो रहा है, आवश्यक कदम उठाता है। इस हेतु उद्योग की योजनाओं का सामयिक निरीक्षण भी किया जाता है।

### प्रमण्डल की क्रियाएँ

भारतीय औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल ने ३० जून १९५६ को ११ वर्ष पूरे किये। इस अवधि में अर्थ प्रमण्डल ने विभिन्न उद्योगों को ६६६६ करोड़ ₹० के ऋण स्वीकृत किये। ३० जून १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में १११६ करोड़ ₹० ऋण के लिए २६ आवेदन आये जिनमें से ११ आवेदकों को ३७६ करोड़ ₹० के ऋण स्वीकृत किये गये जब कि १९५७-५८ वर्ष में १४८८ करोड़ ₹० ऋण के लिए ४८ आवेदनों में से २२ आवेदकों को ७७८ करोड़ ₹० के ऋण स्वीकृत किये गये थे। कुल स्वीकृत ऋणा में से ४२३२ करोड़ ₹० के ऋणों का वितरण ३० जून १९५६ तक किया गया था। १९५८-५९ वर्ष में ७४८ करोड़ ₹० की ऋण राशि का वास्तविक वितरण हुआ जब कि १९५७-५८ में ८३३ करोड़ ₹० का वितरण हुआ था। इस वर्ष कालगत (lapsing) अवधि वापिस किये गये आवेदनों की संख्या अधिक रही तथा ११७१ करोड़ ₹० ऋण के आवेदन वर्ष के अन्त में विचारार्थ थे। निगम में प्रमुख त्रिधा में इस त्रुटि का कारण ऋण प्रदायक राशि का अभाव न होने हुए विदेशों से पूँजीगत एवं अन्य साधन के आयात पर कठोर नियंत्रण होना है। गत वर्षों की भाँति

इस वर्ष भी अथ प्रमण्डल ने अदिकाय ऋण नय उद्योग का स्वीकृत किया, जिनका राजि २८ कराड २० हे जब कि जप ७५५ कराड पूव स्थापित उद्योग का दिय गय ।

ऋण क औद्योगिक वितरण की कल्पना निम्न तालिका म हागी —

उद्योग	स्वीकृत ऋण (लात रुपया म)		
	३० जून १९५८ तक	३० जून १९५८ का समाप्त हान वान वष म	योग
लाच (Food) पय को छोडकर	१२००००	१४५००	२०७२००
टक्स्टाइल	२०७७५	६४००	२७२७५
बनावटी रत	११०००	—	११०००
मकड़ी और काक	३०००	—	३०००
कागज और कागजी उत्पादन	५७५०	—	५७५०
खर उत्पादन	५०५०	—	५०५०
आधारभूत औद्योगिक रसायन	७६६००	—	७६६००
वनस्पति एवं पशु तल तथा चरवी	११००	—	११००
विविध रसायनिक उत्पादन	७७५	—	७७५
काच एवं काच उत्पादन	१२७५०	—	१२७५०
पाटरी चीनी एवं चीनी क वस्तु	६४५	—	६६२५
सीमट	५०७००	११०००	६१७००
लाहा एवं उत्पात	२३००	—	२३००
अलाह धानु	११०००	—	११७००
धानु उत्पादन	२५७५०	२५०	२६०००
यंत्र (विद्युत यंत्र छोडकर)	१४०५०	—	१४२५०
विद्युत यंत्र एवं औजार आदि	१७५७०	६००	१८१७०
रल-संक सामग्री	५०००	५०००	७०००
मोटर गाडिया आदि	१५००	—	१६५००
साइकिल	५०५०	—	५०५०
विविध निमाण उद्योग	४३००	—	४३३०
विद्युत प्रकाश एवं शक्ति	८०५	—	८२७५
योग	२२०००	३७८००	६०६८००

महकारी समितिया का विनयत मकर महकारी समितिया का अथ-प्रमण्डल न विनय सुविधाएँ दी । इस वष क कुल ऋण म १७० कराड २० क ६ ऋण महकारी समितिया को दिय गय जिनम म १६५ कराड २० क ३ ऋण मकर समितिया का तथा २५ लाख ८० का १ ऋण युनकर महकारी समिति का दिया गया । इस प्रकार ३० जून १९५६ तक मकर महकारी समितिया का १४ ३ कराड २० ने ऋण दिय गय । इन ऋण की गारन्टी सम्बन्धित राज्य सरकारान दी है ।

अर्थ-प्रमण्डल ने दिसम्बर १९५७ में औद्योगिक संस्थाओं की ओर से पूंजीगत माल के विदेशी निर्माताओं को स्थगित भुगतान की गारन्टी देने का नया क्षेत्र अपनाया है। इस हेतु निगम के पास पहिले ६ मास में ५ २४ करोड़ रु० के लिए आवेदन आये, जिनमें ३ ९६ करोड़ रु० के आवेदन स्वीकृत किये। इसी हेतु २० जून १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में १६ ५१ करोड़ रु० की गारन्टी के लिए आवेदन आये जिनमें से २५ लाख रु० के स्वीकृत किये गये। ५ १४ करोड़ रु० के आवेदन पर वापिस लिये गये या व्यतीत (lapsed) हुए तथा १२ ३० करोड़ रु० के विचारार्थ थे। इसके लिए प्रमुख कारण विदेशी विनिमय की दुर्लभता के कारण कठोर आयात नियन्त्रण है।

निगम ने १९५७-५८ वर्ष में प्रतिभूतियाँ का अभिगोपन करना भी आरम्भ किया, जब उसने अपनी ऋणी कम्पनी के १ ६० करोड़ रु० के ६ ३% ऋणपत्रों का अभिगोपन किया। फलस्वरूप इस सम्बन्ध में अर्थ प्रमण्डल का उत्तरदायित्व ७५ लाख रु० का है। ३० जून १९५९ को समाप्त होने वाले वर्ष में अर्थ-प्रमण्डल ने ५० लाख रुपये के पूर्वाधिकार अंशों का अभिगोपन किया, फलस्वरूप निगम का अभिगोपन उत्तरदायित्व ३७ ५० लाख रुपए का था। परन्तु कॉर्पोरेशन को इन अंशों का कोई भाग नहीं लेना पड़ा। इसी वर्ष में ५० लाख रुपए के पूर्वाधिकार अंशों का दूसरा अभिगोपन कॉर्पोरेशन ने किया। इनमें से पहिला अभिगोपन औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, जीवन बीमा निगम एवं अर्थ-प्रमण्डल ने संयुक्त रूप से किया था। इस प्रकार कॉर्पोरेशन ने अभी तक १ ६२ करोड़ रु० के अंशों का अभिगोपन किया।

### ऋणों का प्रांतीय वितरण

राज्य	३० जून १९५८ तक इकाइयों की संख्या	राशि (लाख रु०)	३० जून १९५९ तक इकाइयों की संख्या	राशि (लाख रु०)
बम्बई	५८	१८६९ ६५	५९	१९४९ ६५
मद्रास	१९	८५७ ००	२२	९४७ ००
प० बंगाल	२७	६३३ ५०	२७	६३३ ५०
उत्तर प्रदेश	१४	५०० ६०	१५	५६० ६०
मैसूर	१७	४८० ००	१७	५०६ ००
बिहार	१०	४७७ ७५	१२	४९७ ७५
केरल	६	४२७ ५०	६	४२७ ५०
उड़ीसा	५	२९४ ००	५	३७७ ००
आंध्र	१०	३१० ५०	१०	३१० ५०
गुजरात	११	२९६ ५०	११	३०१ ५०
राजस्थान	३	७४ ५०	३	७४ ५०
आसाम	१	४५ ००	१	६० ००
दिल्ली	१	२० ००	१	२० ००
मध्यप्रदेश	१	३ ५०	१	३ ५०
योग	१८५	६२९० ००	१९०	६६६९ ००

## आर्थिक परिणाम

इस वर्ष में निगम का ७३ ०८ लाख रुपए का लाभ हुआ जो गत वर्ष की अपेक्षा १४ ८३ लाख ०० अधिक रहा। इसमें स्पष्ट है कि निगम की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। गत ४ वर्षों के आर्थिक परिणामों से इसकी कल्पना होगी —

(ताब रुपय में)

३० जन का समाप्त होने वाला वर्ष में				
	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९
अजित व्याज	६७ १६	६५ २३	१५४ ३०	२०० ०५
अन्य आय	० ४०	० ६०	० ५४	३ ८३
व्याज विमा	२६ ६८	४६ १७	८६ ८५	११५ ७५
अन्य व्यय	८ ८२	८ ८६	८ ६८	१० २६
अवमूल्यन	० १०	० १३	० १४	० १८
लाभ	३२ ६८	६३ ०	१८ २५	७३ ०८
आयाजिन—आय कर क हनु	१० १८	८५	२१ २१	३७ ७१
मदिराज ऋणा के लिए	२२ १०	१ ४५	—	—
अपरिमित धन तय दलाली	—	—	४ ८३	४ ६४
(बधा क निगमिन पर)	—	—	—	—
मयागिक काप	—	१ ००	—	—
सचित कोप	—	—	११ ५०	१४ १२
भरकार में प्राप्त महायता	११ ४५	—	—	—
महायता राशि की वापसी	—	—	१ ४५	१० ००
लाभान	११ २५	११ ५५	११ २५	११ २५
	(२१०%)	(२१०%)	(२१०%)	(२१०%)
प्राधानापना की ऋणराशि	७७७० ०२	१३६ २५	१४८५ ५०	१११६ ५७
स्वीकृत ऋणराशि	१५१३ ००	११८० ७५	७७८ ५०	३७६ ००
वितरित ऋणराशि	२२० २०	६७७ ५०	८३३ ३५	७७७ ७१

अर्थ प्रमण्डल की आलोचना—अर्थ प्रमण्डल न यद्यपि दस के उद्घाटन का दीवकालीन ऋण प्रदाय से दस व अधिक कालवर की एक बहुत बड़ी कमी का दर किया है फिर भी इसमें विराघ में कुछ आक्षेप है —

(१) अर्थ प्रमण्डल की व्याज दर ऊँची है।

अर्थ प्रमण्डल फरवरी १९५० तक ५.१०% व्याज लेता था। १९५१ में वह दर बढ़ जाने से अर्थ प्रमण्डल ने अपनी व्याज-दर ६.०% की। १९५२-५४ में व्याज की दर ६.१०% तथा २३ अप्रैल १९५७ से ७.०% की। परन्तु विरत

एवं व्याज का समयानुसार भुगतान हान पर अथ प्रमण्डल इस दर में १% की छूट देता है।

वास्तव में देखा जाय तो व्याज दर मुद्रा मण्डी की स्थिति पर निर्भर रहती है। आजकल जब रिजर्व बैंक साग पर नियंत्रण कर रहा है, ऐसी दशा में व्याज दर वास्तव में देखा जाय तो अधिक नहीं है।

(२) अथ प्रमण्डल बायसीन पूँजी की अपेक्षा अधिक राशि के ऋण स्वीकार करता है। यह आर्थिक मिद्धाता व विरुद्ध है जिसमें अथ प्रमण्डल किसी भी समय खतर में पड़ सकता है।

(३) स्वीकृत ऋणा की लगभग ३०% राशि ऋणी उद्योगों में नहीं पायी। इससे अथ प्रमण्डल को व्याज की हानि होती है।

किंतु अब अथ प्रमण्डल का रिजर्व बैंक में ऋण बन का अधिकार है जिससे उसका स्वीकृत ऋणा का भुगतान करने के लिए अधिक राशि रखने की आवश्यकता नहीं रही।

(४) अथ प्रमण्डल की ऋण नीति पम्पपातपूर्ण है क्योंकि अथ प्रमण्डल ने सम्बन्धित राज्य को सबसे अधिक ऋण दिये हैं। वास्तव में भारत में न उद्योगों का और न पूँजी का एक ही राज्य में केन्द्रीकरण होना चाहिए अपितु इनका सम्पूर्ण देश में समान रूप से वितरण होना चाहिए। आशा है कि भविष्य में अथ प्रमण्डल इन त्रुटियों का निवारण करेगा।

(५) यह भी आश्चर्य उगाया जाता है कि ऋण स्वीकार करने में अथ प्रमण्डल बहुत समय लेता है।

अतः इस गिकायत को दूर करने के लिए अथ प्रमण्डल ने १९५७ में वित्तीय शाखा खोली है जिससे ऋणों के वितरण एवं स्वीकार करने में विनम्र न होगा।

(६) ऋण को स्वीकार करने के पूर्व अथ प्रमण्डल प्रबंध अधिकर्ता अथवा सचाराको की व्यक्तिगत जमानत मांगता है।

परंतु वास्तव में यह इसलिए किया जाता है जिसमें ऋणों का समुचित उपयोग औद्योगिक विकास के लिए हो।

अथ प्रमण्डल की कठिनाइयाँ—प्रारम्भिक वर्षों में अथ प्रमण्डल को अपनी क्रियाओं में भारत के दोषपूर्ण औद्योगिक कलेवर के कारण अनेक बाधाएँ रही। ये कठिनाइयाँ निम्न थीं।

(१) अथ प्रमण्डल को आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए उद्योगों

की भावी याजनाआ का पूर्ण विवरण आवश्यक होता है जो अनक उद्यागा द्वारा नहीं दिया जाता ।

(२) अनक कम्पनिया की स्थायी सम्पत्ति व रहन म कठिनाइयाँ उप स्थित हानी है ।

(३) अनेक आवदना व साथ जो याजनाएँ आती है व पूर्ण एवं समुचित तान्त्रिक सलाह म नहीं बनाई जागा और यन्त्र आदि की अनुमानित कीमत तथा याजना की पूर्ति व आवश्यक साधन नहीं दिय जान ।

(४) अनक कम्पनिया के पास पर्याप्त कायगील पजी नहीं हानी जिसम उनके पास भावी याजनाआ की पूर्ति व लिए पर्याप्त साधन नहीं हान ।

(५) एम अनक उद्याग है जा ऋण स्वीकृत हा जान पर भी वधानिक कायवाहिया की पूर्ति नहीं करन जैम यन्त्र आदि व आयात व लिए त्राडमम अथवा नियन्त्रित वस्तुआ व परमिट वना आदि ।

(६) कुछ दशाआ म सरकार उद्यागा का प्रत्यक्ष भ्रण होती है । एसा हान म अथ प्रमण्डल का कठिनाइ होती है ।

अन उद्यागा को इन कठिनाइया व निवारण व लिए प्रयत्नगील हाना चाहिए जिसम अथ प्रमण्डल उनक लिए अधिक उपयोगी हो मके । राज्य अथ प्रमण्डल और भारतीय अथ प्रमण्डल की नियाएँ प्रतियोपी न होन व उद्योग म दानो का काय भ्रण पृथक किया गया है जिसक अनुसार राज्य अथ प्रमण्डल अधिकतम १० लाख ८० अथवा अपनी चुकना पूजी क १०% तक ऋणा क आवदन स्वीकृत कर सकगा ।

## (२) राज्य औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल

भारतीय औद्योगिक अथ प्रमण्डल (I F C) विनयत बडेन्द्र उद्यागा का आर्थिक सहायता दता है और वह कवन लाख-मीमित कम्पनिया का ही ऋण दता है । विन्नु बहुमुखी औद्योगिक प्रगति क लिए यह आवश्यक था कि साम्प्रदारी निजी कम्पनियाँ तथा अन्य छोटे एवं मध्यम उद्योगा का आर्थिक सहायता मिलन का पर्याप्त प्रबन्ध हो । इसा हेतु अप्रैल १८५१ म प्रांतीय औद्योगिक अथ प्रमण्डल विषयक समद म प्रस्तुत हुआ जा अक्टूबर १८५१ म स्वीकृत हा गया है । यह अधिनियम केवल उन्ही राज्या का लागू हागा जिनक नाम भारत सरकार की सूचना म प्रकाशित हाम । अथान् कोई भी राज्य जिनका नाम सरकारी सूचना म प्रकाशित हा जाना है और औद्योगिक आर्थिक आवश्यकताआ का विचार करन पर उस राज्य का यह विश्वास हाना है कि

वहाँ अर्थ-प्रमण्डल की स्थापना हो, तो वहाँ स्थापना हो सकती है। इसकी पूंजी एवं कार्य अधिनियम के अनुसार निम्न है —

**पूंजी**—राज्य अर्थ-प्रमण्डल की पूंजी ५०,००० रु० से ५ करोड़ रु० तक होगी। यह पूंजी राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, मूचीयुद्ध बैंक, बीमा-कम्पनी, विनियोग प्रत्यास (Investment trusts), सहकारी बैंक एवं अन्य आर्थिक संस्थाओं द्वारा दी जायगी। पूंजी का २५% भाग केन्द्रीय सरकार की पूर्व-अनुमति से जनता को निर्गमित किया जा सकता है एवं इसका हस्तान्तरण स्वतन्त्रता से हो सकता है। शेष ७५% भाग का हस्तान्तरण उपरोक्त आर्थिक संस्थाओं तक ही सीमित रहेगा। पूंजी एवं लाभान्न की गारन्टी राज्य सरकार देगी।

**प्रबन्ध**—उनका प्रबन्ध सचालक सभा द्वारा होगा जिसकी नियुक्ति निम्न-वत् होगी —

- |                                                                            |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| (१) प्रांतीय सरकार के मनोनीत सचालक                                         | ... | ३ |
| (२) रिजर्व बैंक के मनोनीत सचालक                                            | ... | १ |
| (३) भारतीय औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल का मनोनीत सचालक                          |     | १ |
| (४) अग्रधारी आर्थिक संस्थाओं द्वारा चुने हुए सचालक                         |     | ३ |
| (इनमें से १ मूचीयुद्ध बैंक तथा १ सहकारी बैंक द्वारा चुना जायगा)            |     |   |
| (५) अग्रधारी जनता द्वारा निर्वाचित सचालक                                   | ..  | १ |
| (६) प्रबन्ध सचालक (इसकी नियुक्ति सचालक सभा की अनुमति से राज्य सरकार करेगी) |     | १ |

प्रत्येक चुन हुए सचालक की अवधि ४ वर्ष होगी। सचालक-सभा की सहायता के लिए एक शासकीय समिति (executive committee) होगी जिसका सभापति प्रबन्ध-सचालक होगा तथा तीन और सदस्य होंगे। इनमें से दो सदस्य मनोनीत सचालकों द्वारा चुने जायेंगे तथा एक चुन हुए सचालकों द्वारा। सचालक सभा को कार्य की सुविधा के लिए सलाहकार समितियाँ नियुक्त करने का अधिकार है।

**प्रमण्डल के कार्य**—(१) औद्योगिक संस्थाओं द्वारा जनता के लिए गये अधिकतम २० वर्ष के ऋणों की जमानत देना।

(२) औद्योगिक संस्थाओं के निर्गमित अंशों एवं ऋण-पत्रों का अभिगोपन करना।

(३) अभिगोपन अनुबन्धों के कारण जो ऋण-पत्र अथवा अंश जनता को न बिक सकें उनको अधिकतम ७ वर्ष में वचना।

(४) औद्योगिक मस्यासा का अधिकतम २० वर्ष के लिए ऋण दत्ता एवं उनका २० वर्ष में दस ऋण पत्रों को खरीदना।

(५) ये अथ प्रमण्डल उपरोक्त कार्यों के अन्तर्गत तब तब ऋण नहीं दे सकत जब तक उन ऋणा के लिए गारन्टरी अथवा अन्य प्रतिभूतियां स्वयं चल यथवा अचल सम्पत्ति जमानत के लिए बचक अथवा गृहन न की जाय।

निविद्ध बाध—(१) किसी भी औद्योगिक प्रमण्डल का १० लाख रुपये से अधिक ऋण दत्त।

(२) किसी भी औद्योगिक प्रमण्डल की प्रतिभूतियां का खरीदना।

(३) जनता से पांच वर्षों में कम अवधि के निभण पत्रों का दत्त।

(४) अपने अग्रे की जमानत पर ऋण दत्त।

राज्य अथ प्रमण्डल की नियाजा की कम्पना अगल पृष्ठ की तानिका में होगी।

### (३) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास-निगम

(National Industrial Development Corporation)

भारत में बहुत दिनों से इस निगम के स्थापना की चर्चा हो रही थी। इसकी स्थापना दिल्ली में २० अक्टूबर १९५४ का हुआ है। यह निगम पूरा रूप से सरकारी स्वामित्व में नियन्त्रण में है परन्तु इसकी रजिस्ट्री भारत की प्रमण्डल अधिनियम के अन्तर्गत की गई है। यह निगम औद्योगिक विकास, आधारभूत एवं प्रमुख सहायक उद्योगों की स्थापना के हेतु आवश्यक तान्त्रिक एवं इंजीनियरिंग अनुभव प्राप्त करने में निजी उपक्रमों का सहयोग लाता है। यह सहकारिता इसी दृष्टि में प्राप्त की जा रही है क्योंकि देश को औद्योगिक विकास की तात्पर्य आवश्यकता है और उपभोक्ता उद्योगों में निजी उपक्रमों का बहुत कुछ कार्य किया है एवं वे देश की भावी भाग का भाग सफलता से पूरा कर सकत हैं। परन्तु आधारभूत एवं प्रमुख सहायक उद्योगों में अलग दृष्टिकोण आवश्यक होता है निगम निजी उपक्रमों सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकत अपितु अपने अनुभव में सहायता दे सकत हैं। अतः इस उद्योगों की स्थापना का कार्य यह निगम करेगा जिनमें तान्त्रिक इंजीनियरिंग एवं औद्योगिक अनुभव का लाभ लेने के लिए निजी उपक्रमों का सहयोग आवश्यक होगा।

पूँजी—औद्योगिक विकास निगम की अधिकृत पूँजी १ करोड़ रुपये है तथा चुकता पूँजी १० लाख रुपये है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ली गई है। इस निगम का प्रमुख कार्यालय दिल्ली में है तथा यह भारतीय प्रमण्डल अधि

प्रान्तीय औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डलो की खियाएँ (३१-३-५७ तक)

५५

मुद्रा, विनिमय एवं अधिकापण

नाम	स्थापना निधि	चुक्ता पूँजी [लाय श०]	३१ ३ ५७ को अप्राप्य रु०	कुल नाम	शासकीय व्यय	गुट नाम	गारटीड याभारा देने हुनु प्राप्त सरकारी सहायता	कुल सरकारी सहायता
१ वेस्ट बंगाल पिनाशल कार्पोरेशन	१- ३ ५४	१००	३४६६१०२	४१८५६७	१२१६०२	२६३२६५	२१६०३५	५८६१११
२ पंजाब	१ २ १३	१००	१६७७६८	५०३१७७	१३३११०	३७०६६१	१२९५३८	२४२०६६
३ बाम्बे स्टेट <sup>१</sup>	३० ११ ५३	२००	१५१०२५००	६२६५५८	१८८६५४	७३८१३६	३११५८१	३३६८८१
४ आंध्र प्रदेश स्टेट <sup>२</sup>	१३ २ १६	१५०	८०३०८१	५१२२६७	११६६६३	४३५७२६	२६५४७६	७०३७४६
५ आसाम	१६- ६ ५४	१००	३६८८६६८	८८६१४३	८०१६८	५६७९७१	१५७०२५	४११३४०
६ ही करन	२३-११-१३	१००	८३६०२३१	१८६११८	१७७०४	६८८८१६	१९३८१	३६४०२६
७ राजस्थान	१७- १ १५	१००	६०५०००	३७८७१७	६२२७६	३१६६४१	१८८०५६	३६८०१३
८ बिहार	२ ११-५४	५०	२३८६०००	१६६६८८	६३४८२	१०६२२६	१४३०००	३०७४४४
९ उत्तर प्रदेश	२१- ८ ५८	१००	१७६६०२४	३१३४८६	६०५६१	२२३३२२१	२३३२९६	३७४०४२
१० मध्य प्रदेश	२६- १ ५५	१००	५१००००	३०१८४२	६७०६६	२३४१६३	२१५८१४	२४६७३३

- १ राज्यो के पुनगठन के कारण बम्बई और सोराष्ट्र के प्रान्तीय अर्थ प्रमण्डला का पुंकीकरण हो गया है।
- २ आंध्र और हैदराबाद राज्य के दोना प्रान्तीय प्रमण्डला क पुंकीकरण से निर्मित।

नियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। इस निगम को अपनी क्रियाओं के लिए जा अन्य राशि आवश्यक होगी वह केन्द्रीय सरकार निम्न रीति में देगी—

(क) औद्योगिक योजनाओं का अध्ययन, अनुसन्धान एवं औद्योगिक निर्माण के लिए नया ऐसी ही अन्य औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए देश में आवश्यक तान्त्रिक एवं प्रशासकीय व्यक्तियों का दल (corps) तैयार करने के हेतु वार्षिक अनुदान (grants) द्वारा अनुदान की राशि का आयोजन वार्षिक बजट में होगा। १९२८-५५ के पूरक बजट में ५ करोड़ रुपए का आयोजन था।

(ख) औद्योगिक विकास निगम की प्रस्तावित औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यकता के समय ऋण देकर।

(ग) इसके सिवा निगम को अपनी कार्यशील पूँजी बढ़ाने के लिए अग एवं ऋण-पत्रों के निर्गमन का अधिकार है।<sup>१</sup>  
बम्बई राज्य द्वारा नया कदम

बम्बई राज्य ने बम्बई राज्य अर्थ-प्रमण्डल के साथ एक नया समझौता किया है जिसके अन्तर्गत राज्य अर्थ-प्रमण्डल १०,००० रु० में ७५,००० रु० तक के ऋण दे सकता है एवं उनका वितरण कर सकता है। अर्थ-प्रमण्डल अपवाद-रतम बनाया में एक ही औद्योगिक इकाई को १ लाख रु० तक ऋण दे सकेगा। राज्य अर्थ-प्रमण्डल द्वारा ये ऋण राज्य-औद्योगिक महायन्त्र अधिनियम के अन्तर्गत दिए जायेंगे। इस हेतु सरकार अर्थ-प्रमण्डल के लिए एक समय में ५ लाख रु० की राशि का आयोजन करेगी जिसके वितरण के बाद उसका विन्यास पुन होगा। परन्तु किसी भी दशा में बजट में आयोजित राशि में अधिक राशि इस हेतु उपलब्ध न हो सकेगी। इन ऋणों की स्वीकृति एवं वितरण में बम्बई राज्य निगम लघु उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में सरकारी नियमों एवं मिष्ठान्तों का पालन करेगा।

ऋण आवेदनों पर विचार करने समय अर्थ प्रमण्डल निम्न आधार पर प्राथमिकता देगा —

- १ ६०,००० रु० से कम राशि के ऋण-आवेदन।
- २ अहमदाबाद तथा बृहन् बम्बई के औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर के आवेदन।
- ३ ऐसे पक्षों के आवेदन जिन्हें तुलनात्मक आधार पर ऋण की अधिक आवश्यकता है तथा जिनके साधन कम हैं।
- ४ प्रमुख निश्चित सम्पत्ति का निर्माण करने के हेतु प्राप्त ऋण आवेदन।

<sup>१</sup> Report of R. B. I. on Currency & Finance, 1931-35.

५. ऐसे पक्षों के ऋण-आवेदन जो अल्पविधि में लगाई गई शर्तों की पूर्ति कर सकते हों।

बम्बई राज्य अर्थ-प्रमण्डल इन ऋणों की १०,००० से ४०,००० रु० राशि तक ३<sup>१</sup>/<sub>०</sub> तथा ५०,००० से १ लाख रु० के ऋणों पर ५% श्याज लेगा। समझौते की शर्तों के अनुसार ऋणों के वापसी की जिम्मेवारी कॉर्पोरेशन पर होगी किन्तु मुफ्फिमल क्षेत्रों में ऋणी सरकारी स्वत्वानों में ऋणों की वित्त देकर चालान कॉर्पोरेशन को भेज सकेंगे। अर्थ-प्रमण्डल पर बम्बई राज्य द्वारा प्रितरित ८,७५,००० तथा इस वर्ष वितरित होने वाले १३ लाख रु० ऋण के धमूली की जिम्मेवारी भी है। इस समझौते के अन्तर्गत बम्बई राज्य अर्थ-प्रमण्डल बम्बई राज्य शासन के अभिवर्तों का कार्य करेगा।<sup>१</sup>

इसी प्रकार की नीति यदि अन्य राज्य भी अपनावे तो निश्चय ही राज्य अर्थ-प्रमण्डलों की उपयोगिता बढ़ेगी तथा क्रियावा का दुहुरापन न रहेगा।

इस प्रकार औद्योगिक विकास के लिए ऋण एवं अनुदान द्वारा आवश्यक राशि सरकार देगी, जिससे यह निगम बिना आर्थिक रुकावटों के अपना कार्य कर सकेगा। अभी तक देश के औद्योगीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ आर्थिक ही रही हैं।

उद्देश्य—(१) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रमुख उद्देश्य देश की औद्योगिक उन्नति के लिए आवश्यक यन्त्र-सम्पन्न, औजार आदि प्रदान करना तथा आधारभूत एवं प्रमुख सहायक उद्योगों के प्रवर्तन एवं स्थापन में प्राथमिकता देना है।

(२) देश के औद्योगिक विकास में सहायक वर्तमान निजी उद्योगों को तान्त्रिक एवं इंजीनियरिंग सेवाओं की सुविधा देना, तथा यदि आवश्यक हो तो पूंजी देना, फिर वह उद्योग भले ही निजी उपक्रमियों के नियन्त्रण में हो।

(३) सरकार द्वारा स्वीकृत निजी उपक्रमियों की औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक तान्त्रिक, इंजीनियरिंग, आर्थिक अथवा अन्य सुविधाएँ प्रदान करना।

(४) प्रस्तावित औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए

(क) आवश्यक अध्ययन एवं अनुसंधान करना,

(ख) उनको तान्त्रिक, इंजीनियरिंग एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करना, तथा

(ग) उनकी पूर्ति के लिए विनियोग राशि देना।

इस प्रकार औद्योगिक विकास निगम का तत्त्व देश के मृदुल औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण में सरकार के साधन या अभिकर्ता के रूप में कार्य करना है जिसमें देश का औद्योगिक विकास तीव्र गति में हो सके ।

प्रबंध — राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम का प्रबंध एक मन्त्रालय सभा करेगी । इसके २० सदस्य हों तथा सभापति वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हों । सचालका को मनोनीत करने का अधिकार केन्द्र सरकार का है । औद्योगिक अनुभव तांत्रिक एवं इंजीनियरिंग कार्यक्षमता की दृष्टि से मन्त्रालय-सभा में १० उद्योगपति ५ अधिकारी (officials) तथा ४ इंजीनियर हैं । इस प्रकार इसका प्रबंध प्रबंध अभिकर्ता द्वारा न होता हुए सचालक सभा द्वारा होता है ।<sup>१</sup>

क्रियाएँ—२२ अक्टूबर १९५४ को निगम की सचालक सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें निम्न उद्योगों का विचार अध्ययन करने का निश्चय किया गया—

(१) जट रई वस्त्र तैयार करके बाजार में सस्ते रसायन उत्पाद बनाने का निर्माण एवं शक्तिशाली आवागमन आदि उद्योगों के लिए आवश्यक आधारभूत यंत्र सामग्री का निर्माण एवं उत्पादन ।

(२) कुछ विचार उद्योगों का अध्ययन ।

(३) वर्तमान समय में जो आधारभूत उद्योग निजी उपक्रम में हैं उनमें यह निगम काम करने में नहीं करेगा और न उनके साथ प्रतियोगिता ही करेगा । उदाहरणार्थ अयुमिनियम फरो मंगनाज आदि ।

(४) सचालक सभा ने इस तथ्य का भी स्वाकार किया कि देश में औद्योगिक विकास के लिए इंजीनियरों तथा तांत्रिक विशेषज्ञों का अभाव है । इसलिए एक विशेष इंजीनियरिंग फर्म (consulting engineers) का कामाचार यह स्थापित किया जाय जो उद्योगों के तांत्रिक समस्याओं का कार्य करे ।

(५) औद्योगिक विकास निगम को तांत्रिक एवं इंजीनियरिंग यांत्रिक सामग्री के डिजाइन नीति-नियम आदि के सम्बन्ध में सहायक देने के लिए ३४

<sup>१</sup> Modern Review November 1954

<sup>२</sup> क्रियाएँ—औद्योगिक मन्त्रालय पृष्ठ १० एवं ११ गीतवचन ।

<sup>३</sup> यह उद्योग है—मिथुन-नाम मंगनीज फरोमोम अयुमिनियम तथा जस्ता बनाई घात डीजल और एंजिन जनरेटर भारत सरकार के आदेश द्वारा कार्यवाही और कोरुप्टर मंगनीज एवं फार्मेन्टिहाइड कावन तक बाजार निर्माण के लिए एकड़ी की लुगदी दृष्टि में नवाइया विनिमय एवं हारमोन एक्स रे और डाक्टरी सामान हाथवाइ इमनान वान आदि ।

इजीनियरो की नियुक्ति हो। ये इजीनियर भावी इजीनियरो का दल निर्माण करन का कार्य करेंगे।

१९५४-५५ में औद्योगिक विनाम निगम ने औद्योगिक उत्पादन की अनवर योजनाओं को मान्यता दी।<sup>१</sup> इन योजनाओं के सम्बन्ध में विदेशी फर्म एवं विशेषज्ञों की सहचारिता में विस्तृत अनुमति दी गई है। यह भी नियत किया गया कि पटमन तथा वस्त्र-उद्योगों के आधुनिकीकरण एवं पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले विशेष ऋण इसी निगम के माध्यम से दिये जायेंगे। इस हेतु इन उद्योगों के आवेदनों की जांच के लिए औद्योगिक विनाम निगम ने दो समितियाँ की नियुक्ति की है।

इस निगम ने १९५७ में निम्न योजनाओं के विकास के हेतु अध्ययन किया, भारी मशीनों का निर्माण, मिनेमा और एकमरे फिल्म, ऑप्टिकल एवं चर्म के काँच, अल्यूमिनियम, आधारभूत ऑर्गेनिक रसायन, अख्तवारी कागज, मिथेटिक रबर, रसायन उद्योग के माध्यम (intermediates for chemical industries)। इसके सिवा १९५८ में जिन योजनाओं के सम्बन्ध में प्राथमिक अध्ययन किया गया था उनमें काफी प्रगति की गई है तथा इस वर्ष में भारी मशीन निर्माण, खान मशीन योजना तथा फाउण्ड्री फोर्ज योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए एक नया निगम की स्थापना की गई है। चर्म के काँच बनाने की योजना को विस्तृत रूप में तैयार की जा रही है। इन सभी योजनाओं के लिए आवश्यक विदेशी विनिमय की पूर्ति के लिए सन्तोषप्रद व्यवस्था भी कॉर्पोरेशन ने कर ली है।

रंग एवं हवाई उद्योग के लिए आवश्यक माध्यमिक रसायनों के निर्माण की व्यवस्था पूर्णता पर है। अल्यूमिनियम मिथेटिक रबर तथा टंगस्टन कार्बाइड योजनाओं का अध्ययन निजी क्षेत्र में सौंपा गया है जिन्होंने नवीन कारखानों तथा पुराने कारखानों के विस्तार के लिए प्रस्ताव दिये हैं। फिल्म बनाने के उद्योग की स्थापना के लिए भी कॉर्पोरेशन वार्ता कर रहा है।

इस वर्ष कॉर्पोरेशन ने वस्त्र एवं जूट उद्योग के पुनर्वास के लिए क्रमशः २५ एवं २३२ करोड़ रु० के ऋण स्वीकृत किये जिनमें से क्रमशः ८६५ लाख तथा १६७ करोड़ रु० का वितरण किया जा चुका है।

<sup>१</sup> ये उद्योग हैं—Steel foundries, forges and fabrication of steel structurals, intermediates for dye stuffs, wood pulp, carbon black, sulphur from pyrites, printing-machinery, air-compressors and fractional horse-power motors and refractories.

इस प्रकार यह निगम देश के औद्योगिक क्षेत्र की कमी को दूर करने के लिए सफलता में वाय कर रहा है। निगम की महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह सरकारी पूँजी से जिन उद्योगों की स्थापना करता है, उस पूँजी की विनियोग के लिए आवश्यकता होने पर ऐसा उद्योग निजी उपक्रमियों को बेच दिया जायगा। वास्तव में यह वान १९५६ की औद्योगिक नीति से असंगत है, परन्तु वर्तमान समय में औद्योगिक विकास की आवश्यकता तथा विनियोग पूँजी की कमी को देखते हुए यह व्यावहारिक कदम है। यह निगम भावी औद्योगिक विकास एवं प्रवर्धन में प्रवन्ध-अभिकर्ताओं का महत्व कम करेगा जिससे उनका उन्मूलन खटवेगा नहीं, जो वाछनीय है।

### (४) औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम

(Industrial Credit and Investment Corporation)

भारत में अभी तक विशेषतः निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए विनियोग करने वाली संस्थाओं का अभाव था। इसको दूर करने के लिए ही अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के तरफावधान में “औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम” की स्थापना बम्बई में ५ जनवरी, १९५५ को की गई। यह निगम भारतीय प्रमण्डल अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। यह निगम एक निजी संस्था है जो निजी क्षेत्र के उद्योगों को सहायता देगी।

मार्च १९५३ में निजी क्षेत्र में विनियोग बाजार का विकास करने के हेतु एक केन्द्रीय मस्या की स्थापना की निपारिण थॉक समिति ने भी की थी। इस निपारिण ने अनुसार ही भारत सरकार की संयुक्त राष्ट्र के फॉरेन ऑपरेशन्स एडमिनिस्ट्रेशन (U S A Foreign Operations Administration) तथा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक के साथ इस सम्बन्ध में चर्चाएँ हुईं। इन्हीं चर्चाओं का अन्तिम रूप “औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम” है।

यह निगम केवल निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए देशी एवं विदेशी निजी विनियोग पूँजी की महत्कारिता का विकास तथा औद्योगिक विनियोग के निजी स्वामित्व एवं विनियोग बाजार का विस्तार करेगा। अपनी पूँजी को औद्योगिक विनियोगों में लगायेगा तथा एक उद्योग की विनियोगिता पूँजी को यथाशीघ्र अन्य उद्योगों में विनियोग करेगा।

पूँजी एवं वार्षिक साधन—औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की अधिकृत पूँजी २५ करोड़ रुपए है जो १०० रुपए के २५ लाख अंशों में विभाजित है। इसकी वर्तमान निर्गमित एष शुक्ता पूँजी ५ करोड़ रुपए है जो निम्न रीति से ली गई है—

(अ) भारतीय बैंक, बीमा प्रमण्डल, तथा इस	
निगम के संचालकों एवं उनके मित्रों ने	... २०० करोड़ रु०
(आ) अमेरिका के निवासी एवं निगमा ने	... ०५० "
(इ) मयुक्त राज्य (U K) के बैंकों एवं	
बीमा कम्पनियों ने	... १०० "
(ई) भारतीय जनता ने	१५० "

यह निगम अपनी मददस्यता वा वितरण विस्तारपूर्वक रखने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगा, जिससे नियन्त्रण शक्ति वा अवांछनीय केन्द्रीयकरण न हो।

केन्द्रीय सरकार ने मार्च, १९५५ में निगम को ७३ करोड़ रुपए का व्याज मुक्त ऋण दिया है। इसका भुगतान १५ वर्ष बाद आरम्भ होगा तथा १५ वार्षिक किश्तों में होगा। परन्तु निगम इस ऋण का भुगतान तभी कर सकेगा जब वह अपने अन्य ऋणों एवं लेनदारियों को चुका देगा।

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक ने इस निगम को आयात की हुई सामग्री तथा सेवाओं के क्रय के लिए १० मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। यह ऋण साल-निगम किसी भी देश की मुद्राओं में ले सकेगा। इस ऋण की अवधि १५ वर्ष है तथा इस पर विश्व बैंक ४½% व्याज देगा। केन्द्रीय सरकार ने इस ऋण की मूल राशि तथा व्याज के भुगतान की जमानत दी है।

**उद्देश्य**—इस निगम का प्रमुख हेतु निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों को सहायता देना है। यह निम्न प्रकार से दी जायेगी—

- १ ऐसे उपक्रमों के निर्माण विस्तार एवं आधुनिकीकरण में सहायता देना,
- २ ऐसे उपक्रमों में देशी एवं विदेशी निजी पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहन एवं बढ़ावा देना,
- ३ विनियोग बाजार को विस्तृत करना एवं औद्योगिक विनियोगों के व्यक्तिगत स्वामित्व को प्रोत्साहन देना,
- ४ निजी क्षेत्र के उपक्रमों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण अथवा उनके समता अंशों (equity shares) को खरीदकर आर्थिक सुविधाएँ देना,
- ५ नये प्रमण्डलों के अंशों एवं प्रतिभूतियों का अभिगोपन करना,
- ६ व्यक्तिगत उपक्रमों द्वारा निजी विनियोग स्रोतों से लिये गये ऋणों की निजी जमानत देना,
- ७ चक्रित (revolving) विनियोग द्वारा यथाशीघ्र पुनः विनियोग के लिए उपक्रमों को राशि प्रदान करना, तथा

८. व्यक्तिगत उपक्रमों को प्रवन्ध सम्बन्धी तान्त्रिक एवं सामाजिक सहायता देना तथा इस कार्य के लिए आवश्यक विशेषज्ञ प्राप्त करने में सहायता देना ।

**प्रवन्ध**—इस निगम का प्रवन्ध संचालक-सभा करेगी जिसमें ११ संचालक तथा १ प्रमुख व्यवस्थापक हैं । इन संचालकों में ७ भारतीय, २ अंग्रेज, १ अमेरिकन तथा १ संचालक वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से हैं । हमारे प्रमुख व्यवस्थापक श्री पी० एम० बील हैं । केन्द्रीय सरकार के ऋण वा भुगतान जब तक नहीं होना, तब तक केन्द्रीय सरकार को एक संचालक नियुक्त करने का अधिकार है ।

**अधिकार एवं दायित्व**—यह निगम अपनी कार्यशील पूंजी बढ़ाने के लिए ऋण ले सकेगा । परन्तु बिम्बी भी देश में ऋण एवं जमानत दिये हुए ऋणों की कुल राशि निगम की अनिर्मित (unimpaired) पूंजी, मचित कोष, केन्द्रीय सरकार का ऋण तथा अतिरिक्त राशि (surplus) के योग के तिगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

**स्थापना तिथि से १ वर्ष पूर्ण होने पर इस निगम को प्रति वर्ष अपने-आपने लाभ का २५% भाग एक मचित कोष में हस्तान्तरित करना होगा, जब तक ऐसे कोष की राशि केन्द्रीय सरकार की ऋण-राशि के बराबर न हो । यह कोष सयोगिक तथा निगम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उपयोगी होगा ।**

**क्रियाएँ**—इस निगम ने ३१ दिसम्बर १९५८ को चार वर्ष पूर्ण किये । इस अवधि में निगम ने उद्योगों को १३३७ लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी । यह निम्न प्रकार से दी गई —

३१-१२-१९५८ वर्ष		३१-१२-५७ वर्ष	
क्रियाओं की मर्यादा	स्वीकृत राशि (लाख ₹०)	मर्यादा	राशि (लाख ₹०)
११ ऋण (भारतीय मुद्रा में)	३४८	६	३२३
६ ऋण (विदेशी मुद्राओं में)	३१६	५	२२१
१८ सामान्य एवं पूर्वाधिकार अथवा तथा ऋण पत्रों का अनिवार्य	५५०	१६	५२५
१४ सामान्य एवं पूर्वाधिकार अथवा में प्रत्यक्ष अभिदान (subscriptions)	१२३	११	८६
योग	१३३७	—	११६५

इस निगम को १९५७ वर्ष में ७५.२२ लाख ₹० का शुद्ध धन्य हुआ जब कि १९५७ वर्ष में २३.०७ लाख ₹० लाभ रहा । इन दोनों ही वर्षों में निगम

ने ४% वार्षिक लाभान का वितरण किया तथा ५ लाख रु० प्रतिवर्ष संचित कोष में स्थानान्तरित किये। इस प्रकार यह निगम निजी उद्योग क्षेत्र में अपनी उपयोगिता का परिचय दे रहा है।

## (५) पुनर्वित्त निगम

### (Re-Finance Corporation)

उद्योगों को अल्पकालीन ऋण व्यापारिक बैंकों से प्राप्त होता है तथा दीर्घ कालीन ऋण प्रदाय के लिए भारतीय एवं राज्य औद्योगिक अर्ध-निगम तथा राष्ट्रीय-निगम कार्य कर रहे हैं। परन्तु उद्योगों को मध्यकालीन ऋण देने वाली समस्याओं का भारत में अभाव था। भारत की बैंकिंग पद्धति इस कार्य के लिए उपयुक्त है क्योंकि भारतीय बैंकों की शाखाएँ देश में बिखरी हुई हैं तथा उन्हें ऋण प्राप्त की मात्र की भी अच्छी जानकारी है। परन्तु वे अल्पकालीन निक्षेपों के आधार पर प्रारम्भिक अवस्था में मध्यकालीन ऋण नहीं दे सकते। अतः एक रिफाइनांस कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई है। यह निगम सूचीबद्ध बैंकों द्वारा उद्योगों को दिये गये मध्यकालीन ऋणों का पुनः अर्ध-प्रबन्धन (refinance) करेगा।

**विचारधारा का उदय**—भारत और अमरीकी सरकार के बीच जो कृषि-वस्तु-समझौता (agricultural commodities agreement) अगस्त १९५६ में हुआ था उस समझौते के अनुसार ५५ मिलियन डॉलर या २६ करोड़ रु० निजी उद्योगों की आर्थिक सहायता के लिए थे। ऐसी आर्थिक सहायता स्थापित बैंकों के माध्य में दी जायगी। इसी हेतु रिफाइनांस कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई।

**कॉर्पोरेशन का संगठन**—यह कॉर्पोरेशन भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत ५ जून १९५८ को निजी कम्पनी के रूप में रजिस्टर्ड किया गया है। इसकी अधिकृत प्रारम्भिक पूंजी १२५ करोड़ रु० है जो निम्न रीति से प्राप्त की गई है—

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया	५ करोड़
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	२५० ,
जीवन बीमा निगम	२५० ,
१४ सूचीबद्ध बैंकों द्वारा <sup>१</sup>	२५० ,

<sup>१</sup> सेंट्रल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ोदा, नेशनल ओव्हरसीज एण्ड ग्रिडलेज बैंक, लॉयड्स बैंक, युनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, अलाहाबाद बैंक, चाटर्ड बैंक, इण्डियन बैंक, युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया, मर्केंटाइल बैंक, देवकरन नानजी बैंकिंग कॉर्पोरेशन तथा स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद।

इसके सिवा अमरीकी समझौते के अनुसार मिलने वाले २६ करोड़ रु० रि-फाइनान्स कॉर्पोरेशन के पास ४० वर्ष के लिए ऋण के रूप में रहेंगे। इस पर भारत सरकार ब्याज लेगी। इस प्रकार कॉर्पोरेशन के पास कुल ३८ ५ करोड़ रुपये रहेंगे।

**प्रबन्ध**—इस कॉर्पोरेशन का प्रबन्ध सचालन-सभा करती है जिसके ७ सदस्य हैं जिसमें रिजर्व बैंक के गवर्नर का समावेश है जो सचालक सभा का सभापति है। इसके सिवा रिजर्व बैंक का १ उपगवर्नर, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का सभापति, जीवन बीमा निगम का सभापति तथा १४ सूचीबद्ध बैंकों के तीन प्रतिनिधिक सचालक हैं।

**उद्देश्य**—इस निगम का उद्देश्य निजी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों के मध्य-कालीन आर्थिक सुविधाएँ देना है जिसकी अवधि ३ से ७ वर्ष होगी। किसी एक औद्योगिक इकाई को ५० लाख रु० से अधिक का ऋण नहीं दिया जायगा तथा य सुविधाएँ केवल उन्हीं उद्योगों को मिलेंगी जिनकी शुद्धता पूंजी एवं निधि गिलावर २½ करोड़ रु० से अधिक नहीं है। इस हेतु निधि में आयकर कोष तथा सामान्य घिसावट कोष का समावेश नहीं होगा। य ऋण प्राथमिक रूप में उत्पादन वृद्धि के लिए विशेषतः ऐसे उद्योगों को दिये जायेंगे जिनका समावेश दूसरी एवं तृतीय योजनाओं में होगा।

इसका प्रमुख हेतु उद्योगों को व्यापारिक बैंकों से प्राप्त ऋण सुविधाओं में विस्तार करना एवं उनको प्रोत्साहन देना है। सदस्य बैंक ऋणों के पुनः अर्थ-प्रबन्धन के लिए इस निगम से आर्थिक सहायता ले सकेंगे।

जून १९५८ के अन्तिम सप्ताह में निगम के सचालक सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें दूसरी निर्णमित पूंजी १२ ५ करोड़ रु० हापी जो १ लाख रु० के १२५० अंशों में विभक्त होगी, यह निर्णय लिया गया।

३० अप्रैल १९५६ तक इस निगम के पास चार बैंकों से २७० ५० लाख रु० ऋण के लिए १० आवेदन आयें जिनमें से ८ प्राथियों का २४२ रु० के ऋण स्वीकृत हुए तथा २ आवेदन विचारार्थ हैं। स्वीकृत ऋणों में से ५० लाख रु० का वितरण हुआ है।

**ब्याज आदि**—कॉर्पोरेशन द्वारा बैंकों से तथा बैंकों द्वारा ऋणियों से ली जाने वाली व्याज-दर में न्यूनतम १½% का अन्तर होगा। परन्तु कॉर्पोरेशन को हस्तान्तरित किये हुए ऋणों के लिए ऋण-प्रदायक बैंक ही जिम्मेदार होंगे।

(६) अन्तरराष्ट्रीय अर्थ-प्रमण्डल<sup>१</sup>

## (International Finance Corporation)

अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व बैंक के सहयोगी के नाते विभिन्न अविकसित देशों के निजी उद्योगों को आर्थिक सहायता देने के लिए गत ४-५ वर्षों से अन्तरराष्ट्रीय अर्थ-प्रमण्डल (IFC) की स्थापना पर विचार हो रहा था। इस संस्था के निर्माण करने का निर्णय गत वर्ष समुक्त राष्ट्र मंच में लिया गया। फलस्वरूप २५ जुलाई, १९५६ को अन्तरराष्ट्रीय अर्थ-प्रमण्डल की स्थापना की गई। इसके प्रथम एवं वर्तमान अध्यक्ष श्री रॉबर्ट एल० गार्नर हैं।

पूंजी—अन्तरराष्ट्रीय अर्थ-प्रमण्डल की अधिकृत पूंजी १० करोड़ डॉलर है जिसका अभिदान (subscription) ५७ राष्ट्रों ने दिया है। इस प्रकार प्रार्थित एवं चुकता पूंजी को राशि ७८४ करोड़ डॉलर है। इसकी पूंजी में प्रमुख देशों का भाग इस प्रकार है—

समुक्त राष्ट्र अमेरिका	३५,१६८,००० डॉलर
समुक्त राज्य (U K.)	१४,४००,००० „
फ्रांस	५,८१५,००० „
भारत	४,४३१,००० „
फ़ेडरल रिपब्लिक जर्मनी	३,६५५,००० „

इसके सिवा आस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, पाकिस्तान तथा स्वीडन ने १०-१० करोड़ डॉलर का अभिदान दिया है।

अन्य सदस्य देशों में बोलीविया, श्रीलंका, कोलम्बिया, कोस्टारिका, डेन्मार्क, डोमीनियन रिपब्लिक, ईक्वेडोर, मिस्र, एल-साल्वेडोर, इथोपिया, फिनलैंड, ग्वाटेमाला, हेटी, होण्डुरास, आइसलैंड, जोर्डन, मेक्सिको, निकारागुआ, नार्वे, पनामा तथा पेरू हैं।

उद्देश्य—इस अर्थ प्रमण्डल का प्रमुख उद्देश्य सदस्य देशों के, विशेषतः कम विकसित क्षेत्रों के, आर्थिक विकास को निजी उद्योगों के माध्यम से प्रोत्साहन देना है।

अन्तरराष्ट्रीय अर्थ-प्रमण्डल यह कार्य विशेषतः विनियोगों के लिए अनुकूल वातावरण के निर्माण तथा विनियोग अवसर, अनुभवों प्रवन्ध एवं सम्भावित (potential) देशी एवं विदेशी विनियोक्ताओं को एकत्र लाकर करेगा।

<sup>१</sup> R. B. I. Bulletin, October, 1956 and American Economy, U S I S and International Finance Corp'n Washington, 25 D C U.S.A

अन्तरराष्ट्रीय अर्थ-प्रमण्डल के अध्यक्ष के अनुसार “यह निगम एक विनियोग-अभिकर्ता (investing agency) के नाते कार्य करेगा तथा निजी उद्योगों को सरकारी जमानत व बिना ऋण देगा।”

विनियोग प्रस्तावों की योग्यता एवं स्वरूप—उक्त उद्देश्या के अनुसार अर्थ-प्रमण्डल विशेषतः निजी उपक्रमों के आने वाले प्रस्तावों पर विचार करेगा तथा सीमान्त रूप से आर्थिक सहायता देगा, यदि उसे यह विश्वास होता है कि उस उद्योग को अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों के प्रस्तावों पर भी विचार करेगा, यदि प्रमुखता से उनका निजी स्वरूप (essentially private character) हो।

साधारणतः उद्योगों के लिये विनियोग प्रस्तावों पर विचार होगा, जिनमें न्यूनतम ५ लाख डॉलर का विनियोग होता हो अथवा अर्थ-प्रमण्डल को न्यूनतम १ लाख डॉलर के विनियोग करने का प्रस्ताव हो।

अर्थ-प्रमण्डल अपनी राशि का विनियोग किसी भी प्रकार से कर सकता है, परन्तु वह पूंजी-शुद्ध (capital stock) या अंशों में विनियोग नहीं कर सकता।

यह अर्थ-प्रमण्डल साधारणतः ५ से १५ वर्ष के लिए ऋण देगा।

अर्थ-प्रमण्डल आर्थिक सहायता केवल उसी दशा में देगा जब उसका सम्बन्धित उद्योग के सम्बन्ध में पूर्ण सन्तोष हो। इस हेतु वह उद्योग को अनुभवी प्रबन्धक भी दे सकेगा परन्तु स्वयं किसी उद्योग का प्रबन्ध नहीं कर सकता। इसके साथ ही अर्थ-प्रमण्डल को सम्बन्धित उद्योग की संचालक-सभा पर अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के हेतु संचालक नियुक्त करने का अधिकार है।

इस प्रकार ‘यह अर्थ-प्रमण्डल अन्तरराष्ट्रीय ढंग पर निजी उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली पहली विनियोग मस्या है। मेरा विश्वास है कि राष्ट्रा के आर्थिक विकास में निजी उपक्रम अत्यन्त प्रभावी एवं गतिशील शक्ति है और यह विश्वास है कि अविकसित एवं विकसित देशों के लिए यह अत्यन्त लाभकर होगा।” (रॉबर्ट एल० गार्नर)

### (७) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

(National Small Scale Industries Corporation Ltd)

लघु उद्योगों का आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में थॉफ समिति ने यह सिफारिश की थी कि लघु उद्योगों को प्राप्त आर्थिक स्रोतों को प्रोत्साहन देने के

लिए एक पृथक् विकास-निगम की स्थापना की जाय। ऐसा निगम लघु उद्योगों के समुचित संगठन, उनके उत्पादन का प्रमापीकरण, मगठित विपणन, वितरण एवं विज्ञापन तथा कच्चे माल का समुक्त अथवा सहकारी पद्धति पर प्रयत्न करने में सहायता देने के लिए एक पृथक् एवं स्वतन्त्र विभाग का आयोजन करे। यह लघु उद्योगों को तान्त्रिक एवं प्रबन्ध सम्बन्धी सेवाएँ उपलब्ध करावे तथा यदि सम्भव हो तो प्रशिक्षण केन्द्र खोले। इसी प्रकार की निवारित कोर्ड फाइण्डेशन तान्त्रिक दल ने भी की थी।

उक्त निवारित के अनुसार भारत सरकार ने फरवरी, १९५५ में 'राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम' की स्थापना की है। इसका प्रमुख हेतु भारतीय लघु उद्योगों को प्रोत्साहन, संरक्षण, आर्थिक तथा अन्य सहायता देना है।

पूंजी—यह निगम निजी सीमित प्रमण्डल के रूप में भारतीय प्रमण्डल अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। इसकी अधिकृत पूंजी ५० लाख रुपए है जिस में से ४० लाख ६० चुकता पूंजी है। केन्द्रीय सरकार ने निगम की सम्पूर्ण पूंजी ली है तथा इसकी कार्यशील पूंजी बढ़ाने के लिए समुचित ऋण भी देगी।

कार्य—यह निगम ऐसे उद्योगों को जिनमें ५० से कम व्यक्ति काम करते हो तथा विद्युत या अन्य शक्ति से काम होता हो, अपना वित्त १०० से कम व्यक्ति काम करते हो किन्तु विद्युत या अन्य शक्ति का प्रयोग न होता हो, जिनकी पूंजीगत सम्पत्ति ५ लाख रुपए से अधिक न हो, सहायता देगा—

(१) लघु उद्योगों को सरकारी आदेशों का समुचित भाग दिलाना।

(२) जिन लघु उद्योगों को ऐसे सरकारी आदेश प्राप्त हैं उन्हें इन आदेशों की पूर्ति के लिए—

(क) ऋण देना,

(ख) तान्त्रिक सहायता देना,

(ग) आवश्यक प्रमाण एवं किस्म की वस्तुओं के निर्माण में सहायता देना।

(३) लघु उद्योग एवं बहुप्रमाण उद्योगों में ऐसा सामान्य लाना, जिससे लघु उद्योग बहुप्रमाण उद्योगों के लिए आवश्यक सहायक वस्तुएँ तथा अन्य वस्तुएँ बनाने योग्य हो।

(४) लघु उद्योगों को बैंक अथवा अन्य आर्थिक संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋणों का अभिगोपन करना एवं गारंटी देना।

क्रियाएँ—इस निगम ने सितम्बर, १९५५ से अपना कार्य आरम्भ किया

तथा लघु उद्योगों को आवश्यक यन्त्र एवं सामग्री मुविभाजनक किस्तों तथा क़ायक़य (hire-purchase) पद्धति पर दान के लिए एक योजना लागू की। प्रारम्भिक निक्षेप (deposits) २०-४० प्रतिशत हैं एवं दो किस्तों में देय है तथा इस पर कॉर्पोरेशन की व्याज-दर ४½ प्रतिशत है।

३१ मार्च १९५२ तक इस कॉर्पोरेशन के पास क़ायक़य पद्धति पर ६,२६,६७,६८६ रु० सागत की ८,४७१ मशीनों की खरीद के लिए २,१०१ आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये। इनमें से १८४,०६४१२ रु० सागत की २,२३४ मशीन आवेदकों को क़ायक़य आधार पर दी गई।

कॉर्पोरेशन के माध्यम से लघु उद्योगों को ३,०४,१४,४०४ रु० के अनुवर्ध<sup>१</sup> प्राप्त हुए। कॉर्पोरेशन अपने थोक-भटारों में 'जनमेवक' मार्के की लघु उद्योगों की निम्न वस्तुओं का विक्रय करना है, चमड़े के जूते, रस, मूनी एवं ऊनी होजरी, काँच के मणी, पाँटरी आदि। कॉर्पोरेशन की देख-रेख में ओलाडा एवं नैनी की औद्योगिक वस्तियां पूरा की गई हैं जिनमें क्रमशः ३५ एवं ३८ कारख़ाने हैं। इसके सिवा यह निगम राजकोट एवं ओखला में ५० जर्मनी सरकार एवं अमरीकी तात्त्विक महयोग मिशन की सहकारिता में प्रोटोटाइप मशीन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर रहा है जहाँ लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रोटोटाइप मशीनों का व्यापारिक उत्पादन होगा एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी।

### सारांश

१ औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल—यह एक संघानिक निगम है जो १९४८ में उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण मुविधाएँ देने के लिए बनाया गया है। इसकी अधिकृत पूँजी १० करोड़ एवं चुकता पूँजी ५ करोड़ रु० है जो रिजर्व बैंक, केन्द्र सरकार सूचीबद्ध बैंक, बीमा कम्पनी तथा सहकारी बैंकों द्वारा ली गई है। इस निगम के कलकत्ता, बम्बई तथा दिल्ली में कार्यालय एवं मद्रास में शाखा है। इसका प्रबन्ध सचालक सभा करती है जिसके १२ सचालक हैं एवं दैनिक कार्यों की देखभाल केन्द्रीय समिति करती है।

अपनी कार्यशील पूँजी बढ़ाने के लिए निगम बंध बेच सकता है। ऐसे बंधों को निगम ने बेचा है जिनकी घटत राशि ३० जून १९५६ को १६७५ करोड़ रु० थी।

यह निगम अधिकतम २५ वर्ष की अवधि के ऋण दे सकेगा तथा इसी अवधि

<sup>१</sup> Contracts from D. G. S. & D.

मे देय ऋणपत्रों एवं अशो आदि का अभिगोपन करता है। कार्यशील पूंजी के लिए रिजर्व बैंक एवं केन्द्र सरकार से ऋण ले सवेगा। परन्तु किसी भी दशा में यह अपनी चुकता पूंजी एवं निधि के १० गुने से अधिक राशि के ऋण नहीं ले सकता।

निगम ने ३० जून १९५६ तक ६६ ६६ करोड़ रु० के ऋण स्वीकृत किये हैं जिनमें से ४२ ३२ करोड़ रु० के ऋणों का वितरण किया गया। निगम देशो उद्योगों से आयातित पूंजीगत एवं अन्य मात के स्थगित भुगतान की गारन्टी देता है। ३० जून १९५६ तक निगम ने ४५१ करोड़ रु० के स्थगित भुगतान की गारन्टी दी है। १९५७-५८ वर्ष से निगम ने अभिगोपन कार्य आरम्भ किया तथा १६० करोड़ रु० के ६१ ऋणपत्रों का अभिगोपन किया। १९५८-५९ वर्ष में १०० लाख रु० के पूर्वाधिकार प्रशो का अभिगोपन किया। इस सम्बन्ध में निगम की कुल जिम्मेदारी १ ६२ करोड़ रु० की है।

निगम की क्रियाओं पर निम्न आक्षेप है, अधिक व्याज-दर, ऋणों के प्रांतीय वितरण में असमानता, कार्यशील पूंजी की अपेक्षा अधिक राशि के ऋण स्वीकार करना, ऋण स्वीकृति में विलम्ब तथा संचालकों एवं प्रबन्ध अधिकर्ताओं की व्यक्तिगत जमानत।

२ राज्य औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल—उक्त प्रमण्डल सीमित कम्पनियों की ही ऋण देते हैं अतः निजी कम्पनियों, साझेदारी तथा सघु उद्योगों के ऋण देने के लिए १९५१ में राज्य अर्थ-प्रमण्डल अधिनियम बनाया गया। इसके अनुसार इन प्रमण्डलों की पूंजी ५०००० रु० से ५ करोड़ रु० तक हो सकती है। तथा २५% पूंजी जनता को निर्गमित हो सकेगी और शेष पूंजी का अधिदान राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, बीमा कम्पनियाँ आदि आधिक सस्थाएँ ही दे सकेंगी।

यह उक्त औद्योगिक सस्थाओं को २० वर्ष के लिए ऋण या ऋणों की गारन्टी या ऋण-पत्रों का अभिगोपन करेगा। इन प्रमण्डलों के अधिप्राप्त ऋणों की राशि ३१ मार्च १९५७ को ४६२ ६५ लाख रु० थी। इस समय भारत में १० राज्यों में राज्य अर्थ-निगम कार्य कर रहे हैं। बम्बई राज्य ने बम्बई राज्य निगम के स्टेट एंड इण्डस्ट्रीज अधिनियम के अन्तर्गत उद्योगों को सहायता देने के लिए अपना एजेन्ट नियुक्त किया है। यदि अन्य राज्य भी ऐसा करें तो क्रियाओं का दुहरापन समाप्त होकर राज्य अर्थ निगमों की उपयोगिता बढ़ेगी।

३. राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम—२० अक्टूबर १९५४ को स्थापित यह निगम औद्योगिक विकास, आधारभूत एवं प्रमुख सहायक उद्योगों की

स्थापना के हेतु आवश्यक तांत्रिक एवं इंजीनियरिंग अनुभव प्राप्त करने में निजी उपक्रमियों को सहायता देगा। इसकी अधिकृत पूँजी १ करोड़ ६० तथा चुकता पूँजी १० लाख ६० है जो भारत सरकार ने दी है। निगम को अपनी क्रियाओं के हेतु जो अतिरिक्त राशि लगेगी उसकी पूर्ति केन्द्रीय सरकार बजट से ऋण देकर करेगी। निगम को भी कार्यशील पूँजी बढ़ाने के लिए ऋण पत्र चालू करने का अधिकार है।

उद्देश्य—

- (१) औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत एवं प्रमुख सहायक उद्योगों की स्थापना एवं प्रवर्तन।
- (२) औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक यन्त्र सयन्त्र, औजार आदि प्रदान करना।
- (३) औद्योगिक विकास में सहायक निजी उद्योगों को तांत्रिक एवं इंजीनियरिंग सुविधाएँ और आवश्यक हो तो ऋण देना।
- (४) सरकार द्वारा स्वीकृत निजी उपक्रमियों की औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए आवश्यक तांत्रिक, आर्थिक, इंजीनियरिंग एवं अन्य सुविधाएँ देना।
- (५) प्रस्तावित औद्योगिक योजनाओं की पूर्ति के लिए—(अ) अध्ययन एवं अनुसंधान करना, (ब) उक्त सुविधाएँ देना

इसका प्रबंध २० सदस्यों की प्रबंधकारिणी करती है एवं इसके सभापति वाणिज्य एवं उद्योगमंत्री हैं।

नियम—इस निगम ने ३१ दिसम्बर १९५८ तक अनेक योजनाओं के सम्वन्ध में अध्ययन चालू किया है तथा भारी मशीन निर्माण, फाउण्ड्री फोर्ज तथा खान-मशीन योजना की कार्यान्वित करने के लिए एक कॉर्पोरेशन की स्थापना की है एवं अन्य अध्ययन कार्य चालू हैं। कॉर्पोरेशन के माध्यम से दस्त्र एवं लूट उद्योग के पुनर्वास के लिए क्रमशः २५ एवं २३२ करोड़ ६० के ऋण दिये गये हैं।

४ औद्योगिक साख्त एवं विनियोग निगम—५ जनवरी १९५५ को स्थापित इस निगम का उद्देश्य निजी क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों के लिए देशी एवं विदेशी विनियोग पूँजी की सहकारिता का विकास, औद्योगिक विनियोगों के निजी स्वामित्व एवं विनियोग बाजार का विस्तार करना है। इसकी अधिकृत पूँजी २५ करोड़ ६० है तथा चुकता पूँजी ५ करोड़ ६० है जो भारतीय बैंक, बीमा कम्पनी आदि से २ करोड़ ६०, अमरीका के निवासी एवं निगमों से

३ करोड़ रु०, समुत्त राज्य के बीमा कम्पनियों एवं बैंकों से १ करोड़ रु० तथा भारतीय जनता से १२ करोड़ रु० ली गई है।

निगम के आर्थिक साधन बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने ७५ रु० का ऋण दिया है जिसका भुगतान १५ वर्ष बाद आरम्भ होगा तथा आयातित सामग्री एवं सेवाओं के हेतु अन्तरराष्ट्रीय बैंक ने १ करोड़ डॉलर ऋण दिया है।

निगम का प्रबन्ध सचालक सभा करेगी जिसमें ११ सचालक हैं। इस निगम ने ३१ दिसम्बर १९५८ तक उद्योगों को १३ ३७ करोड़ रु० की सहायता विभिन्न रूप से दी है।

५ पुनर्वित्त निगम—स्थापित बैंकों के माध्यम से निजी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों को मध्यकालीन आर्थिक सहायता देने के लिए इस निगम की स्थापना जून १९५८ में की गई है। इसकी अधिकृत पूँजी १२५ करोड़ रु० है जो पूर्ण निर्गमित है तथा रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, जीवन बीमा निगम एवं १४ सूचीबद्ध बैंकों से प्राप्त की जायगी। इसके सिवा अमरीका से कृषि-वस्तु सम-भीते के अन्तर्गत प्राप्त २६ करोड़ रु० की राशि इस निगम के पास ४० वर्ष के लिए ऋण के रूप में रहेगी। इस पर भारत सरकार व्याज लेगी।

इस निगम का प्रबन्ध सचालक सभा करती है जिसके ७ सदस्य हैं। इसका सभापति रिजर्व बैंक का गवर्नर है।

३० अप्रैल १९५९ तक निगम के पास ४ बैंकों में २७० ५० लाख रु० के ऋण के लिए १० आधेदन आये जिनमें से २४३ लाख रु० के ८ आधेदन पत्र स्वीकृत किये गये तथा २ विचारार्थ हैं। स्वीकृत ऋणों में से ५० लाख रु० के ऋण वितरित किये गये हैं।

६ अन्तरराष्ट्रीय अथ प्रमण्डल—इसकी अधिकृत पूँजी १० करोड़ डॉलर है जिसका अभिधान ५७ देशों ने दिया है। इसमें भारत का कोटा ४४३१ हजार डॉलर है। इसका उद्देश्य सबस्य देशों के आर्थिक विकास के हेतु निजी उद्योगों के माध्यम से प्रोत्साहन देना है। यह साधारणतः ५ से १५ वर्ष के लिए ऋण देगा अथवा विनियोग करेगा।

७ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम—इसकी अधिकृत एवं चुकता पूँजी क्रमशः ५० एवं ४० लाख रुपए है जो पूर्ण रूप से भारत सरकार ने दी है। यह नियम लघु उद्योगों को सरकारी आदेशों का समुचित भाग दिलाने में तथा ऐसे आदेशों की पूर्ति के लिए ऋण, तांत्रिक सहायता, आवश्यक प्रमाण एवं किस्म की वस्तुओं के निर्माण में सहायता देगा। साथ ही लघु उद्योग एवं बहुप्रमाण उद्योगों में सामंजस्य स्थापित करेगा जिससे लघु उद्योग उन्हे पुरक हो।

३१ मार्च १९५९ तक कॉरपोरेशन ने तबु उद्योग इकाइयों को जवाबदारी आधार पर १,८४,०६,४१३ रु० की २,२३४ मशीनों का प्रदाय किया तथा ३,२४,१४,४०४ रु० के भाल की पूर्ति के आदेश दितवाये । निगम राजकोट एवं ओखला में एक-एक प्रोटोटाइप मशीन उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना कर रहा है ।

## अध्याय २२

### सहकारी बैंक

सहकारी बैंकों का उगम भारत में सर्वप्रथम ब्रह्मों की कृष्णप्रस्तता के निवारण तथा उन्हें सस्ती व्याज दरा पर आर्थिक सहायता देने एवं महाजनो के जगुल में छुड़ाने के लिए किया गया। इसका श्रेय मद्रास प्रान्त तथा उसके प्रणेता श्री फ्रेडरिक निकलसन को है। इन्होंने ही सर्वप्रथम १८६५-६७ की अपनी रिपोर्ट में सहकारी मातृ-समिति की स्थापना का सुझाव रखा जिसमें "दृष्टक को जिस प्रकार की लोचयुक्त एवं स्थायी मातृ की आवश्यकता है वह प्राप्त हो सके।" इस रिपोर्ट के परिणामस्वरूप लॉर्ड कर्जन ने सर एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। इस समिति के सुझाव के अनुसार ही १९०४ में सहकारी मातृ-समिति अधिनियम स्वीकृत किया गया।

सहकारिता का मूल गन्त "एक के लिए सब तथा सब के लिए एक" है अर्थात् यह एक ऐसा संगठन है जिसमें सब व्यक्ति समान अधिकारों के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामुदायिक रूप से काम करते हैं। इससे निर्धनों एवं निर्बलों में भी स्वातन्त्र्य, आत्म विश्वास, बचत तथा विनियोग के सिद्धान्तों का प्रसार होता है।

सहकारी बैंक भी, जैसा कि हम आगे देखेंगे, जनता में फैल-फैल करते हैं परन्तु इनकी तथा व्यापारिक बैंकों की कार्य प्रणाली में भेद है। व्यापारिक बैंक केवल लाभ की दृष्टि में कार्य करते हैं परन्तु सहकारी बैंक परस्पर आर्थिक सहायता एवं सेवा-भाव के उद्देश्य से कार्य करते हैं। इससे माधनहीन गरीबों की सहायता होती है तथा वे अपनी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। इनके संगठन की विशेषता यही है कि एक स्थान के कुछ साधनहीन व्यक्ति कुछ पन्दा बरके तथा अग खरीद कर, अन्य लोगों से निक्षेप लेकर तथा उधार लेकर अपनी कार्यशील पूँजी प्राप्त करते हैं जिससे वे अपने सदस्यों की आवश्यकता के समय ऋण देते हैं। इससे प्रमुख लाभ निम्न है—

(१) परस्पर सहयोग से काम करने के कारण नागरिकता की भावना बढ़ती है तथा आत्म-विश्वास भी जाग्रत होता है।

(२) इनकी कार्यशील पूँजी छोटे-छोटे स्त्रोतों से आती है जिनके पास देने के अन्य बैंकों की पहुँच नहीं होती। इससे देश की निष्क्रिय पूँजी का उपयोग होकर मुद्रा एवं भाग्य की गतिशीलता बढ़ती है तथा चहैमुखी आर्थिक उन्नति होती है।

(३) जिनके पास साधनों की कमी है उन्हें मन्त्रे दरों पर ऋण मिलता है।

(४) मद्रस्य इनके लेख किमी समय भी देन सकने हैं इसलिए महाजनी पद्धति की भांति ये फँसाये भी नहीं जाते।

(५) इनके साथ ही ग्रामीण जनता में चर्च की भावना जाग्रत होती है।

इसी उद्देश्य से भारत में सहकारी सम्पादा का विकास हुआ। ये सहकारी बैंक तथा साख-सम्पादा केवल कृषक की साख-आवश्यकताओं की पूर्ति करने के उद्देश्य से ही बनाई गई थीं, तथा इनका संगठन भी ग्रामीण साख की आवश्यकतानुसार ही किया गया है। साख-वितरण एवं अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से हम सहकारी बैंकों को तीन श्रेणियों में बाँट सकते हैं, जो कृषकों एवं ग्रामीण जनता की मध्यकालीन एवं अन्तर्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं —

(१) प्राथमिक सहकारी साख-समितियाँ—ये दो प्रकार की होती हैं—

(अ) कृषि (ग्रामीण) सहकारी साख-समितियाँ,

(ब) गैर-कृषि (नगर) साख-समितियाँ।

(२) केन्द्रीय सहकारी बैंक।

(३) राज्य सहकारी बैंक।

**सहकारी तथा व्यापारिक बैंक की तुलना**

(१) सहकारी बैंक तथा व्यापारिक बैंक दोनों ही निधेय स्वीकारने हैं परन्तु व्यापारिक बैंक केवल ऐसे ही व्यक्तियों से ऋण देने हैं जो उनका महत्तम उपयोग कर सकें, न केवल उन लोगों को जिनकी राशि उनके पास निक्षेप में होती है। इसके विपरीत, सहकारी बैंक केवल अपने सदस्यों की ही ऋण देने हैं। इस प्रकार व्यापारिक बैंक विनियोजित तथा विनियोग-प्राप्तों को एकत्र लाने का कार्य करते हैं। परन्तु सहकारी बैंक व्यापार की उन्नति की अपेक्षा अपने सदस्यों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं।

(२) व्यापारिक बैंकों का अपने ग्राहकों के साथ विनियेय सम्पर्क नहीं रहता। परन्तु सहकारी बैंकों का ग्राहकों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रहता है क्योंकि मद्रस्य ही विशेषण उनके ग्राहक होने हैं।

(३) व्यापारिक बैंक अन्टी जमानत पर ही ऋण देने हैं, जो केवल वे ही

दे सकते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। इसमें धनी व्यक्ति अधिक धनी तथा निर्धन अधिक निर्धन होता है अर्थात् धन के समान वितरण की भावना व्यापारिक बैंको में नहीं होती। परन्तु सहकारी बैंक साधनहीन व्यक्तियों की आर्थिक सहायता के लिए ही होते हैं जिसमें जनता में स्वावलम्बन एवं वचन की जागृति होती है तथा वे अपनी आर्थिक उन्नति में मग्न होते हैं। इतना ही नहीं यद्यपि सहकारी बैंको की ऋणनीति प्रजानुत्प्रेक्ष्य होंगे में वे ग्रामवासियों एवं नागरिकों में प्रजानुत्प्रेक्ष्य टङ्ग पर सङ्गठन करने की भावना भरते हैं। इससे सभी व्यक्तियों को कार्य करने के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं।

(४) सहकारी बैंक अपने ग्राहकों का होना है तथा विशेषतः उत्पादन-कार्यों के लिए ही ऋण देता है, न कि उपभोग एवं सामाजिक आवश्यकताओं के लिए। इनके द्वारा दिये गये ऋणों पर ध्याज की दर भी कम होती है तथा यह अपने कार्य-क्षेत्र की जनता की वचन को केन्द्रित करता है। परन्तु व्यापारिक बैंक ऋण किम कार्य के लिए लिया जा रहा है यह न देखने हुए केवल यही देखते हैं कि उनकी जमानत सरल है अथवा नहीं।

(५) व्यापारिक बैंको का संचालन, समामेलन आदि भारतीय कम्पनी अधिनियम तथा भारतीय बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत होता है, परन्तु सहकारी बैंको का संचालन भारतीय सहकारीता अधिनियम के अन्तर्गत होता है।

(६) सहकारी बैंको के अगधारी तथा मदस्य ही बैंक की कार्य-प्रणाली का संचालन आदि करते हैं। परन्तु व्यापारिक बैंको का प्रबन्ध अगधारी न करने हुए संचालक एवं प्रबन्धक करने हैं जो अगधारियों के प्रतिनिधि होते हैं।

इस प्रकार व्यापारिक बैंक एवं सहकारी बैंक में सबसे महत्वपूर्ण अन्तर यह है कि सहकारी बैंक का प्रत्येक मदस्य, प्रत्येक अगधारी उस बैंक का स्वामी होता है, वही उधार लेन वाला होता है तथा ऋण देने वाला भी होता है। इसलिए वह अपने उत्तरदायित्व को भूमन कर कार्य करते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य सौंपा जाना है जिसके लिए वह योग्य है। वह सदैव इस बात के लिए प्रयत्नशील रहता है कि उनके ऋणों का मदस्यों की आर्थिक उन्नति के लिए समुचित उपयोग हो।

**प्राथमिक सहकारी साख-समितियाँ**

सहकारी आन्दोलन १९०४ के सहकारी-साख समिति विधान १९०४ से हुआ तथा गन ५५ वर्षों में वे देश में कार्य कर रही हैं। ये सहकारी समितियाँ १९०४ के अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर होती हैं तथा उनका कार्य-क्षेत्र उसी

गांव अथवा नगर तक सीमित रहता है, जिसमें उनका कार्यालय है। कार्य के अनुसार ये समितियाँ दो प्रकार की होती हैं—

(अ) ग्रामीण अथवा कृषि सहकारी साख-समितियाँ, तथा

(ब) नगर अथवा गैर-कृषि सहकारी साख-समितियाँ।

### ग्रामीण सहकारी साख-समितियाँ

संगठन—ये समितियाँ जर्मनी की रेफोसन (Raiffeisen) समितियों के नमूने पर बनाई जानी हैं तथा इनका कार्य-क्षेत्र किसी ग्राम विशेष अथवा विशेष ग्राम-समूह तक ही सीमित रहता है। एक ग्राम के कोई भी दम अथवा दम से अधिक व्यक्ति मिलकर ऐसी समिति बना सकते हैं तथा उस गांव का अथवा ग्राम-समूह का कोई भी व्यक्ति इनका सदस्य हो सकता है।

पूंजी—इनकी पूंजी सदस्यों के प्रवेन-नुस्क में अथ-पूंजी देकर तथा निक्षेप लेकर प्राप्त की जाती है। सदस्य तथा गैर-सदस्य दोनों से निक्षेप लिये जाते हैं। इनके पास निक्षेप अधिक मात्रा में नहीं आने। यद्यपि निक्षेप आकर्षित करने के लिए ही इनकी स्थापना की गई थी परन्तु इसमें बहुतान समितियाँ को सफलता नहीं मिली। इनकी अथ-पूंजी भी अधिक नहीं होती क्योंकि जिस क्षेत्र में ये कार्य करती हैं, वहाँ की वचत पर्याप्त नहीं होती, जिसे वे विनियोग कर सकें। क्योंकि साधारणतः भारतीय किसान गरीब होता है, अतः इनको ऋण आदि देने के लिए कार्यनील पूंजी केन्द्रीय सहकारी बैंको अथवा राज्य सरकार से ऋण लेकर प्राप्त हाती है।

समिति के सब सदस्य विशेष ग्राम अथवा ग्राम-समूह के निवासी होते हैं तथा इन समितियों के ७५% सदस्य कृषक होना आवश्यक है। सदस्यों का दायित्व असीमित होता है।

ऋण-नीति एवं कार्य—य समितियाँ केवल अपने सदस्यों को ही ऋण देती हैं। ऋण केवल कुछ वनवाने, पुराने ऋणों के भुगतान, कृषिजन्म आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा अन्य उपयोगी एवं उत्पादक कार्यों के लिए ही दिये जाते हैं। परन्तु यह बात सदैव सम्भव नहीं होती क्योंकि हो सकता है कि अन्य आवश्यकताओं के लिए किसान महाजनों के पास से ऋण ल तथा उनके चंगुल में फँस जायें। इसलिए समिति आवश्यकतानुसार सामाजिक कार्यों एवं उपभोग के लिए ही ऋण देती है। परन्तु अनुत्पादक ऋणों के लिए अधिकतम मर्यादा प्रति व्यक्ति १०० रुपए है। इस दराँ से फिजूलखर्ची को रोका जाता है। ऋण विशेषतः अचल सम्पत्ति के रहन अथवा एक या दो अन्य सदस्यों की जमानत पर दिये जाते हैं। परन्तु आजकल समितियों ने भण्डारों में रक्ने हुए

उत्पाद (produce) की जमानत पर भी ऋण दिये जाते हैं। कभी-कभी मदस्य की वैयक्तिक मास पर भी ऋण दिये जाते हैं। ऋणों का भुगतान सुविधाजनक विस्तार में किया जाता है। ऋण की अवधि १ से ३ वर्ष तक की होती है, परन्तु विशेष परिस्थिति में ५ वर्ष तक की अवधि भी दी जाती है। ऋणों के व्याज की दर भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न-भिन्न होती है, जो विनियम ६-१ से १२ प्रतिशत तक होती है।

**प्रबंध—**समिति का प्रबंध मदस्यों द्वारा निर्वाचित सामान्य समिति करती है जिनमें एक अध्यक्ष तथा एक कार्यवाह होता है। समिति में यदि अगधारी नहीं है तो समिति का सम्पूर्ण लाभ संचित-कोष में रखना आवश्यक होता है। इस लाभ का कुछ प्रतिशत भाग जन-हित कार्यों में व्यय किया जाता है परन्तु इसके लिए रजिस्ट्रार से आज्ञा लेनी पड़ती है। समितियों को अपने हिमाद-विताव पूर्ण रखने पड़ते हैं, जिनका निरीक्षण रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अक्षेक्ष करता है तथा इन पर रजिस्ट्रार का पूर्ण नियन्त्रण रहता है।

३० जून १९५७ को कृषि माल-समितियों की संख्या, सदस्यता तथा कार्यशील पूँजी क्रमशः १,६१,५१०, ७७,९२,०००, ९८ ३० करोड़ रु० थी। इसी वर्ष उन्होंने ६७ ३३ करोड़ रु० के ऋण दिये।

### नगर सहकारी बैंक (समितियाँ)

**संगठन—**नगर सहकारी बैंक जर्मनी के शुल्के-डीलिट्स्च (Schulze-Delitzsch) तथा इटली के लुझाटी (Luzzatti) बैंकों के समूह पर बनाई जाती हैं। इनका कार्य-क्षेत्र एक नगर (क्स्वा) तक सीमित रहता है। इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, किन्तु समिति के सदस्यों की इच्छानुसार ये असीमित दायित्व वाली भी बनाई जा सकती है। इनके सदस्यों में से ७५ प्रतिशत सदस्य कृषक नहीं होते। कोई भी १० अथवा इससे अधिक धनवित्त मिलकर इसका संगठन कर सकते हैं।

**पूँजी—**इनकी पूँजी विशेषतः अक्ष देवकर प्राप्त की जाती है जिनका मूल्य विशेषतः ५ से १० रु० तक होता है। प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होता है। इनकी कार्यशील पूँजी विशेषतः सदस्यों एवं गैर-सदस्यों के निक्षेपों से ही प्राप्त होती है। ये अपनी कार्यशील पूँजी के लिए सरकार अथवा केन्द्रीय सहकारी बैंकों पर बहुत कम निर्भर रहती है। इतना ही नहीं अपितु इनके पास अधिक पूँजी रहती है, जिसको वे केन्द्रीय बैंकों के पास निक्षेप में रखते हैं अथवा सरकारी प्रतिभूतियों तथा बन्पनियों के अर्शों में विनियोग करते हैं।

साभ वितरण एवं प्रबन्ध—समिति को लाभ का २ भाग संचित कोष में रखना अनिवार्य होता है। शेष का, विशेषतः १० से १५ प्रतिशत, जनहित कार्यों के लिए उपयोग में लिया जाता है और शेष लाभालाभ के रूप में सदस्यों को बाँटा जाता है।

समिति का प्रबन्ध एक मंचालक-सभा करती है जिसमें एक अध्यक्ष, एक कार्यवाह तथा एक खज़ांची होता है। सभी मंचालकों की नियुक्ति सदस्यों द्वारा की जाती है। सब मंचालकों की सभा को साधारण समिति कहते हैं जो समिति की नीति का निर्धारण तथा लाभालाभ का वितरण करती है। कार्यवाह अध्यक्ष एवं खज़ांची प्रबन्ध-समिति के सदस्य होते हैं तथा प्रबन्ध का उत्तरदायित्व इन्हीं पर होता है।

ऋण-नीति—ये साधारणतः बैंक उद्घाटन-कार्यों के लिए ही ऋण देते हैं तथा ऋण इन्हीं कार्यों के लिए दिये जाते हैं जिनके लिए ग्रामीण सहकारी समितियाँ देती हैं। ऋण की अवधि सामान्यतः २ वर्ष होती है परन्तु विशेष स्थिति में ३ से ५ वर्ष तक के लिए भी ऋण दिया जाता है। इनमें प्रति-भूतियों आदि सम्बन्धी शर्तें ग्रामीण सहकारी मातृ-समितियों की भाँति ही हैं। आजकल कुछ नगर सहकारी बैंक अपने सदस्यों को आधुनिक बैंकों की भाँति रोकट-ऋण तथा बिल एवं चैक के मग़्गण की सुविधाएँ भी देने लगे हैं।

सहकारी समिति अधिनियम के अनुसार दोगा ही प्रकार की समितियों पर रजिस्ट्रार का पूर्ण नियन्त्रण रहता है तथा अक़ेक्षण करने के लिए वह समितियों के अक़ेक्षक की नियुक्ति करता है। अक़ेक्षण प्रति वर्ष होता है जिससे समितियों की आर्थिक स्थिति की जागृकारी हो सके। इसके साथ ही समितियों की आर्थिक स्थिति के अनुसार उनको अ, ब, स तथा द, इन चार वर्गों में बाँटा जाता है। जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होनी, उन्हें 'ई' वर्ग में विकास के लिए बिलियन कर दिया जाता है।

गैर-हृदि मातृ-समितियों की संख्या एवं सदस्यता ३० जून १९५७ की प्रमना १०१५० और २२ ३६ लाख तथा इनकी कार्यशील पूँजी १००४१ करोड़ २० थी। इन्होंने ३० जून १९५७ तक ८२ ०७ करोड़ २० के ऋण दिये जो गत वर्ष की अपेक्षा १० ०१ करोड़ २० से अधिक थे।

प्राथमिक सहकारी समितियों की प्रगति—प्राथमिक सहकारी मातृ-समितियों की प्रगति १९२६ तक अत्रावृत्त रूप से होनी गई। परन्तु १९२६ की आर्थिक मंदी का इन पर बुरा प्रभाव पड़ा तथा अनेक समितियों की स्थिति विलियन तक आ पहुँची थी क्योंकि अधिकतर सदस्य ऋणों का चुगतान करने

में जसमयं थे । १९०६-३० में १८३८-४० तक ममिनियों की ऋण देने की शक्ति कृटित हो गई जिसमें ऋणों में कमी हो गई तथा वीतकाल ऋणों की राशि १९३८-३९ में लगभग ११ करोड़ रुपए थी । परन्तु द्वितीय महायुद्ध ने परिस्थिति बदल दी । इसमें कृषि-वस्तुओं की कीमते बढ़ने लगी तथा कृषकों के पास धन की बहुतायत हो गई जिससे १९४५-४६ में वीतकाल ऋणों की राशि ६२३ करोड़ रुपए रह गई । इसके बाद क्रमशः समिति की सहायता एवं मददस्पर्ता में भी वृद्धि होती गई । साथ ही समिति की पूँजी एक और ती वटती गई और दूसरी ओर कृषकों को धन की आवश्यकता अधिक नहीं हुई । वीत-कालीन ऋणा का भुगतान होने रहने में आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ । कृषकों की इस समृद्धि में सहकारी साख-ममिनियाँ साख के साथ अन्य उत्पादन एवं वितरण कार्यों में भी भाग लेने लगीं । परन्तु फिर ग्रामीण जनता एवं सहकारी समितियों का आज भी साख से घनिष्ट सम्बन्ध है । सहकारी समितियाँ भावी ग्रामीण बैंकिंग विकास में अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं, यदि इनका संचालन समुचित रीति में हो और रिजर्व बैंक उनका पर्याप्त मार्ग-दर्शन करे । इस सम्बन्ध में राज्य सहकारिता इन्स्टीट्यूट, बम्बई के अवैतानिक कार्य-वाह ने जो परिपत्र राज्य की सहकारी-संस्थाओं को भेजा वह उल्लेखनीय है—

“सहकारिता आन्दोलन वचन एवं निजी महायता पर आधारित है । कोई भी सहकारिता कार्य तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसके सदस्य अपनी राशि का कुछ भाग निजी-सहायता (self-help) से प्राप्त न करें । कृषि साख-संगठन का प्रारम्भ के पूर्ण भाग में ५ वर्ष में ऐसा विकास करना है जिसमें कि प्रत्येक ग्राम में एक साख-समिति हो, जो सहकारी बैंकिंग विकास की निर्देशक हो ।” परन्तु “बैंकिंग केवल ऋण देने में ही नहीं है अपितु उसके साथ ही निक्षेप आकर्षित करने की योग्यता भी होनी चाहिए । यदि निक्षेप आकर्षित न किये गये तो सारी योजना ही अस्त-व्यस्त हो जायगी । अतः यह आवश्यक है कि सहकारी समितियाँ एवं सहकारी बैंकों को सदस्यों की वचत एकत्र करने का आन्दोलन करना चाहिए जिससे संगठन के लिए आवश्यक धन निजी राशि से ही प्राप्त हो सके ।”

**केन्द्रीय सहकारी बैंक**

प्राथमिक सहकारी साख-समितियों के साधन उनकी आवश्यकताओं की अपेक्षा बहुत कम होते हैं । इनकी महायता के लिए ही केन्द्रीय सहकारी बैंकों का संगठन किया गया । केन्द्रीय सहकारी बैंक किन्हीं विशेष क्षेत्र अथवा जिले की सहकारी साख-समितियों के ऊपर होता है जिसका प्रमुख कार्यालय मुख्या-

नुसार नगर विशेष में स्थापित किया जाता है तथा वह अपनी शाखाएँ अपने क्षेत्र में खोलता है। मैकलेगन समिति की रिपोर्ट में इनका वर्गीकरण तीन वर्गों में किया गया है—

- (अ) जिनकी सदस्यता केवल वैयक्तिक ही होती है,
- (ब) जिनकी केवल सहकारी समितियाँ ही सदस्य होती हैं, तथा
- (ग) जिनकी सदस्यता में व्यक्ति एवं समितियाँ दोनों ही होते हैं।

समिति ने यह भी मुभाव दिया था कि पहले वर्ग के बैंकों का प्रोत्साहन न दिया जाय क्योंकि उनमें कृषि-माल सम्बन्धी वही बुराइयाँ आ सकती हैं जो संयुक्त स्वयंसेवक बैंकों में होती हैं। इस प्रकार के बैंक आजकल नहीं हैं। वर्तमान वर्गों में हमारे एक तीसरे प्रकार के ही बैंक पाये जाते हैं जिनको जमना सहकारी बैंकिंग तथा सहकारी केन्द्रीय बैंक कहते हैं। इस प्रकार की पहली बैंक मद्रास में १९०७ में स्थापित हुई तथा १९११ में बम्बई में। परन्तु अधिकतर केन्द्रीय बैंकों की स्थापना सहकारिता अधिनियम १९१२ के बाद ही हुई तथा बम्बई का केन्द्रीय बैंक, जो १९११ में स्थापित हुआ था, राज्य सहकारी बैंक हो गया।

केन्द्रीय बैंकों का कार्य-क्षेत्र भिन्न राज्यों में नगर या तहसील, तालुका अथवा जिले तक सीमित रहता है तथा अधिकतर बैंक तीसरे वर्ग के हैं।

कार्य—सहकारी बैंकिंग सचो की सदस्यता केवल सहकारी माल-समितियों तक ही सीमित रहती है तथा इनका प्रबन्ध सदस्यों द्वारा निर्वाचित सचालकों द्वारा किया जाता है। यह सच अपने सदस्यों के कार्य का निरीक्षण करता है, उनकी राशि निक्षेप में रखता है तथा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सहायता देता है। इसी प्रकार केन्द्रीय सहकारी बैंक भी सदस्य समितियों के कार्यों की देख-भाल करते हैं, निक्षेप लेते हैं तथा समितियों एवं सदस्यों को आर्थिक सहायता देते हैं। इस प्रकार केन्द्रीय सहकारी बैंक दुहरे कार्य करते हैं—एक तो अपने सदस्यों की रोक-निधि रखना तथा उन्हें आवश्यकता के समय आर्थिक सहायता देना। ये जनता में निक्षेप भी स्वीकार करते हैं। कुछ प्रान्तों में, विशेषतः मद्रास में, स्थानीय अधिकारियों को अपनी राशि या तो सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग करनी पड़ती है या अनिवार्यतः केन्द्रीय बैंक में जमा करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त ये बैंक अन्य बैंकिंग गिजाएँ भी करते हैं; जैसे जनता के भव्य प्रकार के निक्षेप लेना, बिल, बैंक आदि का संग्रहण, चिक्कों का निगमन, प्रतिभूतियों का व्यव-विक्रय, आभूषणादि की मरम्मत आदि। कुछ राज्यों में अचल सम्पत्ति की जमानत पर ऋण देने का कार्य भी ये बैंक करते हैं।

**पूँजी**—इनकी पूँजी अश-विक्रय से, सदस्य समितियों के संचित कोष तथा अन्य कोष, जनता तथा स्थानीय अविकारियों के निक्षेप से प्राप्त होती है। इससे अतिरिक्त ये प्रान्तीय सहकारी बैंक तथा समुक्त स्कंध बैंको से ऋण एवं निक्षेप लेते हैं। स्टेट बैंक से इनको रोक्ड-ऋण भी मिलता है। सदस्य समितियों को ऋण देने के पूर्व ये बैंक अपने अकेलकों द्वारा उनकी आर्थिक स्थिति का निरीक्षण करा लेते हैं। ये निक्षेप लेते हैं अतः उनके भुगतान के लिए इनको अपने पास सम्पत्ति भी रखनी पड़ती है।

इसके अतिरिक्त कुछ राज्यों में केन्द्रीय सहकारी बैंक सहकारी समितियों के विकास के लिए प्रचार तथा सहकारिता-शिक्षा का प्रयत्न करते हैं।

**लाभ नियोजन**—इनको अपने व्यय आदि का भुगतान करने के बाद जो छुट्ट लाभ होता है उसका उपयोग संचित-कोष बढ़ाने तथा लाभांश वितरण में करते हैं। इनके लाभांश की दर विभिन्न राज्यों में ३% से ६% होती है परन्तु सामान्यतः ५% से अधिक वार्षिक लाभांश नहीं दिया जाता। विशेषतः मद्रास राज्य में तो वैधानिक शर्त है कि ये ५% में अधिक लाभांश न दे क्योंकि अधिक लाभांश का वितरण सहकारिता-तत्त्व—लाभ की अपेक्षा सेवा-दान—के विरुद्ध है। इनके सम्बन्ध में “मद्रास सहकारिता समिति” ने लिखा था कि उन्होंने “सहकारिता तत्त्वों पर कृषि साख सङ्गठन में मौलिक कार्य किया है तथा ग्रामीण विकास एवं सहकारिता-शिक्षा की योजनाओं में विशेष रूप से प्रगति की है।”

द्वितीय महायुद्ध का परिणाम इनकी प्रगति पर बड़ा ही अच्छा हुआ है, जिससे इनकी मर्यादा में वृद्धि न होते हुए आर्थिक सङ्गठन अच्छा हो गया है। युद्ध-काल में कृषि-वस्तुओं के मूल्य बढ़ने से कृषकों को ऋण की आवश्यकता न रही, जिससे समितियाँ द्वारा लिये एवं दिये जाने वाले ऋणों में भी कमी हो गई। इससे केन्द्रीय बैंको के पास जमा राशि बढ़ती गई, जिसका उन्होंने अन्य बैंकिंग क्रियाओं में उपयोग किया। युद्धोत्तर काल में भी इनकी प्रगति अच्छी रही।

३० जून १९५७ को इनकी सरया ४५१ तथा सदस्य-सरया ३११ लाख थी। इसी तिथि को इनकी कार्यशील पूँजी ११०.२६ करोड़ रु०, चुकता पूँजी एवं निधि १८.४५ करोड़ रु० थी।

**राज्य सहकारी बैंक**

राज्य सहकारी बैंक देश की सहकारिता-संगठन के शीर्ष (apex) बैंक हैं जो राज्य के सहकारी बैंको का संगठन, नेतृत्व एवं कार्यों का निरीक्षण करते

है। राज्य सहकारी बैंक की आवश्यकता पर १९१५ में मैकलेगन समिति ने जोर दिया था जिससे ये राज्य के सहकारी बैंक एवं समितियों का संगठन एवं नेतृत्व करे तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक पर नियन्त्रण रखे। इसी हेतु राज्य सहकारी बैंक की स्थापना की गई। जून १९५७ के अन्त में इनकी मर्यादा २३ थी, जिनकी चक्रता पूँजी एवं निधि ८७८ करोड़ रु० तथा कार्यशील पूँजी ७६ ५४ करोड़ रु० थी।

इनका संगठन विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रकार है, जैसे बंगाल तथा पंजाब में राज्य बैंकों की सदस्यता व्यक्तिगत तथा सहकारी समितियों दोनों की है, विहार एवं मद्रास में केवल केन्द्रीय सहकारी बैंक ही सदस्य हैं, अन्य कुछ राज्यों में केवल सहकारी समितियाँ ही सदस्य हैं तथा कहीं-कहीं सहकारी समितियाँ तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक भी सदस्य हैं। राज्य बैंक की स्थापना का श्रेय मैकलेगन समिति को है। इन सहकारी समितियों का आपसी लेन-देन रोकने तथा आन्दोलन का मुद्दा बनाने के लिए इन बैंकों की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे केन्द्रीय सहकारी बैंकों का नियन्त्रण हो सके तथा उनके साथ इनका सम्बन्ध हाकर राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में केन्द्रीय बैंक सफल हो। इस प्रकार राज्य बैंक सहकारी आन्दोलन की धुरी हैं।

राज्य बैंक अग्र-विषय में, निक्षेप-स्वीकृति से, व्यापारिक बैंकों से तथा स्टेट बैंक से कार्यशील पूँजी प्राप्त करते हैं। इनके पास केन्द्रीय बैंक की अतिरिक्त राशि भी निक्षेप में रहती है। साख-समितियों को यदि ऋण की आवश्यकता होती है तो उन्हें केन्द्रीय बैंकों के माध्यम से राज्य बैंक ऋण देना है। इस प्रकार ऋण देने का कार्य चार मॉडलों में होता है —

- (अ) व्यक्तियों को सहकारी साख-समितियाँ ऋण देती हैं,
- (ब) सहकारी साख समितियों का केन्द्रीय सहकारी बैंक ऋण देता है,
- (स) केन्द्रीय सहकारी बैंक को राज्य सहकारी बैंक ऋण देते हैं, तथा
- (द) राज्य सहकारी बैंक, स्टेट बैंक तथा व्यापारिक बैंकों से ऋण लेते हैं।

राज्य सहकारी बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंक का ऋण देते हैं। ये साख-समितियों में प्रत्यक्ष लेन-देन नहीं करते, परन्तु जिन राज्यों में राज्य बैंक नहीं हैं, वहाँ ये उनसे प्रत्यक्ष लेन-देन भी करते हैं। इस प्रकार सहकारिता आन्दोलन की आर्थिक धारिका बटान एवं उसका आर्थिक संगठन करने में इनकी अधिक उपयोगिता है क्योंकि सहकारी साख-समितियों के कुल ऋणों के ५०% ऋण केन्द्रीय तथा राज्य बैंकों के दिये हुए हैं। अर्थात् ये एवं प्रकार से ग्राम की सहकारी साख-समितियों तथा मृदा-मण्टी के बीच मध्यस्थ का कार्य कर उनका

सम्बन्ध प्रस्थापित करते हैं। इन्होंने सहकारी आन्दोलन को आर्थिक शक्ति प्रदान की है जिससे बैंकिंग सिद्धान्त का प्रयोग इस आन्दोलन में हो सका है। इसके अतिरिक्त ये विशेष प्रकार की सहकारी समितियों की स्थापना एवं विकास में भी सहयोग देते हैं, जैसे गृह-निर्माण-समिति, विपणन-समिति आदि। मैक्लेगन समिति ने एक अखिल भारतीय सहकारी बैंक की स्थापना का भी प्रस्ताव किया था जो राज्य-बैंकों का शीर्ष बैंक हो। परन्तु रिजर्व बैंक की स्थापना से इसकी आवश्यकता नहीं रही क्योंकि रिजर्व बैंक अब इनको अपने कृषि-साख-विभाग के माध्यम से विशेष सहायता करता है।<sup>१</sup>

द्वितीय महायुद्ध का राज्य सहकारी बैंकों पर प्रगतिजनक प्रभाव हुआ है क्योंकि एक ओर तो इनके निक्षेप बढ़ते गये तथा दूसरी ओर ऋण-प्रदाय स्थायी रहा तथा अदत्त ऋणों का भुगतान भी सन्तोषजनक होता रहा। परिणामस्वरूप इनके विनियोग बढ़ते गये जो युद्धकालीन प्रगति का एक विशेष लक्षण है।

**सहकारी आन्दोलन एवं समितियों की सिफारिशें**

ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति ने ग्रामीण बैंकिंग सुविधाओं के विकास के लिए सहकारी आन्दोलन की सुदृढ़ता पर जोर दिया था। इसके साथ ही इनको अधिक राशि-स्थानान्तरण की सुविधाएँ देने की सिफारिश की थी। गोदामों (warehouses) के विकास के लिए इस समिति ने गोदाम विकास सभा की स्थापना की भी सिफारिश की थी।

ग्रामीण साख सर्वे समिति ने अपनी रिपोर्ट में मकेत किया था कि सहकारी आन्दोलन अब ग्रामीण साख का केवल ३१% भाग देते हैं। यह इस आन्दोलन की असफलता का परिचायक है। इसलिए इस समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं—

- (१) सहकारी आन्दोलन के प्रत्येक स्तर पर राज्य सरकार की साभेदारी हो,
- (२) सहकारी आन्दोलन की साख एवं अन्य आर्थिक क्रियाओं में पूर्ण साम-जस्य हो, विशेषतः विपणन एवं क्रिया-कलापों में (Marketing & Processing),
- (३) कृषि साख कलेक्टर के आधार-रूप में प्राथमिक सहकारी समितियों का विकास बड़ी आर्थिक इकाई के रूप में सीमित देनदारी सिद्धान्त पर हो,
- (४) कृषि-वस्तुओं के समुचित विपणन द्वारा कृषकों को सहायता देने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य गोदाम सङ्गठनों (national and state warehousing organisations) के माध्यम से गोदामों का जाल बिछाया जाय,

<sup>१</sup> देखिए “रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया”—कृषि-साख-विभाग।

(५) सहकारी आन्दोलन के सभी स्तर के कर्मचारियों की शिक्षा के लिए उचित सस्थाओं की स्थापना की जाय,

(६) सहकारी समितियों को सुलभ राशि-स्थानान्तरण की सुविधाएँ देने के लिए स्टेट बैंक की स्थापना हो जो शाखाओं का गामीण क्षेत्रों में विस्तार करे। इस बैंक की स्थापना १ जुलाई १९५५ को हो गई है जिसने चार वर्ष की अवधि में १७६ शाखाएँ खोली हैं।

इन सिफारिशों के अनुसार (१) राज्य सरकार सहकारी आन्दोलन में सक्रिय भाग दे सके, इस हेतु फरवरी १९५६ में राष्ट्रीय कृषि-माल ( दीर्घ-कालीन ) कोष की स्थापना १० करोड़ रु० से रिजर्व बैंक ने की है। इसमें १९५५-५६ से १९५८-५९ के वर्षों में ५ करोड़ रुपए वार्षिक जमा किये गये। इस निधि का निम्न उपयोग है—

(अ) सहकारी साख्त सस्थाओं की पूँजी में हिस्सा देने के हेतु राज्य सरकार को दीर्घकालीन ऋण देना,

(ब) केंद्रीय भूमि वन्धक बैंक को दीर्घकालीन ऋण देना,

(स) मध्यकालीन कृषि-ऋणों का प्रदान करना, तथा

(द) केंद्रीय भूमि वन्धक बैंक के ऋण पर खरीदना।

(२) राष्ट्रीय कृषि माल ( स्थिरीकरण ) कोष की स्थापना भी १ करोड़ रु० से फरवरी १९५६ में रिजर्व बैंक ने की है तथा इसमें १९५६-५७ तथा १९५७-५८ वर्ष में वार्षिक १ करोड़ रु० का अभिदान दिया है। इस कोष का उपयोग राज्य सहकारी बैंकों को मध्यकालीन ऋण देन में होगा जिससे व आवश्यकता के समय अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में बदल सके।

पहिले कोष में से १९५७-५८ में व १९५८-५९ में १४ राज्यों को ६०४ व ५६२ करोड़ रु० के ऋण दिये गये हैं जिससे वे सहकारी माल समितियों की अंश पूँजी में भाग ले सकें, इसमें से २० जून १९५६ तक कमसे ५८३ व ५७४ करोड़ रु० का उपयोग राज्य सरकारों ने किया है। दूसरे कोष का उपयोग करने का अवसर अभी तक नहीं आया।

(३) राष्ट्रीय सहकारिता-विकास एवं भोदाय सभा की स्थापना १ सितम्बर १९५६ को की गई है तथा १० करोड़ रु० की पूँजी में केंद्रीय भोदाय निगम की स्थापना की गई है। इसने ६ भोदायों का निर्माण किया है।

(४) सहकारी प्रशिक्षण के लिए "केंद्रीय सहकारी प्रशिक्षण समिति" की स्थापना की है जिसने सभी स्तर के सहकारी कर्मचारियों की शिक्षा की योजना बनाई है। इस योजना के अनुसार अखिल भारतीय सहकारी शिक्षा-केंद्र पूना

में है जहाँ उच्च अधिकारियों की शिक्षा का प्रबन्ध है। पाँच प्रादेशिक शिक्षा-केन्द्र है जहाँ मध्य-स्तरीय कर्मचारियों को शिक्षा दी जाती है। सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार-खण्डों में  $\infty$  इस्टीमेट है जिनमें सहकारी अधिकारियों की शिक्षा मित्तती है। इसके सिवा प्रत्येक राज्य में निम्न स्तरीय कर्मचारियों की शिक्षा के लिए प्रशिक्षण विद्यालय है। इनमें से एक प्रादेशिक केन्द्र पर भूमि-वधक बैंकिंग की शिक्षा के लिए विशेष पाठ्यक्रम भी है।

द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना में—इस योजना अवधि में सहकारी आन्दोलन का विकास साख के साथ की अन्य आर्थिक क्षेत्रों में किया जायगा। योजना में अल्पकालीन साख के लिए १५० करोड़ रु०, मध्यकालीन साख के लिए ५० करोड़ रु० तथा दीर्घकालीन साख के लिए २५ करोड़ रु० का प्रबन्ध है, जो सहकारी सस्याआ के माध्यम से कृषकों को दी जायगी। इसके सिवा योजना में १०,४०० बड़ी समितियाँ, १००० प्राथमिक विपणन (Marketing) समितियाँ, ३५ सहकारी शक्कर कारखाने, ४८ रुई साफ करने के कारखाने, ११८ सहकारी प्रोसेसिंग समितियों की स्थापना होगी। इसके सिवा केन्द्रीय एवं राज्य गोदाम निगम विपणन समितियों के लिए १५०० गोदामों का तथा बड़ी प्राथमिक कृषि साख समितियों के लिए ४००० गोदामों का निमाण करेगे। विकास की आवश्यकतानुसार इन आकड़ों में परिवर्तन हो सकता है।

रिजर्व बैंक और सहकारी आन्दोलन<sup>१</sup>—(१) रिजर्व बैंक अपने कृषि साख विभाग के माध्यम से सहकारी आन्दोलन के लिए प्रयत्नशील है।<sup>२</sup> रिजर्व बैंक सहकारी आन्दोलन को राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से २% बैंक दर की छूट से ऋण सहायता देता है। विभिन्न वर्षों में राज्य सहकारी बैंकों को दी गई ऋण सहायता निम्न है —

वर्ष राज्य सहकारी मौसमी कृषि आव राज्य सहकारी मध्यकालीन बैंका की मर्यादितता के लिए ऋण बैंकों की सस्या ऋण-राशि  
(करोड़ रुपये में) (करोड़ रुपये में)

१९५४-५५	१५	२१ २१	—	—
१९५५-५६	१६	१९ ६४	१०	१ ४०
१९५६-५७	१७	३५ २५	६	१ ६७
१९५७-५८	१८	४८ २४	१२	७ ७२
१९५८-५९	—	६१ ४३	—	४ ५२

<sup>१</sup> *Commerce, September 19, 1959 & India 1959*

<sup>२</sup> देखिए 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया'।

मध्यकालीन ऋणों की अन्तिम तीन वर्षों की राशि अब कृषि साख (दीर्घ-कालीन) कोष से दी जाती है। इसी कोष से रिजर्व बैंक ने केरल सहकारी केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक को बैंक दर पर १६४० लाख रु० का १ वर्ष के लिए ऋण दिया जिससे यह त्रापनकोर जेडिट बैंक के ऋणपत्र धारियों का भुगतान कर सके। क्योंकि इस बैंक को केरल केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक न खरीदा है।

(२) रिजर्व बैंक भूमि बन्धक बैंक के १०% ऋण पत्र खरीद सकता है यदि उनके मूलधन एवं व्याज के भुगतान की गारन्टी राज्य सरकार न दी हो। १९५० से इस सीमा को २०% कर दिया गया है। इसके सिवा केन्द्रीय सरकार भी पंचवार्षिक योजनाओं की दीर्घकालीन सहकारिता साख की राशि से १ करोड़ रु० तक के भूमि बन्धक बैंकों के ऋण पत्र ले सकती है। अतः केन्द्रीय सरकार की सलाह से रिजर्व बैंक ने भूमि-बन्धक बैंक द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों का ४०% भाग खरीदना मान्य किया है, यदि वे जनता पूरा नहीं खरीदती। इसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक ने केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंकों के ऋण पत्रों ने निम्न अभिदान दिया—<sup>१</sup>

(लाख रुपये में)		(लाख रुपये में)	
१९४६-५०	४१५	१९५०-५२	१८८८
१९५०-५१	२०००	१९५२-५४	१५५६
१९५१-५२	१३००	१९५३-५८	१४८४

इसी प्रकार ३० जून १९५६ को समाप्त होने वाले वर्ष में रिजर्व बैंक ने सीरायट्टा, आंध्र एवं उड़ीसा के केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंकों द्वारा निर्गमित क्रमशः ५०, ३५ और ५ लाख रु० के ऋण पत्रों में से क्रमशः २४, १८५ तथा ५ लाख रुपये के ऋण पत्र खरीदे। क्योंकि वे जनता द्वारा न खरीदे जा सके।

(३) क्षेत्रीय अध्ययन—नगर सहकारी बैंकों के वर्तमान स्थानों के क्लेवर का अध्ययन करने के लिए रिजर्व बैंक के कृषि साख, आर्थिक एवं मासिकी विभाग ने संयुक्त रूप से १० राज्यों के १०० नगर बैंकों की क्रियाओं का अध्ययन मार्च १९५६ में पूर्ण किया। इसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है। इसी प्रकार केरल के कॉयल उद्योग, आगरे के चर्म उद्योग की साख-आवश्यकताओं का अध्ययन कार्य रिजर्व बैंक कर रहा है। १९५३-५८ में बम्बई, केरल एवं मद्रास के मत्स्य उद्योग तथा मद्रास के चर्म-उद्योग की साख-आवश्यकताओं का अध्ययन किया या जिसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है।

<sup>१</sup> Modern Review, October 1954.

(४) सहकारी बैंको का परीक्षण—सहकारी आन्दोलन की सुदृढता के लिए रिजर्व बैंक सहकारी बैंका का परीक्षण भी करता है। इस प्रकार १९५४ ५५ से १९५८ ५९ के पांच वर्षों में क्रमशः ३५ ४४ १०४, २४० और १७८ बैंको का परीक्षण रिजर्व बैंक ने किया। इस प्रकार ३० जून १९५९ तक कुल ६१८ बैंको का परीक्षण किया गया जिनमें ५४५ केन्द्रीय सहकारी बैंक थे। इस हेतु वृषि साख विभाग के चार नये प्रादेशिक कार्यालय १९५८ ५९ में क्रमशः इन्दौर, पटना, लखनऊ तथा बंगलौर में खोले गये जिससे ऐसे कार्यालयों की संख्या ८ हो गई है। न कार्यालय अपने प्रदेश के सहकारी बैंका का परीक्षण करते हैं तथा प्रत्येक प्रदेश के राज्य सहकारी बैंको का वार्षिक तथा केन्द्रीय सहकारी बैंका का द्विवार्षिक परीक्षण करते हैं।

प्रशिक्षण—प्रशिक्षण सुविधाओं का उल्लेख पृष्ठ ६०२ पर किया गया है। इन प्रशिक्षण कन्द्रों में इस वर्ष ८३ उच्च अधिकारी २१५ सहकारी विषय अधिकारी तथा ८० भूमि बन्धक बैंको के अधिकारी प्रशिक्षित किये गये। इसके सिवा राज्यों के इन्स्टीट्यूटों में ४८४६ जूनियर सहकारी अधिकारियों का प्रशिक्षित किया गया।

### सहकारी आन्दोलन की नुटिया

सर मालकाम डालिङ्ग के विचार—कोलम्बो योजना के सलाहकार श्री डालिङ्ग को भारत सरकार ने सहकारी क्षेत्र के आधुनिक निकासों की जांच द्वितीय योजनाओं के सम्बन्ध में कार्यक्रमों की जांच राज्य सहकारी विभागों के संगठन की सुदृढता सहकारी कमचारियों के प्रशिक्षण तथा जिला स्तर एवं इसके नीचे सहकारी आंदोलन के संगठन के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए बुलाया था। इनके रिपोर्ट की प्रमुख बात निम्न है—

(१) द्वितीय योजना के निधारित लक्ष्य आंदोलन के सुदृढ विकास की दृष्टि से बहुत अधिक है। क्योंकि वर्तमान में जो ध्यान नई समितियों के संगठन की ओर दिया जा रहा है उतना ही यदि पुरानी साख समितियों की मजबूती और पुनर्जीवन के लिए दिया जाय तो असफलता का खतरा नहीं रहेगा।

(२) समितियों का निरीक्षण एवं भाग दर्शन ऐसे व्यक्तियों द्वारा होता है जिनमें सहकारिता में निहित मानवी सम्बन्धों के कठिन क्षेत्रों की सफलता के लिए आवश्यक अनुभव नहीं है। और यह बात उच्च स्तर पर और भी अधिक लागू होती है जहां विभागीय अधिकारी सहकारिता के बाहर के क्षेत्रों में होते हैं तथा उनका स्थानान्तरण होता रहता है।

(३) जिस प्रकार से लक्ष्य का निधारण हुआ है उनकी पूर्ति का अधि-

कारी प्रयत्न करते हैं जिससे उनके 'आका' खुद हो। इसमें यह प्रवृत्ति होती है कि "कृषक लक्ष्यो के लिए है न कि लक्ष्य कृषक के लिए।"

(४) आन्दोलन में सरकार का अत्यधिक भाग जो ग्रामीण सर्वे समिति की सिफारिश के अनुरूप है, उसमें आन्दोलन की मूलशक्ति आत्म-निर्भरता एवं स्वतन्त्रता को ठेस पहुँचती है। इसे गम्भीरता में सोचने की आवश्यकता है।

(५) वृहत् समितियों की स्थापना यद्यपि सदस्यों में सहकारी-भावना निर्माण करने में अमूल्य रहेगी फिर भी वे आन्दोलन के लिए प्रश्नात्मक सम्पत्ति (questionable asset) हों सकती हैं। श्री डालिंग के अनुसार इन बड़ी समितियों द्वारा की जाने वाली ऋण प्रदाय में नियोजित वृद्धि कृषक की माख-योग्यता को पर्याप्त रीति में देखने हुए न हो, ऐसी शका है। साथ ही ऋण देने के स्रोतों को मजबूत और विस्तृत करने पर जितना ध्यान दिया गया है उतना ध्यान बचत और मितव्ययिता को प्रोत्साहन देने पर नहीं दिया गया है।

(६) आन्दोलन ने गत वर्षों में बहुत ही धीमी प्रगति की है। विशेषतः केन्द्रीय साख सहकारिता एवं प्राथमिक साख सहकारिता ने क्षयशील पूँजी के अनुपात में निजी पूँजी अथवा निक्षेप बढ़ाने में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं की है। दूसरे, इनके योगकामीन (overdue) ऋणा की राशि में कोई सुधार नहीं हुआ है। तीसरे, प्राथ्य ध्याज की राशि जो १९५०-५१ में ५९% थी, वह सन् १९५४-५५ में ४२% हो गई है। चौथे ६ बड़े राज्या में से ५ राज्यों की समितियाँ हानि पर कार्य कर रही हैं।

(७) कृषक को सबसे अधिक साख-सुविधाएँ बम्बई राज्य में दी जाती हैं परन्तु इनमें ऋणों के भुगतान की अधिकता न होने हुए अदत्त ऋणा की राशि में वृद्धि हो रही है। अतः भविष्य में साख सुविधाएँ देने में सावधानी की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में श्री डालिंग ने सहकारी आन्दोलन की मुहूर्तता में विस्तृत प्रादेशिक अन्तरो की ओर आँख मूँदने के प्रवृत्ति की निन्दा की है। राज्यों की कृषि समितियों में यह अन्तर उनके आकार, सदस्य-संख्या, प्रति व्यक्ति औसत ऋण राशि और विशेषतः समितियों के वर्गीकरण की पद्धति में है।

(८) केन्द्रीय बैंक एवं प्राथमिक समितियों की कार्य-प्रणाली सन्तोषजनक नहीं है। प्राथमिक समितियाँ केन्द्रीय बैंक के एजेंट की भाँति कार्य करती हैं और केन्द्रीय बैंक प्राथमिक समितियों की आन्तरिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करती है जो उनकी स्वतन्त्रता के लिए खतरनाक है। साथ ही ऋण देने की पद्धति में अनावश्यक विलम्ब होता है और प्राथमिक समितियों पर जिम्मेवारी नहीं

रहती। प्राथमिक समितियों का सचिव-कोष जब तक उनकी चुकता पूंजी के बराबर नहीं होता तब तक वे उमका विनियोग अपने व्यवसाय में नहीं कर सकती। ये स्वावटें समितियों की स्वतन्त्रता में बाधक हैं।

(६) मामुदायिक एवं राष्ट्रीय विस्तार मेवा योजनाओं के अन्तर्गत सहकारिता के क्षेत्र में कुशल मार्ग दर्शन का अभाव है, विस्तार अधिकारियों की अनुपस्थिति है और जहाँ ऐसे अधिकारी हैं भी वहाँ उनको क्षेत्रीय अनुभव (field experience) नहीं है।

विभिन्न क्षेत्रों के उक्त दोषों के निवारण तथा सहकारी आन्दोलन की मजबूती के लिए सर मात्कम डालिंग ने निम्न सुझाव दिये हैं —

१ दूसरी योजना में सहकारी आन्दोलन के विकास की गति बहुत तेज है तथा सम्पूर्ण भारत में समानता के विस्तार का जो लक्ष्य अपेक्षित है वह बम्बई, मद्रास और आन्ध्र के लिए भी अधिक है जहाँ का आन्दोलन सब राज्यों से अधिक सुदृढ़ है। इसलिए जिन राज्यों में आन्दोलन कमजोर है वहाँ विपणन की गति धीमी करनी चाहिए और जहाँ आन्दोलन अत्यधिक कमजोर है वहाँ अपेक्षित लक्ष्यों के पूर्ति की अवधि १० वर्ष होनी चाहिए।

२ (अ) आधुनिक समय का अनुभव एवं बीतकालीन ऋणों की अधिकता को देखते हुए इन ऋणों के भुगतान के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है।

(आ) योजना के लक्ष्यों के सम्बन्ध में श्री डालिंग का मत है कि योजना-कार इतने लक्ष्य प्रवृत्त (target minded) हो गये हैं कि वे लक्ष्यों को साधन न समझते हुए उनको ही साध्य समझते हैं। इसलिए उनका सुझाव है कि एक उच्चाधिकारी की नियुक्ति केन्द्र में हो जो राज्यों के सहकारी आन्दोलन का सूक्ष्म अवलोकन करे एवं “गति की वेदी पर सुदृढ़ता का बलिदान नहीं हो रहा है एवं लक्ष्यों पर ध्यान दिया जा रहा है, उनकी पूजा नहीं हो रही है” इस सम्बन्ध में मतर्क रहे।

३ (अ) ग्रामीण साल सर्वे समिति के अनुसार बृहत् समितियों का निर्माण होगा, जिनका कार्य क्षेत्र बड़ा होगा—संभवतः २० गांवों का। इससे सहकारी समितियों का मूल आधार अर्थात् ‘परस्पर सहायता एवं परस्पर सूझ’ से सदस्य वंचित हो जायेंगे।

(आ) “नमिति देनदारी” का सिद्धान्त सम्पन्न कृषकों को आकर्षित करेगा परन्तु निर्धन कृषकों को आकर्षित न कर सकेगा जिनके लाभ के लिए इन समितियों का निर्माण होना है।

(इ) बड़ी समितियों में मेलजोल का वातावरण नहीं रहेगा तथा बड़ा क्षेत्र

होने से समिति तक पहुँच होने में समय भी अधिक लगेगा, अधिक दूरी भी होगी—जो सहकारी मिद्धान्त के लिए भारक होगी।

(ई) समिति की '५००' सदस्य संख्या अधिक है। अतः उनका मुभाव है कि ऐसी समितियों का निर्माण तीन प्रकार में हो और उनके परिणाम ३-४ वर्षों में देने जायें—

(अ) अर्ध एवं सदस्यों में सरकार का भाग,

(ब) धन में सरकार का भाग किन्तु सदस्यता में नहीं,

(ग) न अर्धों और न सदस्यता में ही सरकार का भाग हो।

बड़ी समितियों का कार्यक्षेत्र २० मील में अधिक न हो। उनकी सदस्य संख्या ३०० से ५०० तक रहे तथा इनका नैमासिक अथवा एकीभूत (concurrent) अन्वेषण हो। इनमें व्यापारिक एवं वैयक्तिक क्रियाओं का सम्मेलन हो और ऐसी समितियाँ बनाने के लिए छोटी समितियों का एकीकरण उनके सदस्यों के बहुमत के बिना न हो। इसके साथ ही किसी मभा पर सरकारी प्रतिनिधि के नामें उसी व्यक्ति को चुना जाय जो सहकारिता में गतिमान रहते हैं। अतः तीनों पद्धतियों के प्रयोगात्मक परिणामों का परीक्षण समितियों के आकार, कार्यक्षेत्र, सरकारी भाग तथा मार्गदर्शन, ऋण एवं उनका भुगतान, बीतकाल ऋण, ऋण लेने में अवधि, उत्पादक एवं अनुत्पादक ऋण के सम्बन्ध में किया जाय। संक्षेप में सदस्यों के समिति के साथ के सभी प्रकार के सम्बन्धों का परीक्षण हो।

४ छोटी समितियों को अधिक प्रोत्साहन देने के विशेष प्रयत्न किये जायें क्योंकि आन्दोलन की मजबूती वृद्धि एवं लाख समितियों की अधिकता पर निर्भर है। इसलिए सदस्य संख्या में वृद्धि, मोरीबन्द समितियों की समाप्ति, लघु-समितियों का एकीकरण, निष्क्रिय समितियों का पुनर्जीवन तथा प्रत्येक समिति में प्रशिक्षित मिनता का आयोजन—इस साधना को अपनाया जाय।

५ सहकारी समितियों में सरकार के असाधारण होने से समितियों की स्वतन्त्रता को हानि होगी। इसलिए इसकी बुराइयों के निवारण के लिए समितियों की मभा पर तीन से अधिक प्रतिनिधि सरकार मनोनीत न करे। ऐसे प्रतिनिधियों को सहकारिता का व्यावहारिक एवं सैद्धान्तिक ज्ञान हो। साथ ही इन प्रतिनिधियों में स्टेट बैंक का प्रतिनिधि न हो।

६ समितियों के अन्वेषण की जिम्मेवारी सहकारी-रजिस्ट्रार की हो जो आन्दोलन का निरीक्षण भी करे। क्योंकि ऐसे अन्वेषण का उद्देश्य सुदृष्ट व्यापारिक प्रणाली की गारंटी के साथ ही सहकारी मिद्धान्तों का पालन हो रहा है इसका भी प्रमाण हो।

७ प्रत्येक स्तर के सहकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था हो तथा रजिस्ट्रार का स्थानान्तरण न किया जाय क्योंकि इसका स्थान एवं कार्य महत्वपूर्ण होता है। प्रशिक्षण में मैदान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण का समावेश हो। प्रशिक्षण में भाषणों (lectures) की संख्या कम की जाय तथा सेमिनार-पद्धति का उपयोग किया जाय, जिससे प्रशिक्षार्थी अधिक अध्ययन एवं मनन कर सकें। इस हेतु प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र का पुस्तकालय मुनज्जित हो।

८ सामुदायिक विकास योजना एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में बी० डी० ओ० का स्थान महत्वपूर्ण होता है जिसको सहकारी प्रशिक्षण दिया जाय तथा सामुदायिक विकास मीटों की पूर्णता तक बी० डी० ओ० का स्थानान्तरण न किया जाय।<sup>१</sup>

उक्त मुभाव वास्तव में महत्वपूर्ण और योजनाओं की आँखें खोलने वाले हैं, जो वास्तविक स्थिति को आँख बन्द कर लक्ष्य-प्रवृत्त हो गये हैं। इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने पर निश्चय ही सहकारी आन्दोलन का बलबरा मुदृढ़ हो सकेगा।

### भूमि-बन्धक बैंक

कृषि-व्यवसाय का संगठन औद्योगिक संगठन से भिन्न होने से कृषकों को आर्थिक सहायता देने के लिए सभी देशों में कृषि-साख की समुचित व्यवस्था की गई है। कृषि-साख मुविधारण देने के लिए हमारे देश में भी सहकारी आन्दोलन सरकारी नीति का एक भाग ही है। सहकारी समितियाँ कृषकों को केवल उत्पत्तली एवं मध्यकालीन ऋण देती हैं। परन्तु कृषकों को चाहे वे विश्व के किसी भी कोने में हों, दीर्घकालीन ऋण की आवश्यकता होती है जिससे वे अपने पुराने ऋणों का भुगतान कर अपनी भूमि का स्थायी सुधार कर सकें तथा आवश्यकतानुसार नई भूमि भी खरीद सकें। किसानों को दीर्घकालीन ऋण की पूर्ति भूमि-बन्धक बैंक करते हैं।

परिभाषा—भूमि-बन्धक बैंक उन्हें कहते हैं जो “कृषकों की भूमि के रहन पर उन्हें दीर्घकालीन ऋण देते हैं।” माघारणत अमेरिका, इंग्लैंड आदि देशों में दीर्घकालीन ऋणों की अवधि ३० से ७५ वर्ष होती है, परन्तु भारत में अधिकतम २० वर्ष के लिए ऋण दिये जाते हैं।

प्रकार—भूमि-बन्धक बैंकों की स्थापना तीन प्रकार से की जाती है—

(१) सहकारी भूमि-बन्धक बैंक—एसे बैंक केवल रहन रखी हुई भूमि पर बन्ध (bonds) प्रेषकर राशि प्राप्त करन है जिनमे व केवल अपने मदस्यो को ही ऋण-सुविधाएँ देन हैं। इनमे कभी कभी बाहर के व्यक्तियों को भी मदस्य बना लिया जाता है जिनसे अधिक पूँजी प्राप्त हो सके एवं अच्छे प्रबन्धक, गृहचालक अथवा नगचारी मिल सक। ये बैंक लाभ के उद्देश्य में कार्य नहीं करत अपितु दीर्घकालीन ऋणों पर व्याज की दर कम करना इनका एकमात्र लक्ष्य होता है।

(२) समुक्त स्वरूप भूमि-बन्धक बैंक—य व्यापारिक बैंक की भाँति सीमित देनदारी वाला होता है तथा इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। इनकी पूँजी अथवा ऋण पत्र तथा रहन बन्धा के विपणन से प्राप्त होती है। भारत में इस प्रकार के बैंक नहीं हैं।

(३) अध सहकारी भूमि-बन्धक बैंक—ये बैंक उन व्यक्तियों के एक समूह के रूप में होते हैं जिनको ऋण की आवश्यकता होती है तथा जिनकी पूँजी अथवा के विक्रय से प्राप्त की जाती है। इनके मदस्या की देनदारी सीमित होती है किन्तु अधिकतर कानूनी पूँजी ऋण पत्रों के निर्गमन से प्राप्त की जाती है। भारत में इस प्रकार के बैंक ही अधिकतर हैं।

उगम तथा विकास—भारत में भूमि बन्धक बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयत्न १८८३ में हुआ था जिस समय फ्रेंच ब्रिडिज फासियर के नमून पर एक बैंक की स्थापना हुई जिसने लगभग २० वर्ष काम किया परन्तु बाद में विलीन हो गया। इसके बाद १९०० में भी कई प्रयत्न हुए परन्तु कुछ में ही स्थापना हो सकी जो अल्पकालीन रहा। इन सब बैंकों के विलियन का प्रमुख कारण यही रहा कि ये बड़े-बड़े जमींदारों को ही सुविधाएँ देत रहे। परन्तु सबसे महत्वपूर्ण प्रयत्न मद्रास में हुआ जब १९०६ में प्राथमिक बैंक के संगठन के हेतु केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक की स्थापना की गई। इसके बाद मैसूर (१९०६), बम्बई (१९३५), उड़ीसा (१९३८) तथा बाचीन (१९३५) में इनकी स्थापना की गई। मध्य प्रदेश में राज्य सहकारी बैंक ही प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक की महत्ता करत है।<sup>१</sup> इसके अतिरिक्त भूमि बन्धक बैंक अथवा समितियाँ पश्चिमी बङ्गाल, आसाम, उत्तर प्रदेश तथा अजमेर मेरवाड़ा आदि में भी हैं परन्तु उनकी प्रगति विशेष उल्लेखनीय नहीं है।<sup>१</sup> बम्बई में भी इस क्षेत्र में अच्छी प्रगति हुई है जहाँ १८४७-४८ में एक राज्य भूमि-बन्धक बैंक तथा १५ प्राथमिक

<sup>१</sup> *Review of the Co operative Movement in India, 1946-1948*

भूमि-बन्धक बैंक थे। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में भी इसका अभाव होना तेजजनक है क्योंकि इसी में ही कृषक महाजना पर निर्भर रहे तथा ऋण-भार बढ़ता ही गया तथा इनको जहाँ थे वहाँ भी अधिक सफलता नहीं मिली। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की पिछली समीक्षा में लिखा है कि "इतनी अधिक ग्रामीण जन-गण्यता ये होने हुए भी भारत में भूमि-बन्धक बैंको को अधिक सफलता नहीं मिली। पंजाब में, जहाँ सबसे पहले ऐसे बैंक का निर्माण हुआ, कोई उन्नति नहीं हुई। अन्य राज्यों में भी जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अजमेर, उड़ीसा तथा बंगाल में भी भूमि-बन्धक बैंको का कार्य सन्तोषप्रद नहीं रहा। केवल मद्रास ही में इन बैंको ने उन्नति की है।"

प्रथम युग—इनका विकास १९२६ से प्रारम्भ होता है जब मद्रास तथा मैसूर में केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंको की स्थापना हुई। १९२६ से आर्थिक मंदी का काल था जब कृषि-वस्तुओं के मूल्य गिर रहे थे, भूमि का मूल्य भी कम हो गया था तथा किसानों को अपनी भूमि ऋणों के भुगतान के लिए बेचने की नौबत आ गई थी। ऐसे मकड़ काल में भूमि-बन्धक बैंकों की स्थापना ने कृषकों को अनूद्य सहायता की तथा उनको भूमि की रहन पर ऋण देकर भूमि को महाजनों के हाथ बिकने से बचाया। परन्तु १९२९ से परिस्थिति ने पलटा खाया क्योंकि युद्ध के कारण निर्यात बढ़ने लगे और कृषि-पदार्थों का मूल्य बढ़ने लगा। फलतः कृषकों के पास धन आने लगा और उन्होंने अपने ऋणों का अवधि के पूर्व ही भुगतान कर दिया। इससे दीर्घकालीन ऋणों की प्राप्ति के लिए कृषकों को इनकी उपयुक्तता अब उतनी नहीं रही है फिर भी ये स्थायी भूमि सुधार के लिए ऋण देकर भूमि की उत्पादन-क्षमता बढ़ा कर वर्तमान खाद्य-मकड़ का निवारण करने में अधिक सहायक हो सकते हैं। अतः इनको अब इस दिशा में प्रचार एवं प्रयत्न भी करना चाहिए।

१९५८-५९ में केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक की संख्या १२ तथा प्राथमिक भूमि-बन्धक बैंक की संख्या ३२६ थी। उन्होंने इसी वर्ष क्रमशः ३८० तथा २०५ करोड़ रुपये के ऋण दिये। एवं इनकी सदस्य संख्या क्रमशः ११७ एवं ३३४ हजार थी।

कार्यशील तथा अन्य पूँजी—इनकी कार्यशील पूँजी अथवा वेचकर, निक्षेप की स्वीकृति से, ऋण पत्र तथा बन्ध वेचकर प्राप्त की जाती है परन्तु विशेषतः अधिकांश भाग ऋण पत्रों के विक्रय से प्राप्त होता है। इनके ऋण पत्रों की

मूल राशि तथा व्याज के भुगतान की गारन्टी सरकार देती है एवं ये ऋण-पत्र प्रत्याम-प्रतिभूतियों को धोषी के होते हैं।

**कार्य**—ये दीर्घकालीन अवधि के लिए—सामान्यतः २० वर्ष के लिए—पुराने ऋणों के भुगतान के लिए ऋण देते हैं परन्तु अधिकतम ४० वर्ष के लिए ऋण दे सकते हैं। भारतीय बैंकों ने यह कार्य अभी हाल ही में शुरू किया है। ऋण केवल मदद्यों को उनकी भूमि के रहन पर दिये जाने हैं तथा प्रत्येक मदद्य को दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि सामान्यतः १०,००० रु० अथवा रहन-सम्पत्ति के मूल्य के ५० प्रतिशत होती हैं। सबसे पहले ऋण-प्राप्तक प्राथमिक भूमि-वन्धक बैंक को आवेदन देना है। यह रहन के लिए जो सम्पत्ति है उसका मूल्य-निर्धारण, स्वत्व आदि की जाँच करता है तथा उसके बाद ऋण दिये जाने हैं। इस प्रकार की रहन-सम्पत्ति केन्द्रीय भूमि-वन्धक बैंक को हस्तान्तरित होती है, जिसकी जमानत पर वे आवश्यकता पडने पर नये ऋण-पत्र निर्गमित करते हैं। ऋणों पर व्याज की दर ६% से ६½% सी जाती है तथा निक्षेपों पर २½% से ६% तक द्याज देते हैं।

**प्रबन्ध**—इसका प्रबन्ध संचालक-सभा करती है जो इसकी सामान्य नीति को निश्चित करती है। इसके अतिरिक्त भूमि आदि का समुचित मूल्यांकन करने एवं वैधानिक मलाह के लिए विनयन रहते हैं। ये विशेषज्ञ प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने हैं एवं अपनी मलाह के साथ संचालक-सभा में उन्हें विचारार्थ रखने हैं। संचालक-सभा ऋण देने अथवा न देने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देती है।

**लाभांश**—इनको होने वाला लाभ लाभांश के रूप में मदद्यों को वितरित किया जाता है। परन्तु लाभांश ५% से अधिक नहीं दिया जाता, तथा लाभांश चुकता पूँजी पर ही दिया जाता है। दूसरे, ये बैंक अपने लाभ को लाभांश के रूप में तब तक नहीं बाँट सकते जब तक इनका संचित कोष एक निश्चित राशि तक न आ जाय। मद्रास एवं बम्बई के भूमि-वन्धक बैंकों को लाभ का क्रमशः ४०% एवं ५०% संचित कोष में प्रति वर्ष देना पड़ता है।

इस प्रकार भूमि-वन्धक बैंक की सफलता रहन-सम्पत्ति के मूल्य-रहने मूल्यांकन तथा निम्नो के नियमित भुगतान पर निर्भर है। इन बैंकों ने ग्रामीण ऋण के निवारण में अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य किया है।

**विकास-क्षेत्र**—भारत में आज भी इनके विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र है क्योंकि यह एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कृषकों को अपनी भूमि के सुधार के लिए मर्दव ही दीर्घकालीन ऋणों की आवश्यकता रहेगी। इनके विनाम एवं

प्रगति के लिए प्रान्तीय तथा केन्द्रीय बैंकिंग जांच-समितियों ने निम्न सिफारिशों की हैं —

भूमि-बन्धक बैंकों की स्थापना केवल महवारी तत्वों पर ही होनी चाहिए तथा इनका कार्य-क्षेत्र इतना विस्तृत न हो जिसमें इनका सम्बन्ध ऋणियों से न रहे। भूमि बन्धक बैंकों को अपनी आर्थिक सुदृढता के लिए सचित कोष का निर्माण करना चाहिए तथा जाभाज का वितरण तब तक न हो जब तक उनकी सचित कोष पर्याप्त न हो जाय। कार्यशील पूँजी अगो तथा ऋण पत्रों द्वारा, विशेषतः ऋण-पत्रों के निर्गमन में ही प्राप्त करना चाहिए जिनकी गारन्टी सरकार दे। परन्तु ऋण-पत्रों की गारन्टी के सम्बन्ध में निश्चित हुए रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि "सरकारी गारन्टी की आवश्यकता प्रारम्भिक अवस्था में अवश्य हुई होगी, परन्तु वर्तमान स्थिति इसकी आवश्यकता नहीं बढ़ानी चाहिए और न सीमित राशि ही। एक स्थिति ऐसी आ जानी चाहिए जब भूमि बन्धक बैंक अपने ही पैरों पर खड़े रहें तथा अपनी साल पर ही ऋण-पत्रों का निर्गमन करें। क्योंकि य सस्थाएँ कृषकों को दीर्घकालीन ऋण देने वाली स्थायी सस्थाएँ हैं—अस्थायी नहीं।" भूमि-बन्धक बैंकों को निक्षेप रखने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए और यदि दी जाती है तो निक्षेपों की अवधि अधिक होनी चाहिए। ऋणों की व्याज-दर तथा अवधि ऋणी की आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहनी चाहिए क्योंकि भारत में २० वर्ष की अधिकतम अवधि अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही कम है। जैसे फिनलैंड में ३० वर्ष, चिली में ३३ वर्ष, न्यूजीलैंड में ३६½ वर्ष, आस्ट्रेलिया में ४२ वर्ष, इटली तथा जापान में ५० वर्ष, स्विट्जरलैंड में ७५ वर्ष, डेनमार्क में ६६ वर्ष, हंगरी में ६३ वर्ष, आयरलैंड में ६८½ वर्ष तथा फ्रांस में ७५ वर्ष है। ऋण केवल आर्थिक कार्यों के लिए ही दिये जायें तथा उनका समुचित उपयोग न होता हो तो उन्हें तत्काल ही वापिस लिया जाय। इसके साथ ही भूमि बन्धक बैंकों को यह अधिकार हो कि वे न्यायालय की सहायता बिना रहस्य-भूमि को बेचकर अपनी ऋण-राशि प्राप्त कर सकें। अतएव सम्बन्धित सन्धियों में प्रावदपक मशोधन करना चाहिए।

**भविष्य**—इन सुधारों के साथ भूमि-बन्धक बैंक अधिक सफलता से कार्य कर सकते हैं जिनकी वर्तमान समय में तथा भविष्य में भी तीव्र आवश्यकता रहेगी। अब उनको भूमि-मुवार के लिए अधिकाधिक मात्रा में ऋण देना

चाहिए जिससे वे अधिक मफलता से अपनी अतिरिक्त पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे, विभिन्न राज्या में अनेक ऋणवन्तता सम्बन्धी जो अधिनियम स्वीकृत हो चुके हैं उनमें महाजनो द्वारा दी जाने वाली मायब भी कम हो गई है तथा कृषक इन बैंकों पर अधिक निर्भर रहने लगे हैं।

ऋणा की बढ़ती माँग के केवल दो ही कारण प्रतीत होते हैं। प्रथम तो बढ़ता हुआ जीवन-मूल्य तथा कृषि-यन्त्र, खाद, बलों आदि की बढ़ी हुई कीमतें। दूसरे, महाजनो से साख-प्राप्ति का भ्रान्त बन्द होना, जिससे उनकी निर्भरता बैंकों पर अधिक हो गई है। केन्द्रीय भूमि-वन्धक बैंक ने १९४७-४८, १९४८-४९, एवं १९४९-५० में क्रमशः ७७.५९, १०२.६० एवं १०१.०८ लाख रुपए के ऋण इन तीन वर्षों में दिये। ये ऋण विशेषतः पुराने ऋणा के भुगतान के लिए ही दिये गये हैं जिसमें यह स्पष्ट है कि आज भी उनकी उपयोगिता अधिक है। विशेषतः जब देश की योजनाओं के अन्तर्गत कृषकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से ही साख प्रदाय होगा—यह सिद्धान्त मान लिया गया है।

यदि विभिन्न सरकारी विभागों का सहयोग प्राप्त किया गया तो भूमि-वन्धक बैंक देश के कृषकों को भूमि का उत्पादन बढ़ाने में तथा देश को खाद्यान्न में स्वयं पूर्ण बनाने में महत्त्वपूर्ण तथा समुचित कार्य करेंगे। अतः मन्त्रालय के सहकारी-मन्त्रि श्री ए. बी. देहरी ने जैसा २५वीं भूमि-वन्धक बैंक वार्षिक परिपत्र में कहा है 'उनको भूमि सुधार पर उत्पादन के लिए ऋण देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए।' उन्होंने यह भी कहा कि भूमि-वन्धक बैंक रिजर्व बैंक के निम्न सुझावों पर अधिक ध्यान दे—

(१) भूमि सुधार, भूमि मरफाई एवं विनास, कृषि-यन्त्रों के क्रय के लिए ऋणों को प्राथमिकता दे,

(२) बड़ी सिंचाई-योजनाओं में लाभान्वित क्षेत्रों सामुदायिक विकास-क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय विस्तार-क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली योजनाओं को ऋण दे,

(३) कार्यान्वित कृषि योजना क्षेत्रों की नियोजित साख-योजना से भूमि-वन्धक अपने ऋणों को सम्बन्धित करे।

### सहकारी आन्दोलन एवं सरकार

विभिन्न राज्य सरकार सहकारी आन्दोलन की सफलता के लिए दो प्रकार से सहायता करती हैं। एक तो अधिनियम बनाकर जिससे इनका विकास समुचित हो। दूसरे, अपनी राशि सहकारी बैंकों में निक्षेप के रूप में रखकर तथा इनको ऋण देकर आर्थिक सहायता देना। तीसरे, कृषि साम्य मंत्र सगिति की सिफारिश के अनुसार सहकारी संस्थाओं की अक्ष पूंजी में योग देना।

इस प्रकार रिजर्व बैंक, राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार सहकारी आन्दोलन को जन-जीवन का एक अंग बनाने में प्रयत्नशील हैं, जो आन्दोलन के ज्योतिर्मय प्रवास की ओर सचेत है।

(१) सहकारी समितियों में राज्य सरकारों द्वारा पूंजी-योग (लाख रु० में)<sup>१</sup>

राज्य	राज्य सहकारी बैंक	केन्द्रीय सहकारी बैंक	प्राथमिक कृषि समितियाँ	केन्द्रीय भूमि वन्धक बैंक
आंध्र	४२६	६००	८२४	१००
आसाम	१५००	०५०	—	४००
बिहार	४०००	२०००	—	—
बम्बई	५६४०	३६१०	१६०७४	१०००
जम्मू एवं काश्मीर	१२६०	—	—	—
केरल	५००	—	२७८	१५०
मध्य-प्रदेश	१४६०	३२००	१३८३	—
मद्रास	८००	—	२२०	—
मैसूर	५००	—	—	—
उड़ीसा	४००	६८५	१७६७	२२५
पंजाब	१८००	१३६०	८७७५	—
राजस्थान	८६३	७६२	४७०	—
उत्तर प्रदेश	५००	—	—	—
प० बंगाल	१५००	—	—	—
हिमाचल प्रदेश	८००	—	—	—
योग	२२०१२	१२६२७	३२८२१	१८७५

(२) सहकारिता आन्दोलन—एक दृष्टि में<sup>२</sup>

समिति का प्रकार	संख्या	सदस्यता (हजार)	श्रुण दिये लाख रु०	कायशील पूंजी (लाख रु० में)
(अ) सब समितियाँ	२४४७६६	१६३,७०	१७३,१६	५६७,६७
(ब) राज्य एवं केन्द्रीय समितियाँ				
राज्य सहकारी बैंक	२३	३३	१२३,७१	७६,५४
केन्द्रीय सहकारी बैंक	४५१	३११	१००,८०	११०,२६
केन्द्रीय भूमि बन्धक बैंक	१२	११७	३८०	२१,३२
(ग) प्राथमिक समितियाँ				
कृषि साख समितियाँ	१६१,५१०	६१,१७	६७,३३	६८,३०
प्राथमिक भूमि बन्धक बैंक	३२६	३३४	२०५	१२,७०
गैर कृषि साख समितियाँ	१०१५०	३२,२६	८२,०७	१००,४१

<sup>१</sup> Times of India Year Book 1959-60

<sup>२</sup> प्राथमिक समितियाँ की।

## सारांश

भारत में सहकारी बैंकों का उगम कृषकों की ऋणप्रसूता के निवारण तथा उन्हें सस्ते व्याज दर पर आर्थिक सहायता देने के लिए हुआ। इसका ध्येय मद्रास राज्य तथा थो फ्रेडरिक निकल्सन की है। सहकारिता का मूल मन्त्र "एक के लिए सब तथा सब के लिए एक" है। सहकारी बैंक जनता से लेनदेन करते हैं परन्तु इनकी कार्यप्रणाली व्यापारिक बैंकों से भिन्न है। इनके लाभ हैं —

(१) नागरिकता की भावना तथा आत्मविश्वास का निर्माण, (२) पूँजी छोटे स्तरों से आती है जिनके पास अन्य बैंकों की पहुँच नहीं होती, (३) साधनहीन व्यक्तियों को सस्ते व्याज-दर पर ऋण-सुविधा (४) जालसाजी की पुजाइश नहीं, (५) ग्रामीण जनता में बचत की भावना का निर्माण।

सहकारी बैंक एवं व्यापारिक बैंकों में मुख्य साम्य-भेद निम्न हैं —

(१) दोनों ही निक्षेप स्वीकारते हैं परन्तु व्यापारिक बैंक ऐसे व्यक्तियों को ऋण देते हैं जो महत्तम उपयोग कर सकें। इसके विपरीत सहकारी बैंक केवल सदस्यों को ऋण देते हैं।

(२) व्यापारिक बैंक विनियोक्ता एवं विनियोग प्राप्तियों को एकत्रित करते हैं तो सहकारी बैंक सदस्यों की आर्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करते हैं।

(३) व्यापारिक बैंकों का ग्राहकों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क नहीं होता जो सहकारी बैंकों का होता है।

(४) व्यापारिक बैंकों की ऋणनीति तरलता पर आधारित होती है जबकि सहकारी बैंकों की नीति प्रजातन्त्रात्मक होती है।

(५) व्यापारिक बैंक ऋण के हेतु की अपेक्षा सुरक्षा की ओर अधिक ध्यान देते हैं परन्तु सहकारी बैंक विशेषतः उत्पादन कार्यों के लिए ही ऋण देते हैं।

(६) व्यापारिक बैंक भारतीय सम्पत्ती अधिनियम एवं बैंकिंग कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत होते हैं तो सहकारी बैंक सहकारिता अधिनियम के अन्तर्गत होते हैं।

(७) सहकारी बैंकों के अशुधारी ही बैंक का संचालन करते हैं। किन्तु व्यापारिक बैंकों का संचालन अशुधारियों के प्रतिनिधिक संचालक ही करते हैं।

प्राथमिक मास-समितियाँ—सहकारी साधन-समितियों का निर्माण १९०४ के सहकारिता अधिनियम के बाद होने लगा। इनका कार्य-क्षेत्र गाँव या कस्बे

तक सीमित रहता है। एक गांव के कोई भी दस या दस से अधिक व्यक्ति मिलकर ऐसी समिति बना सकते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं—सहकारी कृषि साख-समितियाँ—जिनके ७५% से अधिक सदस्य कृषक होते हैं तथा सहकारी गैर कृषि साख-समितियाँ—इनके ७५% सदस्य कृषक नहीं होते। ३० जून १९५७ को दोनों प्रकार की क्रमशः १६१,५१० तथा १०,१५० थीं। प्राथमिक समितियों की प्रगति १९२६ तक अवाधित होती रही परन्तु १९२६ की आर्थिक मंदी का प्रभाव इन पर बुरा हुआ जिससे इनकी स्थिति घिलीपन तक आ पहुँची। १९२६-३० से १९३६-४० तक समितियों की ऋण देने की शक्ति कुण्ठित हो गई थी। परन्तु द्वितीय महायुद्ध ने परिस्थिति बदल दी जिससे समितियों की सहाय्य एवं सदस्यता में वृद्धि होती गई। इस समृद्धि से समितियाँ साख के साथ ही उत्पादन एवं वितरण कार्यों में भी भाग लेने लगीं।

केन्द्रीय सहकारी बैंक—ये प्राथमिक साख समितियों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा किसी विशेष क्षेत्र या जिले की सहकारी साख समितियों के ऊपर होते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं :—

(अ) जिनके सदस्य केवल व्यक्ति होते हैं, (आ) जिनकी सदस्यता केवल सहकारी साख समितियों तक ही सीमित होती है तथा (ई) जिनकी सदस्यता में व्यक्ति एवं सहकारी साख समितियाँ दोनों ही होती हैं। मंकलेगन समिति ने पहिले वर्ग की समितियों को निरस्तसाहित करने का सुझाव दिया था। इस प्रकार की पहिली बैंक १९०७ में स्थापित हुई तथा ३० जून १९५७ को इनकी सदस्यता ४५१, सदस्यता ३११ लाख तथा कार्यशील पूँजी ११०२६ लाख ६० थी।

राज्य सहकारी बैंक—ये सहकारी सगठन के प्रमुख बैंक हैं तथा राज्य के सहकारी सगठन, निरीक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ३० जून, १९५७ को इनकी सदस्यता २३, चुकता पूँजी एवं कोष ८७८ करोड़ ६० तथा कार्यशील पूँजी ७६\*५४ करोड़ ६० थी।

सहकारी सगठन में अनेक दोष हैं जिनके निवारण के लिए ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति, कृषि साख सर्वे समिति तथा सर माल्कम डालिंग ने अनेक सुझाव दिये हैं। कृषि साख सर्वे समिति की सिफारिशों के अनुसार रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि साख (दीर्घकालीन) कोष तथा राष्ट्रीय कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष की स्थापना की है जिससे सहकारी साख संस्थाओं की पूँजी में राज्य सरकारें हिस्सा ले सकें, केन्द्रीय भूमि-वन्धक बैंक की दीर्घकालीन ऋण दिये जा सकें तथा उनके ऋण पत्र खरीदे जा सकें। दूसरे कोष का उपयोग

राज्य सहकारी बैंको को मध्यकालीन ऋण देने में होगा जिससे वे अपने अल्प-कालीन ऋणों को आवश्यकता के समय मध्यकालीन ऋणों में बदल सकें। सहकारी गोदामों की स्थापना के लिए केन्द्रीय गोदाम कॉर्पोरेशन की स्थापना हो चुकी है तथा ऐसे ही निगम राज्यों में भी स्थापित होंगे। सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।

रिजर्व बैंक का कृषि साख विभाग राज्य सहकारी बैंकों के माध्यम से पर्याप्त सहायता देता है। यह सहायता बैंक दर से २०% छूट पर ऋण देकर भूमि-व्यय बैंकों के ऋणपत्र खरीदकर, सहकारी प्रशिक्षण की व्यवस्था द्वारा देता है।

वर्तमान मूषिघातों का अध्ययन कर दूसरी योजना के लक्ष्यों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन देने के लिए भारत सरकार ने कोलम्बो योजना के सलाह-कार सर मात्कम डालिंग को नियुक्त किया था जिन्होंने सहकारी आन्दोलन की सुदृढता के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं।

## अध्याय २५

# भारतीय बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम

समुचित एवं सुव्यवस्थित बैंकिंग अधिनियम की आवश्यकता भारत में बहुत पहले से अनुभव की जा रही थी क्योंकि देश में बैंकिंग के नियन्त्रण के लिए बेचान-साध्य विनेस विधान (१८८१) तथा भारतीय कम्पनी अधिनियम के अतिरिक्त अन्य विधान न था। इस आवश्यकता पर सर्वप्रथम केन्द्रीय बैंकिंग जाँच-समिति ने १९३१ में ध्यान दिलाया था। परन्तु उस समय अलग विधान न बनाते हुए केवल कम्पनी अधिनियम में ही संशोधन किया गया। १९३६ का भारतीय कम्पनीज (संशोधन) अधिनियम आया जिसमें बैंकिंग कम्पनियों सम्बन्धी विशेष धाराएँ जोड़ी गईं। इसके बाद १९३९ में रिजर्व बैंक ने भारत सरकार को तत्कालीन विधान की त्रुटियाँ बताकर नये विधान की आवश्यकता का महत्त्व समझाया। क्योंकि देश के अनेक बैंक उस अधिनियम की "बैंक" की परिभाषा में ही नहीं आते थे। परन्तु उस समय भारत सरकार के द्वितीय महायुद्ध में उलझे हुए होने के कारण कुछ न हो सका।

इसके बाद बैंकिंग कम्पनीज विधेयक (१९४५) बनाया गया किन्तु तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा के विलियन के कारण कुछ न हुआ। १९४६ में दूसरा "बैंकिंग कम्पनीज विधेयक (१९४६)" बना, जिसमें प्रथम समिति (select committee) द्वारा कुछ संशोधन होने के बाद वह जनवरी १९४८ में वापिस ले लिया गया। परन्तु २२ फरवरी १९४८ को तीसरा अधिनियम विधेयक पुनः प्रस्तुत किया गया जो फरवरी १७, १९४९ को स्वीकृत होकर १६ मार्च १९४९ से "भारतीय बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम (१९४९)" के नाम से लागू हुआ। इसकी कुल ५६ धाराएँ हैं। इसके लागू होने से देश के निक्षेपकों की सुरक्षा होगी और बैंकिंग संकट का भय भी न रहेगा।

अधिनियम से लाभ—(१) समुचित बैंकिंग अधिनियम देश के निक्षेप-कर्ताओं की बैंकों की वैधमानी तथा असावधानी से होने वाली हानि से रक्षा होगी तथा ऐसे बैंकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर उन्हें दण्डित किया जा सकेगा।

(२) अभी तक जो बैंकिंग सफ्ट आने रहे, उनसे यह स्पष्ट है कि बैंकिंग विधान का अभाव होने से उन पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं था, जिससे बैंको के विलियन से देश की पूंजी की असीमित हानि होनी रही। इस अधिनियम से इस हानि का निवारण होगा एवं बैंकिंग-कनेवर मुदट बनगा। इसके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि अच्छे बैंक अच्छे नियमों से नहीं बनते अपितु अच्छे बैंकरो ने बनने हैं। परन्तु फिर भी नियम-उल्लंघन का भय सीधी राह अपनाने के लिए बाध्य तो करता ही है।

(३) बैंक समाज-सेवा करने वाली संस्थाएँ हैं, इनका नियन्त्रण समाज-हित के लिए नियमित रूप से हो सकेगा।

(४) बैंक की गतिवाओं के अव्यवस्थित विकास पर प्रतिबन्ध रहगा।

इस प्रकार बैंकिंग अधिनियम बन जाने से भारत के बैंकिंग इतिहास में एक नये युग का प्रादुर्भाव हुआ है जिसमें अभी तक जो दोष थे उनका निवारण हो गया है।

परिभाषा—यह अधिनियम भारत के समस्त राज्यों में लागू होता है अर्थात् धारा ३ के अनुसार सहकारी बैंको को छोड़ कर भारत के सभी बैंक पर लागू होता है। अभी तक बैंकिंग सम्बन्धी कोई भी समुचित एवं स्पष्ट परिभाषा नहीं थी जिसका इसमें स्पष्टीकरण है। धारा ५ व के अनुसार 'बैंकिंग' उसे कहने है 'जिसमें जनता से उधार देन अथवा विनियोग के लिए निक्षेप स्वीकार किए जायें तथा जो बैंक, विक्रय अथवा आदेन अथवा अन्य प्रकार से निकाले जा सकें एवं माँग पर भुगताय जायें। कोई भी कम्पनी इस व्यवसाय को तब तक नहीं कर सकती जब तक वह बैंक, बैंकर अथवा बैंकिंग इन शब्दों का प्रयोग अपने नाम के साथ न करे (धारा ७)। इसी प्रकार कोई भी बैंकिंग कम्पनी किसी भी प्रकार का व्यापार, त्रय-विक्रय न अपने नाम में और न दूसरों के नाम में कर सकती है (धारा ८)। बैंकिंग कार्यों की सूची धारा ८ में दी गई है।

प्रबन्ध धारा १०—कोई भी बैंकिंग कम्पनी प्रबन्ध-अधिकारों की नियुक्ति नहीं करेगी और न एस व्यक्ति की नियुक्ति करेगी जो दिवालिया हो, जो कम्पनी से किसी भी प्रकार के कमीशन अथवा लाभ के रूप में पारिश्रमिक लेता हो, जो किसी अन्य कम्पनी का प्रबन्धक या मंचालक हो अथवा जिसकी नियुक्ति प्रबन्धक के तहत ५ वर्षों से अधिक समय के लिए अनुबन्ध द्वारा की गई हो अथवा जो किसी अन्य प्रकार का व्यापार करता हो।

न्यूनतम निधि एवं चुकता पूंजी—इस अधिनियम द्वारा बैंको की न्यूनतम

पूँजी तथा मचित कोप के सम्बन्ध में कुछ शर्तें लगाई गई हैं। ये शर्तें भौगोलिक कार्य-क्षेत्र के अनुसार भिन्न-भिन्न हैं और केवल उन्हीं बैंकों पर लागू हैं जो भारत में रजिस्टर्ड हैं (धारा ११)। ये शर्तें निम्न हैं—

- (१) जो बैंक एन से अधिक राज्य में व्यवसाय करते हों उनकी चुकता पूँजी तथा निधि मिलाकर ५ लाख रु० होगी।
- (२) परन्तु यदि उनका व्यवसाय बम्बई अथवा कलकत्ता में, अथवा दोनों में होगा, तो उनकी चुकता पूँजी एवं मचित कोप दोनों मिलाकर न्यूनतम १० लाख रुपए होना चाहिए।
- (३) यदि कोई बैंक केवल एक ही राज्य में व्यवसाय करता है किन्तु कलकत्ता एवं बम्बई में उसका व्यवसाय नहीं है तो उस बैंक के प्रमुख कार्यालय की चुकता पूँजी एवं कोप मिलाकर न्यूनतम १ लाख रु० होना चाहिए। यदि उसकी शाखाएँ उमी जिले में हैं तो उसकी प्रत्येक शाखा की यही राशि १० हजार रु० किन्तु उसकी शाखाएँ पृथक्-पृथक् जिलों में होने पर यही राशि २५ हजार रु० होनी चाहिए।
- (४) जब किसी बैंक के समस्त कार्यालय एक ही राज्य में हों किन्तु उसकी शाखाएँ बम्बई या कलकत्ता में हों तब उसकी पूँजी एवं निधि मिलाकर न्यूनतम ५ लाख रु० तथा कलकत्ता एवं बम्बई के बाहर की प्रत्येक शाखा की यही राशि २५ हजार रु० होना अनिवार्य है।
- (५) जिस बैंक में केवल एक ही कार्यालय एक ही स्थान पर हों तो उसकी चुकता पूँजी एवं कोप मिलाकर न्यूनतम ५० हजार रुपए होना चाहिए।
- (६) अन्य देश के रजिस्टर्ड बैंक यदि भारत में बम्बई और कलकत्ता को छोड़कर अन्य किसी स्थान में व्यवसाय कर तो उनको न्यूनतम पूँजी एवं निधि १५ लाख रुपए रखनी होगी। किन्तु यदि उनका व्यवसाय बम्बई तथा कलकत्ते में अथवा किसी भी एक स्थान पर हो तो उन्हें २० लाख रुपए पूँजी एवं निधि रखनी होगी।

चुकता, प्रायित एवं अधिकृत पूँजी तथा मतदान (धारा १२)—किसी बैंक की प्रायित पूँजी उसकी अधिकृत पूँजी के ५०% से कम नहीं होनी चाहिए और न उसकी चुकता पूँजी प्रायित पूँजी के ५०% से कम होनी चाहिए। यदि पूँजी बढ़ाई भी जाय तो वह इस नियमानुसार ही दो वर्ष की अवधि में होना चाहिए। इस हेतु उसे रिजर्व बैंक की अनुमति लेनी होगी।

बैंक की पूँजी केवल सामान्य अंशों में ही होनी चाहिए। अथवा सामान्य

अगो में तथा १ जुलाई १८४४ के पहले चेचे गये पूर्वाधिकार अगो में हो सकती है ।

प्रत्येक अगधारी को अपने अगो के अनुपात में मनवान का अधिकार है परन्तु कोई भी एक अगधारी सम्पूर्ण अगधारियों के मता के ५० में अधिक मत नहीं दे सकता ।

रोकड़ निधि—प्रत्येक सूची-बद्ध बैंक को अपनी माँग देनदारी का ५०/० तथा समय देनदारी का २०% रिजर्व बैंक के पास निक्षेप में रखना पड़ेगा (R B I Act, Sec 42) । इसी प्रकार प्रत्येक असूची-बद्ध बैंक को माँग एवं काल-देनदारी का ५० एवं २०, रोकड़ निधि रिजर्व बैंक के अथवा अपने पास, अथवा कुछ रिजर्व बैंक के एवं कुछ अपने पास रखनी होगी (धारा १८) । इस सम्बन्ध का गत मास के अन्तिम शुनवार का विवरण, समय तथा माँग देनदारी की राशि के साथ रिजर्व बैंक के पास प्रत्येक मास की १५ तारीख के पूर्व तीन प्रतियों में भेजना होगा ।

लाइसेंस (धारा २२)—रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त किये बिना कोई भी बैंक भारत में व्यवसाय नहीं कर सकता । यह लाइसेंस अधिनियम के लागू होने के ६ मास में प्राप्त करना अनिवार्य है । नये बैंको को भारत के किसी भी राज्य में व्यवसाय करने के पूर्व रिजर्व बैंक को लिखित आवेदन-पत्र भेजकर लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है । रिजर्व बैंक यह लाइसेंस देने के पूर्व किसी भी बैंक के लेखापुस्तकों की जाँच कर सकता है अथवा निम्न विषय में सन्तुष्टि कर सकता है —

- (१) बैंक अपने निक्षेपकर्ताओं के निक्षेपों का भुगतान करने योग्य है अथवा नहीं,
- (२) बैंक का प्रबन्ध निक्षेपकर्ताओं के हित में है अथवा नहीं, तथा
- (३) जो बैंक भारतीय राज्यों के अतिरिक्त अन्य स्थानों में रजिस्टर्ड है, तो उस देश में भारतीय बैंकों के विरुद्ध किसी प्रकार की वैधानिक शर्तों से नहीं है तथा वह इस अधिनियम की जो धाराएँ लागू हैं उनका पालन करता है अथवा नहीं ।

उपयुक्त बातों की जाँच होने पर यदि रिजर्व बैंक को सन्तोष होता है तो वह लाइसेंस देगा । परन्तु लाइसेंस प्राप्त कर लेने पर भविष्य में भी यदि कोई बैंक इन शर्तों का पालन न करे तो रिजर्व बैंक का उसका लाइसेंस निरस्त कर सकता है ।

शाखाएँ—कोई भी बैंक रिजर्व बैंक से लिखित स्वीकृत प्राप्त बिघे बिना किसी नई जगह में शाखा नहीं खोल सकती और न शाखा का स्थानान्तरण (उम शहर, नगर या गाँव के अनिरिक्त) अन्य स्थानों पर कर सकता है (धारा २३)। ऐसे स्थानान्तरण अथवा नई शाखा खोलने की अनुमति देने के पूर्व रिजर्व बैंक उम बैंक की आर्थिक स्थिति, गत इतिहास, सामान्य व्यवस्था, व्यवसाय, कमाने की शक्ति तथा जनता के हित की दृष्टि में बैंक का निरीक्षण कर सकता है तथा इसमें मन्तोप होने पर ही ऐसी अनुमति देगा।

वैधानिक कोष (धारा १७)—प्रत्येक बैंक को अपनी चुनता पूँजी के बराबर मचित कोष रखना अनिवार्य है। जिन बैंकों का मचित कोष चुनता पूँजी के बराबर नहीं है उनके लाभांश बाँटने के पूर्व प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ का २०% भाग मचित कोष में स्थानान्तर करना अनिवार्य है।

### बैंकिंग कम्पनियों की सम्पत्ति

(१) धारा २४—प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को अविनियम लागू होने के २ वर्ष के अन्त में कुल माँग एवं समय देनदारी के २०% सम्पत्ति भारत में रोकड़, स्वर्ण तथा मान्य प्रतिभूतियों में प्रत्येक व्यापारिक दिन के अन्त में रखनी होगी। इसका मासिक विवरण प्रत्येक बैंक रिजर्व बैंक के पास भेजेगा।

(२) धारा २५—किसी बैंकिंग कम्पनी को प्रत्येक तिमाही के अन्तिम दिन अपनी कुल समय एवं माँग देनदारी के ७५% सम्पत्ति भारत में अथवा भारत के बाहर रखनी होगी। सम्पत्ति में उन्हीं प्रतिभूतियों, प्रतिज्ञा-पत्रों तथा विलों का समावेश होगा जो रिजर्व बैंक कटौती अथवा क्रय-विक्रय कर सकता है अथवा जिनकी जमानत पर वह ऋण देता है तथा आयात एवं निर्यात विल जो भारत में अथवा भारत पर लिखे गये एवं भारत में देय हों एवं उन मुद्राओं में हों जिनकी मान्यता रिजर्व बैंक समय-समय पर सूचित करता है। इसका त्रैमासिक विवरण प्रत्येक बैंक रिजर्व बैंक के पास भेजेगा।

### बैंकिंग कम्पनियों पर अन्य प्रतिबन्ध

धारा १४—कोई भी बैंकिंग कम्पनी अपनी पूँजी पर उनकी जमानत आदि देकर प्रभार निर्माण नहीं कर सकती, अर्थात् अपनी अयाचित पूँजी की जमानत पर ऋण आदि नहीं ले सकती।

धारा १५—कोई भी बैंक अपनी असा पूँजी पर तब तक लाभांश नहीं दे सकती जब तक पूँजी व्ययों का—जिसमें प्रारम्भिक व्यय, मगठन व्यय, असा विक्रय पर कमीशन, दलाली, किसी भी प्रकार की हानि, राशि अथवा मूर्त

सम्पत्ति पर किया हुआ किसी प्रकार का अन्य व्यय आदि सम्मिलित हैं—  
विलोपन (write-off) न हो जाय ।

धारा १६—कोई भी बैंक ऐसे व्यक्ति की सचानक पद पर नियुक्ति नहीं कर सकती जो किसी अन्य बैंकिंग कम्पनी का सचालक हो ।

धारा १६—कोई बैंकिंग कम्पनी प्रत्याम काय रिजर्व साधक काय, सुरक्षा निक्षेप व्यवस्था (safe deposit vaults) तथा रिजर्व बैंक की पूर्व अनुमति से बैंकिंग कार्य के लिए आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त सहायक कम्पनी (subsidiary company) की स्थापना नहीं कर सकती ।

धारा २०—कोई भी बैंक न तो अपने जमा की जमानत पर तथा अपने सचालकों को बिना जमानत व ऋण नहीं दे सकती । इसी प्रकार वह ऐसे किसी भी फर्म अथवा निजी कम्पनी को ऋण नहीं दे सकती जिसमें उसका कोई भी सघातक साभेदार, प्रबन्ध-अधिकर्ता अथवा ऋणा की प्राप्ति के लिए जमानतदार हो ।

धारा २३—रिजर्व बैंक की अनुमति बिना कोई बैंक न नई शाखा खोल सकता है और न वर्तमान शाखा का किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण ही कर सकता है । यह नियम भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं पर भी लागू होता है ।

धारा ४४—कोई भी बैंकिंग कम्पनी रिजर्व बैंक से लिखित प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना अपनी इच्छा से अपना व्यापार बन्द नहीं कर सकती । यह अनुमति उसे तभी प्राप्त होगी जब रिजर्व बैंक को यह विश्वास होगा कि वह अपने ऋणदाताओं का भुगतान करने योग्य है ।

धारा ४५—बैंकिंग कम्पनिया की किसी भी प्रकार की एकीकरण योजना को न्यायालय तब तक स्वीकार नहीं कर सकता जब तक उन्हें रिजर्व बैंक इस आशय का प्रमाण-पत्र न दे कि 'वह एकीकरण निक्षेपकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक नहीं है' । इसी प्रकार कोई भी बैंकिंग कम्पनी किसी भी अन्य बैंकिंग कम्पनी के साथ एकीकरण की व्यवस्था नहीं करेगी अथवा एकीकरण में सहभागी न हो सकेगी जब तक वह रिजर्व बैंक से लिखित आज्ञा प्राप्त न करे । एकीकरण की योजनाओं के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रिजर्व बैंक को है जो सम्बन्धित बैंक को मान्य करना होगा [धारा ४४-(A)] ।

रिजर्व बैंक के अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार

देश की बैंकिंग व्यवस्था का संगठित एवं नियन्त्रित करने के लिए रिजर्व बैंक को सूची-बद्ध तथा असूची बद्ध बैंकों के सम्बन्ध में विशेष अधिकार दिये गये हैं—

धारा १८—रिजर्व बैंक सभी बैंकों की मांग एवं समय लेनदारी का ५% तथा २% अपने पाम जमा रख सकता है। गन मास के अन्तिम शुक्रवार का रोयड-निधि का निवारण सभी बैंकों को प्रत्येक मास की १५ तारीख तक इसे भेजना पड़ेगा।

धारा २१—रिजर्व बैंक को बैंकिंग कम्पनियों के दिये जाने वाले ऋणों को नियन्त्रित करने का अधिकार है। यदि रिजर्व बैंक को यह ज्ञात हो जाय कि बैंक की ऋण-नीति देश के हित में नहीं है तो वह किसी भी बैंक अथवा सभी बैंकों की ऋण-नीति निर्धारित कर सकता है। रिजर्व बैंक किसी भी बैंक विशेष को अथवा सभी बैंकों को यह आदेश दे सकता है कि किन कार्यों के लिए ऋण दिये जायें अथवा किनसे व्याज पर ऋण दिये जायें अथवा जमानत एवं ऋणों में कितना जन्तर (margin) रखा जाय। इस प्रकार का दिया हुआ आदेश सभी बैंकों को पालन करना होगा।

धारा २२—कोई भी बैंक रिजर्व बैंक में लाइसेंस लिये बिना बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकता, जो मन्त्रसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इस धारा के अन्तर्गत नये बैंकों को भी, चाहे वे देशी हों अथवा विदेशी, व्यवसाय करने के पूर्व तथा वर्तमान बैंकों को अधिनियम लागू होते ही ६ मास में लाइसेंस लेना आवश्यक है। इसी प्रकार यदि जिन जतों पर लाइसेंस दिया गया है उनका पूर्ण पालन न किया जाय तो उसे रद्द करने का अधिकार भी रिजर्व बैंक को है।

धारा २३—नई शाखाएँ खोलने अथवा वर्तमान शाखाओं के स्थानान्तरण के पूर्व रिजर्व बैंक को लिखित अनुमति प्रत्येक बैंक को प्राप्त करनी होगी।

धारा २७—प्रत्येक बैंक को वैधानिक रूप (form) में सम्पत्ति एवं देनदारी का स्थिति-विवरण तथा अन्य आवश्यक विवरण रिजर्व बैंक को समय-समय पर भेजने होंगे। परन्तु यदि किसी सूचना की रिजर्व बैंक को आवश्यकता हो तो वह लिखित सूचना देने पर निश्चित अवधि किसी भी बैंक से प्राप्त कर सकता है तथा जन-हित में प्रकाशित भी कर सकता है।

धारा ३५—रिजर्व बैंक किसी भी समय अपनी इच्छा से अथवा केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से किसी बैंक की लेखा-पुस्तकों तथा अन्य सम्बन्धित विवरणों का परीक्षण कर सकता है। ऐसे परीक्षण के रिपोर्ट की एक प्रति परीक्षित बैंक को देनी होगी। परीक्षण किए जाने वाले बैंक के मंचालकों एवं प्रबन्धकों का यह कर्तव्य होगा कि वे परीक्षकों के समक्ष सभी प्रकार की लेखा-पुस्तकें अथवा अन्य सम्बन्धित पत्र आदि प्रस्तुत करें। यदि इस प्रकार के परीक्षण से रिजर्व बैंक को इस बात का संतोष न हो कि उसका प्रबन्ध निक्षेप-कर्ताओं

के हित में हो रहा है तो वह केन्द्रीय सरकार के आदेश से उसे अपना व्यापार बन्द करने की आज्ञा दे सकता है अथवा उसे निक्षेप लेने से रोक सकता है।

धारा ३६ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक—

- (अ) किसी भी बैंक अथवा सभी बैंकों को किसी व्यवहार-विशेष अथवा विशेष व्यवहारों को करने से रोक सकता है अथवा उन्हें अन्य किसी प्रकार की सलाह दे सकता है।
- (ब) सम्बन्धित बैंकों की प्रार्थना पर धारा ४५ के अनुसार होने वाले एकीकरण में मध्यस्थ बन कर अथवा अन्य किसी प्रकार से एकीकरण में सहायता कर सकता है।
- (स) रिजर्व बैंक विधान धारा १५ (१) (३) के अनुसार किसी भी बैंकिंग कम्पनी का ऋण अथवा अग्रिम देकर सहायता कर सकता है।
- (द) धारा ३५ के अन्तर्गत होने वाले परीक्षण-काल में अथवा परीक्षण के बाद उस बैंक को लिखित आदेश दे सकता है कि—
  - (१) बैंक के संचालक रिजर्व बैंक की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सभा का आयोजन करे।
  - (२) आदेश में दी हुई अवधि में रिपोर्ट में दिये गये सुझावों का पालन करे।

### अन्य अधिकार

इन अधिकारों के साथ ही रिजर्व बैंक को समय-समय पर विवरण, स्थिति-विवरण तथा अन्य विशेष प्रकार की आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के हेतु निम्न अधिकार हैं —

१. प्रत्येक सूची-बद्ध बैंकों को प्रत्येक मास की १५ तारीख तक ऐसा विवरण भेजना होगा जिसमें गत मास के अन्तिम शुक्रवार के दिन उसकी कुल मांग देनदारी, समय देनदारी तथा रोक-निधि की राशि होगी [धारा १७]।

२. प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को रिजर्व बैंक के पास नियत रूप में एक ऐसा विवरण भेजना पड़ेगा जिसमें सम्पूर्ण रक्षित ऋणों तथा अग्रिमों की राशि होगी, जो ऐसी कम्पनियों को दिये गये हैं जिनमें बैंकिंग कम्पनी के संचालक अथवा बैंकिंग कम्पनी का निगम न किसी प्रकार का हित हो [धारा २० (२)]।

३. प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को रिजर्व बैंक के पास प्रत्येक मास की १५ तारीख तक ऐसा विवरण भेजना होगा जिनमें धारा २४ (१) के अनुसार उसकी मांग एवं समय देनदारी तथा २५% सम्पत्ति किस प्रकार रखी गई है, इसका विवरण होगा [धारा २४ (३)]।

४. प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को एक ऐमा त्रैमासिक विवरण भेजना होगा जिसमें धारा २५ (१) के अनुसार माँग एवं काल देनदारी की ७५% सम्पत्ति भारत में किम प्रकार रखी गई है, इसका विवरण होगा [(धारा २५ (२)]। इस सम्बन्ध में २० अप्रैल १९५१ से सशोधन किया गया है। इसके अनुसार प्रतिभूतियों की सूची, जो “भारत स्थित सम्पत्ति” में आती है, रिजर्व बैंक प्रकाशित करेगा।

५. प्रत्येक बैंक को वर्ष के अन्त में एक ऐमा विवरण भेजना होगा जिसमें ऐसे लेनों का वर्णन हो जिसमें गत १० वर्षों में कोई लेन देन न हुआ हो तथा ऐसे प्रत्येक लेन में कितनी राशि है [धारा २६]।

६. प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को धारा ८६ के अनुसार स्थिति-विवरण एवं हानि लाभ के लेने तीन प्रतियाँ अरेश्वर की रिपोर्ट के साथ एवं जिस प्रकार से प्रकाशित की गई हो, रिजर्व बैंक के पास भेजनी होगी [धारा ३१]।

७. बैंकिंग कम्पनियों की पुँजी एवं कोष के मूल्यांकन में यदि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था हो तो इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक का निर्णय अन्तिम होगा।

८. बैंकिंग कम्पनियों के बिलियन (liquidation) में यदि धारा ३६ के अनुसार रिजर्व बैंक आसक्तिय निस्तारक (official liquidator) नहीं है बल्कि कोई अन्य है और न्यायालय उसे किसी विषय पर रिजर्व बैंक से सलाह लेने का आदेश दे तो रिजर्व बैंक को अधिकार है कि वह निस्तारण सम्बन्धी किन्हीं भी लेखों का परीक्षण करे एवं उचित सलाह दे। इसके साथ ही दोषी व्यक्तियों का दण्ड देन तथा शीघ्रता से निस्तारण सम्भव बनाने का अधिकार रिजर्व बैंक को है।

### बैंकिंग कम्पनीज (सशोधन) अधिनियम (१९५१)

उक्त धाराएँ बैंकिंग अधिनियम १९४८ तथा १९५० के सशोधन के अनुसार हैं। परन्तु १९५१ में रिजर्व बैंक अधिनियम का सशोधन होने से बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम में निम्न परिवर्तन हुए हैं जो २० अप्रैल १९५१ से लागू हुए—

(१) बैंकिंग अधिनियम की धारा ३१ की पूर्ति के लिए बैंक अपना स्थिति-विवरण, लाभ हानि लेखा तथा अकेक्षक की रिपोर्टें दैनिक समाचार-पत्रों के साथ ही अन्य व्यापारिक, आर्थिक एवं बैंकिंग पत्रिकाओं में प्रकाशित कर सकते हैं।

(२) बैंकों को वैधानिक निधि एवं अन्य विशेष कोषों को पृथक् पृथक् दिखाने की शक्ति हटा दी गई है।

(३) “खरीदे हुए एवं बटौती किये हुए विल” स्थिति विवरण में ‘अग्रिम’

(advances) शीर्षक में मिलाये गये हैं। परन्तु इस पद में “ऋण, रोकड़ ऋण एवं अधिविक्रय” तथा “खरीदे हुए एवं कटौती किये हुए वित्तों” की राशि चिट्ठे में पृथक् पृथक् दिवानी होनी।

### बैंकिंग कम्पनीज (संशोधन) अधिनियम (१९५३)

बैंक का निस्तारण सुविधाजनक बनाने तथा छोटे निक्षेपकर्त्ताओं की सुरक्षा के लिए बैंक-निस्तारण विधि-समिति की सिफारिशों के अनुसार अक्टूबर १९५३ में एक अध्यादेश लागू किया था जिसका समावेश बैंकिंग अधिनियम में दिसम्बर १९५३ के संशोधन में हो गया है। ये संशोधन निम्न हैं —

- (१) हार्डकोट का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है जिससे निस्तारक को ऋणिया के लिए भिन्न भिन्न न्यायालयों में न जाना पड़े।
- (२) बैंकिंग कम्पनियों के मंचालकों के विरुद्ध दावा के सम्बन्ध में विशेष अवधि की सीमा हार्डकोट निर्दिष्ट कर सकता है।
- (३) मंचालकों की देनदारी का शीघ्र निपटारा करने के लिये बैंकिंग कम्पनियों के व्यवहारों के सम्बन्ध में उनकी जनिबाय सार्वजनिक परीक्षा।
- (४) निस्तारक द्वारा वास्तु प्रमाण देन पर बैंकिंग कम्पनी के प्रबन्धक, अधिकारी, मंचालक, निस्तारक अथवा व्यवस्थापक से बैंक की राशि अथवा सम्पत्ति का भुगतान प्राप्त करने के लिए हार्डकोट को विशेष अधिकार है।
- (५) केन्द्रीय सरकार का बैंकिंग कम्पनियों के न्यायालयीन निस्तारक की नियुक्ति करने का अधिकार है।
- (६) बैंकिंग कम्पनियों के ऋणियों के विरुद्ध जादन अथवा कुर्बी का शीघ्र ही कामागित होना।
- (७) उच्च न्यायालय अथवा केन्द्रीय सरकार के निर्देश पर रिजर्व बैंक को निस्तारक बैंक की परीक्षण का, उसमें विवरण अथवा सूचनाएँ माँगने का अधिकार है। यह अधिकार उन बैंकों के सम्बन्ध में भी है जो किसी योजना के अनुसार कार्य कर रही हैं परन्तु जो नये निक्षेप नहीं स्वीकार कर सकती।
- (८) वचन और चल खाता में जिन लोगों की कम राशि होगी उन्हें एक निर्दिष्ट रकम तक के भुगतान में प्राथमिकता।
- (९) बैंक को व्यापार बन्द करने की तिथि से ६ मास में निस्तारक को अपने ऐसे ऋणियों की सूची देना होगी जिसका निपटारा हार्डकोट को करना होगा।

### बैंकिंग कम्पनीज (संशोधन) अधिनियम (१९५६)

रिजर्व बैंक को बैंकिंग कम्पनियों के नियन्त्रण के अधिकार विस्तृत करने के उद्देश्य से दिसम्बर १९५६ में बैंकिंग अधिनियम में पुनः संशोधन हुआ। यह संशोधित अधिनियम १४ जनवरी १९५७ से लागू हुआ। इसके अनुसार—

(१) जन-हित अथवा बैंकिंग समस्याओं के हितों को प्रभावित करने वाली शासकीय अथवा अन्य नीतियों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक बैंकिंग कम्पनियों अथवा बैंकों को आदेश दे सकता है।

(२) बैंक के प्रमुख शासकीय अधिकारियों एवं प्रबन्ध-मंचालकों की नियुक्ति तथा नियुक्ति की शर्तों के सम्बन्ध में रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति लेना बैंकों को अनिवार्य है।

(३) किसी भी बैंक की मंचालक-सभा अथवा अन्य समिति अथवा अन्य सङ्गठित सभा की कार्य पद्धति की जाँच के लिए रिजर्व बैंक अपने अधिकारियों को भेज सकता है अथवा इसी कार्य के लिए एक बैंक की स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए अपने निरीक्षक (observers) नियुक्त कर सकता है।

इन संशोधनों में बैंक की कार्य पद्धति में सुधार होगा तथा उनकी कार्य-क्षमता बढ़ेगी।

### बैंकिंग कम्पनीज (संशोधन) विधेयक (१९५६)<sup>१</sup>

१२ अगस्त १९५६ को भारतीय लोकसभा में यह विधेयक स्वीकृत हो गया। इसका उद्देश्य रिजर्व बैंक को बैंकिंग समस्याओं पर कठोर नियन्त्रण दिलाना है। इसकी प्रमुख बातें निम्न हैं—

बैंक-शाखा—(१) धारा २५ के अन्तर्गत परीक्षण के अलावा अन्य सब बातों के सम्बन्ध में बैंक की शाखा की परिभाषा केवल उसी स्थान तक सीमित कर दी गई है जहाँ निक्षेप लिये जाने हों, बैंकों का भुगतान होना हो अथवा ऋण दिये जाने हों।

(२) प्रबन्ध—किसी बैंकिंग कम्पनी का प्रबन्ध ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकेगा जो किसी ऐसी कम्पनी का मंचालक है जो—

(अ) बैंकिंग कम्पनी की सहायक कम्पनी नहीं है, अथवा

(आ) भारतीय कम्पनी अधिनियम १९५६ की धारा २५ के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नहीं है।

परन्तु ये प्रतिबन्ध ऐसे किसी अस्थायी संचालक को लागू नहीं होंगे जो

अधिकतम ३ मास के लिए अथवा रिजर्व बैंक की सम्मति से जिसकी अवधि अधिकतम ६ मास के लिए और बढ़ाई गई हो ।

(३) सभापति आदि को हटाना—यदि बैंकिंग कम्पनी का प्रमुख शासकीय अधिकारी, व्यवस्थापक, सचालक अथवा गभापति ऐसा व्यक्ति है जो किसी न्यायाधिकरण (tribunal) अथवा अन्य अधिकारी द्वारा सन्निवमो का उल्लंघन करते पाया गया हो तथा रिजर्व बैंक को यह मन्तोष हो कि ऐसे व्यक्ति से बैंकिंग कम्पनी का सम्बन्ध अवाछनीय है तो रिजर्व बैंक उसे उस पद से हटा सकेगा ।

(४) लाभांश की घोषणा—बैंक अपने विनियोग, ऋणपत्र एवं बन्धकों के अवमूल्यन अथवा इवने ऋण में होने वाली हानि को अपलिखित किये बिना लाभांश की घोषणा कर सकेगा, यदि अकेलक इम बात से सन्तुष्ट ह कि इन हानियों के लिए पर्याप्त आयोजन किया गया है । (इससे अकदका की जिम्मेवारी बढ गई है ।)

(५) सचालक का पारिश्रमिक एवं नियुक्ति—पूर्णकालीन अथवा प्रबन्ध सचालक मामान्य अथवा अर्धकालीन सचालक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक निश्चित करन के पूर्व रिजर्व बैंक की अनुमति देना अनिवार्य है ।

(६). समापन—रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह आवश्यक समझे ता वह बैंकिंग कम्पनी के समापन के लिए न्यायालय को आवेदन दे सकेगा ।

(७) अधिनियम का उल्लंघन करने पर दण्ड—इस अधिनियम की किसी धारा का उल्लंघन करने अथवा आवश्यक विवरण, स्थिति विवरण एवं अन्य प्रलेख न भेजने पर सम्बन्धित बैंक के सभी अधिकारी दण्डनीय होंगे ।

समालोचनात्मक अध्ययन—इम प्रकार रिजर्व बैंक को बैंकिंग कम्पनीज अधिनियम से बैंका के सङ्गठन एवं सचालन के लिए अनन्वित अधिकार दिय गये हैं । इस विधान से हमारे देस का अभी तक जो अर्धवन्धित बैंकिंग विकास हो रहा था, वह नियन्त्रित होगा तथा शाखाएँ जो कुछ व्यापारिक केन्द्रों में ही केन्द्रित हो रही थी उन पर प्रतिबन्ध रहेगा । पूर्वी विपयक धाराओं से बैंकों का आर्थिक सङ्गठन अच्छा होगा तथा कमजोर बैंका की स्थापना भी न हो सकेगी । इसी प्रकार रिजर्व बैंक को परीक्षण सम्बन्धी जो अधिकार हैं उनसे बैंक कोई भी ऐसा कार्य न कर सकेंगे जो जनहित एवं निक्षेपकर्ताओं के हितों में न हो ।

परन्तु फिर भी इम अधिनियम में सशोधन के बाद भी कतिपय त्रुटियाँ रह गई हैं क्योंकि ऐसे छोट-छोटे बैंक, जिनकी पूँजी एवं निधि ५ लाख रु०

से कम है उन पर एवं स्वदेशीय बैंको पर यह विधान लागू नहीं होता, जो देश की लगभग ७५ प्रतिशत आवश्यकताओं की तथा लगभग ६० प्रतिशत ग्रामीण मास की पूर्ति करते हैं। जिससे इस विधान के होते हुए भी भारतीय मुद्रा-मण्डी के एक महत्वपूर्ण अंग पर किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि देश की साख-व्यवस्था को किसी भी प्रकार हानि न होते हुए इन पर किसी न किसी प्रकार का वैधानिक नियन्त्रण लगाया जाय, जो देश के बैंकिंग-विवास, मुद्रा-मण्डी व सगठन, तथा साख एवं मुद्रा के सन्तुलित नियन्त्रण के लिए आवश्यक है।

(२) छोटी-छोटी बैंकिंग कम्पनियों पर वैधानिक नियन्त्रण होना भी वाछनीय है, विशेषतः उस स्थिति में जब कि हमारा बैंकिंग-कलेवर अभी अभी कुछ सँभल पाया है, क्योंकि इनके पास न तो पर्याप्त पूंजी ही होती है और न योग्य एवं अनुभवी कर्मचारी ही हैं। ऐसी अवस्था में बैंकिंग-विकाम केवल एक ही अंग से नियन्त्रण के समुचित एवं सुरक्षित नहीं हो सकता। अतः समस्त अव्यवस्थित एवं विभक्त अंगों का एक मूल में नियन्त्रण होना अनिवार्य है, अन्यथा नियन्त्रित एवं व्यवस्थित बैंकिंग कम्पनियों का कार्य क्षेत्र प्रभावित होने की सम्भावना है, जो देश के लिए हितकर नहीं है।

(३) यह विधान (धारा ३) सहकारी बैंको पर भी लागू नहीं होता, विशेषतः जब सहकारी बैंक भी व्यापारिक बैंकों की प्रतियोगिता करने लगे। अतः आवश्यक है कि व्यापारिक एवं सहकारी बैंकों को समानता से नियन्त्रित किया जाय। हा, यह बात ठीक है कि सहकारी भूमि-वन्धक बैंकों के लिये असंग विधान हो क्योंकि वे दीर्घकालीन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यदि यह नहीं हो सकता तो सहकारी बैंकों का कार्य-क्षेत्र पूर्णरूपेण वैधानिक रीति से सीमित किया जाय।

(४) विधान से यह स्पष्ट है कि एकाधिकोप पद्धति का ही विशेष रूप से पालन किया गया है परन्तु भारत जैसे महान् देश के लिए, जिसमें २५०० नगरों में से केवल ४०० नगरों में ही बैंक अथवा उनकी शाखाएँ हैं, अधिक बैंकिंग-विकास की आवश्यकता है। अतः साख बैंकिंग के लिए समुचित नियोजन होना आवश्यक है जिससे देश की विभिन्न व्याज दरों में समानता आ सके तथा सम्भाव्य हानियों का समुचित वितरण हो व्यवस्था-व्यय कम हो एवं बैंकिंग कार्य-क्षमता भी बढ़े। विशेषतः अब तो इसके प्रोत्साहन की ओर भी अधिक आवश्यकता है जब कि ग्रामीण बैंकिंग विकास की नई योजनाएँ कार्यान्वित हो रही हैं।

(५) सम्पत्ति का देनदारी व साथ अनुपात निश्चित न करते हुए यह आवश्यक था कि किसी विशेष प्रकार की सम्पत्ति हो बैंक अपन पास रख जिससे सफ्ट के समय रिजर्व बैंक उनकी जमानत पर आर्थिक सहायता कर सकता है। क्योंकि बैंक के विलियन का कारण पर्याप्त सम्पत्ति का अभाव न होते हुए सम्पत्ति की तरलता का अभाव था, इसलिए सम्पत्ति के अनुपात की अपेक्षा यदि तरलता के लिए विशेष नियोजन किये जान तथा वैधानिक प्रतिबन्ध लगाय जान तो अधिक हितकर होता।<sup>१</sup>

(५) इसके निवा और भी त्रुटियाँ हैं, जैसा सचिव बोर्ड की स्पष्ट परिभाषा न होना, रिजर्व बैंक का सफ्ट-काल में विशेष सहायता देने के लिए अधिनियम की धारा ४ में विशेष आयोजन नहीं है।

फिर भी रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण एंव स्टेट बैंक पर सरकारी नियंत्रण होने से हम विद्वान हैं कि रिजर्व बैंक अपन अनुभव के आधार पर इन त्रुटियों का निवारण करेगा जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का उपयोग अत्यन्त दूरदर्शिता से किया है जिससे बैंकिंग क्लेवर मजबूत और कायक्षम हो गया है। साथ ही बैंक का विलियन भी कम हो गया है और रिजर्व बैंक की नीति शाख बैंकिंग की ही रही है। क्योंकि यद्यपि बैंकों की संख्या कम हो गई है फिर भी बैंकों की शाखाओं में वृद्धि हो रही है। इसमें यह स्पष्ट है कि रिजर्व बैंक अपन अधिकारों का उपयोग दाय एंव जनता के हित में ही कर रहा है।

### सागरा

भारत में समुचित बैंकिंग विधान की आवश्यकता बहुत पहिले से थी, क्योंकि देश में बैंकिंग के नियन्त्रण के लिए भारतीय कम्पनी अधिनियम तथा बेचानसाध्य विलेख अधिनियम के सिवा अन्य कोई अधिनियम न था। इस हेतु पहिला प्रयास १९४५ में बैंकिंग विधेयक बनने से हुआ, किन्तु उस समय केन्द्रीय सभा के भंग होने से कुछ न हो सका। फिर २२ फरवरी १९४८ को दूसरा विधेयक सदन में रखा गया जो १७ फरवरी १९४९ को स्वीकृत होकर १६ मार्च १९४९ से लागू हो गया।

इस अधिनियम में प्रमुख लाभ निम्न हैं—

(१) बैंकिंग क्लेवर सुदृढ़ होगा, (२) निक्षेपकर्ताओं की सुरक्षा होगी,

(३) बैंकों का नियन्त्रण देशहित में हो सकेगा, (४) शाखाओं के अव्यवस्थित विकास पर रोक रहेगी।

अधिनियम की प्रमुख धाराएँ निम्न बातों से सम्बन्धित हैं—

(१) बैंक की परिभाषा एवं कार्य, (२) प्रबन्ध, (३) न्यूनतम निधि एवं चुकता पूँजी की राशि, (४) चुकता, प्रायित तथा अधिकृत पूँजी का अनुमान तथा मतदान के अधिकार, (५) रोकड़-निधि, (६) लाइसेंस की प्राप्ति एवं निरस्ती, (७) बैंकिंग कम्पनियों की सम्पत्ति तथा (८) बैंकिंग कम्पनियों की क्रियाओं पर प्रतिबन्ध।

बैंकिंग अधिनियम से रिजर्व बैंक को निम्न अधिकार हैं—

(१) माँग एवं समय देनदारी के ५% तथा २% निक्षेप तथा इस सम्बन्ध का साप्ताहिक विवरण बैंकों से लेना, (२) बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों को नियन्त्रित करना, (३) रिजर्व बैंक को लाइसेंस देने एवं निरस्त करने का अधिकार, (४) नई शाखाएँ खोलने एवं वर्तमान शाखाओं के स्थानान्तरण की अनुमति देने सम्बन्धी अधिकार, (५) बैंकों का वार्षिक चिट्ठा एवं लाभ-हानि लेखा लेना तथा प्रकाशित करना, (६) अपनी इच्छा से अथवा केन्द्रीय सरकार की आज्ञा से किसी बैंक की लेखा पुस्तकें एवं अन्य सम्बन्धित विवरणों का परीक्षण करना एवं उसकी रिपोर्ट देना, (७) किसी बैंक अथवा सभी बैंकों के विशेष व्यवहारों पर रोक लगाना, (८) बैंकों के एकीकरण में सहायक होना, (९) अधिनियम के अन्तर्गत विवरणों एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं को बैंक से प्राप्त करना तथा (१०) बैंकिंग कम्पनियों के विलीयन में निस्तारक का कार्य करना।

रिजर्व बैंक को अधिनियम लागू होने के बाद इस सम्बन्ध में जो भी अनुभव आये, उन अनुभवों के आधार पर इस अधिनियम में १९५०, १९५१, १९५३ तथा १९५६ में संशोधन किये गये। इसी प्रकार १९५६ में रिजर्व बैंक को बैंकिंग कलेक्टर के कठोर नियन्त्रण सम्बन्धी अधिकार देने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

आलोचना—यद्यपि इस अधिनियम से बैंकिंग कलेक्टर के अनेक दोषों का निवारण हो सकेगा फिर भी इसमें कुछ दोष रह गये हैं—

(१) जिन बैंकों की पूँजी ५ लाख रु० से कम है उन पर तथा स्वदेशी बैंकों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा। इससे मुद्रा मण्डी का एक आवश्यक अंग नियन्त्रित रहेगा।

(२) सहकारी बैंकों पर अधिनियम नहीं लागू होगा।

(३) एक अधिकोष पद्धति का ही पालन विशेष रूप से किया गया है, यह अधिनियम से स्पष्ट है ।

(४) सम्पत्ति का अनुपात निर्धारित करने की अपेक्षा अधिनियम में सम्पत्ति की तरलता पर अधिक ध्यान देना वाछनीय था ।

(५) सचित्त कोष की स्पष्ट परिभाषा अधिनियम में कहीं नहीं है ।

सम्भवतः जैसे-जैसे अनुभव होता जायगा वैसे-वैसे इन त्रुटियों का निवारण होगा, ऐसी भाशा है ।

## परिशिष्ट १

### रिजर्व बैंक एक्ट में संशोधन (१९५७)

- (१) १९५७ के संशोधन ने रिजर्व बैंक, मध्यकालीन ऋण-सुविधाएँ देने के लिए जो आर्थिक संस्थाएँ स्थापित होंगी उनकी पूँजी में अभिदान (contribution) दे सकेगा।
- (२) इस संशोधन से रिजर्व बैंक अभी तक भुनाई गई पत्र-मुद्राओं (जिनका विमुद्रीकरण १९४६ में हुआ था) की देनदारी से मुक्त कर दिया गया है।
- (३) रिजर्व बैंक एक्ट की धारा ४२ में संशोधन किया गया है जिससे रिजर्व बैंक की दूसरी सूची में ऐसी संस्था का समावेश किया जायगा जिसकी अधिसूचना केन्द्रीय सरकार इस हेतु प्रकाशित करे।

### स्टेट बैंक एक्ट में संशोधन (१९५७)

- (१) इससे स्टेट बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना में प्रकाशित किसी आर्थिक संस्था के असा या ऋण पत्र खरीद सकता है अथवा रख सकता है। परन्तु इस हेतु उसे रिजर्व बैंक से परामर्श तथा केन्द्रीय सभा के निर्देश प्राप्त करने होंगे।
- (२) स्टेट बैंक ऐसी संस्थाओं को ६ मास से ७ वर्ष की अवधि के लिए ऋण स्वीकृत कर सकता है।
- (३) केन्द्रीय सभा के आदेशानुसार स्टेट बैंक क्रेय-विक्रय (hire-purchase) पद्धति पर कार्य करने वाली फर्मों एवं कम्पनियों को उनके ऋणों (book-debts) की जमानत पर ऋण दे सकेगा।
- (४) स्टेट बैंक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी कॉर्पोरेशन के गृह-निर्माण को आर्थिक सुविधाएँ देने की योजनाओं में अभिक्ता हो सकता है तथा अभिक्ता के नाते उस राशि से ऋण दे सकता है जो कॉर्पोरेशन अथवा सरकार इस हेतु से इसके पास रखे। ये ऋण अवल सम्पत्ति की जमानत पर भी दिये जा सकते हैं।

## विदेशी विनिमय बैंक—परिशिष्ट २

भारतीय बैंको के विदेशी कार्यालय<sup>१</sup>

### सूची-बद्ध बैंक

१	अलाहाबाद बैंक	३	१३	न्यू बैंक ऑफ इण्डिया	१
२	बैंक ऑफ बड़ोदा	४	१४	ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स	१
३	बैंक ऑफ इण्डिया	११	१५	प्रभात बैंक	१
४	कन्नारा बैंक	१	१६	पंजाब एण्ड सिंध बैंक	१
५	रोन्द्रज बैंक ऑफ इण्डिया	१४	१७	पंजाब कोओपरेटिव बैंक	१
६	हिन्दू बैंक	१	१८	पंजाब नेशनल बैंक	३
७	हिन्दुस्तान कर्मानियल बैंक	१	१९	सदर्न बैंक	१
८	इण्डियन बैंक	५	२०	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया	८
९	इण्डियन ओवरसीज बैंक	६	२१	ट्रेंट्स बैंक	१
१०	लक्ष्मी कर्मानियल बैंक	१	२२	युनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया	१५
११	मेट्रोपॉलिटन बैंक	१	२३	युनाइटेड कर्मानियल बैंक	१२
१२	नेशनल बैंक ऑफ लाहौर	१	२४	युनाइटेड इण्डस्ट्रियल बैंक	१
				कुल	६८

### असूची बद्ध बैंक

१	कर्मानियल बैंक ऑफ इण्डिया	१
२	फ्रंटियर बैंक	१
३	महालक्ष्मी बैंक	३
४	नेशनल सिटी बैंक	१
५	न्यू बंगाल बैंक	१
६	प्रवर्तक बैंक	१

कुल ८

### विभिन्न देशों में भारतीय बैंको के कार्यालय

१	अदन	१	६.	जापान	२
२	ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका	६	७	मलाया	१३
३	बर्मा	६	८	पाकिस्तान	६२
४	श्रीलंका	३	९	यार्डनैण्ड	१
५	हाँगकाँग	२	१०.	मयुक्त राज्य	४

<sup>१</sup> R D I Bulletin, September 1957.

**विदेशी विनिमय बैंक—परिशिष्ट ३**  
**भारतीय सूची-बद्ध बैंको की विदेशी कार्यालयों की सम्पत्ति**  
**एव देनदारी (अंतिम शुक्रवार को)**

[लाख रुपये में]

	१९५५	१९५६
रिपोर्ट देन वाले बैंको की संख्या	३०	३०
कार्यालय संख्या	१०८	१०६
देनदारी		
१ माग निक्षेप	४८,१२	४७,६१
२ समय निक्षेप	१६,०८	१७,२६
३ कुल निक्षेप	६४,२०	६४,२०
४ अन्य बैंको को देनी	१,६१	४,४६
५ शाख समायोजन (Branch Adjustment)	१२,६६	१६,८१
६ अन्य देनदारी	६,६६	७,६७
७ योग	८५,७७	९४,१५
सम्पत्ति		
८ रोकड़	१,६३	२,०८
९ अन्य बैंको में	१३,६७	६,८१
१० माग एव अल्पकालीन ऋण	—	३,६५
११ = ६ व १० का ३ से अनुपात	२४ ८%	२४ ३%
१२ सरकारी प्रतिभूतियों में विनियोग	१६,५३	२१,२३
१३ अन्य विनियोग	१,७६	२,३०
१४ १२ व १३ का ३ से प्रतिशत	३३ २%	३६ १%
१५ खरीदे गए कटौती किए हुए बिल	१४,५६	२०,०३
१६ ऋण एव अगिम	२२,३५	२३,६१
१७ १५ व १६ का ३ से प्रतिशत	५७ ५%	६६ ६%
१८ शाख समायोजन	४,२७	४,१४
१९ अन्य सम्पत्ति	७,३४	७,००
२० योग	८५,७६	९४,१५

## हिन्दी-अंग्रेजी प्रतिशब्दों की आवश्यक सूची

अग्र Forward	आलोचना Criticism
अग्र विनिमय Forward Exchange	उतार चढ़ाव Fluctuation
अग्रिम Advance	उत्क्रांति Evolution
ऋणी Debtor	लेनदार Creditor
अनुपात Proportion	उत्पाद-कर Excise Duty
अन्तरपणन व्यवहार Arbitrage	लोच Elasticity
dealing	उपयोगिता Utility
अन्तरराष्ट्रीय International	ऋण Debt
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा-कोष Interna- tional Monetary Fund	एक धातुमान Mono-metallism
वट्टा Discount	एकाधिकार Monopoly
अपूण धातुमान Limping	एकान्तरपणन Simple Arbitrage
Standard	औद्योगिक Industrial
अप्रतिबन्धित Unrestricted	बीसत Average
अप्रतिबन्धित (मुक्त) टकण Free	कार्य Function
Comage	कीमत Price
अरक्षित Fiduciary	केन्द्रीय Central
अवमूल्यन Devaluation	केन्द्रीय अधिकोष Central Bank
अवैध Illegal	कोष Treasury
असीमित Unlimited	कोष बिल Treasury Bill
असीमित विधिग्राह्य Unlimited	उपशक्ति Purchasing Power
Legal Tender	उपशक्ति-समता Purchasing Power Parity
टिकाऊपन Durability	खाद्यान्न वितरण Food Rationing
आन्तरिक Internal Intrinsic	गति Velocity
आन्तरिक मूल्य Intrinsic Value	गति-सामर्थ्य Mobility
आयात Import	ग्राह्य Acceptable
आयातकता Importer	ग्राह्यता Acceptability
आर्थिक Financial	गीण मुद्रा Token Money

घटक Factor	पत्र-चलन-निधि Paper Currency Reserve
चलन Currency	पद्धति Method
चद-लेखा Current Account	मट्टा Speculation
चलनाधिक्य Over-issue	परिक्ल्पित, परिकात्पनिक Speculative
टक, टकशाला, टकसान Mint	
टक-समता Mint Par	परिवर्तनीय Convertible
टकण Minting, Coinage	परिषद Conference
टकण-बुल्व Brassage	परिषद बिल Council Bills
टकण-लाभ Seigniorage	पुनर्मूल्यन Revaluation
तत्स्थान-दर Spot Rate	पुनःस्थापन Restoration
तत्स्थान-विनिमय Spot Exchange	पुनर्निर्माण Reconstruction
तार-प्रेषण-दर T T Rate	पुनर्गठन Reorganisation
दाशमिक Decimal	पूर्ति Supply
दाशमिक मुद्रा प्रणाली Decimal System of Coinage	पौड-पावने Sterling Balances
द्विधातुमान Bi metallism	कोष Fund
दुर्लभ मुद्रा Hard Currency	प्रतिकूल Unfavourable
धातु-निधि Metallic Reserve	प्रतिज्ञा-पत्र Promissory Note
धातु-मुद्रा Metallic Money	प्रतिनिधिक Representative
धातु-मूल्य Intrinsic Value	प्रति-परिषद-बिल Reverse Council Bills
नि शुल्क Gratuitous	प्रतिबन्धित Restricted
निधि Reserve, Pool	प्रतीक मुद्रा Token Money
नियम Law, Rule	प्रत्यक्ष Direct
नियमन Regulation	प्रत्यक्ष विनिमय Direct Exchange
नियमन करना Regulate	प्रधान मुद्रा, प्रमाणित मुद्रा Standard Money
निराकाम्य-कर Custom Duty	
निर्देशाङ्क Index Number	डाकघर Post office
निर्यात Export	बहु-अन्तरपणन Compound Arbitrage
पक्ष मे Favourable	
पत्र Note	भुत्ति Wages
पत्र-मुद्रा Paper Money	मजदूरी Wages

मन्दो Depression	विनिमय-विल Bill of
मात्रा Quantity	Exchange
माध्यम Medium	विनियोग Investment
मान Standard	विनियोग निधा हुआ भाग
मान्यता Acceptability	Invested Portion
माप, मापक Measure	विनियोगकर्ता (विनियोक्ता) Investor
मितव्ययिता Economy	वाजार Market
मिथिन-दानुमान Sympathism	विपक्ष में Unfavourable
मुद्रा Money	व्यवहार Transaction
मुद्राक Stamp	विषमता Disequilibrium
मुद्राक-कर Stamp Duty	घुल्क Fee, Charge
मुद्रा-परिमाण मिद्धान्त Quantity	नेप Balance
Theory of Money	दोधन (नुगतान) Payment
मुद्रा-वाजार Money Market	संरण-काल Transition Period
मुद्रा-संकोच Deflation	समता Parity
मुद्रा-स्फीति Inflation	समानान्तर Parallel
मूल्य-स्तर Price Level	समानान्तर माप Parallel
मौद्रिक Monetary	Standard
रजिस्व Finance	समायोजन मिलान Adjustment
रोप्य Silver	समायोजित डालर Compensated
रोप्यमान Silver Standard	Dollar
लेखा Account	समाशोधन Clearing
लोच Elasticity	समाशोधन-गृह Clearing House
वर्गीकरण Classification	संवैराह्यता Acceptability
वर्गन Commission	साह्यिकी Statutes
वस्तु-विनिमय Barter	साख Credit
विक्रय Sale	साख-पत्र Credit Note
विकास Development	तालिका Table
विधान Act	सारणी-मान Tabular Standard
विधिग्राह्य Legal Tender	मिक्का Coin
विधि-मूल्य Face Value	मिद्धान्त Theory
विनिमय Exchange	सीमित Limited

सुज्ञेयता Cognisibility	स्वर्णमान Gold Standard
नुरक्षत Security	स्वर्ण-खण्ड-मान Gold Bullion
वहनीयता Portability	Standard
सुविभाज्यता Divisibility	स्वर्ण-चलन-मान Gold Currency
स्वस्थ Stock	Standard
स्वस्थ-विनिमय Stock Exchange	स्वर्ण-विनिमय-मान Gold
स्टर्लिङ्ग क्षेत्र Sterling Area	Exchange Standard
स्टर्लिङ्ग-क्षेत्र डालर निधि Sterling Area Dollar Pool	स्वर्णमान निधि Gold Standard Reserve
स्तर Level	हानिपूर्व डॉलर Compensated
स्थायी (स्थिर) नेत्रा Fixed Account	Dollar
स्थिरता Stability	हानिपूर्ति Compensation
स्वयंपूर्ण कार्यशीलता Automatic Working	